Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

76310

सम्पदा

वर्ष १२, : अंक १

का
गया है,
तथा योजना
है, इसलिए आ
समस्याएं वही हैं,

जनवरी '६३

प्रकाशन मंत्रालय, नई दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तुलना न कीजिए !

बहुत से लोग यह पसन्द नहीं करते कि उनकी पड़ोसियों से तुलना की जाए। यही बात मेट्रिक बाटों के सम्बन्ध में है।

मेट्रिक प्रणाली से ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए मेट्रिक बाटों का उपयोग ज्यों का त्यों किया जाना चाहिये।

मेट्रिक तौलों का जोड़-तोड़ करके मन-सेर का हिसाब न लगाइये।

इससे आपका समय बेकार नष्ट होगा और लेन-देन में अक्सर नुकसान रहेगा।

सही और सुविधाजनक लेन देन के लिए पूर्ण अंकों में

मेट्रिक इकाइयों का प्रयोग कीजि

डी.ए. ६२/५४५

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ग्रन्थ स. १०३८
पुस्तकालय
गुरुकुल काँगड़ी

स्वतंत्र चिन्तना व्यावहारिक और उपयोगी सामग्री : निश्चित सफलता

सम्पदा के १२वें वर्ष में प्रवेश पर

प्रतिष्ठित महानुभावों की शुभ कामनाएं

'सम्पदा' जनवरी १९६३ से १२ वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। इस शुभ अवसर पर हमें देशों उत्साहवर्धक सन्देश प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ यहां दिये जाते हैं:—

"हिन्दी संसार के अर्थशास्त्रीय क्षेत्र में "सम्पदा" ने बड़ी सेवा की है। मैं अपनी शुभ कामनाएं भेजता हूँ।

—श्रीमन्नारायण,
सदस्य योजना आयोग, नयी दिल्ली

हिन्दी भाषा में प्रकाशित होने वाले आर्थिक मासिक पत्रों में "सम्पदा" का प्रमुख स्थान है। सम्पूर्ण देश में चल रही आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में इसने सदैव व्यावहारिक एवं ठोस सामग्री अपने पाठकों के लिए समर्पित की है।

—मोहनलाल सुखाडिया
मुख्य मंत्री, राजस्थान

"सम्पदा १२वें वर्ष में प्रवेश कर रही है—यह जान कर मुझे प्रसन्नता हुई। मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करें।

—श्री रामप्रसाद पोद्दार, बम्बई

"सम्पदा" मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। हिन्दी में ऐसे पत्रों की बहुत आवश्यकता है। आप इसको चला रहे हैं, यह बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी तो कामना इसके लिए हमेशा रहती है।

—श्रीरामकुमार बिड़ला
जे० सी० मिल्स, ग्वालियर

को स्व[illegible]
गया है, त[illegible]
तथा योजना वद्ध[illegible]ता के लिए मेरी शुभ कामनाएं है, इसलिए आज भी अत्यन्त व्यस्त होने से मैं समस्याएं वही हैं, जि[illegible]।

[illegible]नश्यामदास बिड़ला,
कलकत्ता

आपकी पत्रकारिता के लिए हार्दिक बधाई! हिन्दी में इस आर्थिक पत्रिका का उद्देश्य के प्रति सद्भावना के साथ आप जिस प्रकार निःस्वार्थ भाव से सम्पादन कर रहे हैं, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं।

—राममूर्ति महरोत्रा
जे. के. ग्रुप, कमला टावर, कानपुर

इस पत्रिका के द्वारा हिन्दी जानने वालों को आप देश की आर्थिक समस्याओं पर अच्छी जानकारी दे देते हैं। किसी प्रकार के वाद (इज़्म) से न बांधकर आपने जिस स्वतन्त्र नीति का अवलम्बन किया है, उसके कारण इसकी उपयोगिता और भी बढ़ गयी है। मुझे आशा है कि हिन्दी संसार तथा देश की आर्थिक समस्याओं में रुचि लेने वाले इस प्रयत्न को और भी प्रोत्साहन देंगे।

जी. एल. बंसल, सेक्रेटरी,
फैडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ इंडस्ट्री एण्ड कमार्स,
नयी दिल्ली।

'सम्पदा की प्रगति जानकर प्रसन्नता हुई। आप जैसे सुयोग्य सम्पादक के सम्पादकत्व में पत्रिका अवश्य ही सफलता प्राप्त करेगी।

—श्रीगोपाल नेवटिया
बम्बई

मेरी मंगल कामना तो सदैव 'सम्पदा' के साथ रहती है, मुझे आशा है, कि आप जैसे सुयोग्य सम्पादक के नेतृत्व में यह सफलता प्राप्त करेगी।

—दुर्गाप्रसाद मंडेलिया
ग्वालियर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विषय सूची

१. आगामी वर्ष की आर्थिक समस्याएं		५
२. सम्पादकीय टिप्पणी		८
३. देश का विकासशील उद्योग : बाल-बेयरिंग		१०
४. भारत का वस्त्रोद्योग—एक दशक	ला० भरतराम	११
५. श्री गोपालकृष्ण गोखले	श्री गोकुलचन्द जांगिड़	१४
६. तेल के लिए आत्म निर्भरता की ओर	श्री खण्डू भाई देसाई	१६
७. १९६२ का सिंहावलोकन		१९
८. पशु-पालन और दूध की समस्या		२३
९. आसाम का समृद्ध राज्य	श्री सुभाष	२६
१०. तीसरी योजना और देश की प्रतिरक्षा	श्री श्रीमन्नारायण	२७
११. नये कर ही एकमात्र उपाय		२९
१२. विश्व का प्रबल वेग से नगरीकरण		३१
१३. रूस में कीमतें कैसे नियंत्रित होती हैं ?	प्रो० विरयान	३२
१४. नया सामयिक साहित्य		३४
१५. अर्थवृत्त-चयन		३९
१६. तीसरी योजना का प्रथम वर्ष		४१
१७. चीनी आक्रमण और शराब		४५
१८. राज्यों की गति-विधि (मध्यप्रदेश)		४७
१९. भारतीय खेती और नई परिस्थितियां		५०

भारत में अर्थ-शास्त्र के अध्ययन का स्तर नीचे जा रहा है

श्री वी० आर० पिल्ले, अध्यक्ष अखिल भारतीय अर्थ-शास्त्र सम्मेलन

अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए आवश्यक है कि छात्र केवल अपनी पाठ्य-पुस्तकों पर निर्भर न करें, नित्य नयी पैदा होने वाली आर्थिक समस्याओं और नयी गतिविधियों का भी अध्ययन करते रहना चाहिए ।

और हमें विश्वास है कि हिन्दी की एकमात्र आर्थिक पत्रिका 'सम्पदा' विद्यार्थियों की इस कमी को पूर्ण करती है । यदि आप 'सम्पदा' नहीं मंगवाते तो आज से मंगवाना शुरू कर दीजिये । 'सम्पदा' का अध्ययन आपकी जानकारी को अप-टु-डेट रखेगा । बहुत सारे विद्यार्थियों ने परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किये हैं ।

मैनेज

"

२८/११ शक्तिनगर,

दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

113079
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

113079

वर्ष : १२
अंक : ११
जनवरी : १९६३

सम्पदा

आगामी वर्ष की आर्थिक समस्याएं

'सम्पदा इस अंक से अपने जीवन के बारहवें वर्ष में प्रवेश कर रही है। सम्पदा के प्रारंभ के साथ साथ देश के आर्थिक इतिहास में प्रथम पंचवर्षीय योजना के सूत्रपात द्वारा नये अध्याय का श्रीगणेश हुआ। इन ग्यारह वर्षों में देश की आर्थिक नीति निरन्तर आगे बढ़ने की रही है। इसमें अनेक कमियों के बावजूद उसे सन्तोष जनक सफलताएं प्राप्त हुई हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना पहली दो योजनाओं की अपेक्षा अधिक महत्वाकांक्षा पूर्ण थी। इसके लक्ष्य पहली दो योजनाओं के योग के बराबर थे।

तीसरी योजना निरन्तर प्रयत्नों, दस वर्ष कालीन अनुभवों तथा विदेशों से मिलने वाली सहायता आदि के कारण आगे बढ़ती जा रही थी। इस का लक्ष्य ही स्वतः स्फूर्त योजना का निर्माण था। इसमें सन्देह नहीं, कि अनेक असफलताओं के बावजूद यह योजना अपने लक्ष्य पूर्ण कर रही थी।

चीन के हमारी पवित्र भूमि पर निर्लज्ज आक्रमण ने हमारी आर्थिक प्रगति और योजनाओं को एक नया मोड़ देने पर विवश कर दिया है। समस्त राष्ट्र ने इस चुनौती को स्वीकार किया और प्रतिरक्षा के लिए पूर्ण सनद्ध हो गया है, तथापि वह अपनी तीसरी योजना के मुख्य लक्ष्य तथा योजना बद्ध विकास को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आज भी आर्थिक क्षेत्र में हमारी बहुत सी समस्याएं वही हैं, जिन का हल प्रतिवर्ष योजना की पूर्ति के लिए आवश्यक करना होता है। किन्तु युद्ध कालीन नई परिस्थितियों ने नई समस्याओं को भी उत्पन्न कर दिया है।

इस वर्ष हमारी सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि हम राष्ट्र को सैनिक तथा सामरिक दृष्टि से सन्नद्ध कर लें। अब तक हमारी योजनाओं का मुख्य लक्ष्य उद्योग तथा कृषि में अधिकाधिक उत्पादन, शिक्षा, चिकित्सा आदि लोकोपयोगी सेवाओं का विस्तार रहा है। हमने सामरिक तैयारियों पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि आज के संघर्ष युग में आवश्यक था। हमारी राष्ट्रीय आय का बहुत कम भाग रक्षा कार्यों में लगता था। अब नई परिस्थितियों के कारण हमें अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों में कुछ परिवर्तन करने के लिए विवश होना पड़ा है। रक्षा कार्यों को सब से अधिक प्राथमिकता देना सर्वोपरि महत्व पूर्ण कर्तव्य है। हमें अपनी सेना को पूर्णतः प्रशिक्षित और सन्नद्ध करना होगा तथा उसको अधिकाधिक आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित करना होगा। इसके लिए हमें अपने कारखानों में युद्धोपयोगी सामग्री विशेष रूप से तैयार करनी होगी। अभी तक कारखानों में युद्धोपयोगी आधुनिक सामग्री तैयार करने की ओर हमारा ध्यान कम था। हम अपने भोलेपन के कारण यह भूल गए थे कि संसार बहुत कुटिल है। इसलिए हमारी समस्त शक्ति पूंजीगत सामान तथा उपभोग्य सामग्री तैयार करने में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उत्पादन व्यय में कमी : मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण : योजना में हेर फेर

लगी हुई थी। अब हमें अपने कारखानों की उत्पादन प्रक्रिया को जहां बदलना है, वहां तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए हमें विदेशों पर भी निर्भर करना पड़ेगा। हमारे सौभाग्य से अमेरिका, ब्रिटेन आदि मित्र देश हमें उदार सहायता भी दे रहे हैं। फिर भी हमें विपुल मात्रा में विदेशी मुद्रा चाहिए जिससे हम आवश्यक सामग्री विदेशों से ले सकें।

× × ×

विदेशी मुद्रा की प्राप्ति का प्रयत्न तो पिछले अनेक वर्षों से हो रहा है किन्तु अब उसकी आवश्यकता चरम सीमा पर पहुँच गई है। हमारी मुख्य कठिनता यह है कि विदेशों में हमारा निर्यात यथेष्ट मात्रा में नहीं जा रहा। उत्पादन व्यय की अधिकता, बाजार में विदेशों की प्रति स्पर्द्धा तथा हमारे परम्परागत निर्यात की स्थानापन्न वस्तुओं का निर्माण आदि अनेक बाधाएं हैं, जिनका हमें समाधान करना है। उत्पादन व्यय कैसे कम हो, यह स्वयं अनेक प्रश्नों को जन्म देता है। उत्पादन व्यय कम करने के लिए कृषि-जन्य पदार्थों के मूल्य कुछ नीचे गिरने चाहिये, मजदूरी का उत्पादन के साथ सम्बन्ध जोड़ना चाहिए। रेशनलाइजेशन तथा प्रबन्ध-सम्बन्धी कुशलता द्वारा अपनी उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। ये सब प्रश्न अपने आप में बहुत कठिन हैं। न किसान मूल्य स्तरों को कम करना चाहता है और न मजदूर अपनी मजदूरी में एक पैसा कम करने को तैयार है। उद्योगपति भी अपने लाभ में कमी होने पर घोर असन्तोष प्रकट करते हैं। जब तक इन तीनों का समन्वय न हो, उत्पादन व्यय में कमी करना कठिन है। पदार्थों के मूल्य में कमी के बिना हम निर्यात व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, और न विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं।

आज चीन के आक्रमण के कारण देश में राष्ट्रीयता की जो प्रबल भावना उत्पन्न हो चुकी है, उसका पूरा लाभ उत्पादन व्यय में कटौती को मिलना चाहिए। विभिन्न उद्योगों में संचालकों और श्रमिकों में उत्पादन बढ़ाने और परस्पर संघर्ष न बढ़ाने के कुछ प्रशंसनीय प्रयत्न अवश्य हुए हैं। इसी भावना का उत्पादन व्यय में कमी के लिए भी लाभ उठाना चाहिए।

× × ×

युद्ध काल में मूल्यों में वृद्धि नहीं हो, यह बहुत आवश्यक है। सन्तोष की बात यह है कि अभी तक मूल्य नहीं बढ़े हैं, कुछ कम ही हुए हैं। इन्हें अभी और कम करने की आवश्यकता है। इसलिए मूल्यों की स्थिरता के नाम पर निम्नतम मूल्य निर्धारित करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत हमें औद्योगीक पदार्थों के भी मूल्य कम करने की ओर ध्यान देना चाहिए। मूल्यों पर उचित नियंत्रण आगामी वर्ष की एक बहुत बड़ी समस्या है। संभावित अनिवार्य मुद्राप्रसार का जो पहले से ही हो रहा है। परिणाम आज नहीं तो कुछ समय बाद, मूल्य वृद्धि के रूप में हो भी सकता है। हमें विश्वास है कि जनता के सहयोग को देखते हुए हम इस समस्या पर विजय पा सकेंगे।

जनोपयोगी वस्तुओं का—कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में उत्पादन निरन्तर बढ़ते रहना चाहिए। उत्पादन का स्तर हम जितना ऊंचा रख सकेंगे, उतनी ही देश की आवश्यकताएं पूर्ण होंगी और जनता में युद्ध कार्यों के लिए भी उत्साह बढ़ेगा। उत्पादन में वृद्धि हमारे निर्यात को बढ़ाने में ही सहायक न होगी, मुद्रा प्रसार के दुष्परिणामों पर भी अंकुश रखेगी।

× × ×

इस वर्ष की एक नई समस्या यह उत्पन्न हो गई है, कि योजना के लक्ष्यों में थोड़े बहुत हेर फेर करने पड़ रहे हैं। विभिन्न राज्यों की योजनाओं में कुछ कटौती करनी पड़ी है और परिणामतः अनेक जनोपयोगी कार्य इस वर्ष स्थगित कर देने पड़ेंगे। शिक्षा चिकित्सा, मनोरंजन आदि के अतिरिक्त छोटी मोटी सड़कों, बड़े-बड़े भवनों और कुछ कम आवश्यक वस्तुओं के उद्योगों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अनेक नये उद्योगों के लिए न मशीनरी मिल सकेंगी और न विदेशी मुद्रा। आयात होने वाले पदार्थों पर कुछ प्रतिबन्ध बढ़ाने पड़ेंगे। इनके कारण पैदा होने वाली कठिनाइयों को हम दूर कर सकते हैं, बशर्ते कि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मितव्यय की ओर : रहन सहन में सादगी : जन सहयोग : नये भारी कर

जनता का हार्दिक सहयोग प्राप्त हो। यदि हम अपने जीवन को अधिक सादा बना लें, अपने व्यय अधिक से अधिक कम करें और ज्यादा से ज्यादा बचत करने की ओर हमारा ध्यान हो तथा देहातों में लोग श्रमदान करके अपनी अनेक आवश्यकताएं पूर्ण करें तो ये समस्याएं कुछ हद तक दूर हो सकती हैं। २० दिसम्बर को सरकार ने २११ उद्योगों को फिलहाल आयात के लायसंस न देने का निश्चय किया है। इन उद्योगों में ट्रैक्टर, साइकिल, व्यापारिक गाड़ियां, रिफ्रेजिरेएटर, बिजली के पंखे, रेजर, ब्लेड, टाइपराइटर, पानी के मीटर आदि हैं, तो रंग, कास्टिक सोडा, श्रृंगार सामग्री, अखबारी कागज, साबुनवनस्पति पदार्थ भी हैं।

× × ×

नये वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के साथ ही केन्द्र और विभिन्न राज्यों के वित्तमंत्री जो प्रस्ताव उपस्थित करेंगे, उनके लिए देश को अभी से तैयार हो जाना चाहिए। एक अनुमान के अनुसार हमें प्रतिरक्षा बजट में ९-१० अरब रुपये की राशि नियत करनी पड़ेगी। वर्तमान संशोधित बजट के अनुसार यह राशि करीब ४ अरब रुपये है। बहुत सम्भवतः ३ अरब रुपये तक की सहायता विदेशों से मिल सकेगी। शेष ३ अरब रुपया नये करों द्वारा सरकार को प्राप्त करना होगा। विभिन्न राज्यों को केन्द्र अपने अनुदान में जिस तरह कमी कर रहा है, उसे देखते हुए राज्यों को भी नये कर लगाने पर विवश होना पड़ेगा। यह बढ़ा हुआ कर भार सहन करने के लिए देश को उद्यत होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्र नागरिकों से जिस त्याग की आशा करता है, वह उसे करना होगा। आज देश में व्याप्त भावनाओं को देखते हुए करों में इस वृद्धि पर बहुत असन्तोष प्रकट नहीं किया जाएगा, तथापि, हमें यह आशा करनी चाहिए कि वित्त मन्त्री यथासम्भव कम कर लगायेंगे और इनकी अवधि भी यथासम्भव कम रखेंगे। इसके साथ ही प्रशासन को यह भी ध्यान रखना होगा कि वह जहां जनता पर बोझ डाले, वहां अपने खर्चों में भी यथा सम्भव कमी करे। प्रायः प्रतिवर्ष जनता के प्रतिनिधि प्रशासन और उसके आडम्बर पर मित-व्यय का आग्रह करते है, किन्तु इधर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। पिछले वर्षों में प्रशासन और विकासेतर कार्यों का व्यय द्रुतगति से बढ़ता जा रहा है।

× × ×

अहमदाबाद में दिसम्बर के अन्त में अर्थशास्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। वर्तमान संकट के उद्धार के लिए अनेक अर्थ-शास्त्रियों ने जहां पंचवर्षीय योजना में कमी का सुझाव रखा, वहां दूसरे विद्वानों ने तीसरी योजना के लक्ष्यों में थोड़ा बहुत हेर-फेर करते हुए भी मुख्य लक्ष्यों की पूर्ति पर ही बल दिया था। श्री घनश्याम दास बिड़ला ने तो इस के लक्ष्य और भी ऊंचे करने की सलाह दी है। इन विचारकों का मुख्य युक्तिक्रम यह है कि यह युद्ध लम्बा चलेगा और इसके लिए हमें पूंजीगत उद्योगों का विकास स्वयं कर लेना चाहिए, चिरकाल तक हम विदेशों पर निर्भर नहीं रह सकते। जीप, टैंक, वायुयान, तोपें तथा अन्य युद्ध सामग्री की अनेक वर्षों तक जरूरत पड़ेगी। देश का उत्पादन सामर्थ्य जितना अधिक होगा, उतना ही हम शत्रु को रोक सकने व खदेड़ने में समर्थ रहेंगे। दूसरा विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों के उत्पादन सामर्थ्य के कारण ही जीता गया था। भारत सरकार की नीति भी यही है।

उक्त सम्मेलन में अनेक अर्थ-शास्त्रियों ने अतिरिक्त करों को वर्तमान संकट में अनिवार्य बताया और ज्यादा आय वालों को इस समय अधिकतम त्याग करने की सलाह दी है। गत विश्वयुद्ध के अतिरिक्त लाभ कर का उदाहरण भी दिया गया और कुछ विद्वानों ने मुद्रा प्रसार का आश्रय लेने की सलाह दी है, तो कुछ ने प्रशासन के भारी व्यय में भारी कमी पर बल दिया है। वस्तुतः, ये सभी उपाय हमें अपनाने होंगे, तभी हम वर्तमान संकट का सामना कर सकेंगे। सबसे बड़ी समस्या तो जनता का हार्दिक सहयोग प्राप्त करने की है। हम अधिक से अधिक मितव्यय करें—खाने पीने में, कपड़ों में, यात्रा में, तेल व बिजली में, तथा अन्य सुखों के उपभोग में। जिस वस्तु का खरीदना कुछ समय के लिए टल सकता हो, वह न खरीदें, अपना उत्पादन—कृषि व उद्योग में—अधिक से अधिक श्रम करते हुए बढ़ाने का प्रयत्न करें। जनता का हार्दिक सहयोग ही राष्ट्र की समस्याओं का समाधान कर सकता है।

● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बैंक दर में परिवर्तन

जनवरीके प्रथम सप्ताहमें दो समाचार करीब एक साथ मिले हैं। एक नयी दिल्लीसे और दूसरा लन्दन से। नयी दिल्ली से यह घोषणा हुई है कि रिजर्व बैंक ने अपना ब्याज दर ४ प्रतिशत से बढ़ाकर ४॥ प्रतिशत कर दिया है और दूसरी ओर लंदन से यह घोषणा हुई कि वहां बैंक दर ४॥ प्रतिशत से कम करके ४ प्रतिशत कर दिया गया। यह दोनों परस्पर विपरीत घोषणाएं अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुसार हुईं। अपनी स्थापना के बाद १५ वर्ष तक रिजर्व बैंक ने अपना ब्याज दर ३ प्रतिशत रखा। उसका उद्देश्य बाजार में मुद्रा को सुलभ बनाना था। नवम्बर १९५१ में इस ब्याज को ३ से ३॥ प्रतिशत कर दिया गया इसके बाद मई १९५७ में इसे फिर ३॥ प्रतिशत से बढ़ाकर ४ प्रतिशत कर दिया गया। आखिरी परिवर्तन इस जनवरी के आरम्भ में हुआ और ४॥ प्रतिशत कर दिया गया।

दूसरी ओर ब्रिटेनने इसी पहली जनवरी से ब्याज दर कम कर दिया है। भारत में आज रुपये की तंगी है। लोग अधिकाधिक रुपया चाहते हैं। सरकार आज यह नहीं चाहती कि उद्योगों का बिना विवेक के विकास हो। इसलिए वह रुपयेको कुछ महंगा करना चाहती है। बैंक दर में वृद्धि का एक परिणाम यह होगा कि उद्योगों में रुपया लगाने का आकर्षण कुछ कम हो जाएगा और सरकारी सैक्योरिटियों के मूल्य भी कुछ बढ़ जावेंगे। दूसरे, उद्योगों का उत्पादन-व्यय बढ़ जाएगा। सरकार इसे न जानती हो, यह बात नहीं है। इसीलिए उसने त्रिखण्डीय योजना के बजाय द्विखण्डीय योजना की घोषणा की है। इसके परिणामस्वरूप रिजर्व बैंक से अधिक रुपया लेनेवाले बैंकों को अधिक हानि नहीं होगी। अपने कोटे का २५ प्र.श. लेने पर तो ४ की जगह ४॥ प्रतिशत देना होगा। लेकिन २५ से ५० प्रतिशत लेनेवालों को ५ की जगह ४॥ प्रतिशत ही देना पड़ेगा। वस्तुतः बैंक दर में इस ब्याज-वृद्धि का क्या परिणाम होगा, यह कुछ समय बाद ही कहा जा सकेगा।

लंदन में बैंक की दर कम किये जाने के अनेक कारण हो सकते हैं। वहां गोदामों में माल बहुत जमा हो रहा था। उसे निकाल लेने के लिए ब्याज-दर में कमी करना आवश्यक समझा गया। डेढ़ वर्ष पूर्व वहां बैंक की दर ७ प्रतिशत तक थी उस समय ब्रिटेन में रुपये की कमी थी और विदेशी मुद्रा को खींचना आवश्यक था। ज्यों-ज्यों इंगलैंड की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती गयी, त्यों-त्यों वह बैंक-दर कम हो गयी।

जहाजी उद्योग में विदेशी पूंजी

कांग्रेस के संसदीय दल की कार्यकारिणी समिति ने एक प्रस्ताव के द्वारा यह बात स्वीकार कर ली है कि विदेशियों को भारत की जहाजी कम्पनियों के पूंजी-निर्माण में २५ प्र. श. से भी अधिक भाग संभवतः ४० प्रतिशत लेने की अनुमति दी जाए। 'इण्डियन मर्चेंट्स शिपिंग एक्ट' के अनुसार अभी तक विदेशी कम्पनियों को भारत की जहाजी कम्पनियों में २५ प्र.श. से अधिक पूंजी लगाने का अधिकार नहीं है। कुछ अर्थ-शास्त्रियों का यह विचार है कि यदि विदेशी कम्पनियों को अधिक पूंजी लगाने का अधिकार दिया जाय, तो जहाजी उद्योग को अपने विकास के लिए विदेशी मुद्रा की कठिनता कम हो जाएगी।

इस सुझाव के विरुद्ध भारत के जहाजी उद्योग में प्रतिक्रिया हुई है। सिंधिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी की डायरेक्टर श्रीमती सुमति मुरारजी ने बताया है कि २५ प्रतिशत से ४० प्रतिशत तक विदेशी कम्पनियों को शेयर देने की अनुमति देने का सुझाव कहां तक युक्तिसंगत है, यह सोचने की बात है। ऐसा सुझाव देने से पहले भारत के जहाजी-उद्योगों से विचार-विमर्श करना जरूरी था। 'नेशनल शिपिंग बोर्ड' ने जहाजी उद्योग के विकास का लक्ष्य १४.२५ लाख टन रखा था, जिसे योजना-आयोग ने कम करके ११.५ लाख टन कर दिया है। आज भारत में १०.२६ लाख टन के जहाज हैं और २.६८ लाख टन के जहाज बन रहे हैं तथा २.२५ लाख टन के जहाजों का निर्माण विचाराधीन है। यदि यह भी मान लिया जाए कि कुछ जहाज शीघ्र ही बेकाम हो जावेंगे, तो भी हम १२.५ लाख टन के लक्ष्य तक पहुँच ही चुके हैं। इस स्थिति में विदेशी कम्पनियों को इस क्षेत्र में अधिक प्रवेश की अनुमति देना बुद्धि-संगत नहीं है। इन दोनों विचारों में सत्य का एक अंश हो सकता है। लेकिन यह तो ठीक ही है कि जहाजी उद्योग जैसे असाधारण महत्व के उद्योग में विदेशी पूंजीपतियों का जितना कम प्रवेश हो, उतना अच्छा है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

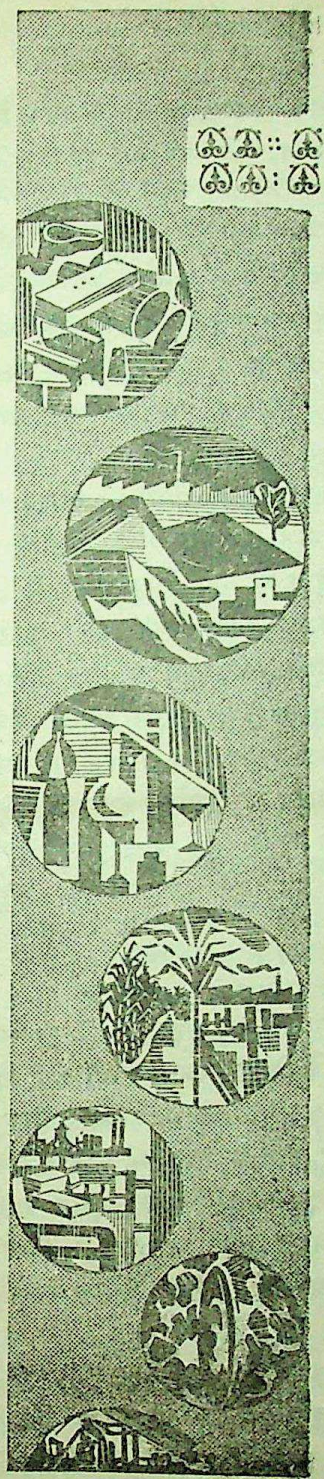

नये क्षितिज

स्वतंत्रता पूर्व युग में भी जनता के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए भारत की योजनाएं और कार्यक्रम थे। पर उनमें मौलिक निर्बलता थी—कि उनका सम्बन्ध जनता की अपेक्षा सरकार के साथ अधिक था।

स्वतंत्रता आई और इसके साथ नव-जागरण और जनता की योजनाएं—जनता के लिए और जनता के द्वारा। इसके परिणाम स्पष्ट थे. अधिक से अधिक बेहतर व सस्ती वस्तुएं अधिक से अधिक लोगों के लिए बेहतर जीवन।

डालमिया उद्योग समूह

निरन्तर ऐसे सामान का अधिक से अधिक उत्पादन करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो हमारे जीवन स्तर को ऊंचा करने में सहायक हो। हम यह काम न केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से किन्तु लगभग एक चौथाई सदी से कर रहे हैं। यह काम कठिन होते हुए भी हम निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं, इस आशा के साथ कि कल का दिन अधिक उज्ज्वल, नव-प्रभात एवं नये क्षितिज से युक्त होगा।

DALMIA ENTERPRISES

डालमिया सिमेंट (भारत) लि., डालमियापुरम् (मद्रास)
डालमिया आयरन एंड स्टील लि., राजगंगपुर व कलकत्ता
डालमिया मेगनेसाइट कार्पोरेशन, सेलम (मद्रास राज्य)
उड़िशा सिमेंट लि. राजगंगपुर (उड़िशा राज्य)
रजा बुलन्द शूगर कं. लि., रामपुर (उ. प्र.)
दि रामपुर डिस्टिलरी एंड केमिकल कं. लि., रामपुर (उ.प्र.)

राष्ट्र की सेवा में सन्निहित

डालमिया उद्योग-समूह

मुख्य कार्यालय—४, सिन्धिया हाउस, नयी दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देश का विकासशील उद्योग : बाल बेयरिंग

देश के औद्योगिक विकास के लिए और विशेष कर इंजिनीयरींग उद्योग में जिन पुर्जों की देश को आत्म निर्भर बनाने की बहुत अधिक आवश्यकता है, इन में से "बाल और रोलर बेयरिंग" एक मुख्य वस्तु है। पम्प बनाने हों, बिजली के पंखे या साइकिल मोटर, डीजल इंजन और मशीन टूल बनाने हों, या सूती मिल की मशीनरी और मोटर गाड़ियां, ट्रक या स्कूटर, रिक्शा बनानी हों या ठेले—इन सबके लिए बाल बेयरिंग की अनिवार्य आवश्यकता होती है। यही कारण है कि योजना आयोग ने इसके उत्पादन और विकास के लक्ष्य अपनी योजनाओं में निश्चित किये हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अनुसार बाल बेयरिंग के उत्पादन और विकास के निम्नलिखित अंक दिये गये हैं :—

	बाल बेयरिंग (लाख की संख्या में)
१९५०-५१	१
१९५५-५६	९
१९६०-६१	२४ (संभावित)
१९६५-६६	१२० (लक्ष्य)
पहले १० वर्षों में प्रतिशत वृद्धि	२३००
तीसरी योजना में प्रतिशत वृद्धि	४००

इन संख्याओं को देखने से ही यह स्पष्ट है कि इस उद्योग के विकास की कितनी अधिक आवश्यकता है। वस्तुतः, इसके बिना देश के अधिकांश उद्योगों को विदेशों से आयात पर निर्भर करना पड़ता है।

आज से १२ वर्ष पूर्व भारत में बाल बेयरिंग बनाने वाला कोई कारखाना नहीं था। न केवल भारत में किन्तु दक्षिण पूर्व एशिया में भी इस तरह का कोई उद्योग नहीं था। सब से पहले १९५० में भारत के प्रमुख उद्योग पति बिड़ला बन्धुओं ने जयपुर में इस उद्योग का श्रीगणेश किया। यह उद्योग इंगलैंड की प्रसिद्ध हाफमैन मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी के प्रशिल्पिक सहयोग से प्रारम्भ किया गया और इस में पहले वर्ष १९ विभिन्न प्रकार के ३२ हजार बेयरिंग बने। लेकिन आज भारत के इस प्रसिद्ध उद्योग संस्थान में भिन्न-भिन्न १८० आकार के ४० लाख बाल बेयरिंग बनते हैं। अकेला यही कारखाना भारत के अधिकांश साइकल, पंखें, बिजली की मोटरों, स्कूटरों, ट्रेक्टरों, क्रेनों, रिक्शा आदि की आवश्यकताएं पूर्ण करता है। इतना बड़ा कारखाना, शायद, एशिया में कोई दूसरा नहीं है।

रेलवे एक्सल बाक्स के बनाने के लिए भी रोलर बेयरिंग की आवश्यकता होती है। अब इसी कारखाने में भारतीय रेलों के लिए "रेलवे एक्सल बाक्स" बनाने का संयन्त्र भी लगा दिया गया है। आजकल इस संयन्त्र से भी ३० हजार एक्सल बाक्स भारतीय रेलों के लिए तैयार होते हैं। भारत में "एक्सल बाक्स" बनाने वाला और कोई दूसरा कारखाना नहीं है।

देश में निरन्तर नये-नये उद्योगों की स्थापना हो रही हैं। पंचवर्षीय योजना में, उद्योग के प्रकरण में, बीसियों नये उद्योगों की गणना की गयी है जो देश में विकसित हो रहे हैं। इसके कारण बाल बेयरिंग की आवश्यकता भी लगातार बढ़ रही है। उदाहरण के लिए, १९५०-५१ में १.०१ लाख साइकिल तैयार हुए थे, जबकि १९६५-६६ में २० लाख साइकिल उत्पादन का लक्ष्य है। इसी तरह पंखें, स्कूटर, मोटर आदि के निर्माण के लक्ष्य भी बहुत ऊंचे हो गये हैं। इन बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जयपुर के इस कारखाने को भी बहुत विस्तृत किया जा रहा है। योजना के अनुसार, इसका उत्पादन दुगुना कर दिया जाएगा और इसके किस्मों में भी बहुत विविधता लायी जाएगी। संसार में उपलब्ध सर्वोत्तम मशीनरी मंगवाई जा रही हैं, जिससे उत्पादन न केवल बहुत बढ़ सके किन्तु इसका स्तर भी ऊंचा हो सके। समस्त देश में एन. बी. सी. के नाम से प्रसिद्ध बाल बेयरिंगस का वितरण करने के लिए भी सब बड़े औद्योगिक नगरों में प्रबन्ध किया गया है। इसका अधिकांश काम मशीनों से होताहै। फिर भी कार्य के विस्तार को देखते हुए इस कारखाने में दो हजार श्रमिक और ३५० कर्मचारी काम करते हैं।

कलकत्ता और बम्बई में भी कुछ वर्षों से बाल बेयरिंग के कारखाने खुले हुए हैं और पूना में भी एक नयी फैक्टरी बन रही है, किन्तु जयपुर की विस्तार योजना को देखते हुए इस उद्योग में उस को प्रमुख और महत्त्वपूर्ण स्थान बना रहेगा। ● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सूती कपड़ा मिलें : गत दशाब्दि पर एक दृष्टि

श्री लाला भरतराम, अध्यक्ष भारतीय कपड़ा मिल संघ

पहली पंचवर्षीय योजना, (१९५१-५६) एक सामान्य आधार पर बनायी गयी थी। इसका मुख्य उद्देश्य था, युद्ध और विभाजन से ध्वस्त देश की वित्त-व्यवस्था में सहायता करना। उस समय सूती-वस्त्र के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, वे ऐसे थे जिन्हें यह उद्योग पूरा कर सकता था। सूत का उत्पादन १६४.० करोड़ पौंड और वस्त्र-उत्पादन प्रतिवर्ष ६४०-० करोड़ गज का लक्ष्य योजना-अवधि के लिए था, इसमें मिल-क्षेत्र का लक्ष्य ४७०.० करोड़ गज था।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के निर्माताओं को उस समय यह आशा नहीं थी कि बिजली करघा के कारखाने, आगामी वर्षों में, इतनी अधिक संख्या में खड़े हो जाएंगे कि वे हाथ करघा और सूती मिलों—दोनों के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर देंगे। १९५१ में करीब ३० लाख हाथ करघे और २३,००० बिजली करघे चालू समझे जाते थे। इस स्थिति को दृष्टि में रखते हुए प्रथम योजना में १७०.० करोड़ (१,७०० मिलियन) गज हाथ करघों के विकेन्द्रित क्षेत्र को सौंप दिये गये।

करघा उद्योग

हाथ करघों को विशेष सहायता देने का कारण यह था कि इससे श्रमिकों को प्रोत्साहन मिलेगा। १९५४ दिसम्बर में प्रकाशित एक सरकारी अभिलेख के अनुसार "आरम्भ में कुछ विशेष ढंग के वस्त्र, जैसे रंगीन साड़ी, लुंगी, सारंग इत्यादि, हाथ-करघा उद्योग के लिए सुरक्षित कर दिये गये थे और मिलों के लिए धोती का उत्पादन, उनके पहले उत्पादन के अनुपात से, सुरक्षित करते हुए उस पर उत्पादन शुल्क लगा दिया गया था। मिल उद्योग में नये करघे लगाने की स्वीकृति नहीं थी। सूती वस्त्र जाँच समिति ने अपनी हाल में पूरी की गयी जांच रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि कपड़ा उत्पादन का समूचा भावी विस्तार केवल छोटे-स्तर के उद्योगों के लिए सुरक्षित रखा जाए। पोशाक बनाने और कपड़े की छपाई के विस्तार के लिए मिल-उद्योग को कोई नये लाइसेंस नहीं दिये जा रहे हैं। खादी और हाथ-करघा उद्योगों के विकास की सहायता के लिए मिल-निर्मित वस्त्र पर अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है।

— लेखक —

इतनी दूरगामी रियायतें और विशिष्ट व्यवहार किये जाने पर भी हाथ करघा उद्योग विशेष उन्नति नहीं कर सका और १९५६ में १७०.० करोड़ (१,७०० मिलियन) गज के लक्ष्य के बावजूद केवल १५०.९ करोड़ (१,५०९ मिलियन) उत्पादन हो सका। इसके विपरीत, मिल क्षेत्र में मार्के की वृद्धि हुई। पहली योजना अवधि के संख्याएं ये हैं—

१९५१—४०७.६ करोड़ गज,
१९५२—४५९.९ करोड़ गज,
१९५३—४८७.८ करोड़ गज,
१९५४—४९९.८ करोड़ गज,
१९५५—५०९.४ करोड़ गज और
१९५६—५३०.६ करोड़ गज।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देश का विकासशील उद्योग : बाल बेयरिंग

देश के औद्योगिक विकास के लिए और विशेष कर इंजिनीयरींग उद्योग में जिन पुर्जों की देश को आत्म निर्भर बनाने की बहुत अधिक आवश्यकता है, इन में से "बाल और रोलर बेयरिंग" एक मुख्य वस्तु है। पम्प बनाने हों, बिजली के पंखे या साइकिल मोटर, डीजल इंजन और मशीन टूल बनाने हों, या सूती मिल की मशीनरी और मोटर गाड़ियां, ट्रक या स्कूटर, रिक्शा बनानी हों या ठेले—इन सबके लिए बाल बेयरिंग की अनिवार्य आवश्यकता होती है। यही कारण है कि योजना आयोग ने इसके उत्पादन और विकास के लक्ष्य अपनी योजनाओं में निश्चित किये हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अनुसार बाल बेयरिंग के उत्पादन और विकास के निम्नलिखित अंक दिये गये हैं :—

	बाल बेयरिंग (लाख की संख्या में)
१९५०-५१	१
१९५५-५६	९
१९६०-६१	२४ (संभावित)
१९६५-६६	१२० (लक्ष्य)
पहले १० वर्षों में प्रतिशत वृद्धि	२३००
तीसरी योजना में प्रतिशत वृद्धि	४००

इन संख्याओं को देखने से ही यह स्पष्ट है कि इस उद्योग के विकास की कितनी अधिक आवश्यकता है। वस्तुतः, इसके बिना देश के अधिकांश उद्योगों को विदेशों से आयात पर निर्भर करना पड़ता है।

आज से १२ वर्ष पूर्व भारत में बाल बेयरिंग बनाने वाला कोई कारखाना नहीं था। न केवल भारत में किन्तु दक्षिण पूर्व एशिया में भी इस तरह का कोई उद्योग नहीं था। सब से पहले १९५० में भारत के प्रमुख उद्योग पति बिड़ला बन्धुओं ने जयपुर में इस उद्योग का श्रीगणेश किया। यह उद्योग इंगलैंड की प्रसिद्ध हाफमैन मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी के प्रशिल्पिक सहयोग से प्रारम्भ किया गया और इस में पहले वर्ष १९ विभिन्न प्रकार के ३२ हजार बेयरिंग बने। लेकिन आज भारत के इस प्रसिद्ध उद्योग संस्थान में भिन्न-भिन्न १८० आकार के ४० लाख बाल बेयरिंग बनते हैं। अकेला यही कारखाना भारत के अधिकांश साइकल, पंखें, बिजली की मोटरों, स्कूटरों, ट्रैक्टरों, क्रेनों, रिक्शा आदि की आवश्यकताएं पूर्ण करता है। इतना बड़ा कारखाना, शायद, एशिया में कोई दूसरा नहीं है।

रेलवे एक्सल बाक्स के बनाने के लिए भी रोलर बेयरिंग की आवश्यकता होती है। अब इसी कारखाने में भारतीय रेलों के लिए "रेलवे एक्सल बाक्स" बनाने का संयन्त्र भी लगा दिया गया है। आजकल इस संयन्त्र से भी ३० हजार एक्सल बाक्स भारतीय रेलों के लिए तैयार होते हैं। भारत में "एक्सल बाक्स" बनाने वाला और कोई दूसरा कारखाना नहीं है।

देश में निरन्तर नये-नये उद्योगों की स्थापना हो रही हैं। पंचवर्षीय योजना में, उद्योग के प्रकरण में, बीसियों नये उद्योगों की गणना की गयी है जो देश में विकसित हो रहे हैं। इसके कारण बाल बेयरिंग की आवश्यकता भी लगातार बढ़ रही है। उदाहरण के लिए, १९५०-५१ में १.०१ लाख साइकिल तैयार हुए थे, जबकि १९६५-६६ में २० लाख साइकिल उत्पादन का लक्ष्य है। इसी तरह पंखें, स्कूटर, मोटर आदि के निर्माण के लक्ष्य भी बहुत ऊंचे हो गये हैं। इन बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जयपुर के इस कारखाने को भी बहुत विस्तृत किया जा रहा है। योजना के अनुसार, इसका उत्पादन दुगुना कर दिया जाएगा और इसके किस्मों में भी बहुत विविधता लायी जाएगी। संसार में उपलब्ध सर्वोत्तम मशीनरी मंगवाई जा रही हैं, जिससे उत्पादन न केवल बहुत बढ़ सके किन्तु इसका स्तर भी ऊंचा हो सके। समस्त देश में एन. बी. सी. के नाम से प्रसिद्ध बाल बेयरिंगस का वितरण करने के लिए भी सब बड़े औद्योगिक नगरों में प्रबन्ध किया गया है। इसका अधिकांश काम मशीनों से होता है। फिर भी कार्य के विस्तार को देखते हुए इस कारखाने में दो हजार श्रमिक और ३५० कर्मचारी काम करते हैं।

कलकत्ता और बम्बई में भी कुछ वर्षों से बाल बेयरिंग के कारखाने खुले हुए हैं और पूना में भी एक नयी फैक्टरी बन रही है, किन्तु जयपुर की विस्तार योजना को देखते हुए इस उद्योग में उस को प्रमुख और महत्त्वपूर्ण स्थान बना रहेगा। ● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सूती कपड़ा मिलें : गत दशाब्दि पर एक दृष्टि

श्री लाला भरतराम, अध्यक्ष भारतीय कपड़ा मिल संघ

पहली पंचवर्षीय योजना, (१९५१-५६) एक सामान्य आधार पर बनायी गयी थी। इसका मुख्य उद्देश्य था, युद्ध और विभाजन से ध्वस्त देश की वित्त-व्यवस्था में सहायता करना। उस समय सूती-वस्त्र के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, वे ऐसे थे जिन्हें यह उद्योग पूरा कर सकता था। सूत का उत्पादन १६४.० करोड़ पौंड और वस्त्र-उत्पादन प्रतिवर्ष ६४०-० करोड़ गज का लक्ष्य योजना-अवधि के लिए था, इसमें मिल-क्षेत्र का लक्ष्य ४७०.० करोड़ गज था।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के निर्माताओं को उस समय यह आशा नहीं थी कि बिजली करघा के कारखाने, आगामी वर्षों में, इतनी अधिक संख्या में खड़े हो जाएंगे कि वे हाथ करघा और सूती मिलों—दोनों के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर देंगे। १९५१ में करीब ३० लाख हाथ करघे और २३,००० बिजली करघे चालू समझे जाते थे। इस स्थिति को दृष्टि में रखते हुए प्रथम योजना में १७०.० करोड़ (१,७०० मिलियन) गज हाथ करघों के विकेन्द्रित क्षेत्र को सौंप दिये गये।

करघा उद्योग

हाथ करघों को विशेष सहायता देने का कारण यह था कि इससे श्रमिकों को प्रोत्साहन मिलेगा। १९५४ दिसम्बर में प्रकाशित एक सरकारी अभिलेख के अनुसार "आरम्भ में कुछ विशेष ढंग के वस्त्र, जैसे रंगीन साड़ी, लुंगी, सारंग इत्यादि, हाथ-करघा उद्योग के लिए सुरक्षित कर दिये गये थे और मिलों के लिए धोती का उत्पादन, उनके पहले उत्पादन के अनुपात से, सुरक्षित करते हुए उस पर उत्पादन शुल्क लगा दिया गया था। मिल उद्योग में नये करघे लगाने की स्वीकृति नहीं थी। सूती वस्त्र जाँच समिति ने अपनी हाल में पूरी की गयी जांच रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि कपड़ा उत्पादन का समूचा भावी विस्तार केवल छोटे-स्तर के उद्योगों के लिए सुरक्षित रखा जाए। पोशाक बनाने और कपड़े की छपाई के विस्तार के लिए मिल-उद्योग को कोई नये लाइसेंस नहीं दिये जा रहे हैं। खादी और हाथ-करघा उद्योगों के विकास की सहायता के लिए मिल-निर्मित वस्त्र पर अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है।

— लेखक —

इतनी दूरगामी रियायतें और विशिष्ट व्यवहार किये जाने पर भी हाथ करघा उद्योग विशेष उन्नति नहीं कर सका और १९५६ में १७०.० करोड़ (१,७०० मिलियन) गज के लक्ष्य के बावजूद केवल १५०.९ करोड़ (१,५०९ मिलियन) उत्पादन हो सका। इसके विपरीत, मिल क्षेत्र में मार्के की वृद्धि हुई। पहली योजना अवधि के संख्याएं ये हैं—

१९५१—४०७.६ करोड़ गज,
१९५२—४५९.९ करोड़ गज,
१९५३—४८७.८ करोड़ गज,
१९५४—४९९.८ करोड़ गज,
१९५५—५०९.४ करोड़ गज और
१९५६—५३०.६ करोड़ गज।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस प्रकार, योजना प्रारम्भ होने के दो वर्ष के भीतर ही, मिल-क्षेत्र को जो लक्ष्य सौंपा गया था, उत्पादन उससे बहुत अधिक बढ़ गया।

तीनों क्षेत्रों के लक्ष्य

दूसरी योजना अवधि—१९५६-६१ में—वस्त्र उत्पादन का लक्ष्य १९६०-६१ तक १८.५ गज प्रति व्यक्ति निश्चित किया गया, जबकि जनसंख्या के ४० करोड़ तक बढ़ जाने का अनुमान लगाया गया था। वार्षिक निर्यात का लक्ष्य १००.० करोड़ गज निश्चित करते हुए उद्योग की तीनों शाखाओं से यह आशा की गयी थी कि एक वर्ष में निर्यात ६७०.० करोड़ गज से बढ़ाकर ८४०.० करोड़ गज हो जाएगा। तीनों क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उत्पादन लक्ष्य निम्न प्रकार रखे गये थे, ताकि १७०.० करोड़ गज का अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त हो सके—

	करोड़ गजों में
(१) हाथ करघा (मिल के सूत के साथ)	७०.०
(२) बिजली करघे (१९५६-५७ और १९५७-५८ में ३५,००० बिजली करघों के लगाने के साथ)	२०.०
(३) अम्बर कपड़ा	३०.०

(४) मिलें (१४,००० स्वचालित करघों के साथ निर्यात के लिए। यह संख्या बाद में १८,००० स्वचालित करघों तक बढ़ा दी गयी)।

(५) बाद में अलाट किया जाने वाला १५.०

इस तालिका से स्पष्ट है कि विकेन्द्रित क्षेत्र को पहली योजना की अपेक्षा जहां बहुत ज्यादा उत्पादन लक्ष्य दिये गये थे, वहां मिल-वस्त्र की घरेलू खपत के लिए वृद्धि करने की कोई गुंजाइश नहीं की गयी। मिल उद्योग से यही कहा गया कि कई शिफ्टें चलाकर वह अपने सामान के अधिक उपयोग के द्वारा उत्पादन वृद्धि करे। इसके लिए यह आकर्षण दिया गया कि १९५६ के पहले ८ महीनों में जो औसतन मासिक उत्पादन हुआ है, उससे अधिक उत्पादन करने पर अक्तूबर १९५६ से ६ पाई प्रतिगज रिबेट दिया जाएगा।

अनबिके कपड़े के अम्बार

परिणाम स्वरूप, मिलें पहले की अपेक्षा बड़ी मात्रा में मोटा कपड़ा तैयार करने लगीं, जिसका नतीजा यह निकला कि बहुत सारा अनबिका कपड़ा जमा हो गया। उस समय स्थिति और भी बिगड़ गयी, जब सितम्बर १९५६ से भारत सरकार ने मिल वस्त्र पर उत्पादन शुल्क एकदम ऊंचा कर दिया, ताकि, जैसा कि कहा गया, कपड़े की खपत ऐसी कम हो जाए कि संप्राप्ति पर्याप्त हो जाए। कपड़े के अतिरिक्त आयात को यह कहकर न्यायसंगत ठहराया गया कि वस्त्र-मिलें बहुत अधिक लाभ उठाती मालूम होती हैं। परिणाम यह निकला कि मिलों के पास अनबिके कपड़ों के अम्बार लग गये। खाद्य पदार्थों की मूल्य वृद्धि के कारण कपड़े की मांग और भी कम हो गयी। १९५६ के अंतिम मासों में स्थिति बहुत खराब हो गयी। स्टाक जमा हो जाने से मिलें संकट में पड़ गयीं। अक्तूबर, १९५६ में मिलों के पास स्टाक जहां ४८०,८२७ गांठें था, वहां १९५७ के इसी मास में स्टाक ६०५,५२६ गांठों तक पहुँच गया। इससे धन की बड़ी राशि बँध गयी। कुछ मिलें इस स्थिति का मुकाबला करने में असमर्थ होने से बन्द हो गयीं। उत्पादन कम हो गया और श्रमिक अस्त व्यस्त हो गये। यह सारी स्थिति दुःख जनक थी, विशेषतः जबकि दूसरी योजना से देश की श्री वृद्धि की आशा की जाती थी।

कुछ रियायतें दी गयीं

इस संकट के निवारण के लिए १९५७, दिसम्बर में सरकार ने पहला पग यह उठाया—मध्य-आकार के कपड़ों पर उत्पादन शुल्क में कमी की, पर यह रियायत पर्याप्त नहीं थी। तब मार्च १९५८ में एक्साइज लेवी पर कटौती की गयी, जो सब किस्म के वस्त्रों पर लागू होती थी। इन उपायों के बावजूद, उद्योग संकटग्रस्त रहा। तब मई १९५८ में सरकार ने एक समिति नियुक्त की, जो इन सब दिक्कतों की जांच करे। इस समिति ने उद्योग की शिकायतों को सही पाया, जिसके फलस्वरूप जुलाई में लेवी में और कमी की गयी। इस सब कटौतियों के बावजूद, शुल्क से सरकार ने ४८ करोड़ रु० प्राप्त करने की आशा रखी थी। इस जांच समिति ने यह बताया कि दूसरी योजना के अन्त तक कपड़े की खपत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष १७.५ गज से अधिक नहीं होगी। इस आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि घरेलू मांग ७००.० करोड़ गज वार्षिक तक सीमित रहेगी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तीसरी योजना के लक्ष्य

दूसरी योजना का समय वस्त्र मिल उद्योग के लिए सुखद नहीं रहा। इसलिए तीसरी योजना के लिए ऊंचे लक्ष्यों का सुझाव देने के लिए इस में उत्साह नहीं था। पर राष्ट्रीय नेताओं के जोरदार आश्वासनों के आधार पर उद्योग ने निम्न प्रकार से उत्पादन का प्रस्ताव किया:—

	करोड़ गज
मिलें	६३०.०
हाथ करघा	२५०.०
अम्बार सूत पर तैयार किया गया वस्त्र	३०.०
बिजली-करघा	५०.०
	९६०.०

यह अनुमान लगाया गया कि इस स्तर पर उत्पादन के लिए रुई की ६६ लाख गांठें प्रति वर्ष चाहिए।

पर तीसरी योजना के निर्माताओं का यह विश्वास है कि ९३०.० करोड़ गज का वार्षिक उत्पादन और ८५.० करोड़ गज निर्यात के लिए—इतना वस्त्र पर्याप्त होगा। मिल क्षेत्र से कहा गया कि वह उत्पादन का वर्त्तमान स्तर ५००.० करोड़ गज से बढ़ाकर ५८०.० करोड़ गज वार्षिक करे और अवशिष्ट ३५० करोड़ गज हाथ करघा और बिजली करघा के लिए रहने दिया जाय।

मिलों का नवीकरण और विस्तार

सरकार ने चालू योजना में ४० लाख नये तकुए और २५,००० स्वचालित करघे लगाने की मंजूरी दी है। इन तकुओं में से ७० लाख मौजूदा इकाइयों की मशीनरी को संतुलित करने के लिए है। लोकसभा में दी गयी एक सूचना के अनुसार कुछ नयी मिलों को लायसैंस दिये गये हैं, ताकि ९.६ लाख तकुए प्राप्त हो सकें, जब कि अन्य २.६५ लाख तकुओं के लिए लाइसैंस दिये गये, ताकि मिलों में पर्याप्त विस्तार हो सके। यह पता नहीं कि इनमें से कितने, वस्तुतः, लगाये गये हैं और कितने चालू किये गये हैं।

कपास की कमी

सूत और कपड़े की निश्चित मात्रा प्राप्त करना भी सहज नहीं है। यह अनुमान लगाया गया है कि २२५.० करोड़ (२,२५० मिलियन) पौंड सूत प्राप्त करने के लिए कपास की ३३ लाख गांठें चाहिए, जिसमें सूती मिलों और विकेन्द्रित क्षेत्र की आवश्यकताएं भी शामिल हैं। योजना में वार्षिक ७० लाख गांठों की व्यवस्था की गयी है। पर देश में कपास के उत्पादन का जो रुख है, उससे आशा नहीं होती कि योजना में निर्धारित लक्ष्य पूरा हो जाएगा।

पिछले तीन वर्षों में मिलों द्वारा कपास की वार्षिक खपत ५२.५ लाख गांठें रही है। इस लिए इसी अवधि में कमी को पूरा करने के लिए ९.५ लाख गांठों का आयात आवश्यक हो गया। महीन और बहुत महीन कपड़ा बनाने के लिए मिलों को लम्बे रेशे की कुछ निश्चित मात्रा में कपास तो आयात करनी ही पड़ेगी। प्रयत्न किया जा रहा है कि "सी आइलैंड" को कपास का उत्पादन मैसूर केरल में बढ़ाया जाए। लम्बे रेशे की कपास में आत्म निर्भरता अभी दूर की बात है। अगस्त १९६२ में समाप्त होने वाले कपास की फसल की अवधि में, ९ लाख गांठ से अधिक कपास की गांठों के आयात के लाइसेंस दिये गये थे जब कि वास्तविक प्राप्ति ८.६ लाख गांठों की हुई।

इस समय इस उद्योग के सम्मुख अविलम्ब दो प्रकार के कार्य हैं। चीनी आक्रमण के कारण मिलों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे बड़ी मात्रा में सुरक्षा सेनाओं के लिए कपड़ा तैयार करें। राष्ट्रीय संकट की दृष्टि से भी यह जरूरी हो गया है कि कपड़े का निर्यात बढ़ाया जाए ताकि विदेशी मुद्रा का अर्जन हो सके। पर प्रतिवर्ष ८५.० करोड़ गज कपड़े के निर्यात के लिए बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता है क्योंकि विदेशी बाजारों में वही माल टिक सकता है जो किस्म और कीमत दोनों दृष्टियों से प्रतिस्पर्द्धा कर सके। यह काम उस समय और भी कठिन हो जाएगा जब ब्रिटेन योरूपीयन सांझा बाजर में शामिल हो जाएगा और इस समय भारतीय वस्त्र के लिए बिना तटकर के ब्रिटेन में प्रवेश करने की जो रियायत है, वह समाप्त हो जाएगी।

● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गोपालकृष्ण गोखले (१८६६-१९१५)

श्री गोकुलचन्द जांगिड़

श्री गोपालकृष्ण गोखले का जन्म १८६६ में कोल्हापूर में हुआ था। सन् १८८४ में उन्होंने बी. ए. करके दक्कन एज्यूकेशन सोसाइटी में प्रवेश लिया। श्री गोखले फरगूसन कॉलेज, पूना में अंग्रेजी साहित्य और गणित में प्राध्यापक रहे, तत्पश्चात् उन्होंने इतिहास तथा अर्थशास्त्र का पद संभाला, सन् १८८७ में वे पूना की सार्वजनिक सभा के एक पत्र के सम्पादक हो गये। सन १९०० में वे बम्बई की विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हो गये तथा १९०२ में वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य हुए। सन् १९०५ में श्री गोखले भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति चुने गये तथा उसी वर्ष उन्होंने 'सर्वेंट ऑफ इन्डिया सोसाइटी' की स्थापना की।

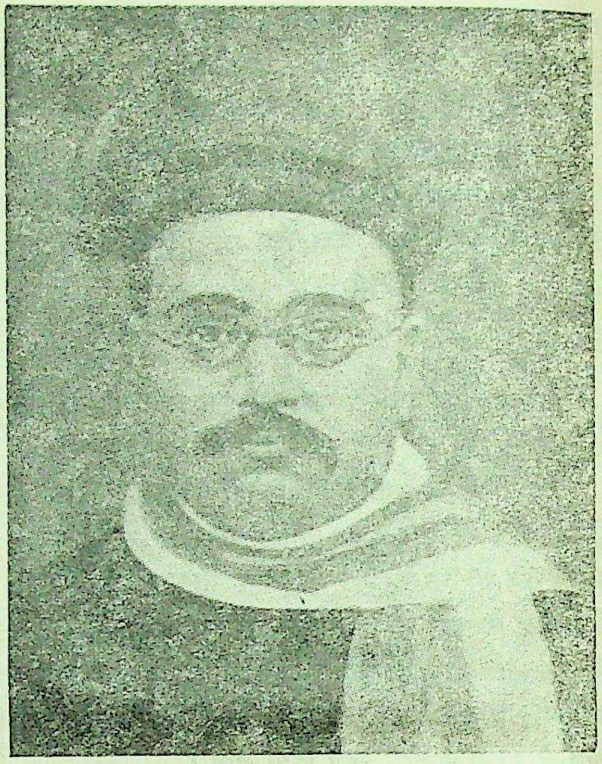

श्री गोपालकृष्ण गोखले

श्री गोपालकृष्ण गोखले श्री रानाडे के ही शिष्य समझे जाने चाहिये। श्री रानाडे के प्रति उनकी श्रद्धा ने उनके विचारों पर भी छाप डाल दी थी। श्री गोखले शिक्षण की दृष्टि से साहित्यिक, मानसिक झुकाव से गणितज्ञ तथा अनिवार्यता के कारण अर्थशास्त्री थे।

श्री गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों की झलक उनके तत्कालीन आर्थिक समस्याओं पर विचारों एवं साधनों से मिलती है। गोखले कांग्रेस में १८८९ में प्रविष्ट हो चुके थे और इसी घटना ने उन्हें राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं पर चिन्तन करने का अवसर दिया।

नमक कर का विरोध

१८९६ में एक वित्त समिति का गठन व्यय में मितव्ययता सुझाने के लिए किया गया था। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर बर्मा के संयुक्त किये जाने से उत्पन्न आर्थिक स्थिति नहीं सुलझ सकती थी, क्योंकि उसमें १५ लाख पौण्ड की कमी पड़ती थी, जिसे नमक पर कर बढ़ाने के द्वारा पूरा करने निश्चय किया गया। गोखले ने इस कर का भारी विरोध किया और इसे शोषणकारी बताया। १८९० में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में नमक कर घटाने के प्रस्ताव के पक्ष में जोरदार वक्तव्य दिया। इसी तरह से १८७७ में हाउस आफ कामन्स में वस्त्र पर आयात कर को हटाये जाने के पारित प्रस्ताव का भी उन्होंने भारी विरोध किया। इसी तरह से उन्होंने लंकाशायर मिल मालिकों के हितों के अनुकूल भारत में कपड़े पर उत्पादन कर लगाए जाने की भी कड़ी आलोचना की।

जमीन का लगान अधिक न हो

(२) भूमि राजस्व के निर्धारण और नीति सम्बन्धी श्री गोखले के विचार उनकी इस समस्या के विश्लेषण के द्योतक हैं। उनका मत था कि भूमि शासन के नियम निश्चित

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और स्पष्ट तथा भारतीय किसान के अनुकूल होने चाहिए। उन्होंने यह पक्ष रखा कि भू राजस्व में बार-बार संशोधन नहीं होना चाहिए। जहां खेती हर प्रत्यक्ष रूप से चुकाते हों वहां राजस्व की मांग कुल उपज की एक-पांचवें हिस्से से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को लोगों से उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए, जितना कि उसे गम्भीर मन्दी और विपद् काल में आवश्यकता होती है। गोखले भू-राजस्व की व्यवस्था का रैयतवारी क्षेत्रों में सुधार चाहते थे। वे बन्दोबस्त के पक्ष में नहीं थे।

धनियों पर अधिक कर हो

गोखले के करारोपण सम्बंधी विचारों से यह स्पष्ट है कि वे निर्धनों पर कर के भार को कम करने के पक्ष में थे तथा भिन्न वर्गों में इसके प्रभाव को न्याय संगत बनाना चाहते थे। तत्कालीन कर व्यवस्था अत्यधिक असमान और निर्धनों पर अधिक भार डालने वाली थी। गोखले के अनुसार भारत में भूमि पर कर सबसे भारी था। निर्धन व्यक्ति ही लगभग सारा उत्पादन कर देते थे। नमक कर भी एक भारी बोझ था। नमक कर के घटाने के पक्ष में सफाई देते हुए उन्होंने कि एक दूसरा कर-सिद्धान्त स्थापित किया, जिसके अनुसार एक स्वस्थ एवं उपयुक्त नीति वह होगी, जिसमें बढ़ते हुए उपभोग के साथ घटते हुए कर पैमाने के आधार पर बढ़ती हुई राज्य आय प्राप्त की जाय। इस सिद्धान्त में अन्तर्निहित तथ्य यह था कि अन्ततोगत्वा समस्त करों का आधार करों की संख्या में वृद्धि नहीं, लेकिन आर्थिक समृद्धि का सामान्य स्तर है। लोगों की वास्तविक समृद्धि को बढ़ाने से कर की समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। यही गोखले का सिद्धान्त था।

सेना पर कम खर्च हो

गोखले के सार्वजनिक व्यय तथा वित्तीय सुधार सम्बन्धी विचार भी ध्यान देने योग्य है। श्री गोखले ने अपने शोधपूर्ण विश्लेषण के बाद यह मत रखा कि भारत में बढ़ते हुए व्यय के भार को भारतवासी अब सहन नहीं कर सकते। देश की आवश्यकता को देखते तथा आय की दृष्टि से सैन्य बल कहीं ज्यादा है। इससे न केवल आर्थिक हानि ही होती है बल्कि चारित्रिक हानि भी होती है। हम अपने जीवन के दिन हीनता के वातावरण में बिताते हैं तथा आगे बढ़ने की भावना जो एक एटन या हेरो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के मस्तिष्क में किसी दिन ग्लैडस्टान, नेलसन या विलिंगडन बनने की आकांक्षा होती है, वह कुचली जाती है। क्योंकि हमें इस व्यवस्था में एक लकड़ी काटने वाले और पानी खेंचने वाले के कार्य तक ही सीमित रहना पड़ता है। आर्थिक विचारों के साथ चारित्रिक समस्याओं का समन्वय करना गोखले ही की विशेषता थी।

वास्तव में श्री गोखले ने आर्थिक विश्लेषण के क्षेत्र में सार्वजनिक वित्त के अध्ययन पर विशेष जोर दिया और उन्होंने यह सुझाया कि मुद्रा सम्बन्धी आय तथा सरकारी व्यय देश के उत्पादन और कुल उत्पादन के वितरण तथा रोजगार के ढांचे को प्रभावित करता है। श्री गोखले आर्थिक नीति के उन प्रश्नों में अधिक रुचि लेते थे, जिनमें उत्पादक स्रोतों के उपयोग से कुशलता बढ़ती थी। उनकी आर्थिक नीति का दूसरा उद्देश्य जिसे वे प्राथमिकता देते थे, वह आय के समान वितरण का था।

मुद्रा प्रसार के सब से पहले विरोधी

गोखले शायद भारत में प्रथम थे, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी व्यय और आय की अर्थ व्यवस्था के कार्य में व्याप्त त्रुटियों को सुधारने में ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह स्पष्ट देख लिया था कि भारत के स्वावलम्बी गांवों की अवस्था मुद्रा के प्रसार से किस प्रकार से विपरीत रूप से प्रभावित होती थी। गोखले ने उस समय अपने विचार रखे, जब भारतीय अर्थशास्त्रियों का अधिकार सरकार की आर्थिक और वित्तीय नीतियों का निर्माण करने में अत्याधिक सीमित था, लेकिन फिर भी वे इसमें सफल हुए। उनका तथ्यों का संकलन तथा प्रतिभाशाली मस्तिष्क में मौलिक ये दो वस्तुएं थीं, जिन्होंने उस समय के अंग्रेज शासकों को विचार करने के लिए विवश किया। यह तत्कालीन समय के भारत के बजट अधिवेशनों और विवरणों में अब भी सुरक्षित है।

—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तेल के लिए आत्म निर्भरता की ओर

भारत के सामान्य जीवन में तेल, अपने विभिन्न रूपों में, महत्वपूर्ण भाग अदा करता है। मशीन के पहियों में यह गति उत्पन्न करता है और सर्वत्र आम जनता के जीवन को प्रभावित करता है। चीनी आक्रमण के बाद तो इसको विशेष महत्व प्राप्त हो गया है। युद्ध की खास चीजों में से यह एक है। इस संकटकाल में सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या अगर उद्योग चलेंगे तभी सैन्य-सामग्री तैयार होगी और उद्योग चलाने के लिए तेल अनिवार्य है।

चीन के इस घृणित आक्रमण से पहले भी भारत तेल-उद्योग के विकास की ओर—विशेषतः देश में प्राप्त साधनों पर बल देते हुए—ध्यान दे रहा था। पिछले आधे दशक में सार्वजनिक क्षेत्र में तेल-उद्योग ने उल्लेखनीय उन्नति की है। इस संकट से अगर हमें कुछ लाभ उठाना है तो वह यही है कि अपनी आवश्यकताओं के लिए इस खनिज प्राप्ति में हम आत्म-निर्भर हो जाएं। हमें इस बात का अभिमान है कि तेल के इस सार्वजनिक क्षेत्र में किये गये प्रयत्नों के फलस्वरूप तीसरी योजना के अन्त तक हम, लगभग, ६० लाख टन गन्दे तेल (क्रूड आयल) का उत्पादन कर लेंगे और इसी क्षेत्र में तेल परिशोधन की शक्ति लगभग ८० लाख टन तक प्राप्त कर लेंगे बशर्ते गोहाटी और बरौनी के सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार और दक्षिण में प्रस्थापित तेल-परिशोधक (रिफाइनरी) की स्थापना हो जाए। इसका यह मतलब नहीं है कि परिशोधन के लिए अधिक संभावनाएं नहीं हैं। क्षेत्र तो इतना विस्तृत है कि दोनों—निजी और सार्वजनिक—क्षेत्र एक दूसरे के सहयोग से बहुत काम कर सकते हैं।

तेल उद्योग पूंजीगत धन का उद्योग है। इसकी कार्य-विधियां पेचदार हैं। इस दृष्टि से भारत के अन्य उद्योगों से इसमें विभिन्नता है, जैसे पहले सर्वेक्षण, भावी स्वरूप, फिर खुदाई (ड्रिलिंग), उत्पादन, परिवहन, परिशोधन और अन्त में विक्रय, पर ये सारे कार्य, आर्थिक दृष्टि से, एक दूसरे के साथ सम्बद्ध हैं।

तेल की उपलब्धि के लिए खुदाई (ड्रिलिंग) करने से पहले, विस्तृत रूप में भूमि-सर्वेक्षण करना पड़ता है ताकि

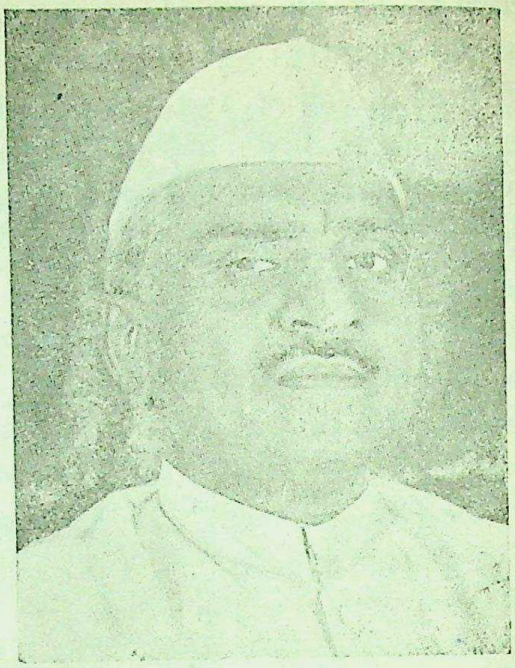

श्री खण्डूभाई देसाई

तेल-प्राप्ति के अनुकूल भू-स्थलों और चट्टानों की जानकारी प्राप्त की जाए। जब इनकी सीमा निर्धारित हो जाए तब इन दबी हुई चट्टानों का पूरा ब्यौरा पता लगाने के लिए फिर सघन सर्वेक्षण किया जाता है। इसके बाद पहला परीक्षा का कुंआ खोदा जाता है। इस पर कितना खर्च पड़ता है, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले परीक्षा के कुंए की खोज में ही—इसके भीतर तेल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है—२५ लाख से १ करोड़ रु० तक खर्च हो जाता है। खुदाई (ड्रिलिंग) होने पर भी तेल की प्राप्ति निश्चित नहीं होती है। व्यापारिक दृष्टि से यह देखना होगा कि उस खुदाई के क्षेत्र में कितने कुंए हैं जिससे तेल के संचित कोष का कुछ आनुमानिक आभास मिल जाए। हरेक कूंएपर १० से १५ लाख रु० तक—अगर गहरा तो इससे भी अधिक—खर्च होता है। दूसरी बात यह है कि जहां तेल की जरूरत होती है, वहां वह बहुधा नहीं मिलता। तेल परिशोधक कारखाने तक लाने के लिए उसे काफी रास्ता तय करना

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पड़ता है और तेल क्षेत्र से परिशोधक केन्द्र तक पाइप लाइन बिछानी पड़ती है। जब गन्दा तेल साफ कर लिया जाता है और पेट्रोलियम वितरण के लिए प्राप्त हो जाता है, तब इसके लिए एक एजन्सी कायम करनी पड़ती है। इस समूची व्यवस्था के लिए पर्याप्त पूंजी और तकनीकी ज्ञान चाहिए। चूंकि तेल को देश के हरेक कोने तक पहुँचना होता है, इसलिए वितरण व्यवस्था ऐसी समर्थ होनी चाहिए जिससे एक सदृश मूल्य पर सर्वत्र सुलभ हो सके।

निजी क्षेत्र में आसाम आयल कम्पनी (बर्मा आयल कम्पनी की मलकीयत) के अतिरिक्त अन्य कोई कम्पनी नहीं थी। इसकी विस्तृत प्रवृत्तियों के फलस्वरूप १९५३-५४ में नहरकटिया और मोरान क्षेत्रों में तेल की प्राप्ति हुई। आसाम के बाहर तेल की प्राप्ति के लिए सबसे पहले इंडो-स्टानवाक परियोजना का गठन हुआ पर बहुत कोशिश करने पर भी बंगाल-भूमि में तेल व गैस की प्राप्ति नहीं हुई। १९५४ में पहली बार तीनों तटवर्ती तेल-परिशोधक आपस में मिले। अभी तक केवल डिग्बोई में परिशुद्ध किये जाने वाले ४ लाख ५० हजार टन तेल के अतिरिक्त समूचा तेल आयात होता था। इनका वितरण निजी क्षेत्र में, तीन मुख्य कम्पनियों द्वारा होता था—बर्मा शेल आयल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी आफ इंडिया, स्टेन्डर्ड वेकम आयल कम्पनी (बाद में एस्सो ईस्टर्न नाम से) और कालटेक्स इंडिया लि०। बर्मा आयल कम्पनी डिगबोई के तेल को आसाम, त्रिपुरा और मणिपुर में बेचती थी। इन तीनों कम्पनियों को मिला कर कुल तेल ३० करोड़ ८८ लाख टन होता था।

इस पृष्ठभूमि में "आयल एंड नेशनल गैस कमीशन" स्थापित किया गया, जो बाद में १९५८ में संसद के एक विधेयक द्वारा एक संवैधानिक स्तर के रूप में आ गया है। विधेयक में हाल ही में किये गये एक संशोधन के अनुसार कमीशन को अपनी शाखाएं खोलने की मंजूरी मिल गयी है। कमीशन ने देश के लगभग सभी भागों में सर्वेक्षण किया है और पंजाब, केम्बे, गुजरात, ब्रह्मपुत्र घाटी में खुदायी की है। इसमें काफी सफलता मिली है।

अभी तक कमीशन ने केम्बे में ३० कूंए खोदे हैं जिनमें से दो तेल-उत्पादक हैं, १५ गैस के हैं और बाकी सूखे हैं अथवा अधिक जांच की प्रतीक्षा में हैं। अंकलेश्वर में पूर्ण किये गये ५४ कूंओं में से ५१ तेल-उत्पादक हैं और केवल ३ खुश्क हैं। रुद्रसागर, असाम, में पूरे किये गये ४ कुओं में से ३ तेल-उत्पादक हैं और एक अभी हाल में पूरा हुआ है पर उसकी जाँच अभी बाकी है। इसके अतिरिक्त, होशियारपुर, आदमपुर, जानुआरी और जीरा में जाँच हो रही है। अंकलेश्वर तेल-क्षेत्र में उत्पादन शुरू हो गया है और वहाँ प्रतिदिन १८०० टन तेल निकलता है।

गोहाटी और बरौनी में तेल परिशोधन के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में "इंडियन रिफाइनरीज लि०" की स्थापना की है जो अपर आसाम में गन्दे तेल का २० करोड़ ७५० लाख टन उत्पादन करेगी। गोहाटी केन्द्र चालू हो चुका है और बरौनी का कार्य हाथ में ले लिया गया है। इन परिशोधकों के ४० लाख टन तक बढ़ाया जा सकता है। गुजरात के कोयाली परिशोधक का सामर्थ्य २० लाख वार्षिक टन है। इन परिशोधकों के तेल का वितरण करने के लिए सरकार ने इंडियन आयल कम्पनी ३० जून १९५९ को बनाई जिसकी पूंजी १२ करोड़ रु० है। देश में पाइपलाइन बिछाने के लिए सरकार ने इंडियन रिफाइनरीज लि० की स्थापना भी की है। इस समय गोहाटी से सिल गुड़ी तक—२६० मील—पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है जिस पर ६ करोड़ रु० खर्च का अनुमान है।

उपर्युक्त सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कार्य करने वाली विविध संस्थाओं के अतिरिक्त भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में बर्मा आयल कम्पनी के साथ ५०:५० की साझेदारी में "आयल इंडिया लि०" के नाम से एक कम्पनी का गठन किया है। इसे संयुक्त सहकारी संस्था कहा जा सकता है और इस क्षेत्र में काम करने वाली कई संस्थाओं से यह विभिन्न है।

(अगामी अंक में समाप्य)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राजस्थान को स्मरण रखिए

*प्राचीन किले *राजप्रासाद *सुरम्य झीलें *वन्य जीवन आवास *तीर्थ स्थान *चित्रकला *मूर्तिकला *सब प्रकार का हस्त उद्योग *छपाई और बंधाई का काम *केलिको की छपाई *लाख की चूड़ियां *पीतल हाथी दांत तथा चन्दन के सामान *जस्ते के बने प्रसिद्ध जोधपुरी बादले *जोधपुरी मोजरियां *कलापूर्ण सामान

* देश का सबसे बड़ा सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म
* विश्व की सबसे लम्बी राजस्थान नहर (निर्माण कार्य चालू है)
* सांभर का स्थलीय नमक उत्पादन क्षेत्र
* देश का सबसे बड़ा ऊन उत्पादन करने वाला प्रान्त
* संगमरमर चांदी तथा पन्ना की भारत प्रसिद्ध खानें

राजस्थान प्रथम पंचवर्षीय योजना में खाद्य-स्वावलम्बी बन गया। द्वितीय योजना काल में १०,८३ लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन किया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में २३ करोड़ रु. खर्च करने व १६ लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन का लक्ष्य।

राजस्थान में सहकारिता का व्यापक प्रचार—आज राज्य में १६१२८ सहकारी समितियां काम कर रही हैं। उनकी संख्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में २९६६३ हो जायगी। सहकारिता और सामुदायिक विकास योजना पर २२.५५ करोड़ रु. खर्च करने का तृतीय पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य।

राजस्थान में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए ९९ वर्ष की लीज पर भूमि-डेढ़ आना प्रति यूनिट सस्ती बिजली—बाहर से व राज्य से खरीदी जानेवाली मशीनों पर बिक्रीकर व चुंगी की माफी व उद्योगों के लिए ऋण की सुविधाएं।

राजस्थान ७३९४ पंचायतों और १३६९ न्याय पंचायतों का राज्य।

जब कभी आप राजस्थान के गुलाबी नगर जयपुर में पधारें तो डी लक्स बस द्वारा जयपुर के दर्शनीय स्थानों, उद्योग केन्द्रों व मुख्य नगर का अवलोकन कीजिए और राजस्थान स्टेट होटल के वातानुकूलित कमरों में ठहर कर आनन्द लीजिए।

राज्य सरकार द्वारा प्रसारित

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१९६२ का सिंहावलोकन

इस वर्ष के अन्त में चीन के आक्रमण ने देश की आर्थिक स्थिति व प्रवृत्तियों पर जो प्रभाव डाला, वह असाधारण और इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। समस्त देश ने मुक्त हस्त होकर चीन के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए सरकार को करोड़ों रु० स्वेच्छा से दान दिये। दो मास में ही यह राशि २६ करोड़ रु० के करीब हो गई है। अभी तक जो राशि एकत्र हो चुकी है पर केन्द्र तक नहीं पहुँची, वह भी करोड़ों रु० में है। विदेशी मुद्रा के अभाव की पूर्ति करने के लिए कई मन सोना भी एकत्र हो गया है। बहनों ने अपने आभूषण उतार-उतार कर दिये हैं। इसी उद्देश्य से स्वर्ण बाण्ड भी जारी किये गये। लेकिन सोने का मूल्य ८२ रु० प्रति १० ग्राम तक गिरकर फिर १०९ रु० हो गया।

समस्त राष्ट्र में देश की प्रतिरक्षा के लिए राजनैतिक चेतना ही उत्पन्न नहीं हुई, आर्थिक चेतना भी उद्बुद्ध हो गई हैं। युद्ध केवल मोर्चे पर नहीं, खेतों और कारखानों में भी लड़ा जाता है, यह विचार सारे देश में फैल गया है। तीसरी योजना की पूर्ति का अर्थ है, युद्ध में विजय, इस विचार ने उद्योगपतियों, मजदूरों व दुकानदारों और किसानों को अधिकतम उत्पादन, कम लाभ, मूल्य वृद्धि पर कड़े नियंत्रण और परस्पर औद्योगिक शान्ति के लिए प्रेरित किया। वे सब लक्षण प्रकट होने लगे, जिनके स्वप्न नेता कभी लिया करते थे। चीन के आक्रमण से देशभर में जिस आर्थिक चेतना का उद्भव हुआ, वही असाधारण घटना है। व्यापारियों व दुकानदारों ने स्वयं मूल्य न बढ़ाने और चोर-बाजारी न करने का दृढ़ संकल्प लिया। इस वर्ष के ८ वें ९ वें महीने में मूल्यों में बेहद वृद्धि आई थी वह कम हो गई।

मूल्य-स्तर

खाद्य पदार्थों तथा उद्योग के कच्चे माल और निर्मित — माल के मूल्यों में उतार के निर्देशक अंक निम्नलिखित हैं—

	१९५५-५६	१९६०-६१	१९६१-६२	अगस्त १९६२	नवम्बर १९६२
खाद्य पदार्थ	९६.६	१२.००	१२०.१	१३१.५	१३९.६
उद्योगों का कच्चा माल	९९.०	१४५.४	१४२.६	१३९.६	१३७.८
कारखानों में निर्मित माल	९९.७	१२३.९	१२६.६	१२९.४	१२९.९

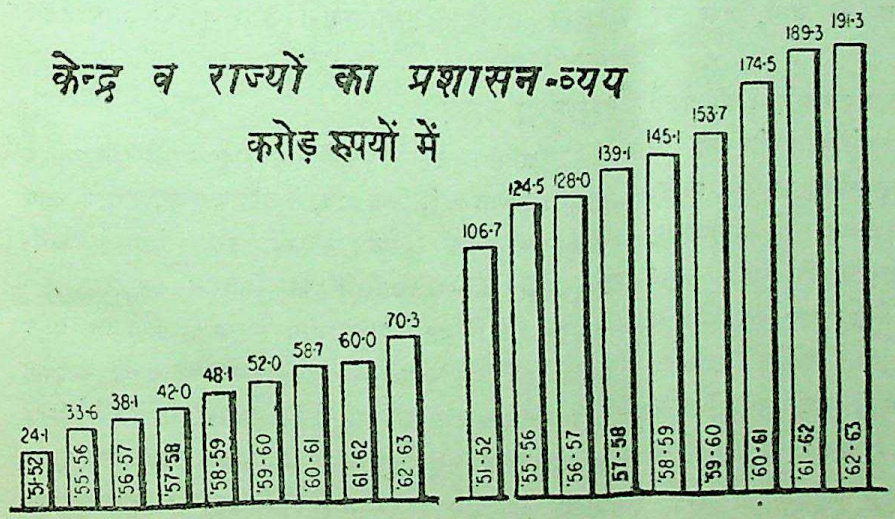

केन्द्र और राज्यों में विकासेतर कार्यों का व्यय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसमें से भी भारी रकम प्रशासकीय सेवाओं पर व्यय होती है। केन्द्रीय प्रशासन में व्यय पिछले ११ वर्षों में तीन गुना और राज्य सरकारों में दुगना हो गया है। १९६२ के वर्ष में अधिकांश अर्थशास्त्रियों और उद्योगपतियों ने प्रशासन व्यय के सफेद हाथी की ओर देश का ध्यान बहुत प्रबल शब्दों में आकृष्ट किया।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

निर्यात-आयात व्यापार में हमें इस वर्ष भी बहुत घाटा रहा है-यह प्रतिकूल सन्तुलन अनेक प्रयत्नों के बावजूद कम नहीं हो रहा। पिछले वर्षों में विदेशी मुद्रा की कितनी हानि हुई, यह नीचे की तालिका से स्पष्ट है :—

विदेशी व्यापार में प्रतिकूल सन्तुलन (करोड़ रु० में)

१९५५-५६	१६६	१९५९-६०	३२२
१९५६-५७	२४३	१९६०-६१	४२९
१९५७-५८	४०१	१९६१-६२	२८१
१९५८-५९	३३१	१९६२ (१० महीने) (अनुमानित)	२३०

आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के बावजूद यह स्थिति कायम है।

निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से सूती मिलों के लिए १२॥ प्रतिशत निर्यात अनिवार्य कर देने का प्रस्ताव किया गया, किन्तु इसमें भी पूरी सफलता नहीं मिली। विदेशी मुद्रा कोष एक वर्ष में १५२.३६ करोड़ रु० से गिरकर ९७ करोड़ रु० रह गया। यह स्थिति बहुत चिन्तनीय है।

विदेशी मुद्रा की स्थिति पहले ही कम शोचनीय न थी, प्रतिरक्षा की बढ़ती हुई आवश्यकताओं ने उसे बहुत विकट बना दिया। युद्ध में करोड़ों रु० एक दिन में खर्च हो जाते हैं। भला हो ब्रिटेन व अमरीका का, जिन्होंने लोकतंत्री देश पर यह महान् संकट देखकर उदार सहायता तत्काल देनी शुरू कर दी। करोड़ों रु० की युद्ध सामग्री आ चुकी है और भविष्य में भी कितनी सहायता दी जाय, इस पर विचार हो रहा है।

वर्ष के प्रारंभ में इण्डिया एड क्लब देशों की बैठकें स्थगित होती रही, पर आखिर में उसने भी पर्याप्त सहायता देने का निश्चय कर लिया। रूस, रूमानिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों की सहायता से अनेक नई प्रायोजनाएं बनीं और इन्हें चालू करने में सहायता दी गई। इस सहायता के साथ ही यह प्रश्न भी पैदा हुआ कि योजना पूर्ति के लिए आवश्यक सामान जुटाये जायें। नवम्बर-दिसम्बर के महीनों में देश के प्रशासकों, उद्योगपतियों और अर्थशास्त्रियों ने इस पर बहुत विचार किया है। छोटी बचत, मितव्यय, तीसरी योजना के कम आवश्यक मदों में कटौती, राज्यों की अनुदान व ऋणों में कमी, प्रशासन व्यय में भारी कमी और नये नये कर लगाने के सुझाव पेश किये गये हैं, जिनका प्रभाव १९६३ में देश पर पड़ेगा।

१९६२ के वर्ष का प्रारम्भ नूनमाटी के तेल संशोधक कारखाने के उद्घाटन के साथ हुआ था। सम्पूर्ण वर्ष तेल उद्योग संशोधन व पाइप लाइन के बिछाने की प्रवृत्तियों के कारण संतोषजनक कहा जा सकता है। यह कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में पहला था।

इस वर्ष तीसरी योजना का दूसरा वर्ष था। यह वर्ष मार्च ६३ में समाप्त होगा। १९६१-६२ के वर्ष की चर्चा पाठक अन्यत्र पढ़ेंगे। सरकारी कारखानों ने लोहे का उत्पादन अवश्य बढ़ाया पर वे लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। योजना के अन्य क्षेत्रों में प्रगति होती रही है। यों तो पहले से ही प्रशासन की अकुशलता की ओर ध्यान खींचा जाता रहा है, पर इस वर्ष अर्थशास्त्रियों ने इसे दूर करने पर विशेष बल दिया, क्योंकि योजना के लक्ष्यों में सरकारी बिलम्ब तथा असावधानी के कारण बहुत कमी रह जाती है। योजना के अनुसार विभिन्न उद्योगों के विकास में कोयला, बिजली और परिवहन की बाधाओं को समस्त देश में अनुभव किया गया। कोयला पर्याप्त नहीं मिला, जो मिला भी उसकी किस्म अच्छी न थी। उपलब्ध कोयले को रेलगाड़ी यथा समय पहुँचा न सकी। इसलिए इस वर्ष कोयले के लदान के लिए ट्रकों, नावों और जहाजों की योजनाएं बनायी गईं।

राष्ट्रीय आय

यद्यपि १९६२ के वर्ष में राष्ट्रीय आय की गणना के अंक प्रकाशित नहीं किये गये, तथापि इस वर्ष राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट निकली, उसने देश के अर्थशास्त्रियों व अधिकारियों को चिन्तित कर दिया है। १९६०-६१ में जब राष्ट्रीय आय में ७.१ प्रतिशत वृद्धि आंकी गई थी, १९६१-६२ में ३ प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ी। इसका अर्थ यह है कि हमारी समस्त योजना का आधार ही बहुत दुर्बल हो गया। इस कमी का मुख्य कारण कृषि क्षेत्र की प्रगति में शिथिलता था। इस कारण योजना आयोग ने कृषि-लक्ष्यों में अधिक विनियोजन का

उपर्युक्त तालिकाओं में सब अंक इकानामिक टाइम्स से लिये गये हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

76310

निश्चय किया है और इसके लिए सामुदायिक योजनाओं व कार्य पद्धति का पुनः संगठन किया जा रहा है।

पिछले कुछ वर्षों से केन्द्रीय सरकार के बजट में क्या परिवर्तन हुए हैं, यह निम्न तालिका से प्रकट होगा—

	आय	व्यय	बचत या हानी
	करोड़ रु. में		
१९५५-५६	४८१.२	४४०.७	+ १०.५
१९५७-५८	६७३.४	६३१.१	+ ४२.१
१९६०-६१	८७७.५	८२६.२	+ ५१.३
१९६१.६२	९७८.३	९४३.४	+ ३४.०
१९६२-६३	१३८१.६७	१३८१.६५	—

बजट लगातार बढ़ते जा रहे हैं

पदार्थों के मूल्य पर जिन तत्वों का प्रभाव पड़ता है। उनमें से एक मुद्रा प्रसार है। यों तीसरी योजना में मुद्रा प्रसार की एक मर्यादा ५५० करोड़ रु. नियत की गयी है किन्तु भारत सरकार ने इसका ६१ प्रतिशत पहले दो वर्षों में ही पूरा कर लिया। इसके साथ ही बैंकों के डिवाजिट तथा उधार राशि भी बढ़ी है। और अभी यह भी संभव है कि संकटकालीन पूरक बजट में ९५ करोड़ रु. की जो अतिरिक्त राशि स्वीकृत हुई है, उसके कारण मुद्रा प्रसार १९६३ में और भी बढ़ जाए। दिसम्बर १९६१ में बाजार में प्रचलित नोट १९४४ करोड़ रु. के थे। नवम्बर १९६२ में इन नोटों की संख्या २०७१ करोड़ रु. हो गयी और दिसम्बर के अन्त तक यह राशि निश्चय ही, अधिक बढ़ गयी है।

बैंक देश की आर्थिक गतिविधि का चित्र उपस्थित करते हैं। निम्न तालिका गत वर्ष की स्थिति पर प्रकाश डालती है।

(करोड़ रु. में)

	२९-१२-६१	२८-१२-६२
बैंकों के डिपाजिट	१८२५.६०	२०३५.४०
सरकारी सैक्योरिटियां	५६९.६९	६५३.७०
बैंकों के कुल क्रैडिट	१४२१.०५	१२७६.२४
×	×	×

१९६२ का वर्ष कराधान दृष्टि से भी बहुत सफल नहीं रहा। केन्द्रीय सरकार ने ६८.२० करोड़ रु. के कर लगाये, जबकि १९६१-६२ में भी ८५ करोड़ रु. के नये कर लगे थे। इसी तरह राज्यों ने भी ४७ करोड़ रु. के नये

(शेष पृष्ठ २२ पर)

पुस्तकालय 113079

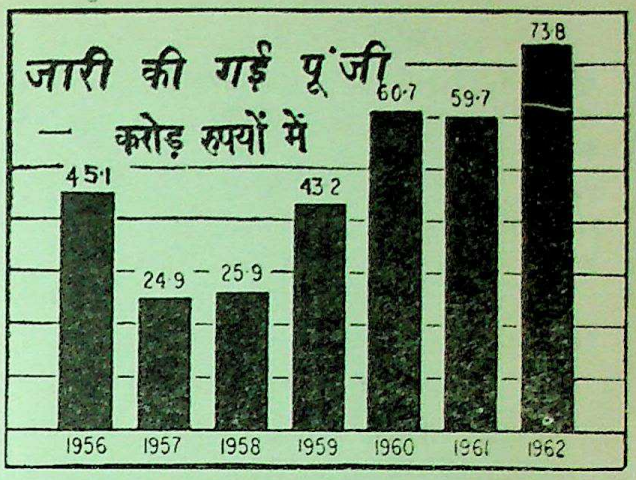

बढ़ती हुई पूंजी औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं और सम्भावनाओं की सूचना देती है।

१९६२ में नई पूंजी

किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए पूंजी का विनियोजन जितना अधिक होगा, विकास की संभावनाएं भी उतनी अधिक होंगी। प्रसन्नता की बात है कि भारत में कुछ अपवाद छोड़कर प्रति वर्ष पूंजी का निर्माण बढ़ता रहा है। १९५१ में करीब ८ करोड़ रु. से बढ़कर १९५२ में ७३.२ करोड़ रु. हो गई। १९६२ में बड़ी व मध्यम आकार की कम्पनियों के लिए ७३.८ करोड़ रु. पूंजी जारी की गई। यह गत वर्ष से २४ प्रतिशत अधिक थी। पिछले वर्षों में कितनी पूंजी जारी हुई, यह निम्न तालिका से प्रकट हो जायगा—

नई पूंजी (करोड़ रु. में)

वर्ष		वर्ष	
१९५१	७.९	१९५७	२४.९
१९५२	४.७	१९५८	२५.९
१९५३	१२.५	१९५९	४३.२
१९५४	३३.२	१९६०	६०.७
१९५५	२६.२	१९६१	५९.७
१९५६	४५.१	१९६२	७३.२

यह जानना भी मनोरंजक होगा कि विभिन्न उद्योगों में वर्ष विनियोजित पूंजी का विभाजन किस तरह रहा हुआ है— 76310

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विभिन्न उद्योगों में पूंजी* १९६२ करोड़ रु. में

सूती मिलें	८.३	रासायनिक	९.६
जूट मिलें	०.६	सीमेन्ट	१.६
अन्य बुनाई	२.०	चीनी	१.२
बैंक	८.४	अन्य	१५.९
इंजिनीयरिंग	२२.२	—	—
कागज	४.२	—	—
		कुल	७३.८

राष्ट्रीय आय

(१९४८-४९ मूल्यों के स्तर पर)

	१९५५-५६	१९६०-६१	१९६१-६२	प्रतिशत वृद्धि
राष्ट्रीय आय (अरब रु. में)	१०४.८	१२६.९	१२९.७	२४
प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय	२६७.८	२९२.५	२९२.५	९
	—	—	—	—

विभिन्न देशों में प्रति रक्षा व्यय

भारत में प्रतिरक्षा व्यय कुल वार्षिक राष्ट्रीय आय का २.१ प्रतिशत है जब कि चीन में ४० प्रतिशत है। अन्य देशों में यह व्यय निम्नलिखित रूप से है—

जापान	१.७	प्रतिशत
पाकिस्तान	३.१	,,
फ्रांस	६.२	(अणु शस्त्रों का विकास)
ब्रिटेन	६.३	,,
रूस	६.३	,,
सं. रा. अमेरिका	९.६	,,

जनसंख्या की दृष्टि से विभिन्न देशों की सेनाओं में निम्नलिखित प्रतिशत है—

भारत	०.१३
चीन	०.३६
सं. रा. अमेरिका	१.३९
ब्रिटेन	१.०१
रूस	१.८८
पाकिस्तान	०.१३

भारत में प्रतिरक्षा का व्यय १९५५-५६ में १८८ करोड़ रु. था। १९६२-६३ के बजट में ३९४ करोड़ रु. रखा गया था और आगामी वर्ष कितना होगा—इसकी कल्पना आज नहीं की जा सकती,

अ. भा. के निर्माता संघ के अध्यक्ष के भाषण से।

(पृष्ठ २ का शेष)

कर लगाये, जब कि १९६१-६२ में भी १४ करोड़ रु. के नये कर लगे थे। योजना आयोग ने ५ वर्षों के लिए केन्द्र को ११०० करोड़ रु. के नये कर लगाने की सलाह दी थी लेकिन सरकार ने नये करों और रेलवे के किराये भाड़े में अधिक वृद्धि से कुल लक्ष्य का ८५० करोड़ रु. वसूल कर लिया। यदि यही दर जारी रही तो पांच वर्षों में केन्द्रीय सरकार ही करीब २१॥ अरब रु. नये करों से वसूल कर लेगी। यह स्मरण रखना चाहिए कि इन करों का लक्ष्य तीसरी योजना की साधारण अवधि के लिए था। नये अ-सामान्य संकट में तो यह मात्रा कितना भयंकर रूप धारण करेगी, इसकी थोड़ी बहुत कल्पना की जा सकती है।

जिन अन्य प्रश्नों ने देश को विशेष विचार करने पर विवश किया, उनमें एक ब्रिटेन का कामनमार्केट में प्रवेश था। यदि वह उसका सदस्य बन गया तो निःसंन्देह भारत के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चाय, चीनी व तमाखू और गृहोधोगों के निर्यात पर भी विशेष विचार किया गया। निर्यात वृद्धि में बाधक देश में अधिक उत्पादन व्यय है। इसे कम करने पर भी बहुत विचार इस वर्ष हुआ है। यह प्रश्न अब एक समिति को सौंपा गया है।

औद्योगिक शान्ति इस वर्ष साधारणतः यथापूर्व रही। कोई बड़ी हड़ताल नहीं हुई। श्री मेहर की अध्यक्षता में बोनस कमिशन दोनों पक्षों के विचार सुनता रहा। इस कमिशन की रिपोर्ट संभवतः इस वर्ष के पूर्वार्ध में प्रकाशित होगी

आसाम में निकलने वाले तेल को के सम्बन्ध में रायल्टी का जो दीर्घकालीन विवाद चल रहा था, वह पं. नेहरू के एवार्ड से समाप्त हो गया। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य को अपने यहां निकलने वाले क्रूड तेल पर ७.५० रु० प्रति टन रायल्टी मिलेगी।

इस तालिका से यह भी स्पष्ट है कि इंजिनीयरिंग उद्योग का सबसे अधिक विकास हुआ है। इसके बाद रासायनिक उद्योगों व बैंकों की ओर विनियोजकों का ध्यान गया है।

*प्रारम्भिक, साधिकार तथा डिबैंचर मिलाकर।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पशु पालन और दूध की महत्त्वपूर्ण समस्या

(श्री जी० विश्वनाथन पिल्ले)

भारत में पशु सबसे अधिक, पर निकम्मे भी बहुत : दुधारु कम : लंदन और न्यूयार्क से अधिक महंगा दूध भारत में : प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करीब १ छटांक।

भारत सदृश कृषि प्रधान देश में पशुपालन का बड़ा महत्त्व है। इस समय भी जब कि इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है, राष्ट्रीय आय का ७ प्रतिशत और कृषि क्षेत्र से प्राप्त आय का १४ प्रतिशत आय पशु पालन से होती है।

वन और मछली पालन विभाग से जो आय होती है, उससे क्रमशः १० गुना और १७ गुना ज्यादा तक पशु पालन से आय होती है। उद्योग और खानों को मिला कर होने वाली आय से इसकी आय ४० प्रतिशत से अधिक है। १९५०-५१ में पशुपालन से ६,००० करोड़ रु. आय हुई, जब कि कुल राष्ट्रीय आय ९५,५०० करोड़ थी।

पशु संख्या भारत में सर्वाधिक

विश्व की कुल गाय-बैल की आबादी का २५ प्रतिशत भारत में हैं। १९५१ में सारे विश्व में ७३ करोड़ २० लाख गाय-बैल और ७ करोड़ ४० लाख में भैंस थीं जबकि केवल भारत में १५ करोड़ ६० लाख गाय-बैल और ४ करोड़ ४० लाख भैंस थीं। मवेशियों की आबादी की घनता विश्व में भारत में सर्वाधिक हैं। १९५१ में यह घनता भारत में प्रति वर्गमील १५ करोड़ ६० लाख (गाय, बैल और भैंस) थी जो केवल डेनमार्क से—जहां यह घनता १८८ प्रति वर्ग मील है—कम है। कनाडा, आस्ट्रेलिया और अमेरिका में यह घनता क्रमशः केवल २.५, और २८ प्रति वर्ग मील है। परन्तु मानव आबादी की दृष्टि से गाय, बैल की संख्या भारत में ज्यादा नहीं है। आस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, न्यूजी लैंड और अमेरिका में मवेशी-मानुष का अनुपात अधिक है। १९६१ की पशु गणना के अनुसार भारत की गाय-बैल की संख्या २२ करोड़ ७० लाख है। इस प्रकार १९५१-६१ के दशक में गाय-बैल की आबादी की वृद्धि १३.५ प्रतिशत हुई।

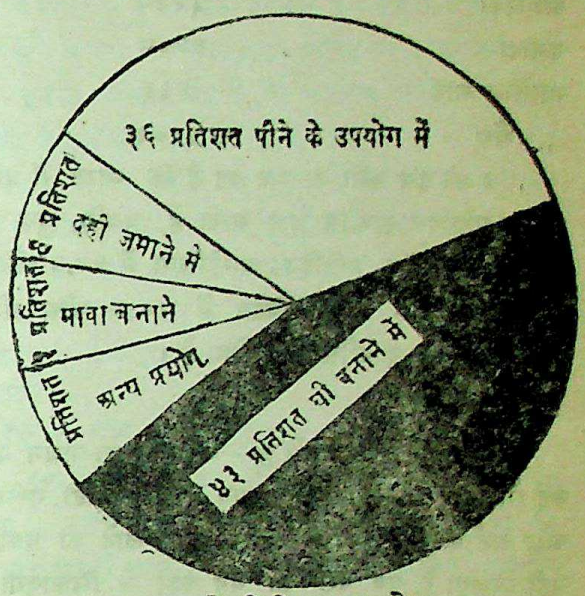

दूध के विभिन्न उपयोग

भैंसों की प्रतिशत वृद्धि, इस अवधि में, अधिक हुई, अर्थात, ४ करोड़ ४० लाख से बढ़कर ५ करोड़ १० लाख, लगभग, १६ प्रतिशत, गाय-बैल १५ करोड़ ६० लाख से बढ़कर १७ करोड़ ६० लाख हो गये, करीब १३ प्रतिशत की वृद्धि।

दूध सबसे कम

दूध देने की दृष्टि से भारत की गाय विश्व में सब-से कम दूध देती है। भैंस ज्यादा दूध देती है, पर डेरी के क्षेत्र में अन्य उन्नत देशों की दुधारु गौ की तुलना में भारत की भैंस अभी बहुत पीछे है। कुछ देशों के दुधारु पशुओं से कितना दूध प्राप्त होता है, यह नीचे की तालिका से स्पष्ट होता है—

प्रति दुधारु गौका औसतन वार्षिक दूध पौण्ड में (१९४५)

देश	औसतन दूध प्रति दुधारु
आस्ट्रेलिया	४३७०
बेलजियम	६३९२

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आयरलैंड	३९६५
इटली	९४५
नारवे	३११८
स्वीडन	५७४२
ब्रिटेन	७६५८
अमेरिका	३२१८
कनाडा	४४०८
भारतीय गाय	४१३
,, भैंस	११०१

दूध की इस कमी का फल यह है कि भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ५ औंस दूध आता है, जबकि, युद्ध से पहले, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आस्ट्रेलिया में ४४.४ औंस, कनाडा में ५६.८ औंस, ब्रिटेन में ४०.७ औंस और अमेरिका में ३५.६ औंस प्राप्त होता है।

प्रमुख कारण

(१) पशु भूखे रहते हैं—भारत में पशु-पालन की कई समस्याएं हैं। भारतीय किसान, पीढी दर पीढी, गरीबी और कर्ज में डूबा रहता है। उसे खुद ही खाने को पर्याप्त नहीं मिलता है, तब पशु को यह कहां से खिलाएगा? वस्तुतः, भारत में पशु-पालन को एक उद्योग के रूप में कभी नहीं समझा गया है। खेती के समान यह भी उसके साथ, प्रासंगिक रूप से, जुड़ा हुआ धंधा है। पशु आवारा घूमने के लिए छोड़ दिये जाते हैं। इससे उनकी नस्ल दुर्बल होती जाती है।

(२) फालतू संख्या—कुछ परम्परागत और धार्मिक विश्वासों के कारण मवेशियों की आबादी बहुत अधिक हो गयी है। पशु-रक्षा की ठीक से व्यवस्था न होने का परिणाम निकला है कि निकम्मे और बांझ मवेशियों की संख्या बहुत बढ़ गयी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस प्रश्न के बारे में कहा गया है कि—

"मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, बिहार और त्रावणकोर-कोचीन में तीन वर्ष से अधिक आयु की दूध देने वाली प्रत्येक १०० गौ के पीछे २०० से ज्यादा बिना दूध देने वाली हैं, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में यह संख्या कम होकर १५० के लगभग रह जाती है और पंजाब में ७५ तक। इन संख्याओं से पता लगता है कि चावल-क्षेत्र और दक्षिणी प्रदेशों में बांझ गौओं की संख्या अधिक है। सामान्य रूप से दूध देने वाली और न देने वाली के बीच अनुपात १-१ का होना चाहिए। बिना दूध देने वाली गौओं की इतनी अधिक संख्या देश पर बड़ा बोझ डालने वाली है।"

मवेशियों के लिए देश में जितना चारा और खाद्य है उस दृष्टि से इनकी संख्या ज्यादा है। यह समझना कि अधिक गाय भैंस होने से दूध की प्राप्ति अधिक होगी—भारी भूल है। इस सम्बन्ध में दूसरी पंचवर्षीय योजना की निम्नलिखित पंक्तियां प्रकाश डालने वाली हैं—

"खोज से पता चलता है कि मवेशियों की वर्तमान संख्या उपलब्ध चारे की मात्रा से पर्याप्त अधिक है। सूखे चारे की दृष्टि से इस समय, कम से कम, एक तिहायी मवेशी फालतू हैं और हरे चारे की दृष्टि से स्थिति और भी अधिक खराब है।"

खेती के लिए बैल

काश्त की दृष्टि से यह अनुमान है कि फी १० एकड़ भूमि के लिए एक जोड़ी बैल पर्याप्त हैं। भारत में खेती की कुल भूमि ३२ करोड़ २० लाख एकड़ है। इसलिए हमें कुल बैल, लगभग, ६ करोड़ ५० लाख चाहिए। १९६१ की जनसंख्या के अनुसार, हमारे पास लगभग ७ करोड़ ५० लाख काम चलाऊ गाय-बैल हैं, ६ करोड़ ८६ लाख बैल और ६ करोड़ ६० लाख भैंसे। इस प्रकार देश में लगभग १ करोड़ सूखे मवेशी हैं। फिर दूध का उत्पादन, आवश्यकता के अनुसार, बहुत कम है। खाद्य और चारे की कमी के कारण, यह सम्भव नहीं है कि दूध की कमी पूरी करने के हेतु दुधारू जानवरों की संख्या बढ़ायी जाए। दूध की मात्रा बढ़ाने से ही यह कमी, कुछ सीमा तक, पूरी हो सकती है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में, भारत की तुलना में, दो तिहाई गौएं हैं पर वहां भारत की अपेक्षा गौएं तीन गुना ज्यादा दूध देती हैं। ब्रिटेन में मवेशियों की आबादी भारत की तुलना में ४ प्रतिशत है पर दूध हमारे उत्पादन से आधा है।

बैल बनाम मशीन

अन्य देशों में गौ-बैल, और भैंसों का पालन दूध और मांस के लिए होता है। पर भारत में उन्हें खेती और

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दूध-दोनों के लिए पाला जाता है। मांस तो प्रासंगिक रूप से प्राप्त हो जाता है। देश की परिवहन व्यवस्था में बैल गाड़ी का स्थान लेने वाला, अभी तक, कोई सशक्त साधन नहीं चालू हुआ है। सड़कों की दुरवस्था होने के कारण देहात में बैलगाड़ी का, अभी तक, प्रमुख स्थान है। मशीनी खेती तो अभी परीक्षण की स्थिति को भी पार नहीं कर सकी है। इसका परिणाम यह है कि अपने समूचे धन्धे के लिए किसान मवेशियों पर ही निर्भर करता है सिवाय उन कामों के, जो परम्परा से मानव श्रम द्वारा किए जाते हैं। पर यह अवस्था बहुत दिन तक नहीं चल सकती। अगर "सहकारिता" गांवों में सफल हो जाती है, तब बड़े-बड़े फार्मों का अस्तित्व होगा और उसके लिए मशीनें बैल का स्थान लेंगी। इसमें पीढ़ियां लग सकती हैं पर सदियां नहीं। पशु-पालन के वास्तविक उत्पादन दूध, मांस, अंडे, ऊन इत्यादि हैं जो इस उद्योग के विकसित होने पर प्राप्त होते हैं। दुधारू और सूखे पशु तैयार करने की दोहरी नीति लाभदायक प्रतीत नहीं होती। इससे बढ़िया नस्ल में गिरावट आ जाएगी और, कुछ समय बाद, दूध देने वाली नस्ल में ह्रास हो जाएगा। सूखे पशु तो पहले ही बहुत हैं। इसलिए हमें दुधारू पशुओं और दुग्ध केन्द्रों के विकास पर ही अधिक ध्यान देना चाहिए। दूध की कमी को दूर करने के लिए भी यह कदम उठाना होगा।

भारत में दूध अमेरिका से भी महंगा

पहली योजना में कहा गया है कि "सर्वेक्षण से पता चलता है कि दूध का खुदरा भाव भारत में अन्य किसी भी महत्वपूर्ण देश से अधिक है।" सरकार द्वारा प्रकाशित "भारत संघ में दूध की बाजार व्यवस्था की रिपोर्ट" (रिपोर्ट आन दि मार्केटिंग आफ मिल्क इन दि इंडियन यूनियन) में प्रकाशित निम्नलिखित तालिका से १९४७ में भारत तथा अन्य कुछ प्रमुख देशों में दूध के भाव ज्ञात होते हैं—

देश	स्थानीय सिक्के में प्रति लिटर का मूल्य	प्रति सेर भारतीय आनों में
ब्रिटेन	८.० पेंस	६.४
आयरलैंड	६.० पेंस	४.८
स्विट्जरलैंड	०.४४ फ्रैंक	५.३
स्वीडन	३३.५ क्रोन	४.५
अमेरिका	१७.५ सेंट्स	६.९
कनाडा	१३.६ सेंट्स	५.३
भारत		१०.०

१९४७ से अब दूध का मूल्य बहुत बढ़ गया है। इस समय नगरों में १ रु० सेर का भाव है। इतनी ऊंची कीमत का होने से भारत में दूध ऐशो-आराम की वस्तु बन गया है। इसका परिणाम यह है कि नागरिक अपने पारिवारिक बजट से दूध को निकाल देने के लिए बाध्य होते हैं और उत्पादकों में यह लोभ आ जाता है कि अपने लिए कुछ भी न रखकर सारा दूध बेच देते हैं। इसलिए, दूध के दाम को युक्ति संगत स्तर पर लाना होगा। दूध की कमी के कारण यह मूल्य वृद्धि है पर साथ ही इसका उत्पादन-व्यय भी ऊंचा है—इस तथ्य से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

निकम्मे पशुओं का इलाज

पशु पालन के सम्बन्ध में योजना में जो कार्यक्रम बनाया गया है, उसके अनुसार, कम दूध देने वाले पशुओं को देश में प्राप्त अच्छी नस्ल से लाभ उठाते हुए अधिक दूध देने वाला बनाया जाए और जिनसे कुछ उत्पादन नहीं होता उन्हें धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाए। नस्ल-सुधार का काम इस ढंग से हो कि दो लाभ हो सकें, दूध मिल सके और खेती भी हो सके। बढ़िया मवेशियों को अच्छा भोजन दिया जाए, बीमारी से रक्षा की जाए, और उत्तम प्रकार से उनकी संभाल हो। केन्द्र-गांव योजना के अन्तर्गत तीन-चार गांवों को मिलाकर करीब ५०० गौओं को—जो तीन वर्ष से ऊपर की हों—रखा जाए और कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग किया जाए। गौशालाएं जंगलों व बंजर जमीनों में हों और वहीं पर अनुपयोगी पशुओं को रखा जाए। वहां चरने की सुविधाएं हों। नई सन्तान को रोकने के लिए बैल वहां न रखे जाएं। चारे की कमी को दूर करने के लिए इसके उत्पादन को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

तीनों योजनाओं में पशु-पालन की ओर कितना कम ध्यान दिया गया है, यह इसी से पता चलेगा कि इस

[शेष पृष्ठ ४६ पर]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आसाम का समृद्ध राज्य

श्री सुभाष

करीब ८५ हजार वर्गमील और ९० लाख जनसंख्या का आसाम भारत का बहुत पिछड़ा हुआ किन्तु अत्यन्त समस्या पूर्ण और दुर्गम राज्य है। इसकी सदा उपेक्षा होती रही है। अधिकांश शिक्षित भारतीय जितना ब्रिटेन आदि देशों के बारे में जानते हैं, उतनी जानकारी आसाम के सम्बन्ध में उनकी नहीं होती। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि आसाम भारत के लिये उपेक्षणीय है।

आर्थिक दृष्टि से आसाम का भारत के लिये असाधारण महत्व है। भारत के निर्यात में चाय का प्रमुख स्थान है। १९६१ में करीब १२५ करोड़ रु. की चाय विदेशों में भारत से गई थी। चाय का अधिकांश आसाम में ही पैदा होता है। आसाम में चाय के छोटे बड़े ७४० बागान हैं, जिनसे करीब ५ लाख कर्मचारी व श्रमिक अपनी जीवीका का निर्वाह करते हैं। यहां ४० करोड़ पौंड चाय प्रति वर्ष उत्पन्न होती है। यह भारत में उत्पन्न होने वाली कुल चाय का ५० प्रतिशत से भी अधिक होता है। संसार की सर्वोत्तम कोटि की चाय भी आसाम में होती है।

चाय के बाद आसाम का बहुत महत्वपूर्ण उत्पादन तेल है। यहां करीब ३५० तेल के कूएं हैं। इस तेल से ४ लाख टन की क्षमता की डिगबोई संशोधन फैक्टरी चलती है। भारत सरकार ने आयल इंडिया कम्पनी के मार्फत नहरकटिया में तेल के नये कूएं खोदे हैं। इन कूओं से प्रति वर्ष ३० लाख टन क्रूड आयल निकलता है। अनुसंधान कर्त्ताओं के एक अनुमान के अनुसार ४.६० करोड़ टन तेल इन कूओं में जमा है। नहरकटिया से नूनमाटी और गोहाटी तक तेल के परिवहन के लिए बिहार में बरौनी तक बड़ी भारी ७२० मील लम्बी पाइप लाइन बन रही है। नूनमाटी की रिफाइनरी में तेल का संशोधन होकर कलकत्ते पहुँचेगा।

तेल के अतिरिक्त आसाम के भूमि गर्भ में ७५.६ करोड़ घनफुट गैस भी विद्यमान है। इस गैस से बिजली उत्पन्न करने का एक बड़ा भारी कारखाना भी आसाम में स्थापित हो चुका है। कोयला भी आसाम को समृद्ध बनाता है।

तेल और गैस की सुलभता के कारण आसाम में रासायनिक खाद के उत्पादन की सम्भावनाएं भी बढ़ गई हैं। फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया वहां ५० हजार टन खाद का एक कारखाना लगाने जा रहा है। इन सब प्रयोजनाओं पर एक अरब रु. से अधिक का व्यय होने की सम्भावना है। इन कार्यों के लिए विदेशों से भी पर्याप्त सहायता मिली है।

पूर्वी पाकिस्तान बन जाने के कारण हमारा आसाम से सीधा स्थलीय व्यापार कम हो गया है। इसलिये हमें जलीय मार्ग से व्यापार करना पड़ता है। यह व्यापार एक विदेशी स्टीमर कम्पनी द्वारा होता है। इस कम्पनी में बहुत से मल्लाह पाकिस्तान के हैं। इन पाकिस्तानियों ने कई सप्ताह तक हड़ताल करदी थी और फलतः स्टीमरों का आना जाना बन्द हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप न आसाम की चाय कलकत्ते की बन्दरगाह तक आ सकी और न कलकत्ते से सीमेंट तथा मशीनरी जो वहां के उद्योग के लिये अत्यन्त आवश्यक थी, आसाम जा सकी। पाकिस्तानियों की हड़ताल ने राजनीतिक रूप ले लिया। इसका भारत की अर्थव्यवस्था और आसाम की उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में रक्षा की समुचित व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इसलिये अधिकारियों ने आसाम को शेष भारत से मिलाने के लिये एक नये मार्ग का विकास करने का निश्चय किया—कलकत्ते से बिहार और वहां गंगा पार करके कारगोला घाट व सिलीगुड़ी होते हुए आसाम—इस मार्ग के विकास से आसाम शेष भारत के साथ पूर्णतः सम्बद्ध हो जायगा और पाकिस्तान के नागरिकों पर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

कृषि की दृष्टि से भी आसाम उपेक्षणीय नहीं है। चाय के अतिरिक्त पटसन भी वहां काफी पैदा होता है और चावल व तम्बाखू की खेती होती है।

चीन, नेफा पर आक्रमण करके हमारे इसी समृद्ध राज्य पर अधिकार करना चाहता है। उसकी गृद्ध दृष्टि आसाम के समृद्ध तेल कूओं और चाय बागानों पर है। इसलिये हमें आसाम की रक्षा और उसके आर्थिक विकास—दोनों पर समुचित ध्यान देना होगा। ● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

युद्धकाल का अर्थशास्त्र

तीसरी योजना और देश की प्रतिरक्षा

श्री श्रीमन्नारायण, सदस्य योजना आयोग

वर्तमान संकटकाल में योजनाबद्ध विकास की पहले से भी अधिक आवश्यकता है क्योंकि आज युद्ध केवल मोर्चों पर ही नहीं, खेतों और कारखानों में भी लड़ा जाता है। प्रस्तुत लेख में श्री श्रीमन्नारायण ने संकटकाल में योजना के महत्व और उसे नये सांचे में ढालने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।

योजनाबद्ध विकास के महत्व को इंगलैंड जैसे विकसित देश भी अब अनुभव कर रहे हैं, हमारा अपना अनुभव भी यही है। एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देश भी भारत की पिछले १० वर्षों की योजनाबद्ध विकास की पद्धति से बहुत प्रभावित हैं। अविकसित देशों को अपना विकास करने में अपने साधनों का अधिकतम सद्उपयोग करना चाहिए और यह तभी हो सकता है, जबकि वे अपनी आवश्यकताओं की एक क्रमिक योजना बना लें, कि, कौनसी पहले और कौन सी पीछे। अव्यवस्थित रूप से कृषि, उद्योग, बिजली और परिवहन के विकास से गड़बड़ पैदा हो जाती है। हमारा अपना अनुभव भी योजनाबद्ध विकास के महत्व को सिद्ध करता है।

आज के राजनीतिक और आर्थिक संकट के दिनों में तो योजनाबद्ध विकास और भी अधिक आवश्यक हो जाता है। हमारी जनसंख्या २ प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ रही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने जो आर्थिक विकास में ५ प्रतिशत वृद्धि की कल्पना की है, उसमें से २ प्रतिशत तो बढ़ती हुई जनसंख्या ही खपा लेगी शेष ३ प्रतिशत वृद्धि हमारे लिए बहुत कम पर्याप्त होगी।

कुछ विचारकों की सम्मति में जब तक चीन के आक्रमण का संकट काल है, हमें अपनी पंचवर्षीय योजना स्थगित कर देनी चाहिए। अब तो हमें अपनी शक्ति का एक-एक बिन्दु अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए लगा देना चाहिए। परन्तु रक्षा की वर्तमान प्रवृत्तियों को देखते हुए यह विचार भ्रम पूर्ण प्रतीत होता है। आज का युद्ध केवल रणक्षेत्र ही नहीं गिना जाता, वह तो प्रत्येक कारखाने और प्रत्येक खेत में कठोर परिश्रम द्वारा लड़ा जाता है। आज की युद्ध अवस्था में तो प्रत्येक मजदूर और प्रत्येक किसान युद्ध का एक सिपाही है। इसलिए, सामाजिक सेवा, भवन निर्माण आदि कुछ क्षेत्रों में भले ही मितव्यय किया जाये, किन्तु कृषि और उद्योग के कार्यक्रम हमें और भी बढ़ाने पड़ेंगे ताकि नागरिकों और सैनिकों की सब आवश्यकताएं यथा समय पूर्ण की जा सकें। और इसलिए योजना बद्ध विकास की आज और भी अधिक आवश्यकता है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय विकास परिषद ने तीसरी योजना को भी युद्ध रक्षा के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया है, यद्यपि उन्होंने इस योजना के कुछ कार्यक्रमों में परिवर्तन स्वीकार किया है। तीसरी योजना के विभिन्न पहलुओं को नए सांचे में ढालने के बारे में योजना आयोग, सम्बन्धित मंत्रालयों और राज्य सरकारों ने कुछ ठोस फैसले किए भी हैं और इसमें कोई शक नहीं कि अपनी योजना के इस परिवर्तित रूप से हमारा सामर्थ्य बढ़ेगा और हम हमलावरों को अपनी भूमि से उठा बाहर खदेड़ सकेंगे।

यह स्पष्ट है कि चीन के साथ लड़ाई के कारण कई महीनों और शायद वर्षों तक हम पर भारी बोझ रहे। हमें अपने अधिकतर साधन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, सैनिकों की तात्कालिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए लगा देने होंगे। परन्तु मुझे विश्वास है कि यह राष्ट्रीय संकट हमारे लिए वरदान भी सिद्ध होगा। एकता, कड़ी मेहनत और त्याग के लिए प्रधानमंत्री की अपील का देशवासियों पर जो तत्काल और शानदार असर हुआ है, वह बड़े संतोष की बात है।

संकट का साहस और निश्चय से सामना करने के लिए सभी राजनीतिक दल, मजदूर संघों, शिक्षा संस्थाओं और सरकारी व गैरसरकारी संगठनों ने अपनी सेवाएं और साधन भारत सरकार को अर्पित किए हैं।

व्यापारियों ने थोक और खुदरा भावों को न बढ़ने देने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

का निश्चय किया है। जनता के सभी वर्गों का यह सहयोग भविष्य में हमारी योजना के लिए बहुत अमूल्य सिद्ध होगा।

आज का संकट प्रच्छन्न रूप से देश के लिए एक वरदान सिद्ध हो रहा है। देश के सभी वर्ग मजदूर किसान, उद्योगपति, व्यापारी, शिक्षा शास्त्री, साहित्यकार, सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी सब देश रक्षा के लिए सन्नद्ध हो गये हैं।

इस आक्रमण के बिना इस उद्देश्य की पूर्ति निस्संदेह कठिन होती। चीन के हमें युद्ध में झोंकने के बाद हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिये।

१. पहला तो यह है, कि भारत सरकार ने बचत करने की जो योजनाएं प्रस्तुत की हैं उनमें सबको सहयोग देना चाहिये। पूंजी निर्माण के लिए बचत सबसे अधिक आवश्यक है। भारत में बचत का दर बहुत कम है। इसे बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है।

२. दूसरी आवश्यक बात हमें उद्योग और कृषि में उत्पादन को युद्ध स्तर पर बढ़ाना चाहिए। अभी तक उत्पादकता बढ़ाने के जो प्रयत्न किए गए हैं वे बहुत सफल नहीं हुए। इस संकट काल में श्रमिकों और उद्योग पतियों को मिलकर उत्पादन बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए और दोनों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की अपेक्षा कर्तव्यों के उत्तरदायित्व पर ध्यान होना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि योजना बद्ध विकास के लिए भोजन और वस्त्र आदि उपभोग्य वस्तुओं का मूल्य नहीं बढ़ने देना चाहिए। अभी तक इस दिशा में किए गए प्रयत्न बहुत प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुए। अब उत्पादकों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं का सहयोग मिलने से मूल्य बढ़ने से रोके जा सकते है। वर्तमान युद्ध ने सबमें सहयोग और देश भक्ति की सुन्दर भावना उत्पन्न कर दी है, और इससे देश की अर्थव्यस्था निश्चय ही सुदृढ़ होगी।

चौथी बात यह है कि इस संकट के समय हमारे सामने अपना यह उद्देश्य स्पष्ट रहना चाहिए कि हमने भारत में समाजवादी समाज की स्थापना करनी है। वर्तमान संकट के कारण इस उद्देश्य में शिथिलता आने का कोई कारण नहीं है।

आदर्श नहीं बदलना

कुछ लोग सोचते हैं कि युद्ध की तैयारी हमें समाजवाद और तटस्थता के आदर्श छोड़ देने को मजबूर कर देगा। लेकिन मेरा यह निश्चित मत है कि यह निष्कर्ष गलत है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्तमान युद्ध के कारण हमें जो तकलीफ उठानी पड़ेगी उससे लोकतंत्री समाज और योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत ही होगा। शान्ति और तटस्थता की नीति हमारी योजना का आधार भी है और वर्तमान परिस्थितियों में भी हमें अपनी उसी नीति का अनुसरण करते रहना है। जो देश संकटकाल में भी अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होता, वह युद्ध में तो जीतता ही है, शान्ति में भी आगे रहता है।

आर्थिक समीक्षा

प्रधान सम्पादक : श्री सादिक अली

सम्पादक : श्री महेन्द्र मेहरा

- हिन्दी में अनूठा प्रयास
- आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख
- आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत

भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक।

वार्षिक मूल्य : ५ रु० एक प्रति २२ नये पैसे

लिखें—व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, नई दिल्ली।

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

युद्धकालीन अर्थशास्त्र

नये कर ही एक मात्र उपाय

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चान्सलर, डा० बी० एन० गांगुली, दिल्ली स्कूल आफ इकानामिक्स के डा० के० एन राज, इंडियन स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टडीज, नयी दिल्ली के डा० ए० एम खुसरो इंस्टीस्टयूट आफ इकानामिक ग्रोथ के डा० राजकृष्ण तथा इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीटयूट के प्रो० जगदीश भगवती—इन छः अर्थ-शास्त्रियों ने देश की वर्त्तमान युद्ध-स्थिति को दृष्टि में रखते हुए एक संयुक्त वक्तव्य में सुरक्षा के साधनों को अधिक शक्तिशाली बनाने और आर्थिक नीति पर विशेष बल दिया है। इनके विचार पाठक इस पृष्ठ पर पढ़ेंगे।

वर्तमान सीमा युद्ध के कई महत्त्वपूर्ण फलितार्थ हैं। इस नयी स्थिति का मुकाबला करने के लिए जिन सशक्त साधनों का अवलम्बन करने की आवश्यकता थी, वे क्रिया में अभी तक नहीं लाये गये हैं। इसलिए हम यह आवश्यक समझते हैं कि स्पष्ट शब्दों में कुछ नीतियों को कार्यान्वित करने के बारे में अपने विचार देश के नेताओं के सामने उपस्थित करें।

४०० करोड़ रु० का अतिरिक्त व्यय

युद्ध बन्दी की परवाह न करते हुए, हमारी सेना मौजूदा सेना के स्वरूप से कम से कम दुगुनी होनी चाहिए। वेतन और भत्ते, हथियार और गोला-बारूद, सड़कों और हवाई अड्डों का निर्माण, नागरिक सुरक्षा इत्यादि से सुरक्षा-बजट में काफी वृद्धि हो जाएगी। सुरक्षा व्यय के न्यूनतम अनुमान के अनुसार, दुगुना हो जाने की संभावना है। इसका स्पष्ट अभिप्राय है ४०० करोड़ रु० का अतिरिक्त वार्षिक व्यय।

इस प्रकार के व्यय का वस्तुओं की उपलब्धि पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। सैनिक सामान को खरीदने के लिए अन्य देशों के साथ जो उधार-पट्टे की तथा अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उनकी पूरी गुंजायश रखते हुए भी हमें वर्तमान साधनों को नागरिक दिशा से सैन्य दिशा की ओर ले जाना होगा। देश की वर्त्तमान शक्ति, वस्तुतः, इस दिशा परिवर्तन की दृष्टि से, बहुत सीमित है। इस समय जो कच्चा माल आयात किया जाता है, उसे चालू सैनिक प्रयोग में लाने के बारे में भी यही बात कही जा सकती है। फिर भी, इस संभावित दिशा-परिवर्तन की सीमा बहुत बड़ी और अवश्यम्भावी है। आयात की सहायता से इस नयी शक्ति-सृजन का विचार करना होगा। वास्तविकता के साथ मूल्यांकन करने के बाद, हम समझते हैं कि, आगामी कुछ वर्षों में विदेशी मुद्रा पर यह बोझ १०० करोड़ प्रति वर्ष से कम नहीं होगा।

दिशा परिवर्तन

उपभोक्ता सामान को कम करके यह दिशा परिवर्तन करना होगा। उपभोक्ता सामान के उद्योगों के लिए आयात में न केवल कमी करनी होगी किन्तु इन उद्योगों के शक्ति सृजन को भी धीमा करना होगा। ऐसा करना आवश्यक होगा, क्योंकि हम अपने कार्यक्रम में कटौती नहीं कर सकते हैं। विनियोजन प्रोजेक्टों को पूरा करने पर जितना बल दिया जाए, उतना ही थोड़ा है। निःसन्देह, इसके लिए कुछ हेर फेर करना होगा और कुछ प्रोजेक्टों में द्रुतगति लानी होगी और अधिक साधनों का प्रयोग करना होगा। मुख्य रूप से पूंजीकत सामान के प्रोजेक्टों को—जो योजना के आधारभूत हैं—रखना होगा और उनका विकास करना होगा। इन्हें शीघ्र गति से पूरा करना होगा। आर्थिक विस्तार के हमारे दूरगामी कार्यक्रम और सुरक्षा योजनाएं इन्हीं प्रोजेक्टों के पूरा होने पर निर्भर करती हैं।

इसके दो परिणाम होंगे—तीसरी योजना में जो स्तर निश्चित किये गये हैं, उससे खपत कम होगी और सुरक्षा व्यय बढ़ जाने से उपभोक्ता सामान की मांग बढ़ जाएगी। ये दोनों तत्त्व एक दूसरे को प्रभावित करते हुए प्राप्त सामान

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के लिए अधिक मांग को पैदा करेंगे।

सार्वजनिक क्षेत्र में कमी नहीं

यह युक्ति ठीक नहीं है कि सार्वजनिक व्यय में कमी करके साधन-वृद्धि की जाए। प्रशासकीय और इमारती व्यय में कमी आवश्यक है। राहत देने वाली योजनाओं को, फिलहाल रोक दिया जाए। पर, इससे आवश्यक साधनों के लिए १५-२० प्रतिशत से अधिक प्राप्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, इन कटौतियों का दूरगामी प्रभाव, लक्ष्य की दृष्टि से, हानि कारक ही होगा।

यह महान् कार्य दान व उधार लेकर भी पूरा नहीं किया जा सकता है। अभी तक इस संकट में जिस बड़ी मात्रामें और शीघ्रता से दान प्राप्त हुआ है, वह उत्साह-जनक है, पर इस महान् कार्य में यह स्वल्प मात्र ही है। अभी तक प्राप्त दान की बड़ी मात्रा भूतकाल की संचित बचत में से ही आयी है, वर्तमान खपत में कटौती करने से प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए यह अभी तक वित्त की प्राप्ति ही हुई है, चालू उत्पादन के लिए आवश्यक साधनों की प्राप्ति नहीं हुई है। उधार प्राप्त राशियाँ भी अपर्याप्त हैं। चूंकि उनपर सूद दिया जाएगा, इसलिए, एक प्रकार से वे राष्ट्रीय कोष पर बोझ ही हैं। बांडों की शर्तें इतनी उदार हैं कि उन पर सूद देना भी बहुत सहज नहीं होगा। फिर यह उधार, विभिन्न मात्रा में, बचत का एक स्वरूप दूसरे स्वरूप में परिवर्तित रूप ही है जबकि सुरक्षा में हुई व्यय-वृद्धि की मांग तो यह है कि उसके अनुरूप राशि के लिए अतिरिक्त बचत हो। इसलिए, दान व उधार जब तक कई गुना ज्यादा न हों और हमारी अधिकतम आशाओं से भी बढ़ कर न हों—तब तक मुद्रास्फीति की ही संभावना है, बशर्त्ते कि अतिरिक्त कर न लगाया जाए।

अतिरिक्त कर

इसलिए, अवश्यम्भावी उपाय अतिरिक्त कर ही हैं। इससे बचा नहीं जा सकता। इसके लिए तत्काल पूरक बजट पेश करना होगा। निरन्तर वृद्धिशील सुरक्षा-व्यय को दृष्टि में रखते हुए पूरक बजट कई सप्ताह पहले ही पेश हो जाना चाहिए था। पर यह अभी तक पेश नहीं हुआ है।

इस बजट को जितनी देर तक टाला जाएगा, उतना ही वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा प्रयत्नों को खतरा है। जब कीमतें चढ़नी शुरू हो जाएंगी, उस समय महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्टों पर बड़ा भारी बोझ पड़ेगा। इस समय, सब दृष्टियों से, जिस स्थिति से बचाव करना है, वह है अंधा-धुंध मूल्य वृद्धि। इस मूल्य वृद्धि का फल यह होगा कि बचत की ओर झुकाव नहीं रहेगा और निम्नतम आय-वर्ग पर कष्ट आ जाएगा।

निःसन्देह चीनी आक्रमण की इस स्थिति में, इस बजट को जनता न केवल सहन करती किन्तु स्वागत करती। इससे, प्रत्यक्ष आवश्यकता पूरी होती और कइयों के लिए 'त्याग' का ठोस स्वरूप होता। इस पूरक बजट का मनो-वैज्ञानिक अवसर अभी तक मौजूद है। बहुत लोग यह अनुभव करते हैं कि राष्ट्रीय सम्मान और त्याग की दृष्टि से सरकार असफल रही है। अधिक देर न करके नये कर लगाने के इस अवसर का पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए।

अवश्य पढ़िए !

"उद्योग-व्यापार पत्रिका"

का

प्रगति विशेषांक

उद्योग-व्यापार पत्रिका जनवरी १९६३ अंक प्रगति विशेषांक के रूप में प्रकाशित हो रहा है जिसमें आप स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अब तक हुई उद्योग तथा व्यापार क्षेत्र में हुई प्रगति एवं भावी-विकास सम्बन्धी झांकी देख सकेंगे।

विशेषांक अत्यन्त ज्ञान-वर्द्धक तथा संग्रहणीय होगा। मूल्य केवल ५० न. पै.। डाक टिकट स्वीकार नहीं किये जाते। शीघ्र ही पोस्टल आर्डर अथवा मनीआर्डर द्वारा मूल्य भेजकर अपनी प्रतियां सुरक्षित करा लें।

विक्रेता एवं विज्ञापन एजेन्टों को भरपूर कमीशन

निदेशक : व्यापार प्रकाशन निदेशालय

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विश्व का प्रबल वेग से नगरीकरण

पिछले कुछ दशकों से विश्व की बढ़ती हुई आबादी की एक विशेषता यह है कि विश्व की जनता का बड़ी शीघ्रता के साथ नगरीकरण हो रहा है और यह काम विश्व की आबादी बढ़ने की अपेक्षा भी तेजी से हो रहा है।

१८०० में विश्व की आबादी का करीब २॥ प्रतिशत ऐसे शहरों व कस्बों में रहता था जिनकी आबादी २० हजार से अधिक थी। १९५० में ऐसी आबादी २१ प्रतिशत हो गई है। दूसरे शब्दों यों कह सकते हैं कि इन १५० वर्षों में विश्व की कुल जनसंख्या जहां २.६ गुणा बढ़ गई है वहां नगरों में रहने वाली आबादी २३ गुणा बढ़ गई है। यह प्रवृत्ति अभी तक कम नहीं हुई है। इस नगरीकरण का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विचारधाराओं पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

आर्थिक प्रभाव

लोग उत्पादक भी हैं और उपभोक्ता भी हैं। एक नागरिक की आवश्यकताएं, इच्छाएं और उत्पादन ग्रामीण की आवश्यकताओं, इच्छाओं और उत्पादनों से, निश्चय ही भिन्न होते हैं। सामान्यतः, एक नगर निवासी की आय एक किसान की अपेक्षा अधिक होती है। एक नागरिक की आय, प्रायः, नकद होती है और ग्रामीण की जिन्स की शक्ल में होती है। नगरीकरण का व्यापारियों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। देशी और विदेशी व्यापारी—उत्पादक और वितरक दोनों—नगर और देहात की आबादी के आपसी परिवर्तन के दर से विशेष रूप से प्रभावित होते हैं।

स्पष्ट है कि नगरीकरण और सामान्य आर्थिक विकास का आपस में गहरा सम्बन्ध हैं। नगरीकरण की वृद्धि से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ता है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों से पता चलता है कि विश्व निर्यात का आधार १९५३ में अगर १०० को मान लें तो १९५८ में यह संख्या १२८ थी। इसी आधार पर १९५८ में आबादी का निर्देशक अंक केवल १०८ था, बुनियादी उत्पादकों का उत्पादन १११ था और निर्माणात्मक उत्पादन ११७ था। इस वृद्धि का एक बड़ा कारण नगरीकरण ही था।

१९वीं सदी के पिछले ५० वर्षों में जो नगरीकरण हुआ, वह इस सदी के पहले ५० वर्षों की अपेक्षा अधिक तेज था। २० हजार की आबादी के नगरों में आधे अरब से अधिक लोग १९५० में रहते थे। १९७५ में, केवल एशिया में ही, २० हजार व अधिक की आबादी वाले नगरों में दूसरे आधे अरब लोग रहने लगेंगे।

नई समस्याएं

नगरीकरण के बढ़ने से कई समस्याएं, चैलेंज, और अवसर पैदा होते हैं। इनमें मुख्य देहाती क्षेत्रों से बड़ी संख्या में जनता का प्रव्रजन है। विकासोन्मुख देशों में शिक्षा और हुनर की कमी और भारी सांस्कृतिक विषमता के कारण प्रव्रजक को नागरिक जीवन के अनुकूल अपने को बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। इसका प्रभाव उसके रोजगार के अवसरों पर भी पड़ता है। नगर की सामाजिक और कल्याणकारी प्रवृत्तियां भी इससे अप्रभावित नहीं रह सकतीं। अकुशल श्रमिकों को उद्योग और व्यापार में खपाया नहीं जा सकता। नगरों में आवास की समस्या भी भयंकर होती है। इसी से सम्बद्ध अधिक भीड़ का होना, अपर्याप्त रिहायश, सफाई की अव्यवस्था, निकम्मा भोजन, इत्यादि समस्याएं भी पैदा होती हैं। इन सबसे सामाजिक अशान्ति पैदा होती हैं, और राजनीति पर भी प्रभाव पड़ता है।

इन समस्याओं का हल करने के लिए संयुक्तराष्ट्र के अन्तर्गत विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संघ, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इत्यादि संस्थाएं काम कर रही हैं। इस ढांचे के अन्तर्गत निजी साहस के लिए पर्याप्त अवसर निकल सकते हैं। नगरों में कम कीमत की बड़े पैमाने पर आवास व्यवस्था होनी चाहिए। विकासोन्मुख देशों के समान विकसित देशों में भी नगरीकरण बढ़ रहा है और साथ-साथ समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। कई उन्नत देशों में पिछले कुछ समय से नगरीकरण कुछ धीमा होगया है। यह आशा की जा सकती है कि आज के विकासोन्मुख देश कुछ समय बाद इस सम्बन्ध में अमेरिका के सदृश हो जाएंगे। १७९० में अमेरिका अनुन्नत व विकासोन्मुख देश कहा जा सकता था। उस समय इसकी नागरिक आबादी कुल आबादी के अनुपात में केवल ५ प्रतिशत थी। १९६० में अमेरिका की नगर आबादी कुल आबादी की ७० प्रतिशत हो गई थी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रूस में कीमतें कैसे नियंत्रित होती हैं ?

ले०—प्रो० ए० एम० बिरमान

सोवियत राज्य ने अपने जन्मकाल से ही कीमतों को, और उनके जरिये आर्थिक कार्यकलाप को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। सोवियत सरकार के प्रारम्भिक वर्षों में यह काम आसान नहीं था। १९२४ के पहले तक गृहयुद्ध और विदेशी फौज हस्तक्षेप के कारण देश में कोई स्थिर मुद्रा नहीं थी और इसलिए कीमतें भी स्थिर नहीं रह सकती थीं। बाद में मुद्रा सुधार के बाद जब मुद्रा स्थिर हुई, तब भी अत्यन्त बिखरे कृषि उत्पादन और व्यापार व्यवस्था में, छोटे पैमाने के व्यापार और परिवहन में व्यक्तिगत सम्पत्ति वालों के प्रभुत्व की वजह से कठिनाइयां बनी रहीं।

कृषि उत्पादन जब ढाई करोड़ निजी घरों में बिखरा हुआ हो, और ८० प्रतिशत खुदरा व्यापार जब व्यक्तिगत पूंजी के हाथों में हो, वैसे समय में राज्य मुख्यतया अप्रत्यक्ष रूप से ही कीमतों का नियंत्रण कर सकता है। जाहिर है कि ऐसा करना काफी कारगर नहीं होता। फिर भी उसने अपनी वित्तीय और दूसरी एजेंसियों के जरिये इस बात का प्रबन्ध किया कि कीमतें मुनाफाखोरी के स्तर तक न पहुँचने पायें। राजकीय उद्योगधन्धों के उत्पादनों को निश्चित कीमतों पर बेचकर उसने कीमतों को बढ़ने से काफी रोका।

लेकिन कीमतों का कारगर नियंत्रण चौथे दशक के आरम्भ से तभी सम्भव हो सका जबकि उद्योग की सभी शाखाओं और कृषि का पूर्ण रूप से या लगभग पूर्ण रूप से समाजीकरण हो गया और राष्ट्रीय आर्थिक विकास की वार्षिक योजनाएं बनायी जाने लगीं।

मूल्य नियंत्रण के विभिन्न तरीके

सोवियत संघ में हम कीमतों को चार कोटियों में विभक्त करते हैं : पूरे देश में बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमतें, वैसी वस्तुओं की कीमतें जो आम तौर पर किसी खास जनतन्त्र में बेची जाती हैं, वैसी वस्तुओं की कीमतें जो मुख्य रूप में स्थानीय बाजार में बिकती हैं, चूना और भवन निर्माण की स्थानीय सामग्रियों, घरेलू सामानों, कुछ प्रकार के बर्तन-भांडों, बिसाती सामानों और बहुत कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतें, आदि। अन्त में सामूहिक फार्मों और किसानों के निजी छोटे बाग-बगीचों के उत्पादनों की कीमतों का नम्बर आता है।

पहली कोटि की वस्तुओं, दूसरे शब्दों में कोयला, तेल, धातुएं, मशीनें, अनेक प्रकार की भवननिर्माण सामग्री, अनाज और रुई आदि की कीमतें एक राजकीय संस्था यानी सोवियत संघ की राज्य योजना समिति द्वारा निर्द्धारित होती हैं।

कई मामलों में, जैसे कि मशीनों के प्रायोगिक नमूनों और ऐसी मशीनों के सम्बन्ध में जिनका नियमित उत्पादन नहीं होता है, राज्य समिति अस्थायी कीमतें तय करती है। ये कीमतें आम तौर पर एक साल तक जारी रहती हैं और उसके बाद स्थायी कीमतें तय कर दी जाती हैं।

किसी खास जनतंत्र में मुख्य रूप से बिकने वाली वस्तुओं की कीमतों को उस जनतन्त्र की राज्य योजना समिति तय करती है। ऐसी वस्तुएं यदि किसी दूसरे जनतंत्र में बेची जाती हैं, तब भी उनकी कीमतों में कोई अन्तर नहीं होता है। हां, यदि ले जाने की दूरी काफी लम्बी हो तो कीमतों में थोड़ी बढ़ती हो सकती है, क्योंकि ऐसे मामले में ऊंची परिवहन दर लागू होती है।

देश को दूरी के हिसाब से अनेक क्षेत्रों में बांटा जाता है जिनमें से प्रत्येक क्षेत्र की कीमत पहले क्षेत्र से कुछ अधिक होती है। कुछ वस्तुओं के लिए तीन या चार क्षेत्र हैं। जिन वस्तुओं के परिवहन में कठिनाई होती है, उनके लिए छः या सात क्षेत्र बनाये गये हैं।

स्थानीय मांगों की पूर्ति के लिए जो वस्तुएं स्थानीय तौर पर उत्पादित की जाती है, उनकी कीमतों को मेहनतकश जनता के डिपुटियों की सोवियतों की क्षेत्रीय कार्यकारिणी समिति निर्द्धारित करती है। आम तौर पर ये वस्तुएं उस खास क्षेत्र से बाहर नहीं बेची जाती हैं, इसलिए उनकी कीमतों में अन्तर नहीं होता।

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुस्तकालय गुरुकुल कांगड़ी

उत्पादन व्यय और कुछ प्रतिशत

योजना के मुताबिक जितने उत्पादन व्यय का हिसाब लगाया जाता है, उसमें कुछ प्रतिशत मुनाफे का जोड़ दिया जाता है। सोवियत कल-कारखानों के उत्पादन व्यय में बहुत से ऐसे मद होते हैं जो दूसरे देशों में नहीं पाये जाते। मुख्य रूप में अस्थायी असमर्थता की अवस्था में दिये जाने वाले लाभ भी उत्पादन व्यय में अतिरिक्त भार के रूप में जोड़े जाते हैं। सामाजिक बीमा के ये कोष कारखानों से जमा किये जाते हैं। श्रमिक अपनी कुल तनखाह की रकम में से ४ से १० प्रतिशत तक इस मद में देते हैं। कौन कितना देगा, यह कारखाने-कारखाने पर निर्भर करता है। जिस कारखाने की उत्पादन परिस्थितियां अधिक जटिल होती हैं, उसे सामाजिक बीमा के लिए उतना ही अधिक देना होता है। कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित करने, यानी मजदूरों और कर्मचारियों को उच्च प्रशिक्षण प्रदान करने, मजदूरों द्वारा किये जाने वाले अन्वेषणों और नवीनीकरण की विधियों को प्रोत्साहन देने के लिए जितने धन की जरूरत होती है और साथ ही मजदूरों के बीच सांस्कृतिक कार्यकलाप के लिए ट्रेड यूनियनों को जो धन दिया जाता है, वे भी उत्पादन व्यय में शामिल होते हैं। इस प्रकार तनखाह के बिल के आधार पर इस प्रकार की जो वसूलियां होती हैं, वे कुल मिलाकर ५ से १२ प्रतिशत हो जाती हैं। यह रकम मुख्य रूप में ट्रेड यूनियन संगठनों के पास चली जाती है और उन्हीं के नियंत्रण में खर्च होती है।

सोवियत संघ में किसी प्रकार की प्रतिद्वन्द्विता नहीं है, न ही वहां उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व है। वहां मुनाफा कमाना अन्तिम लक्ष्य भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वहां व्यय में ३ से लेकर ५ प्रतिशत के योग को मुनाफे का स्वाभाविक स्तर माना जाता है। बच्चों के कपड़े और जूते, पाठ्य पुस्तकें, अनेक औषधियां, रसायन, अनेक तरह की मशीनें, भवन-निर्माण की सामग्रियां और इसी तरह की अन्य वस्तुएं बिना किसी मुनाफे के या बहुत कम मुनाफा लेकर बेची जाती हैं। ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनकी खपत को रोकना वांछनीय माना जाता है। नशीली चीजें और ताश के पत्ते ऐसी ही कोटि में आते हैं। अतएव इन वस्तुओं की कीमतों में ३-५ प्रतिशत से भी बहुत अधिक मुनाफा शामिल होता है। अन्त में, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनके इस्तेमाल को तो राज्य प्रोत्साहित करना चाहता है, लेकिन अभी भी वह यथोचित पैमाने पर उनके उत्पादन का प्रबन्ध करने की स्थिति में नहीं है। फर्नीचर, कुछ प्रकार के कपड़े, रेफ्रीजरेटर, टेलीविजन सेट और कुछ खाद्य सामग्रियां इस कोटि में आते हैं। इन वस्तुओं की कीमतें इस हिसाब से रखी जाती हैं जिससे मांग और पूर्ति में सन्तुलन को बनाये रखने में सहायता मिले। अतएव इनकी कीमतों में भी मुनाफे का अंश अधिक हो सकता है।

सोवियत संघ में कीमतें इस अर्थ में स्थिर होती हैं कि उन पर संकटों का, सट्टेबाजी का या दूसरी स्वयं स्फूर्त प्रक्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। इसका कारण यह है कि राष्ट्रीय अर्थतन्त्र योजना के अनुसार विकसित होता है।

किसी खास वस्तु का उत्पादन यदि बढ़ जाता और उत्पादन व्यय घट जाता है, तो उसकी कीमत पर फिर से विचार किया जाता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आबादी की बढ़ी आय के फलस्वरूप कुछ खास वस्तुओं की मांग उनके सम्भावित उत्पादनों की तुलना में तेजी से बढ़ने लगती है। ऐसे मामलों में उन वस्तुओं की कीमतों को कुछ दिनों के लिए बढ़ा देना होता है। पिछले कुछ वर्षों में यात्री-कारों, कुछ प्रकार के कम्बलों, कुछ प्रकार के फर्नीचरों और इस वर्ष मांस और मक्खन की कीमतों में जो बढ़ती हुई है, वे इसी के उदाहरण हैं।

सामूहिक फार्म शहरों में सामूहिक फार्म के बाजार से अपने उत्पादनों को व्यक्तिगत नागरिकों के हाथ भी बेचते हैं। इसी तरह सामूहिक फार्म में सदस्यों को अपने फार्म से जिनिस के रूप में जो उत्पादन मिलते हैं तथा अपने निजी बाग-बगीचे से वे जो उपज प्राप्त करते हैं, उन्हें भी बड़ी मात्रा में वे बाजार में बेचते हैं। अन्त में, कुछ शहर निवासी भी फल, सब्जियां, फूल तथा कुछ दूसरी चीजें पैदा करके उन्हें बाजार में बेचते हैं।

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नया सामयिक साहित्य

Economies at work—लेखक—श्री जे० डी० खत्री तथा जी० सी० जांगिर, प्रकाशक—किताब महल, दिल्ली। पृ. सं. ४३८, मूल्य १० रु. ५० न. पै.।

Economies at work के शीर्षक से दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुभवी लेखकद्वय का यह प्रयास स्वागत योग्य है। प्रस्तुत पुस्तक में वर्तमान अर्थव्यवस्था एवं उसके संगठन के पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिये उसकी परिचालन एवं विकास विधियों का विश्लेषण किया गया है। पुस्तक के आरम्भ के अध्यायों में अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग, मूल समस्यायें, मुद्रा प्रवाह तथा राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक प्रगति को समझाया गया है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में पाये जाने वाले आजीविका के स्वरूप एवं उनकी प्रमुख विशेषतायें तथा रहन-सहन के स्तर और उत्पादन शीलता और उनकी विषमताओं को सरल एवं सुस्पष्ट ढंग से लिखा गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्याओं तथा इस व्यवस्था की संचालन-विधि को अत्यन्त सरल बना दिया गया है। पुस्तक के अन्तिम अध्यायों में लेखकों ने आयोजन तथा राज्य की आर्थिक गतिविधियों में नियंत्रण को भी विस्तार से समझाया है। वस्तुतः, पुस्तक दिल्ली विश्वविद्यालय में बी. ए. (उत्तीर्ण) के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर लिखी गई है। फिर भी सामान्य पाठकों के लिये भी पुस्तक उपादेय है, जिन्हें आर्थिक विकास की प्रक्रिया को जानने की जिज्ञासा है।

प्रत्येक देश में अर्थशास्त्र के अध्ययन में प्रवेश करने वालों के लिए एक ऐसी पुस्तक उपलब्ध है जो उसे आर्थिक प्रक्रियाओं से सही तथा सरल ढंग से परिचित करदे। भारत में ऐसी पुस्तक का अभाव रहा है। लेखकों ने मुख्य रूप से इसी अभाव की पूर्त्ति के लिए यह पुस्तक लिखी है। जहां तक हो सका है अर्थशास्त्र के कठिन शब्दों के उपयोग के बिना ही विषय सामग्री को समझाया गया है। इस कारण यह पुस्तक उचित दिशा में अपनाया गया प्रथम प्रयास कहा जा सकता है।

पुस्तक में अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं एवं आर्थिक विकास की विधियों को समझाने के लिये अगर चित्रों एवं रेखाचित्रों की सहायता ली जाती तो पुस्तक की उपयोगिता द्विगुणित हो जाती। आशा है कि अगले संस्करण में लेखक इस अभाव को दूर कर सकेंगे। पुस्तक के अन्त में विषय-निर्देशांक का अभाव भी खटकता है।

पुस्तक का मुद्रण एवं साजसज्जा सुन्दर है। मूल्य भी उचित है।

आर्थिक व्यवस्था और विकास—ले० श्री रुद्रदत्त, एम. ए., प्रकाशक—रतन प्रकाशन मन्दिर, आगरा, पृ. सं. ४२६, मूल्य ६ रु. ५० न. पै.।

उपर्युक्त समीक्षित पुस्तक की समकक्षता में 'आर्थिक व्यवस्था और विकास' दिल्ली विश्वविद्यालय के एक अनुभवी अध्यापक का सराहनीय प्रयास है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। प्रथम, यह पुस्तक राष्ट्रीय भाषा हिन्दी में लिखी गई है जो अर्थव्यवस्था तथा विकास की कार्यविधि को समझाती है। दूसरे, यह इस भाषा में लिखी जाकर बी. ए. उत्तीर्ण प्रथम वर्ष के उन छात्रों के लिये उपयोगी है, जो अपना माध्यम हिन्दी रखना चाहते हैं। चूंकि पुस्तक मौलिक रूप से हिन्दी में ही लिखी गई है इसलिये कठिन विषयों को भी सरल, एवं स्वाभाविक ढंग से समझाया गया है। अध्याय के अन्त में विषय-सामग्री का सार दिया गया है, जो लाभप्रद है। 'राष्ट्रीय आय और आर्थिक प्रगति' के अध्याय में दिये हुए 'भारत के राष्ट्रीय लेखों' को अधिक सुबोध बनाने के लिये लेखक को तत्सम्बन्धित टिप्पणी अवश्य देनी चाहिये थी। अध्याय १६ "मौद्रिक व्यवस्था के मूलाश" का विवेचन पुस्तक के प्रारम्भ के पांच अध्यायों के आसपास ही अधिक उपयुक्त रहता, क्योंकि "विशिष्टीकरण के मूल कारण और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार" और "अर्थ व्यवस्थाओं का विकास" के अध्यायों के मध्य यह अध्याय कम ही तालमेल रखता है।

इस पुस्तक में स्थान-स्थान पर भारत के आर्थिक आंकड़े दिये गये हैं, जिससे पाठक आर्थिक क्रियाओं को भलीभांति समझ सकें। उदाहरण भी अधिकतर भारत या अन्य अल्प विकसित देशों से ही लिये गये हैं। इनसे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सारे परिवार के लिए

डी सी एम

के उच्च कोटि के कपड़े

पापलिन	छींटें	मलमल
लिनो	लान्स	लट्ठा
साड़ियाँ	शर्टिंग्ज	ड्रिल्स
शर्टिंग्ज	सजावट के कपड़े	तौलिए

एवं बेड शीट्स आदि

आकर्षक रंगों, शेडों और बनावटों में

डी सी एम के सभी रिटेल स्टोर्स में प्राप्य है ।

डी सी एम वस्त्रोत्पादन में श्रेष्ठता का प्रतीक

दि दिल्ली क्लॉथ एण्ड जनरल मिल्स कं० लि०

दिल्ली

JWT : DCM : 2290

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विषय को समझने में सहायता मिलती है।

'व्यवसायिक वितरण तथा उत्पादिता की समस्या' को भलीभांति समझने के लिये इस अध्याय के कलेवर को थोड़ा बढ़ाना अनिवार्य था। यही बात विशिष्टीकरण के मूल कारण और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में कही जा सकती है।

पुस्तक में लेखक ने विषय सामग्री को समझाने के लिये चित्र, सारिणियों तथा रेखाचित्रों का प्रयोग कर पुस्तक को लाभदायक बना दिया है। पुस्तक के अन्त में पारिभाषिक शब्दों की सूची छात्रों के लिये उपयोगी सिद्ध होगी।

भारतीय आयकर के सरल सिद्धान्त—लेखक : श्री रामनिवास लखोटिया; प्रकाशक—आशा पब्लिशिंग हाऊस, कलकत्ता; मूल्य रु. ४.८०।

पुस्तक का विषय नाम से स्पष्ट है। यह पुस्तक अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए लिखी गई है और हिन्दी में अपने विषय की अनूठी पुस्तक है। लेखक अपने विषय के अधिकारी विद्वान् हैं। लेखक की शैली सरल और सुबोध है। इससे न केवल अर्थशास्त्र और वाणिज्य के विद्यार्थी ही लाभ उठा सकते हैं, लेकिन साधारण व्यापारी और मध्यमवर्गीय कर्मचारी भी जिन्हें आयकर विभाग से काम पड़ता है, बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

भारत सरकार का आयकर अधिनियम बहुत जटिल है। प्रस्तुत पुस्तक में इस समस्त अधिनियम की अच्छी जानकारी दी गई है। १९६१ में आयकर में जो परिवर्तन किये गये हैं उनका भी समावेश कर देने से यह पुस्तक अधिक उपयोगी हो गई है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता वे प्रश्न हैं, जो व्यापारियों, दुकानदारों तथा अन्य मध्यम आय वालों के सामने आते हैं। सामान्य कर्मचारियों आदि के लिए भी ग्रेच्युटी आदि के प्रश्न भी उपस्थित होते हैं। इन सब प्रश्नों का विस्तृत रूप और उनका उत्तर इस पुस्तक की बहुत बड़ी विशेषता है। वेतन, मकान, किराया, भत्ता, सम्पत्ति की गणना, प्रोवीडेन्ट, फन्ड, बोनस आदि से सम्बद्ध सब प्रश्नों के उत्तर उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किये गए हैं। आयकर सम्बन्धी वकीलों के लिए भी यह पुस्तक बहुत उपयोगी होगी। कानून की पेचीदा बातें सरल ढंग से समझाने में लेखक को सचमुच सफलता प्राप्त हुई है। पुस्तक के अन्त में अनेक विश्वविद्यालयों में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर भी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहेंगे।

गोमाता वसुन्धरा—लेखक : डा० रामस्वरूप, प्रकाशक अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ, राजघाट वाराणसी; मूल्य २.५०।

प्रस्तुत पुस्तक का विषय नाम से स्पष्ट है। इसके लेखक गो विज्ञान के अच्छे पण्डित हैं। गो सेवा करने और गो विज्ञान के अध्ययन में उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया है। गाय का महत्व, गो दुग्ध, गो-मूत्र, गो-मय और खाद, गोपरिज्ञान और गोपालन इन पांच खण्डों में उन्होंने अपने विषय का परिपालन किया है।

भारतवर्ष की अधिकांश जनता गऊ को माता मानती है। प्राचीन और मध्यकाल में गऊ का कितना महत्व था और इस्लाम भी किस तरह गऊ हत्या का विरोध करता है, इसका विस्तृत परिचय देते हुए यह बताया गया है कि गाय का दूध भैंस के दूध की अपेक्षा अधिक लाभकारी है। यदि इस प्रकरण पर हम गम्भीरता से विचार करें तो सम्भवतः भारत सरकार को दुग्ध संवर्धन के सम्बन्ध में अपनी नीति बदलनी पड़ेगी। यह एक दुःखद सत्य है कि हम लोग दूध की मात्रा और चिकनाई के नाम पर आज गऊओं की अपेक्षा भैंसों को अधिक महत्व दे रहे हैं। सरकारी डेरियों में भी जो केवल गऊओं के विकास के लिए स्थापित की गई थी आज भैंसे रखी जाने लगी हैं। गो दुग्ध के लाभ और उपयोगिता पर लिखा हुआ प्रकरण तो बहुत अधिक उपयोगी है। वस्तुतः गो-दुग्ध और गऊ का मलमूत्र भी हमारे लिए अत्यन्त लाभकारी है, यह प्रकरण पठनीय है। गो दुग्ध और गऊ दूध और दही शारीरिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है। न केवल खाद की दृष्टि से किन्तु चिकित्सा दृष्टि से भी गोमूत्र अमूल्य माना जाता है।

आशा करनी चाहिए कि पंचायतों, सामुदायिक योजनाओं और विकास खण्डों के सब कार्यकर्त्ता इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे ताकि गो वंश की वृद्धि के साथ-साथ देश की समृद्धि भी बढ़े।

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भूदान गंगा—लेखक श्री विनोबा; प्रकाशक-वर्धा।

आचार्य विनोबा के भूदान सम्बन्धी यात्रा में दिये गये विभिन्न भाषणों और प्रवचनों का संग्रह भूदान गंगा के नाम से किया गया है। इसके पहले छः खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं, सातवें खण्ड में करनाटक, और केरल यात्रा में दिए हुए ४६ भाषणों का संकलन किया गया है। ये निबन्ध विभिन्न विषयों पर हैं जिन में सर्वोदय, साम्यवाद, शान्ति सेना, अहिंसा, हरिजन सेवा, ग्राम दान, आदि विषयों का समावेश है।

साहित्य सन्देश—(साहित्य शास्त्र विशेषांक)—सम्पादक श्री महेन्द्र, साहित्य रत्न भण्डार, आगरा द्वारा प्रकाशित। इस अंक का मूल्य १॥) रु०

बहुत वर्षों से श्री महेन्द्र साहित्य सन्देश के द्वारा साहित्य के विद्यार्थियों और मनीषियों के लिए विचारपूर्ण और सूचनात्मक सामग्री दे रहे हैं। इसके विशेषांक तो वस्तुतः अपने अपने विषय पर अध्ययन पूर्ण पुस्तक का काम देते हैं।

प्रस्तुत विशेषांक में साहित्य शास्त्र के स्वरूप, उद्देश्य तथा मूल दृष्टि आदि पर सविस्तृत विवेचन किया गया है। साहित्य का तात्पर्य क्या है? साध्य क्या है, साहित्य में काव्य, यथार्थ कल्पना आदि का क्या स्थान है और प्राचीन संस्कृत साहित्य की किन मर्यादाओं और परम्पराओं ने भारतीय साहित्य को—प्राचीन व अर्वाचीन साहित्य को क्या देन दी है आदि विषयों पर अध्ययन पूर्ण और सुन्दर लेख इस विशेषांक में आपको मिलेंगे। कुछ एक आलोचनात्मक लेख उपन्यास, नाटक और कहानी तथा निबन्ध आदि के सम्बन्ध आदि में भी साहित्य के विद्यार्थी को अच्छी जानकारी देते हैं। हमें आशा है कि साहित्य के प्रेमी और विद्यार्थी इस अंक से लाभ उठावेंगे।

किस ओर जा रहे हो? (मूल्य २.००) बे आस बोल, (१.००) बे आस की फागें, (१.००) और गरौठा के गढ़ी बन्द। (५० न० पै०)

उपर्युक्त पुस्तकें बे आस प्रकाशन गरौठा झांसी से प्रकाशित हुई हैं। इनके लेखक श्री कृष्णानन्द व्यास हैं। इनके पढ़ने से मालूम होता है, कि व्यास जी संसार की आस पास की घटनाओं को किस पैनी दृष्टि देखते से हैं और उन्हें अपनी मनोरंजक काव्य शैली में चित्रित करते हैं। ग्राम्य वातावरण के चित्रण करने आप में अपनी प्रतिभा का प्रकट करते हैं। बहुत सी कविताओं से इनकी हास्यप्रियता और हास्यरस पर इनका अधिकार प्रकट होता है। इन कविताओं में वर्तमान समय के शासन और वर्तमान सामाजिक परम्पराएं तथा समाज में प्रतिष्ठित समझे जाने वाले नेताओं, सम्पन्नों और साहित्यकारों के दम्भ, छलकेपन और प्रदर्शनात्मक प्रवृत्तियों पर अच्छे चुटीले रंग किए गये हैं। यदि जनपद साहित्य का विकास करना हो तो व्यास जी सफल कवि हो सकते हैं। गरौठा के गढ़ी बन्ध तो बुन्देलों का खण्ड काव्य है जो सत्य के अधिक निकट है। ऐसी पुस्तकें ग्राम साहित्य में अच्छा स्थान पा सकती हैं और प्राचीन कवि परम्परा को एक सीमा तक बढ़ाती हैं। इन पुस्तकों का मूल्य कुछ अधिक दीखता है, जो सामान्य जनता में प्रचार की दृष्टि से सम्भवतः एक बाधा होगी। हम कवि के प्रयत्नों की सफलता चाहते हैं।

सबसे सस्ता सचित्र हिन्दी मासिक

जागृति

जिसे भारत के सभी प्रमुख कवियों,
और कहानीकारों का सहयोग प्राप्त है।
उत्प्रेरक कविताएं, ज्ञानवर्धक लेख, सांस्कृतिक निबंध,
रोचक कहानियां, बाल संसार, साहित्य आगे
बढ़ता है आदि स्तम्भ
तिरंगा आवरण, अनेकों इकरंगे चित्र
४८ से ५६ पृष्ठ को सम्पूर्ण छपाई आर्ट पेपर पर
इस पर भी मूल्य केवल २५ नये पैसे
एजेंटों को ५ से १० प्रतियों पर २५ प्रतिशत और इससे ज्यादा पर ३३⅓ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। डाक खर्च प्रकाशकों के जिम्मे। एजेन्ट नमूने की प्रति के लिए आज ही लिखें।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वित्तीय सहायता

औद्योगिक वित्त-निगम (इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन) द्वारा स्वीकृत ऋण और पेशगी ।

(३० जून १९६२ तक)

उद्योग का स्वरूप	स्वीकृत राशि (करोड़ रु०)	कुल ऋण व पेशगियों का प्रतिशत
१. चीनी उद्योग	३७.०९	२९.०१
२. रासायनिक	१७.३५	१३.३२
३. सूती कपड़े	१३.७०	१०.५२
४. कागज उद्योग	१३.३९	१०.२८
५. सीमेंट	७.६२	५.८५
६. बिजली का इंजिनीयरिंग सामान	५.६५	४.३४
७. किरेमिक्स और शीशा	५.४२	४.१६
८. रेयन उद्योग	४.८०	३.६८
९. मेकेनिकल इंजिनीयरिंग	४.८०	३.६८
१०. लोहा और इस्पात (हल्की इंजिनीयरिंग)	४.४७	३.४३
११. होटल उद्योग	१.८९	१.४५
१२. आटोमोबाइल और ट्रेक्टर उद्योग	१.८८	१.४४
१३. धातु सम्बन्धी उद्योग (अलौह-धातुएं)	१.५२	१.१७
१४. एलूमिनियम	१.६०	१.२३
१५. प्लाई वुड	१.११	०.८५
योग (अन्यों को शामिल करके)	१३०.२७	१००.००

भारत के प्रमुख निर्यात (करोड़ रु. में)

	१९६०-६१	१९६१-६२
खनिज पदार्थ		
आयरन ओर	१६.७८	१७.४५
मैंगनीज ओर	१४.०३	१०.४२
लोहा व इस्पात	५.५७	६.२०
कोल व कोक	३.३४	२.४२
फैरो-मैंगनीज़	४.२२	५.०२
कपड़े		
सूती कपड़ा	५७.६५	४८.३९
जूट का सामान	१३२.८८	१४४.७८
पेय व खाद्य		
चाय	१२३.५९	१२२.४०
काफी	७.२२	९.०१
तम्बाखू कच्चा	१४.६७	१४.०३
तम्बाखू तैयार	१.१३	०.९१
काली मिर्च	८.४५	८.११
काजू	१८.९१	१८.१७
चीनी	२.५०	१४.५५
तेल, घी आदि		
अलसी का तेल	०.८८	०.१४
मूंगफली का तेल	०.२१	१.०३
कैस्टर आयल	६.७१	३.९९
वनस्पति घी	१.०४	०.५१
खलि आदि	१४.३०	१७.३२
विविध		
कपास	८.६६	१४.३३
काटन मिल वेस्ट	२.८९	५.९१
ऊन व बाल	७.७३	९.२०
खालें	१०.०२	८.८३
चमड़ा	२४.८४	२५.४५
लाख	६.३१	४.६२
कुल निर्यात अन्य भी मिलाकर	६३२.४२	६५६.८१

भारत के मुख्य आयात (करोड़ों रु० में)

पदार्थ	१९६०-६१	१९६१-६२
खनिज तेल	६९.१९	९४.३८
अनाज व आटा	१४४.७४	९६.६६
रासायनिक खाद	१३.१९	१४.६१
कपास	८१.७७	६२.६१
अखबारी कागज	५.९५	९.७
रबर	१०.७८	१०.१
कास्टिक सोडा	१.९९	१.७
सोडा खारी	१.८०	६७.४
ऊन	१०.४१	१२.१
रासायनिक पदार्थ	३९.३४	३५.१
रंग आदि	१२.९१	१४.४
औषधियां	१०.५०	११.१
विस्फोटक पदार्थ	११.७३	१४.७
कपड़े	१७.६९	१५.९
आधारभूत धातुएं	१६९.८५	१५१.२
धातु निर्मित पदार्थ	२३४.१६	२१३.१
मशीनरी	२५७.५९	२९४.७
परिवहन साधन	७२.३९	५४.२
कुल आयात अन्य भी मिलाकर	११२१.६२	१०३८.६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुस्तकालय
गुरुकुल काँगड़ी

अर्थ वृत्त चयन

उत्तरी ध्रुव आबाद होगा

उत्तरी ध्रुव इस भूमंडल का सर्वाधिक शीत प्रदेश हैं। यहां मानव किसी प्रकार नहीं रह सकता। यहां, संभवतः, कोई पशु पक्षी भी नहीं है, पर अब सोवियत रूस के वैज्ञानिकों ने ऐसी योजना बनायी है कि इस भूखंड पर भी आबादी हो जाएगी और करोड़ों एकड़ बंजर भूमि खेती-बाड़ी और पशुपालन के योग्य हो जाएगी। निश्चय ही इस से विश्व की जलवायु में आमूल परिवर्तन आ जाएगा। इस योजना का संक्षिप्त रूप इस प्रकार है :—

साइबेरिया और अलास्का को अलग करने वाली बेरिंग की खाड़ी पर एक बहुत बड़ा बांध बनाया जाएगा। अणुशक्ति द्वारा प्रशांत सागर के जल को पम्प द्वारा गरम करके करोड़ों गैलन की मात्रा में आर्कटिक सागर में डाला जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि उत्तरी ध्रुव के बर्फीले प्रदेश की ओर गरम जल बहने लगेगा और वायुमंडल को प्रभावित करेगा। साइबेरिया और कनाडा के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र का अधिक ठंडा और कठोर जलवायु समशीतोष्ण हो जाएगा। परिणाम स्वरूप, प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग में बर्फीले ठंडे जल का प्रवाह नहीं होगा, बर्फ की चट्टानें उसमें तैरेंगी नहीं और एशिया—अमेरिका के बीच जहाजों का आवागमन बिना बाधा के हो सकेगा। इसका एक परिणाम यह भी होगा कि ओरवोटस्क सागर में भी जहाज बेखटके आ-जा सकेंगे। आर्कटिक वृत्त की जलवायु में भी बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि विश्व के जलवायु पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है।

बेरिंग की खाड़ी पर बांध बनाने की योजना रूस की नयी नहीं है। सबसे पहले सन १९२१ में सोवियत रूस में इस पर विचार किया गया था और लेनिन ने अपने इंजिनीयरों को बांध व पुल के नक्शे बनाने का आदेश दिया था। योजना के अनुसार, इस प्रदेश में बिजली की रेल गाड़ियां भी चलायी जाएंगी। इसके पूर्ण होने पर लंदन से पेरिस, मास्को, एंकरेज और वाशिंगटन होते हुए मियासी तक की लम्बी सीधी यात्रा हो सकेगी।

बेरिंग की खाड़ी पर बनने वाले पुल के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बहुत विशाल होगा और इसके आर-पार की चौड़ाई ३६,५९७,१५८ वर्गफुट होगी। यह खाड़ी अधिकांश स्थानों पर १५० फुट गहरी हैं। खाड़ी के सबसे कम दूरी के स्थान पर बनाया गया पुल ५५ फुट लम्बा होगा। अणुशक्ति से संचालित पम्प की पानी गरम करने की शक्ति इतनी अधिक होगी जितनी विश्व के उपलब्ध तेल-स्रोतों से भी पैदा नहीं की जा सकती। यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के समुद्री किनारों का बहुत बड़ा भाग आर्कटिक सागर की ओर पड़ता है और इन समुद्री किनारों की लम्बाई भी बहुत ज्यादा है। इन सभी महाद्वीपों के उत्तरी भाग पर आर्कटिक क्षेत्र के बर्फीले अंधड़ों का अधिक कुप्रभाव पड़ता है। इस योजना से यहां के जलवायु पर काफी प्रभाव पड़ेगा।

इस योजना के राजनीतिक प्रभाव क्या होंगे और इस भीमकाय योजना का संचालन कौन करेगा—इन प्रश्नों का उत्तर देना अभी कठिन है।

सोवियत रूस की वित्त व्यवस्था में परिवर्तन

राष्ट्र की श्रमशक्ति पर कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण को ढीला किये बिना सोवियतसंघ अपने औद्योगिक और कृषि उत्पादनों में वृद्धि के तरीकों में परिवर्तन करने पर विचार कर रहा है। पिछले ४५ वर्षों में जिन सिद्धान्तों के पालन से अभी तक पर्याप्त लाभ नहीं हुआ, उनमें फेरबदल किया जाने वाला है। सोवियत रूस की समूची वित्त व्यवस्था को, प्रधानमन्त्री श्री ख्रुश्चेव के पार्टी की बैठक में दिये गये ५॥ घंटे के लम्बे भाषण के अनुसार, दो मुख्य भागों में बांटा जाएगा—उद्योग और कृषि। प्रत्येक के साथ कार्य संचालक और राजनीतिक समितियां सम्बद्ध रहेंगी जो निरीक्षण का काम करेंगी। श्री ख्रुश्चेव के ३० हजार शब्दों के भाषण से पता चलता है कि इन दोनों विभागों में १९१७ से काफी बरबादी, अव्यवस्था और लापरवाही पायी गयी है। प्रो० वाई० जी० लिबरमन की इस योजना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि कारखाने में बोनस कमाये गये लाभ पर हो, न कि अन्धाधुन्ध उत्पादन की राशियों पर। ऐसा समझा जाता है कि पुराने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ढंग का एकमात्र परिणाम यह होता है कि कारखानों को उत्पादन के न्यून लक्ष्य स्थिर करने का प्रोत्साहन मिलता है। यह भी अब मान लिया गया है कि एक मजदूर, विशेषतः कृषि में, उस समय अधिक उत्पादन करता है जब उसे अपने श्रम से व्यक्तिगत लाभ होता है। कम्युनिस्टों की यह धारणा कि व्यक्तिगत लाभ की भावना को छोड़ देने से और "राज्य ही स्वामी है"—इस लक्ष्य के अन्तर्गत श्रमिक अधिक काम करता है, असत्य सिद्ध हुई है। साथ ही पुरानी पद्धति के अन्तर्गत नौकरशाही का जो विशाल जाल बिछ गया है, उसकी प्रवृत्ति बरबादी और अव्यवस्था की ओर अधिक होती जाती है। ६० वर्षीय सोवियत फार्म महिला श्रीमती नदेझदा जागलादा ने कम्युनिस्ट क्षेत्रों में यह कहकर सनसनी पैदा करदी हैं कि सामूहिक खेती का सारा स्वरूप अशुद्ध है क्योंकि इसके अन्तर्गत किसान बिल्कुल मेहनत से काम नहीं करता। उसे लाभ की प्रेरणा नहीं मिलती और वह अपने परम्परागत इस अभिमान से वंचित हो जाता है कि "मैं अपनी खुद की जमीन पर हल चलाता हूँ और अपने मवेशियों को पालता हूँ।"

चीन में कृषि उत्पादन

१९५८ के अन्त में, पीकिंग ने यह घोषणा करके सारे एशिया को चकित कर दिया कि खेती के नये तरीकों के कारण चीन में रिकार्ड-तोड़ पैदावार हुई है। उसका दावा था कि उस वर्ष चीन में ३७ करोड़ ५० लाख टन अनाज पैदा हुआ, जो चीन की १९५७ की पैदावार से दुगना था। इतना ही नहीं १९५९ में चीन ने पैदावार का लक्ष्य ५२ करोड़ ५० लाख टन घोषित किया।

उस समय तो लोग इन लम्बी चौड़ी डींगों से अवाक् रह गये, परन्तु अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि माओ-त्से-तुंग और उनके गुट के ये दावे बिल्कुल हवाई थे। ६ महीने में ही असलियत खुल गई। अगस्त १९५९ में, चीन सरकार को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी और यह कबूल करना पड़ा कि, "पहले जो आंकड़े घोषित किए गए थे, वे झूठे थे।"

वास्तव में उस साल केवल २५ करोड़ टन अनाज हुआ था; यानी, गलती पूरे १५ करोड़ टन की थी।

इसके साथ ही १९५९ की पैदावार का लक्ष्य भी ५२ करोड़ ५० लाख टन से घटाकर २७ करोड़ टन कर दिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश यह लक्ष्य भी पूरा न हो पाया।

१९६० और १९६१ की फसल के बारे में पीकिंग ने चुप्पी साध ली है। उसने इनके कोई भी आंकड़े प्रकाशित नहीं किए हैं, परन्तु विशेषज्ञों का अनुमान है कि चीन में १९६० में केवल १६ करोड़ टन और १९६१ में १७ से १९ करोड़ टन ही अनाज पैदा हुआ। फलतः अब कम्युनिस्ट चीन अपनी जनता को कंद-मूल खाने का उपदेश दे रहा है।

जीवन साहित्य

हिन्दी के उन मासिक पत्रों में से है, जो—

१. लोकरुचि को नीचे नहीं, ऊपर ले जाते हैं,

२. मानव को मानव से लड़ाते नहीं, मिलाते हैं,

३. आर्थिक लाभ के आगे झुकते नहीं, सेवा के कठोर पथ पर चलते हैं।

जीवन साहित्य की सात्विक सामग्री को छोटे-बड़े स्त्री-बच्चे सब निःसंकोच पढ़ सकते हैं। उसके विशेषांक एक से एक बढ़कर होते हैं।

वार्षिक शुल्क ४ रु. भेजकर ग्राहक बन जाइये।

ग्राहक बनने पर मंडल की पुस्तकों पर आपको कमीशन पाने की भी सुविधा हो जायगी।

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तीसरी योजना का प्रथम वर्ष

श्री गुलजारीलाल नन्दा

१९६१-६२ में योजना पर १,१४८ करोड़ रु० व्यय हुआ, जबकि १९६०-६१ में १,०७१ करोड़ रु० और १९५९-६० में १,०११ करोड़ रु० हुए। यहां सामाजिक सेवाओं आदि के लिए योजना के बाहर की रकमों को साथ मिलाकर १९६१-६२ में विकास योजनाओं पर गत वर्ष की अपेक्षा २१७ करोड़ रु० की वृद्धि हुई। योजना काल के १९६२-६३ वर्ष के लिए होने वाले व्यय की राशि ३०० करोड़ रु० निर्धारित की गयी है। १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में योजना के व्यय का विभाजन निम्न प्रकार है—

(करोड़ रु० में)

	१९६१-६२	१९६२-६३
कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता	१५१	१९२
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	९८	१२५
बिजली	१३१	१६५
उद्योग	२४९	३३३
परिवहन तथा संचार	३०२	३४९
सामाजिक सेवाएं	२०३	२५७
विविध	१४	२५
योग	१,१४८	१,४४६

उत्पादन में वृद्धि

१९६१-६२ में औद्योगिक उत्पादन लगभग ५ प्रतिशत बढ़ा। सूती वस्त्र, जूट तथा चीनी उद्योगों के अतिरिक्त, १९६१-६२ में औद्योगिक उत्पादन में लगभग ८ प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुछ मूलभूत उद्योगों में हुई प्रगति का विवरण नीचे दिया जा रहा है—

	१९६०-६१	१९६१-६२	१९६२-६३
तैयार इस्पात (दस लाख टनों में)	२.४	२.९	३.९
एलुमिनियम (,००० टन)	१८.२	१९.४	३८.०
नाइट्रोजिनियम उर्वरक (,००० टन) नाइट्रोजन की मात्रा में	९७.१	१४०.०	२००.०
फास्फेटिक उर्वरक (,००० टन)	५३.०	६१.९	९०.०
गंधक का तेजाब (,००० टन कलेंडर वर्ष)	३५३.९	४२३.०	५२३,०
मशीनी औजार (मूल्य करोड़ रु० में, कलेंडर वर्ष)	७.२४	८.५०	१०.५०
सीमेंट (दस लाख टनों में)	७.८	८.२	९.५
कागज और गत्ता (दस लाख टनों में)	३४३.०	३६२.८	४००.०
कच्चा लोहा (दस लाख टनों में)	१०.७	१२.१	१३.५
कोयला (दस लाख मेट्रिक टनों में)	५५.५	५५.२	६२.०

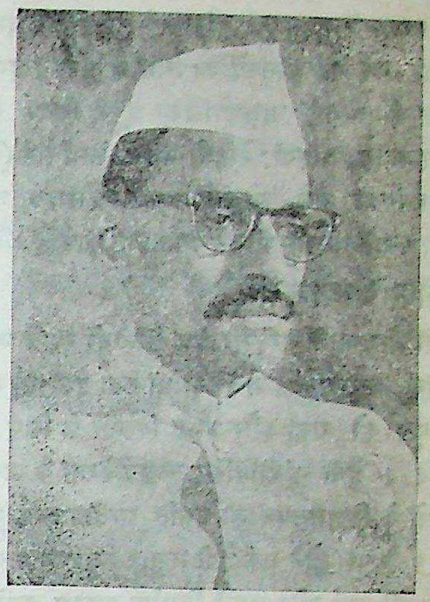

योजना मंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस वर्ष कई महत्वपूर्ण उद्योगों, विशेषतया एलुमुनियम, औद्योगिक मशीनरी, मशीनी औजार, बिजली का सामान, उर्वरक, भारी रसायन और सीमेंट उद्योगों की प्रस्थापित क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इस वर्ष देश में पहली बार कई-नई वस्तुओं का निर्माण हुआ। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं हाइड्रोलिक प्रेस, गियर कटिंग मशीन, टाइमपीस, घड़ियां, रेडियो वाल्व, कम्प्रेसर (सील्ड युनिट). आरगन गैस, पोलीविन्यल क्लोराईड, ब्युटल अल्कोहल, प्लास्टिसिसर और रेयन टायर कार्ड हैं।

औद्योगिक प्रायोजनाएं

दूसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में तीनों स्पात प्लान्टों का निर्माण प्रारम्भ किया गया था तथा इस वर्ष उनका निर्माण पूरा हो गया और उनके विस्तार के लिए कदम उठाये गये। हैवी इंजीनिरिंग कारपोरेशन के अन्तर्गत प्रायोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति सन्तोषजनक रही। १९६१-६२ के पूरा होने तक हैवी मशीन बिल्डिंग प्रायोजना में काफी प्रगति हुई और उसमें निर्माण प्रारम्भ करने की स्थिति आ गई। फाउंड्री फोर्ज प्रायोजना तथा कोयला खनन मशीनरी प्रायोजनाओं में भी सन्तोषजनक प्रगति हुई। इस वर्ष बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने का विस्तार कार्य भी पूरा हो गया। चंडीगढ़ में दूसरे मशीन टूल्स कारखाने के लिये स्थान चुना गया तथा उसके संयंत्र और साज सामान की खरीद के लिए आर्डर दिए गये। हैवी इलैक्ट्रिकल्स प्रायोजना, भोपाल ने जिसमें जुलाई १९६० में उत्पादन आरम्भ हो गया था, कई नई वस्तुओं का उत्पादन शुरू किया और अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाई। रुरकेला उर्वरक प्लान्ट के निर्माण कार्य में काफी अधिक प्रगति हुई।

नेवेली उर्वरक प्लान्ट के निर्माण कार्य की प्रगति सन्तोषजनक रही। ट्राम्बे उर्वरक प्लांट के प्रारम्भिक कार्य का काफी भाग पूरा किया गया और संयंत्र तथा अन्य साज-सामान सम्बन्धी खरीद के लिए आर्डर दिए गये। एफ० ए० सी० टी० के विस्तार की दूसरी अवस्था का कार्य भी लगभग पूरा किया गया। नहरकटिया उर्वरक कारखाने के लिए स्थान प्राप्त किया गया और मुख्य संयंत्र के लिए ठेके दिए गये।

निजी क्षेत्र में उत्पादन-वृद्धि

इस वर्ष निजी क्षेत्र में भी अच्छा विकास हुआ। अनेक उद्योगों की पूरी निर्धारित क्षमता के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गये। औद्योगिक लाइसेंस के प्रार्थना-पत्र १९६० में ३४६७ से बढ़कर १९६१ में ४,०१२ प्राप्त हुए। उन प्रायोजनाओं को जिनसे विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती थी, लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी गई। कागज तथा लुगदी, रासायनिक पदार्थ, सूती कपड़ों के अतिरिक्त अन्य वस्त्र, मोटरगाड़ियों तथा इंजीनियरिंग उद्योगों को अधिक से अधिक पूंजीगत सामान मंगाने के लिए आयात लाइसेंस दिए गये। १९६१-६२ में डिजाइन तथा फेब्रिकेशन की दिशा में उल्लेखनीय विकास हुआ।

१९६१-६२ में ५५२ लाख टन कोयले का उत्पादन हुआ जबकि गत वर्ष ५५५ लाख टन था। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का उत्पादन गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष भी कई कारणों से न बढ़ सका। यद्यपि कोयले का उत्पादन कम हुआ परन्तु क्रियात्मक रूप से कोयले की सप्लाई ३० लाख टन से भी अधिक थी।

यातायात

रेलवे की सुविधाओं के विस्तार, विशेषकर कोयले की गति को तेज करने के लिए १२० करोड़ रु० का अतिरिक्त व्यय स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त माल के यातायात में अधिक तेजी लाने के लिए २५ करोड़ रु० और स्वीकार किया गया जो चौथी योजना के प्रारम्भ में कोयले को गतिशील बनाने में प्रयुक्त हो सकेगा।

१९६१-६२ में मालगाड़ी के डिब्बों का उत्पादन गत वर्ष ११,९८४ से बढ़कर १९,११५ हो गया। करीब ४२२ मील रेल लाईन दोहरी की गई और ३२७ मील मार्ग का विद्युतीकरण किया गया। १९६१-६२ में ७० मील लम्बाई के गुमशुदा सड़क के टुकड़ों और ५ बड़े पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया गया और ३०० मील के राष्ट्रीय मार्गों का सुधार किया गया।

बिजली कार्यक्रम

१९६०-६१, १९६१-६२ और १९६२-६३ के विद्युत उत्पादन और विद्युतीकरण का ब्योरा निम्न प्रकार है—

	१९६०-६१	१९६१-६२	१९६२-६३
संस्थापित उत्पादन शक्ति (मिलियन वाट)	५,५९५	६,१७४	६,८८१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विद्युत उत्पादन (दस लाख किलोवाट घंटे)	२०,०४०	२२,६००	२५,५००
अतिरिक्त कस्बों और नांवों का विद्युतीकरण	१,६००	३,१००	३,५००

तीसरी योजना की बहुत सी बिजली की प्रायोजनाओं के लिए अब विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध कर लिया गया है।

कृषि उत्पादन

१९६०-६१ की तुलना में १९६१-६२ में मौसमी हालात सामान्य स्तर से नीचे रहे। १९६०-६१ के उत्पादन तथा १९६१-६२ की आनुमानिक फसलों का ब्योरा निम्न तालिका में दिया जा रहा है।

फसल	१९६०-६१	१९६१-६२
गेहूँ (लाख टन)	१०८	११६
जौ ,,	२८	३१
चावल ,,	३३७	३३६
ज्वार ,,	९२	७७
बाजरा ,,	३२	३५
मक्का ,,	३९	४०
तिलहन ,,	६५	६८
गन्ना ,,	१०४	९७
कपास (लाख गांठें)	५४	४५
जूट ,,	४०	६३
मेस्ता ,,	११	१७

बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं से खेती योग्य जमीन १९६०-६१ में १२२.४ लाख एकड़ से बढ़कर १९६१-६२ में १३७.५ लाख एकड़ हो गई। १९६२-६२ का लक्ष्य १६० लाख एकड़ रखा गया है। छोटी सिंचाई योजनाओं से खेती योग्य जमीन का अतिरिक्त क्षेत्रफल १६.७ लाख एकड़ था और १९६२-६३ का लक्ष्य २० लाख एकड़ से भी अधिक है।

शिक्षा में प्रगति

शिक्षा में प्रगति का विवरण निम्न प्रकार है—

	१९६०-६१	१९६१-६२	१९६२-६३
प्राइमरी स्कूलों में छात्र (लाख)	३४३	३७८	४१५
मिडिल स्कूलों में छात्र ,,	६३	६९	७६
सेकैंडरी स्कूलों में छात्र ,,	२८	३१	३४

रोजगार की स्थिति

१९६१-६२ में रोजगार के अतिरिक्त अवसर २० लाख तक बढ़ने का अनुमान है और १९६२-६३ में इनके २४ लाख तक बढ़ने की आशा है।

१९६२ में भी योजना के सभी क्षेत्रों में उन्नति हो रही है। अक्तूबर में चीनी आक्रमण से स्थिति कुछ बदल गई है, कुछ साधारण कार्यक्रम शिथिल कर दिये गये हैं, तथापि औद्योगिक उत्पादन पर अधिक बल दिया जाने लगा है। युद्ध की चुनौती को तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य पूर्ण करने के दृढ़ संकल्प के साथ स्वीकार कर लिया गया है।

इस्पात उद्योग की प्रगति तथा भविष्य

प्रतिरक्षा मंत्रालय की विशेष इस्पात आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने दुर्गापुर में ५० हजार टन की क्षमता के बनाए जाने वाले इस्पात कारखाने को निर्धारित समय से १ वर्ष पूर्व ही समाप्त कर देने के लिए एक द्रुत कार्यक्रम अपनाया है।

केन्द्रीय इस्पात तथा भारी उद्योग मंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने एक पत्रकार सम्मेलन में उक्त कार्यक्रम के सम्बन्ध में घोषणा करते हुए बताया कि जापान, ब्रिटेन और फ्रांस ने रैंडर्स भेजे हैं।

सरकार को ऐसी आशा है कि छांटे गए रैंडर्स उस सारी विदेश मुद्रा की व्यवस्था कराने में सहायता दे सकेंगे, जो कि इस योजना के लिए चाहिए।

भद्रावती (मैसूर राज्य) में ८० हजार टन की क्षमता वाले लोहे और इस्पात का जो कारखाना है, उसको नया रूप देने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। सम्भावना यह है कि यह कार्य आगामी वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही समाप्त हो जाएगा। इस योजना में पश्चिमी जर्मनी तथा आस्ट्रेलिया की फर्म सहयोग प्रदान कर रही है।

१९६२-६३ के लिए बिक्री हेतु ४० लाख टन इस्पात का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वह केवल पूरा नहीं हो जाएगा, बल्कि यदि सभी सरकारी और निजी कारखानों

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ने अपनी शत प्रतिशत क्षमता के साथ उत्पादन किया तो लक्ष्य से भी ४ लाख टन अधिक उत्पादन हो जाएगा।

भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर स्थित तीनों सरकारी इस्पात कारखानों के सम्बन्ध में जो विस्तृत कार्यक्रम अपनाया गया है, वह तीसरी योजना की समाप्ति से पूर्व ही पूरा कर लिया जायगा।

रांची में सोवियत संघ के सहयोग से ८० हजार टन की क्षमता का जो भारी मशीनों वाला संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, उसका निर्माण कार्यक्रम से पहले चल रहा है। इसमें आंशिक रूप से उत्पादन कार्य आगामी वर्ष के मध्य से आरम्भ हो जाएगा, तथा पूर्ण उत्पादन सन् १९६७-६८ तक प्रारम्भ हो जाएगा, जबकि वह १० लाख टन क्षमता वाले इस्पात संयंत्र के लिए पूरा सामान बनाना शुरू कर देगा और इस प्रकार देश को लगभग १०० करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकेगी।

तीनों सरकारी कारखानों में बिक्री योग्य इस्पात का मासिक उत्पादन जनवरी १९६२ में १ लाख ९ हजार टन से अक्तूबर में १ लाख ५२ हजार टन तक पहुँच गया था। निजी क्षेत्र में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में उत्पादन जनवरी में १ लाख १६ हजार टन था जबकि अक्तूबर में वह १ लाख २५ हजार टन हो गया।

सरकार ने कोयला खनन मशीन के निर्माण के लिए पोलैण्ड के सहयोग से एक दूसरा संयंत्र स्थापित करने का निश्चय किया था परन्तु अभी इस संयंत्र के स्थान के सम्बन्ध में निर्णय किया जाना है। कोयला खनन सम्बन्धी मशीनों का पहला कारखाना दुर्गापुर में सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। ३५ करोड़ रुपयों की लागत से बनाए जाने वाला यह कारखाना, जिसकी उत्पादन क्षमता ४५ हजार टन की होगी, आंशिक रूप से उत्पादन आगामी वर्ष के मध्य से प्रारम्भ कर देगा तथा पूर्ण उत्पादन सन् १९६५-६६ तक, जबकि वह वार्षिक रूप से ८ करोड़ रुपयों के मूल्य का सामान बनाना शुरू कर देगा। ●

अत्यन्त शुभकामनाओं के साथ

दि न्यू ग्रेट ईस्टर्न स्पि. एंड वीविंग कम्पनी लिमिटेड

१५ ए, हार्निमन सरकल
फोर्ट बम्बई-१

निर्माता

सूती कपड़े और सूती तथा स्टेपल फाइबर सूत के रँगीन और ब्लीच किये कपड़े, लांग क्लाथ माजरी, शीटिंग, रँगीन पापलिन, रंगीन इटालियन, ब्लीच्ड मरसिराइज्ड लेनो :

तार का पता—"न्यूग्रेट" टेलि. नं. २५१२१८

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चीनी आक्रमण और शराब

डा० युद्धवीर सिंह

चीनी आक्रमण पर जब लोकसभा में बहस हो रही थी, तो कुछ संसद-सदस्यों ने दो अद्भुत सुझाव दिये—१. मद्यनिषेध बन्द कर दिया जाय! २. नमक पर कर लगा दिया जाय!

और ये सुझाव तब दिये गये, जबकि पं० जवाहरलाल नेहरू की अपील पर रुपया और सोना रोज बरस रहा है! छोटा-बड़ा, बच्चा-बूढ़ा, स्त्री-पुरुष, हिन्दू-मुसलमान, कांग्रेसी-गैरकांग्रेसी, सब तन-मन-धन देश को अर्पण कर रहे हैं। लोग चन्दा दे रहे हैं—हर महीने देने का वचन दे रहे हैं, लगन से और खुशी से दे रहे हैं।

उस दिन दिल्ली के स्टेशन पर रोटियां बचने वाली एक विधवा वृद्धा के अनुरोध पर उसे मैं पंडितजी के यहां लेकर गया। मैं हैरान रह गया, जब उस फटी धोती पहनने वाली गरीब बुढ़िया ने १४० रु. प्रधानमंत्री को भेंट किये। शायद वह बुढ़िया उमर भर में भी इतना नमक न खायेगी, जिसका कर १४० रु. हो। इस रुपये के साथ जो आशीर्वाद और शुभकामना है, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है? धनी लाखों दे रहे हैं और गरीब अपना सर्वस्व दे रहे हैं। उस दिन मुनीरका गांव के भूतपूर्व नम्बरदार ने ११०० रु. मुझे रक्षा-कोष के लिए दिये, मैं हैरान रह गया, जब उन्होंने कहा कि यह रुपया केवल उनकी उम्र भर की कमाई है!!

इतिहास में शायद यह पहला अवसर है, जब सारा भारतवर्ष एक बाहरी शत्रु के विरुद्ध लड़ रहा है। फौजें नहीं, देश का बच्चा-बच्चा युद्ध में शामिल है। इस समय हमें बहुत ही सोच-विचार कर, पूरे विचार-विमर्श के बाद बात मुँह से निकालनी चाहिए। हमें न तो जोश में होश खोने चाहिए और न जोश को ठंडा पड़ने देना चाहिए। इस समय होश कायम रखने का वक्त है, न कि शराब पीकर या पिला कर होश खोने का। यह तो ऐसा अवसर था, जब कि यह अपील की जाती कि देश के शराबी शराब पीना छोड़ दें और वह धन जो शराब पीने से बचे, रक्षा-कोष में दें। आबकारी, अर्थात् शराब पर जो कर लिया जाता है, वह शराब के मूल्य से लगभग चौथाई हिस्सा होता है। आज चौथाई नहीं बल्कि समस्त रुपया हमें चाहिए। ४०-५० करोड़ रु० की आबकारी की आमदनी को छोड़कर २०० करोड़ शराब की कीमत हमें चाहिए। क्या आज यह अवसर है कि हम देशवासियों से यह कहें कि शराब पीओ, पर हमें रुपये में चवन्नी दे दो? चवन्नी के लिए न केवल हम १ रु. खोयेंगे, बल्कि पीने वाले का होश भी खो देंगे!

गुड़गांव के एक सज्जन ने यह प्रतिज्ञा की कि वे सिगरेट पीना बन्द करते हैं और जो रुपया उससे बचेगा, वह प्रतिमास रक्षाकोष में देते रहेंगे। आज इसी प्रकार की प्रतिज्ञाएं हमारे शराब व तम्बाकू पीने वाले भाइयों से करवानी चाहिए। थोड़े-से रुपये के लोभ में शराब पीने को बढ़ावा देकर अपने देशवासियों को स्वास्थ्य, धन व आचार तीनों की बरबादी करने देना कहां तक ठीक है।

अभी तो गांधीजी के साथी और उनके नेतृत्व में स्वतंत्रता-संग्राम में भाग लेने वाले लोग जिन्दा हैं और भारत तथा राज्य-सरकारों में अच्छे पद पर आरूढ़ हैं। नमक-कर और शराब के कर, दोनों को ही हटाना गांधी जी की दो मुख्य कामनाएँ थीं। नमक-कर उनके जीवन में ही स्वराज्य-सरकार ने हटा दिया था। शराब-कर महाराष्ट्र, मद्रास, गुजरात ने सम्पूर्ण तथा अन्य राज्यों ने आंशिक रूप में नशाबन्दी करके खतम कर दिया था। भारत के लिए वह दिन बदनसीब व बदकिस्मती का होगा, जब वह इन दोनों में कुछ फेर-बदल कर राष्ट्रपिता की छाती में छुरा घोंपेगा।

● ०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दूध और पशु पालन

(पृष्ठ १९ का शेष)

उद्योग के लिए तीनों योजनाओं में केवल १.१ प्रतिशत राशि रखी गयी है जबकि राष्ट्रीय आय में इस मद से ६.९ प्रतिशत की आय होती है। पहली दो योजनाओं में यद्यपि पशु पालन के लिए ७८ करोड़ रु० रखा गया था, पर खर्च केवल ४९ करोड़ रु० हुआ। अनुत्पादक पशुओं के लिए पहली और दूसरी योजनाओं में क्रमशः १६० और ६० गोसदन खोलने का लक्ष्य था जिससे ३,२०,००० मवेशियों की देखभाल हो सके पर वस्तुतः दोनों योजनाओं में क्रमशः २२ और ३४ ही गोसदन खोले जा सके। पहली योजना में कुछ लक्ष्य पूर्ति हुई पर दूसरी योजना में कुछ विशेष उन्नति नहीं हुई। अभी तो इस समस्या के एक अंश को भी हम छू नहीं सके हैं। मवेशियों की कुल आबादी १७ करोड़ ६० लाख है जिसमें ३३ प्रतिशत बेकार हैं, करीब ५ करोड़ ८० लाख को हटाना है। हमारी योजनाओं में कृषि, उद्योग, खनिज, बिजली इत्यादि के बारे में लक्ष्य स्थिर किये गये हैं पर पशु-पालन उत्पादन के सम्बन्ध में कोई लक्ष्य स्थिर नहीं किये गये हैं। पहले पशु-पालन उद्योग का विकास हो, फिर दुग्ध केन्द्रों की संख्या बढ़ सकती है। देहाती वित्त व्यवस्था में दुग्ध उत्पादन का विशेष स्थान है। विदेश से आयातित दूध जहां एक ओर महंगा होता है, वहां वह ताजा न होने से कम लाभदायक भी हो जाता है।

प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध

यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश अधिकांश शाकाहारी है और हमारे दैनिक भोजन में दूध का अनुपशेणीय स्थान है। सन्तुलित भोजन में प्रति व्यक्ति प्रति दिन २० औंस दूध चाहिए और पर, दूध की कमी देखते हुए, हमारे देश के लिए राष्ट्रीय योजना समिति ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन १६ औंस दूध निश्चित किया है जबकि, वस्तुतः प्रति व्यक्ति प्रतिदिन १० औंस पड़ता है। तीसरी योजना में, इस सम्बन्ध में, बड़े स्पष्ट शब्दों में देश की दूध की स्थिति को इन शब्दों में प्रकट किया गया है—"१९५१ में दूध—दूध के उत्पादन सहित—की खपत ४.७६ औंस प्रतिदिन प्रति व्यक्ति थी जबकि १९६१ में यह ४.९० औंस हो गयी। तीसरी योजना के अन्त तक इसके ५.१ औंस प्रतिदिन तक बढ़ जाने की सम्भावना है। इस हिसाब से १० औंस प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का लक्ष्य भी पांचवी योजना के अन्त तक शायद पूरा हो सके, अगर आबादी में वृद्धि न हो!! दुग्ध केन्द्रों पर खर्च की जाने वाली भारी राशियों को देखकर यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इस मद की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वस्तुतः इन राशियों में बहुत सारा अंश, पश्चिमी ढंग के अनुसार, दूध को पेस्चुराइट और प्रोसेसिंग इकाइयों नर खर्च करने को है, दूध की मात्रा बढ़ाने पर नहीं। पर प्रश्न तो यह है कि क्या देश को इस समय दूध की अधिक आवश्यकता है अथवा पश्चिमी ढंग की दूध—प्रक्रियाओं की ?

पश्चिमी ढंग उपयुक्त नहीं

दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए गौ-भैंस की दुग्ध शक्ति को बढ़ाना है। हमारे देश में बहुत बढ़िया नस्ल के गौ-भैंस हैं। अगर इनका वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग किया जाए तो पांचवीं पीढ़ी में ये पशु २५०० पौंड प्रति ब्याहन दूध देने लगेंगे, जबकि मौजूदा औसत ७५० पौंड की है। दूध की मात्रा बढ़ाने को दूसरा मुख्य उपाय चारे की किस्म और मात्रा को बढ़ाना है। खेतों में नाजों के साथ चारे को भी उगाने को उत्साहित किया जाए। एक फसल चारे की जरूर बोयी जाए। २-३ महीने में चारा तैयार हो जाता है। इससे जमीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है। दूध बढ़ाने का तीसरा उपाय दूध-सहकारी समितियों की समूचे देश में स्थापना है। इससे वैज्ञानिक ढंग से दुग्ध-उत्पादन, उसकी व्यवस्था और बिक्री को जहां प्रोत्साहन मिलेगा, वहां चारे के फार्मों की स्थापना से चारे की समस्या भी बहुत कुछ हल हो जाएगी।

इस प्रकार दूध की मात्रा बढ़ जाने से दूध का मूल्य कम होगा। पेस्चुरिजेशन और बोतलों में बन्द करने पर अधिक जोर देने से दूध मंहगा हो जाएगा। त्रिवेन्द्रम का उदाहरण हमारे सामने है। वहां जिला दूध सहकी समिति जिस दूध को पहले रु० १.१२ फी ४८ औंसबेच रही थी, पेस्चुराइज्ड और बोतल में बन्द करने से अब वह उसे ३२ औंस बेचती है। इस प्रकार दूध ५० प्रतिशत महंगा हो गया। ○ ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मध्यप्रदेश में उद्योगी करण की मन्द गति

स्थिर सरकार और एक सूत्र में आबद्ध प्रशासन के अभाव से मध्य प्रदेश के सामुदायिक विकास कार्य तथा सड़क निर्माण, संचार व परिवहन के साधनों का विकास, जल विद्युत और जल शक्ति उत्पादन, तकनीकी कुशलता इत्यादि कार्य पिछड़े रहे। योजना के तीसरे वर्ष के लिए इस प्रदेश के लिए ५०५ करोड़ रु० निर्धारित किया गया है जिसमें ३४-१० करोड़ रु० केन्द्र देगा और १६०४ करोड़ रु० प्रदेश स्वयं जुटाएगा।

इस प्रदेश के उद्योगपतियों को यह शिकायत है कि केन्द्रीय सरकार यहां से गये औद्योगिक लाइसेंसों के प्रार्थना पत्रों पर सहानुभूति से विचार नहीं करती है। १९५७-६१ में प्रदेश—अनुसार औद्योगिक लाइसेंसों का केन्द्र की ओर से जो वितरण किया गया, उसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा बहुत कम है। उदाहरण के लिए, इस अवधि में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में क्रमशः जहां पंजाब में—११, १४०, राजस्थान में—९, ६०, उत्तर प्रदेश में ६, १५६, दिल्ली में २७, ५५८ नयी ज्वाइंट स्टाक कम्पनियां रजिस्टर्ड की गयीं, वहां मध्य प्रदेश में इन दोनों क्षेत्रों में कमशः ३ और ६७ ही कम्पनियां रजिस्टर्ड हुईं। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री बी० एम० मंडलोई ने भी केन्द्रीय सरकार की इस प्रदेश के प्रति उपेक्षा वृत्ति की कड़ी आलोचना की थी।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण यहां की जनता का—जिसमें ६६ लाख आदिवासी हैं और जो प्रदेश की कुल आबादी का एक तिहाई है—जीवन स्तर भी ऊंचा नहीं हो सका है।

इस प्रदेश की यह भी शिकायत है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित "औद्योगिक वित्त निगम" (इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन) द्वारा ३० जून १९६२ तक जो औद्योगिक ऋण दिये गये हैं, उनमें आबादी और आकार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का हिस्सा बहुत न्यून है जो निम्न तालिका से स्पष्ट होता है—

प्रदेश	वर्गमील में क्षेत्र (हजार)	१९६१ में आबादी (करोड़)	लाख इकाइयों की रु०	संख्या
आन्ध्र प्रदेश—	१०६	३.६०	७५०	१६
आसाम —	४७	१.२०	५८३	५
बिहार —	६७	४.६०	८६८	१८
गुजरात —	७२	२.१०	९०५	१७
केरल —	१५	१.७०	९७८	९
मध्य प्रदेश—	१७१	३.२०	१०४	२
मद्रास —	५०	३.४०	१,४४८	२४
महाराष्ट्र —	११९	४.०	२,४३०	५८
मैसूर —	७४	२.४०	८१३	२०
उड़ीसा —	६०	१.८०	५३४	७
पंजाब —	४७	२. ०	६४३	१८
राजस्थान —	१३२	२. ०	४२५	६
उत्तर प्रदेश—	११३	७.४०	९६८	२२
पश्चिमी बंगाल —	३४	३.५०	१,४४६	४२
दिल्ली —	१	.३०	९५	२
योग —	११,७९	४३.९०	१३,०२७	२.६७

केन्द्रीय सरकार के भिलाई के इस्पात के कारखाने और भोपाल में भारी बिजली के कारखाने से मध्य प्रदेश की जनता व उद्योगों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि इनके सहायक उत्पादन प्रदेश से बाहर दूर स्थानों में ले जाये जाते हैं।

इसका यह अर्थ नहीं कि इस प्रदेश का भविष्य आशापूर्ण नहीं है। मध्यप्रदेश सरकार ने उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए भूमि, बिजली, पानी इत्यादि देने में आकर्षक और पर्याप्त रियायतें देने की घोषणा की हुई है। चम्बल जल विद्युत परियोजना के चालू हो जाने पर लगभग ७५ हजार किलोवाट विद्युत शक्ति फालतू रहेगी और प्रदेश के परि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चमी जिलों के लिए उपलब्ध हो सकेगी। प्रदेश ने केन्द्र से ऐसे सार्वजनिक व निजी उद्योगों को इधर प्रेरित करने की मांग की है जो इस विद्युत शक्ति का लाभ उठा सकें। प्रदेश सरकार ने बिजली के लिए ६ न० पै० प्रति इकाई और १ हजार किलोवाट से अधिक प्रयोग करने वालों के लिए ५.३३ न० पै० प्रति इकाई का दर निश्चित किया है। यह पर्याप्त अच्छी रियायत है। द्रुग और बैतूल के जिलों में ९ लाख किलोवाट बिजली पैदा करने की एक नयी योजना बनायी गयी है।

राजस्थान

इस प्रदेश की महत्वपूर्ण व्यापारी फसल कपास है। क्षेत्र की और प्रति एकड़ उपज की दृष्टि से इसकी उत्पादन वृद्धि की राजस्थान में बड़ी गुंजाइश है। १९६०-६१ में कपास का लक्ष्य २.६५ लाख गांठ था पर वास्तविक उत्पादन १.४७ लाख गांठ हुआ। कपास के लिए क्षेत्र ४.९६ लाख एकड़ है। १९५६ से १९६१ तक राज्य में औसतन कपास का क्षेत्र और कपास की उपज क्रमशः ५.९० लाख एकड़ और १.७४ लाख गांठ रही। इस ह्रास के दो कारण है, पहला, खाद्य फसलों के मूल्यों का अधिक होना और दूसरा कपास उत्पादक क्षेत्रों में जिनिंग और प्रेसिंग फैक्टरियों का न होना।

इस ह्रास को दूर करने के लिए १६ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में अगले चार वर्षों में सिंचाई की जाएगी और इसमें से लगभग १० प्रतिशत कपास के लिए उपलब्ध होगी। अब १९६०-६१ के १.४७ लाख गांठों के लक्ष्य से तीसरी योजना के अन्त तक के लिए ३.५२ लाख गांठों का लक्ष्य निश्चित किया गया है। भाखड़ा और चम्बल परियोजनाओं द्वारा सिंचाइ होने वाले इलाके में सेलगभग दो लाख एकड़ कपास के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। तीसरी योजना के अन्त तक कपास का क्षेत्र ९.४१ लाख एकड़ तक हो जाएगा।

कपास की किस्म में सुधार करने के लिए बढ़िया बीज की व्यवस्था की जा रही है। प्रति वर्ष ६ एकड़ जमीन बढ़िया बीज उगाने के लिए सुरक्षित रखी जाएगी। इसके फलस्वरूप ३२ हजार मन बढ़िया बीज किसानों में बांटने के लिए मिल जाएंगा।

मध्यम और लम्बे रेशे की कपास का क्षेत्र राज्य में बढ़ गया है। बंसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र लम्बे रेशे के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। मेवाड़ और गंगानगर में क्रमशः १५ हजार और ३० हजार एकड़ जमीन सामूहिक कार्यक्रम के अन्तर्गत कपास के लिए सघन खेती के रूप में निश्चित की गयी है।

राजस्थान में कपास की बुवाई मध्य अप्रेल से शुरू होकर शुरू जुलाई तक रहती हैं। २ या ३ सिंचाई इस अवधि में दरकार होती हैं। बहुधा, रबी फसल के लिए पानी का इस्तेमाल हो जाने से अप्रेल और मई में कपास के लिए कोई पानी नहीं बचता। राज्य में उर्वरकों के प्रयोग की अभी अधिक आवश्यकता है। कपास के इलाकों में इसका प्रयोग आगामी कुछ वर्षों में अधिक हो सकेगा—ऐसा विश्वास किया जाता हैं।

उत्तर-प्रदेश

७ जनवरी को नेहरू जी द्वारा उद्घाटित रिहन्द जलाशय एशिया की सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। मिरजापुर के पास १८० वर्गमील का यह जलाशय मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ है। जलाशय का नाम "गोविन्दवल्लभ पन्त सागर" है और इस पर ३०,६५ फुट लम्बा और ३०० फुट ऊंचा बांध है। इसमें ३,५०,००० टन सीमेंट लगा है। बांध की सफाई के लिए उसके विभिन्न भागों में चार सुरंगों का निर्माण किया गया है। इस बांध से अढ़ाई लाख किलोवाट बिजली पैदा होगी जिससे उ० प्र० के पिछड़े हुए पूर्वी जिलों में नवजीवन आ जाएगा।

विज्ञापन के लिए

सम्पदा

सर्वोत्तम

साधन है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हाल मार्क आफ क्वालिटी ! !

बढ़िया चमक ! !

भारत

स्टेपल फाइबर यार्न

ड्रिल, चमकीले और रंगीन किस्म के कपड़ों के लिए केवल

भारत स्टेपल फाइबर यार्न का प्रयोग कीजिए

भारत स्टेपल फाइबर यार्न हैंक और कोन दोनों में सुलभ हैं !

विस्तृत जानकारी के लिए निर्माता से सम्बन्ध स्थापित कीजिए

मेसर्स भारत कामर्स एंड इंडस्ट्रीज लि०,

डाकखाना बिरलाग्राम

तार—"भारत" नागदा

फोन नं० R.T.M. 88

(पश्चिमी रेलवे)

भारत के अनेक राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा-संस्थाओं वाचनालयों पंचायतों एवं विकास खण्डों के लिये स्वीकृत

भारत व्यापार पत्रिका

उद्योग तथा व्यापार प्रधान सचित्र हिन्दी मासिक

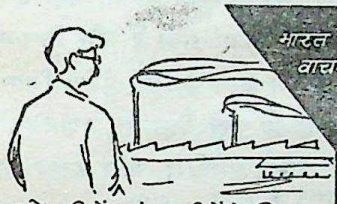

उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के लिए उपयोगी लेख, ताजे समाचार, आर्थिक गतिविधियों की जानकारी तथा व्यापारिक भविष्य-वाणी

अर्थ-शास्त्र के छात्रों के लिए अनेक उपयोगी सामग्री

आम जनता के लिए हर अंक में एक आकर्षक कहानी चल-चित्र उद्योग, व्यंग-विनोद, चित्रमय समाचार एवं कार्टून

- भिन्न-भिन्न वस्तुएं बनाने की योजनाओं का नियमित प्रकाशन
- एक मुफ्त विज्ञापन छापने की व्यवस्था
- आप के उठाये हुए प्रश्नों के उत्तर
- आप की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिये सुझाव एवं शिकायतें स्तम्भ
- आयात निर्यात समाचार, विज्ञान जगत बैंकिंग तथा बीमा समाचार आदि अनेक स्थाई स्तम्भ

वार्षिक चंदा विशेषांकों सहित ६.00 रू.

पृष्ठ संख्या ६४ से ७२ तक

साधारण अंक 0.५0 न. पै.

अन्य जानकारी के लिये लिखें:—

व्यवस्थापक, भारत व्यापार पत्रिका,

पो. बो. नं. ४८, राजा दरवाज़ा, वाराणसी (उ.प्र.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय खेती और नई परिस्थितियां

श्री रामसुभगसिंह, केन्द्रीय कृषि मंत्री

हमारी खेती की दो विशेषताएं रही हैं : पहली तो यह कि खेती हमारा सदियों पुराना परम्परागत पेशा रहा है जिसमें स्थिरता और फूंक-फूंक कर कदम उठाने की भावना बनी रही है, और दूसरे, इससे हमारे लगभग ७० प्रतिशत लोग जीवन-निर्वाह करते रहे हैं। इन्हीं दो बातों के कारण खेती हमारा केवल एक धन्धा ही नहीं है, बल्कि यह हमारे लोगों का एक जीवनक्रम है और इसका हमारे लोगों के जीवन सम्बन्धी दृष्टिकोण और विचार प्रणाली पर गहरा असर पड़ा है।

खेती की इन दो मुख्य बातों की अब तक तो उपयोगिता थी, किन्तु आधुनिक जीवन के बदलते हुए ढांचे को देखते हुए अब इसमें भारी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। पहली बात यह है कि बढ़ती हुई आबादी की खाद्य सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाना जरूरी है और उत्पादन बढ़ाने के लिए खेती में वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना आवश्यक है। दूसरी बात यह कि अब तक लगभग ७० प्रतिशत लोग खेती में लगे हुए हैं, किन्तु अब काफी लोगों को खेती से हटाकर अन्य आवश्यक राष्ट्रीय क्षेत्रों में लगाने की जरूरत है। अमरीका में केवल १२ प्रतिशत लोग और अन्य अधिकांश पश्चिमी देशों में २० प्रतिशत से भी कम लोग खेती में लगे हुए हैं। इसलिए हमें खेती के धन्धे से काफी लोगों को हटाकर रोजगार के अन्य धन्धों में लगाना चाहिए। इस प्रकार का परिवर्तन एक राष्ट्रीय आवश्यकता है।

हमारा पहला कदम यह होना चाहिए कि हम भारतीय खेती में आधुनिक समय के अनुसार परिवर्तन करें और उसे वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने योग्य बनाएं। खेती में सुधार से ही ग्रामीण क्षेत्रों का सुधार होगा और फिर इसी के परिणामस्वरूप हमारी अधिकांश जनता का जीवन स्तर उन्नत होगा।

इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए ही पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन बढ़ाने पर इतना अधिक जोर दिया गया है। सरकार ने धीरे-धीरे खेती पर की जाने वाली व्यय-राशि को बढ़ाया है और देश भर में खेती के नये वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने में सहायता देने वाली सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों का क्षेत्र भी विस्तृत किया है। इसी उद्देश्य को सामने रखकर सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, भरपूर खेती और सघन कार्यक्रम की योजनाओं को आरम्भ किया गया है।

अपने इन प्रयत्नों में हमें काफी सफलता मिली है, किन्तु अब भी हमारी खेती का उत्पादन हमारी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता। अब तक हमने ७ करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधाएं दी हैं। हमने रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाया है और देसी खाद तैयार करने के साधनों का भी विकास किया है। तीसरी योजना की अवधि में हम ६२ लाख टन उर्वरक तैयार करेंगे जिसका अर्थ यह है कि दूसरी योजना की अवधि की अपेक्षा उर्वरकों के उत्पादन में ३०० प्रतिशत वृद्धि होगी। देश भर में केन्द्रीय तथा राज्यीय एजेंसियों द्वारा सुधरे हुए बीजों के वितरण की व्यवस्था की जा रही है। खेती के औजारों में भी सुधार किया गया है और किसान को इन नये औजारों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। खेती में किसानों को कई वैज्ञानिक प्रणालियां इस्तेमाल करने के बारे में सलाह-मशविरा और आवश्यक तकनीकी सहायता देने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जो महत्त्वपूर्ण अनुसंधान किए गए हैं, उन्हें भी किसानों को बताया जा रहा है, ताकि वे उनसे फायदा उठा सकें। कृषि स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों का धीरे-धीरे सारे देश में जाल फैलाया जा रहा है जिससे प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा शिक्षा में कृषि सम्बन्धी शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण स्थान हो जाएगा।

ये सब बातें तो ठीक ही हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अनुसार हमारे खाद्य उत्पादन का लक्ष्य १० करोड़ टन है, परन्तु बदली हुई परिस्थितियों में हमारी जरूरतें भी बढ़ गई हैं, इसलिए इस समय की संकटकालीन अवस्था में सब लोगों पर, विशेषतः किसानों की सहायता और परामर्श देने वाली सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों पर एक विशेष जिम्मेदारी आ गई है। उन्हें अपने इस दायित्व का पूरी तरह से पालन करना चाहिए।

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

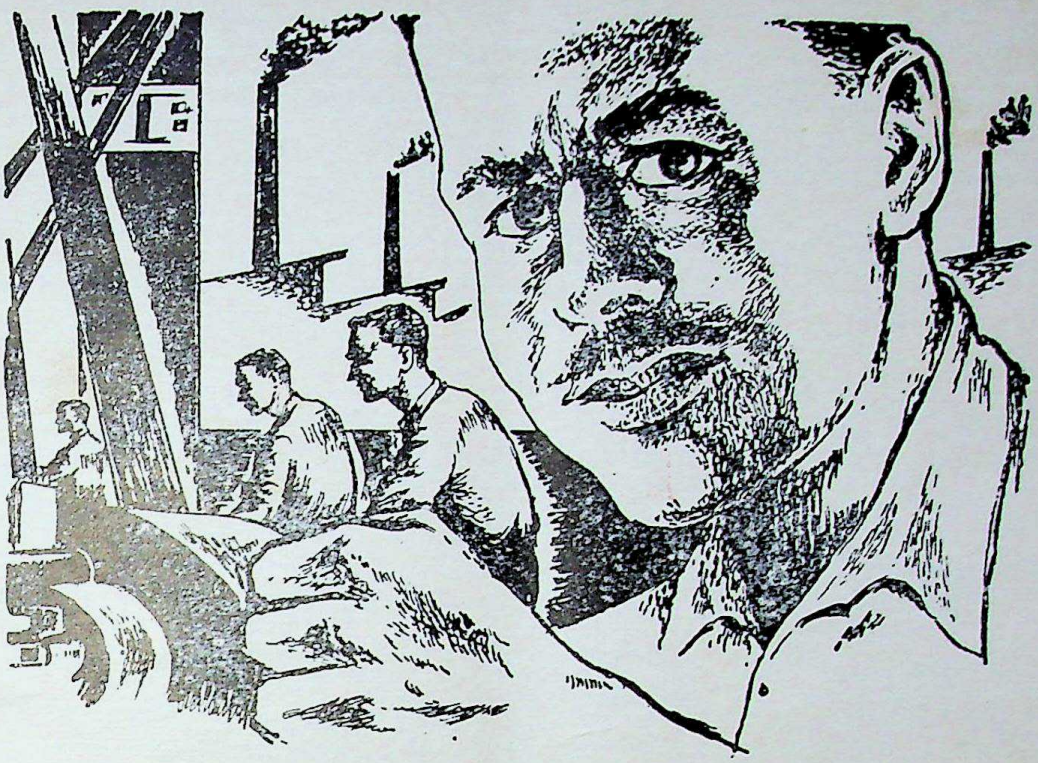

जीत के लिए जी-तोड़ मेहनत

विजय के लिए आपका काम भी बहुत जरूरी है। मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारी सीमा पर लड़ रही सेनाओं को सुदृढ़ करने, राष्ट्र को अधिक साधन सम्पन्न बनाने और सभी मोर्चों पर प्रहार-शक्ति सबल करने के लिए प्रत्येक को उत्पादन बढ़ाने के वास्ते जी-तोड़ मेहनत करना आवश्यक है।

चाहे विशाल औद्योगिक–कारखाना हो या मशीन शॉप, चाहे फाउन्ड्री हो अथवा खराद, सभी प्रकार का काम करने वाले लोगों को उत्पादकता बढ़ाने और अधिक उत्पादन के लिए अधिकाधिक परिश्रम करने का समय आ पहुंचा है। हमें इस बात का पक्का इंतजाम करना है कि सैनिक मोर्चों तक और देश की अन्दरूनी जरूरतों के लिए आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई का प्रवाह निरन्तर और निर्विघ्न चलता रहे।

हर नागरिक एक सैनिक है

खूब उत्पादन बढ़ा कर रक्षा-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए

DA 42/50

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गुरुकुल कांगड़ी

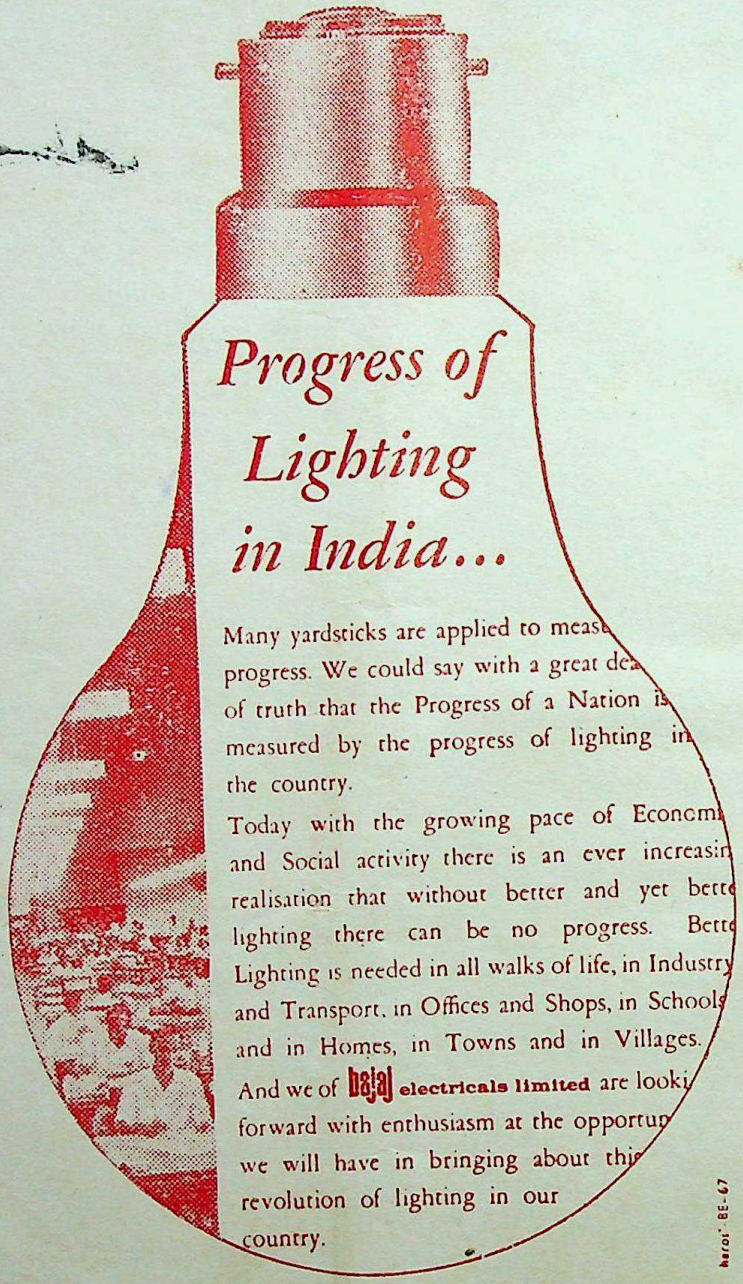

सम्पादक—कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा नवचेतन प्रेस (प्रा०) लि० (लीजिज ऑफ अर्जुन प्रेस) दिल्ली-६ से मुद्रित
अशोक प्रकाशन मन्दिर, २८/११, शक्तिनगर, दिल्ली-६ से प्रकाशित।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा

वर्ष १२ : अंक २

मूल्य
१ न. पै

अशोक प्रकाशन मन्दिर शक्ति नगर, दिल्ली

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एक वैज्ञानिक बात . . .

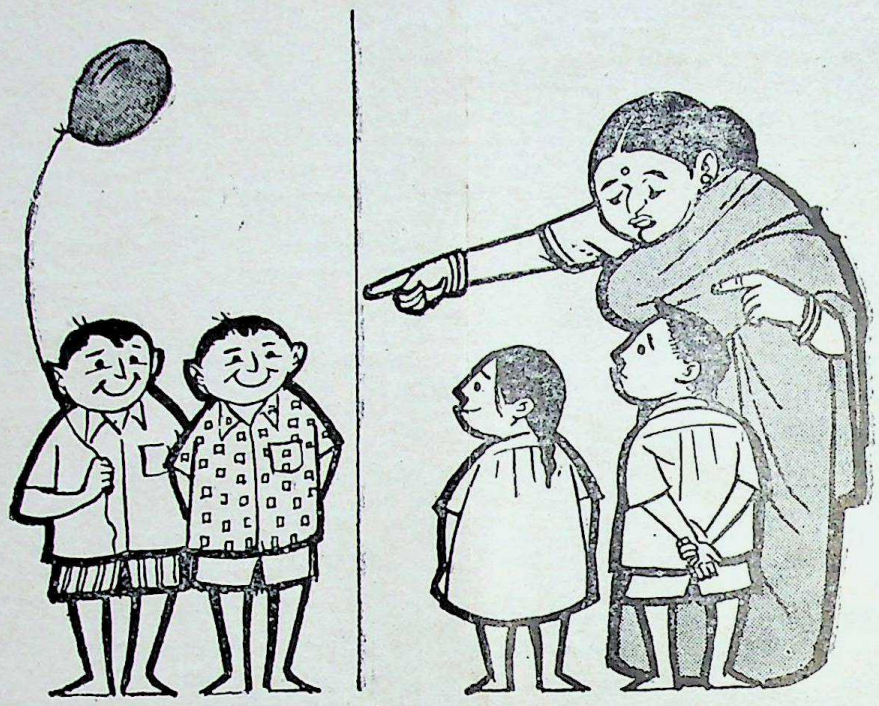

मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि हमें अपने बच्चों की दूसरों के बच्चों से तुलना नहीं करनी चाहिए। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इससे बच्चों के स्वाभाविक विकास में बाधा पहुंचती है। यही बात मेट्रिक बाटों के सम्बन्ध में है। नन्हे मुन्नों (और मेट्रिक बाटों) के गुणों को परखिये और उन्हें ज्यों का त्यों अपनाइये।

मेट्रिक तोल का जोड़-तोड़ करके सेर न बनाइये।

इसमें आपका समय व्यर्थ ही नष्ट होगा और लेन-देन में अक्सर नुकसान रहेगा।

सही और सुविधाजनक लेन-देन के लिए

पूर्ण अंकों में

मेट्रिक इकाइयों का प्रयोग कीजिए

डी ए ६२/५४७

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देश के सुरक्षा निर्माण में सहायता करें
छोटी बचत योजना में रकम जमा करें

जमा करने के तरीके

छोटी बचत योजना

पहले

१२ वर्ष के
नेशनल प्लान सेविंग्स सर्टिफिकेट
५.४१% टैक्स फ्री ब्याज
इनवेस्टमेंट की सीमा—२५,००० रु. तक

१० वर्ष के
ट्रेजरी सेविंग्स डिपाजिट सर्टिफिकेट
४% टैक्स-फ्री ब्याज वार्षिक अदायगी
इनवेस्टमेंट की सीमा २५,००० रु. तक

क्युमुलेटिव टाइम डिपाजिट
५ वर्ष, और १० वर्ष } एकाउन्ट
पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक एकाउन्ट
२½% टैक्स-फ्री ब्याज

अब

नेशलन डिफेन्स सर्टिफिकेट्स
६.२५% टैक्स फ्री ब्याज
इनवेस्टमेंट सीमा ३५,००० रु. तक

१० वर्ष के
डिफेन्स डिपाजिट सर्टिफिकेट
४½% टैक्स फ्री ब्याज वार्षिक अदायगी
इनवेस्टमेंट सीमा ३५,००० रु. तक

क्युमुलेटिव डिपाजिट
५ वर्ष, १० वर्ष, १५ वर्ष } एकाउन्ट
१० और १५वर्षों के एकाउन्ट पर इन्कमटैक्स रिबेट
पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक एकाउन्ट
३% टैक्स फ्री ब्याज

प्रीमियम इनामी बांड

टैक्स फ्री बड़े इनाम, प्रीमियम

उज्ज्वल भविष्य के लिए बचत — स्वतंत्रता के लिए बचत

अधिक जानकारी के लिए

कृपा कर सम्पर्क कीजिये

डायरेक्टर आफ इनफोरमेशन, सचिवालय, अहमदाबाद–१५
डायरेक्टर आफ स्माल सेविंग्स, फाइनेन्स डिपार्टमेंट, सचिवालय, अहमदाबाद–१५
रीजनल डायरेक्टर, नेशनल सेविंग्स, लैंड रिकार्ड्स बिल्डिंग, भद्रा, अहमदाबाद–१
जिला कलक्टर और तालुका मामलतदार

डायरेक्टर आफ इनफारमेशन, गुजरात राज्य, अहमदाबाद द्वारा प्रसारित

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विषय-सूची

सं०	विषय	पृष्ठ
१.	मूल्य वृद्धि : कारण व उपाय	५७
२.	सम्पादकीय टिप्पणियां	५९
३.	आदर्श उद्योगपति ला० श्रीराम (कृष्णचन्द्र विद्यालंकार)	६१
४.	साम्यवादी आर्थिक पद्धति में नई दिशा (श्री ए० डी० श्राफ)	६३
५.	भारत की निर्बल खाद्य स्थिति	६५
६.	भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री नौरोजी (श्री गोकुलचन्द जांगिड़)	६७
७.	भारत में अलुमिनियम उद्योग	६९
८.	तटस्थ नीति से भारत का आर्थिक लाभ (श्री जी. एस. पथिक)	७१
९.	स्वयं स्फूर्त विकास और भारतीय योजना (श्री रामकृष्ण सिंगी)	७५
१०.	हमारी सफलता व असफलता (श्री ओ० पी० मिश्र)	७९
११,	कृषि के संकट कालीन कार्यक्रम (श्री रामसुभग सिंह)	८०
१२.	अर्थ व्यवस्था और सहकारी समितियां	८१
१३.	आयल इंडिया लि० की प्रगति (श्री खण्डूभाई देसाई)	८३
१४.	चीन की आर्थिक नीति व स्थिति	८५
१५.	देश रक्षा व जनता के कर्तव्य	८७
१६.	विभिन्न क्षेत्रों में विकास	८९
१७.	स्वर्ण का उत्पादन और मुद्रा कोश	९१
१८.	पोलैण्ड तथा भारत के आर्थिक सम्बन्ध	९३
१९.	बैंकों की नई प्रगति	९४
२०.	अर्थवृत्त चयन	९६
२१.	इस मास की आर्थिक घटनाएं	१०१

सम्पदा

वार्षिक मूल्य ८ रु० एक अंक का मूल्य ०.७५

टेलीफोन नं० २२५८७३

१९६२ की फ़ाइल

अर्थ शास्त्र के विद्यार्थी सम्पदा की फ़ाइल मंगाते रहते हैं। १९६२ की फाइल की कुछ प्रतियां शेष हैं। जल्दी मंगाइये और परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाइये। ८.५० रु० मनीआर्डर से भेजें।

अंग्रेजी के अर्थशास्त्रीय पत्रों के समकक्ष

सम्पदा के सम्बन्ध में अ० भा० कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री उ० न० ढेबर लिखते हैं—

श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा "सम्पदा" के संचालन में निरन्तर त्याग, रचनात्मक भावना और विषय को पूरी तरह समझने का प्रयत्न है। यह ऐसा हिन्दी पत्र है जिसका मुख्य ध्येय भारत में आर्थिक योजना को कार्यान्वित करना है। जो इस पत्र को पढ़ेंगे उन्हें यह स्पष्ट पता चल जाएगा कि यह अपने स्तर को कायम रखता है और गेट-अप छोड़कर अन्य सब दृष्टियों से यह अपने सदृश अंग्रेजी पत्रों से तुलना में पूरी तरह ठहरता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि वे लोग जो ऊंचे स्तर की पाठ्य सामग्री पेश करने का प्रयास करते हैं, उन्हें केवल इसलिए कष्ट उठाने पड़ते हैं क्योंकि वे हिन्दी में पाठ्य सामग्री उपस्थित कर रहे हैं।

मैं श्री विद्यालंकार की सफलता चाहता हूँ, जो ऐसे निष्ठा युक्त प्रयत्नों से अवश्य उपलब्ध होती है।

१०-१-६३ उ. न. ढेबर, संसद सदस्य

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुस्तकालय
गुरुकुल

वर्ष : १२
अंक : २
फरवरी : १९६३

सम्पादा

मूल्य वृद्धि : कारण और उपाय

पंचवर्षीय विकास योजनायों की सफलता के लिए एक आवश्यक शर्त यह है, कि देश में जीवनोपयोगी पदार्थों के मूल्यों में कोई वृद्धि न हो। चीन के आक्रमण से उत्पन्न संकटकालीन परिस्थितियों में तो यह और भी अधिक हो गया है। जब चीन का आक्रमण शुरू हुआ, तब देश में प्रतिरक्षा कार्यों में सहयोग देने के लिए जो उमंग पैदा हुई, वह चिरकल तक स्थिर नहीं रही, यह दुःखद है, पर सत्य है। इसलिए पिछले दिनों में कुछ मूल्य बढ़ने के आसार दीखने लगे हैं। इस स्थिति से सरकार का चिन्तित होना अत्यन्त स्वाभाविक है। यही कारण है कि योजना आयोग और प्रशासन मूल्य वृद्धि को देखकर चिन्तित हो उठा है, क्योंकि एक बार जब मूल्य वृद्धि का चक्र शुरू हो जाता है, तब उसे रोकना कठिन हो जाता है। मूल्यों को स्थिर रखने के लिए ऋण पर नियंत्रण, अनेक वस्तुओं के सट्टे पर रोक, कुछ अनाजों के मूल्यों का निर्धारण आदि कुछ कदम उठाये भी गये हैं। किन्तु इनको भी पर्याप्त प्रभावकारी न समझकर सरकार ने बैंकों के लिए कुछ अधिक प्रतिबन्ध लगाये हैं। निश्चित कोटे से अधिक ऋण देने से पहले बैंकों को कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा। इन शर्तों में से कुछ अन्न के संग्रह और सट्टे के लिए ऋण देने पर प्रतिबन्ध, सोने तथा शेयरों पर दिये गये ऋण की वापसी हैं।

मूल्य वृद्धि का एक प्रधान कारण यह होता है, कि देश में प्रचलनशील मुद्रा बहुत बढ़ जाती है। जितना अधिक मुद्रा प्रसार होगा, उतनी ही मुद्रा की कीमत कम होगी और परिणामस्वरूप पदार्थ अधिक महंगे हो जायेंगे। भारत के वित्तमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने पिछले वर्ष अपना बजट पेश करते हुए इसीलिए मुद्रा प्रसार का अधिक आश्रय न लेने का वचन दिया था। आज भारत में गत वर्ष की अपेक्षा १८४ करोड़ रुपये के अधिक नोट चल रहे हैं। गत वर्ष की अपेक्षा बैंक क्रेडिट भी १५४ करोड़ रुपये ज्यादा है। जब तक मुद्रा प्रसार पर अधिक कठोर प्रतिबन्ध न होगा, तब तक मूल्य वृद्धि को रोकना बहुत कठिन हो जाएगा। मुद्रा प्रसार और उसके परिणाम को रोकने के लिए २-३ उपाय किए जा सकते हैं।

१. सरकार स्वयं नासिक के प्रैस का आश्रय लेने के प्रलोभन का संवरण करे।

२. अधिक से अधिक कर लगाकर या बाजार से ऋण लेकर भी मुद्रा प्रसार के परिणाम को कुछ सीमा तक रोका जा सकता है।

३. लोग अधिक से अधिक बचत करने का प्रयत्न करें। इसीलिए रक्षा पत्र और स्वर्ण पत्र, इनामी पत्र आदि जारी किए गए हैं। इससे सरकार रक्षा प्रयत्नों और अन्य कार्यों पर जो अधिक रुपया खर्च रही है, वह सन्तुलित हो जाएगा।

बलात् बचत के प्रस्ताव को फिर जारी करना चाहिए।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

५० प्रतिशत बोनस व ५०० रु० से अधिक वेतन पर वार्षिक वृद्धि बचत पत्रों में दी जाने के सुझाव पर विचार किया जा सकता है।

४. कृषि और उद्योग दोनों के पदार्थों और विशेष कर कृषि पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाया जाए। उत्पादन में वृद्धि मूल्यों की नहीं बढ़ने देगी।

५. अन्न आदि पदार्थों के वितरण को अधिक सुविधा जनक और सरल किया जाए। इसीलिए सरकार गेहूँ के भण्डारों और गोदामों का विस्तार करना चाहती है। उसने सब राज्य-सरकारों से अन्न का संग्रह, थोक व्यापार पर निगरानी और सस्ती दुकानों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा है। अनाज की सस्ती दुकानों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। जनता को सब सामान सुलभ हो, इसके लिए सहकारी समितियों के द्वारा हजारों स्टोर खोले जाएंगे। ये स्टोर केन्द्रीय और थोक स्टोरों द्वारा नियन्त्रित होंगे। सहकारी समितियों का कार्य अधिक व्यवस्थित और सुचारु रूप से किया जाय, तभी कुछ लाभ उठाया जा सकेगा। अभी तक के अनुभव से शिक्षा लेने की जरूरत है।

६. अनेक आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की घोषणा की जाए, जिससे कोई छोटे या बड़े व्यापारी अनुचित मुनाफा न ले सकें। व्यापारियों को अपने अपने स्थानों पर मूल्य सूची टॉकने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि जनता से अधिक मूल्य न लिए जा सकें।

७. मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता उग्र राष्ट्रीयता का भाव उत्पन्न करने की है। ऐसी भावना उत्पन्न होने पर ही हम अन्न तथा विभिन्न वस्तुओं के उपयोग में यथासंभव मितव्यय करेंगे, किसी छोटी सी छोटी चीज को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। एक छटांक अन्न भी बरबाद नहीं जायगा। आडम्बर प्रियता को छोड़ना होगा, घरेलू या सामाजिक समारोहों ही में बचत करके लाखों रुपया बचाया जा सकता है। राष्ट्रीय भावना ही हमें कठोर परिश्रम व अधिक उत्पादन की प्रेरणा देगी।

मूल्य वृद्धि एक ऐसा दैत्य है, जिसके सैंकड़ों मुख हैं, सैंकड़ों हाथ पैर हैं। उसका विनाश करने के लिए समस्त देश को एक साथ मिलकर प्रयत्न करना होगा। वह जिस दिशा से बढ़ने का प्रयत्न करें, उसी दिशा में हम विनाश करने के लिए सन्नद्ध रहें।

कृषि लक्ष्य से पीछे

इस अंक में पाठक अन्यत्र खाद्य स्थिति की निर्बलता और शोचनीयता पर एक लेख पढ़ेंगे। योजना आयोग के कृषि मंडल की बैठक में भी कृषि-उत्पादन की प्रगति में शिथिलता को स्वीकार किया गया है। खाद्य उत्पादन १९६५-६६ तक १० करोड़ टन हो जाए, तभी उस समय की ४९ करोड़ जनसंख्या को १५ औंस अन्न, और ३ औंस दाल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन भोजन में मिल सकेगी। इसके अतिरिक्त हमें बीज, चारे तथा बरबादी का भी ख्याल रखना होगा। यह भी ध्यान में रखना होगा कि किसी वर्ष उत्पादन कम भी हो सकता है। तीसरी योजना में ६ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है, यद्यपि पिछले १० वर्षों में (१९४९-५० से १९६०-६१ तक) उत्पादन वृद्धि का अनुपात ३.८४ प्रतिशत रहा है। योजना आयोग के सदस्य श्री श्रीमन्नारायण ने अपने भाषण में बतलाया है कि तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में करीब ८-८ करोड़ टन अन्न पैदा हुआ है। यदि हमें अपना लक्ष्य पूरा करना है तो हमें दुगनी गति से उन्नति करनी होगी। उन्होंने इस बात की ओर भी ध्यान खींचा है कि अभी तक उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, वह खेती का क्षेत्र बढ़ने के कारण हुई है, प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि कम हुई है। इसलिए हम यह आशा नहीं कर सकते कि हम बहुत तेजी से अपना उत्पादन बढ़ा सकेंगे। अधिकांश कृषि योग्य भूमि पर खेती होने ही लगी है। इसलिए अब हमारा प्रयत्न प्रति एकड़ उपज बढ़ाने का होना चाहिए। इस उत्पादन के लिए अनेक उपाय सुझाये जा रहे हैं। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था, अच्छे बीज, नये ढंग की खेती आदि से कुछ उपज अवश्य बढ़ सकती है।

कृषि उत्पादन में सन्तोषजनक प्रगति न होने के लिए उत्तरदायी कौन हैं, इस प्रश्न पर भी विचार हुआ है और स्वभावतः प्रत्येक सम्बद्ध व्यक्ति या संस्था वर्तमान विफलता के लिए एक दूसरे पर दोष मढ़ रही है। केन्द्र राज्यों को अपराधी मानता है और राज्य सामुदायिक योजनाओं के अधिकारियों को। विभिन्न मंत्रालयों में भी परस्पर समन्वय नहीं हैं। श्री टी. टी. कृष्णमाचारी के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शब्दों में तो मंत्री कार्य की अपेक्षा भाषणों पर अधिक जोर देते हैं। जब तक अधिकारी अपनी अकर्मण्यता और उदासीनता को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक कृषि-उत्पादन में हम अपने लक्ष्यों को पूर्ण नहीं कर सकते।

गतिरोध व शिथिलता

केवल कृषि ही नहीं, उद्योग आदि में भी सरकारी अधिकारियों की अक्षमता और उदासीनता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और इसका असर यह हो रहा है कि उद्योग का उत्पादन भी जिस गति से होना चाहिए था, वह नहीं हो रहा। अखिल भारतीय उद्योग-व्यापार मंडल ने निजी उद्योगों की ओर से वर्तमान संकट में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया था, किन्तु वह भी वर्तमान गतिविधि से बहुत असन्तुष्ट है। इस सम्बन्ध में मंडल ने जो वक्तव्य दिया है, हम बिना किसी टीका-टिप्पणी ने उसका आशय नीचे देते हैं—

"गत तीन मास की देश की आर्थिक स्थिति को दृष्टि में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि संकट का मुकाबला करने के लिए जनता में जो उत्साह पैदा हुआ था, सरकार ने उससे कोई ठोस लाभ नहीं उठाया है। आर्थिक दृष्टि से, हमारे विकास का झुकाव गिरावट की ओर है। कृषि-उत्पादन एक ही बिन्दु पर रुक सा गया है और औद्योगिक विकास ढीला हो गया है। वित्त में सिकुड़न आ गयी है। रिजर्व बैंक की नीति ही रुकावट वाली है। स्टाक एक्सचेंज की हालत बुरी है। सरकार की कार्य पद्धति मन्द गति से चलने वाली है, जिससे आर्थिक विकास में बाधा पहुँचती है। यह देखकर विशेष खेद होता है कि उत्तरदायित्व की भारी कमी के साथ साथ प्रशासन के अंगों में निर्णय न कर सकना और ढीलापन, विशेषतः, बढ़ गया है। निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थाओं ने युद्ध-सामग्री तैयार करने के लिए सहयोग के जो प्रस्ताव किये थे, उससे लाभ उठाने के प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं। औद्योगिक-विस्तार की समूची योजना लगभग अवरुद्ध हो गयी हैं। बाजार की हालत ऐसी है कि कोई नयी कम्पनी खड़ी करनी मुश्किल हो गयी है।

"व्यापार और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की थी कि २१० से कुछ ऊपर उद्योगों के लाइसेंस नहीं दिये जाएंगे। सरकार की प्राथमिकता की सूची पर, मुश्किल से, १० उद्योग हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में कोई विशेष उत्साह नहीं दिखायी दे रहा है। सुरक्षा की सारी बढ़ी हुई आवश्यकताएं सार्वजनिक क्षेत्र से पूरी हो सकेंगी, यह असम्भव है। इस सम्बन्ध में यह नहीं भूलना चाहिए कि सामान और सेवाओं के रूप में देश की वित्तीय व्यवस्था में निजी क्षेत्र का योगदान ९० प्रतिशत से अधिक है। देश की आज की दशा में दोनों क्षेत्रों से पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए, तभी, सुरक्षा सामग्री का उत्पादन और विस्तार बढ़ सकेगा। इस स्थिति को सुधारने के लिए अगर अविलम्ब पग न उठाये गये तो देश की वित्तीय स्थिति को जहां भारी धक्का लगेगा, वहां दो नयी भयंकर समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। पहली—हमारी बढ़ती हुई फौजों की तुलना में सुरक्षा-सामान पर्याप्त नहीं हो सकेगा, दूसरी ओर उपभोक्ता सामान अपर्याप्त होगा। फलतः, मांग और मूल्य दोनों में बहुत वृद्धि हो जाएगी और इसके, लिए, व्यापारी वर्ग को दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए प्रशासन-व्यवस्था को कसते हुए उसमें इस वित्तीय दशा के प्रति "द्रुतगति" की भावना को पैदा करना चाहिए।"

संभव है कि सरकार की ओर से इस वक्तव्य का कोई उत्तर दिया जाए, किन्तु इससे वस्तु स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं आता।

ब्रिटेन व कामन मार्केट

आखिर ब्रिटेन की कामन मार्केट में प्रवेश की चर्चा समाप्त हो गयी और इस तरह १६ मास से चल रहे नाटक का पटाक्षेप हो गया। ब्रिटेन का यह आग्रह रहा है कि राष्ट्र मंडल के देशों को भी उसके साथ सम्मिलित रूप से कामन मार्केट की सुविधाएं दी जाएं, परन्तु फ्रांस ने इस शर्त पर ब्रिटेन को सम्मिलित करने की चर्चा से ही इन्कार कर दिया। वस्तुतः फ्रांस कामन मार्केट से ब्रिटेन को अलग रख कर यूरोप में लगातार बढ़ते हुए अमेरिकन प्रभाव को भी समाप्त करना चाहता है। वह अपने भूतपूर्व अफ्रीकी उपनिवेशों को भी जो सुविधाएं देता है, वह सुविधाएं कामन वेल्थ के देशों को देने को तैयार नहीं है। कामन मार्केट के शेष पांच सदस्य देश ब्रिटेन को सम्मिलित करने के पक्ष में थे, किन्तु संविधान के अनुसार एक भी सदस्य को

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वीटो करने का अधिकार है।

इस गतिरोध के कारण अनेक राजनीतिक परिणामों की सम्भावना की जा रही है। सम्भव है, अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर एक ऐसे सांझे बाजार का संगठन करें, जिसमें फ्रांस की उपेक्षा हो जाए परन्तु ऐसा करने से पश्चिमी राष्ट्रों की एकता को खतरा पैदा हो जाएगा और शायद अमेरिका यह किसी तरह भी पसन्द न करे। ब्रिटेन नया कदम उठाने से पूर्व राष्ट्र मंडल के देशों से विचार करना चाहता है। भारत के कुछेक क्षेत्रों में भी इस गतिविधि पर बहुत चिन्ता प्रकट की गयी है परन्तु कुछ दूसरे विचारक ऐसे हैं, जो प्रारम्भ से ही ब्रिटेन ने कामन मार्केट में प्रवेश करने का विरोध कर रहे थे, क्योंकि इस समय ब्रिटेन में भारत को जो सुविधाएं प्राप्त हैं, ब्रिटेन के कामन मार्केट में प्रवेश से उन सुविधाओं को हानि पहुँचती है। इसलिए, फिलहाल हमें तो इस सम्बन्ध में बहुत चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है। भारत कामन-मार्केट के भिन्न भिन्न देशों के साथ द्वि-देशीय समझौते कर सकता है और इन समझौतों द्वारा अपने आयात-निर्यात व्यापार का सन्तुलन कायम रख सकता है।

चीन के कम्यून

पाठक इसी अंक में अन्यत्र चीन की आर्थिक नीति पर एक लेख पढ़ेंगे। चीन की साम्यवादी सरकार ने जिस तरह एक के बाद एक क्रान्तिकारी परिवर्तन करने का साहस किया था, वह किसी तरह सफल नहीं रहा। चीन के क्रान्तिकारी प्रशासन की चरम परिणति कम्यून संस्था में थी। यह थी एक विराट परिवार की योजना, जिसमें व्यक्ति और उसके निजी परिवार का अस्तित्व भी लीन हो गया और सारा समाज अपने को एक विराट परिवार का अंग मानने पर विवश किया गया। यह आदर्श कानों को बहुत भला लगता है, परन्तु यह किसी तरह व्यावहारिक नहीं है। मनुष्य में ममत्व की नैसर्गिक भावना होती है। राज्य ने कम्यूनों की संस्था को बलात् ही लादना चाहा। इसे पूर्व एशिया के विशाल क्षितिज पर सुबह का चमकता हुआ सूर्य बताया गया। किन्तु किसी देश की प्राचीन संस्कृति और परम्पराओं को खत्म करना असम्भव है। चीन का नागरिक भी अपने छोटे से परिवार की व्यवस्था को छिन्न भिन्न होते नहीं देखना चाहता। फलतः चीनी किसान सामूहिक कम्यूनों में वांछित योगदान नहीं दे सके। अपनी भूमि के प्रति परम्परागत आसक्ति उन्हें निरा मजदूर बनकर काम करने नहीं दे सकी। तब फिर ३ स्तरों पर भूमि के स्वामित्व की व्यवस्था की गई। अप्रैल १९५९ में छोटे छोटे टुकड़े कम्यूनों के सदस्यों को वापस लौटा दिये गये। उन्हें सार्वजनिक भोजनालयों में भोजन करने की बजाए अपने अपने घर में खाना खाने की इजाजत दी गई। उत्पादन के साधन भी छोटी इकाई के उत्पादन दलों को सौंप दिए गए। वस्तुतः आज ये कम्यून नाममात्र के ही कम्यून रह गए हैं।

हमें चीन के इस परीक्षण पर कोई विशेष आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। चीन ने एक परीक्षण किया, वह सफल नहीं हुआ। लेकिन हम भारत के उन विचारकों को अवश्य कुछ कहना चाहते हैं, जो कुछ समय पूर्व समाजवाद के आकर्षक नारों में आकर चीन की हरेक अर्थ नीति की खुलकर प्रशंसा करने लगे थे। ऐसा मालूम होता था, कि हमारा अपना कोई व्यक्तित्व ही नहीं है, हमारी कोई स्वतन्त्र विचार दिशा ही नहीं है। आर्थिक नीति के निर्धारण में आदर्शवाद का अवश्य स्थान है, किन्तु व्यावहारिकता और यथार्थवाद की बलि देकर नहीं। भारत की अपनी सभी परम्परायें व प्रथाएं हेय नहीं है। हमें यह भी सन्देह है, कि यदि हमने संयुक्त सहकारी कृषि को बलात् किसानों पर लादना चाहा तो वह सफल न होगी।

सराहनीय प्रयास

"सम्पदा" बारहवें वर्ष में प्रवेश कर रही है, यह जान कर प्रसन्ता हुई। हिन्दी में इस कोटि की पत्रिका का आपका प्रयास सराहनीय है। मैं कभी कभी "सम्पदा" देख लिया करता हूँ। देश के विभिन्न उद्योगों और उनकी समस्याओं में "सम्पदा" विशेष रुचि लेती है।

मुझे आशा है, "सम्पदा" को सबका पूर्ण सहयोग मिलेगा और वह अर्थशास्त्र की एक प्रमुख पत्रिका बन जाएगी।

भरतराम
अध्यक्ष अ० भा० कपड़ा मिल संघ
मैनेजिंग एजेन्ट, दिल्ली क्लाथ मिल्स लि०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एक आदर्श उद्योगपति : स्व० लाला श्रीराम

(कृष्णचन्द्र विद्यालंकार)

ला० श्रीराम

११ जनवरी ६३ को लाला श्रीरामजी के देहावसान से देश के आर्थिक क्षेत्र का एक महान् स्तम्भ उठ गया है। उनकी बहुमुखी सेवाएं न केवल देश के औद्योगिक क्षेत्र में स्मरणीय रहेंगी, बल्कि शिक्षा सम्बन्धी और औद्योगिक अनुसन्धान तथा समाज सेवाओं के सम्बन्ध में भी वे बहुत समय तक याद किए जाते रहेंगे। उन्होंने अपना जीवन केवल १३० लूमों की एक छोटी सी मिल से प्रारम्भ किया और दिल्ली क्लाथ मिल के चारों ओर दूर दूर तक बने हुए औद्योगिक साम्राज्य के अधिपति के रूप में समाप्त किया।

ला. श्रीरामजी का जन्म १८८४ ई. में दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपना व्यापारिक जीवन दिल्ली क्लाथ मिल के एक एप्रेंटिस के रूप में १६ वर्ष की आयु में प्रारम्भ किया था। अपने कठोर परिश्रम, व्यापारिक कुशलता, गम्भीर अध्यवसाय और अपूर्व प्रतिभा के कारण वे न केवल स्वयं उन्नति करते हुए दिल्ली क्लाथ मिल कम्पनी के अध्यक्ष बन गए, बल्कि उन्होंने छोटी सी मिल को एक विशाल वट वृक्ष के रूप में परिणत कर दिया, जिसकी छाया के नीचे आज अनेक उद्योग पनप रहे हैं। आज यह कम्पनी केवल कपड़ा बनाने वाली कम्पनी नहीं है, बल्कि चीनी, डिस्टिलरी, हैवी कैमीकल, फर्टीलाइजर, चीनी के बर्तन, सिलाई की मशीन, बिजली के पंखे, और दूसरा इञ्जीनियरिंग सामान आदि विविध उद्योग इस मिल के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध हैं। आज इसकी ओर से चार कपड़े के मिल चल रहे हैं, दो चीनी की मिलें चल रही हैं। राजस्थान रेयन, राजस्थान विनिल तथा जय इञ्जीनियरिंग संस्थाएं भी लालाजी की औद्योगिक दूर-दर्शिता, संगठन कुशलता और प्रतिभा का परिचय देती हैं।

लालाजी अत्यन्त दूरदर्शी और प्रगतिशील उद्योगपति थे। वे समय की गति को पहचानते थे, इसीलिए उनका जीवन बहुमुखी प्रवृत्तियों का केन्द्र रहा है। उन्होंने केवल पुराने ढर्रे पर सूती मिल चलाने तक ही सन्तोष नहीं किया, बल्कि देश की आवश्यकताओं को देख कर अनेक नये उद्योग खोलने का दूरदर्शितापूर्ण साहस भी किया। जय इञ्जीनियरिंग वर्क्स को यह श्रेय प्राप्त है कि इसके पंखे व सिलाई की मशीनें विदेशों में जाकर पर्याप्त विदेशी मुद्रा का अर्जन करती हैं। उनके सहयोगी जानते हैं, कि वे अपनी मिलों में नये से नया कदम उठाने के लिए सदा प्रवृत्त रहते थे। नई से नई मशीनरी लगाने और स्वयं भी मशीन निर्माण करने में वे देश के बहुत से उद्योगपतियों को पीछे छोड़ गए हैं।

समय की गति को देखकर आज से बहुत पहले ही अपनी मिल में श्रमिकों के साथ सहानुभूति पूर्ण-व्यवहार करने और उन्हें जीवनसम्बन्धी तथा आर्थिक सुविधाएं पहुँचाने में वे उन कुछ उद्योगपतियों में प्रमुख स्थान रखते हैं, जिन्होंने श्रमकल्याण (लेबर वैलफेयर) में देश का नेतृत्व किया है। सरकारी कानून पीछे बनते थे और बहुत सी प्रवृतियों का प्रारम्भ वहां पहले हो जाता था। १९३९ में ही मिल के प्रबन्ध में श्रमिकों को हिस्सा देना और डायरेक्टर बोर्ड में श्रमिकों का एक प्रतिनिधि लिया जाना उनकी दूरदर्शिता और माननीय भावना का सूचक है। सरकार तो आज सह प्रबन्ध स्थापित करने की मांग कर रही है। मजदूरों की शिक्षा, चिकित्सा, आवास, मनोरंजन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आदि विविध प्रवृत्तियां उन्हें एक आदर्श उद्योगपति के रूप में हमारे सामने प्रकट करती है। मजदूरों के खेल कूद, मनोरंजन, नाटक, शिक्षा आदि के कार्यों में वे स्वयं मजदूरों में घुल मिलकर उन्हें प्रोत्साहन देते थे।

औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र में उनकी सेवाओं के कारण ही फैडरेशन आफ इण्डियन चेम्बर्स आफ इण्डस्ट्रीज एण्ड कामर्स के वे अध्यक्ष चुने गए थे। भारत के उद्योग-पति और व्यापारी उन्हें अपना आदरणीय नेता स्वीकार करते थे। उन से वे समय समय पर परामर्श लेते रहते थे। उनकी योग्यता के कारण ही वे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलनों में मिल मालिकों के प्रतिनिधि बनकर सरकार द्वारा भेजे गये। रिजर्व बैंक के वे डायरैक्टर रहे हैं। सिन्द्री फर्टीलायज़र का चेयरमैन भी उन्हें सरकार द्वारा नियत किया गया। इण्डस्ट्रियल फायनेंस कार्पोरेशन के अध्यक्ष रूप में भी उन्होंने भारत के उद्योगों को सहायता के पहुँचाने का प्रशंसनीय कार्य किया।

इन संस्थाओं के अतिरिक्त, उनकी प्रवृत्तियां कितनी विविध थीं, यह उन संस्थाओं की लम्बी सूची से ज्ञात हो सकता है, जिनके साथ उनका सम्बन्ध रहा है। इनमें से कुछ संस्थाएं निम्न लिखित हैं—

(१) पंजाब चैम्बर आफ कामर्स।

(२) इंडियन कौंसिल आफ वर्ल्ड एफेयर्स।

(३) दि आल इंडिया इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।

(४) इंडियन कौंसिल आफ साइन्टिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च।

(५) दि इंडियन स्टैन्डर्ड इस्टीट्यूशन।

(६) श्रीराम इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल रिसर्च इसकी स्थापना मुख्य रूप से उन्हीं के दान से हुई।

समय समय पर संगठित उपसमितियों में सदस्य या अध्यक्ष के रूप में वे सदा सहयोग देते रहे।

समाज सेवा

दिल्ली की बीसियों शिक्षण संस्थाओं से उनका गहरा सम्बन्ध रहा है। इनमें से अनेक संस्थाएं उन्हीं के द्वारा स्थापित की गयी हैं। श्रीराम कालेज आफ कामर्स, लेडी श्रीराम कालेज, इन्द्र प्रस्थ गर्ल्स कालेज, फार वुमेन, हिन्दु कालेज, श्रीराम इंस्टीट्यूट फार इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन्स्टीट्यूट आफ इकानामिक ग्रोथ आदि बीसियों संस्थाएं अमित सहयोग के लिए उनकी ऋणी हैं। शिक्षा कार्य को अधिक संगठित रूप से चलाने के लिए उन्होंने 'श्रीराम एज्यूकेशनल ट्रस्ट' की स्थापना की थी।

लालाजी दिल्ली के नागरिक जीवन में बहुत समय तक प्रमुख भाग लेते रहे और उन्होंने बहुत सी समाज सेवी संस्थाओं की सहायता भी की।

आदर्श उद्योगपति

एक आदर्श उद्योगपति में निम्नलिखित तीन गुण होने चाहिए—(१) अपनी सूझ बूझ, दूरदर्शिता और संगठन, कुशलता के द्वारा अपने उद्योग का निरन्तर विकास। (२) उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के साथ सहानुभूति पूर्ण मानवीय सम्बन्ध, और (३) अपने उपार्जित धनका समाज की सेवा के कार्यों में सदुपयोग।

इन तीनों गुणों की दृष्टि से स्वर्गिय लालाजी आदर्श उद्योगपति थे। फेडरेशन के अध्यक्ष श्री श्रेयांस प्रसाद जैन ने कहा है कि—

लालाजी के देहावसाथ से फेडरेशन का "पथ प्रदर्शक नक्षत्र" खो गया है। "बम्बई के प्रमुख व्यापारिक पत्र" "कामर्स" के १९ जनवरी के अंक में प्रकाशित सम्पादक के इन शब्दों के साथ हम पूर्ण सहमत हैं :—

"ला० श्रीराम ऊंचे सिद्धांतों के व्यक्ति थे। वे इस विचार के कट्टर समर्थक थे कि उद्योगपति जनता का ट्रस्टी होता है और वह श्रमिक, उपभोक्ता, हिस्सेदार और सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। वे इस विचार के भी पूर्ण समर्थक थे कि उद्योग की प्रबन्ध-व्यवस्था और उसके लाभ में श्रमिक का हिस्सा होना चाहिए। निर्यात वृद्धि और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लाला जी बड़े पोषक थे। आधुनिक प्रबन्ध व्यवस्था के प्रशिक्षण और पद्धतियों में उनकी सक्रिय दिलचस्पी रहती थी।

"अपने उच्च आदर्शों के कारण लाला श्रीराम ने भारत के औद्योगिक विकास में एक निश्चित योगदान किया है। वयोवृद्ध उद्योगपति, वैज्ञानिक शोध और शिक्षा के प्रेमी और उदार दानी के रूप में लालाजी चिरस्मरणीय रहेंगे। निश्चय ही, जनता में एक नेता के रूप में उनका जो विशिष्ट जीवन रहा है, वह आज की पीढी को प्रभूत स्फूर्ति देने वाला होगा।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

साम्यवादी आर्थिक पद्धति में नई दिशा ?

श्री ए. डी. श्राफ़

नौ सितम्बर, १९६२ के "प्रावदा" के अन्त में प्रकाशित लेख में, जिसने सोवियत रूस में एक राष्ट्रव्यापी बहस की शुरुआत कर दी है, चारकोव के एक अर्थशास्त्री डा० जे० लीबरमेन ने, "परेशानीवाले केन्द्रीय नियोजन," 'नौकरशाही नियोजकों द्वारा निर्मित उद्यमों के दुर्बल ढांचे' और 'आर्थिक तरीकों के बजाय प्रशासनात्मक तरीकों से उत्पादन प्रभावित करने' की तीव्र आलोचना की है। उन्होंने 'लाभ के इरादे' की शुरुआत करने की दलील दी है। इसी प्रकार सरकारी रशन इकोनोमिक गजट में लिखते हुए एक गोर्की शिपयार्ड के डायरेक्टर, मि एम० युर्येव ने केन्द्रीय नियोजकों के बर्बादीपूर्ण नियंत्रण के बारे में शिकायत की है। उन्होंने इस बात पर अफसोस जाहिर किया है कि 'ऐसे १५ से कम अधिकारी नहीं है जो एक फैक्टरी के डायरेक्टर को आदेश दे सकते हैं और जो प्रायः एक दूसरे के विरोधी होते हैं।' यदि लीबरमैन के लेख को स्वीकार कर लिया जाता है, जैसी की सम्भावना है भी, तो केन्द्रीकृत, व्यापक नियोजन कम्यूनिस्ट रूस से गायब हो जायगा।

कम्युनिस्ट नियोजन में अब इस बात की भी जानकारी बढ़ती जा रही है कि भारी उद्योगों को प्राथमिकता देकर खेती और उपभोक्ता सामान उद्योगों की परवाह न करना वास्तव में गलत है। रूस के प्रधानमंत्री, मि० ख्रुश्चोव ने १९६० में सुप्रीम सोवियत से कहा था कि उपभोक्ता सामानों 'की ही वास्तव में मनुष्य को आवश्यकता रहती है' और सरकार की यह इच्छा है कि उन उपभोक्ता सामानों को इस मात्रा में पैदा किया जाय जिससे कि उनकी तुलना 'पूंजीवादी संसार में सबसे समृद्ध देश, अमेरिका की खपत सतह से' की जा सके। उपभोक्ता सामानों की कमी के बारे में जनता की परेशानी की ६ दिसम्बर, १९६१ की एक रिपोर्ट छपी थी जिस पर 'सरकारी समाचारपत्र' 'इजवेस्तदिया' ने सारे रूस संघ में रेजर ब्लेडों की कमी पर कड़ी आलोचना की थी। देश भर से हजारों शिकायतें प्राप्त बतलाते हुए इस अखबार ने बताया कि एक क्षेत्र में ब्लेडों की कमी इतनी भारी थी कि प्रत्येक परिवार में अपने अपने दाढ़ी वाले फादर क्रिसमस तैयार हो गए क्योंकि १९६२ के पहिले वहां माल पहुँचने की कोई सम्भावना नहीं थी। अनेक शहरों में काले बाजार में करीब रु० ७-५० में एक ब्लैड खरीदने के अलावा पूर्ति का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एक पाठक ने तो इस बात तक पर अफसोस जाहिर किया कि "काफी" काले बाजार के व्यापारी तक नहीं है।

साम्यवादी अर्थव्यवस्थाओं में कृषि ने एक भयानक रूप धारण कर लिया है। रूस में अब खेती के प्रति की गई लापरवाही को पूरा करने का आन्दोलन शुरू किया गया है। १९६१ के अन्त में मास्को में आयोजित एक विशेष सम्मेलन में मि० ख्रुश्चेव ने बुरे किसानों और कृषि निष्णातों को कम्यूनिष्ट पार्टी से निकाल देने की चेतावनी दी थी। इस सम्मेलन को, मि० ख्रुश्चेव ने ठोस कृषि आधार और उपभोक्ता सामानों की वृद्धि के जरिये जीवन-मान बढ़ाने सम्बन्धी अपने प्रयत्नों के क्रम में आयोजित किया गया था। उन्होंने इस सम्मेलन में एक मुख्य रूसी कृषि अनुसन्धान केन्द्र के प्रमुख से कहा कि यदि वे अमरीकी होते और अमरीकी किसानों को वैसी सलाह देते जैसे कि उन्होंने रूसी किसानों को दी है, तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाता। लेकिन सोवियत संघ में, मि० ख्रुश्चेव ने आगे कहा, कि उनको तथा उन जैसे अन्य वैज्ञानिकों को शैक्षणिक सम्मान और यहां तक कि राज्य की ओर से पुरस्कार भी मिलते रहते हैं। मि० ख्रुश्चेव ने उन सभी लोगों को चेतावनी दी कि 'हम इस प्रकार की स्थिति अब सहन नहीं कर सकते हैं।' साम्यवाद के प्रख्यात अधिकृत विद्वान मि डबल्यू० डबल्यू० रोस्टो ने एक विशेष अध्ययन के बाद हाल ही में कम्युनिस्ट देशों की खेती के बारे में होनेवाली परेशानी पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बतलाया कि प्रथम महायुद्ध के पहिले रूस से १ करोड़ टन अनाज निर्यात होता था लेकिन १९२९ से सोवियत नेताओं ने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अपने प्राकृतिक अनाज निर्यातों के बारे में ऐसी नीतियां अपनाई कि जिससे सोवियत संघ को अपने निर्यात की अपेक्षा कृषि पैदावार का आयात अधिक करना पड़ेगा।' मि० रोष्टो इस नतीजे पर पहुँचे कि जब तक किसानों को प्रोत्साहन नहीं दिये जाते तब तक सोवियत फार्मों के उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी। लेकिन प्रोत्साहन देने के लिए किसानों पर लागू सामाजिक और राजनैतिक नियंत्रण हटाने चाहिए और उन उपभोक्ता सामानों को, जिन्हें किसान खरीदना चाहते हैं, भारी उद्योगों तथा शस्त्रों आदि का खर्चा कम कर, अधिक पैदा करना चाहिए।

साथ-साथ अब उद्योगों के राज्यकीय मालिकी के बारे में भी कम्यूनिस्टों के रुख में परिवर्तन हुआ है। हाल ही में इटली के कम्यूनिस्ट नेता मि० पालमीरो टोगलियाटी ने इटली के बिजली प्रतिष्ठानों के राष्ट्रीयकरण को पसन्द नहीं किया है। उन्होंने कहा : 'सार्वजनिक उपयोगिताओं के राष्ट्रीयकरण की मांग किसी ने नहीं की थी। हमने न तो इस तरह के कदम की मांग न कभी की थी और न भविष्य में करेंगे। हमने हमेशा इस बात की जरूरत समझी है कि राष्ट्रीयकृत उपयोगिताओं का निजी उद्योग के वृहद्तर क्षेत्र के साथ सह-अस्तित्व जारी रहे।'

अतः यह बड़े महत्व और उल्लेख की बात है कि काफी बदनाम 'प्रोत्साहन' और 'लाभ के इरादे' को कम्यूनिस्ट देशों में भी उचित स्थान दिया जा रहा है। ५ मार्च, १९६२ के एक भाषण में मि० ख्रुश्चेव ने अधिक खाद्यों को पैदा करने के लिए किसानों को और भी ज्यादा 'भौतिक प्रोत्साहन' देने की घोषणा की थी। अनिवार्य खाद्य पदार्थों की कीमतों में की गई वृद्धि को उचित ठहराते हुए, सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी ने मार्च १९६२ की अपनी प्राथमिक बैठक में 'भौतिक प्रोत्साहनों' पर जोर दिया था। यह बतलाते हुए कि अनेक कृषि पदार्थों की उत्पादन लागत राज्य की खरीद कीमत से ज्यादा होती है कमेटी ने इस प्रकार की हानि को उचित नहीं माना और अधिक कीमतों के जरिये लाभ अर्जित करने की सिफारिश की। कमेटी ने कहा—कि मांस और दूध की खरीद कीमतों को बढ़ाना जरूरी है ताकि सामूहिक फार्मों को इन चीजों की पैदावार करना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद हो, उनके पास आवश्यक माल जमा रहे और भौतिक दृष्टि से उनमें शीघ्रता से पशुपालन सम्बन्धी पदार्थों की पैदावार बढ़ाने की दिशा में रुचि पैदा हो सके। इसके लिए काफी धन की जरूरत है। वह धन आखिर कहां से आयगा? यहां तक कि स्वमतामिमानी कम्यूनिस्ट चीन को भी निष्ठुर आर्थिक नियमों द्वारा मानव प्रकृति के सामने झुकना पड़ा। पेकिंग के 'पीपल्स डेली' में इस बात की रिपोर्ट छपी है कि कामगारों को नकद इनाम और किसानों को निजी प्लाट देने के प्रोत्साहनों को कायम किया गया है ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके।

लेकिन उपरोक्त लीबरमेन के लेख के निष्कर्षों के अनुसार अत्यन्त क्रांतिकारी परिवर्तनों को लागू करने की संभावना है। प्रोफेसर लीबरमेन की मान्यता है कि आर्थिक प्रवृत्ति को केवल लाभ होने के मापदण्ड से ही देखना चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि राजकीय उद्योगों को केन्द्रीय नियोजकों के शिकंजों से मुक्त कर दिया जाय। केन्द्रीय नियोजकों को केवल फैक्टरियों की कुल उत्पादन मात्रा निर्धारित करने के अधिकार ही दिये जायँ। अन्य सभी निर्णयों को फैक्टरियों पर छोड़ दिया जाय और उनके द्वारा प्रदर्शित लाभ के आधार पर देखा जाय। नियोजकों द्वारा अपनाये जानेवाले अवरोधक नियंत्रणों की व्यापकता तथा लाभ के इरादे की बिल्कुल बेदरकारी को समझने के लिए मि. ख्रुश्चेव के कथन पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें कि उन्होंने बतलाया था कि रेयालन में एक मशीन फैक्टरी को, अन्य स्रोतों के अलावा, केवल मंत्रालय से २,५८० विस्तृत निर्देशन दिये गये थे। उस फैक्टरी के डायरेक्टर उस वर्क के दौरान में वरिष्ठ अधिकारियों के सामने करीब १०,२५० रिपोर्टें और विवरण पेश कर रहे थे। इसलिए सोवियत अर्थशास्त्रियों ने बड़े उत्साह के साथ उसका समर्थन व स्वागत किया है।

भारत में भी समाजवाद को लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। योजना आयोग ने अनेक भारी उद्योगों का सरकार द्वारा संचालन इसके लिए आवश्यक माना है और पिछले वर्षों में अनेक उद्योग सरकारी क्षेत्र के लिए सुरक्षित कर दिये गये हैं। स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने व्यापार के एक

(शेष पृष्ठ १०० पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत की निर्बल खाद्य स्थिति

तीसरी पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष के लगभग समाप्ति काल तक भी भारत का खाद्य स्थिति, कई अंशों में, पहले की अपेक्षा भी निर्बल हो गई है। गेहूँ और चावल—खाद्यान्न के दो मुख्य पदार्थ—अभी तक आयात हो रहे हैं। इस स्थिति का राष्ट्रीय आय और मूल्य स्थिति पर तात्कालिक प्रभाव पड़ रहा है।

भारत की खाद्य स्थिति, निश्चित रूप से, अच्छी नहीं है। इसमें किसी प्रकार की अत्युक्ति नहीं है। खाद्यान्न और नकद फसलें—दोनों के बारे में यही स्थिति है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत की शक्ति और साधन ऐसे हैं जिनसे अधिक उत्पादन हो सकता है पर परिणाम अभी तक असन्तोषजनक हैं। इसका एक बड़ा कारण दोषयुक्त प्रशासन है। अगर बड़ी राशि में खाद्यान्न और कच्चा कपास का आयात न हो तो इस वर्ष स्थिति बड़ी विकट हो जाती। जब तक देश में पर्याप्त उपज न बढ़े और मांग व उपलब्धि के बीच की भेद रेखा कम न हो जाए, तब तक हमें आगामी वर्षों में भी आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसका प्रभाव योजना और सुरक्षा—दोनों पर अहितकर पड़ेगा।

प्रति वर्ष वृद्धि का लक्ष्य

जून १९६२ को समाप्त होने वाले फसली साल में—पिछले वर्ष के कुल खाद्य उत्पादन ७ करोड़ ८५ लाख टन में—१ करोड़ १० लाख की कमी आ गयी है। इस कमी में चावल, ज्वार, अनाज और दालों में चना और तूर का विशेष हिस्सा है। अभी तक के अनुमान के अनुसार, १९६२-६३ के फसली वर्ष में ८ करोड़ टन से अधिक उपज नहीं होगी, अर्थात् १९६१-६२ से कुछ ज्यादा और १९६०-६१ के बराबर। इसका मतलब यह होगा कि तीसरी योजना के पहले दो वर्ष में खाद्य-उत्पादन स्थिर ही रहा जबकि खाने वालों की संख्या १ करोड़ ६० लाख तक बढ़ गयी है। तीसरी योजना के आगामी तीन वर्ष में २ करोड़ टन खाद्यान्न बढ़ाने का लक्ष्य है, १९६३-६४ से शुरू करके, अर्थात्, प्रतिवर्ष औसतन ७ करोड़ टन की वृद्धि। यह लक्ष्य अभी तक की अवस्थाओं में तो अप्राप्य प्रतीत होता हैं।

नकद फसलों की स्थिति भी असन्तोषजनक है। १९६१-६२ में कच्ची कपास को बड़ा धक्का लगा, इसका उत्पादन लगभग १७ प्रतिशत कम होकर, इस अवधि में ४५ लाख गांठे रह गया। गन्ने का उत्पादन भी कम हुआ। इसके विपरीत, कच्चा जूट, मेस्ता और तम्बाकू का उत्पादन लक्ष्य से अधिक रहा। जूट के अधिक उत्पादन का कारण यह है कि पश्चिमी बंगाल और बिहार में चावल और गेहूँ की जगह जूट अधिक जमीन में बोया गया। तम्बाखू की खेती के विषय में स्थिति यह है कि इस समय भारत को "विरजिनिया" की तरह की तम्बाखू की बढ़िया किस्म की आवश्यकता है, अधिक मात्रा की नहीं। घटिया किस्म की तम्बाखू का बड़ी मात्रा में उत्पादन केवल मूल्य—ह्रास का कारण बनता है। तिलहन का उत्पादन १९६१-६२ में केवल ५ प्रतिशत बढ़ा जब कि खेती की जमीन में १० लाख एकड़ की बढ़ती हुई।

राष्ट्रीय आय पर प्रभाव

कुल राष्ट्रीय आय का लगभग आधा अंश खाद्यान्नों से प्राप्त होता है। इसमें कमी होने का ही यह परिणाम है कि राष्ट्रीय आय की दर (१९४८-४९ के मूल्यों के आधार पर) १९६०-६१ में ७.१ प्रतिशत से कम होकर १९६१-६२ में २.२ प्रतिशत रह गयी है।

चावल और गेहूँ

रबी की फसलों, १९६१-६२ में, अर्थात्, गेहूँ और जौ ने अच्छी उन्नति की पर खरीफ की फसल में चावल और ज्वार के उत्पादन में भारी ह्रास हो गया जिससे यह वृद्धि कोई विशेष लाभप्रद सिद्ध नहीं हुई। यह ह्रास प्रतिकूल ऋतु के कारण बताया जाता है, जैसे १९६१-६२ में चावल का उत्पादन कुल ३ करोड़ ३६१ लाख टन में लगभग ५०,००० टन कम था यद्यपि बुवाई की जमीन में कुछ एकड़ वृद्धि हुई थी। चावल की यह कमी, विशेषतः, बिहार, पश्चिमी बंगाल और केरल में प्रतिकूल ऋतु के कारण हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि सघन कृषि की दिशा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

में राज्य सरकारें कम दिलचस्पी ले रही हैं। ज्वार की फसल में बहुत कमी आयी, १९६१-६२ के ७६.६ लाख टन में लगभग १७ प्रतिशत का ह्रास, जिसका एक कारण मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र, में अत्यधिक वर्षा का का होना और उत्तर भारत में कड़ी सर्दी तथा टिड्डी दल का आक्रमण था। इस सारी स्थिति में सन्तोषजनक पहलू यही है कि गेहूँ की उपज ने नया रिकार्ड कायम कर दिया। बिहार और मैसूर को छोड़ सब प्रदेशों में यह वृद्धि हुई।

उर्वरकों की कमी

फसलों की इस कमी का एक बड़ा कारण विकास योजनाओं हैं मन्दगति का आ जाना है। यह बात तो सरकार ने भी मानी है कि उर्वरकों की उपलब्धि बहुत अपर्याप्त रही है, १९६१-६२ में नाइट्रोजीनियस उर्वरकों की मांग केवल ५३ प्रतिशत तक ही पूरी की जा सकी। तीसरी योजना में १० करोड़ २८ लाख एकड़ भूमि को छोटी सिंचाई के अन्तर्गत लाना था पर १९६१-६२ में केवल १० लाख ७० हजार एकड़ ही लाया जा सका।

ट्यूब वेलों में भी इसी प्रकार भारी कमी रही। १९६१-६२ में ७३९ ट्यूब वेलों का लक्ष्य था जबकि मार्च १९६२ के अन्त तक केवल ४८२ ट्यूबवेल पूरे हो सके। तीसरी योजना में लक्ष्य २४०० ट्यूबवेलों का है।

बढ़िया बीजों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में योजना में लक्ष्य था, १९६१-६२—१९६५-६६ में १४ करोड़ ८० लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में खेती करना, पर, सरकारी अनुमान के अनुसार इस मद के अन्तर्गत १९६१-६२ और १९६२-६३ इन दो वर्षों में कुल ३ करोड़ ३० लाख एकड़ भूमि इस योजना के अन्तर्गत आ सकी।

मूल्य स्थिति पर प्रभाव

खाद्यान्नों की कमी का प्रभाव मूल्यों पर पड़ना स्वाभाविक ही है। ... तक मूल्य वृद्धि बहुत अधिक नहीं हुई, इसका एक बड़ा कारण अमेरिका से पी० एल० ४८० के अन्तर्गत लगातार हो रहा खाद्यान्न का आयात है। अप्रैल १९६२ से खाद्यान्नों में तनिक तेजी आयी। चावल का मूल्य निर्देशक अंक जून १९६२ में ११० था जबकि १९६१ में १०१ था। गेहूँ का मूल्य जून १९६१ में ८६ से बढ़कर १९६२ फरवरी में १०० हो गया, बाद में कम हो कर ८८ रह गया। पिछले वर्ष की अपेक्षा यह अभी तक २ अंक ज्यादा है। ज्वार के दाम भी पिछले वर्ष की अपेक्षा १५ प्रतिशत अधिक हैं। बाजरा की फसल में १० प्रतिशत बढ़ती हुई। दालों के दाम भी लगभग १५ प्रतिशत बढ़ गये। खाद्यान्नों के मूल्यों में जहां लगभग सर्वत्र वृद्धि हुई, यहां नकद फसलों की मिली जुली स्थिति रही।

१९६२ के पहले ६ मास में अमेरिका से १० लाख ३२ हजार टन गेहूँ का आयात हुआ, जबकि इसी अवधि में पिछले साल १० लाख ५६ हजार टन हुआ था और १९६१ पूरे वर्ष में ३० लाख ९० हजार टन हुआ। चावल का आयात १९६२ की पहली छःमाही में ३,२८,००० टन हुआ जबकि पिछले दो वर्षों की सारी अवधि में क्रमशः २,९४,००० और ३,८४,००० टन था।

अन्न की वसूली

१९६१-६२ में सरकार द्वारा देश में अन्न की खरीद कम रही। चावल और धान की वसूली प्रायः सब प्रदेशों में स्थगित रही। केवल पंजाब और मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकार की ओर से खरीद होती रही। गेहूँ की खरीद भी १९६१-६२ में स्थागित रही। घाटे के क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए सरकारी स्टाक में से देना जारी रहा। १९६१ के अन्त तक सारे देश में ४९,००० फेयर प्राइस की दुकानें थीं।

विविध प्रकार से सरकारी प्रयत्नों के बावजूद, इस समय मूल्य स्तर पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग ५ प्रतिशत अधिक है।

१९६२-६३ की फसल अभी तक के अनुमान के अनुसार, १९६१-६२ से कुछ अच्छी होगी पर १९६०-६१ के स्तर से अधिक उत्तम नहीं होगी। खरीफ के अनाज बाजार में आने लग गये हैं, उनकी स्थिति अच्छी है सिवाय चावल के जिस पर आसाम और पंजाब की बाढ़ों का, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश की अनियमित वर्षा का और उड़ीसा के सूखे का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ज्वार और बाजरा (मोटा अनाज) के बढ़िया होने की आशा है। रबी की फसल के भी बढ़िया होने की संभावना है। दालें भी अच्छी होंगी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत की प्रमुख अर्थशास्त्री (४)

दादाभाई नारौजी

दादाभाई नारौजी का जन्म ४ सितम्बर, १८२५ के दिन बम्बई में हुआ था। वे इंगलैण्ड में स्थापित की गई प्रथम भारतीय वाणिज्य फर्म के साझेदार बने। व्यापार होते हुए भी वे दार्शनिक थे और लाभ के उपार्जन का इतना ध्यान नहीं रखते थे जितना कि अपने देश की प्रतिष्ठा और कल्याण का। वे अपनी फर्म की ओर से व्यापारिक कारोबार के लिए इंगलैंड गये थे लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने इंगलैंड निवासियों को भारत में शासन चलाने के उत्तर-दायित्व पर शिक्षा देनी शुरू की और हिन्दुस्तान के 'होम-रूल' का जोरदार प्रचार और समर्थन किया। महारानी विक्टोरिया के शासन के अन्तिम वर्षों में वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य बने। वे दो बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधान चुने गए। लोग उन्हें प्यार से भारत का पितामह प्रौढ़ (Grand old Man of India) कहकर पुकारते थे। सन् १९१७ में उनका स्वर्गवास हो गया।

दादाभाई नारौजी का उनके काल की कई प्रमुख संस्थाओं के साथ गहरा सम्बन्ध रहा था जिनमें 'दि लन्दन इंडियन सोसायटी' तथा 'दी ईस्ट इण्डिया एसोसिएशन' महत्वपूर्ण हैं। नारौजी ने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जब दो महत्वपूर्ण निबन्ध क्रमशः मई २, १८६७ और नवम्बर २५, १८६७ को पढ़े। पहले लेख का विषय था 'इंगलैंड का भारत के प्रति कर्तव्य'। इसमें उन्होंने इंगलैंड से हर संभव तरीके द्वारा भारत के कल्याण को बढ़ाने की जोरदार अपील की। दूसरा निबन्ध अबीसीनियन युद्ध पर खर्च के सम्बन्ध में था। इसमें नारौजी ने यह जोरदार आवाज उठाई कि भारत पर किसी तरह भी युद्ध का खर्चा न थोपा जाय क्योंकि यह युद्ध इंगलैण्ड के हित के लिए लड़ा गया था। आगे चलकर दादाभाई नारौजी ने उस समय, जबकि रेल या नहरों से सम्बन्धित विवाद बढ़ चला था, एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण किया और उसमें लोगों की अकाल से पीड़ित दुर्दशा को सामने रखा।

दादाभाई नारोजी के समय राष्ट्रीय आय सम्बधी सर-

कारी सूचनाएं न तो सही ही थी और न ही उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध ही थी। 'भारतीय अर्थशास्त्री' ही केवल एक ऐसा पत्र था जो कृषि, खनिज तथा राष्ट्रीय सम्पत्ति के कुछेक साधनों के सम्बन्ध में थोड़े से आंकड़े प्रस्तुत करता था। उन दिनों 'भारत की भौतिक और चारित्रिक उन्नति' के नाम से एक वार्षिक विवरण भी बनाया जाता था जो अपूर्ण भी था और साथ ही भ्रामक भी। इसके विपरीत नारोजी कहा करते थे कि ऐसा वार्षिक विवरण ब्रिटिश-भारत की जनसंख्या की औसत आय और एक स्वस्थ मजदूर की आवश्यकताओं का सही अनुमान और आंकड़े देने में असमर्थ है। उन दिनों भी राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन कई उपयोगों में लाए जाते थे। प्रति व्यक्ति आय देश के आर्थिक स्तर की द्योतक थी। दादाभाई ने सोचा कि समयानुसार बनाए गए ये राष्ट्रीय और व्यक्तिगत आय के आंकड़े आय के प्रवाह को तथा देश की आर्थिक उन्नति अथवा अवनति को बता सकते हैं। अतः १८७० में उन्होंने राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित कुछ आंकड़े इकट्ठे किए और उनसे वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति वार्षिक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आय करीब २० रु० है। इसी के आधार पर उन्होंने 'भारत की आवश्यकताएं और उसके साधन' नामक एक निबन्ध 'दी ईस्ट इण्डिया एसोसियेसन' के सामने १८७० में पढ़ा। इसमें उन्होंने सही तौर से बताया था कि भारत दिन-प्रति दिन गरीबी की ओर अग्रसर होता जा रहा है। राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन में दादाभाई ने देश की एक दो मुख्य फसलें, जिले की सारी कृषि भूमि, प्रति एकड़ उपज तथा उपज की कीमत आदि बातें मुख्य तौर पर ध्यान में रखी। इन्हीं अधूरी सी बातों को लेकर एक सज्जन एफ. सी. डानवर्स ने दादभाई नारौजी के प्राक्कलन की आलोचना की तथा कमियां बताई। मगर दादाजी ने उत्तर में कहा कि अन्तिम परिणाम जो आंकड़ों से निकलते हैं, सही ही होंगे। रेलगाड़ियों के विषय में दादाभाई नौरोजी कहा करते थे कि ये किसी देश के भौतिक उत्पादन में अप्रत्यक्ष रूप से ही सहायता करती है न कि प्रयत्क्ष रूप से। वे यह भी कहा करते थे कि सरकारी भण्डार, स्वयं न तो मुद्रा और न भोजन या अन्य भौतिक वस्तु ही पैदा करता है।

दादा भाई नारोजी के विचारों में आन्तरिक व्यापार देश में स्थित सम्पति को नहीं बढ़ाता है। आन्तरिक व्यापार तो केवल सम्पत्ति का वितरण विभिन्न लोगों में करता है। हां, विदेशी व्यापार देश की वार्षिक आय को बढ़ावा देता है। मगर उस समय के अंग्रेजी शासन के नियम इस क्षेत्र में भी भारत को अभाग्यशाली बनाते हैं, क्योंकि वे विदेशी व्यापार के लाभ के साथ-साथ वार्षिक उत्पादन का भी कुछ हिस्सा देश के बाहर ले जाते हैं। दादा भाई का विचार था कि यदि समस्त देशों के कुल विदेशी व्यापार को लिया जाय तो दुनियां के उत्पादन में विदेशी व्यापार कुछ बढ़ावा नहीं देता— क्योंकि दुनियां के लिए विदेशी व्यापार का स्वरूप वही होता है जो एक देश के लिए आन्तरिक व्यापार का। उनका सिद्धान्त था कि देश की आय में उच्चावचन या कमी वेशी का कारण है उसके उत्पादन के साधनों में कमी या अधिकता आना। यदि भौतिक आय आवश्यकताओं की अपेक्षा कम है तो देश के उत्पादन और क्षमता में गिरावट होगी।

दादा भाई नारोजी ने बढ़ते हुए सैनिक खर्च की निन्दा की और बताया कि देश के लिए यह हानिकारक है। वेब्ली कमीशन के सदस्य के रूप में उन्होंने कहा कि इंगलैण्ड को को ईमानदारी के साथ जो कुछ उसने भारत से लिया है वापस दे देना चाहिए। बड़े आश्चर्य की बात है कि नारोजी ने युद्ध खर्च के आंकड़े तक प्रस्तुत किए थे। सरकारी कर्ज के विषय में वे कहा करते थे कि यह तो राजनैतिक बोझा है न कि इसका स्वरूप व्यापारिक कर्ज से मेल खाता है। यह भारत पर जर्दस्ती थोपा गया है। और इसका कारण भी दूषित शासन ही है। यदि भारत को उसके उत्पादन की ठीक सी कीमत निर्धारित करके स्वतन्त्रता (आर्थिक) दे दी जाय तो उसे किसी की प्रकार के कर्ज की आवश्यकता नहीं है। ये सारे झगड़े गरीबी के हैं जिसके लिए शासकीय अधिकारी नहीं, बल्कि शासन-प्रणाली भी उत्तरदायी है।

करों के क्षेत्र में दादा भाई नारोजी 'समानता का सिद्धान्त' के पक्ष में थे और सरकारी खर्च की हर संभव कटौती का स्वागत करते थे। उस काल में कर भारी थे और असमान रूप से लगाये गये थे। दादा भाई नारोजी ने इसका कड़ा विरोध किया और अपने विचार के समर्थन में कई सरकारी भाषण दिए तथा अन्य आंकड़े भी प्रस्तुत किए। उन्होंने भारी करों की वजह से राजनैतिक अराजकता फैलने की संभावना सरकार के सामने रखी। उन्होंने यह भी बताया कि स्वदेश वासियों की सरकार हो तो इन करों से कुछ लाभ हो सकते हैं, पर विदेशियों की सरकार होने से कोई भी लाभ नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में दादा भाई नारोजी मिल, मार्शल आदि क्लासिकल (पुराने) अर्थशास्त्रियों से प्रभावित थे। इसी लिएउनका विश्वावास था कि श्रम और उत्पादन के अन्य साधन देश में तो गतिशील होते रहते है मगर वे दूसरे देशों के साथ गतिशील और आन्तरिक कीमतें उत्पादन की लागत से सीधा सम्बन्ध रखती है तथा भुगतान के समाचार केवल व्यापार प्रकरणों में ही होते है। इन्हीं सिद्धान्तों की सहायता से दादा भाई ने भारतीय आयात और निर्यात का लेखा बनाया तथा सही स्थिति देश व सरकार के सामने रखी।

(शेष पृष्ठ ६६ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत में अलुमीनियम उद्योग

उत्तर प्रदेश में दरियों के लिए प्रसिद्ध मिरजापुर नगर से लगभग १०० मील दूर भारत के सामान्य गांवों की तरह शान्त, सुषुप्ति ग्रस्त, एक रस, जीवन में मग्न पिपरी गांव है। चारों ओर घने जंगलों से आवृत इस गांव ने अब बहुत सक्रिय रूप धारण कर लिया है। कई औद्योगिक प्रवृत्तियों के कारण आस-पास का जीवन मुखरित हो उठा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां विशाल रिहांद बांध बनाया है। इस बांध के पीछे एक बहुत बड़ा गोविन्द वल्लभ पंत सागर के नाम से जलाशय बना है। यह भारत में मानव-निर्मित सबसे बड़ी झील है। इसमें ८६ लाख एकड़ फुट पानी समा सकता है और इस पानी का फैलाव १८० वर्गमील होगा। रिहान्द बिजली घर की क्षमता २ लाख ५० हजार किलोवाट है।

जिन उद्योगों ने यहां कायाकल्प किया है, उनमें प्रमुखतम अलुमीनियम उद्योग है। बांध से तीन मील दूर भारत के उद्योग पति बिडला बन्धुओं ने अमेरिका के काइजर इंडस्ट्रीज के सहयोग से "हिन्दुस्तान एलुमीनियम कारपोरेशन लिमिटेड" कारखाना खोला है। अमेरिकी सरकार ने इसके लिए कुल मिलाकर ७.५ करोड़ रु० के ऋण दिये हैं। इस समय कारखाने का उत्पादन क्षमता २०,००० टन वार्षिक है किन्तु शीघ्र ही यह क्षमता बढ़कर ५०,००० टन होने वाली है।

तीन समस्याएं और उनका हल

सबसे पहले १९५६ में इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया और एलुमीनियम प्लांट लगाने का निश्चय किया गया। एक भारी उद्योग को चलाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, कच्चे माल के साधन, बिजली की उपलब्धि और यातायात। इन तीनों दृष्टियों से रिहांद बांध का क्षेत्र समुचित पाया गया। एलुमीनयम के लिए सर्वाधिक आवश्यक बाक्साइट बड़ी मात्रा में विन्ध्य क्षेत्र में पाया गया। ५५,००० किलोवाट तक की बिजली रिहांद बांध से मिल सकती थी। रेलवे मंत्रालय ने यह आश्वासन दे दिया कि १९६२ तक इस स्थान को रेलवे-लाइन

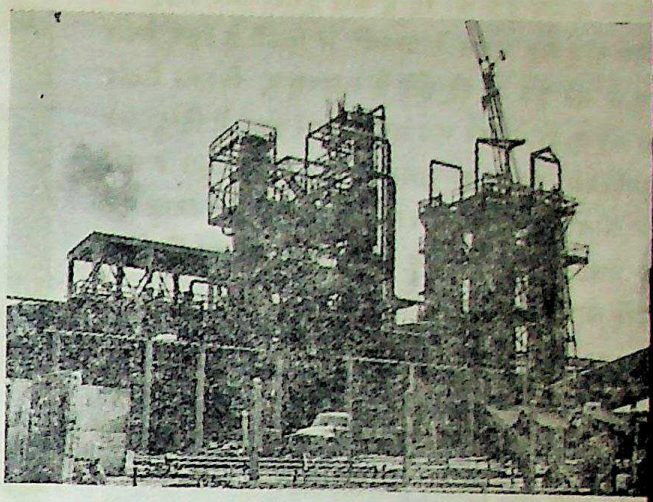

हिन्दाल्को अलुमिनियम संयत्र। यह कारखाना तीसरी योजना में अलुमीनियम लक्ष्य का २५ प्रतिशत तैयार करेगा।

से सम्बद्ध कर दिया जाएगा।

१९६० के प्रारम्भ में इस क्षेत्र के विशाल और घने जंगलों की सफाई प्रारम्भ हो गयी। पर वहां कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी। काम करने वालों के लिए एक झोंपड़ा तक न था। आवास, परिवहन और संचार—तीनों ही बड़ी प्रबल समस्याएं थीं। प्रारम्भ में बम्बई और कलकत्ता से सामान की उपलब्धि होती थी। हजारों की संख्या के कर्मचारियों के लिए मकान, बिजली, पानी आदि की सुविधाएं की गयीं। अधिकांश ने स्वयं ही कच्चे और अस्थायी मकान खड़े कर लिये। इन सब विविध दिक्कतों के बावजूद १९६० अक्तूबर में प्लांट चालू कर दिया गया और २०,००० टन प्रतिवर्ष, एलूमीनयम उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। इस प्रकार दो वर्ष से भी कम समय में भारत में पहली बार इस "श्वेतधातु" का निर्माण प्रारम्भ हो गया।

अलुमीनियम प्लांट के दो विभाग हैं एलुमिनियम और रिडक्शन। अभी रिडक्शन विभाग आयात एलुमिनियम के साथ जारी किया गया है और इस वर्ष सितम्बर में एलुमिनियम के चालू हो जाने की आशा है। विन्ध्य क्षेत्र से बाउक्साइट बड़ी मात्रा में कारखाने में आ रहा है। अब दिन भर दो-तरफा ट्रक चलते रहते हैं, एक और राबर्ट्सगंज से रेणुकूट तक बाउक्साइट और एलु-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नियम के भरे ट्रक आ रहे हैं और दूसरी ओर रेणुकूट से
रेट्स गंज तक भारत के बाजारों में बिकने के लिए तैयार
ल से भरे ट्रक जा रहे होते हैं। सचमुच, विशाल रिहांद
ध की छाया में अब एक नया नगर रेणुकूट में हिन्दुस्तान
लुमनियम कंपनी का उभर रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी
ले औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़े हुए हैं। उनका एक
त्र धंधा कृषि ही है। इस उद्योग के कारण इन जिलों के
ारों लोगों को रोजगार मिल गया है।

ोजना के लक्ष्य

तीसरी योजना में अलुमीनियम का लक्ष्य ८२,५०० । है। इस प्लांट द्वारा देश की लगभग २५ प्रतिशत ावश्यकताएं पूरी होंगी। इस कारखाने के ५०,००० टन विस्तार के लिए भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी । तब इस कारखाने की क्षमता ५७,५०० टन प्रति वर्ष क की हो जाएगी। इस 'बृहत् परियोजना' के लिए कार-ाने के संचालक अपना "थर्मल प्लांट" लगाने का विचार रहे हैं और इसका लाइसेंस शीघ्र मिल जाने की आशा । यहां पर एक "रोलिंग मिल" भी लगाने का निश्चय या गया है। इसके आगामी सितम्बर मास से चालू हो ने की सम्भावना है। तब ए. सी. एस. आर. की तारें ार चादरें यहीं बनने लगेंगी।

अलुमीनियम का यह कारखाना भारत में और दक्षिण-ी एशिया में सबसे बड़ा है।

त्पादन व्यय

अलुमीनियम को वैज्ञानिक "श्वेतधातु" कहते हैं। यह लौह धातु हैं। १९वीं सदी से पहले मानव ने इसका ोग नहीं किया था। पृथ्वी की परतों में ८० प्रतिशत इ धातु मिला हुआ होता है। इसके एक पौंड उत्पादन में ले लगभग २५०० रु० व्यय होते थे और १९वीं सदी अन्त तक यह राशि कम होते-होते १ रु० ५० न. पै. ते पौंड तक पहुँच गयी थी।

भारत में प्रथम योजना काल में इस उद्योग का थोड़ा विस्तार हुआ था, पर दूसरी योजना में मार्के की उन्नति ई। १९६०-६२ में इन गाट की उत्पादन क्षमता लगभग ७,५०० टन और सेमिस की ४४,२०० टन थी। तीसरी ोजना के अन्त तक इनगाट का लक्ष्य १,५०,००० टन के

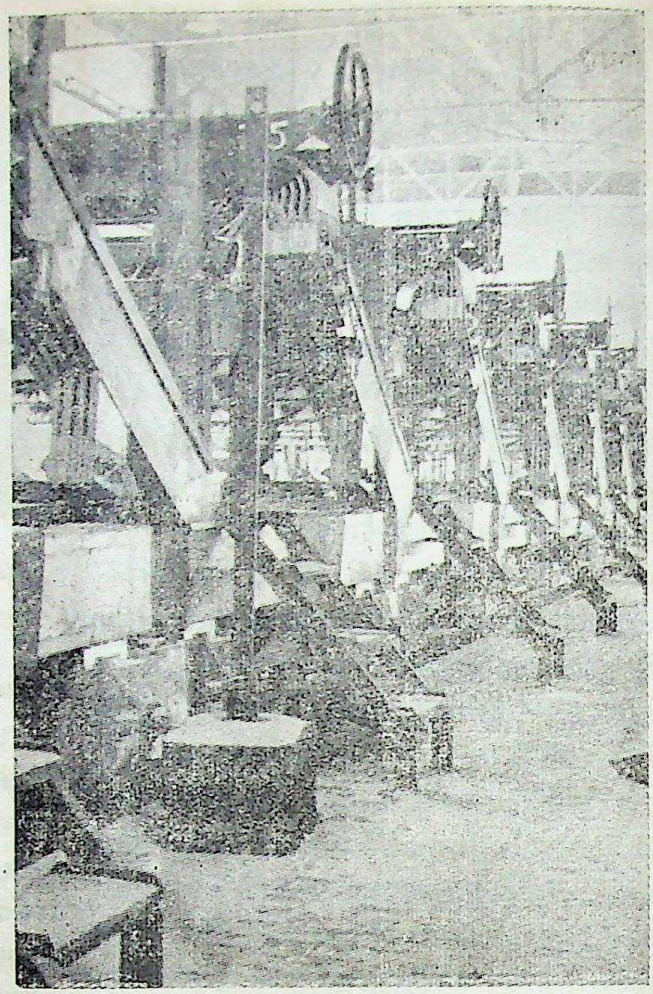

हिन्दालको के इस यंत्र में अलुमिनियम के ठोके बनाये जा रहे हैं।

लगभग है।

भारत में इस धातु के उत्पादन के विशाल स्रोत हैं। बौक्साइट, आधुनिक अनुमान के अनुसार, भारत में २५ करोड़ टन तक विद्यमान है। औद्योगिक वस्तुओं के निर्माण में अलुमीनियम का अब बहुत प्रयोग होने लगा है। तांबा और जिंक के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का बड़ी मात्रा में खर्च होता है। उसे बचाने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योगों के अतिरिक्त तांबा और जिंक का प्रयोजन किया जाए। इन दोनों का स्थान अलुमीनियम ही ले सकता है। इससे अलुमीनियम का प्रयोग अधिक मात्रा में होगा।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१९५६ और १९६० में भारत में अलुमीनियम का विभिन्न उद्योगों में किस प्रकार प्रयोग हुआ, यह निम्न तालिका से स्पष्ट होता है—

उद्योग	टनों में १९५६	टनों में १९६०
बिजली उद्योग	८,९८०	१६,०००
घरेलू और व्यापारी सामान	११,६५०	११,०००
यातायात	२,३५०	७,०००
इमारत और निर्माण	४८०	३,०००
बैंक के काम और पैकिंग	२,५८०	३,०००
खाद्य और खेत	१५	१,०००
अन्य प्रयोग	१,३४५	४,०००
योग	२७,४००	४५,०००

अलुमीनियम का आयात

भारत में अलुमीनियम की जितनी मांग है, उत्पादन उससे बहुत कम है। इस कमी को पूरा करने के लिए इसका विदेशों से आयात करना पड़ता है। १९६१ में करीब ८ करोड़ रु० का अलुमीनियम आयात किया गया। इसलिए इसके प्रयोग पर रुकावट लगानी पड़ी है। ऐसा अनुमान है कि भारत में इस समय उपलब्ध अलुमीनियम से केवल लगभग ५५ प्रतिशत आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं, बाकी के लिए आयात पर निर्भर करना पड़ता है। पहले अलुमीनियम का प्रयोग, मुख्यतः रसोई की धातु के रूप में ही होता था, अब विभिन्न उद्योगों में इसका महत्व पूर्ण स्थान बनता जा रहा है। भारत में प्रति व्यक्ति अलुमीनियम का प्रयोग, विश्व में, सबसे कम है, अर्थात् १९६१ के अनुसार ०.२ पौंड, जबकि अमेरिका में २७ पौंड, ब्रिटेन में १५ पौंड, पश्चिम जर्मनी में १३.३ पौंड, स्वीडन में ११.९ पौंड, कनाडा में ११.५ पौंड।

व्यापारिक दृष्टि से अलुमीनियम पर कम खर्च पड़ता है। लोहे के स्थान पर इस धातु के प्रयोग से ५० प्रतिशत भार की बचत होती है। रेलवे मंत्रालय के खोज, डिजाइन और स्तर संगठन के अनुसार, अलुमीनियम के रेल डिब्बे लकड़ी व लोहे से बहुत हल्के होते हैं, इसलिए उतने ही ईंधन से अधिक रेल डिब्बों को ले जाया सकता है और इस प्रकार अधिक बोझ ले जाने से आय में वृद्धि हो सकती है। जहां अधिक लम्बी रेलगाड़ी ले जानी संभव नहीं, वहां गति में तेजी लायी जा सकती है और इससे इंजिन व रेल-पटरी पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा।

अत्यन्त शुभकामनाओं के साथ

दि न्यू ग्रेट ईस्टर्न स्पि. एंड वीविंग कम्पनी लिमिटेड

१५ ए, हार्निमन सरकल
फोर्ट बम्बई-१

निर्माता

सूती कपड़े और सूती तथा स्टेपल फाइबर सूत के रँगीन और ब्लीच किये कपड़े, लांग क्लाथ माजरी, शीटिंग, रँगीन पापलिन, रंगीन इटालियन, ब्लीच्ड मरसिराइज्ड लेनो :

तार का पता—"न्यूग्रेट" टेलि. नं. २५१२१८

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तटस्थ-नीति से भारत को आर्थिक लाभ

श्री जी० एस० पथिक

●

कुछ अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों का यह मत है कि भारत को कम से कम आर्थिक क्षेत्र में अवश्य ही पश्चिमी देशों के गुट में शामिल हो जाना चाहिए। पर पूर्व और पश्चिम के राजनीतिज्ञों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि निरपेक्ष तटस्थ राष्ट्रों का अस्तित्व और उनकी तटस्थ नीति ने संसार में शान्ति कायम रखने में बड़ी मदद की है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि राष्ट्र के अपने स्वार्थ की दृष्टि से आर्थिक तटस्थता की यह नीति हमारे लिए बड़ी कारगर सिद्ध हुई है। यह भी कहा जाता है कि यदि भारत पश्चिमीय दल में होता तो अमेरिका और पश्चिमी देश बहुत बड़ी आर्थिक सहायता देते, विदेशी पूंजी का उन स्रोतों में विनियोजन होता जिन्हें हम अभी तक छू नहीं सके। हमारे सामने विदेशी मुद्रा का संकट न पैदा होता। इन तर्कों पर विचार करने के पूर्व हमें विदेशी मुद्रा के स्रोतों पर ध्यान देना चाहिए।

स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य

भारत ने अपने लोकतंत्र के ढांचे में आर्थिक विकास को प्रमुख स्थान दिया। वह यह जानते हुए भी इस दिशा में आगे बढ़ा कि देश में पूंजी निर्माण के स्वल्प साधन हैं और साथ ही जनसंख्या का भारी दबाव है। हमारे विकास का कार्यक्रम मोटे तौर पर समाजवादी रूप में निर्धारित हुआ है। यह सही है कि हमारी सिद्धियां प्रभावोत्पादक नहीं हुई किन्तु हमारे कार्यक्रमों ने पश्चिमी देशों के इस ख्याल को जबर्दस्त धक्का दिया कि एशिया के लोग कुछ करने की आकांक्षा नहीं करते या आर्थिक विकास की ओर बढ़ने का उनमें कुछ माद्दा नहीं है। यह विचारधारा भारत के लिए चुनौती थी। जहां तक इस देश के लोगों का संबंध है, उन्होंने यह अनुभव किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए आर्थिक विकास का होना अत्यन्त आवश्यक है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि इस प्रकार के आर्थिक विकास द्वारा ही भारत की स्वतंत्रता और सुरक्षा कायम रह सकती है। यह होने पर ही हम दो महती शक्तियों के घेरे में जाने और उनके कल-पुर्जे बनने से बच सकते हैं। भारत अपने आर्थिक विकास की दिशा में इसी विचारधारा से आगे बढ़ा।

बुनियादी उद्योगों के निर्माण में

आर्थिक विकास की हमारी योजनाएं बड़े परिमाण में पूंजीगत विकास की ओर बढ़ी। द्वितीय और तृतीय पंच-वर्षीय योजनाओं में बुनियादी उद्योगों को विशेष स्थान दिया गया। इन बुनियादी उद्योगों के विकसित होने पर देश तेजी से आर्थिक विकास की ओर बढ़ सकता है, इन उद्योगों के लिए न्यूनतम विदेशी मुद्रा प्रयोजनीय है, इस की आवश्यकता अल्पकालीन समस्या नहीं है। दीर्घ काल से हम इस समस्या का सामना करते आए हैं और आगे भी हमें कुछ समय तक उसका सामना करना पड़ेगा।

यह अभाव इसलिए है कि हम निर्यात व्यापार द्वारा जितनी विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं, उससे अधिक विदेशी मुद्रा की हमें जरूरत पड़ती है। हमारा निर्यात व्यापार जड़वत है। जापान, इंडोनेशिया, सीलोन और पाकिस्तान निर्यात व्यापार बढ़ाने में सफल हुए, किन्तु भारत के निर्यात व्यापार को मक्खी मार गयी। वह बजाय आगे बढ़ने के कई कदम पीछे हटता है। पिछले एक दशक में हमारा आयात प्रतिवर्ष ८०० रुपये का हुआ, किन्तु निर्यात ६५० करोड़ रुपये से ऊपर नहीं चढ़ा। निर्यात और आयात की इस असमानता ने विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पैदा की और इसके लिए विदेशी सहायता लेनी पड़ी।

यह कहा जा सकता है कि देश का सोना एकत्र कर और निर्यात को प्रोत्साहन देकर विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं कम की जा सकती थीं। उस अवस्था में हमें विदेशी सहायता की जरूरत न पड़ती। हमारे निर्यात व्यापार में चाय, जूट और कपड़ा प्रमुख स्थान रखते हैं। इस सबका विदेशी बाजार हैं गला घोटू मुकाबला है। संसार के बाजार में कपड़े की गिरती हुई मांग है और

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्टाक भारी जमा हैं। इन पदार्थों के निर्यात को बढ़ाना भारी काम है। इसका तुरन्त हल होना आसान नहीं है। बढ़ते हुए औद्योगिक पदार्थों का निर्यात दीर्घकालीन समस्या है। विनियोजन को नया रूप देने पर इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।

सोने के एकत्र होने पर भी हमारी कठिनाई बनी रहती है। सारा सोना एकत्र नहीं हो सकता। अन्तर्राष्ट्रीय दामों के अनुसार भारत में २००० करोड़ रुपए का सोना है। यदि यह सब उपलब्ध हो तो उससे हमारी एक योजना पूरी हो सकती है। किन्तु जिस ढंग से और जिस संस्थागत ढांचे में हमारा आर्थिक विकास हो रहा है, उसमें विदेशी सहायता का प्राप्त होना अनिवार्य है।

गत काल में भारत का विदेशी सहायता प्राप्त करना महान् आश्चर्यजनक है। यही एक देश है, जिसे संसार के सब देशों से आर्थिक सहायता मिली। यह क्यों? इसलिए कि उसकी स्वतंत्र और तटस्थता की नीति रही। यह कहना चाहिए कि अमेरिकन राष्ट्रपति केनेडी के प्रशासन ने इस मामले में बड़ी दूरदर्शिता प्रकट की, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी, विशेष रूप से विश्व बैंक ने। विश्व बैंक के डायरेक्टर श्री ब्लैक के तत्वावधान में भारत ने अपनी निरपेक्षता (तटस्थता) की नीति द्वारा एक नया प्रोग्राम बनाया। भारत के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता देने के कार्यक्रम में श्री ब्लैक ने "एड इंडिया क्लब" की स्थापना की। इसमें वे देश शामिल हुए जो भारत के महाजन थे। इन देशों ने विदेशी मुद्रा की समस्या हल करने के लिए भारत को आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया।

आर्थिक सहायता का प्रतीक

विदेशी सहायता के अंकों पर सरसरी तौर पर नजर डालने से यह स्पष्ट होता है कि पंचवर्षीय योजना के आरंभ से दिसम्बर १९६१ तक भारत को इस प्रकार विदेशी सहायता मिली—

	करोड़ रु०
अमेरिका	१००४.६
ब्रिटेन	१८०.२०
कनाडा	११८.२६
पश्चिम जर्मनी	२०६.६७
जापान	६५.७१

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक

आई० डी० ए० फंड और आस्ट्रेलिया से भी सहायता मिली।

सोवियत रूस	३८३.९६
यूगोस्लाविया, रूमानिया, चेकोस्लावाकिया और पोलेंड	५३.४५

पूर्वीय देशों की सहायता

सोवियत रूस और अन्य योरोपियन देशों की सहायता रकम की दृष्टि से प्रभावोत्पादक न प्रकट हो, किन्तु जिन कामों के लिए यह सहायता मिली, वे अपनी अहमियत रखते हैं। यह सहायता उन बुनियादी उद्योगों के निर्माण में लगेगी, जिनके निर्माण से हमारे आर्थिक विकास की उत्तरोत्तर वृद्धि सम्भव है। इतना ही नहीं, हमारे अस्त्र-शस्त्र भी इनमें तैयार हो सकते हैं। पूर्वीय देशों की आर्थिक सहायता का भारी अंश महत्वपूर्ण स्रोतों के विकास में लगा है। इस्पात, तेल, पूंजीगत मशीनों के निर्माण के महान् उद्योग तथा अन्य बुनियादी उद्योग खड़े हुए। इससे देश में बुनियादी विकास की नींव पड़ी। देश में तकनीकों का अभाव होने के कारण यदि पश्चिमीय क्षेत्र से ये उद्योग खड़े किए जाते तो उन पर विदेशी एकाधिकार कायम होने का खतरा था। फिर उनसे जिन आधारों पर समझौते होते, तो उससे हमारा अधिक शोषण होता।

पूर्वीय साम्यवादी देशों की सहायता स्वल्पतम ब्याज पर प्राप्त हुई। उनके ब्याज की दर २॥ प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ी। इतना ही नहीं, इस सहायता का भारी अंश हमारे निर्यात पदार्थों द्वारा चुकाया जा सकेगा। यह मानना पड़ेगा कि रूस ने कम्युनिस्ट देशों को जो सहायता दी, उनने बाद सबसे बड़ी सहायता पाने वाला देश भारत है। यदि भारत तटस्थता की नीति का अवलम्बन न करता, तो उसे यह मूल्यवान सहायता उपलब्ध न होती, जिसने उसकी अर्थव्यवस्था का बुनियादी विकास किया।

विश्व बैंक की सहायता

भारत ने तटस्थता की नीति द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आर्थिक सहायता प्राप्त की। इससे उसे सहायता देने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वाले देशों से कम रकम मांगनी पड़ी। यदि उसे संस्थाओं से पूरी सहायता मिल जाती, तो वह पश्चिमीय देशों से सहायता की मांग न करता। विश्व बैंक शुरू में १९५६ तक योरुप के विकसित देशों को सहायता देता रहा। इसी वर्ष उसने एशिया की ओर अपना कदम मोड़ा। १९६१ तक विश्व बैंक ने ३७३८.१ मिलियन डालर के कुल ऋण में एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के देशों को २७३८.१ मिलियन डालर का ऋण दिया। इसमें एशिया को १९३८.३ मिलियन डालर का ऋण मिला। इसमें १९६१ तक भारत का हिस्सा ७००.६१ मिलियन डालर का है। बैंक के इकरार के अनुसार आई० डी० आई के सहित तीसरी योजना के लिए १९६१-६२ और १९६२-६३ के लिए कुल ऋण ४०० करोड़ डालर की रकम का हैं। एक संस्था की अकेले यह सहायता सचमुच महत्व रखती है, जो बिना किसी बंधन के हैं और जिसमें शोषण की कोई पेचीदगियां नहीं हैं।

गैर तटस्थ देशों का विकास

दूसरी ओर जिन देशों की नीति अ-तटस्थता की है, उससे उन्हें उतना लाभ नहीं पहुँचा, जितना लाभ भारत ने तटस्थता की नीति अपना कर हासिल किया। इस सम्बन्ध में गैर तटस्थ देशों के आर्थिक विकास के आंकड़े प्रत्यक्ष सबूत देने वाले हैं। पाकिस्तान और अन्य गैर तटस्थ देशों में बहुत थोड़ा आर्थिक विकास सम्भव हुआ। पाकिस्तान को भारी सहायता अमेरिका के "म्यूच्युल सिक्यूरिटी एक्ट १९५४" के अन्तर्गत मिली, जो पदार्थ, सेवाएं और वित्तीय रूप में है। अन्य सहायता सैन्य सम्बन्धी है। इस सैनिक सहायता ने इन देशों को बुनियादी उद्योग खड़े करने का अवसर नहीं दिया।

पाकिस्तान को सहायता

पाकिस्तान को बड़े परिमाण में सहायता द्विपक्षीय इकरारनामे के अन्तर्गत मिलनी शुरू हुई। यह इकरारनामा ११ जनवरी १९५४ को लिखा गया, यद्यपि इससे भी पूर्व स्वतंत्र रूप में पाकिस्तान को सहायता मिलती रही। १९६१ तक यह सहायता १००० मिलियन डालर की थी। इसमें सैनिक सहायता, संभवतः, शामिल नहीं है। पदार्थों के रूप में ५०८.४१ मिलियन डालर और योजनाओं के लिए ४२५.१२ मिलियन डालर सहायता दी गयी। इसमें ७६.१२ मिलियन डालर सुरक्षा सहायता भी सम्भवतः शामिल है। इसके सिवाय टैक्नीकल सहयोग, विकास सहायता और क्षेत्रीय सहायता के रूप में १३४.०० मिलियन डालर की सहायता पाकिस्तान को उपलब्ध हुई। योजना का व्यय २२५.८० मिलियन डालर है अर्थात् कुल सहायता का २२.५ प्रतिशत अंश उद्योगों के वास्तविक विकास में लगा। योजना का आरम्भ १९५८ से हुआ। १९५९ में उसकी वृद्धि हुई। पचास प्रतिशत रकम का केवल उपयोग किया गया और इसका बहुत अंश अर्थव्यवस्था के विकसित क्षेत्रों में व्यय हुआ। पदार्थों की सहायता से उपभोक्ता पदार्थ खरीदे गए। केवल ८ या ९ मिलियन डालर प्रतिवर्ष मशीनें और कल पुर्जों के खरीदने में व्यय हुए। सुतरां, पाकिस्तान को १००० करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई।

गैर तटस्थता और शस्त्र सहायता

गैर तटस्थता की नीति में यह एक आकर्षण है कि किसी ब्लाक में शामिल होने पर शस्त्रों की सहायता उपलब्ध होती है। उसके लिए गैर तटस्थ देश को कोई व्यय नहीं करना पड़ता है। ऐसा देश महान् शक्ति का अंगीभूत होने पर उसकी छत्र छाया में आता है, उस अगुआ देश की राजनीति उसकी राजनीति होती है, उस अगुआ देश के शत्रु उसके भी शत्रु होते हैं। इस स्थिति में शस्त्र तैयार करने की ओर उसका ध्यान नहीं जाता और कदाचित जाए भी तो बुनियादी उद्योगों के अभाव में वह उन्हें तैयार नहीं कर सकता। पश्चिम जर्मनी की जुदी स्थिति है। वहां शुरू से ही बुनियादी उद्योगों की नींव पड़ी है। इसलिए वह औद्योगिक विकास में अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के समान स्थान रखता है, भले ही राजनीतिक कारणों से उसे शस्त्र तैयार करने की छूट नहीं है। पर भारत अपनी तटस्थता की नीति द्वारा जिन बुनियादी उद्योग तथा इंजीनियरिंग उद्योगों को स्थापित करने में अग्रसर हुआ, उनसे वह सभी अस्त्र शस्त्र तैयार कर सकता है। अन्य उद्योगों की तरह वह शस्त्र निर्माण में भी आत्म निर्भर हो सकता

(शेष पृष्ठ ९८ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

परीक्षोपयोगी लेख :

स्वयं स्फूर्त विकास अवस्था और भारतीय योजना

—रामकृष्ण सिंगी

पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा किये जा रहे आर्थिक विकास का लेखा-जोखा करते समय, अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न अंगों में हो रही प्रगति को तो आंकना ही है; साथ ही, एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न पर भी दृष्टि डालनी है कि यह नियोजित विकास हमारी अर्थ-व्यवस्था को विकास की किस सीमा पर, किस सोपान पर ला खड़ा करेगा।

आर्थिक विकास एक ऐसी सतत विधि है जो दीर्घ-कालीन प्रयासों द्वारा उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विभिन्न अवस्थाओं में होकर अन्तिम स्वरूप ग्रहण करती है। प्रो. रोस्टोव ने आर्थिक विकास की ५ अवस्थाएं निर्देशित की हैं।

१. परम्परागत समाज (Traditional Society)
२. स्वयं स्फूर्त अवस्था के पूर्व की स्थिति—
(Preconditions for Take off stage)
३. स्वयं स्फूर्त विकास अवस्था (Take off Stage- or Self Sustaining growth)
४. परिपक्वता की ओर (Drive to Maturity)
५. अधिकाधिक उपभोग (High mass Consumption)

स्वयं स्फूर्त की परिभाषा और शर्तें

हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय स्वयं स्फूर्त विकास अवस्था तक पहुंचना है।

प्रो० रोस्टोव ने स्वयं स्फूर्त विकास अवस्था की परिभषा यों की हैं—

"यह वह मध्यकाल है जिसमें विनियोजन की दर इस प्रकार बढ़ती है कि वास्तविक प्रति इकाई उत्पादन में वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार प्रारम्भिक विनियोजन वृद्धि से उत्पादन की विधियों तथा राष्ट्रीय आय के प्रवाह में मौलिक परिवर्तन हो जाते हैं। इन मौलिक परिवर्तनों के फलस्वरूप नवीन विनियोजन दर तथा नवीन प्रति इकाई उत्पादन दर का निरन्तर प्रादुर्भाव होता रहता है।"

वे कहते हैं कि प्रत्येक प्रगतिशील राष्ट्र के आर्थिक इतिहास में एक समय (१० से २० वर्षों का) ऐसा आता है जब अर्थ व्यवस्था में ऐसे आधार भूत परिवर्तन और सुधार होते हैं कि आर्थिक विकास स्वयंभू हो जाता है। इस अवस्था को वे "टेक आफ स्टेज" की संज्ञा देते हैं।

आज के सभी प्रगतिशील राष्ट्र इन्हीं विकास अवस्थाओं से होकर गुजरे हैं।

स्वयं स्फूर्त अवस्था प्राप्त करने के लिए दो प्रमुख आर्थिक शर्तों का पूर्ण होना आवश्यक है—

(१) अधिक पूंजी निर्माण (२) जनसंख्या पर रोक—प्रो० रोस्टोव के अनुसार उक्त दोनों आवश्यकताओं के साथ-साथ अधिक व कुशल उत्पादन व्यवस्था और साहसियों की उपस्थिति भी अत्यन्त आवश्यक है।

किन्तु पिछली दशाब्दी में यूरोप में हुई आर्थिक प्रगति ने टेकनालाजी और अधिक उत्पादकता के महत्व पर प्रकाश डाला है। अधिक पूंजी निर्माण और जनसंख्या पर रोक आवश्यक तो हैं किन्तु पर्याप्त नहीं। उनके साथ ही उत्पादन की रीतियों और विधियों में नये और सुधरे हुए तरीके लगाये जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है ताकि प्रति मनुष्य प्रति घंटे उत्पादन अधिकाधिक और न्यूनतम लागत पर किया जा सके। पुराने और अकुशल उत्पादन संस्थानों को बन्द कर दिया जाकर नये और श्रम संचयक शक्ति संचालित उत्पादन प्रसाधन प्रयोग में लाये जाने चाहिए। साथ ही बाजार अनुसंधान, लागत लेखन और विशेषज्ञ प्रबन्ध-कर्त्ताओं द्वारा समूची उत्पादन व्यवस्था को पूर्ण वैज्ञानिक रूप दिया जाना आवश्यक है।

यह भी आवश्यक है कि देश की अर्थ-व्यवस्था में ऐसे संगठन सम्बन्धी परिवर्तन किये जायँ कि राष्ट्रीय आय का एक विशिष्ट भाग अपने आप पूंजीगत उद्योगों में विनियोजित होने की ओर प्रवृत्त हो जाय। वैसे ही, सरकार की वित्तीय नीति के द्वारा अधिकाधिक बचत का प्रयास

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

किया जाना चाहिये। इतना सब कुछ कहा जाने के बाद भी यह तो मान ही लिया जाना चाहिये कि अधिक पूंजी निर्माण शीघ्र आर्थिक विकास की सर्व प्रमुख आवश्यकता है, विशेषतः, अर्ध विकसित और अविकसित राष्ट्रों में।

अधिक पूंजी निर्माण के लिये देश की राष्ट्रीय आय को अधिकाधिक बढ़ाकर उसका अधिकाधिक अंश विनियोजित किया जाना चाहिए। अर्थशास्त्रियों का मत है कि राष्ट्रीय आय का कम से कम ५ प्रतिशत तो प्रतिवर्ष विनियोजित होना ही चाहिये ताकि स्थिर अर्थ व्यवस्था की स्थिति रहे। क्योंकि जनसंख्या लगभग १ से १॥% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ती है और यदि पूंजी और उत्पादन के अनुपात को ३.१ लिया जाय तो इस विनियोजन से लगभग १॥% राष्ट्रीय आय की वृद्धि होगी और नयी जनसंख्या के लिये आवश्यक साधन जुट जायेंगे; अर्थ-व्यवस्था स्थिर ही रहेगी। कहना न होगा कि उन्नति और विकास के लिये यह आवश्यक है कि इससे कहीं अधिक पूंजी का प्रतिशत विनियोजित किया जाय।

राष्ट्रीय आय में कम वृद्धि

भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने से पूर्व भारतीय अर्थ व्यवस्था इंग्लैंड की दो शताब्दी पूर्व की अर्थ व्यवस्था के समान थी जब औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी। जनसंख्या ग्रामीण थी और कृषि का महत्व अत्यधिक। प्रथम योजना के प्रारम्भ के समय राष्ट्रीय आय १९६० ६१ के मूल्यों पर १०,२४० करोड़ रु. थी और उसका लगभग ५% भाग पूंजी निर्माण के काम आ रहा था। स्पष्ट है कि अर्थ व्यवस्था स्थिर-प्राय थी। प्रथम योजना के अन्त तक राष्ट्रीय आय १८% बढ़ी और उसका लगभग ७-८% भाग विनियोजित होने लगा। दूसरी योजना के अन्त तक विनियोजन की यह दर बढ़ाकर ११.५% कर दी गई और राष्ट्रीय आय १४,५०० करोड़ रु. हो गई। इस प्रकार पिछले दशक में भारत की राष्ट्रीय आय में ४२% की वृद्धि हुई। इस वृद्धि की तुलना संसार के अन्य देशों में इसी काल में हुई वृद्धि से करने पर अत्यन्त महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अन्य देशों में वृद्धि का प्रतिशत यों था—

आस्ट्रिया	८२%	इटली	७७%
बेलजियम	३३	नार्वे	४०
डेनमार्क	३९	ब्रिटेन	२९
फ्रांस	५३	रूस	१६४
पश्चिमी जर्मनी	१०६	हंगरी	८५
ग्रीस	१८९	रूमानिया	१६२
पोलैण्ड	११४	यूगोस्लाविया	१३५

प्रथम और द्वितीय योजना काल में कुछ महत्वपूर्ण संगठन सम्बन्धी परिवर्तन किये गये जो स्वयं-स्फूर्त-विकास अवस्था लाने में सहायक होंगे। उदाहरणार्थ — भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, सामुदायिक विकास योजनाएं, देश का शीघ्रगामी उद्योगीकरण तथा आधार भूत उद्योगों की स्थापना, रोजगार सुविधाओं और अवसरों में वृद्धि, इम्पीरियल बैंक और जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण तथा स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन और कई वित्तीय कारपोरेशनों की स्थापना इत्यादि।

पूंजी-विनियोजन के लक्ष्य

तृतीय योजनाकाल में राष्ट्रीय आय को लगभग रु० १४,५०० करोड़ से बढ़ाकर रु० १९००० करोड़ करना है। चौथी योजना के अन्त तक रु० २५,००० करोड़ और पांचवी के अन्त तक इसे रु० ३३,००० करोड़ से ३४,००० करोड़ रु० तक करने का अनुमान है। यह प्रस्ताव है कि अगले दशक में राष्ट्रीय आय को लगभग ६०% से बढ़ा दिया जाय। वैसे ही प्रति व्यक्ति आय आज के रु० ३३८ से बढ़कर तीसरी योजना के अन्त तक रु० ३८५ या १७% अधिक और चौथी योजना के अन्त तक रु० ५०० के लगभग याने ५०% अधिक करनी है। विनियोजन की दृष्टि से लक्ष्य है कि राष्ट्रीय आय का लगभग १४ से १५% तक विनियोजित होना चाहिये। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि पिछले दशक में कुल विनियोजन—प्रथम योजना में रु० ३,३६० करोड़ और दूसरी योजना में रु० ६,७५० करोड़, १०,११० करोड़ रु० का था और तीसरी योजना के ५ वर्षों में रु० १०,४०० का विनियोजन करना है। स्पष्ट है कि पिछले दशक में जितना पूंजी निर्माण हुआ उतना ही हम करने जा रहे हैं तीसरी योजना के ५ वर्षों में।

किन्तु पूंजी निर्माण की समस्या पर पृथक रूप से विचार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही (१) पूंजी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सारे परिवार के लिए

डी सी एम

के उच्च कोटि के कपड़े

पापलिन •	छींटें •	मलमल
लिनो •	लान्स •	लट्ठा
साड़ियाँ •	शर्टिंग्ज •	ड्रिल्स
शर्टिंग्ज •	सजावट के कपड़े •	तौलिए

एवं बेड शीट्स आदि

आकर्षक रंगों, शेडों और बनावटों में

डी सी एम के सभी रिटेल स्टोर्स में प्राप्य है ।

डी सी एम वस्त्रोत्पादन में श्रेष्ठता का प्रतीक

दि दिल्ली क्लॉथ एण्ड जनरल मिल्स कं० लि०

दिल्ली

JWT : DCM : 2290

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और उत्पादन के अनुपात और (२) जनसंख्या में वृद्धि को दृष्टिगत रखना होगा। पूँजी और उत्पादन के अनुपात से पूंजी की उत्पादनशीलता का पता लगता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अब भी राष्ट्रीय आय का लगभग आधा भाग कृषि से उत्पन्न होता है जो प्रकृति की सारी अनिश्चितताओं के साथ अनिश्चित है। ऐसी स्थिति में पूंजी और उत्पाद का अनुपात अत्यन्त अस्थिर होता है, उद्योग प्रधान देशों की भांति निश्चित और स्थिर नहीं।

पहली दो योजनाओं की समयावधि में कुल रु० १०,११० करोड़ के विनियोजन पर राष्ट्रीय आय में रु० ४,२६० करोड़ की वृद्धि प्राप्त की गई। इस प्रकार पिछली दशाब्दी का पूंजी और उत्पादन का अनुपात आता है—२.३८:१। तीसरी योजना में कुल रु० १०,४०० करोड़ के विनियोग पर राष्ट्रीय आय को रु० ४,५०० से बढ़ाना है। यों विनियोग और वृद्धि का अनुपात लगभग २:३१:१ होगा। स्पष्ट है कि हमारा अनुमान अब अधिक कुशल व तीव्रगामी उत्पादन करने का है। पिछली दो योजनाओं के अनुपात पृथक्-पृथक् रूप से—प्रथम योजना—२.०६:१ और द्वितीय योजना ३:२९:१ थे। प्रथम योजनाकाल में अनुपात के अपेक्षाकृत कम होने का प्रमुख कारण प्रकृति का अनुकूल होना था जो दूसरी योजना में उपलब्ध न हो सका। अब देखना है कि तृतीय योजना में हमारा अनुमान कितना सही बैठता है।

जनसंख्या की वृद्धि—भारी समस्या

जनसंख्या की वृद्धि की समस्या अलग विकराल रूप धारण किये है। पिछले दशक में कुल वृद्धि लगभग ७ करोड़ ७० लाख के आस पास ठहरती है जबकि इसके पूर्व के दशकों में यह वृद्धि कुल ८ करोड़ २० लाख के लगभग थी। अर्थात् पिछले दस वर्षों में लगभग उतनी ही वृद्धि हुई जितनी उसके पहले के दो दशकों में हुई थी। अगले दस सालों याने सन् १९६१ से १९७१ के मध्य जनसंख्या की वृद्धि का अनुमान लगभग १० से १२ करोड़ है और आज से १५ वर्षों बाद अनुमान है कि भारत की जनसंख्या आज की तुलना में लगभग ड्योढ़ी हो जायेगी। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिये जनसंख्या वृद्धि की यह गति एक चुनौती है। आवश्यकता इस बात की है कि इस विकराल समस्या को टालने का हर संभव प्रयत्न किया जाय ताकि देश का आर्थिक विकास सुगम व द्रुत हो सके।

विकास की तरतीब या प्राथमिकताओं के अनुसार प्रथम योजना कृषि प्रधान और द्वितीय उद्योग प्रधान थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना कृषि और उद्योग दोनों में समन्वयकारी योजना है जो दोनों पर लगभग समान जोर देगी। कृषि उत्पादन और खाद्यान्नों में तथा मशीन-निर्माण उद्योगों में तो योजनाकाल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।

यों प्रथम और द्वितीय योजनाकाल में हुई प्रगति के परिणामस्वरूप द्रुत आर्थिक उन्नति का आधार स्थापित हुआ और अब हमारा निश्चय अधिकतम सम्भव पूँजी-विनियोग द्वारा देश को सघन आर्थिक विकास और आत्म-चालित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाना है। वर्तमान संकटकाल ने हमारे संकल्प को दृढ़तर बना दिया है।

उद्योग-व्यापार पत्रिका

देश में उद्योग और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है और आप इससे किस तरह फायदा उठा सकते हैं? देश में क्या-क्या चीजें और कितने परिणामों में कहां कहां बन रही हैं और आप क्या बना कर अच्छी कमाई कर सकते हैं? तरह-तरह के व्यापार की देश-विदेश में क्या दशा है? पंचवर्षीय योजना से हमारी क्या उन्नति हो रही है? ये सभी प्रश्न हैं जिनके उत्तर अवश्य जानने चाहिए और इन सबकी जानकारी जानने का श्रेष्ठ साधन हैं—

उद्योग व्यापार पत्रिका

इसलिए आप ६ रु० भेजकर साल भर के लिए आज ही ग्राहक बन जाइए। नमूना पत्र लिखकर मंगाइए :—

एजेन्टों को भरपूर कमीशन,

पत्रिका विज्ञापन देने का अच्छा साधन है।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुस्तकालय
गुरुकुल कांगड़ी

हमारी सफलता और असफलता

प्रोफेसर ओ० पी० मिश्रा

३१ मार्च १९६१ को द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई और भारत में आर्थिक नियोजन के १० वर्ष पूर्ण हो गये। इस दशाब्दि में सफलताएं भी रही हैं तथा असफलताएं भी। संक्षेप में इस काल की सफलताएं निम्न लिखित हैं :—

आर्थिक नियोजन के कारण देश में विनियोजन की दर में वृद्धि हुई है। पूंजी अब अधिक शर्मीली नहीं रही है। विनियोजन में वृद्धि एक शुभ लक्षण है। प्रसिद्ध अर्थ-शास्त्री प्रो लेविस के मतानुसार आर्थिक प्रगति के निर्धारकों में—आर्थिक उन्नति की इच्छा, ज्ञानका समय और प्रयोग तथा पूंजी का संचय और प्रयोग में, अंतिम निर्धारक अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण होता है। पहली योजना के आरम्भ में कुल विनियोग ५०० करोड़ रुपया प्रति वर्ष होता था लेकिन द्वितीय योजना के अन्त में यह विनियोग १६०० करोड़ रुपये प्रति वर्ष होने लगा।

इस अवधि में राष्ट्रीय वृद्धि ४२% हुई। प्रथम योजना काल में राष्ट्रीय आय में वृद्धि १८% हुई, जबकि लक्ष्य १२०% वृद्धि का ही था। लेकिन द्वितीय योजना काल में राष्ट्रीय आय में वृद्धि २०% ही हुई, जबकि लक्ष्य २५% का था। १९५१ और १९७१ के काल में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि १६% की हुई—२८४) प्रति व्यक्ति १९५०-५१ में और ३३०) रु० १९६०-६१ में।

प्रथम योजना में कृषि को प्राथमिकता प्रदान करने के फलस्वरूप अच्छे बीज, खाद, पुनर्भूग्रहण तथा वर्षा की कृपा के कारण कृषि उत्पादन में ४१% की वृद्धि हुई। कृषि में क्रांति के लिए प्रथम और द्वितीय योजना में अन्य कदम भी उठाये गये। उदाहरणार्थ जमींदारी का उन्मूलन भूस्वामित्व, अधिकारों की रक्षा, भूमि की इकाई पर सीमा, चकबन्दी और सहकारी खेती के सम्बन्ध में जनमत तैयार करते हुए पर्याप्त प्रगति हुई। ग्रामोत्थान के प्रति जागरूकता व्यवहृत की गई। सामूहिक विकास योजनाएं जो प्रधान मंत्री नेहरू के शब्दों में मौन क्रांति है, अब तक ३७७००० ग्रामों को अपनी परिधि के अन्तर्गत ला सकी हैं।

औद्योगिक उत्पादन का निर्देशांक जो १९५०-५१ में १०० था, १९६०-६१ में बढ़कर १९४ हो गया। उद्योग धन्धों के विकास पर बल दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में लोहा इस्पात उर्वरक आदि के अनेकों धन्धे खोले गये। लोक उपक्रम के अन्तर्गत ३ इस्पात कारखाने—दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला—अपना अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिनके कारण ही कभी कभी द्वितीय योजना को 'स्टील प्लान' कह दिया जाता है। उपभोग उद्योगों—वस्त्र उद्योग, चीनी, बाइसकिल, स्कूटर, रेडियो तथा पंखे आदि का विकास हुआ, किन्तु पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन का विकास अपेक्षाकृत मन्द ही रहा।

अतः दशक में विद्युत के विकास पर सार्वजनिक क्षेत्र में ७०५ करोड़ रु० व्यय किये गए। सन् १९५० में विद्युत उत्पादन २३ लाख किलोवाट था, किन्तु इस दिशा में किये गये प्रयत्नों के फलस्वरूप यह उत्पादन १९६०-६१ में ५७ लाख किलोवाट हो गया। यातायात और संचार-साधनों के विकास पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया। गत दशाब्दि में उनके विकास पर १८२२ करोड़ रुपये व्यय हुए। प्रथम और द्वितीय योजनाओं का लक्ष्य रहा है—राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति, हजूर और मजूर की समाप्ति तथा समाजवादी समाज की रचना। दलितवर्गों के उत्थान के लिये—शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, श्रम कल्याण तथा पुनर्वास पर १२८९ करोड़ रुपये व्यय किये गए।

असफलता

भारत की आर्थिक प्रगति प्रतिवर्ष ४% रही है, जबकि इसराईल, ईराक, जापान, प० जर्मनी, ब्राजील और बर्मा आदि की क्रमशः ११%, ९%, ९%, ७.४%, ६% और ६% प्रतिवर्ष रही। यह हमारी बड़ी असफलता है।

अकुशल तथा अल्प उत्पादन ही नहीं, वरन् उत्पादन का वितरण भी सर्वथा असमान रहा है। यद्यपि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट उल्लिखित है कि सभी

(शेष पृष्ठ ८१ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कृषि के संकटकालीन कार्यक्रम

डा० राम सुभगसिंह

राष्ट्रीय संकट घोषित होने के बाद उच्चस्तरीय राष्ट्रीय विकास परिषद ने कृषि को, विशेष कर ऐसे कार्यक्रमों को जिनसे कृषि-उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, बहुत अधिक प्राथमिकता दी है, और केन्द्रीय सरकार ने तृतीय योजना के कार्यक्रमों के अतिरिक्त सात विशेष योजनाएं चलाई हैं और अन्य कार्यक्रमों में कुछ परिवर्तन भी किया गया है। इन योजनाओं का मुख्य केन्द्र-बिन्दु वे क्षेत्र हैं जिनमें तत्काल उपज बढ़ाने की सम्भावना है और जहां तुरन्त उगने वाली फसलें पैदा हो सकें।

इन विशेष योजनाओं में सबसे पहला कार्यक्रम सीमा-वर्ती राज्यों में साग सब्जी की पैदावार को बढ़ाना है। आसाम, पश्चिम बंगाल तथा बिहार की सरकारों ने केन्द्रीय सहायता से १४,५०० एकड़ जमीन में साग-सब्जी लगाने की योजना आरम्भ की है। इस सिलसिले में आसाम में तेजपुर के पास २,००० एकड़ जमीन और पश्चिम बंगाल में सिलिगुड़ी के आस पास १,००० एकड़ जमीन में हरे शाक तथा प्याज, दार्जीलिंग में १,५०० एकड़ जमीन में आलू और बिहार में पुर्णिया, सहरसा और भागलपुर जिलों की १०,००० एकड़ जमीन में प्याज और बुवाया गया है। अनुमान है कि इन क्षेत्रों में ३२,५०० टन साग-सब्जी पैदा होगी।

इन सब कार्यक्रमों ने लिए किसानों को खेती की विधि आदि की सलाह दी गई है और रियायती दर पर सब्जियों के बीज तथा रासायनिक खाद दिलाई गई है। खेती के लिए बीज, खाद आदि सामान जुटाने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को बिना सूद के ऋण दे रही है जो दो फसलों में चुकाया जा सकेगा। सिंचाई के लिए भी १ हजार पम्पिंग सेट लेकर नए योजना क्षेत्रों में भेजे गए हैं।

खाद्य और कृषि मंत्रालय ने केन्द्रशासित दिल्ली तथा देश के ४० और शहरों के आसपास साग-सब्जी की खेती योजनाएं चलाई हैं

दिल्ली में जो २० हजार बीघा जमीन बृहत् योजना के अन्तर्गत नगर के विस्तार के लिए ली गई थी और जिसका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया था, उसमें साग-सब्जी बोई जाएगी।

इन सात योजनाओं में धान की योजना भी है। गहन कृषि कार्यक्रम की तरह इस योजना में भी देश के ४० चुने हुए जिलों में २५ से ३० अ० श० तक धान की उपज बढ़ाई जाएगी। इस कार्यक्रम को तीसरी योजना की शेष अवधि में जारी रखा जाएगा।

संकटकालीन खेती कार्यक्रम में इस फसल और अगली खरीफ की फसल के बीच के समय में जल्दी तैयार होने वाली फसल बुवाई जाएगी, ताकि किसानों में जो उत्साह है उसका उपयोग हो सके। खेत में बची हुई नमी का लाभ उठाने के लिए उसमें उड़द, लोबिया और मूंग तथा जहां सिंचाई के साधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाया है वहां शकरकन्द, प्याज, चीना, कूटकी, ज्वार व बाजरा आदि की फसलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कृषि विशेषज्ञों का अनुमान है कि गहन सूखी खेती द्वारा कृषि-उत्पादन १० से २० प्रतिशत तक बढाया जा सकता है। इस समय १० राज्यों के १०० जिलों में ज्वार, बाजरा, दलहन, कपास और मूंगफली की सूखी खेती की जा रही है। अब ५ करोड़ एकड़ में सूखी खेती कराने की तैयारी हो रही है। मिली-जुली खाद का उत्पादन ९ करोड़ टन से १३ करोड़ २० लाख टन करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

पशु-पालन

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद की पशुपालन शाखा ने आसाम सरकार के सहयोग से मुर्गा, भेड़ व सुअर पालन और दुग्ध पदार्थ उत्पादन करने की योजनाएं बनाई हैं। इनके अलावा आसाम और बिहार में बकरियों की नस्ल सुधारने तथा राजस्थान में ऊन के वर्गीकरण का काम और बढ़ाया जा रहा है।

सम्पा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देश में दूध को सुखाने की ६ मशीनें तथा अन्डे व मुर्गी पालन के १६ बड़े उत्पादन व वितरण केन्द्र और ५० छोटे फार्म स्थापित किए जा रहे हैं।

गहन कृषि कार्यक्रम

जिला गहन कृषि कार्यक्रम, जो गत वर्ष तक सात राज्यों के सात जिलों में चल रहे थे, उनको अब शेष नौ राज्यों के जिलों में भी आरम्भ किया जा रहा है ताकि हर राज्य में गहन कृषि कार्यक्रम जिला हो जाए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ जिलों में उत्पादन में संतोषजनक प्रगति हुई। जहां १९६०-६१ में ३ लाख एकड़ जमीन में गहन कृषि होती थी वहां अब २२ लाख एकड़ जमीन में कृषि हो रही है।

आशाजनक स्थिति

इस समय कृषि-विकास की जो स्थिति है वह काफी आशाजनक है। अनाज तथा कृषि पदार्थों का उत्पादन मात्रा तथा किस्म की दृष्टि से बराबर बढ़ रहा है। पिछले दस वर्षों में चावल का उत्पादन प्रति एकड़ ११ प्रतिशत बढ़ा। १९६१ में धान की सर्वाधिक पैदावार ३ करोड़ २० लाख टन हुई, जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। १९६०-६१ में ५ करोड़ ५० लाख एकड़ में बढ़िया बीज बोए गए। तीसरी योजना में इससे चौगुनी जमीन में बढ़िया बीज बोए जाएंगे।

देश में अब खेती बढ़ाने के लिए पड़ती या नई जमीन अधिक न होने के कारण वर्तमान जमीन में गहन कृषि करके उत्पादन बढ़ाना है। तीसरी योजना में खाद्य उत्पादन कार्यक्रम में रासायनिक खाद के प्रयोग को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है क्योंकि उपज में एक चौथाई वृद्धि इन्हीं के द्वारा हो सकेगी। पिछले दस वर्षों के आंकड़ों से केलशियम, अमोनियम नाइट्रेट तथा अमोनियम सल्फेट जैसे नए रसायनिक खादों के प्रयोग में बहुत वृद्धि हुई है। १९५१:५२ में नाइट्रोजन खाद का विवरण ५५ हजार टन था। दूसरी योजना के अन्त में इसको बढ़ाकर २ लाख टन कर दिया गया, तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में १० लाख टन नाइट्रोजन खाद देने का लक्ष्य है।

हमारा सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम यह है कि हम जनता के उत्साह को ठोस कामों में लगाएं। पंचायतें, खंड-समितियां, जिला परिषद तथा ग्राम-सेना संगठन ऐसी संस्थाएं हैं जिनके द्वारा विकास प्रयत्नों में जनता सक्रिय सहयोग दे सकती है। मुख्य काम यह है कि ऐसी विधि निकाली जाए कि पैदावार बढ़ाने के कार्यक्रम को चलाने में इन संस्थाओं का सही उपयोग किया जा सके।

● ●

(पृष्ठ ७९ का शेष)

व्यक्तियों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय प्राप्त होगा, किन्तु सर्वसाधारण जनता को इस दशक में आर्थिक न्याय व्यवहार में प्राप्त नहीं हुआ है। भारत भूमि के उपयुक्त समाजवाद, सर्वोदय आदि २ उच्चादर्श इस काल में व्यवहार में न आ सके। पी० सी० महालनोबिस कमेटी भी इसी निष्कर्ष पर अभी तक पहुंची है कि आर्थिक नियोजन के जो कुछ भी फल प्राप्त हुए हैं, वे पहले से ही धनी और साधन सम्पन्न व्यक्तियों के द्वारा ग्रहण कर लिये गए हैं, निर्धन उनसे वंचित रहे हैं। यद्यपि प्रथम और द्वितीय योजनाओं का लक्ष्य बेकारी को दूर करना रहा है, फिर भी इस दिशा में सफलता प्राप्त न हो सकी। प्रथम योजना काल में यदि बेकारी ५३ लाख थी तो १९६१ में लगभग १७० लाख और १९६६ तक २५० लाख हो जायगी। जनसंख्या में आशातीत वृद्धि तथा उसके फलस्वरूप नियंत्रण असफलता, दोषपूर्ण शिक्षापद्धति तथा देश का मन्द आर्थिक विकास इस असफलता के प्रमुख कारण है। भारत जैसे अर्धोन्नत तथा अतिवासित देश में जब पूंजीपरक (Capital-intensive) विधियों को अपनाया गया, तो आर्थिक बुराई ने और भी उग्र रूप धारण कर लिया।

खाद्यान्न समस्या भी अब तक प्रश्नसूचक चिह्न रही है। खाद्यान्नों की पूर्ति और मांग में अब तक सामंजस्य स्थापित नहीं हो सका है। कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं जिनमें सफलता नहीं प्राप्त हो सकी है, यथा मूल्य स्तर पर प्रतिबन्ध, जनता के दृष्टिकोण परिवर्तन तथा भ्रष्टाचार तथा लालफीते शाही की समाप्ति। ('आर्थिक जगत' से)

●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थव्यवस्था और सहकारी समितियां

सहकारी आंदोलन लोकतंत्र का आर्थिक रूप है। सहकारी समितियों में प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। इस समय देश में ४,००,००० से भी अधिक गांवों में सहकारियां काम कर रही हैं। इन सहकारियों को मजबूत बनाना हमारा सबसे बड़ा काम है।

सहकारिता आंदोलन भारत में १९०४ में शुरू हुआ। उस समय सहकारी समितियों की स्थापना के लिए कानून बनाया गया था। किन्तु सहकारी आंदोलन की जड़ गांवों में जम न सकी, और यह आंदोलन गांव वालों को सूदखोर महाजनों के चंगुल से न बचा सका।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण करने और छोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समितियों के संघ बनाने की प्रणाली उपयोगी प्रतीत हुई, जिससे निजी उद्यम को कायम रखते हुए उनके संघ बना कर उनको बड़े उद्योगों से होने वाले लाभ मिल सकें। निजी और सरकारी क्षेत्रों के संतुलन के लिए भी सहकारी क्षेत्रका निर्माण जरूरी हो गया। पहली पंचवर्षीय योजना में रिजर्व बैंकने गांव में ऋण व्यवस्था का सर्वे किया। इससे इस व्यवस्था की त्रुटियों पर प्रकाश पड़ा। स्थिति को देखते हुए यह जरूरी समझा गया कि सहकारी समितियों को राज्य से पूरी सहायता मिले।

देश में ६ करोड़ के लगभग खेत हैं, और राष्ट्रीय आय का ५० प्रतिशत भाग इन्हीं खेतों से पैदा होता है। इस लिए यह जरूरी समझा गया कि हर गांव में एक सहकारी समिति अवश्य होनी चाहिए। एक दशक में सहकारी आंदोलन की उल्लेखनीय सफलता हुई है। इस समय देश भर में विविध प्रकार की लगभग ३,००,००० सहकारियां है और इनके ३ करोड़ ५० लाख सदस्य हैं। १९६०-६१ के अंत में, देश में २,००,००० के लगभग सहकारी ऋण-समितियां स्थापित हो चुकी थीं। देश के ७५ प्रतिशत गांव इनके अंतर्गत आ चुके थे और ३० प्रतिशत आबादी इनसे लाभ उठा रही थी।

केरल, गुजरात, मद्रास, महाराष्ट्र, पंजाब, और उत्तर-प्रदेश इन छह राज्यों में ९० प्रतिशत गांव सहकारी संगठन के अंतर्गत आ गये हैं। साधन सहकारी किसानों को ऋण, बीज, खाद और दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति में अधिकाधिक मदद दे रही हैं। महाजन तो जमीन जायदाद पर ऋण देता था, सहकारियां, किसान की उत्पादन क्षमता और आवश्यकता को देखकर ऋण देती हैं। इस प्रकार के ऋणमें हानिका अंदेशा तो रहता ही है। इसलिए सरकार सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों को इस प्रकार के ऋण की डूबी रकम की हानि पूरा करने के लिए विशेष सहायता दे रही है। सरकार ने साधन सहकारियों के हिस्से भी खरीदे हैं ताकि कर्ज लेने के लिए इनकी स्थिति सुदृढ़ रहे।

बिक्री समितियां

अनाज और खेती की अन्य जिंसों की खरीद बिक्री का काम अधिकतर महाजनों के हाथ में हैं। लेकिन सहकारियां अब इस काम को हाथ में ले रही हैं। १९५९-६० के अन्त में देश भर में २५०१ आरंभिक, ५११ जिला और २१ राज्य हाट-समितियां काम कर रही थीं। ८५ प्रतिशत नियंत्रित मंडियों और ५० प्रतिशत अनियंत्रित मंडियों में आरंभिक बिक्री सहकारियां काम कर रही है। आरंभिक और जिला समितियां वर्ष में लगभग १०० करोड़ रु० का माल बेचती हैं।

शक्कर उद्योग में भी सहकारी आन्दोलन ने थोड़े ही समय में काफी उन्नति की है। १९५५-५६ में शक्कर के केवल ३ सहकारी कारखाने थे, आज ३० से अधिक हैं। तेल पेरने और कपास ओटने के धंधों में भी सहकारिता ने बहुत उन्नति की है।

देहात के लोगों को अधिक काम दिलाना भी जरूरी है। इसके लिए श्रम और निर्माण सहकारियों की स्थापना की गई है। इससे मजदूरों को वाजिब मजदूरी मिलती है और निर्माण का खर्च घटता है। १९६०-६१ में इस प्रकार

(शेष पृष्ठ ८४ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आयल इंडिया लि० की प्रगति

गतांक से आगे

(श्री खण्डूभाई देसाई)

आसाम आयल कम्पनी लि० ने अपने तेल क्षेत्र डिगबोई से करीब २४ मील दूर नहर कटिया स्थित तेल क्षेत्र की खोज करके देश के सामने एक नये साहस की सम्भावनाओं का परिचय दे दिया है। इससे ब्रह्मपुत्र घाटी में छिपी हुई इस तेल-सम्पत्ति के रहस्य की जानकारी मिली। इसके फलस्वरूप आयल इंडिया लि० का गठन हुआ जिसके द्वारा देश के तेल स्रोतों के विकास में महत्वपूर्ण भाग अदा करने की आशाएं हैं। १८ फरवरी १९५९ को आयल इंडिया लि० की रुपये की कम्पनी के रूप में बर्मा आयल कम्पनी और आसाम आयल कम्पनी के साथ १४ जनवरी १९५८ में सांझेदारी हुई। इसका पूरक इकरारनामा २७ जुलाई १९६१ को हुआ जिसके अनुसार "आयल इंडिया" को समान साझेदारी के रूप में परिवर्तित किया गया और अब इसके द्वारा अधिक तेल की खोज की जा रही है तथा गोहाटी और बरौनी तक सार्वजनिक क्षेत्र में ७५० मील लम्बी पाइपलाइन बनायी जा रही है। इस समूचे साहस पर ७५ करोड़ रुपया खर्च होगा।

आयल इंडिया ने १४० कुंए खोदे हैं जिनमें १०५ सफलता के साथ तेल व गैस के उत्पादक हैं, १९ कुंओं की अभी अधिक जांच हो रही है और १६ कुंए सूखे हैं। इनके अतिरिक्त, दो कुंए—एक नहर कटिया में और एक मोरान में—खोदे जा रहे हैं। इन कुंओं की खुदाई पर कुल खर्च करीब १७ करोड़ रु० हुआ, औसतन प्रति कूंआ १२ करोड़, रु० जिसमें वहां तक जाने वाली सड़क—का निर्माण, खुदाई जांच, विभागीय और अतिरिक्त खर्च इत्यादि सब कुछ शामिल है। दूर स्थानों से खुदाई के लिए सड़क-निर्माण का खर्च अधिक होता है और आयल इंडिया का निरन्तर प्रयत्न यही होता है कि अधिक कुशलता और द्रुतगति द्वारा लागत में कमी की जाए। १९६१ में "आयल इंडिया" ने ३० कुंए पूरे किये और औसतन ९,५०० से १०,५०० फुट तक की गहरायी तक खोदने में ११ दिन लगे। विश्व के किसी भी तेल-क्षेत्र में खुदाई की तुलना की दृष्टि से यह समय अधिक नहीं है। खुदाई के साथ-साथ कम्पनी कूंओं में तेल निकालने के संयंत्र और पम्पिंग स्टेशन, वर्कशाप, बिजलीघर, भंडार, गोदाम, दफ्तर, निवासगृह तथा अन्य सहायक भवन भी स्थापित करती है। इन चीजों पर २३ करोड़ रु० आनुमानिक खर्च में से कम्पनी पहले ही १५ करोड़ रु० खर्च कर चुकी हैं। इस प्रकार सन्तोषजनक प्रगति हो रही है।

पाइप लाइन

७२० मील लम्बी पाइप लाइन बनाने की दिशा में पहला कदम नहर कटिया से गोहाटी तक २५० मील लम्बी १६ इंच की पाइप लाइन बनाने का काम १९६२ अप्रैल के प्रथम सप्ताह से चालू हो चुका है। दूसरा कदम, अर्थात, गोहाटी से बरौनी तक ४२० मील लम्बी १४ इंच डाइ मीटर की पाइप लाइन लगाने की प्रारंभिक जांच हो रही है। जिस समय यह सारी पाइप लाइन पूरी होकर चालू हो जाएगी, उस समय यह अत्यन्त आधुनिक चीज होगी और पूर्व में दूसरी सर्वाधिक लम्बी लाइन होगी। इस समूची परियोजना का आनुमानिक खर्च लगभग ४९.५० करोड़ रु० है जिसमें से लगभग ३६.०३ करोड़ रु. पहले ही खर्च हो चुके हैं।

नहर कटिया में जो गन्दा (क्रूड) तेल निकला, उसके यातायात के लिए गम्भीर समस्या पैदा हो गयी थी। पर्याप्त गवेषणा के बाद एक ऐसा प्लांट बनाया गया जिसकी सहायता से गन्दे (क्रूड) तेल को पाइप लाइन में से, सामान्य दबाव द्वारा, शीत ऋतु में भी ले जाया जा सके। इस प्लांट के सम्बन्ध में मशीन व अन्य भारी सामान के विदेशों से आयात करने में और उसे प्लांट के स्थान तक पहुँचाने में भारी दिक्कतें आयीं, फिर भी, यह काम सन्तोष जनक ढंग से चल रहा है और इसके शीघ्र ही पूरा हो जाने की आशा है। गोहाटी के तेल-परिशोधक का काम यद्यपि इस प्लांट के बिना भी चल सकता था पर आगामी शीत ऋतु में इस प्लांट की आवश्यकता पड़ेगी और

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गोहाटी से आगे बरौनी तक ४७० मील की यात्रा में यह विशेष लाभदायक सिद्ध होगा—विशेषतः—शीत ऋतु में।

आयल इंडिया का उत्पादन यद्यपि अभी तक ३० लाख टन की वार्षिक उत्पादन की शक्ति से कम है पर इस कम्पनी की १९६१ की वार्षिक रिपोर्ट से ४,६५,६९,९८७ रु० के ग्रास सरप्लस का पता चलता है। अभी तक जितना तेल-उत्पादन हुआ है, उसे काट कर तेल और गैस के ज्ञात और अनुमानित स्रोत निम्न प्रकार हैं—

तेल

ज्ञात तेल कोष = २२५,०००,००० इम्पीरियल बैरल्स

आनुमानित तेल-कोष = ६८,०००,००० इम्पीरियल बैरल्स

कुलयोग = २९३,०००,०७० बैरल्स

(४ करोड़ ६० लाख टन)

प्राकृतिक गैस

ज्ञात कोष = ५०७,००० मिलियन सी० एफ०

अनुमानित कोष = २४९,००० मिलियन सी० एफ०

योग = ७५६,००० मिलियन सी० एफ०

आयल इंडिया लि० को आसाम सरकार की ओर से मिलने वाले एक दूसरे आदेश पत्र के अनुसार १,८८० नये वर्गमील में तेल की खोज करने का अधिकार मिल जाएगा।

आयल इंडिया लि० के ८ डायरेक्टर हैं जिन्हें दोनों पक्ष समान रूप से नामज़द करते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर बी० ओ० सी० का नामजद है और पांच वर्ष तक इस पद का अधिकारी है। फाइनेन्स डाइरेक्टर भारत सरकार का नामजद है और इस पद पर पांच वर्ष तक के लिए है। कम्पनी के चेयरमैन प्रतिवर्ष दोनों के बारी-बारी से होंगे। डायरेक्टरों का बोर्ड विस्तृत नीतियों की रूपरेखा निर्माण कर देता है जिसे कार्यान्वित करना मैनेजिंग डायरेक्टर का काम है। वह तेल क्षेत्रों और पाइप लाइन निर्माण संघ का कार्य जनरल मैनेजर द्वारा संचालित करता है। यूं तो अन्य सामान्य कम्पनियों की तरह इस कम्पनी का कार्य भी चलता है पर इसकी विशेषता यह है कि सरकार और बर्मा आयल कंपनी (बी० ओ० सी०) दोनों के स्वार्थों में ऐक्य है। आयल इंडिया लि० एक ऐसी कम्पनी है जिसमें सरकार और एक विदेशी कम्पनी इस प्रकार दोनों मिलकर पूर्ण सहयोग से राष्ट्र हित में काम कर रही हैं।

(पृष्ठ ८२ का शेष)

की लगभग २,३०० समितियां थीं। रिक्शा और रेडी वालों की भी सहकारियां बन रही हैं।

खेती में भी मिश्रित अर्थ व्यवस्था अर्थात् सरकारी, सहकारी और निजी खेती को साथ साथ चलना है। इस समय देश भर में लगभग १,८०० कृषि सहकारी समितियां हैं। इनके अतिरिक्त १९६० के अंत तक, १,७०० सिंचाई समितियां, २,००० मछियारों की और १७५० दूध वालों की समितियां बन चुकी थीं।

छोटी बचत योजना में सहकारियों ने बड़ा काम किया है। उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड में, १९५८ में सहकारी बाल-बचत योजना शुरू की गई थी। अब इसके अंतर्गत २,००,००० बच्चे हैं, जो थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ रहे हैं। प्रारंभिक सहकारियां और सहकारी बैंक छोटे बचत खाते खोलते हैं और आज बुन्देलखंड के हर दस बच्चे में से एक का बचत खाता खुला हुआ है।

देश के इस संकट में सहकारिता आंदोलन को अभी और काम करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि लोगों को व्यवहार की चीजों का अधिक दाम न देना पड़े। संकट में, सेना की आवश्यकताओं को पहले पूरा करना है इसलिए बहुत सी जरूरी चीजों की कमी भी हो सकती है। इस स्थिति में अगर न रखा जाए, तो इन वस्तुओं के भाव भी बढ़ सकते हैं। इसलिए योजना है कि प्रत्येक ५,००,००० और अधिक आबादी के शहरों में, उपभोक्ता सहकारियां खोली जाएंगी। इस योजना पर १० करोड़ रु० खर्च होगा। आसाम जैसे राज्यों के कम आबादी के कस्बों में भी सहकारी भंडार खोले जाएंगे। इन उपभोक्ता सहकारी भंडारों से सामान उचित दाम पर और अच्छी किस्म का मिलेगा। सहकारी स्टोरों की देखा देखी और दूकानदार भी अच्छी और सस्ती चीज बेचेंगे। उपभोक्ता सहकारी आंदोलन अभी देश में शुरू ही हुआ है। इससे देश के मध्य वर्गीय लोगों का बहुत लाभ होगा और लोग मुनाफा-खोरों के चंगुल से बचेंगे।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चीन की आर्थिक नीति और वर्तमान स्थिति

आज से कुछ वर्ष पूर्व देश के अनेक सार्वजनिक नेता, अर्थ शास्त्री, पत्रकार और संसद् सदस्य चीन जाकर इतने प्रभावित हुए थे कि वे चीन की आर्थिक नीति के गीत गाने लगे थे और भारत को भी उसका अनुकरण करने की सलाह देने लगे थे। परन्तु आज चीन के सम्बन्ध में उपलब्ध सामग्री बताती है कि चीन की आर्थिक नीति की प्रशंसा तथ्यों पर आधारित न होकर चीन की अत्युक्तियों तथा हमारे राजनीतिक सम्बन्धों पर आधारित थी। अर्थ-शास्त्री को तो राजनीतिज्ञों की सी भावुकता में नहीं बहना चाहिए। यदि देश के अर्थ-शास्त्री यह शिक्षा ले सकें, तो वह आर्थिक नीति के निर्धारण के लिए बहुत लाभप्रद होगी। यहां हम चीन की आर्थिक नीति व प्रगति के सम्बन्ध में दो संक्षिप्त लेख दे रहे हैं। इनसे भी हमारे उक्त विचारों की पुष्टि होती है।

सबसे पहले चीन में किसानों को एक नारा देकर उत्साहित किया गया। यह नारा था, 'किसानों को भूमि दो' और इस आंदोलन के अन्तर्गत चीन के सभी जमीदारों को कुचल दिया गया। जमीदारों की समाप्ति के बाद, किसानों को प्रारम्भिक सहकारियों में संगठित किया गया और सहकारियों के अन्तर्गत किसानों को भूमि का स्वामित्व भी सौंप दिया गया। किन्तु कुछ समय पश्चात्, किसानों से न केवल भूमि का स्वामित्व ही छीन लिया गया बल्कि समाजवाद के नाम पर उनको दिहाड़ी पर काम करने वाला एकमात्र मजदूर बना दिया गया।

चीन में कृषि-सुधार का आंदोलन वर्ग संघर्ष पर आधारित है। पहले ज़मीदार वर्ग और किसान वर्ग में झगड़ा था और अब 'अमीर किसान' और 'गरीब किसान' में संघर्ष है।

किसानों को भूमि कैसे दी गई, यह १९५१ में पेकिंग से प्रकाशित एक पुस्तक के निम्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट है—

अपनी मुट्ठियां दिखाकर, सभा में उपस्थित किसानों ने एक ही आवाज में नारा बुलन्द किया कि 'प्रतिक्रियावादी ज़मींदारों को समाप्त करो।' और उन्होंने यंग-हरह-हू को गोली से उड़ा देने की मांग की।

जनसमुदाय फिर चिल्लाया कि 'अपराधी जमीदारों को मार दो, क्योंकि वे अपनी उपज को छिपा लेते हैं और उसे अपनी मरजी से बांटते हैं। "किसानों की एकता अमर रहे।"

४ बजे तक, २० किसानों ने सभा के मंच से अपने दुखों और शिकायतों का वर्णन किया। 'किसान साथियो', न्यायाधीश ने गम्भीर आवाज में कहना शुरु किया, अभी हमने किसानों की शिकायतों को सुना है। इन शिकायतों से सबको पता चल गया होगा कि किस प्रकार ज़मींदार वर्ग हमेशा किसानों का दुश्मन रहा है।'

अपराधियों को मौत की सजा सुनाई गई। उन्हें मौत के घाट उतार कर दफना दिया गया।

किसी भी व्यक्ति को खत्म करने के लिए उसे "जमींदार" कह देना ही काफी होता था। ज़मींदार की परिभाषा बहुत ही निकृष्ट और आसान ढंग से की जाती थी। सिपाही ने पूछा 'क्या वह ज़मींदार है?' हां ज़मींदार है।' भीड़ में से आवाज आई और उस व्यक्ति को तत्काल खत्म कर दिया गया। उन किसानों ने कुछ खुशियां मनाईं जिन्हें कुछ मू भूमि मिली थी (एक मू एक एकड़ का छठा हिस्सा होता है) किन्तु ये खुशियां देर तक न चल सकीं। किसानों में छोटे-छोटे टुकड़ों में जो भूमि बांटी गयी थी, उससे उपज नहीं बढ़ सकी। चीन ने उत्पादक सहकारिता आंदोलन चलाया। इसके अन्तर्गत किसान सामूहिक रूप से खेती करने लगे और उन्हें उसके लिए पारिश्रमिक मिलने लगा। किसान भूमि के मालिक न रहे, वे भूमिजीवी मजदूर हो गये। शुरू शुरू में चीन उत्पादकों की ३०० सहकारी समितियां थी। १९५८ के वसंत में चीन ने घोषणा की कि अब वहां, १,३००,००० सहकारियां है।

'सामूहिक खेती के नाम पर चीन की सरकार ने बड़ी सफाई से किसानों से वह जमीन छीन ली, जिसे कुछ ही वर्ष पहले किसानों से बड़े नुमाइशी ढंग से वितरित किया था। चीन की सरकार अपने लक्ष्य के बारे में पूरी तरह से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्पष्ट थी। उसका लक्ष्य बड़ी सतर्कता से एक कार्यक्रम की प्रगति की पहले तो प्रशंसा करना और बाद में उसे बदलने से पहले उसी कार्यक्रम की निन्दा करना था। जनता को मूर्ख बनाने का कार्यक्रम, निर्धारित योजना के अनुसार चलता रहा। उनकी योजना यह थी कि कार्यक्रम के जिस पहलू को वे अनावश्यक समझे, उसके विरोध में समाचार पत्रों के सम्पादकों के नाम पत्र लिखवा दिये जाएं। सरकार को उस नीति को बदलने का बहाना मिल जाता है।

कम्यून प्रथा

इस सामूहिक स्वामित्व से उत्पादन नहीं बढ़ सका। इसके बाद कम्यून प्रथा को आरम्भ किया गया और कहा गया कि "कम्यून प्रथा प्रगति के घटनाक्रम का एक रचनात्मक नतीजा है।"

बहुत सी सहकारियों और गांवों को एक साथ मिलाकर उन्हें एक प्रशासन के अधीन कर दिया गया। यही प्रशासन अपने ब्लाक की प्रगति का जिम्मेदार होता है। खेतों में किसानों की झोंपड़ियों को नष्ट कर दिया गया। सभी किसानों को बड़े-बड़े कक्षों में बसा दिया गया। तन पर पहने कपड़ों के अलावा इनके पास कोई भी निजी वस्तु नहीं होती। इनको कम्यून के भोजनालय में सामूहिक रूप से भोजन करना पड़ता है और इनके बच्चों की देख-रेख कम्यून की नर्सरियों में होती है। इस प्रकार सरकार को फसल पर नियंत्रण रखने और फसल की कटाई में सुविधा हो गई। सरकार को खाद्य सामग्री के परिवहन और उसे सुधारने में भी आसानी हो गई।

दूसरी पंचवर्षीय योजना

चीन ने १९५७ में जब अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरु की तब उसने बड़े जोर-शोर से इसका प्रचार किया था। परन्तु ३१ दिसम्बर, १९६२ को जब उसकी दूसरी योजना समाप्त हुई तब वह बिल्कुल चुप रहा। मजे की बात यह है कि उसने तीसरी योजना का भी कोई जिक्र नहीं किया।

वास्तव में चीन के बहुत छिपाने के बावजूद यह बात प्रकट हो ही गई है कि उसकी दूसरी योजना बुरी तरह असफल हुई है। उसने जो लम्बी छलांग लेने का प्रयत्न किया, उसमें वह मुंह के बल गिर पड़ा है। उसकी दूसरी योजना में लोगों का रहन-सहन का स्तर गिरा है, अनाज की कमी पड़ी है और उद्योगों का ह्रास हुआ है।

चीन ने अपनी दूसरी योजना में हर साल २५ करोड़ टन अनाज पैदा करने का लक्ष्य रखा और १९५८ की "लम्बी छलांग" के समय यह लक्ष्य बढ़ाकर ५० करोड़ टन कर दिया। परन्तु १९६२ में वहां केवल १८ करोड़ ५० लाख टन अनाज हुआ और कहा जाता है कि १९५९ से १९६२ तक सबसे अच्छी फसल इसी साल हुई। इस प्रकार १९६२ में मूल योजना के लक्ष्य से ३० प्रतिशत कम और 'लम्बी छलांग' योजना के लक्ष्य से ६० प्रतिशत कम अनाज हुआ। चीन को अपने ६० करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए कम से कम २० करोड़ ५० लाख टन अनाज की जरूरत है। इसके अलावा वहां हर साल आबादी दो करोड़ और बढ़ जाती है। उसके लिए भी हर साल ६० से ७० लाख टन तक अतिरिक्त अनाज की जरूरत होगी।

चीन ने यह कमी आस्ट्रेलिया और कनाडा से अनाज मंगाकर पूरी की। पिछले साल उसने ९० करोड़ रु० का अनाज मंगाया। इस साल भी उसने लगभग इतने की रु० का अनाज मंगाया है। उसने अब तक जो अनाज मंगाया है, उसके लिए उसे लगभग १ अरब ७० करोड़ रु० देना है।

चीन की दूसरी योजना में भी निरन्तर गिरावट आई है। वहां इस्पात का उत्पादन १९६० से आधा हो गया है। कोयले का उत्पादन भी ४५ करोड़ से गिरकर २१ करोड़ रह गया है और बिजली का उत्पादन भी लगभग आधा गिर गया है।

अन्य उद्योगों में भी चीन बुरी तरह असफल रहा है। वहां कागज का उत्पादन १९५९ में २३ लाख टन से गिरकर १९६२ में १० लाख टन रह गया। कपड़े का उत्पादन तो इतना गिरा कि उस पर राशन लगा दिया गया, और अब साल में प्रति व्यक्ति केवल १.५ वर्ग गज कपड़ा दिया जाता है, यानी एक व्यक्ति केवल ४ साल के बाद ही अपना सूट बना सकता है। चीन में ट्रक बनाने का जो एक मात्र कारखाना था वह भी १९६० में बन्द हो गया। पता चला है कि वह हांगकांग से पुराने ट्रक खरीद रहा है। ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देश रक्षा और जनता के कर्तव्य

देश की रक्षा की व्यवस्था के लिए केन्द्र और राज्यों की १९६३-६४ की योजनाओं में आवश्यक परिवर्तन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश की पूरी शक्ति और साधनों को देश की रक्षा में लगाना है। योजना में परिवर्तन इस ढंग से किया जाएगा कि (क) वर्तमान संकट का मुकाबला करने के लिए तुरन्त आवश्यक उपाय किए जाएं; (ख) मुख्य उद्योगों की गति में कोई कमी न हो बल्कि और तेजी आए; ये उद्योग हैं—खनिज, परिवहन और संचार, खेती सिंचाई और बिजली; (ग) सरकारी खर्च घटें और (घ) ऐसे काम जिनका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देश की रक्षा या बुनियादी विकास से सम्बन्ध न हो, बन्द या स्थगित कर दिए जावे।

हमारे कर्तव्य

हर उद्योग में भी क्षमता भर काम होना जरूरी है। जो कारखाने कभी चालू नहीं हुए हैं, उन्हें जल्दी चालू किया जाए। कच्चे माल के उपयोग में किफायत की जाए और काम तथा प्रबन्ध पूरी कुशलता से चले। मालिक और मजदूर मिल जुल कर काम करें। हर कारखाना देश की शक्ति बढ़ाने का एक ही उद्देश्य, सामने रखे छोटे-बड़े सभी कारखनों को उत्पादन की योजना, बनाकर काम करना चाहिए। जो साधन अपने देश और प्रदेश में उपलब्ध हों उन का अधिक से अधिक उपयोग हो और कामगरों को काम में सुधार और अच्छी विधि निकालने को बढ़ावा दिया जाए।

देश के विकास और रक्षा के लिए खेती की पैदावार बढ़ाना भी जरूरी है। देश के लाखों किसानों को संगठित करके भरपूर ताकत से खेती में जुटाना चाहिए और उनको बीज, पानी, आदि उपलब्ध करने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद ने छोटी सिंचाई का लक्ष्य १ करोड़ २० लाख एकड़ से बढ़ाकर १ करोड़ ९० लाख एकड़, भू-संरक्षण का १ करोड़ १० लाख से १ करोड़ ६० लाख एकड़ और खेती का २ करोड़ २० लाख एकड़ से ५ करोड़ एकड़ करना स्वीकार कर लिया है। सिंचाई के जो काम नहर, बांध, तालाब, नलकूप आदि से हो सकते हैं, उनका भरपूर उपयोग होना जरूरी है।

खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए उन कामों पर जोर देना चाहिए, जिन्हें लोग स्वयं कर सकते हैं, जैसे भू-संरक्षण और मेड़बन्दी, खेतों में सिंचाई की नालियां बनाना बांधों और नालियों की मरम्मत, पोखर को खोदना और ठीक रखना, खाद तैयार करना, ईंधन के लिए पेड़ लगाना और आबपाशी करना। प्रत्येक गांव व जिले में इन कामों की बाकायदा योजना बनानी चाहिए।

सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में इस ढंग से परिवर्तन करना चाहिए कि उसके द्वारा खेती की तरक्की हो। खेती और कल कारखानों को जोर से चलाने के साथ साथ देश के आर्थिक साधनों को जुटाने का पूरा प्रयत्न होना चाहिए और हर श्रेणी के लोगों को अधिक से अधिक पैसा बचाने को प्रेरित करना चाहिए। तीसरी योजना में बचत का जो लक्ष्य रखा गया है, उससे अधिक रकम इकट्ठी होनी चाहिए। हर व्यक्ति को जितना हो सके उतना खर्च और उपयोग घटाना चाहिए। रक्षा बचत-पत्रों में अधिक से अधिक धन लगवाना चाहिए और नये कर देने को भी सहर्ष प्रस्तुत होना चाहिए।

देश के आर्थिक साधनों को जुटाने के साथ निर्यात भी बढ़ाना जरूरी है। तीसरी योजना में निर्यात का जो लक्ष्य है, न केवल उसमें कोई कमी हो, बल्कि उसे बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। अपने उपयोग से बचा कर अधिक से अधिक खेती की पैदावार, खनिज पदार्थ और सामान्य वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए।

तन-मन-धन सब कर बलिदान
रखनी है भारत की शान

मूल्य स्थिर रखें

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मूल्यों को बढ़ने न दिया जाए। मूल्यों के बढ़ने से विकास का काम रूकेगा, हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी और रक्षा के कामों में बाधा पहुँचेगी। खासकर सामान्य व्यवहार की सामग्रियों के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दाम कदापि न बढ़ने चाहिए और जनसाधारण को जरूरत की वस्तुएं बराबर मिलती रहें।

सरकार भी मूल्य स्थिर रखने के लिए कुछ उपाय कर रही है। सस्ते दामों की दूकानें खोलने के अलावा देशभर में सहकारी भंडार खोले जा रहे हैं। चावल के मुकाबले गेहूँ अधिक है, इसलिए गेहूँ खाने वाले इलाकों में चावल का व्यवहार कम होना चाहिए और चावल खाने वालों को गेहूँ खाने को प्रेरित करना चाहिए।

अनाज और कच्चा माल उपजाने वालों को, उचित दाम मिलना चाहिए, साथ ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उपभोक्ता को भी अधिक दाम न देना पड़े। इसलिए थोक व्यापार को नियंत्रित करना चाहिए और राज्य सरकारों को स्टाक रखना चाहिए। कपड़े और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के अन्य उत्पादन में इस बात पर ध्यान देना जरूरी है, कि अच्छी किस्म का माल पर्याप्त मात्रा में तैयार हो। उत्पादन का खर्च और कारखानेदारों व थोक व खुदरा व्यापारियों के लाभ की रकम भी कम से कम करनी चाहिए।

देश के नव निर्माण के लिए यह बड़ा ही अच्छा अवसर है। संकट के कारण योजना में जो परिवर्तन किये जा रहे हैं, वे हमारी सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति के लिए आवश्यक थे और उन्हें जनता के सोत्साह सहयोग से किया जा सकता है। ● ●

योजना का तीसरा वर्ष

राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थायी समिति ने योजना आयोग के उस प्रस्ताव को पुष्ट कर दिया है, जिसके अनुसार तीसरी योजना के तीसरे वर्ष १९६३-६४ वर्ष के लिए १,७४४ करोड़ रु. व्यय मंजूर किया गया है। इसमें ९४४ करोड़ रु. व्यय केन्द्रीय क्षेत्र के लिए और ७५० करोड़ रु. राज्यों के लिए तथा ५० करोड़ रु. केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के लिए है।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता ४०० करोड़ रु. की दी जायगी, बाकी ३५० करोड़ रु. राज्यों को स्वयं अपने साधनों से उपलब्ध करने होंगे। राज्यों के साधन, अभी तक, २९२ करोड़ रु. के हैं। इस प्रकार उनके साधनों में ५८ करोड़ रु. की कमी है।

केन्द्र और राज्यों में इस राशि का बंटवारा इस प्रकार किया गया है।

	केन्द्र करोड़ रु०	राज्य करोड़ रु०
कृषि	१७.०७	११३.९
सामुदायिक विकास और सहकारिता	१०.१५	६०.५
सिंचाई और बिजली	२५.६६	३३९.७
उद्योग और खनिज	४२८.७३	४०.८
परिवहन और संचार	३६७.१३	३९.९
सामाजिक सेवाएं	८९.९६	१४३.९
विविध	५,५७	११.२
योग—	९४४.२७	७४९.९

इसमें ५० करोड़ रु. केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों का जोड़ लेने से कुल योग १९६३-६३ के लिए १,७४४ करोड़ रु. हो जाता है। ● ●

हिन्दी का एकमात्र
विशिष्ट महिलापयोगी मासिक

शृङ्गार

- जो सुखी पारिवारिक जीवन का आदर्श पथ-प्रदर्शक है।
- जिसे सुप्रसिद्ध लेखिकाओं, लेखकों, पत्रकारों, चित्रकारों, कवयित्रियों तथा कवियों का सहयोग प्राप्त है।
- जिसे ५०००० से ऊपर की संख्या में पाठक प्रतिमास पढ़ते हैं।
- जिसकी प्रतियां न्यूज़ एजेन्टों के पास पहुँचते ही समाप्त हो जाती हैं।
- जो महिला जागृति का प्रतीक है।
- जो सबकी प्रिय पत्रिका है।

वार्षिक : सात रुपये
एक प्रति : ६० नये पैसे

सम्पादिका : लावण्यप्रभा
कार्यालय : १३।३७, शक्तिनगर, दिल्ली-६।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विभिन्न राज्य-क्षेत्रों में विकास

पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में देश के विभिन्न भागों में आर्थिक दृष्टि से कितना विकास हुआ तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस दिशा में क्या कुछ करने का विचार है, इस सम्बन्ध में योजना आयोग ने अध्ययन करके कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। सुविधा के लिए देश को निम्नलिखित पांच क्षेत्रों में बांट दिया गया है :

(१) उत्तरी क्षेत्र—जम्मू-कश्मीर, पंजाब तथा राजस्थान।

(२) मध्य क्षेत्र—मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश।

(३) पूर्वी क्षेत्र—असम, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल

(४) पश्चिमी क्षेत्र—महाराष्ट्र तथा गुजरात।

(५) दक्षिणी क्षेत्र—आन्ध्र प्रदेश, केरल, मद्रास तथा मैसूर।

पहली योजना में राज्यों में सरकारी क्षेत्र के कुल परिव्यय का ७३ प्रतिशत तथा दूसरी योजना में ४४ प्रतिशत व्यय हुआ। तीसरी योजना में राज्यों के लिए ४६ प्रतिशत व्यय की व्यवस्था है। पहली और दूसरी योजना में राज्यों में कुल ३,४९६ करोड़ रुपया व्यय हुआ तीसरी योजना में यह रकम ३,८४७ करोड़ रुपए है।

पहली और दूसरी योजना के कुल परिव्यय में से केन्द्र ने राज्यों को १,९३७ करोड़ रुपये की, अर्थात् कुल व्यय की ५५ प्रतिशत सहायता प्रदान की; तीसरी योजना में यह धनराशि २,४३१ करोड़ रुपए अथवा ६३ प्रतिशत होगी।

तीनों योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों में व्यय का क्षेत्रवार विभाजन नीचे की तालिका में दिखाया गया है :

क्षेत्र	कुल व्यय	राज्यीय संसाधन	केन्द्रीय सहायता
			(करोड़ रुपये)
उत्तरी	१,०६१	३३२	७२९
मध्य	१,४३२	५०९	९२३
पूर्वी	१,६९६	५७९	१,११७
पश्चिमी	१,२२२	७३५	४८७
दक्षिणी	१,९३२	८२०	१,११२
	७,३४३	२,९७५	४,३६८

देश के विभिन्न भागों में जो विकास हुआ है, उसमें सबसे उल्लेखनीय प्रगति कृषि के क्षेत्र में हुई। विभिन्न क्षेत्रों में अनाज की पैदावार में वृद्धि का विवरण इस प्रकार है :

क्षेत्र	१९५०-५१	१९६०-६१ (संभावित)	१९६५-६६
		(लाख टन)	
उत्तरी	८५	११३	१५१
मध्य	१६९	२३८	२९०
पूर्वी	१४३	१८८	२२८
पश्चिमी	६७	९०	१०९
दक्षिणी	१०७	१५९	२१९
सब क्षेत्र	५७१	७८८	९९७

इसी प्रकार कपास, तेलहन, गन्ने और जूट की पैदावार में भी वृद्धि हुई, उसका विवरण इस प्रकार है :

	कपास (लाख गांठ)		
उत्तरी	४.४	९.४	१५.५
मध्य	३.२	५.०	९.०
पूर्वी	०.१	०.१	१-२
पश्चिमी	१४.४	३०.१	२९.३
दक्षिणी	६.९	९.३	१५.६
सब क्षेत्र	२९.०	५३.९	७०.९

जो हैं पैदावार बढ़ाते वे भारत को सफल बनाते

	गन्ना अथवा गुड़ (लाख टन)		
उत्तरी	४.६	११.०	१०.८
मध्य	२९.९	४०.१	४४.६
पूर्वी	५.७	१०.५	१२.६
पश्चिमी	५.६	१०.२	१३.१
दक्षिणी	१०.३	१४.९	१८.३
सब क्षेत्र	५६.१	८६.७	९९.४

सिंचाई और बिजली

पहली दो योजनाओं में सिंचित क्षेत्र में ४२ प्रतिशत

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वृद्धि हुई; आशा है कि तीसरी योजना के अन्त में ८८ प्रतिशत वृद्धि होगी। विभिन्न क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र, बिजली की स्थापित क्षमता तथा गांवों और कस्बों में बिजली पहुँचाने की प्रगति नीचे की तालिका में दिखाई गई है :

क्षेत्र	१९५०-५१	१९६०-६१ (अनुमानित)	१९६५-६६ (संभावित)
	कुल सिंचित क्षेत्र (लाख एकड़)		
उत्तरी	११३	१५७	१९७
मध्य	१५१	१९८	२५४
पूर्वी	११९	१७९	२५४
पश्चिमी	३१	५०	९०
दक्षिणी	१४०	२०४	२५८
सब क्षेत्र	५५४	७८८	१,०४४
	बिजली—स्थापित क्षमता (मेगावाट)		
उत्तरी	९८	४५७	१,१०४
मध्य	२२६	७६५	१,८४४
पूर्वी	५७५	१,८६४	३,२५४
पश्चिमी	४३८	१,२००	२,२१४
दक्षिणी	३३०	१,१७४	२,८५६
अन्य इकाइयां	५९० क्षेत्रीय आंकड़ों में शामिल		१,४४६
सब क्षेत्र	२,२५७	५,४६०	१२,७१८

उद्योग

औद्योगिक गतिविधि का विकेन्द्रीकरण करने में छोटे और बड़े उद्योग एक-दूसरे के पूरक हैं और उनका महत्व भी एक समान है। राज्यीय योजनाओं में प्रत्येक क्षेत्र की सम्भावनाओं के अनुसार ग्रामोद्योगों और कुटीरोद्योगों का विकास करने की व्यवस्था है। उद्योगपुरियां बनाकर, ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में बिजली पहुँचाकर तथा प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार करके देश के विभिन्न भागों में विकास किया जायेगा। छोटे पैमाने के कुछ उद्योग ऐसे हैं, जो एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे क्षेत्र में अधिक आसानी से पनप सकते हैं। पंजाब और मद्रास में छोटे पैमाने के और हल्के इंजीनियरी उद्योगों में तथा दक्षिण में हथकरघा उद्योग में हाल ही में जो विकास परिलक्षित हुआ है, वह इस बात का द्योतक है कि लघु उद्योगों के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में धन की व्यवस्था करने और तकनीकी तथा अन्य प्रकार की सहायता देने के मुकाबले मानवीय और संघटनात्मक बातों का भी कम महत्व नहीं है।

दूसरी योजना में सरकारी क्षेत्र की अनेक परियोजनाओं को देश के विभिन्न भागों में बांट दिया गया था। तीसरी योजना में भी ऐसा किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक परियोजनाओं में वे औद्योगिक परियोजनाएं भी जोड़ ली गईं जो राज्यों की योजनाओं के रूप में आरम्भ की जाती हैं। सरकारी क्षेत्र के विकास में अब राज्य सरकारें अधिकाधिक योग दे रही हैं।

परिवहन और बिजली की सुविधाओं का विस्तार तथा प्रशिक्षण की सुविधाओं का विकास देश-भर में बड़े विशाल पैमाने पर हुआ है, इसलिए विभिन्न राज्यों में ऐसी मूलभूत परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, जिनमें काफी संख्या में उद्योगों का विकास हो सकता है। उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए छोटे और मध्यम उद्योगकर्ताओं के नए वर्ग आगे आ रहे हैं। दूसरे, पिछले कुछ वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र में जो औद्योगिक विकास हुआ है, उसका लाभ अनेक उद्योगों को भी मिल रहा है। इस प्रकार, दूसरी पंचवर्षीय योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र में जो ७०० करोड़ रुपए का पूंजी-विनियोग हुआ, वह अनेक उद्योगों में बांट दिया गया था; जैसे—१५३ करोड़ रुपया धातु उद्योगों में, १२५ करोड़ रुपया इंजीनियरी उद्योगों में, ५८ करोड़ रुपया रासायनिक उद्योगों में, ५६ करोड़ रुपया चीनी उद्योग में, ५८ करोड़ रुपया सीमेंट उद्योग में, ५० करोड़ रुपया सूती, जूट और ऊनी वस्त्र उद्योगों में, ४० करोड़ रुपया कागज और गत्ता उद्योगों में, ३४ करोड़ रुपया रेयन और लम्बे तन्तु के वस्त्र उद्योग में, २२ करोड़ रुपया पेट्रोल-शोधन उद्योग में तथा १०४ करोड़ रुपया अन्य उद्योगों में गया।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में १९६१-७६ की दीर्घकालीन अवधि को सम्मुख रखा गया है और इसी के अनुसार विकास की एक दीर्घकालीन योजना बनाने का काम शुरू हो चुका है। इस दीर्घकालीन योजना के अन्तर्गत विकास-कार्य इस ढंग से किया जाएगा, जिससे कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों का विकास हो और उन्नति की रफ्तार को मन्द किये बिना विकासजन्य लाभों को अधिकाधिक फैलाया जा सके।×

× योजना आयोग द्वारा प्रकाशित 'भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास' का सारांश।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्वर्ण का विश्व-उत्पादन और मुद्रा-कोष

अमेरिका की व्यापारी पत्रिका "फेडरल रिजर्व बुलेटिन" के नवम्बर १९६२ में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, १९६१ में गैर कम्युनिस्ट देशों में सोने का उत्पादन उच्चतम स्तर तक पहुँच गया था, अर्थात् १,२२० मिलियन डालर, (अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष इंटरनेशनल मानिटरी फंड के अनुसार ३५ डालर प्रति फाइन औंस) १९५५ में ९४० डालर मिलियन के स्तर से प्रारम्भ होकर, सोने का उत्पादन प्रतिवर्ष ४ प्रतिशत से कुछ अधिक बढ़ रहा है।

द० अफ्रीका में सब से अधिक

स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन दक्षिणी अफ्रीका में होता है, अर्थात् गैर-कम्युनिस्ट जगत् के कुल उत्पादन का लगभग दो तिहाई। कनाडा दूसरे दर्जे पर, करीब आठवां हिस्सा कुल उत्पादन का, अमेरिका तीसरे दर्जे पर, करीब ४.५ प्रतिशत। अन्य सब देश ३ प्रतिशत व इससे भी कम।

भारत की स्थिति

स्वर्ण उत्पादक देशों में भारत का स्थान १२ वां है। कोलार की स्वर्ण खानें ही हमारी सोना उत्पन्न करने की एकमात्र साधन हैं। पिछले कुछ वर्षों से इन खानों के भंडार में न्यूनता आ गयी हैं, जिससे उत्पादन में ह्रास आ रहा है। १९५५ में भारत का स्वर्ण उत्पादन ७.४ मिलियन डालर का था जो १९६१ में कम होकर ५.७ मिलियन डालर मात्र रह गया है।

विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण-उत्पादक देश सोवियत रूस समझा जाता है, पर इसके उत्पादन का कोई अनुमान प्राप्त नहीं है। साइबीरिया स्थित खानों में अनन्त स्वर्ण भंडार है और सोवियत रूस प्रतिवर्ष अत्यन्त आधुनिक साधनों से इसका निष्कर्षण करता है। सोवियत रूस गैर-कम्युनिस्ट देशों के साथ असंतुलित व्यापार होने पर, कभी कभी इस स्वर्ण भंडार में से कुछ मात्रा भेज देता है। इसका मतलब यह है कि सोविपत रूस का समूचा स्वर्ण इसके भंडार की अति वृद्धि कर रहा है। यह भंडार अब कितना है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

इस समय जो विश्व में जो स्वर्ण-कोष है, उसके आंकड़े नीचे की तालिका में दिये जाते हैं पर ये केवल गैर-कम्युनिस्ट देशों के है। फिर यह स्टाक वे हैं, जो केन्द्रीय बैंकों व सरकारों के पास हैं। निजी व्यक्तियों और संस्थाओं के पास सोने का कितना स्टाक है, यह एक दम अज्ञात है। भारत में रिजर्व बैंक के पास २४७ मिलियन डालर के मूल्य का सोना है पर, जैसा कि कुछ जानकारों का अनुमान है, निजी व्यक्तियों के पास रिजर्व बैंक की अपेक्षा १३ गुणा सोना जमा है। इसलिए, मुद्रा अधिकारियों के पास सोने का जो स्टाक है, उससे देश के समूचे सोने का अनुमान लगाना संभव नहीं है। इसके विपरीत, पश्चिमी देशों की स्थिति यह है कि स्वर्ण-भंडार का बड़ा अंश उन देशों के बैंकों के पास है और निजी व्यक्तियों के पास अपेक्षाकृत कम है।

यही हमारा दृढ निश्चय
होगी भारत की ही जय

१९६१ के अन्त में केन्द्रीय बैंकों और सरकारों के पास स्वर्ण-कोष

देश	मिलियन डालर	कुल योग का प्रतिशत
अमेरिका	१६.९४७	४१.१८
पश्चिमी जर्मनी	३.६६४	८.९०
ब्रिटेन	३.३१८	८.०६
स्विट्जरलैंड	२.५६०	६.२२
इटली	२.२२५	५.४१
फ्रास	२.१२१	५.१५
नीदरलैंडस	१.५८१	३.८४
बेलजियम	१.२४८	३.०३
कनाडा	९४६	२.३०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.

एम. एफ.	२.०७७	५.०६
योग	३६.६८७	८९.१५
अन्य देश	४.४६३	१०.८५
महायोग	४१.१५०	१००.००

गैर कम्युनिस्ट देशों के पास, १९६१ के अन्त में मुद्रा-स्वर्ण का स्टाक, अनुमानतः ४१,१५० मिलियन डालर था। पिछले कुछ वर्षों से यह स्टाक २ प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ रहा है। इसके साथ ही सामान और सेवाओं के रूप में विश्व व्यापार, लगभग ६ प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रहा है। इस प्रकार, विश्व का मुद्रा स्वर्ण जिस गति से बढ रहा है, उससे अधिक तेजी से विश्व-व्यापार में वृद्धि हो रही है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान में कुछ भयंकर दिक्कतें पैदा हो गयी हैं।

यह दिक्कतें और भी उग्र इसलिए हो गयी हैं क्योंकि इस मुद्रा स्वर्ण का वितरण विभिन्न देशों में बड़ा अ-सामान्य है, जैसे अमरिका के पास विश्व के मुद्रा स्वर्ण का ४० प्रतिशत से अधिक जमा है। अन्य कुछ देश जिनके पास अनुपात से अधिक स्वर्ण है, वे हैं—बेलजियम, कनाडा, फ्रास, पश्चिमी जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन। ये ९ देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (इंटरनेशनल मानिटरी फंड) सहित विश्व के मुद्रा-स्वर्ण का लगभग ९० प्रतिशत कब्जे में किये हुए है।

निजी व्यक्तियों के पास छिपा हुआ सोना कितना है, इस का कुछ आभास अप्रत्यक्ष प्रमाणों से मिलता है। १९५६-६१ के ६ वर्षों में, विश्व में कुल स्वर्ण-उत्पादन ६,५६० मिमियन डालर था, परन्तु इसी अवधि में विश्व का स्वर्ण मुद्राका स्टाक ३७,६२० मिलियन डालर से बढकर ४१,१५० मिलियन डालर हो गया, अर्थात् केवल ३,५३० मिलियन डालर। इस से स्पष्ट है कि लगभग ३ मिलियन डालर सोना—विश्व के समूचे स्वर्ण उत्पादन से कुछ कम—निजी व्यक्तियों के हाथों में जमा हो गया।

आर्थिक समीक्षा

प्रधान सम्पादक : श्री सादिक अली

सम्पादक : श्री महेन्द्र मेहरा

- हिन्दी में अनूठा प्रयास
- आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख
- आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत

भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक।

वार्षिक मूल्य : ५ रु० एक प्रति २२ नये पैसे

लिखें—व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, नई दिल्ली।

दूध के विभिन्न उपयोग

सबसे सस्ता सचित्र हिन्दी मासिक

जागृति

जिसे भारत के सभी प्रमुख कवियों, और कहानीकारों का सहयोग प्राप्त है।

उत्प्रेरक कविताएं, ज्ञानवर्धक लेख, सांस्कृतिक निबंध, रोचक कहानियां, बाल संसार, साहित्य आगे बढ़ता है आदि स्तम्भ

तिरंगा आवरण, अनेकों इकरंगे चित्र

४८ से ५६ पृष्ठ को सम्पूर्ण छपाई आर्ट पेपर पर

इस पर भी मूल्य केवल २५ नये पैसे

एजेंटों को ५ से १० प्रतियों पर २५ प्रतिशत और इससे ज्यादा पर ३३⅓ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। डाक खर्च प्रकाशकों के जिम्मे। एजेन्ट नमूने की प्रति के लिए आज ही लिखें।

—सूचना व प्रकाशन विभाग चण्डीगढ़ (पंजाब)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पोलैण्ड तथा भारत के आर्थिक सम्बन्ध

पोलिश-भारतीय आर्थिक सम्बन्धों को शुरू हुए बहुत कम समय हुआ है किन्तु आज उनका क्षेत्र काफी व्यापक हो गया है। १९५६ तक दोनों देशों के सम्पर्क की पूर्ण सम्भावनाओं को ठीक से नहीं समझा गया। उस वर्ष दोनों देशों के बीच एक तीन-वर्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसने उनके आर्थिक सम्बन्धों में एक नया अध्याय शुरू किया। इससे पहले अनेक भारतीय वस्तुएं पोलैण्ड के बाजारों में पहुँचीं। यथा, वनस्पति तेल और घी, लौह तथा मेंगनीज अभ्रक, लाख, खालें, चमड़े, मसाले, नारियल की जटाएं, रेशे तथा बहुत सी अन्य वस्तुएं।

किन्तु १९५६ के समझौते के अन्तर्गत भारत को पोलैण्ड से अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना की कुछ प्रयोजनाओं की पूर्ति के लिए अत्यन्त आवश्यक मशीनरी, रेल परिवहन के लिए सवारी व माल डिब्बे, इत्यादि प्राप्त हुए। बदले में पोलैण्ड ने भारत से बड़ी मात्रा में लौह अयस्क, अभ्रक तथा अन्य परम्परागत निर्यात-वस्तुओं की खरीद की। इस समझौते की अवधि में दोनों देशों के बीच व्यापार का कुल आवर्त दुगुने से अधिक हो गया—१९५६ में यह ३१९६ लाख रुपये का था, और १९६० में यह बढ़कर ६३७७ लाख रुपये मूल्य का हो गया।

रुपयों में भुगतान का समझौता

इसी अवधि में पारस्परिक लाभ के सिद्धान्त पर अमल शुरू हुआ। अदायगी सम्बन्धी कठिनाइयों और आपसी व्यापार को बढ़ाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षों ने १९५८ में फैसला किया कि तमाम अदायगी भारतीय मुद्रा में की जाए। १९५९ में व्यापार का कुल आवर्त १९५८ की तुलना में लगभग ३० प्रतिशत अधिक रहा, जबकि भारत से पोलैण्ड के आयात में १९५८ की तुलना में लगभग १७७ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

नवम्बर १९५९ में नयी दिल्ली में १९६०-६२ के लिए एक नये तीन-वर्षीय व्यापार एवं भुगतान समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस अवधि को १९६३ के लिए बढ़ा दिया गया है।

दोनों देशों के बीच व्यापार का आवर्त १९५९ में ५९३ लाख रु० का रहा। १९६० में यह बढ़कर ६३७ लाख रु० का हो गया और १९६१ में ११३० लाख रु० का। चालू वर्ष (१९६२) के प्रथम छः महीनों कुल मिलाकर ८५० लाख रुपये से अधिक का व्यापार हुआ। भारत से पोलैण्ड के आयात में १९५९ से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि उसने भारत के इंजीनियरिंग उद्योग के उत्पादनों की, उदाहरणार्थ, टैक्सटाइल मशीनों की खरीद शुरू कर दी।

भारत और पोलैण्ड के बीच आर्थिक सम्बन्धों में १९६० से एक बिलकुल नये तत्व का समावेश हुआ। ७ मई १९६० को दोनों देशों के बीच हुए प्रथम दीर्घकालीन समझौते से पोलैण्ड की भारत में नियोजित प्रगति के सिलसिले में एक उत्तरदायित्वपूर्ण स्थिति हो गई। दूसरे शब्दों में, पोलैण्ड भारत की प्रगति में एक साझेदार बन गया। १४३ करोड़ रुपये के ऋण ने भारत को तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अपने विकास कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण प्रायोजनाओं को पूरा करने में मदद दी। इनमें कोयला खान प्रायोजनाएं, कोयला साफ करने के कारखाने और बिजलीघर शामिल हैं।

इन ऋणों का भुगतान भारतीय माल के रूप में किया जायगा। यह तरीका दोनों पक्षों के लिए फायदेमन्द है, क्योंकि एक ओर तो यह पोलैण्ड को पूरे-पूरे औद्योगिक संयत्रों के निर्यात में वृद्धि करने में सुविधा प्रदान करता है, और साथ ही भारत को यह सम्भावना प्रदान करता है कि वह प्राप्त ऋण की अदायगी अपने माल के रूप में कर सके और पोलैण्ड में अपने निर्यात को बराबर विस्तृत कर सके।

अनुशासन में शक्ति,
यही देश की भक्ति।

प्रथम दीर्घकालीन ऋण समझौते में पोलैण्ड से कई एक उद्योगों के लिए मशीनरी मंगाने की व्यवस्था थी। नवम्बर १९६२ में घोषित १५ करोड़ रु० से अधिक के दूसरे दीर्घकालीन ऋण का उपयोग भारत द्वारा मुख्यतया अपने कोयला उद्योग के लिए किया जाएगा। • •

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बैंक और बीमा

बैंकों की नई प्रगति

१९६२ का वर्ष बैंकों के लिये बड़ा लाभप्रद रहा है। इस वर्ष में बैंकों में ग्रॉस डिपॉजिट पिछले वर्ष से २०१.४२ करोड़ रु० से बढ़कर २२३.१९ करोड़ रु० हो गये। बैंकों का विनियोजन भी आलोच्य वर्ष में ६५३.७० करोड़ रु० रहा। गत वर्ष से यह ५७.६९ करोड़ रु० अधिक है। इस विवरण तक सात बैंकों के कार्य विवरण ज्ञात हुए हैं। इनसे यह स्पष्ट है कि बैंकिंग की स्थिति बड़ी उत्साह-वर्धक रही। यह अंक देखते समय यह स्मरण रखना चाहिए कि इस वर्ष सेविंग खातों पर ब्याज दर ज्यादा देना पड़ा है। नये एवार्ड से भी बैंकों के खर्च बढ़ गये हैं। रिजर्व कोश में भी रुपया डालना पड़ा है।

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक—१९६२ में बैंक को करों की व्यवस्था करने के बाद पिछले वर्ष के ७२.६१ लाख रु० के स्थान पर ७३.३४ लाख रु० का लाभ हुआ है। अब रिजर्व कोष २ करोड़ ६० लाख रु० हो गया है। शेयरों पर पूर्ववत् १२% लाभांश कायम रखा गया है।

पंजाब नेशनल बैंक—इस बैंक ने १९६२ में अन्तरिम डिविडैण्ड को मिला कर २० प्रतिशत डिविडैण्ड देने का विचार किया है। बैंक को इस वर्ष टैक्स तथा ग्रैच्युइटी फण्ड निकालने के बाद १२४.१७ लाख रु. का लाभ हुआ है। इसमें गत वर्ष से आनीत १०.३८ लाख रु० भी सम्मिलित है। गत वर्ष कुल १२२.६३ लाख रु० लाभ हुआ था, जिसमें ४.३३ लाख उससे पिछले वर्ष का बकाया था।

यूनाइटेड बैंक ऑफ इन्डिया—इसके डिपाजिटों में ५ करोड़ रु० की वृद्धि हुई और जमा राशि६४ करोड़ रु० से अधिक रही। करों की व्यवस्था करने के बाद बैंकने २१.२० लाख रु० का लाभ दिखाया है, जबकि पिछले वर्ष २०.५० लाख रु० का लाभ था।

देना बैंक—की स्थिति भी बड़ी संतोषजनक रही। करों की व्यवस्था के बाद और पिछले वर्ष से अग्रानीत १३.५१ लाख रु० मिलाकर बैंक को, पिछले वर्ष के ३४.१ लाख रु० के स्थान पर ३७.५९ लाख रु० का लाभ रहा। बैंकने रिजर्व कोष में २३ लाख रु० दिये और अब रिजर्व कोष १ करोड़ रु० हो गया है। अब ३.५० रु० प्रतिशेयर अन्तिम लाभांश दिया गया है। इस प्रकार वर्ष का कुल लाभांश ११% हो गया है।

महाराष्ट्र बैंक—१९६२ में बैंकने ८.४४ लाख रु० का शुद्ध लाभ प्रदर्शित किया है जबकि पिछले वर्ष ८.२४ लाख रु० का शुद्ध लाभ था। लाभांश ९०% पर कायम रखा गया है।

बैंक ऑफ बरोदा—का शुद्धलाभ ६३.१९ लाख रु० रहा, जबकि पिछले साल ६७.६३ लाख रु० का शुद्ध लाभ था। १९६२ के लिये अन्तिम लाभांश पिछले १०% से घटाकर ८% कर दिया गया है। लेकिन यह स्मरणीय है कि इस वर्ष बैंकने १ लाख नये शेयर जारी कर अपनी पूंजी बढ़ा दी थी। इसी कारण से वर्ष का कुल लाभांश १७% के स्थान पर १६% हुआ है।

बैंक आफ इन्डिया—ने १९६२ में १११.५४ लाख रु० का लाभ प्रदर्शित किया है, जबकि १९६१ में ११०.३१ लाख रु० का लाभ था। गत वर्ष से अग्रानीत २९.१६ लाख रु. मिलाकर कुल वितरण योग्य लाभ १४०.७० लाख रु० होता है। बैंकने पहले कुल लाभांश २०% कर दिया है। यह लाभांश बढ़ी हुई पूंजी पर दिया गया है १९६२ में बैंकने ५० रु० चुकाये हुए २ लाख शेयर आर्डिनरी शेयर जारी किये थे। इसके अतिरिक्त गाड़ोदिया बैंक लि० अब इस बैंक में सम्मिलित हो गया है। • •

विदेशों में भारतीय बैंक

भारतीय बैंकों की ९६ शाखाएं भिन्न भिन्न देशों में हैं। इनमें से ४६ तो पाकिस्तान में हैं। ये सब शाखाएं पहले संयुक्त भारत में विद्यमान थीं। देश के विभाजन के परिणाम-स्वरूप उनकी गणना पाकिस्तान में होने लगी। शेष ५० शाखाएं भिन्न भिन्न देशों में हैं। इनमें से कुछ शाखा-कार्यालय अच्छा काम कर रहे हैं किन्तु अधिकांश शाखाओं का कारोबार शिथिल ही है। वे अभी तक बढ़ने आने वाली बाधाओं का सामना नहीं कर सके। सबसे बड़ी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बाधा यह है कि वहां नयी शाखा खोलने और चलाने में बहुत भारी खर्च होता है। फिर, उन देशों में विदेशी नागरिक बहुत कम डिपाजिट जमा कराते हैं। बैंक आफ बड़ौदा के मैनेजिंग डायरक्टर श्री एन. एन. चोक्शी ने एक भाषण में बताया है कि डिपाजिटों की इसी कमी के कारण इन शाखाओं का खर्च भी वहां से नहीं निकलता, हमें भारत से रकम भेजनी पड़ती है। इस लिए कोई भारतीय बैंक विदेशों में अधिक शाखाएं नहीं खोल सकता। श्री चोक्शी ने भारतीय बैंकों को स्वतंत्र रूप से एक स्वतंत्र "फोरन एक्सचेंज बैंक" खोलने की सलाह दी है। उनका यह सुझाव भारतीय बैंक स्वीकार करेंगे या नहीं और यदि करेंगे तो कब और किन शर्तों पर—यह अभी नहीं कहा जा सकता।

आयात जोखिम बीमा योजना

शत्रु की कार्रवाई से माल, कारखाने और देश के अन्दर के जहाजों की हानि के बचाव के लिए आपात जोखिम बीमा लागू हो गया है। इस योजना के अन्तर्गत माल के ८० प्रतिशत मूल्य का बीमा किया जाएगा और २० प्रतिशत मूल्य का जोखिम देश के लिए त्याग के रूप में बीमा कराने वाला स्वयं उठाएगा। इस योजना के अंतर्गत चाय की फसल और खनिज तेल उद्योग की सभी मशीनें तथा यंत्रादि विशेष तौर पर शामिल किए गए हैं, क्योंकि इनका लाभ पूरा देश उठाता है। बीमाशुदा माल के मूल्य पर प्रति १०० रु० पर १५ नए पैसे और कारखाने पर २५ नए पैसे तिमाही किश्त देनी पड़ेगी।

यह किश्त संकटकाल की पूरी अवधि के लिए निर्धारित नहीं की गई है। भविष्य में इसमें फेर बदल हो सकता है, परन्तु कानून में जो अधिकतम किश्त निर्धारित की गई है सरकार उससे आगे नहीं बढ़ेगी।

यह बीमा अनिवार्य किया गया है। इस बीमे के प्रीमियम से ३०-३५ करोड़ रुपये की आवक की जा रही है। अनेक क्षेत्रों में बीमे का प्रीमियम कम करने की मांग की जा रही है।

● ●

क्वालिटी मिनरल सप्लाई सिंडीकेट

प्रोप्राइटर—सी० डीडवानिया

मिनरल व केमिकल के व्यापारी

विशेषताएं

सुपर एक्टिवेटेड (Activated) फुलर्स अर्थ सोडियम तथा पोटेशियम बाईक्रोमेट सब प्रकार की Jack Hammers के स्पेअर पार्टस्

लिखें—४४ ओल्ड कस्टम हाउस स्ट्रीट,

फोर्ट बम्बई १

तार : Sympathy फोन : २५१८३५

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थवृत्त चयन

नारियल का तेल

अनुमान है कि १९६० में संसार में नारियल के तेल का उत्पादन २२ लाख टन था, जो सब वनस्पति तेलों के उत्पादन का लगभग १५ प्रतिशत है। सोयाबीन और मूंगफली के तेल के बाद इसका तीसरा नम्बर है। १९६० में. उत्पादक देशों ने १२ लाख टन नारियल का तेल निर्यात किया। यह कुल तेलों और तेलहन के निर्यात का २० प्र० श० है। नारियल के तेल और खोपरे की लगभग आधी मात्रा पश्चिमी यूरोप में और संयुक्त राज्य अमरीका में इस्तेमाल की जाती है।

नारियल के तेल में कुछ ऐसे गुण हैं, जो उसे मारगैरीन, और साबुन बनाने, तथा दूसरे उपयोगों के लिए बहुत उपयुक्त बनाते हैं। इसकी रासायनिक संरचना में लारिक एसिड का प्रतिशत ऊंचा होता है। संसार में इस प्रकार के केवल दो तेल हैं : नारियल का तेल और ताड़ की गिरी का तेल। लारिक और मारिस्टिक एसिड की अधिक मात्रा के कारण इसका साबुनीकरण सूचक अंक बहुत ऊंचा, २४६ से २६० तक होता है। नारियल के तेल के इस गुण के कारण आसानी से घुलने वाला साबुन बनता है और डिटरजेंटों की झाग देने की क्षमता को बढ़ाता है।

अनुमान है कि भारत में नारियल का आधा उत्पादन खाने के काम में आता है। बिना किसी विशेष शोधन के यह वस्तुओं को तलने के काम में लाया जाता है। इसकी थोड़ी-सी मात्रा, जमाया हुआ तेल बनाने में भी इस्तेमाल की जाती है, पर इस काम के लिए, सस्ते होने के कारण भारत में दूसरे तेल, विशेषतया मूंगफली का तेल, अधिक पसन्द किया जाता है। १९५८ में भारत में जमाये तेल बनाने के लिए ३,०९,००० टन तेल काम में लाया गया था। इसमें नारियल के तेल की मात्रा केवल १०० टन थी, जबकि मूंगफली का तेल २,८०,००० टन था। कुछ नारियल का तेल बेकरी और बिस्कुट बनाने में भी काम आता है। इनके अतिरिक्त जान पड़ता है कि इसका उपयोग घी जैसी अधिक मंहगी वस्तुओं में मिलाने के लिए भी किया जाता है। इस तेल की काफी मात्रा शृंगार और शृंगार सामग्री में उपयोग की जाती है। यह बालों में लगाने और शरीर पर मलने के लिए काम में लाया जाता है। थोड़ा दीपों में जलाने और पुर्जों को चिकनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।

खोपरे और नारियल के तेल के प्रमुख आयातक अब भी पश्चिमी यूरोप के देश हैं। कुल आयात का लगभग ५६ प्र० श० प० यूरोप में और २८ प्र० श० संयुक्त राज्य अमरीका में जाता है। पश्चिमी यूरोप में इसका अधिकतर भाग खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि संयुक्त राज्य अमरीका में अधिकतर तेल अखाद्य वस्तुओं के बनाने में लगाया जाता है।

इस बात की काफी आशा है कि संसार में नारियल के तेल की मांग बढ़ती रहेगी। अधिकतर उत्पादक देशों में नारियल के तेल का खाने में उपयोग बढ़ेगा। इन देशों की जनसंख्या में वृद्धि होने से तो इस तेल की खपत बढ़ेगी ही, इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास से लोगों की आमदनी में जो वृद्धि होगी, उससे भी इस तेल का अधिक उपयोग किया जाएगा। पिछले दिनों में मारगैरीन निर्माण में नारियल के तेल के उपयोग में कमी आई है। इसके स्थान पर समुद्री मछलियों का तेल सस्तेपन के कारण अधिक काम में लाया जा रहा है। साबुन उद्योग में भी इसकी मांग नहीं घट जाएगी, क्योंकि औद्योगिक देशों में साबुन की बजाय संप्रेषित डिटरजैण्टों का प्रयोग बढ़ रहा है।

प्रति ग्राम में सुरक्षा व्यवस्था

मैंने कई दफा कहा है कि हमारी पंचवर्षीय योजना में हम यह मान कर चले हैं कि दुनिया में शांति रहेगी, दुनिया में शांति की आशा रखते हुए उसके आधार पर ही हमारी योजनाएं बनायी गयीं। लेकिन दुनिया में अशांति हुई और भारत के ही नजदीक अशांति हुई तो क्या होगा? हमारे आयात-निर्यातों में बाधा पहुँचेगी, हमारे व्यवसाय-वाणिज्य को धक्का लगेगा। तब योजना का क्या होगा? उसकी जरूरतें पूरी नहीं होंगी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

योजना गिरेगी। आज की योजनाएं अशांति के समय कुछ काम नहीं आ सकती हैं।

लेकिन हमारा ग्रामदान का जो विचार है, वह शांति के समय में तो चलेगा ही, अशांति हो तब भी चलेगा। इतना ही नहीं, अशांति के समय उसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। जब आयात-निर्यात बन्द हो, बाहर से चीजें नहीं आयेंगी और योजनाएं स्थगित हो जायेंगी तो क्या हालत होगी?

—विनोबा

एक जान लेने का खर्च १०,०००० पौंड

पिछले सालों में लड़ाई में किसी आदमी को मारना बहुत अधिक खर्चीला न था। एक सैनिक को मारने का प्रतिव्यक्ति खर्च जो प्रथम महायुद्ध में १०,००० पौंड था, द्वितीय महायुद्ध में १००,००० पौंड हो गया। लेकिन २००० वर्ष पहले किसी भी लड़ाई में एक व्यक्ति को मारने का खर्च केवल एक रुपया था। अब भी अणु-शक्ति के द्वारा यह खर्च घट कर उतना रह जाएगा, जितना २००० वर्ष पहले था। विज्ञान के एक प्रसिद्ध विद्यार्थी ने बतलाया है कि अगर रूस और अमरीका दोनों युद्ध में जुट जाएं तो लगभग ५ खरब टन शक्ति का प्रयोग होगा।

दोनों देशों ने अब तक अपने अणु-परीक्षणों में कुल ५ अरब टन T. N. T. (विस्फोटक शक्ति) का प्रयोग किया है, जबकि अब तक के सारे युद्धों में केवल ५० लाख टन T. N. T. (विस्फोट शक्ति) का प्रयोग किया गया था।

—जी. एस. कोठारी

अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

सबसे बड़ा कार्य

"सबसे बड़ा काम स्वतंत्रता के इन वर्षों में क्या हुआ? विधान का बन जाना, उसके अनुसार चुनाव हो जाना, रियासतों का एकीकरण, काश्मीर में कबायलियों का मानमर्दन, भारत की विदेशों में प्रतिष्ठा, उद्योगों की वृद्धि, पुनर्वास, सभी एक से एक बढ़कर हैं, पर मेरी राय में सबसे बड़ा काम है फावड़ों का जाग उठना—जनता में अपना काम स्वयं करने की भावना का जागरण होना।'

"जगह-जगह लोग फावड़े-टोकरे लेकर इकट्ठे हो जाते हैं और बस देखते-देखते कुआं खुद जाता है, सड़क बन जाती है, तालाब चौड़े हो जाते हैं, स्कूल बन जाता है और उसमें खर्च इतना कम होता है कि हमारे इंजीनिअर उसका हिसाब ही नहीं सोच पाते। सभी दिशाओं में जीवन का स्पंदन आरम्भ हो गया है और निर्माण इतनी गति से हो रहा है कि यह आशा किसी तरह भी शेखचिल्ली का पुलाव नहीं कि अगले १० वर्षों में नया भारत हमें आंख के सामने दिखाई देने लगेगा।"

—श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर'

● ●

हमारी प्रतिज्ञा

भारत के चौदहवें गणतंत्र दिवस पर हम प्रजातंत्र के सिद्धांत में विश्वास प्रकट करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं कि :—

(१) देश की रक्षा के लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने से संकोच नहीं करेंगे।

(२) हम आशा और विश्वास के साथ संकल्प करते हैं कि लड़ाई कितनी ही लम्बी और कितनी ही कठिन क्यों न हो, हमला करने वालों को भारत की पवित्र धरती से निकाल कर ही दम लेंगे।

(३) यह देश हमारा है। हम देश के हैं। देश के लिए जिएंगे। देश के लिए मरेंगे।

जयहिन्द

पंजाब राज्य की नागरिक परिषद् की लोक-सम्पर्क समिति की ओर से प्रचारित

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तटस्थ-नीति

(पृष्ठ ७४ का शेष)

है। अणु अस्त्र तैयार करने की भी उसमें क्षमता है। अतः आर्थिक दृष्टि से भारत और पाकिस्तान—तटस्थ और गैर तटस्थ देशों में भारत की आर्थिक अवस्था पाकिस्तान से श्रेयस्कर है। वस्तुतः, सहायता की रकम तो नहीं, सहायता का प्रतिरूप देश के आर्थिक विकास का निर्माण करता है, जिससे वह सुदृढ़ होता है। भारत को इस मामले में निराश होने का कोई कारण नहीं है। यह तर्क किया जाता है कि प्रत्यक्ष विदेशी विनियोजन इस देश में बढ़ता, यदि हम तटस्थ न होते और पश्चिमीय देशों से मिले होते। पर ऐतिहासिक तथ्यों से इसका सही निरूपण नहीं होता है। १९वीं सदी में एशियाई देशों में जो प्रत्यक्ष विनियोजन हुआ, उससे लाभ की अपेक्षा हानि हुई। यह विनियोजन उन प्राथमिक पदार्थों के उत्पादन में हुआ, जिनसे नीचे दर्जे की आर्थिक वृद्धि हुई। यह विनियोजन बड़े परिमाण में होने पर भी देश अविकसित रहे। फिर व्यापार की विपरीत शर्तों से देश की भारी धन राशि बाहर गयी। इस सारे उत्पादन से देश की जनता को बहुत कम लाभ मिला। संसार के आज को ढांचे में कोई भी देश बिना प्रतिबन्ध के विनियोजन स्वीकार नहीं कर सकता। वह अपनी आर्थिक और राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिए बिना प्रतिबन्ध के विनियोजन को घातक मानता है। उदाहरण के लिए, मध्य पूर्व और लेटिन अमेरिका के देश हैं, जो विदेशी विनियोजकों के गढ़ हैं पर उनकी अर्थ व्यवस्था ने उनके स्वतन्त्र विकास को दबा रखा है।

व्यापार पर प्रभाव

तटस्थता की नीति का भारत के व्यापार पर काफी प्रभाव पड़ा। अतीत में भारत का व्यापार पश्चिमी संसार से सम्बन्ध रखता था, विशेष रूप से ब्रिटेन से। एक देश या कुछ देशों के दल पर आश्रित रहना किसी राष्ट्र के लिए लाभजनक नहीं है, विशेषतः जिस देश के आर्थिक स्रोत स्वल्पतम हैं। यह आश्रित अवस्था तब और भी हानिकारक होती है, जब उन देशों में निर्यात पदार्थों की मांग गिरती जाती है और उनकी आमद पर प्रतिबन्ध लगते हैं। इसलिए व्यापार का सब ओर विस्तार होना आवश्यक है। इसी दृष्टि से भारत ने सोवियत रूस और योरप के पूर्वीय देशों से तटस्थता की नीति द्वारा अपना व्यापार बढ़ाया। हमारा पूर्वीय योरप और सोवियत रूस से कुल आयात का १९५२-५३ में ०·३ प्रतिशत था, किन्तु १९५९-६० में ३.७ प्रतिशत तक पहुँच गया। १९५२-५३ में इन देशों में हमारा निर्यात ०·४ प्रतिशत था, किन्तु १९५९-६० में ८.० प्रतिशत पहुँच गया। इन देशों से आयात का भुगतान रुपए द्वारा किया गया, जिससे हम पर विदेशी मुद्रा का कोई भार नहीं पड़ा। देश में विदेशी मुद्रा के अभाव में रुपए के भुगतान की सुविधा अत्यन्त सहायक हुई। यदि विदेशी राष्ट्र आर्थिक सहायता देने की अपेक्षा सहायता लेने वाले देशों का माल खरीदने की ओर बढ़ें, तो अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट मिट सकते हैं। सोवियत रूस और पोलेण्ड से व्यापारिक इकरारनामों के साथ भारत को यह भी सुविधा मिली कि सामान अपने-अपने जहाजों से भेजा जाए। भारत जहाजी किराये के मद में प्रति वर्ष १५० करोड़ रुपए व्यय करता है, उसमें भारत के जहाजों का हिस्सा केवल २० करोड़ रुपए का है। १३० करोड़ रुपए का किराए का भुगतान भारत की विदेशी मुद्रा के स्रोत पर जबर्दस्त प्रहार है। सोवियत रूस से जहाज का जो इकरार नामा हुआ, उससे भारत प्रतिवर्ष १ करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाने में समर्थ हुआ। आगे चलकर भारत सात आठ करोड़ रुपए बचा सकेगा।

टेक्नीकल सहायता

टेक्नीकल सहायता के क्षेत्र में भारत ने तटस्थता की नीति द्वारा अतिशय लाभ उठाया है। इस देश ने संसार के सभी देशों से टेक्नीकल सहायता उपलब्ध की। अमेरिका से टेक्नीकल सहायता प्रोग्राम के अन्तर्गत ६१४ विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त कीं और १९६१ तक १६०८ भारतीय विशेषज्ञों को अमेरिका में शिक्षा मिली। टेक्नीकल सहायता के अंतर्गत अमेरिका ने रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किए और तत्सम्बन्धी अन्य सुविधाएं दीं। सोवियत रूस ने कोयला, खनिज तेल, और लोहा तथा इस्पात के क्षेत्रों में टेक्नीकल सहायता दी। इन क्षेत्रों के देश में जबर्दस्त स्रोत हैं और अभाव केवल टेक्नीशियनों का है। टेक्

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शियनों के द्वारा हम इन स्रोतों से पूरा लाभ उठा सकते हैं। कोलम्बो योजना के अंतर्गत ब्रिटेन ने भी हमें टेक्नीकल सहायता दी। टेक्नीकल शिक्षा की व्यवस्था के सिवाय ब्रिटेन ने १९६१ तक ३३ मिलियन रुपए के औजार दिये। कनाडा और पश्चिम जर्मनी ने भी हमें इस प्रकार की सहायता दी। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था से भारत के ११२३ युवाओं ने विदेशों में टेकनिकल शिक्षण प्राप्त किया और ११७३ विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त कीं। राष्ट्र संघ ने ३.८ मिलियन डालर के औजार भी दिए।

यह कहानी स्वयं प्रकट करती है कि देश का किस नीति के अपनाने में लाभ है। तटस्थता शांति का मार्ग है, तटस्थ देश किसी से शत्रुता पैदा नहीं करता है और न किसी के संघर्ष में बढ़ता है। इस तटस्थ नीति द्वारा ही भारत अन्य देशों के सहयोग से अपने आर्थिक विकास में अग्रसर हो रहा है। ● ●

दादाभाई नौरोजी

(पृष्ठ ६४ का शेष)

अपने अनुभवी जीवन का प्रमाण दादा भाई नौरोजी ने एक नया 'विदेशी शोषण का सिद्धान्त' निकालकर दिया जो बाद में जाकर प्रसिद्ध उत्सारण सिद्धान्त (The Drain Theory) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। संक्षेप में यह सिद्धान्त बताता है कि स्वदेश वासियों की सरकार देश में चाहे कुछ भी और किन्हीं भी तरीकों से धन उपार्जन करती हो, यह धन कुछ प्रवाह बदलकर देश में ही रहता है। और देश की सम्पत्ति में ह्रास नहीं होता। मगर विदेशी सरकारों से एक देश में उपार्जित धन (जैसा कि भारत में) विदेशों में चला जाता है तथा प्रतिवर्ष देश की सम्पत्ति का ह्रास होता रहता है। इसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने कहा कि (१) उत्पादन का कुछ हिस्सा ब्रिटिश भारत से इंगलैण्ड निर्यात कर दिया जाता है और बदले में किसी भी प्रकार का समान कुछ नहीं आता, (२) किसी भी अवस्था में निर्यात का लाभ देश को नहीं मिलता तथा (३) निर्यात का भाग जो देशी रियासतों का है, तथा जो लाभ देशी रियासतें कमाती है, वे कुल आयात में शामिल कर लिए जाते हैं, जबकि वे मूल या वास्तविक निर्यात में आने चाहिए। इसको उन्होंने व्यापारिक आंकड़ों के आधार पर सिद्ध भी किया।

दादा भाई नौरोजी ही ने लोगों को बताया कि आर्थिक उन्नति ही चारित्रिक उन्नति का पथ प्रदर्शन करती है। और यही कारण है कि भारत का आर्थिक ह्रास ही उसकी गिरती हुई अनुभव गत योग्यता और चारित्रिक पतन के लिए उत्तरदायी है। विदेशी सरकारी संस्थाएं ही हमारी गरीबी का मूल कारण हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि दादाभाई नौरोजी एक सामाजिक दर्शनशास्त्री थे, जो अर्थशास्त्री के रूप में पुराने (क्लासिकल) अर्थशास्त्रियों से ज्यादा भिन्न न थे और अपने समय की राजनैतिक समस्याओं में उलझे हुए थे। फिर भी वे किसी विशेष समुदाय या विचारों के दल से अपना सम्बन्ध नहीं रखते थे। नौरोजी ने अपने समय के देश के आर्थिक ढांचे को लोगों के सामने स्पष्ट रूप से रखा तथा हर संभव तरीके से देश की आर्थिक दशा सुधारने का प्रयत्न किया। एक विदेशी सरकार का शासित देश के प्रति क्या कर्त्तव्य होना चाहिए यह उन्होंने बारबार अंग्रेजों को बताया। उनके अनुसार देश का कल्याण उसकी सुदृढ़ आर्थिक स्थिति पर ही निर्भर करता है। आर्थिक स्थिति देश की उत्पादन शक्ति पर निर्भर रहती है और यह उत्पादन शक्ति देश के वार्षिक भौतिक उत्पादन पर निर्भर करती है। इसके माप के लिए उन्होंने राष्ट्रीय आय प्राक्कलन किया। उस समय आर्थिक विचार (economie concepts) स्पष्ट नहीं थे और न ही आवश्यक आंकड़े उपलब्ध थे। इन कमियों के बावजूद भी दादाभाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे, जिन्होंने न केवल इन विचारों को भलीभांति समझा, बल्कि भारत की स्थिति को समझने और समझाने के लिए इनका उपयोग भी किया।

सम्पदा के

आगामी विशेषांक की

घोषणा की

प्रतीक्षा कीजिये

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

साम्यवादी देशों.....

(पृष्ठ ६४ का शेष)

बड़े भाग पर एकाधिकार कर लिया है, परन्तु समय-समय पर प्रकाशित समाचारों व विवरणों से इन सरकारी उद्योगों की शिथिलता, अक्षमता और राष्ट्रीय हानि का ज्ञान होता रहता है। स्वयं योजना आयोग ने भी सरकारी उद्योगों की प्रबन्ध शिथिलता व अव्यवस्था को स्वीकार किया है। लोकतंत्र में जो अनुशासन के सिद्धान्त पर आधारित होता है।

राजकीय उद्योगों द्वारा कानून का व्यापक उल्लंघन करना बड़ी गम्भीर बात होती है। अगस्त, १९६२ में दिल्ली में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन में कम्यूनिस्ट पार्टी के मजदूर नेता श्री एस० ए० डांगे ने, जिनकी पार्टी समस्त राष्ट्रीयकरण के लिए जोर देती है, कहा कि देश में श्रम कानूनों को सबसे ज्यादा भंग करने वाले हैं राजकीय उद्योग। राज्य सरकारों के अधिकारी अफसर यह शिकायत करते रहते हैं कि राजकीय उद्योग फैक्टरी कानून तथा अन्य नियमों की ओर बहुत कम ध्यान देते हैं। अतः आश्चर्य नहीं है कि विशाल राजकीय उद्योग, हेवी इलेक्ट्रिकल्स (भारत) लिमिटेड की पांचवी वार्षिक रिपोर्ट (१९६०-६१) में आडिटरों ने यह टिप्पणी की है; 'कम्पनी कानून की व्यवस्थाओं को भंग करने की घटनाएं हुई।'

प्रकाशित विवरणों से भी यह बात अब साफ जाहिर हो रही है कि उनमें ऐसी कमजोरियां हैं जो सार्वजनिक हित के लिए घातक है। इसलिए अब राष्ट्रीयकरण और राजकीय मालिकी के बारे में बुनियादी नीति की समीक्षा करने का समय आ गया है। रूस आदि समाजवादी सरकारों के अनुभव भी इस प्रकार की नीति की अनुपयोगिता साबित कर रहे हैं। बम्बई के एक दैनिक समाचार पत्र में लन्दन की दिनांक १५ अक्टूबर १९६२ की एक खबर में कहा गया है : 'इस वर्ष ब्रिटेन के अधिकांश राजकीय उद्योगों को अधिक घाटा होने, और बैंकों तथा सरकार से उनके लगातार काफी कर्ज लेने के फलस्वरूप, राष्ट्रीयकरण के सारे सवाल पर देश में अब एक नया और आलोचनात्मक रुख अपनाया जा रहा है।'

हमारे देश की जनता भी अब राष्ट्रीयकरण और सार्वजनिक क्षेत्र बढ़ाने के नारों से प्रभावित नहीं होती है। समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाले अनेक पत्रों में इस उतरोत्तर बढ़ते हुए सन्देह को व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के तौर पर २६ अक्टूबर, १९६१ के बम्बई के एक दैनिक पत्र में, मेरीटाईम यूनियन आफ इण्डिया के जनरल सेक्रेटरी, श्री जे० आर० रानदेरी ने उस स्थिति पर प्रकाश डाला है जो समुद्री किनारे की फेरी सर्विस पर सरकार की मालिकी के बाद पैदा होगी। सरकार 'किराये की दरों को बढ़ा देगी जैसा कि उसने इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन, रेल परिवहन और मोटर बस परिवहन और व्यवहारतः उन प्रत्येक उपयोगिता संस्थानों में किया है, जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया है। समय का रुख शायद अब इसी तरह का है।' एक लेखक के शब्द थे।" साम्यवाद, तीन महत्वपूर्ण पहलुओं में असफल रहा जो देश के घोषित उद्देश्य हैं। उसने जीवनमान में वृद्धि नहीं की है; उसने बेरोजगारी दूर नहीं की है; और उसने शक्ति के केन्द्रीयकरण पर रोक नहीं लगा पाई है..... ।

सौभाग्य से, कम्यूनिस्ट नमूने के नियोजन और समाजवाद का विकल्प मौजूद है। समय की कसौटी पर खरा उतरा हुआ वह नमूना है जनता का स्वतंत्र उद्योग के लिए नियोजन। संक्षेप में इसका मतलब होता है कि राज्य अपने सुरक्षा और शांति एवं व्यवस्था के प्राथमिक कार्यों को देखे तथा अर्थव्यवस्था के बाहरी ढांचे की व्यवस्था करे, जिससे जनता के निजी उद्योग अर्थात् स्वतंत्र उद्योग का भरपूर विकास हो सके। राज्य, अर्थव्यवस्था का सामाजिक मार्गदर्शन करे, मालिकी के जरिये नहीं, बल्कि नियमन के जरिये। इससे न केवल व्यक्तिगत पहल और उद्योग को पूरा मौका मिलेगा और व्यापक पैमाने में तेजी से विकास होगा बल्कि सामाजिक नियंत्रण और न्याय के उद्देश्य भी प्राप्त हो सकेंगे। ● ●

रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक विवरण से ज्ञात होता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में निजी क्षेत्र में कुल पूंजी १४८४ करोड़ रुपया लगाई गई है। इसमें से १२३४ करोड़ रुपया तो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा एकत्रित किया गया है और २५० करोड़ रुपये की पूंजी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों ने की है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस मास की आर्थिक घटनाएं

कोलम्बो योजना

कोलम्बो योजना की सलाहकार समिति की ग्यारहवीं वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में आर्थिक विकास की आवश्यकता बढ़ गयी है और कुछ देशों में यह काम और भी मुश्किल हो गया है। इस काम में काफी प्रगति हुई है, लेकिन अब भी इस क्षेत्र की जनता का रहन-सहन सुधारने के लिए काफी कुछ करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि १९५० में कोलम्बो योजना की स्थापना के समय से जून, १९६२ तक दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के दो देशों को कुल १२०० करोड़ डालर की बाहरी मदद मिली। सन् १९६१-६२ में कुल १८१ करोड़ ५० लाख डालर की मदद मिली। आलोच्य वर्ष में आर्थिक विकास के साधनों में लगातार वृद्धि हुई। अनुमान है कि १९६२-६३ में इस क्षेत्र के १५ देशों ने अपने विकास कार्यक्रमों पर कुल ५४० करोड़ डालर खर्च किए और १९६२-६३ में ६७० करोड़ डालर खर्च होने की आशा है। यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश देशों ने इस खर्च का काफी भाग शिक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर खर्च किया।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत इस क्षेत्र के देशों को बाहर से मुख्यतः ६ देशों—आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड और अमेरिका से तथा विश्वबैंक—से सहायता मिलती है। आलोच्य वर्ष में आस्ट्रेलिया ने ३९,९९,००० आस्ट्रेलियायी पौंड की शिल्पिक और पूंजीगत सहायता दी। ब्रिटेन ने ३,०९,७०,००० पौंड की सहायता दी। कनाडा ने ३८,१७,००,००० डालर की सहायता दी। न्यूजीलैंड ने २० लाख पौंड की सहायता दी। विश्वबैंक ने १९६१-६२ में २० करोड़ डालर की सहायता दी।

सरकारी तेल शोधक कारखानों का विस्तार

तीन गैरसरकारी तेल शोधक कारखानों के विस्तार और दक्षिण भारत में एक नए तेल शोधक कारखाने की स्थापना से तीसरी योजना के अन्त तक सरकारी क्षेत्र में तेल का उत्पादन ४७ लाख टन से बढ़कर १ करोड़ टन हो जायगा। गुहाटी, बरौनी और कोयली के तीन गैर सरकारी तेल शोधक कारखानों में २५ लाख टन और तेल उत्पादन किया जा सकेगा। चौथे सरकारी तेलशोधक कारखाने में २५ लाख टन तेल का उत्पादन हो सकेगा। इस बात की घोषणा करते हुए केन्द्रीय खान और तेल मंत्री श्री केशवदेव मालवीय ने बताया कि गोहाटी और सिलीगुड़ी के बीच शीघ्र ही एक पाइप लाइन बनाने की कोशिश की जा रही है।

नंगल उर्वरक कारखाने का उत्पादन लक्ष्य के लगभग बराबर पहुँच गया है। चालू वित्त वर्ष में अब तक लगभग २ लाख टन उर्वरक का उत्पादन हो चुका है।

गिनने वाली मशीन का भारत में निर्माण

गिनने और जोड़ करने वाली मशीन बनाने का कारखाना ३४ लाख रु० की लागत से एक स्वीडन कम्पनी के सहयोग से मद्रास के पास शीघ्र खुलने वाला है। इसका नाम होगा "फेसिट एशिया लि०"। भारतीयों को इस विषय का तकनीकी ज्ञान और मशीनरी सम्बन्धी जानकारी सिखाने की जिम्मा स्वीडन कम्पनी ने लिया है।

भारत-अरब में व्यापार समझौता

भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के मध्य हाल ही में हुए व्यापार समझौते के अनुसार वर्तमान समझौते को ही फरवरी १९६६ तक बढ़ाते हुए यह निश्चय किया गया है कि दोनों देशों के बीच ५० प्रतिशत व्यापार बढ़ाया जाए। अरब गणराज्य भारत से चाय, जूट, इंजिनीयरी का सामान, फार्मेसी की, और कीटनाशक औषधियां लेगा तथा भारत अरब गणराज्य से कपास, चावल और पथरी फास्फेट लेगा।

कार्बन ब्लैक कारखाना

दुर्गापुर (पं० बंगाल) के पास कार्बन ब्लैक का कारखाना चालू हो गया है। इस से देशकी कार्बन ब्लैक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की समूची मांग पूरी हो सकेगी और प्रतिवर्ष लगभग दो करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की बचत हो जाएगी।

—सोवियत रूस ने परीक्षण के रूप में भारत से २८ लाख रु० के लगभग ४,००० टन के ताजा केले आयात करना मंजूर कर लिया है। सहकारी उत्पादकों द्वारा ये निर्यात किये जाएंगे।

—१,००,००० टन की क्षमता वाला पिग आयरन का संयंत्र उदयपुर में १९६५ के अन्त तक उत्पादन प्रारम्भ कर देगा। एक विदेशी कम्पनी इसके लिए तकनीक सहायता देगी।

—जीवन बीमा संघ द्वारा अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के साथ सम्पुष्ट किये गये पंचवर्षीय समझौते के अनुसार, जो १ जनवरी १९६२ से कार्यान्वित होगा—वेतन-स्तर, मकान-भाड़ा-भत्ता, इत्यादि समूचे देश के बीमा कर्मचारियों के लिए एक सदृश होंगे और महंगाई भत्ते और जीवन-निर्वाह व्यय अंक की दृष्टि से होंगे तथा १॥ मास का गारंटी शुदा वार्षिक नकद बोनस दिया जाएगा।

—रूस से भारत का व्यापार निरन्तर बढ़ रहा है। १९५८ में दोनों देशों ने पंचवर्षीय व्यापारिक समझौता हुआ था। १९६४ से नया व्यापारिक समझौता होगा। दोनों देशों में परस्पर व्यापार बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने मास्को में जुलाई १९६३ में एक प्रदर्शनी करने का निश्चय किया है। इसके लिए एक परामर्श समिति भी बनाई गई है। उसके अध्यक्ष भारत के प्रमुख उद्योगपति श्री घनश्यामदास बिड़ला है।

—बिहार राज्य के १९६३-६४ के बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है और न ही मौजूदा करों में कोई वृद्धि की गई है। बजट में नाममात्र का १३ लाख रु० का सरप्लस दिखाया गया है। कुल आय १६२.३३ करोड़ रु० और कुल व्यय १६२.२० करोड़ रु० होने की आशा है। बिहार की राष्ट्रीय आय में १९६१-६२ में ४.९७ प्रतिशत वृद्धि हुई है, १९६०-६१ में प्रदेश की राष्ट्रीय आय ८६५.५३ करोड़ रु० थी और १९६१-६२ में इसमें ४३.२० करोड़ रु० की वृद्धि हुई पर प्रति व्यक्ति आय में आबादी में बढोतरी होने से कोई वृद्धि नहीं हुई।

—एक सरकारी सूचना के अनुसार निर्यात के लिए जेवर बनाने वाले सर्राफ १४ कैरट से भी अधिक का जेवर बना सकेंगे, बशर्ते इसके लिए बुनियादी सोना विदेशी ग्राहक की ओर से दिया जाए। स्वर्ण नियन्त्रण बोर्ड के अध्यक्ष श्री जी० बी० कोटक के अनुसार मध्य पूर्व देशों और स्विट्जरलैंड में तस्कर व्यापार द्वारा प्रति वर्ष ५० करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा भारत से बाहर जाती है जिसका प्रधान कारण अन्तर्राष्ट्रीय और भारत में सोने के भावों में भेद है।

पांच पैसे में नया संसार

बांझपन

का ठेके पर इलाज। पहले सफलता पीछे दाम। ब्यौरे के लिए लिखें—

डायरेक्टर—**श्री कुशलभवन, नाभा**

(पंजाब)

सचित्र लोकप्रिय पारिवारिक मासिक

उषा

★ सामाजिक कहानियां, शिक्षाप्रद कथानक, विचारोत्तेजक मनोरंजक लेख, राशिफल, सरस, कविताएं आदि।

★ हानिकारक वस्तुओं, व अश्लील फिल्मों के विज्ञापन स्वीकार नहीं किये जाते।

—यदि आपने अभी तक उषा नहीं देखी है तो शीघ्र ही ३२ न० पै० की टिकिट या मनीआर्डर भेजकर नमूनांक मंगा देखिये। हमें पूरा विश्वास है कि एक बार 'उषा' को देखने के बाद आप हमेशा के लिए उसके हो जाएंगे।

—अन्य जानकारी के लिए लिखिये

सचित्र मासिक उषा कार्यालय,

जवाहर मार्ग, इन्दौर।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यह अपने प्रण को दोहराने का समय है

आइये, आज हम हमलावर को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपने प्रण को दोहराएं। चौकसी और दृढ़ निश्चय में किसी तरह की ढिलाई न आने दें क्योंकि यह आपका अपना युद्ध है। यह फौरन काम करने का वक्त है। राष्ट्र सेवी संगठनों के स्वयंसेवकों की सूची में अपना नाम लिखवायें। कोई भी चीज ज़ाया न करें और फजूलखर्ची बिल्कुल बंद कर दें। खाने की चीजें और कपड़ा बहुत आवश्यक वस्तुएं हैं। इन्हें व्यर्थ नष्ट न करें। समय बड़ा कीमती है। इसे व्यतीत घंटों में न नापें बल्कि यह सोच कर नापें कि आपने क्या क्या काम कर लिया है। अपनी जिम्मेदारी निभायें। हर मामले में और हर समय अनुशासन से काम करें।

चौकस रहें

राष्ट्र की तैयारी में हाथ बटायें

DA62/F5

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुस्तकालय गुरुकुल काँगड़ी

पनिहारिन की अभिलाषा

बहुत दिनों से सोचती थी कि देहातों में
सुन्दर व सस्ते वस्त्र कहां से मिलें।
हमारे परिवार की आमदनी भी सीमित है।

सहसा—

जे० सी० एम० फब्रिक्स

की ओर मेरा ध्यान गया। दूसरे ही
दिन से इन्हें पहिन कर एक सुसज्जित
गृहिणी बन गई।

★

इनकी विशेषताएँ:—

मनभावन रंगों व नयी डिजायनों में बनी छींटें :—
रेजिस्ट, डिस्चार्ज, ओवर डाइड
ब्लीच्ड घाघरापाट, वायल पर छपी साड़ियां
पोपलीन, फलालेन, रंगीन व प्रिन्टेड।
इसके अलावा दूसरी किननी ही नवीनताएं।

निर्माता:—

जियाजीराव काटन मिल्स

बिरला नगर, ग्वालियर

सम्पादक—कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा नवचेतन प्रेस (प्रा०) लि० (लीजिज ऑफ अर्जुन प्रेस) दिल्ली-६ से
अशोक प्रकाशन मन्दिर, २८/११, शक्तिनगर, दिल्ली-६ से प्रकाशित।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा

वर्ष १२ : अंक ३

मूल्य
न. पै

अशोक प्रकाशन मन्दिर शक्ति नगर, दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

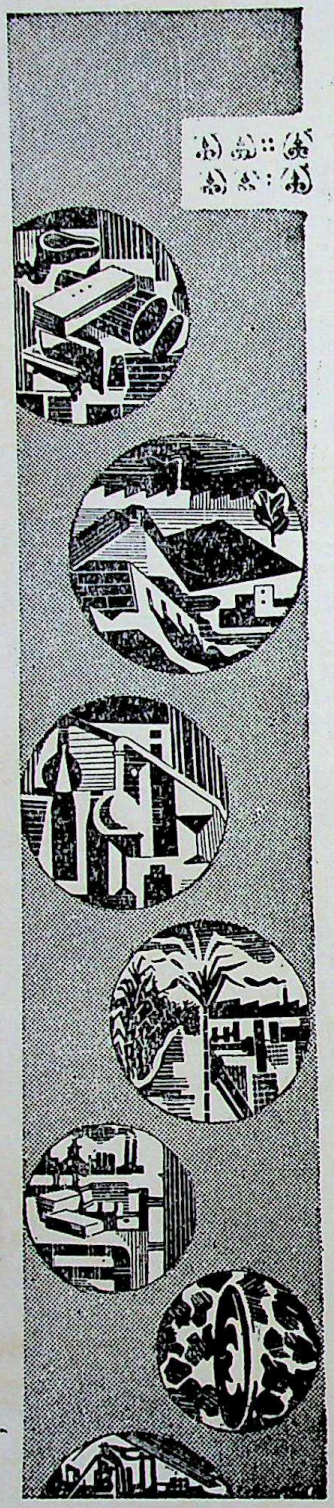

नये क्षितिज

स्वतंत्रता पूर्व युग में भी जनता के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए भारत की योजनाएं और कार्यक्रम थे। पर उनमें मौलिक निर्बलता थी—कि उनका सम्बन्ध जनता की अपेक्षा सरकार के साथ अधिक था।

स्वतंत्रता आई और इसके साथ नव-जागरण और जनता की योजनाएं—जनता के लिए और जनता के द्वारा। इसके परिणाम स्पष्ट थे. अधिक से अधिक बेहतर व सस्ती वस्तुएं अधिक से अधिक लोगों के लिए बेहतर जीवन।

डालमिया उद्योग समूह

निरन्तर ऐसे सामान का अधिक से अधिक उत्पादन करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो हमारे जीवन स्तर को ऊंचा करने में सहायक हो। हम यह काम न केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से किन्तु लगभग एक चौथाई सदी से कर रहे हैं। यह काम कठिन होते हुए भी हम निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं, इस आशा के साथ कि कल का दिन अधिक उज्ज्वल, नव-प्रभात एवं नये क्षितिज से युक्त होगा।

DALMIA ENTERPRISES

डालमिया सिमेंट (भारत) लि., डालमियापुरम् (मद्रास)
डालमिया आयरन एंड स्टील लि., राजगंगपुर व कलकत्ता
डालमिया मेगनेसाइट कार्पोरेशन, सेलम (मद्रास राज्य)
उड़िशा सिमेंट लि. राजगंगपुर (उड़िशा राज्य)
रजा बुलन्द शूगर कं. लि., रामपुर (उ. प्र.)
दि रामपुर डिस्टिलरी एंड केमिकल कं. लि., रामपुर (उ.प्र.)

राष्ट्र की सेवा में सन्निहित

डालमिया उद्योग-समूह

मुख्य कार्यालय—४, सिन्धिया हाउस, नयी दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सारे परिवार के लिए

डी सी एम

के उच्च कोटि के कपड़े

पापलिन •	छीटें •	मलमल
लिनो •	लान्स •	लट्ठा
साड़ियाँ •	शर्टिंग्ज •	ड्रिल्स
शर्टिंग्ज •	सजावट के कपड़े •	तौलिए

एवं बेड शीट्स आदि

आकर्षक रंगों, शेडों और बनावटों में

डी सी एम के सभी रिटेल स्टोर्स में प्राप्य है ।

डी सी एम वस्त्रोत्पादन में श्रेष्ठता का प्रतीक

दि दिल्ली क्लॉथ एण्ड जनरल मिल्स कं० लि०

दिल्ली

JWT : DCM : 2290

उत्सवाश्रम
गुरुकुल काँगड़ी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विषय-सूची

बिषय	पृष्ठ संख्या
१. हमारा आपातकालीन पहला बजट	१०९
२. सम्पादकीय टिप्पणियां	१११
३. १९६३-६४ का युद्धकालीन बजट	११५
४. नये कर प्रस्ताव	११९
५. मुद्रा स्थिति और महंगाई—श्री के० ए० जोसफ़	१२३
६. स्वर्ण समस्या : सरकारी नीति श्री नन्दकिशोर पाण्डे	१२६
७. हमारे सार्वजनिक उद्योग—श्री ए० डी० श्राफ़	१२९
८. सार्वजनिक और निजी क्षेत्र—श्री श्रीमन्नारायक	१३२
९. औद्योगिक अभ्युत्थान में बिड़ला बन्धुओं का योगदान (श्री रामप्रसाद पोद्दार)	१३३
१०. नये वर्ष का रेलवे बजट	१३६
११. विभिन्न राज्यों के बजट	१३९
१२. सर्वोदय पृष्ठ	१४१
१३. महंगाई का मूल : नियंत्रित अर्थशास्त्र (श्री भाईलाल पटेल	१४३
१४. कल्याणवादी अर्थशास्त्र—श्री भैरवलास शर्मा	१४६
१५. इस मास की आर्थिक घटनाएं	१५१

सम्पदा का नया विशेषांक

दिल्ली विकास अंक

सम्पदा के विशेषांक-रत्नों की माला में नया रत्न

दिल्ली विकास अंक

शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा है।

विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा कीजिये।

●

स म्प दा

२८/११, शक्तिनगर

दिल्ली-६

उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के लिए उपयोगी लेख, ताजे समाचार, आर्थिक गतिविधियों की जानकारी तथा व्यापारिक भविष्य-वाणी

अर्थ-शास्त्र के छात्रों के लिए अनेक उपयोगी सामग्री

आम जनता के लिए हर अंक में एक आकर्षक कहानी चल-चित्र उद्योग, व्यंग-विनोद, चित्रमय समाचार एवं कार्टून

भारत के अनेक राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा-संस्थाओं वाचनालयों पंचायतों एवं विकास खण्डों के लिये स्वीकृत

भारत व्यापार पत्रिका

उद्योग तथा व्यापार प्रधान सचित्र हिन्दी मासिक

- भिन्न-भिन्न वस्तुएँ बनाने की योजनाओं का नियमित प्रकाशन
- एक मुफ़्त विज्ञापन छापने की व्यवस्था
- आप के उलझे हुए प्रश्नों के उत्तर
- आप की आवाज़ सरकार तक पहुँचाने के लिये सुझाव एवं शिकायतें स्तम्भ
- आयात निर्यात समाचार, विज्ञान जगत बैंकिंग तथा बीमा समाचार आदि अनेक स्थाई स्तम्भ

वार्षिक चंदा विशेषाँकों सहित ६.00 रु. | पृष्ठ संख्या ६४ से ७२ तक | साधारण अंक 0.५0 न. पै.

अन्य जानकारी के लिये लिखें—

व्यवस्थापक, भारत व्यापार पत्रिका,

पो. बॉ. नं. ४८, राजा दरवाज़ा, वाराणसी (उ.प्र.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वर्ष : १२
अंक : ३
मार्च : १९६३

सम्पदा

आपातकालीन वर्ष का बजट

इस वर्ष चीन के आक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों में यह संभावना की ही जा रही थी कि नये बजट में भारी कर लगेंगे। प्रतिरक्षा कार्यों के लिए ८६७ करोड़ रु. की व्यवस्था करने के लिए स्वभावतः करों का बोझ बढ़ाना जरूरी था। इस आवश्यकता को सभी समझते हैं और इसी कारण भीषण कर वृद्धि के नए बजट से किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। जब यह निश्चित हो कि कर बढ़ाए जाएंगे, तब फिर समस्या का रूप यह रह जाता है कि किन वस्तुओं पर कर लगाये जावें, उनका रूप क्या हो, उनकी मात्रा कितनी हो। प्रत्येक वर्ग अपने उपयोग या उत्पादन की वस्तु पर कम से कम कर चाहता है। वित्त मंत्री श्री देसाई जनता की इस मनोवृत्ति को जानते न हों, सो नहीं, परन्तु वे यह भी जानते हैं कि राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथासंभव देश की समस्त जनता का योगदान लिए बिना काम नहीं चलेगा। जिन को श्री देसाई के पिछले बजट स्मरण है वे यह जानते हैं कि वे किसी एक क्षेत्र के अधिक दोहन की बजाय बीसियों वस्तुओं पर थोड़ा-थोड़ा कर लगाना अधिक पसन्द करते हैं, जिससे बोझ सभी पर सन्तुलित रूप से पड़े। इस वर्ष भी इसी क्रिया की पुनरावृत्ति की गई है, कराधीन वस्तुओं की संख्या पहले से बढ़ गई है। इसी कारण असंतुष्ट वर्ग का क्षेत्र भी बहुत बढ़ गया है। मिट्टी के तेल व साबुन ने यदि निम्न वर्ग पर प्रहार किया है, तो नई डाक दर, चाय, काफी, तम्बाखू, रेशमी व ऊनी कपड़ों और कागज पर लगाये कर मध्यम वर्ग को परेशान करेंगे। सम्पन्न वर्ग के प्रयोग में आने वाली सभी वस्तुओं पर भारी कर लगाया गया है। श्री देसाई की मनोवृत्ति से परिचित व्यक्ति यह जानते हैं कि वे महीन वस्त्र, चीनी, चाय, काफी, सिगरेट के प्रयोग को वस्तुतः कम करने को उत्सुक हैं, ताकि इनका निर्यात अधिक हो सके। इसीलिए वे इन पर कर लगाने व बढ़ाने में विशेष अनौचित्य नहीं देखते।

आय कर में अधिभार (सरचार्ज) आदि के नाम से जो वृद्धि की गई है, उसका मध्यम वर्ग और उद्योग पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। निजी आय पर भारत में पहले ही बहुत अधिक कर है। (देखो तालिका...) अब तो और भी बढ़ जायेगे। इससे स्वैच्छिक बचत काफी कम हो जाएगी। ऊंची आय पर ७०-८० प्रतिशत तक सुपर प्राफिट आदि के नाम से लगाये कर पूंजी निर्माण में बाधा डालेंगे और विदेशी पूंजी के लिए भारत में आने का आकर्षण कम हो जायगा। उद्योग में नई पूंजी लगाने का उत्साह कम हो जायगा और बचत करने की बजाय ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ने लगेगी। उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल तथा आयातित मशीनरी पर आयात करों में वृद्धि भी उद्योगों के विकास में रुकावट डालेगी।

यदि कोई उद्योगपति अपनी कार्य कुशलता से थोड़े

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सी पूंजी लगा कर भी ६-७ प्रतिशत लाभ प्राप्त करता है, तो उसे अपनी कार्य कुशलता के दण्ड स्वरूप अधिलाभ कर चुकाना पड़ेगा और अकुशल उद्योगपति जो कम लाभ प्राप्त करता है या कम लाभ दिखाता है, इस नये दण्ड से बच जाएगा। 'इकानामिक टाइम्स' के एक अनुमान के अनुसार अधिलाभ कर से सरकार को ३६ करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि बजट में केवल २५ करोड़ रु. की आशा की गई है। प्रो. शिनायके कथानानुसार जनता पर सरकार ने करभार कुल राष्ट्रीय आय के ७ प्रतिशत से बढ़ाकर २० प्रतिशत कर दिया है।

स्वयं वित्तमंत्री के कथनानुसार पिछले चार वर्षों में जितना मिलाकर कुल कर भार लादा गया है, उतने से अधिक इसी वर्ष बढ़ा दिया गया है। श्री पालखीवाला ने अधि लाभ कर को "आर्थिक आत्महत्या" की संज्ञा दी है।

नये कर, कर वृद्धि आदि उपाय तो प्रत्येक वर्ष के बजट की सामान्य बातें होती हैं। इस वर्ष वित्त मंत्री ने अनिवार्य बचत के रूप में एक नई योजना उपस्थित की है। योजना आयोग ने अपनी तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में बचत को आय के एक अच्छे साधन के रूप में माना है, किन्तु यह भी एक सत्य है कि उसकी आशाएं कभी पूर्ण नहीं हुईं। जनता में बचत करने की न उमंग रही है और न क्षमता। जो कुछ क्षमता बढ़ी भी है, वह बढ़ती हुई महंगाई तथा ऊंचा जीवन स्तर बिताने की इच्छा ने निगल ली है। इसलिए वित्त मंत्री ने विवश होकर अनिवार्य बचत का एक नया प्रस्ताव पेश किया है, किन्तु यह कहां तक व्यवहार्य होगा, विशेषकर देहातों में, यह देखना है। बोनस को सेविंग सर्टिफिकेट में देने की योजना भी चल नहीं पाई। भूमि सुधार कर की प्रतीक्षित योजना खटाई में ही पड़ गई है। कुछ विरोधीदल इन करों के विरोध में जनता को संगठित करने की योजना भी बनाने लगे हैं। फिर भी यदि यह योजना वित्त मंत्री की इच्छानुसार अनेक कठिनाइयों के बावजूद व्यवहार में आ सकी तो उन्हें इससे ६०-७० करोड़ रु. प्राप्ति की आशा है। पर इस कर की वसूली व व्यवस्था पर कितना भारी खर्च पड़ेगा, इसका अनुमान भी कोई नहीं लगा पाया है।

सभी जानते हैं कि थोड़ा-थोड़ा अप्रत्यक्ष कर लगने से भी अनेक जीवनोपयोगी पदार्थ महंगे हो सकते हैं, इसीलिए वित्त मंत्री ने मूल्य वृद्धि रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाने की घोषणा की है, किन्तु वे कदम सुदूर अन्तर्वर्ती गांवों पर प्रभाव डालने में समर्थ हो सकेंगे इसमें पूर्ण सन्देह है। यह दिल्ली, बम्बई या कलकत्ते में प्रभावकारी नहीं हो रहे, गांवों की तो बात ही दूर है। मिट्टी का तेल, साबुन, बीड़ी आदि सभी महंगे होभी गये हैं बढ़ती हुई महंगाई बचत पर भी बुरा प्रभाव डालेगी। इसका परिणाम होगा सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में वेतन वृद्धि की मांग और फिर महंगाई का दुश्चक्र पूरे वेग से चलने लगे, यह असंभव नहीं है। मध्यम वर्ग के व्यापारियों को परेशान करने के लिए युद्ध बीमा भी एक नया कारण बन गया है।

वित्त मंत्री घाटे की अर्थव्यवस्था का अधिक आश्रय लेना बहुत अच्छा नहीं समझते, इसीलिए उन्होंने नये कर लगाने पर अधिक बल दिया है और लोगों से कर या अनिवार्य बचत के रूप में पैसा अधिक ले लेने पर अधिक बल दिया है। फिर भी वे ११५ करोड़ रु. के लिए नासिक के प्रैस का आश्रय लिये बिना नहीं रह सके। इसका असर महंगाई पर अवश्य पड़ेगा। जिस एक बात पर बजट की कठोर आलोचना सभी दल एक स्वर से कर रहे हैं, वह है सरकारी व्यय में कमी की ओर ध्यान न देना। सभी को यह शिकायत वर्षों से है कि प्रशासन का व्यय निरन्तर बढ़ता जा रहा है। १९६१-६२ में केन्द्र राज्यों का प्रशासन-व्यय यदि १०६.७ करोड़ रु. था, तो १९६२-६३ में वह १९१.३ करोड़ रु. पहुँच गया। इसी वर्ष केन्द्रीय बजट में प्रशासन सेवाओं पर व्यय १९६१-६२ की बजाय २९ करोड़ रु. अधिक रखा गया है। वित्त मंत्री ने जनता पर कर भार बढ़ाने में जितना ध्यान दिया है, उसका २० प्रतिशत भी यदि वे प्रशासन व्यय में कमी कर देते तो जनता को नये कर भार भारी न मालूम पड़ते।

इस संबन्ध में हम कुछ नम्र सुझाव देना चाहते हैं, जिन पर मितव्यय की दिशा में विचार करने से संभवतः कुछ ठोस लाभ हो सकें—

जब तक युद्धकालीन आपत स्थिति है, कला के नाम पर खुलने वाली नृत्य संगीत समितियों और समारोहों को

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता सर्वथा बन्द कर देनी चाहिए। प्रकाशन विभाग की ओर से अप्रचारालक पत्रिकाओं का प्रकाशन बन्द होना चाहिए, रेडियो कार्यक्रमों में कुछ कटौती होनी चाहिए, विभिन्न मंत्रालयों में ऊंचे अधिकारियों की संख्या में यथोचित कटोती होनी चाहिए, विदेशों में जानेवाले डेलीगेटों की संख्या बहुत कम होनी चाहिए, विदेशियों के स्वागत-समारोहों का राजसी खर्च-कम किया जा सकता है, मंत्रियों व अधिकारियों के विविध भत्तों, कोठियों, कारों व टीपटाप अंकुटा अवश्य लगना चाहिए। लोकलेखा समिति जिन सरकारी संस्थानों में अपव्यय बताती है, उन पर कठोर नियंत्रण करना चाहिए, सरकारी उद्योगों को व्यय व कार्य क्षमता में निजी उद्योगों के स्तर पर लाया जाय, बड़े-बड़े कई मंज़िला भवनों का निर्यात ५-६ वर्ष तक स्थगित कर देना चाहिए। १९६०-६१ के स्तर पर मंत्रालयों का व्यय नीचे लाने का प्रयत्न करना चाहिए।

१९६२-६३ का वर्ष

इस वर्ष इतने भारी नये कर लगे हैं कि बजट भाषय के उस पूर्वार्ध की ओर बहुत कम लोगों का ध्यान गया है, जिस में वित्त मंत्री के १९६२-६३ का सिंहावलोकन किया है, यह ठीक है कि इस वर्ष भाकड़ा बांध पूरा होवगा, रिहन्द तथा हीराकुड से बिजली अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगी है और सरकारी उद्योग भी पूर्वापेक्षा या कुछ अधिक उत्पादन करने लगे हैं, किन्तु समग्र दृष्टि डालने से गत वर्ष बहुत उत्साहवर्धक और सन्तोषजनक प्रतीत नहीं होता। वित्त मंत्री ने स्वयं कृषिजन्य पदार्थों की उपलब्धि को सन्तोषजनक नहीं माना, कीमतें भी वर्ष के मध्यमान तक बढ़ गईं। खेती के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए मूल्य वृद्धि का स्तर ऊंचा ही करना पड़ा। गत वर्ष के पूर्वार्ध की अपेक्षा इसी अवधि में इस वर्ष औद्योगिक उत्पादन का स्तर १०.२ प्रतिशत ऊंचा बताते हुए वित्त मंत्री भूल गये हैं कि दूसरी छःमाही में उत्पादन फिर गिरा है। संभवतः उस समय तक उन्हें नवीनतम अंक नहीं मिले थे। उद्योग उत्पादन का सूचक अंक मई १९६२ के १५१.० से गिरकर सितम्बर में १४६.६ रह गया। अक्टूबर में भी सूचक अंक गिरने की प्रवृत्ति रही है। छोटी बचतों के अन्तर्गत भी अनुमान से २० करोड़ रु. की प्राप्ति हुई है। विदेशी मुद्रा की स्थिति सारे वर्षभर वित्त मंत्री के लिए चिन्ता का विषय रही है। मार्च ६२ के अन्त में १२९.७ करोड़ रु. से गिरकर ९७ करोड़ रु. रह गई। गत वर्ष के सिंहावलोकन से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि अगला बजट पेश करते समय वित्त मंत्री राजस्व का अनुमान बहुत कम करते हैं, ताकि कर लगाने के औचित्यको सिद्ध किया जा सके इस वर्ष भी सीमा पूलक उत्पादन पूल्क आदि में अनुमान से अधिक प्राप्ति हुई है।

बचत कम क्यों ?

"शान्तिकाल में हमें उतनी रोटी (जीवन-निर्वाह व्यय) लेनी चाहिए, जितनी हम परिश्रम करके कमा सकते हैं, लेकिन युद्धकाल में रोटी का आकार निश्चित कर दिया जाता है। यदि हम कठोर परिश्रम करते हैं, हम अच्छी तरह लड़ सकते हैं, लेकिन हमें अपना खर्च जरूर घटा देना चाहिए।" ये शब्द प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स ने १९४० में लिखे थे, जब उन्होंने ब्रिटेन के वित्तमंत्रालय को जर्मनी के आक्रमण के बाद संकट कालीन स्थिति के लिए अपने परामर्श दिये थे। यद्यपि आज उत्तरी सीमा पर युद्ध नहीं हो रहा तथापि आज भी हमारे लिए आपातकालीन स्थिति है। इसलिए हमें अपनी आर्थिक नीति और गति-विधि युद्ध काल समझकर ही चलानी चाहिए और इसीलिए यह आवश्यक है कि हम कम से कम व्यय करें और अधिक से अधिक बचत करें। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में 'बचत आंदोलन' की असफलता को स्वीकार किया है। वस्तुतः हमारा बचत आंदोलन किसी तरह सफल नहीं हो रहा। नीचे की तालिका बताता है कि १९५० से १९५९ तक हमने घरेलू बचत अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम की है। एशिया और सुदूर पूर्वीय देशों की आर्थिक स्थिति के अध्ययन से मालूम हुआ है कि इन देशों में घरेलू बचत की स्थिति यह है—

	प्रतिशत
बर्मा	१३.९
लंका	१०.४
चीन (मुख्य भूमि)	१०.३
मलाया	१७.५
इंडोनेशिया	२.८
जापान	२०.९
भारत	८.५

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यह बचत हमारी विकासशील योजनाओं को देखते हुए बहुत कम है। हमारा यह निश्चित मत है कि उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद यदि बचत कम है तो उसके दो मुख्य कारण हैं। (१) हमारी सामान्य जनता का जीवन-स्तर पहले बहुत कम था। इसलिए कुछ आमदनी बढ़ने के बावजूद उसने अपना जीवन-स्तर ऊंचा करने का प्रयत्न अधिक किया और बचत की ओर कम ध्यान दिया। (२) हमारे नेताओं ने मितव्यय और सादगी का आदर्श जनता के सामने नहीं रखा। संसद के इसी बजट अधिवेशन में केन्द्रीय मंत्रिमंडल के बिजली और पानी के सम्बन्ध में सरकार द्वारा लिये जाने वाले खर्चों की जो सूची प्रकाशित की गयी है, वह चौंका देने वाली है। मंत्रियों के बिजली और पानी के प्रति मास के खर्च चार-पांच या सात सौ रु० तक होते हैं। जब तक नेता और सम्पन्न व्यक्ति बचत का आदर्श उपस्थित नहीं करेंगे, तब तक सामान्य जनता से बचत की आशा नहीं की जा सकती।

विदेशी मुद्रा में कमी

हमने ऊपर की पंक्तियों में विदेशी मुद्रा की दुर्लभता का उल्लेख किया है। नीचे की तालिका हमें बताती है कि प्रतिवर्ष विदेशी मुद्रा की स्थिति क्या होती गयी है—

वर्ष के आरम्भ में अप्रेल—करोड़ रु० में

१९५५-५६	७१५.२
१९५६-५७	७२५.२
१९५७-५८	५०४.९
१९५८-५९	२६९.८
१९५९-६०	२१०.५
१९६०-६१	१८०.६
१९६१-६२	१२३.३
१९६२-६३	११२.४
दिसम्बर १९६२	९८.५

यह तालिका इस बात का अच्छा प्रमाण है कि हमें अपने आयात को कम करने और निर्यात को बढ़ाने की कितनी आवश्यकता है?

राज्यों के घाटे के बजट

विभिन्न राज्यों के बजट पाठक "सम्पदा" में अन्यत्र पढ़ेंगे। इन बजटों से राज्यों की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। प्रायः सभी राज्यों के बजट घाटे के हैं और यह घाटा भी करोड़ों रु० का है। मद्रास और मैसूर को छोड़कर सभी राज्यों के मंत्रियों ने नये कर लगाये हैं और स्वभावतः उन्होंने बिक्रीकर का आश्रय अधिक लिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान ने खाद्य अन्नों पर भी बिक्रीकर लगाने की घोषणा की है। गुजरात को तो कृषि आय का कर वापस लेना पड़ा है। यह भी सम्भव है कि तीव्र विरोध के कारण अन्य राज्यों में भी कृषि व बिक्री-कर कम करना पड़े या वापस लेना पड़े। बस-यात्री आय वृद्धि का दूसरा साधन बनाये गये हैं। मोटर गाड़ियों पर भी नये कर लगाये गये हैं और यात्रियों के किराये पर भी कर लगाये गये हैं। इस दृष्टि से सभी राज्यों में यातायात को महंगा कर दिया गया है। केरल, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात ने बिजली के प्रयोग पर भी विविध कर लगा दिये हैं। मनोरंजन-कर भी वित्त मंत्रियों की दृष्टि से छूट नहीं सका है। कुछ राज्यों ने शिक्षा-शुल्क बढ़ा दिया है या पुनः जारी कर दिया है। स्टाम्प-ड्यूटी को भी आय वृद्धि का एक साधन बनाया गया है। इतने पर भी, योजना आयोग के वे लक्ष्य पूरे नहीं हुए, जो उसने राज्यों से आय-वृद्धि के सम्बन्ध में नियत किये थे। और अभी यह भी निश्चित नहीं है कि कितने वित्त मंत्री जनता के असन्तोष का सामना करते हुए अपने कर-प्रस्तावों पर टिके रह सकेंगे?

विदेशों की सहायता

जब भारत में आपातकालीन अर्थव्यवस्था के लिए नये से नये कर लगाये जा रहे हैं, तब अपने मित्र देशों की सामयिक सहायता भी उत्साहवर्धक है। अमरीका व जर्मनी ने हाल ही में भारत से नये समझौते किये हैं। इनके अनुसार अमरीका ११४ करोड़ रु. दे रहा है। यह राशि मार्शल योजना के बाद अमरीका द्वारा किसी एक देश को दी गई किसी भी राशि से अधिक बड़ी है। इस समझौते की एक बड़ी विशेषता यह है कि यह ऋण किसी विशेष योजना के लिए नहीं दिया गया; बल्कि इसका व्यय भारत सरकार की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। अमरीका अब तक भारत को २३१३ करोड़ रु. ऋण आदि के रूप में दे चुका है। इस ऋण की एक बड़ी विशेषता यह है कि ४०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वर्षों तक हम यह ऋण चुका सकेंगे और पहले १० वर्ष हम कोई भी किस्त न चुकाने के लिए स्वतंत्र हैं। इस पर ३।४ प्रतिशत साख शुल्क के अतिरिक्त और कोई ब्याज भी नहीं लगेगा। जर्मनी की सरकार ने ९५ लाख पौंड (करीब १२.८५ करोड़ रु.) पेशगी ऋण देने की घोषणा की है, ताकि हम जर्मनी से आवश्यक मशीनरी खरीद सकें। ब्रिटिश सरकार के पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी ने ब्रिटिश संसद में बताया है कि ब्रिटिश सरकार भी भारत को नई सहायता देने के सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई घोषणा करेगी।

विश्वबैंक से ३०० करोड़ डालर और व्यय लेने की बातचीत चल रही है। दिल्ली की बिजली योजना के लिए अमेरिका १॥ करोड़ रु. दे रहा है। रूस का एक प्रतिनिधि मंडल पंचवर्षीय व्यापार समझौता करने के लिए आया है। कोटा में सूक्ष्म-यंत्र बनाने के कारखाने पर रूसी सहायता की बात चल रही है। ऐसे ही अन्य कार्यों के लिए भी विदेशी सहायता मिलने के कुछ प्रस्ताव हैं। विदेशी सरकारों की सहायताओं के अतिरिक्त विदेशों के उद्योगपति भी निजी रूप में देश के औद्योगिक विकास में सहयोग दे रहे हैं। पिछले ३ वर्षों में विदेशी उद्योगपतियों ने भारत के साथ १३३० समझौते किए हैं। इनमें से ३६७ समझौते ब्रिटिश कम्पनियों से, २२१ समझौते अमरीकन कम्पनियों से और २०१ तथा १०० समझौते क्रमशः पश्चिमी जर्मनी और जापानी कम्पनियों से हुए हैं। जापान पंजाब में बालबेयरिंग के कारखाने की स्थापना में सहयोग देगा। यदि विदेशी पूंजी को अधिक आकृष्ट करने की सुविधाएं दी जाएं तो कोई कारण नहीं कि देश में उद्योगों के लिए पूंजी न मिले, लेकिन नये कर प्रस्तावों से यह भय हो गया है कि विदेशी पूंजी का भारत के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा।

प्रतिव्यक्ति आय कर

केन्द्रीय सरकार के १९६३-६४ के बजट में आयकर पर जो अतिरिक्त अधिभार लगाया गया है, उसका कुछ अंश अनिवार्य बचत योजना के अंतर्गत करदाता की अनिवार्य बचत मान लिया जाएगा।

नीचे की तालिका से यह स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी आय पर एक बच्चे से अधिक वाले विवाहित को अतिरिक्त अधिभारसहित कितनी राशि देनी पड़ेगी, और उसमें से कितना अंशशुद्ध आय कर होगा और कितना अनिवार्य बचत।

आय	कुल कर जिसमें अधिभार शामिल है	अधिकतम कटौती	कर की शुद्ध रकम
३,६००	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
४,२००	१८९	१२५	६४
४,८००	२३३	१४३	९०
५,०००	२४८	१४८	१००
६,०००	३६८	१७६	१९२
७,२००	५३३	१९९	३३४
८,४००	७३०	२२१	५०९
९,६००	९३७	२४२	६९५
१०,०००	१००६	२४९	७५७
१५,०००	२०६८	३३३	१७३५
२०,०००	३६२७	४०७	३२२०
२७,०००	७०४५	४८५	६५५०
३३,०००	१०५०६	५४०	९९६६
३६,०००	१२३०२	५६६	११७३६
४८,०००	२०३९७	६५१	१९७४६
५५.०००	२५८२१	६८६	२५१३५
७०,०००	३८३६४	७४०	३७६२४
१,००,०००	६४८१५	८१८	६३९९७
२,००,०००	१५३०७५	१०७८	१५१९९७
३,००,०००	२४१३७५	१३३८	२४००३७

× परन्तु अनिवार्य बचत योजना के अंतर्गत ३ प्रतिशत के हिसाब से जमा अवश्य कराना होगा

सम्पदा का आगामी विशेषांग—

१॥ रु० भेजकर अपनी प्रति अभी से सुरक्षित करा लें।

—मैनेजर सम्पदा

२८/११ शक्तिनगर, दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हमें क्या करना है ?

इंगलैण्ड की प्रसिद्ध अर्थशास्त्रिणी श्रीमती राबिन्सन ने योजना व प्रतिरक्षा के साधनों की चर्चा करते हुए एक पत्र प्रतिनिधि से कहा है—

"सर्व प्रथम श्रम का संचय करना होगा। आपको यह देखना होगा कि आवश्यक वस्तुओं का केवल आवश्यक उपयोग ही किया जाय। मेरे ख्याल में इस्पात की काफी मात्रा उपभोक्ता उद्योगों में खप रही है। इसे अवश्य ही रोका जाना चाहिए। फालतू क्रय शक्ति को करों द्वारा घटाने की चेष्टा की जानी चाहिए। "उपभोग स्तर को कम करने के लिए यह जरूरी है कि बाजार में उपभोग्य वस्तुओं को जाने ही न दिया जाए। इस अवस्था में ऐसा करना अधिक अच्छा है बजाए इसके कि बाद में खपत पर कर लगाये जाएं। जो उपभोग-स्तर पहले ही काफी नीचे हैं, उन्हें कम किए बिना ही यह कार्य किया जा सकता है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से आय और पूंजी पर उत्तरोत्तर कर लगाना निःस्सन्देह वांछनीय है, परन्तु इसे लागू नहीं किया जा सकता। इसके लिए सख्त तरीके अपनाने होंगे। जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की वस्तुओं की कीमतें कम रखिए और शेष वस्तुओं पर कर लगा दीजिए। इससे न केवल आपके साधनों में वृद्धि होगी, बल्कि आपके सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा मिलेगा।

"सरकारी एकाधिकार के उद्यमों को अपना लाभ और अधिक बढ़ाना चाहिए। इससे आप अपनी प्रतिरक्षा के कुछ खर्च के लिए धन जुटा सकेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के बारे में बड़ा गड़बड़ घुटाला है। लोग उन्हें केवल एक ऐसी सेवा समझते हैं जो अपना खर्चा मात्र निकाले। यह बिल्कुल ही गलत है। लाभों को राष्ट्रीय कार्यों के लिए अतिरिक्त रकम इकट्ठा करने का एक साधन समझा जाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के विषय में और अधिक सार्थक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। केवल निजी क्षेत्र का नियंत्रण करना पर्याप्त नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र को सक्रिय रूप से इसका मुकाबला करना चाहिए।

"विदेशी मुद्रा बड़ी कीमती है और यदि देखा जाए तो उसका उपयोग केवल आधारभूत उद्योगों में ही होना चाहिए, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं। फिर निर्यात का प्रश्न है, निर्यात में कमी का एक कारण यह है कि बाजार सीमित हैं। इन्हें बढ़ाने के लिए हमें विदेशी बाजारों की ओर अधिक खोज करनी चाहिए।"

१९६१-६२ में राष्ट्रीय आय

केन्द्रीय आंकड़ा-संघ (सेन्ट्रल स्टेटिस्टिकल आर्गेनाइजेशन) द्वारा प्रकाशित एक श्वेत पत्र के अनुसार १९४८-४९ के मूल्यों के आधार पर भारत की राष्ट्रीय आय १९६१-६२ में १३,०२० करोड़ रु. थी, जबकि १९६०-६१ में १२,७५० करोड़ रु० और १९५५-५६ में १०,४८० करोड़ रु० थी। १९६१-६२ में २७० करोड़ रु० की वृद्धि हुई।

१९४८-४९ के मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय, १९६१-६२ में २९३.४ रु० थी जब कि १९६०-६१ में २९३.७ और १९५६-५७ में २६७.८ रु० थी। दूसरी योजना अवधि में राष्ट्रीय आय २०.४ प्रतिशत और प्रति व्यक्ति आय में ८.६ प्रतिशत बढ़ी।

अगर मौजूदा चालू मूल्यों की दृष्टि से देखा जाय तो १९६१-६२ में १४,६३० करोड़ रु० राष्ट्रीय आय थी, जबकि १९६०-६१ में १४,१६० करोड़ रु० और १९५५-५६ में ९,९८० करोड़ रु० थी। चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय १९६१-६२ में ३२९.७ रु. थी, जबकि १९६०-६१ में ३२६.२ रु० और १९५५-५६ में २५५.० रु० थी।

इधर भी देखिए

मितव्ययिता के नारों के बावजूद प्रशासन-व्यय किस रीति से बढ़ता जा रहा है, इस सम्बन्ध में आंकड़े प्रस्तुत करते हुए संयुक्त समाजवादी दल के नेता श्री उग्रसेन ने उ० प्र० विधान सभा में बताया कि संकटकालीन स्थिति के पूर्व भीमकाय मन्त्रिमंडल पर होने वाला व्यय केवल ४,५७,००० रु० था। परन्तु अब वह बढ़कर ८,०९,००० रुपया हो गया है, जिसमें ३,६१,२०० रुपये मन्त्रियों के वेतन, १,२०,४०० रुपये उनकी मोटरों एवं १,९७,८०० रुपये यात्रा व्यय आदि पर आया है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१९६३-६४ का युद्ध-कालीन बजट

वित्तमंत्री श्री मुरारजी देसाई

चालू आयोजना के पहले साल अर्थ-व्यवस्था के बुनियादी क्षेत्रों की कमियां—खास तौर से बिजली, परिवहन (ट्रांसपोर्ट), कोयला और इस्पात की कमियां—हमारे लिए चिन्ता का कारण बन गयी थीं। इन्हीं कमियों को देखते हुए १९६२-६३ के बजट में आयोजना के खर्च में भारी वृद्धि करने के लिए व्यवस्था की गयी थी। मुझे यह बताने में खुशी हो रही है कि कोयला, बिजली, इस्पात और परिवहन (ट्रांससोर्ट) मिलने में काफी सुधार हुआ है। आने वाले महीनों में सुधार की यह रफ्तार तेज होती जायगी। सरकारी क्षेत्र की हमारी कुछ बड़ी-बड़ी प्रायोजनाओं (प्रोजेक्ट) ने हमारी और भी तरक्की की है। भाखरा बांध बनकर पूरा हो चुका है और रिहन्द तथा हीराकुड प्रायोजनाओं से प्राप्त होने वाली बिजली की क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। सरकारी क्षेत्र के इस्पात के कारखाने अब प्रायः अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन करने लगे हैं। सारा औद्योगिक उत्पादन बढ़ता जा रहा है और साल की पहली छमाही में यह १९६१-६२ की इसी छमाही से ७.२ प्रतिशत अधिक था।

यह वर्ष

इस साल खेती की चीजों की सप्लाई सब तरफ सन्तोषजनक नहीं रही। चूंकि १९६१-६२ की पैदावार, उससे पहले के साल की पैदावार से ज्यादा नहीं थी, इसलिए कीमतें, खासकर अनाज की कीमतें, मार्च और अगस्त १९६२ के बीच बढ़ गयीं और इस अवधि में थोक मूल्यों के सूचक अंक में ६.१ प्रतिशत की वृद्धि हो गयी। कीमतों को बढ़ने न देने के लिए कई उपाय किये गये। मुद्रा विषयक नीति के अनुसार ऋण के ब्याज की दर बढ़ा दी गयी और साथ ही सट्टे की प्रवृत्तियों की रोकथाम की गयी। खेती की पैदावार को बढ़ावा देने और खेतिहर को यह आश्वासन देने के लिए कि यदि वह पैदावार बढ़ायेगा, तो कीमतों के घटने पर घाटे में नहीं रहेगा, गेहूँ के कम से कम मूल्यों और चावल के अधिप्राप्ति-मूल्यों (प्रोक्योरमेण्ट प्राइसेज) की घोषणा की गयी, कपास का अधिकतम मूल्य और भी ऊंचा किया गया और जूट के मूल्यों को लाभकारी बनाये रखने की व्यवस्था मजबूत कर दी गयी। यह संतोष की बात है कि जनवरी १९६३ के थोक मूल्यों के सूचक अंक का औसत १२६ था, जबकि तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के शुरू में यह १२७.५ था।

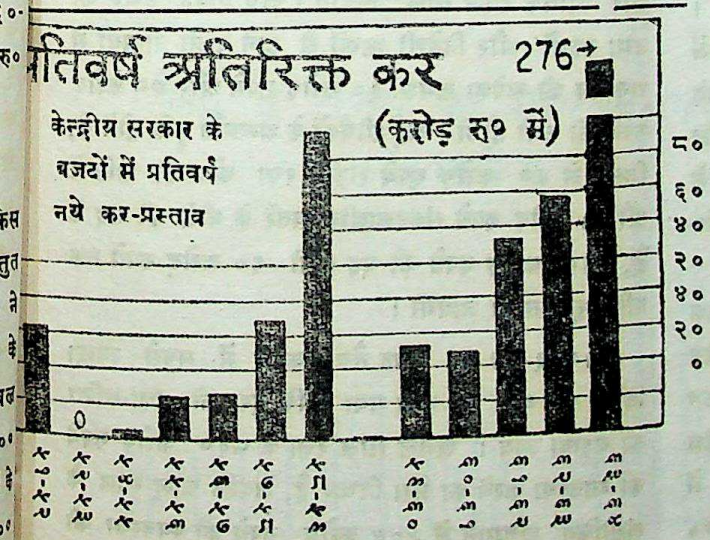

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

केन्द्रीय प्रशासन की वित्तीय स्थिति

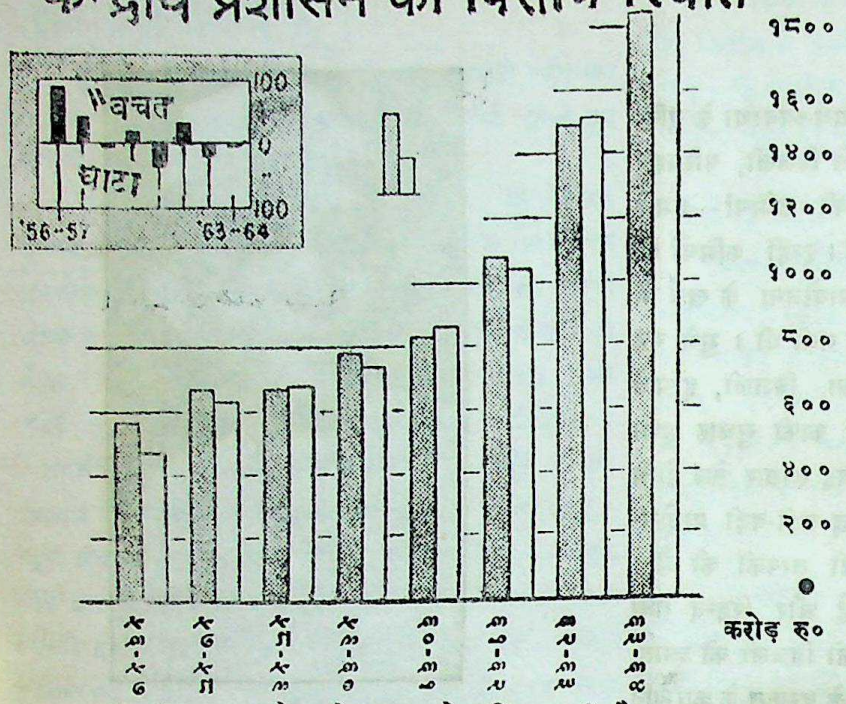

काली पट्टी राजस्व और सफेद व्यय को सूचित करती है।

विदेशों को किये जाने वाले भुगतान की स्थिति सारा साल हमारे लिए चिन्ता का विषय रही। १९६२ की गर्मियों में विदेशी मुद्रा की हमारी प्रारक्षित (रिजर्व) राशियों में भारी कमी हो गयी। रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा मार्च १९६२ के अन्त में १२९.७ करोड़ रुपये से घटकर जून के अन्त में ९७ करोड़ रुपया रह गयी। इसलिए हमें विदेशों से मंगाये जाने वाले माल के कोटे में और भी कटौती करनी पड़ी, और विदेशी-यात्रा पर कड़े प्रतिबन्ध लगाने पड़े। निर्यात सम्बन्धी आमदनी बढ़ने और सहायता के अन्तर्गत पहले से ज्यादा भुगतान होने से पिछले कुछ महीनों में इन राशियों पर पड़ने वाला अतिरिक्त दबाव दूर हो गया।

जहां तक चालू साल की बजट और राजस्व विषयक स्थिति का सम्बन्ध है, पहले राजस्व से १३८०.९३ करोड़ करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान किया गया था, लेकिन सबसे हाल के संकेतों के अनुसार राजस्व-प्राप्तियों की रकम १५०० करोड़ रुपये से कुछ ऊपर चली जायगी। राजस्व में ११९ करोड़ रुपये की जो वृद्धि हुई है उसमें से ७३.७० करोड़ रुपये की प्राप्ति तीन प्रधान शीर्षकों के अन्तर्गत हुई है—उत्पादन शुल्क, निगम आय कर और सीमा शुल्क, अनुमान है कि चालू साल में खर्च की रकम भी १३८१.६५ करोड़ रुपये से बढ़कर १५२२.३१ करोड़ रुपये हो जायगी। इस वृद्धि का सबसे बड़ा कारण रक्षा-सेवाओं के खर्च का बढ़ना है।

५९३ करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष पूंजी खर्च के अलावा, मूल अनुमानों में, राज्यों को कर्ज देने के लिए ४५३ करोड़ रुपये और स्थानीय निकायों (लोकल बाडीज), पत्तन प्रबन्ध समितियों (पोर्ट ट्रस्ट) और सरकारी क्षेत्र के उद्योगों सहित दूसरी पार्टियों को कर्ज देने के लिए १३६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। अब इन कार्यों के लिए खर्च क्रमशः ५२३ करोड़ रुपये और १४७ करोड़ रुपये तक बढ़ जायगा।

उधार लेने के हमारे कार्यक्रम में, छोटी बचतों के अन्तर्गत २० करोड़ रुपये की कमी होगी, लेकिन संकट की स्थिति पैदा होने के बाद जारी किये गये राष्ट्रीय रक्षा बाण्डों की बिक्री से यह कमी न सिर्फ पूरी हो जायगी, बल्कि और अधिक रकम मिल जायगी। पी० एल० ४८० की जमा रकमों और विदेशी ऋणों से होने वाली प्राप्तियों में अनुमान की अपेक्षा क्रमशः ३० करोड़ रुपये और ७८ करोड़ रुपये की कमी होगी। कई शीर्षकों के अन्तर्गत वृद्धि होने से, जिसमें से ४७ करोड़ रुपये राष्ट्रीय रक्षा कोष की प्राप्तियों और ९ करोड़ रुपये संकटकालीन खतरे के बीमे की मद के हैं, २१० करोड़ रुपये की यह कमी ६० करोड़ रुपये तक प्रतिसन्तुलित हो जायगी।

१९६३-६४ का बजट तैयार करने में सबसे ज्यादा विचार इस बात का रखा गया है कि देश की रक्षा-शक्ति को बढ़ाया जाय। अगले साल रक्षा के ८६७ करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का मेरा विचार है, जबकि चालू साल के संशोधित अनुमान में ५०५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है और मूल अनुमान में ३७६ करोड़ रुपये की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

व्यवस्था की गयी थी। साथ ही, केन्द्र के आयोजन सम्बन्धी खर्च के लिए, जिसमें राज्यों को दी जाने वाली सहायता शामिल है, १२२६ करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का मेरा विचार है, जबकि चालू वर्ष के बजट अनुमान में ११०७ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी।

अगले साल के लिए, करों के वर्तमान स्तर के आधार पर, मैं बजट में १५८५.७३ करोड़ रु. के कुल राजस्व और १८५२.४० करोड़ रु. के व्यय की व्यवस्था कर रहा हूँ, जिस से राजस्व खाते में २६६.६७ करोड़ रु. की कमी रह जायगी।

चालू साल के संशोधित अनुमान की तुलना में अगले साल राजस्व में ८५.४८ करोड़ रु० की वृद्धि होने का अनुमान है। अनुमान है कि उत्पादन शुल्कों में ३०.२७ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी जबकि आयकर तथा निगम करों के राजस्व में १५ करोड़ रुपये की और वृद्धि होगी। ब्याज-प्राप्तियों की मद में ४०.५६ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी जिसमें से १८ करोड़ रुपया हिन्दुस्तान स्टील से, १० करोड़ रुपया राज्य सरकारों से और ८.४३ करोड़ रुपया रेलों से प्राप्त होगा। अगर माल और कारखानों के संकट-कालीन खतरे के बीमे से होने वाली प्राप्तियों की रफतार यही रही, तो इनमें २७ करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायगी। हमने यह भी फैसला किया है कि चूंकि सरकार को ब्याज की ऊंची दरों पर कर्ज मिलता है, इसलिए रेलों और डाक तथा तार विभाग को, अगले साल से, साधारण राजस्व में और अधिक लाभांश (डिविडेण्ट) देना चाहिए और इसकी दर ४½ प्रतिशत से बढ़ाकर ४½ प्रतिशत कर दी जायगी। इससे ४.४३ करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी। लेकिन ये वृद्धियां, मौजूदा दरों के आधार पर, सीमा-शुल्कों में, आयात पर और अधिक प्रबन्ध लगने से, १०.४५ करोड़ रुपये की कमी होने, लोहे व इस्पात अधिभार में ११.७० करोड़ रुपये की कमी होने, पी० एल० ४८० अनुदानों में ८ करोड़ रुपये की कमी होने और आय-कर में से राज्यों के हिस्से में २.६८ करोड़ रुपये की वृद्धि होने से आंशिक रूप से बराबर हो जायंगी।

अगले साल राजस्व खाते से १८५२.४० करोड़ रुपये की जो कुल रकम खर्च की जाएगी उसमें ७०८.५१ करोड़ रुपया रक्षा सेवाओं पर और ११४३.८९ करोड़ रुपया असैनिक शीर्षकों के अन्तर्गत खर्च होगा। संशोधित अनुमानों की तुलना में, अगले साल, असैनिक व्यय में ७३.३९ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। सरकारी ऋणों के परिमाण और ब्याज में वृद्धि होने से ऋण-व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ३४.२१ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। प्रशासनिक सेवाओं पर अगले साल ११.८९ करोड़ रुपया ज्यादा खर्च होगा जिसका मुख्य कारण सीमा पुलिस पर और ज्यादा खर्च होना है।

अगले साल पूंजी खाते से ८२७ करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है, जो चालू साल के संशोधित अनुमान से २३४ करोड़ रुपया अधिक है। १०६ करोड़ रुपये की वृद्धि का कारण पूंजी खाते से रक्षा सम्बन्धी खर्च होना है।

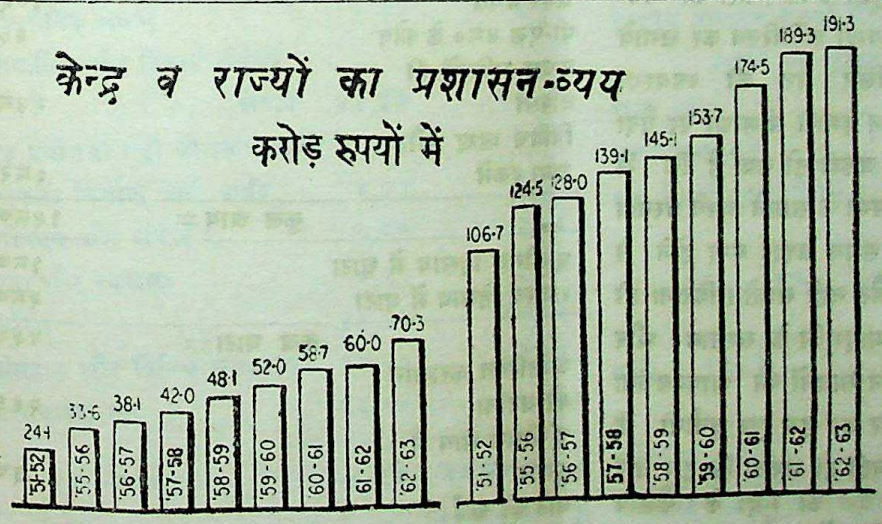

केन्द्र और राज्यों में विकासेतर कार्यों का व्यय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसमें से भी भारी रकम प्रशासकीय सेवाओं पर व्यय होती है। केन्द्रीय प्रशासन में व्यय पिछले ११ वर्षों में तीन गुना और राज्य सरकारों में दुगना हो गया है। १९६२ के वर्ष में अधिकांश अर्थ-शास्त्रियों और उद्योगपतियों ने प्रशासन व्यय के सफेद हाथी की ओर देश का ध्यान बहुत प्रबल शब्दों में आकृष्ट किया।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दूसरी बड़ी-बड़ी वृद्धियों में से हिन्दुस्तान स्टील के ३५ करोड़ रुपये, खाद्य पदार्थों की खरीद के लिए, जिसमें देश के अन्दर अनाज प्राप्त करना शामिल है, ३० करोड़ रुपये के वास्तविक खर्च, रेलों के १५ करोड़ रुपये, डाक और तार विभाग के १३ करोड़ रुपये, राष्ट्रीय राजपथों (नेशनल हाइवेज) के १५ करोड़ रुपये, परमाणु शक्ति (एटोमिक इनर्जी) विभाग के ८ करोड़ रुपये, तेल और प्राकृतिक गैस कमीशन के ८ करोड़ रुपये और ड्रग्स कारपोरेशन के ५ करोड़ रुपये का जिक्र किया जा सकता है।

अगले वर्ष के बजट में आयोजना को कार्यान्वित करने के लिए १२२६ करोड़ रुपये के कुल व्यय की व्यवस्था की गयी है। इसमें से १९६ करोड़ रुपये राजस्व खाते के और बाकी १०३० करोड़ रुपये पूंजी-परिव्यय के रूप में हैं जिनमें ऋण भी शामिल हैं।

आयात के परिमाण को सीमित करने के लिए आवश्यक नियंत्रणों को कामयाबी के साथ लागू करने के लिए यह जरूरी है कि बजट सम्बन्धी व्यवस्था द्वारा उन्हें और भी मजबूत बनाया जाय और इस सम्बन्ध में सीमा-शुल्कों और उत्पादन-शुल्कों दोनों से काम लिया जायगा। ४५४ करोड़ रुपये की कुल कमी का कारण रक्षा सम्बन्धी खर्च में ही प्रायः सारी वृद्धि होना है। साल के शुरू में मुझे आशा थी और मेरा अनुमान था कि आयोजना के पहले दो सालों में तीसरी पंच वर्षीय आयोजना के लक्ष्य के लगभग ८० प्रतिशत भाग की पूर्ति के लिए करों की व्यवस्था कर देने से इस साल ज्यादा अतिरिक्त कर लगाये बगैर ही सभी जरूरी कामों के लिए धन की व्यवस्था करना सम्भव हो जायगा। लेकिन हमारी सीमाओं पर पैदा हुए नए खतरे से मेरे लिए यह जरूरी हो गया है कि मैं और भी ज्यादा करों के लिए सभा के सामने अपने प्रस्ताव रखूं। हमारी सीमाओं पर इस समय लड़ाई बन्द होने से हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ नहीं सकते। कितना ही बड़ा प्रयत्न क्यों न करना पड़े, मातृभूमि के सम्मान और अखण्डता की रक्षा के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है उन्हें जुटाना ही पड़ेगा। और जब हम इस चुनौती के लिए तैयार हो रहे हैं, तो यह नहीं हो सकता कि हम घाटे की असंयत वित्त-व्यवस्था द्वारा देश को मुद्रा के फैलाव (इन्फ्लेशन) की गड़बड़ी में डाल दें।

मुझे इस बात का पूरा पता है कि जिस पैमाने के करों के लिए मैं प्रस्ताव रखने जा रहा हूँ उससे ऐसा बोझ पड़ने जा रहा है जैसा पहले कभी नहीं पड़ा। इस बात के लिए मैंने पूरी कोशिश की है कि जहां तक सम्भव हो करों का अतिरिक्त बोझ समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से पड़े। हमारी जरूरतें इतनी बड़ी हैं कि समाज के गरीब से गरीब लोगों से भी कुछ प्राप्ति की आशा किये बिना हम शायद उन्हें पूरा नहीं कर सकते। जो बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने मौजूद है वह हर नागरिक से कुछ न कुछ त्याग की मांग करती है। इसलिए यह और भी आवश्यक है कि समानता और सामाजिक न्याय के विचार का, जिसे हमने जीवन का अभिन्न अंग मान लिया है, अब पहले से भी अधिक आदर किया जाना चाहिए। ● ●

भारत सरकार का पूंजीगत बजट

१९६३-६४

व्यय	करोड़ रु०
पूंजीगत व्यय	८२७
राज्यों को ऋण	५४१
अन्य संस्थाओं को ऋण	१७५
ऋण की अदायगी	२३१
कुल व्यय	१७७४
आय	
बाजार से उधार	४००
विदेशी सहायता	४६२
अल्प बचत	१०५
पी-एल ४८० के कोष	९०
उधार राशियों की वापसी	२४८
विविध ऋण और जमा रकमें	२८२
कुल आय =	१५८७
पूंजीगत हिसाब में घाटा	१८७
राजस्व हिसाब में घाटा	२८७
कुल घाटा =	४५४
अतिरिक्त कराधान को घटाना	२६६
पूंजीगत आय में सुधार	३७
घाटे की अर्थ व्यवस्था	१५१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नये बजट के अंतिम अनुमान एक दृष्टि में

(लाख रुपयों में)

राजस्व

	संशोधित १९६२-६३	बजट १९६३-६४
सीमा-शुल्क	२,३१,६५	२,२१,२०) +८७,३९*)
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	५,५३,६९	५,८३,९६) +१,०६,६१*)
निगम कर	१,८७,५०	१,९६,००) +३१,००*)
आय सम्बन्धी कर	७७,२३	८१,०५) +३९,००*)
मृत सम्पत्ति शुल्क	१२	१२
सम्पत्ति कर	९,००	९,००) +४०*)
व्यय कर	२०	१०
दान कर	९५	९५
अन्य शीर्षक	१७,७५	१८,३७) +१,५०*)
ऋण व्यवस्था	१,७६,४९	२,१७,०५
प्रशासनिक सेवाएं	६,७५	६,७६
सामाजिक और विकास संबंधी सेवाएं	४३,३७	३१,६१
बहु प्रयोजनी नदी योजनाएं आदि	३९	४५
सरकारी निर्माण कार्य आदि	४,११	४,३८
परिवहन और संचार	६,६७	७,४६
मुद्रा और टकसाल	७०,५६	७३,६८
विविध	२५,६२	२४,९३
अंशदान और विविध समायोजन	२५,२०	२७,६६
असाधारण मद	६३,००	८१,००
जोड़—राजस्व	१५,००,२५	१५,८५,७३) +२,६५,९०*)

व्यय

	संशोधित १९६२-६३	बजट १९६३-६४
करों, शुल्कों और अन्य मुख्य राजस्वों का संग्रह	२३,०७	२३,८३
ऋण व्यवस्था	२,४६,०३	२,८०,२४
प्रशासनिक सेवाएं	७६,३९	८८,२८
सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं	१,५७,२६	१,५५,४०
बहु प्रयोजनी नदी योजनाएं आदि	७८	१,९६
सरकारी निर्माण कार्य आदि	२३,७१	२०,९४
परिवहन और संचार	८,७५	९,७९
मुद्रा और टकसाल	२२,९६	१७,२४
विविध—		
पेंशनें	१०,६४	१०,९८
विस्थापितों पर व्यय	९,९०	८,४१
अन्य व्यय	८८,२०	९१,८९
अंशदान और विविध समायोजन—		
राज्यों को अनुदान	२,१०,२४	२,१७,५५
केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों में राज्यों का हिस्सा	१,२४,९१	१,२८,०७
अन्य व्यय	३,३५	३,४२
असाधारण मदें	६४,६१	८६,१९
रक्षा सेवाएं (वास्तविक)	४,५१,८१	७,०८,५१
जोड़—व्यय	१५,२२,३१	१८,५२,४०
कमी (—)	(-)२२,०६	(-) २,६६,६७))
अधिशेष (+)		(+) २,६५,९०)

* बजट प्रस्तावों का प्रभाव

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१९६३-६४ में नये करों का प्रस्ताव

तीसरी योजना की पूर्ति और विशेषकर प्रतिरक्षा कार्यों के लिए नये वर्ष के बजट में पोने दो अरब रु० के जो अतिरिक्त कर वित्तमंत्री द्वारा लगाये गये हैं, वे संक्षेप से निम्नलिखित हैं—

अप्रत्यक्ष कर

१. नई चीजों के आयात शुल्क में वृद्धि का प्रस्ताव है जिसमें खनिज तेल, मशीनें, लोहे और इस्पात का सामान कपास, रबड़, ताड़, तेल, सिनेमा-फिल्म, तम्बाकू, रंग, धातु का सामान, बिजली के और दूसरे यंत्र और मोटर गाड़ियों के हिस्से शामिल हैं। पेट्रोलियम की ज्यादातर चीजों के उत्पादन व आयात शुल्क में काफी वृद्धि होगी। इन कर प्रस्तावों और दूसरे परिवर्तनों से १९६३-६४ में ६५.९८ करोड़ रु० का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

२. सभी आयात शुल्कों पर १० प्रतिशत का आम सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव है। इससे कुल अतिरिक्त राजस्व २६.७९ करोड़ रु० आंका गया है।

चाय के निर्यात शुल्क को उठा लेने के बाद अब उत्पादन शुल्क की वापसी को बन्द कर देने का प्रस्ताव है। इससे सीमाशुल्कों की प्राप्ति में ५.३८ करोड़ रु० की कमी हो जाएगी। सीमाशुल्कों में होने वाले सभी परिवर्तनों का परिणाम यह होगा कि १९६३-६४ के राजस्व में ८७.३९ करोड़ रु० की वृद्धि हो जाएगी।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

मोटर स्पिरिट तथा डीजल आयल आदि तेलों के बुनियादी उत्पादन शुल्क में कीमत के अनुसार बुनियादी दर बढ़ा दी जायगी। इन वृद्धियों से १९६३-६४ में ४८.४० करोड़ रु० का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

मिट्टी के तेल के शुल्क में वृद्धि से गरीब लोगों पर जो असर पड़ेगा उसे आंशिक रूप से बराबर कर देने के लिए बिना साफ किए हुए असारीय निर्गन्ध वनस्पति तेल, जिसमें खाने के साधारण तेल शामिल हैं, के उत्पादन शुल्क को हटा दिया जाएगा। इससे राजस्व में हर साल १०.२५ करोड़ रु० का घाटा रहेगा। लेकिन वनस्पती, रंग और रोगन और साबुन के शुल्क की दरों में वृद्धि कर दी जाएगी, इससे इन चीजों में पड़ने वाले तेल के लिए जो शुल्क अभी अदा किया जाता था, वह इन पर लगने वाले शुल्क की दरों में वृद्धि होने से लगभग पूरा हो जाएगा।

सिगरेटों के शुल्क की दरों में क्रमिक वृद्धि की जाएगी। सबसे सस्ती फी हजार सिगरेटों पर ७० नए पैसे से लेकर मंहगी सिगरेटों पर फी हजार ८.७० रु० तक होगी। अनिर्मित तम्बाकू के शुल्क की दर में भी ४० न० पै० प्रति किलोग्राम की वृद्धि की जाएगी।

ताम्बे के शुल्क में २०० रु० प्रति मैट्रिक टन वृद्धि करने का प्रस्ताव है। घास की लुगदी बने गत्ते (स्ट्राबोर्ड) का वार्षिक उत्पादन जहां १५०० मैट्रिक टन से ज्यादा है वहां उसके शुल्क में वृद्धि कर दी जाएगी।

डलो (इंगट) की हालत में लगने वाले शुल्क के अलावा इस्पात की बड़ी छड़ों (ब्लूम) दरमियानी छड़ों (बिलेट), खण्डों (स्लैब), इस्पाती छड़ों, टीन की छड़ों और बेलचे की छड़ों (हो बार) पर प्रति मैट्रिक टन ३० रु० का शुल्क लगाया जाएगा। चादरों (शीट) मोटी चादरों (प्लेट), छल्लों (हूप) और नल बनाने की नरम इस्पाती चादर (स्केरप) के शुल्क में भी ३० रु० प्रति टन की कमी कर दी जाएगी। उत्पादन शुल्क की दरों में इन परिवर्तनों से अगले साल ६०.२८ करोड़ रु० का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, जिसमें से ९.६० करोड़ रु० राज्यों को, उनके हिस्से के रूप में दिया जाएगा।

इस वर्ष कोई नया उत्पादन शुल्क नहीं लगाया जाएगा, लेकिन कुछ चीजों के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पर मंहगाई करके, अधिभार (सरचार्ज) लगाया जाएगा, ताकि सिर्फ केन्द्र के लिए जिसे रक्षा का बोझ संभालना पड़ता है, राजस्व जुटाया जा सके।

वैज्ञानिक विधि से तैयार किए रंगों, लिखने और छापने के कागज, जूट की चीजों, शीशा (जिस में प्लेट और शीट का शीशा शामिल नहीं है), चीनी मिट्टी के बर्तनों (चाइनावेयर और पोर्सिलेनवेयर), टीनप्लेट, अन्दर से जलने वाले इंजनों, बिजली की स्टोरेज बैटरियों, बिजली के बल्बों, मोटर स्पिरिट और डीजल तेलों के शुल्क पर १०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रतिशत का अधिभार लगाया जाएगा।

चाय, कहवा (काफी), अनिर्मित तम्बाकू, सिगरेटों, वनास्पती, रंग और रोगनों, साबुन शृंगार-सामग्री, प्लास्टिक की चीजों, सेलोफेन, टायरों, रबड़ की चीजों, कागज (जिसमें लिखने और छापने का कागज शामिल नहीं है), ३५ सूत्रांक (काउंट) से कम के रूई के सूत, ऊनी कपड़ों, आर्ट सिल्क के कपड़ों, सीमेंट, शीशे की प्लेटों और चादरों, बिजली की मोटरों, बिजली की ड्राई बैटरियों, बिजली के पंखों, मोटर कारों को छोड़कर दूसरी मोटर गाड़ियों, फिल्मों और एलूमीनियम पर २० प्रतिशत सरचार्ज लगाया जाएगा। सिगारों, रेयन और ऊन के धागों, ३५ सूत्रांक (काउंट) या उससे अधिक के रुई के सूत, रेशमी कपड़ों, प्रशीतकों (रेफ्रिजेरेटरों) और वातानुकूलन (एयर-कंडीशनिंग) के यंत्रों और उनके हिस्सों, वायरलेस सेटों, रेडियोग्रामों और मोटर गाड़ियों पर ३३॥ प्रतिशत का अधिभार लगाया जाएगा।

अधिभार से कुल ५५.९३ रु० अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। उत्पादन शुल्कों और अधिभारों में किए गए परिवर्तनों से १९६३-६४ में केन्द्र को १०६.६१ करोड़ रु० का वास्तविक अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

प्रत्यक्ष कर

प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के हेतु, व्यक्तियों, अनबंटे हिन्दु परिवारों, बिना रजिस्टरी वाली फर्मों और व्यक्तियों की संस्थाओं की आमदनियों पर, कर लगने के बाद, ४ प्रतिशत से लेकर १० प्रतिशत तक क्रमशः बढ़ने वाला अतिरिक्त अधिभार लगाने का प्रस्ताव है। इस अतिरिक्त दायित्व को अंशतः अनिवार्य जमा बचत द्वारा भुगतान किया जा सकता है। एक विधेयक द्वारा लोगों के विभिन्न वर्गों द्वारा अनिवार्य बचत किए जाने की व्यवस्था करने का अधिकार सरकार को मिल जाएगा। अंदाजा है कि कुल वसूली ६५ करोड़ और ७० करोड़ रु० के बीच होगी।

केन्द्रीय सरकार के लिए रजिस्टर्ड फर्मों द्वारा दिए जाने वाले आयकर पर २० प्रतिशत का अधिभार लगाने का भी प्रस्ताव है। इस व्यवस्था से ४५ करोड़ रु० की अतिरिक्त प्राप्ति होने का अनुमान है।

जो करदाता लगाए गए कर की रकम सम्बद्ध-कर-निर्धारण वर्ष की पहली जनवरी से पहले चुकता कर देंगे, वे अदा किए जाने वाले कर में से १ प्रतिशत की कमी के हकदार होंगे। इसी तरह जो कर दाता अपने विवरणों के आधार पर ३१ दिसम्बर तक सरकारी अदा नहीं करेंगे, उन्हें कर की रकम का २ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना पड़ेगा। यह भी प्रस्ताव है कि कम्पनियों के मामले में, किसी व्यक्तिगत कर्मचारी के पारिश्रमिक और ऊपरी आमदनी के सम्बन्ध में खर्च की जाने वाली कटौती को ६० हजार रु० वार्षिक तक सीमित कर दिया जाए। करों की वसूली में शीघ्रता करने और ऊंची तनखाहों और ऊपरी आमदनियों पर रोक लगाने के इन उपायों से १२ करोड़ रु० की प्राप्ति का अनुमान है।

नए दस-वर्षीय रक्षा जमा-पत्र और बारह-वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा-पत्र भी सम्पत्ति कर अधिनियम के अधीन करमुक्त परिसम्पत्ति की श्रेणी में गिने जाएंगे।

कर की दर और लाभ के प्रतिशत में, निगम कर की प्रणाली में आपसी सम्बन्ध नहीं है। मौजूदा प्रणाली में फेरबदल करने की एक अधिलाभ-कर भी लागू होगा, पर तब, जब किसी कम्पनी की आमदनी, आयकर और अधिकर को घटा देने के बाद, उसकी पूंजी और प्रारक्षित राशियों के ६ प्रतिशत से बढ़ जाएगी। जब वह रकम पूंजी के ६ प्रतिशत से अधिक लेकिन १० प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, तो कर की दर ५० प्रतिशत होगी और १० प्रतिशत से अधिक होने पर ६० प्रतिशत होगी। इस कर से बहुत ज्यादा नफा कमाने की प्रवृत्ति घटेगी और मूल्यों को कम करने में सहायता मिलेगी, अधिलाभ-कर से १९६३-६४ में २५ करोड़ रु० की राजस्व-प्राप्ति का अनुमान है।

अतिरिक्त कर लगाने और स्वेच्छा से बचत करने के प्रयत्न के साथ-साथ अनिवार्य बचत की एक व्यापक योजना भी चालू की जाएगी। एक विधेयक के द्वारा अनिवार्य बचत किए जाने की व्यवस्था करने के लिए सरकार को अधिकार मिल जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत जमा की हुई रकम पांच साल तक निकाली नहीं जा सकेगी और उस पर प्रतिवर्ष ४ प्रतिशत साधारण ब्याज दिया जाएगा।

सभी प्रस्तावित प्रत्यक्ष करों से जो अतिरिक्त प्राप्ति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

होगी, और जिसमें अनिवार्य बचतें शामिल होंगी, उसकी रकम ११०,४ करोड़ रु० होगी। इसमें से ४० करोड़ रु० अनिवार्य बचतों से, ३३ करोड़ रु० आयकर पर लगने वाले केन्द्रीय अधिभार से, २५ करोड़ रु० अधिलाभ-कर से, और १२.४ करोड़ रु० युक्ति-संगत व्यवस्था करने और छूटों में कमी करने या उन्हें बिल्कुल ही उड़ा देने से मिलेंगे।

डाक-दरें

पोस्टकार्ड की ५ न० पै० की मौजूदा दर और जवाबी पोस्टकार्ड की १० न० पै० की मौजूदा दर को बढ़ाकर क्रमशः ६ न० पै० और १२ न० पै० कर दिया जाएगा। स्थानीय पोस्टकार्ड नहीं रहेंगे।

बुक-पैटर्न और सैम्पल-पैकेटों, पार्सलों, रजिस्ट्रेशन की फीस, रसीद पाने की फीस, सर्टीफिकेट आफ पोस्टिंग, बीमा, व्यवसाय सम्बन्धी परमिटों की फीस और पोस्ट-बाक्स के किरायों की दरें भी बढ़ा दी गई हैं। डाक-दरों की वृद्धि से लगभग १५ करोड़ रु० की अतिरिक्त प्राप्ति होने का अनुमान है।

अन्तर्देशीय तारों की दर, बधाई के तारों की दर और एक्सप्रेस तारों की दर को भी बढ़ा दिया गया है। बधाई के तारों और स्थानीय तारों को अलग श्रेणी को समाप्त कर दिया जाएगा। अभी तार के संक्षिप्त पतों के रजिस्ट्रेशन का महसूल बदलता रहता है। भविष्य में इसके लिए, १२ महीने की अवधि के लिए, ५० रु० की एक समान फीस लेने का प्रस्ताव है। इन उपायों से ९५ लाख रु० मिलने का अनुमान है। ट्रंक टेलीफोनों के सम्बन्ध में कुछ रियायतें वापस ली जायंगी। डाक-तार और टेलीफोन की दरों में फेरबदल होने से कुल ४.६ करोड़ रु० की प्राप्ति होगी। ● ●

विश्व में सर्वाधिक व्यक्तिगत कर भारत में

एक अंक शास्त्री के कथनानुसार १२ हजार रु० से ऊपर की आय पर अन्य देशों की अपेक्षा भारत में सब से अधिक कर लगता है। निम्न तालिका से यह स्पष्ट होगा ?

आय	भारत	ब्रिटेन	अमेरिका	मलाया	जापान
रु०	%	%	%	%	%
१३,३३३	६.९	७.७	२.९	२.५	१५.६
२६,६६६	१७.९	१८.८	११.४	६.९	२३.०
४०,०००	२७.७	२२.६	१४.८	१०.३	२७.५
५३.३३३	३५.९	२४.५	१६.९	१२.९	३०.९
६६,६६६	४२.५	२६.५	१८.७	१५.६	३३.९
८०,०००	४७.७	२८.८	१९.९	१८.७	३५.३
९३.३३३	५१.५	३१.६	२१.६	२१.७	३७.२

सार्वजनिक ऋण में १०८५ करोड़ रु० की वृद्धि

१९६३-६४ के अन्त में भारत के सार्वजनिक ऋण में १,०८५ करोड़ रु. की वृद्धि की सम्भावना है, जिससे चालू वर्ष की यह कुल राशि ५,९५१ करोड़ रु० से बढ़कर आगामी वर्ष में ७,०३६ करोड़ तक पहुँच जाएगी।

पिछले २५ वर्षों में सार्वजनिक ऋण ७ गुना बढ़ गया है। १९३९ मार्च में यह ९४९.७७ करोड़ रु० था। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि १९३९ में भारत में जितना बकाया ऋण था, वह भारत से बाहर प्राप्त ऋण के समतुल्य था पर अब पहले प्रकार का ऋण अनुपात से भी अधिक बढ़ रहा है।

आगामी वर्ष के अन्त तक भारत में प्राप्त ऋण के अनुमानों का ब्यौरा इस प्रकार है—चालू उधार—३,०१८.२७ करोड़ रु०, ट्रेजरी बिल, १,८६८.९८ करोड़ रु०, विशेष जारी किये गये उधार (स्पेशल फलोटिंग लोन्स) २७.४३ करोड़ रु०। अगर अन्य अदायगियों को भी शामिल कर लिया जाए तो आगामी आर्थिक वर्ष के अन्त तक कुल राशि ९, ३६३.१९ करोड़ रु० तक पहुँच जाएगी। अन्य अदायगियों में रेलवे, डाक-तारविभाग और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को दिये जाने वाले चन्दे शामिल हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

परीक्षोपयोगी लेख

मुद्रास्फीति और मंहगाई

ले०—प्रोफेसर के० ए० जोसेफ

देश की आर्थिक समस्याओं में एक प्रमुख समस्या मुद्रा स्फीति की है। महंगाई की जननी यही है। पर सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बिना विवेक के घाटे की अधिक व्यवस्था का आश्रय लेती जाती है। इससे मुद्रा-प्रसार बढ़ता है और उससे जनता को परेशान करने वाली महंगाई। विद्वान् लेखक का विश्लेषण नयी दिशा में सोचने की प्रेरणा देता है।

"वर्तमान और भविष्य के बीच की एक कड़ी होने की खास वजह से ही मुद्रा का महत्त्व होता है। वर्तमान पीढ़ी के लिए यह कड़ी अविश्वसनीय रही है।"

—सर ओलीवर फ्रेन्क्स

बिना मुद्रास्फीति और घाटे की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास कठिन होता है; लेकिन अल्पविकसित देशों में घाटे की अर्थव्यवस्था से मुद्रास्फीति पैदा होती है। आम जनता, कीमतों की सतह में लगातार वृद्धि और मुद्रा की क्रय-शक्ति में लगातार गिरावट होने की अजीब हालत से परेशान और कभी कभी निराश हो जाती है; लेकिन फिर भी राजनीतिज्ञों का यह लगातार दावा होता है कि केन्द्रित नियोजन पद्धति के अन्तर्गत देश की प्रगति हो रही है और मुद्रास्फीति समृद्धि का ही एक लक्षण है। दूसरे महायुद्ध के अन्त तक अवस्फीति (डिफ्लेशन) तथा युद्धोत्तर काल में कीमतों में कमी की कुछ आशा विद्यमान थी, लेकिन हाल ही में युद्ध के बाद ऐसे नये कारण पैदा हो गये हैं जिनसे कीमतों में गिरावट की कोई संभावना नहीं दीख पड़ती।

कारण

इन अत्यन्त महत्वपूर्ण नये कारणों का, जिन्होंने वर्तमान युग में मुद्रास्फीति को अनिवार्य बना दिया है, लन्दन के "इकोनोमिस्ट" ने एक लेख-माला में विश्लेषण किया था। इनमें से कुछ तथ्यों पर हमारे नियोजकों और नीति-निर्माताओं को ध्यान देना चाहिए, जिससे कि नियोजन के जरिये समृद्धिशाली नये भारत का निर्माण करते समय मुद्रास्फीति जैसे अवरोधों से दूर रहा जा सके।

प्रत्येक देश में मुद्रास्फीति के अत्यन्त महत्वपूर्ण कारण होते हैं, जैसे युद्ध और एक बड़े युद्ध के बाद पुनर्निर्माण और युद्ध के लिए तैयारियां—जिन्हें सुरक्षा खर्च के नाम से पुकारा जाता है। पुराने जमाने में जब शत्रु को मारने के लिए धनुष और बाणों का उपयोग होता था, युद्ध की लागत बहुत कम होती थी। लेकिन आज दूसरे महायुद्ध में मारे गये प्रत्येक नागरिक पर प्रतिद्वद्वियों ने ७५,००० रुपए खर्च किये, जबकि पुराने जमाने में यह खर्च केवल कुछ नये पैसों का ही होता। आज चारों ओर फैली गरीबी और कमी के बीच संसार में प्रत्येक वर्ष सुरक्षा और राष्ट्रीय बचाव के नाम पर ५०,००० करोड़ रुपये खर्च किये जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपेक्षाकृत अपने को और भी कम सुरक्षित पाता है।

मजदूर संघों की बढ़ती हुई शक्ति के कारण श्रम की कीमत (मजदूरी) स्थायी और अपरिवर्तनशील हो गई है। श्रम क्षेत्र के इस कारण से पैदा होने वाले एकाधिकार के जरिये नीचे से लागत-वृद्धि पैदा होती है और इससे मूल्यों में वृद्धि होती है तथा मुद्रास्फीति ज्यादा बढ़ती जाती है। नये कल्याणकारी राज्य में न वेतनों की कमी संभव है और न लोगों की किसी प्रकार की छँटनी ही।

केन्स के सिद्धान्तानुसार हुई क्रांति के फलस्वरूप सम्पूर्ण-रोजगार की स्थिति पैदा करना लोकतांत्रिक राज्यों का मुख्य उद्देश्य बन गया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के मुख्य साधन निम्नलिखित हैं—बजट सम्बन्धी घाटा, सस्ती मुद्रा, अवमूल्यन, भरपाई सम्बन्धी खर्च, केन्द्रीय नियोजन और जन-शक्ति का लेखा-जोखा। इन सभी का स्वरूप मुद्रास्फीति पैदा करने का है। इसके अलावा केन्स

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के कुछ और भी सिद्धान्त हैं, जैसे कि लागत से अपने आप बचत होती है, बिना अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के आन्तरिक समृद्धि प्राप्त की जा सकती है; सभी आर्थिक परेशानियों की राम-बाण दवा है सस्ती मुद्रा अथवा मुद्रास्फीति प्रक्रिया में वृद्धि की है। उन सभी लोकतांत्रिक देशों में जहां पर बालिग मताधिकार विद्यमान है, झुकाव वामपक्ष की ओर है और वहां मुद्रास्फीति को उत्तेजना मिली है। इन देशों में अवस्फीति या मुद्रासंकोच को अक्सर दक्षिण-पन्थी तथा अलोकतांत्रिक तरीका बताया जाता है।

सभी देशों में

नये कल्याणकारी राज्य में समाज सेवाओं का विस्तार सभी सरकारों के लिए लगातार व्यय-स्रोत बना हुआ है। संसदीय सरकार की पार्टी-पद्धति में प्रत्येक पार्टी ऐसी समाज सेवाओं पर दूसरी पार्टी से ज्यादा खर्च करने की कोशिश करती है। इससे आधुनिक सरकारों के लिए अपने बजटों को सन्तुलित रखने में काफी कठिनाई होती है और फलस्वरूप समुदाय पर अधिक रकम खर्च की जाती है जिससे मुद्रास्फीति के आश्रय की स्थिति पैदा हो जाती है।

सामाजिक न्याय का सिद्धान्त, सम्पत्ति और आय की अधिकतर समानता तथा समाजवाद की बढ़ती हुई उत्तरोत्तर लोकप्रियता के कारण खर्चों और मुद्रास्फीति को उत्तेजना मिलती है। समाजवादी पद्धति की समाज रचना की स्थापना की दिशा में उठाये गये अनेक कदमों के फलस्वरूप बचत कम होती है और यहां तक कि धनवान् वर्गों को भी अपनी बचतों में से बहुत कर देने के लिए बाध्य किया जाता है। इस तरह से खर्च करने की ओर रुख में वृद्धि होती जाती है और जाप्ता करों (कानफिसकेटरी टेक्स) के जरिये बचत की क्षमता कम हो जाती है। यहां तक कि समृद्ध लोगों ने भी खर्च करने के नये दर्शन को अपना लिया है और उसी में खुश रहते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि कल उन पर कौन से नये कर लगा दिये जायंगे। इस प्रकार की आर्थिक अनिश्चितता और ज़ाप्ता कानूनों ने समृद्ध लोगों में खर्च बढ़ाने की भावना को काफी ज्यादा उत्तेजन दिया है।

आर्थिक कन्ट्रोल, खास कर कीमतों के कन्ट्रोल, विनिमय कन्ट्रोल, आयात कन्ट्रोल आदि मुद्रास्फीति की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। जब किसी एक स्थान पर मांग पूरी नहीं होती, तो वह दूसरे स्थान पर बेधडक रूप से पैदा हो जाती है। मूल्यों के नियंत्रणों से, धनी लोगों की जेबों में क्रय-शक्ति की अतिरिक्त मात्रा पैदा हो जाती है और वे नियंत्रित सामानों के लिए ज्यादा कीमतें अदा करते हैं। यह ज्यादा धन दूसरी चीजों की कीमतों को बढ़ा देते हैं और काला बाजार पैदा करते हैं। आजकल की सरकारों के, खासकर उपभोक्ता सामानों के बारे में, हस्तक्षेप से कीमतों में वृद्धि ही होती है। कन्ट्रोलों की पद्धति में मूल्य-तंत्र खराब हो जाता है और समुदाय को सर्वाङ्गीण अभावों और मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ता है।

आजकल की दुनिया आर्थिक दृष्टि से एक दूसरे देश पर परस्पर निर्भर है और सभी देशों के मूल्य स्तर भी परस्पर सम्बन्धित है। दूसरे देशों में पैदा हुए मुद्रास्फीति सम्बन्धी रुख, कुछ समय बाद प्रत्येक देश में पैदा हो जाते है। आज के युग में सबसे अधिक समृद्ध देशों तक में बन्द अर्थव्यवस्था वास्तव में अव्यावहारिक है। आधुनिक सरकारों की व्यापार सम्बन्धी नीतियों से, जो स्वतंत्र व्यापार के क्षेत्र तक में स्वतंत्र व्यापार को बन्द कर देती है और व्यापार नियंत्रण, विनिमय नियंत्रण, कोटा पद्धति आदि की लोकप्रियता के कारण मुद्रास्फीति को बढावा मिलता है। संरक्षण में मुद्रा-स्फीति में काफी वृद्धि होती है और उससे आयात किये गये तथा देशी माल की कीमतें बढती हैं।

मन्दी के बाद पैदा हुए प्रबन्धित मुद्राओं के वर्तमान युग में, और जबकि स्वर्ण-प्रतिमान (गोल्ड स्टेण्डर्ड) को त्याग दिया गया है, मुद्रास्फीति आसान और यहाँ तक कि सम्माननीय बन गई है। घाटे की बजट व्यवस्था की प्रक्रिया तथा फैलाववादी नीतियों के जरिये मूल्यों की आन्तरिक सतहों को बढ़ने दिया जाता है और फिर विपरीत भुगतान शेष को ठीक करने के लिए अवमूल्यन, मूल्यहास और अन्य सभी ऐसे हथियारों का प्रयोग किया जाता है जिनसे मुद्रास्फीति को प्रोत्साहन मिलता है।

दूसरे महायुद्ध के बाद सभी देशों ने विकास के अपने नियोजित कार्यक्रम तैयार किये तथा सभी कम विकसित देश विकास की होड में लग गये हैं। इनमें से अधिकांश कार्यक्रम सबसीडियों, कर्जों, और पूंजीगत आयातों पर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

निर्भर है और ये सभी मुद्रास्फीति को बढ़ाते हैं।

अन्तःराज्यीय सहायता

भूतकाल में, प्रत्येक देश अपने विपरीत भुगतानों को ठीक करने के लिए स्वयं अपने ही साधनों पर निर्भर करता था और सिर्फ उपलब्ध साधनों के आधार पर ही रकमें लगाता था। लेकिन १९४५ से अन्तः राज्यीय दान का विकास किया गया और मार्शल सहायता (एड) चतुः सूत्री कार्यक्रम, और अमरीकी विदेश सहायता जैसी विशेष सहायताओं के जरिये मुद्रास्फीति जारी और कायम रखी गई। संसार के सभी भागों में और खासकर भारत जैसे देशों में, हम लोग एक लगातार आर्थिक संकट, विपरीत भुगतान शेषों और अन्तर्राष्ट्रीय असन्तुलन के युग में रहते चले आ रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की कठिनाइयों को एक बाहरी दयावान परी (जिसका अक्सर डालर वाले अंकिल साम का रूप होता है) के जरिये सुलझाया जाता है और फलस्वरूप सभी देशों में खर्च करने की धुन जारी रहती है। इस दान कार्य से वह परी और भी ज्यादा फूलती जाती है। अब हम कल्याणकारी राज्य को पार कर 'कल्याणकारी विश्व' की ओर जा रहे हैं। अबन्ध-नीति (लेजाफेयर), शांति, स्वर्ण-प्रतिमान, स्वतंत्र व्यापार तथा अन्य अनुदार आदर्शों का स्थान अब केन्द्रित नियोजन, घाटे के बजटों, मुद्रास्फीति के वित्त तथा खर्च करने के नये विश्वास ने ले लिया है। इस नये युग में सरकारी खर्च के लिए कोई सीमा नहीं है, जबकि अन्य सभी लोगों के लिए सीमा है—धन, आमदनी, कार्य, कमाने और यहाँ तक कि सीखने और तालीम पाने तक की सीमा है।

भारी कराधान और जाप्ता कानूनों ने बचत के स्रोतों का पहिले ही शोषण कर लिया है और अब बचत करने वालों को निराशा और नाकामयाबी महसूस होती है क्योंकि उनकी बचत लगातार मुद्रास्फीति की वजह से घटती जाती है। केन्द्रीकृत राजकीय नियोजन ने वित्त और मुद्रा सम्बन्धी नीति का नियंत्रण राजनीतिज्ञों के हाथों में दे दिया है जिनका पेशेवर आकर्षण होता है आशाजनक दृष्टिकोण अपनाना और अर्थव्यवस्था की गुंजाइश से ज्यादा खर्च करना। सम्पूर्ण रोजगार और सामाजिक सुरक्षा ने जनता की क्रयशक्ति को बढ़ा दिया है। इसी तरह स्वतंत्र व्यापार, स्वर्ण-प्रतिमान और स्थायी विनिमय दरों के खत्म हो जाने की वजह से मुद्रास्फीति के विरुद्ध मुख्य निरोध समाप्त हो गये।

मुद्रास्फीति की हानियां

इस मुद्रास्फीति के कुछ परिणाम अत्यन्त खतरनाक होते हैं। उससे अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है, मुद्रा में विश्वास कम हो जाता है, बचत करने और पूंजी लगाने में उत्साह कम हो जाता है, और समुदाय के अधिकांश वर्गों में परेशानी फैल जाती है। वेतन पाने वाले मध्यम वर्ग, पेंशनयाफ्ता तथा स्थिर आमदनी वाले लोगों की हालत अत्यन्त दयनीय होती है। इसी वर्ग के लोग, जो वास्तव में स्थायी लोकतंत्र के मुख्य आधार होते हैं, दोहरे दबाव से परेशान हो जाते हैं। ऊपर से भारी करों के बोझ और नीचे से मुद्रास्फीति के अभिशाप से ये लोग दबे रहते हैं। अतः प्रशासन को चाहिए कि वे मुद्रास्फीति और मध्यम वर्ग की इस समस्या पर ध्यान दें। समुदाय के लिए क्या यह बात उचित है कि वह अपने नागरिक सेवकों; शिक्षकों; क्लर्कों; एकाउन्टेन्टों आदि के साथ मुद्रास्फीति के जरिये उनके वेतनों को कम कर उनके साथ बुरा बर्ताव करे, खासकर उस समय जबकि समुदाय उत्तरोत्तर समृद्ध बनता जा रहा हो और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही हो? भारत जैसे देश में मध्यम वर्ग को अपनी आमदनी में ३० से ८० प्रतिशत तक की कटौती क्यों सहन करनी पड़े, जबकि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही हो?

विश्व बैंक मिशन के सदस्य डा० बर्नस्टेन ने अपनी रिपोर्ट में घाटे की अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति के खतरों पर जोर दिया है। अपर्याप्त साधनों की समस्या का हल, मूल्यों के कन्ट्रोलों और ऋण विस्तार के योग के सहित राशनिंग में नहीं मिलता है। इन कन्ट्रोलों आदि को व्यापक पैमाने और शांतिकाल में दीर्घ समय तक सफलतापूर्वक चलाना कठिन होता है।

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत भारत में जो स्थिति पैदा हो रही है, उससे घाटे की वित्त-व्यवस्था और मुद्रास्फीति पैदा हो रही है और इससे सरकार और जनता दोनों को परेशानी हो रही है। विभिन्न आर्थिक दर्शकांकों से

(शेष पृष्ठ १५० पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्वर्ण समस्या : सरकारी स्वर्ण नीति

श्री नन्दकिशोर पाण्डेय, एम० काम०,

स्वर्ण नियंत्रण से स्वर्ण के प्रति जनता का आकर्षण कम होगा और सोने का अवैध व्यापार भी कुछ कम होगा, यह आशा व्यक्त की गई है। पर लेखक ने नियन्त्रण से प्रादुर्भूत आज की कुछ नई समस्याओं का विवेचन करते हुए ५ लाख स्वर्णकारों के बेकार होने और सोने के बर्मा, नेपाल इत्यादि देशों में खिसक जाने के खतरे की ओर जो संकेत किया है, वह भी उपेक्षणीय नहीं है।

स्वर्णदान एवं स्वर्णबाण्ड की योजना के पश्चात्, ९ जनवरी ६३ को नये स्वर्ण नियंत्रण आदेश की घोषणा की गई है। इस घोषणा का उद्देश्य स्वर्ण के अवैध आयात को रोकना, विदेशी विनिमय की समस्या को सुलझाना तथा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना है।

अवैध सोने के आयात से हानि

स्वर्ण के अवैध आयात से हमारे देश को निम्नलिखित मुख्य हानियां हो रही हैं :—

(१) अवैध स्वर्ण के आयात से विदेशी विनिमय का दुरुपयोग होता है। देश को विकास एवं रक्षा कार्यों के लिए विदेशी विनिमय की नितान्त आवश्यकता है।

(२) भारतीय नागरिकों को स्वर्ण के लिए अधिक मूल्य देना पड़ता है। स्वर्ण अफ्रीका के देशों से लगभग ४० रु० प्रति तोले के भाव लाया जाता है जबकि हमारे देश में १४० रु० तक उसका मूल्य दिया जाता है।

(३) नागरिकों के द्वारा स्वर्ण में अपनी बचत का विनियोग करने के कारण राष्ट्रीय विकास कार्यों के हेतु अल्प बचत आदि के रूप में जो राशि शासन को प्राप्त होनी चाहिए, वह प्राप्त नहीं होने पाती। एक अनुमान के अनुसार १९६१ से १९६२ के बीच लगभग ३०० करोड़ रुपये के स्वर्ण का अवैध आयात हुआ। यदि यह राशि स्वर्ण में विनियोग नहीं की जाती, तो विकास कार्यों के लिए उपलब्ध हो सकती थी।

(४) अनुचित उपायों से प्राप्त, अथवा करों की चोरी से बचाई आय का विनियोग स्वर्ण में कर दिया जाता है। जैसे, यह देखा जा सकता है कि जहां पिछले १२ वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में ८०% वृद्धि हुई है। आयकर केवल १३५ करोड़ से १४२ करोड़ रुपए हुआ।

इन सभी कारणों से यह आवश्यक हो गया कि स्वर्ण के आयात पर नियन्त्रण किया जावे।

नियन्त्रण आदेश का प्रभाव

वित्तमन्त्री महोदय ने राष्ट्र को इन्हीं सब हानियों से बचाने के लिए स्वर्ण नियंत्रण आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के द्वारा स्वर्ण के धातु के रूप में क्रय विक्रय के नियंत्रण तथा इस समय उपलब्ध मात्रा की घोषणा आवश्यक करके जहां अवैध स्वर्ण के आयात के समाप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है, वहां १४ कैरेट की शुद्धता वाले स्वर्ण आभूषणों के निर्माण का कानून बनाकर, स्वर्ण की मांग को कम करने का भी प्रयत्न किया गया है। विचारणीय विषय यह है कि क्या यह प्रयत्न सफल होगा? अवैध स्वर्ण के आयात को तभी रोका जा सकता है, जब देश में स्वर्ण की मांग कम कर दी जावे जिससे मूल्य गिरकर अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य १० ग्राम—५३.५८ न० पै० के बराबर हो जावे, ताकि अवैध स्वर्ण का आयात करना इस व्यवसाय में लगे हुए लोगों के लिए लाभप्रद न रहे। यह आशा की गई है कि १४ कैरेट स्वर्ण की शुद्धता आभूषणों की रखने से स्वर्ण की मांग कम हो जावेगी। एक तो शुद्धता कम हो जाने से स्वर्ण के प्रति आकर्षण कम हो जावेगा और यदि १४ कैरेट की शुद्धता फैशन में आ गई तो भी पूर्वापेक्षा शुद्धता ३३ प्रतिशत के लगभग कम होने से स्वर्ण की वास्तविक मांग कम हो जावेगी। लेकिन इससे मांग में ही नहीं पूर्ति में भी ह्रास होगा। एक ओर अवैध स्वर्ण के आयात के रुक जाने तथा दूसरी ओर अब बदली हुई परिस्थितियों में जनसाधारण द्वारा स्वर्ण विक्रय बहुत कम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

करने से निश्चय ही पूर्ति कम हो जावेगी। तब यह देखना होगा कि मांग और पूर्ति की नई तुलनात्मक शक्ति क्या होती है और उसका मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अतः केवल इस नियंत्रण आदेश से ही कोई बहुत अधिक अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, ऐसी आशा करना तर्कसंगत नहीं होगा। आदेश की घोषणा के पश्चात् ही स्वर्ण आभूषणों का बड़ी मात्रा में विक्रय इसका प्रमाण है।

मूल कारण और उपचार

इस समस्या के समाधान के हेतु गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। स्वर्ण की मांग हमारे देश में केवल मोहवश ही नहीं है। उसकी मांग इसलिए भी है कि उसे पारिवारिक सुरक्षा का साधन, संकटकाल में माना जाता है। दूसरे, कृषकों तथा लघु-व्यवसायियों को स्वर्ण के आधार पर आवश्यकतानुसार उनके व्यवसाय के हेतु साख की प्राप्ति हो जाती है। तीसरे, वित्त संचय की दृष्टि से स्वर्ण एक अच्छा एवं सुरक्षित विनियोग का साधन माना जाता है। उपयुक्त तीन कारणों से स्वर्ण की मांग मध्यमवर्ग के द्वारा हमारे देश में होती है। यह मांग उस मांग से पृथक् है जो उन असामाजिक तत्त्वों द्वारा की जाती है, जो करों आदि के अपवंचन से बचाई आय कर स्वर्ण में विनियोग करना चाहते हैं। परन्तु स्वर्ण की सकल मांग में न केवल यह मांग वरन् सामाजिक परम्पराओं एवं आभूषणों की मांग भी सम्मिलित होती है। यदि स्वर्ण के मूल्य वस्तुतः गिराने हैं तो हमें एक दीर्घ कालीन योजना इस प्रकार की जनानी होगी जिससे स्वर्ण की मांग गिर जावे। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव विचारणीय हैं :—

(१) सभी प्रकार के बीमे की अधिक से अधिक सुविधायें उपलब्ध कराई जावें ताकि आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से स्वर्ण का कोई विशेष महत्व नागरिकों की दृष्टि में न रहे।

(२) कृषकों एवं लघु-व्यवसायियों के साख की उचित व्यवस्था हो, उन्हें सुविधानुसार उनके उद्योग धन्धों के लिए ऋण प्राप्त हो सके। अभी भी ६० से ७० प्रतिशत ऋण स्वर्ण आदि के आधार पर ही प्राप्त किए जाते हैं। इस दृष्टि से सहकारिता आन्दोलन को अत्यधिक द्रुत गति से बढाया जावे।

(३) मूल्य स्थिरता लाई जावे। मुद्रास्फीति रोकना अत्यावश्यक है। यदि रुपये की क्रय शक्ति की स्थिरता पर जनता को विश्वास हो तो मूल्य संचय के उद्देश्य से स्वर्ण की मांग निश्चय ही कम हो जावेगी।

(४) मुद्रास्फीति का नियंत्रण इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि इसी के कारण ही स्वर्ण की मांग वृद्धि हुई है। यदि स्वर्ण के मूल्यों को नीचे गिराना है, तो निश्चय ही मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण करना होगा।

(५) यह भी आवश्यक है कि स्वर्ण के अन्तर्राष्ट्रीय एवं बाजार मूल्य में जो लगभग ७०-८० रु० का अन्तर है, इसे कुछ कम अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य को बढ़ा कर किया जावे। ऐसा सितम्बर १९३९ में किया जा चुका है। ऐसा करने से विदेशी विनिमय के अवैध क्रय को भी रोकने में सहायता मिलेगी।

(६) समाज सुधारकों एवं राजनैतिक पार्टियों द्वारा निरन्तर अथक प्रयास स्वर्ण के प्रति आकर्षण को कम करने के लिए किया जावे तथा १४ कैरेट के स्वर्ण आभूषण लोकप्रिय बनाये जावें जैसी कि इस नियन्त्रण आदेश में व्यवस्था है।

यदि ये समस्त उपाय काम में लाये जाते हैं, तभी हम इस बात की आशा कर सकते हैं कि स्वर्ण की मांग वास्तव में कम होगी, उसके मूल्य कम होंगे और स्वर्ण आयात कुछ रुकेगा।

वर्तमान नीति एवं तज्जनित समस्यायें

अब हम स्वर्ण नियन्त्रण आदेश से सम्बन्धित समस्याओं पर भी विचार करेंगे। स्वर्ण नियन्त्रण आदेश के जारी होते ही कुछ समस्यायें उपस्थित हो गई हैं। उनका समुचित निराकरण करना आवश्यक हो गया है। एक तो चूंकि इस आदेश के अंतर्गत आभूषणों को सम्मिलित नहीं किया गया है, फलस्वरूप जिनके पास स्वर्ण का संग्रह रहा है, उन्होंने शीघ्र ही उनका परिवर्तन आभूषणों में करा लिया है। ऐसी स्थिति में आभूषणों की घोषणा करना भी अनिवार्य कर दिया जाए। दूसरे, इस अधिनियम के द्वारा स्वर्ण के आधार पर अधिकोषोत्तर ऋण का जो निषेध किया गया है, वह कृषकों एवं लघु व्यव-सायियों की दृष्टि से बड़ा घातक सिद्ध हुआ है। गांवों में कृषि तथा छोटे व्यवसायी बड़ी कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं क्योंकि इन व्यवसायों

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

में अभी तक साख का मुख्य आधार स्वर्ण ही रहा है। तीसरे, देश में लगभग पांच लाख स्वर्णकार हैं, उनकी समस्या पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार किया जावे। अन्य उद्योगों में इन्हें काम दिया जावे, या नये १४ कैरेट के आभूषणों के निर्माण का प्रशिक्षण दिया जावे। वैसे इस समस्या को बहुत अधिक तूल देने की आवश्यकता नहीं है। संक्रमण काल में थोड़ी बहुत कठिनाई आ ही जाती है।

यद्यपि इस बात की अभी कोई निश्चित सम्भावना नहीं है कि शासन ने जो अभी तक कदम उठाये हैं उनसे स्वर्ण के मूल्य में ह्रास हो ही जावेगा, तो भी यदि मूल्य में गिरावट आ भी गई तो एक नई समस्या उत्पन्न हो सकती है। हमारे पड़ौसी देशों, पाकिस्तान, बर्मा, नैपाल आदि में यदि स्वर्ण का मूल्य यथावत बना रहता है तो संभव है कि स्वर्ण निर्यात अब भारत से इन देशों को होने लगे। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो अभी से उसके लिए पूरी सावधानी रखनी चाहिए। यह भूलना नहीं चाहिये कि सन् १९३०-३१ से द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ तक हमारे देश में स्वर्ण का मूल्य अन्य देशों से कम होने के कारण लगभग १० करोड़ तोले सोना का, जिसका तत्कालीन मूल्य ३५० करोड़ रुपये था, तथा वर्तमान बाजार मूल्य के आधार जो लगभग १४०० करोड़ रुपये का होता है, निर्यात हो गया था। यह हमारे सम्पूर्ण स्वर्ण कोष का लगभग तृतीय अंश था। पांचवें स्वर्ण की समस्या को चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग से हल करना है अतः स्वर्ण नियंत्रण बोर्ड में अन्य वर्गों तथा दलों के भी प्रतिनिधि लिये जावें। छठे, चांदी पर भी आवश्यक नियन्त्रण किया जावे क्योंकि एक सीमा तक स्वर्ण के स्थान पर चांदी का उपयोग किया जा सकता है।

शासन की दृढ़ता और जन सहयोग

यह भूलना नहीं चाहिये कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। और इसके समाधान पर न केवल हमारा आर्थिक विकास वरन् देश की रक्षा व्यवस्था निर्भर करती है। सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि शासन के निर्णयों में दीर्घ सूत्रता न हो। कहा जाता है कि यदि यह स्वर्ण नियंत्रण आदेश पहले जारी किया जाता तो मनोवैज्ञानिक वातावरण, चीनी आक्रमण के कारण अनुकूल होने से, अधिक सफल हो सकता था। फिर, धीरे-धीरे जिस ढंग से निर्णय लिये गए, उससे भी जिनके पास स्वर्ण का संग्रह है उन्हें इसका आभास हो गया और उन्होंने अपनी रक्षा की व्यवस्था कर ली। हो सकता है, वातावरण बनाने की दृष्टि से ऐसा किया गया हो। दूसरी, महत्वपूर्ण बात यह है कि शासन तन्त्र में दृढ़ता हो और भ्रष्टाचार न आने पाये, अन्यथा मद्यनिषेध की तरह यह भी एक मजाक बनकर रह जावेगा। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कर्तव्य परायणता तथा ईमानदारी पर यह सब निर्भर करता है। लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता अपने दायित्व को समझे। यदि जनता अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती तथा शासन को सहयोग नहीं देती तो सफलता प्राप्त करनी कठिन हो जाएगी। स्वर्ण के प्रति अपने मोह को त्यागना ही होगा। हमारा देश जनतन्त्रवादी है, किसी प्रयत्न की सफलता केवल शासन पर निर्भर नहीं करती। जनता को एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए। स्वर्ण का संग्रह स्वयं उसके हित के विरुद्ध है। आने वाले भविष्य में जब हमारा देश पर्याप्त मात्रा में निर्यात करने की स्थिति में आ जावेगा तब व्यापाराधिक्य अनुकूल होने से विदेशी विनिमय की यह कठिनाई भी नहीं रहेगी। निश्चय ही तब स्वर्ण के मूल्य गिरेंगे और आज जो लोग अत्यधिक ऊंचे मूल्य पर स्वर्ण खरीद रहे हैं, उन्हें पश्चात्ताप करना होगा।

चार हजार करोड़ रुपये के सोने के धनी हम उसे अपने आर्थिक विकास तथा रक्षा कार्यों में न लगाकर यों ही पड़ा रहने दें, यह उचित नहीं है। स्वर्ण नियन्त्रण आदेश की सफलता के आसार भी नजर आने लगे हैं। एक ओर स्वर्ण के तस्कर व्यापार में एक दम कमी आ गई है तो दूसरी ओर इस बीच लगभग ढाई करोड़ रुपये स्वर्ण बाण्डों की बिक्री भी हुई है।

हाथ चलावो, नहीं जानता
दीवारों के होते हैं कान,
सुनता है दुश्मन शैतान

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हमारे सार्वजनिक उद्योग

श्री ए० डी० श्राफ

इस लेख के लेखक देश के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। आज की सरकारी विकास योजनाओं के सम्बन्ध में उनकी दृष्टि सर्वथा भिन्न है। वे देश के आर्थिक विकास के लिए सरकार के उद्योग व्यापार स्वयं हाथ में लेने को न केवल अवांछनीय मानते हैं, बल्कि अव्यावहारिक भी। निजी उद्योग के प्रमुख वक्ता के रूप में उन्होंने अपना अभिमत असंदिग्ध और स्पष्ट रूप से उपस्थित किया है। भिन्न मत रखते हुए भी हम पाठकों व विचारकों से इस लेख में प्रकट विचारों पर चिन्तन करने का आग्रह करेंगे।

लेखक

भारत सरकार के १९६२-६३ के बजट से सम्बद्ध स्पष्टीकरण मेमोरेंडम से पता चलता है कि ७३ राजकीय उद्योगों में से अभी तक केवल १० उद्योगों ने लाभ दिखाया है। १९६०-६१ में ६०५-६३ करोड़ रुपये की लागत पर प्रतिफल २.०१ करोड़ रुपये था जिसका अर्थ केवल ०.३ प्रतिशत हुआ, और १९६१.६२ में ७०९ करोड़ रकम की लागत पर यह प्रतिफल कम होकर १.९५ करोड़ रुपये ही रह गया था। १९६२-६३ के दौरान में लागत की मात्रा बढ़ कर ८०७ करोड़ रुपये और लाभ की मात्रा ३ करोड़ रुपये आंकी गई थी। राज्य सरकारों की मालिकी के उद्योगों की तस्वीर भी कोई अच्छी नहीं है। उदाहरण के तौर पर मध्यप्रदेश विधान सभा की १९६१-६२ वर्ष की सार्वजनिक लेखा समिति की पांचवीं रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित अधिकांश संस्थानों की कार्रवाई "असन्तोषजनक" है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिष्ठानों को हर साल नुकसान होता रहा है और उनके हिसाबों को उचित तरीके से नहीं रखा जाता है। फैक्टरी ने ढाई वर्ष में केवल १८ बाईसिक्लें तैयार कीं जिनमें प्रत्येक की कीमत है १६,००० रुपये। उनमें सैडल फिट करना अब भी बाकी है। फैक्टरी की स्थापित क्षमता इतनी है कि उत्पादन की मात्रा का हिसाब १/१०,००० होता है।

सुरक्षा सेवाओं की १९६१ वर्ष की आडिट रिपोर्ट के अनुसार ६ वर्ष के बाद भी मशीन टूल-कम-प्रोटोटाइप फैक्टरी "लागत पूंजी पर कोई प्रतिफल नहीं दिखा पायी है। बल्कि इसके विपरीत उसने वास्तव में ६८.६३ लाख रुपये (ऊपरी-व्यय) तथा ८.१३ लाख रुपये अर्थात् कुल मिलाकर लगभग ७७ लाख रुपये का नुकसान उठाया है।" १९६२ वर्ष की आडिट रिपोर्ट में ऐसे अनेक उदाहरण भरे हुए है। उनमें से कुछ चीजें, जैसे फोटो एनलार्जर, सिनेमा प्रोजेक्टर और एसप्रेसो काफी की मशीनें 'नागरिक व्यापार के लिए अलाभप्रद स्टोरों का निर्माण है।' जुलाई १९५३ में २७५ रुपये प्रति नग के हिसाब से फोटो एनलार्जरों का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। लेकिन १९५७ तक एक भी नग नहीं बन पाया, हालांकि योजना पर २ लाख रुपये खर्च कर दिये गये। इसलिए १९५७ में निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया।

१९५८ में इन एनलार्जरों को ६०० रुपये नग के हिसाब से तैयार करने की योजना दोबारा तैयार की गई।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिसम्बर १९६१ तक केवल ९ एनलार्जर करीब २,७४५ रु० प्रति नग की लागत से बन कर तैयार हुए। इसी प्रकार के एनलार्जरों की दिसम्बर १९५९ में बाजार में कीमत थी ४५० रुपये! इसी प्रकार दो मूवी प्रोजेक्टरों को बनाने में तीन लाख रुपये खर्च किये गये और फिर योजना रद्द कर दी गई। एसप्रेसो काफी मशीनों के मामले का अपना ही जायका है और उसे स्वयं आडिट रिपोर्ट के शब्दों में ही दोहराना रोचक होगा। रिपोर्ट में कहा है "१९५८-६० वर्षों के दौरान में ईशापुर की रायफिल फैक्टरी ने १५ एसप्रेसो काफी मशीनें, सरकार की बिना औपचारिक स्वीकृति प्राप्त किये या वित्तीय अनुमति लिये कुल ५३,७६४ रुपये की लागत से तैयार कीं। इन मशीनों की किसी प्रकार की व्यापारिक मांग न होने के कारण उनको बेचा नहीं जा सका। उनमें से एक मशीन राज्य के मुख्य मंत्री जी को भेंट की गई। शेष १४ मशीने अब भी (अक्टूबर १९६१) स्टाक में पड़ी हुई है।"

सरकारी स्टील प्लांटों की कहानी सभी लोगों को अच्छी तरह मालूम है। राउरकेला के बारे में सोलवीन कमेटी की रिपोर्ट इस बात के लिए प्रमुख मार्गदर्शक है कि सभी नये उद्योगों को किन-किन बातों से दूर रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ७८ लाख रुपये की हानि तालाबन्दी के फलस्वरूप इसलिए हुई ताकि कुछ कामगरों द्वारा अपने विशेष कार्य के लिए वैध रूप से मांगे गये कुछ सौ रुपयों को बचाया जा सके। हाल ही में सिन्दरी और नंगल फैक्टरियों में उर्वरक (खाद) के स्टाक का ढेर (नंगल में यह मात्रा ४१,००० टन तक की थी) जमा हो गया था, जबकि देश में उसकी पूर्ति कम है और खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिए फार्मों में उस खाद की जरूरत है। इसका कारण यह बताया जाता है कि इस नये उर्वरक का किसानों में काफी प्रचार नहीं किया गया था और बिना बिक्री समन्वय के उत्पादन शुरू कर दिया गया था। रेलवे-उद्योग के सम्बन्ध में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, यह तो सभी भुक्तभोगी जानते हैं।

इस प्रकार की भारी अकार्य क्षमता का जन्म मुख्य रूप से इस तथ्य से होता है कि राजकीय सार्वजनिक उद्योगों का सार्वजनिक कल्याण से कोई सम्बन्ध नहीं है। उनका संचालन नौकरशाही अधिकारी करते हैं, जिनको बिना जिम्मेदारी के अधिकार प्राप्त होते हैं और जिनकी उद्योग या सार्वजनिक कल्याण में अपनी व्यक्तिगत कोई रूचि नहीं होती है। हिन्दुस्तान शिपयार्ड के चेयरमेन, श्री जी. एल. मेहता ने अप्रैल १९६२ में कहा था कि "शिपयार्ड जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में वरिष्ट और जिम्मेदार अधिकारी हमेंशा सेवा और सहकार की भावना नहीं दिखाते हैं, जो उसके सुचारू संचालन के लिए जरूरी होती है।" अर्थव्यवस्था को इस प्रकार के रूख और अकार्य-क्षमता से किस हद तक हानि पहुंचती है इसका अन्दाजा दो जापानी उद्योगपतियों के, जो हाल ही में हमारे देश में आये थे, बयानों से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय अधिकारियों की "नौकरशाही अव्यवस्था" ने जापान में अपने कच्चे लोहे का बाजार खो दिया है। इसके अलावा उन लोगों ने, जिन्हे कच्चे लोहे के व्यापार में कोई अनुभव नहीं था, इस प्रकार के सौदे को तय करने के लिए जापान जाकर जापानी आयातकों तथा वहां की सरकार में सन्देह और गलतफहमियां पैदा कर दीं। भारत के राजकीय व्यापार निगम (स्टेट ट्रेडिंग कोरपोरेशन) के खिलाफ जिसने भारत के विदेशी व्यापार और इज्जत को भारी धक्का पहुँचाया है, यह सिर्फ एक और शिकायत है।

निजी शेयर क्यों नहीं ?

अकार्य क्षमता के इस रिकार्ड की पृष्ठ भूमि में यह आश्चर्य की बात नहीं है कि सरकार, राजकीय उद्योग के शेयर पूंजी में सार्वजनिक हिस्सेदारी का प्रस्ताव, रद्द कर दे। बम्बई के १५ जून, १९६२ के एक समाचारपत्र में चण्डीगढ़ का एक समाचार इस बारे में बड़ा शिक्षाप्रद है। उसमें कहा गया है :

१ पंजाब वित्त निगम को अपने ९ वर्ष के अस्तित्व में पहली बार निजी शेयरहोल्डरों के क्रोध का सामना करना पड़ा।

२ वे निगम की वार्षिक बैठक में भारी संख्या में इकट्ठे हुए और मांग की कि सरकार उनके शेयरों को खरीद ले। उन्होंने यह भी बताया कि उनके शेयर न केवल लाभहीन ही हैं, बल्कि बाजार में उनका कोई खरीद-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दार भी नहीं है।

३ शेयरहोल्डरों का असन्तोष एक मत होकर जाहिर किया गया और एक साधारण बैठक में कड़आपन पैदा हो गया।

राजकीय उद्योगों के उपभोक्ताओं की स्थिति, खासकर जब पदार्थ या सेवाएं एकाधिकारी होती हैं, बड़ी अजीब सी हो जाती हैं। अखबारों में ऐसे दर्जनों पत्र छपते हैं जो राजकीय उद्योगों की आलोचना करते हैं। राजकीय अधिकारों की अकार्यक्षम कार्रवाई के जरिये नागरिकों को होने वाली परेशानी के अलावा एक खतरनाक पहलू और भी है। इस खतरनाक पहलू का उल्लेख सितम्बर १९६२ में मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय में किया गया है। एक दावे पर विचार करने और कर्जदारों को करीब तीन साल तक लटकाये रख कर, जब तक कि सीमित अवधि खत्म हो गई और बाद में बीमा निगम ने सूचित किया कि उनका दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट के जजों ने भारत जीवन बीमा निगम को कड़ी फटकार दी। बुद्धिमान जजों ने कहा कि मैनेजर का उचित स्थान ही बागों में है, जिससे कि वह अधिक और अच्छी चाय पैदा कर सके।

प्रशासन की लम्बी प्रक्रिया

अर्थव्यवस्था के बाहरी ढांचे में ईमानदार और कार्यक्षम प्रशासन तंत्र के महत्व को भी कम नहीं आंका जा सकता है। कानूनों तथा नियंत्रणों की बहुलता तथा अकार्यक्षम प्रशासन ने हमारे आर्थिक विकास में बाधा पहुँचाई है। इस समस्या की विशालता का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ३१ जुलाई, १९६२ को महाराष्ट्र सरकार सचिवालय में २९,४२० मामले ६ वर्षों से भी ज्यादा समय से निपटारे के लिए बकाया थे। इसी तरह ३१ अगस्त, १९६२ को केरल सरकार में ४७,८५९ फाइलें निर्णय के लिए बकाया थीं। आंध्रप्रदेश में आदेश जारी किये जाने के पहले एक फाइल को १४० प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। मैसूर राज्य में एक फाइल की प्रक्रिया में औसतन २७२.२ दिन लगते हैं। इस प्रकार की देरी की पराकाष्ठा इस बात में है कि मामलों पर पेश किये गये सेक्रेटरिएट के २५ प्रतिशत प्रस्ताव सरकार द्वारा नामंजूर कर दिये जाते हैं। इस तरह से "यह मालूम पड़ता है कि यदि सेक्रेटरिएट की जांच प्रभावहीन नहीं, फिर भी काफी हद तक वह बेकार होती है।" (ओरगेनीजेशन एण्ड मेथड स्टडी रिपोर्ट से)

सितम्बर १९६२ की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि ओखला इण्डस्ट्रियल इस्टेट के लिए आयात की गई कई लाख रुपये की मशीनरी लाल फीतेशाही की वजह से बेकार पड़ी हुई है। इस बड़ी लापरवाही के लिए दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अण्डरटेकिंग, सेन्ट्रल पी० डबल्यू० डी०, नेशनल स्माल-स्केल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन और दिल्ली प्रशासन एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे थे। स्वयं प्रधानमंत्री तक ने लालफीतेशाही और बर्बादी पर भारी असंतोष व्यक्त किया है। नवम्बर १९६१ में नई दिल्ली में आयोजित भारतीय मेडीकल काउन्सिल के सम्मेलन में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि "इतने बेशुमार खर्चे" से बनाई जाने वाली इमारतों के बर्बादीपूर्ण तरीके से मुझे बड़ा भय लगता है। ऐसे प्रशासन तंत्र और पद्धतियों में फेर बदल कभी का हो जाना चाहिए था। इस दिशा में पहला कदम यह होना चाहिए कि प्रशासन को, अनावश्यक औद्योगिक और व्यापारिक प्रवृत्ति से मुक्त कर देना चाहिए।

अर्थव्यवस्था के "बाहरी ढांचे" का और एक महत्वपूर्ण और भाग है संचार-व्यवस्था, जिसकी ओरभारी दुर्लक्ष्य किया गया है। मार्च १९६२ में यह देखा गया कि एक लाख से भी ज्यादा तार जिन्हें सामान्य रूप से मोर्स या टेलीप्रिन्टर के जरिये भेजना चाहिए था, डाक के जरिये भेजे गए। इसी प्रकार डाक सेवाओं की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है। नवम्बर १९६२ के एक अखबारी बयान में बताया गया कि बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के ६०० डाकघरों में से अधिकांश डाकघरों ने रजिस्ट्री और मनिआर्डर भेजने का काम बन्द कर दिया है, क्योंकि उनके फार्म नहीं मिलते हैं।

उपाय

राज्य के महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक कर्तव्य है देश के लिए एक स्थायी मुद्रा की व्यवस्था करना। प्रोफेसर बी० आर० शेनाय ने, जिन्होंने घाटे की अर्थ-व्यवस्था के खतरों से हमारे नियोजकों को चेतावनी दी है, बड़े सही तरीके से स्थिति पर प्रकाश डाला है। उन्होंने १९५४-५५ और

(शेष पृष्ठ १५२ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र

श्री श्रीमन्नारायण

सार्वजनिक क्षेत्र को केवल उत्पादन ही नहीं बढ़ाना है, बल्कि सामान्य जनता एवं श्रमजीवी वर्गों के जोश तथा उनकी प्रच्छन्न क्षमताओं को भी प्रकाश में लाना है। इस सम्बन्ध में प्रो० डार्विन का कहना है कि समाजवादी आर्थिक व्यवस्था में निजी लाभ का स्थान सामाजिक हित को ले लेना चाहिए और साथ ही 'प्रत्येक व्यक्ति की अनन्त उत्पादन-क्षमता को, सार्वजनिक हित को दृष्टि में रखते हुए, बौद्धिक तथा नैतिक स्तर पर प्रोत्साहित करना चाहिए।' (प्राबलम्स आफ इकानामिक प्लानिंग, पृ० ६५)। प्रो० गुनार मिर्डल ने भी इस बात पर जोर दिया है कि द्रुत आर्थिक विकास के लिए अनुकूल 'मनोवैज्ञानिक तथा सैद्धान्तिक' वातावरण उत्पन्न किया जाए। (इकानामिक थ्योरी एण्ड अण्डर-डेवैलप्ड रीजन्ज, पृ० ८१)। भारत में पंचायती राज के शुरू होते ही सार्वजनिक क्षेत्र, केन्द्रीय तथा राज्यीय औद्योगिक उद्यमों के साथ-साथ ग्राम पंचायतों के संचालन तथा देख-रेख में विकसित होने वाले ग्रामोद्योगों की ओर भी धीरे २ ध्यान देगा। इस प्रकार के ग्रामोद्योगों को स्थापित करके ही हम थोड़े-से लोगों का नहीं, बल्कि अपने समूचे देश की जनता में नए से रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शक्ति और उत्साह का संचार कर सकते हैं। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्योगों को अधिक जिम्मेदारियां सौंपने के लिए अभी हाल ही में जो फैसले किए हैं, उनका उद्देश्य यही है कि अनेक प्रकार से उनकी उत्पादन-क्षमता को बढ़ाया जा सके। इन सार्वजनिक उद्यमों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अतिरिक्त उत्पादन को राष्ट्र के अन्य विकास-कार्यों में लगाएं। सार्वजनिक उद्योगों में 'न हानि, न लाभ' का सिद्धान्त अब पुराना पड़ गया है।

कार्यदक्षता और कार्यनिष्ठा

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में वाणिज्य, सदाचार तथा ईमानदारी की दृष्टि से सुदृढ़ परम्परा स्थापित होनी चाहिए। जैसा कि फर्डीनांड ज्वीग ने कहा है कि कोई संगठन बहुत अच्छा और लाभप्रद होते हुए भी राष्ट्र की नैतिक आवश्यकताओं की दृष्टि से 'नितान्त असफल' सिद्ध हो सकता है। (इकनामिक आइडियाज, पृ० १५४)। कोई भी समाजवादी समाज, भ्रष्टाचार तथा ईमानदारी से रहित प्रबन्ध के बिना, विशेष रूप से उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में, केवल हल्ला-गुल्ला होकर रह जाता है।

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यविस्तार के सम्बन्ध में कुछ लोगों ने भ्रामक धारणा बना ली है। सम्भवतः उन्होंने इस बात पर पूरी तरह विचार नहीं किया कि तीसरी योजना के कहीं अन्त में जाकर संगठित उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र का अंशदान कुल विनियोग का केवल २५ प्रतिशत ही होगा, और शेष ७५ प्रतिशत फिर भी निजी क्षेत्र के ही पास रह जाएगा। तीनों योजनाओं की अवधि में खनिज उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की पूंजी का विनियोग, जो आरम्भ में १० प्रतिशत से भी कम था, बढ़कर लगभग ३३ प्रतिशत हो जाएगा। भारत में अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विनियोजित कुल धन-राशि की तुलना में, निजी क्षेत्र के विनियोग का अनुपात, पहली योजना में ४६ प्रतिशत से बढ़कर दूसरी योजना में ५४ प्रतिशत तक पहुँच गया है। अनुमान है कि तीसरी योजना में यह अनुपात ६० प्रतिशत और चौथी तथा बाद की योजनाओं में इससे भी अधिक हो जाएगा। जो भी हो, राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में, विशेषकर उपभोक्ता उद्योगों में, निजी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान बना रहेगा। लेकिन, फिर भी, इसे राष्ट्र की बदलती हुई नवीन परिस्थितियों के अनुरूप अपने आपको ढालने के लिए स्वेच्छापूर्वक तत्पर रहना चाहिए और प्रो० मोरिस डोब के शब्दों में निजी क्षेत्र को 'उद्यमकर्ता के काल्पनिक पुनीत लोक' में विचरण नहीं करते रहना चाहिए। (आन इकानामिक थ्योरी एण्ड सोशलिज्म, मोरिस डोब, अध्याय—१)।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष में
खुलकर दान दीजिये

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

औद्योगिक अभ्युत्थान में बिड़ला बन्धुओं का योगदान

श्री रामप्रसाद पोद्दार

लगभग १।। लाख व्यक्तियों को रोजगार देने वाले एक दर्जन बिडला उद्योग, जिनमें ८ प्रतिष्ठान देश के प्रथम ५१ उद्योगों में प्रमुख हैं, जिस कर्मठ, दूरदर्शी और प्रतिभाशाली व्यक्ति की एकनिष्ठा के परिणाम हैं, उसने लगभग आधी सदी पहले एक सामान्य सूती मिल के निर्माण के साथ इस क्षेत्र में प्रवेश किया था। श्री घनश्यामदास बिड़ला ने ही कुछ उद्योगपतियों के साथ सबसे पहले राष्ट्रीय विकास की आर्थिक योजना बनाई और देश का ध्यान आयोजित व्यवस्था की ओर केन्द्रित किया। उनकी महत्वाकांक्षा विश्व के उन्नत औद्योगिक देशों की पंक्ति में भारत को भी खड़ा कर देने और उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने की है।

स्वतंत्रता के पश्चात् हमारे देश में जो सर्वोन्मुखी औद्योगिक उन्नति हुई है, वह वास्तव में देश के कर्णधारों की सूझबूझ एवं दूरदर्शिता का परिणाम है। किसी भी अविकसित अथवा अर्धविकसित देश के उत्थान के लिए विकास योजनाओं का सहारा लेना अत्यन्त आवश्यक एवं हितकर होता है। ऐसा करने से एक ओर जनता का सहयोग प्राप्त होता है और दूसरी ओर देश की प्रगति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। कहना न होगा कि भारत के लिए प्रथम योजना प्रस्तुत करने का श्रेय श्री घनश्यामदासजी बिड़ला को है, जिन्होंने कतिपय अन्य उद्योगपतियों के सहयोग से एक योजना तैयार की थी, जो आगे चल कर 'बाम्बे प्लान' के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके पश्चात् कितनी ही अन्य योजनाएं सामने आयीं, जिनके परिणामस्वरूप देश में 'योजना-आयोग' की स्थापना हुई।

श्री घनश्यामदास बिड़ला

गौरवपूर्ण कहानी

अब तक हम दो पंचवर्षीय योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर चुके हैं और तृतीय योजना में हमने पदार्पण किया है। प्रथम दो योजनाओं के फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े जो १९५०-५१ में १०० थे, वह १९६०-६१ में दुगुने हो गये और तृतीय योजना की समाप्ति तक अर्थात् १९६५-६६ तक इनके सवा तीन गुने से भी अधिक हो जाने की सम्भावना है। इसकी सफलता के साथ-साथ देश को एक नई चेतना, एक नई प्रेरणा और एक नया विश्वास प्राप्त होगा।

प्रथम महायुद्ध के पहले ही कतिपय उद्योग हमारे देश में अपनी जड़ जमा चुके थे, जैसे, कपड़े तथा जूट के कारखाने इत्यादि। सन् १९२२ से अन्य विभिन्न प्रकार के उद्योगों ने जैसे स्टील, कागज, चीनी, सीमेण्ट आदि ने पनपना शुरु किया और सन् १९३६ तक चीनी एवं सीमेण्ट में देश लगभग आत्मनिर्भरता तक पहुँच गया। इन वर्षों में वनस्पति एवं इंजीनियरिंग उद्योगों में भी काफी उत्पादन बढ़ा। दूसरे महायुद्ध तक अल्यूमिनियम, डिजेल एंजिन, पम्प, बाइसिकल, सोडा एश, कास्टिक सोडा इत्यादि उद्योगों का श्रीगणेश हुआ और युद्धोत्तर वर्षों में रेयन, मोटर, कपड़ा मिल की मशीनें तथा एंजिन इत्यादि बनाने के कारखाने स्थापित हुए और अन्य कारखानों के उत्पादन में विशेष वृद्धि हुई।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस प्रकार गत अर्ध शताब्दि देश के औद्योगीकरण की एक लम्बी किन्तु गौरवपूर्ण कहानी है । स्वतंत्रता के बाद देश की आर्थिक स्थिति को अधिकाधिक सहारा मिला और बढ़ती हुई देश की प्रगति में राजनैतिक नेताओं, उद्योगपतियों, व्यापारियों एवं जनसाधारण, सबने मिल कर अपना पूर्ण सहयोग दिया ।

देश में उत्थान के बढ़ते चरण को बिड़ला प्रतिष्ठान ने विशेष बल दिया और पूंजी विकास, धन विनियोग, औद्योगिक उत्पादन, रोजगार एवं राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति में उन्होंने अपूर्व सहयोग देकर देश के औद्योगिक विकास को एक नई दिशा प्रदान की ।

सन् १९१६ में सूत की एक मिल से प्रारम्भ हुए बिड़ला औद्योगिक प्रतिष्ठान ने गत अर्धशताब्दि में अभूतपूर्व प्रगति की है, जो बिड़ला बन्धुओं के अदम्य उत्साह एवं अथक परिश्रम, दूरदर्शिता एवं जनकल्याण की राष्ट्रीय भावनाओं की द्योतक है ।

टेक्सटाइल में सूती तथा ऊनी कपड़े की मिलों के अतिरिक्त विस्कोज एवं एसीटेट की रेयन मिलें तथा रेयन का सूत बनाने की मिलें सम्मिलित हैं । जूट की मिलों का अपना निजी स्थान है । इन्जीनियरिंग उद्योगों में मोटर, साइकिल, बिजली के पंखे बनाने के कारखाने, बायलर एवं बाल बियरिंग तथा रेलवे वैगन बनाने के कारखाने विशेष उल्लेखनीय हैं । चीनी, वनस्पति, रसायन, कागज, रेडियो, प्लास्टिक का सामान इत्यादि प्रतिदिन काम में आने वाली चीजों के कारखाने भी बराबर जनसाधारण की सेवा कर रहे हैं । कुछ समय पूर्व जहाजरानी का कार्य भी चालू किया गया । गत कुछ वर्षों में जो दो महत्वपूर्ण कारखाने स्थापित किये गये वे हैं, उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम और केरल में रेयन का पल्प बनाने के कारखाने ।

दिसम्बर १९६१ की समाप्ति पर बिड़ला उद्योग प्रतिष्ठानों की स्थिति इस प्रकार थी—

उद्योग	ब्लाक (लाख रुपयों में)	बिक्री (लाख रुपयों में)	रोजगार
अ—टेक्स्टाईल			
काटन एवं फलेक्स	२१८२.६६	४७३७.००	५५,७००
सिंथेटिक	३६०५.०७	२८६१.००	१३,२००
जूट	९९४.८६	१००४.००	११,३
ऊन	७४.६०	१४०.००	१,२
योग	६५५७.१९	८७४२.००	८१,४
आ—कागज	१७८५.००	१४००.००	७,२
इ—इंजीनियरिंग	२५३१.८२	५६२७.००	२८,५
ई—रसायन, सीमेंट एवं वनस्पति	११४३.५९	१६९०.००	८,४
उ—बागान	२७६.१८	३६९.००	७,९
ऊ—चीनी	७२३.१२	१५८९.००	६,३
ए—धातु	१४९६.३३	१५४.००	२,२
ऐ—कोयला	१९४.५०	१७२.००	५,०
ओ—विविध	२७३.१५	३३६.००	२,८
पूर्ण योग	१४९,८०.८८	२००,७९.००	१४९,८

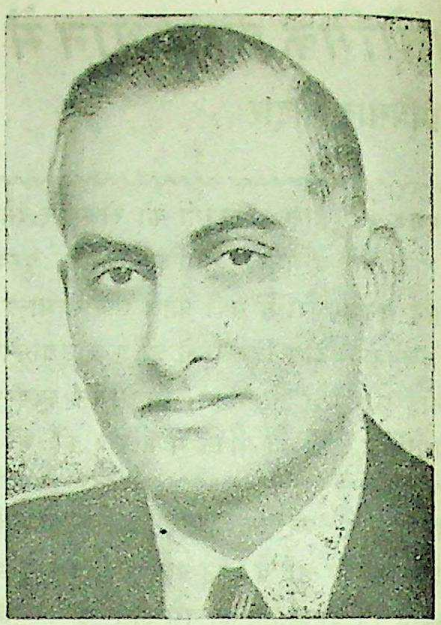

श्री ब्रजमोहन बिड़ला

"इकोनोमिक टाइम्स" के अनुसार १९६१-६२ प्रथम इक्यावन बड़ी २ कम्पनियों के अन्तर्गत जिन बिड़ला प्रतिष्ठानों का स्थान है, वे इस प्रकार हैं—

१ हिन्दुस्तान मोटर्स
२ ग्वालियर रेयन
३ केशोराम काटन मिल्स
४ टेक्समेको

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

५ सेंचुरी स्पि० एंड मेन्यु० कं० लि०

६ जियाजीराव काटन मिल्स

७ ओरियंट पेपर मिल्स

८ बिड़ला जूट मिल्स

इस प्रकार बिड़ला बन्धुओं ने देश के औद्योगिक उत्थान में एक विशेष भाग लेकर देश को समुन्नत एवं सम्पन्न बनाने में महान योग दिया है। उपभोक्ताओं की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने देश के उत्पादन में वृद्धि की तथा उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिये नई-नई वस्तुओं के निर्माण करने के कारखाने लगाये।

दो उपाय

श्री घनश्यामदासजी बिड़ला के अनुसार हमारे देश की गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने के लिये जिन दो उपायों की आवश्यकता है वे हैं, आधुनिक तरीके और उनका उपयोग करने का ज्ञान। बिड़ला प्रतिष्ठान राष्ट्र को समुन्नत करने के लिए दोनों ही में अपना योगदान दे रहा है। उपभोक्ता के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री पैदा करने के अतिरिक्त बिड़ला प्रतिष्ठान मशीनें तथा पूंजीगत माल भी तैयार करता है, जिनकी देश को आत्मनिर्भरता के लिए तथा त्वरित उद्योगीकरण के लिये अत्यन्त आवश्यकता है। बिड़ला प्रतिष्ठान देश के युवकों में से एक सुदृढ़ एवं उन्नतिशील कुशल प्रबन्धकर्त्ता वर्ग भी तैयार कर रहा है, जिन्हें नवीन भारत के उत्तरदायित्व को सम्भालने का अवसर एवं सौभाग्य प्राप्त होगा।❀

इस प्रकार बिड़ला प्रतिष्ठान का उद्देश्य न केवल पूंजी विकास करने का ही है किन्तु उसे निर्माणात्मक कार्यों में लगाने तथा जनता में ज्ञान एवं खुशहाली, स्वास्थ्य एवं रोजगार की वृद्धि में लगाने का भी है। ●●

❀ देश के आर्थिक विकास में सहायक यूनाइटिड कमर्शल बैंक और हिन्दुस्तान टाइम्स, हिन्दुस्तान आदि अनेक प्रतिशित पत्रों के संचालन का श्रेय भी बिड़ला बन्धुओं को है। इस लेख में केवल उद्योगों की ही चर्चा तक लेखक ने अपने को सीमित रखा है। —सम्पादक

अत्यन्त शुभकामनाओं के साथ

दि न्यू ग्रेट ईस्टर्न स्पि. एंड वीविंग कम्पनी लिमिटेड

१५ ए, हार्निमन सरकल

फोर्ट बम्बई-१

निर्माता

सूती कपड़े और सूती तथा स्टेपल फाइबर सूत के रँगीन और ब्लीच किये कपड़े, लांग क्लाथ माजरी, शीटिंग, रँगीन पापलिन, रंगीन इटालियन, ब्लीच्ड मरसिराइज्ड लेनो :

तार का पता—"न्यूग्रेट" टेलि. नं. २५१२१८

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नये वर्ष का रेलवे बजट

१९ फरवरी को संसद में १९६३-६४ का जो रेलवे बजट पेश किया गया, उसमें कुछ विशेषताएं हैं। आम जनता की दृष्टि से उसका एक बड़ा राहत का पहलू यह है कि रेल-भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की गयी। इस वर्ष शुद्ध बचत का अनुमान ३१ करोड़ रु० है और आम राजस्व को रेलवे की ओर से प्रति वर्ष दिये जाने वाले लाभांश में इस वर्ष वृद्धि की जाएगी। १९ करोड़ रु० की अतिरिक्त आय की व्यवस्था इस बजट में की गयी है जो माल और पार्सल के भाड़ों में कुछ वृद्धि करने से प्राप्त होगा। औसतन माल लगभग ६०० किलोमीटर दूर भेजा जाता है। इतनी दूरी के भाड़े में की गयी वृद्धि के हिसाब से नमक के एक किलोग्राम पर मुश्किल से १/८ नया पैसा, एक किलोग्राम चीनी पर १/४ नये पैसे से कुछ कम और एक किलोग्राम अनाज पर लगभग १/१० नया पैसा अतिरिक्त भाड़ा बढ़ेगा। इससे कम भाड़े की वस्तुओं पर औसतन इससे भी कम भाड़ा बढ़ेगा। माल पर भाड़े में यह वृद्धि सरचार्ज की दर ५ प्रतिशत बढ़ाकर की जा रही है। सब्जी, दूध और समाचारपत्रों पर यह सरचार्ज नहीं लगेगा।

पार्सलों के किराये में जो वृद्धि होगी, वह ६०० किलोमीटर की दूरी के लिए प्रति किलोग्राम पर २ नये पैसे से कुछ कम ही होगी। जो जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं और पार्सल दर से कम भाड़े वाली चीजें हैं, उन पर यह वृद्धि और भी कम होगी।

इस प्रकार अनुमान है, माल भाड़े से अतिरिक्त आय

रेलवे बजट एक नजर में

(करोड़ रु० में)

	वास्तविक	बजट	सन्शोधित अनुमान	बजट अनुमान
	१९६१-६२	१९६२-६३	१९६२-६३	१९६३-६४
यातायात से कुल प्राप्ति	५००.५०	५४५.३६	५४९.६२	५९९.६९
संचालन-व्यय	३२५.५१	३५६.६४	३६३.२८	३७९.१८
शुद्ध-विविध व्यय जिसमें राजस्व खाते में दिखाए गए कार्यों का व्यय शामिल है	१०.२४	१६.३५	१४.९१	१६.४०
मूल्य ह्रास आरक्षित निधि के लिए विनिमय	६५.००	६७.००	६७.००	८०.००
कुल जोड़	४००.७५	४४०.२९	४४५.१९	४७५.५८
शुद्ध रेलवे राजस्व	९९.७५	१०५.०७	१०४.४३	१२४.११
सामान्य राजस्व को भुगतान और १९६२-६३ (क) १९६१-६२ के लिए लाभांश ४.२५ प्र. श. की दर से और १९६३-६४ के लिए ४.५० प्र. श. की दर से	९२.८५	६९.३५	६८.७३	८०.६१❀
(ख) यात्री भाड़े पर लगे कर के लिए भुगतान	१२.५०	१२.५०	१२.५०	१२.५०
कुल बचत	२४.४०	२३.२२	२३.२०	३१.००

❀ इस राशि में मूल्य ह्रास आरक्षित निधि के लिए दी जाने वाली १० करोड़ रु० की अतिरिक्त रकम और १९६३-६४ के प्रस्तावों के अनुसार सामान्य राजस्व को दिए जाने वाले लाभांश की ४.०५ करोड़ रु० की अतिरिक्त रकम शामिल है।

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१७ करोड़ रु० और पार्सल-किराये से २ करोड़ रु० अतिरिक्त आय होगी। १९६३-६४ में इस वृद्धि को कार्यान्वित करने के बाद रेलवे की कुल आय ५ अरब ९९ करोड़ ६९ लाख रु० का अनुमान है।

केन्द्रीय राजस्व में रेलवे विभाग की ओर से दिये जाने वाले लाभांश में वृद्धि ४.२५ प्रतिशत से बढ़ाकर ४.५० प्रतिशत कर दी गयी है।

ढुलाई की क्षमता में वृद्धि

पिछले वर्ष इस बात की बड़ी शिकायत थी कि रेलवे की ढुलाई की व्यवस्था काफी दोषपूर्ण थी, जिससे कोयले का संकट पैदा हो गया था। इस वर्ष के बजट में इस कमी को दूर करने का प्रयत्न करते हुए ढुलाई की क्षमता १ करोड़ ७० लाख टन अधिक बढ़ायी जाएगी।

रेलवे-संचालन पर अधिक व्यय

रेल गाड़ियों के साधारण संचालन में ३ अरब ७९ करोड़ १८ लाख रु० के व्यय का अनुमान है जो १९६२-६३ के संशोधित अनुमान से १५ करोड़ ९० लाख रु० अधिक है। इसका एक बड़ा कारण वर्तमान संकट के कारण कोयले का पर्याप्त भंडार रखना, रेल-लाइनों की सुरक्षा और अधिक प्रबन्ध करना इत्यादि खर्च बढ़ गये हैं। मूल्य ह्रास निधि में ८० करोड़ रु० दिया जाएगा। १९६० की अपेक्षा इस वर्ष यह रकम १० करोड़ रु० अधिक है क्योंकि वर्षों पहले खरीदे गये इंजन तथा अन्य रेल-सामग्री का बदलना जरूरी हो गया है। फिर, रेलवे के सामान का नया नवीकरण आवश्यक है।

रेलवे-मुसाफिरों के किराये से जो आय होती है, उसके सम्बन्ध में स्थिति का अनुमान यह है कि १९६२-६३ की अपेक्षा इस वर्ष ५ करोड़ २५ लाख रु० अधिक प्राप्त होगा क्योंकि सवारी-यातायात में १ प्रतिशत बढ़ोतरी की आशा है। १ जुलाई १९६२ को यात्री-भाड़े में संशोधन किया गया था।

३१ करोड़ रु० की बचत का विनियोग

३१ करोड़ रु० की शुद्ध बचत का इस वर्ष अनुमान है। इसका विनियोग किस प्रकार होगा—इस पर प्रकाश डालते हुए बजट में कहा गया है कि पिछले वर्षों की तरह यह रकम विकास निधि में दे दी जाएगी। इस निधि से १९६३-६४ में २६ करोड़ रु० खर्च करने का अनुमान है जिसके फलस्वरूप वर्ष के अन्त में इस कोष में केवल ५ करोड़ रु० बचेगा। यह बचत अधिक नहीं है, फिर भी इससे निधि में वृद्धि तो होगी। इस निधि से कर्मचारियों के हित कार्यों, रेलवे-उपभोक्ताओं की सुविधाओं और सुरक्षा प्रबन्धों पर अधिक खर्च किये जाने की आशा है।

तीसरी योजना में रेलवे-विकास-कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए ३ अरब २५ करोड़ रु० की राशि रखी गयी है। १९५६-५७ की अपेक्षा इस समय कर्मचारियों पर औसतन प्रति कर्मचारी ३० प्रतिशत से भी अधिक खर्च बढ़ गया है।

असम में रेल-व्यवस्था

चीनी आक्रमण के कारण उत्तर-पूर्व सीमान्त रेलवे का महत्व बढ़ गया है और सामान्य की अपेक्षा अब इस लाइन पर ६५ प्रतिशत यातायात बढ़ गया है।

उत्तर-पूर्व सीमान्त रेल लाइन की क्षमता काफी बढ़ा दी गयी है, और इसका अलग प्रशासन बना दिया गया है जिसका मुख्य केन्द्र असम में ही है। कलकत्ता से सिलिगुड़ी तक १९१ किलोमीटर की नयी बड़ी लाइन बिछायी गयी और ८० किलोमीटर की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदला गया, १७३ किलोमीटर छोटी लाइन बढ़ायी गयी तथा १६१ किलोमीटर लम्बी और लाइन बिछायी जा रही है। सिलिगुड़ी के पास एक यार्ड बनाया गया है जिससे बड़ी और छोटी—दोनों लाइनों को संभाला जा सके।

ब्रह्मपुत्र पर पुल

असम की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र पर रेल और सड़क का पुल इस वर्ष की उल्लेखनीय घटना है। देश की बड़ी नदियों में यही एक नदी ऐसी थी जिस पर कोई पुल अभी तक न बना था। इसके बन जाने से उत्तर बंगाल और असम के बीच यातायात में सुविधा हो गयी है।

१९६१-६२ में ५२८ किलो मीटर पर बिजली की रेलें चलायी गयी थीं, १९६३-६४ में ३२९ किलोमीटर पर बिजली की रेलें चलेंगी। अब भारत में कुल १,२१८ किलोमीटर पर बिजली की रेलें चलने लगी हैं।

नयी लाइनें

बजट में यह दावा किया गया है कि डीजल इंजन

(शेष पृष्ठ १५० पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विभिन्न राज्यों के बजट—१९६३-६४

मार्च मास में भारत के विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं में १९६३-६४ के आनुमानिक बजट पेश हुए। अभी तक जिन राज्यों के बजट प्रकाशित हो चुके हैं: उनके संक्षिप्त विवरण यहां दिये जाते हैं :—

नाम राज्य	राशि करोड़ रु० में

महाराष्ट्र

राजस्व आय	१५९.७१
व्यय	१६०.४७

नया कर लगाने से ९५ लाख की आय जिससे आनुमानित ९१ लाख रु० घाटा ४ लाख की छोटी बचत में परिणित हो जाएगा।

पश्चिमी बंगाल

राजस्व आय	११७.०६
व्यय	१०९.७९

३.५ करोड़ रु० के कर से अतिरिक्त आय। बचत ७.२७ करोड़ रु०।

आन्ध्रप्रदेश

राजस्व आय	११८.३६
व्यय	११८.२६

६ करोड़ रु० के कर लगाने के लिए शीघ्र ही एक विधेयक पेश किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश

राजस्व आय	२०१.८२
व्यय	२०६.७९

४.९७ करोड़ रु० का घाटा नये करों से पूरा किया जाएगा।

बिहार

राजस्व आय	—८७.८० करोड़ रु०
व्यय	—८५.५० करोड़ रु०
बचत	—००.५० करोड़ रु०
योजना पर व्यय	—५०.५० करोड़ रु०

केन्द्र से अंश अनुदान व ऋण

राज्यों की वित्तीय स्थिति को समझने के लिए यह जान लेना भी जरूरी है कि विभिन्न मदों में केन्द्र से राज्यों को कितने अनुदान या ऋण आदि मिलते हैं। उत्पादन-शुल्कों में से एक भाग राज्यों को पहले से मिलता था। जब से चीनी, वस्त्र आदि के विक्रीकर उत्पादन-शुल्क के रूप में लिये जाने लगे, राज्यों का इस कर में भाग और भी बढ़ गया। रेल भाड़े पर अधि-भार में भी राज्यों को पहले कुछ अतिरिक्त मिलता था, अब वह अनुदान में शामिल कर लिया गया है। मृत सम्पत्ति शुल्क में से भी राज्य कुछ भाग लेते हैं। आय कर में से तो राज्यों को एक बड़ा भाग बहुत पहले से मिलता रहा है। देखिये—

(लाख रु० में)

	विभाजनीय करों से कुल आय	राज्यों को
१९६२-६३ (संशोधित)	११५४१७	२२४०६
१९६३-६४ (बजट)	११८८७५	२२९९०

वैधानिक प्रावधान के अनुसार भी (अनुच्छेद २७३, २७५ (क) २७८) राज्यों को केन्द्र कुछ अनुदान दिया करता है। पुलिस और वैज्ञानिक शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, सहकारिता और उद्योग, सामुदायिक विकास आदि विविध विभागों के लिए भी केन्द्र राज्यों को अनुदान देता है।

राज्यों को अनुदान

१९६२-६३ संशोधित	२०८६१ लाख रु०
१९६३-६४ बजट	८११४१ ,,

केन्द्रीय सड़क निधि से १९६२-६३ में ३७० लाख और १९६३-६४ के बजट में १७५ लाख रु० राज्यों को देने की व्यवस्था है।

पूंजी से दिये गये उपर्युक्त दोनों वर्षों में २२९३ और २४५८ लाख रु० अनुदान की व्यवस्था है।

विभिन्न औद्योगिक प्रयोजनाओं, आवास योजना, सामुदायिक विकास योजनाओं, हथकरघा-उद्योग, बांध नियंत्रण आदि कार्यों के लिए केन्द्र १९६३-६४ के बजट के अनुसार ५४१.०८ करोड़ रु० राज्यों को ऋण देगा।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मद्रास

	करोड़ रु०
राजस्व आय	१२४.४५
व्यय	१२७.१९
घाटा	२.७४

नया कर कोई नहीं लगाया। केन्द्रीय बिक्री कर में राज्य के अंश और बिक्री कर की दरों को व्यवस्थित करने से घाटे की पूर्ति का संकेत दिया गया है।

उड़ीसा

राजस्व आय	६७.४०
व्यय	६७.१५

बचत ४५ लाख। ऐशो आराम पर बिक्री कर ७ से बढ़ाकर १० प्रतिशत, सड़क और पुलों पर कर, मोटर-वाहन, सिंचाई, बिजली और रजिस्ट्री दरों में वृद्धि।

मैसूर

राजस्व आय	९९.१२
व्यय	९९.५२

घाटा ४० लाख रु०। नया कर कोई नहीं पर बिक्री कर, सिंचाई कर और खुशहाली शुल्क—को पुनः व्यस्थित किये जाने का संकेत है।

पंजाब

राजस्व आय	९५.११
व्यय	१०५.३५

घाटा १०.२४ करोड़ रु०। कुछ नये करों द्वारा घाटे की पूर्ति की जाएगी।

राजस्थान

राजस्व आय	६३.१६
व्यय	६६.१४

घाटा ४॥ करोड़ रु०। नये कर—स्टाम्प ड्यूटी, मोटर गाड़ियों और मोटर बसों पर और सिनेमा के विज्ञापनों पर।

गुजरात

	करोड़ रु०
राजस्व आय	८०.३९
व्यय	७९.०६
बचत	१.३३

पंचायती राज के जारी होने पर यह बचत ९० लाख रु० के घाटे में परिणित हो जाएगी। अन्य अप्रत्याशित कारणों से भी कुल घाटा २.४० करोड़ रु० होगा। कुल घाटा ५.२९ करोड़ रु० पूरा करने के लिए ४.०५ करोड़ रु० के कर लगाये गये हैं।

काश्मीर

राजस्व आय	३,४२१.१२ लाख रु०
व्यय	३,६९८.८४ लाख रु०
घाटा	१३२.२९ लाख रु०

एक करोड़ रु० के नये कर जिनमें कुछ नये मुसाफिर-कर, बिक्री कर का विस्तार और उसमें वृद्धि, बिजली पर शुल्क इत्यादि शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश

राजस्व आय	१,७०,९१,००० लाख रु०
व्यय	२,८६,७०,१०० रु०
घाटा	२,९९,६१,००० रु०

केन्द्र की ओर से प्राप्त अनुदान के द्वारा घाटे की पूर्ति की जाएगी।

केरल

राजस्व आय	७१.६७ करोड़ रु०
व्यय	७०.८७ करोड़ रु०
बचत	८० लाख रु०
अतिरिक्त कर	४ करोड़ रु०

दिल्ली

केन्द्रीय सरकार के १९६३-६४ के बजट में दिल्ली के लिए १८.३७ करोड़ रु० के राजस्व व्यय की और ७.३८ करोड़ रु० के पूंजीगत व्यय की व्यवस्था की गयी है।

असम

	आय करोड़ रु०
राजस्व आय	५१,२५,६०,०००
व्यय	५०,९६,६१,०००

बचत २८.९९ लाख रु० है पर इस वर्ष के लिए बजट का आरंभ ४,३७,८५,००० रु० के घाटे के साथ हुआ है, इसलिए राज्य का घाटे का बचत है। ६ नये कर प्रस्तावों से १७४ लाख रु० की अतिरिक्त आय होगी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

टैक्सटाइल मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड

बेलघरिया, पश्चिम बंगाल

: निर्माता :

१—वाटर ट्यूब बायलर —कम्बस्टन इंजिनीयरिंग कार्पोरेशन (यू. एस. ए.) के सहयोग से, जिसने संसार में विशाल स्टीम का उत्पादन किया है।

२—लंकाशायर बायलर ३० फीट × ८ फीट, २२० पौंड तक (चाप)

३—विभिन्न आकारों के वर्टिकल बायलर १३ फीट × ५ फीट के माप तक

४—सम्पूर्ण शूगर प्लांट —स्टार्क आफ हालैंड के सहयोग से

५—सभी प्रकार के फायर बाक्स और सायफन

६—रेलवे वेगन —प्रत्येक प्रकार के बाक्स सी. आर., सी. एम. आर, एम. बी. टी. पी. एक्स और एम. बी. टी. जैड।

अत्यधिक आधुनिक मशीनों तथा स्वचालित फाउन्ड्रियों से सुसज्जित

*

मैनेजिंग एजेन्ट्स

बिरला ब्रादर्स (प्राइवेट) लिमिटेड

१३, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता-१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हमारे सर्वोदयी वित्तमंत्री

अरबों रु. का बजट बनाने, सम्पन्न और सामान्य जनता से अरबों रु. कर वसूल करने वाला और देश की आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण व्यक्ति भारत का वित्तमंत्री कितना सर्वोदयी और संयमशील है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। उनके जीवन की एक झांकी श्री धर्मचन्द सरावगी के निम्न संदर्भ से मिलती है—

मोरारजी भाई अपने शयनकक्ष में थे। चरखा कात रहे थे। प्लास्टिक का सुन्दर चरखा, जिसमें सूत भी मेरे अन्दाज से ३० नम्बर का निकल रहा था। मैंने पूछा कि महीने में आप कितनी गुंडियां कात लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं नित्य सुबह १ घंटा और रात्रि को १ घंटा कातता हूँ, जिससे १ गुंडी रोज तैयार हो जाती है। मैं कई वर्षों से रोज आधा घंटा कातता हूँ, किन्तु महीने में ४ गुंडियों से अधिक नहीं होती। उन्होंने कहा, मेरे काते हुए सूत की गुंडी भी मैं खुद बनाता हूँ, साथ ही इस चरखे को रोज साफ करके और बन्द करके भी खुद रखता हूँ।

मैं कई वर्षों से स्नान के समय साबुन का उपयोग नहीं करता। कुछ वर्ष पहले तक तो स्नान करने के बाद पानी को गमछे से न पोंछकर हाथों से रगड़ कर ही सुखा लेता था। परन्तु आजकल स्नान के बाद शरीर को गमछे से पोंछकर सूखे गमछे से शरीर को अच्छी तरह रगड़ता हूँ। चीनी का उपयोग तो मैं करता ही नहीं। मोरारजी भाई की उम्र आज ६६ वर्ष है, परन्तु आज भी उनके शरीर में इस चुस्ती का मुख्य कारण स्वास्थ्यकर नियमों का पालन करना ही है।

महाराष्ट्र राज्य का नया कदम

महाराष्ट्र सरकार ने अपने पहाड़ी इलाकों में कॉफी (कहवा) और रबर के बगीचे स्थापित करने की योजना बनाई है। सरकार का कहना है कि पहाड़ियों के ढाल पर अक्सर स्थानीय किसान जंगल काटकर खेती करना शुरू कर देते हैं और चूंकि ढाल की वजह से थोड़े वर्षों में बारिश के कारण मिट्टी घुल जाती है, अतः वह खेत छोड़कर फिर दूसरी जगह आबाद करते हैं। इस प्रकार जंगल उत्तरोत्तर कटते जाते हैं और छोड़ी हुई जमीन वीरान होती जाती है। इस तरह के क्षेत्र जब कॉफी, रबर आदि के बगीचों के लिए दे दिये जायेंगे, तो फिर किसान उसे बरबाद नहीं कर सकेंगे।

बिना किसी योजना के जंगल काट-काट कर खेती करते रहना हानिकारक है और उससे राष्ट्र की क्षति होती है, पर महाराष्ट्र सरकार ने इस बुराई को रोकने के लिए जो कदम सोचा है वह उससे भी ज्यादा हानिकारक है केरल जैसे अन्य प्रदेशों में कॉफी और रबर के बगीचों का जो अनुभव आया है उससे जाहिर है कि इस प्रकार पहाड़ियों के ढाल पर जंगल काट कर बगीचे खड़े कर देने से बाढ़ और मिट्टी के कटाव की समस्या और भी उग्रतर हो जाती है। कॉफी, चाय और रबर इत्यादि के बगीचे धनवान लोग ही खड़े कर सकते हैं। ऐसा अनुमान है कि कॉफी और रबर के बगीचे बनाने में शुरू में करीब तीन हजार रुपये प्रति एकड़ खर्च होता है, और बाद में कई वर्षों तक लगातार करीब पन्द्रह सौ रुपये प्रति एकड़ चालू खर्च। स्थानीय छोटे-छोटे किसान न इतना खर्च कर सकते हैं, न कॉफी, रबर इत्यादि के बगीचे लगा सकते हैं। अतः महाराष्ट्र सरकार के निर्णय का नतीजा यह होगा कि आज जहां हजारों किसान-परिवार खेती करके अपना गुजरबसर करते हैं, वहां चन्द सम्पन्न लोग अपना व्यवसाय खड़ा करेंगे। तिस पर भी जंगल का कटना और बाढ़ का खतरा ज्यों का त्यों बना रहेगा, बल्कि और बढ़ेगा, क्योंकि किसान तो जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े ही आबाद करते हैं, जबकि कॉफी, रबर इत्यादि के बगीचों के लिए तो लम्बे जंगल साफ करने होंगे। क्या इसी तरह समाजवाद की दिशा में हम जायेंगे?

—भूदान यज्ञ

गांधी जी का सर्वोदय

गांधी जी ने सर्वोदयी समाज-व्यवस्था का आदर्श हमें दिया। उस दिशा में बढ़ने का एक मार्ग उपभोक्ताओं के माल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के उत्पादन का विकेन्द्रीकरण करना है। गांधी जी ने इस पर जोर दिया कि जहां तक सम्भव हो, उत्पादन की इकाई छोटी हो, उत्पादन शहरों में केन्द्रीभूत न हो और उसके उपयोग पर ऐसे लोगों का नियन्त्रण न हो जिनका लक्ष्य लगाई हुई पूंजी से अधिकतम मुनाफा कमाना हो। उनकी मान्यता थी कि इस तरीके से निश्चित रूप में कारीगरों को उद्योगों में सक्रिय साझेदार बनाया जा सकता है, उनमें जिम्मेदारी की भावना पैदा की जा सकती है, उनके श्रम के शोषण को रोका जा सकता है और औद्योगीकरण से उत्पन्न सामाजिक बुराइयों और शहरीकरण से पैदा होने वाली अन्य खराबियों—जैसा कि गन्दी बस्तियों आदि से बचा जा सकता है। उद्योगों के विकेन्द्रीकरण द्वारा ही आर्थिक लोकतन्त्र की नींव रखी जा सकती है और उत्पादन के साधनों की सामाजिक मालिकी का विकास हो सकता है।

परन्तु गांधी जी इस बात को भी जानते थे कि कुछ विशेष उद्योगों और खास किस्म की संगठित सेवाओं में सत्ता का या उत्पादन का विकेन्द्रीकरण न तो संभव है और न व्यावहारिक। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची-अधिवेशन के समय से, और शायद उससे पहले से भी, गांधी जी ऐसे उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में थे। परन्तु गांधी जी ने इन बातों पर विस्तार से विचार नहीं किया था कि राष्ट्रीयकरण के अधीन कारीगरों अथवा मजदूरों में सक्रिय साझेदारी की भावना कैसे पैदा की जायगी, या सत्ता के केन्द्रीकरण को कैसे रोका जा सकेगा। राष्ट्रीयकरण में उन्होंने जिन बातों का स्वागत किया वे थीं इन उद्योगों के संचालन में मुनाफे की भावना का अभाव और इस मुनाफे की भावना के स्थान पर समाज की सेवा करने की भावना का होना। और जो बड़े उद्योग व्यक्तियों के निजी हाथ में हों, वैसी व्यवस्था में गांधी जी चाहते थे कि व्यक्ति, फर्म या कम्पनियां अपने को इन उद्योगों के ट्रस्टी मानें और तदनुसार व्यवहार करें। समाज के उत्पादन और वितरण के साधनों को ऐसे लोगों के अधिकार में रहने देना चाहिए जिनके पास उद्योगों में लगाने के लिए धन है बशर्ते कि वे लोग समाज की ओर से उद्योगों का संगठन और प्रबन्ध करें। उन लोगों को समाज का हित अपने निजी या व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर मानना चाहिए। उनकी व्यापार-कुशलता और क्षमता का पुरस्कार समाज उनके लिए जो उचित समझे दें। जैसा कि सहकारी संस्थाओं में होता है, लगाई गई पूंजी पर सीमित आय ही होनी चाहिए। आय का बाकी भाग सारे समाज के लिए या उपभोक्ताओं या मजदूरों के लिए ट्रस्ट के रूप में रखा जाना चाहिए।

यद्यपि दीन-दलितों का उदय ही गांधी जी के जीवन का प्राथमिक लक्ष्य था, तो भी सर्वोदय—सबके उदय के लिए उनका प्रयत्न था। वे मालिकों, या जमींदारों या उन दूसरे लोगों की जो धनी होने के नाते अर्थ-व्यवस्था का नियन्त्रण करते थे, उच्च भावनाओं को जगाकर सर्वोदय में उनका सहयोग चाहते थे। ट्रस्टी-शिप के विचार की बुनियाद यही है।

— श्री वैकुण्ठ मेहता

नोटों की कीमतें प्रतिवर्ष कम हों

आज जो जमीन की खानगी और अबाधित मालकियत चलती है, वह सामंतशाही का अवशेष है। सामंतशाही की जवानी कभी की खतम हुई है। यह अवशेष सामंत-शाही की छोटी, लेकिन प्रतापी बहन पूंजीशाही के सहारे टिका हुआ है। जमीन की बटाई मुफ्तखोरी है, लेकिन ब्याज-किराया-डिव्हिडंड जैसे मुफ्तखोरी के कई प्रकार जब तक राज मान्य हैं, तब तक बटाईखोरी भी क्यों कर मिटेगी? बटाई के पहले ब्याज-बट्टा भी बन्द हो जाना चाहिए। लेकिन जब तक पैसा-पेशा अर्थात् चलन अमर है तब तक ब्याज को मिटाना असंभव है।

लेकिन चलन का अमर होना कोई नैसर्गिक या नित्य की चीज नहीं है। पहले चलन नश्वर ही होता था। उस वक्त का चलन था अनाज। सोना-चांदी के सिक्के जैसे कोई चीज दुनिया में नहीं थी। उस वक्त पुराना, अतिरिक्त और नश्वर अनाज पड़ोसी को देकर उतना ही ताजा अनाज वापस लेने में साहूकार गनीमत समझते थे और लिहाजा सवाई, अर्थात् ब्याज लेना अनुचित समझा जाता था। जब से सोना-चांदी जैसी अमर सम्पत्ति आदमी के हाथ लगी और उनके सिक्कों का चलन जारी हुआ, तब से आदमी की संग्रह-शक्ति और लोभ बढ़ा। साहूकार बिना ब्याज के किसी को उधार क्यों दें? तब से ब्याज लेने की प्रथा सार्वत्रिक बनी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

महंगाई का मूल : नियंत्रित अर्थशास्त्र

श्री भाईलाल भाई डी० पटेल

आजकल देश में मंहगाई का प्रश्न बहुत अधिक उग्र बन गया है। इसे दूर करने के लिए अनेक अर्थशास्त्री राशन व कन्ट्रोल को जारी करने पर बल देते हैं। किन्तु खाद्यमंत्री श्री पाटिल ने इसे स्वीकार नहीं किया। वस्तुतः पिछला अनुभव बताता है कि श्री पाटिल का विचार ही ठीक है। महंगाई दूर करनी हो तो पहले महंगाई के कारण खोजने पड़ेंगे।

दूसरे विश्व युद्ध से पहले प्रत्येक चीज के भाव बहुत ही कम थे। लड़ाई शुरू होने के तीन वर्ष तक अंग्रेजों ने भाव नहीं बढ़ने दिए क्योंकि उनको युद्ध के लिए आवश्यक माल कम से कम दाम में खरीदना था, लेकिन 'भारत-छोड़ो' का आन्दोलन शुरू हो गया और लगभग सभी औद्योगिक नगरों में, विशेषकर अहमदाबाद के सूती कारखानों में, लगभग तीन महीने तक मजदूरों की हड़ताल रही, मिलें और अन्य अनेक कारखाने इस अरसे में बन्द रहे। कपड़े के उत्पादन में भारी कमी हो गई। कपड़े की तंगी होने के कारण कपड़े के भाव दिन दूने रात चौगुने बढ़ते चले गये। इसका असर रोजाना व्यवहार की चीजों पर भी हुआ।

काला बाजार कैसे प्रारम्भ हुआ ?

उधर बंगाल में मानव-निर्मित अनाज का अकाल पड़ा। ३०-३५ लाख मनुष्य भुखमरी से मर गए। इसी अरसे में २५ लाख भारतीय सेना के अतिरिक्त अमरीकी सेना बहुत अधिक संख्या में भारत में उतरी। अंग्रेजी फौजें तो थी ही। इन सभी सैनिकों के लिए राशन की चीजें, जैसी भी हो, कम से कम भाव में प्राप्त करने की सरकार को जरूरत थी, इसीलिए सरकार ने अनाज के ऊपर नियंत्रण लागू कर दिया।

एक बार नियंत्रण लागू होते ही कन्ट्रोल वाला माल इधर-उधर होने लगा और 'काला बाजार' (ब्लैक मार्केट) नामक अभिशप्त प्रथा चालू हो गई, चीनी का कंट्रोल का भाव शहरों में आठ रु० मन था, उसी का भाव गांवों में १२० रु० मन पहुँच गया। शहर में ८ रु० मन गेहूँ मिलता तो जहां गेहूँ की खेती नहीं होती थी वहां गेहूँ का भाव ३० रु० से ३५ रु० मन तक चढ़ गया। मिट्टी के तेल के कनस्तर का भाव गांवों में ३० रु० तक पहुंच गया और पेट्रोल का 'कूपन' २५ रु० गैलन के भाव से बाजारों में बिकता था।

शुरू-शुरू में नियंत्रण बहुत सख्ती से लागू किया गया। जमा किए हुए माल को बाहर लाने के लिए अचानक छापे मारे जाने लगे। इसके परिणामस्वरूप, मिलों के बायलरों में गेहूँ का 'हवन' होने लगा। चीनी या खांड के बोरे पानी के हौजों में डाले जाने लगे, मिट्टी—तेल के कनस्तर नालियों में बहाये जाने लगे।

'लेवी' का प्रारम्भ

युद्ध जीतने के लिए अनाज की समस्या हल करनी जरूरी थी, इसके लिए कलक्टरों ने 'लेवी' में अनाज लेने की सलाह दी, जो धीरे-धीरे सारे प्रान्तों के किसानों के लिए लागू हो गई। अंग्रेजों के जाने के बाद इसकी जिम्मेदारी कांग्रेसी सरकार के ऊपर आई। अफसरों को किसानों से सस्ते भाव पर अनाज लेने की युक्ति आ गई थी, अनाज

लेकिन अब अमर सिक्कों का जमाना बीत चुका है और आदमी का बनाया हुआ कागजी चलन जारी हुआ है। सिक्के सिर्फ रेजगी के लिए रहेंगे। इस कागज की चलन को कालविशिष्ट बनाना आदमी के हाथ की चीज है।

इसलिए मेरा सुझाव है कि इस साल की नोटें इसी साल तक चलें। नये साल में नयी छपी नोटें चलेंगी और पुरानी वाली नोटें शासकीय खजाने में लौटा कर बदले में नयी नोटें लेनी होंगी, जो सौ के बदले चौरानब्बे (या कमोबेश, लेकिन सौ से कुछ कम ही) मिलेंगी। हर साल इस तरह मुद्रालय होता जाय, तो जैसे पुराने अनाज-युग में होता था, वैसे ब्याज लूला पड़ जायगा। ब्याज-बट्टा का सहारा टूट पड़ते ही बटाई मिट जायगी और जमीन का बटवारा सरल बनेगा।

—अप्पा पटवर्धन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कच्चा है, सूखने पर कम हो जाएगा, के बहाने चालीस सेर के मन के बजाय चवालीस सेर का मन गिना जाने लगा। अनाज की समस्या को इस तरह सुलझाने में कांग्रेसी सरकार को भी कोई अड़चन नहीं दिखाई दी। लेकिन किसानों के भी तो बाल-बच्चे थे। उन्हें गिरवी रख कर सरकार को सस्ता अनाज देने के लिए किसान तैयार नहीं थे, इसलिए किसान नकदी फसल की ओर झुके।

तम्बाकू, मूंगफली, गन्ना और कपास की फसलें बढ़ने लगीं, अनाज की फसलें घटने लगीं। इसलिए सरकार ने नकदी फसलों के क्षेत्रफल के ऊपर भी नियंत्रण लागू कर दिया। फलस्वरूप किसानों और पटवारी-मालगुजारों में सांठ-गांठ हुई। नकदी फसलों के बदले अनाज की फसल सरकारी खातों में लिखी जाने लगी। दूसरी ओर जितनी फसल हो, उसके ऊपर 'लेवी' वसूल की जाती थी। पटवारियों को गांव में रहने के कारण किसानों के साथ मेल रखना पड़ता था, इसलिए जितनी फसल हो, उसकी अपेक्षा कम अन्न की पैदावार दिखाई जाती थी।

इसी कारण लोगों की जरूरत और फसल के बीच बड़ा अन्तर पड़ने लगा। विदेशों से अनाज की अन्धाधुन्ध खरीद से यह समस्या सुलझाई गई, क्योंकि उस समय अंग्रेज १८ अरब रुपये का 'स्टर्लिंग बैलेन्स' छोड़ गये थे। इसलिए विदेशी मुद्रा की अड़चन नहीं थी।

इस नियंत्रित राजनीति का दूसरा परिणाम यह भी हुआ कि मिल और कारखाने वालों के लिए अच्छा या सस्ता माल बनाने के लिए कोई बन्धन या कारण न रहा। खरीददारों के लिए पसन्दगी का प्रश्न ही समाप्त हो गया। माल चाहे कितना ही खराब हो, कितना ही महंगा हो, खरीदने वालों को लेना ही पड़ता था। बनाने वालों के 'पौ बारह' थे। फुटकर बेचने का काम भी 'क्रय-विक्रय-संघों' के मारफत होता था। सन् १९४८ में आणंद (गुजरात) के बाजार में 'एस्फाल्ट' जैसा काला गुड़ दिन-दहाड़े उजले बाजार में बिकता था तो उजला (साफ) गुड़ 'काले बाजार' में बिका करता था।

'क्रय-विक्रय-संघों' में भी अनाज में रेत-कंकड़ या कूड़ा-करकट मिलाया जाता और उतने ही परिमाण में अच्छा अनाज निकाल लिया जाता था। इसलिए आखिरकार खरीदने वाले को निश्चित 'कंट्रोल' के भाव से तोल में कम अनाज मिलता था और साफ करने की मजदूरी घाते में थी। कपड़े के वितरण के बारे में भी काफी अव्यवस्था थी।

स्टर्लिंग पावने का अपव्यय

आरम्भ में कण्ट्रोल से उत्पन्न भय से देश की अर्थ-नीति के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। अंग्रेज १८ अरब रुपये का स्टर्लिंग पावना छोड़ गए थे। केन्द्र और प्रान्तों की तिजोरियां तर थीं। दूसरे विश्वयुद्ध के कारण लोगों के पास रुपयों का अच्छा संग्रह भी हो गया था। अधिकांश किसान कर्ज से मुक्त हो गए थे। देश में वास्तविक या कागजी कमी के कारण कोई दिक्कत भी नहीं थी, क्योंकि १८ अरब रुपयों के स्टर्लिंग बैलेन्स से अच्छा (या सड़ा) अनाज अन्धाधुन्ध खरीदा जा सकता था। जमीन के लिए जो कानून बने; उससे भले ही अनाज के उत्पादन में कमी हो तो भी उसका कुछ भी असर मालूम नहीं पड़ता था। सरकारी विभाग भी खूब बढ़ गये। दूसरे विश्वयुद्ध से पहले बाजार में लगभग १ अरब ८० करोड़ रुपये के कागज के नोट चालू थे। इसके बाद मुद्रास्फीति के कारण आज २० अरब ५० करोड़ रुपये के नोट बाजार में चालू हैं।

अंग्रेजों के समय में जितने नोट छपते थे, उनके पीछे ४०% के लगभग सोना-चांदी या चांदी के रुपये बदले में रखने पड़ते थे। अंग्रेजों ने जब बिदा ली तब भारत और पाकिस्तान में ९ अरब रुपये के नोटों के पीछे १८ अरब रुपये का पौण्ड पावना छोड़ गये थे। आज अपने २० अरब ५० करोड़ रुपयों के चालू नोटों की जमानत में सोने और पौण्ड पावने को इकट्ठा करके लगभग २ अरब रुपयों की कुल सम्पत्ति है। बाकी एक-एक रुपये के नोट हैं, वह भी सिर्फ 'कागजी' हैं।

योजनाओं में खेती की उपेक्षा

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी। इसमें खेती के उपयोगी साधन और नक्शों के निर्माण के ऊपर खास ध्यान दिया गया था। इसमें निश्चित धन तो खर्च हो गया, परन्तु यह सारे काम राज्यों द्वारा किये गये। इस काम के लिये नियुक्त अधिकारियों में और खेती के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ऊपर नजर रखने वाले राजकीय पक्ष के सदस्यों में अधिकांश रूप से ईमानदारी और कार्य क्षमता का अभाव दिखाई दिया, जिससे योजना के अनेक काम अधूरे रहे।

इसके बाद प्रशासन ने 'समाजवादी समाज' की नीति अपनाई और दूसरी पंचवर्षीय योजना का अधिकांश भाग बड़े उद्योगों में खर्च करने का निश्चय किया गया। खेती के लिए पहले निश्चित किया हुआ नहरों का काम अधूरा रह गया, जिससे अनाज का प्रश्न प्रति वर्ष विकट होता चला गया। बड़े उद्योगों को प्रति दिन के प्रयोग में आने वाली चीजों के उद्योग की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाने लगी। पर महंगाई बढ़ती ही गयी।

इसके अलावा योजनाओं के खर्च के लिए नए-नए टैक्स केन्द्रीय और राज्य सरकारों की ओर से लगने लगे। महंगाई बढ़ने के कारण कारपोरेशनों, नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों के खर्च भी बढ़ते चले गए और इन संस्थाओं की ओर से नए नए टैक्स लगने लगे। १९६३-६४ में तो कर चरम सीमा पर पहुंच गये। जनता की जेब खाली होकर सरकारी योजनाओं में लगने लगी।

लक्ष्य से उत्पादन कम

इसका इलाज तो एक ही है कि योजनाओं द्वारा रोजाना व्यवहार की चीजें पैदा करने वाले उद्योगों की स्थापना की जाय। जहां तक हो सके उद्योगों का विकेन्द्रीकरण करके छोटे शहरों और गांवों में इन्हें स्थापित किया जाय, बढ़िया और सस्ता माल पैदा करना होगा और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मेहनत का पूरा पूरा मुआवजा मिले, उसकी बुद्धि को विकसित करने का अवसर मिले, इसके लिए ऐसी हालत पैदा करनी पड़ेगी जिससे असली समाजवादी समाज की स्थापना हो सके। दूसरी योजना में खर्च की गई रकम का एक तिहाई भाग प्रधान उद्योगों में खर्च किया गया और तीसरी योजना में योजना की दो तिहाई रकम बड़े बड़े उद्योगों में खर्च की जानी है।

जिस उद्देश्य के लिए धन व्यय होता है उसका कार्यक्षमता के अभाव से सफल परिणाम नहीं निकलता। इस्पात, कोयला, रुई आदि का उत्पादन लक्ष्य से काफी कम हुआ। राज्यों के उद्योगों से योजना के अनुसार ९५ करोड़ डालर के नफे की आशा थी, किन्तु उसके बदले अमेरिका के न्यूज़ वीक के अनुसार १९६१-६२ के साल में सिर्फ ४६ लाख डालर का ही नफा हुआ है, अर्थात्, अब तक अमेरिका से प्राप्त रकम को खर्च करने पर ०.०३% नफा हुआ है।"

हम अमेरिका को ५% ब्याज देते हैं। वर्ल्ड बैंक को ६॥% ब्याज देते हैं। इस ब्याज से प्राप्त रकम को नए उद्योगों में लगाकर उससे ०.०३% पैदा करते हैं। यह तो योजना में लगाई हुई जो परदेशी पूंजी है, जो योजना का २०% है, उसकी बात हुई। योजना में ८०% पूंजी अपने देश की लगी है, जो प्रजा से 'कर' के रूप में वसूल की गई है।

एकाधिकार के बदले स्पर्द्धा

महँगाई कम करने का एक ही इलाज है। जिस एकाधिकार पद्धति से जितना चाहो उतना महँगा खरीदने के लिए प्रजा को बाध्य होना पड़ता है, ऐसे एकाधिकारवाद को खत्म करके स्पर्द्धा (कम्पिटीशन) स्थापित की जाय; प्रत्येक व्यक्ति को खेती और उद्योगों में उसकी शक्ति के अनुसार काम करने की छूट दी जाय; तभी माल का उत्पादन बढ़ेगा। ग्राहक को माल पसन्द और वाजिब दाम पर मिले, ऐसी दुकानें निश्चित की जानी चाहिए। आज तो माल बनाने वाले का बाजार है, उसके बदले माल खरीदने वाले का बाजार होना चाहिए। (अनु० श्रीनारायण भारती)

उषा

★ सामाजिक कहानियां, शिक्षाप्रद कथानक, विचारोत्तेजक मनोरंजक लेख, राशिफल, सरस, कविताएं आदि।

★ हानिकारक वस्तुओं, व अश्लील फिल्मों के विज्ञापन स्वीकार नहीं किये जाते।

—यदि आपने अभी तक उषा नहीं देखी है तो शीघ्र ही ३२ न० पै० की टिकिट या मनीआर्डर भेजकर नमूनांक मंगा देखिये। हमें पूरा विश्वास है कि एक बार 'उषा' को देखने के बाद आप हमेशा के लिए उसके हो जाएंगे।

—अन्य जानकारी के लिए लिखिये

सचित्र मासिक उषा कार्यालय,
जवाहर मार्ग, इन्दौर।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कल्याणवादी अर्थशास्त्र

श्री भैरवलाल शर्मा

अर्थशास्त्र का जन्म १८ वीं शताब्दी में हुआ। एडम स्मिथ को इसके जनक के रूप में हम सभी स्वीकार करते हैं और सन् १७७६ को अर्थशास्त्र के जन्म या प्रवर्तन का वर्ष मानते हैं जबकि इसके प्रवर्तक एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक-"An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations" प्रकाशित की। उस युग में उसकी यह पुस्तक सर्वमान्य और प्रामाणिक समझी जाती थी, पर कुछ ही समय पश्चात् अनेक विद्वानों द्वारा मतभेद और भिन्नताएं प्रकट किये जाने लगी। हर आने वाले अर्थशास्त्री ने अपने ढंग की अपनी परिभाषा दी तथा अर्थशास्त्र को एक विशेष श्रेणी में रखा। इस प्रकार अर्थशास्त्री आते गये, आलोचना की जाती रही, भेद और भिन्नताओं का प्रादुर्भाव एवं हल होता गया, समानता में असमानता और असमानना में समानता आती गई। आशावाद और निराशावाद में उभरता और डूबता हुआ अर्थशास्त्र दिन-प्रति-दिन आगे बढ़ने लगा। एडम स्मिथ, वाकर, जे. बी. से, सिसमोण्डी, मिल, रोश्चर, हिल्डे ब्राण्ड, मार्क्स, जेवन्स, रिकार्डो, मार्शल, पीगू, पेन्सन, बूटन, फेयर-चाइल्ड, सीनीयर, फ्रेजर, थामस, राबिन्स, किन्स, राबिन्सन, मेहता आदि अनेकों अर्थशास्त्रियों की अपनी-अपनी विचारधाराओं के मोड़ के साथ ही साथ अर्थशास्त्र में भी मोड़ आने लगे और इसकी कुछ श्रेणियां-सी बनने लगीं। इन्हीं में से एक श्रेणी है—"कल्याणवादी अर्थ-शास्त्र।"

कल्याणवादी अर्थशास्त्र का प्रादुर्भाव बेन्थम के उप-योगितावादी इस सिद्धांत से होता है कि "The greatest Happiness of the greatest Number" अर्थात्—अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम हित। यही सिद्धांत कल्याणवादी अर्थशास्त्र का मूलाधार है। इस विचारधारा के प्रतिनिधि के रूप में हब्सन के बाद यदि किसी का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है तो वह है प्रो. ए. सी. पीगू का। प्रो. पीगू ने सन् १९२० में अपनी पुस्तक "Economics of Welfare" प्रकाशित की। पहले के अर्थशास्त्रियों ने "कल्याण" (Welfare) शब्द का बहुत कम प्रयोग किया था। इसके स्थान पर "सुख" (Happiness) शब्द का प्रयोग किया था। प्रो. आर. एम. डी. लिटिल ने कहा है कि पीगू ने कल्याणवादी अर्थ-शास्त्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इससे पहले प्रसन्नता या सुख का और उससे पहले सम्पत्ति का नाम लिया जाता था।

परिभाषा—कल्याणवादी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की वह शाखा है, जो एक निश्चित उद्देश्य से आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करती है, अर्थात् यह बताती है कि क्या आर्थिक नीतियां कल्याण में वृद्धि कर रहीं हैं या नहीं। यह शास्त्र कुछ आदर्श नियत करता है और फिर देश में प्रचलित आर्थिक नीतियों का इन आदर्शों के सन्दर्भ में निरीक्षण करता है। इसका मूल उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना होता है।

प्रो. पीगू के अनुसार—"Economic Welfare meaning that part of social welfare which can be brought directly or indirectly into relationship with the measuring rod of money."

आर्थिक विश्लेषण की यह शाखा वर्तमान युग में अधिकाधिक लोकप्रिय होती जा रही है। इसके विपरीत कुछ अर्थशास्त्री ऐसे भी हैं, जो मानव कल्याण से अर्थ-शास्त्र का सम्बन्ध नहीं रखना चाहते! प्रो. राबिन्स का कहना है कि चूंकि मानव कल्याण अपने आप में एक उद्देश्य है—अतः उसे अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र से अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि अर्थशास्त्र—"उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है" ("Economics stands neutral between the end"—Robbins.) किन्तु यह बात असंगत एवं सारहीन है, क्योंकि अर्थशास्त्र किसी न किसी रूप में 'धन' और 'कल्याण' की समस्याओं से सम्बन्धित रहा है। इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हमारे चारों ओर जो दुःख का विस्तार है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, उसे कम किया जाए। हमारा ज्ञान केवल ज्ञान के लिए नहीं, किन्तु इस लिए है कि उसके द्वारा हमारे रोगों और घावों का निराकरण हो।

अतः अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए, अन्यथा इसका कोई महत्व ही नहीं रह जावेगा। श्री फ्रेजर कहते हैं—"An economist who is only an economist is like a poor pretty fish." यही नहीं, जितने भी शास्त्र आज यहां विद्यमान हैं, वस्तुतः सब शास्त्रों का अन्तिम उद्देश्य—मानव कल्याण की वृद्धि ही होती है। पीगू के कथनानुसार अर्थशास्त्र प्रकाश देने वाला और फल देने वाला—दोनों ही है।

अर्थशास्त्र को कल्याणवादी मानने के निम्न कारण हैं—

(१) प्राचीन काल में वास्तविकतावादी होते हुए भी कल्याणवादी दृष्टिकोण से यह प्रभावित था।

(२) एक आदर्श विज्ञान होने से अर्थशास्त्र कल्याण से आवश्यक रूप से सम्बन्धित है।

(३) कल्याण की भावना के अभाव में यह शास्त्र फीका एवं अरुचिकर विज्ञान बन जावेगा।

(४) इस युग में नयी-नयी समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं और उनका हल मानव-कल्याण मानने से ही हो सकता है

हाट्रे के अनुसार "अर्थशास्त्र में से आदर्शवाद को निकाल देने से वह उसी प्रकार व्यर्थ मालूम होगा, जिस प्रकार से हेमलेट वाले नाटक में से उसके नायक को निकाल देने पर यह नाटक वृथा लगने लगता है।"

कल्याणवादी अर्थशास्त्र का स्वभाव—

अर्थशास्त्र के स्वरूप के सम्बन्ध में जिस प्रकार अर्थशास्त्रियों में मतभेद पाया जाता है, उसी प्रकार कल्याणवादी अर्थशास्त्र के सम्बन्ध में भी यह मतभेद उत्पन्न हो गया है, कि इसका अध्ययन यथार्थवादी है या आदर्शवादी? यदि हम कल्याण के साधनों की विवेचना कर दें और उन्हें निर्धारित करने से इंकार कर दें तो क्या यह बात हास्यास्पद नहीं होगी? डा. एम. एल. सेठ के शब्दों में कल्याण के साधनों की विवेचना करना और उन्हें निर्धारित करना या बताना दो नहीं वरन् एक ही बात है।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स और उनके साथियों ने भी इसी बात पर बल दिया है। कीन्स की—"Theory of Employment" अर्थशास्त्र में एक बहुत बड़ी देन है जिसमें वे केवल बेरोजगारी के कारण ही नहीं बताते, किन्तु पूर्ण रोजगार की प्राप्ति हेतु—मार्ग और साधन भी बताते हैं, जिससे कि आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो सके। अतः स्पष्ट है कि इस शाखा का अध्ययन आदर्शवादी दृष्टिकोण पर किया जाता है।

वास्तविकतावादी एवं कल्याणवादी अर्थशास्त्र

वास्तविकतावादी अर्थशास्त्र से अभिप्राय एक निष्पक्ष दृष्टिकोण से आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन एवं विश्लेषण करने का है। इसके विपरीत कल्याणवादी अर्थशास्त्र आर्थिक नीतियों के विश्लेषण से सम्बन्धित है। इन दोनों में भेद का स्वरूप संक्षेप में इस प्रकार है—

वास्तविकतावादी	कल्याणवादी
१ आर्थिक सिद्धांतों का विश्लेषण करता है।	१ आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करता है।
२ केवल 'कारण' और 'परिणाम' से ही सम्बन्ध स्थापित करता है और इस प्रकार 'क्या है?' प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत करता है।	२ न्याय शास्त्र से सम्बन्धित होता है। यह मानव जीवन की भलाई बुराई को देखता है और इस प्रकार नीतियों को निर्धारित करके यह देखता है कि मानव-कल्याण में वृद्धि हो रही है या नहीं।
३ सामान्य एवं विशेष दोनों दृष्टिकोणों का अध्ययन करता है।	३ केवल सामान्य दृष्टिकोण का ही अध्ययन किया जाता है।
४ परीक्षण (कारण एवं परिणाम) के बाद सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाता है जो कि आगम प्रणाली का दृष्टिकोण है।	४ सिर्फ मान्यताओं पर नीतियों का निर्धारण होता है, इस प्रकार यह निगमन प्रणाली को अपनाता है।
५. अध्ययन बिना उद्देश्य के तटस्थ एवं भाव-हीन दृष्टिकोण से किया जाता है।	५ अध्ययन सोद्देश्य होता है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

किन्तु यह ध्यान देने योग्य बात है कि उपर्युक्त भिन्नताओं के होते हुए भी ये दोनों शाखाएं एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। आर्थिक नीतियां आर्थिक सिद्धान्तों से प्राचीन काल से ही सम्बन्धित रही है। प्रारम्भ में तथा ऐतिहासिक जीवन के अधिकांश काल में भी अर्थशास्त्र वास्तव में कल्याणवादी ही रहा है। बाद के अर्थशास्त्रियों ने ही (मुख्यतः राबिन्स) वास्तविकतावादी अर्थशास्त्र को अधिक महत्व दिया और उसे एक प्रथम श्रेणी में रखने की चेष्टा की। फिर भी इसका विकास कल्याणवादी या आदर्शवादी दृष्टिकोण पर ही होता रहा। पिछले ७० वर्षों से कल्याणवादी अर्थशास्त्र अधिकाधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। वास्तव में ये दोनों शाखाएं पृथक्-पृथक् न होकर एक दूसरे की पूरक हैं।

शास्त्र की मान्यताएं

(१) इसमें यह मानकर चला जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही सन्तोष को अधिकतम करने का प्रयत्न करता है।

(२) प्रत्येक व्यक्ति अपना द्रव्य इस प्रकार व्यय करता है कि क्रय की प्रत्येक मद पर मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता समान हो।

(३) आर्थिक जगत् में सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक रूप से उपस्थित रहता है, क्योंकि—"Laissez-faire and Economic welfare go ill together."

(४) समाज के कल्याण को अधिकतम करने के लिए आवश्यक नीतियों का निर्धारण करना एक वैज्ञानिक प्रयास है, न कि नीतिशास्त्र से सम्बन्धित प्रयास है। इस दृष्टिकोण से पृथक् विचार रखने वाला शास्त्र, महात्मा गांधी के शब्दों में, केवल मोम की बनी मूर्ति है, जिस में जीवन के कोई चिह्न नहीं होते। ●

हिन्दी का एकमात्र

विशिष्ट महिलोपयोगी मासिक

शृङ्गार

- जो सुखी पारिवारिक जीवन का आदर्श पथ-प्रदर्शक है।
- जिसे सुप्रसिद्ध लेखिकाओं, लेखकों, पत्रकारों, चित्रकारों, कवयित्रियों तथा कवियों का सहयोग प्राप्त है।
- जिसे ५०००० से ऊपर की संख्या में पाठक प्रतिमास पढ़ते हैं।
- जिसकी प्रतियां न्यूज़ एजेन्टों के पास पहुँचते ही समाप्त हो जाती हैं।
- जो महिला जागृति का प्रतीक है।
- जो सबकी प्रिय पत्रिका है।

वार्षिक : सात रुपये

एक प्रति : ६० नये पैसे

सम्पादिका : लावण्यप्रभा

कार्यालय : १३।३७, शक्तिनगर, दिल्ली-६।

जीवन साहित्य

हिन्दी के उन मासिक पत्रों में से है, जो—

१. लोकरुचि को नीचे नहीं, ऊपर ले जाते हैं,

२. मानव को मानव से लड़ाते नहीं, मिलाते हैं,

३. आर्थिक लाभ के आगे झुकते नहीं, सेवा के कठोर पथ पर चलते हैं।

जीवन साहित्य की सात्त्विक सामग्री को छोटे-बड़े स्त्री-बच्चे सब निःसंकोच पढ़ सकते हैं। उसके विशेषांक एक से एक बढ़कर होते हैं।

वार्षिक शुल्क ४ रु. भेजकर ग्राहक बन जाइये।

ग्राहक बनने पर मंडल की पुस्तकों पर आपको कमीशन पाने की भी सुविधा हो जायगी।

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देश की प्रतिरक्षा के लिए वस्त्रों का अधिक उत्पादन

बिड़ला काटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि०

के

अधिकारी, कर्मचारी व कारीगर देश के जन-जन के लिए
हर किस्म का कपड़ा मिल में तैयार करते हैं

पंजाब की सर्वश्रेष्ठ रुई से

साड़ी, धोती, छीट, लट्ठा, शर्टिंग,
मलमल, कोटिंग, वायलिन, खादी,
दुसूती, चादर आदि

*

कुशल कारीगरों द्वारा बनाये जाते हैं !!

*

बिड़ला काटन स्पिनिंग एण्ड
वीविंग मिल्स लिमिटेड, दिल्ली ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(पृष्ठ १२५ का शेष)

स्पष्ट होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था लागत-मुद्रास्फीति के पहलू से गुजर रही है जो मुख्य रूप से घाटे की वित्त-व्यवस्था का फल है। घाटे की यह वित्तव्यवस्था बिना पर्याप्त साधनों के पूंजीदर में अत्यधिक वृद्धि करने के कारण जरूरी होती है, जिससे लगातार बजट सम्बन्धी घाटे होते रहते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में, बढ़ती हुई आबादी और आमदनी के लिए खपत सामानों की पर्याप्त वृद्धि की ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

अनेक निष्पक्ष अर्थशास्त्रियों के मतानुसार एक स्वतंत्र समाज में मूल्य नियंत्रण और राशनिंग में स्वयं उनके अपने उद्देश्य नष्ट हो जाते हैं और उनसे खपत सीमित नहीं होती है। कुछ समय की बाहरी—दिखाऊ सफलता के बाद वे प्रभावहीन प्रमाणित होंगे। ये प्रशासन कदम शीघ्र ही खपत को बढ़ा देंगे, साधनों को गैर जरूरी पूंजियों की ओर मोड़ देंगे, सोने को जमा करने की उत्तेजना देंगें, पूंजी को निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और इस तरह से वे योजना के लिए साधनों की उपलब्धता को कम कर आर्थिक विकास की गति को मन्द कर देगें। अधिकतम आर्थिक विकास के लिए मुद्रा और मूल्य सम्बन्धी स्थिरता पूर्व-आवश्यकताएं होती हैं।

प्रोफेसर गालब्रेथ अपनी पुस्तक "एफ्लूयेन्ट सोसायटी" में मुद्रास्फीति विषय की समीक्षा में एक अत्यन्त उल्लेखनीय निर्णय पर पहुँचे हैं : "एक स्वतंत्र बाजार में, जिसमें मुद्रास्फीति की स्थिति व्याप्त हो, सिर्फ धन कमाने के उद्देश्य से, एक शिक्षक, उपदेशक या पुलिसमैन की अपेक्षा एक सट्टेबाज या वेश्या का पेशा अपनाना निस्संदेह लाभप्रद होगा।"

भूतकाल में अनेक देशों में मुद्रास्फीति की करुणाजनक घटनाएं हुई हैं। स्टाक एक्सचेंज पर होने वाले सट्टे क्रमशः अपने को वस्तुओं के सट्टे पर स्थानांतरित कर लेते हैं और जिनका अन्त जमीन की कीमतों के सट्टों में होता है, जिसके फलस्वरूप सारी अर्थव्यवस्था अत्यन्त निकृष्ट किस्म की बीमारी से व्याप्त हो जाती है। मूल्य-वृद्धि की अपेक्षा से प्रत्येक व्यक्ति अपनी मुद्रा को चीजों में बदल लेता है और जिससे सामानों के अभाव की स्थिति पैदा हो जाती है। बदले में सरकार अधिक सख्त कन्ट्रोल लगाती है और इस तरह रोग का इलाज करने की बजाय उसके लक्षणों से लड़ने की कोशिश करती है। मुद्रास्फीति, जैसा कि उसका स्वरूप अभी भारत में विकसित हो रहा है, एक स्थायी आर्थिक विकास के उद्देश्य की प्राप्ति में भारी अवरोध प्रमाणित होगी।

अतः यदि मुद्रास्फीति के भारी खतरों से बचना है तो सरकार को अपनी नीति में सुधार करना पड़ेगा और अपने खर्च को साधनों तक ही सीमित रखना पड़ेगा और एक यथार्थवादी आर्थिक नीति अपनानी होगी। हमेशा के संकट से बचने के लिए हमको एक उचित आकार की योजना अपनानी चाहिए न कि बिना साधनों की एक विशाल योजना। सरकार द्वारा सभी मुद्रा सम्बन्धी हथियारों का प्रयोग करने के निश्चय के स्थान पर उसे एक संशोधित मुद्रास्फीति नीति की पूर्व घोषणा करनी चाहिए।

प्रोफेसर ए० सी० पीगू ने भी इस बात पर जोर दिया है कि आर्थिक शक्तियां मनुष्यों पर लागू होती है, बिजली की मशीनों पर नहीं। लन्दन के "इकोनोमिस्ट" द्वारा दी गई सलाह फिर से दोहराने योग्य है : "भारी निराशाओं के बावजूद भी मौका चूक जाने के पहिले मुद्रास्फीति को रोकने के लिए यथाशक्ति साहस बटोर कर कदम उठाने चाहिए। मुद्रास्फीति के जरिये वित्त-व्यवस्था करना खतरनाक है, क्योंकि अन्त में उससे जनता के नैतिक और भौतिक स्तर का पतन होता है—जिससे सभी नियोजन के मूल उद्देश्य ही नष्ट हो जाते हैं।

(पृष्ठ १३७ का शेष)

चलाने से डीजल तेल में बचत होती है।

तीसरी योजना में लगभग १२०० मील लम्बी नयी लाइनें बिछाने और १,४४८ किलोमीटर लाइनें दोहरी करने का लक्ष्य है। ये दोनों कार्य किये जा रहे हैं।

तीसरे दर्जे के लिए सुविधाएं

तीसरे दर्जे के यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए बजट में व्यवस्था की गयी है। सोने के स्थान की सुविधाएं इन्हें अब अधिक मिल सकेंगी। भीड़ कम करने के लिए ४५ नयी गाड़ियां चलायी गयीं। ५२ गाड़ियों के यात्रा मार्ग में वृद्धि की गयी और उपनगरीय रेलों में १०८ नयी गाड़ियां चलायी गयीं। इस से रेलों की यात्रा में प्रतिदिन लगभग ३ हजार किलोमीटर की वृद्धि हुई है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस मास की आर्थिक घटनाएं

गोआ और शेष भारत के बीच तटकर घेरा

गोआ, दमन और दाऊ तथा शेष भारत के बीच जो तटकरका घेरा अभी तक मौजूद था, वह अब हटा लिया गया है। फिर भी, २८ चीजें ऐसी हैं जो इन केन्द्रीय क्षेत्रों से बाहर नहीं जा सकेंगी। इनमें शराब, खाद्यान्न, कैमरा, रेफ्रिजेटर, रेडियो, ट्रानजिस्टर और कुछ खास प्रकार के कपड़े शामिल हैं।

बर्मा द्वारा बैंकों को मुआवजा

बर्मी सरकार ने जिन विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है, उन्हें मुआवजा उन्हीं देशों की मुद्रा में तीन मास के भीतर दे दिया जाएगा और यह उस मूलधन पर दिया जाएगा जिसे वे, प्रारम्भ में, बर्मा में लाये थे। इसके साथ ही, इन बैंकों से प्राप्तव्य ऋण की राशि काटकर इमारतों और अन्य स्थिर सम्पत्ति का मूल्य भी अदा कर दिया जाएगा।

इस प्रकार भारतीय बैंकों की क्षतिपूर्ति की राशि रुपये की मुद्रा में दी जाएगी।

"लोकमान्य"—बिजली का रेल इंजिन

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, कलकत्ता, द्वारा ११ लाख रुपये की लागत से लोकमान्य बालगंगाधर तिलक की स्मृति में बना बिजली का रेल-इंजिन सेन्ट्रल रेलवे की ओर से विक्टोरिया टर्मिनस, बम्बई, रेलवे स्टेशन से चालू हो गया है। इसकी कार्यक्षमता ३६०० अश्वशक्ति है। यह ५६० टन की सवारी गाड़ी ७० मील फी घंटा के हिसाब से और मालगाड़ी २००० टन की ३५ मील फी घंटा के हिसाब से खींच सकता है। इस इंजिन का कुल वजन १२६ टन है।

भारत की निर्यात आय में वृद्धि

१९६२ में भारत के निर्यात में १४ करोड़ रु० की वृद्धि हुई। इस वृद्धि का एक मुख्य कारण यूरुप के बाजारों में भारतीय खल की मांग का बढ़ना है। वृद्धि का दूसरा कारण पूर्वीय यूरुप के देशों द्वारा जूट और तम्बाखू की अधिक मांग थी। वनस्पति तेल की मांग भी बढ़ी।

तेल निकालने के नये प्रयत्न

'तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने निर्णय किया है कि पंजाब, गंगा की घाटी, पश्चिमी बंगाल, कावेरी घाटी और असम में तेल की सघन खुदाई की जाए। यह भी निश्चय किया गया है कि अंकलेश्वर में मौजूदा तेल-उत्पादन १५०० टन को बढ़ाकर २००० टन प्रतिदिन किया जाए, तथा अहमदाबाद के पास आलोक क्षेत्र की चट्टानों की जांच की जाए।

वि. पत्तनम—फारस की खाड़ी के बीच टैंकर

शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया ने कालटेक्स इंडिया लि० के साथ एक करार नामा किया है जिसके अनुसार विशाखापत्तनम बन्दरगाह और फारस की खाड़ी के बीच चलने के लिए एक टैंकर लिया गया है। यह टैंकर जापान की 'हिताची' कम्पनी द्वारा बनाया जाएगा।

कोयले के मूल्य में वृद्धि

कोयला और कोक (हार्ड और साफ्ट दोनों) के दामों में क्रमशः ८० न. पै. और १.०७ फी टन वृद्धि १ मार्चसे इस लिए की गयी है क्योंकि केन्द्रीय श्रम दर बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार कोयला उद्योग पर अतिरिक्त व्यय पड़ा है।

इस वर्ष चीनी का निर्यात

१९६३ के वर्ष में भारत ४५०,००० मीट्रिक टन चीनी का निर्यात करेगा। चीनी के निर्यात की सहायता में कमी आ रही है। १९६२ में ३७३,००० टन के निर्यात पर यह राशि १४.४४ करोड़ रु० थी जब कि १९६१ में २६६,००० टन पर यह १३.२६ करोड़ रु० थी।

मूल्य नियंत्रण का विधेयक

वित्त बिल, १९६३ के अनुसार कुछ वस्तुओं के उत्पादन शुल्क की दरों को बढ़ाने तथा पदार्थों पर विशेष उत्पादन शुल्क लिये जाने के कारण सम्बद्ध वस्तुओं की खुदरा बिक्री की दरों में कुछ फेर बदल जरूरी हो सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारत रक्षा कानून १९६२ के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अधीन अनिवार्य वस्तु (मूल्य नियंत्रण) आदेश १९६३ के अनुसार विज्ञापित किया है कि मिट्टी का तेल, वनस्पति, साबुन और कागज जैसी कुछ रोजमर्रा के काम आने वाली चीजों के अधिक से अधिक कितने भाव बढ़ाए जा सकते हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार इन चीजों को बेचने वाले प्रत्येक विक्रेता को जिसमें वास्तव में इन वस्तुओं को बढ़े हुए शुल्क की दर देकर खरीदा है उसे अपनी दूकान पर मूल्य सूची टांगनी होगी जिसमें यह साफ साफ लिखा होगा कि १ फरवरी, १९६३ को या उसके तुरत पहले अमुक चीज की क्या कीमत थी और भविष्य में वह किस भाव पर उस चीज को बेचना चाहता है।

इस आदेश में मिट्टी के तेल के विविध मूल्य भी नियत किये गये हैं। इसी तरह साबुन, छपाई के कागज आदि के मूल्य में वृद्धि को नियत कर दिया गया है।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

वित्त बिल में चीनी, दियासलाई, पेटेन्ट दवाइयां, जूते, सायकिल के पुर्जे और इस्पात और लोहे की चीजों जैसी कुछ अनिवार्य वस्तुओं पर शुल्क की दरों में किसी तरह का परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है। अतः इनके दाम नहीं बढ़ने चाहिए।

प० जर्मनी से भारत को नया ऋण

पश्चिमी जर्मनी की ओर से भारत को १० करोड़ ७० लाख डीएम (जर्मन सिक्का) ऋण दिया जाएगा जिससे शक्ति-उत्पादन, टेलीकम्युनिकेशन, रेल और बन्दरगाह निर्माण तथा औद्योगिक सामान खरीदा जा सकेगा। बोन में दोनों देशों के बीच इस बारे में करार पर हस्ताक्षर हुए हैं। पिछले वर्ष एक करार के अनुसार तीसरी योजना के दूसरे वर्ष के लिए पश्चिमी जर्मनी ने भारत को ४७ करोड़ डीएम (जर्मन सिक्का) का पूंजीगत ऋण देना था, यह नया समझौता इसमें संशोधन के रूप में है।

—सोवियत संघ की सहायता से भारत सरकार कोटा में सूक्ष्म यंत्रों का कारखाना स्थापित कर रहा है। रूस पूरी तकनीकी सहायता देगा।

—दुर्गापुर में मशीनी औजार और मिश्रित इस्पात (टूल एलाय स्टील) का कारखाना स्थापित करने का काम संतोषजनक ढंग से चल रहा है।

—एक जापानी फर्म के सहयोग से फरीदाबाद में बाल बेयरिंग कारखाना स्थापित किया जा रहा है। जापान ६० लाख रु० की मशीनें देगा।

—भोपाल के भारी बिजली के कारखाने में अप्रैल ६२ से जनवरी ६३ तक २३६ लाख ३० हजार रु० की लागत का काम हुआ है।

—तृतीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में ३१ सीमेंट के कारखाने खोले जाएंगे।

(पृष्ठ १३१ का शेष)

१९६१-६२ के बीच राष्ट्रीय पदार्थों की २७ प्रतिशत मुद्रापूर्ति की ६० प्रतिशत और मूल्यों की ३४ प्रतिशत वृद्धि का उल्लेख करते हुए हाल ही में चेतावनी दी है। "यदि हमारी अर्थव्यवस्था का व्यवस्थित और स्थायी विकास होना है तो हमको पहले इस अजीब तरीके को बन्द कर देना चाहिए। बढ़ती हुई कीमतों के खौलते पानी को ठीक करने का तरीका है नीचे से घाटे के बजट की आग को हटाना; विदेशी सहायता के ठण्डे पानी को उडेलने से तापक्रम केवल थोड़ी देर के लिए ही कम हो सकेगा।"

यथार्थवाद और समय की जरूरत, प्रगति के एक ही स्रोत की ओर इशारा करते हैं और वह है जनता का निजी उद्योग या स्वतंत्र उद्योग। समूहवादी विचारधाराओं का समय अब खत्म हो चुका है। मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि स्वतंत्र उद्योग नये समाज का सन्देशवाहक बनेगा। स्वावलम्बन की इस नई भावना को भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने अपने विदाई भाषण में इन शब्दों में व्यक्त किया था :

"हमें अपने संघर्ष का अनुभव है और उस संघर्ष के दौरान में महात्मा गांधीजी ने हमको अपने आप पर निर्भर होना सिखाया।

"लेकिन आज छोटी-छोटी चीजों के लिए लोग सरकार का मुंह देखते है कि वह उन लोगों के लिए वैसा कर दे। सरकार पर अत्यधिक निर्भर रहने की उस भावना की निन्दा होनी चाहिए, और जनता की पहल, उनके स्वावलम्बन को भरसक प्रोत्साहन मिलना चाहिए।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मैं किस प्रकार सहायक हो सकती हूं ?

इस देश की गौरवमयी परम्परा के अनुसार भारतीय स्त्रियां देश रक्षा के काम में बहुत कुछ मदद दे सकती हैं। वे अपने यहाँ के महिला संगठन में शामिल हो कर रक्षा कार्य में हाथ बटा सकती हैं तथा और भी कई कर्तव्य निभा सकती हैं • राष्ट्रीय रक्षा कोष में दान दें तथा औरों को ऐसा करने के लिए उत्साहित करें। रक्षा पत्र खरीदें। अपना अनुशासन और व्यवहार ऐसा बनाएं जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हों।

- कोई चीज ज़ाया न करें। बिना सोचे समझे खरीदारी न करें और कीमतों को बढ़ने से रोकें।
- सोना न खरीदें, अपना सोना देश के लिए अर्पित करें।
- अपना कार्य दृढ़ता से करती रहें, चाहे कार्य कैसा भी क्यों न हो। अधिक कुशलता से किया गया हर कार्य राष्ट्र के लिए सहायक होता है और उससे भारत की स्थिति और अधिक सुदृढ़ होती है।
- ढिलाई और आलस बिल्कुल छोड़ दें—यह काम का वक्त है, अमल का वक्त है।

चौकस रहें

—राष्ट्र की तैयारी में हाथ बटाएं

डीए ६२/एफ-७

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"सम्पदा" के सम्बन्ध में जानकारी

रजिस्ट्रार न्यूज पेपर्स एक्ट के नियम के अन्तर्गत विज्ञाप्ति

१—प्रकाशन का स्थान	२८/११ शक्तिनगर, दिल्ली-६
२—प्रकाशन की अवधि	मासिक
३—४-५ मुद्रक, प्रकाशक और सम्पादक	कृष्णचन्द्र विद्यालंकार
६—राष्ट्रीयता	भारतीय
७—पता	२८/११ शक्तिनगर दिल्ली-६
८—स्वामित्व	कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

मैं कृष्णचन्द्र विद्यालंकार घोषित करता हूँ कि ऊपर दी गयी जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार बिल्कुल ठीक है।

प्रकाशक—कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

सबसे सस्ता सचित्र हिन्दी मासिक

जागृति

जिसे भारत के सभी प्रमुख कवियों,
और कहानीकारों का सहयोग प्राप्त है।
उत्प्रेरक कविताएं, ज्ञानवर्धक लेख, सांस्कृतिक निबंध,
रोचक कहानियां, बाल संसार, साहित्य आगे
बढ़ता है आदि स्तम्भ
तिरंगा आवरण, अनेकों इकरंगे चित्र
४८ से ५६ पृष्ठ को सम्पूर्ण छपाई आर्ट पेपर पर
इस पर भी मूल्य केवल २५ नये पैसे
एजेंटों को ५ से १० प्रतियों पर २५ प्रतिशत और इससे ज्यादा पर ३३⅓ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। डाक खर्च प्रकाशकों के जिम्मे। एजेन्ट नमूने की प्रति के लिए आज ही लिखें।

—सूचना व प्रकाशन विभाग चण्डीगढ़ (पंजाब)

आर्थिक समीक्षा

प्रधान सम्पादक : श्री सादिक अली
सम्पादक : श्री महेन्द्र मेहरा

- हिन्दी में अनूठा प्रयास
- आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख
- आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत

भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक।

वार्षिक मूल्य : ५ रु० एक प्रति २२ नये पैसे

लिखें—व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, नई दिल्ली।

ग्राम राज (मास में तीन बार प्रकाशित)

सम्पादक—श्री गोकुलभाई भट्ट

"ग्रामराज बहुत ही शानदार और बहुत ही सुन्दर पत्र निकल रहा है। सब तरह की जानकारी इसमें रहती है। राजस्थान के हर शिक्षित भाई बहन के हाथ में यह पत्रिका होनी चाहिए।" —बिनोबा

वार्षिक चन्दा ३) रु०

कार्यालय का पता :

ग्रामराज, किशोर निवास
त्रिपोलिया जयपुर

पाँच पैसे में नया संसार

बाँझपन

का ठेके पर इलाज। पहले सन्तान पीछे दाम। अनगिनत सूने घर आबाद हो गये। एक कार्ड लिखकर ब्यौरा मुफ्त लें।

—डायरैक्टर—
श्री कुशल भवन, नाभा (पंजाब)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सेंचुरी मिल्स बम्बई की प्रसिद्ध फैशन फ्रैब्रिक्स

* असली आरगंडी * लेक्स ब्यूटी मलमल * मोती वायल और फुल वायल
* परमसुख धोती * एम्बास्ड प्रिंट्स * खादी और धारीदार पाप्लीन,
नित्य नवीन डिजाइनों में छपी हुई चमकदार छींट, लट्ठा, ड्रिल्स, चादरें, तौलिये
काटन वेस्ट, कम्बल आदि आदि

नवीन आकर्षण

प्रिश्रङ्क—सेंचुराइज्ड शर्टिंग, पाप्लीन और ड्रेस मेटीरियल

* निर्माता *

दी सेंचुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कं. लि.

इन्डस्ट्रीज हाउस, १५६ चर्चगेट, रिक्लेमेशन बम्बई
मैनेजिंग एजेंट्स : बिरला ग्वालियर प्रा० लि०

क्वालिटी मिनरल सप्लाई सिंडीकेट

प्रोप्राइटर—सी० डीडवानिया
मिनरल व केमिकल के व्यापारी

विशेषताएं

सुपर एक्टिवेटेड (Activated) फुलर्स अर्थ सोडियम तथा पोटेशियम
बाईक्रोमेट सब प्रकार की Jack Hammers के स्पेअर पार्टस्

लिखें—४४ ओल्ड कस्टम हाउस स्ट्रीट,
फोर्ट बम्बई १

तार : Sympathy

फोन : २५१८३५

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रवीण और नवीन का सहयोग···

आज से काफी पहले १९२१ में ही, टाटा स्टील ने जमशेदपुर में एक टेकनिकल इन्स्टिट्यूट कायम किया। उद्देश्य था कर्मचारियों को टेकनिकल शिक्षा देकर पूर्ण योग्य बनाना जिससे वे भारत के प्रथम इस्पात कारखाने में दायित्व के पदों को संभाल सकें। उसके बाद ही, कम्पनी ने कुशल कारीगरों और दूसरे कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग कोर्स चलाया।

पिछले चार वर्षों के भीतर, हिन्दुस्तान स्टील की भारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, जमशेदपुर टेकनिकल इन्स्टिट्यूट ने योजना बनाकर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के सरकारी इस्पात कारखानों के १८०० से अधिक टेकनिशियन जमशेदपुर के प्रशिक्षण सम्बन्धी अनुभव भंडार और अन्यान्य सुविधाओं से फायदा उठा चुके हैं क्योंकि जमशेदपुर में उद्योग सिर्फ रोटी-रोजी का जरिया ही नहीं, बल्कि जिन्दगी का रास्ता है।

जमशेदपुर

इस्पात नगरी

The Tata Iron and Steel Company Limited

IWTTN 5

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष में खुलकर दान दीजिये

सम्पादक—कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा नवजीवन प्रेस (प्रा०) लि० (लीजिज़ ऑफ अर्जुन प्रेस) दिल्ली-६ से मुद्रित

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा

वर्ष १२ : अंक ४

मूल्य
न. पै.

अशोक प्रकाशन मन्दिर शक्ति नगर, दिल्ली

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्वालिटी मिनरल सप्लाई सिंडीकेट

प्रोप्राइटर—सी० डीडवानिया

मिनरल व केमिकल के व्यापारी

विशेषताएं

सुपर एक्टिवेटेड (Activated) फुलर्स अर्थ सोडियम तथा पोटेशियम बाईक्रोमेट सब प्रकार की Jack Hammers के स्पेअर पार्टस्

लिखें—४४ ओल्ड कस्टम हाउस स्ट्रीट,

फोर्ट बम्बई १

तार : Sympathy फोन : २५१८३५

अत्यन्त शुभकामनाओं के साथ

दि न्यू ग्रेट ईस्टर्न स्पि. एंड वीविंग कम्पनी लिमिटेड

१५ ए, हार्निमन सरकल

फोर्ट बम्बई-१

निर्माता

सूती कपड़े और सूती तथा स्टेपल फाइबर सूत के रँगीन और ब्लीच किये कपड़े, लांग क्लाथ माजरी, शीटिंग, रँगीन पापलिन, रंगीन इटालियन, ब्लीच्ड मरसिराइज्ड लेनो :

तार का पता—"न्यूग्रेट" टेलि. नं. २५१२१८

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एक अच्छे कार्य

और अपनी

बचत के लिए

दी पंजाब नेशनल बैंक

में आपका धन सुरक्षित रहता है—उस पर व्याज मिलता है और सबसे सन्तोष की बात तो यह है कि इस धन को उन बड़े-बड़े राष्ट्रीय कार्यों में लगाया जाता है जो देश के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं।

अपने लिए बचाकर—आप देश की सेवा भी करते हैं

दी पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड

रजिस्टर्ड आफिस—पार्लियामेंट स्ट्रीट, नयी दिल्ली

आधुनिक भारतीय बैंकों में सबसे पुराना नाम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
१. सम्पादकीय—कृषि उत्पादन की चिन्तनीय स्थिति	१६१
२. टिप्पणियां	१६३
३. १९६२ में भारत के निर्यात-व्यापर में कमी	१६७
४. उद्योगों का विकास कैसे हो ? —पी० वी० महता	१६९
५. देश की रक्षा के लिए औद्योगिक विकास—सव्यसाची	१७१
६. भारत के आर्थिक विकास में अमेरिका का सहयोग	१७३
७. भारत के सार्वजनिक ऋण —प्रो० रामकृष्ण सिंगी	१७५
८. बाध्य बचत योजना—प्रो० तारपोरवाला	१७७
९. भरपूर खेती—कार्यक्रम	१७९
१०. खादी आन्दोलन का नया स्वरूप —एस० सी० सरकार	१८[illegible]
११. प्रतिरक्षा प्रयत्न और कृषि-कर —प्रो० धर्मेन्द्रसिंह	१८[illegible]
१२. नियोजित अर्थ-व्यवस्था में पूंजी का महत्त्व —वीरेन्द्र अग्रवाल	१८[illegible]
१३. नयी कर-नीति और उद्योग	१८[illegible]
१४. नया सामयिक साहित्य	१९[illegible]
१५. श्रमिक और राजनीतिक दल —श्री जान हेलिंग	१९[illegible]
१६. अर्थ वृत्त चयन	१९[illegible]
१७. सुरक्षा व्यय की पूर्ति	१९[illegible]
१८. आज के प्रमुख प्रश्न —श्री आर० एल० तुली	२०[illegible]
१९. राज्यों की गतिविधि	२०[illegible]
२०. जयन्ती शिपिंग कम्पनी	२०[illegible]
२१. इस मास की आर्थिक घटनाएं	२०[illegible]

सम्पदा के स्थायी ग्राहकों से

१. 'सम्पदा' कार्यालय से पत्र-व्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें । ग्राहक संख्या, व पूरा साफ पता न लिखने की स्थिति में पत्रोत्तर में देरी होने या ठीक उत्तर न देने की पूरी सम्भावना है ।

२. वार्षिक चन्दा समाप्त होने पर अगले वर्ष का चन्दा स्वयं भेजने की कृपा करें ।

३. अगले वर्ष का ग्राहक न रहने की हालत में चन्दा समाप्त होने से हमें एक मास पूर्व सूचना देने की कृपा करें ।

४. 'सम्पदा' की प्रति हर मास की प्रति २० तारीख तक न मिलने की स्थिति में अपने स्थानीय डाकखाने से जानकारी प्राप्त कर के हमें शिकायत भेजें । दो या अधिक मास की प्रतियां न मिलने की शिकायत आने पर 'सम्पदा' कार्यालय एक साथ सब प्रतियां नहीं भेजेगा ।

४. वी० पी० जहाँ तक सम्भव हो, छुड़ाने की कृपा करें । अन्यथा वी० पी० भेजने की सूचना का पत्र प्राप्त होते ही हमें वी० पी० छुड़ाने, न छुड़ाने, चन्दा भेजने या न भेजने की सूचना शीघ्र भेजने की कृपा करें, इससे हमारी असुविधाएं बच जाएंगी ।

—मैनेजर-सम्पदा

सम्पदा का वार्षिक मूल्य आठ रु० है । २८/११ शक्तिनगर, दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वर्ष : १२
अंक : ४
अप्रैल : १९६३

सम्पदा

कृषि उत्पादन की चिन्ताजनक स्थिति

तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्ष समाप्त होने पर यह स्वाभाविक ही था कि इन दो वर्षों की गतिविधि और सफलता या असफलता पर हम विचार करते। संसद के बजट अधिवेशन में योजना के विविध अंगों पर विभिन्न मंत्रालयों के वार्षिक विवरण उपस्थित किये गये और उन पर पर्याप्त चर्चा भी हुई। उद्योग, कृषि, भारी उद्योग, योजना मंत्रालयों ने अपनी प्रगति का लेखा रखा और सदस्यों ने उस पर अपना अभिमत प्रकट किया। अ० भा० कांग्रेस समिति के दिल्ली-अधिवेशन में भी योजना मंत्री की रिपोर्ट पर काफी विचार किया गया। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के अधिवेशन में भी आर्थिक प्रश्नों पर विचार विनिमय में जहां नये बजट-प्रस्तावों की चर्चा हुई, वहां गत वर्ष की सफलताओं व असफलताओं पर भी काफी विचार हुआ।

विचार के विभिन्न अवसरों और विभिन्न संस्थाओं के अधिवेशनों में की गई चर्चा से एक बात निःसन्देह स्पष्ट होती है कि देश में कृषि-उत्पादन अपने लक्ष्यों से बहुत पिछड़ रहा है। कृषि ही देश की समस्त अर्थव्यवस्था का आधार है। भारत की ७५ प्रतिशत जनता कृषि पर निर्वाह करती है, जबकि सं० रा० अमेरिका और कनाडा में केवल १२ प्रतिशत, आस्ट्रेलिया में १३ प्रतिशत, फ्रांस में २६ प्रतिशत और जापान में ४० प्रतिशत जनता के निर्वाह का आधार कृषि है। लेकिन यह ७५ प्रतिशत जनता राष्ट्रीय आय में ५० प्रतिशत भी भाग नहीं लेती। जब पिछले दस वर्षों में राष्ट्रीय आय में ४२ प्रतिशत वृद्धि हुई है, तब कृषि क्षेत्र ३३ प्रतिशत से अधिक अपनी आमदनी नहीं बढ़ा सका। इन दस वर्षों में एक कृषक की आय केवल १५ प्रतिशत बढ़ी है, जबकि कृषि भिन्न क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति २५.५ प्रतिशत आमदनी बढ़ी है। यह बात नहीं कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं में २० अरब रु० कृषि पर व्यय किया गया है। सिंचाई की करोड़ों रु० की योजनाएं, सामुदायिक विकास की देशव्यापी शाखाओं का जाल और सुधरे बीज, उन्नत औजार और तकावी या सहकार समितियों की विस्तृत व्यवस्था आदि के द्वारा भी कृषि-सुधार पर करोड़ों रु० व्यय किया गया है और आज भी किया जा रहा है। फिर भी स्थिति यह है कि देश आज तक अन्न की दृष्टि से स्वावलम्बी नहीं हुआ। पहली योजना की अवधि में यदि ५३८ करोड़ रु० का विदेशी अन्न आयात किया गया था, तो दूसरी योजना के पांच वर्षों में ७११ करोड़ रु० का। अन्न के आयात की गति मन्द नहीं हुई, तीसरी योजना के प्रथम डेढ़ वर्ष में हम करीब २०० करोड़ रु० का अन्न मंगवा चुके हैं। इन संख्याओं से ही स्थिति पूर्णतः स्पष्ट नहीं होती। अन्न के अतिरिक्त हमने इन वर्षों में विदेशों से कपास भी कम नहीं मंगाई। कपास के आयात के अंक निम्नलिखित हैं—

प्रथम योजना	३८४ करोड़ रु०
दूसरी योजना	२४४ करोड़ रु०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तीसरी योजना के १॥ वर्ष १०० करोड़ रु०

इन सब अंकों के साथ जब हम यह देखते हैं कि कृषि का उत्पादन आज भी कम हो रहा, तब हमारा चिन्तित होना बहुत स्वाभाविक है। यही कारण है कि संसद् में, अ. भा. कांग्रेस समिति में उद्योग व्यापार मंडलों में कृषि की स्थिति पर गंभीर चिन्ता प्रकट की गई है। स्वयं योजना मंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा और प्रधान मंत्री पं० नेहरू ने भी इस स्थिति को असन्तोष जनक स्वीकार किया है।

कृषि उत्पादन में सन्तोषजनक प्रगति के लिए इन क्षेत्रों में विविध उपाय सुझाये गये हैं। इनमें से कुछ मुख्य निम्नलिखित हैं :—

१. सिंचाई की व्यवस्था में सुधार कर छोटे-बड़े अन्तर्वर्ती खेतों तक भी पानी को सुलभ किया जाय।

२. बढ़िया बीज और नये किस्म के औजार किसानों के लिए सुलभ किये जावें।

३. रासायनिक खाद का उत्पादन बढ़ाया जाय, विदेशों से अधिक आयात किया जाय और किसानों तक उसके वितरण की उचित व्यवस्था की जाय।

४. ट्रैक्टरों के प्रयोग को बढ़ाया जाय और इसके लिए खेतों की चकबन्दी ऐसे ढंग से की जाय, जिससे ट्रैक्टरों का प्रयोग आसानी से हो सके।

५. संयुक्त कृषि-सहकारिता पद्धति का प्रचार किया जाय।

६. किसानों को तकावी और अन्य ऋण बिना विलम्ब और पेचीदगी के मिल सकें, इसकी समुचित व्यवस्था की जाय।

७. विविध फसलें बोने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाय और इसके लिए गन्ना, गेहूँ, चावल, तमाखू, कपास आदि विविध पदार्थों के निम्नतम मूल्य बुवाई से पहले ही घोषित कर दिये जावें।

८. भरपूर गहन खेती का क्षेत्र बढ़ाया जाय।

९. खेती की अधिकतम सीमा पर प्रतिबन्ध हटाया जाय, क्योंकि छोटे-छोटे खेतों में प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है और बड़े फार्मों में अधिक। इसके विरुद्ध दूसरा मत यह है कि छोटे खेतों पर स्वाभित्व की भावना से खेती में किसान अधिक रुचि लेंगे। इसी कारण जमींदारी प्रथा का उन्मूलन भी किया गया है।

१०. कृषि पर विनियोजन के लिए अधिक आर्थिक राशि निर्धारित की जाय।

११. कृषि विभाग तथा सामुदायिक योजनाओं में अधिक कार्य कुशलता, आडम्बर हीनता और अधिक चुस्ती आदि की ओर ध्यान दिया जाय।

ऐसे ही कुछ अन्य सुझाव भी दिये गये हैं। कृषि मंत्रालय योजना आयोग पर इस शिथिल प्रगति के लिए इलजाम लगता है, तो योजनामंत्री कहते हैं कि कृषि मंत्रालय की तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। कृषि विभाग के अधिकारी ऋतु सम्बन्धी कठिनता—वर्षा की कमी या बाढ़ आदि को सदा उत्पादन की कमी का मुख्य कारण बताते हैं। लेकिन योजना मंत्री ने कहा है कि ऋतु संबंधी कारण ही सम्पूर्ण कथा नहीं है। यदि केवल ऋतु ही उत्पादन का एक मात्र कारण होता तो फिर योजना-निर्माण और मानव-प्रयत्नों की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। योजना मंत्री ने इसकी कुछ जिम्मेदारी राज्यों पर डालते हुए कहा है कि कुछ राज्यों में तो प्रगति हुई है, पर कुछ राज्यों में कृषि को आवश्यक महत्व ही नहीं दिया जाता और कृषि के लिए नियत राशि दूसरे कार्यों में प्रयुक्त कर दी जाती है। स्वयं प्रधान मंत्री ने पंजाब के किसानों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उत्तरप्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में गति बहुत शिथिल रही है।

इन सब कारणों और सुझावों का विवेचन करना हमारा प्रयोजन नहीं है और न यहां उसका स्थान ही है। हम तो सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि समस्त स्थिति पर गंभीर विचार करने की आवश्यकता है। किसी प्रकार का पूर्वाग्रह हमारे विचार में बाधक नहीं होना चाहिए। आदर्श किसी मनुष्य को आगे बढ़ने की अवश्य प्रेरणा देते हैं, किन्तु वस्तुस्थिति की हम उपेक्षा करेंगे, तो जो स्थिति आज कृषि-उत्पादन की है, वह शीघ्र दूर होने वाली नहीं। अच्छे बीज, अच्छा खाद, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था कृषि के लिए अनिवार्य हैं। इसके बाद स्थान आता है साख या सरल किश्तों पर ऋण का। आज सहकारी समितियों पर सरकार करोड़ों रु०-व्यय करती है, पर उसका उपयोग ठीक ढंग से नहीं होता। सब सह-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कारी कर्मचारी न तो सहानुभूतिशील होते हैं और न परिश्रमी। चतुर सम्पन्न इन समितियों का लाभ ले जाते हैं; गर्जमन्द किसान रह जाते हैं। सामुदायिक योजना के कर्मचारी जब तक बाबूगिरी छोड़कर किसानों में घुलमिल नहीं जाते, तब तक वे वस्तुतः किसानों के हृदय में सुधार की भावना उत्पन्न नहीं कर सकेंगे। कृषि-मंत्रालयों के कर्मचारी भी खेतों पर सर्दी गर्मी सहकर ही किसानों को अधिक लाभ पहुँचा सकते हैं। आज रासायनिक खाद पर बहुत बल दिया जा रहा है, पर इसके प्रयोग से पूर्व भिन्न-भिन्न भूमियों का परीक्षण अधिक आवश्यक है। एक ही किस्म की खाद सब भूमियों में काम नहीं दे सकती। एक जगह उससे लाभ होता है, दूसरी जगह वही फसल को नुकसान भी पहुँचा सकती है।

कृषि मंत्रालय फसल के निम्नतम भाव घोषित करने पर बल देता है। हमारी नम्र सम्मति में आज तो भाव स्वयं इतने ऊंचे हैं कि इस प्रश्न का अवसर ही पैदा नहीं होता। १-१॥ रुपया मन मूल्य ऊंचा रखने से किसान अधिक परिश्रमी हो उठेगा, हमें इससे सन्देह है। वह तो आज भी खूनपसीना एक करता है। उसे सुविधाएं दीजिये, शिक्षा दीजिये। मूल्य घोषणा का नारा अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए हैं। फिर मूल्य का ऊंचा निर्धारण हमारी सारी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। जोत की उच्चतम सीमा पर व संयुक्त सहकारी कृषि आदि पर भी व्यवहार की दृष्टि से विचार की आवश्यकता है। हमारा निवेदन यह है कि समस्त स्थिति पर आदर्श व व्यवहार दोनों का समन्वय करते हुए विचार करना होगा।

चौथी योजना का विशाल आकार

अभी तीसरी योजना के दो वर्ष ही पूर्ण हुए हैं, कि योजना आयोग चौथी योजना के निर्माण में लग गया है। किसी योजना का निर्माण आसान काम नहीं होता। इसमें वर्तमान साधनों, विकास की शनैः या तीव्र गति और अपनी सामर्थ्य आदि का ही विचार नहीं करना होता, बल्कि एक दूसरे पर आश्रित उत्पादनों की भी चिन्ता करनी पड़ती है। उदाहरणतः कागज या सीमेंट के उद्योग के लिए यह भी देखना होगा, कि कच्चा माल कहां-कहां से और कितनी मात्रा में उपलब्ध होता है; मशीनरी बनाने के लिए पर्याप्त लोहा और इस्पात किस मात्रा में और किस गति से मिल सकते हैं; उद्योग के लिए आवश्यक सामग्री—कच्चा माल और मशीनरी किस प्रकार सुविधा पूर्वक कम व्यय में यथा स्थान पहुँचाए जा सकते हैं और उद्योग के संचालन के लिए प्रदक्ष शिल्पी और श्रम तथा व्यवस्थापक भी सुलभ हैं या नहीं। बिजली या कोयले के द्वारा उद्योग संचालन शक्ति की प्राप्ति भी योजना निर्माताओं के लिए गम्भीर प्रश्न रहता है। इसी तरह विभिन्न उद्योगों के लिए कृषि उत्पादन की मात्रा ही नहीं देखी जाती, बल्कि कृषि के विकास के लिए आवश्यक सिंचाई तथा कृषि उपकरणों की प्राप्ति और कृषि के विनियोजन के लिए किसानों की आर्थिक सुविधाएं भी देखनी होंगी। इस तरह किसी उद्योग के लिए न जाने कितनी अवान्तर बातों का ध्यान करना पड़ता है, तब जाकर कोई योजना बन सकती है।

योजना आयोग भी चौथी योजना के लिए अभी से योजना के सभी पहलुओं पर विचार करने लगा है। एक अनुमान के अनुसार यह योजना १७० अरब रुपये की बनेगी अर्थात तीसरी योजना से भी ६६ अरब रुपये अधिक की। शायद इतनी महत्वाकांक्षापूर्ण योजना बनाने की उत्सुकता न भी होती किन्तु चीन के आक्रमण के कारण यह अब अनिवार्य-सा प्रतीत होने लगा है, कि देश का आर्थिक विकास और भी अधिक तेजी से किया जाय। सम्भवतः १९६४ के अन्त तक नई योजना का प्रारम्भिक स्वरूप अधिक स्पष्ट हो जायगा।

मशीनरी का आधुनिकीकरण

हमारे देश के आर्थिक विकास की जो अनेक आर्थिक समस्याएं बहुत जटिल हैं, उनमें से एक समस्या यह भी है, कि औद्योगिक विकास के लिए आधुनिकीकरण या रेशनलाइजेशन किया जाय या नहीं। रेशनलाइजेशन और आधुनिकीकरण के समर्थक जब इसमें उत्पादन व्यय की कमी और परिणामतः विभिन्न देशों के साथ प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता देखते हैं। तब इसके विरोधी इसमें बेकारी की वृद्धि देखते हैं। इसी लिए सरकार भी आधुनिकीकरण में तेजी से प्रोत्साहन देने में संकोच कर रही है। बम्बई की एक प्रसिद्ध वस्त्रोत्पादक कम्पनी बाम्बे डाइंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के अध्यक्ष श्री एन. एन. वाडिया ने आधु-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

निकीरण के पक्ष में अपनी कम्पनी का उदाहरण दिया है। पिछले १० वर्षों में इस कम्पनी ने ८॥ करोड़ रुपये की नई मशीनरी अपनी स्प्रिंग मिल में लगाई है।

श्री वाडिया कहते हैं "यह कहीं भी सबसे बड़ी इकाइयों में से एक होगी जिसमें केवल आटोमेटिक लूम हैं—२,१६० एक छतके नीचे। कताई और बुनाई विभागों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के अतिरिक्त, कम्पनी ने एक सबसे बड़ा और सबसे सुन्दर अन्तिम रूप देने वाला प्लांट लगाया है। कम्पनी के पास आधुनिक ढंग के कई प्लांट हैं जो रंगाई, छपाई और सनफोराइज करने वाले हैं और साथ ही सूत को ऊंचे दबाव पर रंगने वाला और मरसीराइज करने वाला प्लांट है। इसका परिणाम क्या है? उत्पादन बढ़ गया है, सूत के रूप में, १९५२ में २ करोड़ ६० लाख पौंड से बढ़कर १९६२ में ४ करोड़ १० लाख पौंड तक हो गया। हम अब प्रतिदिन औसतन ८० हजार पौंड प्रोसेस कर लेते हैं जबकि १९५२ में यह संख्या ३० हजार पौंड प्रतिदिन थी और शीघ्र ही १ लाख पौंड तक होने वाली है। दस वर्ष पहले श्रमिक ८ हजार थे, आज १२ हजार ५०० हैं, अर्थात् ५६ प्रतिशत की वृद्धि। पर इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय तथा यह है कि श्रमिकों की वृद्धि के साथ-साथ उनकी व्यक्तिगत अर्जनशक्ति भी बढ़ गयी है। स्वयंचालित करघा लगने से पहले बुनकर का मूल वेतन ८० रुपया प्रति मास था, जबकि अब वह इसी स्वयंचालित करघे पर २६५ रु० प्रति मास कमा रहा है, अर्थात लगभग तीन गुना अधिक। श्रमिकों का भाग्य इतना जाग गया है कि उनमें से कुछ अब आय-कर देने लगे हैं और समस्त श्रमिक १९६३-६४ के बजट में घोषित बाध्य बचत योजना के अन्तर्गत आ गये हैं।"

'इससे स्पष्ट है कि सरकारी प्रवक्ताओं और श्रम-संगठन के नेताओं द्वारा आधुनिकीकरण के बारे में जो आशंकाएं रोजगार और श्रमिकोंके कल्याण के बारे में प्रकट की गयी थीं, वे निराधार सिद्ध हो रही हैं।

कम्पनी के लगभग ५० फीसदी करघे निर्यात आदेशों को पूरा करने में लगे रहते हैं और इस कम्पनी द्वारा देशके लिए विदेशी मुद्रा अर्जन १० वर्ष पूर्व ३ करोड़ प्रतिवर्ष से बढ़कर १९६२ में ५ करोड़ रु० प्रति वर्ष हो गया है। पिछले ६ वर्षों में कम्पनी ने, वस्तुतः, ३२ करोड़ रु० मूल्य का विदेशी मुद्रा अर्जन किया है।"

श्री वाडिया का उपर्युक्त वक्तव्य अपने पक्ष का समर्थन करता है।

गांधी व गांधीवाद और श्री मालवीय

भारत के ईंधनमंत्री श्री केशवदेव मालवीय का समाजवाद का स्वरूप" शीर्षक से ३० मार्च के हिन्दी टाइम्स में एक लेख प्रकाशित हुआ है। गांधीवाद व गांधी जी से सम्बद्ध एक अंश यहां हम उद्धृत कर रहे हैं। वे लिखते हैं—

गांधीवादी-समाजवाद जैसी कोई स्पष्ट विचारधारा हमारे सामने कभी नहीं आई और वास्तव में गांधीवाद समाजवाद जैसी कोई चीज है भी नहीं। गांधीवाद और समाजवाद की अनेक मौलिक मान्यताएं दिखाई तो अवश्य पड़ती हैं लेकिन समाजवाद और गांधीवाद भिन्न विचार धारायें हैं। समाजवाद का स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय है जबकि गांधीवाद कुछ हिन्दू संस्कृति से प्रभावित है और कुछ मानवतावाद से। लेकिन साथ ही यह भी सत्य है कि इसमें सामन्तवादी व धार्मिक पुट भी अधिक मात्रा में हैं। इसका कारण यह है कि कई शताब्दियों से हमारे विचार सामन्तवादी ऐश्वर्य से प्रभावित रहे हैं और गांधीजी जनता को इन रूढ़िगत विचारों को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते थे। उनके सामने सबसे बड़ा लक्ष्य था, आजादी प्राप्त करना।

'बहुत माने में गांधी जी अन्तर्राष्ट्रीय थे पर वह जनता के स्तर और अंध-विश्वासों से बहुत आगे बढ़ कर बात नहीं करना चाहते थे। संसार के सभी सफल नेताओं का तरीका यही रहा है कि वे जनता के विचारों से थोड़ा ही आगे चल कर अपना काम करते रहे।'

यदि गांधीवादी विचारक सैद्धान्तिक दृष्टि से कुछ विचार प्रकट करेंगे, तो हम उन्हें सहर्ष स्थान देंगे।

भारतीय वस्त्र के विरुद्ध प्रचार

लंकाशायर के मिल मालिकों की ओर से यह मिथ्या प्रचार किया जा रहा है कि भारत का कपड़ा हल्का और सस्ता होता है और अगर इसे उन्नत देशों में निर्बाध आने दिया गया तो वहां की घरेलू कपड़ा मिलों का नाश हो जाएगा। इस प्रचार का उद्देश्य भारतीय वस्त्र के निर्यात पर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रतिबन्ध लगाना है ताकि वे अपना महंगा कपड़ा मनमाने मूल्य पर बेच सकें। इस प्रचार का परिणाम यह हुआ कि यूरोप के सांझा बाजार देशों में भारत को पर्याप्त रियायत न मिलने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका में भी भारतीय वस्त्र के आयात पर रोक लगाने के कदम उठाये जा रहे हैं।

तीसरी योजना में भारत के वस्त्र निर्यात का लक्ष्य ८० करोड़ गज है, जो कुल उत्पादन का केवल १० प्रतिशत है। इसमें भारत की विश्व के गोदाम भरने की भावना एकदम नहीं है। इस निर्यात के द्वारा भारत का एकमात्र लक्ष्य न्यूयतम आवश्यक विदेशी मुद्रा का अर्जन करते हुए अपने अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करना है। अत्यन्त उन्नत देशों के कपड़े के साथ भारत के कपड़े की किसी प्रकार की प्रति स्पर्द्धा नहीं है। सस्तेपन की युक्ति देकर भारत के निर्यात पर जो देश प्रतिबन्ध लगाते हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि भारतीय वस्त्र की कुछ किस्मों के मूल्य चीन, फारमोसा, हांगकांग, युगोस्लाविया, टर्की, जापान और फ्रांस तक से अधिक हैं।

भारत की कपड़ा मिलों की आन्तरिक दशा क्या है, यह कुछ आश्चर्यजनक आंकड़ों से स्पष्ट हो जाएगा। मिलों में लगे कुल तकुओं में लगभग प्रत्येक तीसरा तकुआ ऐसा है, जो ४० वर्ष पुराना है और केवल ८ प्रतिशत आटोमेटिक लूम हैं, जबकि यूरोप में ६० प्रतिशत और अमेरिका में लगभग सम्पूर्ण १०० प्रतिशत ही आटोमेटिक हैं। भारत की कपड़ा मिलें, औसतन, प्रति १ हजार तकुओं पर १०.६८ श्रमिक और प्रति १०० सांचों पर ७०.१२ श्रमिक लगाती हैं जबकि यूरोप में इस मद की संख्याएं बड़ी कठिनता से क्रमशः १-८ और १५.० हैं। स्पिनरों की औसतन मासिक मजदूरी यूरोप में ३७.५० पौंड है और भारत में १०.५ पौंड है और बुनकरों की यूरोप में ४५ पौंड और भारत में १३ पौंड है। किन्तु उत्पादकता के बहुत कम होने के कारण मासिक मजदूरी के हिसाब से निम्न परिणाम निकलते हैं—

	भारत (पौंड)	यूरोप (पौंड)
प्रति १००० तकुए	१११-२¾	६७.१०
प्रति १०० लूम	६००	६७५

दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि भारत में मजदूरी का खर्च यूरोप की अपेक्षा ६० प्रतिशत बुनने में और ३३ प्रतिशत कातने में अधिक है। इससे भी अधिक घाटे की बात यह है कि भारत को कपास नहीं मिलती है। विश्व बाजार के दर से भारत की कपास अधिक महंगी है। भारत के लिए कपड़े का निर्यात लोकतंत्रीय पद्धति के साथ अपनी आर्थिक सुदृढ़ता के लिए अनिवार्य आवश्यकता है।

स्वावलम्बन की प्रवृत्ति

देश के विभिन्न राज्यों में उद्योग की दृष्टि से भी स्वावलम्बन की आकांक्षा बढ़ रही है। प्रत्येक राज्य अपने को उद्योग की दृष्टि से स्वावलम्बी बना रहा है। इसका एक उदाहरण पंजाब सरकार का वह निश्चय है, जिसके अनुसार पंजाब में लोह उद्योग को विकसित करने की योजनायें बन रही हैं। पंजाब सरकार राज्य के हरियाणा क्षेत्र में एक लाख टन कच्चा लोहा प्रतिवर्ष तैयार करने की क्षमता का एक कारखाना और ढाई लाख किलोवाटका ताप बिजली घर बनायगी। पूरी योजना पर करीब ६ करोड़ रुपया खर्च होगा। इस कारखाने और बिजली घर के लिए मशीनों और तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए पंजाब सरकार कुछ ब्रिटिश और यूगोस्लाव फर्मों से बातचीत कर रही है।

एक प्रवक्ता के अनुसार एक कच्चा लोहा तैयार करने के लिए पंजाब के महेन्द्रगढ़ जिले के शुष्क क्षेत्र में मिले करीब ३०-४० लाख टन लोह खनिज का उपयोग किया जाएगा। पंजाब सरकार का डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से एक इस्पात ढलाई कारखाना लगाने का भी विचार है। यह दिल्ली के निकट सोनीपत के पास कहीं बनाया जाएगा। इसके निर्माण में अमरीका की एक फर्म का सहयोग प्राप्त किया जाएगा।

आज प्रत्येक राज्य की स्वावलम्बन की भावना स्वागत योग्य है। आज प्रत्येक देश भी भारत की भान्ति स्वावलम्बी होने का प्रयत्न कर रहा है और देश के विभिन्न भाग भी अपने समस्त देश की इकाई की अपेक्षा अपने राज्य की इकाई को अधिक महत्व देना पसन्द करते हैं। इसी प्रवृत्ति को यदि आगे बढ़ने दिया जाय, तो राज्य के विभिन्न क्षेत्र और जिले भी स्वावलम्बी होने का प्रयत्न करेंगे। इससे जहां विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा वहां कुछ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं में दो समस्यायें मुख्य हैं। एक तो यह है कि प्रत्येक राज्य और प्रत्येक क्षेत्र स्वावलम्बी बनकर अपने देश के ही दूसरे भाग पर अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए निर्भरता छोड़ देगा और परिणामतः देश में एक सुदृढ़ एकता की भावना कुछ कमजोर पड़ सकती है। दूसरी समस्या यह उत्पन्न हो सकती है, कि देश का प्रत्येक भाग अपने-अपने स्वावलम्बन की भावना में पड़कर यह भूल सकता है, किसी उद्योग का विकास करने के लिए वहां अधिक सुविधाएं हैं, हैं भी या नहीं ? और कहीं वहां उत्पादन-व्यय तो नहीं बढ़ जायगा। इस समस्या के दूसरे पहलू भी कुछ कम विचारणीय नहीं हैं। घोर केन्द्रीयकरण की भी अपनी कुछ भारी त्रुटियां हैं, इसलिए इस प्रश्न के सब पहलुओं पर अधिक विचार की आवश्यकता है।

ईंधन का दुरुपयोग

उद्योग का उत्पादन व्यय कम करने पर आजकल बहुत बल दिया जा रहा है। जब तक उत्पादन व्यय कम नहीं होगा, तब तक हम अपनी चीजों को कम कीमत पर नहीं बेच सकेंगे और फलतः निर्यात व्यापार में हम दूसरे देशों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इन २-३ वर्षों में उद्योग ने यह अनुभव किया है, कि बिजली और कोयले की ताकत की कमी के कारण अनेक उद्योग कठिनाई में पड़े हुए हैं। और उनका न केवल उत्पादन ही कम हो रहा है, बल्कि उत्पादन व्यय भी बढ़ रहा है। बिजली और कोयले का उत्पादन व्यय में काफी बड़ा भाग होता है। भारत सरकार ने दो विशेषज्ञों को भारतीय उद्योग में ईन्धन के समुचित प्रयोग के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए ब्रिटेन से बुलाया था। इन दो विशेषज्ञों ने ६० उद्योगों में खपने वाले ईन्धन की जांच पड़ताल की है। इन विशेषज्ञों की सम्मति यह है, कि अनेक दूषित पद्धतियों के कारण ईन्धन का बहुत दुरुपयोग होता है। कुछ उद्योग तो ऐसे हैं, जिनमें ५०% ईन्धन की बचत हो सकती है। यदि कोयले का समुचित प्रयोग किया जाय तो कोयले के अधिक मूल्यों का भी उत्पादन व्यय पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आज से २० वर्ष पूर्व अमेरिका में भी यह अनुभव किया गया था कि वहां ईन्धन का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए वहां ईन्धन के अधिकतम उपयोग की योजना बनाई गई। उक्त विशेषज्ञों ने भी भारतीय उद्योग और सरकार को यह परामर्श दिया है, कि भाप प्रयुक्त करने वाले संयन्त्रों को अधिक सुधारा जाय, ताकि कोयले की भाप का अपव्यय न हो सके। कुछ तकनीक परामर्श इस कार्य के लिए दिए गए हैं।

समाजवाद क्या है ?

समाजवादी गठन के सम्बन्ध में एक संगोष्ठी में विचार प्रकट करते हुए प्रधान मंत्री पं० नेहरू ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र व राज्य क्षेत्र का विकास मात्र समाजवाद समाज के पर्याप वाचक नहीं हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका सामाजिक और आर्थिक जीवन का नियंत्रण करने के लिए अमेरिका में अधिक नियम और कानून हैं, पर अमेरिका को कोई भी समाजवादी देश नहीं कह सकता।

यह दृष्टि हमें अपने सामने रखनी चाहिए। देश या समाज का अर्थ केवल सरकारी संगठन नहीं है। जिस अधिक व्यक्ति उद्योगों का स्वामित्व और संचालन हो और जिस स्थिति में वह अपना पृथक् व्यक्तित्व भी स्थिर रख सकें और लाभ का अधिकाधिक वितरण हो सके, और ऐसी व्यवस्था से जनता के बहुत बड़े भाग को—निम्न भाग को भी—अपनी भौतिक आवश्यकता पूर्ण करने का अवसर मिल सके, वही व्यवस्था समाजवाद होगी और इसके लिए बिना किसी विवेक के सब उद्योगों का राष्ट्रीयकरण अनिवार्य नहीं है। सरकारी उद्योगों में आज विषमता और शोषण का अभाव नहीं है। देश के विभिन्न मजदूर नेता स्वयं सरकारी उद्योगों और सेवाओं में जब तब हड़ताल कराने की जोड़ तोड़ करते रहते हैं। वर्षों में तो श्रमिक संगठनों में यह आवाज भी जोरों से उठने लगी है, कि सार्वजनिक उद्योगों में कारखाना कानून का ठीक तरह से पालन नहीं होता और न त्रिपक्षीय समझौतों का। सरकार का तो यह कर्तव्य है कि वह उद्योगों के स्वयं संचालन पर जितना ध्यान दे, उससे अधिक शोषण को रोकने, अधिकाधिक समान वितरण करने और अनुचित लाभ पर अंकुश लगाने की ओर ध्यान दे। तभी हम समाजवाद की दिशा में कुछ प्रगति कर सकेंगे।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१९६२ में भारत का निर्यात व्यापार

आर्थिक विकास के लिए आयात की अपेक्षा निर्यात का अधिक होना आवश्यक है। विदेशी मुद्रा अर्जन के मुख्य स्रोत निर्यात ही हैं, पर भारत के निर्यात में क्रमिक ह्रास का आना निश्चय ही चिन्ता का विषय है। यह भी आश्चर्य की बात है कि सोवियत गुट के देशों से भारत का निर्यात व्यापार बढ़ रहा है परन्तु अमरीका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी इत्यादि से कम हो रहा है। ऐसा क्यों ? कारणों का विश्लेषण पढ़िये:—

यह बात तो अब सब कोई जान गये हैं कि जिस तेजी के साथ हमारी विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ रही है, हमारा निर्यात उससे पिछड़ गया है। शायद कुछ लोग यह समझते हैं कि श्री मनुभाई शाह के मंत्रित्व में केन्द्र में, लगभग एक वर्ष पूर्व, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारका नया मन्त्रालय स्थापित हो जाने और बाद में 'बोर्ड आफ ट्रेड' कायम हो जाने से भारत ने विश्व के व्यापार में कहीं पैर जमा लिए हों, पर यह आशा अभी तक अधूरी ही पड़ी है। इसके विपरीत निर्यात व्यापार में भारत कोई प्रभाव पैदा नहीं कर सका है। प्रतिमास यह आशा बंधाई जाती थी कि अच्छे परिणाम निकलेंगे, पर इसमें सफलता नहीं मिली। जनवरी में निर्यात के आंकड़े अभी प्रकाशित हुए हैं जिनकी कुल राशि ६२.५ करोड़ रु० है, १९६२ के जनवरी मास से केवल ५.५ करोड़ रु० अधिक! १९६२-६३ के वित्तीय वर्ष (अप्रैल १९६२ से जनवरी १९६३ तक) के १० मास में कुल निर्यात ५७२.५ करोड़ रु० हुआ, पिछले वर्ष से केवल ३ प्रतिशत अधिक अथवा १६०५ करोड़ रु०। इस समय, औसतन, वार्षिक दर से निर्यात ६८७ करोड़ रु० तक हो रहा है, जो बोर्ड आफ ट्रेड द्वारा १९६२-६३ के लिए निर्धारित लक्ष्य से ३३ करोड़ रु० कम है। १९६१-६२ में कृषि और औद्योगिक उत्पादन में मन्दगति होने से और उत्पादन में लागत खर्च अधिक होने से निर्यात में ह्रास आ रहा है।

तीसरी योजना के लक्ष्य

तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में कुल निर्यात १,३५२ करोड़ रु० के होने थे, जिससे बाकी तीन वर्षों के लिए २,३४८ करोड़ रु० से २,४४८ करोड़ रु० की लक्ष्य पूर्ति रह जाती, जबकि तीसरी योजना के कुल निर्यात-लक्ष्य ३७००-३८०० करोड़ रु० के हैं। इसका मतलब यह है कि योजना के आगामी तीन वर्षों में प्रतिवर्ष निर्यात लक्ष्य ७८२ करोड़ रु० से ८१६ करोड़ रु० तक का है, अर्थात्, पहले दो वर्षों में जो उपलब्धि हुई है उससे १०० करोड़ रु० अधिक। क्या भारत इस लक्ष्य तक पहुंच सकेगा ? अभी तक जो स्थिति है, वह आशाजनक नहीं है। अगर स्थिति बदल जाए तो सचमुच यह जादू होगा। पर भारत को यह जादू करना ही पड़ेगा, अगर उसे अपनी बाहर की साख बिना आर्थिक विकास को क्षति पहुंचाये।

निर्यात में मन्द गति होने से ही आयात में समय-समय पर कटौती करनी पड़ती है। १९६२-६३ के पहले १० मासों में आयात केवल ८०० करोड़ रु० के थे लगभग उतने ही, जितने १९६१-६२ में थे, बावजूद विभिन्न उद्योगों द्वारा कच्चे माल, भंडार, फालतू कल-पुर्जे और पूंजीगत सामान की बढ़ती हुई मांग के—,आयात स्थिर थे जबकि निर्यात बहुत कम बढ़ते थे जिससे प्रतिकूल व्यापार की भेद रेखा कम होती गयी थी।

विदेशी-मुद्रा-कोष में ह्रास

वस्तुओं के अनुसार जनवरी १९६३ के निर्यात का ब्यौरा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है पर दिसम्बर १९६२ तक के आंकड़े तो उपलब्ध हैं जिनसे वर्ष के भीतर निर्यात के साधनों का परिचय मिल जाता है। भारत सरकार के कमर्शियल इंटेलिजेन्स और स्टेटिस्टिक्स विभाग, कलकत्ता, द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार १९६२ में कुल निर्यात—पुनः निर्यात सहित—६७४ करोड़ रु० का था, १९६१ से मात्र २ प्रतिशत (१४ करोड़ रु०) अधिक—। यह वृद्धि बहुत ही कम है विशेषतः इस बात का ध्यान

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रखते हुए कि विकास के लिए और सुरक्षा के लिए आयात की आवश्यकताएं निरन्तर बढ़ रही है। इसी का यह परिणाम हुआ कि भारत को १९६२ में ५३ करोड़ रु० तक विदेशी मुद्रा कोष में से निकालना पड़ा जिससे अब केवल ९७ करोड़ रु० बकाया रह गया है, जबकि मित्र देशों से उदार सहायता भी प्राप्त होती रही। निम्न तालिका से १९६२ में भारत के निर्यात—आयात के रुझान और व्यापार—सन्तुलन पिछले वर्ष की तुलना में ज्ञात होंगे—

लाख रुपयों में

	१९६२	१९६१
आयात	१,०९२,०८	१,०७८,०९
निर्यात	६७३,६०	६६०,०९
व्यापार का सन्तुलन	—३८८,४८	—४१७,९७

विपरीत व्यापार सन्तुलन में यद्यपि कुछ कमी आयी पर यह अभी तक निर्यात व्यापार के ५८ प्रतिशत के तुल्य है। इस स्थितिके समान ही चिन्ताजनक बात यह है कि निर्यात की कई चीजों के इकाई मूल्य में कमी आ गयी है, विशेषतः, मसाले, तम्बाखू, चाय, कच्चा मैंगनीज़ इत्यादि। यह ध्यान देने योग्य है कि निर्यात की वस्तुओं की सामान्य राशि (आधार—१९५८=१००) १९६१ में १०५ से बढ़कर १९६२ में (जनवरी से अक्तूबर तक) १०८ हो गयी, पर समूचा—इकाई—मूल्य १११ से गिरकर १०६.५ रह गया। इससे पता चलता है कि अन्य देशों की ओर से प्रतिस्पर्द्धा का दबाव जोर से पड़ रहा है। कुछ संतोष की बात यह है कि भारत के आयात, प्रायः, उन वस्तुओं के हैं जिनके विश्व मूल्य पिछले कुछ वर्षों से कम हो रहे हैं।

व्यापार का सन्तुलन

निम्नलिखित तालिका से पिछले चार वर्षों में भारत के व्यापार का सन्तुलन का पता चलता है—

(आधार : १९५५=१००

	१९६२ जनवरी अक्तूबर	१९६१	१९६०	१९५९
निर्यात के परिमाण का निर्देशक	१०८	१०५	१०१	१०७
निर्यात का इकाई—मूल्य	१०७	१११	१०९	१००
आयात के परिमाण का निर्देशक	११७	१११	१०७	११०
आयात का इकाई-मूल्य-निर्देशक	९४	९९	९८	९३
व्यापार का सन्तुलन	११३	११२	१११	१०७

१९६२ के निर्यात में वृद्धि कुछ चीजों के कारण हुई, विशेषतः खल, जूटका सामान और तम्बाखू, वनस्पति तेल, कच्ची खालें और चमड़े, अभ्रक, कच्चा लोहा। इसके विपरीत भारत के अन्य परम्परागत निर्यातों को धक्का लगा, जैसे चाय, काफी, सूती वस्त्र, चमड़ा, कच्चा मैंगनीज, कच्ची कपास, लोहा और इस्पात के टुकड़े, ऊन, काजू, मछली और जरूरी तेल। बाइसिकल, साइकल पुर्जे, छत्तके पंखे, औषधियां, इस्पात, लोहा, सीमेंट और इमारती सामान का भी निर्यात कम हुआ।

इसलिए यह चिन्ता का विषय है कि कई परम्परागत निर्यात के सामान में भारत अपने पुराने और अच्छे कायम किये हुए बाजारों में से खिसक रहा है। अगर सोवियत गुट के देशों की ओर से माल न मंगाया जाता तो स्थिति ज्यादा खराब हो जाती और १९६२ के कुल निर्यात को धक्का लगता। वस्तुतः, भारत का निर्यात ब्रिटेन, अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी और अफ्रीका—एशिया के अधिकांश देशों को १९६२ में पिछले वर्षों की अपेक्षा कम ही हुआ।

जूट का सर्वाधिक निर्यात

सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जन करने में, पहले की भांति, जूट का सबसे प्रथम स्थान रहा। १९६२ में जूट के दाम, १९६१ की तुलना में, गिर गये थे। अधिकांश औद्योगिक देशों ने १९६२ के न्यून-मूल्यों में जूट खरीदी। १९६१-६२ में भारत में जूट की खेती अच्छी हुई थी जिससे इन देशों की मांग पूरी हो सकी।

विदेशी मुद्रा अर्जन में सहायता देने वाली दूसरी मुख्य वस्तु तम्बाकू है। १९६१ में ४ करोड़ रु० से बढ़कर १९६२ में १८.६८ करोड़ रु० तक इसका निर्यात पहुँच गया। रूस और सोवियत गुट के देशों से इसकी विशेष मांग आयी।

खली और तेल

जूट और तम्बाकू की अपेक्षा इन दोनों में करीब ७० प्रतिशत वृद्धि हुई। पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लावाकिया और पूर्वी जर्मनी में विशेष निर्यात हुआ।

वनस्पति तेल और मूंगफली तेल में विशेष तेजी

(शेष पृष्ठ १७०पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उद्योग का विकास कैसे हो ?

अ० भा० निर्माता संघ का अध्यक्षीय भाषण

श्री पी० वी० महता

उचित व्यापार कर्म मण्डल की स्थापना : राज्य व्यक्तिगत भावना को छोड़ देश का साथ दें : उत्पादन शुल्क और बिक्रीकर सम्मिलित हों : विदेशी मुद्रा की समस्या : भारत प्रशान्त क्षेत्र सहयोग।

वर्त्तमान राष्ट्रीय संकट में उद्योगपति सरकार के साथ पूर्ण सहयोग करने को तैयार हैं। यह ठीक है कि व्यापारी-वर्ग में कुछ काली भेड़ें भी हैं, पर अधिकांश व्यापारियों ने सरकार को पूर्ण सहयोग दिया है। इस संस्था ने ३७ अन्य संस्थाओं के साथ यह प्रण किया था कि ईमानदारी से व्यापार करेगी और इसे कार्यान्वित करने पर दृष्टि रखी जाएगी।

कुछ स्वार्थी लोग समूचे व्यापारिक-वर्गके विरुद्ध द्वेष प्रचार करते रहते हैं जिससे उद्योग और जनता के बीच स्वस्थ सम्बन्ध पैदा होने में बाधा पड़ती है। इसलिए प्रत्येक महत्वपूर्ण उद्योग और व्यापार में—उचित-व्यापार क्रिया-मंडल' (फेयर ट्रेड प्रेक्टिस बोर्ड) स्थापित किया जाए, जो यह देखे कि उसका प्रत्येक सदस्य ईमानदारी के नियमों का पालन करे। अब वह समय नहीं रहा, जब उपभोक्ता का शोषण किया जा सके। कोई व्यापारी इस महंगे सौदे को चला नहीं सकता है, क्योंकि प्रश्न केवल ग्राहक को प्राप्त करना नहीं किन्तु भविष्य के लिए उसे कायम रखना है। इसलिए आवश्यक है कि उत्पादन बढ़िया हो और सामान की पूर्ति प्रतिस्पर्द्धा के मूल्यों पर हो।

पूंजी लगाने वाले यह आशा करते हैं कि उसका उचित प्रतिफल मिले। वस्तुतः लाभ ही विकास का प्राण है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में उद्योगपति कुछ नहीं कर सकते, जैसे केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय कर, तथा कर्ज पर सूद की अदायगी। इसका विकल्प यही है कि क्षमता बढ़ायी जाए और लागत कम की जाए।

अ० भा० निर्माता संघ का श्रमिकों के प्रति दृष्टिकोण उदार रहा है। सरकारी कानून बनाने से पहले ही कल्याणकारी प्रवृत्तियां उद्योगों में जारी कर दी गयी थीं। उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरणादायक योजनाओं को भी प्रारम्भ करना चाहिए।

आर्थिक साधनों के संग्रह के लिए वित्तमंत्री द्वारा उठाये जा रहे साहसिक कदम सराहनीय हैं, पर सरकार को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि अन्तिम लक्ष्य देश की वित्तीय व्यवस्था का विकास और पुष्टि ही है। यह खेद की बात है कि कुछ राज्यों में उद्योग के प्रति उदासीनता का रुख अपनाया जा रहा है। ये राज्य ऐसे उपायों का अवलम्बन कर सकते थे, जिससे पहले से ही करों के बोझ से दबे हुए उद्योग पर अधिक कर लगाने के दायित्व से वित्तमंत्री को बचा लेते। कई वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर उत्पादन शुल्क और बिक्री कर संयुक्त रूप से लग सकते हैं। इससे बिक्री कर में जो बड़ी मात्रा में स्रवण होता है, वह बच सकता है। राज्य सरकारें ही इस सुझाव का विरोध कर रही हैं। उनसे अनुरोध है कि वह इस पर पुनः विचार करें और केवल अपने राज्य के लाभ की दृष्टि से न सोचकर सम्पूर्ण राष्ट्र हित की भावना से सोचें।

मूल सिद्धान्त पर कुठाराघात

अर्थशास्त्र का यह सुविदित सिद्धान्त है कि स्वयं स्फूर्त्त वित्तीय व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उसी से प्रादुर्भूत आय से उसका पोषण होना चाहिए। यहां नए बजट में लगाया गया अधिलाभ कर इस सिद्धान्त पर ही मूलाघात करता है और निजी क्षेत्र के लिए अति आवश्यक पूंजी प्राप्त करने में बाधा डालता है। इससे लाभ दोबारा पूंजी में नहीं लग सकेंगे, पूंजी लगाने वालों को विश्वास नहीं मिलेगा और विदेशी पूंजी के आगमन में रुकावट पड़ेगी। सरकार को संघ की प्रार्थना पर निर्णय करने से पहले पुनः विचार करना चाहिए।

प्रशासन में मितव्ययिता की बड़ी आवश्यकता है और योजना से बाहर के अनावश्यक खर्चों को बन्द किया जाए। योजना क्षेत्र से बाहर के खर्च बढ़ रहे हैं और करों से प्राप्त अधिकांश राजस्व उन्हीं पर खर्च हो जाता है।

विदेशी मुद्रा की प्राप्ति को उत्साहित करने के लिए विदेशों में स्थित भारतीयों को प्रेरणा दी जानी चाहिए कि वे अपना अर्जित धन इस देश में लायें। इसमें जो बाधाएं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हों, उन सबका निराकरण होना चाहिए। इससे करोड़ों रु० की प्राप्ति देश को होगी। देश के भौतिक उत्पादन-साधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग होना चाहिए ताकि उनसे अधिकतम फल-प्राप्ति हो।

कुछ सुझाव

अमेरिका के अतिरिक्त अन्य देशों से आयात की सुविधा के लिए एक ऐसा चक्रशील कोष स्थापित किया जाए, जिससे चालू रहने वाले आयात की वित्तीय व्यवस्था हो सके, जैसा कि मुदलियर कमेटी ने अपनी सिफारिशों में कहा है। 'एड इंडिया क्लब' की आगामी बैठक के अवसर पर सरकार को यह विषय उठाकर सहायता प्राप्त करनी चाहिए। मध्यवर्त्ती और लघु उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पृथक् कोष स्थापित किया जाना चाहिए। योजना में तकनीकी शिक्षा के लिए अधिक राशि रखी जानी चाहिए। पालिटेकनिकल स्कूल अधिक संख्या में जारी किये जाएं। उद्योग और शिक्षण संस्थाओं में निकट सम्पर्क हो, ताकि उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा सके।

सड़क और जल परिवहन के विकास पर अधिक ध्यान देना होगा। जल-परिवहन पर अभी तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है यद्यपि देश में नौका चलने वाली नदियां और लम्बा समुद्र तट है। जहाजरानी के लिए ४९ प्रतिशत विदेशी सहयोग प्राप्त करना ठीक होगा। इस सम्बन्ध में भारत प्रशान्त क्षेत्र के पारस्परिक सहयोग को बढ़ाने के लिए मनिला सम्मेलन ने जो सुझाव दिये हैं वे स्वागत योग्य हैं।

भारत को पहल करके अन्य देशों के साथ सांझे उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से निम्न कदम उठाने चाहिए—

(१) उनके उत्पादनों की बाजार व्यवस्था और आपसी प्रतियोगिता का निराकरण (२) सम्मिलित व्यापार में वृद्धि ताकि उनके अपने क्षेत्र में हमारा न्यायसंगत और वृद्धिशील अंश रहे (३) उस क्षेत्र के कच्चे माल का इस प्रकार अधिक प्रयोग, जिससे क्षेत्र के भीतर ही पक्का माल तैयार हो सके (४) विदेशी मुद्रा के स्रोतों का एकीकरण और ऐसी संस्था का निर्माण जिससे किसी देश की विदेशी मुद्रा की दिक्कत को हल किया जा सके।

चीन के आक्रमण से उत्पन्न संकटकाल से लाभ उठाकर भारत के नव-निर्माण की दिशा में देश के सभी वर्गों को एक साथ अग्रसर होना चाहिए। ● ●

(पृष्ठ १६८ का शेष)

आयी। स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने मूंगफली के तेल के समुद्र पार से कुछ आदेश प्राप्त किये। चीनी का निर्यात भी पिछले साल बढ़ा। रंडी और तिल के निर्यात में भी कुछ वृद्धि हुई। कच्चा चमड़ा और खाल के निर्यात में करीब दो करोड़ रु० की बढ़ती हुई।

चाय और सूती कपड़े को धक्का

पिछले वर्ष जिन चीजों के निर्यात में कमी आयी वे थीं चाय, काफी और सूती कपड़े। चाय की कमी का बड़ा कारण ब्रिटेन के बाजार में लंका से बढ़ रही प्रतियोगिता है। ब्राजिल व अन्य देशों में काफी का स्टाक पड़ा होने से भारत की काफी की मांग कम हो गयी।

सूती कपड़े के निर्यात में कमी आना सबसे अधिक चिन्ता का कारण है। पिछले कई वर्षों से इस कमी के लक्षण प्रकट हो रहे थे। इसके दो बड़े कारण हैं, पहला विश्व बाजार में उग्र प्रतियोगिता और दूसरा भारत में लागत खर्च अधिक तथा उत्पादन में न्यूनता। कच्ची मैंगनीज, कच्ची कपास, रासायनिक पदार्थ, इंजिनीयरिंग का हल्का सामान—इनके निर्यात में भी कमी आयी। अधिक लागत और कच्चे माल की कमी—ये दो इसके मुख्य कारण थे।

सोवियत गुट और पश्चिमी देश

भारत के विदेशी ग्राहकों में सोवियत गुट और यूगोस्लाविया ने १९६२ में १३ प्रतिशत माल खरीदा जब कि १९६१ में केवल ८ प्रतिशत था। कनाडा और आस्ट्रेलिया ने भी पिछले वर्ष से कुछ अधिक खरीदा। ब्रिटेन में निर्यात काफी कम हुआ। स्वीडन और डेनमार्क को छोड़ सांझे बाजार के देशों में निर्यात कम हुआ और पश्चिम जर्मनी के साथ भारत का भारी प्रतिकूल व्यापार चला आ रहा है। अमेरिका में भी निर्यात की मात्रा में कमी आयी। इसी प्रकार जापान सहित अफ्रीका एशियायी देशों ने भी भारत से कम माल खरीदा, अफगानिस्तान, ईरान ईराक, मिस्र, हांगकांग और टांगानाइका को छोड़कर। इन देशों ने कुछ अधिक खरीदा। यहां यह उल्लेखनीय है कि इंडोनेशिया, बर्मा और लंका के आर्थिक सम्बन्ध चीन के साथ अधिक गहरे हो रहे हैं। इस अन्तः क्षेत्रीय व्यापार में कमी आना भारत के लिए चिन्ता का विषय है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देश की रक्षा के लिए औद्योगिक विकास की प्रगति

ले०—सव्यसाची

चीन के अचानक हमले के लिए भारत तैयार नहीं था, लेकिन हमारे यहां ऐसे उद्योग स्थापित हो चुके थे कि हम शीघ्र युद्ध की तैयारी कर सकें। आजकल के युद्ध में केवल हथियारों से लड़ाई नहीं होती। जो देश जितना अधिक उत्पादन करता है, उतनी ही युद्ध में विजय की सम्भावना बढ़ती है। पिछले महायुद्ध में यह बात अच्छी तरह प्रमाणित हो गई। युद्ध जीतने के लिए देश को अपना आर्थिक संगठन करना होता है और अपने सभी साधनों का भरपूर उपयोग करना जरूरी होता है।

वैसे तो युद्ध जीतने के लिए हर क्षेत्र में तेजी से काम करना जरूरी है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र का विकास और संगठन सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि इसी से हथियार, यातायात और संचार के साधन मिलते हैं। दो पंचवर्षीय योजनाओं पर चलने से भारत की आर्थिक स्थिति काफी सुधरी है।

दुगना औद्योगिक उत्पादन

पहली और दूसरी योजना की अवधि में, यानी १९६०-६१ तक भारत में औद्योगिक उत्पादन ९४ प्र० श० बढ़ गया। नये-नये उद्योग खुलते जा रहे हैं जिनके आंकड़े नहीं संकलित हो सकते। अतः वास्तव में औद्योगिक उत्पादन १०० प्र० श० से भी अधिक बढ़ा। १९६० की तुलना में १९६१ में (१९५६ आधार : १०० मानें) औद्योगिक उत्पादन का सूचक अंक १० अंक बढ़ गया। जनवरी-अक्टूबर, १९६२ का सूचक अंक, १९६१ की इस अवधि से १० अंक और बढ़ गया और सूचक अंक १४७ हो गयी।

१० वर्ष की इस अवधि में औद्योगिक उत्पादन ही नहीं बढ़ा, बल्कि अनेक तरह के उद्योग भी कायम हुए, खासकर दूसरी योजना की अवधि में, इस बीच १० लाख टन क्षमता के तीन नये सरकारी इस्पात कारखाने खुले, २ गैर सरकारी इस्पात कारखानों की क्षमता भी दुगनी हो गई।

भारी उद्योगों की स्थापना

बिजली के भारी सामान, भारी मशीनी औजार, और भारी मशीनों के तथा अन्य इंजीनियरी के कारखानों का आरम्भ हुआ। सीमेंट और कागज बनाने की मशीनें भी देश में ही बनने लगीं। रासायनिक उद्योगों में भी काफी प्रगति हुई। नाइट्रोजनी उर्वरक, कास्टिक सोडा, सोडाएश और गंधक के तेजाब का उत्पादन काफी बढ़ गया और यूरिया, अमोनियम फास्फेट, पेनिसिलीन, नकली रेशे, विस्फोटक, पोलिथीलीन, अखबारी कागज और रंग भी बनने लगा।

साइकिल, सिलाई मशीनें, टेलीफोन, बिजली का सामान, सूती कपड़ा और चीनी कारखानों की मशीनों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। कारखानों के मजदूरों को नये हुनर सिखाए गए। उद्योगों में प्रशिक्षित प्रबन्धकों की संख्या भी बढ़ रही है। इन सबसे भारत की औद्योगिक स्थिति इतनी अच्छी हो गई है कि रक्षा के अधिकांश सामान हम अब देश में ही बना रहे हैं।

लोहा और इस्पात, बड़े उद्योगों के आधार हैं। अलमुनियम तांबा, जस्ता और सीसा आदि धातुएं हथियार और अन्य सैनिक सामान बनाने में काम आती हैं, सीमेंट भी अनेक कामों में जरूरी होता है। इनका और अन्य कई इंजीनियरी और रासायनिक उद्योगों का वर्तमान संकट में बड़ा महत्व है। सैनिक सामान के अलावा लोगों की आवश्यकता की चीजें भी आवश्यक हैं, जैसे दवा आदि। रबड़, कपड़ा और रेयन पैराशूट आदि बनाने के काम आते हैं। ऊनी कपड़े भी जरूरी होते हैं।

भारत में लगभग ये सब सामान बनते हैं और अन्य सामान भी आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसके लिए हमें तीसरी योजना में तनिक परिवर्तन भर करना होगा।

नीचे दी गई तालिका में भारत के कुछ प्रमुख उद्योगों के १९५०-१९६० और १९६१ के उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रमुख उद्योगों में उत्पादन

	१९५०	१९६०	१९६१
१—खान :			
कोयला (१० लाख टन)	३२.५	५२.६	५६.१
खनिज लोहा ,,	३.७	१०.७	१२.१
२—धातु उद्योग :			
लोहा ,,	१.५९	४.१५	४.९६
इस्पात ,,	१.०२	२.२१	२.८५
अलमुनियम (हजार टन)	३.७	१८.४	१८.४
तांबा ,,	६.७	७.०	८.७
३—मेकेनिकल इंजीनियरी उद्योग :			
इस्पात की ढली चीजें (हजार टनों में)		३५.५	३७.५
मशीनी औजार (दाम १० लाख रु० में)	२.७	६०.२	७६.१
बिजली के पम्प (हजार में)	३०.०	१०४.४	१२४.८
मोटरगाड़ियां ,,	१४.६	५२.१	५४.३
रेल वेगन ,,		७.५	११.१
मोटर साईकिल ,,		४.०	४.७
स्कूटर ,,		१३.०	१५.३
४—बिजली इंजीनियरी उद्योग :			
ट्रांसफार्मर (हजार कि० वा० में)	१७२	१२८२	१७७५
बिजली की मोटर (हजार होर्स पावर में)	८२	६९९	८२४
रेडियो (हजार में)	४४	२६५	३२६
केबल और वायर :			
१—तांबे के तार (हजार टन)	५.८	९.९	७.६
२—अलमुनियम ,,		२३.०	२२.४
५—रसायन और सम्बद्ध उद्योग :			
अलमुनियम फास्फेट (हजार टनों में) ,,	४८	३९०	३९५
सुपर फास्फेट ,,	५३	३२३	३[illegible]
गंधक का तेजाब ,,	१०४	३६०	४[illegible]
कास्टिक सोड़ा ,,	११	९८	१[illegible]
सोड़ा एश ,,	४४	१४५	१[illegible]
सोमेंट (१० लाख टनों में)	२.७	७.८	[illegible]
रबर टायर और ट्यूब (१० लाख में)	८.९	२६.२	२[illegible]
पेट्रोल (१० लाख टनों में)	०.२	५.८	[illegible]
६—कपड़ा उद्योग :			
रेयन के धागे (हजार टनों में)	२.१	४२.९	४[illegible]
सूती कपड़ा (१० लाख मीटर में)	४२६२	६६२३	७[illegible]
ऊनी कपड़ा (,,)	११.१	१३.४	[illegible]
७—खाद्य पदार्थ :			
चीनी (हजार टनों में)	९९२	२४८५	३[illegible]
वनस्पति (,,)	१७४	३३८	[illegible]
८—बिजली :			
(१० लाख कि० वा० में)	५१०७	१६४३३	१[illegible]

विज्ञापन के लिए

सम्पदा

सर्वोत्तम

साधन है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत के आर्थिक विकास में अमेरिका का सहयोग

सं. रा. अमेरिका द्वारा सहायता प्राप्त केन्द्र

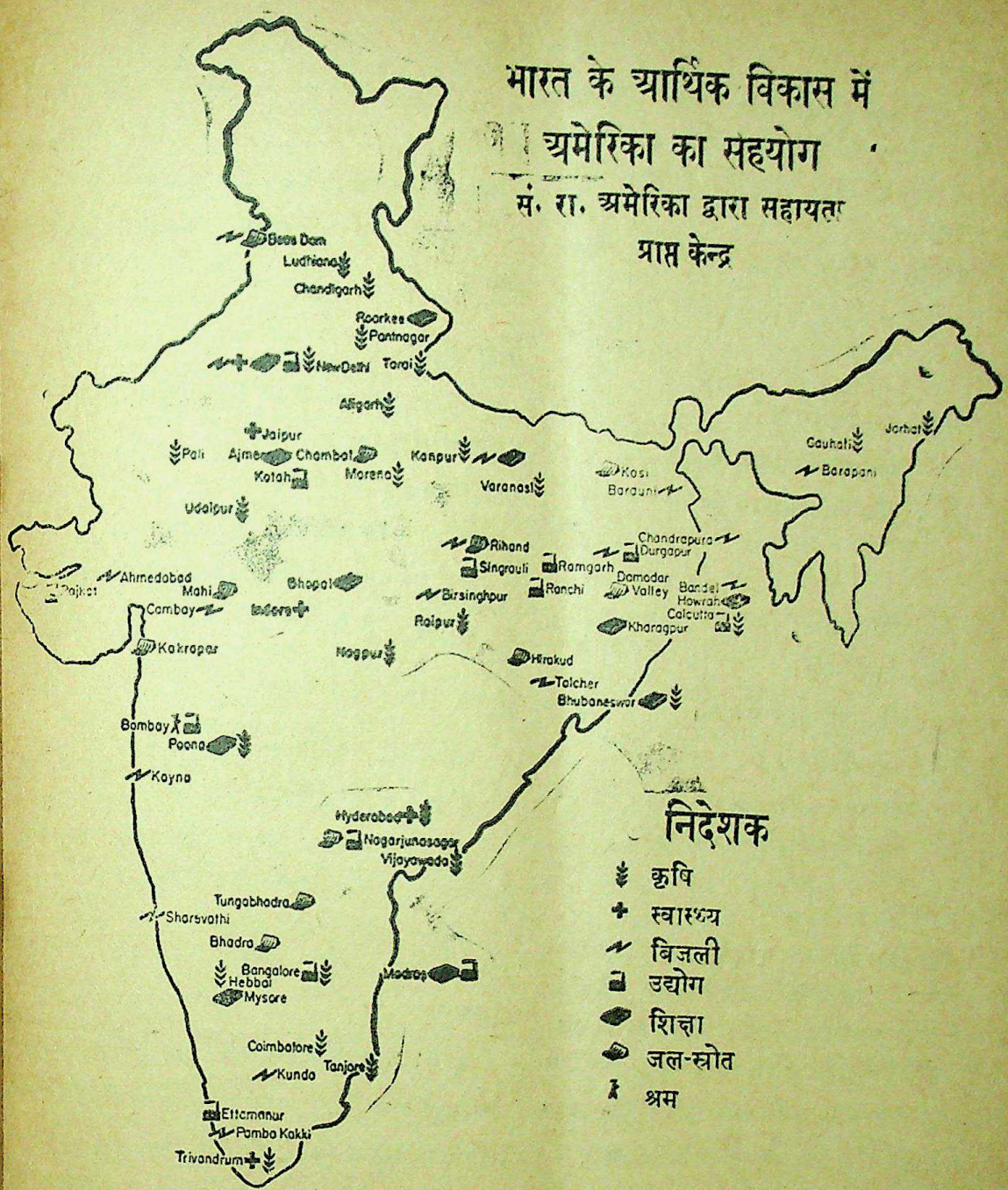

अमेरिका की ओर से भारत को जो आर्थिक सहायता मिल रही है, वह अनुदान और ऋण—दोनों के रूप में है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को, विभिन्न समझौतों और करारों के अन्तर्गत, जितनी धन राशियां देनी स्वीकृत की हैं, उनका कुल योग २,१७३.२ करोड़ रु० होता है। इसमें वह सामरिक सहायता शामिल नहीं हैं, जो चीनी आक्रमण के समय से भारत को दी गयी है।

ऊपर के चित्र में यह बताया गया है कि भारत के किन किन स्थानों पर अमेरिकी सहायता दीजा रही है। इनका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद—कृषि विश्वविद्यालय विकास, मैडिकल शिक्षा, जनरल नर्सिंग, सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा।

नागार्जुनसागर—हैवी इक्विपमेंट ट्रेनिंग सेंटर, नदी घाटी विकास।

विजय वाडा—सिंचाई और ड्रेनेज, विस्तार, फार्म प्रबन्ध।

आसाम

बारापानी—हाइडल स्टेशन।

गोहाटी—कृषि विश्व विद्यालय विकास।

जोराहाट—कृषि विश्वविद्यालय विकास।

बिहार

बारौनी—थर्मल प्लांट।

चन्द्रपुरा—थर्मल प्लांट।

दामोदरघाटी—नदी घाटी विकास।

कोसी—नदी घाटी विकास।

रामगढ़—कोयला खान विकास।

रांची—स्टील ट्रेनिंग (हिन्दुस्तान स्टील)।

दिल्ली

नयी दिल्ली—मेडिकल एज्यूकेशन ट्रेनिंग, पब्लिक हैल्थ एज्यूकेशन, हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ एज्यूकेशन, नेशनल प्राडक्टिविटी काउन्सिल, इंडियन इनवेस्टमेंट सेंटर, इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन, थर्मल प्लांट, मुर्गीपालन, कृषि सूचना, भूमि टेस्टिंग, बीज टेस्टिंग, उर्वरक वर्धन और बिजलीघर।

गुजरात

अहमदाबाद—थर्मल प्लांट

काम्बे—थर्मल प्लांट।

माही—नदी घाटी विकास।

राजकोट—लघु उद्योग विकास,

केरल

एट्टामानुर—उत्पादन और प्रशिक्षण केन्द्र, (फारेस्ट्री ट्रेनिंग)।

पाम्बा—काक्की—जल—विद्युत परियोजना।

त्रिवेन्द्रम—भूमि संरक्षण, मेडिकल एज्यूकेशन ट्रेनिंग।

मध्य प्रदेश

भोपाल—बहु प्रयोजनीय हायर सैकंडरी शिक्षा।

बीरसिंहपुर—थर्मल प्लांट।

इन्दौर—जनरल नर्सिंग।

मोरेना—सिंचायी और जल प्रयोग।

रायपुर—भूमि और उर्वरक, फार्म प्रबन्ध।

सतपुड़ा—बिजलीघर

मद्रास

कोयम्बटूर—कृषि विश्व विद्यालय विकास।

कुंडा—हाइड्रो-इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट।

गुइंडी—(मद्रास नगर)—टैकनिकल एज्यूकेशन इंस्टीट्यूशन, नेशनल प्रोडक्टिविटी कौंसिल।

तंजौर—सिंचाई और ड्रेनेज।

महाराष्ट्र

बम्बई—त्राम्बे फर्टिलाइजर प्लांट, अणु इंजिनीयरिंग और अनुसंधान, रिफाइनेन्स कारपोरेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया (आई. सी. आई. सी. आई.) नेशनल प्रोडाक्टिविटी कौंसिल, सेन्ट्रल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट फार क्राफ्ट्समैन एण्ड इन्स्ट्रक्टर्स।

काकड़ापार—नदी घाटी विकास।

कोयना—हाइड्रो-इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट।

(शेष पृष्ठ २०४ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

परीक्षोपयोगी लेखः—

भारत के सार्वजनिक ऋण : इतिहास, स्वरूप और भविष्य

रामकृष्ण सींगी

"The Country which accepts the policy of budget deficits is treading the slippery path which leads to general ruin, to escape from that path no sacrifice is too great"—इस कठोर और स्पष्ट कथन का समर्थन करने वाला दृष्टिकोण न जाने कब से लुप्त हो चुका है। आज संसार के लगभग सभी राष्ट्र—चाहे विकसित, चाहे विकासशील—घाटे की बजट व्यवस्था का समर्थन करते दृष्टिगोचर होते हैं और इस घाटे की पूर्ति जन ऋण लेकर अथवा नोट छापकर की जाती है। वर्तमान बजटों के घाटे भूतकाल के समान युद्ध अथवा संकटकालीन स्थिति का सामना करने से उत्पन्न नहीं होते, किन्तु देश का आर्थिक विकास करने वाली क्रियाओं के संचालन व वित्तीय व्यवस्था करने के हेतु उत्पन्न किये जाते हैं। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय व्यवस्था के इस साधन का महत्व काफी बढ़ गया है। किन्तु इन्हीं दिनों एक चिन्ता-मिश्रित व्यग्रता भारतीय ऋणों के प्रति प्रगट की जाती है। शंकाएं प्रस्तुत की जाती हैं कि शायद भारतीय सार्वजनिक ऋण बहुत बढ़ गये हैं और कहा जाता है कि कहीं हम 'वर्तमान के लिये भविष्य को गिरवी रखने की भूल' न कर बैठें। इस संदर्भ में भारतीय सार्वजनिक ऋणों पर गम्भीर विचार की आवश्यकता है।

ऐतिहासिक पहलू

भारतीय सार्वजनिक ऋणों का इतिहास ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय से आरम्भ होता है। कम्पनी अपनी प्रतियोगी फ्रान्सीसी और डच कम्पनियों तथा देशी राजाओं से युद्ध करने के लिये समय-समय पर इंग्लैंड की सरकार से ऋण लेती थी। सन् १८६० में जब ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन अपने हाथ में लिया, कम्पनी के ऋण-दायित्व, जिनकी मात्रा उस समय ९३० लाख पौंड थी, भारत सरकार के दायित्व हो गये। ये ही सन् १८७० में बढ़कर १० करोड़ पौंड हो गये। इनमें रुपये तथा पौंड दोनों प्रकार के ऋण सम्मिलित थे। यह लगभग समस्त ऋण अनुत्पादक था।

सन् १८७० के बाद भारत सरकार ने अनेक सार्वजनिक निर्माण कार्य आरम्भ किये, जैसे रेलें, नहरें, सड़कें, पुल तथा विशाल भवन निर्माण सबके लिए अधिक ऋण लेने पड़े। अब भारतीय ऋणों को दो भागों में विभक्त कर दिया गया—उत्पादक और साधारण। पिछली शताब्दी के अन्त तक भारतीय ऋण कुल मिलाकर लगभग २३२ करोड़ रु० थे—१७० करोड़ रु० उत्पादक और शेष साधारण। प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ तक ये ऋण बढ़कर ४१० करोड़ रु० हो गये, जिनमें अनुत्पादक ऋणों का भाग अत्यन्त कम था। किन्तु प्रथम युद्धकाल में ही अनुत्पादक ऋणों में लगभग १६३ करोड़ रु० की वृद्धि हुई और सन् १९२४ तक भारत का कुल ऋण रु० ५३८ करोड़ हो गया, जिसमें रु० २०५ करोड़ साधारण ऋण था।

सन् १९२४ में ऋण भुगतान की एक ८० साला योजना बनी, जिसके अनुसार सन् १९३० तक अनुत्पादक ऋण घटाकर लगभग रु० १७६ करोड़ कर दिये गये। किन्तु १९३०-३२ के मंदीकाल में पुनः घाटे की अर्थव्यवस्था का सहारा लेना पड़ा और सन् १९३४ तक भारतीय ऋण बढ़कर रु० १२२४ करोड़ हो गये। द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ तक भारत सरकार पर रु० ७१० करोड़ के अतिरिक्त और रु० ४६९ करोड़ के पौंड ऋण थे।

द्वितीय युद्धकाल में भारतीय निर्यात अधिक होने से पौण्ड ऋणों के तो परिशोधन का महत्वपूर्ण कार्य हुआ किन्तु आन्तरिक ऋण बढ़ते रहे। सन् १९४६ में स्थिति यों थी—१९३७ करोड़ रु० आन्तरिक और रु० २८ करोड़ पौंड ऋण।

स्वतंत्रता और उसके बाद

सन् १९४७ में भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारत पर कुल रु० २१५९ करोड़ के ऋण थे। विभाजन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पर समस्त ऋणों का दायित्व भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिया और पाकिस्तान ने अपने हिस्से के रु० ३०० करोड़ के ऋण भारत को ३% ब्याज की दर पर ५० किश्तों में देने का वायदा किया यद्यपि पाकिस्तान ने अब तक एक भी पैसा नहीं चुकाया। सन् १९५० तक कुल भारतीय ऋण लगभग २५१६ रु० करोड़ थे, जिनमें से ४३ करोड़ रु० के बाह्य ऋण थे। इस प्रकार देश में आर्थिक नियोजन के आरम्भ के पूर्व के काल में भारतीय सार्वजनिक ऋण राष्ट्रीय आय का लगभग २५ प्रतिशत ही थे।

आर्थिक-योजना काल

पिछले दस वर्षों के नियोजन काल में भारतीय राजकीय ऋणों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के एक महत्वपूर्ण वित्तीय साधन के रूप में इन्हें स्वीकार कर लिया गया है। प्रथम योजना के लगभग ३८% की वित्तीय व्यवस्था ऋणों—आन्तरिक तथा बाह्य—से की गई। योजनाकाल में भारतीय आंतरिक ऋणों में लगभग रु० ५९५ करोड़ और बाह्य ऋणों में लगभग रु० ९० करोड़ की वृद्धि हुई। दूसरी योजना के वास्तविक व्यय के लगभग ३३ % की व्यवस्था ऋणों से हुई। योजना के अन्त में आंतरिक ऋण उसके आरम्भ से रु० २३९५ करोड़ अधिक और बाह्य ऋण लगभग रु० ६८५ करोड़ अधिक थे। सन् १९६१-६२ के अन्त में भारतीय सरकार के आन्तरिक दायित्व रु० ५७०४ करोड़ और बाह्य दायित्व रु० १०९० करोड़ के थे, याने कुल दायित्व सन् १९६१-६२ के अन्त तक रु० ६७९४ करोड़ थे, जो सन् १९६०-६१ से रु० ५१३ करोड़ अधिक थे। ऐसा अनुमान है कि ये बढ़कर १९६२-६३ तक लगभग रु० ७६८१ करोड़ हो जायेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि तृतीय योजना के सार्वजनिक क्षेत्र के कुल व्यय का लगभग ४५% से ५०% भाग की वित्त व्यवस्था सार्वजनिक ऋणों से की जायेगी। उक्त सभी तथ्य इन ऋणों के बढ़ते हुए महत्व पर प्रकाश डालने के लिये हैं।

भारतीय ऋण और राष्ट्रीय आय

यह महत्वपूर्ण है कि सन् १९५०-५१ में भारतीय ऋण कुल मिलाकर रु० २५२२.०५ करोड़ थे और राष्ट्रीय आय सन् १९६०-६१ के मूल्यों पर थी रु० १०,२[illegible] करोड़। इस प्रकार सार्वजनिक ऋण राष्ट्रीय आय का लग[illegible] २५% थे। सन् १९५४ के एक अनुमान के अनुसार भा[illegible] के राजकीय ऋण भारतीय राष्ट्रीय आय के ३०% से [illegible] थे, जबकि ये आस्ट्रेलिया में ८८%, फ्रांस में ४[illegible] ब्रिटेन में १७१% व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ९१% [illegible] १९५८ के अन्त में संयुक्त राष्ट्र का राष्ट्रीय ऋण वहां [illegible] राष्ट्रीय आय का लगभग ६०%, इंग्लैंड में १७०% [illegible] कनाडा में ७५% था, तब भारत में वह केवल ४५% [illegible] था। इसी प्रकार १९६०-६१ में जबकि राष्ट्रीय आय [illegible] १४,५०० करोड़ थी, सरकार के कुल ऋण रु० ६[illegible] करोड़ थे। यों कुल ऋण राष्ट्रीय आय का लगभग ५[illegible] था जो संसार के अन्य कई देशों की तुलना में कम [illegible] स्पष्ट है कि देश की राष्ट्रीय आय को देखते हुए भारत [illegible] सार्वजनिक ऋण अत्यधिक नहीं है।

भारतीय ऋण और उनकी उत्पादकता

इस शताब्दी के प्रारम्भ में कुल ऋणों का लग[illegible] तीन-चौथाई भाग उत्पादक था। विगत दो युद्धों में भा[illegible] सरकार के अनुत्पादक ऋणों में वृद्धि हुई। १९२४ [illegible] उत्पादक ऋणों का प्रतिशत लगभग ७२ था, १९३० [illegible] मन्दीकाल में कुछ अनुत्पादक ऋण बढ़े। द्वितीय युद्[illegible] प्रारम्भ में उत्पादक ऋणों का प्रतिशत ७० था? किन्तु [illegible] के अन्त में घटकर ४२% ही रह गया। इसके बाद से [illegible] ऋण बढ़ते रहे हैं और उनकी तुलना में अनुत्पादक ऋ[illegible] का अनुपात कम होता गया है। नियोजन के आरम्भ के [illegible] तो सार्वजनिक ऋण काफी बढ़े हैं किन्तु क्योंकि ये [illegible] विकास कार्यों के हेतु लिये गये हैं—उत्पादक हैं [illegible] आवश्यक व उपयोगी हैं। तभी तो निकट भूत में उत्पा[illegible] ऋणों का प्रतिशत काफी बढ़ गया है, यथाः सन् १९[illegible] ५३—७१%, १९५५-५६—७७%। १९६०-६[illegible] ८१% तथा १९६१-६२—८४%, अनुत्पादक ऋणों [illegible] प्रतिशत शनैः शनैः कम होता जा रहा है।

परिपक्वता के दृष्टिकोण से भारतीय ऋण

भारत सरकार के आन्तरिक ऋणों का भुगतान [illegible] अवधि के अनुसार विभाजन निम्न तालिका से प्र[illegible] होता है:—

(शेष पृष्ठ १९८ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आज का नया प्रश्न

बाध्य बचत योजना : स्वरूप और आर्थिक महत्व

प्रो० रूसी जाल तारपोरवाला

१९६३-६४ के बजट में "बाध्य बचत योजना" रखी गयी है, जिसके अन्तर्गत ७ श्रेणियों के वे व्यक्ति आते हैं जो आय कर की सीमा से मुक्त हैं। इस योजना का उद्देश्य, वित्तमंत्री के शब्दों में, कराधान के अतिरिक्त, स्वेच्छा बचत से इस संकट काल में सुरक्षा कोष जमा करना है। इसके द्वारा जनता में मितव्ययता और राष्ट्र के लिए बचत की भावना को उद्बुद्ध करना है। यह सात श्रेणियां निम्नलिखित हैं :—

(१) जो भूमि का लगान देते हैं, चाहे वे आय कर देने वाले हों या न हों।

(२) वे व्यक्ति जो आय कर देते है।

(३) नगर क्षेत्रों में जिनकी अचल सम्पत्ति हो और जो सम्पत्ति कर, गृह कर तथा इसी प्रकार का किसी अन्य नाम से कर देते हों। नगर क्षेत्र की परिभाषा यह है कि जहां १० हजार व इससे अधिक व्यक्ति रहते हों।

(४) केन्द्रीय और प्रदेश सरकारों, स्थानीय साधनों, कम्पनियों (सरकारी कम्पनियों सहित) और अन्य प्रकार के कारपोरेशन (सहकारी समितियों सहित)—जिनकी वेतन से प्राप्त वार्षिक आय १५०० रु० व इससे अधिक हो, पर जो आय कर नहीं देते हों—

(५) दुकानदार जिनकी वार्षिक बिक्री १५ हजार रु० व इससे अधिक हो और जो आय-कर न देते हों।

(६) दुकानदारों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति जिनपर पेशा, कारोबार, धन्धा अथवा रोजगार का कर लग सकता है, पर जिन पर आय-कर लागू नहीं होता, और

(७) अन्य सब श्रेणियों के व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय १५०० से अधिक है और जो आय-कर नहीं देते।

इस योजना का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसके अन्तर्गत लाखों ऐसे व्यक्ति आ जायेंगे, जिन्हें इस समय प्रत्यक्ष कर नहीं देना पड़ता। सरकार का लक्ष्य यह प्रतीत होता है कि जिनकी वार्षिक आय १५०० रु० व इससे अधिक है और जो आय-कर नहीं देते, उनसे भी कुछ वसूल किया जाय। इन सातों श्रेणियों से यह तो स्पष्ट है कि इनमें कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय १५०० रु० से भी कम है—जैसे जमीन का लगान देने वाले, अचल सम्पत्ति रखने वाले, दुकानदार—अब वे भी इस योजना के अन्तर्गत आ जाएंगे।

इस विधेयक में यह कहा गया है कि हरेक श्रेणी के व्यक्ति को जिस पर यह योजना लागू होती है,—सिवाय उन लोगों के जो आय-कर देते हैं—बाध्य जमा राशि देनी पड़ेगी, ऐसे दरों पर जिसका निश्चय विभिन्न श्रेणियों के लिए सरकार की ओर से किया जाएगा। फलतः, जो आय कर देते हैं, उन्हें यह सुविधा होगी कि वे जमा रकम को इस योजना के आधीन रखें व न रखें।

जमा रकम की अधिकतम दरें

विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत व्यक्तियों को जिस दर पर जमा रकम देनी होगी, वह इस प्रकार है :—

(१) जमीन का लगान देने वालों के लिए अधिकतम दर १९५९-६० के लगान दर का ५०% होगा।

(२) नगर क्षेत्रों में अचल सम्पत्ति वालों के लिए सम्पत्ति के वार्षिक किराये का ३%, जिस पर सम्पत्ति कर और गृह कर व अन्य इसी प्रकार कर लगता हो।

(३) जो सरकारी, स्थानीय शासन, कम्पनियों व कारपोरेशनों के नौकर हैं, जिनकी वार्षिक आय १५०० रु० से अधिक है, पर जिन पर आय कर नहीं लगता, उनकी वार्षिक आय पर अधिकतम दर ३% होगी।

(४) ऐसे दुकानदार जिनकी वार्षिक बिक्री १५ हजार रु० तक है पर जो आय कर नहीं देते, उन पर वार्षिक बिक्री का एक तिहाई उस वर्ष के एक दम पिछले वर्ष पर।

(५) दुकानदारों से अतिरिक्त जिन पर पेशा, धंधा व अन्य रोजगारों का कर लगता है, पर आय कर नहीं लगता

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उनकी दर वर्ष में पेशा, धंधा व रोजगार पर लगने वाली कर की रशि के तुल्य।

(६) अन्य सब प्रकार की श्रेणियों के व्यक्तियों पर जिनकी आय १५०० रु० वार्षिक से अधिक है, पर जो आय कर नहीं देते, ६० रु० प्रति वर्ष।

इसका मतलब यह है कि इस योजना के अन्तर्गत व्यक्तियों को कुल आमदनी का ३% व अधिक देना पड़ेगा।

जो आय कर देते हैं, उन्हें एक ढंग से, यह छूट दी गई है कि इस योजना के अन्तर्गत बाध्य बचत में दें पर यह बचत की रकम अतिरिक्त अधिभार कर से काटी जा सकती है। इस प्रकार आय कर देने वालों के लिए यह छूट है कि या तो वे अधिभार कर के रूप में पर्याप्त रूप से बढ़ा हुआ आय कर दें अथवा अपने कर के बोझ को बाध्य बचत की योजना में रकम जमा कर कुछ हल्का कर लें और यह रकम वापस मिल सकती है। वेतन भोगी भी इस बचत रकम का प्रमाण देकर अपने आय कर में कमी करा सकता है।

योजना से शक्ति
शक्ति से सुरक्षा

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सब श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए—यहां तक भारत में रहने वाले विदेशी भी—और वे सब भी जो आय कर देते हैं—बाध्य बचत योजना में जमा करने के लिए बाध्य हैं।

इस रकम पर सूद दिये जाने के लिए वित्त-बिल में कहा गया है कि सीधा ४ प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा, चक्र वृद्धि ब्याज नहीं और यह ब्याज आय कर व अधिभार कर से मुक्त होगा। इस योजना में जमा करायी गई रकम पांच वर्षों की समाप्ति पर ही मिल सकेगी। अगर जमा कराने वाला पांच साल से पहले मर जाता है तो बिना किसी रोक टोक के यह रकम उसके उत्तराधिकारी को तत्काल मिलने के बजाय, विधेयक में कहा गया है कि, अगर अधिकारी यह समझे कि यह लोग बड़े कष्ट में हैं और इसके सिवा इनका काम नहीं चल सकता है, तभी यह राशि वापस मिल सकेगी। पर सरकारी अधिकारी को वास्तविक कठिनता का अनुभव कराना सहज बात नहीं है।

बाध्य बचत योजना के अंतर्गत व्यक्ति को किसी प्रशासकीय अधिकारी व अदालत में अपील करने का अधिकार नहीं होगा। इस राशि पर किसी अदालत से डिगरी व जब्ती का हुकुम नहीं हो सकता। बचत की रकम अदा न करने पर उसकी दुगुनी रकम देनी पड़ेगी और इसकी कहीं अपील नहीं हो सकती है। इस योजना के अन्तर्गत ४० करोड़ रु० जमा होने की आशा है, और यह भी सम्भव है कि यह राशि ६५ और ७० करोड़ रु० के बीच तक पहुँच जाए। इस योजना का एक प्रभाव यह होगा कि जनता का धन निजी क्षेत्र में न लगकर सरकारी खजाने में अधिक जाएगा। इस योजना के अंतर्गत देश के लाखों व्यक्ति आ जाएंगे।

आर्थिक समीक्षा

प्रधान सम्पादक : श्री सादिक अली

सम्पादक : श्री महेन्द्र मेहरा

- हिन्दी में अनूठा प्रयास
- आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख
- आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत

भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक।

वार्षिक मूल्य : ५ रु० एक प्रति २२ नये पैसे

लिखें—व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, नई दिल्ली

दूध के विभिन्न उपयोग

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भरपूर खेती-कार्यक्रम का मूल्यांकन

आज योजना के अन्तर्गत तथ्य से कृषि-उत्पादन में भारी कमी को पूर्ण करने के लिए जिस भरपूर खेती पर बल दिया जा रहा है, उसका परिचय इस लेख में पढ़िये।

देश के १५ चुने हुए जिलों में सघन कृषि जिला कार्यक्रम—जिसे भरपूर कार्यक्रम भी कहा जाता है—चालू हो हो चुका है। यह कार्यक्रम फोर्ड संस्थान द्वारा भेजे गये विशेषज्ञ मंडल की १९५९ में जनवरी और अप्रैल के बीच की गई जांच की १० सिफारिशों के आधार पर हैं। इस प्रोग्राम के उद्देश्य यह थे—

(१) नमूने के जिलों में अत्यन्त सक्षम साधनों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य उत्पादन के विस्तार का प्रदर्शन करना जो केन्द्र, राज्य, जिला, प्रखंड, ग्राम और व्यक्तिगत किसान—इन सब में पारस्परिक सहकारिता के प्रयासों पर आधारित हो। (२) किसान और उसके परिवार की आय को बढ़ाना। (३) देहात के आर्थिक साधनों और सामर्थ्य को बढ़ाना। (४) ऐसे पर्याप्त कृषि-आधार उपलब्ध करना, जिससे आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण में द्रुत गति आ सके।

फोर्ड संस्थान की सिफारिशें

फोर्ड संस्थान के विशेषज्ञ मंडल की १० सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(१) खेती पर पर्याप्त उधार मिल सके जो उत्पादन शक्ति पर आधारित हो और सबल सेवा-सहकारियों द्वारा उपलब्ध हो।

(२) उर्वरक, कीटनाशक, अच्छे बीज, नये ढंग के कृषि-उपकरणों तथा अन्य साधनों की शीघ्र उपलब्धि—सबल सेवा सहकारियों द्वारा।

(३) भाग लेने वाले किसानों के लिए मूल्य द्वारा प्रेरणा, चावल और गेहूँ पर (उचित जिलों में मक्का के लिए) मूल्य-समझौतों द्वारा आश्वासन, दो वर्ष पूर्व घोषित कर दिये जाएं।

(४) हाट-व्यवस्थाएं और सेवाएं जिससे किसान को अपनी फालतू बची फसल पर पूरी बाजार कीमत मिले

(५) नमूने के जिलों के प्रत्येक विकास प्रखंड और प्रत्येक गांव में सघन शैक्षणिक, तकनीकी और फार्म प्रबन्ध की सहायता उपलब्ध कराई जाए।

(६) बड़े और छोटे, सब दिलचस्पी लेने वाले किसान अधिक खाद्य उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत फार्म-योजना में भाग लें। (७) अधिक उत्पादन के लिए और ग्राम सुधार के लिए ग्राम-योजनाएं बनायी जाएं जिसमें पशु-सुधार, और ग्राम संस्थाओं को—जैसे सहकारिता, पंचायत, विकास परिषद्, ग्राम नेतृत्व दृढ करना—यह सब भी शामिल हों।

(८) सार्वजनिक श्रम कार्य, स्थानीय श्रम को प्रयोग करते हुए, नाली, बांध, भू संरक्षण, छोटी सिंचाइयां, गोदाम और सड़क बनाना तथा अन्य विकास कार्य जिनसे प्रत्यक्ष रूप में अधिक खाद्य उत्पादन हो—इन्हें हाथ में लेना।

(९) विश्लेषण और मूल्यांकन।

(१०) ग्राम, प्रखंड, जिला, राज्य और केन्द्र द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सब ऐसे साधनों का समन्वय, जिनसे यह सारे कार्य क्रम बढ़ सकें और अधिकतम शीघ्रता तथा सामर्थ्य से कार्यान्वित हो सकें।

जिलों का चुनाव

जिलों का चुनाव इस दृष्टिकोण से किया जाय कि जिले को बड़ी सिंचाई अथवा नालियां बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जिनमें चकबन्दी अभी नहीं हुई है, उन्हें हाथ में न लिया जाए। सामुदायिक विकास का कार्यक्रम इस प्रकार संगठित हो कि वहां ऋण, हाट बाजार और स्थानीय नेतृत्व सुधार के लिए तैयार हो।

फोर्ड संस्थान ने ब्यौरे के साथ उन प्रशासकीय पद्धतियों पर विचार किया, जिनके अनुसार उर्वरक, ऋण और निश्चित मूल्यों पर चीजें इन क्षेत्रों को मुहय्या की जाएंगी। केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय तो इस भरपूर खेती की योजना के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रति प्रारम्भ से ही उत्साह पूर्ण था, पर कुछ राज्य सरकारों का रुख ढीला ही था। सम्भवतः, राज्य सरकारें द्रुत प्रगति के लिए प्रशासन में आवश्यक परिवर्तन के लिए इतनी उत्सुक नहीं थीं।

सबसे अधिक—सबसे कम

१९६० के प्रारम्भ में सात राज्यों के सात जिलों में भरपूर खेती का यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया—अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश), लुधियाना (पंजाब), पाली (राजस्थान), रायपुर (मध्यप्रदेश), शाहाबाद (बिहार), तंजोर (मद्रास) और पश्चिम गोदावरी (आन्ध्रप्रदेश)। इनमें उत्तरप्रदेश में अलीगढ़ परियोजना सबसे पीछे रही और सर्वोत्तम कार्य का यश आंध्र प्रदेश में पश्चिम गोदावरी को मिला। राज्य सरकारों के साथ ब्यौरेवार विचार-विमर्श करने के बाद जिलों का चुनाव किया गया था, पर कुछ प्रेक्षकों का ख्याल है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों के जिलों का चुनाव सम्भवतः सर्वोत्तम नहीं हो सका। तंजौर सबसे पहला जिला था, जिसने अप्रैल १९६० में भरपूर खेती का कार्यक्रम शुरू किया और लुधियाना, पाली, रायपुर और अलीगढ़ ने खरीफ १९६१-६२ से इसे कार्यान्वित किया। इन सात जिलों में १३९ प्रखण्ड हैं जिनमें से ११५ प्रखण्डों में जून १९६२ में भरपूर खेती का कार्यक्रम चालू हो गया था। इन ११५ प्रखण्डों में सारी खेती की जमीन कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आयी थी। उदाहरण के लिए, पाली और शाहाबाद जिलों में जिले की भूमि का केवल २ और ३.८% ही इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया। लुधियाना में यह भरपूर खेती ३६.६%, रायपुर में ८%' पश्चिम गोदावरी में ३०.५%, और तंजोर में १८.७% की गयी। अलीगढ़ की संख्याएं उपलब्ध नहीं हो सकीं।

खाद्य कार्यक्रम की उपेक्षा

जिस समय यह कार्यक्रम शुरू किया गया था, उस समय अनुमान यह था कि पहले वर्ष जिले की खेती की भूमि का २०% इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जाएगा और पांचवें वर्ष में यह संख्या ६५% तक पहुँच जाएगी। भरपूर खेती के समूचे कार्यक्रम के पीछे धारणा यह थी कि तीसरी योजना में कृषि-उत्पादन लक्ष्य में जो ३२% वृद्धि ध्येय रखा गया है, वह भरपूर खेती के जिलों में तीन में पूरा हो जाए और पंचवर्षीय योजना में इन जिलों लक्ष्य ५० और ६०% वृद्धि का था। पाली, शाहबाद अलीगढ़ जिलों में खाद्य-कार्यक्रम की उपेक्षा की गई, यद्यपि इन्हें राज्य के सर्वोत्तम जिले मानकर चुना गया था।

भरपूर खेती के अन्तर्गत १९६०-६१ में कुल एकड़ ३,००,००० से बढ़कर जून १९६२ तक १२,००,००० एकड़ जमीन आ गयी। इन क्षेत्रों में फसल, स्वभावतः सामान्य जिलों से अच्छी हुई, पर जिले में इस प्रकार क्षेत्र चूंकि, अनुपाततः, कम था, इसलिए फसल की इस वृद्धि का प्रभाव जिले की कुल उपज पर कुछ विशेष नहीं पड़ा।

भरपूर खेती के अन्तर्गत कुल १३,२८५ ग्रामों में से केवल ४,७८६—एक तिहायी से कुछ अधिक—गांवों में फार्म योजना के अनुसार काम हो सका और क्षेत्र की दृष्टि से ६५.५१ लाख एकड़ में से १२.११ लाख एकड़ में काम हुआ। १९६२ जून के अन्त तक प्रखण्डों के कुल उपज वाले क्षेत्र में से १८.५% इस योजना के अन्तर्गत आ और सातों जिलों के कुल उपज वाले क्षेत्र की दृष्टि से १५.६%।

किसानों की दिक्कतें

इस कार्यक्रम में भाग लेने का ढंग एक जिले से दूसरे जिले में, बल्कि एक गांव से दूसरे गांव में भी भिन्न था। कुछ गांवों में सब किसानों ने मिलकर काम किया और कुछ में थोड़ों ने ही हिस्सा लिया। और, अधिकांश मामलों में भाग लेने वाले प्रायः ऐसे थे, जिन्होंने सुधरे हुए साधनों का सारी काश्त पर प्रयोग नहीं किया था। एक बड़ी दिक्कत यह थी कि गांवों की आपसी कशमकश को संयोजक दूर नहीं कर सके। किसान को सहकारी संस्थाओं से ऋण लेने की पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। इन सबसे बढ़कर भरपूर खेती के कार्यक्रम में रुकावट, योग्य कार्यकर्त्ताओं का न मिलना है। जो वेतन और सुविधाएं दी जाती हैं, वे आकर्षक नहीं हैं। तंजोर और रायपुर में ग्राम-स्तर-कर्मियों की न्यूनता रही, जिससे इस कार्यक्रम को चलाने में देर लगी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तालमेल की कमी

मई १९६२ में हुए प्रदेश-कृषि-सचिव सम्मेलन में एक प्रश्न सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं में आपसी तालमेल के अभाव का भी प्रश्न उपस्थित हुआ था, विशेषतः सहकारी संस्थाओं के मामले में। इस सम्मेलन में दूसरी समस्या विभिन्न प्रदेश प्रशासनों की जिला स्तर पर जनता को शक्ति-हस्तान्तरित करने की पेश हुई थी। आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने इस सम्बन्ध में काफी साहस का परिचय देते हुए प्रशंसनीय पग उठाये हैं। इस बात की प्रबल मांग की गयी थी कि जन-प्रतिनिधियों को अधिक आर्थिक अधिकार दिये जाने चाहिए। ग्राम-स्तर-सेवकों और सहकारिता निरीक्षकों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, वह भली-भांति पूर्व-आयोजित नहीं होता और उसमें कई कमियां होती हैं।

१९६१-६२ की खरीफ और रबी फसलों के प्रदर्शन-खेतों की संख्या ९,४०० थी। भरपूर कार्यक्रम के अन्तर्गत इनके उत्पादन का आर्थिक मूल्यांकन किया गया। पश्चिम गोदावरी के एक प्रदर्शन-खेत से १५० रु० प्रति एकड़ आमदनी हुई, रायपुर में धान के एक एकड़ से आय की सर्वाधिक वृद्धि ९१ रु० और लुधियाना में गेहूँ से १७८ रु० फी-एकड़ आय-वृद्धि हुई।

बीज और उर्वरक

उन्नत बीजों और उर्वरकों के प्रयोग से पश्चिम गोदावरी और लुधियाना में, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, उपज में पर्याप्त वृद्धि हुई। लुधियाना में नाइट्रोजन वाले उर्वरक का प्रयोग भरपूर खेती के कार्यक्रम के फलस्वरूप ५,४०० टन से बढ़कर ११,००० टन १९६१-६२ में हो गया और १९६२-६३ में २१,००० टन तक हो जाने की आशा है, अर्थात्, प्रति एकड़ खपत १९ पौंड से बढ़कर ६३ पौंड। पश्चिम गोदावरी में इसकी खपत १८,००० टन से बढ़कर १९६१-६२ में ३४,००० टन—अर्थात् ६३ पौण्ड प्रति एकड़ अधिक और १९६२-६३ में ६६,००० टन हो जाएगी। तंजोर में यह वृद्धि २८ पौंड से बढ़कर ५७ पौंड प्रति एकड़ हुई।

भरपूर खेती के कार्यक्रम के अन्तर्गत उपज बढ़ाने में रासायनिक उर्वरक बहुत लाभदायक सिद्ध हुए हैं, पर इनकी उपलब्धि की कोई सक्षम व्यवस्था नहीं है। शाहाबाद, अलीगढ़, रायपुर और पश्चिम गोदावरी में प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही है, तंजोर और लुधियाना में पूर्व स्थापित प्रयोगशालाओं का विस्तार किया जा रहा है और पाली के लिए जोधपुर प्रयोगशाला को दृढ़ किया जाएगा।

भरपूर खेती के जिलों में सहकारिता, ऋण, शाहाबाद को छोड़कर, १९६१-६२ में ११.५८ करोड़ रु० था। इसमें से ५.१ करोड़ रु० इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को दिया गया। ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है। सहकारिता-हाट-समितियों में भी प्रगति हुई है। भरपूर खेती के जिलों के लिए १२०० से अधिक गोदामों की आवश्यकता है, औसतन हरेक में १०० टन, जिससे किसानों को सुविधा से सब सामान मिल सकें। १९६२ मध्य तक ४७० गोदाम बन चुके थे और ३०० बन रहे हैं।

भरपूर खेती का कार्यक्रम आठ अन्य राज्यों के जिलों में चालू किया गया है—मान्दप (मैसूर),,सूरत (गुजरात), कछार (आसाम), भण्डारा (मध्यप्रदेश), पाल घाट और एलेप्पे (केरल) बर्दवान (बंगाल) और जम्मू-काश्मीर के ६ प्रखण्ड।

—नाथ

खादी पत्रिका

* खादी ग्रामोद्योग तथा सर्वोदय विचार पर विद्वत्तापूर्ण रचनाएँ।
* खादी ग्रामोद्योग आन्दोलन देश व्यापी जानकारी।
* कविता, लघुकथा, मील के पत्थर, साहित्य समीक्षा, संस्था परिचय।
* साँख्यकी पृष्ठ आदि स्थायी स्तम्भ।
* आकर्षक मुख पृष्ठ, हाथ कागज पर छपाई।

वार्षिक मूल्य ३) रु., एक प्रति पच्चीस नयेपैसे

संपादक—ध्वजाप्रसाद साहू, जवाहिरलाल जैन

राजस्थान खादी संघ, पो. खादीबाग, (जयपुर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

खादी आन्दोलन का नया स्वरूप

श्री एस० सी० सरकार

खादी आन्दोलन लगभग ७ वर्ष के बाद आधी सदी पूरा कर लेगा। गांधीजी ने १९२० में विदेशी वस्त्रों का बायकाट और खादी को असहयोग आन्दोलन के अंग के रूप में जारी किया था। कुछ समय बाद ही, खादी को आर्थिक महत्व मिल गया और १९३३ में १ करोड़ वर्ग गज खादी के उत्पादन में लगभग २ लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में कपड़े की कमी के कारण खादी को बढ़ावा मिला और १९३९ में इसकी बिक्री १.०९ करोड़ वर्ग गज से बढ़कर १९४२ में २.१६ करोड़ वर्ग गज हो गयी। युद्धोत्तर काल में खादी की बिक्री को धक्का लगा और १९५३-५४ में यह १.१५ करोड़ गज तक कम हो गयी। उस समय सरकार ने अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग संघ बनाया और अप्रैल १९५७ में इसके उत्तराधिकारी के रूप में वैधानिक संस्था—खादी और ग्राम उद्योग आयोग स्थापित किया गया।

इसके बाद से खादी उद्योग में विशेष उन्नति हुई। १९५३-५४ में सब प्रकार का खादी उत्पादन १.१५ करोड़ वर्ग गज से बढ़कर १९६१-६२ में ७.६२ करोड़ वर्ग गज तक—लगभग ६०० प्रतिशत अधिक तक पहुंच गया। खादी की बिक्री १९५३-५४ में १२९.९८ लाख रु० से बढ़कर १९६१-६२ में १,८७७.५४ लाख रु० तक पहुँच गयी। १९५३-५४ में खादी उद्योग में ३,७८,००० व्यक्ति लगे हुए थे, जबकि १९६१-६२ में इनकी संख्या १७,४६.२०० थी, लगभग ३६४ प्रतिशत वृद्धि हुई।

इसी प्रकार स्वावलम्बन खादी—अर्थात् अपने व अपने परिवारके लिए सूत कातना—का प्रचार भी बढ़ गया है, १९५३-५४ में १०.१० लाख वर्ग गजसे १९६१-६२ में ७०.८५ वर्ग गज, लगभग ७०० प्रतिशत की वृद्धि। स्वावलम्बन खादीका बहुत प्रचार नहीं हुआ है। इसका अधिक प्रचार उत्तरप्रदेश, गुजरात, जम्मू-काश्मीर और पंजाब में ही हुआ है।

अपने प्रारम्भ कालसे ही खादी कार्यक्रमके दो उद्देश्य रहे हैं। पहला, स्वयं कातकर आत्म संयम और निजी शुद्ध व्यवहार पर बल देते हुए शारीरिक श्रमकी प्रतिष्ठा स्थापना और दूसरा आर्थिक कार्यक्रम के रूप में देहात रोजगार के अवसर पैदा करना जहां, निर्धनता का साम्रा है। खादी आन्दोलन के इन दोनों पहलुओं पर जोर दि जाता रहा है, पर क्रियात्मक रूप में, इन दोनों में समन्व कभी पैदा नहीं किया गया। गांधीजीने १९४४ में ओर ध्यान दिया और उन्होंने इसे ग्रामीण विकास अभिन्न अंग बताते हुए "समग्र सेवा" के रूप में इस नामकरण किया। इसे मूर्त रूप देनेके लिए "नया मो नाम का कार्यक्रम १९५९ में बनाया गया, जिसके अनु खादी का सम्बन्ध गांव की आवश्यकताओं के आधार गांव के लोगों द्वारा ही बनायी गयी योजना से था। कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक ५ हजार की आबादी ३ हजार क्षेत्र चुने गये। इसका नाम रखा गया "इस ग्राम इकाई" इस प्रकार की १०१७ ग्राम इकाइयां गयीं, जिनमें से ९०० में काम चालू हो चुका है।

चीनी आक्रमण के संकट को दृष्टि में रखते हुए सुझाव दिया गया कि उपभोक्ता से अपील की जाए वह खादी पर मिलने वाली रियायत को स्वेच्छा से दे। इस पर काफी गर्मागर्म विवाद हुआ और यह सुझाव दिया गया कि खादी पर दी जाने वाली सब प्र की रियायत बन्द कर दी जाए। इससे पैदा होने वा समस्या को सुलझाने के लिए यह सुझाव दिया गया समूचे हाथ से काते सूत के लिए मुफ्त बुनाई की सुविध दी जाएं और इसमें किसी प्रकार की सीमा न हो। बु की लागत तीसरी योजना के अन्तर्गत खादी और ग्रा उद्योग आयोगको दी गई राशिमें से दी जाय। अखि भारतीय खादी और ग्राम उद्योग मंडल, खादी कार्यक सम्मेलन और अन्य खादी संस्थाओंके विनोबाजी सान्निध्यमें नवद्वीप में फरवरी १९६३ में हुए सम्मेलन इस मुद्दे पर बड़ी गहराई के साथ विचार विचार वि हुआ। इसमें यह निश्चय हुआ कि सब प्रकार

(शेष पृष्ठ १९९ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रतिरक्षा प्रयत्न और कृषि कर

प्रो० धर्मेन्द्र सिंह कुशवाहा, प्रयाग विश्वविद्यालय

● अनेक अर्थशास्त्री आज देश की विकास योजनाओं व आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसानों से भी काफी योगदान की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि न केवल उनकी संख्या बहुत अधिक है, बल्कि योजनाओं का भारी लाभ भी उन्हें ही होने वाला है। इसलिए प्रायः सभी राज्यों के वित्तमन्त्री कृषि कर को बढ़ाने के पक्ष में हैं। लेखक ने इसी प्रश्न के दूसरे पहलू पर इस लेख में प्रकाश डाला है।

इस बात को अब सभी स्वीकार करते हैं कि भविष्य में किसी भी अप्रत्याशित आक्रमण का सामना करने के लिए भारत को सैनिक तैयारी रखनी चाहिए। यह भी स्वीकार किया जाता है कि योजनाएं जारी रहेंगी। वस्तुतः योजनाएं तो आक्रमण का सामना करने और तत्सम्बन्धी आर्थिक शक्ति का आधार होंगी। इस संदर्भ में यह नहीं भुला देना चाहिए कि इस परिस्थिति में योजनाओं, मुख्यतः राज्यीय योजनाओं में नया दृष्टिकोण और व्यवस्थापन आवश्यक हो गया है। उदाहरणार्थ, अब केवल केन्द्रीय सरकार ही ऋण ले सकती है (यद्यपि इसका कुछ भाग राज्य सरकारों को देने की उसमें व्यवस्था है) और साथ ही राज्यों को केन्द्र से मिलने वाली सहायता की मात्रा भी गत वर्षों की तुलना में आगे कम रहेगी। अतएव राज्य सरकारों को योजना के लिए उपलब्ध आय की इस क्षति-पूर्ति के लिए नये-नये साधनों को जुटाना और अपने क्षेत्र में प्रतिरक्षा प्रयत्नों में योगदान देना होगा। इस सम्बन्ध में ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाने का भी सुझाव दिया गया है। उदाहरण के लिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने मालगुजारी पर २५ प्रतिशत अधिकर लगाने का विधेयक पेश किया है। अनुमान किया जाता है कि इससे राज्य को लगभग ५ करोड़ रुपये की आय होगी।

राष्ट्र की ऐसी संकटमय स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वर्ग को अपना सहयोग देना चाहिए, किन्तु इस भार को यथोचित रूप से वितरित करना चाहिए, ताकि समाज के विभिन्न वर्गों या क्षेत्रों में भेदभाव की भावना उत्पन्न न हो और राष्ट्र एकता के सूत्र में बंधा रहे। राष्ट्रीय संकट की स्थिति के अधिक समय तक बने रहने की सम्भावना के कारण यह और भी आवश्यक हो गया है कि इस भार को विभिन्न वर्गों के बीच न्यायपूर्ण ढंग से वितरित किया जाय। इस दृष्टिकोण से हमें कृषि और कृषि इतर क्षेत्रों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना चाहिए।

अभिप्राय यह नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र पर कोई कर ही नहीं लगना चाहिए और न यही है कि केवल औद्योगिक क्षेत्र पर ही कर लगना चाहिए। राजस्व के सिद्धान्तों के अनुसार यह सुझाव प्रस्तुत है कि हमें किसी क्षेत्र या वर्ग पर कर लगाते समय क्षेत्र की तुलनात्मक करदेय क्षमता को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। किन्तु करदेय क्षमता किसी क्षेत्र की विशालता के अनुरूप हो, यह भी आवश्यक नहीं है। निश्चय ही, कृषि भारतीय अर्थ-व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग ८० प्रतिशत जनसंख्या इसमें लगी हुई है किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कर लगाने की दृष्टि से सबसे पहला उपयुक्त साधन कृषि वर्ग ही है। इसके लिए तो उसकी कर देय क्षमता जाननी आवश्यक है। कृषि पर कर लगाया जाना तभी उचित ठहराया जा सकता है जबकि यह सिद्ध कर दिया जाय कि अन्य क्षेत्रों में कृषि-क्षेत्र से अधिक क्षमता ही नहीं है और जहां कहीं थी भी, उस पर कर लग चुका है। अतः हम यहां कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों की कर देय क्षमता का विवेचन करेंगे।

कृषि की कर-क्षमता

सन् १९६१-६२ के राष्ट्रीय आय सम्बन्धी अनुमानों के अनुसार लगभग ८० प्रतिशत जनसंख्या कृषि-व्यवसाय में संलग्न है, जिससे लगभग ३९.२ प्रतिशत राष्ट्रीय आय का भाग प्राप्त होता है। कृषि से अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में २० प्रतिशत जनसंख्या लगी हुई है और जिससे ६०.८ प्रतिशत राष्ट्रीय आय का भाग प्राप्त होता है। उपर्युक्त आंकड़ों से कृषि एवं कृषि इतर क्षेत्रों की करदेय क्षमता का

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भलीभांति ज्ञान हो जाता है। इससे विदित होता है कि कृषकों की अपेक्षा औद्योगिक क्षेत्र की कर-देय क्षमता अधिक होनी चाहिए। हाल के १९६१-६२ के अनुमानों के अनुसार खानों एवं कारखानों, बैंकों एवं बीमा कम्पनियों, वाणिज्य एवं परिवहन एवं संचार के साधनों से राष्ट्रीय आय का २८.५ प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ, जबकि अन्य क्षेत्रों से राष्ट्रीय आय का ३२.३ प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ। यह तो कृषि वर्ग व कृषि इतर वर्ग की तुलना हुई। यदि हम किसी औसत कृषक की कर देय क्षमता अथवा आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करें तब तो यह और भी स्पष्ट हो जायेगा कि वास्तव में कृषक वर्ग पर कर नहीं लगना चाहिए। यह कहना कि इस वर्ग पर अवश्य कर लगना चहिए, ऐसा प्रतीत होता है कि केवल इस तर्क पर आधारित है कि इसमें ८० प्रतिशत जनसंख्या संलग्न है और यह कितना बड़ा क्षेत्र है। सम्भव है, उत्तर प्रदेश का अधिकर कानून इसी पृष्ठभूमि में पारित किया गया हो !

तो क्या किसान को प्रतिरक्षा के लिए कुछ भी नहीं देना चाहिए ? प्रतिरक्षा के लिए तो उसे देना ही चाहिए किन्तु इस प्रकार के नये कर लगाकर वसूलना अनुचित है। किसान अप्रत्यक्ष करों के रूप में योगदान दे रहा है। विशाल कृषक समुदाय अप्रत्यक्ष कर से आय का एक बड़ा भाग प्रस्तुत करता है। नये अप्रत्यक्ष कर एवं पुराने करों की दर बढ़ाने का तात्पर्य है कि कृषक वर्ग अपनी क्षमता के अनुपात में उचित योगदान दे रहा है।

किसानों का योगदान

एक नये प्रत्यक्ष कर के लगाने से अवश्य ही कृषक वर्ग में क्रोध एवं क्षोभ उत्पन्न होगा। ऐसा कर तो तभी उचित ठहराया जा सकता है जबकि यह स्पष्ट कर दिया जाय कि कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय और फलस्वरूप सापेक्षतः करदेय क्षमता बढ़ गई है। ऐसी धारणा का कोई पुष्ट आधार नहीं है। वस्तुतः प्रत्यक्ष कर कृषि की अपेक्षा औद्योगिक क्षेत्र एवं पेशेवर आय प्राप्त करने वाले के लिए उचित है। इन वर्गों के साथ इस सम्बन्ध में कोई भी नये कदम नहीं उठाये गये हैं। यह तो नहीं कहा जा सकता कि इन वर्गों की आय बढ़ी ही नहीं है, क्योंकि वास्तव में इन्हीं क्षेत्रों की आय में वृद्धि हुई है। एक ओर १९६१-[illegible] के अनुमानों के अनुसार राष्ट्रीय आय के कृषि का [illegible] ०.३ प्रतिशत घट गया है तो दूसरी ओर विभिन्न क्षेत्रों [illegible] २.९ प्रतिशत से लेकर अधिकतम १२.६ प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। सरकारी आंकड़ों की इस सत्यता के उपरान्त [illegible] कृषि के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है ? कहीं इस [illegible] पीछे यह धारणा तो नहीं है कि यह वर्ग स्वेच्छापूर्वक अप[illegible] योगदान नहीं दे रहा है, अतएव इस प्रकार कर लगाना [illegible] उचित है।

वास्तव में राष्ट्र की ऐसी संकटमय स्थिति में प्रत्ये[illegible] व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार योग दे रहा है। प्रत्ये[illegible] वर्ग अपनी-अपनी क्षमतानुसार धन अर्पण कर रहा है [illegible] चूंकि कृषि अत्यधिक व्यक्तिगत पेशा है, इसलिए इस[illegible] योगदान एक संगठित रूप में न होकर यत्र-तत्र बिख[illegible] हुआ है और सम्भवतः इसी कारण उसके त्याग [illegible] बहुत चर्चा नहीं हो सकी है। इसका अर्थ यह नहीं है [illegible] किसान कुछ नहीं या कम दे रहा है। यह प्रत्येक व्यक्ति [illegible] स्पष्ट होना चाहिए कि राज्यों के जिलों में प्रतिरक्षा के लि[illegible] एकत्रित धनराशि का अधिकतर भाग ग्रामीण क्षेत्रों से [illegible] प्राप्त होता है। एकत्र किये गये लाखों रुपये केवल मा[illegible] शहरों अथवा उद्योगपतियों से ही नहीं आते। वे उन व्य[illegible] क्तियों से प्राप्त होते हैं जो खेतों में हल चलाते हैं—यद्यपि [illegible] उनका व्यक्तिगत योगदान थोड़ा ही होता है। किन्तु इस थो[illegible] भाग को देने वालों की संख्या इतनी अधिक है कि एकत्रि[illegible] होने पर वह एक बड़ी राशि हो जाती है, जो वास्तव [illegible] किसी उद्योगपति के निजी योगदान से अवश्य ही अधि[illegible] होगी। साथ ही नये अप्रत्यक्ष करों के लगाने एवं दर बढ़ा[illegible] के फलस्वरूप कृषकों का बढ़ता हुआ योगदान स्पष्ट ही [illegible] है। तब फिर निर्धन कृषक की क्षीण आय पर प्रत्यक्ष क[illegible] की कुल्हाड़ी क्यों चलाई जाय ? सम्भव है कि यहां कोई [illegible] यह तर्क प्रस्तुत करे कि द्रव्य की अत्यधिक आवश्यकता है [illegible] और ऐसी स्थिति में कोई भी छोड़ा नहीं जा सकता। [illegible] किन्तु उन लोगों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि आय प्रा[illegible] करने के अन्य उपाय भी हैं और यह आवश्यक हो जाता [illegible] है कि पहले हम उन उपायों से आय प्राप्त करें। क्यों[illegible]

(शेष पृष्ठ १८७ पर)

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नियोजित अर्थ-व्यवस्था में पूंजी का महत्व

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल

● वित्त मन्त्री के इस कथन में यथेष्ट यथार्थ है कि पिछले दो वर्षों में औद्योगिक विकास के लिए जनता से जितनी नयी पूंजी अपेक्षित थी, उससे अधिक मिली। इससे देश में पूंजी के प्रवाह का पता लगता है। इसका एक कारण तो यह हो सकता है कि पूंजी लगाने वालों को राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में विश्वास और दूसरा कारण कांग्रेस सरकार द्वारा समन्वित प्रणाली में आस्था है।

यह स्पष्ट है कि दोनों विचारधाराओं में काफी अन्तर होते हुए भी उनका लक्ष्य एक है। कि भारत की अर्थ-व्यवस्था सुनियोजित होनी चाहिए। व्यवहार में दोनों सहमत हैं कि राष्ट्र की कर-नीति ऐसी हो कि अधिक बचत की जा सके। इस सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि हमारी योजनाएं इस प्रकार बनायी जायं कि राष्ट्रीय आय बढ़े, लोगों को रोजगार मिले, लेकिन साथ ही लोगों की आय और सम्पत्ति में अधिक से अधिक समानता रहे। लेकिन, योजना में समाजवाद को वितरण का केवल साधन मात्र नहीं माना गया है। समाजवाद की सार्थकता तो इसमें है कि औद्योगिक विकास और भी तेजी से हो। वितरण का महत्व कम नहीं है पर विकसित देशों में उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। विभिन्न देशों की कर-प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि नियोजित विकास के लिए देश के आन्तरिक और बाह्य साधनों को कैसे जुटाया जाय।

योजना आयोग ने सुझाया है कि यदि १९६०-६१ की राष्ट्रीय आय को १३,००० करोड़ रुपये से बढ़ाकर १९६५-६६ में १७,००० करोड़ रु० करना अभीष्ट हो तो तीसरी योजना में कम से कम १६,४०० करोड़ रु. लगाना होगा। वस्तु स्थिति यह है कि दूसरी योजना में अतिरिक्त करों द्वारा १,०५२ करोड़ से अधिक की आय हुई, लेकिन ४,६०० करोड़ रु. की योजना में केवल १,०९० करोड़ रु.की विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की गई थी। अब तीसरी योजना पूरी करने के लिए नये करों द्वारा १,७१० करोड़ प्राप्त करना होगा। किसी भी हालत में विदेशी सहायता पर अधिक निर्भर करना उचित नहीं है। चौथी और पांचवीं योजनाओं को अपने ही साधनों से पूरा करना होगा। फिलहाल राष्ट्रीय आय का ८.९ प्रतिशत करों द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसे तीसरी योजना में ११ प्रतिशत तक बढ़ाना है।

कर लगाने की पद्धति चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो, प्रायः जटिल होती है। कर लगाते समय बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है ताकि आर्थिक ढांचे पर कोई आंच न आये। किसी उद्योगपति ने कहा था कि एक सीमा के बाद उद्योगों से प्राप्त होने वाली सारी आमदनी करों के के रूप में चली जाती है। ऐसी हालत में उद्योगों में धन लगाने की प्रेरणा समाप्त हो जायेगी। निजी क्षेत्रों में लगातार अधिक कर लगाने से बचत में कमी होती रही है और पूंजी निर्माण की गति मन्द हो गयी है। इसके लिए आर्थिक अनुसन्धान की राष्ट्रीय परिषद् बधाई की पात्र है क्योंकि उसने सरकार को इस तथ्य से आगाह कर दिया है। हाल ही के नवीनतम सर्वेक्षण से देश में आमदनी और बचत सम्बन्धी दो तथ्य प्रकाश में आये हैं। उसके अनुसार आमदनी की अपेक्षा बचत में उत्तरोत्तर कमी होती जा रही है।

बचत का क्रम

इसका कारण यह है कि लगभग ८५ प्रतिशत परिवारों की आमदनी ३,००० रुपये वार्षिक से कम है। बचत में इनका कोई योग नहीं रहता। १५,००० रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले सम्पन्न ०.७ प्रतिशत परिवार कुल बचत का १२५ प्रतिशत देते हैं। सर्वेक्षण से यह भी मालूम हुआ है कि ३००० रु० वार्षिक से कम आय वाले परिवारों के बजट में १८७ रु० से ५०० रु० तक और २००० रु० से २११० रु० वार्षिक आय वालों में २४ रु० तक कमी बनी रहती है। इतनी आय तक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कोई आय कर नहीं देना पड़ता। ३००० रु० से ३१११ रु० तक की आय वालों में १५ रु० और ४००० रु० से अधिक आय वालों में ८.१ प्रतिशत और २५,००० रु० से अधिक आय वालों में ४४.५ प्रतिशत की बचत होती है। नागरिक बचत की दर १३.७ प्रतिशत है लेकिन देहाती बचत के साथ यह गिरकर १० प्रतिशत हो जाती है। यदि बचत की यह राशि १९७५ ई० तक दुगुनी हो जाय तो राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था आत्म-निर्भर बन जायगी।

कहा जाता है कि १२०० रु० वार्षिक से कम आमदनी वाले परिवारों पर अप्रत्यक्ष करों का प्रभाव ५ प्रतिशत से भी कम पर पड़ता है। लगभग १२३ लाख शहरी परिवारों में ६० लाख परिवारों का बजट घाटे का होता है। ६००० रु० से अधिक आमदनी वाले ५ लाख परिवारों से कुल शहरी आमदनी का २५ प्रतिशत आता है और उन्हीं से सारी बचत की रकम मिलती है। मध्यम परिवारों ने विकास-कार्यक्रम में काफी योग दिया है। लेकिन इस स्तर पर अधिक बचत बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यदि विकास के कामों के लिए आर्थिक साधन देश के भीतर से जुटाने हैं तो सरकार की कर नीति में भी परिवर्तन वांछनीय होगा। जो लोग अपेक्षाकृत कुछ अधिक सम्पन्न हैं और उद्योगों में धन लगाने को उद्यत हैं वे अधिक करों के बोझ से दबे हुए हैं और उनकी बचत दिनों दिन कम होती जा रही है। सर्वेक्षण से यह भी पता लगा है कि ३०० रु० वार्षिक से कम आय वाले परिवार अच्छी तरह जीवन निर्वाह नहीं कर पाते। बचत के लिए या तो उनकी आमदनी बढ़ानी होगी या उपभोग की वस्तुओं का मूल्य घटाना होगा। यदि मध्यम आमदनी वालों से बचत की व्यवस्था अभीष्ट है, तो सरकार को कर घटाने होंगे, अन्यथा मध्यम वर्ग की कमर टूट जायगी।

कर नीति

आर्थिक विकास के साथ करों द्वारा होने वाली आय भी बढ़नी चाहिए। इसके लिए कर-सम्बन्धी नीति को सुदृढ़ बनाना होगा। तभी अतिरिक्त कर सुलभ होंगे और योजना सफल होगी। योजना की अवधि में निजी उद्योगों का उत्तरदायित्व निश्चित किया जा चुका है। कुछ लोगों की धारणा है कि योजना का अर्थ केवल सरकारी उद्योगों का विकास है लेकिन सत्य तो यह है कि निजी उद्योगों का योजना सफल बनाने में उतना ही महत्वपूर्ण भाग है। पूंजी लगाने के लिए बचत की दर काफी ऊंची होनी चाहिए तभी जनता की खुशहाली बढ़ेगी। कुछ लोगों का तर्क है कि आय की सीमा निर्धारित कर देने से योजना के लिए आवश्यक धन की समस्या हल हो जायगी क्योंकि निश्चित सीमा के ऊपर सारा धन योजना में लगा दिया जायगा जो कि कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम होगा। लेकिन यह तर्क हास्यास्पद है। वास्तव में इसका परिणाम उलटा होगा। आमदनी की सीमा निश्चित कर देने से आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जायगा। सरकारी हस्तक्षेप के कारण अभी से उसका दम घुट रहा है और यदि आय की सीमा निश्चित की गई तो गरीबी और बेरोजगारी दूर करने का साधन भी बन्द हो जायगा जिससे सामाजिक संघर्ष बढ़ जायगा। "कुछ लोगों के हाथों में पूंजी एकत्र हो रही है" यह नारा मिथ्या है और पूंजीवाद को बदनाम करने का तरीका है। सत्य तो यह है कि राज्य के हाथ में सारी राजनीतिक और आर्थिक सत्ता केन्द्रित हो रही है, जिसके विकेन्द्रीकरण की बड़ी आवश्यकता है जब नेतागण आर्थिक समानता का नारा उठाते हैं तो भोली भाली जनता उन पर मुग्ध हो जाती है। लेकिन चुनाव के पहले के नारे चुनाव जीतने के बाद नहीं रहते और अब सरकार को वस्तु स्थिति का सामना करना होगा।

पूंजी निर्माण

हमारी अर्थ-व्यवस्था में पूंजी निर्माण के काम में अच्छी प्रगति हुई है। पहली पंचवर्षीय योजना में ३,७०० करोड़ रु० से बढ़कर दूसरी योजना में ७.४०० करोड़ रु. पूंजी एकत्र हुई। ऐसा मालूम होता है कि पूंजी निर्माण के काम में पहले १९५५-५६ और १९५६-५७ और फिर १९६०-६१ में तेज प्रगति हुई। रिजर्व बैंक के आंकड़ों से पता लगता है कि १९५०-५१ में पूंजी का निवेश लगभग ७ प्रतिशत था जो बढ़कर १९५५-५६ में करीब १० प्रतिशत और १९५८-५९ में ११ प्रतिशत हो गया। केन्द्रीय सांख्यिकीय संस्था ने सुझाव दिया है कि कुल पूंजी निर्माण में निजी क्षेत्रों से करीब ७५ से ८०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की सदी तक रकम लगाई जाती है। ऐसे तो देखने में इससे आर्थिक प्रगति में सुधार मालूम होता है लेकिन अन्य देशों की तुलना में वह बहुत कम है। अमेरिका में करीब १८ प्रतिशत, जापान में २९ प्रतिशत और जर्मनी में लगभग २४ प्रतिशत है। कुछ लोग इन आंकड़ों को मानने से इनकार कर सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की बचत का चित्र भ्रामक है लेकिन इतना तो सर्वमान्य है कि हमारी आर्थिक प्रगति बहुत धीमी है और उसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। यह तभी सम्भव है जबकि अन्य देशों की तरह यहां भी बचत बढ़ायी जा सके। हमारे गांवों और नगरों में पूंजी निर्माण के काम में इतना भेद है कि विकास कार्यों का सारा बोझ केवल शहरी जनता को उठाना पड़ता है। इस स्थिति को दूर करना होगा।

मूल्य वृद्धि

योजना आयोग को विश्वास था कि उद्योगों में लगाने के लिए ६,२०० करोड़ रु० की रकम जुटाने और योजना के लिए ४८०० करोड़ रु० प्राप्त करने से चीजों के मूल्यों पर अनुचित प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन, चीजों की कीमतों में ३५ प्रतिशत बढ़ती हुई। बचत की स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यदि (१९५२-५३) वस्तुओं का मूल्य स्थिर रहता तो द्वितीय योजना में ५,२०० करोड़ रु. बचत की व्यवस्था होती, लेकिन वास्तविक बचत केवल ४,१४० करोड़ रही। इस २० प्रतिशत कमी का कारण सरकार की कर लगाने की नीति है। आशा की जाती है कि तीसरी योजना में निजी क्षेत्रों से औद्योगिक विकास के लिए, ४,१०० करोड़ रु. प्राप्त हो सकेंगे और साथ ही ८.९ प्रतिशत कर की दर भी ११% हो जायगी। योजना आयोग और वित्त मंत्रालय का मुख्य दायित्व योजना को सफल बनाना है। इसके लिए अपनी वित्तीय प्रणाली इस प्रकार बनानी है कि अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके और बचत में बढ़ती होती रहे। कम्पनियों पर लगाया जाने वाला कर ऐसे स्तर पर हो कि पब्लिक और प्राइवेट लि० कम्पनियों को लाभ के आधार पर काम चलाने का अवसर मिले। किसी समाजवादी समाज में संपत्ति कर और उपहार-कर का औचित्य तो सिद्ध किया जा सकता है लेकिन किसी कम्पनी के शेयर होल्डर के लाभांश पर दुहरा और तिहरा कर लगाना कहां तक उचित है। कर सम्बन्धी कानूनों में ऐसी खामियां हैं, जिनके कारण लोग कर अदा करने से मुकर जाना चाहते हैं।

(पृष्ठ १८४ का शेष)

अकारण ही कृषक वर्ग को क्षुब्ध किया जाय और क्यों राष्ट्र व्यापी उत्साह और एकता की लहर को विलीन होने दिया जाय? प्रश्न यह उठता है कि वे अन्य उपाय कौन से हैं?

वैकल्पिक उपाय

हमें आय के लिए कृषि के अतिरिक्त अन्य साधनों को खोजना चाहिए। यह एक सापेक्षतः निर्धन वर्ग है, अतएव इस वर्ग से अप्रत्यक्ष कर के रूप में ही कुछ अधिक मांगना उचित होगा। यदि सरकार को यह विश्वास हो कि कृषि की बारी आ गई है तो यह अधिक उपयुक्त होगा कि बिक्री कर की दरें बढ़ा दी जायं, ताकि कृषक वर्ग का योगदान बढ़ सकें। किन्तु ऐसा करने से पहले अन्य विकल्पों, जैसे मनोरंजन कर एवं विलासिता की वस्तुओं पर लगे कर की दरों को पहले बढ़ा देना चाहिए। दूसरे, राज्यों को हर दिशा में मितव्ययिता बरतनी चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि मितव्ययिता के फलस्वरूप कुछ लाख रुपये ही तो उपलब्ध होंगे और इतने बड़े कार्य के लिए इतनी सी राशि की क्या उपयोगिता है? यदि सभी राज्य ऐसी नीति का अनुसरण करेंगे तो कुल मितव्ययिता के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण देश में करोड़ों रुपये की बचत होगी। अतएव राज्यों को मितव्ययिता का हर साधन अपनाना चाहिए। भले ही इसके लिए मंत्रिगण स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर मन्त्रिमन्डल को घटायें या प्रशासन सम्बन्धी सुधार बरतें, क्योंकि बचत किया हुआ रुपया तो अर्जित रुपये के समान ही है। अतएव कृषक वर्ग पर प्रत्यक्ष कर लगाने के पहले हमें उपर्युक्त उपायों पर भी अमल करना चाहिए। इसके फलस्वरूप एक ओर तो कृषक वर्ग का उत्साह बढ़ेगा और दूसरी ओर जब कृषक वर्ग की कर देनी की बारी आयेगी तो वह स्वेच्छा एवं उत्साह से इस दिशा में आगे बढ़ेगा। राष्ट्र के इस विशाल जन समुदाय का मनोबल और उत्साह राष्ट्र की सबसे बड़ी सम्पत्ति है। उसे क्षुब्ध कर मनोबल और उत्साह को क्षीण करना एक भूल है और अगर कहीं भूल हो गई हो तो उसे सुधारना हमारा कर्तव्य होना चाहिए।

● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नयी कर-नीति और उद्योग

राष्ट्र का निजी उद्योग व व्यापार देश की आर्थिक समस्याओं को किस दृष्टि से देखता है, यह अ. भा. उद्योग व्यापार मण्डल के अध्यक्ष श्री श्रेयांसप्रसाद जैन के विचारपूर्ण अध्यक्षीय भाषण से स्पष्ट है।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत ने जान बूझकर राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक विकास का मार्ग चुना है। सामरिक तैयारी और आर्थिक विकास—इन दोनों में से हमने पिछले को ग्रहण किया है क्योंकि इससे आम जनता का जीवन-स्तर ऊंचा होगा। हमारी यह पसन्द व्यर्थ नहीं गयी है। हमारी योजनाओं से जो फल-प्राप्ति हुई है, वह भले ही "छलांग लगाने" के सदृश न हो पर है वह बड़ी मार्के की। उसके भीतर उज्जवल भविष्य के तत्व मौजूद हैं। पहली दो योजनाओं की अवधि में कुल राष्ट्रीय आय ४२ प्रतिशत वार्षिक बढ़ गयी है पर लगभग २ प्रतिशत वार्षिक आबादी की द्रुत वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय १८ प्रतिशत के लगभग बढ़ी है। प्रत्येक क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता का प्रादुर्भाव हो गया है अथवा क्षमता का निर्माण हो रहा है। न केवल नगरों, किन्तु देहात में भी जीवन का स्तर सुधर रहा है।

दुर्भाग्य से पिछले दो वर्षों में औद्योगिक उत्पादन की गति मंद हो गयी है, यह केवल ७ प्रतिशत बढ़ी, जब कि १९६० में १०.८ प्रतिशत बढ़ी थी। इसके साथ, प्रति व्यक्ति आय भी, केन्द्रीय सांख्यिकी संघ के अनुसार १९६१-६२ कुछ विशेष नहीं बढ़ी। इस मन्दगति के कई सम्मिलित कारण हैं, जैसे परिवहन, बिजली, औद्योगिक कच्चा माल, पूंजीगत सामान की कमी।

फेडरेशन की पूरी जानकारी के अनुसार, निजी क्षेत्र ने सुरक्षा प्रयत्नों को बढ़ाने के लिए तत्काल जिस सहयोग की भावना को पेश किया था, अधिकारियों द्वारा उससे कोई लाभ नहीं उठाया गया। उद्योगों के विकास और विस्तार की योजनाओं पर क्रियात्मक रूप में अवरोध लगा दिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि २११ उद्योगों के प्रार्थना पत्रों को लाइसेंस देने पर अब बिल्कुल विचार नहीं किया जाएगा। पूंजीगत सामान के आयात के लिए जिन उद्योगों को प्राथमिकता की सूची पर रखा गया है, उन की संख्या बमुश्किल २१ है। इस संकट काल में भी सरकारी नीति पुराने ढर्रे पर चल रही है, और स्थिति का मुकाबला करने के लिए प्रभावशाली और शीघ्र कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में यह तथ्य भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस देश में जितने मूल्य का माल पैदा किया जाता है और सेवाएं दी जाती हैं, उनमें ९० प्रतिशत से अधिक का योगदान निजी क्षेत्र द्वारा होता है। यह अवसर तो ऐसा था, जब दोनों क्षेत्रों से संयुक्त रूप से पूरा लाभ उठाया जाता।

देश की बढ़ रही सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्त मंत्री को भागीरथ प्रयत्न करने पड़ेंगे, इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता। देश की अवस्था को दृष्टि में रखते हुए अतिरिक्त बोझ उठाने में भी किसी को शिकायत नहीं है। पर प्रश्न यह है कि क्या इन कर प्रस्तावों से आर्थिक विकास रुक नहीं जाएगा और उत्पादन धीमा नहीं हो जाएगा? वित्त मंत्री ने अपने बजट-भाषण में यह प्रशंसनीय शब्द कहे हैं कि उत्पादन बढ़ाने का विशेष दायित्व निजी क्षेत्र पर है और हमें प्रत्येक ऐसा सम्भव उपाय करना पड़ेगा जिससे कृषि और उद्योग—लघु व बृहत्—दोनों की पूरी शक्ति हमारी लक्ष्य-सिद्धि में संगृहीत हो सके। पर, वित्त मंत्री के कर प्रस्तावों से उत्पादन में रुकावट आएगी और उद्योगों के लिए धन प्राप्त करने के सभी स्रोत सूख जाएंगे। यदि ३०० करोड़ रुपये की बड़ी राशि एक बार ही करों से उगाही जाएगी तो निजी उद्योगों के लिए धन कहां से आएगा?

प्रत्यक्ष करों में काफी वृद्धि की गयी है। इसका बोझ वेतन भोगी जनता और मध्य वर्ग के लोगों को ही उठाना पड़ेगा। जो अधिभार लगाया गया है, वह इतना अधिक है

सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कि उपर्युक्त दोनों प्रकार के वर्गों की पूरी बचत का ही उससे सफाया हो जाएगा। यही हाल निगम या कम्पनी क्षेत्र का भी होगा। ये न कुछ बचत कर सकेंगे और न ही डिविडेंड बांट सकेंगे। निगम क्षेत्र में जो सुव्यवस्थित कम्पनियां हैं, उन पर यह अतिरिक्त अधिभार १५ प्रतिशत से २५ प्रतिशत पड़ेगा और कुछ हालात में तो इससे भी ज्यादा। इस भयंकर कर को युक्ति संगत सिद्ध करने के लिए चाहे कितने तर्क उपस्थित किये जाएं, पर इतना तो निःसंकोच कहा जा सकता है कि इससे उद्योग के सब साधन ठप्प हो जाएंगे और तीसरी योजना में निजी उद्योग पर जो दायित्व डाला गया था, उस पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। योजना के निर्माताओं ने तो यह समझ लिया था कि निजी निगम-क्षेत्र तीसरी योजना के ५ वर्षों में देश के आन्तरिक साधनों से ६०० करोड़ रु० प्राप्त कर के उद्योग में लगा सकेगा। इसमें से आधी रकम लाभ से प्राप्त होनी थी। अधिभार कर से यह, वस्तुतः, प्राप्त करनी असम्भव हो जायगी।

मूल्य तो बढ़ेंगे ही

आयात तटकरों में वृद्धि, नये शुल्क, केन्द्रीय बिक्री कर का दुगुना किया जाना, उद्योग पर अन्य अतिरिक्त बोझ—आपात कालीन संकट बीमा को शामिल न करते हुये भी—इन सब को दृष्टि में रखते हुए मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता हूँ कि इनसे कुछ मूल्य वृद्धि अवश्य होगी। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि जनता को यह समझा दिया जाए कि इस प्रकार की मूल्य वृद्धि न्याय संगत है और उसे सहन करना ही होगा, बजाय इसके कि यह कहा जाए कि कर और मूल्य वृद्धि का आपस में कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। मैं यह अनुभव करता हूँ कि उपभोक्ता इससे विचलित होगा, इस लिए यह दायित्व सरकार का है कि व्यापारी वर्ग की स्थिति को स्पष्ट कर दे।

पिछले दशक में हमारा विश्व व्यापार २ प्रतिशत से कम होकर १ प्रतिशत रह गया है। यह हमारे लिए चुनौती है और हमें इसका दृढ़ता और पूर्णता से मुकाबला करना होगा। हम अपनी निर्यात समस्याओं को अन्य समस्याओं से विच्छिन्न नहीं कर सकते, न ही उनका आंशिक रूप से निराकरण कर सकते हैं। हमें सोचना होगा कि किन कारणों से न केवल हमारा माल आकर्षक नहीं होता, किन्तु विदेशी ग्राहक के लिए मूल्य भी प्रतिस्पर्द्धात्मक नहीं होता। कुछ कारणों से इस समस्या के विभिन्न अंगों पर पूर्ण रूप से विचार नहीं किया गया है। इसके विपरीत घरेलू उपभोग कम करने पर ही जोर दिया जाता रहा है। हमारे इस दृष्टिकोण के विपरीत ब्रिटेन के सांझे बाजार में प्रवेश होने की बात चीत टूट जाने के बाद, वहां के प्रधान मन्त्री ने जो पंच सूत्री कार्यक्रम निर्धारित किया है उसमें उपभोक्ता की मांग की वृद्धि पर बल देते हुए इसे निर्यात की मांग का आधार बताया गया है। हमें इन सब अवरोधों को दूर कर कुछ नये कदम उठाने होंगे।*

* अध्यक्ष के भाषण का सारांश

देश की रक्षा करनी सीखो
जीना है तो मरना सीखो।

उषा

★ सामाजिक कहानियां, शिक्षाप्रद कथानक, विचारोत्तेजक मनोरंजक लेख, राशिफल, सरस, कविताएं आदि।

★ हानिकारक वस्तुओं, व अश्लील फिल्मों के विज्ञापन स्वीकार नहीं किये जाते।

—यदि आपने अभी तक उषा नहीं देखी है तो शीघ्र ही ३२ न० पै० की टिकिट या मनीआर्डर भेजकर नमूनांक मंगा देखिये। हमें पूरा विश्वास है कि एक बार 'उषा' को देखने के बाद आप हमेशा के लिए उसके हो जाएंगे।

—अन्य जानकारी के लिए लिखिये
सचित्र मासिक उषा कार्यालय,
जवाहर मार्ग, इन्दौर।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नया सामयिक साहित्य

पारिभाषिक शब्द संग्रह—केन्द्रीय हिन्दी निर्देशालय, शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा प्रकाशित। पृष्ठ-संख्या १३००, मूल्य १२ रु०।

अनेक वर्षों से हिन्दी को राजभाषा और शिक्षा का माध्यम बनाने की दिशा में यह प्रयत्न किया जा रहा था कि अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी पर्याय प्रकाशित किये जायें। इस कार्य के लिए सैंकड़ों विद्वानों का सहयोग प्राप्त किया गया है। विभिन्न वैज्ञानिक राजनीतिक अर्थशास्त्रीय, पारिभाषिक शब्दों के पहले अलग-अलग कोष प्रकाशित किए गए थे। किन्तु वर्तमान ग्रंथ में उन शब्दों के बिना विषय का विचार किए अक्षर क्रम से दिया गया है, विशेषज्ञों की सूची से मालूम पड़ता है, कि प्रस्तुत पुस्तक में शासन प्रबन्ध, कृषि, वनस्पतिशास्त्र, रसायन, प्रतिरक्षा, इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, कूटनीति, चिकित्सा, शिक्षा, भूगोल, भूगर्भशास्त्र, गणित, यातायात, परिवहन, रेलवे, कानून, आदि बहुत से विषयों के पारिभाषिक शब्दों का समावेश है। कुछ शब्द ज्यों के त्यों अंग्रेजी के ही अपना लिए गये हैं। यदि ऐसे शब्दों का दो-एक पंक्तियों में कुछ परिचय दे दिया जाता तो कलेवर तो अवश्य बढ़ जाता, किन्तु विषय स्पष्ट हो जाता। बहुत से शब्द अप्रचलित, और असाधारण रूप से कठिन दीखेंगे। किन्तु इसी कारण उनका प्रयोग न हो, यह उचित नहीं। प्रयोग से शब्द में शक्ति आती है। आवश्यकता यह है, कि सरकार इन शब्दों को स्वयं अपने प्रकाशनों में प्रयुक्त करना शुरू करे। इस कोष में अभी संशोधन की आवश्यकता न हो, यह बात नहीं है। किन्तु इसी कारण इसके प्रयोग में विलम्ब नहीं करना चाहिए। अर्थशास्त्र के शब्दों को हमने विशेष रूप देखा है वे अधिकांश ठीक दीखते हैं।

स्टैटिस्टिकल एब्सट्रेक्ट राजस्थान (१९६१)—डायरेक्टरेट आफ इकनामिक्स एण्ड स्टैटिक्स, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रकाशित।

पौने चार सौ पृष्ठ की इस बृहदाकार पुस्तक राजस्थान सम्बन्धी बहुत अधिक जानकारी दी गई है। १९६१ की जनगणना के बाद की विविध जानकारी देने के कारण यह ग्रन्थ अधिक उपयोगी और पूर्ण बन है। राजस्थान की जनसंख्या, क्षेत्रफल, कृषि, सिंच उद्योग, शिक्षा, जलवायु, जंगल, पशु, खनिज, ई बिजली, व्यापार, स्वास्थ्य, पंचायत, सहकारी समि राजस्थान का बजट आदि बहुत सी उपयोगी जानकारी पुस्तक से मिलेगी। राजस्थान के सम्बन्ध में यह सब जा कारी संगृहीत करने में बहुत प्रयत्न किया गया है। कारण राजस्थान के अधिकारियों, सार्वजनिक कार्यकर्ता पत्रकारों और अर्थशास्त्रियों के लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी होगी। बीच-बीच में अनेक नक्शे, ग्राफ़ दे देकर भी इसे अधिक उपयोगी बना दिया गया है।

अन्त में हम एक नम्र निवेदन अवश्य करना च हैं। पिछले ३-४ वर्षों से राजस्थान सरकार द्वारा यह घो की जाती रही है कि राज्य सरकार का सब कारोबार हि में हुआ करेगा। यदि यह पुस्तक हिन्दी में प्रकाशित जाती तो हमारी सम्मति में इस पुस्तक का लाभ संख्या में लोग उठा सकते। सम्भवतः एक भी शि राजस्थानी ऐसा न होगा जो हिन्दी न जानता हो। इ विपरीत अंग्रेजी न जानने वालों की संख्या ९८ प्रति से अधिक ही होगी। केवल ५ प्रतिशत के लिए अंग्रे में इतनी जानकारी पूर्ण ग्रन्थ निकालना कहां तक ठीक यह राजस्थान के अधिकारियों के सोचने की चीज है।

पंचायती राज को जानिये—लेखक श्री गुरुशर

ग्राम पंचायत—लेखक श्री विनोबा

सहकारिता और पंचायती राज—लेखक श्री हरिदास सहयोगी।

ये तीनों पुस्तकें अखिल भारत सेवा संघ के प्रका हैं और राजघाट वाराणसी से प्राप्य हैं। इन तीनों विषय अपने नाम से स्पष्ट है। आज विभिन्न राज्यों जिस वेग से पंचायती राज्य स्थापित किए जा रहे हैं, देखते हुए यह आवश्यक है कि कार्यकर्त्ताओं को पंचा के संगठन और उनकी कार्यविधि तथा आदर्शों का अ परिचय हो। आज के दलीय शासन की पद्धति में रा नीतिक दलों की शक्ति प्राप्त करने की दुर्दम्य इच्छा पंचा

सम्प

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के असली उद्देश्य को समाप्त न कर दे, इसकी चेतावनी देते हुए लेखकों ने पंचायत सदस्यों के अधिकारों और कर्तव्यों पर विशेष प्रकाश डाला है।

१. भारतीय संस्कृति
२. श्री योगवासिष्ठ सार
३. श्री शंकराचार्य का मायावाद

इन तीनों पुस्तकों के लेखक दर्शनशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर श्री भीखमलाल आत्रेय हैं और तीनों का प्रकाशन दर्शन प्रिण्टर्स मुरादाबाद ने किया है।

आज के भौतिक सभ्यतावादी युग में, जबकि भारत भी पश्चिम की भाषा में बोलने और विचार करने लगा है, यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हम पहले अपने दर्शन और अपनी विचारधारा को तो समझ लें। आज की अंग्रेजी शिक्षा ने हमें अपने से ही विमुख कर दिया है। हम सोचने लगे हैं कि हमारे यहां ऊंचे जीवन की कोई पद्धति ही न थी। यह पुस्तक हमारे इस भ्रम को दूर कर देगी। हमारी अपनी प्राचीन संस्कृति आध्यात्मिकता मात्र ही नहीं थी, नैतिक और सामाजिक तत्व भी उसे बहुत ऊंचा व जीवन योग्य बनाते हैं और इसे हम बहुत गर्व के साथ संसार के विद्वानों के समक्ष रख सकते हैं।

दूसरी पुस्तक ३२००० श्लोकों के प्रसिद्ध योगवासिष्ठ के चुने हुए सारभूत श्लोकों का संग्रह है और उनका हिन्दी व अंग्रेजी में अनुवाद भी दे दिया गया है। अध्यात्म साहित्य में योग वासिष्ठ का असाधारण महत्व है। इस संक्षेप से सामान्य जन भी इसका लाभ उठा सकेंगे।

तीसरी पुस्तक विद्वान् लेखक के गंभीर परिश्रम का फल है। इसमें शंकराचार्य के मायावाद की चर्चा करते हुए गंभीर अध्ययन व युक्तियों के द्वारा यह भी सिद्ध किया है कि न वेदान्त सूत्र और न उपनिषदें उस मायावाद का समर्थन करती हैं, जिसका प्रतिपादन शंकराचार्य ने किया है। उन्होंने तो परिस्थितियों के वश होकर वैसा अर्थ किया। एक अत्यन्त विवादग्रस्त गंभीर प्रश्न के विवेचन के लिए लेखक बधाई का पात्र है। यदि लेखक त्रैतवाद का दार्शनिक और व्यावहारिक रूप से अधिक चिन्तन करते तो विषय और भी स्पष्ट हो जाता।

बुद्धचित्रावली—लेखक—श्री जीतमल लूणिया। प्रकाशक—हिन्दी साहित्य मन्दिर ब्रह्मपुरी, अजमेर। मूल्य १.५० रु०।

लेखक एक सफल प्रकाशक हैं। उन्होंने प्रकाशन का एक ऐसा रोचक विषय चुना है, जो बहुत अधिक लोकप्रिय व शिक्षा पूर्ण है। महात्मा गांधी, सन्त विनोबा और पं० नेहरू की चित्रावलियां प्रकाशित करने के बाद बुद्ध-चित्रावली प्रकाशित की गई है। इसमें महात्मा बुद्ध के प्रारम्भिक काल से परिनिर्वाण तक की विभिन्न अवस्थाओं ४६ चित्र दिये गये हैं। बालकों को तथा कम या बिना पढ़े लिखे लोगों को इन चित्रों के दर्शन से विश्व की एक विभूति म० बुद्ध के चरित्र की जानकारी मिल जायगी। म० बुद्ध की संक्षिप्त जीवनी और कुछ मुख्य घटनाएं इन चित्रों से ज्ञात हो जाती हैं, फिर भी संक्षिप्त चरित और उनके प्रेरणात्मक सुन्दर उपदेश अन्त में दे दिये गये हैं। समस्त पुस्तक बढ़िया कागज पर सुन्दर छपाई में छापी गई है। सभी चित्र कलापूर्ण और सुन्दर हैं।

सुराना मध्यप्रदेश डायरेक्टरी—प्रकाशक—मैसर्ज सम्पतलाल हेमराज सुराना जैन, इंदौर सिटी। मूल्य ५ रु०, पृष्ठ संख्या लगभग साढ़े छः सौ।

प्रस्तुत पुस्तक मध्यप्रदेश की विविध आर्थिक राजनीतिक सरकारी और गैर सरकारी प्रवृत्तियों और संस्थाओं का परिचय प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इसकी आर्थिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों का परिचय न केवल मध्यप्रदेश वासियों के लिए, बल्कि समीपवर्ती राज्यों के व्यापारियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। मध्यप्रदेश नये संगठन के बाद भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य बन गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यहां भारत में सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से छठा या सातवां। मध्यप्रदेश की जनसंख्या, कृषि, उद्योग, शिक्षा, यातायात का परिचय जिला और तहसील-वार इसमें विस्तार से दिया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत होने वाली विविध प्रगतिशील प्रवृत्तियों का परिचय भी इसकी विशेषता है। मंडियों और व्यवसायों का परिचय व्यापारियों के लिए लाभकारी होगा। नये सिक्कों और नये माप तोल की तालिकायें भी व्यापारियों के लिए दी गई हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

श्रमिक और राजनीतिक दल

लेखकः—श्री जॉन हेलिंग

आज देश का श्रमिक आन्दोलन अधिकांशतः राजनैतिक दलों के प्रभाव में है। श्रम की समस्याओं का अपना भी अस्तित्व होता है, इसे भूलकर राजनैतिक दल श्रम का सत्ता प्राप्ति के अपने उद्देश्य के लिए ही प्रयोग करने लगते हैं। अमेरिका में इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है, यह इन पंक्तियों में पढ़िये।

यूरोप में मुझसे एक सवाल बार-बार पूछा गया—क्या अमरीका में श्रमिक दल (लेबर पार्टी) नहीं है ?

मेरे एक यूरोपियन मित्र ने कहा, "हमारी समझ में नहीं आता कि अमरीका के श्रमिक संगठनों के सदस्यों की संख्या डेढ़ करोड़ से भी अधिक है, फिर भी उन्होंने अपना राजनीतिक दल क्यों नहीं बनाया है ?

मैंने उन्हें समझाते हुए बताया कि इसके अनेक कारण हैं। इसका पहला कारण ऐतिहासिक है। अमरीका की सामाजिक स्थिति हमेशा ऊंच-नीच के भेद-भाव से रहित रही है। वहां कोई वर्ग-विभाजन नहीं रहा कि उसे तोड़ना पड़े। यूरोप के देशों के इतिहास पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि वहां श्रमिकों ने अपने राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक हितों को व्यक्त करने के लिए अपने राजनीतिक दल बनाये। उनके पास इसके अलावा और कोई जरिया नहीं था। परन्तु अमरीका में ऐसी स्थिति नहीं रही।

स्वभावतः, यहां निरन्तर भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक प्रगति होती रही, क्योंकि सौभाग्य से अमरीका में प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में हैं। यहां स्वाभाविक पैदाइश से और बाहर के लोगों के आने से आबादी बढ़ती गई और उन्हें भी इन साधनों को उपयोग में लाने से काम मिलता गया। फलतः जब भी इस प्रकार का कोई दल बनना शुरू हुआ, वह अधिक नहीं टिक सका।

दूसरे, अमरीका के लोगों ने किसी न किसी नाम से श्रमिक दल बनाकर भी देख लिया है। इस प्रकार का पहला प्रयत्न सौ वर्ष से भी पहले किया गया था। परन्तु वह केवल फिलाडेल्फिया शहर तक ही सीमित रहा। इस दल की पहली मांग थी कि शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क हो। इसके कुछ ही वर्ष बाद, तत्कालीन सभी राजनीतिक दलों द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रचलित करने का ध्येय केवल उसी दल तक सीमित न रहकर पूरे राष्ट्र का ध्येय बन गया।

समाजवादी दल

देश के औद्योगिक विकास के साथ-साथ अनेक श्रमिक प्रधान दल बने, परन्तु वे स्थानीय तथा देश के अन्य दूसरे से आगे न बढ़ सके। अमरीका में वर्ग-भेद न होने के कारण ही सम्भवतः समाजवादी दल सुदृढ़ नहीं हो पाया है। इस दशक पहले प्रगतिशील जनतंत्रवादी (प्रोग्रेसिव रिपब्लिकन), राबर्ट एम. लाफोलेटी के नेतृत्व में उनके दल को काफी मत मिले, पर उसका बहुमत केवल एक ही राज्य विसकौंसिन, में हुआ।

इसके कुछ वर्ष बाद डेमोक्रेटिक दल के टिकट पर फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट राष्ट्रपति चुने गये। उन्होंने श्रमिक और सामाजिक कानून बनाए। इससे अनेक लोगों को आश्चर्य हुआ, पर जो श्रमिक आन्दोलन को राजनीतिक रूप दे रहे थे, उन्हें सन्तोष हुआ। तात्पर्य यह कि अमरीका में श्रमिकों की राजनीतिक स्थिति यह है कि संगठित श्रमिक किसी भी राजनीतिक दल से गठबन्धन करने से इन्कार करके ही अपना अधिक से अधिक हित कर सकते हैं।

अमरीका के ट्रेड यूनियन वालों ने यह समझ लिया कि आर्थिक क्षेत्र में सामूहिक सौदेबाजी का जो तरीका अपनाया जाता है, वह राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनाया जा सकता है। मतदान की दृष्टि से, अमरीका के ट्रेड यूनियन आन्दोलन को यह विश्वास है कि वह 'अपने राजनीतिक मित्रों को पुरस्कार और राजनीतिक शत्रुओं को दण्ड' देने के तरीके से अपने हितों की रक्षा कर सकता

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है और प्रगति कर सकता है।

विभिन्न राजनीतिक दलों से सम्बन्ध

अनेक वर्षों तक ट्रेड यूनियन के सदस्यों और उनके परिवार वालों को लगा कि डेमोक्रेटिक दल उनके हितों को आदर से देखता है। परन्तु पिछले कुछ वर्षों के अन्दर, रिपब्लिक दल के उदार नेता यह सिद्ध करने लगे हैं कि श्रमिक-प्रबन्ध सम्बन्धों में श्रमिक संगठनों को उसका मैत्री-पूर्ण योग मिलेगा। जैसे, आइजनहौवर शासन में श्रम-मन्त्री श्री मिचेल को श्रम-विभाग के संचालन के लिए ट्रेड यूनियन आन्दोलन के अधिकांश भाग का आदर प्राप्त हुआ है। स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण विभाग—जो सामाजिक सुरक्षा का संचालन करते हैं और जिन्हें पहले-पहल फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने शुरू किया था, नियमों को सर्वोत्तम तरीके से लागू करने के लिए श्रमिक संगठनों के नेताओं की सलाह लेते हैं।

'ए. एफ. एल. सी. आई. ओ.' के प्रेसीडेंट जार्ज मीनी ने कहा है कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि अगर गैर-दलीय ढंग से श्रमिक संगठनों के हितों की ठीक तरह से रक्षा न की जाए—तो उनके किसी दल में शामिल हुए बिना—अमरीका के श्रमिक इसके विकल्प में अपनी राज-नैतिक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए श्रमिक दल बनाने की सम्भावनाओं पर विचार करेंगे। फिर भी अमरीका के श्रमिकों ने अब तक यही देखा है कि दो दलों के बने रहने से ही उनके राजनीतिक व्यय पूरे होते हैं और श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहती है।

विधि-सम्बन्धी कार्यक्रम

हर हफ्ते अमरीका का ट्रेड यूनियन आन्दोलन अपना विधिकारी कार्यक्रम बनाता है और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दल के सिनेटरों तथा कांग्रेसमैनों के सहारे विशेष प्रस्तावों को आगे बढ़ाता है। जो उनके प्रस्तावों का अनुमोदन या विरोध करते हैं, उनका रिकार्ड रखा जाता है।

सुरक्षा श्रम बैंक

सुरक्षा श्रम बैंक, ग्राम स्वयंसेवक दल योजना का अभिन्न अंग है। इस बैंक के द्वारा हम देशव्यापी स्तर पर गांवों के सबसे गरीब और कमजोर लोगों की सेवाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए खेती की पैदा-वार बढ़ाने के लिए और सामुदायिक निर्माण कार्यों के लिए वे शारीरिक श्रम कर सकते हैं।

इस योजना के अन्तर्गत वह आशा लगाई गई है कि गांवों के सब स्वस्थ स्त्री-पुरुष महीने में कम से कम एक दिन मुफ्त में काम करेंगे। परन्तु सामाजिक न्याय का यह तकाजा है कि गरीब खेतिहर मजदूरों को एक दिन से ज्यादा मजूरी करने पर जनता उन्हें उजरत दे। गांव की बुनियादी एजेंसी होने के कारण पंचायत को ग्राम स्वयंसेवक दल की मार्फत यह बैंक संगठित करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बैंक के साधनों से अधिकतम पैदा-वार की जाए और आय बढ़ानेवाले साधन बनाए जाएं।

जो लोग श्रम या धन देंगे उनके नाम एक रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे जो पंचायत के पास रहेगा। ग्राम उत्पादन कार्यक्रम और अपने क्षेत्र की साधन सम्भावनाओं को देखते हुए पंचायत ऐसे विशिष्ट कार्यक्रम निर्धारित करेगी, जिसमें इस संचित श्रम का उपयोग हो सकेगा। पंचायत यह भी तय करेगी कि कौन से निर्माण कार्य चलाए जाएं, श्रमदान का उपयोग कब और किस तरह किया जाए तथा श्रम की ठोस योजना बनाई जाए। ऐसा करते समय श्रमदान करने वालों से भी सलाह ली जाएगी। ग्राम सभाओं के लगभग सभी सदस्य अपनी मर्जी से बैंक के लिए श्रम करने को तैयार हैं। कुछ चुने हुए कार्यों पर बराबर श्रमदान कराया जाता रहेगा ताकि जो काम हाथ में लिया गया है वह कम से कम समय में पूरा हो सके। ● ●

सम्पदा के
आगामी विशेषांक की
घोषणा की
प्रतीक्षा कीजिये

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थ वृत्त चयन

आर्थिक प्रक्रिया की तीन प्रणालियां

आर्थिक प्रक्रिया के तीन तरीकों—सहकारिता, प्रतिस्पर्द्धा और जोरजबर्दस्ती में से सहकारिता प्रमुख तरीका है। तानाशाही और कम्यूनिजम के अन्तर्गत जोर जबर्दस्ती काम में लाई जाती है। सार्वजनिक अधिकार जोर जबर्दस्ती के आधार पर सहकारिता को अपनाने का ही एक रूप है, और यह स्वैच्छिक सहकारिता के बिलकुल विपरीत है। इस पद्धति के अन्तर्गत एक व्यक्ति को स्वातन्त्र्य, समानता और भ्रातृत्व का राजनैतिक अधिकार नहीं मिल पाता। सहकारी पद्धति के अन्तर्गत वास्तव में आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था रहती है। पूंजीवाद और कम्यूनिज़्म दोनों में व्यक्ति का ख्याल न रख कर भौतिकवाद को ऊंचा स्थान मिलता है। दोनों में स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और भ्रातृत्व के सामाजिक सिद्धान्तों की उपेक्षा बरती जाती है। दोनों प्रकार की पद्धतियों में उपभोक्ताओं व उत्पादकों का कोई नियंत्रण नहीं रहता। पूंजीवाद के अन्तर्गत सत्ता थोड़े से शेयर-होल्डरों के हाथ में आ जाती है। कम्यूनिज़्म में सत्ता चन्द पार्टी के सदस्यों के हाथों में रहती है। दोनों पद्धतियां लोकतंत्रात्मक नहीं है और वे अपनी आर्थिक समस्यायें स्वयं हल करने की शिक्षा लोगों को देने में विफल रही हैं। सहकारिता एक ऐसी पद्धति है, जिसमें स्वतन्त्रता को प्रमुख महत्व दिया जाता है।

पूंजीवाद और कम्युनिज्म के जरिए सम्पत्ति और शक्ति मुट्ठीभर लोगों के हाथ में केन्द्रीभूत हुई है जिससे असन्तुलन पैदा हुआ है तथा भौतिक समृद्धि का वितरण भी समानरूप से नहीं हुआ है। सहकारिता आनेवाले युग के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। इस पद्धति के अन्तर्गत एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।

ब्रिटेन में सहकारिता

पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था में व्यापार बहिष्कार, मजदूरों के झगड़े और तालाबन्दी की घटनाएं आम तौर से देश को मिलेगी। सहकारिता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस पद्धति के अन्तर्गत इन चीजों की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सहकारी समिति का शेयर होल्डर खुद ही स्वामी है, खुद ही मजदूर और मैनेजर हैं। मिसाल के तौर पर ब्रिटेन में ३० दूकानों में से १ दूकान सहकारिता के आधार पर चलाई जाती है। इस देश का $\frac{1}{8}$ खुदरा व्यापार सहकारी समितियों द्वारा होता है। लगभग $\frac{1}{3}$ परिवार सहकारी डेरियों से दूध की सप्लाई लेते हैं। ५ परिवारों में लगभग १ परिवार को डबल रोटी की सप्लाई भी सहकारी समिति करती है। इन सहकारी स्टोरों की सदस्य संख्या १ करोड़ १० लाख है और ये स्टोर कुल घरों के भाग को कोयला और चाय सप्लाई करते हैं। इतना ही नहीं, अंत्येष्टि क्रिया भी लगभग $\frac{1}{5}$ मृत्यु-प्राप्त लोगों की सहकारी समितियों द्वारा की जाती है। सबसे ज्यादा महत्व की बात यह है कि सहकारी समितियां ब्रिटेन की एकाधिकारवादी संस्थाओं के मुकाबले में मूल्य-रेखा कायम रखने में सफल रही हैं। इन सहकारी समितियों ने रेडियोसेट और टेलिविजन सेट बनाने वाली एकाधिकारवादी संस्थाओं का भी मुकाबला किया है और कीमतों को कम लाने में सफल रही हैं। ब्रिटेन की उपभोक्ता थोक व्यापार-समिति के लगे विशाल साबुन के प्लांट उद्योगों के क्षेत्र में उपभोक्ता सहकारी कार्यक्रम के जरिए प्राप्त सफलता के प्रतीक है। स्काटलैंड और ब्रिटेन के थोक सहकारी स्टोर पश्चिमी अफ्रीका में वनस्पति तेल के डिपो चला रहे हैं।

आ. र.

साहस पूर्ण कर-प्रस्ताव उचित ही है

मेरे विचार में अतिरिक्त करों में जनता के प्रत्यक्ष योगदान पर जो बल दिया गया है, वह साहस और बुद्धिमत्ता का परिचायक है। तात्कालिक प्रभाव की दृष्टि से यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि योगदान करों के रूप में है या अनिवार्य बचत के रूप में। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमारी कर-व्यवस्था में एक पुरानी दरार पूरने का साहसपूर्ण प्रयत्न किया गया है, और वह इस तरह कि पहले छोटी आय और मध्यम आय वाले बहुत-से लोग कोई कर नहीं देते थे। फलतः निम्न और मध्यम आय

सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वर्गों से कर के रूप में कुछ लेने के लिए हमेशा हम अप्रत्यक्ष करों का ही सहारा लेते थे । अप्रत्यक्ष करों से मुद्रास्फीति को प्रश्रय मिलता है । वित्त मन्त्री ने जो कुछ किया है, उससे अब स्रोत पर ही क्रय-शक्ति कम हो जाएगी और इससे मुद्रास्फीति खत्म करने में मदद मिलेगी । प्रत्यक्ष करों का सहारा लेने से, विशेषकर गैर-सरकारी क्षेत्र के वेतनों तथा ऊपरी आय की अधिकतम निर्धारित करने से तथा अधि लाभकर लगाने से सम्पन्न और धनी-मानी लोगों को अधिक कर देना पड़ेगा, जोकि समानता की दृष्टि से वांछनीय है । कर के बाद की आय पर जो अधिभार लगेगा, वह भी सम्पन्न और धनी-मानी लोगों पर अतिरिक्त कर ही होगा । पर सम्भवतः यह अधि भार और अधिक हो सकता था । अब तक तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह अधिभार धनिकों में भी अधिक धनी लोगों के अनुकूल है ।

भारतीय अर्थ-व्यवस्था का रूप ही ऐसा है कि यदि कोई बहुत बड़े कर लगाना चाहे, तो उसके लिए जनता का योग लेने के सिवा और कोई चारा नहीं दिखाई देता। इसमें कोई शक नहीं कि यह बजट नागरिक क्षेत्रों में निम्न मध्यम वर्गों तथा निम्न आय वर्गों पर कर का बहुत अधिक बोझ डालेगा । मालगुजारी के अनुपात में कृषकों से बचत के रूप में धन प्राप्त करने की बात तो ठीक है, पर मेरी समझ में नहीं आता कि यहां पर भी क्रमिक वृद्धि का सिद्धांत क्यों नहीं अपनाया गया । आयोजन के पिछले बारह वर्षों में और इस वर्ष के रक्षा बजट में भारत के जिस वर्ग पर अतिरिक्त करों का सबसे कम बोझ पड़ा है, वह है कृषकों का मध्यम तथा उच्च मध्यम वर्ग । अधिकांश कृषक मालगुजारी देते हैं । पर इनमें से वे वर्ग, जिनकी वार्षिक आय ३,०० या इससे अधिक है, उतना कर नहीं देते जितना कि नगरों में उनके भाई-बन्द देते हैं । अनिवार्य बचत तथा अधिभार लगाने से आज यह अन्तर और भी अधिक बढ़ गया है, क्योंकि यह अधिकर आयकर देने वाले वर्गों में से निम्न आय-वर्गों पर लागू होता है ।

इसलिए मेरा यह दृढ़ मत है कि यह कर-ढांचा ग्रामीण क्षेत्रों के मध्यम और उच्च मध्यम वर्गों के मनोनुकूल है । मेरे विचार में ये वर्ग राजनीतिक दृष्टि से बड़े शक्तिशाली हैं, पर यह कोई तुक नहीं कि वे उचित रक्षा-भार वहन न करें । —वी० के० आर० वी० राव०

"राष्ट्र-भारती"

सम्पादक—मोहनलाल भट्ट, हृषीकेश शर्मा

इसमें आपको लब्धप्रतिष्ठ-विद्वान् साहित्यकारों के ज्ञान-पोषक और मनोरंजक अच्छे-अच्छे लेख, कविताएं कहानियां एकांकी, रेखाचित्र, शब्दचित्र आदि रचनायें पढ़ने को मिलेंगी।

इसमें संस्कृत, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि विभिन्न भारतीय भाषाओं की तथा अंग्रेजी, रशियन आदि विदेशी भाषाओं की उत्कृष्ट रचनाओं के सुन्दर हिन्दी अनुवाद भी रहते हैं ।

आज ही मनीआर्डर द्वारा ६) भेजकर ग्राहक बन जाइये

रियायत—स्कूल-कालेजों सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा वाचनालयों को केवल ५) वार्षिक चन्दे में मिलेगी ।

पत्रव्यवहार का पता—

व्यवस्थापक—"राष्ट्रभारती"

हिन्दी नगर, वर्धा

(राष्ट्रभाषा प्रचार समिति)

सबसे सस्ता सचित्र हिन्दी मासिक

जागृति

जिसे भारत के सभी प्रमुख कवियों,

और कहानीकारों का सहयोग प्राप्त है ।

उत्प्रेरक कविताएं, ज्ञानवर्धक लेख, सांस्कृतिक निबंध, रोचक कहानियां, बाल संसार, साहित्य आगे बढ़ता है आदि स्तम्भ

तिरंगा आवरण, अनेकों इकरंगे चित्र

४८ से ५६ पृष्ठ को सम्पूर्ण छपाई आर्ट पेपर पर

इस पर भी मूल्य केवल २५ नये पैसे

एजेंटों को ५ से १० प्रतियों पर २५ प्रतिशत और इससे ज्यादा पर ३३⅓ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है । डाक खर्च प्रकाशकों के जिम्मे । एजेन्ट नमूने की प्रति के लिए आज ही लिखें ।

—सूचना व प्रकाशन विभाग चण्डीगढ़ (पंजाब)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सुरक्षा व्यय की पूर्ति के साधन

चीन के आक्रमण के कारण युद्ध-स्थिति के देर तक चलने की पूरी संभावनाएं हैं। निश्चय ही, इससे भारत का सुरक्षा व्यय दुगुना—लगभग ७०० करोड़ रु० न्यूनतम—प्रति वर्ष होगा, इसके साथ ही, मूल्य-वृद्धि और मुद्रा-स्फीति अनिवार्य है। इसलिए अब तीन समस्याएं हैं, बढ़े हुए सुरक्षा-व्यय की पूर्ति, मूल्य-वृद्धि और तीसरी मुद्रा-स्फीति को रोकना। इसके उपाय लेख में पढ़िए।

यद्यपि पूर्वोत्तर सीमा और लद्दाख दोनों मोर्चों पर युद्ध-विराम है पर यह स्थिति कब तक रहेगी—यह कहना अनिश्चित है। चीन द्वारा एक तरफा युद्ध-विराम के कई कारण हो सकते हैं, पर भारत सरकार युद्ध प्रयत्नों में शिथिल नहीं हो रही है—यह सन्तोष का विषय है। साथ ही पंचवर्षीय योजना के मूल तत्त्व—कृषि और औद्योगिक लक्ष्यों को लघु न करने का भारत सरकार का निश्चय भी प्रशंसनीय है क्योंकि युद्ध शक्ति को उत्तेजित करने और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए यह अनिवार्य है। युद्ध पर होने वाले भारी व्यय के लिए धन की आवश्यकता तो निःसंदेह है। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में प्राप्त (मार्च ६३ तक) लगभग ४५ करोड़ रु० कठिनता से, युद्ध के कुछ दिनों के लिए ही चल सकते हैं। इसी प्रकार स्वर्ण-बांड में कुछ हजार तोले ही प्राप्त हुए हैं, जब कि संचित सोने का अनुमान २० करोड़ तोले है। इसका स्पष्ट अभिप्राय है कि युद्ध-व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर व ऋण लेने के सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं है। वित्त मंत्री ने घाटे की बजट पूर्ति का मार्ग अवलम्बन करने से इंकार कर दिया है।

युद्ध-व्यय के सम्बन्ध में यह बात विशेषतः स्मरणीय है कि इसके द्वारा, व्यय के मुकाबले में, किसी उत्पादक पूंजी का प्रादुर्भाव नहीं होता है। इसका कारण यह है कि युद्ध में भेजा गया अधिकांश सामान और सेवाएं नाश के लिए ही प्रयुक्त होती है। युद्ध काल में अर्थनीति ऐसी होनी चाहिए जिससे युद्ध-काल से प्रादुर्भूत आय का सम्यक् सन्तुलन हो सके।

इस राष्ट्रीय संकट की वित्तीय पृष्ठ भूमि क्या है? तृतीय योजना के प्रथम वर्ष (१९६१-६२) में राष्ट्रीय आय २.२ प्रतिशत बढ़ी, जबकि लक्ष्य ६ प्रतिशत था और आबादी में २.४ प्रतिशत वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन पहले जितना ही रहा और बिजली, परिवहन इत्यादि अवरोधों के कारण औद्योगिक उत्पादन मन्द रहा। विदेश से सहायता आने में देरी होने से विदेशी मुद्रा स्थिर कोष न्यूनतम ९४ करोड़ रु० तक पहुंच गया है। कीमतों पर फिर कुछ दबाव पड़ने लगा है। संकट कालीन स्थिति की घोषणा करने से पहले देश की यही पृष्ठ भूमि थी। उधर संकट कालीन युद्ध-व्यय, न्यूनतम अनुमान के अनुसार, ७०० करोड़ रु० तक प्रति वर्ष होगा, अर्थात् सामान्य स्थिति के युद्ध व्यय से दुगना।

इस समय की स्थिति के अनुसार, सामन्य सुरक्षा व्ययों सहित, सार्वजनिक क्षेत्र का संयुक्त व्यय ३,५०० करोड़ रु० के आसपास है, अर्थात् कुल राष्ट्रीय आय का एक चौथाई और अतिरिक्त सुरक्षा व्यय जो संकट कालीन स्थिति के कारण करना होगा—३००-४०० करोड़ रु०। तृतीय योजना के लिए अगले वर्ष न्यूनतम, १००० करोड़ रु० के अतिरिक्त राष्ट्र को ४,००० करोड़ रु० खर्च करना होगा, अर्थात् १,४०० करोड़ रु० की एक वर्ष में वृद्धि, जिसमें आगामी वर्षों में संभवतः निरन्तर वृद्धि होगी ताकि योजना के मूल तत्त्वों को पूरा किया जा सके। इस समूची स्थिति का परिणाम भयंकर मुद्रा-स्फीति होगा, उसी प्रकार जैसे हिटलर के सत्ता आरूढ़ होने से पहले जर्मनी में हुआ था।

संकट कालीन व्ययों को दृष्टि में रखते हुए अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रभावों को दृष्टि में रखना होगा। अल्पकालीन दृष्टि से, १९६३-६४ के मार्च में पेश होने वाले बजट तक २०० करोड़ रु० सुरक्षा पर खर्च होंगे।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जनता के सहयोग और सरकारी नीति के फलस्वरूप मूल्य वृद्धि पर अंकुश रहेगा। वित्त मन्त्री चीजों पर नियंत्रण लगाने के विरुद्ध हैं पर, समूची स्थिति को दृष्टि में रखते हुए यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि आगामी कुछ मासों में मूल्य वृद्धि (१९५२-५३ का आधार १०० के अनुपात इस समय १२९.१) हो जाए क्योंकि पिछले वर्ष ५ या ६ अंश तक वृद्धि हो चुकी है। अपनी इच्छा से किये गये नियंत्रणों और मात्र देश भक्ति की भावना से मूल्य-वृद्धि देर तक रोकी नहीं जा सकती क्योंकि जनता को उत्साह के लिए स्फूर्ति देना सहज है पर उसे देर तक कायम रखना कठिन है। इसके प्रमाण हाल ही में दिल्ली में मिट्टी के तेल के दाम चढ़ने और सीमेंट के चोर बाजारी में बिकने से मिल चुके हैं। मुद्रा-स्फीति का मुकाबला करने के लिए उपभोक्ता सामान और सेवाओं में बढ़ती होना आवश्यक है क्योंकि संचित धन को बाहर निकालना ही होगा।

युद्ध काल में इस दिशा में, प्रायः जो पग उठाया जाता है, वह है "अतिरिक्त-लाभकर।" यह कर इसलिए न्याय संगत होता है क्योंकि युद्ध काल में प्राप्त लाभ मुद्रा स्फीति के कारण ही होता है, किसी व्यापारिक लाभ द्वारा नहीं। कई व्यापारिक संस्थाओं ने स्वेच्छा से अपने ठोस लाभ का ५ प्रतिशत राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में देना स्वीकार किया है पर आज के संकट काल में धन की इससे बहुत अधिक जरूरत है। इसका एक तरीका यह भी है कि पिछले तीन वर्षों में व्यापार व उद्योग में सामान्य लाभ से अधिक जो लाभ हुआ है, वह बाध्य रूप से दीर्घकालीन सरकारी बांडों में जमा कराया जाए। इसी प्रकार, १ लाख वार्षिक से अधिक व्यक्तिगत आय को भी, बाध्य रूप से, सरकारी बांडों में दिया जाए। इससे, शहरी क्षेत्र में बढ़ी हुई आय की एक अस्थायी सीमा निश्चित हो जाएगी।

संकट स्थिति की घोषणा के बाद स्वर्ण, शेयर और जिन्सों के मूल्य में निजी क्षेत्र में, करीब १ हजार करोड़ रु० का अवमूल्यन आ गया है। अगर वित्त मंत्री, अपने वायदे के अनुसार, स्वर्ण का मूल्य ७० रु० तोले तक ले आयें—जिसकी आशा बहुत कम है—तब वे गैर-शहरी क्षेत्र में छिपे हुए भारी धन में पर्याप्त अवमूल्यन ला सकेंगे। वर्तमान स्थिति के अनुसार, सोना ८२ रु० प्रति १० ग्राम तक गिरने के पश्चात् फिर ११६ प्रति १० ग्राम तक चढ़ गया था। इसलिए, सोने के रूप में निकम्मे पड़े हुए धन पर काबू पाने के लिए कड़े साधनों को अपनाने के बिना कोई चारा नजर नहीं आता। स्वर्ण-बांडों को आकर्षक बनाने का एक उपाय यह हो सकता है कि सरकारी तौर पर प्रत्येक परिवार के वास्ते व्यक्तिगत उपयोग के लिए स्वर्ण की निम्नतम राशि निश्चित कर दी जाए, जैसे २५ तोले, और इससे अधिक रखने को कानूनन अपराध बना दिया जाए। खाद्य-वस्तु बेचने के लाइसेंसदारों की तरह सोने के लायसेंसदार व्यापारी सरकार निश्चित कर दे और इस क्षेत्र से बाहर सोने का भुगतान करने वालों को कड़ी सजा दी जाए। अमेरिका जैसे उन्नत देशों में निजी तौर पर सोने का रखना जुर्म है। तब कोई कारण नहीं कि आज की स्थिति में भारत में भी ऐसा कानून क्यों न बनाया जाए? अगर शीघ्र ही कड़े कदम न उठाये गये तो इनामी बांडों की तरह स्वर्ण-बांड भी निरर्थक हो जाएंगे।

भूमि रखने की सीमा भी निर्धारित करनी होगी ताकि भूमिका सट्टा बन्द हो और देहाती बचत का रुख बदले। कृषि जन्य आय-कर, लगान में वृद्धि और कपास, मूंगफली, तम्बाखू इत्यादि सदृश नकद फसलों पर विशेष अधिक लगान—इत्यादि उपाय भी लाभदायक हैं। इसके साथ ही, केन्द्रीय और राज्यीय स्तर पर अनावश्यक खर्च कम करने में कड़ायी बर्तनी होगी। राज्यों में नागरिक प्रशासन पर खर्च १९६०-६१ में १६७ करोड़ रु० से १९६२-६३ में १९४ करोड़ रु० हो गया है और कुल अ—विकास सम्बन्धी खर्च ४१८ करोड़ रु० से ५२५ करोड़ रु० तक पहुँच चुका है। यदि २५ प्रतिशत कमी इस खर्च में की जाए तो राज्य स्तर पर २५ करोड़ रु० बच जाएगा। इसी प्रकार केन्द्रीय व्यय में भी कटौती होनी चाहिए।

आय वृद्धि का एक अन्य उपाय राज्यों के लिए शराब-बन्दीको समाप्त कर देना है। इससे पुलिस विभाग पर किया जा रहा अतिरिक्त व्यय भी बच जाएगा। इसी प्रकार नमक पर भी पुनः कर लगाया जा सकता है।

इन सब उपायों से, निश्चय ही, सुरक्षा के लिए अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकेगी और योजना-व्यय में भी विशेष कटौती की दरकार नहीं होगी। • •

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सार्वजनिक ऋण

(पृष्ठ १७६ का शेष)

(कुल आन्तरिक ऋणों के प्रतिशत के रूप में)

	१९३९	१९४६	१९५२	१९५४	१९५८	१९६२
अनिश्चित-कालीन-	१८	१५	१०	१०	१८	१०
१० वर्ष से ऊपर-	१६	३४	१९	११	१३	३०
५ से १० वर्ष-	१८	१२	१८	२२	३३	२६
५ वर्ष के भीतर-	१०	१७	९	१२	३६	३४
ट्रेज़री बिल्स-	७	४	१३	१३		
छोटी बचतें	२०	११	१६	१८		
अन्य दायित्व-	१२	७	१४	१४		

तालिका से स्पष्ट है कि द्वितीय युद्धकाल तक दीर्घ-कालीन ऋण अधिक महत्वपूर्ण रहे। तदनन्तर मध्यकालीन और अल्पकालीन ऋणों का बाहुल्य रहा है। रिजर्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार सार्वजनिक ऋण का अधिकांश व्यापारिक बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं लेती रही हैं।

डा. के. सी. चेको के अनुसार "वित्तीय प्रशासन तथा राजस्व नीति की दृष्टि से दीर्घकालीन ऋणों में कमी और अल्पकालीन ऋणों में वृद्धि अनुचित है। जितना अधिक अल्पकालीन ऋण होगा, सरकार को उतनी ही अधिक बार उसका नवीनीकरण करना पड़ेगा। दूसरी ओर, बैंकों और अन्य अल्पकालीन प्रतिभूतियों में विनियोग कर्त्ताओं के दृष्टिकोण से, ऋण की समयावधि जितनी अधिक अल्प होगी ऋणों में विनियोग उतना ही अधिक तरल होगा। इस प्रकार, ऋणों का यह परिवर्तनशील-कलेवर चाहे बैंकों के आस्तियों की तरलता में अभिवृद्धि करे, किन्तु शायद ट्रेजरी और रिजर्व बैंक इसे अधिक पसन्द न करे। यह स्थिति रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति के काल में नियंत्रित साख नीति को अपनाये जाने में कठिनाई पैदा कर देगी क्योंकि जब भी बैंकों को अधिक धन की आवश्यकता होगी, वे अपनी अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बड़ी सरलता से मुद्रा में बिना किसी महत्वपूर्ण हानि के परिवर्तित कर सकते हैं।"

किन्तु डा. जी. पी. गुप्ता के मतानुसार भारतीय सार्वजनिक ऋणों के परिपक्वतानुसार उक्त विभाजन को 'अनुत्तर-दायित्वपूर्ण' नहीं कहा जा सकता।

विदेशी ऋण

पिछली दो योजनाओं के काल में बाह्य ऋणों महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। कुल बाह्य ऋण सन् १९५ ५० करोड़ रु. था जो बढ़कर १९५९ के मार्च के अन्त रु. १३९ करोड़ हो गया तथा १९५९ से १९६२ तक यह वृद्धि अधिक तीव्रता से हुई है। सन् १९५९ में बाह्य ऋण रु. ३९१ करोड़ थे जो १९६०-६१ में रु. करोड़ हो गये और सन् १९६१-६२ तक तो रु. १० करोड़ तक बढ़ गये।

यह महत्वपूर्ण है कि अब हमारे बाह्य ऋणों में अधिक भाग डालर ऋणों का होता है। १९५० से पूर्व काल तक स्टर्लिंग ऋण अधिक महत्वपूर्ण थे। सन् १९ ६२ के अन्त में हमारे बाह्य दायित्व यों थे :—

डालर ऋण—रु. ६५१ करोड़, वेपस्ट जरमनी— १४१ करोड़, यू. के.—रु. १५० करोड़, रूस—रु. करोड़, अन्य रु. ७५ करोड़।

इस परिमाण में विदेशी ऋण प्राप्त किया जाना कि भी दृष्टि से बहुत अधिक तो नहीं है। किन्तु भय इस का है कि हम ऋणों की इस हद तक प्राप्ति के सम्मुख निर्यातों के अर्जन पर ध्यान देना न भुला बैठें। पि दशक में हमारे निर्यातों के सम्मुख तीन प्रमुख समस्या हैं—(१) हमारे मुख्य परम्परागत निर्यातों की मांग नि प्राय है, (२) विदेशों, विशेषतः पश्चिमी यूरोप के दे ने, भारतीय निर्यातों पर नियन्त्रण लगा दिये हैं तथा (३ सरकार और व्यापारिक क्षेत्र दोनों ही एक प्रभावश निर्यात बाजार को बढ़ाने और पूरा करने में असफल रहे हैं

आवश्यकता इस बात की है कि बाह्य ऋणों पर इ निर्भरता कम करने तथा वैसे ही उनके शोधन की व्यव करने के लिये निर्यातों को अधिकाधिक बढ़ाया जाय। सम्भव हो तो सरकार अनुदान देकर निर्यात-पदार्थों लागत कम करे जैसा जापान ने किया था। नवीनी तथा वैज्ञानीकरण द्वारा लागत घटाने के प्रयत्न किया अत्यन्त आवश्यक है। हमारे कारखानों में पूरी क्षमता काम नहीं हो पाता है इसके लिये कच्चे माल तथा व अतिरिक्त की समुचित व्यवस्था की जाना आवश्यक है, ताकि उत्पादन क्षमता व्यर्थ न पड़ी रहे।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

खादी आन्दोलन के नये स्वरूप

(पृष्ठ १८२ का शेष)

रियायतों के बदले हाथ से काते सूत पर मुफ्त बुनायी की रियायत दी जाए, इसके साथ एक जरूरी शर्त, खादी संस्था को यह ध्यान में रखना होगा कि उपभोक्ता को खरीदी हुई खादी पर अधिक दाम न देने पड़ें। इसका पूरा ब्यौरा तैयार करने के लिए २० व्यक्तियों की एक समिति बना दी गयी है। इस बारे में समिति के निश्चयों पर सरकार की मंजूरी की मोहर लगनी भी अनिवार्य है।

नयी योजना में कई विशेषताएं हैं। पहली तो यह कि इससे स्थानीय नेतृत्व और स्थानीय संगठन को बल मिलेगा और वह अधिक सक्रिय होगा। दूसरी, स्थानीय खपत बढ़ जाएगी और बाजार में जाकर बेचने का बोझ कम हो जाएगा। तीसरी, यातायात का खर्च बच जाने से खादी के उत्पादन व्यय में कमी आ जाएगी और अंतिम, खादी पर लगाया गया यह आक्षेप कि इसे व्यापार की वस्तु बना दिया है—समाप्त हो जाएगा।

पर इसका दूसरा पक्ष भी है। इसमें आने वाली दिक्कतों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। पहली, ग्राहक को खरीदने के लिए कोई आकर्षण नहीं रहेगा। दूसरा, मुफ्त बुनाई का सारा महत्व उस समय लुप्त हो जाएगा जब सूत को एक जगह से दूसरी जगह बुनायी के लिए ले जाना और कातने वालों के पास फिर वापस लाना पड़ेगा। बुनाई की सुविधाएं हरेक गांव में मुहय्या करनी पड़ेंगी जहां हाथ के काते सूत का उत्पादन होगा। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि लगभग १ लाख गांवों तक खादी को पहुँचा जाने के बावजूद बुनाई केन्द्र, करीब, इनके १० वें हिस्से में ही है। यह कोई ऐसी कठिनता नहीं है जो अजेय हो, क्योंकि खादी और ग्रामोद्योग आयोग बुनकर परिवारों को उन केन्द्रोंमें आबाद कर रहा है, जहां परम्परागत बुनकर नहीं हैं। योजनाबद्ध होने से इसमें अधिक प्रगति हो सकती है।

मुफ्त बुनाई का आर्थिक पक्ष क्या है—यह अभी बता सकना कठिन है, क्योंकि इसके ब्यौरेवार समूचे पहलू अभी सामने नहीं आये हैं। पर इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस दिशा में किया गया खर्च सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वांछनीय होगा क्योंकि ग्रामीण आबादी के उस हिस्से तक पहुंचेगा, जो विशेष अभावग्रस्त है।

विषाक्त वायुमंडल

विश्व की सबसे बड़ी वातावरण सम्बन्धी समस्याओं में एक वायु मंडल का दूषित होना है। "विश्व स्वास्थ्य संघ" की कोपनहैगम में हुई क्षेत्रीय परिगोष्ठी में यूरोप के बारे में इस समस्या पर विचार किया गया था।

दूषित वायु मंडल के सम्बन्ध में आंकड़ों का संग्रह करना बड़ा कठिन है, इसलिए परिगोष्ठि में निश्चय किया गया कि डाक्टरों, औषधि विक्रेताओं और इंजिनीयरों से लेकर सांख्यिकी वेत्ताओं तक—सबका सहयोग प्राप्त किया जाए। यूरुप में हजारों लोग वायु मंडल के अत्यन्त दूषित होने के कारण मरते हैं क्योंकि अत्यधिक विस्फोटक उत्पादनों के परिणाम स्वरूप जहरीले तत्वों के समाप्त होने का अवसर ही नहीं आता। नगरों के वायु मंडल को भयावह और विषाक्त करने के दो बड़े कारण हैं, सल्फर डायोक्साइड और कार्बन मोनोक्साइड। पहले का निर्माण कोयला और ईंधन के तेलों से होता है और गले तथा छाती के रोगों का मुख्य कारण यही है। दूसरे प्रकार का विष मोटर वाहनों से होता है और इस धूंए के साथ जिनका निरन्तर सपर्क होता है, जैसे मोटर गैरेजों के मजदूर, ड्राइवर, कन्डक्टर, यातायात के पुलिस सिपाही इत्यादि। इससे भी अधिक घातक अभाव पड़ता है। इससे भी अधिक घातक अभाव पैदा होता है। हाइड्रो-कार्बन का जो ईंधन के जलने और कम्बस्टन इंजिन से पैदा होता है। फेफड़ों के कैंसर का यह भी एक प्रबल कारण है।

औद्योगिक क्षेत्रों और नगरों के ऊपर जो कुहासा जैसा बिखरा रहता है, वह भी जन-स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्र न्यून करने के साधन जहां उपलब्ध नहीं हैं, वहां यह अधिक काला होता है। इसमें कई प्रकार की गैसों का सम्मिश्रण होता है, जो उस क्षेत्र की आबादी के लिए, निश्चय ही हानि कारक होता है। धूल-मिट्टी भी इसी प्रकार की रोग जनक है।

आज के वैज्ञानिकों को वायु मंडल की शुद्धि का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। भारत की यज्ञ-प्रथा द्वारा क्या इस समस्या का हल नहीं हो सकता?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आज के कुछ प्रमुख प्रश्न

श्री आर० एल० तुली, जनरल मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक लि०

● हमारी योजनाओं का अभी तक उद्देश्य कृषि को पुष्ट करना ही रहा है। यही हमारी वित्त-व्यवस्था का आधार है। इस्पात, रसायन, वस्त्र,—इन कुछ प्रमुख उद्योगों और सीमित हल्के इंजिनीयर उद्योग—इनकी प्रगति पर भी हमारा ध्यान केन्द्रित रहता है। विकास का मुख्य स्वरूप इधर-उधर खाली स्थानों को भरना ही रहा है। इस समय सुरक्षा-प्रयत्नों के कारण—हमारी योजनाओं में, निश्चय ही, महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। हमारे भावी उत्पादन का स्वरूप इसी के अनुकूल होना चाहिए। पर हम अपनी तीसरी योजना का परित्याग अथवा उसकी बहुत गहरी कांट-छांट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमारी समूची वित्त-व्यवस्था को ही ठेस पहुँचेगी।

सुरक्षा उद्योगों को प्राथमिकता

सरकार इस बात का पहले ही संकेत दे चुकी है कि लोहा—इस्पात, मशीनरी औजार, बिजली का सामान, उर्वरक, भारी इमारती काम और जहाज गोदी के उद्योगों की ओर विशेष ध्यान दिया जायगा और अगले वर्ष की योजना में इनके लिए विशेष राशि रक्खी जाएगी। भारी कम्प्रैसर और पम्प, रोलर बेयरिंग, समुद्री डीजल इंजिन प्लेट बेसल वर्क्स—इन्हें इस योजना की अवधि में पूरा किया जाएगा। कम आवश्यक परियोजनाएं जैसे, घड़ी और कैमरे के कारखाने और बन्दरगाहों का सुधार—इन्हें अभी प्रतीक्षा की सूची में रखा गया है। उद्योग पुरियों के निर्माण में कटौती की जाएगी। जमीन खोदने वाले और बिजली के समान के उद्योग बढ़ाने होंगे। इंजिन और नयी रेल-लाइनों का जाल—जिनका सम्बन्ध सुरक्षा के साथ है—बिछाना होगा। भिलाई इस्पात कारखाने ने अपनी उत्पादन क्षमता पूरी कर ली है और रूरकेला, दुर्गापुर, इस्पात कारखानोंसे कहा गया है कि वे ९० प्रतिशत उत्पादन क्षमता एक वर्ष में बढ़ा लें। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की तरह निजी क्षेत्र में भी सुरक्षा-उद्योगों का विस्तार करना होगा।

साधनों का संग्रह

विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के साथ-साथ सुरक्षा उद्योगों के लिए साधन जुटाने पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। इसके लिए कई कदम उठाने होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में जनता उत्साह से धन दे रही है। इस दिशा में पंजाब का योगदान विशेष प्रशंसनीय है। सुरक्षा के भारी खर्चों की दृष्टि से यह राशि भले ही अपर्याप्त हो। पर इससे प्रत्येक नागरिक के हृदय में आत्म गौरव की भावना जागृत होगी। स्वर्ण बांड, राष्ट्रीय सुरक्षा बांड और सुरक्षा डिपाजिट सार्टिफिकेट—इन्हें सफल बनाने के साथ-साथ जनता को अधिक त्याग के लिए तैयार करना होगा, जिससे न केवल राजस्व-वृद्धि हो, किन्तु मुद्रा स्फीति पर भी कड़ी रोक लगे। युद्ध-प्रयत्नों में—जब उत्पादन और सेवाओं के लिए भारी व्यय करने पड़ते हैं—और जिनकी वित्त-व्यवस्था में उत्पादन शीलता कुछ नहीं होती है—तो मुद्रा स्फीति की समस्या उभर आती है और साधनों के वितरण को प्रभावित करती है। इस मूल्य रेखा का नियन्त्रण इस समय एक मुख्य चिन्ता का विषय बन जाता है। इस दिशा में सर्वोत्तम उपाय उपभोग पर रुकावट लगाना है। सुरक्षाकोष में दान देने अथवा राष्ट्रीय बचत बांड ले लेने—इत्यादि से निजी उपभोग में कमी नहीं आती है। इसका तो मुख्य उपाय खपत पर ही रोक लगाना है। खपत में ४ या ५% की कमी से बचत की काफी राशि सुलभ हो सकती है। आडम्बर का स्थान त्याग को देना होगा।

उद्योग में अवरोध

महत्व के साधनों को वृथा नष्ट होने देने से और कुछ सीमा तक उन्हें उपभोग भी से बचाना होगा। पिछले कुछ वर्ष से औद्योगिक उत्पादन की गति मंद हो गयी है। इसमें बड़ी रुकावटें, बिजली, कोयला और परिवहन की हैं। बुनियादी उद्योगों को वर्तमान संकट की दृष्टि से

सम्पर्क

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कसना होगा।

उत्पादन वृद्धि में एक बड़ी रुकावट कच्चे माल की कमी है, स्वदेश से और आयात से कच्चा माल न मिलने से जब कारखाने भूखे रहेंगे, तब उत्पादन कैसे बढ़ेगा? अगर कुछ कच्चा सामान आयात भी करना पड़े तो मुद्रा-विनिमय के प्रश्न से रुकावट नहीं आनी चाहिए क्योंकि विदेशों में भारत के लिए गहरी सहानुभूति की भावना है। निर्यात वृद्धि पर भी विशेष ध्यान देना होगा और इसके लिए विदेशी बाजारों का अविलम्ब अध्ययन करना होगा।

कई उद्योग ऐसे हैं जिनकी उत्पादन क्षमता पिछले दशक में काफी बढ़ चुकी है—जैसे इंजिनीयरी और रसायन—पर इनका वास्तविक उत्पादन काफी कम है। अगर इन उद्योगों में तीन पारियां चलें और पूंजीगत सामान पूर्ण शक्ति से काम करें, तो औद्योगिक उत्पादन, निश्चय ही बढ़ जाएगा।

कुछ सुझाव

मैं कुछ मुद्दे यहां उपस्थित करता हूँ जिन पर अविलम्ब ध्यान देना चाहिए:—

(१) सामान का प्रबन्ध और अनुसंधान—सामान की निरन्तर कमी और महंगाई और साथ में वित्तीय साधनों की असफलता हमें यह सोचने को बाध्य करती है कि हम प्राप्त सामान का युक्ति संगत प्रयोग करें, विभिन्न आकृतियों और डिजाइनों में उसे वृथा नष्ट न करें और इस दिशा में निरन्तर अनुसंधान करते रहें।

(२) मानव-बल—कुशल मानव-बल की बड़ी कमी है। इसका बहुधा उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए तकनीकी प्रशिक्षण की संस्थाएं बड़ी संख्या में खोली जानी चाहिए।

(३) द्रुत निर्णय—प्रशासन व्यवस्था ऐसी हो, जिसमें युद्ध की तैयारी द्रुतगति से हो सके। इसके लिए निर्णय त्वरित गति से होने चाहिए।

(४) आपातकालीन संकट बीमा—भारत सरकार द्वारा आपातकालीन संकट बीमा की योजना बड़ी अच्छी है। इस से जनता का नैतिक स्तर ऊंचा होगा और निजी पूंजी को उत्साह मिलेगा।

मुद्रा नीति

आपतकालीन स्थिति में सरकार द्वारा युद्ध व्यय बढ़ जाने से मुद्रा स्फीति बढ़ जाती है। घाटे की अर्थ-व्यवस्था भी इसे बढ़ाने में सहायक होती है। इन दोनों का हल यही है कि सरकार बचत और सरकारी ऋण को प्रोत्साहन देकर इस फैली हुई मुद्रा को वापस ले ले। इस कदम को सक्रिय बनाने के लिए रिजर्व बैंक को चाहिए कि सरकारी सिक्यूरिटियों के लिए बाजार में मांग पैदा करे। निजी उत्पादकों को सुगम शर्तों पर ऋण मिल सके, इसकी भी व्यवस्था की जाए।

जनता से सम्पर्क

पिछले कुछ दशकों से व्यापार और उद्योग जनता के साथ सम्पर्क के महत्व को अधिक समझने लगे हैं। व्यवसायी को केवल अधिकतम लाभ पर ही दृष्टि न रखकर राष्ट्र और जनता की समस्याओं में भी दिलचस्पी लेनी होगी। व्यवसायी को, मुख्यतः, तीन प्रकार के लोगों से काम पड़ता है (१) ग्राहक (२) कर्मचारी और (३) हिस्सेदार। ये तीनों एक दूसरे से विच्छिन्न नहीं है, पर वे तीन बातें चाहते हैं—

(१) न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम सामान व सेवाएं।

(२) उच्चतम वेतन स्तर, और काम की अच्छी शर्तें।

(३) अच्छा डिविडैंड और पूंजी का मूल्य। व्यवसायी को इन तीनों में समन्वय करना होगा, समाज के भौतिक और मानवीय साधनों के प्रशासक के रूप में और अपने मानवीय लक्ष्यों की दृष्टि से। प्रायः यह समन्वय असन्तोषजनक होते हैं पर उसे अपूर्ण संसार में रहते हुए अपने चुनाव करने होते हैं और इनमें से कोई भी अन्तिम रूप से सन्तोषप्रद नहीं होता। उसका एक मात्र लक्ष्य यही होना चाहिए कि वह क्षुद्र स्वार्थ भावना से मुक्त रहे और जिस जनता से उसका सम्पर्क होता है, उसके प्रति सामाजिक कर्तव्यों का पालन करे।*

---

*दिल्ली चैम्बर आफ कामर्स के १२वें वार्षिक अधिवेशन में दिये गये भाषण से।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गुजरात आगे बढ़ रहा है

संकट काल की स्थिति का मुकाबला करने के लिए गुजरात राज्य में आर्थिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कृषि और औद्योगिक उत्पादनों को बढ़ाने के लिए योजना की प्राथमिकताओं को पुनः व्यवस्थित किया गया है। राज्य के खनिज पदार्थों को निकालने के लिए एक कारपोरेशन स्थापित किया जा रहा है। जब से यह राज्य पृथक् बना है, तब से भारत सरकार ने इस राज्य में नये उद्योगों को प्रारम्भ करने के लिए १६५ नये लायसेंस दिये हैं और १८४ लायसैंस वर्तमान उद्योगों के विस्तार के लिए स्वीकृत किये हैं। गुजरात औद्योगिक विकास संघ और गुजरात लघु-उद्योग संघ—इन दोनों का गठन किया गया है।

अहमदाबाद, बड़ौदा, भावनगर और राजकोट में ७० लाख रु० की लागत से उद्योगपुरियां स्थापित की गयी है।

कृषि क्षेत्र के लिए अल्प कालीन और मध्यमकालीन वित्त में १९६३-६४ में ३५ करोड़ रु० की बढ़ोतरी की जाएगी। दीर्घ कालीन ऋण १९६३-६४ के लिए ११.७३ करोड़ रु० से बढ़ाकर लगभग १६ करोड़ रु० किये जाएंगे। आवश्यक वस्तुएं निश्चित रूप और मूल्य में उपलब्ध हो सकें, इसके लिए सहकारी उपभोक्ता-भंडार खोले जा रहे हैं।

इस वर्ष में, अभी तक, सहकारियों ने अल्प और मध्यम-कालीन वित्त २५ करोड़ रु० तक का पेशगी दिया है, अगले वर्ष यह ३५ करोड़ रु० हो जाएगा।

उकई और नर्मदा बहुमुखी परियोजनाएं अभी प्रारंम्भिक स्थिति में हैं। शेमुंजी परियोजना लगभग पूर्ण होने वाली है। धन्तिवाद परियोजना पर काम अच्छे ढंग से हो रहा है।

आगामी वर्ष धुवरन विद्युत केन्द्र चालू होने से बिजली की स्थिति में सुधार हो जाएगा। मार्च के अन्त तक गुजरात बिजली बोर्ड १५,००० किलोवाट बिजली पैदा कर लेगा—ऐसी आशा है। धुवरन बिजली घर की क्षमता दुगुनी करने का विचार है।

राजस्थान नहर की पहली शाखा

साढे अढसठ मील लम्बी सूरतगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी (वितरक नहर) विशाल राजस्थान नहर परियोजना की प्रथम शाखा है तथा हनुमानगढ़—रावतसर सड़कों के चौराहे से एक मील नीचे की ओर स्थित है। यह नहर प्रति सैकण्ड १५४८ क्यूसेक पानी ले जायेगी तथा इससे गंगानगर जिले की सूरतगढ़, रायसिंहनगर तथा अनूपगढ़ तहसीलों में ३,८४,००० एकड क्षेत्र लाभान्वित होगा।

जिस क्षेत्र में होकर यह नहर गुजरती है वह पहले बहुत अल्प जन संख्या वाला क्षेत्र था जहां कुल ८-१० गांव थे और उनमें भी किसी अजनबी को आश्रय मिलना असम्भव सा ही था। इस क्षेत्र में भूगर्भीय जल की सतह

जी तोड़ मेहनत कीजिए
राष्ट्र की कुशलता बनाइए

१२० से १३० फुट तक गहरी है और वहां का पानी भी इतना खारा है कि उसे पीने अथवा सिंचाई के काम में लेना सम्भव नहीं है। किन्तु इस वितरक नहर के पूर्ण होने पर इस क्षेत्र की निश्चित रूप से काया-पलट हो जायेगी और यह समृद्ध एवं हरा-भरा बन जायेगा।

यह प्रारम्भ में ९२ फुट चौडी तथा ६.४ फुट गहरी कच्ची नहर के रूप में बनाई गई है जो धीरे धीरे ४९ फुट चौडी तथा ४.५ फुट गहरी रह जाती है। एक स्थान पर एक बिजलीघर के निर्माण की योजना है, जो इस पानी से २५०० किलोवाट विद्युत शक्ति उत्पन्न करेगा।

इस वितरण नहर से, जिसके निर्माण पर २६३ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है, प्रतिवर्ष २,४०,००० एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी तथा ४०,००० टन गेहूँ, १०,००० टन कपास, ८०,००० टन गन्ना तथा १२,००० टन तिलहन का उत्पादन होगा जिनका मूल्य आज के बाजार भावों से ४ करोड़ रुपये आंका गया है।

सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जयन्ती शिपिंग कम्पनी उन्नति की ओर

जयन्ती शिपिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड १६ अप्रैल को सार्वजनिक कम्पनी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। इस कम्पनी के शेयर होल्डर श्री माइकेल कुलकुन्दिस बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की सदस्यता से मुक्त हो रहे हैं और उनके सारे हिस्से शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। कंपनी की प्रदत्त पूंजी २-८५ करोड़ रु० है, जबकि हिसाब की पुस्तकों में लिखित के अनुसार कंपनी के चेयरमैन डा० तेजा का १४ लाख रु० का उधार है। अगर यह राशि भी पूंजी में शामिल कर ली जाए तो कम्पनी की पेड-अप पूंजी ३ करोड़ रु० के करीब हो जाएगी। इस पेड-अप पूंजी में कंपनी के चेयरमैन डा० तेजा का हिस्सा २.३० करोड़ रु० अर्थात् लगभग ८० प्रतिशत पूंजी का होगा।

१५ वां जहाज

दो वर्ष से कम अवधि के बीच जयन्ती कम्पनी ६ लाख टन के जहाज प्राप्त कर लेगी। इतनी बड़ी सफलता विश्व में अभी तक किसी ने प्राप्त नहीं की है। कंपनी के पास आज १४ जहाज हैं और १५ वां जहाज भी शीघ्र आने वाला है। इसका नाम गोतम जयन्ती है और यह इस समय जापान के नागासाकी जहाज गोदी में तैयार है। जयन्ती कम्पनी भारत में पहली ऐसी कम्पनी है, जिसे २० प्रतिशत से अधिक विदेशी सहयोग मिला है।

५४ हजार टन का टैंकर नागासाकी में बन रहा है। वह इस वर्ष ६ दिसम्बर को भारत को सौंप दिया जाएगा। इसी आकृति का दूसरा टैंकर अगले वर्ष दे दिया जाएगा। हरेक जहाज का खर्च ३.३० करोड़ रु० होगा। आगामी १२ वर्ष तक दोनों के लिए पर्याप्त कामकाज है।

विश्व में किसी जहाजी कंपनी ने इतने थोड़े समय में इतनी उन्नति नहीं की है, जितनी जयन्ती कम्पनी ने की है। १ नवम्बर से १५ दिसम्बर तक—६ सप्ताह की अवधि में—कंपनी ने १४ जहाज प्राप्त कर लिये हैं। कुछ ही दिनों में ३३,००० टन अतिरिक्त प्राप्त होने वाले हैं, जिससे कुल योग २,५०,००० टन का हो जाएगा।

३३,२५० टन का सामान वाहक गोतम जयन्ती १३ अप्रैल को अपनी पहली समुद्र यात्रा पर गोआ पहुँच रहा है। कच्चा लोहा इसमें लादा जाएगा।

भारत सरकार से ऋण

जयन्ती कम्पनी को अभी तक भारत सरकार से २३ लाख रु० मिल चुका है, यद्यपि सरकार का वायदा करीब २० करोड़ रु० का है। कंपनी इन ऋणों का प्रयोग सीधे जहाज गोदी में करेगी कोचीन में एक मरम्मत गोदी कायम की जाएगी और एक तैरने वाला घाट बम्बई बन्दरगाह में बनाया जाएगा। यह खेद की बात है कि यद्यपि बम्बई भारत का सबसे बड़ा बन्दरगाह है पर लदान उतारने में यह सबसे धीमा है। सामान्यतः आदि जयन्ती को खाली होने में बम्बई में ३५ दिन लगते हैं यद्यपि इसे ६ दिन से अधिक नहीं लगने चाहिए। इसका एक कारण यह है कि लदान उतराई की दर कम है और गोदाम के स्थान की न्यूनता है। मद्रास और विशाखापत्तनम में लदान-उतराई में कम समय लगता है।

• •

अनाज के शत्रु

जब तक भारत को विदेशों से अनाज मंगाना पड़ता है, तब तक जूट, गन्ना, मूंगफली, हल्दी, सरसों और तम्बाकू पैदा करना देश के लिए एक आपत्ति है। हम इन छः को अनाज का रिपु समझते हैं।

तम्बाकू बिलकुल निकम्मी चीज है। बाकी पांच चीजें कुछ काम की हैं, किन्तु उनकी भी मर्यादा है। वे मर्यादा से ज्यादा बढ़ीं और देश में अनाज के लिए जमीन कम रही तो हिन्दुस्तान के लिए बड़ी आपत्ति रहेगी।

—विनोबा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(पृष्ठ १७४ का शेष)

नागपुर—भूमि- टेस्टिंग ।

पूना—भूमि संरक्षण, कृषि-सूचना, टैकनिकल एज्यूकेशन इन्स्टीट्यूशन ।

मैसूर

बैंगलोर—सिंचाई विस्तार, "हाट लाइन्स" ।

भद्रा—नदी घाटी विकास ।

हेब्बोल—कृषि विश्व विद्यालय विकास ।

मैसूर नगर—बहु प्रयोजनीय सैंकडरी शिक्षा ।

शरावती—हाइड्रो-इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट ।

तुंगभद्रा—नदी घाटी विकास ।

उड़ीसा

भुवनेश्वर—कृषि विश्व विद्यालय विकास, बहु प्रयोजनीय सेकंडरी शिक्षा ।

हीराकुड—नदी घाटी विकास ।

तालचेर—थर्मल प्लांट ।

पंजाब

व्यास बांध—नदी-घाटी विकास, हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट ।

चंडीगढ़—भूमि संरक्षण, इंजिनीयरिंग, हाइब्रिड

लुधियाना—कृषि विश्व विद्यालय विकास ।

राजस्थान

अजमेर—बहु प्रयोजनीय सैंकडरी शिक्षा ।

चंबल—नदी घाटी विकास ।

जयपुर—नर्सिंग कालेज डेवलेपमैंट ।

कोटा—हैवी इक्विपमेट ट्रेनिंग सेंटर ।

पाली—कृषि विस्तार (एग्रोनामी) ।

उदयपुर—कृषि विश्व विद्यालय विकास ।

उत्तरप्रदेश

अलीगढ़—कृषि इंजिनीरयिंग, सिंचाई और ड्रेनेज, फार्म प्रबन्ध ।

कानपुर—कृषि विश्वविद्यालय विकास, टेकनिकल एज्यूकेशन इंस्टीस्यूट (टी. ई. आई.) थर्मल प्लांट ।

पन्तनगर—कृषि विश्वविद्यालय विकास ।

रिहांद—नदी घाटी विकास, हाइड्रो-प्रोजेक्ट ।

रुड़की—टैकनिकल एज्यूकेशन इंस्टीट्यूशन ।

सिंगरौली—कोयला खान विकास ।

तराई—हाइब्रिड मैज प्रोडक्शन ।

वाराणसी—कृषि विश्वविद्यालय विकास ।

पश्चिमी बंगाल

बंदेल—थर्मल प्लांट ।

कलकत्ता—दुग्ध प्लांट और पशु फार्म, प्रोडक्टिविटी कौंसिल ।

दुर्गापुर—थर्मल प्लांट, स्टील ट्रेनिंग ।

हावड़ा—टैकनिकल एज्यूकेशन इंस्टीट्यूशन ।

खड्गपुर—टैकनिकल एज्यूकेशन इंस्टीट्यूशन ।

१९६२ में ही भारत ने अन्य देशों की तुलना में अधिक अमरीकी विदेशी सहायता प्राप्त की ।

—

ग्राम राज (मास में तीन बार प्रकाशित

सम्पादक—श्री गोकुलभाई भट्ट

"ग्रामराज बहुत ही शानदार और बहुत ही पत्र निकल रहा है । सब तरह की जानकारी इसमें है । राजस्थान के हर शिक्षित भाई बहन के हाथ में पत्रिका होनी चाहिए ।" —वि

वार्षिक चन्दा ३) रु०

कार्यालय का पता :

ग्रामराज, किशोर निवा

जयपुर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस मास की आर्थिक घटनाएं

भारत का योरोपीय देशों से प्रतिकूल व्यापार

यूरूपीय सांझा बाजार कमीशन के अध्यक्ष ने भारत सरकार के वित्तमंत्री श्री मुरारजी देसाई और व्यापार व उद्योग मंत्री श्री के० सी० रेड्डी को विश्वास दिलाया है कि कमीशन भारत की निर्यात व व्यापारिक सन्तुलन की समस्या के प्रति सहानुभूति पूर्ण रुख अपनाएगा। इस समय प्रतिकूल व्यापार की राशि १३० करोड़ रुपये हैं। इस वर्षके पहले आधे भाग में निर्यात के कम हो जाने से स्थिति अधिक बिगड़ गयी है। उनका यह भी सुझाव है कि अन्तिम निर्णय होने तक भारत पश्चिमी यूरूपीय देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार में कमी कर दे।

'एड इंडिया क्लब' की सहायता

तीसरी योजना के तीसरे वर्ष १९६३-६४ के लिए 'एड इंडिया क्लब' से १,०० करोड़ डालर से अधिक मिलने की आशा है, जब कि पिछले वर्ष केवल ८७.०० करोड़ डालर मिले थे। इस वर्ष के लिए भारत की विदेशी मुद्रा की न्यूनतम आवश्यकता १३० करोड़ डालर है।

इस क्लब की बैठक वाशिंगटन में ३० अप्रैल और १ मई को हो रही है। अमेरिका इस क्लब के सदस्य ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, कनाडा और जापान को अपनी सहायता की मांग बढ़ाने के लिए कहेगा। भारत के प्रशासक व अर्थशास्त्री इस बैठक की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।

२५ लाख को रोजगार

योजना आयोग ने ४५० देहाती परियोजनाओंको चालू करने की योजना बनायी है, जिनके अन्तर्गत तीसरी योजना के अन्त तक २५ लाख बेरोजगारों का काम मिल सकेगा। इन परियोजनाओं में सहायक सड़कों के निर्माण पर विशेष जोर दिया जायगा।

भारतीय जहाज रानी में विदेशी सहयोग

भारत सरकार ने निश्चय किया है कि भारतीय जहाज कम्पनियों में विदेशी वित्त अंश की मात्रा २५ प्रतिशत से बढ़कर ४० प्रतिशत होगी। इससे भारत के जहाज उद्योग में अधिक तेजी आनेकी सम्भावना है। जहाजी कम्पनियों के अध्यक्ष और संचालक ७५% भारतीय होंगे, इसलिए विदेशियों के प्रभुत्वका कोई खतरा नहीं हो सकता।

आवश्यक वस्तु मूल्य नियंत्रण आदेश

१ मार्च, १९६३ से कुछ चीजों का उत्पादन शुल्क बढ़ जाने पर, भारत सरकार ने भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत आवश्यक वस्तु (दाम नियंत्रण) आदेश, १९६३ जारी किया है। इसमें बताया गया है कि थोक और खुदरा व्यापारी मिट्टी का तेल, वनस्पति पदार्थ, कपड़े धोने का साबुन और छपाई तथा लिखने का कागज आदि ज्यादा से ज्यादा कितने दामों पर बेच सकते हैं।

—भारत-अमेरिका के बीच हाल ही में हुए एक समझौते के अनुसार अमेरिका पी. एल. ४८० अंतर्गत भारत को १.२ करोड़ रु० का तम्बाखू बेचेगा। इस समझौते के अनुसार अमेरिका ऊंची किस्म का पत्ते का तम्बाखू २० २० करोड़ ६० पौण्ड भारत को देगा जो बढ़िया सिगरेट बनाने में प्रयुक्त होगा। भारत रुपयों में रकम अदा करेगा।

—सरकारी इंडियन आयल कम्पनी देश के प्रमुख नगरों में २३० पैट्रोल पम्प और ३२ डिपो चला रही है। इस कम्पनी ने सोवियत रूस से पैट्रोल की ऐसी चीजें काफी मात्रा में आयात की हैं, जिनकी देश में कमी है। नूनमाटी (आसाम) और बरौनी (बिहार) के सरकारी तेल शोध कारखानों का तेल भरने के लिए कम्पनी ने स्थल सेना का एक और नौ सेना के दो टैंक लिए हैं।

इंडियन आयल कम्पनी ने न्यूयार्क की मौबिल पैट्रोलियम कम्पनी के साथ एक समझौता किया है, जिसके अनुसार इंडियन आयल ब्लेंडिंग लि० नाम की कम्पनी खोली जाएगी। यह कम्पनी बम्बई और कलकत्ता में कारखानों व मोटरों आदि के तेल के कारखाने बनाएगी।

• •

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अब लिटर अनिवार्य

देश भर के व्यापार में अब तरल पदार्थ मापने के मेट्रिक पैमानों का प्रयोग अनिवार्य हो गया है • किलोग्राम और मीटर पिछले वर्ष से ही अनिवार्य हो गए हैं, इस प्रकार अब माप-तौल की मेट्रिक प्रणाली ही भारत में एक मात्र कानूनी प्रणाली है • मेट्रिक प्रणाली की सरलता का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए इसकी इकाइयों (लिटर, मीटर और किलो) को उनके आन्तरिक मूल्य के अनुसार ज्यों का त्यों इस्तेमाल कीजिए • मेट्रिक पैमानों की पुराने माप-तौल जैसे सेर वगैरह से तुलना न कीजिए।

सही और सुविधाजनक लेन-देन के लिए

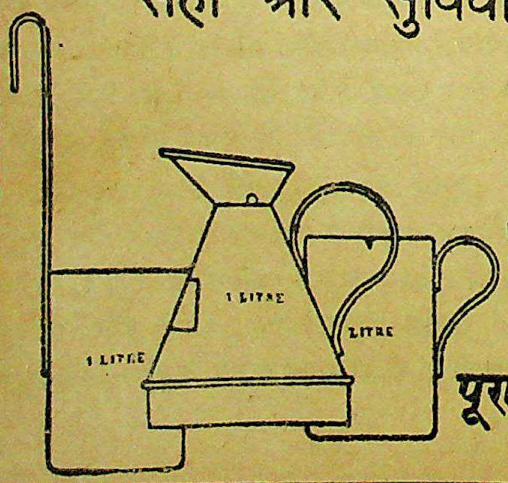

मेट्रिक इकाइयों का

पूर्ण अंकों में प्रयोग कीजिए

DA 62/80

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सारे परिवार के लिए

डी सी एम

के उच्च कोटि के कपड़े

पापलिन	छींटें	मलमल
लिनो	लान्स	लट्ठा
साड़ियाँ	शर्टिंग्ज	ड्रिल्स
शर्टिंग्ज	सजावट के कपड़े	तौलिए

एवं बेड शीट्स आदि

आकर्षक रंगों, शेडों और बनावटों में

डी सी एम के सभी रिटेल स्टोर्स में प्राप्य है ।

डी सी एम वस्त्रोत्पादन में श्रेष्ठता का प्रतीक

दि दिल्ली क्लॉथ एण्ड जनरल मिल्स कं० लि०

दिल्ली

JWT : DCM : 2290

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शीघ्र प्रकाशित होगा शीघ्र प्रकाशित होगा

सम्पदा का नया विशेषांक

दिल्ली-विकास अंक

यद्यपि दिल्ली क्षेत्रफल व जनसंख्या भी दृष्टि से विभिन्न राज्यों में बहुत छोटा है परन्तु भारत के केन्द्र में स्थित होने से तथा देश की राजधानी होने के कारण इसका अपना महत्व है। आज दिल्ली समस्त देश की प्रायः समस्त आर्थिक प्रवृत्तियों का भी केन्द्र होता जा रहा है। इसकी अपनी समस्याएं है और अपनी विशेषताएं हैं।

इन विशेषताओं व समस्याओं का विवेचन करने और दिल्ली की विविध आर्थिक गतिविधियों पर प्रकाश डालने के लिए सम्पदा का

दिल्ली-विकास अंक

प्रकाशित किया जा रहा है। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि यह विशेषांक भी विद्वत्तापूर्ण और ज्ञानवर्धक लेखों व नक्शों, चित्रों और ग्राफ आदि सभी अपनी विशेषताओं से युक्त, उपयोगी संग्रहनीय व पठनीय होगा।

१६ फार्म, मूल्य होगा १ रु० ५० न० पै०

यह अंक भारी संख्या में प्रकाशित हो रहा है, फिर भी हमें सन्देह है कि हम इसकी मांग पूरी कर सकेंगे। इसलिए अपनी प्रति १ रु० ५० न० पै० भेजकर सुरक्षित करालें।

विज्ञापनदाता विज्ञापन के लिए भी अपना स्थान सुरक्षित करा लें।

विशेष जानकारी के लिए पत्र व्यवहार करें:—

व्यवस्थापक—सम्पदा १८।११ शक्तिनगर दिल्ली।

मुद्रक—कृष्ण चन्द्र विद्यालंकार द्वारा नवचेतन प्रेस (प्रा०) लि० (ओलिव ऑफ अर्जुन प्रेस) दिल्ली-६ में मुद्रित
आर्य प्रकाशन मन्दिर, १८/११, शक्तिनगर दिल्ली-६ से प्रकाशित।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा

वर्ष १२ : अंक ०५

मूल्य
न. पै.

अशोक प्रकाशन मन्दिर शक्ति नगर, दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

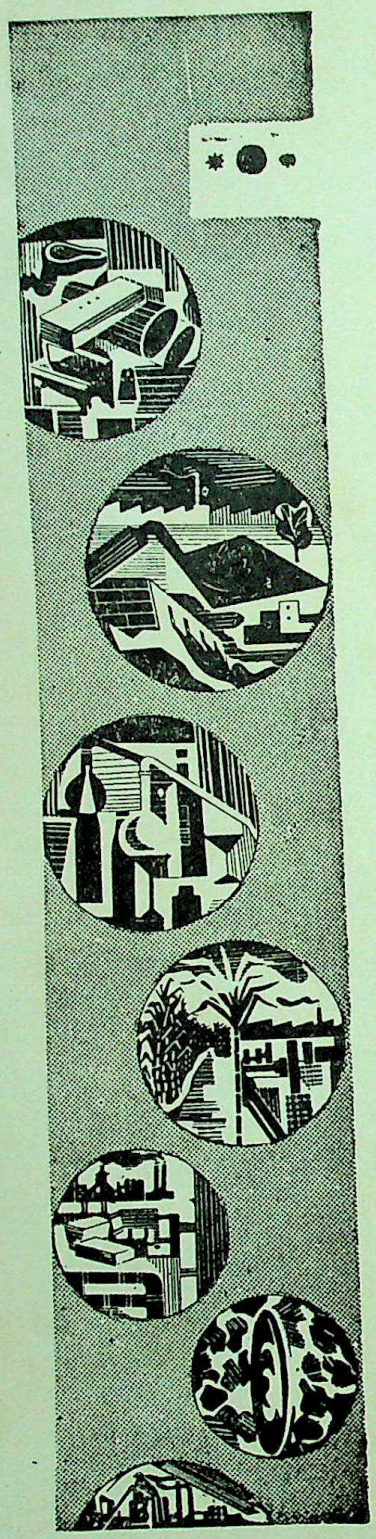

नये क्षितिज

स्वतंत्रता पूर्व युग में भी जनता के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए भारत की योजनाएं और कार्यक्रम थे। पर उनमें मौलिक निर्बलता थी—कि उनका सम्बन्ध जनता की अपेक्षा सरकार के साथ अधिक था।

स्वतंत्रता आई और इसके साथ नव-जागरण और जनता की योजनाएं—जनता के लिए और जनता के द्वारा। इसके परिणाम स्पष्ट थे, अधिक से अधिक बेहतर व सस्ती वस्तुएं अधिक से अधिक लोगों के लिए बेहतर जीवन।

डालमिया उद्योग समूह

निरन्तर ऐसे सामान का अधिक से अधिक उत्पादन करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो हमारे जीवन स्तर को ऊंचा करने में सहायक हो। हम यह कामना न केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से किन्तु लगभग एक चौथाई सदी से कर रहे हैं। यह काम कठिन होते हुए भी हम निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं, इस आशा के साथ कि कल का दिन अधिक उज्ज्वल, नव-प्रभात एवं नये क्षितिज से युक्त होगा।

DALMIA ENTERPRISES

डालमिया सिमेंट (भारत) लि., डालमियापुरम् (मद्रास)
डालमिया आयरन एंड स्टील लि., राजगंगपुर व कलकत्ता
डालमिया मेगनेसाइट कार्पोरेशन, सेलम (मद्रास राज्य)
उड़िशा सिमेंट लि. राजगंगपुर (उड़िशा राज्य)
रजा बुलन्द शूगर कं० लि०, रामपुर (उ० प्र०)
दि रामपुर डिस्टिलरी एंड केमिकल कं. लि., रामपुर (उ.प्र.)

राष्ट्र की सेवा में सन्निहित

डालमिया उद्योग-समूह

मुख्य कार्यालय—४, सिन्धिया हाउस, नयी दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गुरुकुल कांगड़ी

शीघ्र प्रकाशित होगा !! शीघ्र प्रकाशित होगा !!

सम्पदा का नया विशेषांक

दिल्ली-विकास अंक

यद्यपि दिल्ली क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से विभिन्न राज्यों में बहुत छोटा है, परन्तु भारत के केन्द्र में स्थित होने तथा देश की राजधानी होने के कारण इसका अपना महत्व है। आज दिल्ली समस्त देश की प्रायः समस्त आर्थिक प्रवृत्तियों का भी केन्द्र होता जा रहा है। इसकी अपनी समस्याएं है और अपनी विशेषताएं हैं।

इन विशेषताओं व समस्याओं का विवेचन करने और दिल्ली की विविध आर्थिक गतिविधियों पर प्रकाश डालने के लिए सम्पदा का—

दिल्ली-विकास अंक

प्रकाशित किया जा रहा है! यह बताने की आवश्यकता नहीं कि यह विशेषांक भी विद्वत्तापूर्ण और ज्ञानवर्द्धक लेखों व नक्शों, चित्रों और ग्राफ आदि सभी अपनी विशेषताओं से युक्त, उपयोगी संग्रहणीय व पठनीय होगा।

१६ फार्म, मूल्य होगा १ रु. ५० न. पै.

यह अंक भारी संख्या में प्रकाशित हो रहा है, फिर भी हमें सन्देह है कि हम इसकी मांग पूरी कर सकेंगे। इसलिए अपनी प्रति १ रु. ५० न. पै. भेजकर सुरक्षित करा लें।

विज्ञापनदाता विज्ञापन के लिए भी अपना स्थान सुरक्षित करा लें।

विशेष जानकारी के लिए पत्र-व्यवहार करें

व्यवस्थापक—**सम्पदा २८/११ शक्तिनगर दिल्ली**

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विषय-सूची

सं०	विषय	पृष्ठ
१.	तृतीय योजना की गतिविधि	२१३
२.	सम्पादकीय टिप्पणियां	२१५
३.	सरकारी इमारतों का निर्माण	२१८
४.	विगत दशाब्दि में बजट की प्रवृत्तियां (कृष्णचन्द्र विद्यालंकार)	२१९
५.	भारत की आर्थिक उन्नति में अवरोध (श्री हरवाडकर)	२२२
६.	महान् अर्थशास्त्री डा० राव (कृष्णचन्द्र विद्यालंकार)	२२४
७.	नवनिर्माण में बैंकों का सहयोग (श्री तुलसीदास किलाचन्द)	२२६
८.	भारत में अलोह धातु उद्योग	२२९
९.	कम्यूनिस्ट क्रान्ति का शिकार—चीनी किसान	२३०
१०.	जहाजरानी उद्योग में नया साहस	२३१
२१.	सर्वोदय पृष्ठ—	
	भूदान का द्वादशवर्षीय युग	२३२
	धूम्रपान : राष्ट्रीय आय व स्वास्थ्य (सरदारमल जैन)	२३३
२२.	उत्तरप्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र (श्री दीनानाथ दुबे)	२३५
२३.	महिलाएं व गृह-उद्योग	२३७
२४.	बिजली व उद्योग की प्रतिस्पर्धा : गैस	२३९
२५.	अर्थवृत्त-चयन	२४०
२६.	राज्यों की गतिविधि—	
	अहमदाबाद का वस्त्र उद्योग	
	राज्य अदायगी नहीं करते	
	मध्यप्रदेश में विकास	२४१
२७.	रासायनिक रंगों की शताब्दी	२४२
२८.	इस मास की प्रमुख आर्थिक घटनाएं	२४४

* * *

सम्पदा के वार्षिक मूल्य में वृद्धि

कागज, छपाई तथा अन्य व्यय बढ़ जाने के कारण हमें विवश होकर सम्पदा का वार्षिक मूल्य ८ रु० से बढ़ा कर ८.५० रु० करना पड़ रहा है। किन्तु जून ६३ तक ग्राहक बन जाने वालों को इस वर्ष के लिए ८) रु० में ही सम्पदा मिलेगी। इसलिए शीघ्रता करें।

वी० पी० व रजिस्ट्री का भी खर्च १ मई १९६३ से बढ़ गया है। इसलिए यदि ग्राहक मनी आर्डर से वार्षिक मूल्य भेजेंगे, तो न केवल उन्हें बचत होगी, हमें भी महुत सुविधा होगी।

—व्यवस्थापक सम्पदा २८/११ शक्तिनगर, दिल्ली-६

सम्पदा के स्थायी ग्राहकों से

१. 'सम्पदा' कार्यालय से पत्र-व्यहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें।

२. वार्षिक चन्दा समाप्त होवे पर अगये वर्ष का चन्दा स्वयं भेजने की कृपा करें। अगले वर्ष का ग्राहक न रहने की हालत में हमें एक मास पूर्व सूचना देने की कृपा करें।

मैनेजर—सम्पदा २८/११ शक्तिनगर, दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वर्ष : १२
अंक : ५
मई : १९६३

सम्पदा

तृतीय योजना की गतिविधि

किसी भी योजना की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि समय-समय पर हम उसकी प्रगति, सफलता व असफलता पर दृष्टिपात कर लिया करें और यह देख लिया करें कि हमारे लक्ष्य आशा के अनुरूप पूर्ण हो रहे हैं या नहीं तथा यदि कमी है तो कहां और किन कारणों से। हाल ही में हुई अ. भा. कांग्रेस समिति के सामने जो विवरण प्रस्तुत किया गया, वह इसी दृष्टि से बहुत महत्व-पूर्ण है। इसमें कहा गया है कि कृषि-उत्पादन की प्रगति पहले दो वर्षों में धीमी रही है। दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष १९६०-६१ में मौसमी हालात असाधारणतया अच्छे रहे, जबकि तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में अर्थात् १९६१-६२ और १९६२-६३ में मौसमी हालात इतने अनुकूल नहीं थे। प्रमुख फसलों की पैदावार के आंकड़े पंचवर्षीय लक्ष्य की तुलना में निम्न प्रकार हैं :—

मद		उत्पादन			
		१९६०-६१	१९६१-६२	१९६२-६३	१९६५-६६
				अनुमानित	लक्ष्य
खाद्यान्न	लाख टन	७९७	७८६	८०८	१०००
तिलहन	,,	६५	६८	६८	९०
ईख (गुड़)	,,	१०४	९७	८८	१००
कपास	लाख गांठें	५४	४५	५४	७०
जूट	,,	४०	६३	५४	६२

स्पष्ट है कि पिछले दस वर्षों की कृषि उत्पादन-वृद्धि की दर में अभी कोई सुधार नहीं हुआ है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में जो प्रयत्न अथवा पूंजी-विनियोग किया गया है उसका प्रतिफल हमें अभी प्राप्त नहीं हुआ है और तीसरी योजना में जो प्रयत्न या पूंजी-विनियोग किया जा रहा है उसका प्रतिफल भी आगे चल कर मिलना है।

जहां तक औद्योगिक उत्पादन का प्रश्न है, कृषि क्षेत्र की अपेक्षा उद्योगों के क्षेत्रों में कुछ अधिक उन्नति हुई है किन्तु फिर भी इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आधार वर्ष १९५६ = १००) १९६१-६२ में ५.६ प्रतिशत बढ़ गया और १९६२-६३ में ८ प्रतिशत और बढ़ जाने का अनुमान है। लेकिन तीसरी योजना में पांच वर्ष के भीतर औसत औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने की जो कल्पना की गई है उससे यह उत्पादन-वृद्धि की दर एक चौथाई है। पंचवर्षीय लक्ष्य की तुलना में मुख्य उद्योगों की स्थिति आगे की तालिका के अनुसार है :

जहां तक बिजली-उत्पादन का प्रश्न है १९६०-६१ में कुल बिजली-उत्पादन क्षमता ५६ लाख किलोवाट थी, जो १९६१-६२ में बढ़कर ६१ लाख किलोवाट हो गयी। १९६२-६३ में बिजली-उत्पादन-क्षमता बढ़कर ६७.८ किलोवाट हो गयी, जबकि १९६५-६६ तक १३० लाख किलोवाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य है। रेल विकास कार्यक्रम के क्षेत्र में १९६०-६१ में मूल यातायात १५४० लाख टन था जो १९६१-६२ में बढ़कर १५८० लाख टन हो गया और १९६२-६३ में १७३० लाख टन हो गया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जबकि १९६५-६६ में मूल यातायात २१५० लाख टन तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इस गति से लक्ष्य पूरा नहीं होने वाला है।

औद्योगिक उत्पादन के निम्न लिखित अंकों से स्पष्ट है कि दो वर्षों में हमने लक्ष्य के अनुसार उन्नति नहीं की है। अब तीन वर्षों में हम अपने लक्ष्यों को कहां तक पूर्ण कर सकेंगे ?

इसी विवरण में आगे कहा गया है कि कृषि और औद्योगिक उत्पादन हमारी आर्थिक उन्नति की आधार-शिला ही नहीं, बल्कि सुरक्षा-सम्बन्धी हमारे प्रयासों की सफलता की भी कसौटी है। उत्पादन का अधिकांश भाग गैर-सरकारी प्रयासों पर निर्भर करता है। गैर-सरकारी सामाजिक कार्यकर्ताओं की लगातार यह कोशिश होनी चाहिए कि वे जनता के प्रयास को सही दिशा में लगाएं

मद	इकाई	उत्पादन १९६०-६१	१९६१-६२	१९६२-६३ अनुमानित	१९६५-६६ लक्ष्य
१. इस्पात पिण्ड	लाख टन	३३	४३	५१	९२
२. मशीनी औजार (संगठित क्षेत्र)	करोड़ रुपए	७.२	८.५	१२.०	३०.०
३. नाइट्रोजन उर्वरक	१००० टन	९७.२	१४२.३	१८४.०	८००.०
४. पैट्रोलियम पदार्थ	लाख टन	५७	६०	७०	९८६
५. कोयला	,,	५४७.२	५४३.३	६२०.०	९७०
६. सूती कपड़ा (मिलों में बना)	लाख गज	५०८४०	५१०००	५१०००	५८०००
७. सूती कपड़ा (हाथकरघा)	,,	१९३००	२१०००	२२८००	२८०००

यद्यपि तीसरी योजना की अवधि में महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रगति हो रही है, फिर भी कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति में काफी कमी रह जाने का अन्देशा है। कई मामलों में (जिनमें बोकारों का स्टील का कारखाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है) रुपए की काफी व्यवस्था हो जाने के बावजूद विदेशी-विनिमय के अभाव में परियोजना निश्चित समय पर आरम्भ नहीं की जा सकी। कई ऐसे मामले भी हैं जिनमें भारत तथा विदेशों में कायदे कानून की कठिनाइयों और प्रशासन सम्बन्धी कमियों के कारण काम समय पर शुरू नहीं किया जा सका। देश के लिए विदेशी-विनिमय अर्जित करने के लिए निर्यात-व्यापार बढ़ाना जरूरी है। यहां तक कि इस काम के लिए घरेलू खपत को कम करने के उपाय भी काम लाए जा सकते हैं।

अभी हमारे सामने बहुत बड़ा काम है, न केवल हमें अपनी पिछली कमियों को दूर करना है, बल्कि आपत्कालीन स्थिति के कारण यह आवश्यक हो गया है कि कई क्षेत्रों में पहले से भी अधिक ऊंचा लक्ष्य स्थापित किए जाएं।

और कार्यक्षमता बढ़ाने तथा अपव्यय को रोकने के लिए सलाह और सहायता दें।

लघु-उद्योगों के क्षेत्र में वे सहकारी समितियों के संगठन में सहायता देने, व्यक्तिगत रूप में काम करने वाले कारीगरों को आर्डर दिलाने में सरकार से रुपए उधार दिलाने व आवश्यक चीजें प्राप्त करने में सहयोग देकर वे बहुत सी मुश्किलें कम कर सकते हैं, लेकिन कृषि-उत्पादन के क्षेत्र में वे सबसे ज्यादा जरूरी हैं। और जब उत्पादन कम और मांग अधिकाधिक बढ़ रही हो, तो विशेष प्रयास की आवश्यकता है।

कांग्रेस समिति के सामने प्रस्तुत नोट में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के अनेक सुझाव देते हुए अन्त में कहा गया है कि यह जरूरी है कि शहरों और गांवों में जन-उत्साह को सही रचनात्मक दिशा में लगाया जाए। उद्योग या कृषि, हर क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक के अनुशासन के साथ निरन्तर प्रयास करते रहने से प्रतिरक्षा-प्रयत्नों को सबसे ज्यादा बल मिलता है और अर्थ-व्यवस्था के द्रुतगति-विकास में भी सहायता मिलती है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संसद के सामने प्रस्तुत योजना आयोग की रिपोर्ट में भी इन दो वर्षों की शिथिल प्रगति को स्वीकार किया गया है। उपर्युक्त विवरण को दोहराते हुए इसमें बताया गया है कि १९६१-६२ में राष्ट्रीय आय में कुल २.१ प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में औसत ४ प्रतिशत और १९६०-६१ में ७.१ प्रतिशत वृद्धि हुई थी कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में योजना आयोग के लक्ष्य पूर्ण नहीं हुए।

योजना आयोग व अन्य अर्थशास्त्री इस शिथिलता को तो स्वीकार करते हैं, पर क्या यह आज आवश्यक नहीं है कि हम अपनी योजना सम्बन्धी समस्त दृष्टिकोण को ही बदलने पर गंभीर विचार करें।

पांचवीं योजना में :

योजना आयोग का लक्ष्य १९७०-७५ तक देश से गरीबी को समाप्त करना है। उस समय तक देश की जन-संख्या करीब ६० करोड़ तक पहुँच जाएगी। तब प्रत्येक व्यक्ति अपने रहन-सहन पर २० रु. प्रति मास खर्च कर सके, इसके लिए यह जरूरी है कि हमारी समृद्धि सात प्रतिशत वार्षिक की गति से हो। तीसरी योजना के अन्त तक हमारी राष्ट्रीय आय का लक्ष्य १९० अरब रु. है, यह बढ़ कर १९७५-७६ में ३७५ अरब रु. हो जाना चाहिए। परन्तु इसके लिए भी आवश्यक है कि हमारी आय का २५ प्रतिशत पुनः विनियोजन में लग जाए। योजना आयोग यह आशा नहीं करता और न हमें करनी चाहिए कि दीर्घ-काल तक विदेशों से हमें विपुल सहायता प्राप्त होती रहेगी। फिर अन्तर राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए किसी समय संभव है कि पांचवीं योजना तक विदेशी सहायता सर्वथा बन्द हो जाए। तब हमें अपने पैरों पर स्वयं खड़ा होना होगा। अतिरिक्त करों से हमें अपनी आय ७-८ अरब रु. तक बढ़ानी पड़ेगी। सार्वजनिक उद्योगों से राष्ट्रीय आय में पर्याप्त योगदान की सम्भावना पर भी योजना आयोग विचार कर रहा है। १९६५-६६ तक इनमें ७१० करोड़ रु. आय की आशा है, तो १९७०-७१ और १९७५-७६ तक क्रमशः २०८० करोड़ और ३९०० करोड़ रु. आय की आशा की जा सकती है। इसी तरह निजी क्षेत्र से भी आय बढ़ने की आशा करनी चाहिए।

आर्थिक विकास एक लम्बी श्रृंखला है, जो किसी एक पंचवर्षीय योजना तक समाप्त नहीं हो जाता। विकास की स्वयं स्फूर्त स्थिति आने तक हमें अनेक योजनाएं बनानी पड़ेंगी।

योजना आयोग के अधिकारियों व अर्थशास्त्रियों का दिमाग इसी दिशा में सोचते हुए अन्नोत्पादन का लक्ष्य पांचवीं योजना के अन्त तक १३ करोड़ टन तक करना चाहता है। जीवन स्तर बढ़ने के परिणाम-स्वरूप चीनी तेल, कपड़ों व साबुन की खपत भी प्रति व्यक्ति दुगनी या कुछ अधिक हो जाने की सम्भावना है। पैट्रोलियम व कोयले से निर्मित पदार्थों का उत्पादन पांच गुना, बिजली सिमेन्ट व रासायनिक पदार्थों का छः गुना, इस्पात व मशी-नरी का उत्पादन १९६०-६१ की तुलना में १२ गुना तक बढ़ जाएगा। योजना आयोग नई औद्योगिक वृद्धि और नई आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप आयात व निर्यात में भी सम्भावित परिवर्तनों पर विचार कर रहा है।

ये सब अंक अभी बिल्कुल प्रारम्भिक कल्पना की स्थिति में हैं। इनमें बार-बार परिवर्तन और संशोधन होंगे और तब तक तीसरी व चौथी योजना के परिणाम भी कुछ स्पष्ट हो जाएंगे और उसके बाद ही पांचवीं योजना का अन्तिम रूप कुछ स्पष्ट हो सकेगा। • •

राज्यों की वित्तीय स्थिति

इस वर्ष के विभिन्न राज्यों के बजट देखते हुए मालूम होता है कि राज्यों के वित्त मंत्रियों ने कुल मिलाकर ४२ करोड़ रु० के नये कर लगाये हैं। यह राशि अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन योजना आयोग ने उनसे जो आशा की थी, और जिसे राज्यों ने स्वीकार कर लिया था, वह ६० करोड़ रु० थी। इसका अभिप्राय यह है कि उन्हें अब १८ करोड़ रुपये की कमी अनुभव हो रही है। बात यहीं नहीं समाप्त हो जाती। तीसरी पंचवर्षीय योजना में उनके लिए ७५० करोड़ रुपये का व्यय लक्ष्य निर्धारित किया गया है, किन्तु उसके पास ६९२ करोड़ रुपये से अधिक के साधन नहीं है, इसलिए ५८ करोड़ रु० का यह अन्तर भी राज्यों को पूर्ण करना है। १९६२-६३ में योजना पर विभिन्न राज्यों ने जो व्यय किया था, उससे ६ प्रतिशत अधिक अर्थात कुल ७४७ करोड़ रु० का व्यय राज्यों के नये बजट में निर्धारित किया गया है। वस्तुतः राज्यों ने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विभिन्न कारणों से आय के नये साधनों को प्राप्त करने की पूरी चेष्टा ही नहीं की। बल्कि बिहार जैसे राज्य ने तो अपना योजना बजट करीब ९ करोड़ रुपया गत वर्ष से कम कर दिया है। सब राज्यों का ३ वर्ष का योजना बजट मिलाकर २०५३.३ करोड़ रुपया होता है, जबकि योजना आयोग ने यह लक्ष्य ३८९६ करोड़ रुपया रखा। इसका अर्थ यह है कि अभी केवल ५२.७ प्रतिशत व्यय हुआ है। क्या राज्य अब आगामी २ वर्षों में १९६४-६५, १९६५-६६ में शेष ४७.३ प्रतिशत कार्य पूरा कर लेंगे। जिस तरह राज्यों की गतिविधि चल रही है, उससे तो यह सम्भावना पूर्ण होती प्रतीत नहीं होती। राज्यों ने जो कर १९६१-६२ और १९६२-६३ में लगाये हैं, वे कर भी ५ वर्षों में ३१० करोड़ रुपये से अधिक की आमदनी नहीं कर सकेंगे। राज्य सरकारें नये-नये कर लगाते हुए गांवों के मतदाता किसानों से एक ओर डरती हैं, और दूसरी ओर वे कोई ऐसी मौलिक योजनायें भी नहीं चला पाती हैं, जो राज्यों की आय का अच्छा स्रोत बन सकें। एक लेखक के अनुसार आज समस्त देश में कृषि से होने वाली आय ५००० करोड़ रुपये है। यदि इस पर २ प्रतिशत भी कर वृद्धि की जाय, तो १०० करोड़ रुपये की आमदनी बढ़ सकती है। किन्तु क्या राज्य सरकारें इतना साहस कर सकेंगी ?

परस्पर विरोधी आंकड़े

आज के अर्थशास्त्र और योजना निर्माण का मुख्य आधार अंक-गणना है। हमारी प्रगति और आवश्यकताओं के सम्बन्ध में आंकड़े जितने ठीक होंगे, उतना ही हम निश्चित रूप से ठीक मार्ग अपना सकेंगे। लेकिन आज देश में विविध उत्पादनों, व्यापार और आवश्यकताओं के सम्बन्ध में जो अंक प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हीं के यथार्थ होने पर भी संदेह किया जा सकता है। ये अंक कितने अप्रामाणिक होते हैं, इसका एक उदाहरण हाल ही में सामने आया था। पिछले छः महीनों में व्यापार मन्त्रालय ने निर्यात के जो अंक प्रकाशित किए थे, रिजर्व बैंक ने उससे बिल्कुल भिन्न अंक प्रकाशित किए हैं। रिजर्व बैंक के आंकड़े उससे १७ करोड़ रुपये कम हैं। हमें यह मालूम नहीं कि इतने भारी अन्तर का कारण क्या है। सम्भव है कि दोनों की गणना पद्धति भिन्न-भिन्न हो। किन्तु वस्तुतः सच्चाई कहां है, यह हम नहीं कह सकते। स्थिति पर पूर्ण प्रकाश डालने के लिए हमारे सामने वास्तविक तथ्य आना चाहिए। इस गणना-पद्धति में कहीं न कहीं दोष अवश्य है। व्यापार मन्त्रालय के पास जो सूचना जाती है, वह बन्दरगाहों से निर्यात व्यापारियों से प्राप्त होने वाली सूचनाओं से होती हैं। गुजरात के बन्दरगाहों से बाकसाइट निर्यात के जो अंक प्राप्त हुए, वे व्यापारिक सूचना के से प्राप्त होने वाले अंकों से कहीं अधिक थे। कुछ पूर्व जब दिल्ली और लन्दन में सूत के व्यापार पर हुई, तब उसका आधार पिछले वर्ष के व्यापार को गया था। व्यापार सूचना विभाग ने उस समय जो दिए थे, यह सन्देह है कि वे वास्तविक निर्यात से बहुत थे। आवश्यकता इस बात की है कि एक निश्चित पद्धति का निर्धारण किया जाना चाहिए और गणना विभागों द्वारा उसी का पालन किया जाना

बाध्य बचत योजना वैधानिक है

बाध्य बचत योजना वैधानिक है व नहीं—उठायी गयी इस आशंका पर कानूनी दृष्टि से अपना मत प्रकट करते हुए भारत सरकार के एटार्नी श्री सी० के० दफ्तरी ने घोषणा की कि इस विधेयक स्वीकार करने के लिए संसद को अधिकार

फलतः अब बाध्य बचत योजना का विधेयक, संशोधनों के साथ, संसद द्वारा स्वीकृत हो गया है।

भारत सरकार फिर बाजार में

भारत सरकार ने घोषणा की है कि ३॥ प्रति १९६३ के बांड जिनके पास हैं और जो १२ मई हो रहे हैं और १९६३-६५ के ३ प्रतिशत के ऋण पास हैं और जो १ जून को भुगतान किये जाने उन्हें यह सुभीता दिया गया है कि वे अपने ४ प्रतिशत १९६९ के ऋण जो ९९-५० प्रतिशत १९८६ के ४॥ प्रतिशत एट-पार में रूपान्तरित कर

इन ऋणों का मुख्य अंश रिजर्व बैंक के इसलिए सरकार को रूपान्तरित करने में कोई नहीं होगी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सारे परिवार के लिए

डी सी एम

के उच्च कोटि के कपड़े

पापलिन	छींटें	मलमल
लिनो	लान्स	लट्ठा
साड़ियाँ	शर्टिंग्ज	ड्रिल्स
शर्टिंग्ज	सजावट के कपड़े	तौलिए

एवं बेड शीट्स आदि

आकर्षक रंगों, शेडों और बनावटों में

डी सी एम के सभी रिटेल स्टोर्स में प्राप्य है ।

डी सी एम वस्त्रोत्पादन में श्रेष्ठता का प्रतीक

दि दिल्ली क्लॉथ एण्ड जनरल मिल्स कं० लि०

दिल्ली

JWT : DCM : 2290

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सरकारी इमारतों का निर्माण : दूसरा पहलू

भारत सरकार के "दिल्ली राजधानी खर्च" के मद में १९६२-६३ के संशोधित बजट में ७.८ करोड़ रु० इमारतों पर खर्च हुआ। १९६३-६४ के बजट में यह राशि ७.४ करोड़ रखी गयी है जबकि १९६१-६२ में यह राशि बजट में केवल ४.९ करोड़ रु० थी। ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार की भवन-निर्माण की भूख अथवा आवश्यकता निरन्तर बढ़ रही है। दिल्ली से बाहर केन्द्रीय पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा बनायी जाने वाली इमारतों का बजट भी कम नहीं है। १९६३-६४ में यह राशि बजट में ७.७ करोड़ रु० प्रस्तावित की गई है। १९६२-६३ में यह राशि ९.२ करोड़ खर्च की गई (संशोधित)। सन्तोष की यही बात है कि इस वर्ष के बजट में यह राशि कम है। क्या वर्तमान आपातकालीन स्थिति इस महकमे पर लागू नहीं होती? उधर आवास गृह बनाने की सामाजिक योजनाएं पिछले वर्ष की २१ करोड़ रु० की राशि से कम करके इस वर्ष १३ करोड़ रु० की कर दी गयी है।

दिल्ली में दफ्तरी स्थान की कमी के बारे में इस मंत्रालय ने अपनी इस वर्ष की रिपोर्ट में अपना दृष्टिकोण इस प्रकार उपस्थित किया है —

"वस्तुतः यहां ३४ लाख वर्ग फुट की दफ्तरी स्थान की कमी है। किराये पर इतनी सुविधा से यह भूमि नहीं मिल सकती है और जब मिलती है, तब किराया बहुत अधिक होता है, अर्थात १०० वर्ग फुट का १०० रु० प्रतिमास, अथवा प्रतिवर्ग फुट का १२ रु० वार्षिक, जबकि दफ्तर के लिए उपयोग में आने योग्य जगह का (बरामदा, सीढ़ी, गुसलखाना इत्यादि छोड़कर) जिस पर कई मंजिल की इमारत बनती है, खर्च प्रति वर्ग फुट ४५ रु० पड़ता है। इस प्रकार इमारती लागत ४ वर्ष के किराये से भी कम पड़ती है। इसलिए सरकार के लिए दफ्तरी इमारतें बनाना मितव्यय है, अपेक्षा वर्तमान भारी किराये पर जगह लेने के।"

प्रश्न

इस सम्बन्ध में तीन प्रश्न उठते हैं। क्या इस समय उपलब्ध स्थान का कम उपयोग नहीं हो रहा? दूसरा युद्ध काल में बनाये गये हट मैंट्स का मरम्मत आदि के अधिक काल के लिए उपयोग नहीं हो सकता? क्या भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत कम व उचित किराये पर इमारतों का अधिग्रहण नहीं हो सकता? इन सब प्रश्नों का उत्तर केवल 'नकार' में नहीं हो सकता? इस मंत्रणालय ने २५.७ लाख वर्गफुट पर आनुमानिक ८.३ करोड़ रु० की लागत से इमारतें बनाने की मंजूरी दी है, पर क्या आपातकालीन स्थिति को देखते हुए कम से कम ६ इमारतों का निर्माण स्थगित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे सभी शुरू भी नहीं हुई हैं।

सरकारी कर्मचारियों के लिए दिल्ली व अन्य स्थानों पर १०४,००० आवास इकाइयों की जरूरत है, जबकि उपलब्ध लगभग ३५००० इकाइयां ही हैं, पर अगर निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी—जिनकी स्थिति सरकारी कर्मचारियों की तुलना में अधिक खराब है—किसी प्रकार गुजारा कर सकते हैं, तो मौजूदा संकट को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार यह खर्च, फिलहाल रोक नहीं सकती? पिछले ९ वर्षों में "निम्न आय—समूह आवास योजना" के अन्तर्गत ६००० रु० वार्षिक से कम आय वाले व्यक्तियों के लिए केवल ७५,००० मकान बनाये जा सके हैं। जिनकी आय ६,००० रु० और १५,००० रु० वार्षिक के बीच है, उनके लिए "मध्यवित्त समूह आवास योजना" के अन्तर्गत सारे भारत में केवल ४३७५ के लिए मकान बन सके हैं। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए असन्तुष्ट होने का यह पर्याप्त कारण क्या विद्यमान नहीं है?

सम्पदा के

आगामी विशेषांक की

प्रतीक्षा कीजिये

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विगत दशाब्दि में बजट की प्रवृत्तियां

कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

इस वर्ष वित्त मन्त्री ने चीनी आक्रमण से उत्पन्न परिस्थिति के नाम से बहुत से कर लगाये हैं, लेकिन जो पाठक पिछले १०, १२ वर्षों की बजट स्थिति का अध्ययन करते रहे हैं, वे जानते हैं कि कर बढ़ाने की प्रवृत्ति नई नहीं है। देश के स्वाधीन होने और पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत देश के पुनर्निर्माण के बाद से लगातार केन्द्रीय सरकार का बजट बढ़ता रहा है। नीचे की तालिका से यह स्पष्ट हो जायगा :—

भारत सरकार का बजट एक दृष्टि में, (१९५०-५१ से १९६३-६४ तक)

(करोड़ रु० में)

	१९५०-१९५१	१९५५-१९५६	कुल प्रथम योजना	१९५६-१९५७	१९६०-१९६१	कुल द्वितीय योजना	१९६१-१९६२	१९६२-१९६३	१९६३-१९६४
राजस्व	४०५.९	४८१.२	२,२३२.४	५६३.२	८७७.५	३,५६२.९	१,०५६.१	१,३७५.४	१,७२३.६
व्यय	३४६.७	४४०.७	१,९८३.०	४७३.९	८२६.२	३,३४२.९	९३१.२	१,३९७.४	१,७२४.४
बचत या घाटा	+५९.२	+४०.५	+२४९.४	+८९.३	+५१.३	+२२०.०	+१२४.९	—२२.०	—०.९

इस तालिका से यह स्पष्ट है कि प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार का बजट छलांगें भरता रहा है। १९५०-५१ में जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हुई थी, केन्द्रीय सरकार का राजस्व ४०६ करोड़ रुपये के करीब था। यह राजस्व प्रतिवर्ष बढ़ता गया, क्योंकि सरकार नये-नये कर लगाती ही गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में यह ४८१ करोड़ रुपये तक पहुँच गया। एक वर्ष लगाये गये नये कर स्थिर रूप से लगते रहे, उनमें कोई कमी नहीं हुई। दूसरी योजना के शुरू होते ही राजस्व ने बड़ी छलांग मारी। ८२ करोड़ रुपये की राजस्व में वृद्धि हो गई, जो दूसरी योजना के अन्त तक पहुँचते-पहुंचते ८७७.५ करोड़ रुपये के राजस्व के रूप में हमारे सामने आई। यदि पहली योजना की अवधि में कुल राजस्व २२३२.४ करोड़ रुपये था, तो दूसरी योजना में बढ़कर ३५६२.९ करोड़ रुपये हो गया। तीसरी योजना के श्री गणेश से तो राजस्व और भी तीव्र गति से बढ़ा। १९६१-६२ और १९६२-६३ में यह राजस्व १९६०-६१ की अपेक्षा क्रमशः १७८.९ और ४९७.९ करोड़ बढ़ गया। इस वर्ष तो चीन का आक्रमण और प्रतिरक्षा की गम्भीर समस्या थी। इसलिए करीब ढाई अरब रुपये के नये करों का प्रस्ताव किया गया।

कारण

एक प्रश्न यह भी उपस्थित होता है कि आखिर किन कारणों से केन्द्रीय सरकार एक के बाद एक कर लगाती जाती है। इस प्रश्न के कुछ निम्नलिखित उत्तर हैं :—

१. पंचवर्षीय योजनाओं के साथ-साथ सरकार की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। १५०-२०० वर्षों के अंग्रेजी शासन में राष्ट्र निर्माण की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया था। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और ग्राम-सुधार आदि बातों की ओर विदेशी सरकार की बहुत कम रुचि थी। पंचवर्षीय योजनाओं में इन प्रवृत्तियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। इन कारणों से सरकार के उत्तरदायित्व निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं और उन्हें निभाने के लिये सरकारी बजट प्रतिवर्ष बड़े होते जा रहे हैं। १९५०-५१ में समाज सेवाओं व विकास कार्यों पर ३९.५ करोड़ रुपया व्यय हुआ था, तो १९६२-६३ में १९०.९ करोड़ अर्थात् करीब चार गुना।

२. ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है, यह महंगाई बढ़ती जाती है। इस कारण न केवल सब पदार्थ मंहगे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मिलते हैं, बल्कि छोटे बड़े सरकारी कर्मचारियों के वेतन भी बढ़ाने पर सरकार को विवश होना पड़ता है। ज्यों-ज्यों जनता की आमदनी बढ़ती है, त्यों-त्यों मंहगाई और भी बढ़ जाती है और इसका प्रभाव सेवाओं पर पड़ता है। रेलवे व डाक कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का खर्च निकालने के लिये डाक व रेल के भाड़े किराये बढ़ाने पड़ गये। यह स्थिति आम विभागों के लिये भी लागू होती है। दिल्ली को 'ए' स्थिति का नगर घोषित करते ही एक करोड़ रुपये का व्यय बढ़ गया।

३. प्रशासन व्यय निरन्तर बढ़ता जा रहा है। प्रशासन में सरकारी अफसरों, कर्मचारियों व चपरासियों की संख्या ही नहीं बढ़ रही, उनके वेतन और भत्तों में भी अनापशनाप वृद्धि होती जा रही है। किसी समय मंत्रिमण्डल बहुत छोटा था, आज वह हरा भरा जंगल बन गया है। सेक्रेटरियों, डिप्टी सेक्रेटरियों, और अंडर सेक्रेटरियों व सुपरिण्टेण्डेन्टों और उनके सम्बद्ध कर्मचारियों पर व्यय निरन्तर बढ़ता जा रहा है

टैक्स आदि की वसूली के तथा अन्य प्रशासनिक व रक्षा संबन्धी व्यय किस तरह बढ़ गये हैं, यह निम्नलिखित अंकों से स्पष्ट हो जायेगा :—

४. सेना का व्यय भी संसार में सैनिक शस्त्रास्त्रों की आधुनिकता के कारण बढ़ता जा रहा है। १९५०-५१ में जो व्यय १६४.१ करोड़ रु० था, वह १९६३-६४ (बजट) में ७०८.५ करोड़ रु० हो गया, अर्थात् करीब सवा चार गुना।

५. एक और बोझ जो निरन्तर बढ़ता जा रहा है, वह ऋणों की किश्तों व ब्याज का है। आवश्यकता पड़ने पर सरकार को आसानी से कर्ज मिल जाते हैं, लेकिन जब चुकाने का समय आता है तब वित्त-मन्त्री भारी कठिनाई में पड़ जाते हैं। १९५०-५१ में ऋणों के मद में केन्द्र ने केवल ३७.३ करोड़ रुपये बजट में रखे थे, जबकि १९६१-६२ में संशोधित बजट के अनुसार २४६.० करोड़ रुपये की और नये वर्ष के बजट में तो २८०.३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

६. प्रतिवर्ष अन्न के आयात के लिए भी १-१॥ अरब रुपये की एक बड़ी राशि आज भी सरकार को निर्धारित करनी पड़ती है।

७. केन्द्र पर एक और बोझ है जो निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसका कारण है राज्यों में राष्ट्रनिर्माण की

सं० तालिका १

केन्द्रीय सरकार के व्यय (करोड़ रु० में)

	प्रथम योजना का			द्वितीय योजना का			बजट		
	१९५०-५१	१९५५-५६	कुल व्यय	१९५६-५७	१९६०-६१	कुल व्यय	१९६१-६२	१९६२-६३	१९६३-६४
कर वसूली	१०.२	१२.५	५८.४	१४.४	२२.४	९३.७	२१.२	२३.१	२३.[illegible]
प्रशासनिक व्यय	२१.३	३३.६	१३८.३	३८.१	५८.७	२३८.९	५९.२	७६.४	८८.[illegible]
प्रतिरक्षा सेवाएं	१६४.१	१७२.२	८९५.७	१९२.१	२४७.६	११७८.२	२८९.५	४५१.८	७०८.[illegible]
ऋण व्यय	३७.३	४३.१	१९९.२	३९.१	७७.१	२७६.३	८२.८	२४६.०	२८०.[illegible]
पैंशन व प्रिवी पर्स आदि	—	—	—	—	—	—	१०.२	१०.६	१०.[illegible]
आवश्यक व्यय	—	—	—	—	—	—	१३.८	६४.६	८६.[illegible]
विविध	५१.३	५७.८	२२४.१	५१.३	१३१.५	४३६.१	६८.५	९७.८	१००.[illegible]
समाज सेवाएं	३९.५	८२.४	२७६.३	१०८.१	२३६.४	८८४.४	१७६.३	१९०.६	१८८.[illegible]
राज्यों को अनुदान ऋण व अंशदान	१५.६	३५.९	१३१.७	२८.३	४८.५	२१७.९	१९८.०	२१३.६	२२१.[illegible]
अन्य व्यय	७.३	३.२	५९.३	२.४	४.१	१७.३	११.७	२२.९	१७.[illegible]
कुल व्यय	३४६.६	४४०.७	१९८३.०	४७३.८	८२६.०	३३४२.८	९३१.२	१३९७.४	१७२१.[illegible]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रवृत्तियों के कारण उनका बढ़ता हुआ उत्तरदायित्व। केन्द्र इन उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए निरन्तर राज्यों के अनुदान व सहायता की राशि बढ़ाने पर विवश होता जा रहा है।

अनुदान, व अंशदान की दर व्यवस्था के कारण केन्द्र ने ऋण व सहायता के रूप में राज्यों को कितनी राशि दी, यह इन अंकों से प्रकट होती है :—

१९५०-५१ में जो राशि केवल १५.६ करोड़ रु० थी वह बढ़ते बढ़ते १९८.० करोड़ रु० तक पहुँच गई और १९६३-६४ (बजट) में तो २२१.० करोड़ रु० पर आ गयी है।

इस तरह हमने संक्षेप में देखा कि केन्द्रीय सरकार का राजस्व बजट किन कारणों से सुरसा के बदन की तरह बढ़ता जा रहा है। १९५०-५१ की अपेक्षा इस वर्ष चार गुना बढ़ गया है। इनमें से अनेक खर्च ऐसे हैं, जिनमें थोड़ी या बहुत कटौती अवश्य की जा सकती है। लेकिन सरकार अपने आडम्बर, शानदार कोठियों, बढ़िया फर्नीचर, मोटरों व भत्तों में कमी नहीं करना चाहती और इनका भार भी देश की जनता को उठाना पड़ता है।

आमदनी के स्रोत

अब हम एक दृष्टि इस पर भी डालें कि सरकार अपने भारी खर्च पूरा करने के लिए आमदनी किन स्रोतों से करती है :

१. आय और व्यय पर कर।
२. सम्पत्ति व पूंजी पर कर।
३. पदार्थों व सेवाओं पर कर।
४. रेलवे व डाक तार आदि सेवाओं से।

इन करों से सरकार को दस वर्ष पूर्व कितनी आमदनी होती थी और आज क्या होती है, यह नीचे लिखी तालिका से स्पष्ट होगा :—

(करोड़ रु० में)

	१९५०-५१	१९६०-६१	१९६३-६४
१. आयकर, कारपोरेशन तथा व्यय कर	१२५.७	१९२.०	३४७.२
२. सम्पत्ति व पूंजीकर	—	९.३	१६.१
३. तटकर, उत्पादन-कर, रेलवे किराया-कर आदि	२३१.३	५२९.०	८८५.४
४. रेलवे, डाकतार व टकसाल आदि से	२३.२	७१.५	१२२.९

नये संशोधनों के अनुसार ये कर २० करोड़ रुपये कम होंगे। इन करों में उत्पादन कर तो बहुत तेजी से बढ़ा है। दर में भी वृद्धि हुई है और नई वस्तुओं पर भी कर लगा है। १९५०-५१ में उत्पादन करों से केन्द्र की ४६७.५ करोड़ रु० की आय हुई थी, १९५६-५७ में १७३.२ कूती गई है। १९६०-६१ में ३४१.३ करोड़ रु० और नये बजट में ५६२.५ करोड़ रु० की आय कूती गयी है।

इन करों तथा उद्योग आदि सेवाओं तक ही सरकार के आय-साधन सीमित नहीं है। साधारण व्यक्तियों, व्यापारियों व उद्योगों की भांति सरकार भी अपने खर्च चलाने के लिए समय समय पर देश व विदेशों में भारी ऋण लेती हैं। नीचे की तालिका से कुछ स्थिति स्पष्ट हो जायगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा लिये गये ऋण (करोड़ रु० में)

	३१ मार्च १९३९ तक	३१ मार्च १९६३ तक	३१ मार्च १९६४ तक
भारत में	४८४.८	४५७१.६	५२५५.८
विदेशों में	४६५.०	१३७९.०	१७९०.२
युद्ध सहायता	—२०.६	—२०.६	—२०.६
कुल सार्वजनिक ऋण	९२९.२	५९३०.०	७०१५.४
दूसरी देनदारियां	२५२.५	२०६६.४	२३४८.८
कुल ऋण	११८१.७	७९९६.४	९३६४.२

इन ऋणों पर सरकार को कितना प्रतिवर्ष किश्त व ब्याज के रूप में चुकाना पड़ता है, यह तालिका नं० २ में देखिये।

इतना ही हो तो गनीमत है, लेकिन सरकारों के पास अपनी आय बढ़ाने का एक और साधन होता है, जो नागरिकों के पास नहीं होता। नासिक के प्रैस में यथेच्छ मात्रा में नोट छाप सकती है। घाटे की यह अर्थ-व्यवस्था

(शेष पृष्ठ २४४ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बढ़ती हुई जनसंख्या

भारत की आर्थिक उन्नति में अवरोध

श्री वी० वी० हरबाडकर

जब माल्थस ने १७८९ में अपनी "जनसंख्या-वृद्धि की समस्या" की परिकल्पना प्रकाशित की थी, उस समय विश्व की आबादी लगभग ९२ करोड़ थी। आज ३ अरब १२० करोड़ से अधिक है। भारत में १९६१ में आबादी ४३ करोड़ ९० लाख २३५ थी, जबकि १९५१ में ३५ करोड़ ९० लाख थी। इन १० वर्षों में अप्रत्याशित रूप से २१.५० प्रतिशत की वृद्धि हो गई। इसलिए, भारत की आज सबसे मुख्य और प्रथम समस्या इस आबादी का, आर्थिक विकास की दृष्टि से, नियंत्रण ही है।

आर्थिक विकास का अभिप्राय

जब हम आर्थिक विकास की बात कहते हैं तो उसका क्या अभिप्राय होता है? इसमें दो तत्वों का समावेश होता है। पहला, समूचे आर्थिक सामान की प्रति व्यक्ति उत्पादकता में अधिकता और दूसरा आर्थिक सामान और सेवाओं की प्रति व्यक्ति अधिक खपत। "आर्थिक विकास" इस शब्द के अन्तर्गत ही यह भाव है कि उस देश में उत्पादन कम है, प्रति व्यक्ति आय कम है और प्रति व्यक्ति खपत कम है। स्पष्ट ही, यह पिछड़ी हुई और अ-विकसित आर्थिक स्थिति के लक्षण हैं और इस बात का संकेत करते हैं कि अधिक बचत, अधिक पूंजी विनियोग, अधिक उत्पादन और खपत—इन सब पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

तीन आधार

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश ने आर्थिक उन्नति के लम्बे और कठिन मार्ग का पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा अवलम्बन किया है, ताकि हम विशाल पैमाने पर फैले हुए अभाव से मुक्ति पाकर आम जनता के कल्याण के आधार पर राष्ट्र निर्माण कर सकें। इसके लिए आवश्यक है कि सामूहिक और प्रति व्यक्ति उत्पादन और आय में सुधार और वृद्धि हो ताकि जीवन स्तर ऊंचा हो सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति तीन साधनों पर निर्भरता करती है (१) आबादी की वृद्धि-दर (२) पूंजी विनियोग के लिए बचत और (३) पूंजी व उत्पादन—दोनों के बीच अनुपात वृद्धि। इन्हीं बातों को दृष्टि में रखते हुए, दूसरी योजना की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि १९६०-६८ तक राष्ट्रीय आय १९५०-५१ की तुलना में दुगुनी और १९७३-७४ तक प्रति व्यक्ति आय दुगुनी होनी संभव हो जाएगी। किन्तु आर्थिक विकास की दृष्टि से पहली बात अर्थात जनसंख्या के सम्बन्ध में विचार तक इस लेख में हम अपने को सीमित रखना चाहते हैं।

पुष्टिकारक भोजन नहीं मिलता

भारत की समस्या के तीन मुख्य स्वरूप हैं। पहला, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, दवाई और अन्य आवश्यक सामग्री सेवाओं की दृष्टि से जीवन स्तर बहुत नीचा है। भारत में प्रति व्यक्ति दैनिक भोजन, लगभग १८०० केलोरी का होता है, जबकि शरीर के लिए न्यूनतम २५०० केलोरी चाहिए। इसके विपरीत कनाडा, अमेरिका और उत्तर-पश्चिम यूरोप में औसतन प्रति व्यक्ति के भोजन में ३,००० से ३,४०० केलोरी होती है। इसलिए, देश के करीब ५ करोड़ अथवा १२ प्रतिशत से अधिक व्यक्ति कम पुष्टिदायक भोजन मिलने से रोगी रहते हैं।

शिशु संख्या में वृद्धि

हमारी सामाजिक समस्या का दूसरा पहलू यह है कि मृत्यु संख्या धीमे-धीमे कम हो रही है। १९०१ में यह ४२.६, प्रति हजार थी। १९५१ में २७.४ और १९६१ में २१.६ प्रति हजार रह गई। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होने और मलेरिया जैसी आम लोगों की बीमारियों पर काबू पाने और कम होने के कारण और प्रसूति मृत्यु संख्या में भारी न्यूनता आ गयी है। तीसरी योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य योजनाएं जिस समय पूरी हो जाएंगी, तब मृत्यु-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संख्या में और भी न्यूनता आ जाएगी।

इसके विपरीत हमारे देश में शिशु जन्म संख्या अभी बढ़ रही है, ४० प्रति हजार, जबकि पश्चिमी यूरुप में यह केवल १८ प्रति हजार है।

इन तीनों का देश की आर्थिक स्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है।

आबादी की वृद्धि में तेजी से हमारे जीवन-स्तर को ऊंचा करने के सारे प्रयत्न निकम्मे हो रहे हैं। (१९६०-६१ की कीमतों के आधार पर) तीसरी योजना में १९६६ में प्रति व्यक्ति आय ३८५ रु. तक पहुँच जाने की आशा है, अर्थात् १७ प्रतिशत अधिक। इसी अवधि में राष्ट्रीय आय ३१ प्रतिशत तक बढ़ जाने का अनुमान है। इस वृद्धि का आधा वह शिशु-समूह खा जाएगा, जो तब तक नयी आबादी में बढ़ोतरी पैदा करेगा।

दूसरी बात यह है कि १९७३-७४ तक प्रति व्यक्ति आयको दुगुना करने के लिए बहुत भारी प्रयत्न करना होगा। तीसरी योजना में ६ प्रतिशत वार्षिक आर्थिक विकास की दर १९७३-७४ तक प्रति व्यक्ति आयको दुगुना नहीं कर सकेगी, क्योंकि आबादी के बारे में जो अनुमान लगाये थे, वे गलत निकले हैं। योजना आयोग ने आबादी की वृद्धि की दर १.२५ प्रतिशत वार्षिक रखी थी, जबकि बढ़ोतरी की दर २.१५ प्रतिशत वार्षिक रही। १९७३-७४ तक प्रति व्यक्ति आयको दुगुनी करने के लिए ६.८ प्रतिशत वार्षिक अथवा १३.५ प्रतिशत राष्ट्रीय आय को, जो १९६०-६१ में १४,५०० करोड़ रु. थी, दुगना करना पड़ेगा।

बेरोजगारी बढ़ रही है

तीसरी बात, हमारे योजनाबद्ध आर्थिक विकास का मुख्य लक्ष्य पूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करना है। परन्तु इस समय आबादी की वृद्धि की जो रफ्तार है—२.१५ प्रतिशत—उससे रोजगार की स्थिति बिगड़ गयी है। १९६१ में बचे हुए बेरोजगार ९० लाख थे। तीसरी योजना में केवल १ करोड़ ४० लाख को रोजगार देने का प्रस्ताव है। अगर यह लक्ष्य पूरा भी हो जाए तब भी, १९६६ तक बेरोजगारों की संख्या, लगभग १ करोड़ २० लाख से १ करोड़ ३० लाख तक होगी, उन लाखों के अतिरिक्त जो कम या आधे रोजगार पर हैं।

दो-मोर्चों पर हमला

आर्थिक विकास का लक्ष्य पूरा करने के लिए हमें दो-मोर्चों पर हमला करना होगा—एक भारी आर्थिक विकास और दूसरा, सन्तान वृद्धि में कमी। पहले के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का क्रम चल रहा है। पांचवीं योजना १९७५-७६ तक प्रति व्यक्ति आय ५३० रु. वार्षिक हो जाएगी, इसी अनुपात से पूंजी-विनियोग तीसरी योजना के १४-१५% वार्षिक से बढ़कर उस समय १९-२०% वार्षिक हो जाएगा। इसी प्रकार घरेलू बचत तीसरी योजना में ११.५% से बढ़कर पांचवीं योजना तक राष्ट्रीय आय का १८-१९% हो जाएगी।

सन्तति निरोध के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता है। अभी तक इधर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। पहली और दूसरी योजनाओं में इस कार्य के लिए, क्रमशः ६५ लाख और ५ करोड़ रु. की नाम मात्रकी राशियां रखी गयी थीं। इस काम के लिए सुयोग्य डाक्टरों और सामाजिक कर्मियों को—विशेषता देहात के लिए भारी कमी है। परम्परागत सन्तति-निरोध के साधन बहुत असफल रहे हैं।

परिवार नियोजन के कुछ उपाय

परिवार नियोजन पर विशेष ध्यान देना होगा। तीसरी योजना में इसके लिए ५० करोड़ रु. रखा गया है। रेडियो, फिल्म इत्यादि द्वारा विश्व प्रचार के अतिरिक्त, इस काम के मंत्रालय लिए स्वास्थ्य के अन्तर्गत एक पृथक् मंत्री की नियुक्ति, सन्तति निरोध की लाभप्रद, सक्षम और हानि-शून्य गोलियों का प्रचार, कानूनी उपायों का अवलम्बन, जैसे चौथे बच्चे के बाद से टैक्स में वृद्धि, वंध्याकरण की सुविधाएं—बड़े पैमाने पर, शिक्षा का प्रसार—इत्यादि उपायों का अवलम्बन किया जाना चाहिये।

इन सब कार्यों के लिए यदि आवश्यक हो तो एक पृथक् मंत्रालय स्थापित करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए, जो इन सब कार्यों का निरीक्षण और संचालन कर सके। अभी तक सरकार ने इस कार्य को बहुत गौण स्थान दिया है।

(शेष पृष्ठ २२८ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

महान् अर्थशास्त्री डा० राव

कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

योजना आयोग के नये सदस्य डा० वी० के० आर० वी० राव भारत के अर्थशास्त्री विद्वानों में ऊंचा स्थान रखते हैं। आर्थिक क्षेत्र में आपका सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक आधार अंकित करना है। वे पहले अर्थशास्त्री हैं, जो अपने अर्थशास्त्रीय अध्ययन और विवेचन के कारण योजना-आयोग के सदस्य नियत किये गये हैं।

अहमदाबाद में एल० डी० आर्टस कालिज के प्रथम प्रिंसिपल रहने के बाद वे दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख पद पर नियुक्त प्रथम व्यक्ति थे। यहां उनकी योग्यता का बहुत विकास हुआ और वे शीघ्र ही देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों में गिने जाने लगे। दिल्ली स्कूल आफ इकनामिक्स के वे संस्थापक थे और वही प्रथम निर्देशक नियत हुए। उनके निर्देशन में यह स्कूल भारत के प्रमुख अर्थशास्त्र की संस्था बन गया। अपने इस कार्य से भी पूर्णतया संतुष्ट न होकर उन्होंने इन्स्टीट्यूट आफ इकनामिक ग्रोथ की स्थापना की और वहां भी ये प्रथम संचालक थे। इसी पद पर से उन्हें प्रथम महान अर्थशास्त्री के रूप में वे योजना आयोग का सदस्य बनाया गया। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में प्रथम रहने की कीर्ति को अब तक कायम रखा है।

अर्थशास्त्री के रूप में डा० राव ने इस सदी के चौथे दशक में ख्याति प्राप्त की। आप की पुस्तक 'नेशनल इनकम आफ ब्रिटिश इण्डिया १९३०-३१' एक प्रामाणिक और विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ है। इसी प्रबन्ध पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आपको डाक्टर की उपाधि मिली। १९५७ में राष्ट्रीय आय का अनुसन्धान करने के लिए जो सम्मेलन बुलाया गया, उसमें उनका भारी योगदान रहा। कीन्स के सिद्धान्तों की अर्धविकसित देशों की पृष्ठ भूमि में की गई आपकी विवेचना महत्वपूर्ण है। भारत की द्रव्य और विनिमय सम्बन्धी प्रचलित समस्याओं पर भी आपने चिन्तन और लेखन किया है। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व डा० राव ने अनेक रूपों में सरकार की ओर से काम किया था। वे कुछ दिन तक वाशिंगटन में भारत के खाद्य परामर्श दाता भी रहे। इसी समय उन्हों ने अर्थशास्त्र का गम्भीर अध्ययन

महान् अर्थशास्त्री डा० राव

और आर्थिक प्रगतियों का अनुसंधान अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। तब से इनके सामने अनेक प्रलोभन आए, पर उन सबको लात मार कर वे केवल अनुसन्धान कार्य में प्रवृत्त रहे। यही कारण था, कि आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति के गौरवपूर्ण पद से भी मुक्त होकर इंस्टीट्यूट आफ इकनामिक ग्रोथ के प्रमुख पद का कार्य अपने हाथ में लिया।

भारतीय दृष्टि

अनेक प्रकाण्ड अर्थशास्त्रियों की रूढिवादी विचार धारा में डा० राव विश्वास नहीं रखते। वे प्रत्येक प्रश्न को भारतीय दृष्टि से विचार करते हैं। जब मैं उन से मिलने के लिए उनके कार्यालय में गया, तो उनकी मेज पर अर्थशास्त्र की पुस्तकों और सरकारी रिपोर्टों का अम्बार लगा था, वहां दूसरी ओर स्वामी विवेकानन्द और श्री शिवाजी की पुस्तकें तथा गीता पर लिखी गई पुस्तकें भी दृष्टि गोचर हुईं। उनका स्पष्ट प्रभाव उनकी चिन्तन पद्धति पर पड़ा प्रतीत होता है।

उनके एक लेख में उच्चवर्ग के विलासपूर्ण जीवन की आलोचना करते हुए कहा गया है, कि जब तक उच्च

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अपने वैभव प्रदर्शन को छोड़ कर संयम और सादगी का जीवन व्यतीत नहीं करता तब तक मजदूर और किसान भी, और बचत करने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। वे लिखते हैं—

"वास्तव में उच्च वर्ग के लोग जब उन्हें उपभोग पर संयम रखने के लिए कहते हैं तो उनका यह सोचना स्वाभाविक है कि उच्च वर्ग को स्वयं पहले इस पर अमल करना चाहिए, खास तौर से जब कि उच्च वर्ग द्वारा अपने उपभोग में कमी लाने से उनकी आधारभूत आवश्यकताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। स्थिति यह है कि जनसाधारण के उपभोग में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है और बचत के लिए राष्ट्रीय आवाहन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नतीजा यह हुआ है कि उच्चवर्ग के अत्याधिक उपयोग के परिणामस्वरूप प्रदर्शन प्रभाव के कारण जन साधारण के उपयोग में वृद्धि हुई है और बचत की दर में कमी आई है।"

इसी तरह वे आज की सरकार की अर्थनीति की आलोचना करते हुए लिखते हैं—"अर्ध विकसित देशों की सरकारें शायद यह भूल जाती हैं कि वे गरीब जनता की प्रतिनिधि हैं और कर राजस्व उन्हें जनसाधारण से ही मिलता है, जिनमें कर देने की समुचित शक्ति भी नहीं है, फिर भी वे अपनी आधारभूत आवश्यकताओं से धन बचाकर टैक्स अदा कर रहे हैं। इस लिए अर्ध विकसित देशों की सरकारों को उन्नत देशों की तुलना में शासन प्रबन्ध पर व्यय अथवा उपभोग में अधिक मितव्ययी होना चाहिए। भारत सरकार भी इस सामान्य प्रवृत्ति से नहीं बच पाई है। नतीजा यह हुआ है कि वह आज जनता को मितव्ययिता बरतने के लिए बाध्य करने और उनके अत्यधिक उपभोग रोकने के कार्य में अपने आपको कमजोर पा रही है। अत्यधिक सरकारी उपभोग का अर्थ सीमित साधनों का आर्थिकेतर निर्धारण ही नहीं, बल्कि जनसाधारण पर प्रदर्शन प्रभाव का सिद्धांत कार्यरत होना भी है। इस से लोगों की अधिक खर्च करने की मनोवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है और सरकार के व्यय के लिए कर देने का उनमें उत्साह खत्म हो जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह समस्या भाषणों, बड़ी-बड़ी बातों और अपीलों से हल नहीं हो सकती। भारत की जनता आज उपदेश पसन्द नहीं करती। जो कहते हैं उसकी बजाय जो करते हैं, उसका उन पर ज्यादा असर पड़ता है। गांधी जी दरिद्रनारायण की केवल बात ही नहीं करते थे, बल्कि वे स्वयं भी गमछा पहनते, तीसरे दर्जे में रेल यात्रा करते और झोंपड़ी में रहते और सोते थे। उनकी मितव्ययता ध्यानाकर्षी थी। इसलिए जब वे सादगी से जीवन व्यतीत करने की बात कहते थे तो उनके शब्दों में वजन होता था। यदि देश में अत्यधिक उपभोग को निरुत्साहित करने अथवा मितव्ययिता और सादगीपूर्ण उपभोग स्वरूप को प्रोत्साहन देने के लिए समुचित वातावरण पैदा करना है तो उपर्युक्त प्रकार की नीति काम में लाने की जरूरत है।"

उनके ये विचार केवल समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हों, ऐसा हम नहीं मानते। समाजवाद के साथ-साथ उन पर भारत की आध्यात्मिक विचार धारा का प्रभाव भी अवश्य पड़ा है। वे भारत को केवल पश्चिमी अर्थशास्त्रियों की दृष्टि से नहीं देखना चाहते। अणुव्रत आंदोलन में उनकी रूचि इसी का एक प्रमाण है।

यह भी हमारे लिए हर्ष की बात है कि आज कल के अंग्रेजी के अन्ध भक्त अर्थशास्त्रियों से वे भिन्न विचार रखते हैं। वे हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद पर रहते हुए उन्होंने हिन्दी को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया। जब इन पंक्तियों का लेखक सम्पदा के लिए लेख लेने के लिए गया तो वे हिन्दी में इस तरह के ऊंचे स्तर के पत्र को देख कर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसी दिन एक विचारपूर्ण लेख लिख कर मुझे दे दिया।

आज वे योजना आयोग के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। आज इस आयोग के सामने जो समस्याएं हैं, उन से वे भली भांति परिचित हैं। प्रोग्राम इवेल्यूएशन अथवा कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं का गम्भीर अध्ययन किया है। इस लिए यह आशा की जाती है कि योजना आयोग में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। उनकी नियुक्ति इस लिए भी स्वागत योग्य है कि वे भूतपूर्व प्रतिरक्षा मंत्री श्री कृष्णा मेनन के स्थान पर योजना आयोग के सदस्य

(शेष पृष्ठ २२८ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नव निर्माण में गौरवपूर्ण सहयोग

श्री तुलसीदास किलाचन्द

स्टेट बैंक को छोड़कर, शेष सब भारतीय बैंक केवल मात्र अपने साधनों पर ही निर्भर करते हैं। पिछले दशक की अपेक्षा अब भारतीय बैंकों की आय घट गयी है, मुख्यतः खर्च बढ़ जाने के कारण १७ बैंकों के प्रकाशित विवरणों के अनुसार, कर देने के बाद, १९६२ में उनकी २ प्रतिशत आय गिर गयी। समूची आय का कुल लाभ १०.६ प्रतिशत हुआ।

पर, बैंकों पर अब जो नये बोझ पड़े हैं, विशेषतः अधिलाभ कर से, उससे इनका विस्तार रुक जायेगा और जनता के बचत संग्रह पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अधिलाभ कर, लगभग, ५ करोड़ रु० अधिक का होगा। अगर इससे राहत न मिली तो वे न केवल अपने कर्मचारियों को बोनस और हिस्सेदारों को डिविडैंड न दे सकेंगे, किन्तु उत्पादन प्रवृत्तियों में भाग लेना भी उनके लिए कठिन हो जाएगा।

अधिक दफ्तर खुल गये हैं

पिछले दशक में भारतीय बैंक पद्धति ने कितनी प्रगति की है, यह इसी से पता लगेगा कि १९६१ के अन्त में भारत के प्रत्येक ९९,००० व्यक्तियों के पीछे बैंक का एक दफ्तर था, जबकि एक दशक पहले यह संख्या १,३७,४०० थी। १९५२-६१ में भारतीय बैंकों की कुल परिसम्पत (एसेट्स) १,१३९ करोड़ रु० से बढ़कर २,६०४ करोड़ रु०—अर्थात दुगुनी से भी अधिक हो गयी है। यह राशि राष्ट्रीय आय की करीब पांचवां हिस्सा है।

जनता में बचत की प्रवृत्ति

उपलब्ध वित्तीय साधनों का संग्रह करके बैंक आर्थिक विकास के लिए सरकार को उधार देकर राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने में और विदेशी आक्रमण को रोकने में सहायक हो रहे हैं। राष्ट्र की बेकार पड़ी बचत का संग्रह करके बैंक राष्ट्र के द्रुत औद्योगिक और व्यापार विस्तार में प्रबल सहायक हो रहे हैं। १९५२ के अन्त तक बैंक कार्यालय २,६७१ से बढ़कर १९६१ में ४,३८८ हो गये। इस प्रकार जमा करने की आदत का अधिक क्षेत्र में और अधिक जनता में बैंकों द्वारा प्रसार किया गया। इस समय बैंक कार्यालयों की संख्या ४,६११ तक पहुंच गया है। उनके अर्ध-शहरी कार्यालय ७७४ से बढ़कर १,४२७ हो गये हैं, अर्थात १९५२ में २९ प्रतिशत से बढ़कर १९६१ में ३८ प्रतिशत तक पहुँच गये।

बैंकों के पास डिपाजिट हिसाबों की संख्या ३२ लाख से बढ़कर ६५ लाख से अधिक हो गयी है, अर्थात १०० प्रतिशत अधिक, और डिपाजिट राशियों की संख्या १९५१ में ८९२ करोड़ से बढ़कर १९६१ में २,०४९ करोड़ रु०, अर्थात १३० प्रतिशत अधिक। कुल डिपाजिटों का आधा व्यक्तियों का है।

उत्पादन वृद्धि में सहयोग

यह समझना भूल है कि जनता की बचत को बैंक अपने बक्सों में बन्द कर देते हैं। वे इन राशियों को उत्पादन कार्यों के लिए उधार देते हैं। यही उनका मुख्य काम है। पिछली दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में बैंक से उधार लेने वाले हिसाबों की संख्या २२० प्रतिशत बढ़ गयी, अर्थात् ३.८ लाख से १२.३ लाख और विभिन्न प्रकार के ऋण जो इन्हें दिये गये—जैसे उत्पादन के लिए, माल भेजने के लिए, अल्पकालीन आर्थिक न्यूनता को पूरा करने के लिए, जबकि अधिक और स्थिर पूंजी का गठन किया जा रहा हो, अस्थायी दिक्कतों को दूर करने के लिए, और देश की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए—४३५ करोड़ रु० से बढ़कर १,३२१ करोड़ रु० हो गये, अर्थात १४७ प्रतिशत वृद्धि। ऋण की राशि की अपेक्षा ऋण लेने वालों की संख्या में वृद्धि यह दर्शाती है कि पिछले दशक की अपेक्षा अब बैंक का ऋण विभिन्न स्तरों की जनता को अधिक विस्तार से सुलभ हो गया है। बैंकों से ऋण लेने वालों में उद्योग का हिस्सा १९५२ में एक तिहाई से भी कम था, जो १९६१ में आधे से भी अधिक हो गया।

सरकार के उधार लेने के कार्यक्रमों को बैंक उदारता से पुष्ट करते हैं। सरकारी सिक्यूरिटियों में उनका विनियोग

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१९५२ में ३१९ करोड़ से बढ़कर १९६१ में ५७५ करोड़ रु० हो गया और १९६२ में वह ७११ करोड़ तक पहुँच गया। निस्सन्देह, सरकार के सुरक्षा और विकास के कार्यक्रमों को अग्रसर करने में बैंक निरन्तर हिस्सा लेते रहेंगे।

१ लाख कर्मचारी

बैंकों की वित्तीय व्यवस्था के सम्बन्ध में मालूम हुआ है कि पिछले दशक में परिगणित बैंकों का कार्यरत अर्जन ४८ करोड़ रु० से बढ़कर १२७ करोड़ रु० हो गया। इस अधिक आय का उपयोग शाखाओं की संख्या वृद्धि, कर्मचारियों को अधिक वेतन और संचित कोष को बढ़ाने में हुआ। इस समय बैंकों की ४,६०० से अधिक शाखाएं हैं और इनमें एक लाख से अधिक प्रशिक्षित और सक्षम व्यक्ति कार्य करते हैं। १९५२-६१ में स्टाफ में ३२,००० से अधिक व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। बैंक उन्हें अच्छा वेतन देता है, ताकि वे प्रसन्न और सन्तुष्ट रहें।

जमा रकमों पर ब्याज

बैंकों का संस्थापन व्यय १९५२ में १७ करोड़ रु० था, अब दुगुने से अधिक बढ़कर १९६१ में ३६ करोड़ रु० हो गया। अन्य कार्यशील व्यय भी ६ करोड़ रु० से बढ़कर लगभग दुगुने ब कर ११ करोड़ रु० हो गये हैं। जमा रकमों पर जो ब्याज दिया जाता है, वह लगभग चार गुना बढ़कर १३ करोड़ रु. से ४९ करोड़ रु. हो गया है, जो कार्यशील आय का क्रमशः २८ प्रतिशत और ३८ प्रतिशत द्योतक हैं। कोष निर्माण के लिए क्रमशः बढ़ रहे लागत खर्च की वृद्धि से, अन्य बातों के साथ, इस बात का परिचय भी मिलता है कि भारत सरकार की महंगी अर्थनीति का विकास हो रहा है और डिपाजिटरों की आय ऊंची हो रही है।

सर्वत्र, व्यय आधिक्य के कारण कर से पहले बैंकों की कुल अर्जन का प्रतिशत १९५२ में २३.९ प्रतिशत से कम होकर १९६१ में २२.६ प्रतिशत रह गया। १९६१ का वर्ष बैंकों के लिए अपवाद रूप से समृद्धि का वर्ष था। इससे पहले तीन वर्षों में यह संख्या क्रमशः १९.१ प्रतिशत, १६.४ प्रतिशत और १४.३ प्रतिशत थी।

लाभ के अनुपात से कर अधिक

लाभ पर करों की कटौती बैकों के लिए सबसे अधिक कटौती है। १९५२ में ३.६ करोड़ रु० से चार गुना बढ़कर १९६१ में १४.४ करोड़ रु० तक पहुँच चुकी है। लाभ के अनुपात में कर ३० प्रतिशत से बढ़कर ४८ प्रतिशत हो गये हैं। इससे सरकार को सीधा लाभ पहुँचता है।

डिविडेंड की राशि २.५ करोड़ रु० से बढ़कर ४.६ करोड़ रु० हो गयी, पर कुल लाभ के अनुपात की दृष्टि से यह २१ प्रतिशत से १५ प्रतिशत रह गया है। लाभ के कर्मचारियों का हिस्सा (बोनस) अढ़ाई गुना बढ़कर १.३ करोड़ रु० से ३.३ करोड़ रु० हो गया है। संचित कोष के लिए निश्चित राशि ४॥ गुना अधिक हो गयी है, ८० लाख रु० की तुच्छ राशि से बढ़कर अब ३.५ करोड़ रु० तक पहुँच चुकी है और कुल लाभ के अनुपात में ६.६ प्रतिशत से बढ़कर ११.६ प्रतिशत तक। बैंक अपना अन्तः संचय कोष भी बना रहे हैं ताकि अप्रत्याशित और प्रतिकूल अवस्थाओं का मुकाबला किया जा सके, क्योंकि भारत सदृश द्रुतगति से विकासशील देश में ऐसी स्थिति का आना अनिवार्य होता है।

पिछड़े क्षेत्रों में शाखाएं

देश के न केवल वित्तीय विकास किन्तु सुरक्षा प्रयत्नों को भी दृष्टि में रखते हुए यह आवश्यक है कि अर्ध शहरी और पिछड़े क्षेत्र में बैंकों की अधिक शाखाएं खोली जाएं। रिजर्व बैंक की एक वर्ष पहले की एक सूचना के अनुसार १४०० ऐसे कस्बे हैं, जिनमें बैंक सुविधाओं का एकदम अभाव है। आज भी इन कस्बों की यही स्थिति है। इन स्थानों पर शाखाएं खोलने के लिए समस्त बैंकों का स्टेट बैंक को शामिल करते हुए सहयोग चाहिए।

१९५१ और १९६० के दशक में इम्पीरियल बैंक और बाद में उसके उत्तराधिकारी स्टेट बैंक ने २५००० से कम की आबादी वाले कस्बों में १४३ बढ़ाकर ५१९ शाखाएं अर्थात् २६३ वृद्धि की, जबकि बैंकों की कुल शाखाओं की वृद्धि १३० प्रतिशत हुई। इसी अवधि में, अन्य परिगणित बैंकों ने अपनी अर्ध शहरी शाखाओं को ६१७ से वृद्धि करके १०३१ तक पहुंचा दिया है, अर्थात् ७० प्रतिशत वृद्धि हुई है।

अन्य भारतीय बैंकों की स्टेट बैंक से तुलना करते समय, हमें यह बात भूलनी नहीं चाहिये कि स्टेट बैंक को

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१९५७ और १९६१ के बीच डेवलेपमेंट और इंटग्रेशन फंड से ८२ लाख रु० नयी शाखाओं का घाटा पूरा करने के लिए दिया गया परन्तु निजी बैंकों को इस प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल सकी ।*

*भारतीय बैंक एसोशियेशन के अध्यक्ष पद से दिये गये भाषण का सारांश ।

(पृष्ठ २२३ का शेष)

हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि बढ़ती हुई जन-संख्या भारत के आर्थिक विकास के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है । इसका मुकाबला उसी उत्साह और तैयारी के साथ होना चाहिए जैसे हम मलेरिया, हैजा, प्लेग का मुकाबला करने के लिए कहते हैं । इस में सफलता पा कर ही हम आर्थिक गतिरोध से बच सकते हैं । माल्थस की परिकल्पना, जब तभी असत्य सिद्ध हो सकती है जब हम जन संख्या की वृद्धि की अपेक्षा आर्थिक विकास की गति और अधिक तेज कर दें । यदि परिवार नियोजन सफल नहीं होता, और जन संख्या आज की ही ऊंची गति से बढ़ती जाती है, तो पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य —जनता के जीवन स्तर में-उन्नति- पूर्ण नहीं हो सकता ।

(पृष्ठ २२५ का शेष)

बनाए गए हैं । इसका अर्थ यह है कि योजना आयोग के सरकारी मंत्री मण्डल का अनुपात कम हो जाएगा । आज पंचवर्षीय योजनाओं की प्रगति में अनेक बाधाएं आ खड़ी हुई हैं । योजना आयोग कभी-कभी वस्तुस्थिति की उपेक्षा करने लगता है, तो कभी सरकारी अधिकारी उसके संचालन में पूर्ण सहयोग नहीं देते और योजना के कार्य और ध्येय दोनों के लक्ष्य अपूर्ण रह जाते हैं । डा० राव इस दिशा में क्या योगदान दे सकेंगे, यह एक दो वर्षों में स्पष्ट हो जायगा ।

नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड

जयपुर

सदा

राष्ट्र की समृद्धि और सद्भावना

के लिए उपस्थित है

क्योंकि

प्रिसीशिन बाल और रोलर बियरिंग,

स्टील बाल्स, स्पिंडल इन्सर्ट्स,

और

रेलवे की वेगन और लोको के लिए

यह एक्सल बाक्सों का एक मात्र

निर्माता है ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत में अलोह धातु-उद्योग

• अलोह धातुओं में तांबा, जस्ता, अलमुनियम, सीसा, टिन, मैग्नीशियम, निकल और ऐन्टीमनी विशेष महत्वपूर्ण हैं। इन धातुओं के हमारे अभी तक ज्ञात भंडार बाक्साइट, मैग्नेसाइट, इल्मेनाइट और मैंगनीज को छोड़ कर, अपेक्षाकृत अल्प हैं। योजना के अनुसार देश में अलोह धातुओं को तैयार करने का काम पूरे तौर से गैर-सरकारी उद्योगों के हाथ में रहा है।

प्रमुख अलोह धातुओं का उत्पादन और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में उनकी अनुमानित आवश्यकतायें निम्नलिखित हैं :

कुछ प्रमुख अलौह धातुओं का उत्पादन और अनुमानित आवश्यकता (टनों में)

धातु	उत्पादन (१९६०)	अनुमानित आवश्यकता (१९६५-६६)
अलमुनियम	१८,२५५	११५०००
तांबा	८,९१०	१४५०००
जस्त	—	१८५०००
सीसा	३,७४५	५९०००
टिन	नहीं	१०५००
ऐन्टीमनी	८१२	१०००
मेग्नीशियम	नहीं	३००

अलमुनियम को छोड़ कर सब धातुओं के ज्ञात अयस्क स्रोत बहुत कम हैं और उन्हें अधिकतर बाहर से मंगाना पड़ता है। प्रस्ताव है कि केवल धातुओं को ही बाहर से मंगाया जाये और ऐसी व्यवस्था की जाये कि पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सब प्रकार के अर्धनिर्मित सामान देश में ही तैयार किये जाने लगें।

अलमुनियम—यह पृथ्वी की पपड़ी में बहुतायत से उपस्थित खनिजों में पाया जाता है। इस प्रकार यह निश्चय ही बहुत दिनों तक मिलता रहेगा। इसके गुण व धर्म बहुत उपयोगी हैं। इसकी विद्युत और ऊष्मा संवाहकता ऊंची है और परावर्तकता भी अधिक है। इस लिए इसने बहुत से विद्युत उपयोगों में, विशेषतया हमारे जैसे उन देशों में जहां बिजली उद्योग के लिए आवश्यक तांबा काफी मात्रा में प्राप्य नहीं है, तांबे का स्थान ले लिया है। अलमुनियम की कुछ मिश्र धातुयें मृदु इस्पातों से भी अधिक मजबूत होती हैं, साथ ही हल्की होती है। इसलिए वह बहुत-सी पुरानी वस्तुओं के स्थान पर इस्तेमाल किया जाने लगा है। अलमुनियम की स्वीकार्यता का अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि संसार में इसका उत्पादन जो १९०५ में केवल १२,००० टन था, बढ़ कर १९५८ में ३८.१ लाख टन पहुँच गया है। इस में से संयुक्त-राज्य अमरीका का भाग १५६६; कनाडा का ६२८; रूस का ५५०; जापान का ९४; चीन का ३३; और भारत का ८ हजार टन है।

भारत में अलमुनियम के अयस्क, बाक्साइट का कुल भंडार २५ करोड़ टन से अधिक है। इनमें से आधा उच्च श्रेणी का और अलमुनियम निकालने के योग्य समझा जाता है। आजकल भारत में ६० प्रतिशत बाक्साइट गुजरात में निकाला जाता है। दूसरे विशाल क्षेत्र बिहार, मध्यप्रदेश, मैसूर और मद्रास में हैं। पिछले दिनों में भारत में अलमुनियम का उत्पादन बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि यहां बिजली अब अधिक मिलने लगी है। बिजली अलमुनियम धातु के निकलने के प्रक्रम में एक अनिवार्य साधन है। गोहाटी और बरौनी में नये पैट्रोलियम शोधन कर कारखानों के बनने से वह कोक भी जो अभी इस उद्योग के उपयोग के लिए बाहर से मंगाया जाता है, देश में ही प्राप्त होने लगेगा। अलमुनियम उद्योग के लिए क्रायोलाइट और फ्लोर-स्पार भी बाहर से मंगाये जाते हैं।

तांबा—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने १९४८ के लिए जो अंक प्रकाशित किये हैं उनके अनुसार उस वर्ष पीतल के घरेलू बर्तन ६,३२५ टन और दूसरा सामान १,८४५ टन बनाया गया। तांबे के बर्तन १३४ टन बनाये गये थे और दूसरे किसी सामान को बनाने में तांबे का उल्लेखनीय उपयोग नहीं किया गया था। अलौह अर्धनिर्मितों का उद्योग पिछले दस वर्षों में विकसित हुआ है और अब तांबे का सबसे अधिक उपयोग पीतल उद्योग में

(शेष पृष्ठ २४५ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कम्यूनिस्ट क्रान्ति का शिकार—चीनी किसान

जी० एम० एस० राधवा

आरम्भ में जब चीनी कम्युनिस्ट अपने देश की राजनीति में सक्रिय हुए और उन्होंने कुमिनतांग सरकार से सत्ता छीनने में जो संघर्ष किया, उससे लगता था कि चीनी कम्युनिस्ट किसानों का उद्धार करेंगे। ऐसा लगता था कि चीनी साम्यवाद ग्राम-सुधार और न्याय पर आधारित होगा और सर्वहारा वर्ग के नाम पर तानाशाही कायम नहीं की जाएगी।

चीन के गृहयुद्ध के समय जो क्षेत्र कम्युनिस्ट फौजों के अधिकार में थे, वहां पर जमींदारों से जमीन छीनकर भूमिहीन किसानों को दी गई। लेकिन उस समय जमीन को सरकारी नियंत्रण में लेने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि सहकारिता के आधार पर खेती करने को बढ़ावा दिया गया। १९४३ में स्वयं माओ त्से तुंग ने कहा था कि हमारे भूमि-सुधारों का अभिप्राय यह नहीं है कि उपज पर सरकार का अधिकार हो। उस पर किसानों का ही अधिकार होना चाहिए। पर, यह बीस साल पहले की बात है। दस साल पहले यानी चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना के कुछ साल बाद तक भी भूमि पर किसानों का ही अधिकार था। १९४९ और १९५२ के बीच बहुत बड़े पैमाने पर भूमि-वितरण कार्यक्रम चलाया गया। लगभग ४० लाख जमींदारों से जमीन छीनकर ४-५ करोड़ गरीब किसान परिवारों को यह जमीन दी गई। किसानों को जो जमीन मिली, वह थोड़ी थी, लेकिन भूमिहीन किसान के लिए जमीन का छोटा-सा टुकड़ा भी अत्यधिक मूल्यवान होता है और इसी कारण चीन के किसान अपनी नई सरकार के प्रति आभारी थे। पर चीन के सीधे-सादे किसान यह नहीं जानते थे कि यह सब धोखा है। साम्यवादी शासन के प्रति उनके मनमें वफादारी पैदा करने के लिए ही यह जाल बिछाया जा रहा है और अन्त में जमीन उनसे भी छीन ली जाएगी।

१९५३ में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति ने सहकारी खेती का कार्यक्रम लागू करने का निश्चय किया। आरम्भ में जो किसान इन सहकारियों के सदस्य बने, उनकी भूमि पर उनका स्वामित्व रहने दिया गया। किसानों ने सहकारी समितियों को जो भूमि दी उसकी उपज के अपने हिस्से के अलावा उन्हें खेतों में काम की मजूरी भी दी गई। पर जल्दी ही इसे समाप्त कर दिया गया और सामूहिक फार्म बनाये गये। इन फार्मों की उपज का हिस्सा किसानों को मिलना बन्द हो गया और वे फिर भूमिहीन खेतिहर मजदूर ही रह गये।

चीन के कम्युनिस्ट शासकों का दावा है कि किसानों ने स्वेच्छा से अपनी जमीन सामूहिक फार्मों को दी। पर सचाई कुछ और ही है। किसानों पर अपनी जमीन सामूहिक फार्मों को देने के लिए बहुत दबाव डाला गया। सरकार की तरफ से ऋण, खाद, और अन्य सुविधाएं उन्हीं किसानों को मिलती थीं, जो अपनी जमीन सामूहिक खेती को देते थे। इसके अलावा जो किसान इसमें शामिल नहीं हुए, उन पर अधिक कर लगाया गया और अन्त में आतंक और दबाव के द्वारा उन्हें अपनी ज़मीन सामूहिक खेतों को देने के लिए बाध्य किया गया।

चीन के कम्युनिस्ट शासक यह जानते थे कि जब तक जमीन किसानों के अधिकार में रहेगी, वे तेजी से औद्योगीकरण का अपना कार्यक्रम कभी भी पूरा नहीं कर सकेंगे। उन्हें किसान को अधिक अनाज उपजाने के लिए ही बाध्य नहीं करता था, बल्कि उस पूरी उपज को अपने अधिकार में लेना था, चाहे किसान को भूखा ही क्यों न मरना पड़े।

चीन के औद्योगीकरण का पहला शिकार वहां का किसान हुआ। सामूहिक खेतों में किसानों से कम मजूरी पर कमरतोड़ काम कराया गया। जिस तरह कारखानों में काम के हिसाब से मजूरी दी जाती है, उसी तरह किसानों को भी मजूरी दी गई।

१९५८ में कम्यूनों की स्थापना से चीन के सामूहिकीकरण कार्यक्रम ने एक नई दिशा ली। एक-एक कम्यून में सौ सामूहिक खेत रखे गए। इन्हें खेती के अलावा औद्योगिक उत्पादन का काम भी सौंपा गया। कम्यून केन्द्र

(शेष पृष्ठ २३४ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत के जहाजरानी उद्योग में नया साहस

श्री धर्म यशदेव

पश्चिम में जब ईसाइयत का आविर्भाव हुआ, उससे बहुत पहले भारत में नौका-निर्माण का विज्ञान काफी विकसित हो चुका था और यूरोपीय राष्ट्रों की एक समुद्री ताकत बनने से बहुत पहले ही भारतीय जहाज अफ्रीका, मिस्र, यूरोप, मलाया, सुमात्रा, जावा, बाली और अन्य दूर के देशों के साथ व्यापार करते हुए बड़े समुद्रों का चक्कर लगाया करते थे।

प्राचीन तथा मध्ययुगीन भारत में जहाज बनाने की कला बहुत विकसित थी। ११वीं सदी में लिखी गई "युक्ति कल्पतरु" में भारत में बने २७ किस्म के जहाजों का विवरण दिया गया है। उनमें सबसे बड़ा २७६ फुट लम्बा, ३६ फुट चौड़ा तथा २७ फुट गहरा था। आधुनिक मायनों में इसका मतलब है—२,३०० टन डेड वेट का जहाज। १३वीं सदी में मार्कोपोलो ने भारतीय जहाजों को अपने साथ छोटी-छोटी नावें ले जाते हुए भी देखा जो जहाज के दोनों ओर बंधी लटकी रहती थीं। जरूरत पड़ने पर उन्हें समुद्र में उतारा जा सकता था।

लो के अनुसार १८१६ तक भी "बम्बई में बने जहाज 'सेलसटूर्ट' फ्रिगेट के फर्स्ट लेफ्टिनेंट ने उसके निर्माता जमशेद जी बोअन जी को लिखे एक पत्र में लिखा है कि "५ अन्य युद्धपोतों तथा १२ व्यापारिक जहाजों के साथ सेलसटूर्ट जहाज बाल्टिक सागर की बर्फ में फंस गया। इसमें से सिर्फ सैलसट्टे ही टूटने से बचा और उसी की बदौलत सबकी जान भी बच गई।"

ब्रिटिश काल के प्रतिबन्धात्मक कानूनों की वजह से भी हमारे उद्योग को क्षति पहुँची और प्रथम विश्वयुद्ध तक इसके पुनर्जीवन के सब प्रयत्नों पर पानी उंडेला जाता रहा। फलस्वरूप समुद्र पर से भारतीय जहाजों का लोप हो गया।

स्वाधीनता के बाद राष्ट्रीय सरकार ने भारतीय जहाजरानी का तेजी से विकास करने की नीति ही बनाली।

इस नीति को प्रारम्भ करने तथा युद्धोत्तर पुनर्निर्माण की आम हलचलों के कारण कई नई जहाज कम्पनियां बनीं, जिसमें इण्डियन स्टीमशिप कम्पनी, भारत लाइन और ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग भी शामिल थीं। साथ ही पुरानी कम्पनियों की गतिविधि भी बढ़ी। उदाहरणार्थ, सिन्धिया स्टीमशिप कम्पनी ने कई नये जहाज प्राप्त किए और ब्रिटेन तथा अमरीका के साथ व्यापार में भाग लेना शुरू कर दिया। बम्बई स्टीम तथा मलाबार ने भी तटीय व्यापार के लिए अतिरिक्त जहाज प्राप्त किए।

युद्ध से पहले के वर्षों में तटीय व्यापार में भारतीय जहाजों का हिस्सा जहां सिर्फ ३३॥ प्रतिशत था, वहां सारा व्यापार उन्हीं के हाथ में है। और जहां पहले भारतीय जहाज भारत, बर्मा और लंका के तट से बाहर नहीं जाते थे, वहां अब वे कई महत्वपूर्ण समुद्रपारीय मार्गों पर व्यापार के लिए जाते हैं। जैसे—भारत, ब्रिटेन, यूरोप, भारत-आस्ट्रेलिया और भारत-दूरपूर्व, जापान। हाल के वर्षों में भारतीय जहाजों की आय भी बढ़ी है।

पहली योजना

पहली योजना के शुरू में अर्थात् १९५०-५१ में भारत के पास ३.९१ लाख जी. आर. टी. के जहाज थे, जिनमें से २.१७ लाख जी. आर. टी. तटीय व्यापार में और १.७४ लाख जी. आर. टी. समुद्रपारीय व्यापार में लगे थे। पहली योजना में २.१५ लाख जी. आर. टी. की वृद्धि के लिए व्यवस्था की गई थी जिसमें से १.०५ लाख जी. आर. टी. तटीय व्यापार के लिए तथा १.१ लाख जी. आर. टी. समुद्रपारीय व्यापार के लिए थी। कुल लक्ष्य ६ लाख जी. आर. टी. प्राप्त करने का था। इसके मुकाबले पूर्ति सिर्फ ४.८ लाख जी. आर. टी. की हुई।

दूसरी योजना में अधिक जहाज प्राप्त करने के लिये मूलतः ४६ करोड़ रुपये दिए गए थे। बाद में यह रकम बढ़ाकर ५४.५ करोड़ रुपये कर दी गई। योजना में वास्तविक खर्च ५४.६ करोड़ रुपया हुआ। भौतिक लक्ष्यों की

(शेष पृष्ठ २४६ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भूदान का द्वादश वर्षीय युग

भूदान : एक क्रांतिकारी आंदोलन

जो भी जमीन-सुधार के काम अब तक तय हुए हैं, उससे कोई भी पूरे सन्तुष्ट नहीं हैं। कृषिकारों की हालत में जरूर कुछ फरक पड़ा है, लेकिन कृषि की समस्याएं करीब-करीब वैसी ही रही हैं। भारत जैसे मुल्क में किसी क्षेत्र में तबदीली लाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हमारा मार्ग अगर साफ न हो तो समस्याएं और भी विकट बन सकती हैं। और जहां तक मेरी राय है, वहां तक आज तक हमारी जमीन की समस्याओं का कोई भी साफ इलाज हमारे हाथ में नहीं आया है। नतीजा यह पैदा हुआ है कि हमारे देश के किसानों में से करीब ५५ से ६० फीसदी किसान पांच एकड़ से कम जमीन का टुकड़ा बोते हैं। इससे न तो जमीन की औसत एकड़ पैदावार बढ़ती है और न किसानों की हालत में कोई बुनियादी फरक हो सकता है। जहां तक मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि ऊपरी इलाजों से इस जमीन का प्रश्न कभी भी हल नहीं हो सकेगा, न कृषि की तरक्की जितने पैमाने पर हम चाहते हैं, उतने पैमाने पर हो सकेगी; और कृषिप्रधान इस मुल्क को हर साल अपना सिर विदेशों के सामने अन्न के लिए झुकाना पड़ेगा।

सारी हालतों को देखते हुए श्री विनोबा जी ने 'ग्रामदान' और 'भूदान' का एक क्रान्तिकारी इलाज दिखाया है। —उ० न० ढेबर

'एक महत्वपूर्ण सफलता'

आचार्य विनोबा भावे सर्वथा स्वेच्छया तथा अहिंसात्मक आन्दोलन द्वारा भूमि विहीनों में १० लाख एकड़ भूमि वितरित करने में सफल हुए हैं; यह कोई कम सफलता नहीं है।

सरकार को सभी राज्यों में भूमि कानून लागू करने के बावजूद यह आशा नहीं है कि वे सभी क्षेत्रों में जोत की भूमि की सीमा निर्धारित करने के बाद १० लाख एकड़ भूमि एकत्र कर भी सकेगी। —श्री मन्नारायण

भूदान यज्ञ के १२ वर्ष

भूदान नेता आचार्य विनोबा भावे ने अपने भू[illegible] आन्दोलन के १२ वर्ष समाप्त कर लिए। १२ वर्ष [illegible] जबकि वह तेलंगाना की महत्वपूर्ण यात्रा कर रहे थे, [illegible] पच्चमपाली में भूमि का प्रथम दान मिला। उसके [illegible] उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों में नियमित आन्दो[illegible] शुरू कर दिया और गांव-गांव पैदल जा कर भूदान प्रा[illegible] किया।

गत १२ वर्षों के दौरान में विनोबा जी को ४३ [illegible] एकड़ भूमि तथा ५५०० गांव दान में मिले। इनमें [illegible] १० लाख एकड़ भूमि भूमिविहीन लोगों में बांटी [illegible] चुकी है।

भूदान यज्ञ के विशेषांक से ज्ञात होता है कि फर[illegible] १९६३ तक देश में कुल १,४५,१२३ रु० का सम्पत्ति[illegible] भी हुआ है। इस अवधि तक सर्वोदय पात्र से [illegible] २२७४९ रु० प्राप्त हुये हैं। सूत्रदान १०६४८ रु० [illegible] हुआ है।

ग्राम निर्माण में खादी का स्थान

१९६१-६२ में खादी और ग्रामोद्योग कमीशन द्[illegible] खादी और ग्राम विकास के लिए दी गयी सहायता १९[illegible] ६१ में २०.९८ करोड़ रु. से बढ़कर २५.४० करोड़ [illegible] तक दी गयी। इसी अवधि में खादी प्रतिष्ठानों की [illegible] बढ़कर १,४०२ हो, गयी जिनमें से ८६६ रजिस्टर्ड प्रति[illegible] थे और ५३६ सहकारी थे जबकि पिछले वर्ष में [illegible] क्रमशः ७२० और ४१९ थे। चालू वर्ष में खादी [illegible] उत्पादन और बिक्री में सराहनीय प्रगति हुई है। वि[illegible] प्रकार की खादी का कुल उत्पादन १९६०-६१ में ६ [illegible] ४७.८ लाख वर्गगज जिसका मूल्य १४.२३ करोड़ था [illegible] बढ़कर १९६१-६२ में ७ करोड़ ४१.६ लाख वर्ग गज [illegible] मूल्य १७.३७ करोड़ रु. का हुआ। बिक्री में भी [illegible] प्रकार वृद्धि हुई। १९६०-६१ में १४.०७ करोड़ [illegible] बढ़कर १९६१-१९६२ में १९ करोड़ रु. तक हुई। [illegible] वर्ष में इस उद्योग ने १७.३६ लाख व्यक्तियों को रो[illegible] दिया।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

धूम्रपान और राष्ट्रीय आय व स्वास्थ्य

सरदारमल जैन

अपनी अज्ञानता के वशीभूत हो विश्व के अधिकांश प्राणी अमीर-गरीब, बालक-वृद्ध, स्त्री-पुरुष सभी तम्बाकू के विष का सेवन करते हैं। बीड़ी, सिगरेट, सुरती, सूंघनी आदि तम्बाकू के ही अनेक रूप हैं। धूम्रपान इस युग का आधुनिकतम फैशन बन गया है। एक साधारण कुली से या किसान से लेकर बड़े से बड़ा बुद्धिजीवी-नेता, सेठ, अफसर सभी धूम्रपान के गुलाम बने हुए है। यह बुराई दिनों दिन अधिकाधिक लोगों के दिलों में अपना घर बनाती जा रही है।

तम्बाकू के उत्पादन में अमेरिका और चीन के बाद भारत का ही स्थान है। आजकल वर्ष में लगभग ७८ करोड़ पौंड तम्बाकू पैदा होता है, जिसमें से ८०% से अधिक बीड़ी, सिगरेट, हुक्के आदि के रूप में भारत में ही खप जाता है। शेष के निर्यात से देश को १५ करोड़ रु० वार्षिक की विदेशी मुद्रा मिलती है। भारत का यह तम्बाकू विश्व के लगभग ५० देशों को जाता है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले ९ वर्षों में सिगरेटों का उत्पादन दुगने से भी ज्यादा हो गया है। जहां १९६१ में ४१ अरब सिगरेटें बनीं वहां १९५२-५३ में १८ अरब सिगरेटें बनी थी। जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है—

वर्ष	सिगरेटें (लाखों में)
१९५५	२२८२८८
१९५६	२६३०३३
१९५७	२८८९२४
१९५८	२९८४०४
१९५९	३२१६६०
१९६०	३९९७०८
१९६१	४१०६४०

सरकार को इस उद्योग से करों के रूप में प्रतिवर्ष लगभग ५१ करोड़ रु० की आय होती है।

धूम्रपान के दुष्परिणाम

कौन नहीं जानता कि तम्बाकू का प्रयोग हमारे लिए हर दृष्टि से हानिकारक है। तम्बाकू के खाने-पीने से नाक के भीतर की चमड़ी खराब हो जाती है और गला बिगड़ जाता है। जैसे रसोई घर धुएं से काला हो जाता है वैसे ही नाक, गला, सीने के भीतर के पोले भाग, स्वर तथा अन्न की नलिका आदि धूम्रपान से काले पड़ जाते हैं और फिर धीरे २ सारे शरीर में विष फैल जाता है।

आस्ट्रेलिया की वायुसेना के निर्देशालय की राय है कि २० या अधिक सिगरेट नित्य पीने से आंखों की ज्योति कम हो जाती है। प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि सिगरेट पीने से उसका धुंआ रक्त की नालियों में मिल जाता है, जिसके परिणामस्वरूप रक्त में आक्सीजन लेने की की क्षमता कम हो जाती है और फिर धीरे-धीरे आंखों की रोशनी में २० प्रतिशत तक की कमी हो जाती है।

टाटा मेमोरियल अस्पताल, बम्बई के डाक्टरों और विशेषज्ञों ने फेफड़ों के कैंसर के १४६० मरीजों के अध्ययन विश्लेषण से निष्कर्ष निकाला है कि फेफड़े के कैंसर का मुख्य कारण धूम्रपान है। धूम्रपान से खाने की नली में कैंसर हो जाता है। महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, गुजरात और आन्ध्रप्रदेश के ३४ हजार व्यक्तियों पर किये गये प्रयोगों से पता चला है कि धूम्रपान करने वाले और तम्बाकू खाने वाले लोगों में कैंसर के कीटाणु अपेक्षाकृत अधिक थे। मैडिकल रिसर्च कौंसिल आफ ब्रिटेन की एक खोज रिपोर्ट में भी कहा गया है कि अनेक देशों के अनेक व्यक्तियों पर किये गये प्रयोगों से पता चला है कि दुनियां में कैंसर के मरीजों अधिक संख्या सिगरेट पीने वालों की ही होती है। अमेरिकन कैंसर रिसर्च सोसाइटी का भी यही मत है। डाक्टरों का मत है कि तम्बाकू खाने व पीने से मुंह में भी कैंसर हो जाता है और यह रोग इतना भयंकर होता है कि इसका अभी तक कोई इलाज नहीं निकाला है।

सरकारी सहयोग आवश्यक

इस सार्वजनिक बुराई को दूर करने में राष्ट्रीय सरकार का सहयोग भी नितान्त आवश्यक है। आदत को छुड़ाने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के लिए धूम्रपान कानूनन वर्जित हो जाना चाहिए। लेकिन दुःख है कि हमारी अर्थ लोलुप अर्थ व्यवस्था उन सब हानियों की तरफ ध्यान नहीं देती और सरकार भी तम्बाखू और सिगरेट उद्योग से करों के रूप में और निर्यात व्यापार के रूप में होने वाली आय के कारण इस विषैले दुर्व्यसन को रोकने की बजाय निरन्तर प्रोत्साहित कर रही है।

सरकार को इस उद्योग से पर्याप्त आर्थिक लाभ होता है और इस बेरोजगारी के जमाने में कुछ लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या यह लाभ उस हानि से बड़ा है जो कि धूम्रपान करने से देश के करोड़ लोगों का स्वास्थ्य चौपट कर रही है। आज अर्थ शास्त्र की दृष्टि में सब कार्यों का मानदंड केवल रुपया रह गया है किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मानव जीवन का हित रुपये से भी अधिक मूल्यवान है। इस मूल तथ्य की उपेक्षा के कारण ही राष्ट्रपिता बापू वर्तमान अर्थ शास्त्र को अनर्थ शास्त्र कहते थे। समाज कल्याण की योजनाओं में यहां हम बिना आय की अपेक्षा किए करोड़ों रु० व्यय कर देते हैं, वहां तम्बाकू के प्रयोग से होने वाली राशि को कम नहीं कर सकते, तो उसे बढ़ने तो नहीं देना चाहिए, भलेही कुछ आर्थिक हानि ही सहन करनी पड़े। फिर अभी तो हमारे सामने तम्बाकू से भी ज्यादा महत्वपूर्ण समस्या खाद्य-सामग्री की है। क्यों न हम तम्बाकू का नियंत्रण करके अन्न उत्पादन को अधिक प्रोत्साहित दे ताकि हमारा देश अधिक खुशहाल हो।

खादी व ग्रामोद्योगों का महत्त्व

खादी और ग्रामोद्योगों को सिर्फ लोगों के दिलों से इस भ्रम को दूर ही नहीं करना है कि देश के आर्थिक निर्माण में खादी और ग्रामोद्योगों की महत्ता कम है, बल्कि उन्हें यह भी बता देना है कि देश के जीवन में पवित्रता, निर्भयता और आत्म-निर्भरता के अतिरिक्त सहिष्णुता, सहयोगिता और समादर की भावनाएं भरने की क्षमता भी उसमें है।

एक अनुमान के आधार पर हमारे देश के १० करोड़ घरों में से लगभग ३ करोड़ घर ऐसे हैं जिनकी पारिवारिक आय सालाना ६०० रुपये से कम है। इन तीन करोड़ में से एक करोड़ घर तो तो ऐसे हैं जिनकी सालाना आय ३००-४०० रुपये के ऊपर-नीचे हैं। उनकी शोचनीय अवस्था की कल्पना करना मुश्किल है—शायद, आज की दुनिया में इस तरह के कम ही परिवार और जगह रहते हैं। इन लोगों की आबादी यूरोप के कुछ देशों की आबादी के बराबर हो सकती है। खादी का संदेश इस आबादी के लगभग ५वें हिस्से तक ही अब तक पहुँच सका है। बाकी लोगों तक संदेश पहुँचाने का काम हमें करना है।

क्रांति का शिकार किसान

(पृष्ठ २३० का शेष)

आर्थिक टुकड़िया ही नहीं, बल्कि सैनिक टुकड़ियां भी बनीं। जिन दिनों खेतों में अधिक लाभ न होता, कम्यून के सदस्यों से सिंचाई के लिए नहरें आदि बनाने में जबरदस्ती काम लिया जाता। इसके अलावा कम्यूनों को थोड़ा लोहा और इस्पात तैयार करने का काम भी सौंपा गया। अन्त में कम्यूनों को अपनी सैनिक टुकड़ियां तैयार करने और उन्हें ट्रेनिंग देने का काम भी सौंपा गया। इन्हीं सैनिक टुकड़ियों के बल पर ही १९५८ में चीन के कम्युनिस्ट शासकों ने घोषणा की कि उनकी बड़ी नियमित सेना के अलावा ३ करोड़ की जनसेना भी है।

यह कहना व्यर्थ ही है कि किसान स्वेच्छा से कम्यून नहीं छोड़ सकता, चाहे उसे यह कितना भी नापसन्द क्यों न हो। देश के भीतर ही यात्रा और कुछ दिन किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है। यही चीनी किसान की कहानी है, जिसे कम्युनिस्टों ने पहले भूमि सुधार और सहायता के कार्यक्रमों से अपनी ओर खींचा और अन्त में सत्ता हाथ में आ जाने पर उसे फिर भूमिहीन खेतीहर मजदूर बना दिया। वस्तुतः वह चीन की क्रांति के जाल में फंसकर उसका शिकार बना है।

—(आकाशवाणी के सौजन्य से)

—

सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उत्तरप्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र तथा ग्रामोद्योग

श्री दीनानाथ दुबे

देश पर चीनी हमला होने से सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रामोद्योगों का विकास करना बहुत आवश्यक हो गया है। जनता की उसकी गुजरबसर भर करने जैसी स्थिति से ऊपर उठाने हेतु इन उद्योगों के लिए एक ऐसे व्यापक, विशाल कार्यक्रम की नितांत आवश्यकता है, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्ची सामग्री पर आधारित हो और कार्यक्रम उस रूप में मोड़ा जाय कि वह जनता में अपनी विकास योजनाओं के प्रति लोक रुचि जागृत करे। सीमावर्ती क्षेत्रों में ऊनी-खादी उद्योग तथा अन्य अनेक ग्रामोद्योग बड़ी आसानी से लाभदायक रूप में विकसित किये जा सकते हैं।

चीन के नृशंस आक्रमण को देखते हुए कांगड़ा और कूलू घाटी से लेकर अल्मोड़ा तक के भूभाग को एक नया महत्व प्राप्त हो गया है। यहां की जनसंख्या विरल है, लोगों में ऊन कताई और बुनाई के कला कौशल की परम्परा चली आयी है। इसके अतिरिक्त ग्रामोद्योगों के काम में आने वाली कच्ची सामग्री की प्रचुरता है।

स्थानीय आबादी

चीनियों ने हमारे देश के जिस भूभाग पर अपना अनाधिकार दावा किया है, उसमें उत्तर प्रदेश का बाराहोती आदि भूभाग आता है। चीन ने अपने ताजा युद्ध विराम में भारतीय सैनिकों की २० कीलोमीटर वापसी की जो शर्त लगायी है उसके अनुसार माणा, नीति, बाराहोती, लीपूलेक आदि स्थानों से हमें हट जाना होगा। ये सब क्षेत्र मैदानी अंचलों से काफी दूर है और मौजूदा समय यातायात के सभी साधन (वायु-पत्र को छोड़कर) काफी देर में वहां पहुँचते हैं। सभी पर्वतीय क्षेत्र जिसमें उत्तर काशी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, आदि पर्वतीय जिले हैं, अभावों और समस्याओं के क्षेत्र हैं। यहां के निवासियों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त विपन्न है। अधिकांश निवासी या तो फौज में भरती होते हैं अथवा छोटी-छोटी नालियों में खेती कर अपना जीवन यापन करते हैं। तिब्बत पर चीन का अधिकार हो जाने और चीन की वर्तमान नीति से इस क्षेत्र के लिए लम्बे समय तक के लिए एक संकट पैदा हो गया है।

इस स्थिति का जो पहला प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है, वह यहां के भोटिया व्यापारियों और ऊनी खादी उद्योग पर है। इस तथ्य पर जाने के पहले यह जान लेना अत्यन्त समीचीन होगा कि पूरा पर्वतीय प्रदेश ७ जिलों में विभक्त है जिसे हम कूमायूं और उत्तराखण्ड के भूभाग के नाम से जानते हैं। इसका बहुत कम भाग शहरों में रहता है।

धन्धे

पर्वतीय क्षेत्र और उग्र शीत पड़ने के कारण भेड़ पालन और उसके ऊन से कपड़ा बुनना यहां का परम्परागत व्यवसाय रहा है। भोटिया इसमें विशेष रूप से लगे हैं। इनका व्यापार पहले तिब्बत में होता था किन्तु अब यह असम्भव हो गया है। हस्तनिर्मित खड्डियों और तकुओं के माध्यम से इस क्षेत्र में कताई-बुनाई होती है। कताई का काम अधिकतर पुरुष और बुनाई का काम महिलायें करती है। जोहार दारमा (अल्मोड़ा), माणा, नीति (चमोली), हरसिल मटवाड़ी (उत्तरकाशी) स्थानों में कताई-बुनाई मुख्य कार्य है। भोटिया स्त्रियां थुलमा, गुदमा, पंखी, पट्टू, कम्बल गलीचा आदि बनाती हैं। मिलिंग, फिनिशिंग आदि सभी काम इन्हीं के द्वारा होता है।

अभी तक इन सब के लिए कच्चा माल (तिब्बती ऊन) तिब्बत से प्राप्त होता था, किन्तु मौजूदा स्थिति में उसका आना बन्द हो गया है। अतः जो भी ऊनी खादी कार्य इस क्षेत्र में चल रहा है उसके लिए कच्चा माल न मिलने के कारण एक विशेष कठिनाई आ गयी है। यों तो उसकी कमी दूर करने का सरकारी स्तर पर विशेष प्रयास किया जा रहा है, किन्तु कच्चे माल की समस्या केवल इसी वर्ग के लिए नहीं, वरन् हमेशा के लिये पैदा हो गयी है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बड़े उद्योगों को खड़ा करने में काफी समय लगेगा, जबकि आवश्यकता तात्कालिक है। तात्कालिक हल खादी, ग्रामोद्योग के माध्यम से ही सम्भव है।

खादी और ग्रामोद्योग—

सौभाग्य की बात है कि इस क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योग के काम के प्रसार के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। प्रचुर मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है। यदि व्यवस्थित आधार, कुशल कार्य-क्षमता और नेतृत्व में इन उद्योगों का विकास किया जाय तो ये उद्योग सिर्फ स्थानीय आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं करेंगे वरन् मैदान में भी अपने उत्पादन को सरलता से भेज सकेंगे। खादी ग्रामोद्योग के क्षेत्र में चालू प्रवृत्तियों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

स्थानीय वस्त्र की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्त्र स्वावलम्बन की तरफ विशेष ध्यान अभी तक नहीं दिया गया है। यदि स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति वस्त्र स्वावलम्बन के आधार पर की जाय तो क्षेत्रीय निवासियों की वस्त्र सम्बन्धी जरूरतें पूरी हो सकती हैं और एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है।

तालिका

जिला	खादी उत्पत्ति केन्द्र	खादी बिक्री केन्द्र और प्रशिक्षण केन्द्र	ग्रामोद्योग सहकारी समितियां	ग्राम इकाइयां
उत्तर काशी	९	४	—	१
चमोली	२६	११	—	१
पिथौरागढ़	१५	५	७	१
टेहरी गढ़वाल	१०	५	३	१
पौड़ी गढ़वाल	१२	५	५	३
अल्मोड़ा	४०	३१	१९	—

आमदनी

वर्तमान समय में इस क्षेत्र में सड़क निर्माण आदि का कार्य तेजी से चल रहा है। स्थानीय निवासियों को उसमें रोज ५-६ रुपये मिल जाते हैं। अतः कन्तिनों या बुनकरों को ऊनी खादी उद्योग में अधिक से अधिक पारिश्रमिक मिलना चाहिए अन्यथा वे अन्य कामों की ओर आकर्षित हो जायेंगे, भले ही उनका यह काम अस्थाई हो। कताई के साथ-साथ बुनाई का कार्य गांव-गांव तक बढ़ाने की आवश्यकता है। ऊनी खादी के अतिरिक्त ग्रामोद्योगों का प्रसार अत्यन्त आवश्यक है। फिलहाल इस क्षेत्र में लुहारी तथा बढ़ईगीरी, रेशा, चर्मोद्योग, मधुमक्खी-पालन, हाथ धान कुटाई तथा आटा चक्की, हाथ कागज, कुछीर चूना उत्पादन, तेलघानी तथा ताड़गुड़ उद्योगों के प्रसार की काफी सम्भावना है। इन उद्योगों की गतिविधि पर भविष्य में प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा।

आर्थिक समीक्षा

प्रधान सम्पादक : श्री सादिक अली

सम्पादक : श्री महेन्द्र मेहरा

- हिन्दी में अनूठा प्रयास
- आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख
- आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत

भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक।

वार्षिक मूल्य : ५ रु० एक प्रति २२ नये पैसे

लिखें—व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, नई दिल्ली।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

महिलाएं और गृह उद्योग

श्री पी० सी० सेखड़ी

● किसी देश का सफलतापूर्वक विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक महिलाएं उसमें सक्रिय भाग न लें। औद्योगिक विकास में महिलाओं की विशेष स्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। आर्थिक तंगी के कारण घुटन शील जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा नारी अपने परिवार की आर्थिक चिन्ताओं को हल्का कर सकती है, अगर वह अपने खाली समय का उपयोग सामान्य चीजों के उत्पादन में लगाये। यह पूछा जा सकता है कि कारखाने की बनी चीजों के मुकाबले में इन घरेलू उत्पादनों की बिक्री का क्या अवसर हो सकता है ? पर यह आशंका व्यर्थ है। घर की बनी चीजों की किस्म अच्छी होती है और कीमत भी मुनासिब होती है। घरेलू चीज बनाने में कारखानों की तुलना में एक बड़ा लाभ यह है कि इनके लिए अच्छे सामान का प्रयोग किया जा सकता है। अचार चटनी इत्यादि जो बाजार में बिकती हैं, काफी महंगी होती है और उनकी किस्म भी खास अच्छी नहीं होती है। फिर, हमारे देश में अभी टीन के डिब्बों में बन्द खाद्य-सामग्री को खरीदने का रिवाज नहीं है। अनुभव और विज्ञापन की कमी के कारण, संभवतः, सफलता पहले न मिले पर इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। अपने उत्पादन को अच्छा बनाने की ओर दृढ़ता से लगे रहना चाहिए, तब, समय आने पर सफलता अवश्य मिलेगी। उत्पादन का बाह्य रूप पूर्ण हो, चीज अच्छी हो और कुछ सूझ-बूझ से काम लिया जाए तो निर्मित वस्तु अवश्य ही चल निकलेगी।

विश्व के अत्यन्त उन्नत औद्योगिक देशों में भी घरेलू और कुटीर शिल्प राष्ट्र निर्माण में बड़ा भाग अदा करते हैं। कुटीर-शिल्प और घरेलू उद्योग औसतन मध्यवित्त परिवारों को रोजगार देने में बड़े महत्वपूर्ण साधन रहे हैं। भारत में मानव-बल तो बहुत है और अधिकांश जनता ऐसी ही है, जिसके पास अल्पकालीन धन्धा ही है। कुटीर-शिल्प इस स्थिति-सुधार में बहुत सहायता दे सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में हमने देखा कि नागरिक और सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति-दिशा में कुटीर-शिल्प ने उत्पादन बढ़ाकर कितनी अधिक सहायता दी और नाजुक तथा कठिन अवसर पर सामान की आपूर्ति की, जैसे, पैराशूट कपड़े का सीना, बम रेक क्रेडल्स, पेट्रोल इन्फैक्टर्स।

बेरोजगारी और जीवन स्तर का ऊंचा होना—यह दोनों अब ऐसी समस्याएं बन गयी हैं कि लगभग ला इलाज हो चुकी हैं। इनका सर्वोत्तम इलाज घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देना है। ये ऐसे उद्योग हैं जिनमें पूरे समय का और आंशिक समय का रोजगार काफी लोगों को मिल सकता है। समस्या का हल इसी में है। जिनकी पूंजी बचत किये गये कुछ सैंकड़ा रु० ही होते हैं, वे भी थोड़ी पूंजी से घर में विविध प्रकार का सामान बना सकते हैं और थोड़े से प्रचार से अच्छी बिक्री हो सकती है। जैसे, शीशे की बनी चीजों में, चूड़ियां, मनके, बोतल, फलास्क, टेबल का सामान, लेम्प का सामान, नक्काशी किये कांच के बर्तन, — थोड़ी सी पूंजी और खाली समय की मेहनत से ये चीजें बन सकती हैं। शौकीन और कला की ओर झुकाव रखने वाली महिलाएं दस्तकारी की चीजें, चित्रकला, प्लास्टिक की वस्तुएं इत्यादि बना सकती है।

कागज की चीजों में—हाथ का बना कागज, स्याही-चूस, लपेटने वाला कागज, खिलौने, ट्रे, वेस, बावल्स, इत्यादि। इनके अतिरिक्त कागज के बड़े बस्ते, विभिन्न आकारों के कागज के लिफाफे, झोले और गत्ते के डिब्बे इत्यादि चीजें ऐसी हैं जो बड़ी जल्दी बिक सकती हैं।

सौन्दर्य प्रसाधनों में, ऐसी कई चीजें हैं जो घर में बनायी जा सकती हैं, स्नो, चेहरे का पाऊडर, ब्यूटी क्रीम, पेस्ट जुएलरी—ये सब ट्रेड गाइडों से सुभीते से सीखी जा सकती हैं और मुनाफे पर बेची जा सकती हैं।

आज के उद्योगों में प्लास्टिक का बड़ा महत्व है और इसकी बनी कई चीजें बाजार में हाथों हाथ बिक जाती हैं। प्लास्टिक की कई उपयोगी चीजें घर में बन सकती हैं,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जैसे, हाथ के बैग, खिलौने, बनावटी फूल, हाथ घड़ी के तस्मे इत्यादि।

खाली समय में स्त्रियां स्वादिष्ट शरबत, फलों का रस, आचार, मुरब्बे इत्यादि बना कर पड़ोसियों व खुले बाजार में बेचे जा सकते हैं।

इसी प्रकार निम्नलिखित उद्योग महिलाओं द्वारा घरों में आंशिक समय व पूरा समय देकर अपनी आयको बढ़ाने के लिए प्रारम्भ किये जा सकते हैं, बुनना, कपड़ों की छपाई, तैयार पोशाक बनाना, जुराब, चमड़े का सामान, खिलौने, खाने की चीजें, पिकल, जेम। मुर्गी पालन भी ऐसा उद्योग है जिसे महिलाएं सुभीते से लगन के साथ कर सकती हैं, रसोई की सब्जियों के लिए भी काफी लाभ-दायक गुंजायश है।

अन-पढ़ी व कम पढ़ी महिलाएं इन चीजों का निर्माण कर सकती हैं जिनके लिए बाजार में हमेशा मांग रहती है—पिनकी गद्दी, मोमबत्ती बनाना, नाला-परांदा, दरी, नमदा, लेस, पैंसिल, जुराब, हाथ से चलायी जाने वाली मशीनों पर टाई, बैत और प्लास्टिक के बटुए बैग, बुनाई की चीजें, बैत-प्लास्टिक के तार के बैग, साबुन, गुड़िया बनाना, बैत की टोकरियां, तिनकों के हैट, हाथ के पंखे, फूलदान बनाना इत्यादि।

● ●

भूदान-यज्ञ साप्ताहिक युग-विशेषांक—संपादक : सिद्धराज ढड्ढा प्रकाशक : अखिल भारत सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१ इस विशेषांक का मूल्य : दो रुपया, वार्षिक मूल्य : छः रुपया।

आचार्य विनोबा जी द्वारा प्रारम्भ किये गये भूदान-यज्ञ आंदोलन को १८ अप्रैल १९६३ को १२ वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर भूदान-यज्ञ का यह युग-विशेषांक प्रकाशित किया गया है।

सन् १९५१ में तेलंगाना पदयात्रा में विनोबाजी को सौ एकड़ भूमि का पहला दान मिला था। इसे उन्होंने परमेश्वर का संकेत मानकर भूदान-यज्ञ का सूत्रपात किया। तब से उनकी यह पदयात्रा १२ वर्ष तक अखंड रूप चलती रही है।

प्रस्तुत विशेषांक में इस आन्दोलन के विविध पहलुओं की जानकारी तो है ही, आनुषंगिक और संबद्ध कार्यक्रम तथा आर्थिक, सामाजिक-क्रांति के साथ-साथ ग्रामदान, जयजगत, विश्वशांति आदि विषयों का विवेचन भी आन्दोलन की स्थिति को समझने में सहायक है। इस अंक में विनोबा, दादा धर्माधिकारी, धीरेन्द्र भाई, अण्णा साहब, मनमोहन चौधरी, श्रीकृष्णदास जाजू, ठाकुरदास बंग आदि सर्वोदय विचारकों के ज्ञानवर्धक लेख पठनीय हैं। इनसे आन्दोलन तक की सफलता का भी पता चलता है। विविध प्रकार के आंकड़ों से अंक का ऐतिहासिक महत्व बढ़ गया है। अनेक लेख चिन्तन व विचार की प्रेरणा देते हैं। सब मिलाकर अंक की सामग्री पठनीय और संग्रहणीय है।

●

उषा

★ सामाजिक कहानियां, शिक्षाप्रद कथानक, विचारोत्तेजक मनोरंजक लेख, राशिफल, सरस कविताएं आदि।

★ हानिकारक वस्तुओं, व अश्लील फिल्मों के विज्ञापन स्वीकार नहीं किये जाते।

—यदि आपने अभी तक उषा नहीं देखी है तो शीघ्र ही ३२ न० पै० की टिकिट या मनीआर्डर भेजकर नमूनांक मंगा देखिये। हमें पूरा विश्वास है कि एक बार 'उषा' को देखने के बाद आप हमेशा के लिए उसके हो जाएंगे।

—अन्य जानकारी के लिए लिखिये

सचित्र मासिक उषा कार्यालय,

जवाहर मार्ग, इन्दौर।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बिजली और ईंधन का प्रतियोगी : प्राकृतिक गैस

• बिजली उत्पन्न करने के अभी तक दो ही मुख्य साधन थे, कोयला और तेल। पर इनकी प्रतियोगिता में जो नयी चीजें खड़ी हो गयी हैं, वे हैं—प्राकृतिक गैस और अणु-शक्ति। इन पंक्तियों में हम प्राकृतिक गैस की ही चर्चा करेंगे।

पश्चिमी यूरुप में गैस का उत्पादन, अपेक्षाकृत कम है, पर तेजी से बढ़ रहा है। १९५० में यह छःगुना बढ़ गया, ३२०० मिलियन वर्गफुट प्रतिदिन। अतलांतिक के दूसरी ओर, अमेरिका में १९५८ से गैस ने विद्युत का स्थान लेकर कोयले को पछाड़ दिया है। अन्य कई देशों में भी गैस का प्रचार बढ़ रहा है।

शक्ति विशेषज्ञों के एक अनुसंधान मंडल का कहना है कि निकट भविष्य में प्राकृतिक गैस विश्व की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा कर देगी और १९७० तक सम्भवतः २० प्रतिशत तक पहुँच जायगी। सोवियत रूस तो धीरे-धीरे अपनी कोयले पर आश्रित अर्थ-व्यवस्था को गैस की ओर ले जा रहा है, १९६५ तक उसका लक्ष्य १८ से २० प्रतिशत तक गैस का योगदान प्राप्त करने का है।

यातायात और वितरण की समस्या

गैस के उपयोग में सबसे मुख्य प्रश्न यातायात और वितरण का है। जिन देशों में इसके विस्तृत क्षेत्र हैं और जहां सुभीते से पहुँचा जा सकता है, वहां इसके बड़े बाजार खड़े हो गये हैं। यह बात इसीसे स्पष्ट हो जाती है कि अमेरिका में गैस का प्रयोग कुल पश्चिमी देशों के सम्मिलित प्रयोग से ९ गुना अधिक हो गया है। यातायात के साधनों की कमी का यह परिणाम है कि वेनेजुएला और मध्यपूर्व देशों में यद्यपि गैस के विशाल भंडार हैं, पर उसके लिए कोई समीपस्थ बाजार न होने से वे निरुपयोगी और बन्द पड़े हैं।

इन समस्याओं का साहस के साथ मुकाबला किया जा रहा है। ब्रिटिश गैस कौंसिल करोड़ों रुपयों की एक ऐसी योजना प्रारम्भ कर रही है जिसके द्वारा कुल आवश्यकता की १० प्रतिशत गैस द्रवी रूप में सहारा के गैस क्षेत्रों से आयात की जायगी। ३०० मील से अधिक लम्बी पाइप लाइन बनाने के ९० लाख पौंड के ठेके ब्रिटेन में गत अगस्त मास में दिये जा चुके हैं। १९६४ में यह योजना कार्यान्वित हो जायगी। टैंकों द्वारा इस द्रवीभूत गैस को जहाज द्वारा लाना भी इसमें शामिल है।

इस योजना में एक दोष यह है कि प्रत्येक द्रवीभूत इकाई पर अन्य ईंधनों की अपेक्षा—जैसे तेल—खर्च अधिक पड़ेगा। "शैल फ्रेन्जाइज" कम्पनी की खोज के अनुसार, टैंकर से तेल लाने की अपेक्षा इस गैस पर ३ से ६ गुना अधिक जहाज खर्च पड़ेगा क्योंकि इसमें कई तकनीकी उलझनें हैं।

समुद्र के नीचे पाइप लाईन

यातायात की समस्या का दूसरा हल यह है कि उत्पादक क्षेत्र से उपभोक्ता-क्षेत्र तक पाइप लाइन लगायी जाए। अगर यह सब पाइप लाइनें भूमि पर से गुजरें तो कम समस्याएं पैदा होंगी, जैसा कि अमेरिका में है। फ्रांसीसी खोज करने वालों का विचार है कि आगामी कुछ वर्षों में तकनीकी आविष्कारों से यह सम्भव हो जाएगा कि समुद्र के नीचे से भी पाइप लाइन गुजर सके। फ्रांस और इटली के सहयोग से इस दिशा में उत्साहप्रद कार्य हो रहा है।

इस सम्बन्ध में तीसरा दृष्टिकोण—जो कम महत्वपूर्ण नहीं है—वह है कि वर्तमान गैस कम्पनियों और उनकी वितरण व्यवस्था के बीच अधिक सहयोग हो, ताकि गैस वितरण व्यवस्था का एक दूसरे के साथ सम्पर्क रहे। और प्रमुख उपभोक्ताओं को नियमित रूप से गैस की सम्प्राप्ति होती रहे।

पश्चिमी यूरोप में अधिक मांग

पश्चिमी यूरुप इसमें अधिक दिलचस्पी ले रहा है। १९६३ में पश्चिमी जर्मनी ५३,००० मिलियन वर्ग फुट गैस लेना चाहता है। यह राशि पश्चिमी जर्मनी के अपने देश में पिछले वर्ष के गैस के कुल उत्पादन से लगभग तीन गुना अधिक है। उत्तरी इटली और दक्षिणी फ्रांस में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। फ्रांसीसी वितरण

(शेष पृष्ठ २४२ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थ वृत्त चयन

भारत में कम बचत

योजना आयोग की विकास योजनाओं का एक मुख्य आधार यह है कि राष्ट्रीय बचत के रूप में एक पर्याप्त भाग का प्रति वर्ष उद्योग वृद्धि आदि में विनियोजन हो। यह बचत जितनी अधिक होगी, उतना ही विनियोजन अधिक होगा और उतना ही नया उत्पादन अधिक होगा। इसीलिए योजना आयोग और प्रशासन लोगों को अपने खर्च कम करने और बचत करने के लिए कहता है। किन्तु भारत में प्रतिशत बचत लक्ष्य के अनुसार नहीं हो रही है और फलतः पूंजी निर्माण भी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा।

सुदूर-पूर्व के देशों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करनेवाले संयुक्त राष्ट्रसंघ के एक दल ने इन देशों की बचत के सम्बन्ध में एक तुलनात्मक विवरण प्रकाशित किया है। इससे मालूम होता है कि भारत में बचत अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। निम्न अंक इस लक्ष्य को स्पष्ट करेंगे —:

प्रतिशत बचत

बर्मा	१३.६	मलाया संघ	१७.५
श्री लंका	१०.४	भारत	८.५
चीन की मुख्य भूमि	१०.३	इंडोनेशिया	२.३
ताइवान	३.९	पाकिस्तान	२.५

सहकारिता अपनों की दृष्टि में

—'सहकारिता की प्रगति में बाधा मुख्य रूप से प्रशासकीय या वित्तीय कारणों की वजह से नहीं पड़ी, बल्कि सैद्धान्तिक, राजनीतिक, सामाजिक व स्वाभावगत कारणों से पड़ी। सहकारिता की राष्ट्रीय नीतियों के पूरा होने में सरकारी व गैर सरकारी स्वार्थी तत्व अड़चनें पैदा कर रहे हैं। यद्यपि राष्ट्रीय नीति स्पष्ट रूप से सहकारिता के पक्ष में है, फिर भी प्रोसेसिंग कार्यों के लिए लाइसेंस देने में निजी क्षेत्र को तरजीह दी जाती है। श्रम सहकारी समितियों या वन सहकारी समितियों के मुकाबले कि सहकारी समितियों से काम कराए जाते हैं। बिचौलियों खातिर फेरीवालों की सहकारी समितियों की उपेक्षा जाती है। कुछेक राज्यों में मन्त्रियों और अफसरों ने कारी समितियों में अब भी पद ग्रहण कर रखे हैं और तरह वे जन-आन्दोलन के विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं हमें सहकारिता आन्दोलन की गति और दिशा के बारे इस दृष्टि से विचार करना चाहिए जिससे यह सरकार और नीजी क्षेत्र के बीच एक मजबूत रचनात्मक सन्तुलन शक्ति का काम कर सके।' श्री सु. दे.

"यद्यपि तीनों योजनाओं में सहकारिता महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है परन्तु इस बावजूद मैं आपके आगे सहकारिता की खुशनुमा तस्वीर पेश नहीं कर सकता। १९६०-६१ में सहकारी समितियों को मजबूत बनाने का जो कार्यक्रम चलाया गया था, उसमें कोई खास सफलता प्राप्त नहीं हुई। खराब काम करनेवाली समितियों को बन्द करने की दिशा में भी सुस्ती से काम हो रहा है। समितियों ने अपने डिपाजिट बढ़ाने, बकाया वसूल करने और आत्म-निर्भर बनने के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। सहकारी आन्दोलन की सफलता की सच्ची बड़ी पहचान यह है कि क्या उससे कमजोर वर्गों को लाभ पहुँच रहा है। परन्तु हमारे पास कोई ऐसे आंकड़े नहीं हैं कि कमजोर वर्गों के सदस्यों का प्रतिशत क्या है, उनकी संख्या घट रही है या बढ़ रही है। यहां तक कि सहकारी बिक्री और प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी प्रगति असन्तोषजनक ही है। तीसरी योजना के पहले वर्ष में सहकारी खेती समितियां खोलने की दिशा में जो उत्साह दिखाया गया था वह मन्द पड़ता जा रहा है। विभिन्न वर्षों के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, वे पूरे नहीं हो रहे और काम कम किया जा रहा है। सहकारी समितियों में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है और राजनीतिक नेता अपने पिट्ठुओं को कर्ज दिलाने में ही लगे रहते हैं। उनसे वसूल करने की ओर उनका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। विभिन्न सहकारी क्षेत्रों में उत्पादन लक्ष्य से कम हुआ। श्री वि.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भूख की जटिल समस्या

भूख की जटिल समस्या की गम्भीरता का अन्दाजा निम्नलिखित आंकड़ों से लगाया जा सकता है। संसार की वर्तमान जनसंख्या ३०,००० लाख के करीब है और जिस हिसाब से वह आजकल बढ़ रही है, उसके अनुसार १९८४ में दुनिया की आबादी ४०,००० लाख हो जाएगी। मौजूदा हालत यह है कि दुनिया के दो-तिहाई लोगों को ठीक से भोजन नहीं मिलता। मनुष्य के खून की हरारत कायम रखने के लिए और शरीर के अंग-प्रत्यंगों को सक्रिय बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि वे ऐसे भोजन का प्रयोग करें जिसमें शक्ति की मात्रा औसत रूप में २,५०० से २,६०० कैलोरी के बीच हो। इस शक्ति के अलावा मनुष्य शरीर को औसतन ७० ग्राम प्रोटीन चाहिए तथा विटमिन और अन्य चीजों की भी जरूरत होती है जो प्रायः मंहगी खाद्य वस्तुओं से ही प्राप्त होती हैं। खाद्य और कृषि संस्था (एफ० ए० ओ०) के अनुसार १९४७-४८ में दुनिया के लोगों की भोजन द्वारा शक्ति पाने की औसत २,२१० कैलोरी थी और २०,००० लाख लोगों की औसत २,५०० कैलोरी से कम थी। ७० ग्राम अथवा इससे अधिक प्रोटीन लेने वाले लोगों की संख्या घट कर केवल ४८०० लाख ही रह गई। डाक्टर पांसे के अनुसार भारतवर्ष में १९५६ से १९५९ के तीन वर्षों में, यह औसत प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से १८९८ कैलोरी और प्रोटीन की ४९.३ ग्राम ही रही है।

आबादी से अधिक मोटर गाड़ियां

क्या आप ऐसे देश की कल्पना कर सकते हैं जहां प्राइवेट मोटर वाहनों की संख्या वहां की आबादी से अधिक हो, कोयले की अपेक्षा अणुशक्ति से अधिक बिजली प्राप्त हो और आय तथा उत्पादन का परिमाण अरबों डालरों में नहीं, किन्तु खरबों डालरों में आंका जाए, और "मध्यवित्त" परिवार की परिभाषा यह हो जो ११,००० डालर (लगभग ५० हजार रु.) वर्ष में खर्च करता हो।

यह देश अमेरिका है जो सन् २००० में—४ पीढ़ियों से भी कम समय में—इस स्तर पर पहुंच जाएगा।

खेती की जमीन पर्याप्त होगी क्योंकि औसतन फार्म एकड़ ५० से १०० प्रतिशत खाद्य आजकी अपेक्षा अधिक पैदा करेगा। फार्म से अधिक अन्न का उत्पादन अभी कई वर्ष तक रहेगा। सबसे अधिक जिस वस्तु की कमी रहेगी वह आबादी के लिए भूमि की होगी। इस समय अमेरिका की आबादी १८ करोड़ है, १९८० में इसके २४ करोड़ ५० लाख की संभावना है और सन् २००० में ३३ करोड़ १० लाख की आशा है।

पर अगर जंगल, व्यवस्थित भूखंड और खेती की भूमि का बहुविध उपयोग न किया गया तो सन् २००० में खेल, पर्यटन और समृद्ध व्यक्तियों के रहने के लिए भूमि की कमी हो जाएगी, १९६० की अपेक्षा ८५ प्रतिशत अधिक।

२० वर्ष और इससे अधिक आयु के जितने मोटर-चालक हैं, मोटरें उनसे अधिक हो जाएंगी पर कई गाड़ियां मध्य आकार की बन जाएंगी, कई वायु के और कई जल के मार्ग का अवलम्बन कर लेंगी, अगर सड़क के मोड़ पर गणक-नियंत्रित यातायात बहुत भारी हो गया।

१९६० में राष्ट्रीय उत्पादन ५०० खर्ब डालर (लगभग २००० खर्ब रु.) का था, १९८० में यह दुगुना हो जाएगा और सन् २००० में चारगुना, १९६० की क्रयशक्ति से दो खरब डालर ज्यादा। विद्युत् शक्ति तीन गुनी हो जाएगी। २०वीं सदी के अन्त तक लगभग आधी विद्युत् शक्ति की जगह परमाणु शक्ति ले लेगी, साथ ही कोयले का प्रयोग बढ़ जाएगा। १९९० के बाद कूड़ा-कबाड़ जैसी चीजों की भारी कमी हो जाएगी।

कुछ उत्पादनों का लागत खर्च बढ़ जाएगा, अथवा उनकी किस्म में गिरावट आ जाएगी, जैसे कच्चे लोहे और तेल-भंडार कम हो जाएंगे पर इनकी जगह लेने वाली अन्य वस्तुएं और तकनीकी ज्ञान से सुधरी हुई चीजें सुलभ हो जाएंगी।

बिना बुनावट का नये ढंग का कपड़ा

वस्त्र उद्योग में अब एक नया दूरगामी कदम उठाया जा रहा है। अभी तक कपड़े की अच्छाई व मजबूती देखने के लिए सूत की परख होती थी पर अब उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। अब शीघ्र ही देश में बिना बुनावट वाला कपड़ा बन सकेगा। कपड़ा कमिश्नर ने मिलों द्वारा इस प्रक्रिया को प्रारम्भ करने से पूर्व कुछ तकनीकी शर्तें उसके सामने रखीं थीं जिनका

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पूरा किया जाना अनिवार्य था। अभी तक टाटा और दिग्विजय मिल—यह दो ही इन शर्त्तों को पूरा कर सकी हैं। इन्हें क्रमशः ५० हजार पौंड और ७६ हजार पौंड का उत्पादन करने की आज्ञा मिल चुकी है। कानपुर की मिलें इन शर्त्तों को पूरा करने में अभी तक असमर्थ होने से इस आज्ञा से वंचित ही हैं।

यह विश्वास किया जाता है कि इस नयी प्रक्रिया से भारत का कपड़ा उत्पादन इतना सुन्दर, आकर्षक और मजबूत हो जाएगा कि विदेशों में उसका निर्यात बढ़ सकेगा। इस नये ढंग से कपड़ा उत्पादन करने के लिए विदेशों से तकनीकी जानकारी प्राप्त कर ली गयी है, और तदनुसार मशीनरी भी लगायी जा रही है जिस पर ६ लाख रु० की लागत आती है। विदेशी कम्पनियों का सहयोग भी प्राप्त किया जा रहा है। यह समझा जाता है कि इस किस्म का कपड़ा निर्यात के लिए विशेष रूप से तैयार किया जायगा।

भारत में उर्वरा शक्ति

भारत के समक्ष वस्तुतः भूमि की कोई आधारभूत समस्या नहीं है। भारत में एक एकड़ भूमि पर एक भारतीय की आजीविका निर्भर करती है, जबकि जापान में एक एकड़ भूमि से पांच जापानी अपनी आजीविका कमाते हैं, और उन्हें अपनी आजीविका कमाने में कोई कठिनाई नहीं होती।

जापानियों और भारतवासियों के जीवन-स्तर में विद्यमान अन्तर एकड़ और जनसंख्या का अनुपात भारत के अधिक अनुकूल होने के बावजूद—जापान द्वारा प्रयुक्त की जा रही वैज्ञानिक कृषि विधियों की कुशलता और सफलता का मापदण्ड है। यदि, भारत अपना कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उसी प्रकार की और उतनी ही विस्तृत वैज्ञानिक कृषि-विधियों का उपयोग करे तो भारत भी इतनी ही सफलता प्राप्त कर सकता है। इस क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति किए जाने की सम्भावनाएं हैं।

अमेरिका की अपेक्षा भारत को रासायनिक खाद की कहीं अधिक आवश्यकता है। इसका एक कारण तो यह है कि भारत की जनसंख्या अपेक्षाकृत बहुत अधिक है। दूसरा कारण यह है कि दोनों देशों में रासायनिक खाद उद्योग के विकास की अवस्थाएं भी भिन्न हैं। अमेरिका में रासायनिक खाद उत्पन्न करने वाले ७५ बड़े-बड़े कारखाने हैं, जबकि भारत में इनकी संख्या केवल ६ है। भारत में कई अन्य कारखाने निर्माणाधीन अथवा विचाराधीन हैं, और कारखानों के निर्माण की योजना तैयार की जा रही है।

विदेशों में आमों की मांग

पता चला है कि पिछले साल हमारे देश से लगभग २६ लाख रुपए के आम विदेशों में भेजे गए। इससे पहले साल करीब २० लाख रुपए के आम भेजे गए थे। विदेशों में हमारी आम की चटनी की मांग भी खूब बढ़ रही है और पिछले साल करीब ४६ लाख रुपए की चटनी बेची गई।

(पृष्ठ २३६ का शेष)

प्राकृतिक गैस

व्यवस्था के अन्तर्गत ८० लाख वर्ग फुट प्राकृतिक गैस दक्षिण फ्रांस के लाक्क प्रदेश से पहले ही वितरित की जा रही है।

फ्रांसीसी क्षेत्रों में इस समय लगभग ४५ करोड़ घन फुट गैस प्रतिदिन उत्पन्न होती है और देश के विभिन्न भागों में वितरित की जाती है। इससे फ्रांस की ५ प्रतिशत से अधिक बिजली की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। फ्रांस के लाक्क क्षेत्र से ५ गुना अधिक गैस भंडार सहारा में है। समुद्र के नीचे से पाइप लाइन का निर्माण जब हो जाएगा तब सहारा से सम्बद्ध हो जाने पर यूरुप में प्राकृतिक गैस के उपयोग की सम्भावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। इस पाइप लाइन के मार्ग के बारे में अभी विचार हो रहा है। इस समय अल्जीरिया के आरजेव स्थान पर गैस के लिए बन्दरगाह बन रहा है, जो १९६४ तक पूरा हो जायगा। उस समय ब्रिटेन के लिए द्रवीभूत गैस लेने के लिए पहला १२,००० टन का टैंकर वहां जाएगा।

प्राकृतिक गैस के भंडार पूर्वी पाकिस्तान, भारत, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी मिले हैं। भारत में श्री केशवदेव मालवीय के नेतृत्व में भारत का प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा प्राकृतिक गैस का विकास हो रहा है। इसकी चर्चा फिर कभी···

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अहमदाबाद की कपड़ा मिलों पर संकट

सूती कपड़ा उद्योगों में अहमदाबाद का विशिष्ट स्थान है। नगर में ७२ सूती मिलें हैं, जो कुल मिलाकर २० प्रतिशत बुनाई क्षमता और १५ प्रतिशत कताई क्षमता को बनाते हैं और मिल के अन्तर्गत सब पारियों में १,३०,००० श्रमिक प्रतिदिन औसतन काम करते हैं। इन मिलों से कुल भारत का करीब एक चौथाई कपड़ा और $\frac{1}{5}$ सूत का उत्पादन होता है। लागत खर्च, करों के असह्य बोझ कोयले और बिजली की कमी के कारण यहां की मिलें अब संकटग्रस्त स्थिति में आ गयी हैं। यहां की मिल एसोसिएशन से पदमुक्त हो रहे अध्यक्ष श्री चमनलाल रसिकलाल नागरी के कथनानुसार एक ओर सतत वृद्धिशील उत्पादन-व्यय और दूसरी ओर स्वेच्छा से मूल्य-नियमन योजना के कारण ये मिलें एक बड़े घातक चक्र में फंस गयी हैं। श्री नागरी के शब्दों में केवल एक वर्ष में केन्द्र, राज्य और नागरिक अधिकारियों द्वारा लगाया गया अतिरिक्त कर-बोझ १९६२-६३ में ११ करोड़ रु० तक पहुँच चुका है।

इन प्रतिकूल अवस्थाओं के कारण "दी सन फोराज्ड" कपड़े का सरकार द्वारा बाध्य रूप से निश्चित किया गया निर्यात स्थगित कर दिया गया है। मिलों की पूर्णतम सद्भावना के होते हुए भी, निश्चित मात्रा में बाध्य-निर्यात की योजना की पूर्ति असम्भवप्राय ही है। चाहे बढ़िया किस्म से और चाहे उत्पादन व्यय कम करके अहमदाबाद की मिलों का आधुनिकीकरण और पुनर्वास जल्दी होना चाहिए। और मिलों को परिवर्धित घिसाई भत्ता और विकास-रिबेट दे दिया जाए तो कपड़ा मिल उद्योग अपने आन्तरिक साधनों से अपने को पुष्ट कर सकती है। सूती मिल का औसतन जीवनकाल २५ वर्ष से कम करके १५ वर्ष करना होगा—ऐसा कपड़ा मिल के प्रशासक श्री प्रबोध जे० शाह ने वहां कहा है। अमेरिका में भी ऐसा ही किया जा रहा है। जापान में भी मशीनरी की औसत आयु १७ वर्ष तनाई के लिए १५ वर्ष बुनाई और १० वर्ष प्रोसेसिंग के लिए निश्चित की गई है।

राज्य अदायगी नहीं कर रहे

केन्द्रीय सरकार के राजस्व-प्राप्ति के हिसाब परीक्षक के अनुसार राज्यों ने केन्द्र से ऋण रूप में प्राप्त बड़ी राशियों का भुगतान नहीं किया है और जो किया भी है वह अनियमित रूप से किया है। ब्याज खाते में भी अभी तक कोई राशि नहीं दी गयी है। ये ऋण निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी कुल राशि ८३२.७५ करोड़ रु० से बढ़कर मार्च १९६२ के अन्त तक २,२१९.१४ करोड़ रु० तक पहुंच गयी है, अर्थात् ६ वर्ष में १,३८६.३९ करोड़ रु० की वृद्धि! १९६१-६२ में राज्य सरकारों को कुल पेशगी रकम ४४४.४७ करोड़ रु० दी गयी थी।

राज्यों में अतिरिक्त प्रस्तावित कराधान

(१९६१-६२ से १९६३-६४ तक)

(करोड़ रुपयों में)

राज्य	१९६१-६६ की अवधि के लिए लक्ष्य	अतिरिक्त प्रस्तावित कराधान १९६१-६२	१९६२-६३	१९६३-६४
आंध्र प्रदेश	५३	—	५.००	—
आसाम	१६	०.१५	१.५८	१.६२
बिहार	५०	—	०.६५	—
गुजरात	२९	०.८०	२.०८	४.०५
जम्मू-कश्मीर	८	—	१.१०	१.००
केरल	२३	१.९८	—	४.८५
मध्य प्रदेश	४८	३.००	५.००	१.९३
मद्रास	४५	—	६.२९	—
महाराष्ट्र	५२	१.००	५.०८	०.९५
मैसूर	४२	१.७०	४.००	—
उड़ीसा	२३	०.६९	१.५७	अप्राप्य
पंजाब	४०	१.३१	३.८०	५.३२
राजस्थान	३२	१.३५	१.३८	४.००
उत्तर प्रदेश	१०९	५.२१	४.००	—
प० बंगाल	४०	—	०.९५	३.५०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मध्य प्रदेश में विकास

राज्य में बड़ी सिंचाई योजनाओं को प्रारम्भ करने का विचार हो रहा है। गोदावरी से नहर निकालने के लिए राज्य को ४०० करोड़ खर्च करना पड़ेगा। इस राशि की व्यवस्था करना राज्य के लिए एक समस्या है। फिलहाल इसलिए छोटी सिंचाई योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए केन्द्र से भी पर्याप्त सहायता मिल सकती है। इससे खाद्य उत्पादन बढ़ेगा। यमुना की सहायक नदी बेतवा और नर्मदा से नहर निकालने के लिए अतिरिक्त ६०० करोड़ रु. खर्च होगा।

भारत के सबसे बड़े जिले बस्तर—जो इसी राज्य में है—के विकास पर अब विशेष ध्यान देने का निश्चय किया गया है। अभी तक तो यह जंगली पशुओं का अड्डा बना हुआ है। अब इस क्षेत्र में जल-विद्युत् योजनाओं, कागज, गत्ता और फाइबर उद्योगों का सूत्रपात किया जा रहा है। रेल-लाइन भी बनायी जा रही है। कच्चे लोहे की खानें खोदी जाएंगी। इस इलाके में खाद्य-उत्पादन को भी बढ़ाया जाएगा। केन्द्रीय सरकार के खाद्य और कृषि, सिंचाई और बिजली, आवास और पुनर्वास और भारी उद्योग मंत्रालयों के अधिकारियों ने इस जिले का वहां आकर सर्वेक्षण किया है और कई योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है।

इसके साथ ही, राज्य सरकार ने ६० हजार आदिवासी और भूमिहीन मजदूरों के हरिजन परिवारों को खेतीयोग्य बेकार पड़ी जमीन पर ६१ लाख रु. खर्च करके आबाद करने का निश्चय किया है। केन्द्र की ओर से भी इस योजना को पुष्टि मिली है, जिसके अनुसार प्रत्येक परिवार को अधिकतम ५०० रु. देने के आधार पर ७५ प्रतिशत और २५ प्रतिशत ऋण राज्य को दिया जाएगा।

खादी पत्रिका

* खादी ग्रामोद्योग तथा सर्वोदय विचार पर विद्वत्ता पूर्ण रचनाएँ।
* खादी ग्रामोद्योग आन्दोलन की देश व्यापी जानकारी।
* कविता, लघुकथा, मील के पत्थर, साहित्य समीक्षा, संस्था परिचय।
* साँख्यकी पृष्ठ आदि स्थायी स्तम्भ।
* आकर्षक मुख पृष्ठ, हाथ कागज पर छपाई।

वार्षिक मूल्य ३) रु., एक प्रति पच्चीस नये पैसे

संपादक—ध्वजाप्रसाद साहू, जवाहिरलाल जैन

राजस्थान खादी संघ, पो. खादीबाग, (जयपुर).

विगत दशाब्दि में बजट की प्रवृत्तियां

(पृष्ठ २२१ का शेष)

भी एक मात्रा में होनी चाहिए, किन्तु गरज सब कुछ करा लेती है और वित्तमंत्री इसकी भी हत्या नहीं कर सकते। पूंजीगत बजट में बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। नीचे की तालिका से मालूम होगा कि सरकार ने नासिक के प्रैस का कितना आश्रय लिया है।

घाटे की अर्थ-व्यवस्था (करोड़ रु० में)

१९५०-५१	३.७		
१९५५-५६	१५९.८	१९६१-६२	६४.[illegible]
कुल प्रथम योजना	४०३२	१९६२-६३	२१७.[illegible]
कुल दूसरी योजना	९१८.०	१९६३-६४	१३७.[illegible]

उपर्युक्त विवरण से पाठकों को बजट के सब पहलुओं का ज्ञान नहीं होगा। केन्द्रीय बजट के दो मुख्य अंग होते हैं, एक तो राजस्व बजट और दूसरा पूंजीगत बजट। पूंजीगत बजट के अंतर्गत भारी खर्च सम्मिलित होते हैं, जो भारी मशीनरी और बड़े निर्माण-कार्यों पर होते हैं। बांध, बड़े-बड़े कारखाने और योजना के अंतर्गत काम पूंजीगत बजट में शामिल किये जाते हैं। इनकी चर्चा हमने अपने इस लेख में नहीं की। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसका महत्व कम है। पूंजीगत बजट के अंतर्गत १९६३-६४ के बजट में १८२० करोड़ रुपये की व्यवस्था है जबकि १९५०-५१ में कुल १८२.७ करोड़ रु० का पूंजीगत बजट था। इसके लिए सरकार देश या विदेशों से भारी ऋण या सहायता लेती है। विश्व बैंक से करोड़ों रुपये लेती है, नासिक के प्रैस का आश्रय लेती है, इनामी या स्वर्णबाण बेचती है, डाकखाने की बचत का उपयोग करती है, आदि-आदि। ऋणों की चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। छोटी बचत

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

से पहली योजना में २३१.३ करोड़ और दूसरी योजना में ३६३.३ करोड़ रु० प्राप्त हुआ था और नये बजट में १४४.८ करोड़ रु० का अनुमान किया गया है। पूंजीगत बजट के अतिरिक्त राज्य, म्यूनिसिपल कारपोरेशन व कमेटियां आदि स्थानीय संस्थाएं भी अपने-अपने क्षेत्र में जनता पर कर लगाती हैं।

पिछले १०, १२ वर्षों में ये कर भी लगातार बढ़ते रहे हैं। समय के साथ-साथ राज्य के उत्तरदायित्व बढ़ते जाते हैं। जनता की आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं, उन सबको पूर्ण करना सरकार का—केन्द्र, राज्य और नगर, कस्बे या पंचायत का कर्तव्य होता है। नई आवश्यकताओं को, जो नित बढ़ रही हैं, पूर्ण करने के लिए जनता से सरकार अधिकाधिक त्याग की आशा भी करती है। लेकिन नई व्यवस्था में इस बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा कि कर उतने ही लगाये जायें, जितने सहन किये जा सकें और उनसे भविष्य के विकास में कोई बाधा न हो। कर लगाने से पहले यह देखना भी आवश्यक है कि जो धन हम प्राप्त कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग तो नहीं होता। ●

भारत में अलौह धातु उद्योग

(पृष्ठ २२९ का शेष)

नहीं किया जाता।

तांबे का महत्वपूर्ण अयस्क चालकोपाइराइट है जो तांबे का द्विगुण सल्फाइड है। भारत में जो चालकोपाइराइट अयस्क आज निकाला जा रहा है यह बिहार के सिंघभूमि जिले में पेसावनी खानों में स्थित है। १९६० में इन खानों से ४४८००० टन अयस्क प्राप्त हुआ था और इन से ८,९१० टन तांबा निकाला गया था। राजस्थान में खेतड़ी और दरीबो क्षेत्र में तांबे अयस्कों की बड़ी जमावटों का पता चला है। समझा जाता है कि इससे १९६४ के मध्य तक अयस्क तांबा निकाला जाने लगेगा।

जस्त—जस्त और उस की मिश्र धातुओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सब माल विदेशों से मंगाया जाता है। जिंक ब्लैंड, जो जिंक का सल्फाइड होता है, भारत में राजस्थान की जवार खानों में पाया जाता है। बिहार के धनबाद जिले में कटरास नामक स्थान पर जस्त निकालने का एक कारखाना बनाया जायगा, जिसकी उत्पादन क्षमता १२,००० टन वार्षिक होगी। यहां गंधक का तेजाब और सुपर फास्फेट भी बनाया जाएगा। राजस्थान में भी १५,००० टन क्षमता का एक कारखाना बनाया जा रहा है।

अनुमान है कि जस्त की मांग जो अभी ६०,००० टन के आसपास है १९९६ तक प्रति वर्ष १,८५,००० टन हो जाएगी। देसी और बाहर से मंगाये गये सांद्रित अयस्क से उस वर्ष तक इस धातु की उत्पादन क्षमता २७,००० टन हो जाएगी।

जस्त आमतौर से चादरों और पट्टियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इनके निर्माण का देश में जो प्रबन्ध है उससे १९६५-६६ तक काम चल जाएगा। जस्त का बहुत बड़ा उपयोग लोहे की चादरों और तारों पर चढ़ाने में किया जाता है। राष्ट्रीय धातुकर्म शाला में एक ऐसी विधि का आविष्कार किया गया है, जिससे लोहे की चादरों और पट्टियों पर अलमुनियम की तह चढ़ाई जा सकती है। ये तहें जस्त की तह के समान ही लोहे की रक्षा करती है।

सीसा—सीसे या लेड के खनिज जस्त में मिले हुए पाये जाते हैं। रासायनिक उद्योग में जहां पात्रों और नलों का क्षरण गंधक के तेजाब के कारण अधिक होता है, सीसे की चादर लोहे या लकड़ी के बर्तनों के भीतर अस्तर की भांति इस्तेमाल की जाती है।

सीसे की ढालों का उपयोग रेडियमधर्मी पदार्थों के विकिरणों और एक्स-रे से बचने के लिए तथा गैसों और पानी के लोहे के नलों की जड़ों को भरने के लिए, रसायनिक कारखानों के फर्शों के लिए और इस्पात के ऊष्मा उपचार की हौदियों में भी उसका इस्तेमाल होता है। सीसे के बहुत से योगिक रंगों के रूप में इस्तेमाल किये जाते हैं।

टाइटेनियम—अलमुनियम, लोहे और मैग्नीशियम के बाद टाइटेनियम पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक पायी जाने वाली धातु है। यह धातु अब सैनिक और रसायनिक उद्योगों में काफी इस्तेमाल की जाने लगी है। इसका उत्पादन पिछले वर्षों में कुछ नहीं से अमरीका में २०,००० टन तक और जापान तथा ब्रिटेन में क्रमशः २००० और १६०० टन वार्षिक तक पहुँच गया है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इसका खनिज इल्मेनाइट और रूटाइल हैं। इनकी कुछ विशाल जमावटें भारत में मौजूद हैं। दक्षिण के कुछ स्थानों पर समुद्र तट की रेत में ५० से ६० प्रतिशत तक टाइटेनियम आक्साइड उपस्थित है। ये क्षेत्र महाबलीपुरम से कन्याकुमारी तक, मुट्टम-पुड्डार, कोविलम, अवजैंगो—वारकल्ली और निन्डाकारा में स्थित है। केरल में इसकी बड़ी जमावटें हैं जहां से प्रति वर्ष २-३ लाख टन माल निकाला जाता है। अभी तक टाइटेनियम धातु भारत में नहीं निकाला जाता है और इसका अयस्क अधिकतर बाहर भेजा जा रहा है।

मैग्नीशियम—मैग्नीशियम और मैग्नीशयम आधारित मिश्र धातुएं सबसे हल्की हैं। मैग्नीशियम अभी भारत में नहीं तैयार किया जाता है। उसकी हमारी लगभग ३०० टन वार्षिक की आवश्यकता अभी आयात से पूरी होती है। हलके खनिज डोलोमाइट और मैग्नेसाइट की जमावटें देश के बहुत से भागों में पाई जाती है। डोलोमाइट की ज्ञात बड़ी जमावटें उड़ीसा के सुन्दरगढ़ में बीरमित्रपुर और पम्पोश नामक स्थानों पर हैं। आज कल डोलोमाइट की ९७ प्रतिशत मात्रा इन्हीं स्थानों से प्राप्त होती है।

टिन—यह धातु अपनी अक्षरणीयता और अविषैलेपन के कारण टिन के डिब्बों के लिए और वैयरिंग निर्माण के वास्ते इस्तेमाल की जाती है। अभी तक भारत में ऐसी कोई जमावटें नहीं मिली है, जिनसे यह धातु निकाली जा सके। १९६५ के लिए हमारी वार्षिक आवश्यकता का अनुमान लगभग १०,५००० टन है; टिन का आयात किया जाता है और कतरन में से धातु को पुनः निकाला जाता है। ●

जहाजरानी उद्योग में हाल की सफलताएं

(पृष्ठ २३१ का शेष)

दृष्टि से दूसरी योजना के अन्त तक ९ लाख जी. आर. टी. जहाज हो जाने थे लेकिन वस्तुतः ८.६ लाख जी. आर. टी. हो पाए।

तीसरी योजना

तीसरी योजना में जहाजरानी बढ़ाने का लक्ष्य यद्यपि मूलतः ३.७५ लाख जी. आर. टी. से बढ़ा कर ५.५ लाख जी. आर. टी. कर दिया गया है तथापि आयोजन आयोग ने राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड की यह सिफारिश नामंजूर कर दी थी कि सन् १९६५-६६ तक १४.२ लाख टन का लक्ष्य पूरा किया जाए जिसमें १०.८ लाख टन समुद्रपारीय व्यापार के लिए और ३.४ लाख टन तटीय व्यापार के लिए हो। आज अतिरिक्त जहाजरानी का लक्ष्य यद्यपि ५.५ लाख टन है तथापि इस उद्देश्य के लिए पहले के ५५ करोड़ रुपये के वित्तीय लक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त ४ करोड़ रुपये जहाजरानी विकास कोष से मिल सकेंगे और ७ करोड़ रुपया जहाजरानी कम्पनियों के अपने साधनों से प्राप्त होने की आशा की जाती है।

योजना-निर्माताओं ने सदा यह महसूस किया है कि जहाजरानी के विस्तार को उच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए और यह बात बार-बार कही गई है। लेकिन हमेशा ही विदेशी मुद्रा की कठिनाई दीवार बन कर खड़ी हो जाती है। यह एक प्रकार का दुश्चक्र है। पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध न होने के कारण भारत अपना व्यापारिक बेड़ा इतना नहीं बढ़ा सकता जितना वह चाहता है और चूंकि भारत के पास अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सही किस्म के जहाज पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं इसलिए अपने समुद्रपारीय व्यापार के लिए विदेशी-मुद्रा के रूप में उसे भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।

जयन्ती का प्रवेश

डा. जे. धर्मतेजा द्वारा जयन्ती शिपिंग कम्पनी के सूत्रपात से यह दुश्चक्र टूट गया प्रतीत होता है। इसने भारतीय जहाजरानी के घटना पूर्ण इतिहास में एक नया अध्याय खोला है। सन् १९६० में डा. धर्मतेजा ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले दो-तीन वर्षों में ३ लाख डेडवेट (लगभग २ लाख जी. आर. टी.) के बल्क कैरियर (बड़ी तादाद में माल ढोने वाले) तथा ट्राम्प (किसी निश्चित मार्ग पर न चलने वाले) जहाज प्राप्त करने की एक नई योजना का भारत सरकार को सुझाव दिया। डा. तेजा की योजना कई प्रकार से अनूठी थी। इस प्रकार की चीज पहले कभी सरकार के सामने नहीं आई थी। डा. तेजा ने यह दिखा दिया कि इस ऋण-वित्त-योजना के अधीन ५५ करोड़ रुपये की राशि के, जो भारतीय जहाजरानी के विकास

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में दी गई है, बहुत थोड़े अंश से ही वांछित टन के जहाज प्राप्त किए जा सकते हैं।

डा० तेजा की योजना का सार यह था कि संसार के जहाज निर्माण के बड़े-बड़े कारखानों को १०० प्रतिशत ऋण देने के लिए मनाया जा सकता है और इन जहाजों को खरीदने वाली भारतीय कम्पनी को जहाजों की डिलीवरी के समय सिर्फ १० प्रतिशत रकम देनी होगी और बाकी ९० प्रतिशत कीमत ७ समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जा सकती है। इस प्रकार जहाज उद्योग में शत प्रतिशत ऋण की व्यवस्था अनहोनी और अनसुनी है। डा. तेजा ने सरकार को सुझाव दिया कि उनकी योजना पर सरकार की स्वीकृति इस रूप में होनी चाहिए कि जिन चीजों के आयात-निर्यात पर सरकार का नियंत्रण है, जैसे अनाज, लोह, खनिज, अन्य खनिज पदार्थ और रासायनिक खाद आदि उनके परिवहन के बारे में एक दीर्घकालीन करार किया जाए। भारत ४ करोड़ टन से अधिक माल का आयात-निर्यात करता है जिसमें से सिर्फ १० प्रतिशत भारतीय जहाजों में ढोया जाता है। इस ४ करोड़ टन माल में से ६० लाख टन से अधिक सरकारी नियंत्रित चीजें होती हैं जो बड़ी तादाद में ढोयी जाती हैं।

भारत सरकार ने डा. तेजा की योजना को पसन्द किया और जयन्ती शिपिंग कम्पनी प्राइवेट लि. तथा शिपिंग डेवलेपमेण्ट फण्ड कमेटी के बीच १८ फरवरी १९६१ को अंतिम ऋण समझौता हो गया।

सुपर आयल टैंकर

इस ऋण समझौते के लिए बात-चीत के दौरान में जयन्ती शिपिंग कम्पनी प्राइवेट लि० ने भारत सरकार के सुझाव पर ३३००० टन डेडवेट का सुपर आयल टैंकर 'आदि जयन्ती' २४ अगस्त, १९६१ को प्राप्त किया। यह टैंकर फिलहाल ११ और वर्षों के लिए शेल आयल कम्पनी के पास चार्टर किया हुआ है।

इस सप्ताह जयन्ती का (और भारत का) दूसरा बल्क कैरियर 'गौतम जयन्ती' जो १० अप्रैल १९६३ को मित्सुबिशी कम्पनी के नागासाकी यार्ड में डिलीवर किया गया, अपनी प्रारम्भिक यात्रा पर भारत आ रहा है। गौतम जयन्ती कम्पनी को डिलीवर होने से पहले ही १२-१३ महीने के लिए चार्टर हो गया। अपनी पहली यात्रा पर गोआ पहुंचने के बाद 'गौतम जयन्ती' २६,००० टन भारतीय लोह खनिज यूरोप के बाजारों में ले जाएगा। इस प्रकार अपने भाई 'भारत' के समान 'गौतम' ने भी भारत के लिए कीमती विदेशी-मुद्रा कमानी शुरू कर दी है।

गौतम जयन्ती के बाद इसी श्रेणी के ६ और जहाज कम्पनी प्राप्त कर रही है। तीसरा बल्क कैरियर 'अकबर जयन्ती' मई १९६३ में और चौथा बल्क कैरियर 'चन्द्रगुप्त जयन्ती' जुलाई १९६३ के अन्त में डिलिवर होगा। आशा की जाती है कि मई १९६४ तक १४ अन्य जहाजों के अलावा जयन्ती के पास ८ बल्क कैरियरों का एक बेड़ा हो जायगा, जो अपना सिर ऊंचा किए भारतीय तिरंगा लहराते हुए महासमुद्रों का चक्कर लगाएंगे और भारत की सामुद्रिक कीर्ति और ज्यादा उज्ज्वल बनाएंगे।

अक्तूबर-दिसम्बर १९६२ के बीच ६ सप्ताह के रिकार्ड समय में जयन्ती ने १२ जहाज खरीदे। आज जयन्ती के बेड़े में ३२,००० टन का एक टैंकर है जो टाइम-चार्टर पर चल ही रहा है और १२ मालवाही जहाज हैं जिनमें से प्रत्येक करीब ११,००० डेडवेट टन का है। इनमें से ७ जहाज भारत के तट पर चल रहे हैं और अन्य ५ भारत व अमरीकी बन्दरगाहों के बीच तथा जापान व अन्य देशों के बन्दरगाहों के बीच माल ढो रहे हैं।

सबसे सस्ता सचित्र हिन्दी मासिक

जागृति

जिसे भारत के सभी प्रमुख कवियों,
और कहानीकारों का सहयोग प्राप्त है।

उत्प्रेरक कविताएं, ज्ञानवर्धक लेख, सांस्कृतिक निबंध,
रोचक कहानियां, बाल संसार, साहित्य आगे
बढ़ता है आदि स्तम्भ

तिरंगा आवरण, अनेकों इकरंगे चित्र
४८ से ५६ पृष्ठ की सम्पूर्ण छपाई आर्ट पेपर पर

इस पर भी मूल्य केवल २५ नये पैसे

एजेंटों को ५ से १० प्रतियों पर २५ प्रतिशत और इससे ज्यादा पर ३३⅓ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। डाक खर्च प्रकाशकों के जिम्मे। एजेन्ट नमूने की प्रति के लिए आज ही लिखें।

—सूचना व प्रकाशन विभाग चण्डीगढ़ (पंजाब)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रासायनिक रंगों की शताब्दी

श्री सतीश सक्सेना

लगभग ५० वर्ष पूर्व भारत में नील का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। जर्मनी के रासायनिक रंगों के आविष्कार ने इस व्यापार को बिलकुल ठप्प कर दिया। १०० वर्षों में संसार के रंग उद्योगों में जो जबरदस्त रद्दोबदल हुए हैं, उसकी कहानी हमारे लिये प्रेरणात्मक है। —सम्पादक

कोलतार से बनने वाले रंग का सबसे पहिले आविष्कार १८५६ ई० में एक जर्मन प्रोफेसर होफमेन की लन्दन स्थित रसायनशाला में उसके एक अंग्रेज शिष्य द्वारा हुआ था। यह युवक उस समय कोलतार से कुनीन बनाने का प्रयत्न कर रहा था, जो एक पेड़ की छाल से बनती थी ताकि वह सस्ती बन सके। उसके एक प्रयोग में अनायास ही एक रंगीन बनी हुई चीज मिली, जो रेशम को लाल बैंगनी रंग में रंगता है। संसार में यह सर्वप्रथम रासायनिक रंग था।

रसायनिक रंग बनाने का कार्यक्षेत्र फिर जर्मनी बन गया, जहां १८६३ में होयश्टर कार्बवर्क और बेयर डाई वर्क्स नामक दो संसार प्रसिद्ध फर्मों का जन्म हुआ। इसके साथ ही अन्य दो प्रसिद्ध फर्म भी बने जिनमें वास्फ और अगफा है, जो अब फोटोग्राफी के सामान के लिये मशहूर है। होयश्ट, जो इस समय पश्चिमी जर्मनी के रसायनिक उद्योग के सबसे बड़े फर्मों में एक है, ने गत फरवरी मास में अपने जन्म की शताब्दी बड़े शान से मनाई थी। इसने अपने १०० वर्ष के कार्यकाल में संसार के रासायनिक रंगों के उद्योग में क्रान्ति की है। इस अवसर इस फर्म के एक रासायनिक ने रंगों की खोजबीन के इतिहास पर प्रकाश डालते हुये बताया था कि इस समय भी नये-नये प्रकार के रंगों का आविष्कार होता रहता है।

नील के रंग—एक शताब्दी पूर्व सभी कपड़े पेड़ों से बनाये गये रंगों से रंगे जाते थे, जैसे नील और मजीठ। मजीठ से बना हुआ रंग "टार्किश रेड" के नाम से प्रसिद्ध था और कीमती होता था। १८८० ई० एडोल्फ वान बेयर नामक जर्मन रासायनिक ने नील का विश्लेषण कर लिया और रसायनिक ढंग से उसको बना लिया। होयश्ट और बास्फ नामक फर्मों ने नील से बनने वाले रंगों के तकनीकी विकास के लिये करीब सवा तीन करोड़ रुपये मशीनरी खरीदी और १८९७ ई० में यह बाजार में आ गई। इस आविष्कार से संसार के रंग उद्योग में और कुछ देशों की कृषि में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया। रासायनिक रंगों की प्रतियोगिता में भारत का नील का उद्योग ऐसा ठप्प हुआ, जो अब तक नहीं पनप सका है। नील का दाम ८ शिलिंग प्रति पौण्ड से गिरकर ३ शिलिंग रह गया। नये रंगों के कारण रंगाई का मूल्य भी चौथाई रह गया। इन्हीं कम्पनियों ने रंग बनाने की दूसरी प्राकृतिक चीज मजीठ की भी मिट्टी खराब कर दी।

इसके बाद से तो बेशुमार तरह के रंग बनाये जाने लगे। रोज बदलने वाले फेशन व रसायनिक कपड़ों के विकास ने रंगों के विकास को बहुत बल प्रदान किया। रंग बनाने वालों के सामने इतनी समस्यायें हैं कि वह अगले १०० वर्ष तक व्यस्त रहे।

इस्तेमाल का ढंग—विभिन्न प्रकार के रंगों के साथ साथ उनको इस्तेमाल करने के ढंगों में भी महान परिवर्तन हो गया है। इनमें एक है कपड़ों पर एक विशेष प्रकार की गोंद द्वारा रंग को जमाना। इसमें उसी तरह वारनिश की जाती है जिस प्रकार लकड़ी, कागज या धातुओं पर। कपड़ों पर भी अब एक प्रकार की वार्निश की जाती है। कपड़ों के ऊपर रंगों के कोटिंग फैला दिये जाते हैं और उसे रासायनिक गोद से चिपका दिया जाता है, यह टिकाऊ मजबूत पक्का रंग हो जाता है।

कुछ रंग ऐसे होते हैं जो अपने आप चढ़ जाते हैं। वस्फ के एक रासायनिक ने एक सिद्धान्त १९१४ में निकाला

(शेष पृष्ठ २५० पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस मास की आर्थिक घटनाएं

जनरल बीमा का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा

भारत सरकार के निश्चय के अनुसार फिलहाल जनरल बीमे का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा। अन्य कई कारणों में एक कारण वर्तमान संकट काल का होना भी है। यह भी बताया गया है कि १९६१ में जनरल बीमा की कारोबार भारतीय कंपनियों की राशि ३१.८५ करोड़ रु. और विदेशी कंपनियों १२.४६ करोड़ रु. थी।

विदेशी ऋणों की अदायगी

१९६३-६४ और १९६५-६६ के बीच विदेशी ऋणों की अदायगी १३५.८९ करोड़ रु. होगी। सूद की अदायगी का बोझ १३९.१८ करोड़ रु. होगा।

कुल मूल धन की अदायगी में से १०३.१२ करोड़ रु. विदेशी मुद्रा में देना होगा, ३१.३८ करोड़ रु. की मुद्रा में, जिससे भारतीय माल खरीदा जाएगा और ३१.२९ करोड़ रुपयों में। इन रकमों पर सूद की राशि क्रमशः ७६.४२ करोड़ रु., ११.९५ करोड़ रु. और ५०.८१ करोड़ रु. होगी।

भारत में ब्रिटिश कम्पनियों की पूंजी

रिजर्व बैंक आफ इंडिया से प्राप्त नवीनतम संख्याओं के अनुसार भारत में जितनी निजी विदेशी पूंजी लगी है, उसमें लगभग ७८ प्रतिशत ब्रिटेन की है। पिछले ३॥ वर्षों में औद्योगिक सहयोग के जितने नये समझौते हुए हैं, उनमें से प्रत्येक तीन में से एक के साथ ब्रिटिश फर्मों का सम्बन्ध रहा है। १९६० में ब्रिटिश कम्पनियों का कुल पूंजी विनियोग बढ़कर ४४.५ करोड़ रु. हो गया। इसमें से करीब ३० करोड़ रु. तेल उद्योग में गया। अगर इस राशि को छोड़ भी दिया जाए, फिर भी निजी ब्रिटिश पूंजी में कुल वृद्धि १४.५ करोड़ रु. की थी, जो १९५६ से लेकर अभी तक सर्वाधिक है। ब्रिटेन के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि १९६१ में कुल वृद्धि (तेल उद्योग और बीमा छोड़कर) करीब १६ करोड़ रु. थी। कई कारणों से पिछले कुछ वर्षों में, भारत में ब्रिटिश पूंजी विनियोग, अपेक्षाकृत कम हुआ है। १९५७ में ६.३ करोड़ रु० से १९५८ में इसमें २ करोड़ रु. की कमी आयी पर १९५९ में इसमें फिर कुल १.५ करोड़ रु. की वृद्धि आ गयी।

इस कमी का बड़ा कारण यह है कि कुछ ब्रिटिश कम्पनियां पर्याप्त राशियों को वापस खींच रही हैं, जैसे जीवन बीमा कम्पनियां क्योंकि इनका अब राष्ट्रीयकरण हो गया है।

निजी ब्रिटिश पूंजी विनियोग में लगभग आधी वृद्धि उस लाभ से आती है, जो ये कम्पनियां यहां से प्राप्त कर फिर वापस यहीं लगा देती हैं। १९६० में, समूचे विदेशी पूंजी विनियोग का प्राप्त लाभ १४.५ करोड़ रु. था जिसमें से ब्रिटिश स्वार्थवाली कम्पनियों का लाभ करीब दो-तिहायी था।

भारत में निजी विदेशी पूंजी विनियोग के मुख्य स्रोत ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और पश्चिमी जर्मनी हैं। ४४३ करोड़ रु. के पूंजी विनियोग के साथ ब्रिटेन सबसे आगे हैं, उसके बाद अमेरिका ७२.६ करोड़ रु., स्विट्जर लैंड ८.९ करोड़ रु. और पश्चिमी जर्मनी ६.८ करोड़ रु.। कनाडा, जापान, पाकिस्तान और मलाया मिलकर १४.१ करोड़ रु. पूंजी लगी हुई है।

मोटर गाड़ियों के पुरजे

मोटर गाड़ियों के हिस्से और पुर्जे बनाने वाले छोटे कारखानों की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान में हुई थी, क्योंकि उन दिनों पुराने पुर्जों व हिस्सों को बदलने के लिए विदेशों से नये कल-पुर्जे मंगाना कठिन हो गया था। सन् १९६० में कुल मिलाकर ५१,६६० मोटरगाड़ियां बनाई गयीं और बड़े व छोटे दोनों तरह के कारखानों में १५ करोड़ रु० के मोटरगाड़ियों के हिस्सों व पुर्जों (टायर, ट्यूब व रबड़ की अन्य वस्तुएं, बैटरियों और बाल बियरिंग छोड़ कर) का निर्माण हुआ। इसमें से ६ करोड़ रु० का माल छोटे कारखानों में तैयार हुआ। इस क्षेत्र में लघु उद्योगों का योग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है और अब देश में प्रतिवर्ष कुल २६-२७ करोड़ रु० के हिस्से व पुर्जे बनाए

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जाते हैं। जिन में से १०-११ करोड़ रु० का माल छोटे कारखानों में बनता है। आशा की जाती है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उत्पादन इतना बढ़ जायेगा कि देश में १ लाख मोटर गाड़ियां सालाना बनने लगेंगी और उनमें लगने वाले औसतन ८०-९० प्रतिशत पुर्जों व हिस्सों का निर्माण भी देश में ही होने लगेगा।

हाल ही में मोटर उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद ने ऐसी वस्तुओं की सूची बना दी है जिनका निर्माण केवल सहायक उद्योगों द्वारा ही कराया जायेगा। इस सूची में लगभग १५० वस्तुएं हैं, जिनमें से लगभग १०० वस्तुएं लघु उद्योग क्षेत्र के सहायक कारखानों में बनायी जा सकती है। अब सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र के सहायक कारखानों में लगाई जा सकने वाली पूंजी की अधिकतम सीमा भी बढ़ा कर १० लाख रु० कर दी है।

(पृष्ठ २४८ का शेष)

था पर उससे उत्पादन १९५२ में होयस्ट के कारखाने से सका, इसमें कुछ ऐसे रसायनिक तत्व होते हैं जो चीज के अन्दर जजब होते हैं, इन पर धुवां रोशनी का असर नहीं होता और इनका रंग बराबर बना रहता है। यह रुई ऊन आदि के लिये बहुत उपयोगी है। अब से सौ वर्ष पूर्व यह बात स्वप्न में भी नहीं थी और अगले १०० वर्ष में यह क्या रूप ले सकेगा यह कहना मुश्किल है। परन्तु यह स्पष्ट है कि वैज्ञानिक अनुसन्धान पर यथेष्ठ ध्यान दिये पश्चिमी का यह विशाल उद्योग भी भारत के नील के उद्योग तरह चौपट हो सकता है। भारत अपने औद्योगिक तभी कायम रख सकेगा जब उसके साथ-साथ विज्ञान अनुसन्धान कार्य भी चलेगा।

हिन्दी का एकमात्र

विशिष्ट महिलोपयोगी मासिक

श्रृंगार

- जो सुखी पारिवारिक जीवन का आदर्श पथ-प्रदर्शक है।
- जिसे सुप्रसिद्ध लेखिकाओं, लेखकों, पत्रकारों, चित्रकारों, कवयित्रियों तथा कवियों का सहयोग प्राप्त है।
- जिसे ५०००० से ऊपर की संख्या में पाठक प्रतिमास पढ़ते हैं।
- जिसकी प्रतियां न्यूज़ एजेन्टों के पास पहुँचते ही समाप्त हो जाती हैं।
- जो महिला जागृति का प्रतीक है।
- जो सबकी प्रिय पत्रिका है।

वार्षिक : सात रुपये

एक प्रति : ६० नये पैसे

सम्पादिका : लावण्यप्रभा

कार्यालय : १३।३७, शक्तिनगर, दिल्ली-६।

"राष्ट्र-भारती"

सम्पादक—मोहनलाल भट्ट, हृषीकेश शर्मा

इसमें आपको लब्धप्रतिष्ठ-विद्वान् साहित्यकारों के पोषक और मनोरंजक अच्छे-अच्छे लेख, कविताएं कहानि एकांकी, रेखाचित्र, शब्दचित्र आदि रचनायें पढ़ने को मिलें

इसमें संस्कृत, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी विभिन्न भारतीय भाषाओं की तथा अंग्रेजी, रशियन विदेशी भाषाओं की उत्कृष्ट रचनाओं के सुन्दर हि अनुवाद भी रहते हैं।

आज ही मनीआर्डर द्वारा ६) भेजकर ग्राहक बन

रियायत—स्कूल-कालेजों सार्वजनिक पुस्तकाल तथा वाचनालयों को केवल ५) वार्षिक चन्दे में मिलेगी।

पत्रव्यवहार का पता—

व्यवस्थापक—"राष्ट्रभारती"

हिन्दी नगर, वर्धा

प्रचार (राष्ट्रभाषा समिति)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा

सैंकड़ा प्राप्त पत्रों में से
कुछ सम्मतियां

आर्थिक प्रश्नों पर ज्ञानवर्धक सामग्री व स्वतंत्र चिन्तन की एक मात्र हिन्दी पत्रिका

१. क्या आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं और परीक्षा में सफल होना चाहते हैं ? — तो देखिये छात्र क्या कहते हैं कि सम्पदा ने उनको कैसी सहायता दी ?

२. क्या आप अर्थशास्त्र के अध्यापक हैं और छात्रों को योग्य बनाना चाहते हैं ? — तो अपने विद्वान सहयोगी प्राध्यापकों व शिक्षाविदों की सम्मतियां देखिये ।

३. क्या आप देश के आर्थिक विकास और आर्थिक प्रश्नों में रुचि रखते हैं ? — तो केन्द्र व राज्यों के मंत्रियों के 'सम्पदा' सम्बन्धी विचारों से लाभ उठाइये ।

४. क्या आप उद्योग व व्यापार की प्रगति व समस्याओं की जानकारी चाहते हैं ? — तो देखिये प्रमुख उद्योगपति सम्पदा के संबंध में कैसी ची सम्मति रखते हैं ।

५. क्या आप पत्रों के सुशिक्षित व विचारशील पाठक हैं ? — तो पढ़िये देश के प्रतिष्ठित हिन्दी पत्र व सम्पादक क्या कहते हैं ?

सम्पदा का वार्षिक मूल्य रु. ८.५० आज ही मनीआर्डर से भेजकर इस उत्कृष्ट पत्रिका के ग्राहक बन जाइये

सम्पदा २८/११, शक्तिनगर, दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थशास्त्र के विद्यार्थी और अध्यापक कहते हैं ?

सम्पदा पर ही निर्भरता : परीक्षा में सफलता के लिए वरदान : छात्र सम्पदा पर झपटते हैं : प्रत्येक अंक में भरपूर सामग्री : कुशल व योग्य सम्पादन

कालेज की छात्रा-कृष्ण कुमारी शर्मा, रांची लिखती है—

—हम जैसे अर्थशास्त्र के विषय को लेने वालों के लिए "सम्पदा" बहुत ही सहायक सिद्ध हुई है। भारतीय अर्थशास्त्र में अधिकतर "सम्पदा" पर ही निर्भर करना पड़ता है। कालेजों के विद्यार्थी ही क्या, अन्य लोग भी इस पत्रिका को पढ़कर लाभ उठाते हैं···

"सम्पदा" के प्रत्येक अंक में नयी वस्तु पढ़ने को मिलती है। विशेषांक बहुत ही लाभप्रद होते है।

हमारे कालेज के सभी विद्यार्थी इस पत्रिका को चाव से पढ़ते हैं। फरवरी, १९५७

* * *

परीक्षा में सफलता

"सम्पदा" के ग्राहक (संख्या ११९२) विद्यार्थी श्री लक्ष्मणदास वर्मा अपने १८-९-६२ के पत्र में गणेशगंज, आगरा से लिखते हैं—

—मुझे आपकी पत्रिका ने जो सफलता परीक्षा में दिवाली दी, उसकी सराहना शब्दों में नहीं की जा सकती।

* * *

मैं कितने ग्राहक बनाऊं ?

अहमदाबाद से श्री जवाहर शाह हिम्मतलाल १९-९-६२ के पत्र में लिखते हैं—

मैं "सम्पदा" को बड़ी दिलचस्पी से पढ़ता हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि दूसरों को ग्राहक बनाकर अपने सामयिक का ग्राहक बनूं।

* * *

"सम्पदा" पर छात्र झपटते हैं

बिड़ला कालेज, (राजस्थान) से तृतीय वर्ष के छात्र श्री विजय लिखते हैं—

कालेज के वाचनालय में "सम्पदा" आती है, पर उससे मुझे विशेष लाभ नहीं होता, क्योंकि मेरे सहपाठी "सम्पदा" के आते ही उस पर इतना झपटते हैं कि पढ़ने को मिलती ही नहीं। दो-चार दिनों में ही कुछ चालाक विद्यार्थी उसके उपयोगी लेख फाड़कर ले जाने लगते हैं और मास का अन्त आते तो टाइटिल और विज्ञापन के पृष्ठ ही रह जाते हैं। इसलिए आप मेरे नाम से नीचे लिखे पते पर "सम्पदा" भेजना आरम्भ कर दें।

* * *

श्री श्रणिकलाल जैन, एम-काम इन्दौर—

श्रम समस्याओं के विषय के लिए मैंने व मेरे दोस्तों ने आपके यहां से "सम्पदा" के मजदूर अंक मंगाये हैं। वे बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए।

दिसम्बर, १९५७

* * *

अर्थशास्त्र के अध्यापकों के मत

प्रो. विश्वम्भर नाथ, झरिया

श्री विद्यालंकार जी के कुशल और योग्य सम्पादन की छाप हरेक पन्ने पर है। अनेक लेख पर्याप्त सूचनाओं से युक्त होने के कारण अधिक रुचिकर है।

जनवरी, १९५९

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थशास्त्र के अध्यापक....?

अपनी मौलिकता और अपनी विशेषताएं : विद्वत्तापूर्ण साहित्य : सम्पदा के विशेषांक गीता व बाइबिल के समान : विद्यार्थियों के लिए लाभदायक

डा० कुंज बिहारीलाल भार्गव, संचालक आर्थिकी एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश

—सम्पदा में पिछले कई वर्ष से देखता हूँ और दिन-प्रतिदिन इसे प्रगति के पथ पर बढ़ते देखा है। इसकी अपनी मौलिकता है, अपनी शैलियां हैं और निर्विवाद रूप से वह भली प्रकार से देश की आर्थिक समस्याओं पर प्रकाश डालती रही है। इसका हमारी आज की सामाजिक अर्थ-व्यवस्था में अपना विशिष्ट स्थान है।

* * *

श्री ए० एस० श्रीवास्तव, अर्थशास्त्र अध्यापक, टीकमगढ़ (म० प्र०)

मुझे "सम्पदा" बड़ी उपयोगी लगी है। अब अधिकांश छात्र हिन्दी माध्यम द्वारा पढ़ना पसन्द करते हैं। इसलिए उनके लिए यह पत्रिका बड़ी लाभदायक सिद्ध होती है। "सम्पदा" के विशेषांक भी बड़े मार्के के होते हैं।

* * *

डा० एल० सी० जैन, सागर विश्वविद्यालय (म० प्र०)

अर्थशास्त्र के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालने तथा विद्वत्तापूर्ण और उच्च कोटि के साहित्य के निर्माण में "सम्पदा" बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है।

* * *

श्री राजनारायण गुप्त—

"सम्पदा" ने पिछले वर्षों में जो सफलता प्राप्त की है, वह हिन्दी जगत् के लिए एक गौरव का विषय है।

* * *

प्रो. गिरिराज प्रसाद गुप्त

"सम्पदा" का प्रत्येक अंक मुझे कालेज के ग्रन्थालय में पढ़ने को मिल जाता है। प्रत्येक अंक में नयी सामग्री नया चयन और भरपूर सूचनाएं होती हैं।

अक्तूबर, १९५४

* * *

अर्थशास्त्र के अध्यापक श्री ओम्प्रकाश तोषनीवाल, (हापुड़)—

"सम्पदा" के विशेषांक तो हमारे लिए गीता और बाइबिल के समान हैं।

सम्पदा के विशेषांक

दूसरी व तीसरी योजना अंक, मजदूर अंक, सहकारी कृषि अंक और दशाब्दी अंक की कुछ प्रतियां शेष हैं। ७) रु. भेजकर मंगा लें।

विद्यार्थियों के लिए विशेष सुविधा

अर्थशास्त्र के जो विद्यार्थी प्रिंसिपल का प्रमाणपत्र भेजेंगे, उन्हें मनीआर्डर भेजने पर सम्पदा ७ रुपयों में मिलेगी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'सम्पदा' पर हिन्दी के प्रतिष्ठित पत्रों की सम्मतियां

प्रत्येक अंक ही विशेष अंक : राष्ट्र भाषा की रत्नमणि : हमारे लिए वरदान साहस तथा अध्यवसाय : निष्पक्ष दृष्टिकोण तथा स्वतंत्र विवेचन : यथार्थ में हिन्दी जगत की सम्पदा : प्रत्येक अंक में सूचनात्मक सामग्री।

"सरस्वती" के शास्त्री सम्पादक श्री श्रीनारायण चतुर्वेदी—

'सम्पदा' से हिन्दी का गौरव बढ़ा है। इसने अपने लेखों और टिप्पणियों द्वारा पाठकों को देश की आर्थिक व्यवस्था और अवस्था समझने में बड़ी सहायता की है। इसकी उपयोगिता असंदिग्ध है।"

* * *

"हिन्दुस्तान" दैनिक, नयी दिल्ली

"सम्पदा" विशुद्ध आर्थिक पत्रों की कमी की पूर्ति करने के लिए एक ठोस कदम है। यह स्वागत योग्य प्रयास है।

* * *

नवभारत टाइम्स हिन्दी दैनिक दिल्ली

—लेख-चयन और सम्पादन में विशेष परिश्रम किया जाता है।

* * *

श्री कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर,
सम्पादक "नया जीवन" सहारनपुर

इन दस वर्षों में "सम्पदा" ने तीनों पंचवर्षीय योजनाओं पर तो उत्तम विशेषांक दिये—और भी कई विशेषांक—और सच तो यह है कि उसका हरेक अंक ही अपनी चुनी व सुसम्पादित सामग्री के कारण विशेष अंक रहा। इस सफलता के लिए भाई कृष्णचन्द्र जी को, जो असफलताएं झेलनी पड़ी होंगी, उन्हें तो हम कल्पित भी नहीं कर सकते। पर वे स्थिर रहे, डटे रहे। मैं उनके प्रति अपना अभिवादन प्रकट करता हूँ, इस आशा के साथ कि हर पुस्तकालय और शिक्षा संस्था में "सम्पदा" को स्थान मिलेगा।

* * *

"नया जीवन", मासिक, सहारनपुर

—देश जिस आर्थिक क्रान्ति के दौरान में से गुजर रहा है, उसमें यह प्रकाशन हमारे लिए वरदान है।

* * *

श्री तिलकसिंह, सम्पादक "पांचजन्य" लखनऊ—

"सम्पदा" यथार्थ में हिन्दी जगत की "सम्पदा" है और आर्थिक पत्रों की कमी को पूरा करने का एक बहुत बड़ा साधन है। उसका निष्पक्ष दृष्टिकोण, स्वतंत्र विवेचन तथा समस्याओं को समझने की दृष्टि अनुकरणीय है।

* * *

आजकल (मासिक) के
सम्पादक श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार

सम्पदा हिन्दी की एक श्रेष्ठ अर्थ-सम्बन्धी पत्रिका है। इसके संचालक अत्यन्त साहस तथा पूर्ण अध्यवसाय के साथ यह उपयोगी पत्रिका प्रकाशित कर रहे हैं।

* * *

"विश्व मित्र" (दैनिक), कलकत्ता

"सम्पदा" विद्यार्थियों, व्यापारियों और सर्व साधारण के लिए बहुत उपयोगी है।

* * *

"प्रदीप"—दैनिक पटना

"सम्पदा" का प्रकाशन राष्ट्र भाषा के रत्नमणि भंडारों की अभिवृद्धि की दिशा में एक महान् प्रयत्न है।

* * *

दैनिक "वीर अर्जुन" दिल्ली

—प्रत्येक स्तम्भ में सूचनात्मक सामग्री है। गम्भीर आर्थिक समस्याओं को सरल भाषा में समझाना पत्रकी मुख्य विशेषता है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत के प्रमुख उद्योगपतियों की दृष्टि में 'सम्पदा'

एक महान अभाव की पूर्ति : स्वागत-योग्य प्रयत्न : विशेषांक स्थायी साहित्य की वस्तु : उत्तम पत्रिका : ईस्टर्न इकानामिस्ट का प्रतिरूप : महत्वपूर्ण सेवा :

श्री व्रजमोहन विडला, भू० पू० अध्यक्ष अ० भा० उद्योग व्यापार मण्डल, कलकत्ता—

—"सम्पदा" की उन्नति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ और इसकी सफलता चाहता हूँ।

* * *

श्री शान्तिप्रसाद जैन, भू० पू० अध्यक्ष अ० भा० उद्योग व्यापार मण्डल कलकत्ता—

—मैं "सम्पदा" की विशेष उन्नति चाहता हूँ।

अप्रैल, १९५३

* * *

ला. भरतराम, अध्यक्ष अ० भा० उद्योग व्यापार मण्डल, संचालक दिल्ली क्लाथ मिल्स

—"सम्पदा" हिन्दी में आर्थिक पत्रों के अभाव को पूर्ण करने की दिशा में किया गया स्वागत योग्य प्रयत्न है। इसकी सामग्री विविध तथा सूचना पूर्ण होती है।

अप्रैल, १९५४

* * *

श्री त्रिलोकीनाथ, जनरल मैनजर, दिल्ली क्लाथ मिल्स, दिल्ली—

—आपका पत्र आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में बड़ी भारी कमी को पूर्ण करेगा।

जनवरी, १९५७

* * *

श्री रामप्रसाद पोद्दार, सैंचुरी मिल्स, बम्बई,

"सम्पदा" का प्रत्येक अंक पढ़ने योग्य होता है और विशेषांक स्थायी साहित्य की वस्तु।

अप्रैल, १९५४

* * *

श्री जी० एल० बंसल, सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री—

यह अर्थशास्त्र के विषयों की जानकारी और विचार देकर हिन्दी पाठकों की बहुत महत्वपूर्ण सेवा कर रही है। मैं कामना करता हूँ कि यह चिरकाल तक हिन्दी पाठकों की सेवा करती रहे।

* * *

श्री ताराचन्द साबू, कलकत्ता

समय-समय पर मैं इसे पढ़ता रहता हूँ और मैंने सदा इसे रोचक एवं उपयोगी पाया है।

जनवरी, १९५६

* * *

श्री पद्मपत सिंहानिया उद्योगपति, कानपुर—

यदा-कदा "सम्पदा" देख लिया करता हूँ। यह एक उत्तम पत्रिका है।

जुलाई १९५४

* * *

श्री रामरतन गुप्त, उद्योगपति, कानपुर

"सम्पदा" द्वारा हिन्दी में एक महान् अभाव की पूर्ति सी होती दिखायी पड़ रही है। सामग्री का चयन सुन्दर ढंग से किया गया है।

अप्रैल, १९५३

* * *

श्री हरिश्चन्द्र माथुर, संसद, सदस्य, जोधपुर, राजस्थान

"सम्पदा" अंग्रेजी के आर्थिक पत्र "ईस्टर्न इकानामिस्ट" का प्रतिरूप है।

दिसम्बर, १९५४

* * *

दिल्ली के यशस्वी पत्रकार और जन सम्पर्क, समिति, दिल्ली के अध्यक्ष, श्री गोपीनाथ अमन—

"चाहे हिन्दी ने कितनी ही उन्नति की है, परन्तु अभी तक अर्थशास्त्र जैसे विषयों में अंग्रेजी पत्र ही अग्रसर माने जाते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि "सम्पदा" अपने विषय में अंग्रेजी पत्रों से पीछे नहीं है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

केन्द्र व राज्यों के मंत्रियों की दृष्टि में 'सम्पदा'

विश्लेषणात्मक व उपयोगी लेख : व्यावहारिक व ठोस सामग्री : राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान : महत्त्वपूर्ण सफलता : उपयोगिता व महत्त्व का कायल : सन्तुलित विचारों की छाप : बहुत विचारपूर्ण व सुसम्पादित पत्रिका ।

श्री लालबहादुर शास्त्री, गृह मंत्री

—हिन्दी समाचार पत्र जगत् में अर्थशास्त्र सम्बन्धी कुछ गिने चुने पत्र ही हैं । "सम्पदा" मासिक हिन्दी पाठकों को इस दिशा में पिछले ११ वर्षों से सेवा कर रही है । "सम्पदा" के लेख विश्लेषणात्मक तथा उपयोगी होते हैं ।

जनवरी, १९५९

* * *

श्री गुलजारीलाल नन्दा, योजना मंत्री

"इस पत्रिका में आर्थिक समस्याओं के विभिन्न दृष्टिकोणों का ही समावेश है । अतः मेरा मत है कि यह पत्रिका उन लोगों के लिए उपयोगी होगी, जिनका सम्बन्ध योजनाओं के प्रचार और क्रियान्वयन से है ।

जनवरी, १९६२

* * *

श्री श्रीमन्नारायण, सदस्य योजना आयोग

—आर्थिक विषयों में "सम्पदा" द्वारा हिन्दी साहित्य को जो लाभ मिला है, उसके लिए बधाई देता हूँ ।

जनवरी, १९५९

* * *

श्री जगजीवनराम, रेलवे मंत्री भारत सरकार—

इस पत्र ने अपने पाठकों में आर्थिक चैतन्य उत्पन्न करके राष्ट्रीय उत्थान में योगदान कर प्रशंसनीय कार्य किया है ।

जनवरी, १९५८

* * *

श्री व्यंकटेश विष्णु द्रविड़, श्रम मंत्री, मध्यप्रदेश—

आर्थिक विषयों के पत्रों में "सम्पदा" ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । यह कोई साधारण सफलता नहीं है । मुझे "सम्पदा" के प्रारम्भ से ही उसके अंकों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । मैं प्रत्येक सुशिक्षित हिन्दी भाषी व्यक्ति का यह कर्त्तव्य समझता हूँ कि वह इस को अपना यथासम्भव सहयोग दे ।"

* * *

श्री अमरनाथ विद्यालंकार, शिक्षा मंत्री, पंजाब

—"सम्पदा" के जितने अंक मेरी नजरों से गुजरे उन्हें मैंने अत्यन्त उपयोगी और उच्च कोटि के लेखों पूर्ण पाया है ।

जनवरी, १९

* * *

श्री मोहनलाल सुखाडिया, मुख्य मंत्री, राजस्थान

हिन्दी क्षेत्र में प्रकाशित होने वाले आर्थिक मासि पत्रों में "सम्पदा" का प्रमुख स्थान है । सम्पूर्ण देश चल रही आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की प्रवृत्तियों सम्बन्ध में इसने सदैव व्यावहारिक एवं ठोस सामग्री पाठकों के समक्ष प्रेषित की है ।

* * *

श्री मिश्रीलाल गंगवाल भोपाल, (म० प्र०)—

"सम्पदा" के जन्म से ही उसके प्रति मेरा स्वाभाविक ममत्व रहा है । मैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हि मासिक पत्र के रूप में उसकी उपयोगिता और महत्व कायल हूँ । और इससे भी अधिक प्रशंसक रहा हूँ प्रति आपकी आस्था और निष्ठा का ।

* * *

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्तमंत्री, राजस्थान—

आरम्भ से ही आपके स्वस्थ और सन्तु विचारों की छाप सम्पदा पर है । "सम्पदा" बहुत विचा और सुसम्पादित पत्रिका है ।

* * *

श्री श्रीप्रकाश, राज्यपाल, मद्रास

मुझे आशा है "सम्पदा" हमारे देश और समाज अनेक आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में समर्थ होगी ।

दिसम्बर, १९

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

What eminent economists, industrialists and journals say about Sampada

Greatly impressed : A bold venture : Standard comparing English journals : New lead to Hindi journalism :

I was greatly impressed by the standard of this publication.

—*Gulzari Lal Nanda.*

* * *

Shri Vidyalankar's efforts in bringing out "Sampada" is a continuing sacrifice—constructive and full of understanding, Those who will read the journal will find that it maintains a standard which can compare favourably with other similiar journals in English, barrring the get up. It is a tragedy that those who try to bring out standard material have to suffer hardships, simply because they are forming the material in Hindi.

—*Shri U. N. Dhebar, Ex-President, All India Congress 10.1.1963.*

* * *

It fills a want in Hindi commercial literature.

—*R. G. Saraiya.*

* * *

"Sampada" has given a new lead to country.

—*Shri Padampal Singhania, Kanpur, —January, 1957.*

* * *

Congratulations to the Editor, great pains have been taken for this special number.

—*Sh. G. D. Birla, January 1957,*

* * *

Welcome efforts. My congratulation in bringing out this standard publication.

—*Lala Bharat Ram, President F. I. C. C. I.*

* * *

I wish your magazine every success in its endeavour to spread knowledge of industry amongst its readers.

—*Sh. Brijmohan Birla, July 1954,*

* * *

I was very much pleased that efforts are being made for bringing out a journal in Hindi containing information about the industrial statistics and development in the country.

—*N. L. Kanodia, Calcutta.*

July 1954,

* * *

I hope, your monthly shall receive all possible encouragement from the industrial and commercial establishment.

—*Sh. P. D. Singhania, Kanpur.*

September 1954,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

What eminent economists . . . .

Great pains, : standard publication : new venture in Hindi World : high quality : a wealth of useful imformation

A bold venture in Hindi Journalism 'Sampada' deals comprehensively with economic information. It deserves support.

—*The Eastern Economist, New Delhi.*

* * *

All this makes this number (Bhoomi-Sudhar Ank) almost a reference number and deserves a place in all librarie's and on every social worker's and patriot's table.

—*The "Marhatta", (Weekly), Poona.*

* * *

'Sampada' is the best guide for digesting and understanding the economic situation of the country.

—*"Commerce and Industry"*
January 1957, New Delhi.

* * *

Hindi readers will benefit immensely from this publication.

—*"Organiser" (Weekly),*
January 1957, Delhi.

* * *

The number would help the readers in finding his place and aspiration in the national economy. The magazine has been well brought out and is finely printed.

—*"Thought" (Weekly),*
January 1957, Delhi.

* * *

The "Sampada" is a journal devoted to the economic problems of the country. It claims to make a new venture in the Hindi world.

—*'Search Light' (Daily),*
Januury 1957, Patna.

* * *

From the subject dealt with in the various articles (Mazdoor Ank) which are informative and cover wide range. I discern catholicity of out-look which is essential for maintaining an objective angle.

—*Sh. V. K. R. Menon,*
Directot I.L.O.,
January, 1957, India Branch, New Delhi

* * *

Your economic journal is of a high quality.

—*P. C. Jain, Allahabad University*

* * *

It contains a wealth of useful information.

—*Sh. Gaj Raj Singh*
Ex-Director of Education
Rajasthan.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आप चाहे कुछ भी काम क्यों न करते हों...

आपका काम
देश के लिए
किया गया काम है।

आप, आपका काम, आपका जीवन सभी कुछ उस भारत के अभिन्न अंग हैं जो आज कुशलता तथा शक्ति बढ़ाने के काम में जी जान से जुटा है। इस वक्त ढील-ढाल या अकुशलता के लिए कोई जगह नहीं है। आपका काम चाहे कुछ भी क्यों न हो, वह पूरी चतुराई और उत्तम ढंग से होना चाहिए। काम में रुकावट या कोई और अड़चन न आने दें और कुछ भी ज़ाया न करें। पूरी कुशलता से पूरी शक्ति से अपने काम में लगे रहें। विजय आप सरीखे लाखों-करोड़ों लोगों की कठोर मेहनत का ही फल होती है।

DAV—63/70

जी तोड़ मेहनत करें

अधिक उत्पादन और सुदृढ़ रक्षा के लिए

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस अवसर पर आकर्षक वेशभूषा के लिए

GWALIOR RAYON FABRICS

ग्वालियर रेयॉन

टैरिलीन
(आई० सी० आई०)
पॉलियेस्टर फाइबर

'TERYLENE'
Polyester ICI Fibre

सूटिंग्स
उपयुक्त एवं उत्कृष्ट पहनावा है

NPS/GRI/50

सम्पादक—कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा नवचेतन प्रेस (प्रा०) लि० (ओजिज ऑफ अर्जुन प्रेस) दिल्ली-६ से मुद्रित
अशोक प्रकाशन मन्दिर, २६/२१, रूपनगर, दिल्ली-६ से प्रकाशित।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा

वर्ष १२ : अंक ६
जून, १९६३

अशोक प्रकाशन मन्दिर शक्ति नगर, दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आप चाहे कुछ भी काम क्यों न करते हों...

आपका काम
देश के लिए
किया गया काम है

आप, आपका काम, आपका जीवन सभी कुछ उस भारत के अभिन्न अंग हैं जो आज कुशलता तथा शक्ति बढ़ाने में जी जान से जुटा है। आपका काम चाहे कुछ भी क्यों न हो, वह पूरी मुस्तैदी व दक्षता से होना चाहिए। काम में रुकावट या देर न होने दें। विजय आप सरीखे लाखों-करोड़ों लोगों की कठोर मेहनत का ही फल होती है।

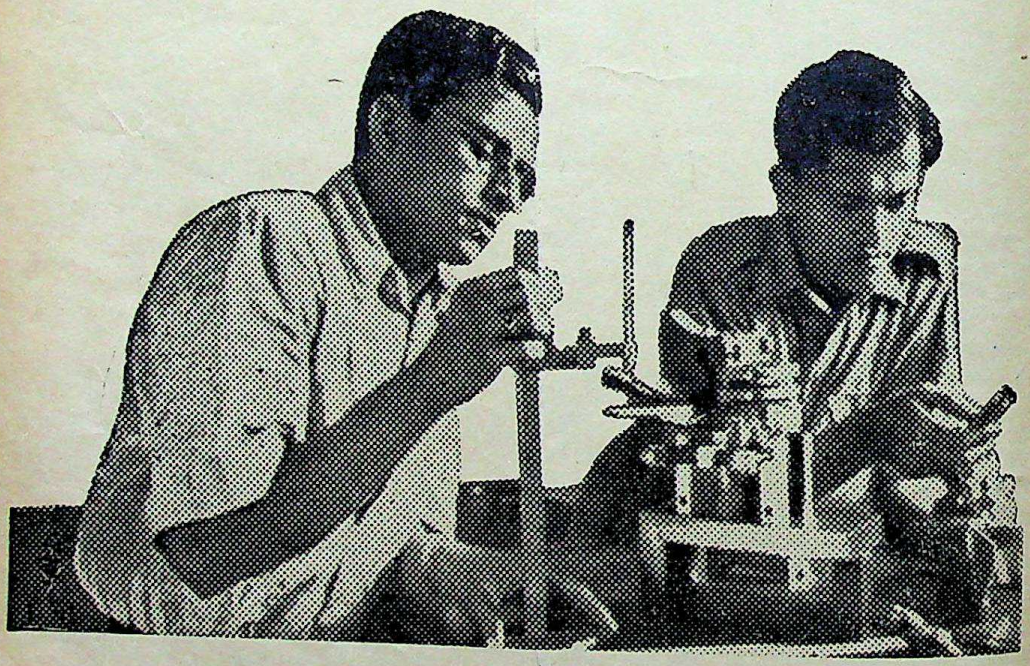

जी तोड़ मेहनत करें

भारत के विकास और देश की रक्षा के लिए

DA—63/F2

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

13 JUN 1963

सारे परिवार के लिए

डी सी एम

के उच्च कोटि के कपड़े

पापलिन •	छीटें •	मलमल
लिनो •	लान्स •	लट्ठा
साड़ियाँ •	शर्टिंग्ज •	ड्रिल्स
शर्टिंग्ज •	सजावट के कपड़े •	तौलिए

एवं बेड शीट्स आदि

आकर्षक रंगों, शेडों और बनावटों में

डी सी एम के सभी रिटेल स्टोर्स में प्राप्य है ।

डी सी एम वस्त्रोत्पादन में श्रेष्ठता का प्रतीक

दि दिल्ली क्लॉथ एण्ड जनरल मिल्स कं० लि०

दिल्ली

JWT : DCM : 2290

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विषय-सूची

सं०	विषय	पृष्ठ
१.	श्रम की नई प्रवृत्तियां	२६५
२.	सम्पादकीय टिप्पणियां	२६७
३.	विकासशील अर्थव्यवस्थ में कराधान — श्री रुस्तम सी. कपूर	२७१
४.	जापान का उन्नतिशील वस्त्र-उद्योग — श्री ए. एन. बुच	२७४
५.	आधी दुनिया को भरपेट भोजन भी नहीं	२७५
६.	योजना के लक्ष्यों से कम उत्पादन — श्री नरोत्तम शाह	२७६
७.	टैनेसी घाटी की प्रगति — श्री ब्रेगनर	२७९
८.	हमारा सांख्यकी पृष्ठ	२८२
९.	सहकारी आंदोलन व पंचवर्षीय योजना — श्री एस. पी. वार्ष्णेय	२८३
१०.	अमेरिका में भी निर्धनता पर···? — श्री के. वी. माधव	२८६
११.	आपत्तिकाल में मूल्य निर्धारण — श्री परसराम मनवानी	२८[illegible]
१२.	कागज उद्योग — श्री सरदारमल जैन	२९[illegible]
१३.	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष	२९[illegible]
१४.	बढ़ते ऋणों की समस्या — आचार्य विनोबा	२९[illegible]
१५.	कितनी कम आय — श्री उ. न. ढेबर	२९[illegible]
१६.	रेलों की बढ़ती हुई क्षमता — श्री कृपाल सिंह	२९[illegible]
१७.	भूमिहीन मजदूरों की समस्या — श्री बालकृष्ण	२९[illegible]
१८.	हमारे उद्योग—बिजली, मंहगाई, परामर्श, राष्ट्रीय आय व उद्योग, अधिकांश समय खाली	३०[illegible]
१९.	इस मास की प्रमुख घटनाएं	३०[illegible]

★ ★ ★

अगस्त में दिल्ली विकास अंक

यह विशेषांक आगामी स्वाधीनता दिवस–१५ अगस्त को प्रकाशित होगा। इसे अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए बहुत संभवत जुलाई का अंक जुलाई में प्रकाशित न होकर अगस्त के अंक के साथ संयुक्त रूप में प्रकाशित हो। इस प्रकार पाठकों को अधिक से अधिक उत्तम सामग्री मिलेगी। आशा है। जुलाई का अंक यदि न निकले, पाठक क्षमा करेंगे।

व्यवस्थापक
"सम्पदा"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वर्ष : १२
अंक : ६
जून : १९६३

सम्पादकीय

श्रमिकों की नई प्रवृत्तियां

जयपुर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ का १४वां वार्षिक अधिवेशन हुआ है। उसकी समस्त कार्यवही पर एक दृष्टि डालने से दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली तो यह कि अब मजदूर नेताओं में सरकारी उद्योगों के प्रति असन्तोष बढ़ता जा रहा है। अनेक वक्ताओं ने, जिनमें भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम मन्त्री श्री खण्डूभाई देसाई प्रमुख हैं, सरकारी उद्योगों की कठोर आलोचना की। उन्होंने कहा कि एक अरसे से सरकारी उद्योगों में बड़ी धांधली चल रही है। इनके उच्च अधिकारी इतनी लापरवाही बरतते हैं कि उससे सार्वजनिक उद्योग के प्रति न जनता का कोई आकर्षण रहा है और न श्रमिकों का अफसोस तो यह है कि सरकारी उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों में निजी उद्योगों के श्रमिकों की अपेक्षा भी अधिक असन्तोष है। निजी उद्योगों का जो हाल २०-२५ वर्ष पूर्व था, वही हाल आज सरकारी उद्योग का है। सार्वजनिक उद्योग के कर्ताधर्ता समझते हैं कि सरकार उनकी है, पुलिस, फौज उनकी, है। जैसा वे करेंगे, उसका समर्थन करने वाले मिनिस्टर भी राज्य और केन्द्रीय सरकार में बैठे हैं। इसलिए वे श्रमिकों के साथ गैरजुम्मेदाराना व्यवहार करते हैं। उनकी मनमानियों से श्रमिकों में सरकारी उद्योग के खिलाफ जो असन्तोष रूपी ज्वाला सुलगी अन्दर ही अन्दर सुलग रहा है, न जाने कब वह विस्फोटक रूप धारण कर ले।

अपने भाषण में सार्वजनिक उद्योग के प्रति इन्टक के गम्भीर असन्तोष का कारण बताते हुए एक नये रहस्य का भी उन्होंने उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि यदि कम्युनिस्ट कार्यकर्ता जरा भी ऊधम या हुड़दंगबाजी करते हैं तो अधिकारी उनकी बात मान लेते हैं, जबकि इन्टक के रचनात्मक सुझावों को भी अस्वीकृत कर दिया जाता है। सार्वजनिक उद्योगों में इन्टक युनियनों को मान्यता तक नहीं दी जाती। वहां के अधिकारी तो इन्टक और कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को आपस में भिड़ाने का भी काम करते हैं। अन्य अनेक वक्ताओं ने भी सार्वजनिक उद्योगों के प्रति गम्भीर असन्तोष प्रकट किया।

आज से कुछ वर्ष पूर्व एक सरकारी उद्योग में की गई हड़ताल के सम्बन्ध में, जो कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं द्वारा संगठित की गई थी, पं० जवाहरलाल नेहरू ने उसे पीठ में छुरा घोंपना कहा था। इन्टक के कार्यकर्ताओं को कोई देशद्रोही या अनुत्तरदायी नहीं कह सकता। यदि उनके उत्तरदायी नेता भी सरकारी उद्योगों की कठोर आलोचना करते हैं, तो यह समझ लेना चाहिए कि वस्तुतः उनमें कोई बड़ी खराबी है और वह खराबी निजी उद्योगों को गाली देने से दूर नहीं हो सकती। भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय को गम्भीरता पूर्वक यह सोचना चाहिए कि सरकारी उद्योगों में श्रम सम्बन्धी नियमों का पालन क्यों नहीं होता? अधिकारियों की श्रम के सम्बन्ध में धारणा ही अच्छी नहीं है अथवा वे श्रम नियमों का पालन करने में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। यदि श्रम-सम्बन्धी नियमों में ही कोई ऐसा दोष है, जो आदर्शवादिता के उत्साह में आ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गया है तो उसे दूर करना उसका कर्तव्य है।

अब तक सरकार उद्योग और श्रम के विवाद में मध्यस्थ का काम करती थी, किन्तु जब से उसने स्वयं उद्योग-संचालन का उत्तरदायित्व लेना शुरू किया है जब से वह मध्यस्थ या निर्णायक के ऊंचे पद से नीचे आकर स्वयं भी एक पक्ष या पार्टी बन गई है। अब मजदूर उससे न्याय करने की भिक्षा नहीं करता, बल्कि अपना विरोधी दल मान कर उससे भी संघर्ष करना चाहता है। इन्टक का यह अधिवेशन इसका एक स्पष्ट प्रमाण है, यद्यपि इसके अधिकांश नेता कांग्रेस के सदा समर्थक रहे हैं और आज भी हैं।

इसी प्रसंग में एक प्रश्न यह उठता है कि समाजवाद क्या है, और क्या समाजवाद से—उद्योगों के राष्ट्रीय करण मात्र से—श्रमिकों की समस्याएं दूर हो जायंगी ? सब उद्योगों का बिना विवेक के राष्ट्रीयकरण समाजवाद नहीं है। समाजवाद वस्तुतः एक भावना का नाम है, जिसमें श्रमिक के प्रति न्याय, समानता और उदार व्यवहार अनिवार्य माना जाता है। कोई उद्योग निजी है या सरकारी है, यह न समाजवाद की कसौटी है और न श्रमिकों के साथ उचित न्याय की ! यदि समाजवाद से केवल उद्योगों का राष्ट्रीयकरण ही अभिप्रेत हो, तो यह समाजवाद के साथ अन्याय करना होगा। इन्टक के इस अधिवेशन से यह कुछ अधिक स्पष्ट हो गया है

इन्टक के जयपुर अधिवेशन में एक दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया गया है। इस प्रस्ताव का आशय यह है कि कम्युनिस्टों द्वारा संचालित ट्रेड युनियन कांग्रेस का सम्बन्ध उस अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ (डब्ल्यू. एफ. टी. यू.) से है, जिसका एक सदस्य भारत पर निर्लज्जता पूर्वक आक्रमण करने वाला चीन भी है। कम्युनिस्ट नेता चीन से किसी रूप में सम्बन्ध रखें, यह राष्ट्र द्रोह का ही एक प्रतीक है। अ. भा. ट्रेड युनियन कांग्रेस कम्यूनिस्ट पार्टी की ही एक अंगभूत संस्था है। की यह प्रतिज्ञा है कि कम्युनिज्म का विस्तार समूचे संसार में किया जाए। उसका राष्ट्रीय सीमाओं में विश्वास नहीं है। इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि राष्ट्रवादी और कम्युनिस्ट अपने आप में परस्पर विरोधी शब्द हैं। कोई भी कम्युनिस्ट राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। फिर ट्रेड यूनियन कांग्रेस मजदूर सदस्यों की दृष्टि से भी अल्पमत में है। इसलिए सरकार से इस प्रस्ताव में यह मांग की गई है कि वह केवल इन्टक ही को मान्यता प्रदान करे, जो कि सबसे अधिक प्रातिनिधिक है और जिसके तात्कालिक और अन्तिम लक्ष्य राष्ट्र हित के विरुद्ध नहीं हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था (आई. एल. ओ.) में प्रतिनिधित्व का यही प्रतिमान स्वीकार किया जाता है। देश के अन्दर भी प्लान्ट स्तर पर मान्यता की दृष्टि से उसी यूनियन को मान्यता दी जाती है, जिसका बहुमत हो।

जहां तक युक्ति क्रम का सम्बन्ध है, इन्टक का यह प्रस्ताव असंगत नहीं है। लेकिन व्यवहार दृष्टि से इसे अमल में लाने से बहुत कठिनाइयां पैदा होंगी। सरकार ट्रेड यूनियन कांग्रेस की मान्यता समाप्त करें, इसके लिए यह भी आवश्यक है कि देश में उसका प्रभाव भी बहुत कम हो। अब भी देश के बहुत से मजदूर कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं के प्रभाव में हैं। स्वयं इन्टक को ही यह शिकायत है कि सरकारी उद्योगों के अधिकारी कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं का अधिक आदर करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाणों के होते हुए भी सरकार ने अभीतक किन्हीं कारणों से कम्युनिस्ट पार्टी को राष्ट्रद्रोही मान कर उस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। ऐसी स्थिति में वह उनकी मजदूर संस्था को मान्यता देने से कैसे इन्कार कर सकती है ? जब कांग्रेस, विधान सभा व संसद् के चुनावों में कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग का हार्दिक स्वागत करती है, तब उससे यह आशा भी नहीं की जानी चाहिए कि वह इन्टक का प्रस्ताव स्वीकार कर लेगी। इंटक के नेताओं को अपने पैरों पर स्वयं खड़े होना चाहिए और मजदूरों में अपनी सेवाओं के द्वारा इतना प्रभाव स्थापित कर लेना चाहिए कि वे कम्युनिस्टों के प्रभाव से मुक्त हो सकें।

तीसरे वर्ष की सहायता

भारत मित्र सहायक देशों की चिर प्रतीक्षित बैठक [illegible] जून को हो गई। इसमें ६१॥ करोड़ डालर की सहायता भारत को इस वर्ष देने का निश्चय किया गया। इस बैठक में विश्व बैंक के अतिरिक्त अमरीका, आस्ट्रेलिया, इटली,

सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम और नीदरलैंड के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। भारतवर्ष ने १२ करोड़ डालर की मांग की थी। इस निश्चय का एक पहलु यह है कि यह राशि पिछले दो वर्षों की अपेक्षा कम है। पहले दो वर्षों में यह सहायता क्रमशः १२९.५० करोड़ व १०७ करोड़ डालर की मिली थी। इस तरह यह सहायता निरन्तर कम होती गई है।

लेकिन इसका दूसरा एक पहलू भी है।

इस बैठक से पहले भारत सरकार ने यह सुझाव रखा था कि यदि एक देश किसी निश्चित योजना के लिए सहायता देता है तो भारत पर से यह पाबन्दी उठा ली जाए कि उसी देश से उस योजना के लिए माल लिया जाए। इसे स्वीकृति प्राप्त हो गई है। अधिकांश सहायता बिना विशेष प्रयोजन के दी जायगी, जिससे भारत आवश्यकतानुसार उसका उपयोग कर सकेगा। यह सम्मेलन इस बात पर भी सहमत हो गया है कि चौथी योजना के लिए वह प्रारम्भिक व्यय भारत को देगा, क्योंकि विकास तो एक लम्बी श्रृंखला है। चौथी योजना के लिए तैयारी तीसरी के समाप्त होने से पहले ही कर लेनी चाहिए। अमेरिका ने इस बात पर बल दिया है कि विकास एक लम्बी श्रृंखला है, इसलिए भारत को जो सहायता दी जाय, वह नाम मात्र के ब्याज पर दी जाय। इसे भी सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया है। इससे भी भारत को काफी सहायता मिल जायगी।

ब्रिटेन व जर्मनी ने पहले वर्ष में क्रमशः २२.५ करोड़ और १८.२ करोड़ डालर की सहायता दी थी। दूसरे वर्ष कुछ कमी कर ली गई। यदि ये दोनों देश ही प्रथम वर्ष की भांति सहायता देते, तो भारत की मांग पूरी हो जाती। केवल जापान ऐसा देश है जिसने इस वर्ष अपनी सहायता की राशि बढ़ा दी है। गत वर्ष उसने ५५ करोड़ डालर सहायता दी थी। अब वह ६० करोड़ डालर देगा। विश्व बैंक ने २ करोड़ डालर अधिक सहायता देने का वचन दिया है।

अभी जुलाई में फिर इन देशों की वाशिंगटन में बैठक होगी। इसमें इस राशि के बढ़ाये जाने की सम्भावना है। हमारी आवश्यकताएं जितनी विशाल हैं, उतनी सहायता मिले, यह हम आशा भी नहीं कर सकते और विशेषकर जबकि हम अमेरिका व ब्रिटेन आदि से प्रतिरक्षा के कार्य में भी विपुल सहायता चाहते हैं।

•

बोकारो एक पहेली

बोकारो का प्रस्तावित कारखाना भी एक अजीब पहेली बन गया है। इसके सम्बन्ध में अमेरीका कोई अन्तिम निर्णय ही नहीं कर पाता। वह बार-बार आशा दिलाता है, लेकिन अभी और विचार की आवश्यकता है, यह कह कर निर्णय को अनिश्चित कर देता है। स्वयं राष्ट्रपति कनैडी का आश्वासन भी अभी तक अन्तिम निश्चय में सहायक नहीं हुआ। बोकारो का इस्पात का कारखाना अमेरिकी सहयोग से बनने की योजना है। अमेरिकन विशेषज्ञों की टोली ने कुछ सुझाव यातायात, कच्चे माल और प्रबन्ध के सम्बन्ध में दिये थे। इसी कारण बोकारो के प्रबन्ध के लिए हिन्दुस्तान स्टील लि० से अलग संस्था बनाने का प्रस्ताव किया गया है। उसके अन्य भी सुझावों पर अनुकूल विचार किया गया है। श्री कृष्णमाचारी ने अमेरीका जाकर उसके सन्देहों को दूर करने का प्रयत्न किया है। इस योजना की सम्भावनाओं पर फिर से जांच पड़ताल करने की बात से भारत सरकार के मन्त्री श्री सुब्रमण्यम इतने खिन्न हुए हैं कि उन्होंने एक भाषण में यहां तक कह दिया है कि बोकारो का कारखाना तो बनेगा, भले ही अमेरिका का सहयोग प्राप्त हो या न हो। अमेरिका को यदि सहयोग नहीं देना है तो स्पष्ट इनकार कर दे। इस तरह २ वर्षों से इस मामले को लटकाते रहने का कोई अर्थ नहीं है। जो कुछ करना है, हां या नहीं में तुरन्त जवाब मिलना चाहिए यदि १९६८ तक इस कारखाने से १४ लाख टन इस्पात पैदा करना है, तो इस एक आध महीने में ही कार्य प्रारम्भ हो जाना चाहिए। एक तरफ अमेरिका भारत को प्रशंसनीय सहायता दे रहा है, दूसरी तरफ बोकारो के बारे में लगातार टालमटोल कर रहा है। इन दोनों बातों में परस्पर कोई संगति नहीं है।

तमाखु का योजना में स्थान

योजना का सीधा साधा अर्थ यह है कि देश की कुल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आवश्यकताओं का यथासम्भव ठीक-ठीक अनुमान किया जाए और इसके बाद अपने साधनों को देखते हुए उपयोगिता की दृष्टि से उनकी पूर्ति का यथा क्रम प्रबन्ध किया जाए। इसका अर्थ यह है कि जो चीज जितनी आवश्यक हो, उसको उतनी प्राथमिकता दी जाए और जो चीज जितनी कम आवश्यक हो, उतना ही उसे बाद में लिया जाए।

साधारणतः अर्थ शास्त्र जनता की भौतिक आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति के सम्बन्ध में विचार करता है। किन्तु वस्तुतः यदि अर्थ शास्त्र मानव समाज के हित के लिए है, तो उसे नैतिक व हित की दृष्टि से भी उसकी आवश्यकता का विवेचन करना होगा। उपयोगिता और आवश्यकता की कसौटी को नैतिकता और स्वास्थ्य तथा चरित्र से अलग नहीं किया जा सकता। केवल विशुद्ध आर्थिक दृष्टि से विचार करना एकांगी हो होगा। योजना आयोग को भी प्राथमिकता का निर्धारण करते हुए सिर्फ भौतिक दृष्टि से विचार नहीं करना चाहिए। सर्वोदय के विचारकों की दृष्टि से इसी लिए तम्बाकू की खेती और उस पर जनधन की अपार शक्ति का व्यय देश के अन्न सकंट का एक कारण है।

आज देश में तम्बाकू की खेती का क्षेत्रफल ४१४.८ हजार हैक्टेयर(एक हैक्टेयर करीब २॥ एकड़) है। तम्बाकू के निर्यात से देश को विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। इस उद्योग में लगे हुए लोगों की संख्या भी कम नहीं है किन्तु ये तथ्य ही तम्बाकू को प्राथमिकता देने के पर्याप्त कारण नहीं हो सकते। तम्बाकू जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ नहीं है। इसके विपरीत वह समाज में बहुत प्रचलित होने के बावजूद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसी स्थिति में यदि एक एकड़ क्षेत्र में तम्बाकू न बोकर अनाज बोया जाए, तो इसका देश को लाभ ही होगा। सरकार मितव्यय के लिए विलास की वस्तुओं पर कुछ न कुछ प्रतिबन्ध लगाती है। तम्बाकू सब गरीब पीते हैं, यह कहने से जीवन के लिए अनिवार्य वस्तु नहीं हो जाती। यदि तम्बाकू से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, तो उसके स्थान पर अनाज बोकर विदेशों से मगाये जाने वाले अनाज में कमी करके विदेशी मुद्रा बचाई भी जा सकती है। किन्तु इसके विपरीत तीसरी योजना में २५ हजार टन अतिरिक्त तमाखू उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कितनी अतिरिक्त भूमि और कितने अतिरिक्त साधन व्यय होंगे इसके अंक हमारे पास नहीं हैं। आज ऊपर से लेकर छोटे व्यक्ति तक सभी तम्बाकू के व्यसन के शिकार है। यदि इसको रोकने के लिए सरकार और सामाजिक संस्थाएं सहयोग पूर्वक देश में एक अभियान जारी करें, तो देश के करोड़ों रु० बच सकते हैं। अनाज भी अधिक पैदा हो सकता है। उपर्युक्त दृष्टि से हम योजना आयोग के सदस्यों, देश के प्रशासकों और अर्थशास्त्रियों से इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने का अनुरोध करना चाहते है। देश की कितनी जन और श्रम शक्ति तथा अपार साधन इस कार्य में व्यय हो रहे हैं, जो नैतिक और स्वास्थ्य सम्बन्धी दृष्टि से लाभ कारी नहीं है। इसी प्रसंग में हमें अर्थ शास्त्र के क्षेत्र और उसकी कसौटी कर भी पुनः विचार करना होगा। इस दृष्टि के अभाव के करण ही म. गांधी बर्तमान अर्थशास्त्र को 'अनर्थ शास्त्र' कहते थे। ● ०

सूती मिलों में उत्पादन व्यय

शेयरों के मूल्य वस्तुतः एक ऐसा थर्मामीटर है, जिससे किसी उद्योग की स्थिति और भविष्य का अध्ययन हो सकता है। जब भविष्य अच्छा हो और लाभ की संभावना हो तो शेयरों का बाजार ऊंचा हो जाता है, अन्यथा मूल्यों का स्तर नीचे गिर जाता है। कुछ दिन पूर्व कपड़ा मिलों के शेयरों की निम्नलिखित तालिका पत्रों में प्रकाशित हुई थी—

(शेयर रुपयों में)

कम्पनी का नाम	२९-५-६३	एक वर्ष पूर्व	दो वर्ष पूर्व
बोम्बे डाइंग	६१.००	६९.७०	६६.२०
सैंचुरी	५५७.००	६६४.००	६७३.००
स्टैण्डर्ड	८०२.००	१०२५.००	१५४८.००
श्री अम्बिका	१,१५५.००	१४४६.००	१३२९.००
कैलिको	७३४.००	१११८.००	१११०.५०
दिल्ली क्लाथ	४२.१२	५७.००	४४.००
केशवराम काटन	२८.००	३२.४४	३४.००

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस तालिका से यह स्पष्ट है कि एक या दो वर्ष पूर्व के स्तर से आज शेयरों के मूल्य बहुत कम हैं। इसका अर्थ यह है कि लोग कपड़ा उद्योग में कम दिलचस्पी लेने लगे हैं, क्योंकि कपड़ा उद्योग से पहले की अपेक्षा कम लाभ मिल रहा है। इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तरफ कपड़े का उत्पादन व्यय बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ बिक्री में तेजी नहीं आ रही है। १९६२ में मिलों को १९६१ की अपेक्षा कम लाभ हुआ है और आज जिस अवस्था में से मिलें गुजर रही हैं, उसे देखते हुए यह भय हो रहा है कि मिलों को इस वर्ष नुकसान न हो।

कुछ दिन पूर्व बम्बई में इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष लाला भरतराम ने बढ़ते हुए उत्पादन व्यय के कारणों की चर्चा करते हुए कहा था :

'भारतीय कपास के उच्चतम मूल्य १२५ रु० प्रति गांठ बढ़ा दिए गए हैं। विदेशी कपास पर ३८.१२ रु० प्रति गांठ आयात कर लगा दिया गया है। कच्चे माल और स्टोर के सामान की कीमतें बढ़ गई हैं। वेतन बिल में भी काफी वृद्धि हुई है। जनवरी १९६२ से मजदूरों की तनख्वाह २ रुपए प्रति मास बढ़ा दी गई है। महंगाई भत्ता भी बढ़ गया है। स्टेट इन्श्योरेंस स्कीम के मातहत मिलों का देय भाग १। से २॥ प्रतिशत कर दिया गया है। किराए के केन्द्रों में बिजली पर कर बढ़ा दिए गए हैं। रंगों और रासायनिक पदार्थों की कीमतें चढ़ गई हैं।

'इसके अतिरिक्त युद्धकालीन खतरा बीमा और अन्तः राज्यीय बिक्री कर में वृद्धि से भी उत्पादन व्यय बढ़ गया है। सब आयातित पदार्थों पर आयात कर बढ़ा दिए गए हैं। उधर राज्य सरकारें भी अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए

गणेश

डिलाइट फैन

क्वालिटी में बिना मुकाबले का
चलने में बहुत बढ़िया

आज ही एक खरीदें

दि गणेश फ्लोर मिल्स क० लि०

६४-६५ नजफगढ रोड़, नयी दिल्ली—१५

सोल एजेन्टस :—दिल्ली-ओरयिन्टल इलैक्ट्रिक कं०, भागीरथ पेलेस, चांदनी चौक, फोन—२२५६४४

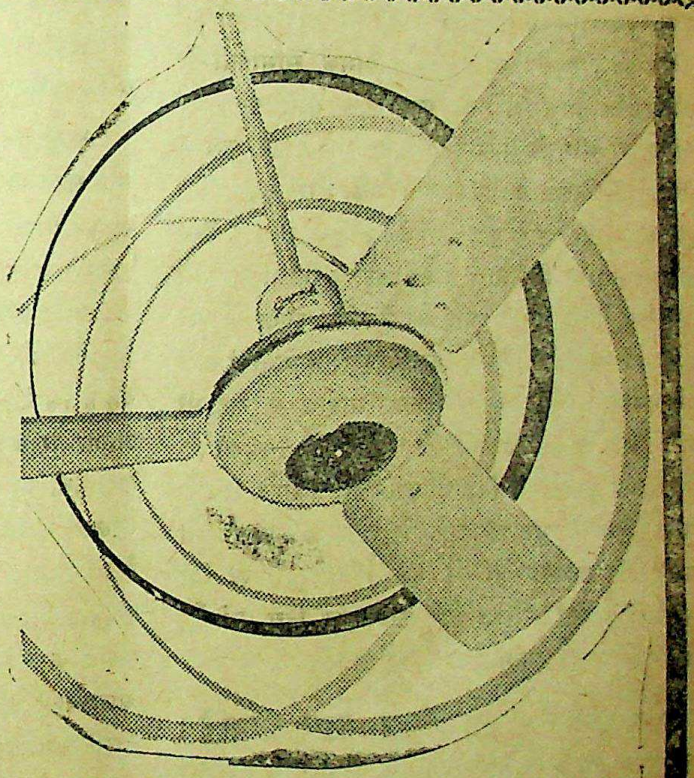

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कपास और मिल स्टोर पर बिक्री कर बढ़ा रही हैं। ट्रकों के यातायात आदि पर भी कर लग रहे हैं।'

फैडरेशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि कपड़े के मूल्य नियत करते समय इन सब बातों पर भी विचार किया जाए। टैरिफ कमीशन शीघ्र ही सरकार को वस्त्र के उत्पादन-व्यय के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट में कोई सुझाव पेश करने वाला है। देखना यह है कि यह वस्त्र का कितना उत्पादन-व्यय और कितना उचित मूल्य निर्धारित करता है।

सहकारी समितियों की विशाल योजना

भारत सरकार ने बढ़ती हुई मंहगाई को रोकने के लिये यह प्रस्ताव किया है कि स्थान स्थान पर सहकारी समितियों द्वारा जनता को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध हों। यह योजना बहुत बड़ी है। इसमें दस करोड़ रुपया व्यय होगा। समस्त देश में दो सौ स्टोर थोक बिक्री के लिये खोले जायेंगे, जो ४००० प्राथमिक समितियों को सामान देंगे। थोक स्टोरों की एक लाख रुपये की शेयर पूंजी होगी और दो लाख रुपये ऋण व अनुदान रूप में दिये जायेंगे, जिससे वे गोदाम बना सकें और ट्रक आदि खरीद सकें। प्रारम्भ के कुछ वर्षों तक उन्हें व्यवस्था के लिये कुछ सहायता भी मिलेगी। इस योजना के क्रियान्वित होने पर सरकार ने यह आशा व्यक्त की है कि जनता के पूर्ण सहयोग से यह थोक और फुटकर सहकारी समितियां स्वयं चलने लगेंगी। इसी प्रकार योजना आयोग ने यह भी प्रस्ताव किया था कि किसानों से अनाज की वसूली का कार्य सरकार सहकारी समितियों द्वारा करे, जिससे बीच के व्यापारी लोग जो मुनाफा खाते हैं, उसका लाभ सीधे किसानों और उपभोक्ताओं को मिले। मजदूरों को भी सहकारी समितियां संगठित करने के परामर्श दिये गये हैं, जिससे बढ़ती हुई महंगाई को रोका जा सके।

सहकारी समितियों का विचार बहुत अच्छा है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या आज की स्थिति में सहकारी समितियां मूल्यों को सही स्थिति में ला सकेंगी और अगर बढ़ती हुई मांग के अनुरूप अनाज का उत्पादन न हुआ तो क्या मूल्य कम हो सकेंगे? फिर क्या सहकारी समितियां अनाज आदि की वसूली, प्रबन्ध, परिवहन और भंडार की व्यवस्था को निजी व्यापारियों की अपेक्षा मितव्यय से कर सकेंगी?

आसाम सरकार ने सहकारी पण्य समिति के द्वारा अनाज वसूली की व्यवस्था की थी। इस कार्य में उसे बिल्कुल असफल होना पड़ा। आसाम की चावल मिलों के संगठन का कहना है कि पर्याप्त प्रोत्साहन के अभाव में यह समितियां गांव से बहुत कम चावल वसूल कर सकीं। १९६० ई० में इस सहकारी शीर्षस्थ पण्य संस्था ने पचास लाख मन चावल इकट्ठा किया और १९६१ में ४५ लाख मन। १९६३ ई० में यह वसूली ३५ लाख मन तक ही रह गई, और अब सम्भावना यह है कि इस वर्ष केवल २५ लाख मन ही चावल इकट्ठा होगा। इस सहकारी समिति ने किसानों को आठ रुपये प्रतिमन चावल दिया है, जबकि खुले बाजार में यह चावल १२ से १४ रुपये तक बिक रहा था। तो किसान सहकारी समिति को क्यों तरजीह देते?

सामुदायिक योजना मन्त्री श्री एल. के. ने स्वयं कृषि और सहकारी विभागों की अकुशलता और सुस्ती के लिये बहुत भर्त्सना की है। इसलिये यह आवश्यक है कि सहकारी समितियों का जाल बिछाने से पूर्व यह व्यवस्था भी करली जाये कि सहकारी समितियां अपना कार्य अधिक मितव्यय और कुशलता से करें। अभी तक का अनुभव यह है कि यह सहकारी समितियां सरकार की सहायता के आधार पर खड़ी तो हो जाती है, परन्तु ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती। बेईमानी, उदासीनता, अव्यवस्था और आलस्य के कारण सरकारी रुपया भी बरबाद हो जाता है। कोई बड़ी योजना भी इन दुर्गुणों के कारण असफल हो सकती है। इसलिए १० करोड़ रु० की योजना के प्रारम्भ करने से पूर्व अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। आदर्शवादी स्वप्न यथार्थ की चट्टान से चूर-चूर न हो जावे, इसकी सतर्कता हमें कर लेनी चाहिए।

—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विकासशील अर्थव्यवस्था में कराधान

डॉ रुस्तम सी. कूपर

13 JUN 1963

आर्थिक विकास के लिए साधन जुटाने की किसी भी पद्धति में कराधान का योग काफी बड़ा रहता है। फिर भी, उसे अविवेकपूर्ण तरीके से और न असीमित मात्रा में ही लगाया जा सकता है। उसका अमल भी बड़ी सावधानी के साथ एक समर्थ औषधि के रूप में करना पड़ता है। कराधान को सामान्य तौर से साधनों के अन्य दो बड़े हिस्सों के साथ, अर्थात् जनता से कर्ज लेने और घाटे की वित्त व्यवस्था, लागू किया जाता है। अतः वित्त मंत्री की समस्या यह होती है कि इन तीनों साधनों के बीच ऐसा उत्कृष्ट अनुपात निर्धारित किया जाय जिससे ज्यादा विकास हो सके। यह काम, इन तीनों साधनों से होनी वाली प्राप्ति को सन्तुलित कर उपलब्ध-निधियों को अधिकतम करने की जरूरत पर, घरेलू पूँजी का स्वस्थ और ओजस्वी विकास कर समुदाय के विभिन्न वर्गों की कर देने की क्षमता पर अनुचित भार न डाल कर और लगातार बचतों और पूँजी रचना के लिए जरूरी वातावरण पैदा करने की ओर ध्यान देकर किया जा सकता है। और फिर इन सभी कामों को कम जीवनमान, प्रति-व्यक्ति थोड़ी आमदनी और आय तथा समृद्धि की बड़ी असमानता की पृष्ठभूमि में करना पड़ता है। इन समस्याओं का समाधान बड़ी तेजी के साथ लेकिन राष्ट्रीय समृद्धि और आय को बढ़ाने के उद्देश्य से, बजाय इसके कि दुर्लभ साधनों को फिर से प्राथमिकतया वितरित करने की कोशिश की जाय, होना चाहिए।

मुद्रास्फीति पर काबू

किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, यदि उसका समाधान प्रभावपूर्ण और क्रमबद्ध तरीके से नहीं किया गया, एक बड़ी समस्या खड़ी कर देती है। फिर भी, इसका यह मतलब नहीं कि प्रत्येक विकासशील देश के लिए भयानक मुद्रास्फीति का होना जरूरी ही होता है। १९५० और १९६० के बीच ६३ देशों में से कम-से-कम १६ देश ऐसे थे, जिनके विवरण उपलब्ध है, जो अपनी घरेलू मूल्य सतह की वृद्धि को १.५ प्रतिशत या इससे भी कम की वार्षिक औसत तक ही सीमित रख सकने की अच्छी स्थिति में थे। इसमें कुछ अल्प-विकसित देश थे जो, विभिन्न असरकारक तरीकों के जरिये अपने मूल्यों को काबू में रखने में सफल रहे। लेकिन इसके विपरीत, भारत में मूल्यों के निम्न रुखों पर विचार करना चाहिए। मार्च १९६० को समाप्त हुए चार वर्षों में थोक मूल्यों में २६.५ प्रतिशत की, कृषि पदार्थों की कीमतों में ३१.८ प्रतिशत, औद्योगिक कच्चे सामानों में २४.९ प्रतिशत, खाद्य कीमतों में ३७.४ प्रतिशत और आम निर्वाह खर्च में २८ प्रतिशत वृद्धि हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि निर्वाह-खर्च में औसत ७ प्रतिशत वृद्धि हुई। इस रुख के बारे में हमारे नियोजकों को अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। अतः मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए तात्कालिक रूप से उठाये जानेवाले कदमों में सरकारी खर्च में कमी, रेल भाड़ा, बिजली, डाक सेवाएं आदि जैसी सार्वजनिक सेवाओं की कीमतों पर काबू रखना और उत्पादकता और कार्यक्षमता के अनुपात में कामगारों की वेतन-दर को सम्बद्ध करना (जबकि वह मूल अल्पतम वेतन की सीमा से ज्यादा हो) विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से समुदाय से अतिरिक्त क्रयशक्ति को खींचने के लिए, हालांकि कराधान एक प्रतिमानित उपाय माना गया है, लेकिन भारतीय दशाओं के सन्दर्भ में इस बात पर जोर देना जरूरी हो जाता है कि काफी हद तक मुद्रास्फीति, केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा विभिन्न राजकीय उद्योगों के गैर उत्पादक खर्चों की वजह से पैदा होती है। हाल ही की रिपोर्टों के अनुसार राजकीय उद्योगों में हाल ही के वर्षों में लागत पूँजी पर ०.५ प्रतिशत से भी कम लाभ हुआ है।

चूंकि सादे शब्दों में मुद्रास्फीति का अर्थ होता है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बहुत ज्यादा मुद्रा का बहुत थोड़े सामान के पीछे दौड़ना इसलिए आबादी के प्रति व्यक्ति के हिसाब से सामानों और सेवाओं के उत्पादन की वृद्धि रफ्तार को यथासंभव बढ़ाने की दिशा में भरसक कोशिश करनी चाहिए । सही कराधान की नीति अपना कर और उत्पादकों को समुचित प्रोत्साहन देकर इस प्रक्रिया को काफी बढावा दिया जा सकता है ।

विकासशील अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक समस्या है मुद्रास्फीति और मूल्य सतह के बीच उचित सम्बन्ध कायम रखने की आवश्यकता । इस बात पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि मुद्रापूर्ति का विस्तार (संक्षेप में अधिक नोटों को छापना) और कर्जों का विस्तार अत्यन्त तेज रफ्तार से न होने पाये । उसका सम्बन्ध, अनिवार्यतः और हमेशा, विदेशी साधनों तथा विदेशी मुद्रा की उपलब्धता सहित विकास के लिए यथार्थ साधनों को उपयोग में ला सकने की देश की क्षमता के साथ होना चाहिए । खास तौर से, विदेशी विनिमय साधनों की कमी के कारण पूँजीगत सामानों और जरूरी कच्चे माल का आयात बिलकुल सीमित होने के सन्दर्भ में "मुद्रास्फीति सम्बन्धी दबावों पर दृढता से काबू करना और उत्पादन तथा बचतों को बढाने के प्रयत्नों को तीव्र करना जरूरी है ।" (रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में श्री एच० वी० आर० आयंगर का ८-२-१९६० का कथन) ।

मध्यम वर्ग का स्थान

विकासशील अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, मध्यम वर्ग के लिए अनेक खास समस्याएं पैदा कर देती है । निस्सन्देह यह बड़े अफसोस की बात हैकि अन्य देशों में जहाँ मध्यम वर्ग की अभिवृद्धि को बढती हुई अर्थव्यवस्था का प्रतीक माना गया है, हमारे देश के लिए अनेक बड़े नेतागणों ने सुझाव दिया है कि इस देश में मध्यम वर्ग के अस्तित्व के लिए कोई औचित्य नहीं हैं । इसलिए इस बात पर जोर देना और उसे दोहराना जरूरी है "राष्ट्रीय उत्पादन को बढाने तथा पदार्थों के वितरण में असमानताओं को कम करनेवाली द्विलक्ष्यीय अर्थव्यवस्था में एक विकासवान-मध्यमवर्ग एक विकासवान-साधन आधार का अभिन्न अंग है ।" इंडियन मर्चेन्ट्स चेम्बर इकोनोमिक रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग फाउन्डेशन द्वारा प्रकाशित "इन्फ्लेमेशन इन ए डेवलपिंग इकोनोमी" के पृष्ठ ७१ से उद्धृत)" । मध्यम वर्ग से अपेक्षा की जाती है कि बचत करने और पूँजी लगाने की क्षमता में उसका विकास हो । लेकिन मूल्यों में मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण बचत करने की क्षमता कम हो जाती है जो आन्तरिक साधनों से या रकमों को एकत्रित्रत करने सम्बन्धी आँकडो को सफलतापूर्वक पूरा करने में अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है । मध्यम वर्ग अपनी वर्तमान आमदनियों से (जो बढ़ते हुए निर्वाह खर्च को पूरा करने में कम पड़ती है) न केवल बचत करने में असमर्थ मालूम पड़ता है बल्कि वास्तव में अपनी पुरानी बचतों का सहारा हैं या कर्ज लेते हैं, ताकि अपने चालू जीवनमान को कायम रख सकें । फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में पूँजीगत प्रयत्न धीमे पड़ने जाते हैं ॥ (उपरोक्त सन्दर्भ, पृष्ठ ८०)

इससे एक बात साफ जाहिर होती है, और वह यह कि सीधे कराधान में इस वर्ग को पर्याप्त राहत देने की जरूरत है । परोक्ष कर लगातार बढते जायँगे और समाज के किसी भी खास वर्ग या श्रेणी को परोक्ष करों से राहत देना, सिवाय एक अत्यन्त सीमित मात्रा के, असंभव हो जायगा । इसलिए, मध्यम वर्ग की मुक्ति इसी बात में है कि उसे सीधे कराधान में पर्याप्त राहत दी जाय ।

विकासशील अर्थव्यवस्था तक में विभिन्न भागों की विकास अवस्था में भी, खासकर भारत जैसे विशाल देश में जहाँ विभिन्न प्रकार के भौगोलिक विस्तार मौजूद है, बड़ी असमानताओं का होना प्रायः निश्चित सा है । इस दिशा में न केवल केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा ध्यान देने की जरूरत है बल्कि व्यापारिक और औद्योगिक समुदाय की भी जो देश के इन भागों में उपयुक्त उद्योगों की स्थापना की ओर काफी ध्यान दे सके । ऐसी हालत में, सरकार, स्वयं अपनी विशाल फैक्टरियों को कायम करने के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अपनाने के बजाय, पर्याप्त सेवाओं और सुविधाओं की व्यवस्था कर इन विस्तारों में उद्योगों को शुरु करने के लिए उचित वातावरण पैदा कर अधिक असरकारक तरीके से सहायता कर सकती है । कर सम्बन्धी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रोत्साहन भी काफी हद तक सहायक बन सकते है। इस सम्बन्ध में इटली, ग्रीस, और पाकिस्तान तक के उदाहरणों का उल्लेख करना उचित होगा जिन्होंने इस समस्या को, देश के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े विस्तारों तक के लिए सीमित आकर्षक कर प्रोत्साहन देकर सफलतापूर्वक सुलझाया है। लेकिन इस प्रकार के कर-प्रोत्साहनों को असरकारक बनने के लिए उन्हें सही रूप से सहायक होना चाहिए। ऐसे कर-प्रोत्साहन निस्सन्देह असफल हो जायँगे जो केवल कागजों पर ही रहते हैं और जिनमें विकास में सहायक बनने की सरकारी इच्छा सच्ची और निष्ठा युक्त नहीं होती है। हाल ही का निर्यात लाभों पर (यह पूरी तरह जानते हुए कि निर्यात व्यापार में ज्यादा लाभ नहीं है) १० प्रतिशत कर-प्रोत्साहन और लागत पूँजी पर ६ प्रतिशत तक सीमित नये औद्योगिक संस्थानों के लिए दी गई कर-छुट्टी कुछ इसी प्रकार की कागजी रियायतें हैं। क्योंकि यह बात सभी लोग जानते हैं कि अधिकांश मामलों में जब तक कोई संस्थान विकास रिबेट और डिप्रीशियेशन एलाउन्स से लाभ उठा चुकता है, बाद में इस राहत के योग्य शायद ही कुछ लाभ शेष रह जाता है। कम-से-कम पिछड़े विस्तारों में शुरू किये गये उद्योगों के लिए हमारी सरकार बिलकुल कर-छुट्टी (बिना किसी पारिमाणिक राहत के) देने के लिए आगे क्यों नहीं आती है? इस प्रकार की विशेष राहत की अवधि, अन्य मामलों की पांच वर्ष की अवधि के स्थान पर, कम से कम १० वर्ष की होनी चाहिए। इस प्रकार की १० वर्षीय सम्पूर्ण कर-छुट्टी अनेक दूसरे देशों में, उनके आर्थिक दृष्टि से पिछड़े विस्तारों के लिए एक आम पहलू रही है।

छोटे उद्योगपति और व्यापारी

विकासशील अर्थव्यवस्था में अनेक छोटे उद्योगपतियों का तथा व्यापारियों की समस्याओं पर ध्यान देना पड़ता है। ये लोग मौके पर पहुँच कर आर्थिक विकास में काफी योग देते है। वास्तव में आमदनियों, और समृद्धि की विशेषताओं को कम करने सम्बन्धी प्रक्रिया की पूर्व-मान्यता है बड़ी संख्या में छोटे-छोटे अनेक उद्यमी लोगों के एक नये वर्ग की वृद्धि जिन्हें वित्त और और अन्य सुविधाएं सहित अनेक प्रकार की सहायता की जरूरत होती है। इस दिशा में सरकार ने कर-प्रोत्साहन के रूप में कुछ भी नहीं किया है। यदि इन छोटे-छोटे लोगों को अपने उत्पादन-घटकों का विस्तार करना होता है तो उन्हें बैंकों या अन्य स्थानों से कर्ज लेना पड़ता है। इसके लिए उन्हें प्रायः अपने व्यापार को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में गठित करना पड़ता है। इसका मतलब होता है ५० प्रतिशत वापिस न किये जानेवाले कर के रूप में कम्पनी पर भारी भार और इसके अलावा उद्यमी के डिवीडेन्टों तथा पारिश्रमिक पर लगाने वाले और कर। इसकी वजह से एक छोटे व्यक्ति के लिए अपने व्यापार को एक निजी कम्पनी में बदलना कोई खास महत्व नहीं रखता हैं। भले ही वह व्यापार अन्य दृष्टिकोणों से वांछनीय लगे। इसलिए, निजी कम्पनियों के लिए कुछ निर्धारित आमदनी तक करों की कम दरें लेकर रचनात्मक कर-राहत देना वांछनीय हैं। या इसके बदले में किसी प्राइवेट कम्पनी के शेयर होल्डरों को यह विकल्प दिया जाय कि यदि वे चाहें तो उनसे एक रजिस्टर्ड हिस्सेदारी के रूप में कर वसूल किया जाय। यह एक नया परिवर्तन लगेगा लेकिन उसके सभी प्रभावों को देखते हुये बात गौर करने योग्य है।

विकासशील अर्थव्यवस्था में कराधान की नीति बनाते समय ऐसे दो और पहलू है जिन पर सावधानता पूर्वक विचार करना चाहिए और जिनका नीचे उल्लेख किया जाता है। एक पहलू है समुदाय की बचतों पर पड़ने वाला कराधान का असर। विकास के लिए आंतरिक साधन, बचतों की वृद्धि के साथ-दोनों प्रकार की बचते, वैयक्तिक और निगमित—इतने निकट से सम्बद्ध है कि उनका महत्व काफी बढ़ गया है। इसी प्रकार, कराधान की नीति का बाहरी साधनों पर पड़ने वाले असर पर भी समान रूप से ध्यान देना चाहिए। हालांकि, सरकार ने भूतकाल में इन दोनों पहलुओं पर विचार किया है। फिर भी, देश और विदेश में लोगों में इस प्रकार की भावना मौजूद है कि समस्या के इन पहलुओं पर निर्णय लेते समय पूरी तौर से विचार नहीं किया गया है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जापान का उन्नतिशील वस्त्र-उद्योग

श्री ए० एन० बुच

पश्चिम में कपड़ा-उद्योग ब्रिटेन के और पूर्व में जापान के नेतृत्व से विकसित हुआ। ब्रिटेन की अपेक्षा जापान में इसकी प्रगति अधिक शीघ्रता से हुई। इसके विशेष कारण हैं मनोहर प्राकृतिक स्थितियां, द्रुतगामी स्वयं-चालित मशीनें, काम की अत्यन्त अनुकूल परिस्थितियां और महिला-श्रमिकों का अधिक अनुपात। कपड़ा मिलों के साथ छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं जिनमें लड़कियों के लिए न केवल रहने की सुविधाएं हैं किन्तु उनकी ज्ञान वृद्धि के भी वहां साधन हैं।

कारखानों में उत्पादन का ढंग भी उल्लेखनीय है। पुराने ढर्रे की मन्द गति से चलने वाली मशीनों की जगह बहुत तेज चलने वाली स्वचालित मशीनें हैं। इससे अपने आप निरन्तर कतायी होती रहती है। यह जापान की अपनी विशेषता है और इसी के कारण यहां के कपड़ा उद्योग में क्रान्ति आ गयी है। कपास को ब्लोरूम में डाल देने के बाद फिर किसी सामान को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है।

इस विधि में काम करती हुई ३० लड़कियां पौने आठ घन्टों में ६,००० पौंड सूत तैयार कर देती हैं। एक लड़की १० कतायी-फ्रेमों पर काम करती हैं। जापानी कारखानों में सूत टूटने की संख्या विश्व के कारखानों की अपेक्षा सबसे कम है।

लड़कियां अधिक

जापानी कपड़ा मिलों से ८० प्रतिशत लड़कियां हैं और इनमें करीब ४० प्रतिशत २० वर्ष से कम आयु की और ३६ प्रतिशत ३०-३० आयु-सीमा की हैं। इस प्रकार, ७६ प्रतिशत लड़कियां ३० वर्ष से कम आयु की हैं। जापान की समृद्धि उस समाज व्यवस्था पर आधारित हैं जिसके अन्तर्गत ये अल्प आयु की लड़कियां अपनी शिक्षा के साथ-साथ हाथों का धंधा करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

जापान में कपड़ा मिलें, भारत के विपरीत, छोटे-छोटे कस्बों में हैं। प्रत्येक मिल के भीतर मनोहर, प्राकृतिक पारिवारिक अवस्थाओं के अन्तर्गत निवास-कक्ष (डारमिटरी) बने हुए हैं जिनमें रहने के कमरे, एक प्रार्थना भवन, सबके लिए स्नान व शौचालय, दवाई घर, प्रसाधन कोणक, सांस्कृतिक कार्यक्रम भवन, फूलों की क्यारियां, खेल कूद का स्थान, टेलीवीजन—इत्यादि सब कुछ होता है। इनमें ही निवास करने के कारण लड़कियां दो पारियों में काम करती हैं। ये निवास कक्ष बहुत साफ-सुथरे रखे जाते हैं। सब प्रकार की सुविधाओं के साथ लड़कियों को सीना, कातना, बुनना, गाना, नाचना, चित्र-कला इत्यादि सिखाने की भी व्यवस्था होती है। हरेक कमरे में ७ या ८ लड़कियां होती हैं। हरेक को चारपाई और अलमारी दी जाती है। खाने-पीने के लिए हरेक निवास कक्ष में भोजनालय व जलपान गृह होता है। सस्ते दरों पर भोजन-व जलपान दिया जाता है। वृद्ध महिलाओं का स्टाफ इन निवास कक्षों पर निरीक्षण रखता है। चारों ओर उद्यान रहता है। पुरुष श्रमिकों के लिए कारखाने के बाहर व्यवस्था होती है।

दिन की पारी, प्रातः ५ बजे प्रारम्भ होती है और रात्री का काम १० बजे के बाद से, कानून के अनुसार, महिलाओं के लिए निषिद्ध है। इसलिए दूसरी पारी रात्रि १० बजे के बाद समाप्त हो जाती है। जापान में, सामान्यतः तीसरी पारी नहीं चलती है।

मजदूरी का ढंग

जापान की कपड़ा मिलों में मजदूरी का ढंग दुनिया की अन्य मिलों से तनिक भिन्न हैं। समय की दर और काम के अंश की दर—और कभी दोनों—के आधार पर मजदूरी दी जाती है। वैतनिक कर्मचारियों को महीने में एक बार वेतन मिलता है। क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के भत्ते दिये जाते हैं। बुनियादी मजदूरी के लगभग २३ प्रतिशत ये भत्ते होते हैं। "सत्र के अन्त का अस्थायी वेतन" जून और दिसम्बर में दिया जाता है और दो या तीन मास की मजदूरी के अनुसार यह वेतन भिन्न-भिन्न होता है। भारत के बोनस से

(शेष पृष्ठ २७८ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आधी दुनिया को भरपेट भोजन भी नहीं है

खाद्य और कृषि संगठन ने विश्व की खाद्य-स्थिति की जो तीसरी पड़ताल की है, उसके महत्वपूर्ण निष्कर्ष में से शायद सबसे मुख्य यह है कि यद्यपि पिछले दशक में अनाज की खपत पहले की अपेक्षा काफी बढ़ी है, लेकिन विश्व के लगभग आधे लोग भूखे रहते हैं या उनको पोषक खाना नहीं मिलता या दोनों कठिनाइयां उनके सामने हैं—बी० आर० सेन,

पिछले कुछ वर्षों में विश्व की आबादी में असाधारण वृद्धि हुई है और इस वजह से खाद्य और पोषण की समस्या और भी विकट हो गई है। १९४६ में खाद्य और कृषि संगठन ने ७० देशों द्वारा दिए गए तथ्यों के आधार पर वहां का सर्वेक्षण किया था। इन देशों की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का ९० प्रतिशत थी। इस पड़ताल से पता चला था कि विश्व के बहुत बड़े इलाके के लोगों को अपर्याप्त खाना मिलता है।

१९५२ में दूसरी पड़ताल की गई, जिससे पता चला कि विश्व के लगभग ६० प्रतिशत लोगों को २,२०० कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से भी खाना नहीं मिलता। हाल ही में जो तीसरी पड़ताल हुई है, उससे पता चला है कि कम विकसित देशों के अधिकांश लोगों को प्रतिदिन जो भोजन उपलब्ध होता है, उसमें २,१५० कैलोरी की मात्रा भी नहीं होती, जबकि विकसित देशों के लोगों को ३,०५० कलौरी प्रतिदिन मिलती हैं। अनुमान है कि कम विकसित देशों के कोई २० प्रतिशत लोगों को खाना नहीं मिलता और कोई ६० प्रतिशत लोगों को ऐसा खाना मिलता है जिसमें पर्याप्त पोषक तत्व नहीं होते।

१९४६ में जब विश्व की खाद्य स्थिति की पड़ताल प्रकाशित हुई थी, तो प्रतिवर्ष एक प्रतिशत आबादी बढ़ने का अनुमान था और १९५२ में जो दूसरा सर्वे प्रकाशित किया था, उसमें भी आबादी कोई खास नहीं बढ़ी थी, लेकिन पिछले दशक में विश्व के बड़े भागों में बीमारियों पर काबू होने और चिकित्सा की अच्छी सुविधाएं मिलने से लोगों की औसत आयु बढ़ने लगी और प्रतिवर्ष कोई दो प्रतिशत के हिसाब से आबादी बढ़ी।

१९३८ से १९६० के बीच विश्व की आबादी में कोई ८० करोड़ की वृद्धि हुई जिसमें से ६५ करोड़ की वृद्धि कम विकसित देशों में हुई। कम विकसित देशों में, ५० करोड़ की वृद्धि केवल सुदूर-पूर्वी देशों में हुई। १९३८ में विश्व की कुल जनसंख्या का ६७ प्रतिशत हिस्सा कम विकसित देशों में रहता था, जबकि अब वहां विश्व के ७२ प्रतिशत लोग रहते हैं। इस असाधारण वृद्धि से विश्व में भोजन की समस्या और भी जटिल हो गई हैं।

खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई विश्व की भोजन सम्बन्धी पड़ताल के अनुसार सुदूर-पूर्व के देशों में अब आधी दुनिया बसती है, जबकि वहां के लोगों को विश्व के कुल भोजन का एक-चौथाई भाग मिलता है। इसके विपरीत यूरोप, ओसेनिया (आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) और उत्तर अमरीका के लोगों को जो विश्व की कुल आबादी का २९ प्रतिशत भाग है, दुनिया के भोजन का ५७ प्रतिशत खाने को मिलता है और उनके भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा भी अधिक होती है।

उत्पादन बढ़ा

यह ठीक है कि विश्व-युद्ध के बाद खाद्य-पदार्थों का उत्पादन कोई ५० प्रतिशत बढ़ा है। विकसित और कम-विकसित, दोनों ही प्रकार के देशों में उत्पादन इसी दर से बढ़ा है। कम विकसित देशों ने अधिक जमीन में खेती शुरू करके और विकसित देशों ने मुख्यतः प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाया है। लेकिन उत्पादन बढ़ने से विकसित देशों में प्रतिव्यक्ति जितना अधिक भोजन उपलब्ध हुआ है, अविकसित देशों में प्रतिव्यक्ति उसकी मात्रा नाम मात्र बढ़ी है।

यही कारण है कि विकसित देशों के लोगों को कम विकसित देशों की अपेक्षा अधिक खाना मिलता है, क्योंकि वहां प्रतिव्यक्ति खाद्य की पैदावार भी अधिक है। विकसित देशों में खेती की पैदावार कम विकसित देशों से लगभग दूनी है। वहां प्रत्येक पशु से लगभग पांचगुना दूध और मांस मिलता है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

योजना के लक्ष्यों से कम खाद्य उत्पादन

श्री नरोत्तम शाह

१९६२-६३ वर्ष के खाद्य-उत्पादन की ठीक राशि तो अभी तक मालूम नहीं हो सकी है पर प्राप्त अनुमानों से ज्ञात होता है कि ८०० टन के करीब है, आज से दो वर्ष पूर्व १९६०-६१ में भी यही संख्या थी। तीसरी योजना के पहले दो वर्षों के समान तीसरे वर्ष में भी खाद्य उत्पादन में कमी रहेगी। खाद्यान्नों के—विशेषतः चावल के मूल्य बढ़ रहे हैं। इस मोर्चे पर हमारी क्या स्थिति है और भविष्य में अल्प-कालीन व दीर्घ-कालीन स्थिति क्या होगी, इस पर विचार करना चाहिए।

भारत की खेती, बहुत कुछ, वर्षा पर निर्भर करती है। अगर किसी वर्ष अच्छी खेती हो जाए तो हमें उस पर अत्यधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए। हमें दूरगामी दृष्टि से विचार करना होगा।

कम विकसित देशों में खेती की कम पैदावार के कारण स्पष्ट हैं। वहां खेत इतने छोटे होते हैं कि उनमें अपने अपने परिवार के लिए ही पर्याप्त अन्न नहीं मिल पाता और दूसरे खेती पुराने तरीके से की जाती है। खेती के लिए आवश्यक औजार और सामान तक खरीदने को ऋण नहीं मिलता। बहुत से देशों में, खासकर सुदूरपूर्व में जमीन को उपजाऊ बनाए रखने के लिए वर्षों तक कुछ भी नहीं किया गया है। सिंचाई के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं मिलता: किसानों को टेकनीकल सलाह देने का भी पर्याप्त प्रबन्ध नहीं किया गया।

यदि विश्व की आबादी संयुक्त राष्ट्र के कनुमान के अनुसार इस तरह से बढ़ती चली गई तो १९७५ में, आज की सी असन्तोषजनक स्थिति बनाए रखने के लिए भी कोई ३५ प्रतिशत अधिक भोजन की जरूरत होगी। कम विकसित देशों को अपना उत्पादन लगभग ८० प्रतिशत बढ़ाना होगा और दूध, मांस, मक्खन आदि का उत्पादन १२० प्रतिशत से भी अधिक बढ़ाना होगा। इतनी वृद्धि हो जाने पर भी लोगों को उतना ही भोजन मिल सकेगा, जितना आजकल मिल रहा है।

दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष (१९६०-६१) में अच्छी फसल हुई। खेती चोटी की हुई, ७ लाख ६७ हजार टन। इतनी अच्छी खेती होने पर भी ३० लाख ५० हजार टन खाद्यान्न आयात किया गया ताकि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन १६ औंस अन्न मिल सके। पिछले चार वर्षों से खाद्यान्न की खपत १६ औंस प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है, पर विदेश से अन्न मंगवाकर ही यह स्तर कायम रखा जा सका है। यद्यपि विदेश से आयात अन्न—हमारी खपत का भाग ४ प्रतिशत ही पूरा करता है पर इसका देश की सम्पूर्ति में एक निश्चित स्थान है और इससे अन्न की मूल्य रेखा स्थिर रखने में सहायता मिलती है। इस लिए अगर उत्पादन में तनिक भी न्यूनता आती है तो उसका समूची अन्न-सम्प्राप्ति पर प्रभाव पड़ता है।

हमारी खाद्य योजना का एक दुःखद स्वरूप यह है कि हमने खाद्य-आयात को अनिवार्य मान लिया है, कम से कम तीसरी योजना के अन्त तक सुरक्षित भंडार के लिए तीसरी योजना में अन्न का लक्ष्य स्थिर करते हुए यह निश्चय किया गया था १९६०-६१ में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खपत १६ औंस से बढ़ कर १९६५-६६ में १७.५० औंस प्रतिदिन प्रति व्यक्ति हो जाएगी। १९६१ में आबादी ४३ करोड़ ८० लाख से बढ़कर १९६६ में ४९ करोड़ २० लाख हो जाएगी—यह अनुमान लगाया गया था। इसी के आधार पर उत्पादन का लक्ष्य १० लाख टन रखा गया था। इस लक्ष्य को स्थिर करते हुए १९६०-६१ के उत्पादन के वास्तविक तथ्य उपलब्ध नहीं थे। अज्ञात सूचना के आधार पर ही ७ लाख ६० हजार टन के उत्पादन की कल्पना कर ली गयी थी। तीसरी योजना का लक्ष्य, इसी लिए, ३२ प्रतिशत अधिक रखा गया था। १९६०-६१ वास्तविक फसल, लगभग ८० लाख टन हुई। अब स्थिति यह पैदा हो गयी कि ३२ प्रतिशत अनुमानित वृद्धि की जगह केवल २५ प्रतिशत वृद्धि हुई।

तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में खाद्यान्न का उत्पादन ७ करोड़ ८६ लाख टन हुआ जबकि १९६०-६१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

में ७ करोड़ ९७ लाख हुआ था। इस प्रकार तीसरी योजना के पहले वर्ष में कोई वृद्धि नहीं हुई। स्पष्ट है, तीसरी योजना के तीसरे वर्ष का लक्ष्य १० लाख टन निश्चित करने में भूल हुई। वस्तुतः १९४९-५० और १९५९-६० को आधार बनाना चाहिए था। अगर ऐसा किया जाता तो १९६५-६६ के लिए १० लाख टन की जगह ८ लाख ८० हजार टन का लक्ष्य स्थिर किया जाता।

यह बात तो साफ जाहिर है कि केवल यही कसौटी कि हमें विदेश से अन्न मंगवाना पड़ रहा है, इस बात का दृढ़ प्रमाण है कि हमारी खाद्य-नीति में कोई दोष है। विदेश से यहां आने वाले खाद्यान्न में भी वृद्धि हो रही है। पहली योजना में इसकी राशि २४ लाख टन थी, जबकि दूसरी योजना में ३४ लाख टन और तीसरी योजना के पहले वर्षों में भी यह राशि बढ़ती रही है। १९६०-६१ में बहुत अच्छी फसल हुई थी। फिर भी हमें ५० लाख टन खाद्यान्न आयात करना पड़ा।

इस लिए हमारी खाद्य नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे कि कम फसल के वर्षों में भी इतना अन्न पैदा हो जाए जिससे जनता की मांग पूरी होती रहे। मांग दो बातों पर निर्भर करती है, आबादी की वृद्धि और प्रति व्यक्ति की आवश्यकताएं। विश्व खाद्य संघ से सम्बद्ध और खाद्य पर एक उच्च-प्रामाणिक व्यक्ति के रूप में डा० पी० वी० सुखाले का कहना है कि पुष्टि की दृष्टि से भारत को प्रति वर्ष १०० लाख टन खाद्यान्न का घाटा रहता है और लगभग इतनी ही मात्रा में फल, सब्जियों और अन्न पोषक तत्वों की कमी है।

आप आगे कहते हैं—"भारत में प्रतिवर्ष लगभग १०० लाख बच्चे पैदा होते हैं जिससे आबादी प्रतिवर्ष बढ़ रही है। इस अतिरिक्त आबादी को खिलाने के लिए कम से कम २० लाख टन की अधिक उपज होनी चाहिए। अभी तक भारत अधिक से अधिक ३ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि ही कर सका है अर्थात—आवश्यक विकासदर का केवल दो-तिहायी भाग ही। भारत की खेती की वृद्धि प्रति वर्ष ३ प्रतिशत से कुछ अधिक होती है। हमारी आबादी प्रतिवर्ष २.५ प्रतिशत की दर से बढ़ रही है और कृषि-उत्पादन १.५ से २ प्रतिशत प्रतिवर्ष तक।"

यह घाटे की स्थिति कैसे दूर हो—इसके लिए हमें कठोर श्रम करने की आवश्यकता है।

दी सेंट्रल बैंक आफ इंडिया लिमिटेड

हैड आफिस :—

महात्मा गांधी रोड, फोर्ट, बम्बई—१

संस्थापित—१९११

आकर्षक रेटों पर ३ दिन से ५ साल तक के लिए डिपाजिट मंजूर किये जाते हैं।

ज्यादा ब्यौरे के लिए हमारे किसी दफ्तर से, कृपा करके, सम्पर्क करें।

एन० के० करंजिया

मैनेजिंग डायरक्टर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(पृष्ठ २७४ का शेष)

इसकी तुलना की जा सकती है।

एक लड़की का बुनियादी वेतन उसकी आयु और उसके सेवा काल पर निर्भर करता है। एक जैसे काम के लिए पुरुष और स्त्री के वेतन में कोई भेद नहीं है। पर, क्रिया रूप में, एक जैसे काम पुरुषों और स्त्रियों को नहीं दिये जाते। लड़कियों को कुछ विशेष छुट्टियां दी जाती हैं। वार्षिक वैतनिक छुट्टियों का सम्बन्ध सेवा काल से होता है, अर्थात्, जितना अधिक सेवा काल, उतनी ही अधिक वैतनिक छुट्टियां। इसके अतिरिक्त, विविध प्रकार की सामाजिक सुरक्षाएं प्रत्येक कर्मचारी को प्राप्त होती हैं।

कपड़ा उद्योग में अन्य उद्योगों की अपेक्षा वेतन अधिक मिलता है। जापान की वेतन-व्यवस्था अपर्याप्त नहीं हैं। कर्मचारी चाहें तो ७ प्रतिशत सूद पर अपनी बचत कम्पनी में जमा कर सकते हैं। जापान का श्रमिक वर्ग, वैतनिक व मजदूरी वाला, मालिकों के व्यवहार से सन्तुष्ट प्रतीत होता है।

कार्य निवृत्त होने की आयु ५५ वर्ष है पर महिला श्रमिक पर्याप्त पहले ही निवृत हो जाती हैं। सब प्रकार के कर्मचारियों के लिए तकनीकी शिक्षा का प्रबन्ध प्रत्येक मिल में है। अन्य उद्योगों की तुलना में जापान की कपड़ा मिलों में दुर्घटनाओं व चोट लगने की संख्या कम है। चिकित्सा और सुरक्षा का मिलों में बढ़िया प्रबन्ध है।

कपड़ा मिलों के श्रमिकों की यूनियनें हैं जिनकी कुल सदस्य संख्या जुलाई ६२ तक ४३०,००० थी। हरेक फैक्टरी में एक यूनियन होती हैं। मालिक-श्रमिक के झगड़ों का निर्णय कराने में ये यूनियनें बड़ी सहायता देती हैं। सामाजिक सुरक्षा की प्रत्येक मिल में पूरी व्यवस्था है।

• •

उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के लिए उपयोगी लेख, ताजे समाचार, आर्थिक गतिविधियों की जानकारी तथा व्यापारिक भविष्य-वाणी

अर्थ-शास्त्र के छात्रों के लिए अनेक उपयोगी सामग्री

आम जनता के लिए हर अंक में एक आकर्षक कहानी चल-चित्र उद्योग, व्यंग-विनोद, चित्रमय समाचार एवं कार्टून

भारत के अनेक राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा-संस्थाओं वाचनालयों पंचायतों एवं विकास खण्डों के लिये स्वीकृत

भारत व्यापार पत्रिका

उद्योग तथा व्यापार प्रधान सचित्र हिन्दी मासिक

- भिन्न-भिन्न वस्तुएँ बनाने की योजनाओं का नियमित प्रकाशन
- एक मुफ्त विज्ञापन छापने की व्यवस्था
- आप के उलझे हुए प्रश्नों के उत्तर
- आप की आवाज़ सरकार तक पहुँचाने के लिये सुझाव एवं शिकायतें स्तम्भ
- आयात निर्यात समाचार, विज्ञान जगत बैंकिंग तथा बीमा समाचार आदि अनेक स्थाई स्तम्भ

वार्षिक चंदा विशेषाँकों सहित ६.00 रू.

पृष्ठ संख्या ६४ से ७२ तक

साधारण अंक 0.५0 न. पै.

अन्य जानकारी के लिये लिखें —

व्यवस्थापक, भारत व्यापार पत्रिका,
पो. बॉ. नं. ४८, राजा दरवाजा, वाराणसी (उ.प्र.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्रियात्मक लोकतन्त्र का ज्वलन्त प्रतीक : टैनेसी घाटी

ऑब्रे जे० ब्रेगनर

१८ मई ६३ को अमेरिका के प्रख्यात टेनेसी नदी घाटी अधिकरण की स्थापना को ३० वर्ष पूरे हो गये। योजना बद्ध विकास की दृष्टि से भले ही सोवियत रूस ने एक नया मार्ग प्रदर्शन किया हो, अमेरिका की बहु-मुखी टैनेसी घाटी का विकास इस योजना में अपना एक महत्व रखता है।

यह योजना भी देश में फैले विकट आर्थिक संकट और बेरोजगारी को दूर करने की दृष्टि से तैयार की गई थी। भारत भी पिछले १२ वर्षों से योजना बद्ध विकास के मार्ग को अपना रहा है। दामोदर वैली कारपोरेशन की योजना का तो आधार ही टैनेसी योजना है। इस दृष्टि से टेनेसी योजना की प्रगति का विवरण रोचक व उपयोगी होगा।

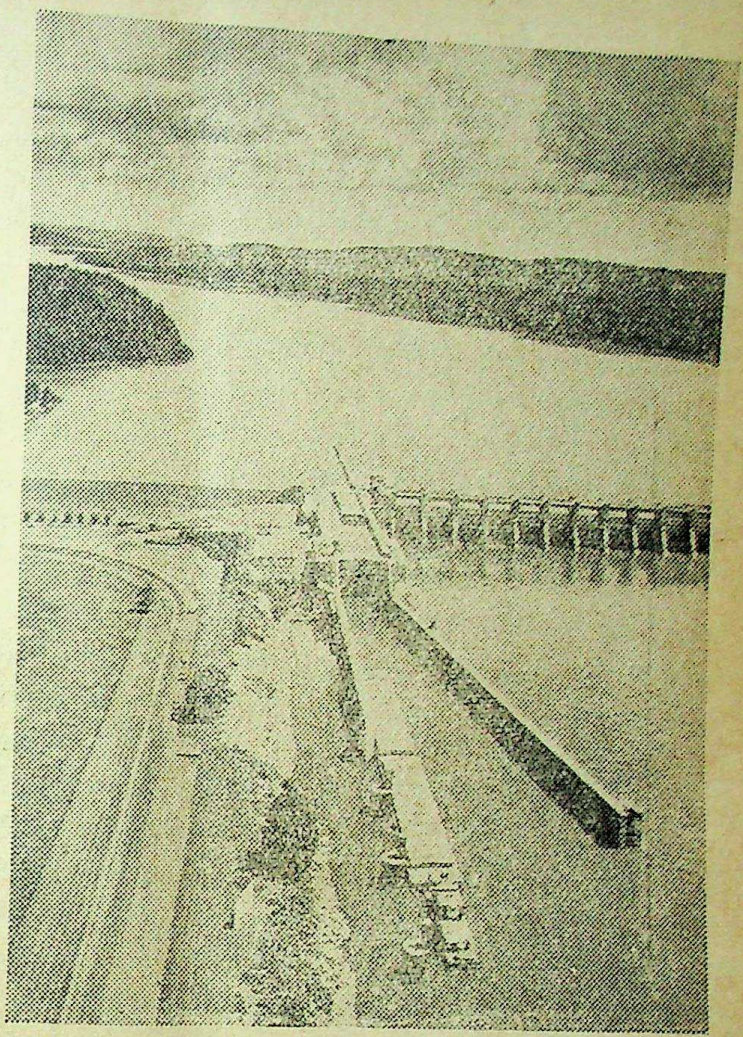

टैनेसी घाटी योजना का एक दृश्य

सभी अमेरिकियों के मध्य 'टी वी ए' के नाम से विख्यात इस अधिकरण की स्थापना अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा स्वीकृत एक कानून के अन्तर्गत टेनेसी नदी पर स्थित बांधों और प्लाटों के संचालन, अमेरिका की कृषि के लिए नई-नई प्रकार की रासायनिक खादों के विकास, टेनेसी नदी में नौका-नयन की व्यवस्था करने और बाढ़ों पर नियन्त्रण करने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना के अन्य उद्देश्यों में दक्षिणी राज्यों के विकास की दृष्टि से राष्ट्र के अन्य भागों से पिछड़े विशाल क्षेत्रों के उपयोगार्थ जल विद्युत-शक्ति का उत्पादन करना, उसके वितरण की व्यवस्था करना तथा इस क्षेत्र के साधन-स्रोतों का उचित ढंग से संरक्षण और विकास करना तथा उनका उपयोग करना भी शामिल था।

'अपनी सेवा अपने आप करने' में लोगों की सहायता कर 'टी वी ए' जनता की सेवा करता है। वह न केवल जनता के लिए बल्कि जनता द्वारा मिलकर साधनों का

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विकास करने के सिद्धान्त में भी दृढ़ निष्ठा रखता है। 'टी वी ए' प्रगति के लिए आवश्यक उपकरण सुलभ करता है जैसे बाढ़-नियन्त्रण, नौका-नयन, सस्ती विद्युतशक्ति, कृषि-सहायता और शिक्षा। लेकिन इन समस्त उपकरणों का उपयोग जनता ही अपनी प्रगति के लिए आवश्यक वस्तुओं का असीमित परिणाम में उत्पादन करने के लिए करती है।

पिछले ३० वर्षों में टेनेसी नदी घाटी में जो कुछ घटा है, वह इस सरल सत्य को नाटकीय ढंग से सिद्ध करता है कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर क्षेत्र राष्ट्र के लिए शान्तिकाल में एक आर्थिक भार तथा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक कमजोर हथियार होता है। लेकिन प्राकृतिक साधन स्रोतों के बुद्धिमत्तापूर्ण विकास के द्वारा मजबूत बना दिया गया क्षेत्र और वहां की जनता का नया नेतृत्व अधिक उन्नत जीवन-स्तर के लिए एक राष्ट्रीय देन तथा स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए शक्ति का स्रोत होता है।

१९३३ में, जबकि देश व्यापक आर्थिक मन्दी का शिकार हो रहा था, टेनेसी नदी घाटी ने एक बड़ी आर्थिक समस्या का रूप धारण कर रखा था। इस घाटी की नदियों का विकास नहीं हुआ था, बहुत अधिक संख्या में वृक्षों के काटे जाने तथा दावानलों से सुरक्षा की कोई व्यवस्था न होने के कारण इसके जंगल समाप्त--प्राय हो रहे थे; इसकी भूमि का बहुत अधिक क्षरण हो चुका था तथा यहां के निवासी राष्ट्र की औसत प्रति व्यक्ति आय से ४० प्रतिशत से भी कम प्रति व्यक्ति आय पर किसी प्रकार अपना जीवन काट रहे थे। जबकि इस क्षेत्र में विशाल जलराशि अनियन्त्रित रूप में बेकार बहती रही, यहां के फार्मों और छोटे-छोटे कस्बों को प्रकाश प्राप्त करने के लिए केवल तेल के लैम्प और मोमबत्तियां ही सुलभ थीं।

आज टेनेसी नदी घाटी एक ऐसा क्षेत्र है, जहां क्षरण के कारण नग्न हो गए पहाड़ी ढलान पुनः हरे-भरे चरागाहों और घने वनों से आच्छादित हो गए हैं। इन घने वनों के कारण निकट भविष्य में वहां नए-नए लकड़ी उद्योगों का विकास होगा, जिनमें अधिकाधिक लोगों को काम मिलेंगे। बाढ़ों की विनाश लीला के कारण जो भूमि [illegible] थी, वहां आज लाखों डालर की लागत के औद्योगिक और मनोरंजन विकास कार्य चल रहे हैं। ये लाभ आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं हैं। सस्ती विद्युतशक्ति सुलभ होने के फलस्वरूप आधुनिक ढंग का जीवन व्यतीत करने के जो अवसर आज यहां लोगों को सुलभ हैं, उनको आंकड़ों के रूप में नहीं मापा जा सकता।

'टी वी ए' ने इस बात को बहुत ही नाटकीय ढंग से सिद्ध कर दिया है कि घरों, स्कूलों, फार्मों और फैक्टरियों में अधिक परिणाम में विद्युतशक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन देकर सस्ती बिजली अपने उत्पादन-व्यय की पूर्ति स्वयं कर सकती है। 'टी वी ए' के संस्थापकों ने विद्युतशक्ति को एक वस्तु के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे उपकरण के रूप में मान्यता दी जिसका उपयोग आजादी के साथ अधिक उत्पादनशील अर्थ-व्यवस्था के निर्माण में किया जा सकता था। उनकी यह मान्यता बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण थी।

आज, इस प्रदेश के ९८ प्रतिशत से भी अधिक फार्मों पर विद्युतशक्ति है, जबकि १९३३ में केवल ३ प्रतिशत फार्मों पर ही विद्युतशक्ति थी। घाटी में स्थित २५ प्रतिशत घर आजकल विद्युतशक्ति द्वारा गर्म किए जाते हैं, और विद्युत उपकरणों की खरीद में यह क्षेत्र राष्ट्र के अन्य सभी क्षेत्रों से आगे है।

विद्युत शक्ति वस्तुतः जनता का उपकरण है। घरों में गृहणियों द्वारा इसका उपयोग सफाई और धुलाई सम्बन्धी कार्यों के लिए होता है। किसान पानी खींचने, करने और गायों को दुहने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कारखानों की मशीनों और उपकरणों को चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है तथा उत्पादन में वृद्धि करने तथा श्रमिकों के भार को हल्का करने में भी यह सहायता करती है।

उन बाढ़ों पर नियंत्रण करने के लिए, जो कभी टेनेसी और मिसीसिपी नदी की घाटियों में रहने वालों के लिए मौत, विनाश और तबाही लाती थीं, 'टी वी ए' द्वारा अनेक बांधों का निर्माण किया गया है, जिनमें जल को संग्रह करने के लिए कुल मिला कर १ करोड़ २० लाख एकड़ फुट (१५ अरब क्यूबिक मीटर) स्थान है। इस

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

व्यवस्था द्वारा टेनेसी नदी के जल प्रवाह को कम करना अथवा कुछ समय के लिए उसे पूरी तरह रोक देना भी सम्भव है। बाढ नियन्त्रण प्रणाली के कारण अब तक १८ करोड़ डालर की क्षति रोकी जा चुकी है, जबकि नियन्त्रण प्रणाली पर कुल मिलाकर ४० लाख डालर की धनराशि लगाई गई है। लोगों के लिए यह जानकारी ही बहुत अमूल्य निधि साबित हुई है कि उनके घरों और व्यवसायों को अब बाढ़ों से कोई खतरा नहीं रहा।

'टी वी ए' की बहु उद्देश्यीय बांध प्रणाली के अन्तर्गत जब 'ग्रेट लेक्स आफ द साउथ' नामक जल-प्रणाली का निर्माण नहीं हो गया, तब तक तेज धारा और छिछले चट्टानी तल प्रदेश के कारण टेनेसी नदी में नौका नयन सम्भव नहीं था। अब शान्त जल की ६५० मील लम्बी जल श्रृंखलाएं इस क्षेत्र को राष्ट्र के अन्य आन्तरिक जल-मार्गों से सम्बद्ध करती है।

'टी वी ए' द्वारा ९ फुट के नौका-नयन योग्य जल मार्ग का निर्माण कर दिए जाने के बाद इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास भी तीव्र गति से हुआ। १९३३ के बाद से लेकर अब तक गैर-सरकारी उद्योग तट के किनारे अनेक उद्योगों का निर्माण करने पर ८५ करोड़ ४० लाख डालर से अधिक पूंजी लगा चुके हैं।

उद्योगों के विकास का अर्थ है लोगों के लिए नये काम, प्रादेशिक वस्तुओं और प्रादेशिक साधन-स्रोतों की और अधिक मांग, इसके फलस्वरूप घाटी के निवासियों की आय में और वृद्धि। इसके साथ ही इस जल-मार्ग ने व्यवसायियों को कम खर्च पर इस क्षेत्र में अपनी वस्तुएं पहुँचाने में समर्थ बना दिया है। मध्य-पश्चिमी क्षेत्र के गेहूँ बहुल क्षेत्रों का अनाज इस जल-मार्ग द्वारा टेनेसी की घाटी में स्थित मिलों में पहुँचाया जाता है। इस प्रकार व्यवसायी ढुलाई पर होने वाले व्यय में कमी करने में समर्थ हो गए हैं, तथा राष्ट्र भर के लोगों को नई मण्डियों तथा सस्ती वस्तुएं प्राप्त करना सम्भव हो गया है।

मसेल शोल्ज (अलाबामा) स्थित 'टी. वी. ए. का फर्टलाइजर-म्यूनिशन उर्वरा केन्द्र में रासायनिक उर्वरक एक वैज्ञानिक क्रान्ति से गुजर रहा है, क्योंकि यहां 'टी. वी. ए. के वैज्ञानिक और इन्जिनियर किसानों को अधिक उन्नत कोटि का रासायनिक खाद सुलभ करने और कम लागत पर वस्तुओं का निर्माण करने के हेतु अधिक उन्नत उत्पादन विधियों का विकास करने के लिए अनवरत प्रयत्नशील रहते हैं।

'टी. वी. ए.' के कृषि विकास कार्यक्रम के बीज वे दो रासायनिक कारखाने थे, जिन की स्थापना अमेरिकी स्थल सेना ने युद्ध कार्यों के लिए की थी। कृषि को अधिक स्थायी, अधिक समृद्ध परन्तु साथ ही अधिक लोचशील व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से प्रेरित हो कर गैर-सरकारी उद्योगों और कृषि कालेजों की सहायता से 'टी. वी. ए.' ने शस्त्रास्त्रों का निर्माण करने वाले इन दोनों कारखानों को कृषि उपकरणों का निर्माण करने वाले कारखानों में बदल दिया। 'टी. वी. ए.' द्वारा आयोजित परीक्षणात्मक प्रदर्शन कार्यक्रमों के अन्तर्गत ३१ राज्यों के ऐसे किसान को रासायनिक खाद और टैक्निकल सहायता सुलभ की जाती है, जो कृषि की उन्नत विधियों की प्रभावशालिता अपने पड़ोसी किसानों के समक्ष प्रदर्शित करते हैं।

आज टेनेसी नदी घाटी के १ करोड़ ५० लाख एकड़ अन्य क्षेत्र में से ९६ प्रतिशत क्षेत्र में दावानलों से सुरक्षा की व्यवस्था करली गई है। इस बन्य प्रदेश ने ५० हजार से अधिक व्यक्तियों को लकड़ी-उद्योग अथवा उस से सम्बन्धित अन्य उद्योगों में नौकरियां सुलभ की हैं। क्षरण से क्षत-विक्षत और बेकार भूमि पर रोपित वृक्ष भूमि के क्षरण को रोकने के साथ-साथ किसानों को नकदी आय का साधन भी सुलभ करते हैं।

वस्तुतः आज 'टी. वी. ए.' समस्त संसार में क्रियात्मक लोकतन्त्र का ज्वलन्त उदाहरण माना जाता है। हर वर्ष अन्य देशों के १५०० से अधिक व्यक्ति 'टी. वी. ए.' का निरीक्षण करने के लिए आते हैं। टेनेसी घाटी में आज जो परिवर्तन हो रहे हैं, वे उन परिवर्तनों के अनुकूल हैं, जिनके लिए प्रत्येक राष्ट्र के निवासी आकांक्षी हैं। फलस्वरूप, अन्य देशों की अनेक नदी घाटी निकास योजनाएँ 'टी. वी. ए.' के ढंग पर बनाई गई हैं।

• •

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय

	राष्ट्रीय आय (करोड़ रुपये)		प्रति व्यक्ति आय रुपये	
	तत्कालीन मूल्यों के अनुसार	१९४८-४९ के मूल्यों के अनुसार	तत्कालीन मूल्यों के अनुसार	१९४८-४९ के मूल्यों के अनुसार
१९४८-४९	८,६५०	८,६५०	२४९.६	२४९.६
१९४९-५०	९,०१०	८,८२०	२५६.०	२५०.६
१९५०-५१	६,५३०	८,८५०	२६६.५	२४७.५
१९५१-५२	९,९७०	९,१००	२७४.२	२५०.३
१९५२-५३	९,८२०	९,४६०	२६५.४	२५५.७
१९५३-५४	१०,४८०	१०,०३०	२७८.१	२६६.२
१९५४-५५	९,६१०	१०,२८०	२५०.३	२६७.८
१९५५-५६	९,९८०	१०,४८०	२५५.०	२६७.८
१९५६-५७	११,३१०	११,०००	२८३.३	२७५.६
१९५७-५८	११,३९०	१०,८९०	२७९.६	२६७.३
१९५८-५९	१२,६००	११,६५०	३०३.०	२८०.१
१९५९-६०	१२,९५०	११,८६०	३०४.८	२७९.२
१९६०-६१	१४,१६०	१२,७५०	३२६.२	२९३.७
१९६१-६२*	१४,६३०	१३,०२०	३२९.७	२९३.४

टिप्पणी :—प्रति व्यक्ति आय का अनुमान जनसंख्या की वृद्धि की उस दर पर आधारित है जिसका १९४१, १९५१ और १९६१ की जनगणना के आंकड़ों से पता चला है।

राष्ट्रीय आय के विभिन्न स्रोत

(वर्तमान मूल्यों के आधार पर)

अरब रुपयों में

	१९४८-४९	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१	१९६१-६२
१. कृषि	४२.५	४८.९	४५.२	६९.०	६८.५
कृषि पशु पालन आदि	४१.६	४७.८	४३.९	६६.९	६६.६
जंगल	०.६	०.७	०.७	१.१	१.२
मच्छी पालन	०.३	०.४	०.६	१.०	०.७
२. खाने और छोटे बड़े उद्योग	१४.८	१५.३	१८.५	२६.०	२८.०
खाने	०.६	०.७	१.०	१.६	१.७
कारखाने	५.५	५.५	७.८	१३.२	१४.६
तीसरी पंच वर्षीय छोटे उद्योग	८.७	९.१	९.७	११.२	११.७
३. व्यापार परिवहन आदि	१६.०	१६.९	१८.८	२३.४	२४.७
संचार व्यवस्था	०.३	०.४	०.५	०.६	०.७
रेलें	१.७	१.८	२.५	३.६	३.८
बैंक और बीमा	०.५	०.७	०.९	१.६	१.८
अन्य व्यापार और यातायात	१३.५	१४.०	१४.९	१७.६	१८.४
४. अन्य सेवाएं	१३.४	१४.४	१७.३	२३.७	२५.७
५. देशमें कुल उपज	८६.७	९५.५	९९.८	१४२.१	१४६.९

पंचवर्षीय योजना में निर्धारित व्यय और विनियोजन

करोड़ रु० में

अवधि	सार्वजनिक क्षेत्र निर्धारित व्यय	सार्वजनिक क्षेत्र विनियोजन	निजी क्षेत्र विनियोजन व्यय	कुल विनियोजन
	(१)	(२)	(३)	(४)
पहली पंचवर्षीय योजना	१,९६०	१,५६०	१,८००	३,३६०
दूसरी पंच वर्षीय योजना	४,६००	३,७३१	३,१००	६,८३१
योजना	७,५००	६,३००	४,१००	१०४००
कुल	१४,०६०	११,५९१	९,०००	२०,५९१

सार्वजनिक क्षेत्र के लिए साधन

	पहली योजना	दूसरी योजना	तीसरी योजना
(१) अतिरिक्त कर	७५२	१,०५२	१,७१०
(२) रेलवे का योगदान	(—)	१५०	१००
(३) अन्य सार्वजनिक उद्योगों द्वारा	—	—	४५०
(४) राजस्व का शेष सन्तुलन	—	५०	५१०
(५) सार्वजनिक ऋण	२०५	७८०	८००
(६) छोटी बचत आदि	३०४	५७०	८६५
(७) विविध पूंजीगत आय	१७८	६०	२७५
(८) घाटे की अर्थ अवस्था	३३३	९४८	५५०
(९) विदेशी सहायता	१८८	१,०९०	२,२००
कुल	१९६०	४६००	७५००

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सहकारी आन्दोलन तथा पंचवर्षीय योजना

एस. पी. वार्ष्णेय एम. ए. ए. कॉम

सहकारिता और योजना—दोनों का संचालन एक साथ होना चाहिए। किसानों के कष्टों को दूर करने में तो सहकारिता रामबाण के समान है। पर, इस सहकारिता के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, जिनका गंभीर विवेचन विद्वान् लेखक के शब्दों में पढ़िए—

सहकारी कार्यकर्त्ताओं में आजकल एक विवाद चल पड़ा है कि सहकारी आन्दोलन तथा योजनाएं एक साथ कार्य नहीं कर सकते क्योंकि सहकारी आन्दोलन के सिद्धांत योजना के सिद्धान्तों से मेल नहीं खाते। कुछ लोगों का विचार है कि जहां योजना है वहां सहकारिता की बात हास्यास्पद है परन्तु वास्तव में क्या यह बात सत्य है? इसका विश्लेषण करने के लिये हमें सहकारी आन्दोलन तथा योजना के सिद्धान्तों का अध्ययन करना होगा।

सहकारी योजना समिति (१९४६) के अनुसार "सहकारिता एक प्रकार का संगठन है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक समानता के आधार पर अपने आर्थिक हित में उन्नति के लिये संगठित होते हैं।

इस परिभाषा का विश्लेषण करने पर सहकारिता के निम्न सिद्धान्त दृष्टिगोचर होते हैं।

(१) ऐच्छिक संगठन (वालैंटरी एसोसियेशन)—सहकारी समितियों के सदस्य बनने के लिये कोई दबाव नहीं डाला जाता है। जो भी व्यक्ति सदस्य बनते हैं, अपनी इच्छानुसार ही बनते हैं। सहकारी समिति को छोड़ने की भी स्वतंत्रता प्रत्येक सदस्य को होती है। संस्था में लगी सभी सम्पत्ति छोड़ने पर लौटा दी जाती है।

(२) लोकतंत्र प्रबन्ध (डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन)—हर सदस्य का स्तर बराबर होता है। पूंजी अधिकार का आधार नहीं है। हरएक सदस्य को एक वोट दिया जाता है चाहे उसने कितनी ही पूंजी लगाई हो। इस प्रकार से सहकारिता में शोषण का स्थान नहीं है।

(३) लाभ का समानता के आधार पर वितरण—समिति में लाभ होने पर उसका वितरण समानता के आधार पर होता है। जो व्यक्ति जितना अधिक समिति को लाभ कराता है उतना ही अधिक लाभ उसको समिति से मिलता है। उदाहरण के लिये, यदि एक उपभोक्ता समिति में ५ रु० सैंकड़ा लाभ का वितरण होता है तो १०० रु० का सामान खरीदने वाले को ५ रु० लाभ तथा ५०० रु० का सामान खरीदने वाले को २५ रु० लाभ में से हिस्सा मिलेगा।

(४) सर्वव्यापकता (यूनिवर्सल इंट्रिप्रेशन)—एक सहकारी समिति का सदस्य कोई भी चरित्रवान व्यक्ति हो सकता हैं। जाति, रंग, नस्ल या धर्म का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है।

(५) स्वशासन (आटोनामी)—एक सहकारी संस्था का प्रबन्ध उसके सदस्य ही करते हैं। सहकारी संस्था न तो सरकार से कोई सहायता मांगती है तथा न कोई प्रबन्ध में दखल ही पसन्द करती है। उत्पत्ति, बिक्री, प्रबन्ध इत्यादि से सम्बन्धित सभी नीतियां समिति के सदस्य निर्धारित करते हैं।

(६) पारस्परिक सहायता—पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता होती है। जो लोग आपस में मिलकर सहकारी संस्था स्थापित करते हैं अपनी व्यक्तिगत कमजोरी के कारण एक दूसरे की सहायता के बिना कार्य नहीं चला सकते और क्योंकि सबको एक साथ ही सहायता की आवश्यकता नहीं होती, जैसे एक सहकारी साख समिति में—वहां जिन लोगों को सहायता की आवश्यकता होती है, उनकी सब मिलकर सहायता करते हैं। इस प्रकार समय समय पर सबकी सहायता होती रहती है। इसके अतिरिक्त दूसरे लोगों के साथ उन्नति करना, न कि दूसरे लोगों को पीछे छोड़कर उन्नति करना सहकारिता का उद्देश्य है।

डिकिनसन के अनुसार "आर्थिक नियोजन से तात्पर्य बड़े-बड़े आर्थिक निर्णयों को करना है। एक तय करने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वाली सत्ता पूरी आर्थिक पद्धति की व्यापक जांच पड़ताल के द्वारा सोच विचार करके निर्णय करती है कि क्या और कितना उत्पन्न करना है और यह किसे मिलना है।

इस प्रकार योजना में एक सत्ता के अन्तर्गत कार्य करना पड़ता है तथा योजना सर्वव्यापी भी हो सकती है। सारी आर्थिक क्रियाओं—उत्पादन, उपभोग, वितरण तथा विनिमय—पर एक ही केन्द्रीय अधिकारी का नियंत्रण होता है। इसके विपरीत सहकारिता जनसाधारण का आन्दोलन है और कोई केन्द्रीय प्रभुसत्ता नहीं होती। सभी कार्य सदस्यों की इच्छा के अनुसार होते हैं। सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती। सहकारी आन्दोलन योजना की तरह सारे प्रदेश में एक साथ लागू नहीं किया जाता। यह तो धीरे-धीरे बढ़ता जाता है क्योंकि सहकारी संस्थाओं के दरवाजे हर एक के लिये खुले हैं, चाहे कुछ लोग उसमें शामिल हों या सब। वस्तुतः बिना दबाव के कभी भी किसी देश में सहकारी संस्थाओं में सभी लोग शामिल नहीं हुए हैं, चाहे सहकारिता का कार्य कितना ही प्रशंसात्मक क्यों न हो। अतः कुछ लोगों के विचार में सहकारिता और योजना एक साथ लागू नहीं किये जा सकते।

सहकारिता में दबाव नहीं

परन्तु दोनों विचारों का गहन अध्ययन करने पर कहा जा सकता है कि योजना और सहकारी आन्दोलन साथ-साथ चल सकते हैं। हमारे देश की सहकारी संस्थाएं इसका उदाहरण हैं। सहकारिता एक ऐच्छिक संगठन है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि सहकारी संस्थाओं को राज्य की नीतियों के विरुद्ध चलने का अधिकार है। ऐच्छिक संगठन से तात्पर्य तो यह है कि एक मनुष्य को सहकारी समिति में शामिल होने का अधिकार है चाहे वह शामिल हो या न हो यह बात दूसरी है। इसके अतिरिक्त शामिल होने पर वह उसे छोड़ भी सकता है। सदस्यों को यह भी स्वतंत्रता है कि वे व्यक्तिगत रूप में किसी भी राजनैतिक संस्था के सदस्य हो सकते हैं। इस दृष्टि से सारे देश के अन्दर सभी सहकारी संस्थाएं ऐच्छिक संगठन हैं। संयुक्त खेती जैसे महत्वपूर्ण विषय में भी अनिवार्यता या दबाव का प्रयोग नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा यह कहा है कि सहकारिता चाहे धीमी गति से बढ़े परन्तु दबाव का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वित्तीय सहायता, विज्ञापन, शिक्षा, सस्ता तथा मुफ्त साहित्य का वितरण, सहकारी संस्थाओं को सरकारी व्यक्तियों की मुफ्त सेवायें आदि देकर सहकारिता को बढ़ावा दिया जाता है, दबाव का प्रयोग नहीं किया जाता। सहकारी संस्थायें एक योजना के अनुसार आगे बढ़ रही हैं तथा जनता को लाभ पहुंचा रही हैं। योजना बनाते समय सहकारी संस्थाओं से परामर्श लिया जाता है और फिर योजना के अनुसार उनको चलना पड़ता है। सरकार केवल साधारण नीतियों का निर्धारण करती है तथा सहकारी संस्थाओं के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। इस प्रकार भारत में योजना तथा सहकारिता साथ-साथ चल रही है और यह दलील कट जाती है कि जहां योजना है वहां सहकारिता की बात हास्यास्पद है।

भारत जैसे अर्ध विकसित देश के लिये सहकारिता ही ऐसा हथियार है जिसके द्वारा भारत की जनता का उद्धार किया जा सकता है। भारत की जन-संख्या का एक बहुत बड़ा भाग गांवों में रहता है तथा गांवों के लिये जहां और कोई व्यवस्था चलाना कठिन तथा सामर्थ्य के बाहर है, सहकारी संस्थायें ही अत्यन्त उपयोगी रहेंगी, क्योंकि ये जन साधारण की संस्थायें हैं तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप हैं। इस सिद्धान्त को "कृषि रायल कमीशन" के विचारों से पुष्टि मिलती है। कमीशन ने कहा है कि "अगर सहकारिता असफल होती है तो भारतीय कृषि की सभी आशाओं पर पानी फिर जाएगा। वास्तव में सहकारिता के अलावा अन्य किसी ढंग से ग्रामीण जनता का भला करना कठिन प्रतीत होता है।" १९५४ में अखिल भारतीय ग्रामीण साख जांच समिति ने स्पष्ट कहा था कि "यद्यपि सहकारिता असफल हो गई है परन्तु इसको सफल होना ही चाहिये" इस कथन से हम समझ सकते हैं कि आज के युग में हमारे देश में सहकारिता की कितनी आवश्यकता है।

शोषण का एकमात्र इलाज—सहकारिता

भारत की अर्थ-व्यवस्था की उन्नति ग्रामों की उन्नति पर निर्भर है। गरीब किसान को अधिक उत्पादन के लिये अच्छे बीज, खाद तथा औजारों की जरूरत रहती है;

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अपनी भूमि में सुधार करने की, ट्यूबवैल तथा पक्के कुएं आदि बनवाने की आवश्यकता है। इसके लिये धन चाहिये। साहूकारों द्वारा धन महंगा पड़ता है। व्यापारिक बैंक अच्छी प्रतिभूति न होने के कारण कोई विशेष सहयोग नहीं दे रहे हैं, अतः केवल सहकारी बैंक ही किसानों को उचित ब्याज पर रु० दे सकते हैं। इसके अलावा किसानों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं के बिक्री केन्द्र इस प्रकार के होने चाहिये जिससे उनका शोषण न हो। कहा जाता है कि किसानों को कीमत का जो उपभोक्ता देता है ५५% से ७०% तक ही मिलता है। यह प्रतिशत फल, अंडे, मछली इत्यादि जैसी शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं में और भी कम होता है, इसलिये इस शोषण का एक मात्र इलाज सहकारी बिक्री है।

समाजवादी समाज की स्थापना करने का भी सहकारिता एक बहुत सुन्दर ढंग है। पूंजीवाद से अब हम समाजवाद की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो सहकारिता को ही लाना होगा। साम्यवाद के क्रान्तिकारी परिवर्तनों के कुप्रभावों को हम भली भांति जानते हैं। इन सब कार्यों को पूरा करने के लिये हमें योजनाओं की आवश्यकता है। योजना आयोग भी इन्हीं विचारों को व्यक्त करता है, तथा आयोग की राय में खेती, सिंचाई की छोटी-छोटी योजनायें, लघु स्तरीय उद्योग, खेती की वस्तुओं की बिक्री, मकान बनाने की योजनायें, विशेष रूप से सहकारिता में अच्छी प्रकार सम्पन्न हो सकती हैं। तीसरी योजना में भी सहकारिता के कुछ लक्ष्य रखे गये हैं जैसे योजना के अंत तक ६०% किसान संख्या प्राथमिक साख समितियों की सदस्य बन जाएंगे तथा सदस्य संख्या ३.७ करोड़ तक हो जायेगी। ऐसा अनुमान है कि कृषकों के लिये ५३० करोड़ रु० का अल्पकालीन तथा मध्यकालीन वार्षिक ऋण समितियां दे सकेंगी। १५० करोड़ रु० की दीर्घकालीन साख की व्यवस्था का अनुमान है। तीसरी योजना के अंत तक प्रत्येक मंडी में कम से कम एक सहकारी बिक्री समिति हो जायेगी। इस प्रकार २५०० बिक्री समितियों के स्थापित सहकारिता से न केवल सारे देश को लाभ पहुंचने की आशा है, बल्कि हम तो संसार में एक सहकारी राष्ट्र-मण्डल स्थापित करने का स्वप्न देख रहे हैं। ●

संचालक, पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश

की

विज्ञप्ति संख्या ४।५५८० : २७।३३, दिनांक १५

द्वारा

पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत

सुन्दर पुस्तकें

		रु०	आ०
वेद सार	प्रो० विश्वबन्धु	१	८
प्रभु का प्यारा कौन ? (२) भाग ?			
सच्चा सन्त		३	
सिद्ध साधक कृष्ण		३	
जीते जी ही मोक्ष		३	
आदर्श कर्मयोग		३	
विश्व-शान्ति के पथ पर		१	
भारतीय संस्कृति	प्रो० चारुदेव		
बच्चों की देखभाल	प्रिंसिपल बहादुरमल	१	१२
हमारे बच्चे	श्री सन्तराम बी. ए.	३	१३
हमारा समाज		३	
व्यावहारिक ज्ञान		२	१२
फलाहार		१	४
रस-धारा		०	१४
देश-देशान्तर की कहानियां		१	
नये युग की कहानियां		१	१२
गल्प मंजुल	डा० रघुबरदयाल	१	
विशाल भारत का इतिहास	प्रो० वेदव्यास	३	८

१० प्रतिशत कमीशन और ५० रु० से ऊपर के आदर्शों पर १५ प्रतिशत कमीशन।

विश्वेश्वरानन्द पुस्तक भंडार

साधु आश्रम, होशियारपुर, पंजाब

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अमरीका में भी "निर्धनता" पर....?

प्रो० के० बी० माधव

"अमेरिका में गरीबी" ये शब्द एक भारतीय पाठक के लिए आश्चर्य पैदा करने वाले हैं । हमारे दिमाग में अमेरिका का जो चित्र है, उसके अनुसार वह 'सोने की लंका' के समान समृद्धि से आपूरित देश है। पर तथ्य यह है कि वहां पर गरीबी को मापने का स्तर हमारे देश से सर्वथा भिन्न है। अमेरिका के ३ करोड़ ८० लाख व्यक्ति—अर्थात् कुल आबादी के एक चौथाई से अधिक—"निर्धनता" पर गुजारा कर रहे हैं और अन्य ३ करोड़ ९० लाख व्यक्ति "अभाव" की अवस्था में हैं।

अमेरिका की एक गैर— राजनीतिक और आर्थिक अनुसंधान में लगी "कान्फ्रेन्स आन इकोनामिक प्रोग्रेस" संस्था ने इस विषय में काफी खोज के बाद आंकड़े इकट्ठे किये हैं। अमेरिका के आर्थिक जीवन पर ये दिलचस्प प्रकाश डालने वाले हैं।

अमेरिका में "निर्धनता" को एक सापेक्ष शब्द समझ कर उसका सम्बन्ध जीवन की आवश्यकताओं, जीवन स्तर, उस स्थान का जीवन-व्यय इत्यादि के साथ जोड़ा जाता है। अमेरिका में ऐसा परिवार जिसकी वार्षिक आय लगभग ९.७५० रु० (२००० डालर) हो, अत्यन्त निर्धन समझा जाता है जब कि इतनी ही आय वाला परिवार भारत जैसे अनुन्नत देश में पर्याप्त समृद्ध माना जाता है। ९.७,५० रु० (२००० डालर) से कम आय वाला, "परिवार" से असम्बद्ध, अकेला रहने वाला "निर्धनता की रेखा" से भी निम्न समझा जाता है और कई व्यक्तियों वाले परिवार की वार्षिक आय अगर १९,५०० रु० (४००० डालर) से कम हो तो उस परिवार को "निर्धन" कक्षा में शामिल किया जाता है।

दूसरी श्रेणि है "अभावग्रस्त" की, अर्थात् व्यक्ति की आय ९.७५० रु० और १४.६२५ रु० के बीच (२००० डालर और ३ हजार डालर के बीच) और बहु सदस्यक परिवार की १९.५०० रु० और ४९,३७५ रु० (४००० से ६००० डालर के बीच)। इस श्रेणि को "सुख-सुविधा-रहित" कहा जाता है। अमेरिका में "समृद्ध" शब्द इतना अस्पष्ट है कि इस "समृद्धि" की प्रारम्भिक रेखा कहां पर है—यह पता लगाना कठिन है। १९६० की जन संख्या के अनुसार, अमेरिका के लगभग ४ करोड़ ५० लाख बहु सदस्यक परिवारों में से केवल ७.३ प्रतिशत और अकेले व्यक्ति रूप से रहने वाले १ करोड़ अथवा १ करोड़ १० लाख में से लगभग ५ लाख व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आय लगभग ६७.००० रु० (१५,००० डालर) व इससे अधिक है। इन्हें "समृद्ध" श्रेणि में रखा जा सकता है।

यह आर्थिक अनुसंधान समिति प्रो० गाल ब्रेथ के इस कथन से सहमत हैं कि "अमेरिका में निर्धनता कोई बोझिल संकट नहीं है। यह, लगभग, बाद का विचार है।" समिति का कहना है कि यह परिणाम निकालना न्याय-संगत ही है कि लगभग ४५०० रु० (१,००० डालर) वार्षिक से कम आय वाले परिवार अमेरिका में निर्धन हैं और एक परिवार की न्यूनतम आय १८,००० रु० (४,००० डालर) निर्धनता से ऊपर है।

समिति का कहना है कि अमेरिका में इस समय दो समस्याएं बढ़ रही हैं—बेरोजगारी और निर्धन-समृद्ध के बीच की भेद रेखा। समिति की शिकायत है कि अमेरिकी योजनाओं का रुख, इस समय, सोवियत रूस की नकल करते हुए शस्त्रों की वृद्धि, आकाशीय ग्रहों की खोज और अन्तर राष्ट्रीय सहायता की ओर अधिक है । इस प्रकार अमेरिका "नेता" बनने के बदले सोवियत रूस का "अनुगामी" बन रहा है। समिति ने यह भी खोज करके बताया है कि अमेरिका की उत्पादन शक्ति और उसके उचित प्रयोग के बीच गहरा भेद है जिसका परिणाम यह है कि आर्थिक वितरण विषम हो रहा है।

ऐसी परिस्थितियों के फलस्वरूप अमेरिका की समस्याएं बेरोजगारी, अवसरों का विषम वितरण, सामाजिक, सुरक्षा और आय की सुव्यवस्था—यह सब हैं।

समिति के अनुसार, अमेरिका में १९६० के स्तर के अनुसार १९३५-३६ से १९४७ के बीच निर्धन व्यक्तियों

(शेष पृष्ठ ३०६ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आपत्तिकाल में मूल्य निर्धारण

श्री परसराम मनवानी, बी० काम०

आपत्तिकालीन में मूल्यों के निर्धारण के कुछ विशेष पहलू होते हैं जिन्हें जानना एक स्वतंत्र देश ने नागरिकों के लिए आवश्यक हो जाता है। ऐसी जानकारी से देश की आर्थिक स्थिति को संगठित तथा सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलती है।

मांग और मूल्य का सम्बन्ध

किसी भी वस्तु की मांग का उसके मूल्य से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। ग्राहकों की किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा इस पर निर्भर होती है कि उन्हें इसके लिए कितना मूल्य देना पड़ेगा। इसलिए सामान्यतः, यह देखा गया है कि किसी वस्तु के मूल्य के गिरने के साथ-साथ उसकी मांग की मात्रा बढ़ती जाती है और मूल्य के ऊंचे होने के साथ-साथ वह कम होती जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी वस्तु की मांग और मूल्य में विपरीत सम्बन्ध होता है। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि जिस अनुपात में मूल्य घटता या बढ़ता है उसी अनुपात में मांग भी घटे या बढ़े। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि यदि उनका मूल्य तनिक सा भी घट जाए तो मांग की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जब ऐसी वस्तुओं का मूल्य थोड़ा सा भी बढ़ जाता है तो मांग बहुत घट जाती है। कुछ अन्य वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी मांग की मात्रा मूल्य के घटने और बढ़ने से बहुत कम प्रभावित होती है।

ऐसी वस्तुओं के मूल्य में, जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, कितनी भी घट बढ़ हो, उनकी मांग बहुत कुछ वही रहती है। परन्तु आराम की वस्तुओं के विषय में यह बात देखी गई है कि मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में होता है जिसमें कि मूल्य में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में होता है जिसमें कि मूल्य में परिवर्तन होता है। विलासिता की वस्तुओं की मांग बहुत लोचदार होती है। ये ऐसी नहीं होती कि जिनके बिना काम चल ही न सके। यदि इनका मूल्य बढ़ जाता है तो उनका उपभोग कम हो जाता है। यदि इनका मूल्य गिर जाए तो इनका उपभोग बहुत बढ़ जाता।

इसके साथ ही किसी वस्तु की मांग की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी और कोई स्थानापन्न वस्तु है अथवा नहीं। जिस एक वस्तु की बहुत-सी स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, उसकी मांग ऐसी वस्तु की अपेक्षा, जिसकी स्थानापन्न वस्तु हो ही नहीं, अधिक लोचदार होगी।

पूर्ति का मूल्य पर प्रभाव

जिस प्रकार मूल्य के परिवर्तन का वस्तुओं की मांग पर प्रभाव पड़ता है उसी प्रकार वस्तुओं की पूर्ति पर भी पड़ता है। जब मूल्य बढ़ता है तब पूर्ति भी बढ़ जाती है और जब मूल्य घटता है तब पूर्ति भी घट जाती है। जब मूल्य बढ़ जाता है तो ऐसे उत्पादकों को भी, जिनकी लागत अधिक होती है, माल उत्पादन करने और बेचने में लाभ होने लगता है। अतः वे उत्पादन करने लगते हैं और कुल उत्पत्ति बढ़ जाती है। इसके विपरीत, यदि मूल्य कम हो गया, तो कुछ उत्पादक जिनकी लागत मूल्य से अधिक होती है माल बेचना रोक देते हैं, इस प्रकार पूर्ति कम हो जाती है।

आपत्ति काल में मूल्य अधिक

परन्तु आपत्तिकाल में मूल्य को मांग और पूर्ति की शक्तियों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसे समय में सेना के लिए बहुत से माल की आवश्यकता पड़ती है और कभी कभी कारखानों व खेतों आदि का विनाश भी बहुत होता है। अतः साधारण जनता के उपभोग के लिए माल की कमी हो जाती है, अर्थात् माल की पूर्ति कम और मांग अधिक। इसका परिणाम यह होता है कि मूल्य ऊंचा होने लगता है। मूल्य ऊंचा होते जाना जनता के लिए बहुत कष्टमय होता है। विशेषतः, नौकरी पेशे वालों की आय स्थिर रहती है और यदि सब वस्तुओं के मूल्य बढ़ते जांए तो उन्हें कई दिक्कतों का अनुभव करना पड़ता है। तब सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है और यह प्रयत्न

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

किया जाता है कि मूल्य बढ़ने न पाए।

युद्धकाल में सेना को बहुत-सी सामग्री की आवश्यकता होती है जिसे सरकार खरीद लेती है। इससे जनता के लिए माल की पूर्ति में कमी हो जाती है। इसके दो प्रभाव होते हैं। एक तो कीमतें बढ़ने लगती हैं और दूसरा सभी लोगों को आवश्यक वस्तुओं का मिलना कठिन हो जाता है। जिनके पास अधिक पैसा होता है वे बाजी मार जाते हैं और अपनी जरूरत से भी अधिक माल खरीद लेते हैं। इसके विपरीत जो कम पैसे वाले होते हैं उनको वस्तुएं या तो मिल नहीं पातीं या वे अधिक मूल्य न दे सकने के कारण खरीद नहीं सकते। इसके साथ ही सेना का व्यय भी कई गुना अधिक बढ़ जाता है जिससे मुद्रा स्फीति की स्थिति आ जाती है और रुपये की क्रय शक्ति गिरने लगती है। परन्तु मूल्यों को बाजार की सामान्य शक्तियों की दया पर नहीं छोड़ दिया जाता। सरकार मूल्य नियंत्रण, राशनिंग और वितरण व्यवस्था द्वारा हालात को सुधारने की चेष्टा करती है।

मूल्य नियंत्रण से लाभ व हानि

मूल्य नियंत्रण एक ऐसा साधन है जिससे मूल्यों पर जल्दी से काबू पाया जा सकता है। परन्तु पिछले युद्धों के इतिहास से यह पता चलता है कि अपने आप में यह साधन अर्थात् मूल्यों को निर्धारित करना, काफी नहीं होता। इससे कई कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। या तो चोर-बाजारी के कारण यह साधन बिल्कुल ही प्रभाव खो बैठता है और लोग कानून तोड़ने लगते हैं या फिर जिन वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण लगाया जाता है वे बाजार से गायब होने लगती हैं।

यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि व्यवहार में हर एक वस्तु के मूल्य का नियंत्रण करना सम्भव नहीं होता और न ऐसा किया ही जा सकता है। कुछ खास वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण लगाया जाता है जिससे उन वस्तुओं के उत्पादन करने में लाभ कम होने लगता है और उत्पादनकर्ता ऐसी वस्तुएं बनाना शुरू कर देते हैं जिनके मूल्य नियंत्रित नहीं होते और जिनमें लाभ की गुंजायश अधिक रहती है। इसलिए सरकार के लिए खपत और पैदावार पर भी नियंत्रण लगाना आवश्यक हो जाता है।

खपत पर राशनिंग द्वारा नियंत्रण लगाया जाता है, यह निश्चित कर दिया जाता है कि हर एक व्यक्ति 'अमुक' वस्तु की अधिकतम कितनी मात्रा खरीद सकता है। राशनिंग का आसान तरीका यह है कि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा को आंका जाए, उसे देश की जनसंख्या से भाग दिया जाए, ताकि यह पता लगे कि देश के हर व्यक्ति के लिए कितनी वस्तु उपलब्ध हो सकती है। इसके बाद हर एक व्यक्ति को एक राशन कार्ड दिया जाए जिससे वह निश्चित अवधि में निश्चित मात्रा में ही वस्तुएं खरीद सके। यह बात जितनी ही कहने में आसान है उतनी ही करने में कठिन है क्योंकि लोगों की आदतें और आवश्यकताएं एक समान कभी नहीं होतीं। जैसे, एक ऐसे आदमी को जो कड़ी मेहनत करता है उतना ही राशन देना जितना कि एक बच्चे को दिया जाता है, अनुचित होगा। इसलिए विभिन्न वर्गों के लिए विशेष राशन प्रणालियां लागू करनी पड़ती हैं। यह बात अवश्य है कि राशन प्रणाली को कितना भी सोच विचार कर क्यों न बनाया जाए, फिर भी सभी व्यक्तियों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकतीं। राशनिंग का यह मूल-भूत सिद्धान्त है कि कुछ आवश्यक वस्तुओं का राशनिंग न करके उन पर केवल मूल्य नियंत्रण ही लागू किया जाता है।

कच्चे माल का भी नियंत्रण

खपत के राशनिंग के साथ-साथ उत्पादन के लिए मिलने वाले कच्चे माल पर भी नियंत्रण लगाया जाता है। यह काम इतना आसान नहीं होता जितना खपत का राशनिंग होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक उद्योग की बिलकुल ही भिन्न आवश्यकताएं होती हैं और सभी को एक समान कच्चा माल देने से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए इस प्रकार का नियंत्रण लगाने से पहले उद्योगों को वर्गीकृत किया जाता है और यह वर्गीकरण युद्ध की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर किया जाता है। ऐसे उद्योगों को, जिनके माल की युद्ध के लिए अधिक आवश्यकता होती है, प्राथमिकता दी जाती है और उसी अनुपात के उसके लिए कोटा निर्धारित किया जाता है। सामान्यकाल में यदि किसी उद्योग को किसी कच्चे माल की अधिक आवश्यकता होती है और यदि वह मार्केट में कम होता है तो अधिक मूल्य देकर उस कच्चे माल को खरीद

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लिया जाता है, यहां तक कि, अपने से भी अधिक आवश्यकता वाले उद्योग को वंचित रखा जा सकता है। परन्तु नियंत्रण से यह लाभ होता है कि इसके अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही नहीं की जा सकती, सरकार को सबसे पहले उस उद्योग की आवश्यकताओं के बारे में सन्तुष्ट करना अनिवार्य हो जाता है।

कर वृद्धि और ऋण लेना

युद्ध काल में मुद्रास्फीति के कारण बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए सरकार जिन अन्य उपायों को काम में लाती है वे हैं करों को बढ़ाना तथा जनता से ऋण लेना। ऐसा होना असम्भव है कि युद्धकाल में भी सरकार बिना करों को बढ़ाए काम चला सके। ऐसे समय में करों को बढ़ाना न केवल सरकारी आय बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है किन्तु इसलिए भी आवश्यक होता है क्योंकि ऐसा करने से बाजार से पैसा खिंच आता है और लोगों की क्रयशक्ति घट जाती है। क्रयशक्ति के कम होने से वस्तुओं के लिए मांग कम हो जाती है और स्वतः ही मूल्यों के बढ़ने में रुकावट आ जाती है। द्वितीय महायुद्ध के समय करों को बढ़ाने के साथ करों के कानून में भी काफी सुधार किए गए थे। आय कर में यह नियम बना दिया गया कि कमाने के साथ ही साथ आयकर भी जमा कराया जाए। ऐसा करने से सरकारी आय बढ़ने के साथ-साथ वस्तुओं का उपयोग भी नियंत्रित हो गया। फिर भी करों की बढ़ाने की भी हद होती है जिसके बाद नहीं बढ़ाए जा सकते। तब, सरकार को जनता से ऋण लेने पड़ते हैं, जैसे वर्तमान आपत्ति के कारण सरकार ने कई प्रकार की नई ऋण योजनाएं चालू की हैं, नैशनल डिफेन्स सर्टिफिकेट, गोल्ड बांड इत्यादि। ऐसे ऋणों से कई अप्रत्यक्ष लाभ भी होते हैं। जब व्यापारियों और कम्पनियों से ऋण लिए जाते हैं वे अपने खर्चे कम कर देते हैं, जनता की क्रयशक्ति कम हो जाती है और कीमतों में रुकावट आती है।

इसके विपरीत यदि सरकार चाहे तो नोट छाप सकती है तथा बैंकों से ऋण लेकर आसानी से युद्ध का खर्चा चला सकती है परन्तु इससे एक ओर मुद्रास्फीति और दूसरी ओर कीमतें हद से अधिक बढ़ जाती हैं। ऐसे तरीकों को तभी काम में लाया जाना चाहिए जब और साधनों से धन एकत्र करना कठिन हो जाए।

सरकारी हाथों में उद्योग व दुकानें

इसके अलावा ऐसे उद्योगों को जो युद्ध के लिए आवश्यक माल बनाते हैं अथवा जिनको निजी व्यापारियों के हाथों में हानि की सम्भावना रहती है, सरकार अपने हाथ में ले लेती है। ऐसा करने से सरकार अपनी नीति के अनुसार आसानी से उत्पत्ति का रुख बदल सकती है और युद्ध के लिए साधन जुटा सकती है। इसके अलावा ऐसे उद्योगों से होने वाला लाभ भी सरकारी खजाने में जाता है। एक यह भी लाभ होता है कि पूंजीपतियों को कीमतों को ऊंचा करने का प्रोत्साहन कम मिलता है क्योंकि अगर कीमतें चढ़ गयीं तो सरकार के हस्तक्षेप का डर रहता है कि कहीं वह ऐसे उद्योगों को अपने नियंत्रण में न लेले।

मूल्यों पर काबू रखने और आवश्यक वस्तुओं की जनता की उपलब्धि के लिए सरकार फुटकर दुकानें भी खोलती है। इस संकटकाल में हमारी सरकार ने सहकारी दुकानें खोलने पर अत्यधिक जोर दिया है और सहकारी संस्थाओं तथा उपभोक्ताओं की सहकारी दुकानों को हर प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि वर्त्तमान संकट के कारण किसी भी हालत में मूल्यों को बढ़ने नहीं दिया जाएगा बल्कि उनको कम करने की चेष्टा की जाएगी। इस दिशा में जनता का उत्साह तथा व्यापारियों का कार्य सराहनीय रहा है। चेम्बर्स आफ कामर्स तथा अन्य छोटे-छोटे व्यापारियों के संगठनों द्वारा ऐसी घोषणाएं की गई हैं कि वे कीमतों को नहीं बढ़ने देंगे, और व्यापारियों ने ऐसा किया भी है। उपभोक्ताओं को चाहिए कि वे अधिक से अधिक सहकारी दुकानें खोलें और प्रयत्न करें कि कीमतों के बारे में सरकार पर कम से कम बोझ पड़े ताकि सुरक्षा के कामों की तरफ ध्यान केन्द्रित किया जा सके।

हमें इस संकटकाल में यह मिसाल कायम करनी है और भारत के आर्थिक इतिहास में पहली बार करनी है कि युद्धकाल में भी भारत में कीमतें बढ़ने के स्थान पर कम हुईं और उत्पादन घटने के स्थान पर इतना बढ़ा कि सेना और जनता की आवश्यकताएं पूरी होने के बाद माल का निर्यात पहले से अधिक किया गया। अपव्यय को भी बंद करना होगा। ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कागज़ उद्योग और उसकी समस्याएं

श्री सरदार मल जैन, बी० काम०

साक्षरता और राष्ट्रीय जीवन के चौमुखी विकास के साथ-साथ कागज का उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। कागज किसी देश की विकास की गति का अच्छा मापक है। इस दृष्टि से भारत अभी बहुत पीछे है। कच्चे माल की कमी इस उद्योग की एक बड़ी समस्या है। गन्ने की छोई से कागज बन सकता है पर यह खेद की बात है कि चीनी मिलें उसे आग में फूंककर नष्ट कर देती हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय धन का नाश हो रहा है।

ज्ञान-संवर्द्धन का आधार-स्तम्भ कागज भारत को चीन की देन है। विश्व में सर्व प्रथम कागज का उत्पादन चीन में शुरू हुआ। प्रारम्भ में कागज हाथ से बनाया जाता था और आज भी, भारत के कई भागों में, कागज हाथ से बनता है। आधुनिक प्रणाली पर कागज का निर्माण सर्व प्रथम १९वीं शताब्दी के अन्त में शुरू हुआ जबकि १८६७ में पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी के किनारे "बाली पेपर मिल" की स्थापना हुई। १८८० में सरकार ने देशी कागज उद्योग के साथ प्राथमिकतापूर्ण व्यवहार की घोषणा की। परिणामस्वरूप उद्योग को विस्तार की प्रेरणा मिली और १९०० तक देश में ७ कारखाने हो गये जिनकी उत्पादन क्षमता १९००० टन प्रति वर्ष थी। प्रथम महायुद्ध काल में उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिला, पर युद्धोपरान्त आने वाली प्रतिस्पर्द्धा ने उद्योग की स्थिति डांवाडोल कर दी। फिर भी १९२४ तक कागज का उत्पादन ३३००० टन हो गया और मिलों की संख्या ९ हो गई। १९३३ में उत्पादन ४३००० टन था जो १९४३ में बढ़कर १ लाख टन हो गया। द्वितीय महायुद्ध के कारण कागज का आयात बन्द हो गया, अतः विवश होकर १९४२ में सरकार को मूल्य नियंत्रण करना पड़ा। यह नियन्त्रण १९५१ तक लागू रहा। उसके बाद से अब उद्योग का नियन्त्रण उद्योग विभाग एवं नियमन अधिनियम के द्वारा होता है।

वर्तमान-स्थिति

इस समय भारत में कागज के छोटे-बड़े २० से ज्यादा कारखाने हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है—प० बंगाल ४, बम्बई ३, मध्य प्रदेश में २, उत्तर प्रदेश में २, बिहार, उड़ीसा, पंजाब—प्रत्येक में १-१ व दक्षिण भारत में ६, और मैसूर, ट्रावनकोर, हैदराबाद और मद्रास में। देश की कुछ प्रमुख पेपर मिलें इस प्रकार हैं-(१) अपर इंडिया कूपर पेपर मिल्स, लखनऊ (१८७९), टीटागढ़ पेपर मिल्स, बंगाल (१८८२), डेकन पेपर मिल्स, पूना (१८८७) पंजाब पेपर मिल्स (१९२५) स्टार पेपर मिल्स (१९३६) ओरियंट पेपर मिल्स (१९३६) आदि।

नई मिलें—भारत सरकार द्वारा नियुक्त 'पेपर पैनल' ने कागज के २२ नये कारखाने खोलने का परामर्श दिया है। बांगड, सोमानी समूह ने कागज का एक कारखाना वैस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लि० के नाम से बम्बई राज्य के कारावाड जिले में डंडेली के निकट स्थापित किया है। इसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन ६० टन कागज होगी। महाराष्ट्र के कोयना बिजली क्षेत्र में एक कारखाना श्री शांतिप्रसाद जैन व दूसरा कोल्हापुर में बिड़ला ग्रुप स्थापित कर रहे हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता १०० टन प्रतिदिन होगी। इन्हें अनुमति पत्र मिल चुके हैं। आन्ध्र में भी निजी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी जा चुकी है। एक कारखाना उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है। ७ नई मिलें स्थापित करने के लाइसेंस दिए जा चुके हैं। दो कारखाने भवानीपुर व मैसूर (मद्रास राज्य) में स्थापित हो रहे हैं। पंजाब व हिमाचल प्रदेश में भी एक-एक कारखाना खोला जा रहा है।

इसके अलावा सरकार १३५ लघु स्तर के कागज का निर्माण करने वाले संयत्रों की स्थापना करना चाहती है। इनमें से ६० से अधिक को उत्पादन लाइसेंस दिए जा चुके

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हैं। ऐसी आशा की जाती है कि प्रत्येक छोटे संयत्र के लिए कागज की विशेष किस्म का निर्माण करने का काम अलग अलग सौंपा जाएगा।

उत्पादन—आजकल देश में लगभग ४ लाख टन कागज का वार्षिक उत्पादन होता है। सेल्यूलोज के विशेषज्ञ श्री डब्ल्यू० ेट ने अनुमान लगाया है कि यदि भारत में सभी साधनों का उचित उपयोग किया जाय तो वह अकेला ही ४० वर्ष तक सारे विश्व की कागज की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। पिछले वर्षों में कागज का उत्पादन इस प्रकार रहा—

वर्ष	उत्पादन
१९५५	१,८४,८८४ टन
१९५६	१,९३,४०४ ,,
१९५७	२,१०,१३२ ,,
१९५८	२,८३,००४ ,,
१९५९	२,९४,०२४ ,,
१९६०	३,४६,३२४ मीट्रिक टन
१९६१	३,६३,९९२ ,,
अगस्त १९६२	२,५२,२३८ ,,

स्पष्ट है कि कागज का उत्पादन निरन्तर बढ़ रहा है। अकेला पश्चिमी बंगाल देश के कुल उत्पादन का ७५% भाग उत्पन्न करता है।

प्रति व्यक्ति खपत—हमारे देश में शिक्षा का पर्याप्त विकास न होने के कारण कागज की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक खपत केवल ३ पौंड ही है जो कि विश्व के अन्य देशों की तुलना में नगण्य है।

देश	प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत खपत
अमेरिका	३५० पौंड
इंग्लैंड	१७५ ,,
कनाडा	१५० ,,
जर्मनी	७५ ,,
मिस्र	४ ,,
भारत	३ ,,

अखबारी कागज—भारत में लगभग ३३० से भी ज्यादा समाचार पत्र निकलते हैं जिनकी कुल २७॥ लाख प्रतियां रोज प्रकाशित होती हैं, अर्थात्, प्रति १६० व्यक्तियों के लिए अखबार की एक प्रति। इस समय भारत में अखबारी कागज का एकमात्र कारखाना मध्य प्रदेश में खंडवा के निकट नेपा नगर में है। इसने जनवरी ५५ में उत्पादन शुरू किया था। इस समय यह ६० टन सफेद अखबारी कागज प्रतिदिन औसत रूप से बना रहा है। इस पर ६॥ करोड़ रु० की पूंजी लगी हुई है तथा इसकी उत्पादन क्षमता ३६००० टन वार्षिक है। इस कारखाने में करीब एक हजार व्यक्ति काम करते हैं। समुचित विकास होने पर यह कारखाना देश के ⅓ अखबारी कागज की मांग पूरी कर सकेगा। इस प्रकार ४ करोड़ रु० प्रतिवर्ष बाहर जाने से बचेगा। शंकर नगर (हैदराबाद) में भारत सरकार एक और अखबारी कागज का कारखाना खोल रही है।

नोटों का कागज—अब तक भारत सरकार नोट और सिक्यूरिटियों को छापने के लिए इंग्लैंड से कागज आयात करती रही है। लेकिन अब २॥ लाख रु० की लागत से देश में ही सिक्योरिटी पेपर का एक कारखाना खोला जा रहा है।

पूंजी और श्रम—१९३२ से पूर्व इस उद्योग में अधिकांश पूंजी विदेशी थी। १९५३ में इस उद्योग में ६५% पूंजी भारतीय हो गई और अब यह प्रतिशत और भी बढ़ गया है। इस समय उद्योग में लगभग ३५ करोड़ रु० की पूंजी लगी हुई है और लगभग ३४ हजार मजदूर स्थायी रूप से कार्य करते हैं।

पंचवर्षीय योजनायें एवं उद्योग—

प्रथम योजना—प्रथम योजना के आरम्भ में देश में कागज की १७ मिलें थीं जिनका उत्पादन १,१४,००० टन था। अखबारी कागज आयात किया जाता था और स्ट्राबोर्ड का उत्पादन २२,००० टन था। योजना में उत्पादन लक्ष्य इस प्रकार रखा गया—कागज एवं कागज बोर्ड २ लाख टन, अखबारी कागज २७ हजार टन व स्ट्राबोर्ड ५२,६०० टन। योजना काल में यद्यपि हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाये पर उसके करीब अवश्य पहुंच गये। प्रथम योजना में कागज उद्योग विकास के लिए ११ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई थी।

द्वितीय योजना—इस योजना में कागज उद्योग के

(शेष पृष्ठ ३०१ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आई. एम. एफ.) की उपयोगिता

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष या इंटरनेशनल मोनेटरी फंड, (आई-एम-एफ) की स्थानपना १ मार्च १९४७ को हुई थी और ३१ मार्च १९६३ को इसके १६ वर्ष समाप्त हो गये। इस अवधि में फंड ने किस प्रकार अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयत्न किया है, यह विचारणीय प्रश्न है।

इस फंड के प्रारम्भ काल से ३० अप्रैल १९६२ तक ४४ सदस्य राष्ट्रों ने इस फंड से धन राशियां लीं और कई राष्ट्रों ने फंड के साधनों का अनेक अवसरों पर प्रयोग किया। तीन अतिरिक्त सदस्यों ने फंड से वित्तीय सहायता निकट आश्रय (स्टेंड बाई) की व्यवस्था के रूप में ली, फंड में से कोई राशि नहीं ली। फंड के ४७ सदस्यों में से चार अफ्रीका में हैं, पांच मध्यपूर्व में, सात सुदूर पूर्व में, १२ यूरोप में और १९ लेटिन अमेरिका में। फंड में से सदस्यों द्वारा कुल खरीद ६.२६५ मिलियन अमेरिकी डालर थीं।

निम्न तालिका से १९६२-६३ में फंड की प्रवृत्तियों का परिचय मिलता है—

१९६२ अप्रैल से १९६३ दिसम्बर तक फंड में से देशों द्वारा ली गई राशि

(अमेरिकी डालर मिलियन)

मास	देश	मुद्रा	फंड से राशि जो ली गयी	निकट आश्रय ली गयी स्टैंड बाई	उधार की राशि
जून, १९६२	भारत	कोई मुद्रा	—		१००
८ अगस्त, १९६२	ब्रिटेन	कोई मुद्रा	—		१०००
अगस्त १९६२	घाना	डालर और पौंड	१४.२५	—	
अक्तूबर, १९६२	उरु	'गुए' कोई मुद्रा	—		३०

फंड की ओर से दी जाने वाली सहायता का रूप यह नहीं है कि सदस्य राष्ट्र को वास्तविक रूप में फंड का हस्तान्तरण किया जाए। फंड के साधनों तक सहायता के इच्छुक देश की पहुँच ही इस बात की गारंटी हो जाती है कि खरीद की गयी रकम सुरक्षित है। इससे सहायता के इच्छुक देश की रकम की अदायगी की दिक्कतें दूर हो जाती हैं। फंड की प्रवृत्तियों के उल्लेखनीय लाभ यह हुए हैं कि १९५६ में विश्व के मुद्रा संगठन में दरार पड़ने से बच हो गया, १९५७ में यूरुपीय विनिमय-बाजार में तनाव कम गया, और देशों को अपनी मुद्रा-स्थिरता के कार्य क्रम सहायता प्राप्त हो गयी।

फंड प्रारम्भ से ही बड़ी सावधानता के साथ, अपने प्रवृत्तियों का संचालन कर रहा है। इसके उद्देश्य में कहा गया है कि "फंड का उद्देश्य मेम्बरों को इसके साधनों के प्रयोग करने की स्वीकृति देने का मतलब यही है कि उन्हें अपनी वित्तीय व्यवस्था में अनुकूलता लाने का अवसर मिल जाए, न कि अनुकूलता लाने की आवश्यकता से अपने को बचा लें। अगले वर्ष फंड ने निश्चय किया कि मार्शल सहायता प्राप्त करने वाले देश इससे लाभ नहीं उठा सकेंगे। इससे इसकी प्रवृत्तियां सीमित हो गयीं। १९५३ में फंड ने अपनी प्रवृत्तियों का विस्तार किया। इस समय कहा गया कि फंड सदस्य राष्ट्रों के लिए "निकट आश्रय' (स्टैंड बाई) के रूप में खड़ा होने को तैयार है। इस व्यवस्था के द्वारा एक सदस्य राष्ट्र विदेशी मुद्रा की एक निश्चित मात्रा निश्चित अवधि के लिए प्राप्त कर सकता है।"

१९४८ तक इस फंड का काफी कारोबार हुआ जिसका कुल योग ५६७६ मिलियन डालर था। इसके बाद, कारोबार की दृष्टि से, १९४९ से १९५५ तक के वर्ष फंड के लिए निर्बल थे। इन छः वर्षों में कुल कारोबार ४१ मिलियन डालर का हुआ। इसका कारण यह था कि यूरुपीय देश तो मार्शल योजना पर निर्भर करके अपनी दिक्कतों का हल करते थे और कामनवेल्थ तथा लेटिन अमेरिकी देश द्वितीय विश्वयुद्ध में जमा किये गये आर्थिक संचयों से अपना काम चलाते थे।

१९५६-५७ में फंड की प्रवृत्तियों में खास तेजी आयी। १९५८ के अंत तक फंड की संचित राशि लगभग ९ बिलियन डालर थी जो १९६१ के अंत तक १२ बिलियन डालर हो गयी। इस राशि में ३ बिलियन डालर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अधिक सोना है और ६ बिलियन डालर से अधिक रूपान्तर हो सकने वाली मुद्राएं हैं। १ मई १९६१ से ३० अप्रैल १९६२ तक की अवधि फंड की कार्यशीलता की दृष्टि से उल्लेखनीय था। १५ फरवरी १९६१ को १० सदस्यों ने अपनी विनिमय मुद्राओं का रूपान्तर किया जाना मान लिया। ये देश थे—बेलजियम, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंडस, पेरस, स्वीडन और ब्रिटेन। इससे फंड का क्षेत्र विस्तृत हो गया और सदस्य राष्ट्रों को अपने भुगतान में अधिक सुविधाएं मिल गयी। एक और सुविधा १९६१ में सदस्य राष्ट्रों को दी गयी। अप्रैल १९५८ तक फंड से रकम की वापसी (विदड्रायल) अमेरिकी डालर में ही हो सकती थी। उस समय यह ९१.७ प्रतिशत थी। इस बन्दिश के हट जाने से १९६१ में अमेरिकी डालर में वापसी कुल ३६.४ प्रतिशत हुई, बाद में यह और भी कम होकर ३४.७ प्रतिशत रह गयी।

फंड इस बात के लिए धन्यवाद का पात्र है कि इसके द्वारा उन देशों को—जो औद्योगिक नहीं है—ठीक अवसर पर सहायता मिल जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान की कड़ी समस्या कच्चा माल पैदा करने वाले देश ही अनुभव कर रहे हैं। मार्च १९६३ में फंड द्वारा घोषित की गयी नयी योजना के अनुसार, सदस्य राष्ट्रों के लिए विदेशी राष्ट्रों के भुगतान में आने वाली दिक्कतों का निराकरण हो सकेगा। उस अवस्था में सदस्यों को अपने कोटे का २५ प्रतिशत अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा।

इस प्रकार फंड अनुन्नत देशों की उल्लेखनीय सहायता कर रहा है।

• •

हिन्दी का एकमात्र
विशिष्ट महिलोपयोगी मासिक

शृङ्गार

जो सुखी पारिवारिक जीवन का आदर्श पथ-प्रदर्शक है

- जिसे सुप्रसिद्ध लेखिकाओं, लेखकों, पत्रकारों, चित्रकारों कवयित्रियों तथा कवियों का सहयोग प्राप्त है।
- जिसे ५०००० से ऊपर की संख्या में पाठक प्रतिमास पढ़ते हैं।
- जिसकी प्रतियां न्यूज़ एजेन्टों के पास पहुँचते ही समाप्त हो जाती हैं।

महिला जागृति का प्रतीक है।

- जो सबकी प्रिय पत्रिका है।

वार्षिक : सात रुपये
एक प्रति : ६० नये पैसे

सम्पादिका : लावण्य प्रभा

कार्यालय : १३।३७, शक्तिनगर, दिल्ली-६।

"राष्ट्र-भारती"

सम्पादक—मोहनलाल भट्ट, हृषीकेश शर्मा

इसमें आपको लब्धप्रतिष्ठ-विद्वान् साहित्यकारों के ज्ञान-पोषक और मनोरंजक अच्छे-अच्छे लेख, कविताएं कहानियां एकांकी, रेखाचित्र, शब्दचित्र आदि रचनायें पढ़ने को मिलेंगी

इसमें संस्कृत, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आ विभिन्न भारतीय भाषाओं की तथा अंग्रेजी, रशियन आदि विदेशी भाषाओं की उत्कृष्ट रचनाओं के सुन्दर हिन्दी अनुवाद भी रहते हैं।

आज ही मनीआर्डर द्वारा ६) भेजकर ग्राहक बन जा

रियायत—स्कूल-कालेजों सार्वजनिक पुस्तकालयों था वाचनालयों को केवल ५) वार्षिक चन्दे में मिलेगी।

पत्रव्यवहार का पता—

व्यवस्थापक—"राष्ट्रभारती"
हिन्दी नगर, वर्धा
प्रचार (राष्ट्रभाषा समिति)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नगर व उनकी जनसंख्या

आबादी	नगरों की संख्या १९६१ की जन गणना	नगरों की संख्या १९५१ की जन गणना	नगरों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि	जनसंख्या हजारों में १९६१	१९५१	जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि
क श्रेणी (१,००,००० से ऊपर)	१०७	७४	+४४.६	३५,११०	२३,७२५	+४८.[illegible]
ख श्रेणी (५०,०००—९९,९९९)	१४१	१११	+२७.०	९.९२६	७,५४५	+२७.[illegible]
ग श्रेणी (२०,०००—४९,९९९)	५१५	३७५	+३७.३	१५,६५०	११,१३५	+४०.[illegible]
घ श्रेणी (१०,०००—१९,९९९)	८१७	६७०	+२१.९	११,२५८	९,२९१	+२१.[illegible]
ङ श्रेणी (५, ०००—९,९९९)	८४४	१,१८९	—२९.०	६.३१३	८,४७२	—२५.[illegible]
च श्रेणी (५,००० से नीचे)	२६६	६३८	—५८.३	८७९	२,१०९	—५८.[illegible]

इस तालिका से यह स्पष्ट है कि उच्च श्रेणी के नगरों में संख्या और जनसंख्या कम हुई है। और [illegible] नगरों की संख्या अधिक होती गई है।

बढ़ते शहर : एक गंभीर समस्या

विनोबा

०

यह एक चिंता का विषय है कि भारत में शहर बढ़ रहे हैं। शहर अगर पुरुषार्थी होते, दुनियाभर के साथ व्यापार करते, जो माल देश में आता है वह यहीं बनाते तो कुछ लक्ष्मी वहां रहती, कुछ पुरुषार्थ वहां रहता। अभी इतना होता है कि कोई तेल की मिल खोलता है, कोई चावल मिल खोलता है। यानी जो काम गांव के लोग कर सकते हैं, वे शहर के लोग करते हैं। गांव के लोग काम करते तो घर-घर में उद्योग मिलता, वह घर-घर का उद्योग शहरवालों ने ले लिया और मिल के द्वारा गांव- गांव को माल सप्लाई करते हैं। ग्राम में कुछ जीवन नहीं रहता। ग्रामों पर शहर का असर रहता है और ग्रामीण शहर की ओर खिंचते चले आते हैं।

परदेश का माल शहरों को चूसता है और गांव के लोग आकर शहर पर हमला करते हैं, क्योंकि उनको गांव में काम नहीं मिलता। तो ग्रामों के लोगों का आक्रमण और परदेश के माल का आक्रमण जैसे दो आक्रमणों के बीच शहर वाले पिस जाते हैं। ग्रामवासियों का आक्रमण और शहरों की गंदी बस्ती के कारणों से कौटुम्बिक जीवन का स्वास्थ्य टिकता नहीं और दुराचार बढ़ता रहता है, रोग बढ़ते रहते हैं। कहा जाता है कि न्यूयार्क से भी प्रति एकड़ घनी बस्ती है, लंदन में और उसके दुगुने से भी ज्यादा घनी बस्ती है कलकत्ता में इस प्रकार के जो शहर बनते हैं, उनको सब प्रकार की तकलीफें होती हैं उनके शहर की शक्ति-क्षीण होती है। इसका उपाय एक ही है कि ग्रामीण बस्ती शहर में आने से रुके और आगे शहर बढ़े नहीं, यह देखें।

गांव रमणीय बनें

ग्राम अच्छा हो, स्वच्छ हो, उसमें जीवन की सह-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लियतें हों, स्वच्छ हवा-पानी मिले. इसके अलावा बच्चों की तालीम की योजना हो, उत्तम उद्योग हो, खेती में फसल बढ़ाने की योजना हो, चित्रकला, गायन, खेल आदि की योजना हो। इस तरह से प्रत्येक गांव रमणीय बने तो ग्रामीण लोग नाहक शहर में नहीं जायेंगे। तो आज शहर के बारे में भी कुछ न कुछ किया जा सकता है।

शहरों का पुनरुत्थान

आजकल शराब बढ़ रही है तो कैसे रोका जाय? एक उपाय है कि ग्राम-ग्राम एक परिवार बने और हर गांव का आयोजन हर गांव करे, तो उन पर कौन शराब लादेगा। गांव वाले तय करेंगे तो शराब को गांव में नहीं आने देंगे। उसका बहिष्कार डालेंगे, तिस पर भी शराब लादने का सरकार का आग्रह रहा तो सरकार ग्रामीणों की शत्रु बनेगी। ऐसी सरकार टिकेगी नहीं। देश में कई सवाल ऐसे हैं, जो ग्राम-स्वराज्य के जरिये ही हल हो सकते हैं।

योजना कैसी हो?

ऐसी एक योजना देश में सर्वोदय के सामने है और ऐसी एक योजना देश में कम्युनिस्टों के सामने हैं। और आज चाहे कांग्रेस हो, चाहे पी० एस० पी० हो या जनसंघ हो, उनके दिमाग में कोई योजना नहीं। सब उत्पादन बढ़ाने की बात बोलते हैं। उत्पादन बढ़ाना यह बहुत बड़ी नहीं, यह एक मामूली चीज है। सब विचारकों के लिए सोचने का विषय यह है कि उत्पादन किस ढंग से बढ़े? गांव का और शहरों का कैसा आयोजन हो? जमीन का वितरण कैसे हो? गांव-गांव में शक्ति कैसे पहुँचे? शहर को समाज जीवन कैसे हो? नीचे गिरे हुए मनुष्य को ऊपर कैसे उठावें? बहिनों का समाज में क्या स्थान हो? शिक्षा की योजना क्या हो? साहित्य की क्या दृष्टि हो? विज्ञान को क्या निर्देश दें? चिकित्सा की कौन सी पद्धति अपनायें? ये सारी चीजें योजना में आनी चाहिए। किसी राजनैतिक पक्ष ने इन विषयों में खास सोचा हो मुझे मालूम नहीं। प्लानिंग कमीशन बैठा है, उसने सोचने का ठेका ले लिया है और वह प्रान्तों को पूछ-पूछ कर अपनी योजना बनाता है। प्रांतों ने हां कहा तो कमीशन योजना बनायेगा। प्रांतों ने ना कहा तो कम करेगा। लेकिन कम्युनिस्टों के सामने जीवन की एक योजना है—सांइटिफिक एप्रोच है।

कम्युनिस्ट छोटी चीज है। कम्युनिज्म बड़ी चीज है, क्योंकि वह विचार है। वह कुल दुनिया में चल रहा है। ऐसा कोई देश नहीं जहां वह विचारधारा पहुँची नहीं। हिन्दू-धर्म कुल दुनिया में नहीं है। इस्लाम-धर्म कुल दुनिया में नहीं है। बौद्ध-धर्म भी कुल दुनिया में नहीं, पृथ्वी पर कहीं-कहीं है। लेकिन साम्यवाद समस्त संसार में है, क्योंकि वह एक जीवन विचार है। यह नया आया है। कुछ देशों ने इस पर अमल करने की कोशिश की, उसका परिणाम निकला है। उसका साहित्य बना है और वह लाखों की तादाद में बिकता है। उसका मुकाबला करने वाला, उसके दोषों से रहित और उसके गुणों से युक्त और जिसमें और भी अधिक गुण भरे हैं, ऐसा विचार खड़ा किया जायेगा, तभी है।

सर्वोदय—एक दर्शन

हमारा यह दावा है कि सर्वोदय के सामने एक दर्शन है। वह दर्शन केवल परिस्थिति के स्वरूप बना नहीं। परिस्थिति के अलावा मनुष्य स्वभाव, आध्यात्मिक भूमिका ध्यान में लेकर बना है। जैसे कम्युनिज्म एक प्रतिक्रिया मात्र है, वैसे वह प्रतिक्रिया नहीं। कम्युनिज्म केपिटलिस्ट सोसायटी की प्रतिक्रिया है। सर्वोदय स्वयंभू विचार है, समन्वित विचार है और समग्र विचार है।

शहरी कृत्रिमता टिकेगी नहीं

एक अंग्रेजी कविता है "डेजर्टेड विलेज"। इसके आगे "डेजर्टेड सिटीज" ऐसा काव्य भी बनने वाला है। इसमें हमें कोई शंका नहीं। और मान लीजिए कि शहर बढ़ रहे हैं तो वह खेल खतम होने के लिये हो रहा है। दीपक जब बड़ा होता है तब उसका आखिर का समय होता है। इसी तरह शहर बढ़ रहे हैं—टोकियो, न्यूयार्क लंदन, पेकिंग, बर्लिन, कलकत्ता, बम्बई, ये सब डेजर्टेड सिटीज होने वाले हैं। साइन्स बढ़ेगी और विकेन्द्रीकरण बढ़ेगा, तब एक-एक गांव सुन्दर बनने लगेगा। अभी "वीक-एंड" के लिये गांव में जाते हैं। तब सब समय के लिये गांव में रहेंगे।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कितनी कम आय !

श्री उ० न० ढेबर

अन्याय के प्रतिकार के लिए दो मार्ग हैं—एक पूंजीवाद का और दूसरा साम्यवाद का। पूंजीवाद में विश्वास करने वालों का कहना है, उत्प्रेरणाओं और श्रमिक इन दो की व्यवस्था हो, तो सम्बन्धी व्यवस्था अपने आप हो जायेगी। साम्यवादियों का कहना है कि उत्पादन के समस्त साधनों एवं वितरण और विनिमय की व्यवस्था पर राज्य का पूरा अधिकार तथा स्वामित्व हो और दूसरे केवल श्रमिक हों। 'उत्प्रेरणा' एक निर्दोष शब्द है। उत्प्रेरणा का ठीक अर्थ केवल आर्थिक प्रोत्साहन ही नहीं लेना चाहिए, न इसका अर्थ प्रोत्साहन में से ही होना चाहिए, जो सम्पन्न अथवा निर्धन देशों में प्रायः लिया जाता है। अन्यथा विषमताएं दूर होने की अपेक्षा बढ़ती ही नहीं जायेंगी बल्कि नयी-नयी विषमताएं भी पैदा हो जायंगी। इसी तरह जैसा कि पूंजीवादी व्यवस्थ में होता है, रोजगार देने का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि मनुष्य अपनी स्वाभाविक आवश्यकताओं की उपेक्षा कर काम करें, नहीं तो विषमताओं में और वृद्धि होगी तथा दूसरे कितने ही अनर्थकारी कार्य होंगे।

उत्पादन, वितरण और विनिमय के समुचित साधनों पर राज्य का स्वामित्व होने का यह अर्थ है कि आर्थिक क्षेत्र में लोगों के अधिकार का अंत और एक छोटे-से वर्ग के हाथ में जनता का भविष्य सौंप देना, फिर चाहे वह वर्ग जनता में कितनी ही सहानुभूति क्यों न रखता हो। इस प्रकार की व्यवस्था तभी सफल हो सकती है, जब कोई यह विश्वास दिलाए कि एक अच्छे और हमदर्द व्यक्ति का उत्तराधिकारी भी उतना ही अच्छा और हमदर्द होगा पर इस प्रकार का विश्वास दिलाना असम्भव है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में 'काम' का अर्थ 'एक ही काम देने वाले मालिक पर निर्भर रहना है।'

गांधी जी ने हमारा ध्यान घर में, पड़ोस में, गांव और राष्ट्र में बढ़ती हुई असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता की ओर आकर्षित किया था। उन्होंने उस मनः स्थिति पर ध्यान दिया, जो इन सभी असमानताओं की जड़ है। उन्होंने बार-बार यह कहा कि इन असमानताओं और विषमताओं के उन्मूलन का उपाय विदेशों की कोई जड़ी-बूटी नहीं है, और न इसका उपाय किसी पुस्तक में ही मिल सकता। सच कहा जाय तो अर्थशास्त्र के सिद्धान्त भी हमारे दुख-दर्दों को दूर करने के लिए अधिक सहायक नहीं हो सकेंगे।

> एक अंग्रेज अर्थशास्त्री ने कहा है कि समाजवाद उस टोप के समान है, जिसकी आकृति इसलिए विकृत हो गयी है कि प्रत्येक व्यक्ति उसका इस्तेमाल करने लगा है। पर यदि मुझे कोई पूछे कि समाजवाद क्या है, तो मैं कहूँगा कि वह "सामाजिक परिवर्तन का शास्त्र, विज्ञान है।"

हमारी आर्थिक अवस्था क्या है? मनुष्य को भोजन, घर, शिक्षा, दवा-दारू और बुढ़ापे में सहायता की आवश्यकता होती है। साठ प्रतिशत से भी अधिक परिवारों के मुखिया इन आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अपने आपको असमर्थ पाते हैं। एक व्यक्ति को केवल पौष्टिक भोजन के लिए ही कम से कम ३५ रुपए की प्रति मास आवश्यकता पड़ती है, जबकि भारत में सबसे नीचे के वर्ग की मासिक आय ६.६० रुपए है। इससे ऊपर की श्रेणी के २० प्रतिशत लोगों की आय ९.६० रुपए है, और जो इससे ऊपर के दशवें में आते हैं, ११.७० रुपए है। इसी प्रकार चौथे दशक की १३.२६ रुपए, पांचवें की १६.३५ रुपए और छटे की २१.५० रुपए आय हैं।

ढील नहीं दृढ़ता

राष्ट्र की तैयारी में हाथ बटाइए।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रेलों की बढ़ती हुई क्षमता

श्री कृपालसिंह, रेलवे बोर्ड

• पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ के समय रेलों की मार्ग लम्बाई ५४,००० किलोमीटर थी। ८५५ करोड़ रुपये की पूंजी इन रेलों में लगी हुई थी और स्टेशनों की संख्या थी ६,०००। इनसे प्रतिवर्ष लगभग १२८ करोड़ यात्री और ९.३ करोड़ मीटरिक टन माल की ढुलाई हो रही थी। पहली पंचवर्षीय योजना में रेलों के मद की ४१९ करोड़ रुपये की राशि मुख्यतः रेल-पथ और चल-स्टाक के पुनः स्थापन पर खर्च की गयी, क्योंकि यह काम पिछले युद्ध और विभाजन के फलस्वरूप काफी बकाया में पड़ गया था और इसे करना बहुत जरूरी था। उस राशि में से रेलों की वहन-क्षमता बढ़ाने पर बहुत कम खर्च किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में यात्रियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई, परन्तु माल की ढुलाई ११.६ करोड़ टन तक पहुँच गयी थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में २१०० किलोमीटर से अधिक नयी लाइनें बनायी गयीं और लगभग १६०० किलोमीटर इकहरी लाइन दोहरी की गयी। इसी अवधि में ७५०० नये सवारी डिब्बे- २१६० नये इंजन और ९८००० नये माल डिब्बे चलाये गये।

इन आंकड़ों से पता चलता है कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं की १० वर्ष की अवधि में, माल यातायात में ६८ प्रतिशत और यात्रियों की संख्या में २५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि में रेलपथ में ९ प्रतिशत, इंजनों की संख्या में २६ प्रतिशत, सवारी डिब्बों की संख्या में ३७ प्रतिशत और माल डिब्बों की संख्या में ४७ प्रतिशत की बढ़ती हुई। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि इन दस वर्षों में, जबकि परिवहन का भार लगभग १०० प्रतिशत बढ़ा, परिवहन के लिए आवश्यक साधनों में इससे कहीं कम वृद्धि हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में रेल के इंजन व गाड़ियों आदि से पहले बहुत अधिक काम लिया गया।

तीसरी योजना में प्रगति

तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में १४५० किलोमीटर दोहरी लाइनें और ५१८ किलोमीटर नयी लाइनें बनाकर, रेल-पथ में २०१८ किलोमीटर की वृद्धि की गयी। इस अवधि में माल की वार्षिक ढुलाई १७.७ करोड़ मीटरिक टन और यात्रियों की संख्या लगभग १७३ करोड़ तक पहुँच गयी। अन्य वर्षों की अपेक्षा १९६२-६३ में भारतीय रेलों पर माल यतायात में सबसे अधिक वृद्धि हुई। रेलों ने इस वर्ष में पिछले वर्ष से १ करोड़ ५२ लाख टन अधिक माल की ढुलाई का लक्ष्य रखा था। लेकिन वास्तव में माल की ढुलाई, पूर्व वर्ष से १ करोड़ ६५ लाख मीटरिक टन अधिक हुई। इन दो वर्षों में २६६० नये सवारी डिब्बे, ७०० नये इंजन और ३४९०० नये माल-डिब्बे भी चालू किये गये। आज रेल-कर्मचारियों की संख्या लगभग १२ लाख और स्टेशनों की संख्या ६,६३५ है। १९६२-६३ की अनुमानित कुल यातायात-प्राप्ति ५५० करोड़ और संचालन-व्यय ४३० करोड़ रुपये हैं।

वर्तमान योजना के शेष तीन वर्षों में, आशा है कि रेलों में २,२०० किलोमीटर दोहरी लाइन, १२०० किलोमीटर नयी लाइन, १४०० इंजन, ४००० सवारी डिब्बे और ८५,००० माल डिब्बों की और वृद्धि हो जाएगी। कुछ मीटर गेज (छोटी लाइनों) को बड़ी लाइन में बदल दिया जाएगा और कुछ के समानान्तर बड़ी लाइन बिछाई जाएगी।

बिजली गाड़ियां

तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में माल-यातायात बढ़कर २६ करोड़ मीटर टन और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में ४२ करोड़ मी० टन पर पहुँच जाएगा, जबकि यात्रा-यातायात में प्रतिवर्ष ४ से ५ प्रतिशत की बढ़ती होगी। इस बढ़ते हुए यातायात को सम्हालने के लिए परिचालन और क्षमता बढ़ाने के नये तरीके अपनाये जा रहे हैं। १९५५-५६ तक बिजली गाड़ियां केवल बम्बई और मद्रास के इर्द-गिर्द ही चलती थीं, लेकिन पिछले ८ वर्षों में १६१० किलोमीटर रेल मार्ग पर बिजली-गाड़ी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चलने लगी हैं। इसमें हावड़ा डिवीजन के उपनगरीय खण्ड भी शामिल हैं। तीसरी योजना के अन्त तक या चौथी योजना के प्रथम वर्ष तक हावड़ा से कानपुर, आसनसोल से राऊर केला, हावड़ा से टाटानगर, बम्बई से भुसावल, बम्बई से पूना और मद्रास से विल्लुपुरम तक के मार्ग का बिजलीकरण पूरी तरह से हो जाएगा। सियालदह डिवीजन के उपनगरीय खण्डों का बिजलीकरण तेजी से हो रहा है और उम्मीद है कि उत्तरी खण्ड में पहली बिजली गाड़ी वर्ष के मध्य में चालू हो जाएगी। इस समय मुख्य लाइनों पर सिर्फ माल गाड़ियां बिजली के इंजनों से खींची जा रही हैं। लेकिन ज्यों ही चितरंजन इंजन कारखाने से, जहां बिजली के इंजनों का निर्माण शुरू हो चुका है, बिजली के इंजन पर्याप्त संख्या में मिलने लगेंगे, चौथी योजना में सवारी गाड़ियों का भी बिजलीकरण कर दिया जाएगा। पिछले १० वर्षों में चालू नये इंजनों में बिजली के १४६ और डीजल के ३२८ इंजन हैं, जो तेज रफ्तार हैं और जो प्रतिदिन कहीं अधिक माल ढो सकते हैं। अब तक डीजल इंजनों का इस्तेमाल भीड़-भाड़ वाले खण्डों तक ही सीमित रहा है, क्योंकि उनमें यातायात का भार संभालने में भाप के इंजन अपर्याप्त साबित हुए। इन डीजल इंजनों में से कुछ इंजन सैनिक महत्व के खण्डों और उन खण्डों पर काम कर रहे हैं जहां पानी की कमी है। उन खण्डों पर भी डीजल इंजनों को चलाने का विचार है जो कोयला-क्षेत्रों से काफी दूर हैं। देश में डीजल तेल के उत्पादन की बढ़ती के साथ-साथ अन्य देशों की भांति भारतीय रेलों में भी अधिकाधिक डीजल इंजनों का उपयोग किया जाएगा।

दर्पण के तरीकों में इन परिवर्तनों के अलावा अन्य अनेक तरीकों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जा रहे हैं। इकहरी लाइनों की जगह दोहरी लाइन बिछाने का भी बड़ा कार्यक्रम बनाया गया है। इस समय केवल १३ प्रतिशत रेलवे लाइनें दोहरी हैं और बाकी सभी लाइनें इकहरी हैं। आशा है कि चौथी योजना के अन्त तक बड़ी लाइन के प्रायः सभी मुख्य मार्गों पर जैसे कलकत्ता दिल्ली, कलकत्ता-बम्बई, कलकत्ता-मद्रास, मुगलसराय-अमृतसर, दिल्ली-बम्बई, दिल्ली-मद्रास, बम्बई-मद्रास, मद्रास-कोचीन दोहरी लाइनें हो जाएंगी।

रेलों के सामान का देश में निर्माण

इस समय भारतीय रेलें अपनी आवश्यकता के सवारी डिब्बे, माल-डिब्बे और भाप के इंजन अपने देश में ही, रेलवे कारखानों या अन्य सरकारी व निजी कारखानों से प्राप्त कर सकती हैं। चितरंजन कारखाने में बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण शुरू हो चुका है और इस वर्ष के अन्त तक वाराणसी के डीजल इंजन कारखाने में डीजल भी बनने लगेंगे, जैसे-जैसे इन इंजनों की संख्या उनके लिए बिजली के मोटरों इत्यादि की मांग भी बढ़ेगी, जो बिजली का सारा सामान बनाने वाले भोपाल स्थित कारखाने में बनेंगे। अब रेल की पटरियां, इस्पात के प्लेट और चद्दर, इस्पात के पुर्जे सेक्शन, पहिये और धुरे अपने देश में ही बनाये जा रहे हैं। यांत्रिक सिगनल के सभी उपस्कर अब भारत में उपलब्ध हैं और बिजली सिगनल व दूर-संचार उपस्करों का निर्माण भी शुरू हो गया है। देशी सामान बनने की प्रगति का पता इसी से चलेगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुल १४७० करोड़ रुपये के खर्च में से, केवल २५०-२७५ करोड़ रुपये की ही विदेशी मुद्रा खर्च होने की सम्भावना है।

ग्राम राज (मास में तीन बार प्रकाशित)

सम्पादक—श्री गोकुलभाई भट्ट

"ग्रामराज बहुत ही शानदार और बहुत ही सुन्दर पत्र निकल रहा है। सब तरह की जानकारी इसमें रहती है। राजस्थान के हर शिक्षित भाई बहन के हाथ में यह पत्रिका होनी चाहिए।" —विनोबा

वार्षिक चन्दा ३) रु०

कार्यालय का पता :

ग्रामराज, किशोर निवास

जयपुर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

13 JUN 1963

भारत में भूमिहीन मजदूरों की समस्या

श्री बालकृष्ण कुमावत, एम० काम०, साहित्यरत्न

इस समय देश में सर्वाधिक उपेक्षित देहात का वह वर्ग है जिस के पास एक इन्च भी भूमि नहीं है और जिसका जीवन आधार एक मात्र खेती ही है। इन "खेतीहर मजदूरों" की कई विकट समस्याएं हैं। इनकी मासिक आय 'औसतन, २५-३० रु. के लगभग होती है। इतनी स्वल्प राशि में ये बेचारे खेतीहर मजदूर किस प्रकार अपना और परिवार का जीवन निर्वाह करते हैं— इसकी कल्पना करना भी दुष्कर है। जमींदारों और मालिकों के पास बंधक रूप में पुश्त-दर-पुश्त इन्हें फंसा रहना पड़ता है। पशुओं से भी बदतर जीवन·····

हमारी वर्तमान ग्रामीण-अर्थ व्यवस्था जिन समस्याओं से पीड़ित है उनमें भूमि-हीन मजदूरों की समस्या अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ग्रामीण जनसंख्या में भूमिहीन मजदूरों का प्रतिशत बहुत अधिक है। अखिल भारतीय कृषि-मजदूर-जांच-समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का ८२ प्रतिशत भाग गांवों में निवास करता है। इस ग्रामीण-जनसंख्या में ३० प्रतिशत भूमिहीन मजदूर हैं। यह प्रतिशत उड़ीसा, बिहार, मध्यप्रदेश तथा मद्रास प्रन्तों में और भी अधिक पाया जाता है। १९६१ की जनगणना के अनुसार कुल ग्रामीण जनसंख्या में भूमि-हीन मजदूरों का प्रतिशत बढ़कर ३४ के लगभग हो गया है। भूमि-हीन मजदूर-परिवारों की संख्या १९६१ में ९८० लाख थी जो कि १९६१ में बढ़कर १३१० लाख हो गई। इस प्रकार गत दस वर्षों में ३३० लाख अतिरिक्त परिवारों की वृद्धि हुई। जन संख्या की वृद्धि के साथ-साथ भूमि-हीन मजदूरों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। यदि वृद्धि की दर यही रही तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अगले १५ वर्षों में अर्थात् १९७६ तक भूमि-हीन मजदूर-परिवारों की संख्या में ५०० लाख अतिरिक्त परिवारों की वृद्धि हो जायगी। यह वृद्धि वास्तव में चिन्ता का विषय है।

कृषि पर अनावश्यक बोझ :—

कृषि-क्षेत्र में जो कुछ रोजगार गांवों में मिलता है उसी पर प्रायः भूमि-हीन मजदूर निर्भर करते हैं। गैर-कृषि-क्षेत्र में उन्हें जो रोजगार मिलता है वह बहुत कम दिनों के लिये होता है तथा अनिश्चित भी। अतः मुख्यतः वे कृषि क्षेत्र में मिलने वाले रोजगार पर ही अवलम्बित रहते हैं। कृषि-क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में बहुत ही न्यून वृद्धि होती है। दूसरी ओर यह ध्यान देने योग्य है कि कृषिक परिवार के सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि होरही है जिससे कृषि में काम करने के लिये परिवार के सदस्य स्वयं बढ़ते जा रहे हैं। परिणामस्वरूप, मजदूरों की मांग में कमी होती जा रही है। अतः भूमि-हीन मजदूरों की वृद्धि कृषि पर एक अनावश्यक बोझ होती जा रही है। यदि इन मजदूरों को दूसरी ओर रोजगार नहीं दिया जायगा तो हमारी कृषि इनका भार सहन करने में असमर्थ होगी।

ग्रामीण बेरोजगारी में वृद्धि:—

भूमि-हीन-मजदूरों की निरन्तर बढ़ती हुई संख्या के फलस्वरूप ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या गम्भीर होती जा रही है। आज भूमि-हीन मजदूर को गांवों में साल भर में करीब $\frac{1}{3}$ समय के लिए बेरोजगार रहना पड़ता है। उनकी संख्या में जैसे-जैसे वृद्धि होती जायगी वैसे-वैसे बेरोजगारी अधिक बढ़ती जायगी। जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के विकास के अभाव में गैर कृषि-क्षेत्र में रोजगार के अवसर बहुत कम मिलते हैं। केवल कृषि क्षेत्र में ही थोड़ा बहुत रोजगार मिल पाता है। यदि इस समस्या की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया तो ग्रामीण बेरोजगारी की स्थिति और भी खराब हो जायगी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समाज में सबसे पिछड़ा वर्ग :—

आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से भूमि-हीन मजदूर सबसे पिछड़ा वर्ग है। एक भूमि-हीन-मजदूर की औसत आय १०७ रु. वार्षिक है जबकि प्रति उपभोग-इकाई उसका वार्षिक व्यय १३५ रु. है। न्यूनतम जीवन स्तर तो दूर रहा, उसकी उदर पूर्ति भी नहीं होने पाती। भोजन में उसे केवल घटिया अनाज ही प्राप्त होता है और वह भी अपर्याप्त मात्रा में। उसे पूरा शरीर ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं मिलते। रहने के लिये उसे एक टूटी घास की झोंपड़ी ही उपलब्ध होती है। अधूरा-भोजन, अधूरा-वस्त्र एवं अधूरा आवास, यही उसका आर्थिक जीवन है। इसके अतिरिक्त समाज में वह सम्पन्न वर्गों द्वारा हीन दृष्टि से देखा जाता है। नियोक्ता उससे मनमाना काम लेता है और बदले में बहुत कम मजदूरी देता है। आय से व्यय अधिक होने के कारण वह हमेशा ऋण-ग्रस्त रहता है। इसी कारण उसे नियोक्ता के यहां स्थायी रूप से न्यूनतम जीवन-मजदूरी से कम मजदूरी पर काम करने के लिये बाध्य होना पड़ता है। कभी-कभी तो उसका सारा जीवन एक ही नियोक्ता के यहां काम करते करते समाप्त हो जाता है।

भूमि-हीन मजदूर शहरों की भांति संगठित भी नहीं है। शहरों में जिस प्रकार मजदूरों के हितों की रक्षा के के लिये ट्रेड यूनियन या अन्य संघ पाये जाते हैं इस प्रकार का कोई भी संगठन ग्रामीण मजदूरों का नहीं पाया जाता। इसी कारण, भूमि-हीन मजदूरों की मजदूरी, काम का समय इत्यादि नियोक्ता की इच्छा द्वारा ही निर्धारित होते हैं। इस प्रकार इस वर्ग का शोषण होना स्वाभाविक ही है।

भूमि-हीन मजदूरों की संख्या में वृद्धि होने से तथा उनको अन्यत्र रोजगार न मिल सकने के कारण, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा कृषि पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कृषि में विकास करने से जो लाभ मिलता है वह इस वृद्धि कारण के निष्फल सा हो जाता है। शहरी एवं ग्रामीण आय का अन्तर कम होने की अपेक्षा बढ़ता जा रहा है।

प्राथमिकता देने की जरूरत—

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि भूमिहीन मजदूर आज आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है। श्री विनोबा भावे के शब्दों में "भूमिहीन मजदूर आर्थिक चढ़ाव की सबसे नीचे की सीढ़ी पर है जो कि पिछड़ेपन की अन्तिम स्थिति है।" हमारी आर्थिक योजनाओं में भूमिहीन मजदूरों की समस्या पर पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है। जो भी कार्य अभीतक उनकी उन्नति के हेतु किये गये, हैं उनसे समस्या में किसी प्रकार का सुधार नहीं हो पाया है। अन्य वर्ग की अपेक्षा यह वर्ग उपेक्षित सा ही रहा है। वास्तव में एक माता को सबसे कमजोर बालक की अधिक चिन्ता करनी चाहिए। अतः हमारी आर्थिक योजनाओं में इस समस्या की ओर योजना-निर्माताओं द्वारा अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। जब हमने समाजवादी समाज रचना एवं आर्थिक समानता लाने का प्रण कर लिया है तो हमें इस सबसे अधिक पिछड़े वर्ग की उन्नति की ओर अधिक ध्यान देना होगा। इस वर्ग को अछूता छोड़ देने पर हमारा आर्थिक विकास अधूरा ही रह जायगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारे आर्थिक विकास की आधार शिला है। ग्रामीण-अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये हमें इस दुर्बल एवं पिछड़े वर्ग की उन्नति को प्राथमिकता देनी होगी, कृषि विकास के साथ-साथ कुटीर एवं ग्रामोद्योगों का जाल बिछाना होगा जिससे भूमि-हीन मजदूरों को रोजगार के पर्याप्त अवसर दिये जा सकें। हमें श्रमप्रधान-योजनाओं की ओर विशेष ध्यान देना होगा, तब ही कृषि पर इस अनावश्यक बोझ को कम किया जा सकेगा और इस वर्ग की आर्थिक उन्नति हो सकेगी।

सम्पदा के

आगामी विशेषांक की

प्रतीक्षा कीजिये

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(पृष्ठ २९१ का शेष)

लिए ४४ करोड़ रु० व्यय करने की व्यवस्था की गई। अनुमान था कि कागज का उत्पादन ४.५० लाख टन व स्ट्राबोर्ड और अखबारी कागज का उत्पादन क्रमशः ६० हजार टन हो जाएगा। मगर इस बार भी योजना काल में हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाये।

तृतीय-योजना—यह हमारा तृतीय योजना काल चल रहा है। ऐसा अनुमान है कि १९६५-६६ तक ७ लाख टन अखबारी व अन्य कागज की दरकार होगी। इस समय उद्योग की क्षमता ४.१० लाख टन है जिसे बढ़ाकर तीसरी योजना के अन्त तक ८.२० लाख टन कर दिया जाएगा। अखबारी कागज की क्षमता ३० हजार टन से बढ़ाकर १.५ लाख टन करने का प्रस्ताव है। योजना काल में कागज उद्योग पर करीब ६६ करोड़ रु० खर्च होने का अनुमान है।

बाधाएं एवं निदान

यद्यपि कागज उद्योग दिनो दिन अधिकाधिक प्रगतिशील है, सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्र इसके विकास में सक्रिय हैं तथापि उद्योग में समुचित विकास में निम्न बाधाएं हैं जिनका निराकरण नितान्त आवश्यक है।

(१) आधुनिकीकरण—उद्योग में लगी अधिकांश मशीनें पुरानी हैं जिनकी उत्पादन क्षमता कम है और वृथा भी अधिक जाता है। नतीजा यह होता है कि उत्पादन मूल्य बढ़ जाता है, जो कि उद्योग विकास में बाधक है। अतः कारखानों में नई मशीनें लगाने की आवश्यकता है। अभी इसमें सभी प्रकार की मशीने व पुर्जे बाहर से मंगवाने पड़ते हैं जो महंगे पड़ते हैं एवं उनके आयात में समय भी काफी लगता है अतः देश के इन्जीनियरिंग उद्योग को कागज के निर्माण में प्रयुक्त मशीने यहीं बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

आज विश्व के अन्य देशों में कागज की उत्पादन प्रणाली में आमूल परिवर्तन आ चुका है। नये-नये यंत्रों व वैज्ञानिक प्रणालियों के प्रयोग से कम समय, श्रम एवं पूंजी में अधिक व अच्छा कागज बनने लगा है। अतः भारत को भी इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिये। कागज उद्योग में नई-नई मशीने व नये तरीके काम में लाये जाने चाहिये ताकि उत्पादन लागत में कमी हो, और उद्योग का विकास हो।

(२) कच्चा माल—यद्यपि कागज उद्योग में काम आने वाला सभी कच्चा माल देश में उपलब्ध है, पर उसकी प्राप्ति में कई बाधाएं हैं जिससे उद्योग को आवश्यक कच्चा माल समय पर नहीं मिल पाता और इस प्रकार उद्योग विकास नहीं कर पाता। कागज निर्माण का सबसे प्रमुख कच्चा माल बांस है। तदर्थ समिति के अनुसार देश में बांस का भंडार १८,००००० टन है जो कि बढ़ते हुए उत्पादन लक्ष्य के लिए अपर्याप्त है। सवाई घास और गन्ने की छोई से भी कागज बनाया जा सकता है, पर इसकी उपलब्धि भी सीमित है। सवाई घास थोड़ी मात्रा में प्राप्त है और गन्ने की छोई चीनी मिलों द्वारा जला कर नष्ट कर दी जाती है। विदेशों में कागज निर्माण में पहाड़ी वृक्षों (कोनीफिक्स) की लकड़ी काम में ली जाती है। यद्यपि भारत में भी यह लकड़ी उपलब्ध है, पर इसे प्राप्त करना कठिन है क्योंकि यह हिमालय के ऊंचे घने जंगलों में पाई जाती है, जहां पहुंचने के लिए सभी यातायात के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। कच्चे माल के उत्पादक राज्य अन्य राज्यों में स्थित कारखानों को कच्चा माल देने में

जीवन साहित्य

हिन्दी के उन मासिक पत्रोंमें से है, जो—

१. लोकरुचि को नीचे नहीं, ऊपर ले जाते हैं,
२. मानव को मानव से लड़ाते नहीं, मिलाते हैं,
३. आर्थिक लाभ के आगे झुकते नहीं, सेवा के कठोर पथ पर चलते हैं।

जीवन साहित्य की सात्विक सामग्री को छोटे-बड़े स्त्री-बच्चे सब निःसंकोच पढ़ सकते हैं। उसके विशेषांक एक से एक बढ़कर होते हैं।

वार्षिक शुल्क ४ रु. भेजकर ग्राहक बन जाइये।

ग्राहक बनने पर मंडल की पुस्तकों पर आपको कमीशन पाने की भी सुविधा हो जायगी।

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भेद-भाव पूर्ण नीति का प्रयोग करते हैं। कच्चे माल की इन समस्याओं का निदान निम्न प्रकार हो सकता है।

(अ) देश के वन-विभाग को बांस के उत्पादन एवं वितरण का कार्य अपने हाथ में ले लेना चाहिए ताकि सभी कारखानों को कच्चा माल मिल सके।

(आ) चीनी मिलों के लिए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि वे छोई की जगह कोई अन्य पदार्थ जलाये या फिर कम छोई जलाये, ताकि कागज मिलों को नियमित रूप से गन्ने की छोई मिल सके।

(इ) देश के भीतरी भागों में रेलों और सड़कों का पर्याप्त विकास आवश्यक है, ताकि कच्चा माल कम मूल्य में आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचाया जा सके। हिमालय के घने जंगलों को साफ किया जाय व वहां सड़कों का निर्माण किया जाय ताकि वहां की लकड़ी नीचे लाई जा सके।

(ई) यूकेलिप्टस, वैटल और शहतूत के वृक्षों की लकड़ी कागज बनाने के लिए उपयोगी है। अतः आवश्यक है इन किस्मों के पेड़ बड़ी संख्या में उगाये जाये।

(उ) फटे-पुराने चिथड़ों व अन्य प्रकार की घास आदि का भी कागज निर्माण में प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि उत्पादन मूल्य कम हो सके।

कागज उत्पादन का अन्य कच्चा माल, रासायनिक पदार्थ—गंधक व कास्टिक सोडा आदि आयात करने पड़ते हैं परन्तु विदेशी मुद्रा की कमी व आयात प्रतिबन्ध इस दिशा में बाधक है। परिणामस्वरूप समय पर आवश्यक वस्तु उपलब्ध नहीं होती। अतः सरकार को चाहिए कि वह उद्योग के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध करे व आयात प्रतिबन्ध पर कुछ छूट दे।

(४) अकुशल श्रमिक—देश के कागज उद्योग में लगे अधिकांश श्रमिक ग्रामीण किसान आदि हैं, जो अशिक्षित और अकुशल होने के कारण नई तकनीक समझ नहीं पाते, परिणामस्वरूप नई मशीनों पर काम नहीं कर सकते और इस प्रकार उत्पादन कुशलता बढ़ाई नहीं जा सकती। इसके लिए आवश्यक है सरकार देश में कुछ ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करे जहां इन लोगों को उचित शिक्षा दी जा सके।

(५) कर-भार—अत्यधिक कर-भार से कागज का मूल्य निरन्तर बढ़ता जा रहा है जो उद्योग विकास में बाधक है। इसके अलावा शिक्षा प्रसार के लिए उचित मूल्य पर कागज उपलब्ध करना सरकार का प्रथम कर्तव्य है अतः उद्योग पर से कुछ कर हटाये जाने चाहिए या उन पर छूट दी जानी चाहिए।

(६) पूंजीपतियों की उदासीनता—निजी क्षेत्र उद्योग के प्रति उदासीन हैं क्योंकि वहां कच्चे माल के मूल्य में ६०% की व श्रमिकों की लागत में ३०% की वृद्धि हुई है वहां कागज के मूल्यों में केवल १२% की वृद्धि हुई है। यही नहीं ३० से ४० प्रतिशत माल सरकार द्वारा लागत मूल्य पर ही खरीद लिया जाता है। अतः कागज उद्योग लाभप्रद धंधा नहीं रहा है।

उपसंहार

उपर्युक्त विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण व आंकड़ों से स्पष्ट है कि देश के कागज उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है। देश में शिक्षा, उद्योग व मुद्रण कला का निरन्तर अधिकाधिक विकास हो रहा है, अतः कागज की मांग बढ़ेगी और यह बढ़ी हुई मांग उत्पादन को प्रोत्साहन देगी, जिससे उद्योग का अधिक विकास होगा। हर्ष है कि निजी व सरकारी दोनों ही क्षेत्र इस दिशा में क्रियाशील हैं।

—

तैयारी में हाथ बटाओ
अपनी पूरी शक्ति लगाओ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हमारे उद्योग

बिजली-उत्पादन की नई योजना

अब सरकार भी बिजली की समस्या को अधिक गंभीरता से देखने लगी है। इसी लिए उसने अमरीका, ब्रिटेन, बेल्जियम और फ्रांस के विशेषज्ञों का एक मंडल भारत में बुलाया है। यह मंडल समस्त देश में विद्युत विकास की संभावनाओं पर विचार करके एक दस वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। ४ मास तक संभवतः इसकी रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच जाएगी। कमेटी में योजना आयोग और विविध सम्बद्ध मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी हैं।

समस्त देश की आवश्यकताओं को देखते हुए एक यह सुझाव दिया जा रहा है कि बिजली की दृष्टि से देश को कुछ विद्युत ग्रिड-क्षेत्रों में बांट दिया जाए और फिर इन क्षेत्रों में आवश्यक बिजली उपलब्ध करने की एक निश्चित योजना बनाई जाए। इस क्षेत्रीय विभाजन में राज्यों की भौगोलिक सीमाओं का पालन नहीं किया जायगा। एक राज्य नहीं, बल्कि एक क्षेत्र की दृष्टि से यह निश्चय किया जाएगा कि बिजली का कारखाना कहां बने और कहां न बने। अभी तक की विचार परम्परा से ऐसा प्रतीत होता है कि देश कुल सात विद्युत ग्रिड क्षेत्रों में बांटा जाएगा। इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि विद्युत उत्पादन का काम केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में लेगी। बिजली के वितरण आदि के सम्बन्ध में समझौता करके पहले राज्यों का असन्तोष दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा। एक अनुमान के अनुसार ये सात क्षेत्र निम्नलिखित होंगे :—

(१) केरल, मद्रास, मैसूर और दक्षिणी आंध्र।

(२) उत्तरी आंध्र, दक्षिणी उड़ीसा, पूर्वी महाराष्ट्र और केन्द्रीय दक्षिणी मध्यप्रदेश।

(३) गुजरात, पश्चिमी मध्यप्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण वर्ती राजस्थान।

(४) हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान।

(५) उत्तरप्रदेश और उत्तरी मध्यप्रदेश।

(६) बिहार, बंगाल, दामोदर घाटी और उत्तरी उड़ीसा।

(७) असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नेफा और नागालैंड।

इन सब क्षेत्रों में स्थापित एजेंसियां अपने-अपने क्षेत्र में विद्युत-उत्पादन की योजनाएं बनाएंगी। यह अनुमान किया गया गया है कि यदि इन क्षेत्रों में स्थापित एजेंसियों को अपने-अपने क्षेत्र में विद्युत उत्पादन का काम सौंपा गया तो बिजली के खर्च में काफी कमी आ जाएगी, न केवल पूंजीगत खर्चों में करोड़ों रु० की बचत होगी, बल्कि उत्पादन-व्यय भी कम हो जाएगा। इस नई व्यवस्था का एक बड़ा राजनैतिक लाभ अवश्य होगा। आज राज्य और राज्यों के अधिकारी तथा विधायक केवल अपने राज्य की संकुचित दृष्टि से ही बिजली के उत्पादन व वितरण पर विचार करते हैं। नये प्रस्ताव के अमल में आने के बाद राज्यों की भौगोलिक सीमाओं को छोड़ कर हमारी दृष्टि अधिक उदार और व्यापक हो जायगी। हम साधन, व्यावहारिकता और आवश्यकता की दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार करने लगेंगे। प्रांतीयता की भावना का कुछ कमजोर होना अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभ है।

करोड़ों रुपये का परामर्श

किसी योजना के सम्बन्ध में केवल परामर्श प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को कितनी भारी रकम खर्च करनी पड़ती है, इसके दो उदाहरण अभी हाल में सामने आए हैं। अलाए स्टील प्रोजैक्ट के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए भारत सरकार दस्तूर एण्ड कम्पनी को ८८ लाख रु. दे चुकी है। कनाडा की एक फर्म से भी इसी बारे में परामर्श करने के लिए उसे २.४० करोड़ रु० देना तय हुआ है। इसका अर्थ यह है कि ५० करोड़ रु० की एक योजना के लिये केवल परामर्श का व्यय ३.२८ करोड़ रु० हो गया है।

बोकारो में लोहे का कारखाना स्थापित करने के लिए वर्षों से बातचीत चल रही है। अमेरिकन मिशन के आने से पहले इसी दस्तूर एण्ड कम्पनी से परामर्श मांगा गया था और इसके लिए ७ लाख रु० सरकार ने इसे दिया था। नैवेली प्रोजैक्ट के सम्बन्ध में भी उसी कम्पनी को ३

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लाख रु० परामर्श शुल्क दिया जा चुका है। यह जानकर भी शायद पाठकों को विस्मय हो कि इस कम्पनी को लौह इस्पात मंत्रालय प्रतिवर्ष 'रिटेनर' के रूप में २ लाख रु० देता है।

राष्ट्रीय आय व उद्योग

१९६० में भारत की राष्ट्रीय आय में कारखानों का भाग ९ प्रतिशत था। अमरीका में यह भाग ३१ प्रतिशत और ब्रिटेन में ३५ प्रतिशत था। यदि उद्योगों के लाभ को देखा जाए तो भारत में यह भाग केवल २.६ प्रतिशत था, जबकि ब्रिटेन और अमरीका में औद्योगिक लाभ क्रमशः कुल राष्ट्रीय आय का ९.७ और १०.८ प्रतिशत था।

डिविडैन्ड और राष्ट्रीय आय में १९५१ में अनुपात ·०७ और १०० था, जबकि १९६० में यह अनुपात १ और १०० हो गया। इसी अवधि में अमरीका और ब्रिटेन में यह अनुपात ३.३ से ३.२ और १.४ से २.३ प्रतिशत हो गया।

१९५१ में उद्योगों पर लगे टैक्स राष्ट्रीय आय को ०.८ प्रतिशत के बराबर थे लेकिन १९६० में यह अनुपात बढ़कर १.१ प्रतिशत हो गया। इसके विपरीत ब्रिटेन और अमरीका में यह अनुपात कम हो गया। ब्रिटेन में ६ प्रतिशत से गिरकर ४.५ और अमरीका में ८.१ से गिरकर ५.३ प्रतिशत रह गया। कुल करों की दृष्टि से भारत में उद्योगों पर कर ७२ प्रतिशत बढ़ गये, जबकि अमरीका में करों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ और ब्रिटेन में केवल २३ प्रतिशत बढ़े।

निम्नलिखित सूची से मालूम होता है कि भारत, ब्रिटेन और अमरीका में उद्योगों को अपने पास एकत्र सब स्रोतों पर कितने प्रतिशत लाभ होता रहा है—

प्रतिशत लाभ

साल	भारत	ब्रिटेन	अमरीका
१९५१	४८.३	२७.१	२३.४
१९३२	३५.५	४१.०	२१.३
१९५३	६८.४	३७.७	२६.०
१९५४	४०.५	३४.९	२८.४
१९५५	४७.६	३३.२	२१.७
१९५६	२३.१	३१.७	२१.९
१९५७	११.२	२८.८	२०.९
१९५८	२१.४	३८.०	१४.४
१९५९	४५.३	३०.५	१६.६
१९६०	३१.९	२४.६	१७.०

यों तो प्रतिशत उक्त सभी देशों में गिरा है, लेकिन भारत में यह गिरावट सबसे अधिक है।

भारत में बना पहला जहाज

न्यूयार्क में भारत के महा-वाणिज्यदूत श्री एस० के० राय के कथनानुसार भारतीय जहाजरानी निगम अगले महीने से महीने में एक बार भारत से अमरीका को सीधे जहाज से माल की ढुलाई शुरू करेगा। यह पहला मौका है, जबकि भारत में बना जहाज अमरीका को माल लेकर जाएगा।

कारखानों में ६० प्रतिशत समय खाली

मारिस सोलोमन ने कलकत्ते की कुछ फैक्टरियों का सर्वेक्षण किया था। उनके सर्वेक्षण के अनुसार इन फैक्टरियों में कुल समय के केवल ४० प्रतिशत भाग में ही मशीनों से लाभ उठाया जाता है। बाकी समय मशीनों को लगाने, उनकी मरम्मत करने अथवा कच्चे माल की प्रतीक्षा में निकल जाता है। कुछ समय का ६ प्रतिशत भाग रोटी खाने की छुट्टी में बीतता है तो १८ प्रतिशत भाग मजदूरों की अज्ञात कारणों से अनुपस्थिति में निकल जाता है। कैनटीन में जाने में १.८ प्रतिशत भाग और शौचालय जाने में समय का १.८ भाग खर्च होता है। इसी प्रकार एक काम से दूसरे काम को शुरू करने में ३ प्रतिशत वक्त लगता है और सामान लाने, औजारों को तेज करने और औजारों को लाने में क्रमशः ३ प्रतिशत, ८ प्रतिशत और ५ प्रतिशत समय व्यतीत होता है। हिदायत पाने में ९ प्रतिशत समय और काम शुरू करने में जो देरी होती है अथवा समय से पहले काम बन्द कर देने में ५.५ प्रतिशत समय खर्च होता है।

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस मास की आर्थिक घटनाएं

सहकारी उपभोक्त स्टोरों की व्यवस्था

केन्द्रीय सरकार देश भर में उपभोक्ता स्टोर खोलने की जो व्यवस्था कर रही है, उसके लिए अनाज, कपड़े, मिट्टी के तेल और दवा जैसी रोजमर्रा काम आने वाली मुख्य वस्तुओं की सप्लाई का व्यापक प्रबन्ध कर दिया गया है।

उपभोक्ता स्टोरों को अनाज केन्द्रीय गोदामों से मिलेगा। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे अनाज बांटने का काम सहकारियों को सौंपें और उन्हें सस्ते दामों की दुकानें माना जाए। वस्तुओं के भाव ज्यादा न बढ़ने देने के उद्देश्य से थोक बिक्री की सहकारियां प्राथमिक सहकारियों का काम करेंगी। आटे की उन मिलों से, जिन्हें आयातित गेहूँ मिलता है, कहा गया है कि वे थोक बिक्री की सहकारियों को माल सप्लाई करने में प्राथमिकता दें।

उपभोक्ता स्टोरों को कपड़े की सप्लाई करने की भी व्यवस्था की गई है। कपड़े की मिलें उपभोक्त स्टोरों और सस्ते दामों की दुकानों को एक्स-मिल दर पर अपने कुल उत्पादन का दस प्रतिशत देने को तैयार हो गयी है।

इस समय १२ राज्यों में राज्य हाट सहकारियां उपभोक्ता सहकारियों को इंडियन आयल कम्पनी का मिट्टी का तेल दे रही हैं। इन राज्यों के नाम हैं : महाराष्ट्र, मैसूर, गुजरात, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा पश्चिम बंगाल, बिहार और आसाम।

गैर सरकारी क्षेत्र के कई विख्यात कारखाने उपभोक्ता सहकारियों को आम दवाइयां रियायती दामों पर देने को तैयार हो गए हैं। राष्ट्रीय कृषि सहकार हाट संघ को उपभोक्ता स्टोरों के लिए ५० लाख रु० के सूखे मेवे, खजूर आदि आयात करने के लाइसेंस दिए गए हैं।

पेट्रोल की चीजों में आत्मनिर्भरता

गुजरात में कोयली में तीसरे सरकारी तेलशोधक कारखाने के शिलान्यास के साथ भारत ने पेट्रोल के उत्पादनों में आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम और आगे बढ़ाया है। यह कारखाना बड़ोदा से १० किलोमीटर दूर, बाजुआ रेलस्टेशन के समीप खोला गया है। इसे तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, रूस की आर्थिक और शिल्पिक मदद से बना रहा है। इस कारखाने में आयोग के अंकलेश्वर और कालोल के तेल कुओं से निकाला गया तेल, साफ किया जाएगा।

कारखाना बनाने का काम दो चरणों में पूरा होगा। पहले चरण के पूरा होने पर कारखाने की क्षमता १० लाख टन तेल साफ करने की होगी। दूसरे चरण के बाद कारखाने की क्षमता दुगनी हो जाएगी। पहला चरण दिसंबर १९६४, में और दूसरा जुलाई १९६५ में पूरा होगा। उसके बाद जल्दी ही इस कारखाने की क्षमता बढ़ा कर ३० लाख टन कर दी जाएगी।

कोयली तेल शोधक कारखाना खास तौर से मिट्टी के तेल और डीजल तेल की कमी को दूर करने के लिए बनाया जा रहा है। कारखाने में ५३६००० टन मिट्टी का तेल, १० हजार टन तरल पेट्रोल, और ३७१४०० टन मोटर गैसोलीन का उत्पादन होगा। वहां २५ हजार टन दाबक पदार्थ, ८० हजार टन : शोधक गैस और ४२२,००० टन ईंधन तेल का उत्पादन होगा।

खनिजों के उत्पादन में वृद्धि

देश में १९६२ में १ अरब ८६ करोड़ ८० लाख रु० के खनिज निकाले गए। पिछले साल १ अरब ६६ करोड़ २० लाख रु० के खनिज निकाले गए थे। १२ प्रतिशत की यह वृद्धि कोयले, सोने, जिप्सम, चूने के पत्थर और नमक के अधिक उत्पादन के कारण हुई है।

१९६२ में १ अरब ३३ करोड़ ८० लाख रु० का कोयला निकाला गया जो सब खनिजों के उत्पादन का ७२ प्रतिशत है। इस वर्ष २७ करोड़ २० लाख रु० की खनिज धातुएं निकाली गईं, जो कुल उत्पादन के मूल्य का १५ प्रतिशत है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विदेशों से सहायता

भारत सरकार और अमरीका सरकार के बीच ४ करोड़ रु० (८४ लाख डालर) के ऋण के करार पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह ऋण आंध्र प्रदेश की रामगुन्दम बिजली योजना की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता के लिए दिया गया है।

श्री गालब्रेथ ने यह घोषणा की कि उनकी सरकार ने भारत सरकार को विदेशी मुद्रा में दो और ऋण स्वीकार किए हैं। पहला ऋण ७७ लाख डालर (३ करोड़ ७० लाख रु०) का है और इससे झरिया की कोयला-खानों में एक रस्सा-मार्ग (रोप-वे) बनाया जाएगा। दूसरा ऋण ५१ लाख डालर का है और यह राशि दुगड़ा के कोयला धोने के कारखाने का उत्पादन दुगना करने पर खर्च की जाएगी। ये दोनों योजनाएं बिहार राज्य में चालू हैं और इनसे इस्पात कारखानों के उपयोग का कोक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकेगा।

जिन चार ऋणों की २१ मई को घोषणा हुई, उनकी कुल राशि १३ करोड़ ८० लाख रु० है। इन ऋणों की राशि का भुगतान ४० वर्ष में होगा। इस अवधि को दस वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। इन ऋणों पर ब्याज नहीं लगेगा, पर ¾ प्रतिशत "सर्विस चार्ज" देना होगा। भारत सरकार के कृषिमंत्री श्री एस० के० पाटिल ने वाशिंगटन में पी एल ४८० की अन्तर्गत नये समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

रूस

बरौनी (बिहार) और कोयली (गुजरात) के तेल साफ करने के कारखानों को बढ़ाने तथा पालघाट (केरल) के निकट पुदुमेरी में दूसरा सूक्ष्म-यंत्र कारखाना स्थापित करने के लिए रूस से आर्थिक तथा टेक्नीकल सहायता लेने के बारे में सोवियत रूस और भारत सरकार ने अन्तिम निर्णय कर लिया है।

समझौते में, बरौनी और कोयली तेल शोधक कारखानों को तीसरी योजना में बढ़ाने की व्यवस्था है, जिससे प्रत्येक कारखाने में हर साल २० के बजाए ३० लाख टन कच्चा तेल साफ किया जा सके। इन कारखानों को बढ़ाने पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होगी, वह ११ करोड़ २५ लाख रुबल (५९ करोड़ ५३ लाख रु०) ऋण से बची रकम में से दी जाएगी। यह ऋण सोवियत रूस ने फरवरी, १९६१ में दिया था।

बरौनी कारखानों में इस साल के अन्त तक १० लाख टन तेल साफ करने का यंत्र चालू हो जाएगा। दूसरा १० लाख टन तेल साफ करने का यंत्र सम्भवत: अप्रैल, १९६४ में चालू हो जाएगा।

कोयली कारखाने में १० लाख टन तेल साफ करने का पहला यंत्र १९६४ के अन्त तक लग जाएगा। दूसरा यंत्र उसके ६ महीने बाद लगेगा।

जापान

जापान भारत को तीसरी योजना के पहले दो वर्षों के लिए ५ अरब ४० करोड़ येन (७ करोड़ १४ लाख रु०) का अतिरिक्त ऋण देगा। यह २८ अरब ८० करोड़ येन के उस दूसरे ऋण के अतिरिक्त है, जो जापान के एक्स-पोर्ट-इम्पोर्ट बैंक और अन्य प्राइवेट जापानी बैंकों ने भारत को जापान से माल खरीदने के लिए देने का निर्णय किया।

यह ऋण दुर्गापुर विशेष इस्पात और मिश्रित धातु योजना के लिए तथा दोनों सरकारों की सहमति से जापान से माल खरीदने पर खर्च किया जाएगा। यह ऋण १५ वर्षों में चुकाया जाएगा, पहले पांच वर्षों तक इसे चुकाने की जरूरत नहीं।

(पृष्ठ २८६ का शेष)

में ४.८ प्रतिशत कमी हुई। १९४७-५३ के बीच इन निर्धन व्यक्तियों में २.७ प्रतिशत कमी हुई। इसी अवधि में समृद्ध अमेरिका परिवारों की संख्या ४.५ प्रतिशत से बढ़कर ७.३ प्रतिशत हो गयी और कुल पारिवारिक आय में उनका हिस्सा १८.५ प्रतिशत से बढ़कर २४ प्रतिशत तक हो गया। इसका अभिप्राय यह है कि न केवल "निर्धनता" में कमी आयी किन्तु धनियों के धन में भी वृद्धि हुई और अपनी संख्या में अनुपात से वे अधिक आराम से रहने लगे।

इसके परिणाम स्वरूप, अगले वर्षों में अमेरिका में आर्थिक विकास की दर मंद हो सकती है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देश की प्रतिरक्षा के लिए वस्त्रों का अधिक उत्पादन

बिड़ला काटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि०

के

अधिकारी, कर्मचारी व कारीगर देश के जन-जन के लिए
हर किस्म का कपड़ा मिल में तैयार करते हैं

पंजाब की सर्वश्रेष्ठ रुई से

साड़ी, धोती, छीट, लट्ठा, शर्टिंग,
मलमल, कोटिंग, वायलिन, खादी,
दुसूती, चादर आदि

कुशल कारीगरों द्वारा बनाये जाते हैं !!

*

बिड़ला काटन स्पिनिंग एण्ड
वीविंग मिल्स लिमिटेड, दिल्ली ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१५ अगस्त के स्वाधीनता दिवस पर

सम्पदा का नया विशेषांक

दिल्ली-विकास अंक

यद्यपि दिल्ली क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से विभिन्न राज्यों में बहुत छोटा है, परन्तु भारत के केन्द्र में स्थित होने तथा देश की राजधानी होने के कारण इसका अपना महत्व है। आज दिल्ली समस्त देश की प्रायः समस्त आर्थिक प्रवृत्तियों का भी केन्द्र होता जा रहा है। इसकी अपनी समस्याएं है और अपनी विशेषताएं हैं।

इन विशेषताओं व समस्याओं का विवेचन करने और दिल्ली की विविध आर्थिक गतिविधियों पर प्रकाश डालने के लिए सम्पदा का—

दिल्ली-विकास अंक

प्रकाशित किया जा रहा है। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि यह विशेषांक भी विद्वत्तापूर्ण और ज्ञानवर्द्धक लेखों व नक्शों, चित्रों और ग्राफ आदि सभी अपनी विशेषताओं से युक्त, उपयोगी संग्रहणीय व पठनीय होगा।

१६ फार्म, मूल्य होगा १ रु० ५० न० पै०

यह अंक भारी संख्या में प्रकाशित हो रहा है, फिर भी हमें सन्देह है कि हम इसकी मांग पूरी कर सकेंगे। इसलिए अपनी प्रति १ रु. ५० न. पै. भेजकर सुरक्षित करा लें।

विज्ञापनदाता विज्ञापन के लिए भी अपना स्थान सुरक्षित करा लें।
विशेष जानकारी के लिए पत्र-व्यवहार करें।

व्यवस्थापक—**सम्पदा २८/११ शक्तिनगर दिल्ली**

सम्पादक—कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा नवचेतन प्रेस (प्रा०) लि० (लीजिज ऑफ अर्जुन प्रेस) दिल्ली-६ से मुद्रित
अशोक प्रकाशन मन्दिर २८/११, शक्तिनगर, दिल्ली-६ से प्रकाशित।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पादा

दिल्ली विकास अंक

अशोक प्रकाशन मन्दिर शक्ति नगर, दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

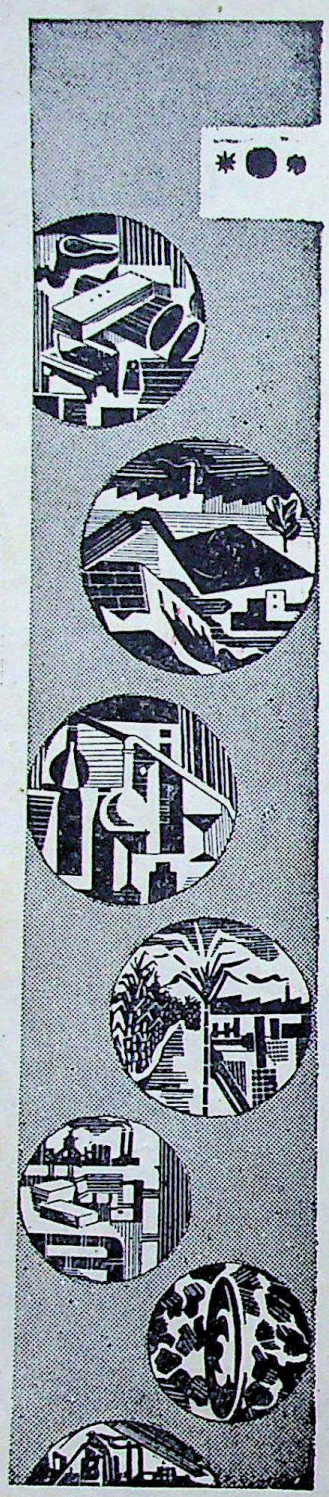

न ये क्षि ति ज

स्वतंत्रता पूर्व युग में भी जनता के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए भारत की योजनाएं और कार्यक्रम थे। पर उनमें मौलिक निर्बलता थी कि उनका सम्बन्ध जनता की अपेक्षा सरकार के साथ अधिक था।

स्वतंत्रता आई और इसके साथ नव-जागरण और जनता की योजनाएं—जनता के लिए और जनता के द्वारा। इसके परिणाम स्पष्ट थे, अधिक से अधिक बेहतर व सस्ती वस्तुएं अधिक से अधिक लोगों के लिए बेहतर जीवन।

डालमिया उद्योग समूह

निरन्तर ऐसे सामान का अधिक से अधिक उत्पादन करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो हमारे जीवन स्तर को ऊंचा करने में सहायक हो। हम यह कामना न केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से, किन्तु लगभग एक चौथाई सदी से कर रहे हैं। यह काम कठिन होते हुए भी हम निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं, इस आशा के साथ कि कल का दिन अधिक उज्ज्वल, नव-प्रभात एवं नये क्षितिज से युक्त होगा।

DALMIA ENTERPRISES

डालमिया सिमेंट (भारत) लि., डालमियापुरम् (मद्रास)
डालमिया आयरन एंड स्टील लि., राजगंगपुर व कलकत्ता
डालमिया मेगनेसाइट कार्पोरेशन, सेलम (मद्रास राज्य)
उड़िशा सिमेंट लि. राजगंगपुर (उड़िशा राज्य)
रजा बुलन्द शूगर कं० लि०, रामपुर (उ० प्र०)
दि रामपुर डिस्टिलरी एंड केमिकल कं. लि., रामपुर (उ.प्र.)

राष्ट्र की सेवा में सन्निहित

डालमिया उद्योग-समूह

मुख्य कार्यालय—४, सिन्धिया हाउस, नयी दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली प्रगति के पथ पर

क्षेत्रफल ५७३ वर्ग मील

जनसंख्या २६.४ लाख
(सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार)

देश के अन्य भागों की तरह दिल्ली प्रदेश भी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सन् १९५१ से प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

पहली पंचवर्षीय योजना में

(१) विकास कार्यों का शुभारम्भ
(२) शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, कृषि व घरेलू दस्तकारियों से सम्बन्धित योजनाओं का संचालन
(लगभग ७ करोड़ रु. खर्च हुए)

दूसरी योजना में

(१) सिंचाई, बिजली, स्वास्थ्य व कृषि में प्रशंसनीय प्रगति
(२) शिक्षा का प्रसार
(३) समाज-कल्याण व गृह-निर्माण से सम्बन्धित योजनाओं पर अमल
(४) औद्योगिक बस्तियों की स्थापना
(लगभग ४० करोड़ रु. खर्च हुए)

तीसरी योजना में

(१) गृह-निर्माण पर अधिक बल
(२) बिजली, सिंचाई, यातायात की सुविधाओं की बढ़ोतरी
(३) शिक्षा की ओर विशेष ध्यान
(४) औद्योगिक बस्तियों का विस्तार
(५) तकनीकी प्रशिक्षण की ओर प्रभावकारी कदम
(६) मास्टर प्लान पर अमल आरम्भ आदि आदि
(इस योजना पर ९८ करोड़ रु. खर्च होंगे)

"देश की सुरक्षा के लिए विकास कार्यों में सहयोग दीजिये।"

प्रकाशक—निदेशक, जन-सम्पर्क विभाग, दिल्ली प्रकाशन, दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विज्ञापन दाताओं की सूची

	पृष्ठ
१. अजुध्या टैक्सटाइल मिल्स लि०	५०
२. आत्माराम एण्ड सन्स	९३
३. इण्डियन टूल्स मैन्युफैक्चरर्स	५
४. उड़िशा सीमेंट	१०८
५. कमला साडी हाउस	७३
६. क्वालिटी मिनरल्स सप्लाई सिंडिकेट	८८
७. चानना सेल्स कारपोरेशन	१११
८. जीवन रेडियोज	६५
९. जे. के. आर्गेनाइजेशन	३७
१०. टाटा आयरन वर्कर्स	६६
११. ट्रेडिंग इंजिनीयरिंग वर्कर्स	१०६
१२. डालमिया साहस	२
१३. डीडवानिया एण्ड कं०	८९
१४. दिल्ली क्लाथ मिल्स	३०
१५. दिल्ली-प्रशासन	३
१६. बजाज इलैक्ट्रिकल	मुख पृष्ठ-४
१७. बिड़ला काटन मिल्स	३८
१८. भारत आर्ट वर्क्स	५३
१९. भारत सरकार का विज्ञापन विभाग	१०४
२०. मेहता एण्ड सन्स	७५
२१. मैचवैल्स इलैक्ट्रिकल्स	मुख पृष्ठ-३
२२. रामपुर इंजिनीयरिंग कं०	१०३
२३. वसुधा लैण्ड एण्ड फाइनैंस कं०	४५
२४. वंसीलाल एण्ड कं०	१७
२५. विक्टर एपैरल प्रा० लि०	५०
२६. सरन मोटर्स प्रा० लि०	८२
२७. साठे बिस्कुट	७०
२८. सैंचुरी स्पि. मै. मिल्स कं० लि०	७०
२९. सैन्ट्रल बैंक	८९

'सम्पदा' के स्थायी ग्राहकों से

१. "सम्पदा" कार्यालय से पत्र व्यवहार करते समय अपनी **ग्राहक संख्या** अवश्य लिखें।

२. वार्षिक चन्दा समाप्त होने पर अगले वर्ष का चन्दा स्वयं भेजने की कृपा करें, अगले वर्ष का ग्राहक न रहने की हमें एक मास पूर्व सूचना देने की कृपा करें।

३. जुलाई ६३ से 'सम्पदा' का वार्षिक चन्दा रु० ८.५० तथा नमूने की कापी का मूल्य ८० न० पै० हो गया है।

४. समय पर हर मास की २० तारीख तक "सम्पदा" न मिलने पर हमें तुरन्त सूचना दें इससे पहले डाकखाने और आस पास के मित्रों से पूछ ताछ कर लें।

संयुक्त अंक की सूचना ग्राहकों को

यह अंक जुलाई-अगस्त का संयुक्त विशेषांक है। जुलाई का पृथक् अंक इस बार प्रकाशित नहीं किया गया। इसलिए जुलाई के अंक के लिए पत्र व्यवहार करने का कष्ट न करें।

एजेंट चाहिए

इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, चन्दौसी और आगरा में सम्पदा के विक्रय के लिए उत्साही एजेन्ट चाहिए।

मैनेजर
सम्पदा
२८/११ शक्तिनगर दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विषय-सूची

सं०	विषय		पृष्ठ
१.	यह दिल्लीविकास-अंक	(सम्पादकीय)	७
२.	दिल्ली सच्चे अर्थों में भारत की राजधानी हो।	श्रीमन्नारायण सदस्य योजना आयोग	८
३.	श्रम ही सम्पदा का स्रोत	श्री शम्भूनाथ	९
४.	संतुलित और संगठित कार्यक्रम	श्री भगवानसहाय चीफ कमिश्नर दिल्ली	९
५.	दिल्ली पर उत्तरदायित्व	श्री भरतराम	१०
६.	दिल्ली का विकास और महत्व		११
७.	दिल्ली की अपनी विशेषताएं और समस्याएं		१२
८.	गुलाब के फूल मुझे चुभते हैं		१३
९.	चिरयौवना दिल्ली का नवनिर्माण	श्री लेखराम	१४
१०.	चित्रावलि		१८
११.	उद्योगीकरण : भविष्य और समस्याएं	श्री भगवानसहाय	२३
१२.	१९६१ से १९६३ तक दिल्ली	श्री दीनानाथ सिद्धान्तालंकार	२६
१३.	परिवर्तनशील आर्थिक स्वरूप	श्री पी० एन० धर	२८
१४.	शिक्षा में सबसे आगे दिल्ली	श्री बी० डी० भट्ट	३०
१५.	दिल्ली का चतुर्मुखी विकास	श्रीकृष्णकिशोर	३१
१६.	दिल्ली की विकास योजनाएं	श्री ल० ओ० जोशी	३५
१७.	दिल्ली में स्वायत्त शासन का विकास	श्री शिवचरण गुप्त एम० पी०	३८
१८.	यह आपकी दिल्ली है—१		४२
१९.	दिल्ली का विकास : कुछ ऐतिहासिक घटनाएं		४४
२०.	मास्टर प्लैन नक्शा		४७
२१.	यह आपकी दिल्ली है—२		४८
२२.	देहली का विशाल काय मास्टर प्लैन		५१
२३.	मास्टर प्लैन : नियंत्रण	श्री ब्रह्मप्रकाश संसद् सदस्य	५५
२४.	देहली में आवास की समस्या	श्री बलराज मधोक	५७
२५.	भूमि सुधार कानून व इसकी नीति	श्री गोपीनाथ अमन	५९
२६.	दिल्ली में सिंचाई		६१
२७.	दिल्ली में ग्रामरक्षा संगठन	श्री आनन्दशंकर शर्मा	६२
२८.	बिजली की अपर्याप्त अव्यवस्था		६४
२९.	कपड़े की भारी मण्डी, दिल्ली	श्री व्रजभूषण सरन	६७
३०.	दिल्ली के व्यापार की समस्याएं	श्री ओ० पी० अग्रवाल	६९
३१.	दिल्ली के व्यापार और उद्योग		७१
३२.	दिल्ली में कपड़े की खपत	श्री केडिया	७३
३३.	दिल्ली एक सांस्कृतिक संगम	श्री गोपीनाथ अमन	७४

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

३४. दिल्ली की गृहिणी की आर्थिक समस्या	श्रीमती माधुरी श्री वास्तव	७१
३५. दिल्ली सबसे महंगा		७८
३६. आबादी की असमान-घनता		८०
३७. दिल्ली में कम्पनियों का विकास	डा७ श्री राज० के० निगम	८३
३८. दिल्ली में बिक्री कर		८१
३९. दिल्ली का औद्योगिक विकास	श्री एन० एन० टण्डन	८७
४०. दिल्ली के उद्योग की समस्याएं		९०
४१. सुनियोजित विकास	श्री रामलाल वर्मा	९१
४२. मशीनरी उद्योग का विकास	श्री ओमप्रकाश रहेजा	९२
४३. बाहर से अनुमानित खाद्य का आयात		९४
४४. दिल्ली प्रशासन का बजट		९५
४५. दिल्ली निगम का बजट		९६
४६. दिल्ली क्लाथ मिल्स		९७
४७. दिल्ली के श्रमिक और श्रम समस्या		९९
४८. बेघरों का घर रैनबसेरा	श्री सुरेन्द्र सैनी	१०७
४९. मकान मालिक बनाम किरायेदार		११३
५०. दिल्ली फैक्ट्री ओनर्स एसोसियेशन		११४

दि इंडियन टूल मैन्यूफेक्चर्स लि०

१०१, सायन रोड, बम्बई—२२

की पूर्ण शुभ कामनाओं के साथ

निर्माता :—

ट्विस्ट ड्रिल्स, रियेमेर्स कटर्स, टेप्स, केरबिड टिप्स और

टूल्स और क्रोमीटर्स

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वर्ष : १२
अंक : ७-८
जुलाई, अगस्त : १९६३

सम्पदा

सम्पदा का दिल्ली विकास अंक

यों तो स्वाधीनता प्राप्ति और विकास योजनाओं के प्रारम्भ के बाद देश के सभी राज्य अपने आर्थिक व भौतिक विकास में लग गये हैं, किन्तु इन वर्षों में दिल्ली का महत्व जिस निश्चित अबाध गति से बढ़ा है उसकी तुलना किसी अन्य राज्य से नहीं की जा सकती। स्वतंत्र विश्व में भारत के बढ़ने के बदलने के साथ साथ उसकी राजधानी का महत्व भी निरन्तर बढ़ता गया है।

दिल्ली भारत की गौरवमयी राजधानी है। इसलिए क्षेत्रफल में अन्य राज्यों की तुलना में नगण्य होते हुए भी उसे अनेक ऐसी सुविधाएं प्राप्त रही हैं, जो अन्य राज्यों को प्राप्त नहीं हो सकीं। कोई निकटवर्ती बन्दरगाह नहीं है, लोहे, कोयले या तेल की भी खानें यहां नहीं हैं, न यहां बड़े बड़े उद्योगों के विकास के लिए अनुकूलता है, फिर भी उसका आर्थिक महत्व कम नहीं है।

"सम्पदा" ने देश की आर्थिक प्रगति व विभिन्न आर्थिक समस्याओं पर पूर्णतः विचार करने के लिए समय समय पर विशेषांक प्रकाशित करके हिन्दी की पत्रकारिता में एक नई स्वस्थ परम्परा स्थापित की है। पर हमने यह अनुमान किया है कि भारत इतना विशाल देश है और उसके विविध राज्यों की आर्थिक समस्याएं इतनी अलग-अलग हैं कि उनका किसी एक अंक में समावेश नहीं हो सकता। ऐसा प्रयत्न करना किसी भी राज्य के साथ अन्याय होगा। इसलिए हमारा यह विचार रहा है कि विभिन्न राज्यों की आर्थिक समस्याओं पर पृथक् पृथक् विशेषांक प्रकाशित करें। यह स्वाभाविक ही था कि ऐसा करते समय हम भारत की राजधानी और "सम्पदा" के अपने केन्द्र दिल्ली से ही इस प्रयत्न का श्रीगणेश करें। प्रस्तुत विशेषांक इस का ही परिणाम है।

दिल्ली की अपनी विशेष परिस्थितियां है, अपनी कुछ विशेषताएं और अपनी कुछ समस्याएं हैं। इस विशेषांक के पृष्ठों में इन सब पर संक्षेप से विविध अधिकारी लेखकों ने प्रकाश डालने का यत्न किया है। प्रारम्भ में हमारा यह विचार था कि दिल्ली एक छोटा सा राज्य है, इसलिए इस पर कम प्रयत्न करना पड़ेगा। लेकिन ज्यों ज्यों हम दिल्ली की समस्याओं की गहराई में जाने लगे, हमारा यह भ्रम दूर होता गया। विषय के साथ न्याय करने के लिए हमें यह प्रतीत हुआ कि अभी और अधिक प्रयत्न की आवश्यकता है। परन्तु अंक का कलेवर बढ़ने का भय था, और समय की भी अपेक्षा थी, इसलिए हम अनेक पहलुओं को इसमें भी नहीं दे सके। उदाहरण स्वरूप दिल्ली और उसके निकटवर्ती स्थानों में दिल्ली के औद्योगिक—बड़े या छोटे विभिन्न उद्योग जो विशाल महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, उनका परिचय देने के लिए एक पृथक् ही विशेषांक की आवश्यकता है। हमारा विचार है कि निकट भविष्य में इन पर प्रकाश डालने के लिए भी एक विशेषांक प्रकाशित करें।

प्रस्तुत अंक के प्रकाशन में हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमारा विचार वर्ष के प्रारंभ में इसे निकालने का था, किन्तु दो मास पूर्व चीन के भारत पर विश्वासघातपूर्ण और निर्लज्ज आक्रमण के कारण स्वभावतः समस्त देश का ध्यान नये संकट की ओर चला गया। जो जहां और जिस स्थिति में था, इस आपातकालीन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्थिति का मुकाबला करने के लिए योगदान में जुट गया। फलतः, यह विशेषांक भी स्थगित करना पड़ा। किसी राज्य के सम्बन्ध में अंक प्रकाशित करने के लिए सरकारी अधिकारियों से आवश्यक विवरण की प्राप्ति आवश्यक है। वह हमें बहुत विलम्ब से प्राप्त हो सकी और वह भी पूरी नहीं। कुछ भाग्य की बात कि इन्हीं महीनों में अनेक विभागों के अधिकारी बदल गये। मार्च में हमने उनसे प्रार्थना की और वे आश्वासन देते रहे, पर दो महिने बीतते बीतते नया अधिकारी आगया। इस कारण भी सामग्री की प्राप्ति में विलम्ब हुआ। फिर भी दिल्ली राज्य के निवर्तमान माननीय चीफ कमिशनर, नये आने वाले चीफ सैक्रेटरी तथा कुछ अन्य अधिकारियों के सहयोग के बिना यह अंक प्रकाशित न हो सकता। अनेक लेखकों ने भी हमें सहयोग दिया है। उनके निकट भी हम कृतज्ञ हैं।

जिन अनेक लेखकों के लेख समय और स्थान के अभाव के कारण प्रकाशित नहीं हो सके, उनके निकट हम क्षमा प्रार्थी हैं।

यह अंक जैसा बन पड़ा, पाठकों के सामने है। हमें आशा है, यह अंक अधिकारियों तथा जनता का ध्यान दिल्ली की समस्याओं की ओर खींचने में अवश्य कुछ सफल होगा। दिल्ली की समस्याओं का समाधान सरकार, निगम और जनता सबके सम्मिलित सहयोग से ही सम्भव है। हमें आशा है कि हम सब मातृभूमि की इस गौरवमयी राजधानी का उज्ज्वल भविष्य बनाने में एक साथ मिलकर अनथक प्रयत्न करेंगे।

—कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

—:—

दिल्ली सच्चे अर्थों में भारत की राजधानी हो

दिल्ली शहर भारतीय संसद्, भारत सरकार व योजना आयोग के दफ्तरों का केन्द्र है। यहीं से विभिन्न क्षेत्रों की योजनाएं प्रसारित होती हैं और यह प्रयत्न किया जाता है कि वे देश के सभी हिस्सों में संचालित हों। किन्तु दिल्ली शासन की सूचनाओं का प्रदेशों में तभी आदर हो सकता है, जब उन्हें पहले दिल्ली शहर में लागू करने का पूरा प्रयत्न किया जाय। नहीं तो "दिये तले अंधेरे" वाली कहावत ही चरितार्थ होगी और भारत की जनता यही कहेगी कि दिल्ली से योजनाएं तो बहुत निकलती हैं, लेकिन उनका पालन दिल्ली शहर में ही नहीं होता। इस दृष्टि से यह बिल्कुल आवश्यक है कि दिल्ली शहर भारत का एक आदर्श नगर हो और हमारी सभी योजनाओं का दर्शन यहां मिल सके।

योजना आयोग में जब हम विभिन्न योजनाओं की चर्चा करते हैं तो इस बात पर हमेशा जोर देते हैं कि इन योजनाओं को पहले दिल्ली में सफल बनाने का भरसक प्रयत्न किया जाय। अगर हम ऐसा न कर सकें तो फिर इन योजनाओं के पीछे कोई नैतिक बल नहीं रहता और राज्य सरकारें यही महसूस करती हैं कि दिल्ली बहुत प्रकार की योजनाएं बनाता है, लेकिन स्वयं दिल्ली में उन्हें कार्यान्वित करने की कोशिश नहीं करता।

हम सब यही चाहते हैं कि दिल्ली शहर का बहुमुखी विकास हो और जो कोई नागरिक यहां आवे, वह नई प्रेरणा व उत्साह लेकर जावे। जब ऐसा हो सकेगा, तभी दिल्ली सच्चे अर्थ में भारत की राजधानी बन सकेगी।

—श्रीमन्नारायण

नयी दिल्ली
१६-७-६३

नई दिल्ली, २० फरवरी, १९६३

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संतुलित और संगठित कार्यक्रम

हर्ष की बात है कि "सम्पदा" पत्रिका अपना दिल्ली विशेषांक प्रकाशित कर रही है । ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तो दिल्ली के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है, परन्तु उसकी आर्थिक तथा औद्योगिक स्थिति का यह विवेचन कदाचित् मौलिक प्रयास है।

२— राजधानी होने के अतिरिक्त दिल्ली देश के तीन सर्वप्रमुख नगरों में से एक है । इस नगर की महत्ता के अनुकूल इसकी समस्याएं भी स्वभावतः जटिल तथा ग्रंथियुक्त हैं। राष्ट्र वैभव का प्रतीक होने के कारण दिल्ली को धनधान्यपूर्ण बनाना अनिवार्य है, जो औद्योगीकरण के बिना सम्भव नहीं। राष्ट्र विभाजन के पश्चात् एक भारी जनसमुदाय के दिल्ली में आ पहुँचने के कारण बेकारी की समस्या और भी भीषण हो गई है, जिसके निवारणार्थ दिल्ली में अनेक उद्योगों, विशेषतया ऐसे उद्योगों—जिनमें श्रम-बल की अधिकतम खपत हो, को बढ़ावा देना आवश्यक है। शिक्षित वर्ग में बढ़ती हुई बेकारी को रोकने के लिये अभी और बहुत सी टैकनीकल संस्थाओं को जन्म देना होगा।

३— इन सब उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिये एक संतुलित, संगठित तथा विशद कार्यक्रम का आयोजन वांछनीय है। इस दिशा में प्रयत्न पहले ही प्रारम्भ हो चुके हैं किन्तु अभी वे कदाचित् समस्याओं के अनुरूप नहीं हैं।

४— मुझे पूर्ण आशा है कि यह विशेषांक उपरिवर्णित तथा उनसे सम्बन्धित सभी समस्याओं पर यथेष्ट प्रकाश डालेगा और उनके सुलझाने के लिये ऐसे सुझाव भी देगा, जो सहजरूपेण कार्यान्वित हो सकें।

—भगवानसहाय
चीफ कमिश्नर दिल्ली

श्रम ही सम्पदा का स्रोत

मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि "सम्पदा" का "दिल्ली विकास अंक" प्रकाशित किया जा रहा है। दिल्ली आज केवल भारत की राजधानी ही नहीं, बल्कि संसार का एक महत्वपूर्ण केन्द्र भी बन गयी है। अब ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व के साथ-साथ उसका औद्योगिक महत्व भी बढ़ता जा रहा है।

प्राचीन काल में भारतीय कुटीर उद्योग उन्नति के शिखर पर थे और भारतीय शासक उनके विकास के लिये पूरी सहायता करते थे। भारत की स्वाधीनता के बाद अब केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें ऐसे उद्योग-धन्धों को काफी महत्व देने लगी हैं। "सम्पदा" यदि दिल्ली के उद्योग-धन्धों की उन्नति में लोकरुचि जागृत कर सके, तो सराहनीय होगा।

अर्थशास्त्री इस बात पर बल देते हैं कि श्रम ही वह स्रोत है, जिससे सब सम्पदा उत्पन्न होती है। मानव के अस्तित्व का मूलाधार श्रम है और यह कहना भी गलत न होगा कि मानव का निर्माण श्रम द्वारा ही होता है। मुझे पूर्ण आशा है कि "सम्पदा" श्रम के इस महत्वपूर्ण पहलू को भी ओझल नहीं करेगी।

मैं "सम्पदा" की सफलता की कामना करता हूँ।

—शामनाथ
अगस्त, १९६३

डिपुटी मिनिस्टर, सूचना व प्रसारण भारत सरकार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली पर महान् उत्तरदायित्व

दिल्ली बहुत प्राचीन नगर है। यहां इतिहास की बहुत सी घटनायें घटी हैं। सोलह वर्ष पूर्व दिल्ली में भारतीय स्वातन्त्र्य सूर्य का उदय हुआ था। उसके बाद हमारे देश में एक नया युग प्रारम्भ हुआ और वह है हमारे पुनर्निर्माण का युग। अब हमें अपने भविष्य-निर्माण का अवसर मिला है और यह हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है।

इन १५ वर्षों में राष्ट्रीय आय १० अरब से बढ़ कर १४ अरब रुपये हो गई है। उद्योगों के उत्पादन में भी अभूतपूर्व उन्नति हुई है। इस्पात का उत्पादन १० लाख टन से बढ़ कर ४० लाख टन हो गया है। चीनी, कपड़े और इन्जीनियरिंग के सामान निर्माण में भी आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। परन्तु हम इससे भी अधिक प्रगति कर सकते हैं, यद्यपि अपने अनुभवों को देखते हुए यह प्रगति भी प्रशंसनीय है।

नैतिक उन्नति

किन्तु इस आर्थिक विकास के साथ एक दूसरा भी पक्ष है और वह कुछ अन्धकारपूर्ण है। आर्थिक उन्नति का आदर्श अपने सामने रखते हुए हम यह भूल गये हैं कि जीवन में किन वस्तुओं या गुणों का आदर करना चाहिए। हमारा नैतिक आचरण गिर गया है। बाहरी आक्रमण को तो हम दूसरों की सहायता लेकर रोक भी सकते हैं, किन्तु हमारा नैतिक उद्धार किसी दूसरे की सहायता से नहीं हो सकता है।

अतीत का गौरव गान करते हुए हमें वर्तमान की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमारे देश की प्रतिष्ठा भौतिकवाद के कारण नहीं, आध्यात्मिक उन्नति और नैतिक अभ्युत्थान के कारण थी। हमारी अपनी संस्कृति भारत के गौरव और सम्मान का कारण थी। अब भी हमें यह सोचना है, कि हम दुनिया को क्या दे सकते हैं। विश्व की उन्नति में हमारा योगदान चरित्र और अपनी संस्कृति के प्रचार से हो सकता है। धर्म का अर्थ साम्प्रदायिकता नहीं, नैतिकता है।

दिल्ली के सिर पर

इस दृष्टि से दिल्ली वालों पर बहुत भारी उत्तरदायित्व है। दिल्ली के जीवन और दिल्ली की प्रवृत्तियों का प्रभाव समस्त देश पर पड़ता है। इसलिए, दिल्ली निवासियों की सेवा करके, उसकी विविध क्षेत्रों में उन्नति करके हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। यदि दिल्ली का उद्योग और व्यापारी वर्ग अपने लाभ में से कुछ प्रतिशत निकाल कर जनता की सेवा के लिए एक ट्रस्ट कायम कर दें, तो हम अपनी जनता से अधिक निकट सम्पर्क स्थापित करेंगे और उसकी वास्तविक सेवा कर सकते हैं। मैं दिल्ली का एक नम्र नागरिक हूँ। दिल्ली के नागरिकों का स्नेह मुझे प्राप्त है, इसलिए मुझे सम्पदा के दिल्ली-विकास-अंक के द्वारा दिल्ली के नागरिकों से यही निवेदन करना है, कि वे अपने चारित्रिक और नैतिक गुणों का विकास कर राष्ट्र के अभ्युत्थान में सहयोग देवें।

भरतराम

अध्यक्ष फैडरेशन आफ चैम्बर्स कामर्स एण्ड इंडस्ट्री

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली का विकास और महत्त्व

हजारों वर्ष पूर्व योजना बद्ध विकास : सब युगों की प्रतीक दिल्ली : दिल्ली-विकास सात खण्डों में

दिल्ली या इन्द्रप्रस्थ का महत्व आज से नहीं, प्राचीन महाभारत काल से है, जब पांडवों ने एक विस्तृत वन प्रदेश को साफ करके मय नामक एक महान इंजिनीयर की देख-रेख में राजधानी के रूप में इसे बसाया था। बहुत सम्भवतः भारतवर्ष के इतिहास में एक योजना-बद्ध विकसित नगर निर्माण का यह पहला उदाहरण था। यों इतिहास में अयोध्या, पाटलिपुत्र आदि अनेक सुन्दर नगरों का विस्तृत वर्णन मिलता है, तथापि किसी निर्जन वन खण्ड को साफ कर एक नये नगर के निर्माण का प्रथम उदाहरण दिल्ली ही है।

इसके बाद भले ही किसी-किसी समय दिल्ली का महत्व कुछ क्षीण हो गया हो, किन्तु भारत के इतिहास में उसका महत्व निरन्तर रहा है। और यही कारण है कि दिल्ली बार-बार उजड़ कर भी फिर बसती रही। और इसका प्रमाण दिल्ली के आस-पास फैले हुए वे प्राचीन ध्वंसावशेष हैं, जो आज भी दिल्ली में होने वाली महान क्रान्तियों का स्मरण कराते हैं। यदि पांडवों का पुराना किला महाभारत युग की स्मृति कराता है तो, अशोक की लाट, दिल्ली पर अशोक के शासन का परिचय देती है। कुतुब की लाट और लोहे की प्रसिद्ध लाट भी हिन्दु शासन की स्मृति कराती हैं। इसी लाट को बाद में कुतुबुद्दीन ने रूपान्तरित करके कुतुब की लाट का नाम दिया। इसके बाद दिल्ली पर अनेक मुस्लिम वंशों ने शासन किया और इनके समय में भी दिल्ली कई बार उजड़ी और कई बार बनी। अकबर के पिता हुमायूं का मकबरा हुमायूं की याद दिलाता है, तो उसके बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय के तो बीसियों स्मारक आज दिल्ली में मिलते हैं। इनकी निर्माण कला को देखकर उस समय के दिल्ली के आर्थिक वैभव का भी कुछ अनुमान लगाया जा सकता है।

१८५७ की प्रथम स्वातंत्र्य-क्रान्ति के असफल होने के बाद यद्यपि अंग्रेजों ने कलकत्ता को भारत की राजधानी के रूप में स्वीकार किया, तथापि दिल्ली के अतीत गौरव और असाधारण महत्व ने अंग्रेजों को भी दिल्ली को ही राजधानी बनाने पर विवश किया।

अंग्रेजों ने दिल्ली को राजधानी बना दिया, पर वे यमुना के किनारे बनी दिल्ली से सन्तुष्ट नहीं हो सके। उन्होंने एक विशाल और भव्य नई दिल्ली का निर्माण किया। इस तरह दिल्ली कई बार बनी और कई बार बिगड़ी और आज ऐतिहासिकों के अनुसार नवीं दिल्ली बन रही है।

इस नई दिल्ली में भी निरन्तर परिवर्तन हो रहा है, और ऐसा मालूम होता है, कि कायाकल्प ही हो गया है। उजड़ करके फिर नये सिरे से और नया भव्य रूप लेकर संसार में आना दिल्ली की अपनी विशेषता ही है। हमें विश्वास है कि उसकी यह विशेषता आने वाले हजारों वर्षों तक कायम रहेगी।

संक्षेप से हम दिल्ली के विकास को निम्नलिखित खण्डों में बांट सकते हैं :—

१. पाण्डव-युग में दिल्ली का निर्माण

२. राजपूत काल में दिल्ली का महत्व

३. मुसलमान वंशों का दिल्ली-विजय। इस काल में गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी और सूरी वंशों द्वारा सत्ता के लिए परस्पर संघर्ष के कारण दिल्ली का बार-बार बनना व उजड़ना

४. मुगल वंश की दृढ़ता और मुगल बादशाहों की कला-प्रियता के कारण दिल्ली का नव निर्माण।

५. १९११ में अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को भारत की राजधानी बनाना।

६. १९४७ में स्वतन्त्र भारत की राजधानी होने और पश्चिमी पंजाब से आने वाले लाखों शरणार्थियों के कारण दिल्ली के असाधारण महत्व और अकल्पित विस्तार में वृद्धि।

७. आज का मास्टर प्लान इसी विस्तार का ही एक चरण है।

• •

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली की अपनी विशेषताएं और समस्याएं

दिल्ली की अपनी कुछ विशेषताएं हैं और इसी कारण उसकी अपनी कुछ समस्याएं हैं।

यदि हम दिल्ली के क्षेत्रफल पर दृष्टि डाले तो हमें मालूम होगा कि इसका कुल क्षेत्र फल ५७८ वर्ग मील है। इसमें से भी ६६ वर्ग मील नगर ने घेरा हुआ है और ५०१ वर्ग मील में गांव फैले हुए हैं। अर्थात् नगर और गांवों के क्षेत्रफल का अनुपात १ और ६.५ है। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से देहातों में जन संख्या यदि ३ लाख के करीब है, तो नगर में यह जनसंख्या २३,५९,४०८, इसका अर्थ यह है कि यदि गांव और नगरों के क्षेत्र फल का अनुपात १ और ६॥ है तो आबादी का अनुपात बिल्कुल उलट कर ७॥ और १ का होगा।

जन-संख्या में तेजी से वृद्धि

दिल्ली में जनसंख्या की इस असाधारण वृद्धि के भी कुछ अपने कारण हैं।

(क) दिल्ली सदा से भारत का केन्द्र रही है और राजधानी होने के कारण इसका आकर्षण सदा बढ़ता रहा हैं। इसलिए कृषि-भूमि के उपलब्ध न होते हुए भी लोग अपनी सत्ता और आजीविका के लिए सदा दिल्ली की ओर खिंचते चले आये हैं।

(ख) देश के दुर्भाग्य-पूर्ण विभाजन के बाद तो पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए आकर्षण और आश्रय का प्रधान केन्द्र दिल्ली बन गया। यही कारण है कि १९५१ की जन संख्या से दिल्ली में करीब ९०% जनसंख्या बढ़ गई। इसके बाद भी १९६१ में की गई जनगणना से यह पता चलता है कि करीब १ लाख व्यक्ति प्रति वर्ष पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों से यहां आ जाते हैं। कहावत है कि जो एक वार दिल्ली में आ गया वह अपनी इच्छा से तो बाहर जाने का नाम नहीं लेता।

(ग) दिल्ली दीर्घ काल से भारत की राजधानी रही है। इसलिए केन्द्रीय प्रशासन में काम करने वाले छोटे-बड़े कर्मचारी व अधिकारी अपने अपने सम्बन्धी और परिचितों को कोई भी समय निकाल कर दिल्ली में बुला लेने की जोड़-तोड़ करते रहते हैं। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद सरकार ने बहुत से नये कार्य और उत्तरदायित्व अपने हाथ में लिये हैं। इसलिये प्रतिवर्ष सैकड़ों छोटे-बड़े नये उप-विभाग खुलते रहते हैं और उनमें ज्यादा लोगों को आजीविका मिल जाती है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में करीब तिगुनी हो गई है।

(घ) दिल्ली चिरकाल से भारत की राजधानी रही है। इसलिए समय-समय पर आने वाली सरकारों ने सड़क या रेल द्वारा दिल्ली का सम्बन्ध सभी भागों से स्थापित करने का प्रयत्न किया है। यही कारण है कि यातायात की इस सुविधा के कारण दिल्ली शहर उद्योग और कृषि का बड़ा केन्द्र न होते हुए भी वितरण का अच्छा केन्द्र बन गया है। कपड़ा हो, अनाज हो, फल हों, किराने और लोहे का सामान हो, दिल्ली एक प्रमुख वितरण केन्द्र रहा है और आज भी यह अपनी इस स्थिति को सुरक्षित किये हुए है। यही कारण है कि नगर के अन्तर्वर्ती भाग में अनगिनत कटरों का जाल फैला हुआ है, जिनमें लाखों रु. का प्रतिदिन व्यापार हो रहा है। इन्हीं कटरों में लाखों नागरिक वितरण पर ही अपनी आजीविका चलाते हैं।

विभिन्न पेशे

जब जनसंख्या लगातार बढ़ रही हो और कृषि के लिए भूमि बहुत उपलब्ध न हो तो यह बहुत स्वाभाविक है कि लोग आजीविका के दूसरे साधन ढूंढ़ें। दिल्ली की नवीनतम जनसंख्या से पता चलता है कि दिल्ली में अपेक्षाकृत किसान बहुत कम हैं। समस्त भारत में कृषि जीवियों का अनुपात ७५% से अधिक है पर दिल्ली में करीब १५% है। करीब ४०% यहां सरकारी नौकरी आदि पर गुजारा करते हैं और करीब डेढ़ लाख व्यक्ति व्यापार और व्यवसाय में। करीब-करीब पौने दो लाख व्यक्ति बड़े कारखानों में काम करते हैं।

उपर्युक्त परिस्थितियों और विशेषताओं के कारण दिल्ली की आर्थिक समस्यायें भी अन्य राज्यों की अपेक्षा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सर्वथा भिन्न है। संक्षेप में, इन समस्याओं को हम निम्न लिखित मुख्य भागों में बांट सकते हैं।

(१) दिल्ली में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आवास और गृह निर्माण की कठिन समस्या।

(२) दूर-दूर तक फैली हुई नई या पुरानी बस्तियों में आने-जाने के लिये समुचित यातायात की समस्या।

(३) दिल्ली के व्यापारिक वितरण केन्द्र का असाधारण स्थान सुरक्षित रहे, इसके लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करना जिससे दिल्ली के व्यापारी यथापूर्व देशके विभिन्न भागों से अपना व्यापारिक सम्बन्ध बनायें रखें।

(४) निरन्तर बढ़ती हुई आबादी के लिए पानी व बिजली की उचित गति-शील व्यवस्था करना।

(५) दिल्ली में कच्चे माल की कमी और स्थान के अभाव से भी बड़े उद्योग स्थापित नहीं हो सकते। इसलिये छोटे-छोटे उद्योगों को स्थापित करने की आवश्यक सुविधाएं देना। यह काम विभिन्न उद्योगपुरियां स्थापित करके किया जा सकता है, जिनमें बिजली-पानी, पुरजों का निर्माण, सड़क और यातायात आदि की सुन्दर व्यवस्थाहो।

दिल्ली की विभिन्न बस्तियों और गलियों में सैकड़ों कुटीर उद्योग चल रहे हैं। इनके लिए और उद्योग पुरियों में चलने वाले उद्योगों के लिये न केवल कच्चे माल और औजारों की जरूरत है, वरन उनका माल बेचने के लिये भी सरकार को प्रोत्साहन देने वाली व्यवस्था करनी चाहिए।

(६) दिल्ली की आर्थिक व्यवस्था को संतुलित रखने के लिए यह आवश्यक है कि समीपवर्ती राज्यों से जन समूह के दिल्ली में आने पर किसी प्रकार नियन्त्रण लगाया जाए अन्यथा दिल्ली की समस्यायें सुरसा के बदन की तरह निरन्तर बढ़ती जायेंगी। ● ○

गुलाब के फूल मुझे चुभते हैं!!

—गांधी जी

महात्मा गांधी सेगांव की अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। बा उनके पैर धो रही थीं और सारा पानी जमीन पर फैंकने की बजाय बाल्टी मे लेती जा रही थी।

पैर धो चुकने के बाद गांधीजी ने बा से कहा—यह पानी सामने की गुलाबों की क्यारी में डाल दो। बा ने वैसा ही किया।

इस समय श्रीमन्नारायण भी वहाँ मौजूद थे। गांधीजी ने एक बार गुलाब के फूलों की ओर देखा और फिर श्रीमन्नारायण जी से कहा कि ये गुलाब मुझे काँटे की तरह चुभते हैं। श्री श्रीमन्नारायण इस का आशय नहीं समझ सकें। बोले—ये फूल तो बड़े प्यारे और सुन्दर हैं। ये आपको कैसे चुभते हैं?

गांधीजी ने उन्हें जो उत्तर दिया, उसकी उन्होंने कल्पना भी न की थी। लेकिन वह उत्तर उन्हें जीवन भर स्मरण रहेगा। इस उत्तर ने उन्हें गांधीजी की नई दृष्टि का ज्ञान दिया।

गांधीजी ने कहा कि आज देश में गम्भीर अन्न संकट है और हम अपनी आँखों की तृप्ति के लिए, सौंदर्य का रस लेने के लिए अनाज का जगह गुलाब बोते हैं। यदि इस क्यारो में अनाज बोया जाता, तो एक आध व्यक्ति का एक आध समय तो उदर पूर्ण हो जाता, इसलिए उसकी जगह बोये गये गुलाब के ये पौधे मुझे कांटों की तरह से चुभते हैं।

कितना मार्मिक था वह उत्तर! आज भी यह उत्तर सनातन सत्य की भांति दिल्ली के मध्यवर्गीय और सम्पन्न नागरिकों तथा अधिकारियों का मार्ग दर्शन कर सकता है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चिरयौवना दिल्ली का नव-निर्माण

—श्री लेखराम

दिल्ली की मूलभूत आवश्यकताएं और समस्याएं क्या हैं, उनकी पूर्ति के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं, उन प्रयत्नों में कितनी सफलता प्राप्त हो रही है, असफलताओं के कारण क्या हैं आदि प्रश्नों का ज्ञानवर्धक तथा विवेचनात्मक संक्षिप्त विवरण एक अनुभवी वयस्क पत्रकार के इस लेख में पाठक पढ़ेंगे ।

नव-निर्माण की दिशा में अग्रसर दिल्ली की प्रमुख समस्याओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है । (१) मूलभूत आवश्यकताओं से सम्बन्धित समस्याएं, (२) नगर के सौन्दर्य और सुषमा से सम्बन्धित समस्याएं, (३) आबादी सम्बन्धी समस्या ।

मूलभूत आवश्यकताओं से सम्बन्धित समस्याओं में से प्रमुख, नागरिकों के आवास, परिवहन, यातायात-मार्गों, पीने तथा अन्य प्रकार से उपयोग में आने वाले स्वच्छ और सामान्य जल तथा घरों को प्रकाशित तथा छोटे और बड़े उद्योगों को संचाजित करने वाली विद्युत-शक्ति संबंधी समस्याएं हैं ।

नगर के सौन्दर्य तथा सुषमा से सम्बन्धित समस्याओं में नगर में उद्यानों और खेल के मैदानों का विकास, स्वस्थ वातावरण का निर्माण तथा नगर के सौन्दर्य को विकसित करने की समस्याएं सम्मिलित हैं ।

दिल्ली की आबादी पिछले १५ साल में १० लाख से बढ़कर २६ लाख से ऊपर हो गई है । ऐसी दशा में आबादी सम्बन्धी समस्या भी प्रमुख समस्या के रूप में आज समुपस्थित है तथा नगर के पुनर्निर्माण की दृष्टि से इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति आवश्यक है ।

प्रशासकीय प्रयत्न

स्पष्ट रूप से इन प्रस्तुत समस्याओं के समाधान की दृष्टि से अनेक सराहनीय प्रयास प्रशासन की ओर से किये गये हैं, तथा अनेक नई योजनाएँ भी इस समय प्रस्तुत हैं, फिर भी, यह बात निस्संकोच कही जा सकती है कि अभी तक इनमें से किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं खोजा जा सका है । प्रशासन के भागीरथ प्रयत्नों और बारम्बार दिये गये आश्वासनों के बाद भी ये समस्याएं किसी न किसी रूप में आज भी विद्यमान हैं ।

इन प्रशासकीय प्रयत्नों की विफलता के वास्तविक कारण क्या हैं, इसकी चर्चा करने से पूर्व इस दिशा में किये गए प्रयत्नों का संक्षिप्त सिंहावलोकन प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे कि वस्तु स्थिति को समझने में आसानी और सुविधा प्राप्त हो सके । सरकारी प्रकाशनों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अब तक विभिन्न समस्याओं को हल करने की दृष्टि से निम्न प्रगति की गई है :—

बिजली

२० हजार किलोवाट अतिरिक्त बिजली प्राप्त करने की दृष्टि से, १९४८ में २ करोड़ ३० लाख रु० खर्च कर एक योजना शुरु की गई । यह योजना १९५२ में पूरी हो गई । प्रथम पंचवर्षीय योजना में ४ हजार ८०० किलोवाट अतिरिक्त विद्युत् का उत्पादन भी किया गया । १९५१ में १० हजार किलोवाट विद्युत् नंगल से प्राप्त हुई । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में १० हजार किलोवाट अतिरिक्त बिजली नंगल से मिली । इस प्रकार अब दिल्ली नगर को ७७,००० किलोवाट बिजली उपलब्ध है । स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व, जबकि दिल्ली को केवल १२ हजार किलोवाट विद्युत् उपलब्ध थी, वहां अब उसमें ४५ हजार किलोवाट की वृद्धि हो गई है ।

वृद्धि का यह क्रम आबादी और नगर की आवश्यकताओं की वृद्धि के क्रम की तुलना में उससे कहीं धीमा है ।

जल

पानी की प्राप्ति में सम्बन्ध में प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया है कि नगर की जल सम्बन्धी मांग की पूर्ति की दृष्टि से चन्द्रावल में एक नया वाटरवर्क्स खोला गया है, जिससे प्रतिदिन १ करोड़ ५० लाख गैलन पानी प्राप्त हो सकेगा । पुनर्वास मन्त्रालय ने जामिया मिलिया के निकटवर्ती वाटरवर्क्स का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भव्य भवनों की सुषमामयी नगरी दिल्ली

दिल्ली के दो रूप हैं—अभ्रंकश शानदार भव्य भवनों से चमचमाती हुई नई दिल्ली और गरीबों की नागरिक सुविधाओं से विहीन कराहती हुई झुग्गी झोपड़ियां-पहले रूप के दर्शन यहां कीजिये।

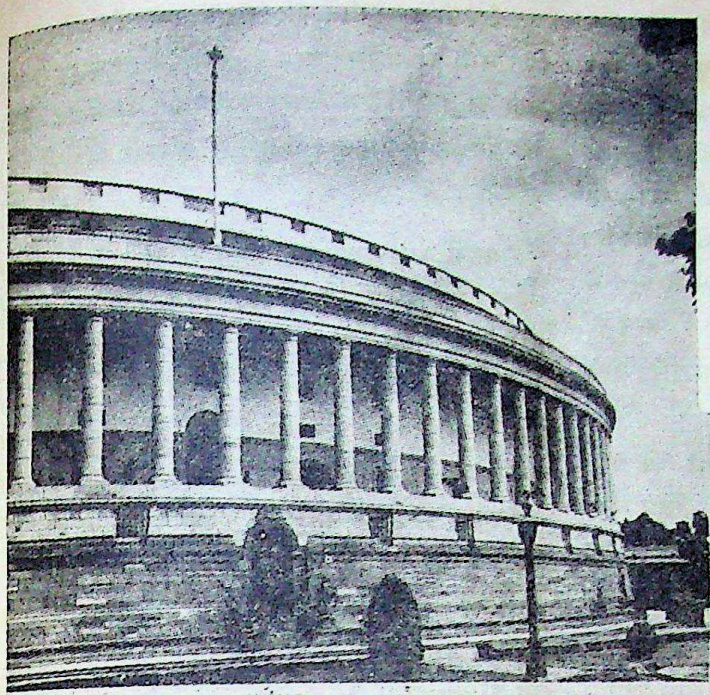

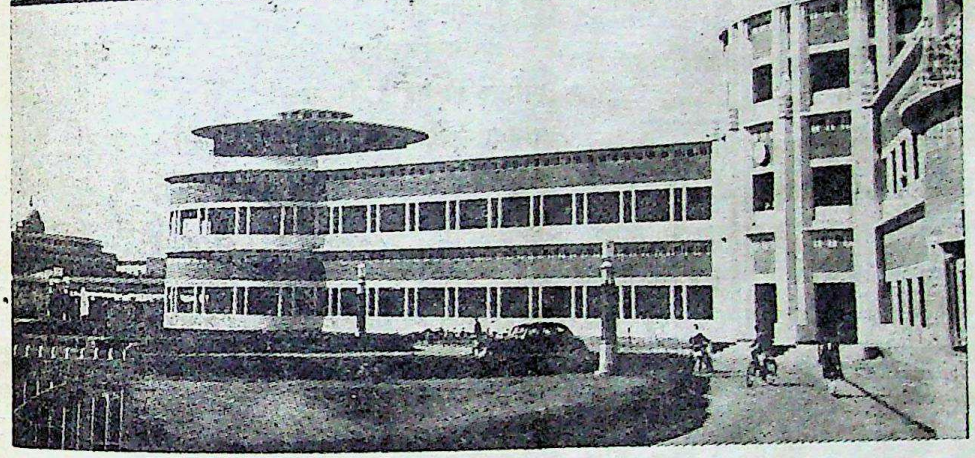

आकाशवाणी भवन संसद् भवन और अशोक होटल (नीचे)

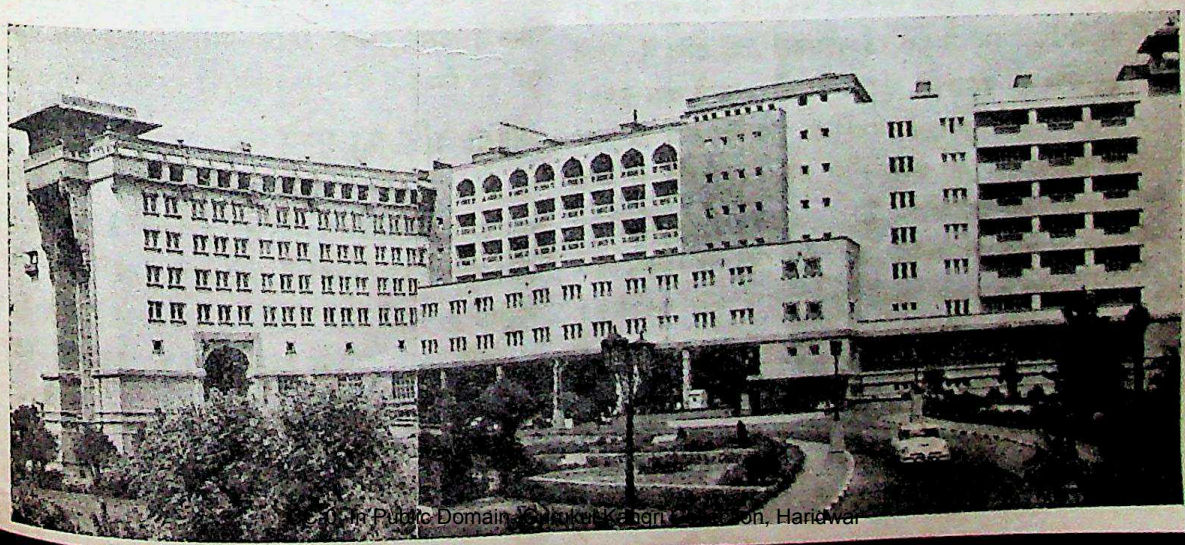

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है तथा इससे अब २० लाख गैलन के स्थान पर ६० लाख गैलन पानी प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट प्रशासन की ओर से प्रकाशित की गई है, यद्यपि उसमें इस समस्या की कोई चर्चा नहीं है, तथापि तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा प्रस्तुत करते हुए यह बात कही गई है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में दो महत्वपूर्ण क़दम इस सम्बन्ध में उठाये गये हैं। इनमें से एक तो वजीरबाद में बांध का निर्माण तथा दूसरे चन्द्रावल वाटरवर्क्स से प्राप्त होने वाले जल की अभिवृद्धि।

दिल्ली के नागरिक जिस भीषण जल कष्ट को अनुभव करते हैं, विशेषकर ग्रीष्म ऋतु में उन्हें जिस संकट का मुकाबला करना पड़ता है, उक्त शब्दों को देखते हुए प्रतीत ऐसा होता है कि सम्बन्धित अधिकारियों ने उसे अनुभव नहीं किया।

परिवहन साधन और सड़कें

अप्रैल १९५० में, जबकि दिल्ली ट्रान्सपोर्ट अथारिटी ने परिवहन का काम संभाला, तो उसके पास केवल २६४ बसें थीं। १२ साल बाद आज, दिल्ली परिवहन के पास ७८६ बसें हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समाप्ति तक ९०० बसें हो जाने का आश्वासन दिलाया गया था, तीसरी पांचसाला योजना में १०० बसों की और वृद्धि करने की बात सोची गई। दिल्ली में परिवहन साधनों के विकास का यह संक्षिप्त इतिहास है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा प्रस्तुत करते हुए बताया गया है कि नगर में लगभग १,२०० मील लम्बी सड़कें हैं। इसके साथ ही यह बात भी स्वीकार की गई है कि "तेजी से बढ़ रहे यातायात को दृष्टि में रखते हुए नगर की बहुत सी सड़कों को चौड़ा करने तथा सड़कों और नालों पर नये पुल बनाने की आवश्यकता है।" द्वितीय योजना के सम्बन्ध में प्रकाशित रिपोर्ट से पता चलता है कि इस अवधि में ३८ लाख रु० की निश्चित रकम में से आधी से भी कम खर्च की गई। कुल खर्च १६ लाख ५ हजार रुपये हुआ है। इस प्रकार २१ लाख ९५ हजार की राशि बिना खर्च हुए बच रही।

दिल्ली के नागरिक परिवहन साधनों और सड़कों की जिस कमी को अनुभव करते हैं, उसे देखते हुए इतनी बड़ी रकम का बचा लिया जाना, इस बात का द्योतक है कि उक्त समस्या के समाधान में पूरी दिलचस्पी नहीं ली गई।

आवास

प्रमुख समस्याओं में निवासियों की आवास सम्बन्धी समस्या भी सम्मिलित है। इस सम्बन्ध में प्रशासन की ओर से जो प्रयत्न किये गये हैं, उनका ब्यौरा इस प्रकार है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में गृह-निर्माण कार्य के लिए क़र्ज देने की दृष्टि से २ करोड़ रु० की रकम पृथक् रखी गई थी। १९५६ तक इसमें से ७४ लाख रु० के क़र्ज दिये गये तथा इसके अतिरिक्त २० लाख रु० भूमि की प्राप्ति पर खर्च आये। दूसरी पंचवर्षीय योजना में १ करोड़ ११ लाख रुपये अल्प-आय, ७५ लाख रु० मध्य आय तथा २ लाख रुपये देहाती जनता को गृह-निर्माण के लिए क़र्ज देने की योजना थी।

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा में यह बात स्वीकार की गई है, कि गृह-निर्माण सम्बन्धी क़र्ज देने की योजना यद्यपि सफल रही है, तथापि आबादी में जिस अनुपात से वृद्धि हो रही है उसकी तुलना में गृह-निर्माण की वर्तमान गति संतोषजनक नहीं समझी जा सकती। फलस्वरूप, तृतीय योजना में १९ करोड़ ५ लाख की रकम इस कार्य के लिए रखी गई है, जिसमें से ११ करोड़ २५ लाख रु० दिल्ली प्रशासन को, ७ करोड़ ८० लाख रु० दिल्ली निगम को तथा १ करोड़ २५ लाख रुपये नई दिल्ली नगर पालिका को मिलेंगे।

आवास की समस्या आज भी जिस उग्र रूप में विद्यमान है, उससे प्रत्येक व्यक्ति परिचित है। स्वयं प्रशासन भी इस दिशा में की गई प्रगति की रफ्तार से संतुष्ट नहीं।

सुषमा वृद्धि का प्रश्न

नगर के सौन्दर्य की अभिवृद्धि के प्रश्न पर भी प्रशासन द्वारा ध्यान दिया गया है। उदाहरण के रूप में, नगर और उसकी उपयस्तियों में छोटे-छोटे उद्यानों और खेल के मैदानों के रूप में हरी पट्टियां (ग्रीन बेल्ट्स) छोड़ दी गई हैं। रोशनआरा बाग में जापानी ढंग का उद्यान विकसित

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

करने की योजना है तथा इस सम्बन्ध में कार्य चालू है। कुछ अन्य उद्यानों को विकसित करने के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की योजनायें तैयार की गई हैं। नगर में कृत्रिम झीलें और तालाब तैयार करने के बारे में भी कुछ योजनाएं तैयार की गई हैं। यमुना नदी पर सात-आठ मील लम्बी और १॥ या दो मील चौड़ी एक झील तैयार करने की भी एक समय चर्चा चली थी। इस योजना का क्या हुआ, यह बात प्रशासन की रिपोर्टों से स्पष्ट नहीं होती। शायद खर्चीली होने से इसे स्थगित कर दिया गया है। दिल्ली नगर को प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में जिस जल कष्ट का सामना करना पड़ता है, यद्यपि उसे ध्यान में रखने पर यह योजना अधिक खर्चीली नहीं थी। इस झील के निर्माण से पर्याप्त जल संचित किया जा सकता तथा उससे नगर के साल भर के जल खर्च की पूर्ति की जा सकती है।

नगर की शोभा में अभिवृद्धि करने वाले अन्य भी अनेक प्रयत्न प्रशासन की ओर से किए गए हैं। उदाहरण के रूप में भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए १ मार्च १९६१ को बम्बई अधिनियम लागू किया गया। गैर-सरकारी प्रयत्नों के फलस्वरूप पटरियों पर सोने वाले व्यक्तियों के लिए रैन-बसेरों की व्यवस्था की गई। अपाहिजों और छूतहा रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आश्रय-स्थल भी सरकारी प्रयत्न से संचालित हैं। समाज-कल्याण की अनेक प्रकार की योजनायें प्रशासन की ओर से चालू हैं।

लेकिन इन व प्रयत्नों से क्या नगर का एक भी भाग ऐसा बन हो सका है, जो सचमुच ही दर्शनीय हो, जिसे संसार की अन्य राजधानियों की तुलना में सगर्व प्रस्तुत किया जा सके ? यह अभीष्ट होने पर सुलभ भूमि के एक-एक इंच के टुकड़े के सम्बन्ध में सोच-समझकर योजना बनानी होगी। हर घास के टुकड़े की सावधानी से देखभाल, सड़कों को सुन्दर फूलदार वृक्षों से सजाने, आने और जाने वाली सड़कों के बीच की पटरियों को रंग-बिरंगे पौधों से सुसज्जित करने, ऐतिहासिक स्थलों की पुरानी दीवारों को सुन्दर बेलों से आच्छादित करने तथा इनके आस-पास के स्थानों की सफाई करके उन्हें वृक्षों, पौधों और हरी-भरी घास से सुशोभित करने की आवश्यकता है।

समाज-कल्याण योजनाओं के सम्बन्ध में अधिक सतर्कता और इन पर व्यापक रूप में अमल करने की आवश्यकता है। भिक्षा-वृत्ति कानून जब लागू हुआ, तब भिक्षा-वृत्ति के अभिशाप से कुछ समय के लिए नगर को बहुत कुछ छुटकारा प्राप्त हो गया। किन्तु बाद की उपेक्षा-वृत्ति ने समस्या को जड़-मूल से उखाड़ देने के स्थान पर फिर नगर में इस समस्या को उत्पन्न कर दिया। यही स्थिति रैन-बसेरों की भी है। इसकी व्यापक और अनिवार्य व्यावस्था से नगर के उद्यान और पटरियां जिस गन्दगी का भार ढोते हैं, उसमें पर्याप्त कमी हो सकेगी। बेघरबार लोगों के लिए स्नानगृहों और शौचालयों की आधुनिक व्यवस्था भी गन्दगी को कम करने का कारण सिद्ध हो सकती है। थूकने और गन्दगी बिखेरने पर भी यदि प्रतिबन्ध लागू करके उस पर दृढ़ता से अमल किया जाये, तो इससे भी नगर की सुन्दरता की वृद्धि में सहायता मिल सकती है। नगर में अवारा घूमने वाले पालतू पशुओं के

(शेष पृष्ठ १०२ पर)

बंसीलाल एण्ड को०

एस्पलैंड रोड, दिल्ली-६

बाइसिकल का सारा सामान सस्ते और रियायती दामों पर हर समय यहां से मिल सकता है।

पूरे ब्यौरे के लिए :

बंसीलाल एण्ड को०

एस्पलैन रोड, दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सारे परिवार के लिए

डी सी एम

के उच्च कोटि के कपड़े

पापलिन •	छींटें •	मलमल
लिनो •	लान्स •	लट्ठा
साड़ियाँ •	शर्टिंग्ज •	ड्रिल्स
शर्टिंग्ज •	सजावट के कपड़े •	तौलिए

एवं बेड शीट्स आदि

आकर्षक रंगों, शेडों और बनावटों में

डी सी एम के सभी रिटेल स्टोर्स में प्राप्य है ।

डी सी एम वस्त्रोत्पादन में श्रेष्ठता का प्रतीक

दि दिल्ली क्लॉथ एण्ड जनरल मिल्स कं० लि०

दिल्ली

JWT : DCM : 2290

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

केन्द्रीय सरकार के गृहमंत्री अतः
दिल्ली के सर्वोच्च प्रशासक

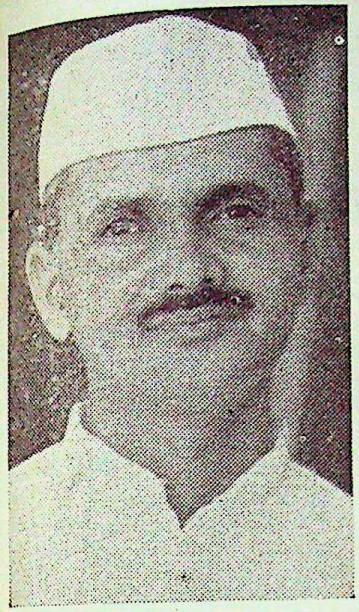

श्री लालबहादुर शास्त्री

दिल्ली के कुशल प्रशासक
चीफ़ कमिश्नर

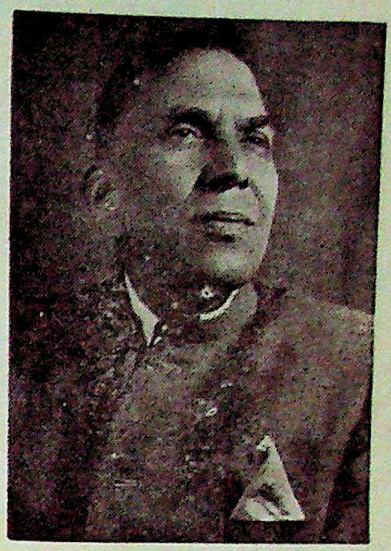

श्री भगवान सहाय

दिल्ली के प्रमुख प्रशासक

दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी

श्री कृष्णकिशोर

जन-सम्पर्क समिति के अध्यक्ष

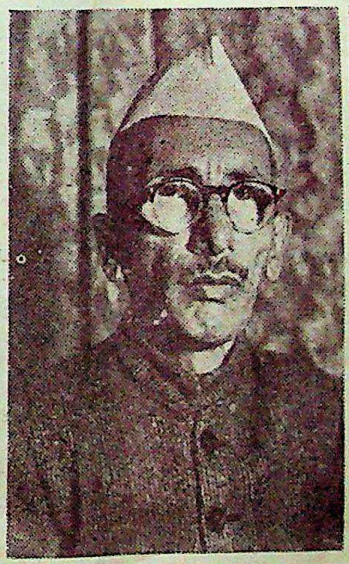

श्री गोपीनाथ अमन

उद्योग परामर्श समिति के अध्यक्ष

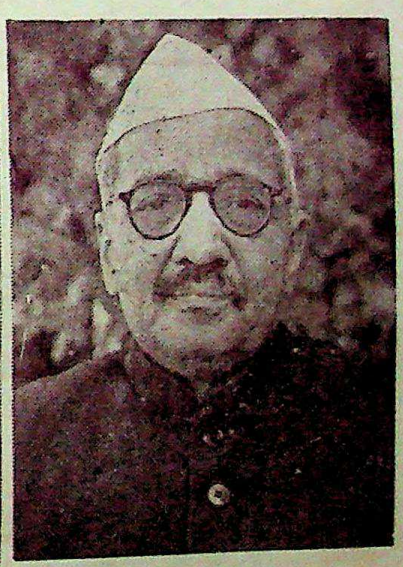

डा० युद्धवीर सिंह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली के औद्योगिक अभ्युत्थान के नेता व प्रवर्तक

स्वर्गीय लाला श्रीराम

योग्य पिता

दिल्ली के प्रमुख उद्योगपति

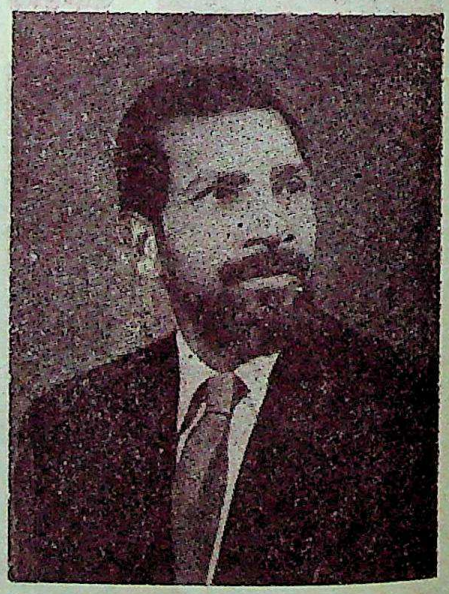

योग्य पुत्र

लाला भरतराम

अध्यक्ष अखिल भारतीय फैडरेशन ई. का.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गुरुकुल कांगड़ी

सजीसजीली दिल्ली के दो शानदार उपनगर

रामकृष्णपुरम् का एक दृश्य

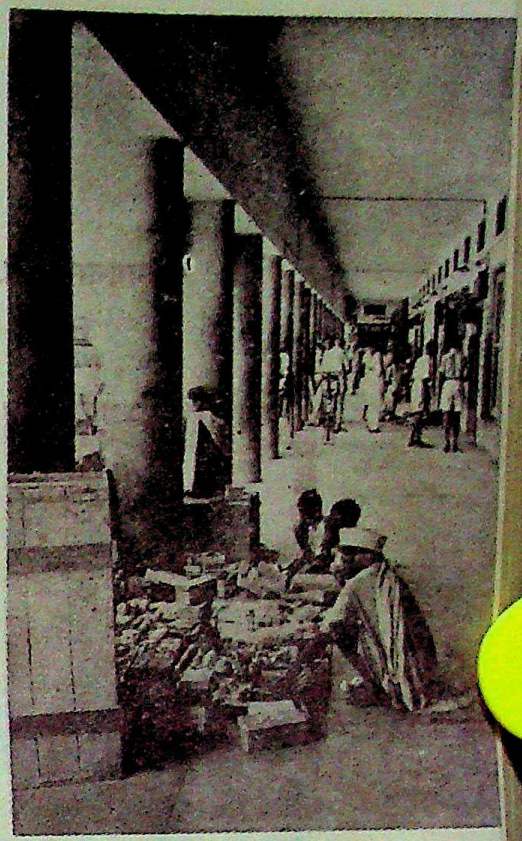

लोदी कालोनी का एक बाजार

दिल्ली के देहातों में

देहात के प्रसन्न किसान

देहात में बुनाई-कढ़ाई सीखती हुई बहनें

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समय-समय पर आनेवाली बाढ़ों के कारण
दिल्ली का एक करुण दृश्य

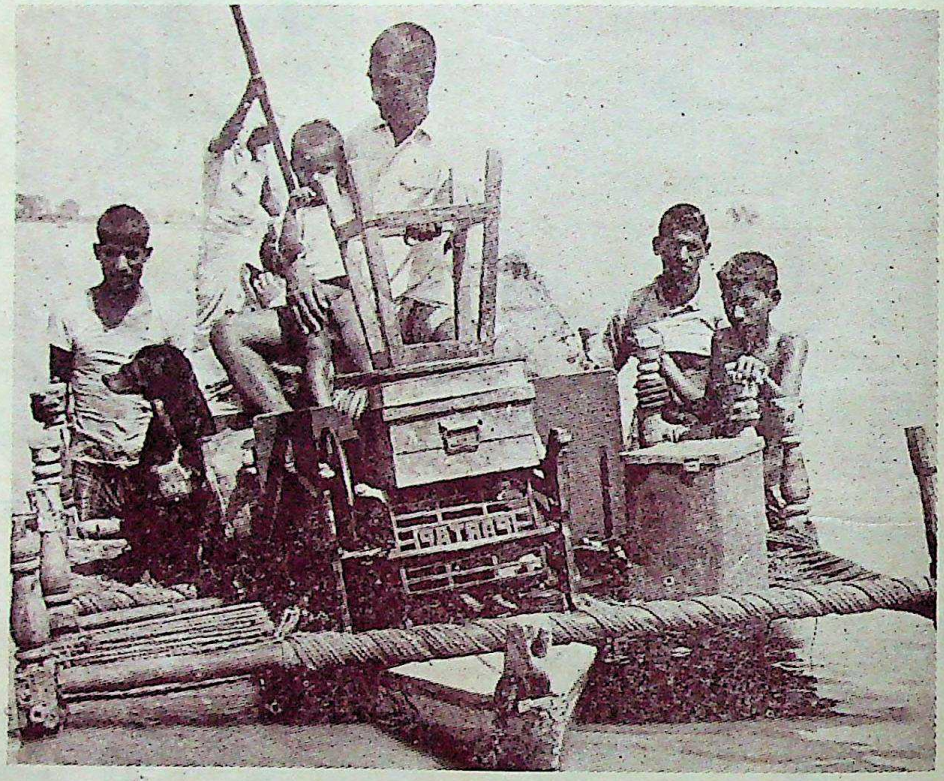

दिल्ली के नये मास्टर प्लैन का एक उद्देश्य दिल्ली में आनेवाले जल-प्रलय और उसके कारण दीखने वाले उपर्युक्त दृश्यों को भी भविष्य में रोकना है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देहली का उद्योगीकरण : भविष्य और समस्याएं

श्री भगवान सहाय, चीफ कमिश्नर, दिल्ली

दिल्ली का औद्योगिक फैलाव अनिवार्य है, क्योंकि देश की राजधानी होने के साथ-साथ उत्तर भारत का यह सर्वाधिक प्रमुख नगर है। १९८० तक दिल्ली की आबादी ५५ लाख हो जाएगी और इसमें से कमसे कम २० लाख के लिए रोजगार का प्रबन्ध उद्योगों में ही करना होगा, जबकि इस समय दो लाख से भी कम ही श्रमिक हैं।

इस विसंवादी स्थिति में मास्टर प्लान द्वारा दिल्ली का भावी स्वरूप क्या होगा, इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रदेश के चीफ़कमिश्नर महोदय का लेख बहुत प्रेरणादायक और नवदिशा सूचक है।

जब हम दिल्ली के उद्योगीकरण की चर्चा करते हैं, तब यह प्रश्न उठना एक दम स्वाभाविक है कि क्या देश की राजधानी में उद्योगों की स्थापना को उत्साहित करना चाहिए ? तर्क यह दिया जाता है कि उद्योगों को उत्साहित करने से दिल्ली की आबादी बढ़ेगी, जिससे राजधानी की पहले से ही घनी आबादी में अधिक घनता आ जाएगी। एक यह भी तर्क है कि किसी नगर को नितान्त औद्योगिक स्वरूप देने में कई ऐसी प्रशासनिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जिनका देश की राजधानी में उत्पन्न होना वांछनीय नहीं होता है। इन तर्कों पर विचार करते हुए हमें सोचना होगा कि क्या दिल्ली में औद्योगिक वित्त-व्यवस्था को उत्साहित करना उचित है ?

दिल्ली की आबादी बढ़ेगी

किसी क्षेत्र की आबादी बढ़ने के दो कारण होते हैं (१) मृत्यु से अधिक जन्म होना, (२) बाहर से लोगों का आना (आव्रजन)। नगरों में दूसरे कारण की विशेष प्रधानता होती है। देहाती क्षेत्रों में यह समस्या नहीं होती। दिल्ली में आव्रजन के स्वरूप की जांच करने से पता चलता है कि पिछले दो दशकों से यह विशेषरूप से बढ़ा है और तानाशाही उपायों को अपनाये बिना यह आव्रजन बन्द नहीं हो सकता। इसका कारण स्पष्ट है। खेती की जमीन पर बढ़ रहा बोझ जनता को इस बात के लिए बाध्य करता है कि वे अन्यत्र जाकर रोजगार तलाश करें। एक बड़ा नगर इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए बड़ा आकर्षण है। १९५५ में दिल्ली में प्रति-व्यक्ति आय लगभग ७०० रु. थी, जबकि इसकी तुलना में अखिल भारतीय आय २६० रु. के लगभग थी। देहाती क्षेत्र पर दिल्ली जैसे नगर का प्रभाव अपरिहार्य है। इसलिए यह तो मानना ही पड़ेगा कि आगामी वर्षों में दिल्ली की आबादी अवश्य बढ़ेगी। विविध प्रकार के आंकड़े इकट्ठा करने की विधियों से यह अनुमान लगाया गया है कि १९८१ में दिल्ली की आबादी ५५ लाख के आसपास तक पहुंच जाएगी। हम चाहें उद्योगों को प्रोत्साहन दें या न दें, सत्य यह है कि दिल्ली की आबादी बढ़ेगी। इसलिए हमारी योजना रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की ओर होनी चाहिए।

कई देशों के राष्ट्रीय विकास के अध्ययन से पता लगता है कि आर्थिक विकास की तुलनात्मक प्रारम्भिक अवस्था में २५ से ३० प्रतिशत तक श्रमिक वर्ग निर्माण कार्यों में लगता है। उद्योगों का नागरिक क्षेत्रों में केन्द्रित होना स्वाभाविक ही है क्योंकि वहां पर ही यातायात, बिजली, कुशल श्रमिक और तैयार माल के लिए हाट-बाजार की सुविधाएं मिल सकती हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तर भारत में दिल्ली एक बड़ा प्रभावशाली नगर है और इस सारे क्षेत्र के थोक बाजार पर नियंत्रण करता है। इसलिए साहसी उद्योगपतियों का दिल्ली की ओर आकृष्ट होना स्वभाविक ही है।

अब यह मानना तो स्वाभाविक ही है कि दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की अर्थ व्यवस्था में उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। पश्चिमी देशों में जितनी राजधानियां हैं, वे उत्कृष्ट औद्योगिक क्षेत्र हैं। भारत में १० सबसे बड़े नगरों की औसतन ३० प्रतिशत से भी अधिक श्रमिकों की जीविका उद्योगों पर निर्भर है। दिल्ली में यह संख्या १८ प्रतिशत के लगभग है।

उद्योगों का स्वरूप और विस्तार

उद्योग दिल्ली की तीन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं—(१) राष्ट्रीय विकास में दिल्ली का सहयोग केवल एक ही दिशा तक सीमित व अवरुद्ध न रहेगा और उत्पादक कार्यों से प्राप्त पूंजी का नये पूंजी-वर्धक क्षेत्रों में प्रयोग होगा। (२) निर्माणात्मक कार्यों के बढ़ने से रोजगार के अवसर बढ़ते रहेंगे। सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि इन प्रवृत्तियों में लगी पूंजी में सरकारी राशि का अंश बहुत कम है, निजी पूंजी ही अधिक है। इससे सरकार को भी लाभ होता है। (३) यह निर्माण कार्य अपने कर्मचारियों को आय के उस स्तर पर प्रतिष्ठित कर देते हैं, जो अति-निम्न और अति-उच्च—दोनों के बीच मिलीजुली श्रेणी का होता है और सामाजिक तनाव को दूर करने में यह वर्ग बड़ा सहायक होता है।

१९५१ की जन-गणना से पता चलता है कि करीब १.२ लाख व्यक्ति ही उद्योगों में लगे हुए थे। इसके साथ उन बहु संख्यक व्यक्तियों को भी जोड़ लेना चाहिए, जो अप्रत्यक्ष रूप से उद्योगों से सम्बद्ध होते हैं। आज स्थिति यह है कि विभिन्न प्रकार के छोटे-बड़े उद्योगों में लगभग दो लाख व्यक्ति नियुक्त हैं। संगठित उद्योगों में—अर्थात् फैक्टरी एक्ट के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों में—श्रमिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। १९५१ से १९५७ में इनकी संख्या ४२,६०० से बढ़कर ४५,७०० हो गयी। लगभग ३५,००० श्रमिक संगठित उद्योगों में हैं। संगठित क्षेत्र में सबसे अधिक श्रमिक दिल्ली की चार कपड़ा मिलों में हैं जो बहुत वर्षों से यहां स्थापित हैं। दिल्ली में भारी उद्योग स्थापित नहीं हो सकते, क्योंकि इनका कच्चे माल के समीप होना जरूरी होता है। दिल्ली में ऐसे उद्योग अधिक स्थापित हो रहे हैं जो देश में किसी भी स्थान पर कायम हो सकते हैं। ओखला और नजफगढ़ के अतिरिक्त दिल्ली में कोई सुस्पष्ट निर्धारित औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। शाहदरा, आनन्दपर्वत, सराय रोहल्ला, रोहतक रोड, सदर बाजार और सब्जीमंडी में ग्रांड-ट्रंक रोड के आसपास उद्योगों की अधिकता है।

दिल्ली का श्रम वर्ग

१९४७ के बाद दिल्ली का द्रुत उद्योगीकरण हुआ, जब विभाजन के बाद शरणार्थी यहां बड़ी संख्या में आये। पंजाब से आये लोग उद्योग-मानस के थे। आबादी के एकदम बढ़ जाने से उपभोक्ता सामान बड़ा लाभ दायक उद्योग बन गया। १९४७ में पंजीकृत कारखानों की संख्या २०० थी। १९५९ में वह १००० तक हो गयी और इस समय इनकी संख्या १,२०० के आस पास है।

इस अवधि में संगठित औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की ५० प्रतिशत वृद्धि हुई। अगर कपड़ा मिलों को अलग छोड़ दिया जाए तो रोजगार में १०० प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई। दिल्ली के कारखानों में १२ से १२ प्रतिशत श्रमिक उन उद्योगों में हैं, जो स्थानीय बाजार के लिए सामान बनाते हैं। कुल श्रम वर्ग में ४ से ६ प्रतिशत ऐसे हैं जो दिल्ली से बाहर के बाजार के लिए उत्पादन करते हैं। रेडियो निर्माण, बिजली के बल्ब, सिलाई की मशीन, लाऊड स्पीकर, बिजली के उपकरण, प्लास्टिक और बाइसिकल—ये कुछ उद्योग ऐसे हैं, जिनमें दिल्ली ने सारे भारत में सर्व प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया है।

दिल्ली के विभिन्न उद्योगों में श्रम-वर्ग का प्रतिशत वितरण किस प्रकार है, यह निम्न तालिका से पता चलता है :—

	१९२१	१९३१	१९४१	१९५१
खेती	२२.३०	२५.३१	१६.१३	१०.१९
उद्योग	२२.१२	२०.७१	२३.७६	१८.३९
इमारती काम	४.९३	६.२९	८.९३	९.७०
परिवहन और संचार	५.३७	७.१३	५.१७	५.६०
वाणिज्य और वित्त	१६.६९	१२.८२	१४.७१	१९.९१
धंधे और उदार कलाएं	३.३४	२.९४	४.६३	५.१५

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सार्वजनिक सेवा	५.५२	५.७०	८.८१	१६.८७
सार्वजनिक उपयोगिता	३.८०	३.६५	२.४५	१.३४
अन्य सेवाएं	१५.६३	१५.१५	१५.४०	१२.६६

इस तालिका से स्पष्ट है कि दिल्ली की समृद्धि में उद्योग का विशेष योगदान है। मास्टर प्लान में लगाया गया यह अनुमान कि १९८१ में उद्योग में लगी श्रमशक्ति २५ प्रतिशत तक हो जाएगी, कुछ कम ही है, अधिक नहीं। हमारी योजना ऐसी होनी चाहिए जिससे उद्योगों में ही ५.१५ लाख को रोजगार मिल सके। आम तौर पर, श्रम-वर्ग कुल आबादी का ३६-४० प्रतिशत है। १९८१ में दिल्ली में इस वर्ग में आने वाली संख्या २। लाख हो जाएगी। यह बड़ा भारी काम है, क्योंकि इस समय सब प्रकार के उद्योगों में कुल दो लाख के करीब व्यक्ति लगे हुए हैं।

उद्योग नगर से बाहर हों

उद्योग की बुनियादी आवश्यकताएं हैं, स्थान, बिजली और प्रशिक्षित कर्मी। औद्योगिक क्षेत्र से जनता के लिए कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं, अपने कार्य स्थान को व वहां से बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना, बड़ी मात्रा में भारी सामान का यातायात और कई कारखानों का कर्ण-कटु शोर, शराब, धुंआ, दुर्गन्ध इत्यादि। इन कारणों से उद्योग क्षेत्र, आबादी-क्षेत्र से काफी दूर ही होना चाहिए। इसलिए यह निश्चय किया गया है कि भूमि के वृहत्-खंडों "औद्योगिक क्षेत्र" के रूप में पृथक् निर्धारित कर दिया जाए, ताकि औद्योगिक कार्य उसी में सीमित रहें। इस बात का ध्यान रखा गया है कि प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र सड़क और रेल द्वारा सम्बद्ध हो। श्रमिकों के आने जाने की सुविधा के लिए, इस प्रकार के औद्योगिक जिले दिल्ली के सब ओर निर्धारित किये गये हैं। फिलहाल, ५ हजार एकड़ जमीन औद्योगिक विकास के लिए निश्चित की गयी हैं, जो नजफगढ़, ओखला, आजादपुर, रोहतक रोड और शाहदरा में स्थित हैं। आवश्यकता होने पर इन क्षेत्रों के विस्तार की भी गुंजायश है।

औद्योगिक विकास की रूपरेखा

इन क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में ओखला में अपनाई गई प्रणाली सर्वाधिक उत्तम समझी गयी है। जहां ४ वर्ष में ही रोजगार के आंकड़े २५० से १८,०० तक पहुँच गये हैं। विकास का यह कार्य दिल्ली विकास प्राधिकारी (डेवलेपमेंट एथारिटी) और दिल्ली प्रशासन को सौंपा गया है और उन्हें इस के लिए विस्तृत अधिकार दे दिये गये हैं। सेहत, सफाई की निगम सेवाएं और बिजली की उपलब्धि नगर निगम के जिम्मे रखी गयी हैं। धन की तंगी के कारण विकास का काम धीमे-धीमे किया जाएगा। यह भी व्यवस्था की गयी है कि इस क्षेत्र के उद्योग स्वयं मिलकर "सहकारी समितियां" बना लें और भूमिका विकास कर लें। इसके अतिरिक्त बिजली और पानी का प्रश्न भी है। पानी के लिए तो हमें पड़ोसी राज्यों—पंजाब और उत्तर प्रदेश—पर निर्भर रहना पड़ेगा। बिजली के लिए पहले यह ख्याल था कि भाखड़ा—नांगल बांध से पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल जाएगी, पर अब ऐसा प्रतीत होता है कि पंजाब के पास फालतू बिजली कम है। इस-लिए अब दिल्ली में ही थर्मल मशीनरी द्वारा बिजली के उत्पादन का निश्चय किया गया है। १९६५-६६ में दो लाख किलोवाट बिजली उपलब्ध हो जाने की आशा है।

प्रशिक्षण की प्रचुर सुविधाएं

दिल्ली में ऐसी सुविधाएं इस समय मौजूद हैं, जिनसे २,६०० कारीगर प्रति वर्ष प्रशिक्षण ले सकते हैं। तीसरी योजना में प्रति वर्ष ४३०० कर्मियों को प्रशिक्षण देने की गुंजायश रखी गयी है। इसके अतिरिक्त, ओखला औद्योग पुरी में प्रति वर्ष २४० छात्रों के प्रवेश की व्यवस्था के साथ एक पोलिटेकनिक खोल दिया गया है। महिलाओं के लिए भी इसी प्रकार का एक स्कूल खोला जा रहा है। दिल्ली में अन्य भी कई संस्थाएं प्रशिक्षण देने का काम कर रही हैं।

उद्योगों का ठीक प्रकार से संचालन करने के लिए एक बड़ी आवश्यक चीज श्रमिक वर्ग का सन्तुष्ट रहना है। दिल्ली में उद्योगों की वृद्धि के साथ-साथ इस समस्या पर बड़ी सावधानी से विचार करना होगा।

सरकार उद्योगों को ऋण और मशीनरी के लिए उधार बिक्री की सुविधाएं प्रदान करती है। तीसरी योजना में ६० लाख रु० पेशगी सरकार द्वारा देने का प्रस्ताव है। दिल्ली के उद्योगों के प्रति स्टेट बैंक, पंजाब वित्त निगम फाइनेंशल कारपोरेशन और राष्ट्रीय लघु उद्योग (निगम नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन) का सहयोग भी प्रशंसनीय है। ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देहली—१८६१ से १९६३ तक

—श्री दीनानाथ सिद्धांतालंकार

भारत के प्रधान मंत्री नेहरूजी के शब्दों में "दिल्ली पुराने और नये भारत का प्रतीक हैं।" एक ओर डिफेन्स कालोनी और दूसरी ओर चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, फतहपुरी, खारी बावली, सदर बाजार, नया बाजार इत्यादि बड़े बाजारों के पीछे लगने वाली तंग गलियां—जिनमें कइयों में केवल प्रवेश मार्ग ही हैं और बाहर निकलने के रास्ते बन्द हैं और कटरे जिनमें लाखों का व्यापार होता है—इन दोनों की एक साथ तुलना से नेहरूजी के कथन की पूर्ण पुष्टि होती है। पिछले कुछ वर्षों से जिस तेजी के साथ दिल्ली की वृद्धि हो रही है, वैसी भारत क्या विश्व के बहुत कम नगरों की हुई है।

१८६१ में दिल्ली का एक पृथक् जिले के रूप में गठन हुआ था। उस समय इसकी आबादी एक लाख से भी कम थी। १३ वर्ष बाद, जब इस जिले को एक कमिश्नर के आधीन किया गया, उस समय भी इसकी आबादी लगभग, पूर्ववत् ही थी। अब दिल्ली की आबादी २६,५८,६१२ है, अर्थात्, लगभग डेढ सदी बाद ६॥ गुना से अधिक। प्रतिवर्ष १ लाख की दर से राजधानी में आबादी की वृद्धि हो रही है। हर पांच वर्ष के बाद पुराने लखनऊ जितना शहर दिल्ली के साथ जुड़ जाता है।

१९३१ में दिल्ली मात्र कुछ सरकारी दफ्तरों का नगर था। सर एडवर्ड लुटएन्स ने उस समय जिस नयी दिल्ली की कल्पना की थी, वह आज अन्तर्राष्ट्रीय सूत्र संचालक बनी हुई है। एक छोटे व्यापारी नगरी से आज दिल्ली उत्तर भारत का एक प्रमुख औद्योगिक और भारत का वितरक केन्द्र बना हुआ है।

इस नगर की अकल्पनीय वृद्धि ने उसके स्वरूप को एकदम बदल दिया है। लोगों के रहने का ढंग बदल गया है। बिल्कुल आधुनिक ढंग के मकान अपना सिर उभार रहे हैं। आज से दो दशक पहले बनी सड़कें आज यातायात के लिए एकदम तंग हो गयी हैं। आमोद प्रमोद के स्थान अब पहले के स्थानों से सर्वथा भिन्न हैं।

पुरानी दिल्ली में यद्यपि अभी तक कटरें और हवेलियां मौजूद हैं, पर वे अब विशाल दिल्लीका कुछ अंश मात्र ही हैं। ३० वर्ष पहले तो दिल्ली, मुख्यतः इन्हीं का नाम था। इन कटरों और तंग बाजारों के चारों ओर, कई मीलों तक, अब दिल्ली ने पहले के रूप से सर्वथा भिन्न रूप धारण कर लिया है।

"वस्तुतः, अब दिल्ली कई नगरों के समूह का नाम हो गया है और इनमें से हरेक स्वरूप, मूल और धंधे की दृष्टि से दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं"—दिल्ली के मास्टर प्लान में लेखकों के ये शब्द सर्वथा ठीक हैं। इन नगरों में शामिल हैं "भारी भीड़ के, पुराने, ऊंची सफीरों से घिरे, अनाप शनाप बने पहाड़गंज और नया बाजार—जैसे हिस्से और दूसरी ओर "शानदार" सिविल लाइन्स, विशाल विश्वविद्यालय क्षेत्र और अभिमानी सरकारी अफसरों की नयी दिल्ली, तथा पश्चिम में रंगा कनाट प्लेस। पिछले वर्षों में कई नये "उपनगर" इस दिल्ली के साथ जुड़ गये हैं, कुछ विशिष्ट समृद्ध लोगों के और अत्यन्त आधुनिक नगर, जैसे, चाणक्यपुरी, फ्रेंडस कालोनी, डिफेन्स कालोनी, जोरबाग, गोल्फ लिंक इत्यादि।

आधुनिक ढंग के बने इन "उपनगरों" में वे सब सुख-सुविधाएं प्राप्त हैं जिनकी आज से २० साल पहले दिल्ली का एक नागरिक कल्पना भी नहीं कर सकता था। राजेन्द्र-नगर, तिलकनगर, मोतीनगर, कमलानगर, मालवीयनगर, लोदी रोड कालोनी, रूपनगर, कृष्णनगर, गांधीनगर इत्यादि दिल्ली में उपनगर नये ढंग से आबाद किये गये हैं। वहां के निवासियों की आर्थिक स्थिति और रुचि-परिवर्तन के परिणामस्वरूप अब एक व ढेढ दशक पहले बने मकानों में अब परिवर्तन आ रहा है। जैसे राजेन्द्रनगर में पहले सब बैरकनुमा छोटे-छोटे मकान थे, अब इनकी जगह नये डिजाइन के, दो व तीन मंजिले मकान खड़े हो रहे हैं।

दूसरे दशक में

जिन्होंने दिल्ली को इस सदी के दूसरे और तीसरे दशक में देखा है, वे अब इसे देखकर आश्चर्य से भौचक्के रह जाते हैं। १९२२ में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली विश्वविद्यालय सिविल लाइन्स पर उस मकान में प्रारम्भ हुआ था, जहां अब स्विस होटल है। इस की विज्ञान प्रयोगशाला काश्मीरी गेट में दुकानों के ऊपर एक छज्जे में थी। सेंट स्टीफेन्स कालेज काश्मीरीगेट में था, जहां गांधीजी और महा कवि टागोर तत्कालीन कालेज के वाइस-प्रिन्सिपल श्री सी० एफ० एंडरूज से मिलने जाया करते थे। उस समय विश्वविद्यालय के पास दीक्षान्त समारोह के लिए कोई हाल या कमरा नहीं था, इस लिए ओल्ड सेक्रेटरिएट के मुख्य हाल में—जहां केन्द्रीय एसेम्बली के अधिवेशन होते थे—दीक्षान्त उत्सव होते थे। ओल्ड सेक्रेटरिएट के उस कमरे में जहां तत्कालीन वायसराय लार्ड चेम्सफोर्ड ने रालेट एक्ट पर १९१९ में हस्ताक्षर किये थे। अतः स्वतंत्रता युग के दिल्ली के नेता और जन-सम्पर्क विभाग के अध्यक्ष श्री गोपीनाथ अमन बैठते हैं। १९११ में वायसराय भवन का निर्माण पूरा हुआ और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आ गयी। उन दिनों दिल्ली में एक अस्पताल था, जो केवल गोरों के लिए था। अब यह सबके लिए खुला है और इसका नाम है "हिन्दुराव अस्पताल।"

३०वें दशक के प्रारम्भ में मिंटो रोड एक तंग पगडंडी थी, जो पुरानी और नयी दिल्ली को जोड़ती थी। जहां अब इरविन अस्पताल है, वहां उस समय कब्रिस्तान था। ३०वें दशक में कनाट प्लेस बना। इसके बाद बंगाली मार्केट बनी। जहां इस समय सेंट्रल सेक्रेटरिएट, राष्ट्रपति-भवन और आकाश वाणी भवन हैं वहां इधर की इमारतों के लिए माल ढोने और पहुँचाने के लिए छोटी रेल लाइन बिछी हुई थी। उस समय इस स्थान का नाम था "आरा-मशीन" क्योंकि बिजली के बड़े-बड़े आरे यहां लगे हुए थे। विजय चौक के चारों ओर उभरे हुए स्थान का नाम "रायसीना" था।

पहाड़गंज में लगभग २०० मकान ही थे। करौलबाग का विकास ४०वें दशक में प्रारम्भ हुआ, पर विभाजन के बाद इसका विशेष विस्तार हुआ है। लोदी कालोनी का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के समय फौजियों के रहने के लिए हुआ था। ऊंचे सरकारी अफसरों ने यहां रहने से इन्कार कर दिया था, क्योंकि दफ्तर से दूर, रास्ते खराब और रात को गीदड़ बहुत चिल्लाते थे। बाजार करने के लिए यहां के लोग कनाट प्लेस, दरियागंज व चांदनीचौक तक जाते थे। पांचवें दशक तक जोरबाग वृक्षों और फुल-वाड़ियों का केन्द्र था। १२ वर्ष पहले जहां मोर नाचते थे वहां आज आलीशान इमारतें बनी हुई हैं। ●

एक तलिस्मां

मैं आप को एक तलिस्मां देता हूँ। जब कभी आप सन्देह में हों अथवा जब आप अपनी ही चिन्ता में बड़े व्यस्त रहते हों, उस समय निम्नलिखित जांच को अपने पर लागू करें।

आप की दृष्टि में जो सर्वाधिक निर्धन व निर्बल हो और आप कभी उससे मिले हों तो उसके चेहरे का स्मरण कीजिये और अपने आप से पूछिए कि आप जिस कदम को उठाने जा रहे हैं, क्या उसका कोई उपयोग उस निर्धन व निर्बल व्यक्ति के लिए हो सकता है? क्या इससे उसे कोई लाभ होगा? क्या इससे उसे अपने जीवन व भाग्य पर कोई नियंत्रण प्राप्त होगा? दूसरे शब्दों में, क्या इससे भूखे और आध्यात्मिक दृष्टि से भुखमरी के शिकार लाखों लोगों को स्वराज्य प्राप्ति में प्रेरणा मिलेगी?

तब आपकी शंका और आपकी चिन्ता पिघलती नजर आएगी।

—महात्मा गांधी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देहली का परिवर्तनशील आर्थिक स्वरूप

प्रो० पी० एन० धार, इंस्टीट्यूट आफ इकोनामिक ग्रोथ, दिल्ली

दिल्ली अभी तक, पूर्ण रूप से औद्योगिक नगर नहीं है। यद्यपि इसका प्रारम्भ महाभारत काल से हुआ है, पर यह सदा स्थिर नहीं रही है। कहते हैं, यह सात बार उजड़ी और बसी है। मुगल काल में, यहां की आबादी, अधिकांश, महलों और बादशाहों की छावनियों से संबंध रखने वाली होती थी। उस समय के विदेशी यात्री बर्नियर के शब्दों में—"दिल्ली की सारी आबादी छावनी में इकट्ठी होती है, क्योंकि इसका रोजगार और निर्वाह दरबार व फौज पर आधारित होता है। इसके सिवाय यहां की आबादी के पास कोई विकल्प नहीं है।" इसलिए यहां उद्योग भी वही ज्यादा चमके, जो हाथ की कारीगरी के थे और जिनका सम्बन्ध बादशादों के महलों से ही अधिक था। जैसे हाथी दांत का काम, गलीचा बुनना, सोने-चांदी की नक्काशी, सोना, चांदी, तांबा, और पीतल के वर्तन तथा रेशम की चीजें।

वस्तुतः-दिल्ली का उद्योगीकरण १९वीं शताब्दी के अन्त में हुआ। युद्ध काल में इन्हें प्रोत्साहन मिला। १९५१ में दिल्ली की प्रशासन ने ऐसे ४,६३४ संस्थानों की सूची बनायी थी जो ८६ विभिन्न उद्योगों से सम्बद्ध हैं। १९३१-१९५१ के बीच दिल्ली की आबादी तीन गुणा बढ़ गयी है। इस अवधि में दिल्ली के स्वरूप में कई उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं, जिनकी साक्षी दिल्ली राज्य के रोजगार के स्वरूप के विश्लेषण से मिलती है। दिल्ली राज्य में खेती-बाड़ी और इससे सम्बद्ध धन्धों में लगे लोग १९३१ में २५ प्रतिशत से कम होकर १९५१ में १० प्रतिशत रह गये, इमारती काम में लगे हुए ६ प्रतिशत से बढ़कर करीब १० प्रतिशत हो गये, सार्वजनिक सेवा पर निर्भर करने वाले ६ प्रतिशत से बढ़कर १७ प्रतिशत हो गये, तथा व्यापार—वाणिज्य पर निर्भर करने वाले १३ प्रतिशत से बढ़ कर लगभग २० प्रतिशत हो गये। उद्योगों की दृष्टि से दिल्ली के रोजगार का अनुपात इस अवधि में २० प्रतिशत से कम होकर १८ प्रतिशत रह गया। भारत के दिल्ली जितने आकार के अन्य नगरों की तुलना में इस राजधानी का औद्योगिक आधार सबसे छोटा है। मद्रास और पूना तक में वहां की आबादी के २५ प्रतिशत लोग निर्माण उद्योग में लगे हुए हैं।

दिल्ली के औद्योगिक नगर न होने का प्रमाण इसके कुल उत्पादन पर हुई आय के ब्यौरे से भी पता चलता है। दिल्ली मास्टर प्लान के लिए टाऊन प्लानिंग आर्गेनाइजेशन द्वारा १९५१-५५ का दिल्ली राज्य की अर्थव्यवस्था का जो ब्यौरा बनाया गया है, वह निम्न तालिका (पृ० २९) से स्पष्ट होता है।

इस तालिका से स्पष्ट है कि व्यापार और पूंजी (फाइनेन्स) तथा सार्वजनिक सेवाओं का दिल्ली अर्थव्यवस्था में खान और उद्योग की अपेक्षा अधिक हिस्सा है। यह भी स्पष्ट होता है कि विभाग-अनुसार राज्य का वित्तीय स्वरूप, लगभग, परिवर्तन रहित है। प्रसंगवश, यह भी पता चलता है कि खान और उद्योग का अंश जहां १८ प्रतिशत है वहां इस क्षेत्र में रोजगार भी १८ प्रतिशत ही है। इसका अभिप्राय यह है कि दिल्ली में औद्योगिक उत्पादनता, लगभग, उतनी ही है जितनी इसकी बाकी अर्थव्यवस्था में है। आम तौर पर, औद्योगिक उत्पादनता औसतन अर्थव्यवस्था की उत्पादनता से बहुत ज्यादा होती है।

इस सम्बन्ध में दिल्ली की विशेषता इसके कृषि क्षेत्र के लघु स्वरूप के कारण है। व्यापार पूंजी (वित्तीय-व्यवस्था) और सार्वजनिक सेवाएं मिलाकर ४५ प्रतिशत होती हैं। इसका यह कारण भी है कि दिल्ली के औद्योगिक स्वरूप में बड़े उद्योगों का कम हिस्सा है। फिर भी इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि दिल्ली में औद्योगिक तत्त्व ५० से ३५ प्रतिशत के लगभग भी नहीं है। यदि बिजली अधिक सुलभ हो और इस्पात तथा अन्य धातुओं के समान मध्यवर्ती उत्पादन अधिक सुभीते से प्राप्त हों तो दिल्ली का औद्योगिक उत्पादन बड़ी तेजी से बढ़ जाएगा। अधिक बिजली और कच्चा माल मिलने पर ओखले का उत्पादन, अवश्य ही, दुगना हो सकता है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मूलभूत स्वरूप वितरण केन्द्र

वस्तुतः, दिल्ली का मूलभूत स्वरूप तो व्यापार और वित्त का केन्द्र होने में है। गंगा-जमुना दो-आब के बीच और पंजाब के दूसरे किनारे पर यह स्थित है। देश के विभाजन तथा भारत की सीमा अमृतसर हो जाने के कारण दिल्ली, निःसन्देह उत्तर पश्चिम भारत का प्रमुख नगर बन गया है और थोक व्यापार, बैंक, निर्माता उद्योग, कुशल सेवाओं के लिए दिल्ली की ख्याति फैल चुकी है और हाट-बाजार का केन्द्र बन गयी है। दिल्ली के चारों ओर फरीदाबाद, गाजियाबाद, सोनीपत, गुड़गांव इत्यादि नगरों का एक छोटा चक्र बन गया है और इस सारे चक्र में उद्योगों का फैलाव हो रहा है। कुछ दूरी के नगर—अलीगढ़, करनाल, मेरठ, मथुरा इत्यादि भी दिल्ली की परिधि से सम्बद्ध हैं। कुछ ही दिनों में ये नगर दिल्ली के प्रभाव क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे। तीसरे बड़े १०० मील व्यापी चक्र में आगरा, जयपुर, अम्बाला इत्यादि नगर हैं, जो व्यापारिक रूप में दिल्ली पर ही निर्भर करते हैं। यह सम्भव है कि भविष्य में दिल्ली को औद्योगिक नगर बनाने की चेष्टाएं और प्रवृत्तियां इन निकटवर्ती नगरों और कस्बों में प्रवाहित हो जाएं, जिससे दिल्ली की वर्तमान अंधाधुंध वृद्धि धीमी पड़ जाएगी।

दिल्ली राज्य की कुल आय में विभिन्न विभागों का प्रतिशत भाग

(१९५१-५५)*

नाम	१९५१	१९५२	१९५३	१९५४	१९५५
कृषि (पशु पालन वन और मत्स्य पालन सहित)	४-९	४-७	५-०	४-२	३-८
खान और उद्योग	१७-८	१७-४	१७-७	१६-८	१८-०५
इमारत	५-०	५-२	४-९	४-९	५-१८
सार्वजनिक उपयोगिताएं	०-७	०-९	०.९	०-९	०-९९
व्यापार और पूंजी (फाइनेन्स)	२४-८	२४-७	२४-७	२६-२	२५.७१
परिवहन और संचार	४-८	५-३	५-४	५-७	५.८८
सार्वजनिक सेवा	२०-८	२१-४	२०-६	२०-४	१९.५०
धन्धे और उदार कलाएं	७-०	७.४	७-२	७-१	६-९२
व्यक्तिगत सेवाएं	३-०	३-१	३-०	३-०	३-०३
अन्य सेवाएं	१-७	१.८	१.७	१.७	१.६०
मकान जायदाद से आय	६.८	७.०	६.७	६.७	६.४३
ऐसी आय जिस पर आय कर लगता है पर अन्य जगह नही लगी है	२.६	१.०	२.७	२.३	२.८९
योग	९९.९	९९.९	९९.९	९९.९	१००.००

* १९६१ की जनगणना के अंक पृ० ४३ पर देखिये। इस क्रम में बहुत परिवर्तन नहीं हुआ।

सम्पदा के आप ग्राहक नहीं हैं, तो बनिये और यदि हैं तो दूसरों को ग्राहक बनाइये।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली शिक्षा में सब से आगे

—श्री बी० डी० भट्ट,
संचालक शिक्षा विभाग

१९६१-६२ में दिल्ली में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं १,३७३ थीं। इनमें से १३.२६ प्रतिशत सरकार द्वारा और ७१.६७ प्रतिशत विभिन्न स्थानीय संस्थाओं द्वारा—जिसमें दिल्ली नगर निगम भी शामिल है—चलायी जा रही हैं, १४.७१ प्रतिशत सहायता प्राप्त और बाकी ०.३६ प्रतिशत बिना सहायता प्राप्त स्कूल हैं। इन स्कूलों में छात्रों की कुल संख्या गत वर्ष ५,३९,७६९ थी (३,२८,५६८ लड़के और २,११,२०१ लड़कियां) इसका शिक्षा क्रम के अनुसार ब्यौरा इस प्रकार है—

	छात्र
प्राइमरी या पहले के स्कूलों में	३,४७,५४९
मिडिल/सीनियर बेसिक स्कूलों में	१,२६,८९९
हाई/हायर सेकेंडरी स्कूलों में—	६३,३२१
	५,३९,७६९

इनमें लगभग ११,१०० छात्र देहात के हैं।

१९६१-६२ में शिक्षा पर व्यय ३,२६,४७००० रु० हुआ, जो पिछले वर्ष से २१,१८,००० रु० अधिक था। सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में ८वीं कक्षा तक की शिक्षा मुफ्त है। अखिल भारतीय दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में १९६०-६१ में दिल्ली भारत में सबसे आगे था। ब्यौरे के अनुसार—

शिक्षा स्तर	समूचे भारत में प्रतिशत	दिल्ली में प्रतिशत
१. प्राइमरी (६-११ वर्ष की आयु)	६३	८९.१८
२. मिडिल (११-१४ वर्ष की आयु)	२३	६८.००
३. हाई/हायर सेकेंडरी (१४-१७ वर्ष की आयु)	—	३५.३

शिक्षा का बजट (रु० में)

दिल्ली में शिक्षा का बजट इस प्रकार है—

	संशोधित बजट १९६२-६३	आनुमानिक बजट १९६३-६४
बोर्ड आफ हायर सेकेंडरी शिक्षा	७,००,०००	—
गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल	१,५६,५२,०००	१,५६,५१,०००
गैर सरकारी सेकेंडरी स्कूलों को ग्रांट	१,०१,५०,०००	९९,५०,०००
स्थानीय संस्थाओं को सेकेंडरी शिक्षा के लिए ग्रांट	५,५६,०००	५,६६,०००
प्राइमरी शिक्षा	७६,६४,०००	८१,७३,०००

दिल्ली के कालेज

इन पंक्तियों में हमने केवल हायर सेकेंडरी तक के स्कूलों की चर्चा की है, किन्तु दिल्ली में शिक्षा क्षेत्र बहुत विस्तृत हैं। जहां भारत सरकार का शिक्षा मन्त्रालय हो, वहां यह स्वाभाविक भी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्तर्गत १९६०-६१ तक २२ कालेज, १० विभिन्न पेशों के कालेज, और ३ विशेष शिक्षण कालेज चल रहे थे। बाद के दो वर्षों में तो यह संख्या बढ़ गयी है। १९६०-६१ में करीब २० हजार छात्र इन कालेजों में पढ़ते थे और केन्द्रीय सरकार करीब अढ़ाई करोड़ रु० खर्च करती थी। इसके अतिरिक्त दिल्ली में अनेक अनुसन्धान संस्थाएं विज्ञान की शिक्षा देती

(शेष पृष्ठ ९२ पर)

दिल्ली का शिक्षा में प्रथम स्थान

विश्व विद्यालयों में नामांकन के मामले में दिल्ली का प्रथम स्थान है जहां प्रत्येक दस लाख व्यक्तियों पर ९१२२ छात्रों का नाम विश्व विद्यालय में अंकित है।

दिल्ली के बाद पश्चिमी बंगाल और पंजाब का क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान है। इन राज्यों में प्रति दस लाख व्यक्तियों पर क्रमशः ४७६४ और ३०५१ छात्रों का नाम विश्व विद्यालयों में लिखा गया है।

सन् १९६१-६२ में भारतीय विश्व विद्यालयों की एक नामांकन सर्वेक्षण की रिपोर्ट से।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली का चतुर्मुखी विकास

श्री कृष्णकिशोर, मुख्य सचिव, दिल्ली राज्य

७, १७ और ९८.२७ करोड़ रु०

सन् १९५१ में पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से देश के अन्य सभी राज्यों के साथ दिल्ली भी योजना-बद्ध विकास के रास्ते पर चल पड़ी। किन्तु ७ करोड़ रुपयों की पहली पंचवर्षीय योजना शीघ्र ही अगले ५ वर्षों के लिये १७ करोड़ की योजना बन गई और अब तीसरी पंचवर्षीय योजना तो ९८.२७ करोड़ रुपयों की है। केवल इसी एक तथ्य से स्पष्ट है कि दिल्ली का विकास किस गति से और किस मात्रा में हो रहा है।

राष्ट्र की राजधानी होने के कारण दिल्ली नगर की ही आबादी २७ लाख है। ग्रामीण क्षेत्र में केवल ३ लाख लोग रहते हैं। पिछले १५ वर्षों में नगर में ४० बड़ी-बड़ी नई बस्तियां बनाई जा चुकी हैं। नगर के विस्तार के ही कारण दिल्ली नगर निगम का अधिकार क्षेत्र, प्रदेश के लगभग ३०० गांवों तक विस्तृत कर दिया गया है, ताकि ग्रामीण विकास योजनाओं के साथ-साथ नागरिक योजनाओं का लाभ भी दिल्ली के ग्रामवासियों को मिल सके। सामुदायिक कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि, सिंचाई, बिजली, बागबानी, सहकारिता, भूमि संरक्षण इत्यादि सभी अंगों में विकास हुआ है। उद्योग धन्धों की उन्नति के साथ-साथ घरों, सड़कों, बिजली व पानी, मजदूरों, स्कूलों, अस्पतालों, परिवहन आदि की सभी समस्याएँ एक साथ ही सामने आ गईं। इसके पहले कि पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों के बसाने की समस्या सुलझ पाती, इन बड़ी-बड़ी समस्याओं को हल करने का प्रश्न ही सामने नहीं आया, वरन् इनका आकार भी दिन प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा है। इनमें से कृषि, सामुदायिक विकास, पंचायत, तकनीकी प्रशिक्षण आदि दिशाओं में दिल्ली में जो विकास हुआ है, संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है।*

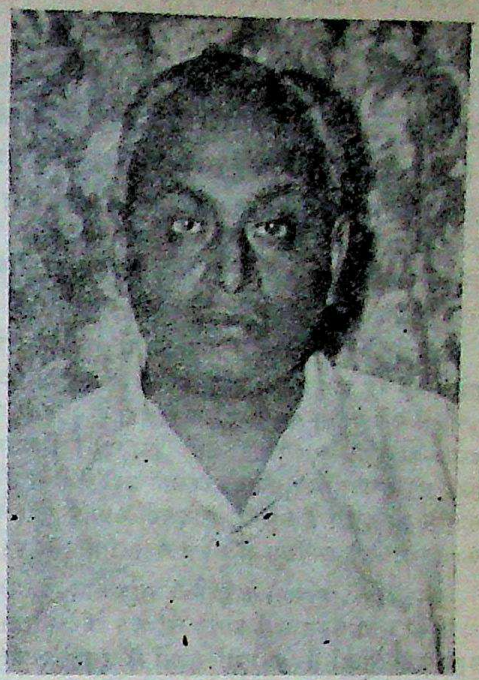

दिल्ली प्रदेश में कृषि

देश की आर्थिक स्थिति का आधार कृषि है। इसलिये राष्ट्र के विकास में कृषि की शीघ्र उन्नति की बड़ी आवश्यकता है।

देश के दूसरे हिस्सों को देखते हुए दिल्ली प्रदेश में खेती की अपनी ही विशेषताएँ हैं। कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र बहुत सीमित है—३,६५,५९८ एकड़ में से केवल २.१७ लाख एकड़ में खेती होती है। शहरी क्षेत्र की बढ़ती को देखते हुए तो अन्दाज है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल केवल १.९० लाख एकड़ रह जायगा। दूसरी ओर दिल्ली प्रदेश की आबादी भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इस लिए खेती से उपज बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में खेती योग्य भूमि में अधिकाधिक उपज पैदा करने के लिए सभी सम्भव कदम उठाए जा रहे हैं। रासायनिक खाद, उन्नत बीज, फसल को नष्ट करने वाले कीटाणुओं व टिड्डी आदि से बचाव तथा यथासम्भव सिंचाई की उन्नति के साधन किसान तक पहुँचाने के लिए सभी सम्भव उपाय प्रयोग में लाये जा रहे हैं।

---

* इस अंक के अनेक अन्य लेखों से दूसरी भी दिशाओं की प्रगति का परिचय मिलेगा।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पहले १५ वर्षों में कृषि के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है। भूमि संरक्षण, खाद व रासायनिक खाद का प्रयोग, बागबानी और अनाज की खेती में बहुमुखी उन्नति हुई है। किसानों में खेती के नये व उन्नत तरीकों के उपयोग के सम्बन्ध में विशेषतया जागृति और रूचि पैदा हुई है। खेती योग्य भूमि के ८० प्रतिशत भाग में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जा रहा है और गेहूँ, बाजरा, चावल व ज्वार सभी जिन्सों के लिए पुराने बीजों की जगह नई किस्म के उन्नत बीज बोये जा रहे हैं।

रासायनिक खादों का किसान लोग काफी मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। उनकी मांग इतनी बढ़ गई है कि पूरी मात्रा में उसे पहुंचा सकना कठिन हो रहा है। इसी प्रकार फसल को नुकसान पहुँचाने वाले कीटाणुओं को मारने के लिए भी रसायनों का प्रयोग किसान बड़ी तेजी व इतमीनान से करने लगे हैं। चूहों, टिड्डियों तथा पोहली के दूर व नाश करने के कार्यक्रम में भी वे बड़ा उत्साह ले रहे हैं।

दिल्ली की आबादी के बढ़ने के साथ-साथ सब्जियों व फलों की मांग बहुत अधिक बढ़ गई है। ये दोनों ही चीजें बहुत बड़ी मात्रा में पड़ोसी राज्यों से मंगाई जाती हैं। इसलिए बागबानी की सभी योजनाओं में फल व सब्जियों की उपज को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है।

भूमि संरक्षण

भौतिक विभागों के अनुसार भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में दिल्ली प्रदेश में ४ किस्म की जमीन है :—

१. खादर—नदी के किनारे की जमीन।
२. बांगर—नहर से सींची हुई जमीन।
३. डाबर— नीची जमीन जहां पानी भर जाता है।
४. कोही या पहाड़ी—पथरीली जमीन।

जलवायु की दृष्टि से दिल्ली प्रदेश अर्ध-शुष्क और तोष्ण कटिबन्ध है। यद्यपि दिल्ली प्रदेश का क्षेत्रफल बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी भूमि संरक्षण की अनेक प्रकार की समस्याएँ यहां भी पाई जाती हैं। काफी बड़े क्षेत्र में हवा व पानी दोनों के ही द्वारा भूमि का कटाव जारी है। एक तरफ ढालू जमीन होने के कारण बढ़िया मिट्टी पानी के साथ बह जाती है और दूसरी तरफ हल्की मिट्टी तेज हवा के साथ उड़ जाती है जिससे भूमि की उपजाऊ पर्त खत्म हो जाती है।

प्रदेश का एक बहुत बड़ा क्षेत्र सतह में नीचा है और उसपर पानी भर जाता है। पानी के बहने का ठीक साधन न होने के कारण भूमि में शोरा, रेह और लोना बढ़ता जा रहा है, विशेषकर पिछले ६-७ वर्षों में काफी हिस्से में रेह हो गया है। प्रदेश के दक्षिणी भाग में अरावली पर्वत श्रेणियों में पानी के कारण तेजी से कटाव हो रहा है। भूमि संरक्षण की इन समस्याओं के अध्ययन से स्पष्ट है कि राजस्थान के मरुस्थल का दिल्ली के छोटे से प्रदेश पर प्रभाव पड़ रहा है। इस समय भूमि संरक्षण के लिए छोटी-बड़ी कुल मिलाकर विविध १७ योजनाएं तैयार की जा चुकी हैं।

आजादी खतरे में है।
अपनी पूरी ताकत लगा कर इसकी रक्षा कीजिए।
—जवाहरलाल नेहरू

उत्पादन बढ़ाइये

आज अधिक उत्पादन भारत के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शरीर के लिए जीवन-दायक रक्त। आप खेतों और कारखानों में जितना अधिक उत्पादन बढ़ायेंगे, देश को उससे उतनी ही अधिक ताकत मिलेगी।

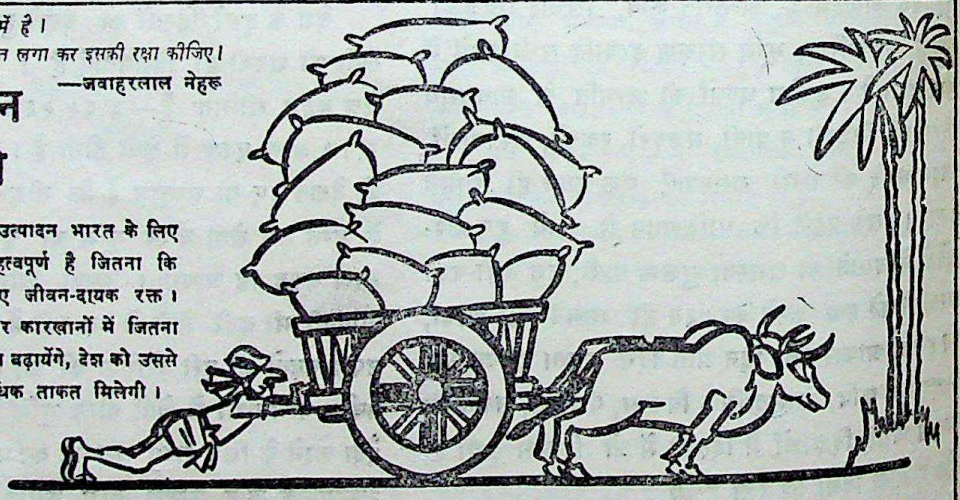

रक्षा व्यवस्था को सबल बनाइये

DA 63/FC

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

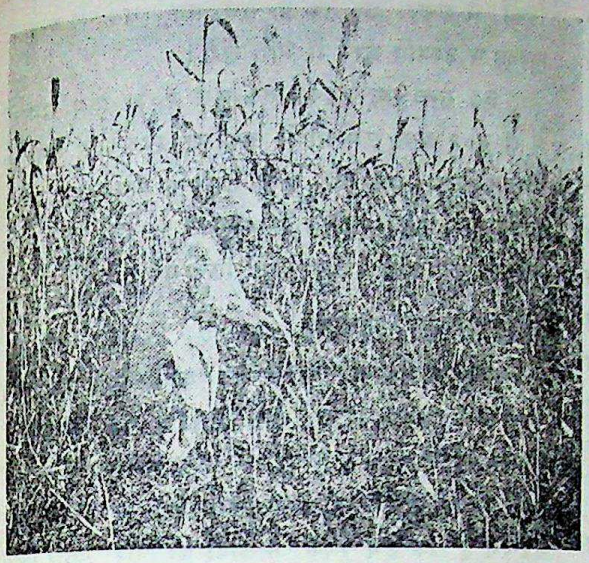

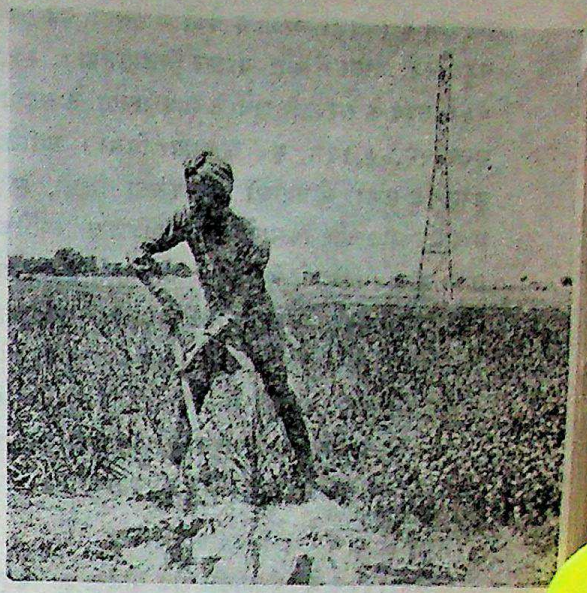

सामदायिक योजना के अन्तर्गत कृषि-विकास के दो दृश्य

सिंचाई

दिल्ली की औसत सालाना वर्षा लगभग १२ इंच है जो अधिकतर बरसात के मौसम में जुलाई व सितम्बर महीनों के बीच बरसती है। इन महीनों में भी लगातार वर्षा न होने के कारण खरीफ की फसल पकने तक के लिये काफी पानी भूमि में नहीं पहुँच पाता।

सिंचाई के मुख्य साधन कुएं ही हैं। यद्यपि ३३हजार एकड़ भूमि में नहरों से सिंचाई हो सकती है, किन्तु नहरों से खेती के लिए पूरा पानी नहीं पहुंच पाता और इस क्षेत्र में भी कुओं पर ही निर्भर होना पड़ता है। दिल्ली राज्य में लगभग १० हजार खुले हुए कुएं हैं।

दिल्ली के किसानों के खाते बहुत छोटे-छोटे हैं और वे स्वयं उनकी सिंचाई के प्रबन्ध के लिए अधिक धन नहीं लगा सकते। यही कारण है कि कृषि व खाद्य मन्त्रालयों ने दिल्ली के किसानों को कुएं बनाने, रहट लगाने, कुएं बोरिंग करने, पम्प लगाने व ट्यूब वेल बनाने के लिये कर्जा देने के लिए तीसरी पंच वर्षीय योजना में १७.४५ लाख रुपये का प्राविधान किया है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

अक्तूबर सन् १९५२ को प्रथम सामुदायिक विकास खण्ड अलीपुर के प्रारम्भ के साथ दिल्ली प्रदेश के सामुदायिक विकास कार्यक्रम का श्रीगणेश हुआ। अक्तूबर सन् १९५२ में नजफगढ़ में कार्य प्रारम्भ किया गया। शाहदरा का राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड सन् १९५५ में चालू हुआ और इस तरह पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त तक दिल्ली प्रदेश के ग्रामीण हिस्से का तीन चौथाई सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आ गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूरे ग्रामीण भाग में विकास योजनाएं लागू हो गई और अलीपुर, नजफगढ़, खंजावला, शाहदरा और महरोली में पांचों विकास खण्डों के मुख्य कार्यालय क्रमशः रखे गये। सन् १९५८-५९ में खण्डों की प्रथम अवस्था पूरी हुई और अलीपुर नजफगढ़ तथा नांगलोई विकास खण्ड द्वितीय अवस्था में प्रविष्ट हुए।

स्वभावतः सामुदायिक विकास कर्यक्रमों में कृषि को सबसे अधिक प्रधानता दी गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले २ वर्षों के अन्त तक २८,४७८ उन्नत औजार बांटे गये।

सामुदायिक कार्यक्रम का मुख्य आधार जनता का

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सहयोग है। दिल्ली ग्रामीण क्षेत्रों में हमको यह सहयोग बहुत बड़ी मात्रा में और बराबर मिलता रहा। ३५,८६,-०१९ रुपये के सरकारी खर्चे के साथ जनता के सहयोग का मूल्य २८,३५,१६८ रु० के बराबर मिला। नतीजा यह हुआ कि सभी योजनाओं में सफलता मिली, कृषि का उत्पादन बढ़ा और किसानों का सामाजिक व आर्थिक स्तर ऊंचा हुआ। किसानों ने विकास योजना में बड़ी लगन व मेहनत से सहयोग दिया। उनकी सफलता केवल इसी बात से प्रत्यक्ष है कि दिल्ली प्रदेश को ५०-५० हजार रुपयों के दो इनाम केन्द्रीय सरकार से रबी १९५९-६० व खरीब १९६० की फसलों के उत्पादन पर प्राप्त हुए, जो हमारे छोटे से प्रदेश के लिये बड़े गौरव की बात है।

पंचायती राज

सन १९५९ में पंचायती राज योजना का उदघाटन हुआ। अक्तूबर-दिसम्बर १९५९ के बीच पंचायतों के चुनाव किये गये और २०५ ग्राम पंचायतें तथा २२ सर्किल पंचायतें, जिनमें २४२४ चुने हुए जनता के प्रतिनिधि थे, स्थापित की गईं। पंचायत राज कार्यक्रम के विकास के साथ-साथ ग्राम विकास परिषदें, और खण्ड विकास समितियों के स्थान पर चुनी हुई पंचायतें व ब्लाक पंचायत समितियों ने काम करना प्रारम्भ किया।

सन् १९६२-६३ में पंचायतों की कुल आमदनी ७,-७५,७८६ रु० हुई जिसमें ५३,१५४ रुपये जनता के दान व चन्दे के रूप में आये थे, १,१२,९९७ रुपया अनुदान में मिला, ३८९, २६ रु० जमीन के मुआवजे के रूप में मिला, २१,५४१ रु० की आमदनी तालाबों से और ९२,-२६२ रुपये की आमदनी खदान-परमिटों से तथा १,०७,-५६४ रुपये की आमदनी अन्य जरियों से हुई थी। पिछले वर्ष ७४६ मामले पंचायती अदालतों के सामने प्रस्तुत किये गये, जिनमें से ६५६ पर फैसला हुआ और ६३ मामले ऊपर की अदालत में भेजे गये।

ग्रामीण स्वयंसेवी सेना

ग्रामीण स्वयंसेवी सेना की स्थापना २६ जनवरी, १९६३, में की गई, ताकि राष्ट्र की सुरक्षा तथा देश की आर्थिक उन्नति दोनों के ही लिए ग्रामीण क्षेत्रों में निहित साधनों की क्षमता व जनशक्ति का पूरा-पूरा उपयोग हो सके। इस दिन एक बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली के नागरिकों ने शपथ ली कि वे तन, मन, धन से राष्ट्र की सुरक्षा व उन्नति करने में भाग लेंगे।

३१ मार्च सन् १९६३ तक कुल २०५ ग्राम सभाओं में से २०३ ग्राम सभाओं में ग्रामीण स्वयंसेवी सेना का संगठन किया गया और उनके दलपति नियुक्त हुए। इस कार्यक्रम के तिहरे उद्देश्य के अन्तर्गत ७२६२ स्वयं सेवक उत्पादन कार्यक्रमों के लिए भर्ती किये गये। ❀

तालाबों का विकास

गांव के तालाबों को उन्नत करने की योजना सन् १९५६ में प्रारम्भ की गई थी। दिल्ली में ३५० तालाब हैं जिनमें से केवल १०० में पूरे वर्ष पानी भरा रहता है और इनमें मछलियां पाली जा सकती हैं। इस योजना का उद्देश्य है कि उन १०० तालाबों को और गहरा किया जाय, उनको सुडौल और मजबूत बनाया जाय, ताकि उनमें पूरे साल पानी भरा रह सके। इस काम के लिये ग्राम पंचायत को सरकार की ओर से खर्च का ५० प्रतिशत अनुदान के रुपयों में २००० रुपये तक दिया जाता है।

१० तालाब तीसरी पचवर्षीय योजना के पहले दो सालों में तथा २६ तालाब उन्नत किये जा चुके हैं।

एक योजना के अनुसार ४० ग्रामीण तालाबों में प्रतिवर्ष २ लाख मछलियां पालने का विचार है। मत्स्य विकास योजना के अनुसार १०० ग्रामीण तालाबों में प्रतिवर्ष ६ लाख मछलियां पालने का विचार है। इससे पहले केवल ४ लाख मछलियां प्रति वर्ष पाली जाती थी।

तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण

पढ़े लिखे बेरोजगार व्यक्तियों की समस्या सभी प्रशासकों के सम्मुख है। इसके अलावा पड़ौसी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान व पंजाब के बेरोजगार व्यक्ति भी दिल्ली के एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में अपने नाम दर्ज कराते हैं। बेरोजगारी की इस समस्या को हल करने के लिये ही अब ऐसे पेशों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की

❀इस सम्बन्ध में श्री आनन्दशंकर शर्मा का एक लेख (पृष्ठ ६२) देखिये।

(शेष पृष्ठ १०५ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली की विकास योजनाएं—कुछ विशेषताएं

श्री लक्ष्मीनारायण ओंकारलाल जोशी, भू० पू० मुख्य सचिव, दिल्ली राज्य

स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त ही पश्चात् योजनाबद्ध विकास का जो प्रभात प्रारम्भ हुआ, उससे देश का कोना कोना नवजागरण का अनुभव कर रहा है—अतएव यह स्वाभाविक ही था कि नये भारत की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में थी विकास योजनाओं की नई किरणों का प्रकाश पड़ता। योजना बनाने और उन्हें गण-तंत्रिक समाज में इतने बड़े पैमाने पर क्रियान्वित करने के इस महान् प्रयास ने जहां देश-विदेश के गण्यमान्य व्यक्तियों से साश्चर्य प्रशंसा पाई, वहां भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न स्तर पर विकसित हुई देश की अनेक इकाइयों की विकास योजनाएं बनाने के प्रयोगों ने देशवासियों को नये अनुभव, नई निष्ठाएं और नई प्रौढ़ता भी प्रदान की है।

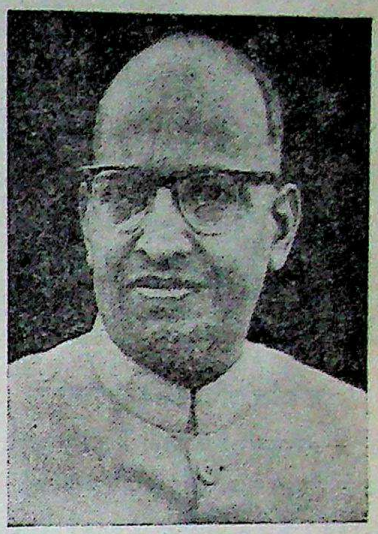

लेखक

विशेषताएं

दिल्ली संघीय क्षेत्र, विकास योजनाओं के बनाने और उनके क्रियान्वित करने—दोनों दृष्टियों से, अपनी विशेषताएं रखता है। उनमें से ही कुछ का उल्लेख करना इन पंक्तियों का प्रयोजन है। कई नगरों से बनी हुई एक विशाल और वेर्धिर्धिष्णु नगरी और लगभग ३०० "ग्रामों" से बना हुआ यह क्षेत्र न केवल देश के सभी राज्यों से किंतु कई संघीय क्षेत्रों से भी विस्तार में छोटा है। इसका कुल विस्तार ६०० वर्ग मील से भी कम है। इसी कारण नगर से कुछ ही बाहर निकलते ही हम या तो पंजाब या उत्तर प्रदेश की सीमा में जा पहुँचते हैं। विस्तार में इतना छोटा होने पर भी देश की यही एक ऐसी इकाई है जहां की औसत जनसंख्या ४५०० प्रति वर्गमील से भी अधिक है, और जहां के कुछ भागों में जनसंख्या का घनत्व डेढ़ लाख प्रति वर्ग मील के लगभग पहुँच जाता है। इसके अतिरिक्त, यही एक ऐसी इकाई है जिसका अधिकांश भाग शहरी बस्ती है और जिसका प्रमुख उद्योग खेती नहीं है। यहां तो जो भाग ग्रामीण समझा जाता है, वह भी देश के सामान्य ग्रामीण क्षेत्र से बहुत भिन्न है क्योंकि वह पास में बसे हुए और फैलते हुए इस नगर से अधिकाधिक प्रभावित होता जा रहा है।

दिल्ली क्षेत्र का विकास पिछले कुछ वर्षों में केवल इसी कारण नहीं हुआ है कि वह संसार के सबसे बड़े गणतन्त्र की चिरयौवना राजधानी है, किंतु इस कारण भी हुआ है कि वह अनेक नये-नये उद्योगों और व्यापार के महत्त्वपूर्ण केन्द्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। इन्हीं कारणों से १९५९ से १९६१ तक के दशक में यहां की जनसंख्या में लगभग ५१ प्रतिशत वृद्धि हुई और १९४१ की तुलना में तो आज की जनसंख्या लगभग तिगुनी हो चुकी है। वृद्धि की इस गति के आधार पर भविष्य का अनुमान लगाकर, नई विकास योजनाओं में सन् १९८१ ई. तक दिल्ली की आबादी लगभग ५५ लाख आंकी गई है। किसी एक नगर या क्षेत्र की आबादी का इतनी तेजी से बढ़ना अपने आप में एक विशेषता है जो कई समस्याओं को उत्पन्न करती है और योजना-विशेषज्ञों को उनका हल ढूंढने के लिये आह्वान करती है।

साक्षरता और शिक्षा के क्षेत्र में भी दिल्ली की अपनी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

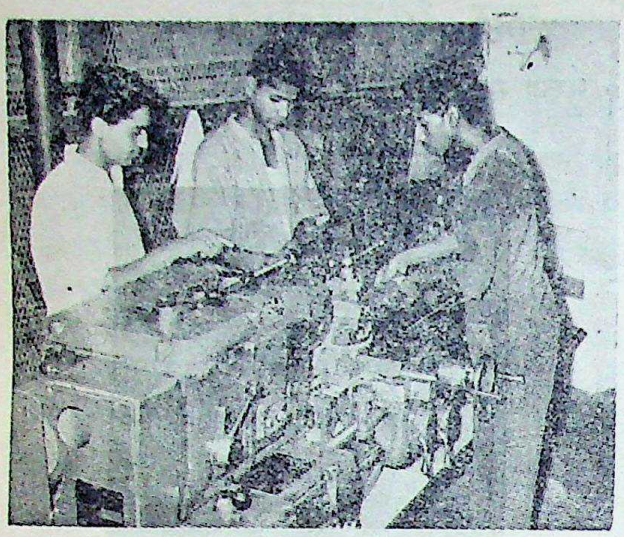

तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था

विशेषताएं हैं। पिछली जनगणना में साक्षरता के प्रतिशत की दृष्टि से दिल्ली ने अच्छी प्रगति दिखाई है और साक्षरता १९५१ के ३८ प्रतिशत से बढ़कर १९६१ में ५२ प्रतिशत तक पहुंच गई है। इस क्षेत्र में पहले केरल सर्व प्रथम था। वह प्रथम स्थान पाने का गौरव अब दिल्ली क्षेत्र को प्राप्त है। शिक्षा की सुविधाओं का माध्यमिक स्तर तक विस्तार तो यहां की अन्य राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के समान हो रहा है परन्तु उच्चतर शिक्षा की सुविधाएं, विशेषतः तकनीकी शिक्षा की सुविधाएं, यहां बहुत ही कम रहीं और सामान्य कालेज स्तर की शिक्षा के लिये भी यहां के कई निम्न श्रेणी में परीक्षा से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी आसपास के अन्य राज्यों के नगरों में जाते रहे हैं। सौभाग्य से पिछले दो तीन वर्षों से इस ओर ध्यान गया है और तकनीकी शिक्षा के केन्द्र द्रुतगति से बढ़ाये जा रहे हैं।

जन सहयोग के आधार पर सामुदायिक विकास का जो देशव्यापी कार्यक्रम चला, उसमें दिल्ली को विशेष प्राथमिकता मिलने पर भी (उसके सारे क्षेत्र में विकासखंड बहुत पहले ही बन गये थे तो भी), इस क्षेत्र की बहुत सी जनता तबतक इस योजना के लाभ से वंचित रही, जब तक सामुदायिक विकास की कल्पना नगरों तक नहीं फैली। इस दिशा में अभी तो श्रीगणेश ही हुआ है। ग्रामीण भाग में भी "जन सहयोग से विकास" का सिद्धान्त इस कारण अच्छी तरह नहीं जमा कि एक तो वैसे भी शहरों के निकट के ग्रामों में यह सहयोग प्राप्त करना अपेक्षाकृत कठिन रहता है और दूसरे, दिल्ली क्षेत्र के ग्राम दिल्ली नगर निगम की अधिकार-सीमा एवं कार्य-सीमा में शामिल हो जाने के कारण, ग्रामीणों में यह भावना दृढ़तर होती गई कि नगरों के समान इन ग्रामों को भी आवश्यक सुख-सुविधाएं—बिजली, पानी, पाठशाला, यातायात, चिकित्सालय आदि—बिना श्रमदान या प्रत्यक्ष जन सहयोग के मिल सकेंगी। किसी सीमा तक नगर निगम के सीमा-विस्तार का यह परिणाम हुआ भी है कि नागरिक क्षेत्र से प्राप्त आय में से पर्याप्त धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में निगम की ओर से व्यय की गई है।

पिछले कुछ वर्षों से विकेन्द्रीकरण और पंचायती राजव्यवस्था पर देश में विशेष बल दिया जा रहा है। इस पहलू से देखने पर दिल्ली क्षेत्र में यह विशेषता पाई जाती है कि यह सारा क्षेत्र, नई दिल्ली नगरपालिका और कैंटोनमेण्ट बोर्ड की सीमाओं को छोड़कर, दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत है और विकास योजनाओं का लगभग दो-तिहाई व्यय निगम के द्वारा ही होता है। निगम के विधान में ग्रामीण क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिये एक विशिष्ट समिति की व्यवस्था है और इस समिति को निगम की ओर से अधिक अधिकार देने का भी प्रावधान है। परन्तु साथ ही ग्रामों में पंचायतें स्थापित हैं जिनका निगम या उसकी ग्रामीण क्षेत्र समिति से कोई सम्बन्ध नहीं है। ग्रामीण विकास में थोड़ा बहुत दखल रखने वाली खंड-विकास-समितियां भी हैं परन्तु वे न तो पंचायतों से संबद्ध हैं न ग्रामीण क्षेत्र समिति से। यह एक अद्भुत रचना है, जिसमें स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं की कड़ियां एक दूसरे से बिना जुड़ी बनी हुई हैं और तीन-सोपान वाले "पंचायती राज" के नये विचार के क्रियान्वय की प्रतीक्षा कर रही हैं।

संस्थाओं की विविधता

एक और महत्वपूर्ण विशेषता है—विकास योजनाओं को बनाने वाली और उन्हें अमल में लाने वाली संस्थाओं की विविधता—दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका, दिल्ली प्रशासन, केन्द्रीय गृह मंत्रालय और अन्य

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सभी विकास-सम्बन्धी केन्द्रीय मंत्रालय दिल्ली क्षेत्र के लिये योजनाएं बनाते हैं और उन पर अमल करते हैं। इससे कई दिशाओं में अधिक और अच्छा भी काम हो है किन्तु इस व्यवस्था में समन्वय का, एक सम्पूर्ण, सर्वांगीण आयोजन का अभाव रहता ही है। इस स्थिति को दृष्टि में रखते हुए हाल ही में भूमि विकास तथा आवास सम्बन्धी नई योजना में समन्वय की विशेष व्यवस्था की गई है।

अन्त में केवल एक विशिष्टता का और उल्लेख-मात्र कर देना पर्याप्त होगा। दिल्ली की उपर्युक्त विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के विकास की योजनाओं में देश के अन्य भागों से भिन्न प्राथमिकताएं हो सकती हैं और सम्भवतः होंगी। दिल्ली क्षेत्र के लिए बिजली, उद्योग, जल प्रदाय, यातायात, शिक्षा, चिकित्सा आदि अत्यन्त महत्व के और लगभग समान प्राथमिकता के प्रश्न हैं; और उत्तरोत्तर जो योजनाएं बन रही हैं वे, इस बात का प्रमाण हैं कि इन सब दिशाओं में दिल्ली ऐसी उन्नति करेगा, जो कि देश के अन्य भागों के लिये भी आदर्श होगी।

• •

औद्योगीकरण द्वारा पूर्ण रोजगार और विकास का लक्ष्य··· !

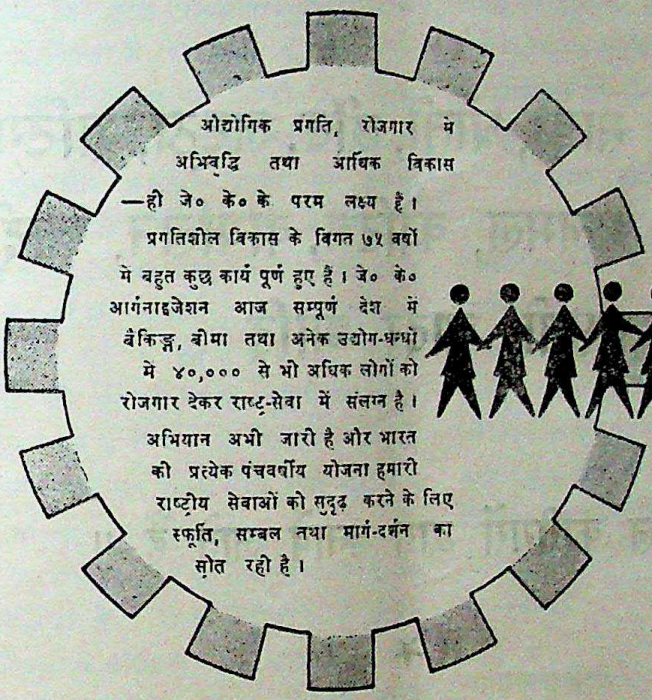

भारत की ४४ करोड़ जन-संख्या में से श्रमिक केवल ३१.७ प्रतिशत लोग ही है और इस रोजगार स्थिति में जे० के० का महत्वपूर्ण योगदान है।

जे. के. ऑरगनाइज़ेशन

भारत का महान् औद्योगिक तथा व्यावसायिक संगठन

कानपुर • बम्बई • कलकत्ता

JKO/H/2/63

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देश की प्रतिरक्षा के लिए वस्त्रों का अधिक उत्पादन

बिड़ला काटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि०

के

अधिकारी, कर्मचारी व कारीगर देश के जन-जन के लिए
हर किस्म का कपड़ा मिल में तैयार करते हैं

पंजाब की सर्वश्रेष्ठ रुई से

साड़ी, धोती, छींट, लट्ठा, शर्टिंग,
मलमल, कोटिंग, वायलिन, खादी,
दुसूती, चादर आदि

*

कुशल कारीगरों द्वारा बनाये जाते हैं !!

*

बिड़ला काटन स्पिनिंग एण्ड

वीविंग मिल्स लिमिटेड, दिल्ली ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तथ्यपूर्ण विवेचना

दिल्ली के स्वायत्त शासन का विकास

श्री शिवचरण गुप्त, संसद सदस्य

• दिल्ली में नागरिक प्रशासन का इतिहास सन् १८६२ में "दिल्ली म्युनिसिपल कमीशन" की स्थापना के साथ प्रारम्भ हुआ, जिसे बाद में दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के नाम से पुकारा जाने लगा। लगभग पचास वर्षों तक दिल्ली में यही एक ऐसा स्थानीय निकाय था जिसकी सीमा में सारा शहरी इलाका सम्मिलित था। सिविल स्टेशन की नोटिफाइड एरिया कमेटी की स्थापना भारत सरकार की राजधानी सिविल लाइन्स के इलाके में बनने के कारण १६ जनवरी १८६३ को हुई जब कि नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी, जिसे पहले "रायसीना म्युनिसिपैलिटि" कहा जाता था, नई दिल्ली में राजधानी के निर्माण के साथ-साथ बनी। इसका उद्देश्य नई दिल्ली के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को निजामुद्दीन, जगंपुरा और अलीगंज गांवों का सफाई-नियन्त्रण सौंपना था, क्योंकि ये गांव नई राजधानी के निर्माण के लिये अधिगृहीत कर लिए गये थे। इसी प्रकार अन्य स्थानीय निकायों की स्थापना भी शहर के विस्तार के फलस्वरूप होती चली गई। इन में से दक्षिणी दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी और पश्चिमी दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी विभाजन के पश्चात इन क्षेत्रों में बसी विस्थापितों की नई बस्तियों को नागरिक प्रशासन देने के लिये बनाई गईं।

पहला नागरिक बजट

दिल्ली में म्युनिसिपल बजट का विकास अध्ययन की दृष्टि से बड़ा मनोरंजक है। डिप्टी कमिश्नर श्री एफ० एच० कूपर ने दिल्ली के कमिश्नर को ५ फरवरी, १८६३ को जो पत्र लिखा था, उससे पता चलता है कि काफी अर्से तक "दिल्ली म्युनिसिपल कमीशन" की आय का प्रमुख साधन था चुंगी की नीलामी। इस साधन से मिलने वाली ८२००० रुपये की राशि में से ४८००० रुपये पुलिस कर्मचारियों के वेतन में खर्च हो जाते थे और केवल ३४,००० रुपये की राशि कमीशन के लिये बचती थी। पुलिस पर होने वाला यह भारी खर्च अनेक वर्षों तक नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करने वालों के लिए चिन्ता का विषय बना रहा।

पहला नागरिक बजट कमीशन की एक सब-कमेटी ने अपनी २८ मई, १८६३ की बैठक में बनाया। कमीशन की ओर से इस सब-कमेटी को यह अधिकार था कि वह कर्मचारियों में फेर बदल कर सके और कमीशन के दायित्वों को पूरा करे। अपनी १ जून, १८६३ की बैठक में कमीशन ने इस बजट को कुछ परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर लिया। इसी बैठक में एक यूरोपियन सदस्य ने यह संशोधन रखा कि भारतीय नायब सुपरिटैंडेंट और उसके दो जमादारों को हटाकर सफाई की देखभाल के लिए एक यूरोपियन सुपरिटेन्डेन्ट को रखा जाय, किन्तु कमीशन के यूरोपियन चेयरमेन का निर्णायक मत विपरीत होने के कारण इसे स्वीकार न किया जा सका।

उस समय सबसे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी थे श्री देवकीनन्दन, सुपरिटेन्डेन्ट जिन्हें ६० रुपये मासिक मिलता था। उन के वेतन को बाद में बढ़ा कर १०० रु० मासिक कर दिया गया था। कमीशन के चेयरमैन दिल्ली के कमिश्नर कर्नल हैमिल्टन और आनरेरी सैक्रेटरी मि० डब्ल्यू० एच० मार्शल थे। बहुत सालों बाद कमीशन में पूरे दिन काम करने वाला वैतनिक सैक्रेटरी नियुक्त किया गया। इस बैठक में स्वीकार किये गये कर्मचारियों का विवरण इस प्रकार है:

१. सुपरिटैंडेन्ट	१	१०० रुपये मासिक
३. जमादार	२, २० रु प्रत्येक	४० ,, ,, ,,
२. नायब सुपरि०	१	५०
४. मुंशी	३, १० रु० प्रत्येक	३० ,,
५. चपरासी	४, ५ रु० प्रत्येक	२० ,,
६. टैक्स कलक्टर	१	८रु० मासिक
७. इंगलिश आफिस, कर्मचारी-वर्ग		५० रु० मासिक

म्युनिसिपल प्रशासन की आय बढ़ाने के उद्देश्य से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इसी बैठक में कमीशन ने निम्नलिखित टैक्स और लागू किये :

नगर कर अर्थात् "चुंगी"

तम्बाकू : पत्ती और सभी प्रकार की बनी तम्बाकू ४ आने से एक रु० प्रति मन।

घी : १ रु० प्रति मन।

शक्कर : बनी हुई और साफ १ रु० प्रति मन।

तेल : ४ आने प्रति मन।

खाल : मूल्य का ६¼%

खुण्डला : ७५ तोले भार का ८वा० भाग।

कोयला : वजन के अनुसार एक से आठ आने तक।

चूने का पत्थर : १ आना प्रति मन।

पान : ३ पाई से ६ पाई तक प्रति डोली।

२—पानी और रोशनी की दर, प्रति बड़ी दूकान से दो आने, और छोटी दूकान से १ आना मासिक थी।

३—फेरी वालों तक पटरी पर सामान बेचने वालों से तहबाजारी की दर : (जूते, कपड़े, मिठाई, फल, टोपी, खिलौने, जड़ी बूटी, पान, मशाल, पतंग, रस्सी और किताब बेचने वाले, सोने चांदी के सिल्क पर काम करने वाले और हरी सब्जियां बेचने वाले। आठ आने मासिक

चमार, फूल बेचने वाले, रोटी वाले। चार आने मासिक

यह निर्णय किया गया कि करों की आमदनी दिल्ली बैंक में "दिल्ली म्युनिसिपल फण्ड" के नाम से रखी जाय। बैठक में बजट के कुछ मोटे सिद्धान्त भी निश्चित किये गये और इस प्रकार दिल्ली में बहुत छोटे पैमाने पर म्युनिसिपल बजट का श्री गणेश हुआ।

बजट को देखने से पता चलता है कि सभी टैक्सों से होने वाली कुल आमदनी ९४५१२ रुपये थी। इस में ४८,००० रु० पुलिस पर और कर का छटा भाग सेना पर खर्च किया जाता था और म्युनिसिपल प्रयोजनों के लिए केवल ३८,७६२ रु० की राशि बचती थी। बजट में आय-व्यय लगभग बराबर रहता था।

आय में शनैः शनैः वृद्धि

इस साल के और इसके बाद के कुछ सालों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यह अनुमान है कि १८५७ के संघर्ष के बाद दिल्ली की आबादी एक लाख से भी कम रह गई थी। १८९१ की जनसंख्या के अनुसार आबादी बढ़कर १.९२ लाख हो गई थी। इसके बाद ज्यों ज्यों आबादी बढ़ती गई और शहर फैलता गया, दिल्ली की नागरिक आवश्यकताएं भी बढ़ती गईं। म्युनिसिपल आय और व्यय भी तेजी से बढ़ा और १८८४-८५ में जब कि आबादी दो लाख से भी कम थी, दिल्ली म्युनिसिपल कमीशन का राजस्व बजट ३,०३, ९०० रुपये हो गया। १९०१-१९०२ में यह ५, ८६, ५२८ रुपये हुआ और अगले २५ वर्षों में १९२५-२६ तक बढ़कर ५ गुणा से भी अधिक ३१९१, ९९३ रु० हो गया। १९३८-३९ की लड़ाई आरम्भ होने के समय राजस्व बजट ५० लाख से अधिक हो गया। किन्तु आय के साधन इस अनुपात से नहीं बढ़े और लड़ाई के दिनों में सेवाओं में लगातार बढ़ोतरी होने के कारण दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी आर्थिक संकट में फंस गई, जिससे निकलने के लिए उसे ३३ लाख मूल्य की भूमि बेचनी पड़ी।

अगस्त १९४७ के बाद ५ लाख से भी अधिक विस्थापितों के आ जाने के कारण दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी का बजट असाधारण रूप से बढ़ा। कमेटी की आय जो १९४६-४७ में ६८.७२ लाख थी १९५०-५१ में १४६.४६ रु. लाख हो गई और १९५२-५३ में १९२.०९ रु० लाख हो गई। १९५६-५७ में सरकारी कर्ज को मिलाकर आय और व्यय क्रमशः २,९०,५०,९४८ रु० और २,९९,७६,३६७ थे। दिल्ली नगर निगम की स्थापना से पहले दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी की आय सरकारी कर्ज को मिलाकर ३,१३,६९,५९४ रु० थी। निगम में मिलाये गये १० स्थानीय निकायों में से नजफगढ़ नोटिफाइड एरिया कमेटी को निकाल कर शेष की आय १९५७-५८ में ४,०३,९२,४६४ रु० थी।

इस लम्बे अर्से में म्युनिसिपल करों के ढांचे में कोई खास फेर बदल नहीं हुई। दिल्ली के स्थानीय निकायों पर १९११ का पुराना पंजाब म्युनिसिपल एक्ट लागू था।

सम्पर्क

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

म्युनिसिपल करों के दकियानूसी ढांचे को बदलने की सभी कोशिशें बेकार साबित हुईं। १८८५ में ही नागरिकों से सफाई-शुल्क वसूल करने की एक तजवीज इस लिये रखी गई थी कि सफाई का खर्चा पूरा किया जा सके, किन्तु इसे अव्यावहारिक समझा गया और दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी ने बहुमत से इसे अस्वीकार कर दिया।

वैज्ञानिक टैक्स-प्रणाली

म्युनिसिपल सेवाओं के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हमेशा आय के साधन बढ़ाने की आवश्यकता को अनुभव करते रहे हैं। सन् १९३४ में चीफ कमिश्नर के वित्तीय सलाहकार श्री जहीद् ने म्युनिसिपल टैक्सों की जांच की थी और अपनी रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया था कि दिल्ली में म्युनिसिपल टैक्सों की प्रणाली को बदला जाना चाहिये। उन का यह विचार था कि म्युनिसिपल आय का प्रमुख साधन टर्मिनल टैक्स, जो एक अप्रत्यक्ष कर है, पुराने ढंग का टैक्स है। इसके स्थान पर दिल्ली में एक प्रगतिशील और वैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार म्युनिसिपल टैक्स लागू किये जाने चाहिये। उनकी इन सिफारिशों पर २५ साल तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। दिल्ली नगर निगम की स्थापना के बाद पहले म्युनिसिपल कमिश्नर श्री पी० आर० नायक ने निगम के सामने अपनी टैक्सों सम्बन्धी तजवीजें पेश कर के यह काम किया।

निगम का बजट

दिल्ली नगर निगम का पहला बजट अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। नए टैक्सों की तजवीजों के साथ निगम द्वारा इस का स्वीकार किया जाना ऐतिहासिक महत्व रखता है। इससे दिल्ली में लागू म्युनिसिपल टैक्सों की सौ साल पुराने ढांचे के स्थान पर एक ऐसी कर-प्रणाली का सूत्र-पात हुआ, जो बड़े शहरों की अवस्थाओं के अनुरूप है। इस बजट को न केवल देश की नई कार्पोरेशन का आय व्यय का अनुमान कहा जा सकता है बल्कि इससे इस बात का भी संकेत मिलता है कि किस, प्रकार ५४८ वर्गमील के इलाके में रहने वाली २० लाख जनता की नागरिक आवश्यकताओं को पूरा किया जायगा। चूंकि इस बजट का दिल्ली की विशाल जनसंख्या के दिन प्रतिदिन के जीवन से सम्बन्ध था, जनता में इस के प्रति काफी दिलचस्पी रही।

इस बजट पर विचार करते समय हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि निगम की स्थापना हो जाने से दिल्ली में पहली बार ऐसे प्रशासन की स्थापना हुई, जिसके अधीन सभी प्रकार की म्युनिसिपल सेवाएं थीं। दर असल तो एक दृष्टि से यह निगम बम्बई से भी बड़ा कहा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में बिजली बनाने की जिम्मेदारी निगम की है, जब कि बम्बई में इस पर निगम का नियन्त्रण नहीं है। निगम की स्थापना के साथ न केवल शहर के दस स्थानीय निकायों को ही समाप्त किया गया है बल्कि बिजली बनाने और उसकी सप्लाई, परिवहन, और पानी की सप्लाई तथा गन्दे पानी की निकासी के स्वतन्त्र संगठन भी उसे सौंप दिये गये हैं।

यह निगम टोकियो को छोड़ कर दुनियां का दूसरा सबसे बड़ा निगम है।

(शेष पृष्ठ ११२ पर)

पुरानी दिल्ली की याद

कसौटी कहते हैं जिसको,
वह शहर देहलीं था,
यहां के संग में पारस
का था असर पैदा।
वतन को छोड़ कर हर
सिम्त से जो आते थे
इसी जगह से सब
इन्सान बन के जाते थे।
सुबह तो जाम से गुजरती है।
शब उसके बाम पै गुजरती है,
आकबत की खबर खुदा जाने
अब तो आराम से गुजरती है॥

दिल्ली जो एक शहर था, आलम में इन्तिखाब,
रहते थे मुन्तखिब हो जहाँ रोजगार के।
उसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया,
हम रहने वाले हैं, उसी उजड़े दियार के॥

—मीर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यह आपकी दिल्ली है (अंकों में)—१

क्या आप यह जानते हैं ?
नहीं तो अब जानिये

इन स्तम्भों में हम दिल्ली-सम्बन्धी कुछ अंक देकर जानकारी दे रहे हैं। प्रयत्न यह किया गया है कि ये अंक यथासम्भव नवीनतम और प्रामाणिक हों, पर कुछ अंक हब प्राप्त नहीं कर सके। अधिकांश सामग्री दिल्ली सरकार के सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रकाशित विवरण संगृहीत की गई है। इन अंकों से दिल्ली की गतिविधि पर एक सरसरी दृष्टि डाली जा सकती हैं।

क्षेत्रफल व जनसंख्या

	क्षेत्रफल	आबादी
दिल्ली	५७३ वर्ग मील	२६,५८,६१२
ग्रामीण क्षेत्र	४४६.९ वर्ग मील	२,९९,२०४
नागरिक क्षेत्र	१२६.१ वर्ग मील	२३,५९,४०८

इससे स्पष्ट है कि ग्रामों के विस्तृत क्षेत्रफल होते हुए भी आबादी ३ लाख से अधिक नहीं है, जबकि करीब एक चौथाई क्षेत्रफल होते हुए भी नागरिक क्षेत्र की आबादी ग्राम क्षेत्र की अपेक्षा १२ गुना है।

दिल्ली के भी भिन्न-भिन्न भागोंकी जनसंख्या की दृष्टि से घनता अलग-अलग है। यह अन्यत्र एक लेख में देखिये।

जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि

दिल्ली की जनसंख्या में वृद्धि की गति क्रमशः निम्न-लिखित हैं—

वर्ष		
१८९१	३,७३,१३६	
१९०१	४,०५,८१९	(९% की गति से वृद्धि)
१९११	४,१३,८५१	(२% की गति से वृद्धि)
१९२१	४,८८,४५२	(१८% की गति से वृद्धि)
१९३१	६,३६,२४६	(३०% की गति से वृद्धि)
१९४१	९,१७,९३९	(४४% की गति से वृद्धि)
१९५१	१७,४४,०७२	(९०% की गति से वृद्धि)
१९६१	२६,५८,६१२	(५२% की गति से वृद्धि)

दिल्ली में जन्म-मरण की मासिक औसत

वर्ष	जन्म	मृत्यु
१९५७ में	६,१३९	१,७०९
१९५८ में	५,७००	१,७३९
१९५९ में	६,३०४	१,७८१
१९६० में	६,३१२	२,०९४
१९६१ में	६,५५५	१,८४७

दिल्ली में कृषि उत्पादन

(सन् १९४९-५० की पैदावार = १०० मानकर)

	१९६०-६१	१९५९-६०
कुल खरीफ फसलों की पैदावार	८६.१	१११.६
कुल रबी की फसलों की पैदावार	१२७.१	१२५.१
दालें	१५७.७	७०.६
कुल खाद्य पदार्थ	११४.२	११५.०
कुल अखाद्य पदार्थों की फसलों की पैदावार	१४८.१	१२२.६
कुल पदार्थ	१२३.४	११७.१

राष्ट्रीय बचत में

राष्ट्रीय बचत आन्दोलन में दिल्ली राज्य में कितनी प्रगति हो रही है, यह नीचे की तालिका से मालूम होता है।

लाख रु. में

वर्ष	कुल विनियोजन	विकास कार्यों में विनियोजन
१९५६-५७	८.३०	२.३०
१९५७-५८	९.०२	१.७०
१९५८-५९	१०.४४	२.६९
१९५९-६०	१०.४९	२.१२१
१९६०-६१	१२.९५	४.१
१९६१-६२	१२.७२	३.०४

इनामी बाण्डों के द्वारा दिल्ली राज्य में कुल १५.८१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लाख रुपया एकत्र हुआ जबकि समस्त भारत में एकत्र रुपये की राशि ३.३२ करोड़ रुपये थी।

दिल्ली में औसतन रोज की डाक

	१९५२	१९६२
(१) बिना रजिस्ट्री की चीजें, डेलीवरी की गयी	३,६५,०००	५,८२,०००
(२) रजिस्टर्ड चिट्ठियां डाक से भेजी गयीं	१०,६००	२२,०००
(३) रजिस्टर्ड पार्सल डाक से भेजे गये	१,९००	१,९००
(४) बीमा शुदा चीजें डाक से भेजी गयीं	५००	७००
(५) मनीआर्डर भेजे गये	४,१००	६,९००
(६) मनीआर्डर अदा किये गये	७,०००	७,९००
(७) डाक मोटरों द्वारा तय की गयी दूरी	२,४०० किलोमिटर	५,२०० किलोमिटर

दिल्ली में रजिस्टर्ड गाड़ियां

१९६२ के मध्य में दिल्ली राज्य में रजिस्टर्ड गाड़ियां (ट्रक, बस, मोटर, टैक्सी आदि) की कुल संख्या ८२.५९० थी। इनसे टैक्स और फीस के रूप में सरकार को निम्नलिखित रूप से आमदनी हुई।

वर्ष	टैक्स	फीस (रुपये)
१९६०-६१	२९,८४,२३१	१४,३४,५६९
१९६१-६२	३५,८०,६१८	१४,१९१९९

दिल्ली में आजीविका के अनुसार जन-संख्या

श्रेणी	कुल दिल्ली पुरुष	कुल दिल्ली स्त्री	दिल्ली (नगर) पुरुष	दिल्ली (नगर) स्त्री	दिल्ली ग्रामीण क्षेत्र) पुरुष	दिल्ली ग्रामीण क्षेत्र) स्त्री
(क)—काम करने वाले						
१. कृषक	३४,६०९	२०८५५	३०,७४१	१९,५३९	३,८६२	१,३११
२. खेतीहर मजदूर	५,१०१	२,२२४	४,१८६	१८९७	९१५	३२७
३. खान, वन, मछली शिकार, बागबानी, आदि	६,९१८	१,७४८	२,३००	९२०	४,६१८	८२८
४. घरेलू दस्तकारी	१३,१९४	३,५१६	३,१३७	८८९	१०,०५७	२,६२७
५. घरेलू उद्योग के अतिरिक्त अन्य निर्माण कार्य	१,६३,३५३	६,९७१	११,४६६	३,७५९	१,५१,८८७	३,२१२
६. भवन निर्माण	३२,६०५	२,७५५	२,३४१	४७९	३०,२६४	२,२७६
७. व्यापार और वाणिज्य	१,४४५७९	२,१४८	२,६५५	२६३	१,४१,९२४	१,८८५
८. परिवहन, स्टोरेज, और संचार	४८,६७३	८९६	२१३५	४७	४६,५३८	८४९
९. अन्य सेवायें	३२९,२५६	३५,०५६	१४,५१४	२,३६८	३,१०,७४२	३२,६८८
योग (क)	७,७८,२८२	७६१६९	७७४७५	३०१६१	७००८०७	४६००८
(ख) काम न करने वाले	७,११,०९६	१०,९३०६५	८४,५१७	१०७०५१	६२६,५७९	९८६०१४
क और ख का योग	१४८९३७८	११,६९,२३४	१६१९९२	१३७२१२	१३२७३८६	१०३२०२२

स्रोत—(भारत की १९६१ का जनगणना की सांख्यिकी विभाग दिल्ली।)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली का विकास : कुछ ऐतिहासिक घटनाएं

दिल्ली का इतिहास बहुत प्राचीन है। वर्तमान दिल्ली का इतिहास भी आज के बहुत से पाठकों को मालूम नहीं है। हम इन पंक्तियों में कुछ उन घटनाओं का तिथिक्रम देना चाहते हैं, जो दिल्ली के विकास में अपना थोड़ा बहुत महत्व रखती हैं। हमारी जानकारी पूर्ण नहीं है। बहुत सी जानकारी प्रयत्न करने पर भी उपलब्ध नहीं हुई। फिर भी हमारा यह ख्याल है कि यह जानकारी पाठकों को मनोरंजक प्रतीत होगी।

१. १८५७ में प्रथम स्वातन्त्र्य युद्ध की विफलता के बाद दिल्ली पर बाकायदा अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया।

२. लेकिन १९११ में दिल्ली को अंग्रेजों ने भारत की राजधानी के रूप में स्वीकार किया।

३. १८६३ में दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी की स्थापना हुई। इसकी पहली बैठक २३ अप्रैल १८६३ को हुई।

४. चांदनी चौक में १८६४ और १८६९ के बीच में २२,१३४ रुपये की लागत से घण्टाघर बनाया गया, जो बाद में—१९५१ में गिर गया।

५. १८६७ में म्युनिसिपल कमेटी ने पहली बार भारत सरकार से १ लाख रुपये का ऋण लिया।

६. १८७० में नार्थब्रुक के दिल्ली आगमन पर कोतवाली के सामने फव्वारा बनाया गया।

७. टेली फोन का सबसे पहला उल्लेख १८८० में मिलता है। इन टेलीफोनों का सम्बन्ध उस समय पुलिस चौकियों से ही था।

८. १८८३ में ओखला नहर बनाई गई।

९. १८८५ में म्युनिसिपल प्रबन्ध में निर्वाचित प्रतिनिधि भी म्युनिसिपल कमेटी में लिए जाने लगे।

१०. २६ मार्च १८९६ में दिल्ली क्लाथ मिल की रजिस्ट्री हुई।

११. १८९० में गिलहरी मिल की स्थापना हुई थी, इस की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी। बाद में श्री कन्हैयालाल बागला ने हनुमान मिल के नामसे खरीद लिया। १९२० में इसे बिड़ला ब्रदर्स ने खरीदा।

१२. १८९० में म्युनिसिपल वाटर वर्क्स की स्थापना हुई।

१३. १८९० में पहले पहल इन्कम टैक्स लगाया गया।

१४. १८९२ में दिल्ली पिंजरापोल का संगठन किया गया।

१५. १८६६ में अलाहबाद बैंक की ब्रांच खुली।

१६. इसी सन् में २ रुपया फी मवेशी पर कर लगाया गया, जिसे १९०८ में हटा लिया गया।

१७. १८९४-१८९५ में वाटर वर्क्स पूरा बन गया।

१८. १९०० में बिजली की सप्लाई का एकाधिकार एक अंग्रेज कम्पनी को दिया गया।

१९. १९०२ में १ जनवरी को पहली बार हाउस टैक्स लगाया गया।

२०. १९०२ में स्ट्रीट लाइट अस्थायी रूप से दरबार के लिए लगाई गयी।

२१. १९०४ विक्टोरिया जनाना हस्पताल की आधार शिला १९ फरवरी को रखी गई।

२२. १९०६ में पुल मिठाई के पास पशु औषधालय खोला गया।

२३. ३ अप्रैल १९०६ को पन्जाब नेशनल बैंक की पहली शाखा दिल्ली में खुली।

२४. २ जुलाई १९०६ को इलैक्ट्रिक ट्रामवे के लिए आर्डर जारी किया गया।

२५. १९०८ को ३ जून को ट्राम वे शुरू हो गई। पहले बिजली घर काबुली गेट में बनाया गया था, पीछे लाहोरी गेट में स्थानान्तरित किया गया।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

२६. १९११ में कुवों से पानी निकालना बन्द किया गया।

२७. १९११-१३ में वाटर वर्क्स की क्षमता बढ़ाई गई।

२८. १९१२ में चांदनी चौक की नहर बन्द की गई।

२९. १९१२ में दिल्ली भारत की राजधानी बन जाने के कारण म्युनिस्पिल कमेटी का विधान बदला गया और पदाधिकारियोंके सिवा सरकारी मैम्बर ४ से ३ कर दिए गए। और निर्वाचित सदस्य ११ कर दिए गये।

१७ दिसम्बर १९१२ को दिल्ली को पंजाब से पृथक् कर दिया गया। १९१३ में १६ जनवरी को सिविल लाइन्ज की एरिया कमेटी और नजफगढ़ एरिया कमेटी की भी स्थापना की गई।

३२. १९१६ में दिल्ली राज्य में इन्कम टैक्स लगाया गया।

३३. १९६१ में शाहदरा, नरेला, और रायसीना कमेटियों की स्थापना हुई।

३४. १९१८-१९ में एक और पानी का पम्प लगाया गया।

३५. १९१९ दिसम्बर में नरेला नोटीफाईड एरिया कमेटी संगठित की गई।

३६. १४मार्च१९२२ में दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और श्री हरिसिंह गौड़ वाइस चांसलर नियुक्त किये गये।

३७. १९४७, १५ अगस्त को दिल्ली में स्वतंत्र्य-सूर्य और लाल किले पर तिरंगा।

३८. १९५७ में २८ दिसम्बर को म्युनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिली।

३९. १९५८ में मार्च २० म्युनिसिपल कार्पोरेशन की चुनाव हुए।

वसुधा

इस बात का गर्व करती है कि इसने २॥ वर्ष के अल्प समय में सरकार द्वारा स्वीकृत ४ कालोनियां बेच कर अद्वितीय सफलता तथा नाम पैदा कर लिया है।

अपने ग्राहकों तथा जनता के आग्रह पर अब यह कम्पनी अपनी

पाँचवीं कालोनी

राम पार्क एक्सटेंशन की बिक्री का श्रीगणेश कर रही है

बजीराबाद ब्रिज के खुलने तथा सरकार द्वारा लोनी-गाजियाबाद सड़क पर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के प्रस्ताव पुनर्जीवित करने से लोनी क्षेत्र की सर्व प्रियता इतनी बढ़ गयी है कि अब सभी बड़े-बड़े व्यक्ति उस क्षेत्र में प्लाट लेने तथा मकान बनाने के लिए उत्सुक हैं। यदि आप मकान बनाने अथवा प्लाटों में रुपया लगाने के तनिक भी इच्छुक हों तो यह मौका हाथ से न जाने दीजिए। तुरंत इस नयी कालोनी में प्लाट बुक कराइए।

पूरी जानकारी के लिए कृपया वसुधा लैंड एण्ड फाइनेन्स कम्पनी १४/१५ शंकर टेरेस दिल्ली, फोन २२२००६ से सम्पर्क स्थापित करें।

प्लाट दिखाने के लिए कम्पनी की तरफ से मुफ्त सवारी (फ्री ट्रान्सपोर्ट) का अपना प्रबन्ध है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

100% TERYLENE ICI Polyester Fibre

The SHIRT You Do'nt Iron

Victor

LUXURY WEAR

The Finest Wear For Men Of Distinction

Manufactured by :

Victor Apparel Pvt. Ltd. Bombay-13.

अजुध्या टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड

आजादपुर दिल्ली-६

का मतलब है !!

१. धोती
२. साड़ी
३. चादर
४. ग्रे मार्किन
५. ब्लीच शर्टिंग
६. पापलीन
७. दुसूती
८. माजरी
९. सेलुलर शर्टिंग
१०. लांग क्लाथ रंगीन
(क) बढिया सुन्दर रंग में
(ख) आकर्षक डिजाइन

टेलीफोन : २२४५११
: २२२३४८

तार :
अजुध्या
दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली का मास्टर प्लैन

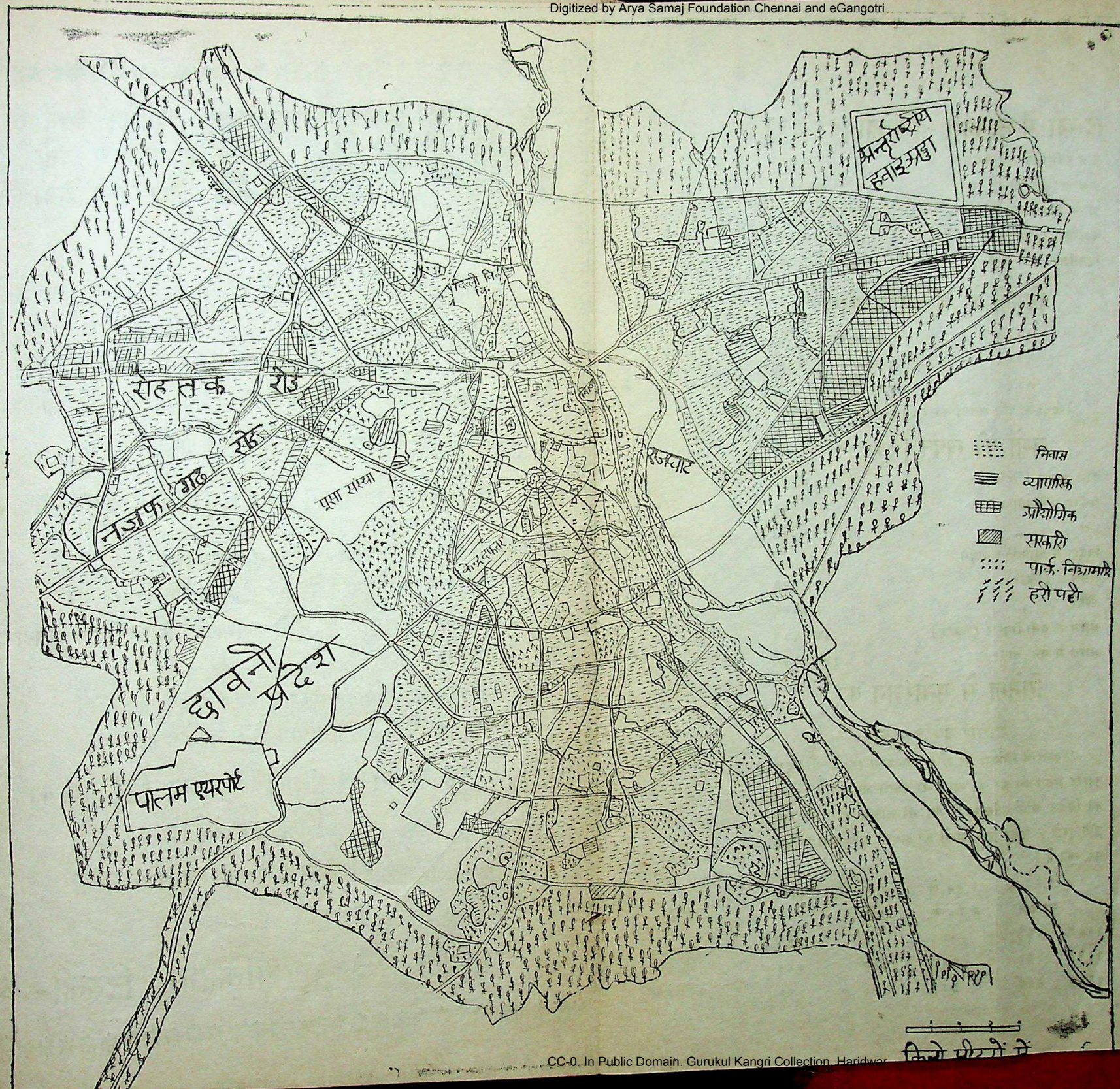

मास्टर प्लैन के कुछ अंग

* १९८१ में संभावित जनसंख्या ४६ लाख
* एक नया विश्वविद्यालय : पांच विश्वविद्यालय केन्द्र
* २२ नये कालेज
* २० नये हस्पताल (प्रत्येक ५०० पलंग वाला)
* एक सांस्कृतिक संस्था—६०० एकड़
* रेल गाड़ियों के चार रेलवे पुल
* ८ विभागों व १३६ जोनों में नगर का विभाजन
* बड़ी मिलें नगर से दूर
* ७.८० लाख मकान
* प्लैन पर कुल संभावित व्यय ७५० करोड़
* निम्न आय वाले लोगों के लिए आकर्षक गृह-योजना
* बस व ट्रकों के ठहरने की पृथक् व्यवस्था
* व्यापार, उद्योग व सरकारी दफ्तरों के लिए पृथक्-पृथक् क्षेत्र
* प्रत्येक विभाग में स्कूल, पार्क व चिकित्सालय आदि आदि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यह आपकी दिल्ली है—२

दिल्ली में साक्षरता

साक्षर			कुल प्रतिशत
कुल	पुरुष	स्त्रियां	
१४०२२९८	९०४८०१	४,९७,४९७	५२.७

प्रतिशत की संख्या से दिल्ली का स्थान सब राज्यों से ऊंचा है। दिल्ली के बाद केरल में प्रतिशत ४६.८ है।

दिल्ली में उच्च शिक्षा

विश्व-विद्यालय	१
बोर्ड आफ एजुकेशन	१
कालेज	२२
रिसर्च इंस्टीट्यूट	३
प्रोफैशनल कालेज	१०
सोशल एजुकेशन कालेज	३

दिल्ली में चार राष्ट्रीय उद्योग शाखाएं हैं—नेशनल फ़िज़िकल लैबोरेटरी, सैण्ट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सैण्ट्रल इंण्डियन मैडिसिनल प्लांटस आर्गनाइजेशन और सैण्ट्रल साइण्टिफिक आर्गेनाइजेशन, इंडियन कौंसिल आफ एग्रिकल्चरल रिसर्च, श्रीराम इंस्टिट्यूट फार इण्डस्ट्रियल रिसर्च और नेशनल मलेरिया इंस्टिट्यूट भी दिल्ली में उपयोगी कार्य कर रही है।

दिल्ली से प्रकाशित पत्र

अंग्रेजी	३४९	उर्दू	१३१
हिन्दी	१६६	पंजाबी	२५
बंगला	५	संस्कृत	२
गुजराती	१	उड़िया	१
कन्नड़	३	तामिल	५
मलयालम	४	तेलगू	४
मराठी	२		

द्वैभाषिक	९५
बहुभाषिक	३१
अन्य	१२
कुल	८३६

दिल्ली में सहकारी समितियां [१९६२]

कुल समितियों की संख्या	२०५६
कुल सदस्यों की संख्या	१९७३५२
अपने कोश (रु०)	२०५५९२६६
कर्मचारी पूंजी (रु०)	१३,२७,९५,३५२
डिपाजिट (रु०)	७०,९९,९०,४२१

दिल्ली में रेडियो लाइसेंस

१९५७	८०९३२
१९६०	१२११७२
१९६१	१४९५५२

रेडियो के प्रति जनता की रूचि निरन्तर बढ़ रही है।

नशों की खपत [१९६२]

देशी शराब (लिटर)	५९३१९२
अफीम (किलोग्राम)	६६
भंग ,,	३००३०
विदेश से आयातित वाहन,	
स्पिरिट (लिटर)	५३६२३
बीयर ,,	१००६
भारत में बनी स्पिरिट (लिटर)	३७५६३६
भारत में बनी बीयर ,,	१२२९६१२

सिनेमा से मनोरंजन कर

(आधार वर्ष १९४९)

दिल्ली में सिनेमा का शौक बढ़ता जा रहा है और इस कारण मनोरंजन कर की आय भी बढ़ती जा रही है। नीचे की निदेश अंक तालिका से यह भी मालूम होगा कि अब ऊंचे दरजे के टिकट लेने वालों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक बढ़ रही है।

	१.२५ रु. या कम	१.२५ से २.५० रु.	२.५० से ऊपर	सामान्य
१९५७	२६२	१७६	९१	२३१
१९६०	२७२	२६०	१०७	२६६
१९६२	२५८	३७४	१९०	२८९

सम्पदा

आर्थिक प्रश्नों पर ज्ञानवर्धक सामग्री व स्वतंत्र चिंतन की एक मात्र हिन्दी पत्रिका

१. क्या आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं और परीक्षा में सफल होना चाहते हैं?
२. क्या आप अर्थशास्त्र के अध्यापक हैं और छात्रों को योग्य बनाना चाहते हैं?
३. क्या आप देश के आर्थिक विकास और आर्थिक प्रश्नों में रुचि रखते हैं?
४. क्या आप उद्योग व व्यापार की प्रगति व समस्याओं की जानकारी चाहते हैं?
५. क्या आप पत्रों के सुशिक्षित व विचारशील पाठक हैं?

तो सम्पदा पर विस्तृत सम्मति पत्र पढ़िये, इसमें आप पढ़ेंगे

—कि छात्रों को सम्पदा ने कैसी सहायता दी?
—कि विद्वान प्राध्यापकों व शिक्षाविदों के क्या विचार हैं।
—कि केन्द्र व राज्यों के मंत्री 'सम्पदा' के सम्बन्ध में कितनी ऊंची सम्मति रखते हैं?
—कि प्रमुख उद्योगपति सम्पदा के संबंध में क्या कहते हैं।
और फिर आप सम्पदा मंगाये बिना न रहेंगे।

यह सम्मति-पत्र मंगाने के लिए सिर्फ एक कार्ड लिख कर भेजिये

मूल्य ८.५० रु० वार्षिक

सम्पदा २८/११, शक्तिनगर, दिल्ली—६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देहली का विशालकाय मास्टर प्लान

अनेक कारणों से दिल्ली की आवास समस्या सबसे अधिक विषम है। मास्टर प्लान इसी समस्या का समाधान है। इस खण्ड में मास्टर प्लान, उसके गुण दोष तथा सम्बद्ध विषयों पर विभिन्न पहलुओं से अनेक लेख दिये जा रहे हैं। इन लेखों से पाठक स्वयं इस समस्या से भली-भांति परिचित हो सकेंगे।

दिल्ली की आबादी निरन्तर बढ़ रही है। इसलिए हमारी सबसे कठिन समस्या इस बढ़ती हुई आबादी के लिए निवास का समुचित प्रबन्ध करने की है। यों तो दिल्ली में बाहर से आने वाले विस्थापित पुरुषार्थियों तथा दूसरे गरजमन्द लोगों ने अपनी इच्छानुसार जहां-तहां मकान या झुग्गी झोंपड़ियां बना ली हैं, पर उनमें से अधिकांश निवास-योग्य नहीं है। वहां न पानी की व्यवस्था है, न रोशनी तथा अन्य नागरिक सुविधाओं की। फिर वे संख्या में भी बहुत अपर्याप्त हैं। इसलिए निश्चित योजनाबद्ध विकास की जरूरत थी। भारत सरकार का उद्देश्य समाजवाद की स्थापना है। इसलिए यह भी जरूरी है कि हमारी आवास योजना में समाजवाद के उद्देश्य को ओझल न किया जाए। अर्थात् वह योजना सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होनी चाहिए। गरीबों को भी रहने और जीवन की सब सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकार उसमें मिलना चाहिए। अंग्रेज सरकार ने नई दिल्ली को बसाते समय केवल बड़े बड़े सरकारी अफसरों और अमीरों की सुविधाओं का ही ध्यान रखा था।

दिल्ली के व्यवस्थित विकास के लिए यह भी आवश्यक था कि यह देखा जाए कि अधिक से अधिक कितने लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पानी और बिजली का प्रबन्ध सुविधा से हो सकता है। प्रति व्यक्ति भोजन, स्नान, घर की सफाई और फ्लश आदि के लिए कितना पानी उपलब्ध हो सकता है। इसी तरह घरों की अपनी जरूरतों तथा गलियों व सड़कों के लिए आवश्यक मात्रा में बिजली उपलब्ध करने की सम्भावनाओं की उपेक्षा भी नहीं की जानी थी। उसी के साथ २ बढ़ते हुए यातायात की सब सम्भावनाओं को देखकर छोटी बड़ी सड़कों और पुलों की भी व्यवस्था करनी थी।

किसी शहर में, खास कर दिल्ली जैसी राजधानी में केवल नगर निवासियों की ही व्यवस्था नहीं करनी होती। दिल्ली के नगर निगम, दिल्ली की सरकार और भारत की सरकार के बड़े २ दफ्तरों और विभिन्न सरकारी संस्थाओं के लिए भी भूमि का एक विशाल खण्ड चाहिए। इसी तरह प्रत्येक बस्ती में लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दुकानें चाहिए, व्यापारियों के लिए छोटे-बड़े केन्द्र चाहिए, उनके लिए सैकड़ों छोटे-बड़े गोदाम चाहिए, कार खानों के लिए चाहें वे बड़े उद्योग हो, चाहे लघु अथवा कुटीर उद्योग हों, सबके लिए काफी स्थान चाहिए। नगर निवासियों और उनके बाल बच्चों के लिए अपनी बस्तियों में छोटे २ बाग-बगीचे चाहिए। स्कूलों और कालिजों के विद्यार्थियों के खेलने के लिए मैदान चाहिए, हर एक बस्ती में आवश्यकता के अनुसार स्कूल, कालिज, पुस्तकालय, सिनेमा गृह, बाग-बगीचे और हस्पतालों की भी हमें व्यवस्था करनी होगी और यह ध्यान रखना होगा कि दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी में सभी सुविधाएं यथा सम्भव अपने निकट ही मिल सके। इसी तरह रेलों के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था करनी पड़ेगी। रेलवे स्टेशन, मालगोदाम, मुसाफिरखाना और रेलवे यार्ड आदि उपर्युक्त सब दृष्टियों को सामने रखते हुए दिल्ली के लिए योजनाबद्ध विकास की आवश्यकता देर से अनुभव की जा रही थी।

सितं० ६२ से लागू

दिल्ली का मास्टर प्लान ८ जुलाई १९६० को प्रकाशित किया गया था और इस सम्बन्ध में आपत्ति सुझाव मांगे गए थे। जनता व अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं व केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सम्मतियों पर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विचार करने के बाद पक्का मसौदा किया गया और दिनांक १-९-६२ से मास्टर प्लान लागू कर दिया गया।

२. मास्टर प्लान में सन् १९८१ तक की दिल्ली नगर की रूपरेखा निर्धारित की गई है। इसके अन्तर्गत १०१०४८० एकड़ भूमि आती है। अंदाज है कि सन् १९८१ तक दिल्ली नगर की आबादी ४६ लाख हो जायेगी। इस भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से रखा गया है :

भूमि का उपयोग	क्षेत्रफल एकड़ में	कुल का प्रतिशत
१—घरों के लिए	४७३६०	४२—९
२—बड़े उद्योग	२५६३	२—३
३—औद्योगिक	६०१६	५—४
४—सरकार	८१६३	७—४
५—मनोरंजन	२६१६२	२३—७
६—सार्वजनिक व अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएँ	८८५७	८—०
७—कृषि (पौध)	२९४	०—३
८—परिवहन(रेल को छोड़कर)	२६०४	२—४
९—सड़क-१५० फीट या ज्यादा चौड़े नाले	५९६०	५—३
१०—रेलवे की जमीन (स्टेशनों, अहातों और लाइनों को शामिल)	२५१८	२—३
	१०१०४८७	१००

प्लान की मुख्य सिफारिशें यह हैं :

१. पुराने शहर की घनी आबादी का फैलाव व नई दिल्ली व सिविल लाइन के फैलाव को घना करना।

२. सबसे पहले पुराने शहर में स्कूलों, दवाखानों, खेल-कूद के लिए पार्क व मैदान इत्यादि बनाकर सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबन्ध करना। उसी प्रकार केवल बड़ी व मुख्य सड़कों को ही चौड़ा करना।

३. पटरियों पर सोने वालों को बस्तियों में स्थान देकर आबाद करना ताकि वह पड़ोस में घुलमिल सकें। लगभग ७०,००० से कम आमदनी वाले व्यक्ति प्रतिवर्ष ग्रामीण क्षेत्रों से नगर में आते हैं। उनके रहने की समस्या का हल निकालना। इसके लिए प्लान प्राधिकारी ने कई क्षेत्रों में जगहें निर्धारित कर दी हैं जहां ऐसे वर्ग के लोग सस्ते किस्म के घर बना सकेंगे। केवल उनका नक्शा दिये हुए स्तर के मुताबिक होना चाहिए।

४. उद्योग योजनाओं के लिए जगह को पूरा करना। औद्योगिक क्षेत्र को फैलाने का इरादा है और नगर में १५ जगहों पर खरीददारी के लिए केन्द्र बनाने का प्रस्ताव है जिससे खरीद फरोख्त एक ही स्थान पर केन्द्रित न रहे और नगर के आठों भागों में सब चीजें सुविधा से मिल सकें।

सरकारी दफ्तरों के लिए भी स्थान निर्धारित किया गया है। औद्योगिक विकास के लिए नये क्षेत्र भी रखे गये हैं। सब्जी मण्डी के अलावा दो और बड़ी-बड़ी फलों व तरकारियों की मण्डियों का स्थान रखा गया है। एक ओखला रेलवे स्टेशन के पास और दूसरा सराय रोहेला के निकटदया बस्ती में। अनाजों के गोदाम बनाने के लिए जगह रखी गई है और नया बाजार व जी० बी० रोड के घने इलाकों में अनाज की थोक बिक्री वालों के कार्यालय और फुटकर बिक्री की दुकानें रहेंगी। इसी प्रकार लकड़ी के गोदाम अलग रखे जाएंगे। तेलीवाड़े व देशबन्धु गुप्ता रोड पर केवल फुटकर बिक्री की टालें होंगी। १५ एकड़ का टुकड़ा महरोली रोड पर रेलवे लाइन की क्रासिंग के पास बाजार के लिए रखा गया है। तेल के डिपो के लिए जो कि इस समय रोहतक रोड पर है और वहीं रहेगा व कुछ अधिक जमीन नागलोई, रेलवे स्टेशन, पालम स्टेशन, और शाहदरा में होगी। दक्षिणी दिल्ली में किचनर रोड और रिंग रोड के चौराहे के पास यूनिवर्सिटी केन्द्र बनेगा। २२ नये कालेजों का प्रबन्ध रखा गया है जिसमें से प्रत्येक १५ एकड़ की भूमि पर होगा और ३०-४० एकड़ भूमि पर ५ और यूनीवर्सिटी केन्द्र बनेंगे जिनमें से प्रत्येक पर ४-४ या ५-५ कालेज रहेंगे।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पांच-पांच सौ पलंग वाले २० और अस्पताल बनेंगे, जिसमें प्रत्येक, १५ से २५ एकड़ तक की भूमि पर होगा।

एक नई यूनिवर्सिटी और सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था के लिए इंजीनियरिंग कालेज के दक्षिण-पश्चिम की तरफ ६०० एकड़ भूमि सुरक्षित रखी गई है। यह भूमि सप्रू हाउस के पास जनपथ के पूर्व की ओर और प्रस्तावित नागरिक केन्द्र में इसी आशय के लिए जो भूमि दी जा चुकी है, उसके अतिरिक्त होगी। सीरी गांव के आस पास ४-५ एकड़ भूमि अखिल भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र के लिए भी रखी गई है। प्लान में मनोरंजन व खेल कूद के लिए पार्क, स्कूलों और सामुदायिक केन्द्रों व बाजार के लिए दिल्ली के आठों जिलों में जगह रखी गई है।

शाहदरा के बड़े पैमाने पर विकास के लिए प्लान में एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र और ४ सवारी गाड़ियों के पुल रखे गये हैं। अन्दाजा है कि १९८१ में शाहदरा की आबादी लगभग ७॥ लाख हो जायगी। पुरानी और नई दिल्ली के बीच में दो और बड़ी सड़कें निकालने की भी सिफारिश की गई है। एक सर्कुलर रोड और पार्लियामेंट रोड को मिलाते हुए और दूसरी मथुरा रोड से कालेज रोड और फिरोजशाह रोड को मिलाते हुए। प्लान में बिजली पानी और मैले की गन्दी नालियों पर भी विचार किया गया है तथा बिजली पानी की कलों इत्यादि का प्रबन्ध किया गया है।

मास्टर प्लान के चालू करने के लिए जितनी जमीन सरकार को अधिगृहीत (अक्वायर) करनी है, उसमें से १२००० एकड़ भूमि ली जा चुकी है और विभिन्न सहकारी संस्थाओं में बांटी जा चुकी है।

नगर क्षेत्रों से जमाव दूर करना

अधिकतर सवारी गाड़ियों के खड़ा करने, गोदामों, ग्वालों के मवेशियों और कुम्हारगिरी, बढ़ईगिरी और चमारगिरी आदि पेशों से ही जमवट होता है। सवारी गाड़ियों को हटाने के लिये दूसरी जगहें तैयार की जा रही हैं, जैसे—

(१) काश्मीरी गेट के बाहर की तरफ दूसरे प्रदेशों से आने जाने वाली बसों का अड्डा। दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर वाला बसों का अड्डा इधर ही चला आयेगा।

(२) लाल किले के पीछे रिंग रोड और यमुना नदी के बीच में खाली बसों और गाड़ियों को खड़ा करने का अड्डा।

गोदामों के लिये दो अलग मौके तय किये गये हैं और इनमें से एक की योजना तैयार भी हो गयी है। इस

भारत आर्ट वर्क्स

६/६३७८ नया बांस

दिल्ली-६

फोन : २२७६६४

सरकार द्वारा अपने काम के लिए स्वीकृत व अधिकृत

* लाइन ब्लाक
* हाफ़टोन ब्लाक
* बहुरंगे ब्लाक
* आकर्षक व कलापूर्ण डिजायन और
* सिनेमा स्लाइड

सभी के उत्कृष्ट निर्माता

रंगीन फिल्मों से रंगीन ब्लाक बनाना हमारी अपनी विशेषता है।

भारत आर्ट वर्क्स, ६/६३७८ नया बाँस दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

योजना के चालू हो जाने के बाद तेलीवाड़ा और देशबन्धु गुप्ता रोड के लकड़ी के व्यापारी हट जायेंगे और वहां आने जाने वालों के लिये काफी जगह हो जायगी । साथ ही आग लगने का खतरा भी दूर हो जायगा ।

इसी तरह ५ ऐसे गांवों का भी विकास किया जा रहा है, जो नगर की सीमा से बिल्कुल लगे हुए हैं । ग्वालों, कुम्हारों इत्यादि को इन्हीं गांवों में बसाने का निश्चय है ।

"दिल्ली में ५ प्रतिशत धनी हैं, १५ प्रतिशत मध्यम वर्गीय हैं और शेष ८० प्रतिशत गरीब हैं। गरीबों से निवास के लिए जमीन की खरीद की कीमत और उसके विकसित करने का खर्च लिया जायेगा। धनियों को सार्वजनिक नीलामी के आधार पर जमीनें दी जायेंगी।

"अगर योजना को सफल बनाना है तो कोल्हू में पीस कर साधन पैदा करना होगा वरना उत्थान का दूसरा मार्ग नहीं है।" —श्री भगवान सहाय

दिल्ली विकास अधिनियम १९५७ के अनुसार पहले क्षेत्र (ज़ोन) के विकास की योजना तैयार की जानी है, जिसके आधार पर विस्तृत योजना बनाई जाएगी । सन् १९८१ तक तक के नगर-क्षेत्र को ८ भागों में बांटा गया है जिनमें कुल १३६ क्षेत्र (ज़ोन) बनेंगे ।

निम्न आय वालों के लिए

दिल्ली में घरों की अत्यधिक कमी को कम करने के लिए खासतौर से गैर-सरकारी वर्गों के लिये, दिल्ली विकास प्राधिकारी ने "किराया-खरीद-बीमा आवास योजना" को बनाया है । खासतौर से निम्न व मध्यम आय वाले वर्गों के फायदे के लिए इस योजना के अनुसार नये डिजाइन के दुमन्जिले घर या दो-दो कुनबों के रहने लायक बने बनाये घर जनता के लिये तैयार किये जायेंगे । घर का किराया खरीद मूल्य खरीदने वाले के बीमा के अनुसार होगा। इससे लाभ यह होगा कि यदि खरीदार जल्दी मर जाय तो घर खुदबखुद उसके परिवार की जायदाद हो जाएगा और इस तरह एक बहुत बड़ी बुनियादी जरूरत का स्थायी प्रबन्ध हो जायगा ।

व्यावहारिक पहलू

कागज पर कोई योजना बना लेना जितना आसान है उतना ही कठिन उसे क्रियान्वित करना है । मास्टर प्लान को भी व्यावहारिक रूप देना आसान काम नहीं है । दिल्ली की पुरानी गलियों में बहुत घनी आबादी है । बहुत सी गलियां अंधकार पूर्ण हैं, इनमें मकान छोट २ कबूतर खाने से लगते हैं । इन सबको फिर बसाना और खुली जगह भेजना जहां भारी खर्च की अपेक्षा रखता है, वहीं लोगों को बाहर जाने के लिए तैयार करना भी बहुत दुःसाध्य कार्य है। इसी तरह विरला मिल, दिल्ली क्लाथ मिल आदि मिलों को वर्तमान स्थान से हटाकर दूर भेजने में करोड़ों रु. का व्यय है।

दिल्ली की समस्त जनता को आश्रय देने के लिए योजना निर्माताओं ने यह अनुमान लगाया है कि ७.८५ लाख मकान बनाने पड़ेंगे। इनमें से १.५ लाख मकान तो सरकारी कर्मचारियों के लिए ही आवश्यक है और १.१ लाख मकान कम आमदनी वालों के लिए १४.८५ लाख निजी मकानों की भी आवश्यकता पड़ेगी । इन मकानों के निर्माण पर ही करीब ६५० करोड़ रु० के व्यय की संभावना है । समस्त योजना पर ७५० करोड़ रु० के व्यय का अनुमान किया गया है ।

फिलहाल विकास संस्था को ५ करोड़ रु० दिये गये हैं, जिनसे यह आस पास की जमीन खरीद सकेगी । एक स्थान पर १०० एकड़ जमीन खरीद कर वह सहकारी समितियों या मकान बनाने वालों को बेच देगी, और इससे आया हुआ रुपया वह दूसरी जमीन खरीदने के काम में लगेगा । इस तरह यह ५ करोड़ रुपया बार २ इस्तेमाल होगा । मिलों को नई जमीन बहुत कम कीमत पर मिल जाएगी और उन्हें अपनी पुरानी जमीन बेचने का अधिकार रहेगा । इस जमीन को वे अच्छे दामों में बेचकर मिलों के पुनः निर्माण का भारी खर्च वसूल कर सकेंगे ।

यह समस्त विशाल योजना दोषरहित है, यह कोई भी नहीं स्वीकार करता, किन्तु इसे यथासंभव आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का प्रयत्न अवश्य किया गया है । लेकिन इसकी सफलता कागजी योजना पर नहीं, व्यावहारिक कठिनाइयों पर विजय पाकर ही अमल में लाने पर निर्भर करती है । इसलिए १०-१५ या २० वर्ष बाद ही इस प्लैन पर कोई निश्चित सम्मति दी जा सकेगी । ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मास्टर प्लान : नियंत्रण व विलम्ब

चौ० ब्रह्मप्रकाश संसद सदस्य

निवास या उद्योग के लिए मकान बनाना हो तो उसके लिए निम्नलिखित की आवश्यकता अनिवार्य होती है :

१. भूमि सुलभ हो और उसका मूल्य ऐसा हो, जो बनाने वाले की सामर्थ्य से बाहर न हो।

२. मकान बनाने के लिए आवश्यक साधन। यदि अपने पास रुपया न हो तो किसी तरह रुपये की व्यवस्था अवश्य हो सके।

३. मकान का नक्शा और उसकी अधिकारी संस्था द्वारा स्वीकृति।

४. जहां निवास या कारखाने के लिए मकान बनाया जाए, वहां बिजली और पानी की व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिए। मकान बनाकर भी यदि पानी और उसके निकास का (सीवर, ड्रेनेज) का प्रबन्ध नहीं होगा, तो रहना ही मुश्किल हो जायेगा।

५. निवास-क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा चिकित्सा और मनोरंजन आदि का प्रबन्ध भी अवश्य होना चाहिए।

इन सब चीजों की व्यवस्था जहां सुलभता से हो सके, उसका प्रबन्ध किसी सुनिश्चित योजना या मास्टर प्लान के द्वारा ही हो सकता है। मास्टर प्लान एक ऐसी सुनियोजित व्यवस्था है, जिसमें समस्त प्राप्त होने वाली भूमि को ऐसे ढंग से बांटा जा सकता है, जहां मकान या कारखाना बनाने वाले को उक्त सुविधाओं के साथ-साथ यह भी देखना आवश्यक है कि इन सब भूमि खण्डों में यातायात की पर्याप्त सुविधा हो, आवश्यकता से अधिक भीड़-भाड़ न हो। दिल्ली का मास्टर प्लान इसी दृष्टि से बनाया गया है। समस्या केवल आज की नहीं है। हमें जो योजना बनानी है, उसमें आगे के बीस वर्ष बाद आनेवाली समस्याओं का ध्यान भी रखना है।

कैसे प्लान बना ?

दिल्ली के नये मास्टर प्लान में अधिकारियों और इंजीनियरों ने अपनी सम्पूर्ण आवश्यकताओं का अनुमान किया और मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर विचार किया। समस्त प्रदेश को उन्होंने अनेक विभागों में बांट

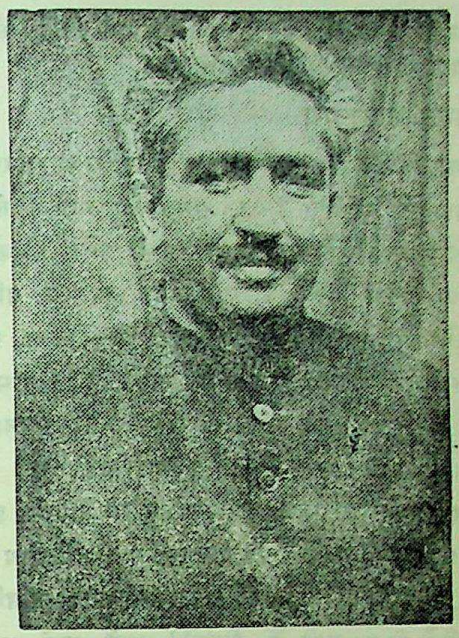

लेखक

दिया और फिर प्रत्येक विभाग में सब नागरिक सुविधाएं मिल सकें, इसकी भी बाकायदा योजना बनाई। एक-एक विभाग की विस्तार से जांच पड़ताल की गई और सारी जमीन नापी गई। यह भी देखा गया कि उस विभाग में कितनी आबादी हो सकती है। कितने छोटे या बड़े और किस संख्या में प्लाट बन सकते हैं, और उसके लिए पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, हस्पताल आदि की कितनी आवश्यकता होगी। अब तक करीब दो दर्जन विभागों (ज़ोन) की विस्तृत योजना तैयार हो सकी है।

नियंत्रण आवश्यक

लेकिन इस योजना को कागजों पर लिख लेने से काम नहीं चलता। यदि लोग अन्धाधुन्ध अपनी इच्छा से मकान बनाते जायें, तो मास्टर प्लान की योजना धरी-धराई रह जायगी। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार मकानों के निर्माण पर दृढ़ नियंत्रण करे। इसीलिए सरकार ने हजारों एकड़ जमीन जब्त कर ली है, जिसका खरीदना

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और बेचना सरकारी आज्ञा के बिना नहीं हो सकेगा। सरकार उसी टुकड़े पर मकान बनाने की स्वीकृति देगी, जिसका योजना-बद्ध विकास कर लिया जायगा, अर्थात् जहां पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, पार्क आदि की एक निश्चित व्यवस्था कर ली जायगी।

विलम्ब अनिवार्य

यह ठीक है कि इस नियंत्रण और सब सुविधाओं की आवश्यक व्यवस्था में बहुत समय लग जाता है, लेकिन यह तो अनिवार्य है। बिजली, पानी और सड़कों की व्यवस्था करोड़ों रुपये के व्यय और वर्षों के परिश्रम की अपेक्षा रखते हैं। और ऐसे कार्यों में कितना समय लगेगा, इसकी पाठक कल्पना कर सकते हैं? इसलिए मकान बनाने के इच्छुक लोगों को कुछ धैर्य तो रखना ही होगा। अभी तो विकास विभाग के पास आर्किटैक्टों और इंजीनियरों की भारी कमी है। इसलिए भी विभिन्न इलाकों के अध्ययन और नक्शे आदि बनाने में अधिक समय लग रहा है, फिर भी ऐसी भवन-निर्माण सहकारी समितियों को जमीनें दी जा चुकी हैं, जिन्होंने पहले स्वयं जमीनें खरीद ली थीं और बाद में जब्त कर ली गई थीं।

मास्टर प्लान का एक मुख्य उद्देश्य उन कालोनाइजरों के हाथ से दिल्ली की भोली-भाली और गरजमन्द जनता को बचाना है जो बिना किसी निश्चित योजना से बनी बस्तियों को लोगों के मत्थे मढ़ देते हैं और अपने पैसे खरे कर लेते हैं, जहां न पानी की सुविधा रहे और न काफी पार्क आदि की। अनधिकृत बस्ती बसाने वाले कालोनाइजर वस्तुतः हमारे आने वाले बच्चों के साथ खून की होली खेल रहे हैं।

दो ही विकल्प

मास्टर प्लान के अनुसार विकास में विलम्ब तो हो रहा है, परन्तु इसके सिवाय और दूसरा चारा ही नहीं है। हमारे सामने दो ही विकल्प हैं। एक यह कि जनता को आवश्यक सुख सुविधाएं पहुँचाने के लिए नियंत्रण किया जाय और उसमें कुछ विलम्ब को सहन किया जाय, दूसरा विकल्प यह है, कि सरकार किसी तरह का नियंत्रण न करें और दिल्ली में अराजकता और अव्यवस्था (केयास) फैल जाय। यह निश्चित है कि विलम्ब, परन्तु नियंत्रित व्यवस्था को लोग अधिक पसन्द करेंगे, और जल्दबाजी तथा अव्यवस्था को कम।

भूमि का मूल्य

मास्टर प्लान की योजना के अनुसार जो जमीन दी जा रही हैं, वह करीब २५-२६ रु. गज की कीमत से दी जा रही हैं। यह कहा जाता है कि यह मूल्य बहुत अधिक और अनुचित है। सरकार को इतनी मुनाफाखोरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन वस्तुस्थिति की जानकारी इस आरोप को मिथ्या प्रमाणित कर देगी। आज साधारणतः किसानों को ५ रुपये गज जमीन की कीमत देनी पड़ती है। पहले के कालोनाइजर २ रुपये गज से अधिक नहीं देते थे और उसमें भी केवल ३० प्रतिशत भूमि गलियों और सड़कों के लिए रखकर शेष ७० प्रतिशत खरीदारों को बेच देते थे। अब सरकार ५ रुपये गज की कीमत से जमीन खरीदती है और ६० प्रतिशत जमीन सड़कों, पार्कों, स्कूलों, हस्पतालों आदि के लिए निकाल कर केवल ४० प्रतिशत भूमि खरीदारों को बेचती है। और इस पर भी ७½ रु. प्रति गज भूमि के विकास पर खर्च करना पड़ता है। इस तरह भूमि २०-२२ रु. प्रति गज बैठती है। ३ रु. प्रतिगज उसे व्यवस्था सम्बन्धी खर्चा तथा आवर्तक कोष के लिए लेना पड़ता है। इस तरह मास्टर प्लान में न "लाभ और न हानि" का स्थान सामने रखा गया।

पट्टे पर

मास्टर प्लान के अन्तर्गत सारी भूमि पट्टे पर दी जाती है, और खरीदार को बिना इजाजत के बेचने का हक नहीं है। यदि वह बेचेगा तो अतिरिक्त मूल्य का ५० प्रतिशत सरकार को भी देना होगा।

इसी तरह जमीन केवल उसीको दी जायगी, जिसके पास पहले दिल्ली राज्य में कोई अपना प्लाट या मकान न हो। इसका भी मुख्य कारण यह है कि हमारा उद्देश्य समाजवाद की स्थापना है। हम नहीं चाहते, कि अमीर लोग कई कई प्लाट खरीद कर भारी मुनाफा कमावें। पट्टे की स्थिति में ही भूमि के क्रय विक्रय पर सरकार कोई न कोई नियन्त्रण कर सकती है।

• •

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देहली में आवास की समस्या

श्री प्रो० बलराज मधोक

पश्चिम में उद्योगीकरण के फलस्वरूप आबादी का देहातों से कस्बों और नगरों की ओर आना एक सुविदित घटना है। यही बात अब भारत तथा एशिया के अन्य विकासशील देशों में हो रही है। १९६१ की जनगणना के अनुसार अधिकांश भारतीय नगरों में आबादी की एकदम वृद्धि हो गयी है।

दिल्ली और कलकत्ता की आबादी

यह वृद्धि दिल्ली और कलकत्ता इन दो नगरों में विशेष रूप से हुई है, जिसका बड़ा कारण पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों का बड़ी संख्या में आना है। दिल्ली की आबादी १९४१ में जहां केवल ५ लाख के लगभग थी, वहां १९६१ में वह २६ लाख के करीब हो गयी है और अब ३० लाख से अधिक का अनुमान है। देश की राजधानी होने के साथ-साथ वृद्धिशील व्यापारिक और औद्योगिक केन्द्र होने से आगामी कुछ वर्षों में दिल्ली की आबादी में तीव्र वृद्धि की आशा है।

आबादी की इस बढ़ती ने सर्वत्र आवास की समस्याओं को पैदा कर दिया है। दिल्ली में यह समस्या विशेषतः उग्र है। १९५७ में जब दिल्ली का "मास्टर प्लान" बनाया जा रहा था, उस समय १,२५,००० बकानों की कमी का अनुमान था। उस समय यह घोषणा की गयी थी कि प्रति वर्ष दिल्ली को २५,००० नयी निवास इकाइयों की आवश्यकता होगी, ताकि आबादी की वार्षिक वृद्धि का मुकाबला किया जा सके। १९६२ में जब "मास्टर प्लान" अन्तिम रूप में प्रकाशित हुई, तब इस संख्या को बढ़ाकर ३०,००० तक कर दिया गया।

इस समूची मांग को और बकाया चली आ रही कमी को पूरा करने के लिए बड़े विस्तृत पैमाने पर गृह-निर्माण के कार्य को हाथ में लेना आवश्यक था। राज्य के लिए यह सुअवसर था कि वह भूमि-विकास और गृह-निर्माण के काम को हाथ में लेते हुए निजी क्षेत्र में पहले से ही नियुक्त संस्थाओं के काम को व्यवस्थित करता हुआ उनका सहयोग प्राप्त करता।

लेखक

दिल्ली प्रशासन का गलत कदम

पर दिल्ली प्रशासन ने इस मार्ग को अपनाने के बदले समस्त भूमि विकास के कार्य पर १८९२ विकास के भूमि अधिग्रहण कानून की धारा ४ के अन्तर्गत एकाधिकार करने, प्राप्त करने व निरोध लगाने का निश्चय किया। लगभग ५०,००० एकड़ भूमि—जिसमें निजी कालोनाइजरों और सहकारी गृह निर्माण सोसाइटियों की भूमि भी शामिल थी—दिल्ली प्रशासन ने यह युक्ति देकर जब्त कर लिया कि वह स्वयं इसका विकास करेगा तथा टाउन प्लेनरों ने जो विशिष्ट रूप निश्चित किये हैं, उनके अनुसार करते हुए आम जनता के लिए यह विकसित प्लाट मकान बनाने के नाम से उपलब्ध कर लिये।

गत चार वर्ष से दिल्ली प्रशासन और उसकी विभिन्न संस्थाएं—डेपलेवमेंट एथारिटी—इस मामले में चुप बैठी हुई हैं। इसने अभी तक दो हजार प्लाट भी विकसित नहीं किये हैं, जबकि समस्त निजी संस्थाओं को बाहर धकेल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिया गया है । इससे भी बुरी बात यह है कि विकसित प्लाटों का मूल्य २७ रु० प्रति वर्ग गज से ५० रु० प्रति वर्ग गज तथा प्रति वर्ष कुछ लीज़ की राशि — घोषित किया गया है, जबकि निजी कालोनाइजर इनकी होल्ड प्लाटों का बढ़िया इलाकों में १५ रु० से २० रु० प्रति वर्ग गज तक बेच रहे थे । इसका परिणाम यह हुआ है कि पुरानी आबादी के इलाकों और कालोनियों को छोड़कर नये मकान पिछले चार वर्षों से बनने रुक गये हैं, जबकि आबादी का बोझ बढ़ रहा है । इसका एक परिणाम यह निकला है कि किराये १०० प्रतिशत से एकदम चढ़कर ३०० प्रतिशत तक हो गये हैं । राजेन्द्र नगर और डिफेन्स कालोनी जैसी कालोनी में दुगुने किराये हो गये हैं और दो कमरों के फ्लेट का किराया, सामान्यतः १५० रु० से २०० रु० तक हो गया है । इसके परिणामस्वरूप, विकसित प्लाटों के दाम भी बहुत ऊंचे चढ़ गये हैं । पिछले दिनों चाणक्यपुरी में सरकार के लोककर्म विभाग द्वारा नीलाम किये गये प्लाट, कल्पनातीत रूप से, २०० रु० से ४०० रु० प्रति वर्ग गज तक बिके ।

अनधिकृत मकानों की वृद्धि क्यों ?

एक औसतन नागरिक के लिए, चाहे वह नौकरी पेशा हो व व्यापारी हो, इतना अधिक किराया व प्लाट का मूल्य देना सम्भव नहीं है । इसलिए वह अविकसित भू-खंड पर अनाधिकृत मकान बनाने अथवा सरकारी जमीन पर "झुग्गी-झोंपड़ी" बनाने की ओर झुक जाता है । पिछले चार वर्षों में झुग्गी व गंदी बस्तियों की वृद्धि तेजी से बढ़ गयी है और राजधानी की हरेक रिहायशी कालोनी के पास इस प्रकार की गन्दी बस्तियां अनिवार्य हो गयी है । जब सरकार इन अधिकृत बस्तियों को गिराने लगती है, तब जनता की ओर से हिंसात्मक प्रतिक्रिया होती है, जैसा कि गत मार्च में निमड़ी कालोनी में हुआ । यहां के हताश लोगों ने ६ मार्च को नगर-निगम के कार्यालय पर हमला करके निगम अधिकारियों को पीटा । निगम पार्षद डर के मारे भाग गये । मूल बात यह है कि जनता छत चाहती है, वह मौजूदा किराया देने में असमर्थ है । इसलिए वह निगम के भ्रष्टाचारी अधिकारियों के साथ मिलकर अथवा उनकी जान बूझ की चुप्पी से फायदा उठाकर कानून को अपने हाथ में लेने पर उतारू हो जाती है । कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या भी अनधिकृत मकान बनाकर रहती है ।

लाठी प्रहार समस्या का हल नहीं

बड़ी-बड़ी लाठियां चलाकर अथवा अनधिकृत मकानों को गिरा देने से इस समस्या का हल नहीं हो सकता । अब स्थिति ऐसी आ गयी है कि इस समस्या को ज्यादा टाला भी नहीं जा सकता । स्पष्ट है कि सरकार स्वयं तो इस समस्या का हल करने में असमर्थ है । इस दिशा में उसे सबसे पहला कदम यह उठाना चाहिए कि भूमि-विकास के बारे में वह "एकाधिकार की मनोवृत्ति" छोड़ दे । उसे निजी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करते हुए सहकारी आवास-निर्माण संस्थाओं के लिए भूमि मुक्त करते हुए उन्हें न्यूनतम विशिष्टीकरण दे देना चाहिए ताकि वे शीघ्र भवन-निर्माण-कार्य प्रारम्भ कर सकें । फिलहाल, सूखी टट्टियों वाली कलोनी ही स्वीकृत की जाएं, जिससे, कम से कम, गन्दी बस्तियों की वृद्धि तो रुक जाए । निगम सेवाओं के लिए कुछ विकास-व्यय अग्रिम लिया जा सकता है ।

सरकार स्वयं सस्ते मकान बनाए

इसका दूसरा उपाय यह है कि सरकार स्वयं विभिन्न टाइपों के अपने मकान बनाये । ऐसे मकान जनता को उधार-पट्टे के आधार पर, आमदनी को दृष्टि में रखते हुए, दिये जाने चाहिए । कम आमदनी के लोगों को दिल्ली में छत के नीचे बसाने का यही तरीका है । इस आयोजन के प्रारम्भिक खर्च को पूरा करने के लिए कुछ प्लाटों के निश्चित प्रतिशत को सरकार नीलाम कर सकती है । जो लोग मकान का मूल्य दे सकते हैं, उनसे प्राप्त रकमों के द्वारा सरकार कम आय वालों के लिए मकान मुहैया कर सकती है ।

हमारे ये कुछ सुझाव हैं । इन पर पूर्ण रूप से और गहराई के साथ विचार करने के लिए एक सशक्त उच्च समिति कायम की जानी चाहिए । पश्चिमी जर्मनी और इजरायल द्वारा इस समस्या के हल करने के ढंग से भी लाभ उठाया जा सकता है । ••

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भूमि-सुधार कानून व उसकी गति

श्री गोपीनाथ अमन, अध्यक्ष जन-सम्पर्क समिति, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली

जब सन् १९५२ में दिल्ली विधान-सभा बनी तो जिन बातों पर सबसे पहले विचार आरम्भ हुआ, उनमें से एक दिल्ली का भूमि-सुधार कानून भी था। मुझे भूमि सुधार कमेटी का प्रधान बनाया गया था। यह उस समय की बात है, जब मैं मंत्री नहीं बना था और दिल्ली विधान-सभा का उपाध्यक्ष था। पहले कांग्रेस-पार्टी में इस सुधार की चर्चा हुई। कारण यह था कि दिल्ली में दो कानून चल रहे थे — एक पंजाब का और एक उत्तरप्रदेश का — और यह एक आश्चर्यजनक बात थी कि उत्तरप्रदेश का सन् १९०१ का कानून दिल्ली में लागू था। इन ५१ वर्षों में उत्तरप्रदेश में भूमिधारी के ४ कानून बदल चुके थे, परन्तु दिल्ली में वही कानून लागू होता चला आया, जो पहले उत्तरप्रदेश में था। विचार यह हुआ कि ऐसा कानून बनाया जाय जो दोनों को मिला कर एक कर दे। यह विधेयक सन् १९५३ में तैयार हुआ और सन् १९५४ में इसने कानून का रूप धारण कर लिया। परन्तु कुछ सज्जनों ने इसके विरुद्ध हाईकोर्ट (उच्च न्यायालय) में दावा दायर कर दिया। इसलिये सन् १९५५ से इस पर पूरी तरह अमल दरामद शुरु हुआ। इसके साथ-साथ पंचायत राज का विधेयक था। उसकी तो अजीब गति हुई। सन् १९५४ में दिल्ली की विधान-सभा ने यह कानून बनाया। सन् १९५५ में राष्ट्रपति ने उसकी स्वीकृति दी, परन्तु उसके साथ-साथ उसके नियम भी बनने थे। विचार था कि दो वर्ष के भीतर उसके नियम बन जायेंगे परन्तु हुआ यह कि नवम्बर सन् १९५६ में दिल्ली विधान-सभा टूट गई और उसी के साथ नियम बनाने का काम भी कुछ ढीला पड़ गया। होते-होते यह हुआ कि सन् १९५९ में ये नियम बने। इस बीच में दिल्ली नगर निगम का विधेयक भी बना। नगर निगम का चुनाव भी हो गया और अप्रैल सन् १९५८ को नगर निगम स्थापित भी हो गया। इससे एक अजब सूरत पैदा हो गई। पंचायत राज के नियम नगर निगम बनने से पहले बन जाते तो नगर निगम के विधेयक में उसका लिहाज रखा जाता, परन्तु कानून और

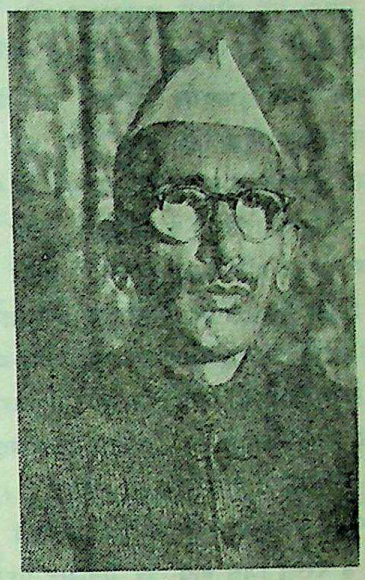

लेखक

नियम के बीच में जो साल का समय बीता, उसका यह परिणाम हुआ कि बहुत-सी बातें नगर निगम के कानून में और पंचायतों के कानून में परस्पर-विरोधी हो गईं। हमारे भूमि-सुधार के कानून में 'कार्पोरेशन' का तो कोई ज़िक्र नहीं और न हो सकता था, क्योंकि वह तो सन् १९५४ में बन चुके थे और नगर निगम का कानून सन् १९५७ में बना। भूमि सुधार के कानून में पंचायत राज के कानून का हवाला था। जब यह सब स्थिति गृह-मंत्री स्वर्गीय गोविन्द वल्लभ पन्त के सामने पहुँची तो उन्होंने अपनी सलाहकार समिति से एक विधेयक पेश कराया, जिसमें परस्पर-विरोधी धाराओं का समन्वय किया गया था। यह तो थी एक कठिनाई।

दूसरी कठिनाई यह थी कि दिल्ली में सिन्ध और सीमा प्रान्त से आये हुये सज्जनों को जिनके पास वहां भूमि थी, यहां भी भूमि दी गई। पंजाब के विस्थापितों को केवल सर दातार सिंह को छोड़कर पंजाब में भूमि मिली। अब जिन लोगों को दिल्ली में भूमि मिली, उन पर दिल्ली के भूमि-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सुधार कानून को लागू नहीं किया गया, क्योंकि दिल्ली विधान-सभा केन्द्र के मातहत (अधीन) थी। परिणाम-स्वरूप यहां कोई ऐसा विधेयक नहीं बन सकता था, जिसका केन्द्र के कानून से विरोध हो। इस मामले को लेकर उस समय के मुख्य-मंत्री चौधरी ब्रह्मप्रकाश और मैं (जो उस समय कृषि-मंत्री था) भारत सरकार के मंत्रियों के पास जिनमें स्वर्गीय रफी अहमद किदवाई भी थे, गये परन्तु उन्होंने साफ कह दिया कि किसी राज्य का बनाया हुआ कानून हमारे केन्द्र के कानून के विरुद्ध नहीं हो सकता। इस-लिये जो भूमि कस्टोडियन के मातहत है जो विस्थापितों को, पंजाब, सरहद और बलोचिस्तान में छोड़ी हुई भूमि के बदले में मिली है, उस पर दिल्ली भूमि-सुधार कानून को लागू नहीं किया जा सकता। इसका परिणाम यह हुआ कि जो भूमि विस्थापितों को मिली, उसमें खेती करने वालों को भूमि-धारी का अधिकार नहीं मिला। उदाहरण के रूप में, मुकुन्दपुर का मामला पेश किया जा सकता है। विस्तार से तो कुछ कहने की बात नहीं क्योंकि कचहरी में मामला चल रहा है परन्तु जिस बात पर मत-भेद पैदा हुआ, वह यही थी कि जो लोग वहां कई पीढियों से खेती कर रहे हैं, वे अपना भूमिधारी का अधिकार चाहते हैं और जो पंजाब के विस्थापित सज्जन भूमि के मालिक बने हैं, उनका कहना है कि इस भूमि पर भूमिधारी का कानून लागू नहीं हो सकत।।

दिल्ली में भूमिधारी की एक कठिनाई और भी है कि अभी तक ऐसे गांव हैं, जिनमें सन् १९०१ का उत्तर प्रदेश का कानून लागू है, क्योंकि जिन ग्रामों का अर्ध-नागरिक या नागरिक ग्राम माना गया, उन पर भूमि सुधार का कानून लागू नहीं हुआ, इसलिये वहां वही पुराना उत्तर प्रदेश का कानून चलता आ रहा है। यह बात तो जमना पार के गांवों की हुई जो शाहदरा के इलाके में हैं। इस पार भी ऐसे गांवों पर भूमि सुधार का कानून लागू नहीं है।

एक और कठिनाई भू-राजस्व कानून (लैंड रेवेन्यू एक्ट) की है। यह कानून भी दिल्ली की विधान-सभा ने भूमि सुधार और पंचायती-राज के कानून के साथ बनाया था, परन्तु नियम बनाने में इतनी देर लगी कि १ मार्च, १९६३ को वे लागू हुये। यूं समझिये कि विधेयक बनने और नियम के साथ कानून के लागू होने में १० वर्ष का अन्तर रहा। इसे विधान-सभा के टूट जाने के कारण समझिये या इस कारण कि केन्द्रीय शासन में होने के कारण पग-पग पर भारतीय-शासन का सहारा लेना पड़ता है उसका सुंह देखना पड़ता है।

सारांश यह कि दिल्ली में गांव तो बहुत थोड़े हैं—३६० गांव छट कर अब ३०० से भी कम रह गये हैं परन्तु यहां की समस्याएं बहुत जटिल हैं। ग्रामों के अर्ध-नागरिक बनने के कारण केन्द्रीय-शासित होने के कारण, केन्द्रीय शासन के इतना निकट होने के कारण और यहां की जनता की जानकारी और वाचाल-शक्ति अधिक होने के कारण दिल्ली की दूसरी समस्याओं की भांति यहां की भूमि-सुधार की समस्या भी बहुत जटिल है। पंचायत-राज और नगर निगम के परस्पर-सम्बन्ध का मामला अभी तक कोई निश्चित रूप धारण नहीं कर सका। दिल्ली प्रशासन ने तो अपनी ओर से पंचायत और पंचायत समितियों को अधिकृत कर दिया है, परन्तु नगर निगम में अभी यह समस्या विचाराधीन है, शायद नगर निगम का रूपान्तर होने पर यह समस्या सुलझ सके।

भूमि सुधार

१२ मार्च १९५९ को भारत के राष्ट्रपति ने संसद द्वारा पारित दिल्ली भूमि सुधार (संशोधित) अधिनियम १९५९ पर अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसके अन्तर्गत ३०६ गांवों पर यह नियम लागू होता है। इन सब गांवों में बिचौलियों को समाप्त किया जा चुका है और ३८४९४ एकड़ के क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों के ८०३६ मुजायरों को भूमिधारी बना दिया गया है। मुआवजे की राशि ११६५००० रु. है। अब काश्तकारों का प्रशासन से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया है।

बेकार पड़ी समस्त भूमि गांव-सभाओं को बांट दी गई है, चकबन्दी का कार्य बहुत थोड़े गांवों में हो सका है, बहुत से गांव पहाड़ी या नदी घाटी और शहरी क्षेत्र होने के कारण चकबन्दी के योग्य भी नहीं हैं।

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली में सिंचाई

किसी भी देश या राज्य के आर्थिक विकास में सिंचाई और बिजली का असाधारण महत्व होता है। किन्तु दिल्ली का यह दुर्भाग्य है कि यहां सिंचाई के साधन बहुत अपर्याप्त हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि दिल्ली के विकास में यहां की विदेशी सरकारों का ध्यान केवल नगर के विकास और बड़ी-बड़ी सड़कों के निर्माण की ओर ही अधिक गया। उनकी दृष्टि में सम्भवतः दिल्ली के देहातों का कोई महत्व ही नहीं था। यही कारण है कि नई दिल्ली के निर्माण पर जहां करोड़ों रुपया खर्च हुआ, वहां देहातों के किसानों की प्रमुख आवश्यकता सिंचाई की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया।

पश्चिमी जमना नहर

दिल्ली में सिंचाई का बड़ा साधन पश्चिमी जमना नहर है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस नहर के विस्तार की योजना बनाई गई थी, लेकिन इसकी सफलता के लिए पंजाब सरकार का सहयोग अनिवार्य था। वह उसे नहीं मिला। इस लिए दिल्ली सरकार का ध्यान छोटी सिचाई योजना की ओर अधिक गया। स्थान-स्थान पर कुएं तथा विद्युत कूप खोदे गए और थोड़ा बहुत नहरों में भी विस्तार किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना की समीक्षा के अनुसार ९९० नए कुएं खोदे गए, १२० पुराने कुओं की सफाई की गई, ३२ विद्युत कूप लगाए गये, ३०४ रहट के कुएं खोदे गये हैं। इन सब प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप १५ हजार नई एकड़ भमि में सिंचाई हो सकी।

सिंचाई की प्रगति

निम्नलिखित तालिका से मालूम होता है, कि पिछले कुछ वर्षों में सिंचाई की दृष्टि से किस गति से प्रयत्न हुआ:

	१९५८-५९	५९-६०	६०-६१	६१-६२
१ कच्चे कुएं	४०	९३	१३	४
२ पक्के कुएं	२३०	२३६	२४७	१२२
३ कच्चे कुओं का जीर्णोद्धार	१८	३२	१	०
४ पक्के कुओं का जीर्णोद्धार	१८२	१३९	३७	२४
५ ट्यूब वैल	०६	८	१४	२५
६ पम्प सैट	२२	१६	२९	१२
७ रहट	१२५	३७४	१४९	९३
८ अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र (एकड़)	३४८३	२७२७	१९०७	१४४३
९ जोत के योग्य नई भूमि (,,)	५८६	६७३	६०२	१०५

खेती योग्य केवल २.८७ लाख एकड़ जमीन में से २.१७ लाख एकड़ भूमि में खेती हो पाती है, जिसमें से ८८ लाख एकड़ में नहर या कुंओं से सिंचाई होती है।

शाहजहां के समय से

ओखला नहर १८८३ ई० में जारी की गई थी, किन्तु इससे पहले दिल्ली के मुगल बादशाह शाहजहां के समय उसके प्रमुख इंजीनियर अली-मरदानखां १६२६ ई० में पश्चिमी जमना नहर का प्रारंभ कर चुके थे।

वस्तुतः दिल्ली की अर्थ व्यवस्था में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण भाग नहीं है। दिल्ली की कुल जनसंख्या का करीब ८वां भाग देहातों में रहता है और उसमें से भी एक भाग ऐसा है, जो खेती पर गुजर नहीं करता। यही कारण है कि दिल्ली की अर्थ व्यवस्था में खेती का भाग बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा। दिल्ली शहर के निरन्तर बढ़ते रहने के कारण तो आस पास के खेत और बाग बगीचे नागरिक बस्ती में परिणत होते जा रहे हैं। इस लिए यह आशा भी नहीं करनी चाहिए कि दिल्ली राज्य में सिंचाई का महत्व बढ़ जाएगा।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली में ग्राम-रक्षा संगठन

लेखक—श्री आनन्द शंकर शर्मा

सामुदायिक विकास आज की नई परिस्थितियों में पंचायतों के द्वारा का नया मोड़ ल रहा है, स्वावलम्बन की भावना उत्पादन के बढ़ाने में किस तरह सहायक हो रही है, श्रम बैंक व ग्राम सेवा के रूप में दिल्ली के ग्रामों में कैसा उत्साहजनक प्रवृत्तियां चल रही हैं, इसका परिचय इस लेख में पढ़िये।

देश के इस वर्तमान संकट में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को एक नवीन रूप दिया गया है और वह है लोकतन्त्र के आधार पर सारे ग्रामवासियों की महान् शक्ति का सदुपयोग। और यह कार्य सौंपा गया है ग्राम पंचायतों को। दिल्ली की ३ लाख २५ हजार ग्रामीण जनता ने इस योजना का मुक्त हृदय से स्वागत किया है और प्रत्येक पंचायत ने इस विषय में अपने ग्रामवासियों को उचित मार्गदर्शन कराने का दृढ़ संकल्प किया है।

गणतन्त्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर दिल्ली के ३०५ गांवों में सार्वजनिक सभाएं की गईं, जिनमें सर्वप्रथम प्रधान मंत्री नेहरूजी का ग्राम पंचायतों के नाम संदेश सुनाया गया। उसके पश्चात् सारी सभाओं में उन वीर जवानों व अफसरों के प्रति सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिन्होंने मातृभूमि की मर्यादा और अखंडता की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। साथ ही, उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा की कि चीनी आक्रमण से उत्पन्न इस राष्ट्रीय संकट का सामना करने के लिये वे समस्त साधन जुटाकर भारत की पवित्र भूमि से आक्रान्ता को निकालकर ही दम लेंगे। प्रधानमंत्री के आदेशानुसार ग्राम सभाओं ने यह निश्चय किया कि किसी समीप कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त ग्राम स्वयंसेवक दलों की स्थापना की जाये। नवयुवकों में सुरक्षा के प्रति एक अपूर्व उत्साह व जोश की लहर उमड़ रही है और सब एक होकर आपसी भेदभाव भुलाकर अग्नि परीक्षा देने को तत्पर हैं।

लेखक

ग्राम पंचायतों ने यह अपना पवित्र कर्तव्य समझा है कि राष्ट्रीय संकट में देश के सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत करें।

उत्पादन अभियान

दलपतियों ने तुरन्त ही मजबूत ग्राम सेना बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाये और नवयुवकों की भर्ती प्रारम्भ कर दी गई। अब यह अनुमान है कि दिल्ली के पांच विकास खण्डों से चुनी हुई ग्राम सेना की संख्या २० हजार के लक्ष्य को पार करके २५ हजार तक पहुँच जायेगी। इस कार्य में युवक मंडलों ने सक्रिय रूप से भाग लिया है। इस समय दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में १२० मंडल हैं।

उत्पादन, जन शिक्षा व ग्राम रक्षा

दलपतियों के नेतृत्व में त्रिसूत्रीय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और उस पर दृढ़ता से कार्य आरंभ हो गया है। राजधानी के निकट होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में हरी सब्जी, तरकारी, मुर्गी पालन व पशुपालन पर

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विशेष ध्यान दिया गया है। दिल्ली प्रशासन के विकास विभाग ने हरी सब्जी व तरकारियों के उत्पादन बढ़ाने हेतु एक अभियान चालू किया है और योजना के अनुसार खंड व पंचायत स्तर पर पूरे तालमेल का प्रबन्ध कर दिया है। उत्पादन बढ़ाने की विशेष जिम्मेदारी ग्राम सेना पर डाल दी गई है। सब्जियों की खेती के लिए उत्तम बीज का प्रबन्ध हो चुका है और बादली, कारोनेशन पिलर व ओखला से खत्ते के खाद व गंदे पानी के खाद का वितरण शीघ्रता के साथ हुआ है।

पंचायतों का प्रशंसनीय कार्यक्रम

कई पंचायतों की कार्य सेनाओं ने इस विषय में उल्लेखनीय कार्य किया है। हरेवली की ग्राम सेना ने अपने दलपति के नेतृत्व में कुछ ही दिनों में नहर के दहानों की मरम्मत करली और जिन खेतों में पानी जाने के लिये नालियां नहीं थीं, वहां सिंचाई की सुविधाओं का प्रबन्ध कर दिया है।

दिल्ली के गांवों में सहकारी सेवा समितियों का जाल सा बिछा हुआ है। इस समय सारे देहात में ३८५ समितियां हैं और बहुत से गांवों में एक से अधिक समितियां भी हैं। अब इनकी सदस्यता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे सदस्यों को आवश्यक प्रथम व दूसरी सुविधाएं मिल सकें। मदनगिर गांव का प्रत्येक परिवार सहकारी सेवा समिति का सदस्य है और समिति ने किसी बाहरी संस्था से कर्जा नहीं लिया है। समिति का कार्य सराहनीय है। साथ ही हरी सब्जी व तरकारियों के उत्पादन के साथ-साथ, माल की बिक्री के प्रबन्ध पर भी विचार किया गया है। यह योजना बनाई गई है कि सब्जी की ९ मंडियां और खोली जायें, जिससे बीच के दलालों का मुनाफा समाप्त हो जायगा और किसानों को अपनी उपज के दाम मिल सकेंगे। सब्जी व फलों को कोल्ड स्टोरेज में रखने की भी योजना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्राम सभाओं की सार्वजनिक भूमि खेती-बाड़ी के लिये उठा दी गई है, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो।

महिलाओं ने आभूषण दे दिये

महिला शाखाएं अपने स्वयंसेवक दल की ४५ महिला शाखाएं बना चुकी हैं और बनने जा रही इन शाखाओं ने रक्षा कोष और बाध्य बचत कार्य, बुवाई, सिंचाई के अतिरिक्त गांवों में जवानों के परिवारों की देख-भाल की जिम्मेदारी को सम्भाल लिया है। हरियाने की महिलाएं सदा से वीर जननी रही हैं और उन्हें अपने शूरवीर पुत्रों के पराक्रम पर गर्व रहा है, जिसका इतिहास साक्षी है। इस बार भी उन्होंने जवानों को उनकी आरती उतारकर व शत्रु से दृढ़ता के साथ लोहा लेने की प्रतिज्ञा लेकर मोर्चे पर भेजा है।

महरौली खण्ड की विराट सभा में ग्रामीण महिलाओं ने अपने सोने, चांदी के आभूषण श्रीमती इंदिरा गांधी को देकर इस बात का परिचय दिया कि वे पुरुषों से किसी बात में पीछे नहीं रहना चाहतीं। साथ ही महरौली विकास खंड ने अपने बचत कार्यों से सारे देश के लिये उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस खंड का सारे देश भर में पहला स्थान आया है।

अनुशासन का महत्व

ग्राम स्वयं सेवक दलों के लिये शारीरिक कार्यक्रम व ड्रिल का प्रबन्ध अनिवार्य है। इसके लिये एक योजना बनाई गई है, जिससे प्रत्येक सदस्य को आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। जनता कालिज अलीपुर में प्रशिक्षणों का विशेष प्रबन्ध किया गया है। इसके अन्तर्गत कार्यकर्त्ताओं को आग से सुरक्षा, प्राथमिकता चिकित्सा, स्वास्थ्य, सफाई, ग्राम रक्षा कार्यक्रम आदि का प्रशिक्षण दिया गया है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि दल के सदस्यों में अनुशासन में रहने की भावना बलवती हो गई है जिससे रक्षा प्रयासों में बड़ी सहायता मिल सकेगी। अलीपुर, नजफगढ़, मवाना, नरेला, महरौली, कंझावला, फतहपुरबेरी, नांगलोई व लाडोसराय के गांवों में एक महीने का प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षक कोर्स दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त महरौली व शाहदरा के खंडों के महिला कल्याण केन्द्रों में प्राथमिक सहायता के प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया गया है, जो लाभप्रद सिद्ध हुआ है।

१२ दिवस का श्रम बैंक

दिल्ली के ग्रामवासियों की श्रमदान में सक्रिय योग देने

(शेष पृष्ठ ६५ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली में बिजली की अपर्याप्त व्यवस्था

यदि नहरी सिंचाई को दिल्ली में कोई खास महत्त्व प्राप्त नहीं है तो इसका यह अर्थ नहीं कि सिंचाई या बड़े-बड़े बांधों से सम्बद्ध बिजली का भी दिल्ली में कोई महत्त्व नहीं है। दिल्ली नगर की जनसंख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है और यहां छोटे बड़े उद्योग बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं। इसलिए बिजली की मांग भी निरन्तर तेजी से बढ़ रही है। देश के दुर्भाग्य-पूर्ण विभाजन के बाद दिल्ली की आबादी बहुत तेजी से बढ़ गई और यहां सैंकड़ों छोटे बड़े दफ्तरों, विभिन्न देशों के छोटे-बड़े राजदूतावासों की स्थापना के कारण भी बिजली की खपत निरन्तर बढ़ती गई। उद्योगों की संख्या किस गति से बढ़ी, यह इस तालिका से स्पष्ट है: —

वर्ष	संख्या	वर्ष	संख्या
१९४५	२२५	१९५०	४५०
१९५६	७२५	१९६०	१०६१

बीसियों उद्योग ओखला और नजफगढ़ की उद्योग पुरियों में खुल गये। दिल्ली के चारों ओर बीसियों छोटे बड़े सुन्दर नगर बन गए—इन सब उद्योगों के विकास का परिणाम यह हुआ कि दिल्ली में बिजली की खपत निरन्तर बढ़ती जा रही है।

पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में दिल्ली में कुल तीन बिजली घर थे—सैंट्रल पावर स्टेशन, बेलारोड और लाहोरी गेट। इन तीनों स्टेशनों की उत्पादन क्षमता कुल ३४.७८६ किलोवाट थी और असल में इतनी बिजली भी आसानी से उत्पन्न नहीं होती थी।

पहली योजना में ९६ सौ किलोवाट के दो इंजन लगाये गये। परिणामतः पहली योजना के अन्त में दिल्ली में बिजली की उत्पादन क्षमता करीब ४५ हजार किलोवाट हो गई। किन्तु वस्तुतः ४० हजार किलोवाट से अधिक बिजली उपलब्ध नहीं होती रही। पंजाब सरकार से एक समझौता किया गया, जिसके अनुसार नांगल की १० हजार किलोवाट बिजली दिल्ली को मिलने लगी, और इस तरह प्रथम योजना के अन्त तक दिल्ली में ५० हजार किलोवाट बिजली प्राप्त हो गई।

लेकिन दिल्ली की आवश्यकता बढ़ती जारही थी। यह अनुमान किया गया कि १९६०-६१ तक दिल्ली को कम-से-कम १४,६०० किलोवाट बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद अनेक योजनाएं बनी, जिन्हें दूसरी पंच वर्षीय योजना में थोड़ा बहुत क्रियान्वित भी किया गया। राजघाट, लाहौरीगेट और किलोकरी में तीन नए डीजल स्टेशन स्थापित किये गये। चन्द्रावल में भी एक स्टेशन बनाया गया। इन सब प्रयत्नों का परिणाम यह हुआ कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ८० हजार किलोवाट बिजली उपलब्ध होने लगी।

यह सब प्रयत्न भी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकते थे। केवल उद्योगों की ही आवश्यकता नहीं बढ़ती जा रही थी, नगर निवासियों का जीवन स्तर भी बढ़ रहा था। हर एक नागरिक अपने घर पंखा, रेडियो लगाने को उत्सुक था। चूल्हा और प्रैस आदि की जरूरतें भी बिजली से पूर्ण करने की इच्छा हर एक गृहिणी करने लगी। प्रशासकों ने गांवों को भी सब्ज बाग दिखाते हुए गांवों में बिजली लगाने का आश्वासन दिया था। यह भी पूर्ण करना था। दूसरी योजना के अन्त तक ५०, गांवों में बिजली पहुँचा दी गई। तीसरी योजना के प्रारम्भ में कुछ अन्य गांवों को भी बिजली से जगमग करने की योजना पर अमल शुरू होगया। अब तक १०८ गांवों में बिजली आगई है।

१९६१ के अन्त तक बिजली के उत्पादन और बिजली की खपत की निम्नलिखित दो तालिकाओं से आजकल की स्थिति बहुत अधिक स्पष्ट हो जायगी।

बिजली का उत्पादन

(किलोवाट, घन्टे हजारों में)

औसत प्रतिमास

वर्ष	स्टीम से उत्पन्न	गैस डीजल से उत्पन्न	नागल से खरीद	कुल उपलब्ध बिजली
१९६०	२५,०७०	...	...	...

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१९६१	२१,९७९	३३,५९	१४,७०३	४०,०४३
१९६१	२०,२८६	२,२३३	२२,०५४	४४,५७३

बिजली की खपत

(किलोवाट घण्टे हजारों में)

	घरेलू	व्यापार और छोटे उद्योग	सेना आदि के लिए	खेती सिंचाई गली रोशनी
१९६०	७,३४४	६,१३४	१३,०९८	१,४६२
१९६१	६,६८४	५,३१०	१६,४६३	८८२
१९६२	७,४७५	५,९७८	१८,१३२	९९४

	सार्वजनिक कार्य व नालियों के पम्प	कुल बिजली की खपत
१९६०	३,४७४	३१,५०९
१९६१	२,९२०	३२,२५९
१९६२	४,३००	३५,९७७

आज यह अनुभव किया जा रहा है कि बिजली का उत्पादन और पंजाब से खरीद की वर्तमान मात्रा काफी नहीं है। भिन्न-भिन्न छोटे बड़े उद्योगों के लिए बिजली की मांग बढ़ रही है। समय समय पर दिल्ली में बिजली का फेल हो जाना और शहर के भिन्न-भिन्न मार्गों का अन्धकार में डूब जाना आम बात हो गई है।

म्यूनिसिपल कारपोरेशन की एक रिपोर्ट से मालूम होता है कि १९५८-५९ में यदि दिल्ली इलैक्ट्रिक सप्लाई अण्डरटेकिंग को २५२ लाख रु० बिजली के बिलों से वसूल हुए थे तो १९६०-६१ में ३८९ लाख रु. वसूल हुए हैं। इसी अवधि में बिजली का उपयोग करने वालों की संख्या १,०७४५४ से बढ़कर १६८००० हो गई है। भूमिगत केबल बिछाने की १ करोड़ रु. की योजना बनाई गई है।

दिल्ली का आकार नये-नये उपनगरों के निर्माण द्वारा निरन्तर बढ़ रहा है। वाटर वर्क्स को भी बढ़ने के लिए अधिक बिजली चाहिए। इसलिए आज आवश्यकता यह है कि बिजली घरों में नए संयंत्र लगाए जाए और पंजाब सरकार से जहां नांगल में बिजली बहुत तैयार होती है, अधिक बिजली ली जाए। तभी दिल्ली के बढ़ते उद्योगों को लाभ हो सकता है।

(पृष्ठ ६३ का शेष)

की परम्परा रही है। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश गांवों को जीवन की आवश्यक सुविधायें प्राप्त हो गई है। ग्रामवासियों ने दूसरी योजना में स्वेच्छापूर्वक २२ लाख रुपये नकदी व श्रमदान के रूप में दिये हैं। इस कारण श्रम बैंक की योजना उन्हें नई नहीं लगी है। प्रत्येक परिवार के वयस्क ने एक महीने में एक दिन अर्थात् एक वर्ष में १२ दिन का श्रमदान देना स्वीकार कर लिया है, जो बैंक के आधार पर सुरक्षित रहेगा और आवश्यकता के समय उपयोगी सिद्ध होगा। जो वयस्क अस्वस्थता या और किसी कारण से श्रम दान न कर सकेंगे, उनसे उसका मूल्य लिया जावेगा। इस प्रकार श्रमदान का अब व्यापक रूप हो गया है और प्रत्येक गांव का वयस्क समुदाय इसमें सम्मिलित है। इस संगठित श्रमदान से सिंचाई की नालियों की समस्या धीरे-धीरे हल होती जा रही है। श्रमदान के उपयोग का पूरा भार गांव पंचायतों पर है।

दिल्ली के ग्राम प्रधानों व कार्यकर्ता स्वयं पूरे त्याग व बलिदान के लिये तत्पर है और प्रत्येक कठिनाई का दृढ़ता व एकता के साथ मुकाबला करने के लिए कटिबद्ध हैं।

For Better Results
USE
MICRO
High Class
Padders and Trimmers
Manufactured by:
MICRO
Electronics Corpn.,
NEW DELHI।
Sole Distributors:
Jeewan Radios,
RADIO PLACE,
DELHI-6.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चुनौती का पक्का जवाब

इस वर्ष तीसरी जनवरी को जमशेदपुर इस्पात कारखाने के 'ई' ब्लास्ट फर्नेस को बुझाया गया कि फिर से लाइनिंग हो, बढ़ाया भी जाय। वह बहुत बड़ा काम था जिसमें २१०० टन रीफ्रेक्टरी, १७०० मीटर पाइप, ७६०० मीटर बिजली का केब्ल और ११०० टन इस्पात तथा कास्टिंग लगती थी।

जब १८० दिनों की मूल समय-सूची को आधा करके ९० दिन किया गया तो बहुत-से लोगों ने उसे असंभव ही समझा। मगर टाटा स्टील के कुछ इंजीनियरों, टेकनीशियनों और मजदूरों ने इस चुनौती को मंजूर किया और ८४ दिनों में काम पूरा कर डाला, अर्थात् बेहद कड़ी समय-सूची से भी ६ दिन पहले ही।

प्रति दिन ३१५ टन की योग्यता का यह 'ई' ब्लास्ट फर्नेस ४५ वर्ष पहले अमेरिका में पुराना ही खरीदा गया था। अब इसकी योग्यता को बढ़ाकर सिंटर बोझ के बिना प्रति दिन ६६० टन और सिंटर तथा साइज्ड आयरन ओर के साथ ७२५ टन किया गया है।

रेकार्ड तोड़नेवाली यह सफलता मिलजुल कर पक्का काम करने, तकनीकी जानकारी और कम से कम खर्च से अधिक से अधिक उत्पादन करने की लगातार कोशिश का और भी एक उदाहरण है जो जमशेदपुर की खूबी है जहाँ उद्योग सिर्फ रोजी-रोटी का एक जरिया ही नहीं बल्कि जिंदगी का रास्ता है।

जमशेदपुर
इस्पात नगरी

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में खुलकर दान दीजिये

JWTN 11

The Tata Iron and Steel Company Limited

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कपड़े की भारी मंडी दिल्ली

दिल्ली भारत की राजधानी है। समस्त देश की शासन व्यवस्था की बागडोर केन्द्रीय सरकार दिल्ली ही चला रही है। यह देश की राजधानी दिल्ली वर्तमान से ही नहीं, प्राचीन काल से चली आ रही हैं। यह देश की धुरी है, साथ ही साथ देश के मध्य में स्थित है। बम्बई, कलकत्ता मद्रास आदि देश के प्रमुख शहरों से करीब १००० मील की दूरी पर है। सुरक्षा और शासन की दृष्टि से देश की राजधानी के लिए अन्य कोई ऐसा उपयुक्त स्थान नहीं है।

श्री ब्रजभूषण सरन
अध्यक्ष, हिन्दुस्तानी मर्केन्टाइल असोसियेशन

शताब्दियों पूर्व से

दिल्ली की प्रसिद्धि और प्रमुखता केवल राजधानी के कारण ही नहीं है, बल्कि कपड़ा व अन्य वस्तुओं के वितरण केन्द्र से भी है। दिल्ली प्राचीन काल से कपड़े का प्रमुख केन्द्र चला आ रहा है। ६००-७०० वर्ष पूर्व के बने कपड़े के पुराने कटरे इसके साक्षी हैं। मुगल शासकों के काल में भी यह कपड़े का वितरण केन्द्र रहा है। ढाका की महीन मलमल, चंदेरी व बनारस का सिल्की जरी और कमखाब का कपड़ा, फर्रुखाबाद की छींटे व गिलाफ तथा देश भर के जुलाहों के हाथ के बने कपड़ों का वितरण केन्द्र दिल्ली था। जिस समय अहमदाबाद का नाम निशान भी नहीं था, बम्बई एक छोटा सा शहर था, उस समय भी दिल्ली कपड़े का बड़ा वितरण केन्द्र था।

इस समय दिल्ली कपड़ा वितरण की दृष्टि से उत्तर भारत का प्रमुख केन्द्र है। यहां से भारत के सभी राज्यों को विशेषकर उत्तर-प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल, मध्य प्रदेश आदि स्थानों को कपड़ा जाता है। विभाजन से पूर्व दिल्ली मंडी से कपड़ा पूर्व को असम, व पश्चिम से काबुल और कन्धार तक जाता था। इस समय दिल्ली मण्डी से ७०-८० करोड़ रुपये के मूल्य का वार्षिक कपड़ा बाहर जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ३ वर्ष पूर्व दिल्ली से करीब ५५६६०००० गज कपड़ा प्रतिमाह अन्य स्थानों को निर्यात होता था। दिल्ली मण्डी में बम्बई, अहमदाबाद, मद्रास, कानपुर आदि से आयात होता है। इसमें ८७ प्रतिशत भाग देश की अन्य मंडियों को निर्यात होता है। इधर दिल्ली की कपड़ा मिलों में उत्पादन भी होता है। इस उत्पादन का ९० से ९५ प्रतिशत भाग अन्य मण्डियों को निर्यात होता है। समस्त देश में जितने सूती व ऊनी और रेशमी कपड़े का उत्पादन हो रहा है, उसका १३ प्रतिशत भाग दिल्ली के थोक व्यापार द्वारा विक्रयार्थ वितरण किया जाता है। इस समय देश में कपड़े (सूती ऊनी और रेशमी) का उत्पादन ६२,५४,६०,००० मीटर प्रतिमास है। इसमें से दिल्ली बाजार में प्रतिमास ८२२९६००० मीटर कपड़ा थोक व्यापार से बिकता है।

दिल्ली मण्डी में ९० हजार कपड़े की गांठें (प्रति गांठ में करीब १०००० मीटर कपड़ा) प्रतिमाह आकर कपड़ा व्यापारियों को बेची जाती है। इसका मूल्य करीब १२ करोड़ २५ लाख रु० होता है। कपड़े का यह विक्रय करीब १२०० कपड़े के व्यापारियों के द्वारा होता है। इसमें से दिल्ली में सिर्फ १०६०० करोड़ की गांठें प्रतिमाह खपती हैं, जिनका मूल्य २ करोड़ ६७ लाख रुपये होता है।

दिल्ली में प्रत्येक व्यक्ति ४ गज प्रति माह के हिसाब से कपड़े की खपत है। दिल्ली में कलकत्ता, बम्बई आदि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रमुख शहरों के मुकाबिले में ऊनी कपड़ा अधिक खपता है। वैसे दिल्ली में कपड़े की खपत में सूती ७५ प्रतिशत और ऊनी ५ प्रतिशत पड़ता है। गत १० वर्ष से दिल्ली में रेशमी, नकली रेशमी, कपड़े की भी खपत काफी बढ़ गई है। इसकी खपत शहर के मुकाबले में देहाती क्षेत्र में अधिक है।

व्यापारी और एजेंट

दिल्ली में १२००-१५०० कपड़े के थोक व्यापारी है। बम्बई, अहमदाबाद, इन्दौर, कानपुर तथा अन्य उत्पादन केन्द्रों से वहां के एजेन्टों की मार्फत थोक कपड़ा खरीद करते हैं। ये थोक व्यापारी इस कपड़े को दिल्ली में स्थित कमीशन एजेन्टों को जिनकी संख्या २५ है, बेचते हैं। कमीशन एजेन्ट कपड़े के वितरण में अपना कार्य करता है। वह एक रुपया प्रति सैंकड़ा कमीशन थोक व्यापारी से तथा ८ आना प्रति सैकड़ा खरीद व्यापारी से लेता है। दिल्ली मंडी में कपड़े का पूर्ण वितरण इन कमीशन एजेन्टों द्वारा होता है, जबकि बम्बई में कमीशन एजेन्टों द्वारा ७५ प्रतिशत ही वितरण होता है। दिल्ली में प्रतिदिन हजारों व्यापारी, दुकानदार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आदि से आते हैं और कपड़े की कोठियों के माध्यम से कपड़ा खरीदते हैं। ये व्यापारी कपड़ा खरीदकर कोठी में छोड़ जाते हैं। ये कपड़े की कोठियां गांठें व बिल्टी तैयार कराकर माल भिजवा देती है। ऐसा करने से व्यापारी को समय की बचत और बहुत सुविधा होती है।

दिल्ली मंडी में जो सूत और कपड़ा बाहर से आकर वितरण होता है, उसके सन् १९६२ के उपलब्ध आंकड़े निम्न प्रकार हैं,

माल	मनों में
१—सूती व ऊनी कपड़ा और सूत	१७६२६३२
२—रेशमी कपड़ा और सूत	२६७३६

इससे ऐसा अनुमान होता है कि सूत का भाग कुल कपड़े के भाग का ५ प्रतिशत तथा रेशमी कपड़े का भाग २ प्रतिशत है। इस कारण राजधानी में सूती कपड़े का आयात १६७४५०० मन और रेशमी कपड़े का आयात २६२०१ मन है। इसमें करीब ६८ प्रतिशत सूती तथा ७२ प्रतिशत रेशमी रेल द्वार बाहर से आता है। शेष कपड़ा सड़क मार्ग द्वारा पहुँचता है।

दिल्ली में कपड़े का अधिक आयात बम्बई और अहमदाबाद से होता है। इसके अतिरिक्त मद्रास, इन्दौर तथा उत्तर प्रदेश के नगर कानपुर और मोदी नगर से भी होता है।

आयात

दिल्ली हिन्दुस्तानी मर्कन्टाइल एसोसियेशन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विभिन्न स्थानों से माल निम्न प्रकार आयात होता है—

स्थान	आयात भाग
बम्बई और अहमदाबाद	५५ प्रतिशत
मद्रास और इन्दौर	१०-१५ प्रतिशत
कानपुर और मोदीनगर	५-१० प्रतिशत
काश्मीर आदि अन्य स्थानों से	५ प्रतिशत

नकली रेशमी कपड़ा उत्तर भारत में मोदीनगर, टांडा और बनारस से तथा पंजाब में अमृतसर और लुधियाना से आता है।

निर्यात

दिल्ली खास की खपत के मुकाबले में दिल्ली मंडी से अन्य स्थानों के लिए कपड़े का निर्यात अधिक होता है। नीचे की तालिका बताएगी कि दिल्ली मन्डी से किस-किस प्रान्त के लिए कितना कितना भाग निर्यात के रूप में जाता है।

स्थान	निर्यात प्रतिशत भाग
पंजाब	३० प्रतिशत
उत्तर प्रदेश	२० ,,
हिमाचल प्रदेश	५ ,,
राजस्थान	२० ,,
जम्मू और काश्मीर	५ ,,
बिहार	२ से ३ ,,
नैपाल	२ से ३ ,,
मद्रास बम्बई बंगाल और आसाम	५ ,,

दिल्ली के थोक व्यापारी के अतिरिक्त कपड़े की खुदरा दुकानें करीब ३००० से ऊपर हैं। ये दुकानें दिल्ली के हर

(शेष पृष्ठ ७० पर)

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली के व्यापार की समस्याएं

श्री ओ. पी. अग्रवाल

दिल्ली के व्यापारियों की भी प्रायः वही समस्याएं हैं, जो अन्य व्यापारिक नगरों की हैं। यूनाइटेड चैम्बर आफ ट्रेड एसोसिएशन ने अखिल भारतीय उद्योग वाणिज्य संघ में जो प्रस्ताव विचारार्थ इस वर्ष भेजे थे, उनके उल्लेख से हमें दिल्ली के व्यापारियों की सामान्य समस्याओं का ज्ञान हो जाता है।

१. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अधिकतम योगदान और सहयोग का विश्वास तथा मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण का निश्चय,

२. बिक्री कर को उत्पादन कर में सम्मिलित कर लेने की आवश्यकता।

३. टेलीफोन के दरों में कमी

४. औद्योगिक वित्तीय नियम की अप्रयुक्त धनराशि को ऋण के रूप में व्यापारियों को देने की व्यवस्था।

५. बिक्री कर के लिए एक परामर्श समिति की आवश्यकता।

६. बढ़ते हुए व्यापार और उद्योग की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए रेलवे की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता।

७. आयातनीति में ऐसे सुधार, जिनसे उद्योग और व्यापार के मार्ग में बाधा न हो।

इन प्रस्तावों से ज्ञात होता है, कि दिल्ली की व्यापारिक और आर्थिक समस्याएं अन्य नगरों से भिन्न नहीं है।

दिल्ली के चीफ कमिश्नर को कुछ समय पूर्व व्यापारियों की उक्त संस्था की ओर से एक आवेदन पत्र दिया गया था। उससे दिल्ली की अनेक समस्याओं पर कुछ प्रकाश पड़ता है। सबसे बड़ी आवश्यकता यातायात की व्यवस्था में विकास की है। दिल्ली नगर की बढ़ती हुई निर्माण सम्बन्धी आवश्यकताओं को देखते हुए तथा दिल्ली के वितरण केन्द्र की दृष्टि से भी यह आवश्यक है, कि यहां ट्रकों की संख्या २ हजार की बजाय ५ हजार कर दी जाय।

दिल्ली के पास कोई समुद्र तट नहीं है, किन्तु इसका व्यापारिक महत्व बढ़ता जा रहा है। इसलिए यदि स्वीट-जरलैंड और चैकोस्लोवेकिया की तरह दिल्ली को भी एक स्थलीय बन्दरगाह (Dry Port) के रूप में परिणत कर दिया जाय, तो दिल्ली के द्वारा भारत के उत्तरी प्रदेश की सुविधाएं और भी बढ़ जायंगी। रेलवे के यातायात में भी नई आवश्यकताओं के साथ बहुत परिवर्द्धन करना चाहिए। टोकियो की प्रणाली के अनुसार रिंग रेलवे का निर्माण बहुत शीघ्र होना चाहिए ताकि लोगों को विभिन्न स्थानों और अपने दफ्तरों तक पहुँचने में अधिक विलम्ब न हो। अब बसों पर बहुत देर लगती है, तथा उनकी प्रतीक्षा में भी बहुत समय नष्ट हो जाता है।

दिल्ली के उद्योग, जो अधिकांश लघु और मध्यम उद्योगों की श्रेणियों में आते हैं, निरन्तर बढ़ रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि मास्टर प्लान में उनके लिए पर्याप्त क्षेत्र की गुंजायश रखी जाय। नजफगढ़, नरेला, बदरपुर और शाहदरा में अनेक खण्ड एक सुनिश्चित योजना के आधार पर उद्योगों के विकास के लिए निश्चित कर देने चाहिए। इन क्षेत्रों में उद्योगों के लिए पानी, बिजली आदि की सब सुविधाएं देनी चाहिए। दिल्ली में बिजली की खपत बहुत तेजी से बढ़ रही है। उद्योग के जरूरतों, बढ़ती हुई आबादी और सरकारी व गैर-सरकारी दफ्तरों के निर्माण के कारण भी बिजली तथा पानी की खपत लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन दुःख की बात यह है कि बिजली की व्यवस्था असन्तोषजनक है। कोयला भी दिल्ली में बहुत दूर से आता है। वह भी पर्याप्त मात्रा में सुलभ नहीं होता। इसलिए और भी अधिक आवश्यक है कि बिजली की उपलब्धि यहां पर्याप्त मात्रा में हो।

सभी जानते हैं कि दिल्ली व्यापारिक वितरण का एक बड़ा केन्द्र है। दिल्ली की आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार ही व्यापार और वाणिज्य है, इसलिए यहां बड़े-बड़े गोदामों का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। मास्टर प्लान में जहां रिहायशी मकानों, स्कूलों, अस्पतालों और पार्कों की व्यवस्था के लिए ध्यान दिया चाहिए, वहां यह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भी आवश्यक है कि भिन्न-भिन्न स्थानों पर अच्छे गोदाम भी, जो प्रायः दुकानों के निकट हों, सुलभ बनाये जावें।

दिल्ली अनाज की बड़ी मण्डी है। यहां लाखों रुपये के अनाज का व्यापार प्रतिदिन दिल्ली के व्यापारियों द्वारा होता है। दीर्घकालीन अनुभव के कारण यहां के व्यापारी बहुत अच्छा कारोबार कर रहे हैं। इसलिए यदि अनाज के व्यापार को कभी सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, जिस की आशंका समय-समय पर की जाने लगती है, तो दिल्ली के अनाज के व्यापार को इससे बड़ा धक्का लगेगा।

चुंगी के सम्बन्ध में भी व्यापार और उद्योग को समय-समय पर कुछ कठिनताएं आती रहती हैं। इस तरह ट्रकों और रेलवे वेगनों से माल उतारने व लादने आदि के सम्बन्ध में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर समय-समय पर सरकार का ध्यान खेंचा जाता है। यों तो ये समस्यायें प्रायः सभी नगरों में समान रूप से रहती हैं लेकिन दिल्ली के वितरण केन्द्र होने से इनका महत्व कुछ अधिक हो जाता है। बिक्री कर भी देश के अन्य भागों की तरह से दिल्ली में भी एक समस्या ही है। ● ●

बच्चों की जिन्दगी न्यारी ही होती है। उन्हें खेल-कूद से बड़ा ही प्यार होता है... और उन्हें ऐसा ही प्यार है माल्टेक्स बिस्कुटों से। साठे माल्टेक्स बिस्कुट उन्हें अतिरिक्त शक्ति देते हैं जो कि क्या बच्चों और क्या बड़ों की रोजमरी की जिन्दगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है!

साठे बिस्कुट
पीढ़ियों के लिए शक्ति!

साठे बिस्कुट एण्ड चॉकलेट कं. लि., पूना-२

(पृष्ठ ६८ का शेष)

हिस्से तथा उपनगरों तक में हैं। दिल्ली में खुदरा कपड़ा दुकानदार की औसत पूंजी ५०,००० रुपये है। दिल्ली में खुदरा कपड़े की बिक्री का वार्षिक औसत १ लाख रुपये के करीब पड़ता है। विक्रय कर के आंकड़े बतला रहे हैं कि १९५५ में [illegible] २००० रु० का कपड़ा बिका था। १९५६ के ९ माहों में ७६२०१[illegible] रुपये का कपड़ा बिका था।

कपड़ा कर्मचारी

दिल्ली में थोक तथा खुदरा कपड़े की दुकानों पर काम करने वाले मुनीमों, सैलसमैनों की संख्या [illegible] से अधिक है। इसके अतिरिक्त [illegible] उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी पल्लेदार, हाथ ठेले वाले, बड़े ठेले [illegible] कोठियों में काम करने वाले मुनीम खरीद करने वाले, नौकर-चाकर [illegible] की संख्या करीब १८००० है। दुकानदारों के अतिरिक्त दिल्ली फेरी से कपड़ा बेचने वालों की संख्या करीब ३५०० है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली के व्यापार और उद्योग

भारत के भिन्न-भिन्न बड़े नगरों में दिल्ली का अपना एक स्थान है। आज दिल्ली केवल राजनैतिक दृष्टिसे ही महत्त्व नहीं रखती, व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से भी इसका महत्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

वितरण केन्द्र

दिल्ली रेलवे की दृष्टि से बहुत सुविधाओं का केन्द्र है। इसके राजधानी होने के कारण देश के भिन्न-भिन्न भागों से इसका सम्बन्ध रेलवे और सड़कों के द्वारा बहुत बढ़ चुका है। यही कारण है कि बड़े-बड़े बहुत उद्योग न होते हुए भी दिल्ली व्यापार की दृष्टि से एक अच्छा वितरण केन्द्र है। पंजाब, पश्चिमी उत्तरप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, नेपाल और मध्यप्रदेश के व्यापारी प्रायः दिल्ली से ही अपना माल मंगवाते हैं। मुख्य वितरण केन्द्र की यह स्थिति आज से नहीं, कई दशाब्दियों से चली आ रही है। यदि हम कई शताब्दियां कहें तो भी कोई अत्युक्ति न होगी। शाहजहां की दिल्ली शताब्दियों से भारत का आकर्षण बनी हुई है। सभी राज्यों के व्यापारी अपना माल यहां बेचते हैं और प्रायः समीपवर्ती राज्यों के छोटे-बड़े दुकानदार यहां से माल ले जाते रहे हैं। कपड़े का तो यह बहुत अच्छा वितरण केन्द्र रहा है। सब्जी का व्यापार भी लाखों रुपये का प्रतिदिन का होता है। गोटा, किनारी यहां का अपना ही उद्योग रहा है।

आज भी दिल्ली व्यापारिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, यह यूनाइटेड चेम्बर आफ ट्रेड एसोसियेशन की उस सूची से मालूम हो जाता है, जिसमें उसके भिन्न-भिन्न सदस्य संगठनों की परिगणना की गई है। हम यहां उन संगठनों का नाम निर्देश करना चाहते हैं। इससे यह मालूम हो जायगा कि आज दिल्ली में कितने प्रकार का व्यापार और कितने प्रकार के उद्योग चलते हैं। स्थानाभाव से हम इन संगठनोंका पृथक् परिचय नहीं दे सकते।

१. आल दिल्ली सराफा एसोसिएशन
२. आल इण्डिया रेडियो मर्चेन्ट्स एसोसियेशन (डी० जोन)
३. दिल्ली वनस्पति मर्चेन्ट्स एसोसिएशन
४. व्यापार एसोसिएशन (सदर बाजार)
५. क्लाथ कमीशन एजेन्ट्स यूनियन
६. दाल चावल कमेटी
७. दिल्ली ब्रिक किलन ओनर्स एसोसियेशन
८. दिल्ली बिल्डिंग मैटीरियल मर्चेन्ट्स एसोसिएशन
९. दिल्ली सिगरेट बीड़ी डीलर्स एसोसिएशन
१०. दिल्ली क्लाथ मर्चेंट्स एसोसिएशन
११. दिल्ली क्लाथ रिटेलर्स एसोसिएशन
१२. दिल्ली फ्लोर एण्ड ग्राम दाल मिल्स एसोसिएशन
१३. दिल्ली फुटवीयर रिटेलर्स एसोसिएशन
१४. दिल्ली फारन क्लाथ डीलर्स एसोसिएशन
१५. दिल्ली जनरल मर्चेंट्स एसोसिएशन
१६. दिल्ली ग्लास सिण्डीकेट
१७. दिल्ली ग्लास वेयर मर्चेंट्स एसोसिएशन
१८. दिल्ली ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन
१९. दिल्ली ग्रामोफोन डीलर्स एसोसिएशन
२०. दिल्ली मोटर ट्रेडर्ज एसोसिएशन
२१. दिल्ली आयल मर्चेंट्स एसोसिएशन
२२. दिल्ली आप्टीशियन्स एसोसिएशन
२३. दिल्ली पेंट मर्चेंट्स एसोसिएशन
२४. दिल्ली पेपर मिल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन
२५. दिल्ली प्रोविन्शियल टैक्सटाइल रिटेलर्स एसोसिएशन
२६. दिल्ली पब्लिशर्ज एसोसिएशन
२७. दिल्ली स्टेट कैमिस्ट्स एसोसिएशन
२८. दिल्ली स्टेशनर्ज एसोसिएशन
२९. दिल्ली स्टेशनरी मैन्युफैक्चर्ज एसोसिएशन
३०. दिल्ली शुगर मर्चेंट्स एसोसिएशन
३१. दिल्ली थ्रेड बाल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
३२. दिल्ली टैक्सटाइल एण्ड ज़री मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
३३. दिल्ली वाच ट्रेडर्ज एसोसिएशन
३४. इलैक्ट्रिकल मर्चेंट्स एसोसिएशन,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

३५. एज्यूकेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन
३६. फ्लोर मिल्ज एण्ड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन
३७. फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन
३८. फ्लोर मर्चेंट्स एसोसिएशन
३९. फ्रूट एण्ड वैजोटेबल मर्चेंट्स यूनियन
४०. फर्नीचर मर्चेंट्स एसोसिएशन, नई दिल्ली
४१. गार्डन ओनर्स एण्ड जमीदारान एसोसिएशन
२.४ जैनरल मशीनरी मर्चेंटस एसोसिएशन
४३. हैंड लूम क्लाथ मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन
४४. हाइड मर्चेंट्स एसोशिएशन
४५. इण्डो अफगान चैम्बर आफ कामर्स
४६. कपड़ा कमेटी (पहाड़ गंज)
४७. किराना कमेटी
४८. मशीनरी मर्चेंट्स एसोसिशन
५०. दिल्ली मिल्क एण्ड स्वीट मर्चेंटस एसोसिएशन
५१. मिश्री बताशान मैन्यूक्चरर्स एसोसिएशन
५२. मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन
५३. नान—राशण्ड क्लाथ डीलर्स एसोसिएशन
५४. पहाड़ गंज बाजार एसोसिएशन
५५. राजधानी साइकल व्यापार मण्डल
५६. रंग रसायन व्यापार संघ
५७. सदर कैंप मर्चेंट्स एसोसिएशन
५८. श्री महालक्ष्मी बुलियन एक्सचेंज लिमिटेड
५९. दिल्ली साइकल डीलर्स एसोसिएशन

उपर्युक्त सूची से ही दिल्ली के व्यापार और उद्योग संगठनों का पूर्ण विवरण नहीं मिल जाता। हिंदुस्तान मर्कण्टाइल एसोसिएन एक पृथक् संस्था है, जिसके सदस्य दिल्ली के थोक कपड़ा व्यापारी हैं। यह संस्था अपने आपमें एक बड़ी संस्था है। लोहे के व्यापारियों का भी एक पृथक् संगठन है। इन दोनों संस्थाओं के द्वारा कपड़े और लोहे के व्यापारी अपने अपने हितों का प्रतिनिधित्व और संरक्षण करते हैं।

इन विभिन्न संगठनों के अतिरिक्त दिल्ली में बीसियों किस्म के ऐसे व्यापार और उद्योग चल रहे हैं, जिन का अभी तक संगठन या तो बना नहीं है अथवा इन पंक्तियों के लेखक को इस का ज्ञान नहीं है।

सेंचुरी मिल्स बम्बई की प्रसिद्ध फैशन फ्रैब्रिक्स

★ असली आरगंडी ★ लेक्स ब्यूटी मलमल ★ मोती वायल और फुल वायल
★ परमसुख धोती ★ एम्बास्ड प्रिंट्स ★ खादी और धारीदार पाप्लीन,
नित्य नवीन डिजाइनों में छपी हुई चमकदार छींट, लट्ठा, ड्रिल्स, चादरें, तौलिये,
काटन वेस्ट, कम्बल, आदि आदि

नवीन आकर्षण

प्रिश्रङ्क—सेंचुराइज्ड शर्टिंग, पाप्लीन और ड्रेस मेटीरियल

★ निर्माता ★

दी सेंचुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कं. लि.

इन्डस्ट्रीज हाउस, १५९ चर्चगेट, रिक्लेमेशन बम्बई

मैनेजिंग एजेंट्स : बिरला ग्वालियर प्रा० लि०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली में कपड़े की खपत

● श्री केडिया

दिल्ली जहां वितरण का केन्द्र है, वहां प्रति व्यक्ति खपत की दृष्टि से भी सम्भवतः दिल्ली सबसे बाजी मार गया है। कुछ मनोरंजक अंक देखिये—

सम्भवतः, दिल्ली वस्त्र वितरण का सबसे बड़ा केन्द्र है। दिल्ली की मिलों में जितना कपड़ा तैयार होता है, उससे बहुत ज्यादा कपड़ा अन्य राज्यों से यहां आता है और वह फिर पंजाब, राजस्थान, बिहार, उत्तरप्रदेश तथा अन्य समीपवर्ती राज्यों में यहां से वितरित होता है। स्वयं दिल्ली में भी कपड़े की काफी खपत होती है। नीचे की तालिका से मालूम होगा कि दिल्ली में सूती ऊनी, रेशमी तथा नकली रेशमी कपड़े का कितना व्यापार होता है। इस तालिका में खद्दर शामिल नहीं है।

प्रतिवर्ष कपड़े का व्यापार—करीब एक सौ करोड़ मीटर।

उपर्युक्त कपड़े का आनुमानिक मूल्य—करीब २७० करोड़ रुपया।

उपर्युक्त वस्त्र की मात्रा देश की कुल सूती मिलों के उत्पादन का १३वां भाग है।

दिल्ली में कपड़े का जितना व्यापार होता है, उसमें से ११.६ करोड़ मीटर की खपत दिल्ली में होती है और, शेष ८८.४० करोड़ कपड़ा दिल्ली से बाहर वितरित होता है। दिल्ली में खपने वाले कपड़े की कीमत करीब ३२ करोड़ रु० होगी। दिल्ली में कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत ५२ मीटर होती है, जिसका मूल्य करीब १५० रु० है। (एक मीटर= १७॥ गिरह)

यदि इस ५२ मीटर कपड़े का वर्गीकरण किया जाए तो सम्भवतः प्रति व्यक्ति औसतन खपत निम्नलिखित होगी—

सूती कपड़ा	४० मीटर
ऊनी कपड़ा	२॥ मीटर
दूसरे सब कपड़े	९॥ मीटर

ऊनी कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत दिल्ली में दूसरे बड़े नगरों (कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि) की अपेक्षा सबसे अधिक होती है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि समुद्र तटवर्ती नगरों में सर्दी बहुत कम पड़ती है।

कपड़े के व्यापार में लगे हुए लोगों की संख्या करीब ३५ हजार है। इसमें मिलों के मजदूर शामिल नहीं हैं।

फोन : २२३८८९ तार : कमलासाड़ी

कमला साड़ी हाऊस

(प्रोप० रामनाथ श्यामसुन्दर)

१२०६ मालीवाड़ा, चांदनी चौक, दिल्ली-६

शुभ विवाह के अवसर पर आधुनिक सुन्दर एवं कलात्मक औरंगाबाद, शान्तिनिकेतन, कांजीवरम्, बंगलौरी, बनारसी, चन्देरी, लखनऊ काम, जारजट, जयपुरी गोटा काम, टेरालीन, हैंडलूम, काटन साड़ियाँ प्रिन्टेड

तथा

ब्लाऊज पीस हर समय थोक व खरीज में तैयार मिलते हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली : एक सांस्कृतिक संगम

श्री गोपीनाथ अमन, अध्यक्ष, जन-सम्पर्क समिति, दिल्ली

दिल्ली शताब्दियों से भारत और उसके इतिहास का प्रतीक रही है। उसने सैकड़ों संघर्ष और उतार-चढ़ाव देखे हैं, इसलिए वह विभिन्न जातियों और संस्कृतियों की अद्भुत संगम बन-स्थली गई है। विद्वान लेखक ने इसी का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत लेख में दिया है।

दिल्ली भारत के प्राचीनतम नगरों में से हैं। इतिहास से पूर्व युग को जाने दीजिये, महाभारत के समय में भी दिल्ली का अपना एक स्थान था। आज के ज़िला मेरठ के अन्तर्गत हस्तिनापुर से इन्द्रप्रस्थ तक एक ही सिलसिला था—यह सब दिल्ली ही थी। नवीन हिन्दू-युग में महाराज पृथ्वीराज के समय दिल्ली एक अच्छा खासा नगर था। मुसलमानों के आने के बाद, जैसा हर आक्रमण में होता है, पहले तो कुछ गड़बड़ रही, परन्तु मुसलमान यहीं बस गये। कुछ यहां के लोग भी मुसलमान हो गये।

दिल्ली पर हमले

दिल्ली हिन्दू-मुसलमानों का मिला जुला नगर हो गया। मुहम्मदशाह तुग़लक ने इस दिल्ली को उजाड़ कर दौलताबाद बसाना चाहा, मगर दिल्ली, उजड़ी रहने वाली न थी। दौलताबाद में उसका जी न लगा और फिर उसने दिल्ली को राजधानी बनाया। मुस्लिम-युग में दिल्ली पर कई आक्रमण हुए, जिसमें बाबर, अहम्मदशाह अब्दाली और नादिरशाह के हमले प्रसिद्ध हैं। पानीपत एक प्रकार दिल्ली का ही फाटक समझा जाता था। इसलिये पानीपत की तीन लड़ाइयां कही जाती हैं। कुरुक्षेत्र की लड़ाई, बाबर और लोधी की लड़ाई, और फिर अहमद शाह अब्दाली की लड़ाई। इन आक्रमणों से सामयिक गड़बड़ तो हुई परन्तु दिल्ली का क्रमिक विकास बढ़ता रहा और इसी का परिणाम सांस्कृतिक संगम था। दिल्ली को अन्तिम झटका सन् १८५७ में लगा, जब अंग्रेजों की जीत हुई और हिन्दुस्तान की हार। अन्तिम मुगल बादशाह गद्दी से उतार दिये गये और ऐसा लगा कि अब दिल्ली का सांस्कृतिक संगम समाप्त हो रहा है, परन्तु ऐसा हुआ नहीं—इसका कुछ रूप तो बदला। वैसे ही सन् १९४७ में देश का विभाजन होने से कुछ सामयिक गड़बड़ हुई परन्तु वह जल्दी ही समाप्त हो गई।

इन सब बातों के कहने का मतलब यह है कि दिल्ली में अनेक संस्कृतियों का संगम है। हिन्दू संस्कृति—और यदि बौद्धों और जैनियों को हिन्दुओं से अलग माना जाय तो उनकी संस्कृति, मुस्लिम—संस्कृति और यदि मुसलमानों में भी अलग-अलग विभाग किया जाय तो पठान-संस्कृति और मुगल-संस्कृति, फिर अंग्रेजों की संस्कृति और जहां तक भारत के प्रान्तों का सम्बन्ध है, दिल्ली पर सबसे अधिक प्रभाव पंजाब प्रान्त का है। यों तो दिल्ली में पहले भी लाखों हिन्दुओं और मुसलमानों की पंजाबी बस्ती, थी परन्तु सन् १९४७ में देश के विभाजन से पश्चिमी पाकिस्तान से जो लोग आये, उससे उनकी संख्या दुगुनी हो गई और यहां के लाखों मुसलमान भी पाकिस्तान चले गये। हमें इस सब पृष्ठभूमि में दिल्ली का सांस्कृतिक रूप देखना है।

पंजाब और उत्तरप्रदेश का प्रभाव

एक तो पुरानी दिल्ली है जो फसील के अन्दर या उसके पश्चिम में बसी है—यों समझिये कि दरियागंज से लेकर सदर बाजार तक पुरानी दिल्ली है। पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए लोगों की बस्ती-कालोनियों के रूप में बस गई और जिन मुहल्लों से मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई उनमें भी अधिकतर इन्हीं लोगों की बस्ती है। नई दिल्ली में तो सभी प्रान्तों के लोग पाये जाते हैं। पंजाब के बाद जिस प्रान्त के सबसे अधिक लोग दिल्ली में बसते वह उत्तरप्रदेश है। इसलिये उत्तरप्रदेश और पंजाब की संस्कृतियों का प्रभाव दिल्ली पर अधिक पड़ा है। पंजाब में जीवन अधिक सुखी उत्तरप्रदेश में कम। पंजाब में तीव्रता उत्तरप्रदेश में नम्रता-बस यों समझिये कि दोनों में शराब और अफीम का अन्तर है। इन दोनों का संगम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली में हुआ।

जमना बाजार और अशोक होटल

जहां तक अंग्रेजी संस्कृति का सम्बन्ध है, अंग्रेजों के चले जाने के बाद से दिल्ली में अंग्रेजी सभ्यता अधिक दिखाई देने लगी है। पुरुष हों या स्त्री, लड़के हों या लड़कियां, जो अच्छे खाते-पीते घराने के हैं, उनमें से अधिक की भावना यही है कि पश्चिमी वेशभूषा धारण की जाय, पश्चिमी खाना और पश्चिमी तरीके हों। दिल्ली के जो बड़े-बड़े होटल हैं, उनमें पश्चिम का रंग विद्यमान है। दूसरी ओर उत्तरप्रदेश के वे गरीब मजदूर, जिनकी भाषा पर भी हंसी की जाती है और जिनके रहन-सहन का मजाक उड़ाया जाता है—इनमें से कई घास छीलते हैं, कई झल्ली उठाते हैं, कई ठेला चलाते हैं और कई साइकल रिक्शा चलाते हैं, जिनके तन पर कपड़ा है पर फटा हुआ। इनका सांस्कृतिक रूप देखना हो तो रात में जब ये अपने झांझ खड़ताल लेकर गाने बैठते हैं तब देखिये। उनमें पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं, परन्तु सूरदास, तुलसीदास और कबीर के भजन उन्हें कंठस्थ हैं और ये छोटी-छोटी टोलियों में बैठकर गाते हैं। आधी रात तक गाते रहते हैं। यह बात और है कि पड़ोस के साहब बहादुर या बड़े बाबू डंडा दिखाकर उन्हें चुप करा दें क्योंकि इन भजनों से इनकी नींद में विघ्न पड़ता है। सप्रू हाऊस, अशोक होटल, चेम्सफोर्ड-क्लब में एक संस्कृति दिखाई देती है और जमना बाजार और टोकरीवालान आदि में दूसरी।

समाजवादी ढंग से संगम

यह कहना कठिन है कि दिल्ली का पूर्ण सांस्कृतिक विकास कब तक होगा, परन्तु ऐसा लगता है कि अभी तक संस्कृति की रूपरेखा ही तय नहीं कर पाये हैं। पुराने फैशन का दाढ़ी वाला मौलवी अपनी संस्कृति रखता है और नये फैशन के सफा-चट चेहरे वाला मुसलमान अपनी। शायद इन मुसलमानों में मौलवी सबसे अधिक साम्प्रदायिक समझा जाता है। मौलवियों ने मुसलिम लीग का विरोध किया और फैशन परस्तों ने साथ दिया, परन्तु उसे देखकर यह धोखा होता है कि जैसे यह तो "सेक्यूलर" हैं और मौलवी साहब साम्प्रदायिक। इसी प्रकार हिन्दुओं में भी तिलकधारी चोटी रखने वालों में शायद इतनी साम्प्रदायिकता नहीं, जितनी अंग्रेजी वेशभूषा वालों में है।

इस प्रकार दिल्ली में अनेक संस्कृतियां पाई जाती हैं। यह तो नहीं कहना चाहिये कि उनमें परस्पर विरोध है, परन्तु हम इन्हें संगम तो नहीं कह सकते। सच बात तो यह है कि जब तक समाजवादी ढांचा स्थापित न हो, उस समय तक संगम होना भी कठिन है। क्लबों में जाने वालों और झौंपड़ी में रहने वालों की संस्कृति का कैसा संगम हो सकता है। जो मध्यवर्ग है, वह ऊपर वालों को तो पूछता है, परन्तु स्वयं दीन-हीन लोगों से मिलने में उसे संकोच है। अब जो भावात्मक एकता का प्रयत्न किया जा रहा है, यदि यह सफल हुआ तो कह सकेंगे कि दिल्ली में सांस्कृतिक संगम की नींव पड़ गई है, परन्तु इसमें कितना समय लगेगा यह कहना बहुत कठिन है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे विद्यालयों में सांस्कृतिक संगम की बुनियाद अच्छी पड़ सकती है, परन्तु हम लोग जिन्होंने प्रान्तीयता और साम्प्रदायिकता के वातावरण में आंख खोली है, शायद ही अपने जीवन में दिल्ली में यह सांस्कृतिक संगम देख सकें।

आपकी आंखें कमजोर हैं

रक्षा करिए

नजर के असली शीशे—स्फेरिकल २ रु. ५० न. पै.
सिलैंडर नं. २ तक—३ रु. ५० न. पै.
स्फेरिकल सिलैंडर नं. ४ तक—४ रु.
धूप के चश्मे—५ से ६ रु. क्रुक्स शीशों के साथ और इससे बढ़िया फ्रेम भी व रियायत खरीदें।

मेहता एण्ड संस

चश्मे वाले, १६/११ आर्य समाज रोड,
करौलबाग, नयी दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली की गृहिणी की आर्थिक समस्या

परिवार की आर्थिक समस्या का अहसास तो गृहिणी को ही सबसे अधिक होता है—जितनी लम्बी चादर हो, उतना ही टांग फैलाओ को वास्तव में कार्यपरिणत करना सुगृहिणी जितनी अच्छी तरह जानती है, उतना और कोई नहीं। कदाचित् यही कारण है कि माता वर ढूंढ़ने के समय धन पर अधिक ज़ोर देती है :—

कन्या वरयते रूपं
माता वित्तं पिता गुणम्।
बान्धवाः कुलमिच्छन्ति
मिष्टान्नमितरे जनाः॥

उसे ही अर्थ की महत्ता और पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने में उसकी आवश्यकता का वास्तविक अनुभव है।

प्राचीन काल में कन्या को ससुराल भेजते समय जो शिक्षा दी जाती थी, वह कुछ इस प्रकार की थी :—

शुश्रुषस्व गुरुन् कुरू प्रियसखी वृत्तिं सपत्नीजने
भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः।
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्यांगनाः॥

किन्तु आज यह शिक्षा यदि दी जाय तो कोरी शिक्षा ही रहेगी वह कन्या के लिये तनिक भी उपयोगी नहीं है। आज तो उसे इस बात का अच्छी तरह प्रशिक्षण देना है कि यदि पति की आमदनी ३०० रु० माह हो तो वह घर कैसे चलायेगी, ५०० रु० माह हो तो क्या-क्या काम और कैसे करेगी और अगर १२५ रु० माह ही हो तो स्वयं भी उसकी आमदनी को बढ़ाने के लिये कैसा प्रयत्न व क्या उपक्रम करेगी। जब हम दिल्ली की गृहिणी की बात सोचते हैं, तब तो ऐसी शिक्षा की आवश्यकता और भी तीव्र हो जाती है।

घर की समस्या

सच पूछिये तो दिनों दिन बढ़ती हुई आबादी और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दिल्ली की महत्ता ने ही गृहिणी की आर्थिक समस्याओं को कठिन बनाने वाली परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। इसमें सबसे पहली है घर की समस्या—

लेखिका

श्रीमती माधुरी श्रीवास्तव
अण्डर सैक्रेटरी, दिल्ली राज्य

गृहिणी को अपने बजट में आमदनी का कम से कम एक चौथाई तो घर के किराये के लिये देना ही पड़ता है, फिर भी जरूरी नहीं है कि वह घर उसकी पसन्द या जरूरतों के अनुसार हो, या उस मुहल्ले में हो जहां से उसके पति का कार्यालय पास हो या अन्य सुविधाएं सुलभ हों। अधिकांश परिवारों को तो एक दूसरे के साथ मिल कर घर लेने पड़ते हैं, जिनमें रसोईघर चाहे अलग हो, पर शौच व स्नान के लिये साझेदारी करनी ही पड़ती है। एकान्त या प्राइवेसी का तो नाम भी नहीं है। आपके यहां क्या खाना बना, कौन आया, कौन गया, आपने बच्चों को कब मारा, वे आपस में कब लड़े, आप अपना काम स्वयं करती हैं या धोबी महरी व जमादार लगा रखे हैं, आदि बातें सार्वजनिक ज्ञान की वस्तुएं बन जाती हैं। ऐसी दशा होते हुए भी गृहिणी को आमदनी का एक चौथाई घर के किराये पर देना ही पड़ता है।

मासिक बजट

जब रहने को जगह मिली तो खाने की चिन्ता हुई। राशन के खर्च का तो बता सकना ही मुश्किल है क्योंकि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली में अनाज का दाम प्रतिवर्ष बढ़ता ही चला जा रहा है। आटा, दाल, चावल, चीनी, चाय, मसाला, बेसन, सूजी, घी तेल पर ही दो बच्चों वाले एक साधारण परिवार का खर्च कम से कम ६०) माह अवश्य ही है—दूध सब्जी व फल, जो परिवार के हर सदस्य के लिये आवश्यक हैं, दिल्ली में पूरे वर्ष बहुत ही महंगे रहते हैं। अन्य जगहों में सब्जी व फल अपनी अपनी फसल पर सस्ते हो जाते हैं और कम से कम मौसमी चीजें लोगों को सस्ती मिल जाती हैं। पर दिल्ली में भिन्डी व परवल १) रु० सेर से कम नहीं होते, टमाटर ॥) सेर से कम नहीं। यहां तक कि अनेकों फलियां व साग जैसे पालक, चोलाई, कुलफा आदि भी बहुत समय आने आने सेर से कम मिलते ही नहीं। दूसरी ओर पौष्टिक भोजन व स्वास्थ्य शिक्षा में सब्जी खाने पर ही जोर दिया जाता है। गृहिणी बेचारी क्या करे। घर में छप्पर भी तो नहीं है कि इसी पर सेम, तराई व लौकी की बेल चढ़ा ले।

इस पृष्ठ भूमि में जरा नीचे के तीन बजट, जिनकी मैं जानकारी ले पाई, देखिये। छोटे-छोटे बच्चों वाले परिवार हैं यह

आमदनी—	१५०) रु०	३००) रु०	५००) रु०
खर्च प्रतिमाह :—			
घर का किराया	५)	४०)	६२)
राशन	४५)	१०५)	(गोश्त सहित) ८०)
घी दूध	१०)	३०)	१३०)
सब्जी फल	१०)	२०)	४५)
शिक्षा (१) पढ़ाई	१०)	२०)	५०)
(२) सिलाई	१०)	२०)	५०)
(३) संगीत कला आदि १६	—		—
कपड़े	१०)	२५)	५०)
आनेजाने सवारी आदि में	२५)	२५)	२५)
मित्रों का स्वागत आतिथ्य आदी विवाह आदि में	१०)	१५)	३०)
एक महरी या नौकरानी	—	१५)	१५)
दवा इलाज	१०)	१५)	१५) सरकारी
साबुन-तेल आदि	२)	२)	१०) नौकर है।
पान बीड़ी सिग्रेट	८)	१०)	—
फर्नीचरकी मरम्मत बदली आदि	३)	—	—
धोबी या धुलाईखर्च	३)	३)	१०)
पानी या बिजलीआदि	७)	३)	१५)
मनोरंजन	—	—	१०)
	१६८	३४८	५६७

बजट वैसे ही आमदनी से ज्यादा हो गया—फिर गृहिणी बिचारी पीर—बबर्ची—भिश्ती—खर सब कुछ तो स्वयं है ही। परिणाम आम तौर से यह होता है कि पहले वर्ग वाले परिवार में बच्चे बारहों महीनों एक वस्त्री ही रहेंगे—शिक्षा कटेगी, फलसब्जी दूध सब कट जायेंगे—स्वास्थ्य सबों का भगवान भरोसे ही रहेगा और वे कर्जा लेने देने के लिये जब तब बाध्य होंगे। पत्नी कुछ दिनों बाद किसी न किसी रोग से ग्रस्त होनी ही है, बहरहाल उम्र काट ही ली जायगी।

इन तीनों किस्मों से ऊपर आमदनी वाले बजटों के विषय में सोचना आवश्यक नहीं है, क्योंकि दिल्ली की २६ लाख जनता में से ८०-९० प्रतिशत इन्ही तीनों के आस पास आ जाती हैं।

गृहिणी का व्यस्त जीवन

दशा नितान्त कठिन होने पर भी गृहिणी की सुयोग्यता से ही इन बजटों वाले घरों को भी आनन्द-युक्त, साफ सुथरे, कैलैंडरों से सजा हुआ पायेंगे। इनमें बैठकर

---

*इस लेख की सुयोग्य लेखिका ने जिन तीन परिवारों से उनके घर के खर्च का हिसाब पूछा है, वे बहुत भाग्यशाली हैं और सम्भवतः काफी वर्षों से किराये के मकान में रह रहे हैं, अन्यथा आज दिल्ली की बस्तियों में एक कमरा भी ५० रुपये से कम में नहीं मिलता। इसी तरह आज का साधारण गृहस्थ पान बीड़ी पर १५-२० रुपये से प्रतिमास कम खर्च नहीं करता। दफ्तर दूर होने पर १०-१२ रु० प्रतिमास सवारी पर भी खर्च होता है। मनोरंजन, अखबार आदि पर भी ५-१०) रु० न्यूनतम खर्च करना पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसे अन्य जरूरी खर्चों में भारी कटौती करनी पड़ती है।
—सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आप को शान्ति, विश्राम व सहृदयता का अनुभव होगा—दिल्ली की गृहिणी ऐसा स्वर्ग रूप गृह बनाने के लिये क्या नहीं करती, उसकी दिनचर्या क्या है, मानो घड़ी लगी हुई स्वचालित मशीन है :—

१—उठना	प्रातः ४ बजे
बच्चों की तैयारी व स्कूल भेजना।	
२—दैनिक क्रम--खाना तैयार करना। पति को दफ्तर भेजना।	९.३० बजे तक
३—घर साफ करना व ठीक करना, पूजा-पाठ, कपड़े धोना, बाजार जाना	२ बजे तक
४—बच्चों की वापसी, उन्हें खाना देना आदि	३ बजे तक
५—कपड़ों की मरम्मत बटन लगाना आदि गृहस्थी के अन्य छोटे-मोटे कार्य	४-३० बजेतक
६—शाम के नाश्ते या खाने का प्रबन्ध बच्चोंको शामके लिये तैयार करना	
पति का कार्यालय से लौटना सायंकाल का खाना पीना	४-३० से ९-३० बजे रात तक
कहीं घूमने जाना या घर में ही परिवार के साथ, छोटे बच्चों को पढ़ाना इत्यादि बच्चों को सुलाना	
अगले दिन के लिये तैयारी कपड़ों में स्त्री करना आदि सवेरेके खानेके लिये कोई प्रबंध आवश्यक हो तो करना।	१०-३० बजेतक

इसी दिनचर्या में से, जो महिलाएं अपनी घर की आमदनी को बढ़ाने के लिये काम भी करती हैं, वे दो घंटे दोपहर से पहले या ५ बजे से पहले निकाल लेती हैं और अपने इस समय के काम को किसी तरह बाक़ी समय में पूरा करती हैं।

अपनी ऐसी जटिल गृहस्थी को सुचारु रूप से चलाने और आमदनी के अन्दर ही खर्च करने के लिये गृहिणी सतत प्रयत्नशील रहती है—तभी तो खारी बावली से राशन का सामान खरीदने में या सब्जी मण्डी में फल लेने में कुछ किफायत होगी, सिर्फ इसीलिये वह अपने पहले से ही न्यस्त कार्यक्रम में भी कुछ समय निकाल कर इन्हीं जगहों से सामान लाने का प्रयत्न करती है। लीजिए बस की भीड़ धक्के का सामना और सामान लादने की मेहनत भी उसी की हुई।

दूकानें खुलने व बन्द होने का समय जब से निर्धारित हो गया है, तब से पति की जो थोड़ी बहुत सहायता उसे बाजार से खरीदारी करने में मिलती थी, वह भी जाती रही। उसका भार भी अधिक गृहिणी के ही हिस्से में आया।

दिल्ली राजधानी होने के कारण मेहमानों का आना भी अन्य शहरों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही रहता है—कोई काम से आता है कोई छुट्टियों में राजधानी घूमने ही। ऐसे अवसर पर मेहमान के साथ जैसी मैत्री या सम्बन्ध हो, तदनुसार खर्च बजट में से निकालने की कला तो केवल गृहिणी ही जानती है। इतना ही नहीं, मेहमानों के जाने के बाद उसने अमुक खर्च कैसे निकाला, पति को इसकी जवाबदेही के लिए भी उसे तैयार रहना पड़ता है।

यह सचमुच आश्चर्य की ही बात है कि इतना सब होते हुए भी दिल्ली की गृहिणी मनोरंजन—कार्यक्रमों के लिये भी कुछ न कुछ खर्च व समय दोनों ही निकाल लेती है—आखिर बच्चों को घुमाने-फिराने, खेल तमाशा आदि दिखाने या कभी-कभी सिनेमा ले जाने की जिम्मेदारी भी तो उसी की है। उसे अपने बच्चों का पूरा ध्यान है फिर भला वह इसमें चूक क्यों करे?

लालित्य प्रिय हृदय को सन्तुष्ट रखने के लिये कुछ न कुछ सजावट व फूल पौधों के दो गमले भी गृहिणी अवश्य रखेगी—उनमें स्वयं ही रोज पानी देगी, चाहे जितना भी उसे काम हो और उन्हें धीरे-धीरे बढ़ता हुआ देखने का आनन्द लेगी।

अपनी आर्थिक समस्या को सुलझाने की उधेड़-बुन में, सभी खर्चों को ठीक-ठीक बैठाते रहने और उसी के साथ अपनी स्निग्ध-भावनाओं को भी यथा समय जागृत रखने में उसकी नारी सुलभ रचनात्मक व कलात्मक शक्ति को प्रवाह मिलता है और उसका विकास होता है।

सौजन्यता और शान्ति के साथ दिल्ली की चहल पहल में दिखाई पड़ने वाली गृहिणी एक बहुत बड़ी आर्थिक समस्या की उलझन को अपने अन्दर निरन्तर छिपाये रहती है—निकट भविष्य में तो उसके उससे निश्चिन्त होने की कोई आशा दिखती नहीं, वरन् बढ़ने की ही संभावना अधिक है।

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली लंदन से भी महंगा है

(संयुक्तराष्ट्र की रिपोर्ट के आधार पर)

संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से प्रकाशित एक पुस्तिका के अनुसार—जिसका सारांश भारतीय पत्रों में २९ अप्रैल १९६३ को प्रकाशित हुआ था—नयी दिल्ली में रहने वाले संयुक्तराष्ट्र के कार्य कर्त्ताओं का जीवन-व्यय न्यूयार्क के जीवन व्यय का ९३ प्रतिशत है।

वेतन सम्बन्धी विभिन्नताओं को दिखाने वाली संयुक्त-राष्ट्र द्वारा प्रकाशित तालिका के आधार पर यह प्रतिशत ज्ञात हुआ है।

संयुक्तराष्ट्र के कर्मचारियों के लिए राओ डे जानेरियो जैसे शहरों की अपेक्षा नयी दिल्ली में रहना अधिक महंगा है। इन शहरों में जीवन व्यय न्यूयार्क का ६३ प्रतिशत है। अन्य शहरों का प्रतिशत इस प्रकार है :—

काहिरा—६५ प्रतिशत
अंकारा (७८ प्रतिशत)
बौन (८२ प्रतिशत)
लंदन और करांची (दोनों जगह—७९ प्रतिशत)

विश्व के जिन ४५ देशों में संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी काम करते हैं, उनमें चिली देश का सान्तिआगो सबसे सस्ता है, अर्थात्—न्यूयार्क आ ५३ प्रतिशत।

लाइबेरिया के अन्तर्गत सबसे महंगा शहर मैनाग्विया है, अर्थात् ११५ प्रतिशत और नागेरिया के अन्तर्गत लाओस में १०५ प्रतिशत है।

दिल्ली में आय की दृष्टि से प्रतिशत विभाजन

मासिक आय रु०	प्रतिशत
०-७५	०.५
७५-१००	१.९
१००-१५०	१२.५
१५०-२००	१९.७
२००-३००	२५.२
३००-५००	२२.७
५००-७५०	७.९
७५०-१०००	३.२
१०००-१५००	२.५
१५०० से ऊपर	२.०

दिल्ली में विभिन्न वर्गों के परिवारों का मासिक व्यय— (रुपयों में)

भोजन, पेय, तमाखू व नशा	१५८.१ (४०.७)
ईंधन व प्रकाश	१४.३ (३.७)
मकान व घरेलू नौकर आदि	५५.८ (१४.४)
कपड़े, बिस्तर व जूते	५७.५ (१४.८)
विविध	१०२.७ (२६.५)
कुल	३८८.३ (१००)

कोष्ठक की राशि व्यय का कुल प्रतिशत है

श्रमिकों का व्यय-निदेशक

(१९४९=१००)

१९५०-५१	१०२
१९५६-५७	११२
१९६०-६१	१२१
१९६१-६२	१२८

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली में आबादी की असमान घनता : वर्तमान और भविष्य

भारत की राजधानी दिल्ली के निर्माण का इतिहास बहुत पुराना है। मुसलमानों के आगमन से भी बहुत पहले दिल्ली या इन्द्रप्रस्थ का निर्माण प्रारम्भ हो चुका था। इसके बाद भारतीय इतिहास ने अनेक छोटी-बड़ी क्रांतियां देखी हैं। अनेक राजवंश आये और चले गये। इन सब अतीत के दीर्घकालीन वर्षों में दिल्ली बसती रही और अनेक भाग उजड़-उजड़ कर फिर बसे। आज भी दिल्ली का विस्तार जारी है। लेकिन समय की परिस्थितियों और रहन-सहन के भिन्न-भिन्न स्तरों और बदलती हुई इच्छाओं और आवश्यकताओं के अनुसार कभी कोई बस्ती बहुत घनी बसी और कोई बस्ती बहुत विरल। नीचे के विवरण से मालूम होगा कि इन बस्तियों की सघनता या विरलता में भारी अन्तर रहा।

शाहजानाबाद का पुराना शहर जिसमें चांदनी चौक, फतहपुरी, लालकुंआ, सीताराम बाजार और जामा मस्जिद का समीपवर्ती भाग सम्मिलित है, बहुत घना बसा हुआ है। इसकी आबादी प्रति एकड़ ३५० बैठती है। इस क्षेत्र में छोटी-छोटी तंग गलियां और घरों के छोटे छोटे कमरे दीर्घ काल से बहुत भारी जनसंख्या को आश्रय दिये हुए हैं। इन क्षेत्रों में धूप, रोशनी और प्रकाश की बहुत कमी है।

दूसरी ओर नया बसा हुआ दरियागंज है, जहां जनसंख्या की घनता २०० व्यक्ति प्रति एकड़ है। पुराने शहर के अन्य अनेक भागों भी, जैसे सब्जी मण्डी, की बहुत सी गलियां घनी बसी हुई हैं।

नई दिल्ली का निर्माण बाकायदा व्यवस्थित रूप से हुआ। अंग्रेज इन्जीनियरों ने भारतीय धन की उपेक्षा करते हुए बड़ी-बड़ी कोठियों के निर्माण पर जोर दिया। इस कारण वहां की आबादी बहुत विरल है। कर्जन रोड पार्लियामेंट स्ट्रीट, और गोल मार्केट में ५० से ७५ व्यक्ति प्रति एकड़ रहते हैं। दिल्ली की बहुत बड़ी संख्या को यहां सरकारी दफ्तरों आदि के कारण काम मिलता है। और इसके लिए उन्हें बहुत दूर-दूर से आना पड़ता है। इसलिए मास्टर प्लान में यह सिफारिश की गई है कि इन क्षेत्रों में काफी अधिक मकान बनाये जायें, ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति अपने कार्य स्थानों (दफ्तरों आदि) के अधिक निकट हो सकें और तब यातायात की समस्या भी कुछ सरल हो जायगी। मास्टर प्लान में १५० व्यक्ति प्रति एकड़ बसाने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली के दक्षिण में तो अकबर रोड के आस पास आबादी केवल २०-२५ व्यक्ति प्रति एकड़ है। यहां बहुत बड़ी-बड़ी कोठियों के कारण बहुत कम लोग बसते हैं। मास्टर प्लान ने यहां आ लक्ष्य ७५ व्यक्ति प्रति एकड़ का रखा है। पंडारा रोड के आस-पास भी मास्टर प्लान में यही लक्ष्य रखने का सुझाव दिया गया है। लोदी स्टेट, गोल्फ लिंक, सुन्दर नगर, काका नगर आदि क्षेत्रों में प्रति एकड़ ५०-६० आदमी रहते हैं। मास्टर प्लान इस लक्ष्य को बदलना नहीं चाहता।

इनर रिंग रोड और रिंग रोड़ के बीच में प्रति एकड़ ७५ से १०० व्यक्ति रहते हैं। रिंग रोड के दक्षिण में भी यही स्थिति रखने का सुझाव मास्टर प्लान में दिया गया है। कालकाजी के पास मास्टर प्लान की सम्मति में कुछ अधिक घनी आबादी होनी चाहिए, क्योंकि इसके समीप ओखला की उद्योगपुरी में काम करने वाले लोगों को बसाना चाहिए। किन्तु मथुरा रोड़ के पश्चिम में फ्रेण्डस कालोनी और प्रधानमंत्री की कोठी के पास तीन मूर्ति के क्षेत्र में मास्टर प्लान के निर्माता वर्तमान २५ व्यक्ति प्रति एकड़ के लक्ष्य को बढ़ाना नहीं चाहते। यह क्षेत्र सम्भवतः बड़े आदमियों के लिए सुरक्षित रखने की अभिलाषा है। चाणक्य पुरी, मोतीबाग, किचनर रोड को ५० व्यक्ति प्रति एकड़ के आधार पर बसाया जा रहा है। रिंग रोड के दक्षिण में सरकार ११०० एकड़ की योजना पर अमल कर रही है जिसमें ७५ से १०० व्यक्ति प्रति एकड़ बसाये जायेंगे, और उससे भी अधिक दक्षिण में ५० से ७५ व्यक्ति प्रति एकड़ का लक्ष्य सामने रखने की सम्मति मास्टर प्लान ने दी है।

सिविल लाइन, अलीपुर रोड, और अलीपुर रोड

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आदि के क्षेत्रों में आज केवल २५ व्यक्ति प्रति एकड़ रहते हैं। यह क्षेत्र भी बड़े बड़े सरकारी अफसरों और अमीरों की कोठियों का रहा है। इस में लोगों को बसाने की अधिक क्षमता है। मास्टर प्लान के लेखकों ने इस क्षेत्र के वासियों पर दया करके ५० से ७५ तक का लक्ष्य रखा है, जिससे इस हरे भरे पहाड़ी और उसके नीचे के क्षेत्र में अधिक भीड़ भाड़ न हो।

शक्ति नगर, रूप नगर, कमला नगर, जवाहर नगर आदि नये बसे हुए उप नगर हैं। यहां की आबादी १५० व्यक्ति प्रति एकड़ है जो औसतन बहुत ठीक है। राणा प्रताप बाग, विजय नगर, माडल टाउन आदि में यह आबादी अभी १०० व्यक्ति प्रति एकड़ है। मास्टर प्लान इस में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता। मालरोड से उत्तर और जी० टी० रोड से पूर्व के क्षेत्रों में बहुत आबादी की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां जमीन का बहुत-सा भाग बड़ी बड़ी सड़कों में खप जायगा।

पुरानी दिल्ली के पश्चिम में अन्धामुगल आदि के इलाके हैं। शहर की अन्तरवर्ती भीड़ को कम करने के लिए लोगों को यहां बसाना होगा। इसलिए यहां की आबादी नई योजना में १०० से १२५ व्यक्ति प्रति एकड़ की हो जानी चाहिए। रोहतक और अम्बाला जाने वाली रेलवे लाइनों के पास भी आबादी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इसके निकट उद्योग क्षेत्र आ जाता है और कारखानों में काम करने वालों को दूर नहीं बसाया जा सकता।

करौल बाग का विकास अभी हाल ही में तेजी से हुआ है। यहां २०० व्यक्ति प्रति एकड रहते हैं। देव नगर, राजेन्द्र नगर, पश्चिमी पटेल नगर आदि में घनता १०० से १५० व्यक्ति प्रति एकड़ है। इसको और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

छोटी लाइन के पश्चिम में आज घनता १०० से १५० व्यक्ति प्रति एकड़ है। नजफगढ़ सड़क के पास भी ७५ से १०० व्यक्तियों की घनता रखनी चाहिए। ज्यों ज्यों उद्योग क्षेत्र से दूर चले जायें, त्यों त्यों घनता कुछ कम होती जानी चाहिए।

यमुना के पार शाहदरा का पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है। हमारा आदर्श १९८१ तक ७ लाख तक की आबादी का होना चाहिए। इधर नये उद्योगों का निर्माण हो रहा है। इसलिए शाहदरा के दक्षिण में १०० से १२५ तक और दूसरे क्षेत्रों में ७५ से १०० तक की घनता होनी चाहिए।

भविष्य में भी असमानता

मास्टर प्लान में आबादी का जो वितरण और भविष्य के लिए जो लक्ष्य रखा गया है, उससे यह स्पष्ट है कि मास्टर प्लान के निर्माता कुछ व्यावहारिक मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते रहते हैं। जहां बहुत घनी आबादी है, उसमें वे यथासम्भव कम परिवर्तन करना चाहते हैं। इसी तरह वे नई आबादियों में रहने वाले सम्पन्न वर्ग और अधिकारी वर्ग को खुली हवा व रोशनी में रखना चाहते हैं। इसलिए वहां की जनता को बहुत बढ़ाने के हक में नहीं हैं। यद्यपि समाजवाद का आदर्श सरकार के सामने अनेक वर्षों से है। यही कारण है कि आबादी की घनता को एक समान करने का प्रयत्न नहीं किया गया। व्यावहारिक कठिनाइयों का भी विचार मास्टर प्लान के निर्माताओं के सामने रहा है।

मास्टर प्लान की योजना के अनुसार १९८१ तक दिल्ली नगर के निम्नलिखित आठ भागों में आबादी और क्षेत्र फल का विभाजन इस प्रकार किया गया है :—

भाग	१९८१ की आबादी	क्षेत्रफल एकड़ों में
(क) पुराना शहर	३,२२,६००	१,३७०
(ख) नगर विस्तार	३,९८,२००	२,५९०
(ग) सिविज लाइन्ज	३,५५,२००	३,४८०
(घ) नई दिल्ली	६,३४,१००	६,९३०
(ङ) शाहदरा	७,४४,१००	७,८९०
(च) दक्षिण दिल्ली	७,८१,१००	९,४००
(छ) पश्चिमी दिल्ली	७,४४,३००	८,२४०
(ज) पश्चिमी यमुना नहर या उत्तर पश्चिम	६,०६,२००	७,४६०
योग	४५,८५,८००	४७,३६०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली के आदर्श नागरिक

दिल्ली भारत की राजधानी ही नहीं, भारत की महत्त्वपूर्ण आकांक्षाओं की प्रतीक भी है। भारत की आर्थिक समृद्धि के लिए नीति निर्धारण दिल्ली से ही होता है। समस्त विश्व के देश दिल्ली पर सदा अपनी दृष्टि रखते हैं

इसलिए

दिल्ली के नागरिकों पर उत्तरदायित्व भी बहुत अधिक आ गया है। आर्थिक योजनाओं की पूर्ति में राष्ट्र के प्रति अपने-अपने कर्तव्य का पालन करने का हम दृढ़ संकल्प करें और उसका सम्पूर्ण आस्था से पालन करें।

—सरन मोटर्स प्रा० लि० द्वारा प्रसारित—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली में कम्पनियों का विकास

डा० राज. के. निगम निदेशक, अनुसंधान और सांख्यिकी विभाग

लगभग ५७३ वर्ग मील क्षेत्रफल और केवल २७ लाख की आबादी वाला दिल्ली राज्य पिछले कुछ वर्षों से औद्योगिक और व्यापारिक प्रवृत्तियों के कारण प्रमुख बन गया है। यहां के उद्योग विविध प्रकार के हैं। सूती कपड़ा, होजरी, आटा-पिसाई, वनस्पति तेल, रंग-वार्निश, चमड़े का और हलका इंजिनीयरी का सामान, साइकिल निर्माण इत्यादि जहां वृद्धिशील आधुनिक उद्योग हैं, वहां दिल्ली में कई ऐसे उद्योग भी हैं जो कई सदियों से परम्परागत पारिवारिक रूप में चले आ रहे हैं, जैसे, सोना, चांदी, तांबा, पीतल के काम, लोहे की चीजें, हाथी दांत व नक्काशी और सोना-चांदी के गोटा-किनारी, सिल्मा-सितारा। समूचा दिल्ली नगर करीब एक हजार छोटी-बड़ी फैक्टरियों से भरा हुआ है और यहां हजारों वर्कशाप हैं। औद्योगिक प्रवृत्तियों में वृद्धि होने से व्यापारिक कार्य भी इस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं।

सरकारी दफ्तरों का प्रभाव

आस-पास के राज्यों और विशेषतः पंजाब के साहसी व उद्योग प्रिय शरणार्थियों के आने से जहां दिल्ली की औद्योगिक और व्यापारिक प्रवृत्तियों में बढ़ती हुई है वहां एक दूसरा बड़ा कारण यह है कि देश की राजधानी होने से सरकारी दफ्तरों व अधिकारियों से तत्काल जानकारी व परामर्श प्राप्त करने की सुविधाएं प्राप्त हैं, तथा उद्योगों के लाइसेंस, पूंजी जारी करना, ऋणों की स्वीकृति, अर्थात् लाइसेंस, परमिट इत्यादि भी शीघ्र प्राप्त हो सकते हैं। इन्हीं सुविधाओं को दृष्टि में रखते हुए कई पड़ोसी राज्यों के साहसिकों ने अपने कल-कारखाने यहां लगा दिये हैं।

दिल्ली के व्यापारियों को यह भी सुविधा है कि वे अपना माल निकटवर्त्ती राज्यों—पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू-काश्मीर—में अधिक सुभीता और कम खर्च के साथ फैला सकते हैं।

दिल्ली तथा अन्य राज्य

दिल्ली में जो रजिस्टर्ड ज्वाइंट कम्पनियां हैं, उनकी संख्या से इसके महत्व का पता चलता है। ३१ मार्च १९६१ को लगभग १,६२० कंपनियां ५८ करोड़ रु० की पेड-अप पूंजी के काम यहां कर रही थीं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में जितनी कम्पनियां हैं, दिल्ली में उनसे बहुत अधिक है। इन तीनों राज्यों में क्रमशः १०८२,४३३ और ८१३ कम्पनियां हैं। इतना ही नहीं, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र और मद्रास—राज्यों को छोड़कर दिल्ली में कम्पनियां अन्य सब राज्यों से अधिक हैं। विभाजन से पहले बंगाल और स्वतन्त्रता से पहले बम्बई राज्य, प्रारम्भ से ही देश के अन्य प्रदेशों की तुलना में कम्पनियों की संख्या और पेड-अप केपिटल की दृष्टि से अन्य सब राज्यों से आगे थे। पूंजी विनियोग और कम्पनियों की संख्या की दृष्टि से पिछले दो दशकों में तीसरा दर्जा मद्रास का रहा है और दूसरी पंचवर्षीय योजना में मद्रास की उपलब्धियां विशेष शानदार रही हैं। कम्पनियों की संख्या की दृष्टि से आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान दिल्ली की तुलना में १/१० व १/३ हैं और गुजरात, केरल, मैसूर, पंजाब और उत्तर प्रदेश १/२ से ३/४ तक के बीच हैं। यह अनुपात मद्रास में १॥ गुना, महाराष्ट्र में ३ गुना और पश्चिमी बंगाल में ६॥ गुना है।

पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र की ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों में लगी पूंजी दिल्ली की तुलना में लगभग ६ गुना, और मद्रास से १॥ गुना है। बिहार में पूंजी विनियोग का अनुपात दिल्ली से लगभग ३ गुना है जिसका मुख्य कारण वहां ३०० करोड़ रु० की पूंजी की हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी का होना है। बाकी राज्यों में पेड-अप पूंजी विनियोग दिल्ली से कम ही है।

१९१८ से १९६० तक

निःसन्देह, ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों की वृद्धि दिल्ली में मार्के की हुई है। १९१८ में ५५ लाख पेड-अप पूंजी की कुल १७ कम्पनियां थीं, १९३०-३१ में इनकी संख्या १०८

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हो गयी, पेड-अप पूंजी १.०७ करोड़ रु०। १९२९-३३ की भारी मन्दी के समय दिल्ली के इस व्यापार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और कम्पनियों की संख्या लगभग दुगुनी हो गयी। १९३९-४० के अन्त में कम्पनियों की कुल संख्या २६१ और उनकी पेड-अप पूंजी ३.६ करोड़ रु० तक थी। १९४०-५१ के दशक में कम्पनियों और पेड-अप पूंजी-दोनों क्रमशः चार गुना और ९ गुना तक बढ़ गये। ५० के दशक में, कम्पनियों की संख्या और उनकी पेड-अप पूंजी में क्रमशः ५०% और ८०% वृद्धि हुई। इस प्रकार पिछली ४० वर्ष की अवधि में दिल्ली की कम्पनियों की पेड-अप पूंजी में लगभग १०० गुना वृद्धि हुई है। यूं तो समूचे देश के इस सामूहिक साहस में वृद्धि हुई है पर अन्य राज्यों की तुलना में दिल्ली में यह वृद्धि सचमुच आश्चर्यजनक और उत्तमतर है।

दिल्ली की मुख्य कम्पनियां

दिल्ली की पुरानी कम्पनियों में दो विशेष प्रमुख, सबसे पुरानी और सुसंगठित हैं। ये हैं, गणेश फ्लोअर मिल्स और दिल्ली क्लोथ एण्ड जनरल मिल्स। इन दोनों की रजिस्ट्री क्रमशः १८५१ और १८८९ में हुई थी। इस सदी के प्रारम्भ में तीन सूती मिलें, नामतः, हनुमान एण्ड महादेव स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, दि किशन काटन स्पिनिंग मिल, और दि जमुना काटन स्पिनिंग मिल्स, और दो आटा मिलें, दि नार्थर्न इंडिया फ्लोर मिल्स, और दि जोहन्स फ्लोर मिल्स—अच्छी चल रही थीं, पर अब वे नहीं हैं या स्वामित्व वनाम बदल चुकी हैं। दिल्ली क्लोथ और जनरल मिल्स का कार्य क्षेत्र कपड़े के अतिरिक्त अन्य विविध क्षेत्रों में भी फैल गया है, जैसे, चीनी, केमिकल्स इत्यादि। गणेश फ्लोर मिल्स ने अपने प्रारम्भिक काम आटा पीसने के काम को बदल कर वनस्पति तेल और बिजली के पंखे बनाने का काम शुरु कर दिया है। बिरला काटन एण्ड स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी भी दिल्ली की एक प्रमुख मिल है, जो १९२० में बिड़ला बन्धुओं द्वारा कन्हैयालाल बागला से खरीद कर नये नाम से चलाई गई थी।

छोटे उद्योग अधिक

वस्तुतः, दिल्ली के इस सामूहिक क्षेत्र का सम्बन्ध बड़े कारखानों की अपेक्षा छोटे और मझौले कारखानों से अधिक है। ५० लाख रु० व इससे अधिक की पेड-अप पूंजी की कम्पनियां दिल्ली में एक दर्जन से भी कम हैं जबकि ५० लाख रु० से लेकर ५ लाख रु० से कम तक की पेड-अप पूंजी की मध्य-आकृति की कम्पनियां, लगभग, १०० हैं। कुल १६२० कम्पनियों में से अवशिष्ट १५०० कम्पनियां छोटे सम्मिलित साहस ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनियां हैं। सरकारी विशालकाय कम्पनियों को छोड़कर यहां निजी क्षेत्र में १ करोड़ व इससे अधिक रु० की अधिकृत पूंजी की संगठित कम्पनियां १० हैं। इन १० में से बहुत कम ऐसी हैं जिनके पास इस क्षेत्र में, वास्तविक, फैक्टरी का स्थान व प्लॉट अपना हो।

सरकारी उद्योगों में बढ़ती

दिल्ली के औद्योगिक विस्तार के सम्बन्ध में, पिछले कुछ समय से, एक विचित्र स्थिति यह पैदा हो गयी है कि बड़े उद्योगपतियों ने जहां इस क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने से अपना हाथ खींच लिया है, वहां सरकार ने अनेक विशाल साहसों की रजिस्ट्री करायी है। इनकी संख्या १६ से कम नहीं हैं। राजधानी को औद्योगिक विस्तार का दूसरा दिलचस्प पहलू यह है कि ऐसा कोई उपभोक्ता सामान नहीं है, जिसकी कम्पनी दिल्ली में न हो। भारी उद्योगों से लेकर हल्के उद्योगों तक—यह विविधता और विचित्रता यहां पाई जाती है। निम्नलिखित तालिका से इस विविधता का कुछ परिचय मिल सकता है :—

३१ मई १९६१ तक दिल्ली कम्पनियों की औद्योगिक विविधता—पेड-अप पूंजी लाखों रु० में

महत्त्व पूर्ण उद्योग समूह	सार्वजनिक कम्पनियां		निजी कम्पनियां		कुल कम्पनियां	
	संख्या	पेड-अप पूंजी	संख्या	पेड-अप पूंजी	संख्या	पेड-अप पूंजी
१. फ्लोर मिल्स	२	७२.४०	४	५.१८	६	७७.५८
२. खाने योग्य वनस्पति तेल	२	१२.२१	३	९.१६	५	२१.३७
३. दुग्धशाला उत्पादन	—	—	६	२१.०३	६	२१.०३
४. चीनी निर्माण	१०	२०८.०९	१	१५.००	११	२३३.०९

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

५. बर्फ निर्माण	२	२०.००	६	१६.८५	८	३६.८५
६. एरिएटेड और खनिज जल	—	—	४	४.२९	४	४.२९
७. काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग	३	४७८.७८	२	०.७९	५	४७९.५७
८. वेविंग एण्ड नेरो फेब्रिक्स	१	.७५	२	१६.३५	३	१७.१०
९. दरी, कम्बल इत्यादि निर्माण	—	—	१	३.४४	१	३.४४
१०. होजरी और बुना हुआ सामान	१	.५३	३	२.७६	४	३.२९
११. पहनने वाली पोशाकें	—	—	७	५.८४	७	५.८४
१२. चमड़े का सामान और जूते	१	०.१७	३	१.३१	४	१.४८
१३. लोहा और इस्पात का बुनियादी निर्माण	४	१६.१०	१३	११.९२	१७	२८.०२
१४. मोटर वाहन	३	३२.०५	३६	१०६.२१	३९	१३८.२६
१५. बाईसिकल	३	४९.०९	१२	१७.२३	१५	६६.३२
१६. परिवहन साजो-सामान	१	१.५५	१९	३७.८५	२०	३९.४०
१७. बिजली के पंखे	१	१३.३६	२	०.३१	३	१३.६७
१८. खेती के औजार	१	०.३२	१२	६०.१२	१३	६०.४४
१९. मशीन टूल्स	२	१३.८६	१७	१९.६६	१९	३३.५२
२०. पीतल, तांबा और इनेमल का सामान	—	—	६	९.८१	६	९.८१
२१. स्टेन लेस स्टील का सामान	—	—	१	५.०९	१	५.००
२२. चिकित्सा और दवाइयां	६	६.७६	२८	१४.४६	३४	२१.२२
२३. साबुन	१	२.३३	१	७.२९	२	९.६२
२४. रोगन, रंग इत्यादि	—	—	९	१०.७२	९	१०.७२
२५. अन्य कैमिकल सामान	१	०.०५	१२	१००.२९	१३	१००.३४
२६. ईंटें, टाइलें	२	३.९१	५	८.७२	७	१२.६३
२७. पाइप, अन्य सीमेंट उत्पादन	—	—	४	४१.२१	४	४१.२१
२८. मिट्टी और चीनी मिट्टी का सामान	२	१३.१५	२	५.००	४	१८.१५
२९. शीशा और शीशे का सामान	—	—	३	१३.२५	३	१३.२५
३०. रबड़ निर्माण	—	—	३	७.७७	३	७.७७
३१. फर्नीचर	१	१.२८	६	२.३६	७	३.६४
३२. मुद्रण और प्रकाशन	१७	३५.२५	५९	४६.९०	७६	८२.१५
३३. खिलौने खेल और व्यायामका सामान	१	५.००	५	३.६५	६	८.६५
३४. सड़क यातायात	२	१.०१	१४८	६३.३१	१५०	६४.३२
३५. भंडार और भंडारी करण	६	३६.८६	१०	४६.९९	१६	८३.८५
३६. फिल्म चित्र उत्पादन और वितरण	१४	३७.७१	५५	२८.९८	६९	६६.६९
३७. होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि	४	१६५.२२	१०	२३.०२	१४	१८८.२४

दिल्ली में प्रतिवर्ष, औसतन, १४० नयी कम्पनियां रजिस्टर होती हैं। १९५०-५१ में १५० से बढ़कर १९६०-६१ में ३०० नयी कम्पनियों की रजिस्ट्री हुई। नई कम्पनियों में अधिकांश वित्तीय और व्यापारी कम्पनियां हैं। वर्तमान प्रवाह की दृष्टि में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि दिल्ली उत्तर भारत में एक प्रमुख और महत्व पूर्ण व्यापार—वाणिज्य केन्द्र बन जाएगा तथा दृढ़ वित्तीय केन्द्र भी बन जायगा। छोटे-छोटे उद्योगों का भी यहां राज्य के प्रत्येक कोने में विस्तार हो जाएगा।*

*एक अंग्रेजी लेख के आधार पर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली में बिक्री-कर

दिल्ली राज्य के राजस्व पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहां आमदनी का सब से बड़ा स्रोत बिक्री कर है। भूमि राजस्व, उत्पादन कर, स्टाम्प और दूसरे कर आदि से दिल्ली राज्य को इतनी आमदनी नहीं होती, जितनी कि बिक्री कर से है, यह स्वाभाविक भी है। अपेक्षाकृत अन्य राज्यों के दिल्ली में शिक्षित और सम्पन्न व्यक्तियों का जनसंख्या के अनुपात से प्रतिशत बहुत अधिक है। इस राज्य में कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। सरकारी नौकरों की संख्या काफी अधिक है और वे अपने जीवन में अपेक्षाकृत ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जिन पर बिक्री कर लगता है। १९६१ व ६२ की यह तालिका बताती है कि कुल १३ करोड़ ५६ लाख रुपयों के राजस्व में करीब ६ करोड़ रुपये अर्थात् ५०% से कुछ कम बिक्री कर से आय हुई। राजस्व की कुछ प्रमुख मदों के अंक निम्नलिखित हैं।

१—बिक्री कर	५,९३,१७,७.७
२—उत्पादन कर	१,६९,५६,७४७
३—स्टाम्प	१,३०,६०,१०९
४—अन्य कर	२,६६,२६,९२४
५—भूमि राजस्व कर	६,१८,९,६५

१९६३-६४ के बजट में बिक्री कर से ७०७.५० लाख रु० का अनुमान है।

दिल्ली राज्य द्वारा प्रकाशित संख्याओं से मालूम होता है कि १९६१ ई० में प्रति तिमाही निम्नलिखित वस्तुओं पर निम्नलिखित रूप से बिक्री कर वसूल हुआ है।

क्र. सं. नाम बिक्री वस्तु	बिक्री कर हजार रुपयों में
१—कपड़ा	२९
२—मकान तिर्माण सामग्री	३५४
३—लोह सामग्री	५४२
४—मशीने	३९७
५—मशीनों व मोटरों के पुर्जे	१७७१
६—साईकिल व पुर्जे	२५६
७—पैट्रोल इत्यादि	३७८
८—कैमीकल	१३८
९—चर्म का सामान	१६१
१०—इमारती लकड़ी	२२१
११—जेवरात	१२१
१२—औषधियां (आयुर्वैदिक एलोपैथिक	२०८
होमियो पैथिक	७००
१३—जनरल मर्चेंट की वस्तुएं	७००
१४—भोजनालय और रेस्टोरैंट	३००
१५—अन्य	३८४३
योग	९५८१

इस तालिका से दिल्ली निवासी नागरिकों की रुचियों और आवश्यकताओं का भी कुछ ज्ञान होता है। अन्य राज्यों की अपेक्षा दिल्ली के नागरिक मोटरों, साईकिलों, औषधियों तथा आराम की वस्तुओं पर अधिक खर्च करते हैं। यदि हम कुल बिक्री कर को देखें तो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति १९६१-६२ में बिक्री कर करीब २३.७ रुपया बिक्री कर पड़ता है और इस में से भी अधिकांश रुपया नागरिकों को देना पड़ता है। नागरिकों का अर्थ है दिल्ली के नागरिक क्षेत्र को देना पड़ता है। पाठकों को यह बात मालूम होनी चाहिये कि इस बिक्री कर में वह बिक्री कर शामिल नहीं है जो कि केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय सरकार के रूप में वसूल करती है।

दिल्ली में मकानों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस कारण इमारती सामान इमारती लकड़ी लोहे आदि की खपत बहुत है। साईकिलों, मोटरों, पंखों, रेडियो, टाइप-राइटरों सीने की मशीनों आदि की खपत भी प्रति व्यक्ति औसत दृष्टि से दिल्ली में अधिक है।

दिल्ली में लाखों रुपये की शृंगार सामग्री बनती है। किन्तु इसके अतिरिक्त दिल्ली के बाजार में बाहर से आने वाले क्रीम पाऊडर और दन्त मंजन, सुगन्धित तेल की मात्रा प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होगा।

सन	मीट्रिक टनों में क्रीम पाऊडर आदि	सुगन्धित तेल	अंग्रेजी तम्बाकू सिगरेट आदि
१९५९	७७	३९	२८७
१९६०	११०	४०	३७९
१९६१	३०३	४१	४१४

सम्पादा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली का औद्योगिक विकास

श्री एन. एन. टंडन संचालक उद्योग, दिल्ली राज्य

दिल्ली का औद्योगिक क्षेत्र में एक विशेष स्थान है। वैसे तो परम्परागत दृष्टि से देखने पर पता चलेगा कि दिल्ली शताब्दियों से मलमल, फूलकारी के काम, कालीन और लेस इत्यादि के लिए मशहूर रहा है। साथ ही, हाथी दांत और दिल्ली ज़रदोज़ी के काम के लिए भी प्रसिद्ध रही। परन्तु पिछली शताब्दि के उत्तरार्द्ध से ले कर अब तक दिल्ली में आधुनिक उद्योग धन्धों की निरंतर वृद्धि हुई है। पिछली लड़ाई और उसके बाद तथा देश के विभाजन के उपरान्त तो यह प्रगति और भी तीव्र हो गई।

दिल्ली : एक व्यावसायिक क्षेत्र

देश के विभाजन के पहले दिल्ली में जहां केवल कपड़े की मिलें और कुछ ढलाई खाने इत्यादि थे, वहां अब अनेक प्रकार के उद्योग धन्धें स्थापित हो गए हैं। उस समय फैक्टरीज़ एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड फैक्टरियां केवल २०० थीं। १९५१ में ४९२, हो गईं १९५६ में ८९०, १९६० में १०६१ और अब ३००५ के लगभग है।

दिल्ली में उद्योग धन्धों की वृद्धि के कई कारण हैं। दिल्ली केवल भारत की राजधानी ही नहीं रही है। वह शताब्दियों से एक बड़ा भारी व्यावसायिक क्षेत्र भी रहा है। २०० मील की परिधि में उसका व्यावसायिक प्रभाव अनुभव किया गया है। यहां के २६ प्रतिशत काम करने वाले व्यक्ति व्यावसायिक काम-धन्धों में संलग्न हैं। यह अनुपात देश के १० बड़े शहर में से किसी में भी नहीं है। दिल्ली को रेल व सड़क की सुविधाएं प्राप्त हैं। उपभोक्ता सामान के लिए यहां बहुत गुंजायश है। इसके बहुत से कारण हैं। दिल्ली में बाहर से कच्चा माल मंगवाना, बने बनाए सामानके मंगवाने से कहीं अधिक लाभप्रद है। दूसरा, दिल्ली में ही उपभोक्ता सामान की असाधारण मांग है। यह ध्यान में रखने योग्य है कि यहां काम करने वालों में से दो-तिहाई लोग ऐसे हैं, जो वह सामान बना रहे हैं, जिसकी खपत दिल्ली में ही होती है।

उद्योगधन्धों से रोजगार

हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली की जनसंख्या निरन्तर तीव्र गति से बढ़ रही है। अनुमान है कि १९८१ में दिल्ली की जनसंख्या लगभग ५० लाख हो जायगी। नये उद्योग धन्धे दिल्ली में इस बढ़ने वाली जनसंख्या को काम दे सकेंगे। उद्योग धन्धे एक ऐसी सतह को जन्म देते हैं, जो नौकरियों से अधिक परन्तु शायद सरकारी नौकरी से कम है। इस प्रकार के मध्यम वर्ग से शायद सामाजिक तनाव कुछ कम होगा।

राजधानी बनाम उद्योग-क्षेत्र

बहुधा प्रश्न किया जाता है कि दिल्ली में उद्योग धन्धों को क्यों स्थान दिया जा रहा है। दिल्ली तो भारत की राजधानी है। वहां उद्योग न रह कर केवल रहने की सुविधा ही होनी चाहिए। यह भय व्यक्त किया जाता है कि दिल्ली की राजधानी का व्यक्तित्व उद्योग और मिलों के धूएं में लुप्त हो जायगा। इस प्रश्न का उत्तर देते समय हमें दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र का बड़े ध्यान से परिवेक्षण करना होगा।

दिल्ली की केवल १.६ प्रतिशत भूमि ही उद्योग धन्धों के प्रयोग में है। अन्य बड़े नगरों में ४ या ५ प्रतिशत का अनुपात है। काम करने वालों का केवल छटा भाग ही उद्योग धन्धों में है जब कि कलकत्ता में ३१ प्रतिशत और पूना में ३६.१ प्रतिशत है। परन्तु

यह बिक्री कर सभी राज्यों की तरह दिल्ली में भी निरन्तर बढ़ता जा रहा है। न केवल बिक्री कर की दर ही बढ़ रही है बल्कि प्रति वर्ष नई वस्तुओं पर कर बढ़ता जा रहा है। जब हम बिक्री कर की आमदनी का हिसाब लगाते हैं तब हम यह नहीं भूल सकते कि अधिकांश दूकानदार और ग्राहक बिक्री कर की चोरी करते हैं। दूकानदार माल को खपानेके लिए बिल ही नहीं बनाते और ग्राहक भी इससे बचने के लिये बिल बनवाये बिना ही माल खरीद लेते हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कोई भी पूना को अत्यधिक औद्योगिक नहीं मानता। मास्टर प्लान के अनुसार औद्योगिक काम करने वालों की संख्या १९८१ में कुल काम करने वाली संख्या की एक चौथाई हो जायगी, जो अधिक नहीं है।

परन्तु महत्वपूर्ण बात तो यह है कि दिल्ली के भौगोलिक, आर्थिक व्यावसायिक प्रसंग में औद्योगिक प्रगति अनिवार्य है। योजना बनाने वालों, प्रशासकों तथा उत्तरदायी मनुष्यों का कार्य उसे सही मोड़ देना है। इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य २० वर्ष की अवधि में ५,८०० एकड़ भूमि में उद्योग धन्धों को स्थापित करना है। एक विशेष कार्य उन उद्योगों को पुराने स्थानों से हटाना है, जो मास्टर प्लान के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र नहीं माने गए हैं। २,८०० एकड़ जमीन पर तो यह कार्य बहुत ही शीघ्र कर देना है। इस प्रकार का कार्य संसार में आज तक कहीं नहीं किया गया है। यह बहुत कुछ सही योजना बनाने पर निर्भर करता है और उस योजना को कार्यान्वित करना और भी दुस्तर है। हमें यह अनुमान करना होगा कि इस क्षेत्र में जल, बिजली, कच्चे सामान और मशीनों की कितनी आवश्यकता होगी। एक जगह से दूसरी जगह अपने उद्योगों को ले जाने वालों को सुविधा भी देनी होगी।

उद्योगों का उज्ज्वल भविष्य

नये औद्योगिक क्षेत्रों में चले जाने से उद्योगपतियों को लाभ होगा। अभी स्थान व विद्युत के अभाव के कारण वे अपने कार्य को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में भूमि मिल जाने पर वे अपने काम को बहुत कुछ बढ़ा पायंगे। इससे उत्पादन में बहुत वृद्धि होगी। उनके पड़ोसियों को भी बहुत राहत पहुँचेगी। तब तक दिल्ली एक बहुत सुन्दर नगर भी बन सकेगा।

सब हालात को सोचते हुए हमारा दृढ़ विश्वास है कि दिल्ली मार्के की औद्योगिक प्रगति कर सकेगी और उसका भविष्य उज्ज्वल है। दिल्ली की औद्योगिक, व्यावसायिक और आर्थिक स्थिति, सरकार की ओर से सुविधा तथा उद्योग पतियों की नैसर्गिक हिम्मत और उनका अद्भुत सामर्थ्य—ये सब तथ्य हमारी आशा को पुष्ट करने वाले हैं।

क्वालिटी मिनरल सप्लाई सिंडीकेट

प्रोप्राइटर—सी० डीडवानिया

मिनरल व केमिकल के व्यापारी

विशेषताएं

सुपर एक्टिवेटेड (Activated) फुलर्स अर्थ सोडियम तथा पोटेशियम बाईक्रोमेट सब प्रकार की Jack Hammers के स्पेअर पार्टस्

लिखें—४४ ओल्ड कस्टम हाउस स्ट्रीट,

फोर्ट बम्बई १

तार : Sympathy

फोन : २५१८३५

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Supreme by every test

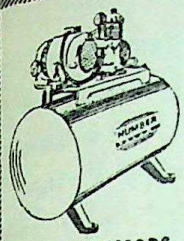

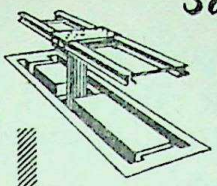

HYDRAULIC CAR LIFTS

AIR COMPRESSORS

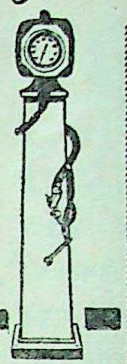

Humber

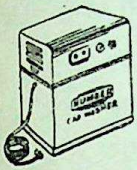

TOWER GAUGES

CAR WASHERS

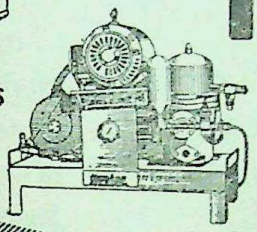

engineered for peak performance in modern garages, spray painting workshops and industrial establishments.

Manufactured by

DIDWANIA BROTHERS PVT. LTD.

KASHMERE GATE DELHI-6

एयर कम्प्रैसर

हम्बर

हाइड्रोलिक कारलिफ्ट

कारवाशर, टावरगाज़

तार—डिडवानिया,
काश्मीरी गेट, दिल्ली—६

फोन—कार्यालय २२२२५६
२२१७२८

The Gentral Bank Of India Limited

HEAD OFFICE

MAHATMA GANDHI ROAD,
FORT, BOMBAY-1.

ESTABLISHED—1911

DEPOSITS ACCEPTED FOR PERIODS FROM 3 DAYS & 5 YEARS AT ATTRACTIVE RATES

FOR FURTHER DETAILS PLEASE CONTACT ANY OF OUR OFFICES

N. K. KARANJIA
Managing Director

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देहली के उद्योग की समस्यायें

पिछले दो तीन वर्षों से दिल्ली के उद्योग जिन कठिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वे संक्षेप से निम्नलिखित हैं :—

श्रम-समस्या

(१) दिल्ली के औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्रों में श्रम की स्थिति बहुत विकट होती जा रही है और उद्योग एवं व्यापार के अधिकारियों के लिये बहुत कठिनता का कारण बन गई है। अनेक अवांछनीय तत्वों ने अपने-अपने स्वार्थों और अपने दल के प्रभाव को बढ़ाने की अभिलाषा से दिल्ली के श्रमिकों को अपना औजार बनाना शुरु किया है। इसके कारण न केवल मजदूरों में ही पारस्परिक गुट बन्दी बढ़ती है, पर उद्योग का वातावरण भी अशांत हो जाता है, उद्योग में अनुशासन हीनता बढ़ती है और इसका प्रभाव उत्पादकता पर पड़ रहा है। औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिये सरकार ने जो सुझाव दिये हैं, और जिन्हें श्रमिकों के नेताओं ने भी स्वीकार कर लिया है, उनका पालन भी पूर्णतः नहीं हो रहा है।

बिजली

दूसरी कठिनता जो दिल्ली के उद्योग को बाधा पहुँचाती है वह है बिजली की दुर्लभता। दिल्ली राज्य का बिजली बोर्ड न तो लोगों को बिजली दे पाती है और न कार्पोरेशन ही उनके साथ सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करता है। आज दिल्ली को करीब १,२०००० किलोवाट बिजली की आवश्यकता है, जबकि बिजली की उत्पत्ति ८०,००० किलोवाट से भी कम है। बिजली की कमी को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि जहां भाखड़ा नागल से अधिक बिजली प्राप्त करने की चेष्ट की जाये, वहां बड़े-बड़े उद्योगों को स्वयं अपने उपयोग के लिये बिजली के उत्पादन की अनुमति और सुविधा दी जाये। इससे दिल्ली के बिजली बोर्ड पर भी कम व्यय भार पड़ेगा और बिजली का संकट भी किसी अंश तक हल हो जायेगा।

मास्टर प्लान

दिल्ली के उद्योगों के विस्तार में एक बड़ी बाधा यह है कि मास्टर प्लान में उसे उद्योग प्रधान नगर नहीं माना गया। एक हद तक यह ठीक भी है। दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के सैकड़ों और हजारों दफ्तर होने के कारण यहां सरकारी कर्मचारियों की संख्या अधिक है। स्थान का अभाव होने के कारण भी यहां बड़े-बड़े उद्योग स्थापित नहीं हो सकते, फिर भी यहां उद्योगों के विकास की जो भी संभावनायें हैं उनका पूरा उपयोग करना चाहिये।

कोयला

दिल्ली के उद्योग के सामने चौथी समस्या है कोयले की दुर्लभता या उसका समय पर न मिलना। यह समस्या दिल्ली में ही नहीं, अन्य नगरों के उद्योगों के सामने भी है। कोयला खानों से नहीं निकलता, अथवा रेलों की ऐसी व्यवस्था है कि कोयला यथा समय दिल्ली नहीं पहुँच पाता, इस बहस में हम नहीं पड़ना चाहते। स्थिति यही है कि दिल्ली के उद्योगों को यथा समय पर्याप्त कोयला नहीं मिल पाता। समय-समय पर दिल्ली के भट्टे वाले कोयला न मिलने पर बहुत परेशान हो जाते हैं।

यातायात-व्यवस्था

दिल्ली की एक समस्या उन क्षेत्रों में यातायात, सड़क और बस सर्विस की कमी है, जो क्षेत्र नये उद्योगों की दृष्टि से विकसित हो रहे हैं और जहां नये-नये उद्योग स्थापित हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में जिस गति से उद्योग बढ़ रहे हैं, उस गति से सड़कों और यातायात का विकास नहीं हो रहा। अनेक स्थानों पर, विशेषकर नजफगढ़ क्षेत्र में, रेलवे क्रासिंग और सड़कों के अभाव से विशेष कठिनता होती जा रही है।

श्रमिक कानून

भारत सरकार के समय-समय पर बनाये हुये नियमों तथा श्रमिक न्यायालयों द्वारा दिये जाने वाले निर्णयों आदि के कारण जो कठिनता में देश के सब उद्योगों को सहन करनी पड़ती है, उन कठिनताओं का दिल्ली के उद्योग को भी सामना करना पड़ता है। हमने इस लेख में संक्षेप के कुछ उन समस्याओं का परिचय दिया है, जिनका दिल्ली से विशेष रूप से सम्बन्ध है।

सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली का सुनियोजित विकास : तीसरी योजना

रामलाल वर्मा, निदेशक जन सम्पर्क विभाग, दिल्ली

देश के दूसरे भागों की तरह दिल्ली ने भी सन् १९५१ में पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से सुव्यस्थित विकास के पथ पर चलना शुरु किया। पहली योजना में सात करोड़ रुपये से भी कम की राशि रखी गई थी। दूसरी योजना का आकार पहली योजना से लगभग पांच गुणा अधिक था जिसके लिए लगभग ४० करोड़ रुपये निर्धारित किए गए, जो विकास की ओर एक साहसिक प्रयास था। तीसरी योजना के लिये ९८.२७ करोड़ रुपये राजधानी को चहुँमुखी विकास के लिये दिये गये हैं।

भारतीय संघ की अन्य इकाइयों की तुलना में दिल्ली मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र है। इसकी लगभग २७ लाख की आबादी में से केवल ३ लाख लोग लगभग ३०० गांवों में रहते हैं। शेष लोग नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और ६० से अधिक नई बसी हुई बस्तियों में रहते हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि दिल्ली की पंचवर्षीय योजनायें नगर व अर्ध शहरी आबादी और उसकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर बनाई जाती है।

पहली और दूसरी योजनाओं के अन्तर्गत सन्तोषजनक प्रगति कर लेने के बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना में दिल्ली प्रदेश के लिये अधिक आशाजनक कार्यक्रम पूरा करने का संकल्प किया गया है। इसके लिये ९८.२७ करोड़ की राशि निश्चित की गई। दिल्ली प्रशासन की तीसरी योजना के प्रमुख विषय हैं कृषि, छोटी सिंचाई कार्यक्रम, बाढ़ नियंत्रण, उद्योग, रोजगार व तकनीकी प्रशिक्षण, शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं व आवास।

गलियों व मार्गों में प्रकाश, बिजली, सड़क निर्माण, प्राथमिक शिक्षा, गन्दे क्षेत्रों की सफाई, पानी की सप्लाई, जन स्वास्थ्य व परिवहन आदि की व्यवस्था का भार दिल्ली नगर निगम पर है।

तीसरी योजना में वे आवश्यक कदम उठाये गये हैं, जिनके द्वारा दिल्ली प्रदेश में हर स्कूल जाने योग्य बच्चे को दाखिला मिल सके। मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थानों की संख्या १२१४ से चढ़कर १५०७ तक पहुँच गई है।

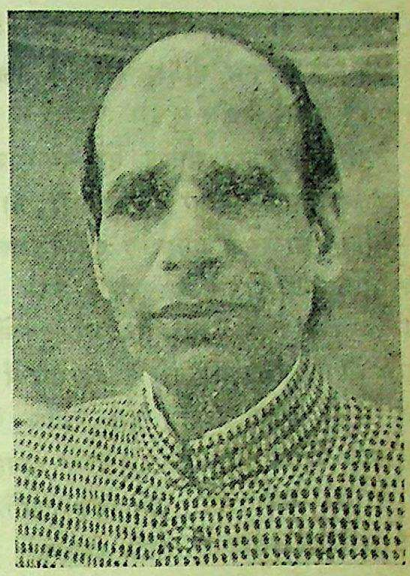

लेखक

हायर सेकेन्डरी स्कूलों में ६०,००० अतिरिक्त दाखिले की व्यवस्था करने का विचार है। हायर सेकेंडरी स्कूलों में चालू सत्र में जो लोग भर्ती किये जा चुके हैं उसके अलावा ८,६०० दाखिले की व्यवस्था करने की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं। आम शिक्षा के साथ-साथ प्राविधिक शिक्षा की उन्नति करने का भी प्रयास किया जा रहा है। तीन पोलीटेक्नीकल संस्थान स्थापित किये गये हैं जिनमें से एक लड़कियों के लिये है।

दस जूनियर टेक्निकल स्कूलों में से दो में शिक्षण कार्य इस बर्ष से शुरू हो गया है। इनमें ९ से ११ वीं दर्जे तक की प्राविधिक शिक्षा दी जाती है।

दिल्ली प्रशासन ने आवास की समस्या में सुधार लाने के लिये हर छः महीने में २,००० प्लाटों को मुहैया करने का दायित्व लिया है।

सहकार

सहकार के क्षेत्र में अब विस्तार की अपेक्षा एकीकरण

(शेष पृष्ठ १२२ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मशीनरी उद्योग का विकास

श्री ओम्प्रकाश रहेजा

विभाजन से पहले दिल्ली में मशीन निर्माण का उद्योग नहीं के बराबर ही था। उस समय उत्तर भारत में कानपुर और लाहौर—ये दो नगर ही मशीनरी के लिए प्रसिद्ध थे। विभाजन के बाद लाहौर से इस उद्योग के अधिकांश व्यापारी दिल्ली ही आकर आबाद हो गये। उस समय पुरानी दिल्ली के नया बाजार में मशीनरी की दो तीन दुकानें थीं। नया बाजार में अधिकांश दुकानें गल्ले की हैं और अच्छा कारोबार होने से वे वहां से उठने को तैयार नहीं हो सकती थीं। जी० बी० रोड पर दुकानें मिलनी कुछ सहज थीं। इसलिए मशीनरी के व्यापारियों ने जी० बी० रोड पर ही दुकानें खोलीं। इस बाजार के सामने रेलवे का माल गोदाम है जिसकी एक पक्की दीवार लम्बी लाहौरी गेट तक चली गयी है। कुछ लोगों ने इस दीवार के सहारे ही लकड़ी के खोखे डाल कर मशीनरी का काम शुरू कर दिया। इस प्रकार जी० बी० रोड इस व्यापार का अब एक प्रमुख केन्द्र बन गयी है।

अधिकांश मशीनें भारत निर्मित

मशीन बेचने वाली इस समय छोटी-बड़ी सब मिला कर १०० से अधिक दुकानें हैं। ये दुकानें थोक और परचूनी--दोनों प्रकार का माल बेचने वाली हैं। इन सब में करीब दो हजार व्यक्ति काम करते हैं। इस उद्योग में केवल दिल्ली में १ करोड़ रु० से अधिक की पूंजी लगी है। मशीनरी में लगभग ९७% भारत निर्मित है, बाकी २-३ प्रतिशत विदेश से आयात होती है। इस ९७% भारतीय मशीनरी से भी करीब ५०% दिल्ली में ही बनती है। बड़े साइज की मशीनें भी अब दिल्ली में बनने लग गयी हैं। मशीनरी के कुछ व्यापारियों की अपनी फैक्टरियां भी हैं।

वितरक केन्द्र

दिल्ली, प्रधानतः, मशीनरीका वितरक केन्द्र है, निर्माण केन्द्र नहीं। अधिकांश मशीनें बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में बनती हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब हिमाचल प्रदेश और जम्मू-काश्मीर—इन राज्यों की मांग, प्रायः, दिल्ली से ही पूरी होती हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं, वितरक केन्द्र होने से, दिल्ली इस समय अच्छा विकसित हो गया है। करीब ५ करोड़ रु० का वितरण प्रतिवर्ष दिल्ली द्वारा होता है। दिल्ली की अधिकांश फैक्टरियां अपने लिए मशीनें दिल्ली से ही खरीदती हैं। अधिकांश जिन मशीनों की बिक्री होती है वे वर्कशाप मशीनरी पम्पिंग सेट, एलेक्ट्रिक मोटर और मिल स्टोर की मशीनें हैं। छापाखाने की मशीनों की मार्केट दिल्ली में नहीं हैं। ये प्रायः "रि बिल्ट" होकर कलकत्ता, बम्बई से अथवा विदेशों से आयात होती हैं।

कृषि सम्बन्धी उपकरण मशीनरी की दूकानों पर प्रायः नहीं मिलते। पम्पिंग सेट ही ज्यादा ये दुकानें बेचती हैं। कृषि-उपकरण ट्रैक्टर बेचने वाले ही, प्रायः, बेचते हैं क्योंकि अधिकांश कृषि-उपकरणों का सम्बन्ध टैक्टरों के प्रयोग के साथ ही है।

मुख्य समस्याएं

इस उद्योग की मुख्य समस्याएं निम्न लिखित हैं :—

(१) हमारी सब से बड़ी समस्या गोदाम के स्थान की कमी का होना है। अगर हमारे पास बड़े-बड़े गोदाम होंगे तो हम अच्छे ढंग के "शो रूम" बनाकर ग्राहक को

सम्पदा

(पृष्ठ ३० का शेष)

हैं तथा राजनीति, बिदेशी भाषाएं तथा मिल-प्रबन्ध आदि की शिक्षा देने की व्यवस्था भी है।

इन सबका परिणाम यह हुआ है कि दिल्ली का स्थान अन्य सब राज्यों में, शिक्षा की दृष्टि से, सबसे प्रथम हो गया है जबकि यह गौरव, कुछ वर्ष पहले, केरल को प्राप्त था। समस्त भारत में साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत जहां २४.० है वहां केरल में ४६.८ और दिल्ली में ५२.७ हैं। साक्षर स्त्रियों का प्रतिशत दिल्ली में ४२.५ है जबकि समस्त भारत में १२.९ और केरल ३९.९ है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अपनी ओर खींच सकते हैं, उसमें इसके लिए दिलचस्पी पैदा कर सकते हैं और सबसे बड़ा लाभ यह कि जहां मांग पैदा कर सकते हैं, वहां उसे बढा भी सकते हैं। मौके पर चीज न होने से ग्राहक की मांग तत्काल पूरी नहीं होती और बाहर से माल आने तक उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसका बिक्री पर भी असर पड़ता है।

(२) हमारी दूसरी समस्या ट्रेन्ड व्यक्तियों की कमी है। पालिटैक्निकल स्कूलों व इंजिनीयरिंग कालेजों के पढ़े हुए छात्र हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं होते क्योंकि एक तो उन्हें क्रियात्मक ज्ञान बहुत कम होता है, केवल बुनियादी ज्ञान ही होता है। दूसरी बात यह कि उन्हें विशिष्ट (स्पेशेलाइज्ड) ज्ञान नहीं दिया जाता। ये लोग बड़े कारखानों व सरकार के इंजिनीयरी महकमें में भले ही उपयोगी हों पर मशीनरी की दुकानों पर बहुत सफल सिद्ध नहीं होते।

किसी टैक्निकल स्कूल का पढा व डिप्लोमा प्राप्त युवक मशीनरी की दुकान पर २५० रु० मासिक वेतन पर नियुक्त हो जाता है। यह इस व्यापार का न्यूनतम वेतन है। इस वेतन की अधिकतम सीमा ५०० रु. तक है। सब कम्पनियां तो नहीं पर कुछ बड़ी कम्पनियां वर्ष में दो मास का बोनस भी अपने कर्मचारियों को देती हैं।

(३) इस उद्योग की तीसरी समस्या बिक्री कर है। सामान्य बिक्र कर तो अन्य व्यापारियों की तरह हमें भी देना पड़ता है पर हमें दोहरा देना पड़ता है। एक तो अपने आढ़ती को और दूसरा दो प्रतिशत के हिसाब से उस ग्राहक को जिसे हम माल भेजते हैं।

मशीनरी-विक्रेताओं का एक नियमित रूप से संघ बना हुआ है जो सरकार द्वारा स्वीकृत है। यह संघ मशीनरी उद्योग के व्यापारियों के लिए पर्याप्त लाभ प्रद सिद्ध हो रहा है।

विज्ञापन के लिए

सम्पदा

सर्वोत्तम

साधन है

स्थायी महत्व की पुस्तकें

—भारत के प्रमुख उद्योग (पुरस्कृत)
वेद प्रकाशसिंह ७—५०

—दस महान् अर्थ शास्त्री
जोसेफ ए. शुम्पीटर ६—५०

—आर्थिक विकास का सापेक्ष चित्रण
जॉन केनेथ गैलब्रेथ २—०

—आर्थिक प्रगति की कुँजी
डी० जी० वतूलस १—०

—आर्थिक विचारधाराएँ
डा० श्रीकृष्ण श्रीवास्तव १०—०

—समय की प्रगति
कैथराइन बी० शिप्पैन २—०

—आधुनिक व्यावसायिक संगठन
प्रो० जयप्रकाश रस्तोगी ७—६०

—कार्यालय कार्य विधि
रामचन्द्रसिंह सागर ६—०

—नयी राह
चेस्टर बोल्स ६—०

—शासन पक्ष निदर्शन
राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन ६—०

आत्माराम एण्ड संस

काश्मीरीगेट, दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देहली में बाहर से अनुमानित खाद्य आयात

औसत मासिक (मीट्रिक टनों में)

पदार्थ	१९५९	१९६०	१९६१	१९६२
गेहूँ	२२,७८०	२५,२१६	२३,६१६	४२,७९१
चना	१५,६०१	८,६५१	७,२६१	७,९८६
चावल	३,५४०	२,५०७	३,१८२	३,००१
मोटा अनाज	१६,८२५	१७,८०२	२४,८०४	२२,४८५
मैदा या आटा	१,१३८	५,५६३	५७७	१५३
दालें	१,५५१	१,३६६	१,३२१	७९७
विशुद्ध चीनी	६,७४८	५,१९७	५,८४१	५,८९६
मिठाइयां, मछली, अण्डे और मांस	५४६	५२४	६७७	७७७
चाय	२७४	११४	४०९	५५५
घी, क्रीम और मक्खन	१,०६१	१,२२५	१,४७७	१,२२१
वनस्पति घी	२७४	२१८	७४	—
सूखे फल, नारियल खजूर आदि	२,०३५	२,१८५	२,४०५	—

उपर्युक्त तालिका से मालूम हो जाता है कि आप दिल्ली निवासी कितना खाते हैं। इस तालिका में दिल्ली के देहात में पैदा होने वाले अनाज अथवा वनस्पति उद्योग में बनने वाला वनस्पति तेल आदि सम्मिलित नहीं हैं किन्तु यह उत्पादन समस्त दिल्ली की खपत को देखते हुए बहुत नहीं है और कृषि जन्य पदार्थ तो, अधिकांशः देहात में ही खप जाते हैं। इसलिए, दिल्ली नगर की दृष्टि से ये अंक बहुत अधिक भ्रामक नहीं होंगे।

ये अंक मासिक औसत के हैं। यदि इन्हें जनसंख्या पर—विशेष कर दिल्ली की नगर निवासी जनसंख्या पर—बांट दिया जाए तो यह अनुमान हो सकता है कि दिल्ली में प्रति व्यक्ति उपर्युक्त पदार्थों की कितनी खपत होती है। यह अनुमान करते समय यह भी ध्यान में रखना होगा कि छोटे शिशुओं को हमें इस औसत में नहीं गिनना होगा।

उपर्युक्त तालिका से मालूम होता है कि १९५९ में गेहूँ, चना, चावल आदि अधिक मात्रा में दिल्ली में मंगवाये गये थे। परिणामतः, १९६० में इनकी कमी करनी पड़ी। इस तालिका से यह भी मालूम होता है कि दिल्ली में मछली, अंडे और मांस का प्रयोग जनसंख्या की अपेक्षा भी अधिक तेज गति से बढ़ रहा है। चाय का प्रयोग तो पिछले तीन सालों में, करीब दुगुना हो गया है। यह आश्चर्य की बात है कि इस सूची से अशुद्ध चीनी के प्रयोग में कुछ कमी प्रतीत होती है। इसका थोड़ा-बहुत स्थान विशुद्ध चीनी ने ले लिया है।

सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देहली प्रशासन का बजट

राजस्व आय
(लाख रु० में)

	संशोधित अनुमान ६२-६३	आनुमानिक बजट ६३-६४
१. भूमि मालगुजारी	६.६९	७.३४
२. राज्य उत्पादन शुल्क	१,८२.१६	१२४.९१
३. सरकारी टिकट शुल्क	१०९.५०	११५.५०
४. जंगलात	०.४०	०.४१०
५. रजिस्टरी	११.९९	१३.४९
६. वाहनों पर कर	६०.००	१००.००
७. बिक्री कर	६५२.५२	७०७.५०
८. अन्य कर व शुल्क	२८०.४१	२८२.६९
९. ऋण-सेवाएं	९६.७४	१०२.८७
१०. नागरिक प्रशासन	७६.२४	७२.९१
११. विविध (विशुद्ध)	८.३८	९.०५
महायोग राजस्व आय	१४८४.५८	१५३६.६६

राजस्व व्यय
(लाख रु० में)

राजस्व पर सीधी मांग	८०.७३	४८.२५
नहरें, बांध, ड्रेन आदि	४.८१	४.०८
सामान्य प्रशासन	५५.२५	६०.६३
न्याय-प्रशासन	२५.४८	२५.१४
जेल	१०.७७	१०.८३
पुलिस	२५७.६८	२९५.९४
शिक्षा	४८०.२५	५०६.८३
चिकित्सा	८२.९१	९७.१८
सार्वजनिक स्वास्थ्य	५.९८	२.०४
कृषि	८.९०	९.५३
पशु-चिकित्सा	६.८७	६.७३
सहकारिता	७.८३	७.८७
उद्योग	७.१४	९.२३
विविध व्यय	९५४३	१४८.१४
विविध	५२२.२४	६०३.८५
अ—सामान्य व्यय, सामुदायिक योजना एन. सी. सी. स्थानीय विभाग सहित	९.७२	४१.९७
महायोग राजस्व व्यय	१६०७.२६	१८६८.६४

उपर्युक्त बजट के अंक देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य की सरकारी टिकट, रजिस्टरी, गाड़ियों पर टैक्स और बिक्री कर आदि से आमदनी ज्यादा बढ़ रही है। बिक्री कर तो, करीब, ५० लाख रु० से भी ज्यादा बढ़ गया है और यही हाल गाड़ियों पर लगे करों का है। यह दोनों संख्याएं दिल्ली के समृद्ध होने की अथवा राज्य द्वारा कर वृद्धि के परिणाम हैं—यह इन अंकों से स्पष्ट नहीं होता।

प्रशासन प्रबन्ध में सवा पांच लाख रु० की वृद्धि हुई है और पुलिस में करीब ४० लाख रु० की, शिक्षा में भी २६ लाख रु० का खर्च बढ़ा है। उद्योगों का विकास तीव्रतर गति से होने की आशा है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली निगम का बजट १९६३-६४

आय	स्थायी समिति द्वारा स्वीकृत	व्यय
१. सामान्य कर, अप्रत्यक्ष कर और विविध राजस्व	७,२८,४७,५००	४८,१३,७००
२. चल सम्पूर्ति	—	१५,००,०००
३. शिक्षा	१,२५,५२,०००	२,४४,४७,९००
४. पुस्तकालय	—	१,७०,६००
५. सार्वजनिक स्वास्थ्य	७,१२,७००	४५,५९,९००
६. डाक्टरी चिकित्सा	३,७१,१००	९४,१५,५००
७. सफाई, गली-सफाई	१,७५,०००	१,२२,९४,९००
८. सफाई, नालियां और सीवर	—	१,०८,८३,६००
९. सड़कें और आम रोशनी	१६,४०,०००	७९,०३,८००
१०. इमारतें, भूमि ग्रहण और व्यवस्था	४०,५७,०००	५१,७७,२००
११. फायर ब्रिगेड	८,७५-०००	२०,९२,७००
१२. लाइसेंस देना, अनधिकृत स्थान से हटाना	२३,०५,९००	५,५२,५७०
१३. बाग और खुले स्थान	५०,०००	१८,८३,३००
१४. मार्केट और कसाई खाने	५,५०,०००	३,५८,०००
१५. सुधार योजनाएं, गन्दी बस्तियों की सफाई, झुग्गी, झोपड़ी योजनाओं को हटाना	२२,१५,०००	१८,९२,०००
१६. पूंजीकोष से राजस्व को अंशदान, उधार और योजना कार्यों के हिसाब में	३५,००,०००	१,६८,०४,१००
१७. बिजली हिसाब में से हस्तान्तरण	४०,००,०००	२३,००,०००
कुल आय	९,२७,५०,६००	कुल व्यय १०,७०,५३,७००

देश की आर्थिक समस्याओं को समझने के लिए सम्पदा का पढ़ना अनिवार्य है।

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली का विशालतम उद्योग

दे हली क्लाथ मिल्स : सफलता की ओर

दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लि० का वर्तमान स्थिति तक जो विकास हुआ है उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। १८८९ में एक छोटी बुनाई के मिल के रूप में इसका प्रारम्भ हुआ था। दिल्ली क्लाथ मिल ने पिछले ७५ वर्ष में निरन्तर प्रगति की है और अब उस दिन की प्रतीक्षा है जब इस का पौन सदी का हीरक समारोह उत्साह पूर्वक मनाया जाएगा। दिल्ली क्लाथ मिलने देश के औद्योगिक क्षेत्र में जो अपना विशिष्ट स्थान बनाया है वह स्वर्गीय लाला श्री राम जी के बुद्धि मत्ता पूर्ण नेतृत्व के कारण ही है। लालाजी का सम्बन्ध इस मिल के साथ १९१२ में शुरू हुआ और अपने जीवन के अन्तिम काल तक बना रहा।

चार कपड़ा मिलें

डी. सी. एम. के विकास के दो विशेष पहलू हैं—समय-समय पर नयी फैक्टरियों का निर्माण और निर्माण की प्रवृत्तियों में विविधता। इस समय कम्पनी चार कपड़ा मिलों और अनेक उद्योगों की व्यवस्था करती है! (इनमें से तीन मिलें एक ही क्षेत्र में हैं और एक अन्य पाकिस्तान में है)। एक रेशम की मिल, दो बड़ी चीनी की मिलें, उत्तर प्रदेश में, एक डिस्टलरी, एक भारी कैमिकल और एसिड बनाने का प्लांट, और एक वनस्पति फैक्टरी। दो और फैक्टरियां बन रही है—एक पी. वी. सी. और कास्टिक सोडा के निर्माण के साथ कैलशियम कार्बाइड और दूसरी रायन टायर कार्ड के लिए—दोनों ही राजस्थान में बन रही है।

रासायनिक पदार्थ भी

कम्पनी की प्रवृत्तियां किस प्रकार विविध ढंग की है—इसका सर्वोत्तम प्रमाण इसके अनेक प्रकार के उत्पादनों से मिलता है। हमारी कपड़ा मिले सूती धागा और कपड़ा, छींट और तौलिये और नक्काशी वाले रेशमी कपड़े तैयार करती है। दौराला शूगर वर्क्स चीनी की टिकियां, बिस्कुट आदि और पावर अलकोहल तैयार करता है। रासायनिक पदार्थों में, अन्य चीजों के इलावा, उर्वरक कास्टिक सोडा, सुपर फास्फेट, फैरिक अलुम, लिक्विड क्लोराइन, और सल्फरिक, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड—शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इंजिनीयरिंग विभाग बड़ी तेजी के साथ एक नयी प्रवृत्ति को बढा रहा है और वह है अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टी करण के अनुसार रासायनिक प्लान्टों का विस्तार।

कम्पनी की वित्तीय स्थिति

कम्पनी का वित्तीय विस्तार कितना विशाल रूप धारण कर रहा है, यह कुछ आंकड़ों से स्पष्ट हो जाएगा। १९६२ में कम्पनी का कुल उत्पादन ३० करोड़ रुपये का था। इसमें सुरक्षित और अतिरिक्त बचत ७ करोड़ रुपये से अधिक थी जबकि हिस्से की पूंजी ४.५ करोड़ रु. थी। सम्पत्ति (एसेट्स) १६ करोड़ रु. तक के थे और कुल रकम का सामान २१ करोड़ रु. से अधिक का था। मोटे रूप में पूंजी की वापसी ४,२९ करोड़ रु. की थी, जो सामूहिक पूंजी (ब्लाक कैपिटल) पर २४.५% और उत्पादन (टर्न ओवर) पर ११.१% थी।

स्वर्गीय लाला श्रीराम का दिल्ली क्लाथ मिल के साथ जो सम्बन्ध रहा, उसका वर्णन पहले हो चुका है। कम्पनी के वर्तमान बोर्ड आफ डायरेक्टर में ऐसे महानुभाव हैं, जो व्यापार और सार्वजनिक जीवन में प्रमुख स्थिति रखते हैं। इस बोर्ड के सभापति लाला श्रीराम के सुपुत्र लाला भरत राम हैं। आप औद्योगिक क्षेत्र में अपनी दूरदर्शिता, व्यापारिक प्रतिभा और रचनात्मक तथा उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व के लिए सुविख्यात हैं। इस बोर्ड में लाला चढ़तराम भी हैं जिनमें प्रतिकूल अवस्थाओं में से भी मार्ग निकाल लेने, पहल करने और ठोस कल्पना करने के विशिष्ट गुण हैं।

कुछ विशेषताएं

डी. सी. एम. ने एक से अधिक दिशाओं में औद्योगिक जगत का नेतृत्व किया है। स्वर्गीय लाला श्रीराम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की दूरदर्शिता का ही यह परिणाम है कि १९३९ से ही प्रबन्धक मंडल में श्रमिकों का एक प्रतिनिधि डायरेक्टर के रूप में लिया जाता है।

यह कम्पनी एक अन्य क्षेत्र में भी सबसे आगे है और वह है बड़ी संख्या में अपने ही खुदरा वस्त्र भंडारों का संचालन जहां निश्चित दर पर कपड़ा बेचा जाता है। इस समय, लगभग ३०० वस्त्र भंडारों की ऐसी श्रृंखला काम कर रही हैं। विकासोन्मुख अर्थ व्यवस्था में कपड़े की कमी को दृष्टि में रखते हुए, इस प्रकार के भंडारों का महत्व बढता जाता है।

पूंजी लगाने वाले को पिछले वर्षों में जो लाभ मिला है, उसका अनुमान इसी बात से लगया जा सकता है कि १९६२ में कुल पेड अप पूंजी ४.५१ करोड़ रु. में से ३.४८ करोड़ रु. तक बोनस शेयरों की वह राशि थी, जो समय समय पर जारी की गयी थी।

निष्ठवान कार्यकर्त्ता

आगामी वर्षों में कम्पनी अपने चालू उद्योगों को उन्नत करने के अतिरिक्त नयी प्रवृत्तियां भी जारी कर रही है। १९६२ में कम्पनी का श्रमिक बल विभिन्न स्तरों पर लगभग २५ हजार व्यक्तियों का था और इनकी कुल वेतन राशि ५.७२ करोड़ रु. थी। पिछली तीन चौथायी सदी से इस औद्योगिक संस्था का ऐसा सुदृढ, संगठन और प्रेरणादायक विकास हुआ है कि इसे एक शब्द में "सफलता का अजस्र प्रवाह" कहा जा सकता है। ● ●

दिल्ली में वन

दिल्ली में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत ११,८०० एकड़ भूमि में छोटे बड़े सब मिलाकर ४० वनों का विकास किया जा रहा है। इस वर्ष आभा नगर में २२६ एकड़ में और जजापुर में ७०० एकड़ में दो और वन लगाए जायेंगे।

यमुना के किनारों पर भूमि को कटाव से बचाने के लिए ५०० एकड़ में वृक्ष लगाए गए हैं। दिल्ली प्रदेश में सड़कों के किनारे और रेल लाइनों के बगल में १८० मील में वृक्ष लगाए जा रहे हैं।

दिल्ली में वृक्षारोपण आन्दोलन की सफलता इस बात से प्रकट होती है कि सन् १९५० में वनों से केवल दो सौ रुपए की वार्षिक आय थी जो सन् १९६२-६३ के दौरान २० हजार रुपए तक बढ़ गई है।

(पृष्ठ ११५ का शेष)

पर अधिक बल दिया जा रहा है। सहकारी समितियों की संख्या ३१ मार्च १९६३ तक २००९ हो गई है जिसके २०३,२४५ सदस्य हैं। २८१ समितियों का विघटन किया गया है। कृषि सहकारी समितियों की संख्या ८५० है जिसके २५,२६७ सदस्य हैं। इसके साथ साथ २१ संयुक्त फार्मिंग समितियां भी काम कर रही हैं जिनके ३४९ सदस्य हैं।

वर्तमान राष्ट्रीय संकटकालीन स्थिति के दौरान दिल्ली में एक सुदृढ़ ग्राम स्वयं सेवक दल तैयार किया गया है जिसमें ११२००० जवान हैं। इनके सामने तीन कार्यक्रम रखे गये हैं। कृषि उत्पादन की वृद्धि में योग देना, सामूहिक शिक्षा प्रसार और जन सुरक्षा कार्यों का संगठन करना।

उद्योग

दिल्ली के उद्योगों का यह प्रयास है कि तीसरे योजना काल में काफी लाभदायक प्रगति की जाये। तीसरी योजना के गत दो वर्षों में ४७६ पार्टियों को छोटे उद्योग धन्धों के लिये २३ लाख रुपये अग्रिम दिये गये हैं। ओखला स्थित औद्योगिक बस्ती में ४० फैक्टरियों का निर्माण कराया गया है जो लगभग पूर्ण हो चुका है। खेल के समान बनाने वाली ४१ फैक्टरियों के शेडों का निर्माण चल रहा है।

पानी और बिजली की सप्लाई के सम्बन्ध में उत्साह जनक प्रगति हुई है। प्रथम योजना के समय प्रतिदिन ३५ मिलियन गैलन पानी सप्लाई किया जाता था। अब ९० मिलियन गैलन प्रतिदिन दिया जा रहा है। तीसरी योजना का लक्ष्य १३५ मिलियन गैलन प्रतिदिन आंका गया है। इसी प्रकार बिजली पहली योजना के समय ३७,००० किलोवाट दी जाती थी जो दूसरी योजना के अन्त में ८८,००० किलोवाट हुई और तीसरी योजना के पूरा होने पर, आशा है २,४५,८०० किलोवाट का लक्ष्य पूरा हो सकेगा।

राजधानी का सबसे महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रम मास्टर प्लान है जिसे अन्तिम रूप देकर क्रियान्वित किया जाना है। मास्टर प्लान पर विस्तृत लेख अन्यत्र देखिये। ●

सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली के श्रमिक और श्रम समस्या

वैसे तो दिल्ली भारत की राजधानी बहुत काल से है, किन्तु स्वतन्त्रता के बाद से देश में औद्योगिक जागृति उत्पन्न होने के कारण दिल्ली का महत्त्व व्यापारिक, औद्योगिक, लघु-औद्योगिक और हस्तकला की दृष्टि से भी विशेष हो गया है। यद्यपि यहां पर कलकत्ते और बम्बई जैसे न तो बड़े-बड़े कारखाने हैं और न ही कुछ विशेष कारणों से शायद हो सकते हैं। जिस प्रकार दिल्ली के उद्योग राजधानी होने के कारण अपना विशेष महत्त्व रखते हैं, उसी प्रकार इन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक और उनकी समस्यायें भी अपनी ही विशेषता रखती हैं। ज्यों ज्यों दिल्ली के उद्योग बढ़ते जाते हैं, त्यों-त्यों श्रमिक, उनकी समस्यायें और औद्योगिक झगड़े भी बढ़ते जा रहे हैं।

प्रथम श्रम अधिकारी की नियुक्ति १९४८ ई० में हुई। इनके साथ उस समय एक श्रम निरीक्षक, एक दुकानों तथा व्यापारिक संस्थाओं का निरीक्षक और चार उप निरीक्षक थे। उस समय मुख्य निरीक्षक फैक्टरी का कार्यालय पृथक् था और उसमें एक फैक्टरी निरीक्षक थे। अब उद्योग कार्यक्रमों व तदनुसार तेजी से बढ़ती हुई श्रम समस्याओं को सुलझाने के लिए एक श्रम-आयुक्त, चार समझौता अधिकारी, दो श्रम अधिकारी, एक श्रम अधिकारी तथा मुख्य निरीक्षक दुकान व व्यापारिक संस्थायें, एक श्रम कल्याण अधिकारी, एक सहायक श्रम अधिकारी, एक रिसर्च असिस्टैंट, एक स्टेट मैनेजर, सत्रह दुकान आदि के निरीक्षक, दस लेबर वैलफेयर सुपरवाइजर, एक म्यूजिक टीचर, एक कढ़ाई तथा सिलाई की अध्यापिका, एक मुख्य निरीक्षक फैक्टरी, पांच फैक्टरी निरीक्षक, जिनमें से एक बायलर और विद्युत निरीक्षक भी है। और एक मैडीकल निरीक्षक के अतिरिक्त अनेक क्लर्क और चौथे दर्जे के कर्मचारी हैं। श्रम विभाग का यह विस्तार दिल्ली की बढ़ती हुई श्रम समस्याओं का द्योतक है।

श्रम समस्याएँ

मुख्य श्रम समस्तएँ इस प्रकार हैं :—

१. भिन्न-भिन्न प्रकार के श्रमिकों के भिन्न-भिन्न प्रकार के औद्योगिक झगड़े।

२. श्रम कानूनों को भली भांति लागू करना।

३. श्रमिकों का कल्याण और मनोरंजन।

४. श्रमिकों के आवास का प्रबन्ध।

५. श्रमिकों को श्रम-विषयों और श्रम कानूनों की जानकारी करवाना व उनकी शिक्षा देना।

श्रमिकों की ५ श्रेणियां

दिल्ली के उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को हम पांच मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं :—

१. घर व सड़क बनाने वाले श्रमिक।

२. रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिक।

३. लघु उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक।

४. व्यापारिक संस्थाओं और दुकानों में काम करने वाले श्रमिक और

५. परिवहन में काम करने वाले श्रमिक।

१—भवन और सड़क निर्माण में काम करने वाले श्रमिक अधिकतर राजस्थान के हैं। दिल्ली में नये-नये सरकारी भवनों और व्यापारिक भवनों के साथ-साथ दूतावासों के भवन भी बन रहे हैं। इनके अतिरिक्त दिल्ली निवासी भी अपने रहने के मकान बनवाते रहते हैं। भवन और सड़क निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक एक स्थान पर स्थायी तौर पर नहीं रह सकते। जहां काम होता है उसके समीप ही बस जाते हैं। इसी कारण ये लोग कच्ची झोंपड़ियां ही बनाते हैं। ये श्रमिक दैनिक वेतन पर काम करते हैं। इनका वेतन 'न्यूनतम वेतन कानून' के अन्तर्गत निर्धारित है। ये काम अधिकतर ठेके पर होते हैं। जब कभी ठेकेदार से इन्हें वेतन समय पर नहीं मिलता तो इन श्रमिकों को श्रम विभाग से मदद लेनी पड़ जाती है। माह जून, १९६२ में वेतन बढ़वाने के लिये भवन निर्माण में लगे सैकड़ों श्रमिकों ने काम करना बन्द कर दिया था। इस उद्योग में लगे श्रमिकों का फैक्ट्रियों में काम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

करने वाले श्रमिकों की तरह मालिक और नौकर का सम्बन्ध नहीं होता। अतः इन पर न तो प्राविडेन्ट फन्ड एक्ट लागू होता है और न ही कर्मचारी राज्य बीमा कानून लगता है।

२—रजिस्टर्ड फैक्टरियों में काम करने वाले श्रमिक मुख्य रूप से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के हैं। दिल्ली में लगभग १२०० रजिस्टर्ड फैक्टरियां हैं, जिनमें ६२,००० श्रमिक काम करते हैं। कुछ फैक्टरियों ने – जैसे दिल्ली क्लाथ मिल, बिरला मिल, स्वतन्त्र भारत मिल और हिन्दुस्तान इंसैक्टीसाइड ने अपने श्रमिकों के लिये क्वार्टर बनवाये हैं। दिल्ली प्रशासन, सब्सीडाइज़्ड इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत करमपुर, नजफ़गढ़ रोड, नई दिल्ली पर अब तक २,००० से अधिक क्वार्टर बनवा चुका है। किलोकरी के १४४ क्वार्टर दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली नगर निगम से हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी के श्रमिकों को किराये पर देने के लिये लिये हैं। इसी प्रकार ५६ क्वार्टर नगर निगम ने हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी के श्रमिकों को किराये पर दिये हैं। बाकी श्रमिक, श्रमिक बस्तियों और कटरों आदि में रहते हैं।

३—लघु-उद्योग, व्यापारिक संस्थाओं और दुकानों में काम करने वाले श्रमिक भी अधिकतर दिल्ली, उत्तरप्रदेश और पंजाब के हैं। फैक्टरियों में काम करने वाले श्रमिकों की तरह इनके लिये कोई सरकारी सहायता प्राप्त आवास योजना नहीं है। इन पर राजकीय कर्मचारी बीमा योजना कानून भी लागू नहीं होता। दिल्ली की दुकान और व्यापारिक संस्थाओं का कानून इन पर लगता है। श्रमिकों के काम करने का समय, वेतन देने की मियाद, अतिरिक्त समय, अवकाश आदि इन्हीं के अन्तर्गत निर्धारित किये जाते हैं। इन नियमों की विशेषता यह है कि साढ़े नौ बजे सुबह दुकानें और आठ बजे सुबह व्यापारिक संस्थायें खुलती हैं और साढ़े सात बजे सायं दुकानें और ६ बजे सायं व्यापारिक संस्थायें बन्द हो जाती हैं। इससे श्रमिकों से अधिक काम लेने की गुंजाइश कम हो गई है।

४—परिवहन उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी अधिकतर पंजाब और दिल्ली के हैं। ये लोग न्यूनतम वेतन कानून के अन्तर्गत आते हैं। ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट के अन्तर्गत नियम बन गये हैं और इस एक्ट के शीघ्र ही लागू हो जाने की आशा है।

जून, १९६२ से पूर्व निर्देशक उद्योग विभाग ही श्रम विभाग के कार्य को देखते थे। दिल्ली के बढ़ते हुए औद्योगिक विवादों के कारण दिल्ली में श्रम विभाग के लिये अलग अधिकारी की नियुक्ति की आवश्यकता अनुभव हुई और दिल्ली के प्रथम श्रमायुक्त ने ४-६-६१ को भार संभाला। नजफ़गढ़ और शाहदरा के श्रमिकों की सुविधा के लिये दो क्षेत्रीय कार्यालय भी खोले गये हैं।

औद्योगिक विवाद

१ अप्रैल, १९६२ से ३१ मार्च, ६३ तक समझौता विभाग ने १०८७ औद्योगिक झगड़े निपटाने का प्रयत्न किया, जिनमें ५७५ में समझौता हो गया और २६० में कोई समझौता नहीं हो सका। २५४ औद्योगिक झगड़े न्यायालय में भेजने के लिये दिल्ली प्रशासन को भेजे गये। २२ केसों में दोनों पार्टियां आर्बीट्रेशन के लिये राजी हो गईं। हड़ताल व तालाबन्दी के कारण इस समय में ३१९८३ श्रम दिन (मैन डेज़) नष्ट हुए।

निर्णय (अवार्ड)—दिल्ली की औद्योगिक अदालत ने १-४-६२ से ३१-४-६३ तक धारा ३३-ए के अन्तर्गत प्रार्थना पत्रों के १३६ निर्णय दिये। मालिकों और ट्रेड यूनियनों ने ३ मामलों में औद्योगिक अदालत के निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।

शिकायतें—१-४-६२ से ३१-३-६३ तक २१३२ शिकायतें नौकरी से निकालने, छंटनी, काम बंदी, बोनस, आदि की आईं। समझौते के बाद रु० १३१५०९.७५ नये पैसे श्रमिकों को दिलवाये गये।

ट्रेड यूनियन विभाग

श्रमायुक्त ही ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार भी हैं। ३१-३-६३ तक ४१३ ट्रेड यूनियनें रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। दिल्ली में चार मुख्य ट्रेड यूनियनें काम करती हैं:—

(१) इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस।
(२) आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस।
(३) यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस और
(४) भारतीय मजदूर संघ।

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अधिकतर यूनियन इनसे सम्बन्धित हैं। बहुत सी स्वतन्त्र ट्रेड यूनियनें भी हैं।

श्रम-कल्याण विभाग—इसका कार्य श्रम कल्याण केन्द्रों का प्रबन्ध और श्रम कल्याण से सम्बन्धित है। दिल्ली में १० श्रम कल्याण केन्द्र हैं :—

(१) चूड़ी वालान (२) मोडल बस्ती
(३) कमला नगर (४) रीडिंग रोड
(५) डिप्लोमेटिक एन्क्लेव (६) कोटला मुबारकपुर
(७) शाहदरा (८) ओखला
(९) करोलबाग (१०) नजफ़गढ़ रोड

इन केन्द्रों में श्रमिकों की शिक्षा व मनोरंजन के लिये रेडियो हैं। हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी की पत्र-पत्रिकायें भी इन केन्द्रों में श्रमिकों के पढ़ने के लिये आती हैं। हिन्दी, उर्दू के नाटक और उपन्यास भी श्रमिकों को पढ़ने के लिये दिये जाते हैं। नजफ़गढ़ रोड के श्रम कल्याण केन्द्र में टेलीविजन भी हैं। मोडल बस्ती और नजफ़गढ़ रोड के श्रम कल्याण केन्द्रों में श्रमिकों की स्त्रियों और लड़कियों को कटाई-सिलाई और कढ़ाई भी सिखाई जाती है। जो लड़कियां कोर्स पूरा करके पास हो जाती हैं उन्हें प्रमाण पत्र भी प्रदान किये जाते हैं। इन केन्द्रों में श्रमिक कैरम, शतरंज, कबड्डी, वाली बाल आदि खेलते हैं। मैचों का भी प्रबन्ध होता है। ये केन्द्र आजकल संकट कालीन सूचना केन्द्रों का भी कार्य कर रहे हैं। माह में एक बार प्रत्येक केन्द्रों में निःशुल्क फिल्म भी दिखाई जाती है जिसका लाभ हजारों की संख्या में श्रमिक उठाते हैं।

न्यूनतम वेतन, दुकान तथा व्यापारिक संस्था विभाग—

इस विभाग का काम दुकान और न्यूनतम वेतन कानूनों को लागू करना है। न्यूनतम कानून भवन और सड़क निर्माण, दाल और आटे की चक्की, आटोमोबाइल सर्विस स्टेशनों, सैटल बर्किंग ऐस्टाबिलशमेन्ट्स, मोटर ट्रान्सपोर्ट और स्थानीय निकायों (लोकल बाडीज़), प्रिंटिंग प्रेस, फाउन्ड्रीज, स्टोन क्रशिंग और क्यूरीज पर लागू होता है। मुख्य निरीक्षक समेत १७ निरीक्षक इन कानूनों को लागू करने की देख भाल करते हैं।

दिल्ली में लगभग ८०,००० रजिस्टर्ड दुकानें और व्यापारिक संस्थाएं हैं, १-४-६२ से ३१-३-६३ तक दुकानों के निरीक्षकों ने २३२३१ निरीक्षण किये। ४७९४ चालान किये, २५५२ मुकदमे दिल्ली की अदालतों ने तय किये और उनमें ८३६९० रुपया जुर्माना किया।

औद्योगिक आवास विभाग

इस विभाग का कार्य अनुदान प्राप्त श्रमिक आवास योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण, सरकारी आवास योजना के अन्तर्गत बने भवनों का अलाटमेन्ट और प्रबन्ध करना है जो सरकारी भवन निर्माण समिति और निजी मालिक अपने सदस्य कर्मचारियों के लिये मकान बनवाना चाहते हैं।

नजफ़गढ़ रोड पर २००० से अधिक क्वार्टर सरकारी औद्योगिक आवास के अन्तर्गत बन चुके हैं। शाहदरा में १७० बीघे और १२ बिसवे जमीन औद्योगिक श्रमिकों के लिये घर और कल्याण केन्द्र बनवाने के लिये प्राप्त करने के प्रयत्न जारी है। इसी प्रकार ओखला में भी औद्योगिक कर्मचारियों के आवास के लिये २२६ एकड़ भूमि ली गई थी, जिसका अधिक भाग ग्रीन बेल्ट में आ जाने के कारण उसके बजाय दूसरी जमीन प्राप्त की जा रही है। शाहदरा में ५२८ क्वार्टर और ओखला में ६२६ क्वार्टर बनने हैं।

फैक्टरी विभाग

इस विभाग का कार्य फैक्टरी ऐक्ट, पेमेन्ट आफ़ वेजेज़ ऐक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, बायलर एक्ट आदि को लागू करना है। श्रमायुक्त दिल्ली प्रशासन स्थायी आदेश एक्ट के अन्तर्गत प्रमाणित अधिकारी भी है। मार्च १९६३ तक ५९ स्टेन्डिंग आर्डर प्रमाणित हो चुके हैं। ● ●

सम्पदा आपकी अपनी पत्रिका है।
इसके ग्राहक बनिये और समीपवर्ती पुस्तकालय को सम्पदा मंगाने पर विवश कीजिये।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चिरयौवना दिल्ली का निर्माण

(पृष्ठ १७ का शेष)

बारे में कोई ऐसी व्यवस्था करनी आवश्यक है जिससे उन्हें शहर से हटा भी दिया जाए तथा साथ ही जिससे कि लोगों की धार्मिक भावना को किसी प्रकार की ठेस भी न पहुँचे।

शहर की शोभा में अभिवृद्धि करने वाली एक अन्य योजना नगर की गन्दी बस्तियों की धीरे-धीरे समाप्ति है। प्रथम पांचसाला योजना के अन्तर्गत अजमेरी गेट की गन्दी बस्तियों को समाप्त करने की महत्वपूर्ण योजना अमल में आई। अब यह क्षेत्र नगर का शानदार व्यापारिक केन्द्र बन गया है। प्रतीत ऐसा होता है कि इस असाधारण सफलता से भी नव-निर्माण में संलग्न अधिकारियों को प्रोत्साहन और बल प्राप्त नहीं हुआ। फलस्वरूप द्वितीय पांचसाला योजना में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। आवश्यकता इस बात की है कि गन्दी बस्तियों को सुन्दर बस्तियों के रूप में परिणत करने का यह कार्य निरन्तर चालू रहे। इस कार्य को बड़ी और छोटी योजनाओं में विभाजित कर के, इस दिशा में सतत प्रयत्न जारी रहने आवश्यक हैं।

आबादी का प्रश्न

राजधानी की आबादी सम्बन्धी समस्या के सम्बन्ध में, प्रतीत ऐसा होता है, कि शासन ने कोई निश्चित नीति नहीं बनाई है। सरकारी दफ्तरों को अन्यत्र ले जाने की जिन योजनाओं की चर्चा यदा-कदा सुनाई पड़ती है, उनसे ऐसा भ्रम होता है कि प्रशासन आबादी को नियंत्रित करना चाहता है। इसके विपरीत नगर में छोटे और बड़े उद्योगों की योजनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि आबादी को नियन्त्रित करने की बात नहीं सोची जा रही। ऐसी दशा में सब से पहली आवश्यकता इस बारे में स्थिति के स्पष्टीकरण की है।

संसार के बड़े नगरों की तुलना में दिल्ली नगर की आबादी कुछ अधिक नहीं है। लन्दन और न्यूयार्क जैसे नगरों की आबादी दिल्ली नगर से कई गुनी हैं। स्वयं देश में कलकत्ता और बम्बई दो ऐसे नगर हैं, जिनकी आबादी दिल्ली से बहुत अधिक है। यदि दिल्ली नगर का समुचित योजना-बद्ध विकास किया जा सके तथा जल, विद्युत, परिवहन, सड़कों और आवास आदि की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था संभव हो, तो आबादी का नियन्त्रण अनिवार्य और आवश्यक नहीं होगा। यदि ऐसा प्रबन्ध संभव न हो, तो सचमुच आबादी के नियन्त्रण की बात सोचनी होगी।

मूल अड़चनें और न्यूनताएं

दिल्ली नगर की विविध समस्याओं और उनके सम्बन्ध में की गई प्रगति की संक्षिप्त चर्चा करने के उपरांत यह आवश्यक है कि इन समस्याओं के समाधान में जो मूल अड़चनें और न्यूनताएं हैं उनकी भी संक्षेप में जानकारी प्रदान की जाए। प्रशासन द्वारा प्रकाशित विवरणों को ध्यान में रखते हुए, इन्हें निम्न रूप में क्रम-बद्ध किया जा सकता है :—

(१) नगर-निर्माण के लिए किसी केन्द्रीय अधिकारी व्यक्ति या इकाई का अभाव। बहुत से कार्य बहुत सी संस्थाओं में बंटे हुए हैं। आवश्यकता इन्हें एक सूत्र में पिरोने की है, जिससे प्रगति को तीव्र किया जा सके तथा किसी इकाई के ढीले पड़ने पर उसका ध्यान इस बारे में आकर्षित किया जा सके। यह अधिकारी व्यक्ति या इकाई असफलता अथवा धीमी प्रगति होने पर इस सम्बन्ध में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। आज कार्य की पूर्ति की जिम्मेदारी किसी की भी नहीं है।

(२) समस्या के तात्कालिक रूप पर दृष्टि तथा उसके समाधान की चेष्टा। भविष्य में समस्या का स्वरूप क्या होगा, इस सम्बन्ध में उदासीनता और उपेक्षा की वृत्ति का परिणाम यह है कि समस्या को हल करने के समस्त प्रयत्न विफल रहते हैं। प्रगति करने की समस्या पूर्ववत् बनी रहती है। प्रायः समस्त मूलभूत समस्याओं के बारे में स्थिति यही है कि उनका समाधान करते हुए भविष्य की मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। फलस्वरूप वे समस्याएं आज तक बनी हुई हैं और उनकी समाप्ति नजर नहीं आती। ऐसी दशा में, समस्याओं का हल खोजने से पूर्व, भविष्य की मांगों का क्रमबद्ध विवरण तैयार किया जाना आवश्यक है। इस विवरण को सम्मुख रख कर ही समाधान सोचे जायें।

(३) गौण और तात्कालिक समस्याओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया जायें। यह स्पष्ट है, कि समस्त दिल्ली

सम्पूर्ण

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राज्य तथा उनके निकटवर्ती क्षेत्र समय बीतने के साथ दिल्ली नगर के अंश बन जायेंगे। ऐसी दशा में दिल्ली प्रशासन द्वारा कृषि और सिंचाई जैसी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाना अनावश्यक है। इस प्रकार की तात्कालिक समस्याओं के बारे में तात्कालिक उपाय ही खोजे जाएं देहात के गृह-निर्माण नगर के अनुरूप ही होना चाहिये। अन्यथा इस सम्बन्ध में व्यय किया गया धन बेकार ही जायेगा।

(४) बिखरे हुए असम्बद्ध कार्यों के स्थान पर क्रम-बद्ध योजनाओं को क्रियात्मक रूप देना। इससे स्पष्ट परि-णाम प्राप्त किये जा सकेंगे तथा जो न्यूनताएं रह जायेंगी, वे भी साफ नजर आयेंगी।

मय दानव की आवश्यकता

कहते हैं कि जब दिल्ली नगर को सर्व प्रथम पाण्डवों ने बसाया था, तब उन्होंने इस नगरी के निर्माण के लिए मय दानव की सहायता ली थी। मय को अनेक कलाओं में अपूर्व निपुणता प्राप्त थी। उसने अपने कौशल से पाण्डवों के लिए चमत्कारपूर्ण मय नगरी की सृष्टि की थी, जो अनेक प्रकार के अचरजों और आकर्षणों से पूर्ण थी।

स्वन्त्रता की प्राप्त के बाद, अब जब कि दिल्ली का पुनर्निर्माण हो रहा है, तब सब से बड़ी आवश्यकता ऐसे ही किसी मय दानव अथवा योग्य, दूरदर्शी, अनुभवी, तथा भविष्य को आंक सकने और उसका मूल्यांकन करने में समर्थ इन्जिनियरों, वैज्ञानिकों और प्रशासकों की एक दल या इकाई की है, जो अपने कार्य और उत्तरदायित्व दोनों से परिचित हो। योग्यता की दृष्टि से अधिकतम समर्थ व्यक्तियों के दिल्ली में विद्यमान रहते हुए भी, दिल्ली अपने पुनर्निर्माण के लिए तो कोई ऐसी इकाई जुटा सकी है और न निर्माण-कार्य में दिलचस्पी रखने वाला कोई प्रशासक अपने लिए खोज सकी है। ऐसी दशा में अब जिस प्रशासक को दिल्ली के लिए चुना जाये, नगर के पुनर्निर्माण से उसकी निर्माण सबन्धी क्षमता का निश्चय कर लिया जाये तथा उसे अपने इस उत्तर-दायित्व से पूर्णतया अवगत कर दिया जाये। दिल्ली की समस्याओं के समाधान का यह भी एक प्रमुख अंग है।

यदि इन सब बातों पर ध्यान दिया गया, तब यह कोई अद्भूत बात नहीं होगी कि अगले दस या बीस सालों में दिल्ली नगर संसार के अन्य राजधानी नगरों के समकक्ष आ जाये। यह नगर एक बार फिर अपने ऐति-हास प्राचीन स्वरूप को प्राप्त करले माया नगरी के रूप में परिणत हो जाये।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अब

लिटर

अनिवार्य

देश भर के व्यापार में अब तरल पदार्थ मापने के मेट्रिक पैमानों का प्रयोग अनिवार्य हो गया है • किलोग्राम और मीटर पिछले वर्ष से ही अनिवार्य हो गए हैं, इस प्रकार अब माप-तौल की मेट्रिक प्रणाली ही भारत में एक मात्र कानूनी प्रणाली है • मेट्रिक प्रणाली की सरलता का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए इसकी इकाइयों (लिटर, मीटर और किलो) को उनके आन्तरिक मूल्य के अनुसार ज्यों का त्यों इस्तेमाल कीजिए • मेट्रिक पैमानों की पुराने माप-तौल जैसे सेर वगैरह से तुलना न कीजिए।

सही और सुविधाजनक लेन-देन के लिए

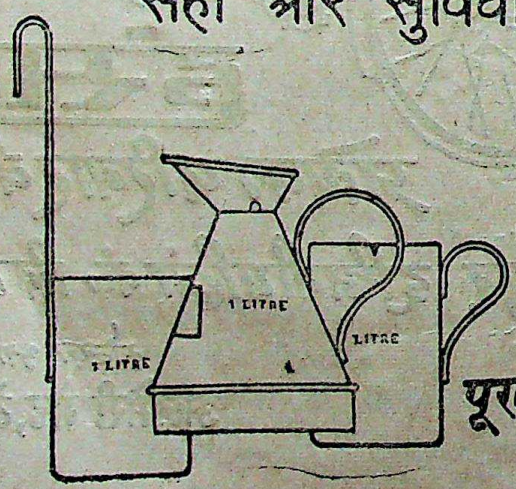

मेट्रिक इकाइयों का

पूर्ण अंकों में प्रयोग कीजिए

DA 63152

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(पृष्ठ ३४ का शेष)

जा रही है जिनमें रोजगार मिलने की गुंजाइश है या जिनके नये होने के कारण काम करने वालों को कमी है। उद्देश्य यह है कि सभी लोग साधारण शिक्षा लेकर दफ्तरों में ही सरकारी नौकरी की तलाश में न बैठे रहें, प्रत्युत अन्य उद्योग धन्धों के लिए अपने को तैयार करें।

प्रशिक्षण आर्य-क्रम

इस समय रोजगार, प्रशिक्षण व तकनीकी शिक्षा निदेशालय में दो प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है :—

(१) क्राफ्टसैन प्रशिक्षण—१८ महीनों का है और इसके अन्तर्गत ४० इंजीनियरी व गैर इंजीनियरी विभिन्न पेशों की ट्रैनिंग दी जाती है। जैसे फिटर, टर्नर, धातु की चद्दरों का काम, मैकैनिक, रेडियो मैकैनिक रेफ्री-जेटर मैकैनिक, औजार बनाना इत्यादि। पूसा, अरब की सराय, तिलक नगर, मालवीय नगर, सब्जीमंडी, खानपुर तथा कर्जन रोड के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है। इनमें से कर्जन रोड का संस्थान केवल महिलाओं के लिये है। निःशुल्क प्रशिक्षण के अलावा एक तिहाई प्रशिक्षार्थियों को २५ रुपये महीने की दर से वजीफा भी दिया जाता है। कुछ प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क छात्रावास की सुविधा भी दी जाती है।

(२) काम सीखने वालों का प्रशिक्षण—यह प्रशिक्षण अप्रेंटिस एक्ट १९६१ के अन्तर्गत दिया जाता है। इस एक्ट के अनुसार अलग-अलग औद्योगिक कारखानों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

तकनीकी शिक्षा

गोविन्द बल्लभ पंत पौलीटैकनिक, ओखला और पूसा पौलीटैकनिक में सिविल, मेकैनिक, और बिजली इंजीनियरी का डिप्लोमा कोर्स है। कोर्स की अवधि ३ साल है, जिसके बाद २ साल का वास्तविक अनुभव किसी औद्योगिक कारखाने में कराया जाता है।

महिला पौलीटेकनिक

केवल महिलाओं के लिए एक पौलीटैकनिक खोला गया है जिसमें ऐसे पेशों का प्रशिक्षण दिया जाता है जिनके लिए महिलाएं विशेष रूप से उपयुक्त हैं, जैसे

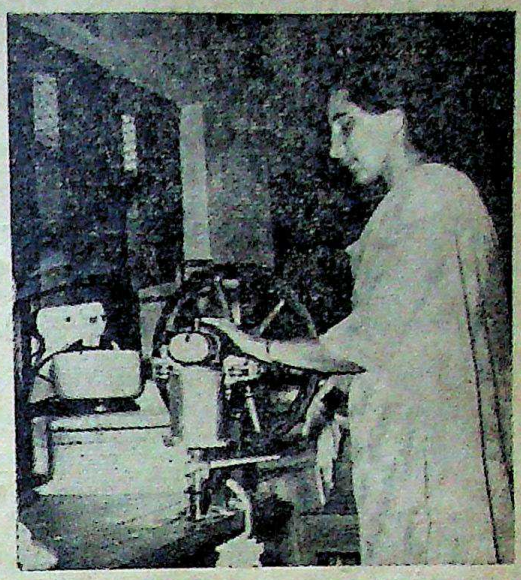

प्रदर्शन व भीतरी सजावट, पुस्तकालय विज्ञान (लाइब्रेरी साइंस), लिखापढ़ी व दफ्तरी काम, चिकित्सा प्रयोगशाला का तकनीक, पुरातत्व कार्य, इलेक्ट्रोनिक, औद्योगिक कला और दवाइयां बनाना। उद्देश्य यह है कि महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में ऐसे पेशों के लिए तैयार किया जा सके, जिन्हें उनकी आवश्यकता है व जहां उनकी मांग दिनों दिन बढ़ रही है, पर उपयुक्त महिला कर्मचारियों का अभाव है।

समाज कल्याण निदेशालय

वैसे तो समाज कल्याण का कार्य प्रदेश में बहुत पुराना चला आ रहा था किन्तु समाज कल्याण निदेशालय की स्थापना दिल्ली प्रशासन में मार्च १९५९ में ही हुई। इस समय जो आश्रमगत संस्थाएं व अन्य योजनाएं प्रशासन के अन्तर्गत चालू हैं उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(१) जांच व रिमांड होम—लड़कों के लिए

(२) चिल्ड्रेनहोम नरेला व बाल विहार नजफगढ़, बवाना, बरवाला और नरेला।

(३) अपराधी बच्चों के लिए विशेष स्कूल

(४) बालिकाओं के लिए जांच व रिमांड होम तथा विशेष स्कूल—

(५) मानसिक विकारों के रोगी बच्चों के लिए आश्रम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पहली जनवरी १९६२ से चिल्ड्रेन एक्ट १९६० दिल्ली में लागू किया गया। इसके अंतर्गत एक बाल बोर्ड व बाल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। इसके पहले बम्बई चिल्ड्रेन एक्ट १९२४, दिल्ली प्रदेश में लागू था। इनके अलावा महिलाओं व बच्चों की सहायता के लिए अन्य कुछ सेवाएं भी चालू हैं।

इन सरकारी योजनाओं के अलावा १५ गैर-सरकारी संस्थाओं को जो आर्थिक सहायता दी जाती है, वह पिछले २ वर्षों में करीब छः लाख रु० के करीब थी।

For Top Efficiency and

Mechanical Reliability

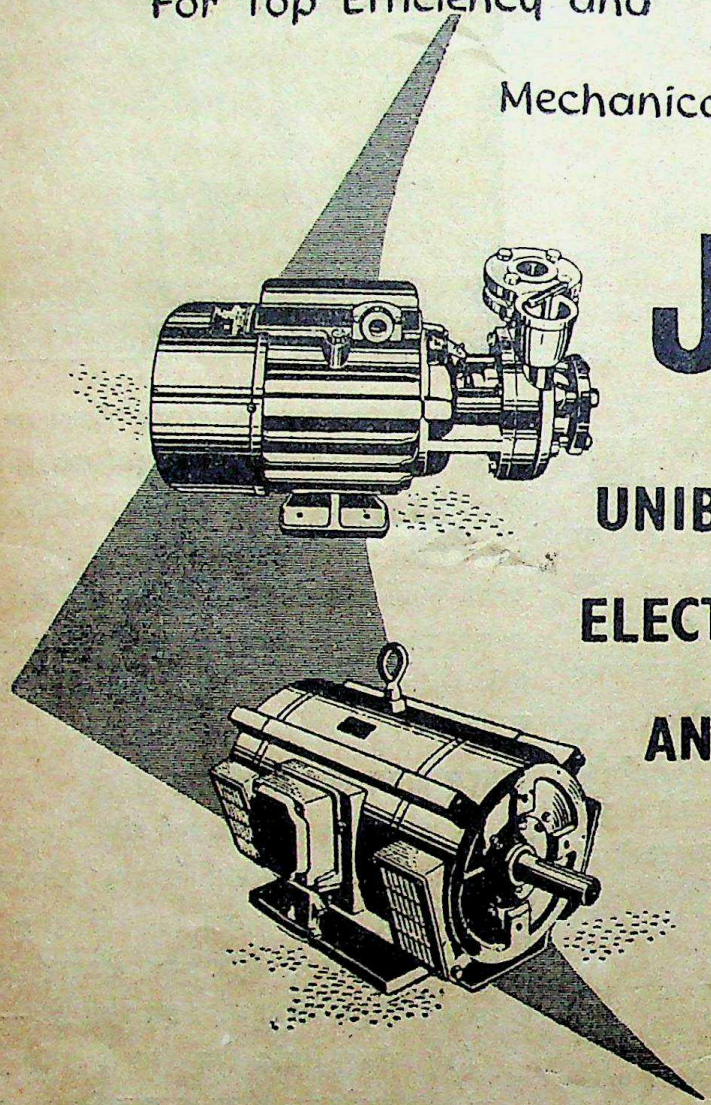

JYOTI

UNIBUILT PUMPS

ELECTRIC MOTORS

AND STARTERS

ज्योति

Distributors for : Delhi, Punjab & Himachal Pradesh

TRADING ENGINEERS

50, G. B. ROAD, DELHI-6.

Grams : UNIBUILT

Phone : 27475

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली की एक ज्वलन्त समस्या

बेघरों का घर—रैन बसेरा

कुमारी सुरेन्द्र सैनी, भारत सेवक समाज, दिल्ली

दिल्ली की आबादी बढ़ जाने से अनेक गरीब, बेघर बार लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं, जिन्हें रात को गरमी, सर्दी, या बरसात में सोने के लिए केवल पटरी पर ही स्थान मिलता है।

प्रत्येक समाज में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, जिनका गाढ़ सम्बन्ध मानवता से होता है। मानव प्राणी के लिए प्रेम, सहानुभूति और श्रद्धा के भाव रखने वाले कुछ कार्यकर्त्ताओं ने दिल्ली की पिछड़ी हुई जनता की ओर ध्यान दिया। उनकी न केवल बेकार, बीमार, विधवा, अनाथ और पीड़ित किरायेदारों से ही भेंट हुई, मगर ऐसे लोगों से भी सम्पर्क हुआ, जो दिन भर कड़ी मजदूरी करके अपनी रोजी कमायें, मगर रात को निश्चिन्त सो कर अपनी थकान भी दूर न कर सकें। उनके पास रहने को घर नहीं, और सोने को कोई स्थान नहीं। वे बाजार में पटरियों पर या खुले में जमीन पर सोते हैं। गर्मी हो या सर्दी, आंधी हो या तूफान, वे लोग प्रकृति देवी के प्रकोप के शिकार होते हैं और उसकी क्रूरता से बचने के लिए भी कहीं भाग नहीं सकते।

१२ हजार व्यक्ति पटरी पर सोने वाले

ऐसे बेघर लोग प्रायः मजदूर वर्ग के होते हैं, जैसे कि कुली, रिक्शा चलाने वाले, झल्ली वाले, भिखमंगे, बूट पालिश करने वाले और बेकार। इसमें सब जाति, धर्म व प्रान्त के लोग शामिल हैं। १९५४ में कुछ स्वयं सेवकों ने रात्रि के समय गणना की थी और उसके अनुसार ६००० एसे व्यक्ति थे। मगर अब यह अनुमान है कि करीबन १२००० ऐसे आश्रय हीन व्यक्ति हैं।

सात रैन बसेरे

फल स्वरूप दिसम्बर १९५६ में भारत सेवक समाज की ओर से पहला रैन बसेरा खोला गया। रैन बसेरे का अभिप्राय तो नाम से ही स्पष्ट है। इसमें बेघर मजदूर पेशा लोगों को लिया गया और उनके सोने के लिए सुविधा की गई। उनके लिए कम्बल, दरी, पानी, पैखाना, खेल और अखबार इत्यादि का प्रबन्ध किया गया। प्रौढ़ शिक्षा की सुविधा भी दी गयी। सुबह ७ बजे यह लोग अपने काम पर चले जाते हैं और शाम को ७ बजे सोने के लिए आ जाते हैं। दिन में यहां कोई नहीं ठहर सकता। रात्रि को सोने के लिये एक आना दैनिक लिया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रक्खा गया कि रैन बसेरे में भिखमंगा, बेकार व परिवार सहित कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं पा सकता। केवल १५ व्यक्तियों के वास्ते यह जगह काफी थी। यह प्रयास सफल हुआ। इसकी मांग बढ़ने लगी और दो वर्ष बाद रैन बसेरों की संख्या सात हो गई जिनमें ५०० के करीब लोग प्रतिदिन आश्रय ले सकते हैं।

दिल्ली की जनता ने इस योजना का स्वागत किया। हम यह गर्व से कह सकते हैं कि सात वर्ष में एक नया पैसा भी सरकार से अनुदान के रूप में नहीं लिया गया। सब रैन बसेरे चन्दे पर और दैनिक शुल्क जो लिया जाता है, उसी पर चलते हैं। अधिकतर सहायता दिल्ली की रोटरी क्लब से मिली।

योजना कमीशन और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने इस योजना को बहुत प्रोत्साहन दिया। दिल्ली में अधिक रैन बसेरे खोलने के लिए योजना कमीशन ने एस समिति बनाई है। यह भरसक प्रयत्न किया जा रहा है कि आगामी वर्ष में छः नये रैन बसेरे खुल जाएं।

मानव-समस्या

प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल ने कहा है कि यह मानव समस्या है और इसका हल भी मानवता के व्यवहार से ही हो सकता है। स्वयं तीन रैन बसेरों का दौरा करके उन्होंने कहा कि "इन लोगों को नाश्ता जरूर देना चाहिए। भूखे पेट घर से बाहर न जाएं।" इसका प्रयास भी किया गया मगर अभी तक पूर्ण सफलता नहीं मिल सकी है।

आशा है, शीघ्र ही ऐसा समय आयेगा कि दिल्ली में एक भी व्यक्ति पटरी पर सोता हुआ न मिलेगा। समाजवाद की कसौटी है कि लोगों की पांच आवश्यकताएं

(शेष पृष्ठ १११ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उड़िशा सीमेंट लिमिटेड

समवाय की तेरहवीं वार्षिक साधारण सभा में ५ अगस्त १९६३ को राजगंगपुर (उड़िशा राज्य) में श्री जे. डालमिया द्वारा प्रदत्त भाषण का सारांश

सज्जनो !

आपके समवाय की १३वीं वार्षिक साधारण सभा में आये हुए आप सबका स्वागत करने में मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है। सकल बिक्री में १० प्रतिशत वृद्धि के होते हुए भी आपके समवाय ने जो लाभार्जन किया है, वह १९६१ की ११०.५९ लाख रु० की राशि की तुलना में १४२.२० लाख रु० होने से कम है।

बहुत विचार के पश्चात् आपके निदेशकों ने जनरल रिजर्व को १३.५० लाख रु० हस्तान्तरित करके उसे सम्पुष्ट करने के पक्ष में निर्णय किया, यद्यपि इसके कारण लाभांश में १५ प्रतिशत से १० प्रतिशत कमी करने की आवश्यकता हुई। पर, मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि सेंट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू को आपके समवाय की ओर से प्रतिनिधित्व आय-कर कानून १९६१ की धारा ८४ और १०१ के अन्तर्गत रियायत के लिए किया गया था। उसका सम्बन्ध विभिन्न ऊष्मसह संयंत्रों से प्राप्त लाभ के साथ था, उसमें सफलता मिली है। कर-मुक्ति-लाभ से प्राप्त कुल राशि ३१,०१,८७३ रु० तक है और १९६२ वर्ष के लाभांश से इस राशि के अधिक होने के कारण इस लाभांश में से मूल कर में कोई कमी नहीं की जाएगी। कर-मुक्ति लाभ में से ६,१७,८७३ रु० की राशि को आगे ले जाया गया है और भविष्य के लाभांशों के लिए इसकी प्राप्ति हो सकेगी।

प्रसंगवश, मैं यह बात कहना चाहूँगा कि लाभांश से मूल में ही कर की कटौती और सरकारी ऋण पत्रों पर सूद— इनसे मध्य आय-वर्ग के लोगों के लिए बड़ी दिक्कत पैदा हो रही है यद्यपि कानून में यह उपबन्ध है कि जिनकी आय कर योग्य सीमा से कम है, उन्हें कर मुक्ति का प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। न्यून आय वाले लोग पहले ही जीवन-व्यय में लगातार वृद्धि के कारण अपने आपको संभाल सकने में कठिनता अनुभव कर रहे हैं। ये लोग सहायता के पात्र हैं और मैं वित्त मंत्री से बल-पूर्वक अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर विचार करें और एक व्यक्तिगत अंशदायी को जिसका लाभांश ३०० रु० व इससे कम है, उसे आय-कटौती से मुक्ति दें।

आपके निदेशकों के प्रतिवेदन में जैसा कहा गया है कि दो मध्यस्थों में सम्मति-भेद होने के कारण, बिजली के खर्च का झगड़ा पंच (अम्पायर)—श्री एम. सी. महाजन, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश—के पास भेजा गया था। पंच ने अपना फैसला दे दिया है, जिसमें उन्होंने उस आधार का निर्णय किया है, जिसके अनुसार समवाय द्वारा दिये जाने वाले बिजली खर्च की गणना की जानी चाहिए। इस राशि की वास्तविक गणना में कुछ समय लगेगा, पर आपके समवाय द्वारा जो राशि दी जाने वाली है— वह ९२.०९ लाख रु० के आधे से भी कुछ कम है। इस राशि को बचत पत्र में आकस्मिक देयता के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

अब मैं भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी उस "उत्साहप्रद योजना" की ओर संकेत करना चाहता हूँ जो १ जनवरी १९६३ से प्रारम्भ की गयी है और जिसका उद्देश्य वज्रचूर्ण उद्योग का अधिकतम उत्पादन करना है। आपके समवाय का जहां तक सम्बन्ध है, १९६३ में ३,८०,००० टनों से अगर अधिक उत्पादन किया गया तो अतिरिक्त टनों के लिए ५.५० रु० प्रति टन अधिक उत्पादन मूल्य होगा। इस योजना के पीछे जो उद्देश्य है, निश्चय ही, वह प्रशंसनीय है और मैं आशा करता हूँ कि इस योजना को, जो फिलहाल चालू वर्ष के लिए ही वैध है, मूल्य पद्धति का नियमित अंग तब तक बना दिया

सम्पादन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जायगा, जब तक अवरोध मूल्य सरकार द्वारा नियमित किये जाते हैं। पर, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूँगा कि १९६०-१९६२ के कलैंडर वर्षों में जो अधिकतम उत्पादन किया गया है, वह उन उत्पादकों को, उनके बिना किसी अपराध के, घाटे पर रख देता है, जिन्होंने अधिकतम उत्पादन के लिए अपने प्रयास जारी रखे और इस अवधि से सम्बद्ध तीनों वर्षों में उत्पादन के लक्ष्य व लक्ष्य के समीप तक उत्पादन किया। इस आधार पर विचार करने से, उत्साह की योजना अपना लक्ष्य स्वयं ही समाप्त कर देगी और इस योजना को सफल बनाने के लिए, जिस सतत प्रयास की आवश्यकता है, वह रुक जाएगा। इससे अच्छा और काम चलाऊ तरीका यह होता कि पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक इकाई में जितना औसतन उत्पादन हुआ है उसकी सामान्य अवस्था से इसका सम्बन्ध जोड़ा जाता। मेरा यह विश्वास है कि इस दृष्टि से और कुछ अन्य छोटे संशोधनों के द्वारा, यह योजना अपना उद्देश्य ठीक तौर पर पूरा कर सकेगी और वज्रचूर्ण की सब इकाइयों को एक निश्चित उत्साह प्रदान करने वाली होगी।

ट्रैफिक कमीशन द्वारा खर्च की जांच किये जाने के बाद से सरकार ने जो विभिन्न उगाहियां लागू की हैं, उनके प्रभावों के परिणाम-स्वरूप, सरकार ने अवरोध मूल्य में रु० २.७५ न० पै० प्रति टन की वृद्धि की स्वीकृति दी है और यह रकम १ जून १९६३ से वज्र चूर्ण उत्पादकों को अदा की जानी चाहिए। आप के समवाय को अदा किया जाने वाला अवरोधन मूल्य रु० ७२.२५ न० पै० प्रति टन होगा। आपके समवाय द्वारा की गयी मांग से यह वृद्धि कम पड़ती है और सरकारी कार्यवाही के परिणाम-स्वरूप जो लागत खर्च बढ़ गया है, उसे कुछ अंश तक ही अपने में समेट सकती है। फिर, सरकार के इस आदेश को १-११-१९६१ से पूर्व प्रभावकारी नहीं बनाया गया है। मैं आशा करता हूँ, सरकार वास्तविक दृष्टिकोण अपनाएगी और वज्र-चूर्ण उत्पादकों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, क्योंकि सरकारी कार्यवाहियों के कारण—जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं—उत्पादन खर्च बढ़ गये हैं।

ऊष्म सह उद्योग को कुछ विशिष्ट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस उद्योग की संस्थापित क्षमता (सीमेंट के मसालें और डेड बर्न्ट मेग्नेसाईट को छोड़ते हुए) १९६२ के अन्त तक और ऊष्म-सहों की नाम सूची की हाल की बैठक में १९६४ के आधार पर विचार की गयी संख्याओं की दृष्टि से, और १९६३ के अन्त तक जैसी पूर्व आशा रखी गयी हैं,—इन सब दृष्टियों से यह क्षमता इन वर्षों के लिए क्रमशः ६,६७,४००; ८,३१,७००; ९,४०,७०० टन हैं, और इस समय जो लाइसेंस सक्रिय कार्यान्वित हो रहे हैं और जो संयंत्र निर्माणाधीन हैं—उनसे यह क्षमता १९६५ में लगभग १२ लाख टन तक बढ़ जाएगी। ऊष्म सह उद्योग का यह विस्तार इस्पात उत्पादन की क्षमता पर आधारित है, जो तीसरी योजना के अन्त तक प्रति वर्ष १०० लाख टन के लक्ष्य तक पहुँच जाएगा। पर, ऐसा प्रतीत होता है, १९६४-६५ तक व १९६५-६६ तक भी इस्पात उद्योग के उत्पादन का दर प्रति वर्ष ६० लाख टन से अधिक नहीं होगा।

अब मैं ऊष्म सहों की आवश्यकताओं की, जो वास्तविक हैं और जिनकी संभावना हो सकती है—ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। १९६२ में जो उत्पादन हुआ—जिसे अग्निमृद् (फायर क्ले), सैलका (सिलिका) और पैठिक (बेसिक) ऊष्म सहों की लगभग मांग का प्रतिनिधित्व करने वाला कहा जा सकता है—वह ५,३२,७८० टन, अर्थात् संस्थापित क्षमता का ८० प्रतिशत था। १९६४-६५ के लिए आवश्यकताएं—जब इस्पात उद्योग का उत्पादन-दर लगभग ६० लाख टन प्रति वर्ष होगा—१,३१,५०१ टन की होंगी अर्थात्, १९६४-६५ में संस्थापित क्षमता का ६७ प्रतिशत।

इन आंकड़ों पर विचार करने से पता चलेगा कि इस उद्योग की स्थिति में क्रमशः गिरावट आ रही है, जबकि १९६२ में इसकी सम्पूर्ण अप्रयुक्त २० प्रतिशत क्षमता १९६४-६५ में बढ़कर ३३ प्रतिशत हो जाएगी। जैसा कि मैंने पहले कहा है, अगर अग्निमृद्, सैकजा और पैठिक ईंट की संस्थापित क्षमता १९६५ में बढ़कर १२ लाख टन हो जाती हैं और मांग लगभग वही रहती है जैसी १९६४-६५ में थी—लगभग ६ लाख टन से ऊपर—तब उद्योग की ५० प्रतिशत की क्षमता बेकार रहेगी। यह स्थिति स्वयं ही बड़ी हानिकारक होगी। उद्योग इस बात की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संभावना की भी उपेक्षा नहीं कर सकता कि प्रति टन उत्पन्न इस्पात में ऊष्म सह की खपत की दर का अनुमान अधिक लगाया गया है। हमारा सम्बन्ध उन संकेतों के साथ भी है कि इस्पात उद्योग की नयी क्षमता, अधिक कर के, एल० डी० विधि अथवा अन्य आकसीजन विधि द्वारा इस्पात बनाने के लिए आयोजित की जाए, जिसमें परम्परागत पैठिक ऊष्म-सहों के बदले केवल तारकोल से बंधी डोलोमाइट ईंटों की ही आवश्यकता पड़ती है।

इस्पात उद्योग में, पहले से बदलकर अब सब खुली पैठिक भट्टियों का प्रयोग कल्पनातीत तेजी से बढ़ रहा है, जबकि सैकजा ईंटों की मांग में निरन्तर कमी आ रही है। मैं यह अनुभव करता हूँ कि जब इस्पात उद्योग की क्षमता में प्रमुख विकास आयोजित किये जा रहे हैं, ऊष्म सहों की मांग निरन्तर एक स्तर पर नहीं रह सकती, क्योंकि इस्पात उद्योग की क्रिया में आने वाली आवश्यकताओं से ही इसमें पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हो सकती है। यह इस्पात उद्योग और ऊष्म सह उद्योग—दोनों के लिए लाभप्रद होगा। अगर इस्पात उद्योग अपनी मांग निर्माणात्मक कामों के लिए ऊष्म सहों की अपनी मांग पहले से ही इस तरह से बनाये और रखे ताकि ऊष्म सह उद्योग इसकी क्षमता का पूर्ण लाभ के साथ प्रयोग कर सके तो इस्पात उद्योग ऊष्म सहों के आयात के खतरे से छुटकारा भी पा सकेगा, क्योंकि अल्पकालीन पूर्व सूचना पर वह देश में ऊष्म सह प्राप्त नहीं कर सकता—यह बात मान लेने पर भी कि ऊष्म सह उद्योग के रूप में कुछ पहले का इतना अतिरिक्त सामान विद्यमान भी है। मेरे पूर्व कथन से इतना तो स्पष्ट ही है कि ऊष्म सह-उद्योग की क्षमता बढ़ाने का कोई न्याय संगत कारण अभी कई आगामी वर्षों तक नहीं हो सकता है।

यह सौभाग्य की बात है कि आपके समवाय ने कुछ खास ढंग के ऊष्मसह बनाने का काम विकसित किया है, जैसे, सैकजा कोक चूल्हे की ईंटें, फोरस्टेराइट ईंटे, ब्लास्ट फर्नेस ईंटे, जलाई गयी पैठिक छत की ईंटें, रासायनिक ढंग से बनायी गयी इस्पात की ढंपी पैठिक छत की ईंटे इत्यादि। इनमें से अधिकांश, अभी तक, आयात की जाती थीं। इस ढंग से हम न केवल विदेशी मुद्रा को बचाने में अपना योगदान करेंगे, किन्तु इस उद्योग में अधिक उत्पादन से पैदा होने वाली दिक्कतों का मुकाबला करने में भी अधिक समर्थ होंगे।

इस्पात उद्योग और ऊष्मसह उद्योग—दोनों को ही लाभ होगा अगर, जहां तक सम्भव हो, ईंटों की आकृति और परिमाण एक स्तर का हो और समस्त इस्पात के संयंत्रों के लिए एक जैसा विशिष्ट स्वरूप अपना लिया जाए। इससे न केवल निर्माण में सुविधा रहेगी, किन्तु अल्पकालीन सूचना पर इसकी उपलब्धि भी संभव हो सकेगी। इस भारतीय स्तर के विशिष्ट स्वरूप को अपनाने से कुछ विदेशी विशिष्ट रूपों के ऊष्मसहों के आयात करने की प्रवृत्ति भी कम हो जाएगी। मेरा विश्वास है कि सम्बद्ध अधिकारी इस समस्या से भली प्रकार परिचित हैं, और इस क्षेत्र में अन्य जितने आयात हो रहे हैं, उनमें कटौती करते रहेंगे।

इस उद्योग के लिए ठीक ढंग का कच्चा माल प्राप्त करने की दिक्कतें अभी तक जारी हैं। इसका कारण खनिज लाइसेंस की नीति और कुछ राज्यों द्वारा उसे कार्यान्वित करने का ढंग है। पर मुझे अब यह कहने में प्रसन्नता है कि इन दिक्कतों को दूर करने के महत्व पर ऊष्मसहों की नाम सूची द्वारा अधिक ध्यान दिया जा रहा है। कुछ राज्यों की यह प्रवृत्ति हो रही थी कि उनकी सीमा से बाहर औद्योगिक कामों के लिए खनिज पदार्थों के प्रयोग पर खानों के लाइसेंस देने में रोक लगायी जाए, पर अब इसमें कमी हो रही है। पर खानों की लीज और आगे के लाइसेंस देने व उनका निपटारा करने में बार-बार देरी होती है। फिर भी, देश में इस समय कार्यतत्परता और मितव्यय पर जो जोर दिया जा रहा है, उससे हम आशा करते हैं कि ऐसे मामलों का निपटारा अधिक शीघ्रता के साथ होगा।

इस उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे माल के स्रोतों की तलाश करने में भारत के भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग ने कुछ अनुसंधान किये हैं, जैसे, ऊंचे दर्जे का एलुमिना प्लास्टिक और नान प्लास्टिक अभिमृद्, कच्चा क्रोन, बाक्साइट इत्यादि। उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

वज्र चूर्ण के सम्बन्ध में १५ सितम्बर १९६२ को औद्योगिक समिति के चौथे अधिवेशन में यह निश्चय

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

किया गया था कि एक त्रिपक्षीय समिति कायम की जाए जो अभी तक के कार्यभार की जांच के प्रकाश में तीनों वज्रचूर्ण के कारखानों जैसी कार्यभार की जांच का प्रश्न वज्र चूर्ण के अन्य कारखानों के बारे में भी सोचे और, साथ ही, इन जांचों को पूरा करने के लिए उचित माध्यम की सिफारिश करे। लगभग सात मास बीत जाने के बाद यह उप समिति अभी कायम की गयी है और अभी इसने अपना काम शुरू करना है। मैं फिर बलपूर्वक यह कहूँगा कि इस प्रकार की खोज में शीघ्रता लाई जाए ताकि कार्यभार के मूल्यांकन का काम वज्र चूर्ण उद्योग में वेतन-निर्धारण पर पुनर्विचार करने से पहले ठीक प्रकार पूरा हो जाए।

अन्त में, मैं आपकी ओर से और निदेशकों की ओर से समवाय के श्रमिकों, कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवाओं की हार्दिक सराहना करना चाहता हूँ जो इस वर्ष के अन्दर हमें प्राप्त होती रही हैं।

विशेष द्रष्टव्य—यह १३ वीं वार्षिक आम सभा की कार्यवाही की रिपोर्ट नहीं समझी जानी चाहिए। • •

(पृष्ठ १०७ का शेष)

पूरी हों—खाना, कपड़ा, मकान, औषधि और पढ़ाई। गन्दी बस्तियों में रहने वाले और पटरियों पर सोने वालों की आवश्यकताएं प्राथमिक हैं और उधर शीघ्र ही ध्यान देना होगा। सफलता जनता और सरकार के सहयोग पर निर्भर है।

भरी बीच पटरी पर सोने वाले इन लोगों को चोर, उच्चके और जेबकतरे कह कर छोड़ दिया जाता है। मगर इनमें आपको ऐसे भी उत्कृष्ट मानव मिलेंगे जो अपना कर्त्तव्य पूरी तरह अपने परिवार व पड़ौसी के प्रति ही नहीं बल्कि देश के प्रति भी समझते हैं और उसके लिये सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। इनमें ऐसे लेखक व कलाकार भी हैं जो लोगों के हृदय को अपनी कला से प्रफुल्लित व उत्तेजित करके उन्हें मानवता का पाठ पढ़ा सकते हैं।

GRADED No. 1
by DGS & D
Govt. of India

Designed for
Greater
Efficiency

IEC

MOTOR DRIVEN
PRECISION
LATHES

with automatic change Gear box, quick acting controls. All geared and cone pulley type.

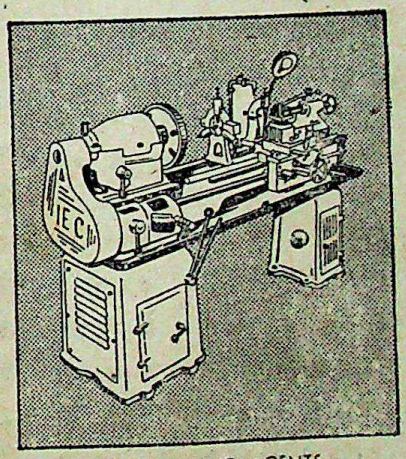

MANUFACTURERS:
CHANANA BROS.
26, OKHLA INDUSTRIAL ESTATE
NEW DELHI-20. PHONE 72832

SOLE SELLING AGENTS

CHANANA SALES CORPN.
53, HANUMAN ROAD, NEW DELHI
Phone 42538

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्वायत्त शासन का विकास

(पृष्ठ ४१ का शेष)

निगम की सीमा में ३०० से अधिक गांव हैं। इससे उसे शहरी और देहात दोनों इलाकों का संगठित ढंग से विकास करने का अवसर मिला है और सारे देश में इस साहसपूर्ण परीक्षण के लिये दिलचस्पी है। देहातों में आवागमन के साधनों का सुधार, साफ पानी की सप्लाई, बिजली और अन्य सेवाओं की व्यवस्था जैसी बड़ी समस्याएं हल की जानी हैं। बजट में इस इलाके की सेवाओं और सुविधाओं के लिये जो व्यवस्था रखी गई है, वह निगम के इस दृढ़ निश्चय का प्रतीक है कि गांवों को भी धीरे-धीरे शहरी इलाके के स्तर पर लाना है।

शहरी इलाके में भी विकास के कई स्तर हैं। नई दिल्ली का जो इलाका निगम को सौंपा गया है, उसमें खुले स्थान, सुनियोजित मकान, और मार्केट हैं, जबकि इसके विपरीत, चारदीवारी के अन्दर वाले शहरी इलाके में गंदी बस्तियां हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में विस्थापितों की बस्तियां हैं, जिनके स्तर सामान्य से बहुत नीचे हैं। बहुत सी ऐसी अनधिकृत बस्तियां भी बस गई हैं, जहां नाम मात्र को भी नागरिक सेवाएं नहीं हैं। सुधार की योजना बनाते समय विभिन्न इलाकों की विशेष अवस्थाओं का ध्यान रखा गया है। यह पहले की उस परिपाटी से भिन्न है, जिसमें उपलब्ध राशि की विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में वहां की आवश्यकताओं को देखे बिना लगभग समान रूप में बांट दिया जाता था।

निगम को अपनी बपौती में ३३७.३३ लाख का वह कर्जा भी चुकाना था, जो पिछले दस स्थानीय निकायों ने लिया था। इसके साथ ही भारत सरकार से लिये गये इस कर्ज का ब्याज भी देना था, जिसकी दर अधिकतर मामलों में ५ प्रतिशत है। पहले बजट में २१.६८ लाख रूपये की राशि इसके लिये रखी गई। १ अप्रैल १९५९ को देय राशि ३१५.६५ लाख रु. थी। अधिकांश मामलों में अदायगी ३० वर्षों में की जानी है। ७ अप्रैल १९५८ को, जबकि निगम की स्थापना हुई, उसके पास रोकड़ बाकी १५.२७ लाख रु. थी। तबसे अब तक उसके व्यय में निरन्तर वृद्धि हुई है। १९५८-५९ में व्यय ४५५.०२ लाख, ५९-६० में ५७१.०७, ६०-६१ में ६६९.६१, ६१-६२ में ७१८.१२ था, सन् १९६२-६३ में १०.१० करोड़ और ६३-६४ में १०.७० करोड़ रु. खर्च होने का अनुमान है।

इसी प्रकार सरकारी अनुदान जो १९५८-५९ में १.२५ करोड़ था उसके १९६३-६४ में २.५२ करोड़ हो जाने का अनुमान है। म्युनिसिपल टैक्सों तथा फीसों से होने वाली आय का भी जो १९५८-५९ में २.४५ करोड़ थी, उसके १९६३-६४ में ६.५९ करोड़ हो जाने का अनुमान है।

सशक्त प्रशासन

दिल्ली की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसके लिये जो शहरी सुविधाएं देनी जरूरी हैं, उसके लिए और भी रुपया चाहिये। गंदी बस्तियों का साफ करना, स्कूलों और अस्पतालों व पार्कों को बनाना और साथ ही दिल्ली को मास्टर प्लान के अनुसार विकसित करना, इस सब में काफी धन की आवश्यकता है। धन के साथ-साथ जरूरत है एक अच्छे शक्तिशाली, ईमानदार और योग्य प्रशासन की, ताकि जो भी योजनाएं बनें उनको तेजी के साथ कार्यान्वित किया जा सके। जब तक यह बात नहीं होगी तब तक केवल टैक्सों की आमदनी से रुपया बढ़ाने तथा भारत सरकार के अनुदान से काम नहीं चल सकता।

पिछले चन्द सालों का जो अनुभव है, उससे पता चलता है कि मौजूदा प्रणाली में कहीं कमी है। निगम की सारी जिम्मेवारी एक जगह पर नहीं है। वह प्रशासन में, स्टैचूटरी कमेटियों और कारपोरेशन में बंटी हुई है। इससे जितनी प्रगति होनी चाहिए थी, नहीं हुई है। जो रुपया जनता के खून पसीने की कमाई से टैक्सों द्वारा लिया जाता है, उसके बारे में जनता को यह विश्वास होना चाहिए कि उस रुपये का सदुपयोग हो रहा है और शासन में आलस्य व भ्रष्टाचार नहीं है। यदि एक मजबूत मेयर-इन-काउंसिल बनादी जाय और सारे शासन भार की जिम्मेवारी उसकी हो, तो काम काफी ठीक तरह से चल सकता है। इस प्रकार की सिफारिश स्वयं कारपोरेशन ने की है। भारत सरकार इस पर विचार कर रही है। जितनी जल्दी इस व्यवस्था को लागू कर दिया जायगा, उतना ही दिल्ली और इसके नागरिकों के हित में होगा।

• •

सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली की एक विकट समस्या

मकान मालिक बनाम किरायेदार

दिल्ली में किराया नियंत्रण कानून १९५८ में लागू हुआ था। पर आशा थी कि इस से मालिक मकान और किरायेदारों के बीच तनाव कम हो जाएगा। किरायेदार जहां उचित किराया देने से सन्तुष्ट होगा, वहां मालिक मकान को भी अपनी पूँजी पर उचित वापसी पाकर प्रसन्नता होगी। पर पिछले पांच वर्षों में स्थिति में सुधार की अपेक्षा बिगाड़ ही अधिक हुआ है। आज दिल्ली की अदालतों में लटके और फंसे हुए करीब १० हजार मालिक मकान और किरायेदारों के मुकदमे इस बात की साक्षी हैं कि स्थिति कितनी गम्भीर है। इस कानून की कृपा से कुछ व्यक्तियों को इस महकमें में नौकरी मिल गयी हो, इस के अतिरिक्त इस कानून से अभी तक कोई ठोस लाभ नहीं हुआ प्रतीत होता है। किरायेदार तो पहले की तरह ही परेशान है। महीने-महीने बाद किराये तो बढ़ ही रहे हैं। करौलबाग के शानदार इलाके पश्चिमी विकास के क्षेत्र (डब्ल्यू० ई० ए०) में तीन कमरों के फलैट का किराया १० रु० से लेकर १०० रु० तक बढ़ गया है।

मध्यम श्रेणी के मालिक मकान

दिल्ली की समस्याओं में यह भी एक प्रमुख समस्या है। एक ओर किरायेदार की जहां शिकायतें हैं, वहां दूसरी ओर मालिक मकान की अपनी करुण गाथा है। मकान मालिकों में अधिकांश मध्यम व निम्न मध्यम श्रेणियों के लोग हैं। ये सरकारी व गैर सरकारी प्रायः नौकर, छोटे-मोटे दुकानदार या कारोबारी हैं। इधर-उधर से कुछ पूंजी जुटाकर व कर्ज लेकर इन लोगों ने मकान बनाये हैं। जो किराया मिलता है, उससे किसी प्रकार ऋण की वापसी, सूद की अदायगी व नगरनिगम के विविध कर दे पाते हैं। इस प्रकार मालिक मकान व किरायेदार—दोनों के लिए अदालतों में धक्के खाना और पेशियां भुगतना कठिन हो जाता है। अगर दोनों पक्षों में से कोई हार भी जाता है तो वह ऊंची अदालत में जाने में संकोच नहीं करता। यह बात भी गलत नहीं है कि वकीलों की कृपा से मालिक मकानों व किरायेदारों में मुकदमेबाजी बढ़ रही है और दलालों की हरकतों से किरायेदारों को अधिक किराया देना पड़ता है।

किराया प्रशासक की नियुक्ति

दिल्ली की आबादी तो लगातार बढ़ रही है। इस पर रोक लगाना कठिन है। आबादी बढ़ने के साथ-साथ मकानों की समस्या भी उग्र से उग्रतर हो रही है। इस लिए इस समस्या का कोई स्थिर इलाज ही सोचना पड़ेगा। इस समय कानून तब गतिशील होता है जब दोनों पक्षों में कोई एक फरियाद करे। हमारा सुझाव यह है कि एक ऐसा प्रशासक नियुक्त किया जाए, जिसका एक मात्र कार्य ही किराया नियंत्रण हो। जब तक सरकार स्वयं इस मामले में गहरी दिलचस्पी न लेगी, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। इस प्रशासक का पूर्ण रूप से संगठित एक विभाग हो। इसके पास दिल्ली के प्रत्येक मकान का पूरा इतिहास हो। यह कानून बना दिया जाए कि मालिक मकान व किरायेदार दोनों में से कोई भी सीधा सौदा न कर सके, किन्तु किराया प्रशासक के द्वारा ही दोनों का सम्पर्क हो और किराया निर्धारित हो। दोनों पक्षों में से जो भी कानून तोड़े वह दण्डित किया जाए। "उचित किराया" इस प्रकार निर्धारित किया जाय, जिससे मकान मालिक को अपनी पूंजी पर अधिकतम लाभ मिल सके और किरायेदार को आवास का सुख उपलब्ध हो सके।

दूसरी बात यह कि जब कोई मकान खाली हो, तब उसे किराये पर चढ़ाने की जिम्मेदारी किराया नियंत्रक प्रशासक की ही हो। इससे दलालों से छुटकारा मिल जाएगा और मकानों के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी।

यह कहा जा सकता है कि इन कठोर नियमों के फलस्वरूप राजधानी में मकान बनने कम हो जाएंगे, पर यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि अगर मालिक मकान को बिना दलाली दिये घर बैठे स्वयं ही किरायेदार मिल जाए और प्रतिमास किराया भी नियमित रूप से मिलता रहे, तो उसके असन्तुष्ट रहने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। ● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली फैक्टरी ओनर्स असोसियेशन

दिल्ली के छोटे बड़े सब उद्योगों की समस्याओं पर विचार करने और उन्हें समय-समय पर परामर्श व और सहायता देने के लिये दिल्ली फैक्टरी ऐसोसियेशन के नाम से १९५७ ई० में संस्था स्थापित हुई थी। इस संस्था की स्थापना दिल्ली के प्रतिष्ठित महान उद्योगपति स्वर्गीय लाला श्रीराम ने की थी। यह वह समय था, जबकि समस्त देश में भीषम आर्थिक मन्दी छाई हुई थी और व्यापार एवं उद्योग दोनों की स्थिति बहुत ही शोचनीय हो रही थी। ऐसी विकट स्थिति में इस संस्था के महान संस्थापक लाला श्रीराम के नेतृत्व में इस संस्था ने केवल अपनी ही स्थिति को सुदृढ़ नहीं किया, बलिक दिल्ली के उद्योगों को भी निराशा और उदासीनता के भंवर से निकालने में बहुत सहायता प्रदान की है।

इस संस्था के मुख्य कार्य निम्न लिखित हैं:।

(१) व्यापार और उद्योग की विशेष समस्याओं का अध्ययन।

(२) उन समस्याओं के हल करने के लिये उद्योगों को परामर्श और सहयोग।

(३) उद्योगों की ओर से स्थानीय संस्था, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के पास विभिन्न प्रश्नों पर प्रति निधित्व व विचार विनिमय।

(४) सरकार की नीतियों, आज्ञाओं और कानूनों के सम्बन्ध में उद्योगों को जानकारी देना।

(५) औद्योगिक नियमों की व्याख्या और उन पर अमल करने के लिए उद्योगों को आवश्यक सूचना देना।

(६) औद्योगिक विवादों से सम्बन्द्ध विभिन्न अदालतों और सरकारी अधिकारियों से विचार विनिमय तथा आवश्यकता पड़ने पर मुकदमे लड़ना।

(७) विभिन्न उद्योगों को औद्योगिक विवादों के सम्बन्ध में कानूनी परामर्श देना।

१९३१ से १९६३ ई० तक इसके अध्यक्षों में सर श्रीराम, श्री बैजनाथ रयाल, लाला कृपानारायण, लाला चरतराय, श्री मुरलीधर डालमियां, श्री भीकूराम जैन और श्री बी. एन. भास्कर आदि के नाम यह बताने को पर्याप्त हैं कि यह संस्था किस तरह विभिन्न उद्योगों का प्रतिनिधित्व करती है। बड़े उद्योग इस संस्था के सदस्य हैं, वहां कपड़ा इंजीनयररिंग, बनस्पति, श्रृंगार सामग्री, साबुन, सैनिटरी वेयर, तैल, आटे की मिलें, मोटरों के वर्कशाप, बर्फ के कारखाने आदि विविध उद्योग भी इस संस्था के द्वारा अपनी समस्यायें राज्य के सामने रखते हैं। इस समय इस संस्था के सदस्यों की संख्या १०२ है।

यह संस्था दिल्ली के उद्योगों की उन सभी समस्याओं पर तो विचार विनिमय करती ही है, जो अखिल भारतीय महत्व की होती हैं और जिन पर समस्त देश के व्यापारी और उद्योगपति विचार विनिमय करते हैं। किन्तु इनके अतिरिक्त कुछ ऐसी समस्यायें होती हैं, जिनका सम्बन्ध केवल दिल्ली से होता है। ऐसी जिन समस्याओं पर पिछले दो तीन वर्षों में इस संस्था में विचार किया गया, उन में से कुछ मुख्य निम्न लिखित हैं :—

(१) दिल्ली का मास्टर प्लान और उस में दिल्ली के उद्योगों का भविष्य।

(२) दिल्ली में कोयले, बिजली और पानी की दुर्लभता तथा उनके समाधान के उपाय।

(३) दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्रों में यातायात व सड़कों की उचित व्यवस्था।

(४) दिल्ली के कारखानों द्वारा उत्पन्न बिजली पर कार्पोरेशन द्वारा टैक्स।

(५) दिल्ली में एक ड्राई पोर्ट बनाने की संभावना।

(६) दिल्ली के औद्योगिक कर्मचारियों, मजदूरों, और कर्मचारियों के लिये आवारु समस्या।

(७) नजफगढ़ और ओखला की औद्योगिक बस्तियों के विकास की योजनायें आदि आदि।

इस संक्षिप्त सूची से ही हम इस संस्था के कार्यकलाप की कल्पना कर सकते हैं।

सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सुभाषित रत्न-माला

दूसरा संस्करण

सम्पादक : कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

८ वर्ष पूर्व इस पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था और हाथों-हाथ बिक गया था। कई वर्षों से यह पुस्तक अप्राप्य थी और इसकी मांग निरन्तर बढ़ रही थी। अब परिवर्धित संस्करण आकर्षक रूप सज्जा में प्रकाशित हुआ है। इस संग्रह में पढ़िये—

- वैदिक एवं संस्कृत-साहित्य के अगाध भंडार से चुने गये ऐसे सरल सुन्दर श्लोक और मंत्र, जिन्हें छोटे-बच्चे भी सुविधा के साथ कंठस्थ कर सकते हैं।
- प्रत्येक श्लोक और मंत्र का सरल सुबोध हिन्दी में अर्थ।
- पुस्तक के अंत में अर्थ-सहित कुछ ऐसी सूक्तियां जिनका उपयोग छात्र अपने निबन्धों में कर सकें।
- आपके बच्चों के स्वस्थ मानसिक विकास और उनमें नैतिक चेतना जगाने के लिए यह रत्न-माला अनिवार्य है।
- उपहार और पुरस्कार देने के लिए बहुत उपयुक्त।

मूल्य एक प्रति रु. १.१५ न. पै.। "सम्पदा" के ग्राहकों से अपनी ग्राहक संख्या लिखने और ८५ न. पै. प्राप्त होने पर "बुक पोस्ट अंडर पोस्टल सार्टिफिकेट" द्वारा भेजी जाएगी।

अशोक प्रकाशन मन्दिर

२८/११ शक्तिनगर, दिल्ली-६

उषा

★ सामाजिक कहानियां, शिक्षाप्रद कथानक, विचारोत्तेजक मनोरंजक लेख, राशिफल, सरस कविताएं आदि।

★ हानिकारक वस्तुओं, व अश्लील किस्मों के विज्ञापन स्वीकार नहीं किये जाते।

—यदि आपने अभी तक उषा नहीं देखी है, तो शीघ्र ही ३२ न० पै० के टिकिट या मनीआर्डर भेजकर नमूनांक मंगा देखिये। हमें पूरा विश्वास है कि एक बार 'उषा' को देखने के बाद आप हमेशा के लिए उसके हो जाएंगे।

—अन्य जानकारी के लिए लिखिये

सचित्र मासिक उषा कार्यालय,

जवाहर मार्ग, इन्दौर।

आर्थिक समीक्षा

प्रधान सम्पादक : श्री सादिक अली

सम्पादक : श्री हरतीर्थ सिंह

- हिन्दी में अनूठा प्रयास
- आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख
- आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत

भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक।

वार्षिक मूल्य : ५ रु० एक प्रति २२ नये पैसे

लिखें—व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, नई दिल्ली।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हिन्दी का एकमात्र
विशिष्ट महिलोपयोगी मासिक

शृङ्गार

- जो सुखी पारिवारिक जीवन का आदर्श पथ-प्रदर्शक है
- जिसे सुप्रसिद्ध लेखिकाओं, लेखकों, पत्रकारों, चित्रकारों कवयित्रियों तथा कवियों का सहयोग प्राप्त है।
- जिसे ५०००० से ऊपर की संख्या में पाठक प्रतिमास पढ़ते हैं।
- जिसकी प्रतियां न्यूज़ एजेन्टों के पास पहुँचते ही समाप्त हो जाती हैं।
- जो महिला जागृति का प्रतीक है।
- जो सबकी प्रिय पत्रिका है।

वार्षिक : सात रुपये
एक प्रति : ६० नये पैसे

सम्पादिका : लावण्य प्रभा

कार्यालय : १३।३७, शक्तिनगर, दिल्ली-६।

आरसी

(सचित्र पारिवारिक मासिक)

कहानी * कविता * लेख * कढ़ाई * बुनाई * पाठशाला * माँ और शिशु * ढोलक के गीत * बाल-मन्दिर * चलचित्र-जगत् * पुस्तक परिचय * इसके साथ ही प्रति माह एक कढ़ाई का नमूना उपहार में।

१ प्रति, ५० न० पै० वार्षिक मूल्य ६.०० रु०

आज ही ग्राहक बनिये।

विशेष सूचना—आरसी का अनन्त अंक "राजेन्द्र-स्मृति-अंक" होगा। एजेन्ट अभी से अपनी प्रतियां सुरक्षित करा लें।

व्यवस्थापिका, आरसी, श्वाकर टाउन
सिकन्द्राबाद (आ० प्र०)

सबसे सस्ता सचित्र हिन्दी मासिक

जागृति

जिसे भारत के सभी प्रमुख कवियों,
और कहानीकारों का सहयोग प्राप्त है।
उत्प्रेरक कविताएं, ज्ञानवर्धक लेख, सांस्कृतिक निबंध,
रोचक कहानियां, बाल संसार, साहित्य आगे
बढ़ता है, आदि स्तम्भ
तिरंगा आवरण, अनेकों इकरंगे चित्र
सम्पूर्ण छपाई आर्ट पेपर पर
इस पर भी मूल्य केवल २५ नये पैसे

एजेंटों को ५ से १० प्रतियों पर २५ प्रतिशत और इससे ज्यादा पर ३३⅓ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। डाक का खर्च प्रकाशकों के जिम्मे। एजेन्ट नमूने की प्रति के लिए आज ही लिखें।

—सूचना व प्रकाशन विभाग चण्डीगढ़ (पंजाब)

ग्राम राज (मास में तीन बार प्रकाशित)

सम्पादक—श्री गोकुलभाई भट्ट

"ग्रामराज बहुत ही शानदार और बहुत ही सुन्दर पत्र निकल रहा है। सब तरह की जानकारी इसमें रहती है। राजस्थान के हर शिक्षित भाई बहन के हाथ में यह पत्रिका होनी चाहिए।" —विनोबा

वार्षिक चन्दा ३) रु०

कार्यालय का पता :

ग्रामराज, किशोर निवास
जयपुर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शीघ्र ही प्रेस में जा रहा है।

न र्म दा

का

पं० बालकृष्ण शर्मा नवीन अंक

इस विशेषांक की सबसे बड़ी विशेषता पत्रकार प्रवर पं० बनारसीदास चतुर्वेदी को लिखे गए उनके व्यक्तिगत पत्रों का प्रकाशन होगा, जो स्व० नवीनजी अलमस्ती, हंसोड़ वृत्ति और विरलतम स्नेह भाव का एक अत्यन्त मनोहर रूप पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर देंगे।

इस विशेषांक द्वारा नर्मदा का प्रयास नवीन जी के साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और मानवीय व्यक्तिगत विषय पक्ष पर पूरा प्रकाश डालने का है।

इस विशेषांक के सम्पादक हैं:
पं० बनारसीदास चतुर्वेदी
श्री शम्भुनाथ सक्सेना,

पृष्ठ संख्या १५०, अनेक व्यक्तिगत व पारिवारिक चित्रों सहित···मूल्य ३ रु०

नर्मदा कार्यालय, नूतन प्रिंटिंग प्रेस,
ग्वालियर (म० प्र०)

"जीवन-साहित्य" का अनूठा विशेषांक

राजेन्द्र-संस्मरण अंक

अवश्य पढ़िये

राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन तथा सर्वश्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, श्रीमन्नारायण, राजकुमारी अमृतकौर आदि की मूल्यवान श्रद्धांजलियां।

- सर्वश्री गाडगिल, बनारसीदास चतुर्वेदी, श्रीराम शर्मा, ज्ञानवती दरबार, विश्वनाथ शर्मा, देशबन्धु मालिक, ब्रजलाल बियाणी आदि के मार्मिक संस्मरण।
- राष्ट्रकवि मैथिलीशरणजी की हृदयस्पर्शी कविता।

इनके अतिरिक्त और भी बहुत-सी दुर्लभ सामग्री इस अंक में मिलेगी।

विशेषांक का मूल्य
२॥) होगा, लेकिन पत्र के ग्राहकों से इसके लिए अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिया जायेगा।

वार्षिक शुल्क के ४) भेजकर तत्काल ग्राहक बन जाइये।

सस्ता साहित्य मंडल
नई दिल्ली

अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद का मुख्य पत्र

स्वस्थ जीवन

प्रधान सम्पादक — श्री राधाकृष्ण नेवटिया
प्रबन्ध सम्पादक — श्री धर्मचन्द सरावगी
एक प्रति २० न० पै० — वार्षिक ५) रुपया मात्र

साहित्य के साथ अपने सुन्दर स्वास्थ्य के लिए कविता, कहानी, संस्मरण तथा डायरी और परिषद की गतिविधि पढ़ें। आज ही पांच रुपया भेजकर ग्राहक बन जाइए। विज्ञापन देकर लाभ उठावें। सहयोगी बन्धु अपनी नवीन कृतियां हमें भेजें।

कार्यालय :—
"जैन हाउस"
८।१ एस्प्लेनेड ईस्ट,
कलकत्ता-१

भारत की उद्योग नीति

लेखक—प्रो० रामनरेश लाल

भारत सरकार ने १९४८ में जो उद्योग नीति निर्धारित की थी, १९५६ में संशोधन के बाद से वही आज भी हमारी उद्योग नीति का आधार है। इसलिए, उद्योग नीति को समझने के लिए उक्त पुस्तिका का अध्ययन बहुत लाभदायक होगा। मूल्य, डाक व्यय सहित ७५ न० पै०।

"सम्पदा" के ग्राहकों को अपनी ग्राहक संख्या लिखने और ६० न० पै० का टिकट भेजने पर रियायती मूल्य में यह पुस्तक भेजी जाएगी। वी० पी० से नहीं भेजी जाएगी।

अशोक प्रकाशन मन्दिर
२८।११, शक्तिनगर दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संचालक, पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश

की

विज्ञप्ति संख्या ४।५५८० : २७।३३, दिनांक १५

द्वारा

पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत

सुन्दर पुस्तकें

		रु०	आ०
वेद सार	प्रो० विश्वबन्धु	१	८
प्रभु का प्यारा कौन ? (२) भाग			
सच्चा सन्त			३
सिद्ध साधक कृष्ण			२
जीते जी ही मोक्ष			३
आदर्श कर्मयोग			३
विश्व-शान्ति के पथ पर			१
भारतीय संस्कृति	प्रो० चारुदेव		
बच्चों की देखभाल	प्रिंसिपल बहादुरमल	१२	१
हमारे बच्चे	श्री सन्तराम बी. ए.	३	१३
हमारा समाज		३	
व्यावहारिक ज्ञान		२	१२
फलाहार		१	४
रस-धारा		०	१४
देश-देशान्तर की कहानियां		१	
नये युग की कहानियां		१	१२
गल्प मंजुल	डा० रघुबरदयाल	१	
विशाल भारत का इतिहास	प्रो० वेदव्यास	३	८

१० प्रतिशत कमीशन और ५० रु० से ऊपर के आदर्शों पर १५ प्रतिशत कमीशन।

विश्वेश्वरानन्द पुस्तक भंडार

साधु आश्रम, होशियारपुर, पंजाब

भारत के अनेक सरकार, सरकारों द्वारा शिक्षा-संस्थाओं, वाचनालयों, पंचायतों तथा विभागों स्थापना के लिये स्वीकृत

भारत व्यापार पत्रिका

उद्योग तथा व्यापार प्रधान सचित्र हिन्दी मासिक

लोकप्रियता के कारण

★ भिन्न-भिन्न वस्तुएँ बनाने की योजनाओं का नियमित प्रकाशन
★ आपके उलझे प्रश्नों के उत्तर
★ आपकी आवाज सरकार तक पहुँचाने के लिए 'सुझाव एवं शिकायतें' स्तम्भ
★ एक विज्ञापन रियायती दर पर छापने के लिए 'रियायती दर विज्ञापन कूपन' की व्यवस्था
★ विज्ञान जगत ★बैंकिंग तथा बीमा समाचार ★आयात निर्यात समाचार
★ बाल जगत आदि अनेक स्तम्भ
★ आकार डबल क्राउन १/८
★ पृष्ठ संख्या ६४ से ७२ तक
★ वार्षिक चन्दा विशेषांकों सहित ६ रुपये
★ साधारण अंक ५० नये पैसे

★ उपयोगकर्ताओं एवं व्यापारियों के लिए उपयोगी लेख ★सस्ते समाचार
★ आर्थिक गतिविधियों की जानकारी
★ व्यापारिक मार्गदर्शन

आम जनता के लिए रुचिकर।
★ एक आकर्षक कहानी ★फलित ज्योतिष
★ गंगा की लहरें में अवगाहनीय ★विज्ञान समाचार

★ गृहशास्त्र के छात्रों के लिए एक उपयोगी लेख

आज ही अपनी प्रति सुरक्षित कर लें।

अन्य जानकारी के लिये लिखें:—
व्यवस्थापक,
भारत व्यापार पत्रिका,
पो. बॉ. न. ४८, राजा दरवाजा,
वाराणसी (उ.प्र.)

खादी पत्रिका

✳ खादी ग्रामोद्योग तथा सर्वोदय विचार पर विद्वत्ता पूर्ण रचनाएँ।

✳ खादी ग्रामोद्योग आन्दोलन की देशव्यापी जानकारी।

✳ कविता, लघुकथा, मील के पत्थर, साहित्य समीक्षा, संस्था परिचय।

✳ साँख्यकी पृष्ठ आदि स्थायी स्तम्भ।

✳ आकर्षक मुख पृष्ठ, हाथ कागज पर छपाई।

वार्षिक मूल्य ३) रु., एक प्रति पच्चीस नये पैसे

संपादक— ध्वजाप्रसाद साहू, जवाहिरलाल जैन

राजस्थान खादी संघ, पो. खादीबाग, (जयपुर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंखों की परम्परा

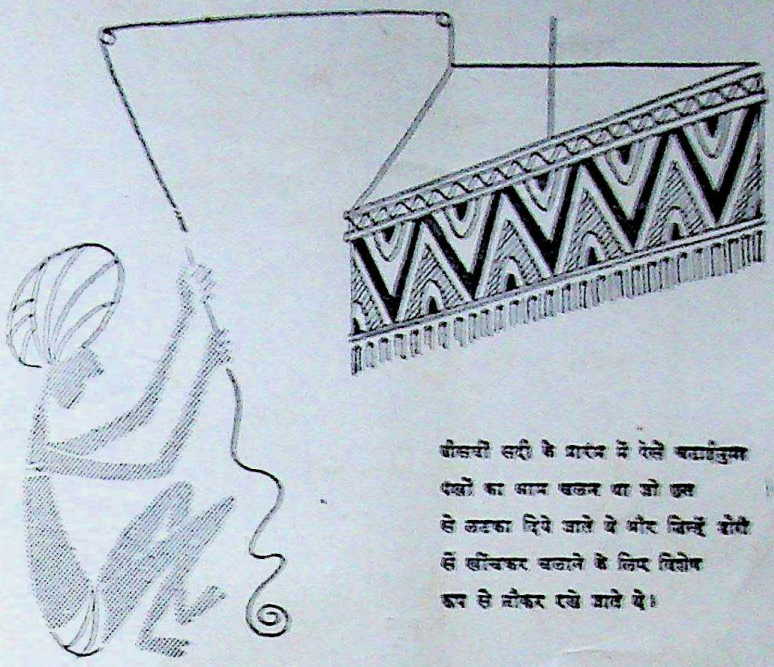

बीसवीं सदी के प्रारंभ में देखे जानेवाले पंखों का आम चलन था जो छत से लटका दिये जाते थे और जिन्हें डोरी से खींचकर चलाने के लिए विशेष रूप से नौकर रखे जाते थे।

बढ़िया उत्पादनों का स्थान सस्ती वस्तुएँ नहीं ले सकतीं!

Kassels

कैसल्स एअरमास्टर

मेसर्स वेल इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड

पो. बॉ. बॉक्स १५६, नयी दिल्ली

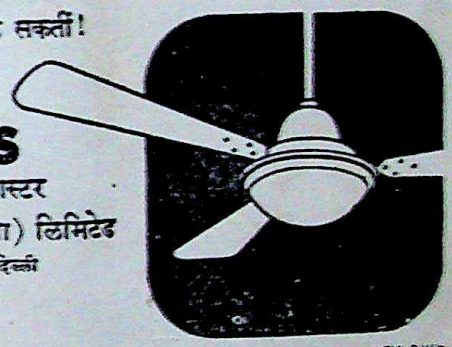

MEY-3HIN

फैक्टरी – पूना-६

सोल सैलिंग एजेंट्स :

मैसर्स बजाज इलैक्ट्रिकल्स लि.

बम्बई * नई दिल्ली * कलकत्ता * मद्रास

* कानपुर * इन्दौर * वर्धा * गोहाटी

* पाटन * हैदराबाद * जयपुर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

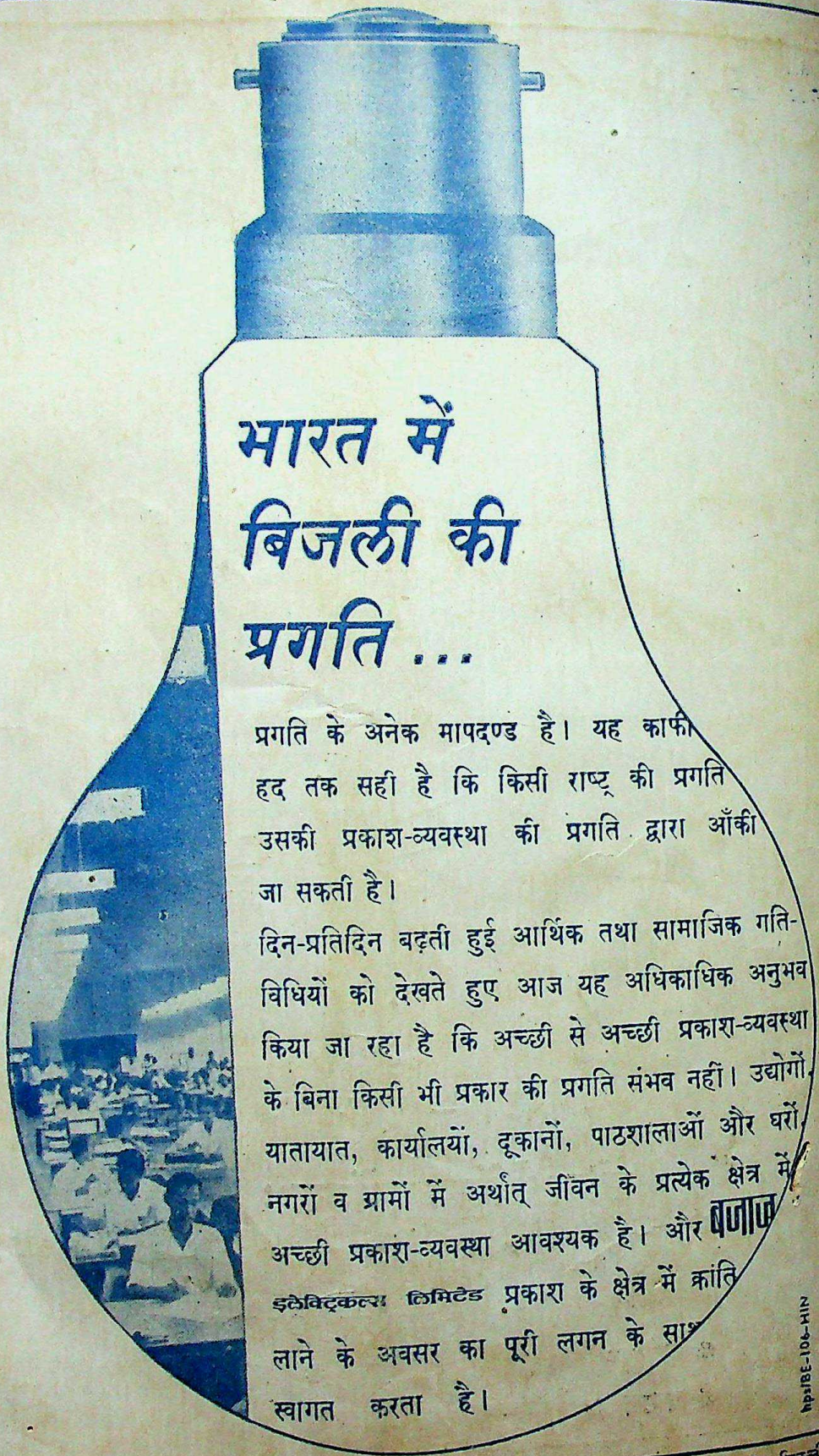

सम्पादक—कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा नवचेतन प्रेस (प्रा०) लि० (लॉजिज ऑफ अर्जुन प्रेस) दिल्ली-६ से मुद्रित
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

7003.0

सम्पदा

वर्ष : १२ अंक : १

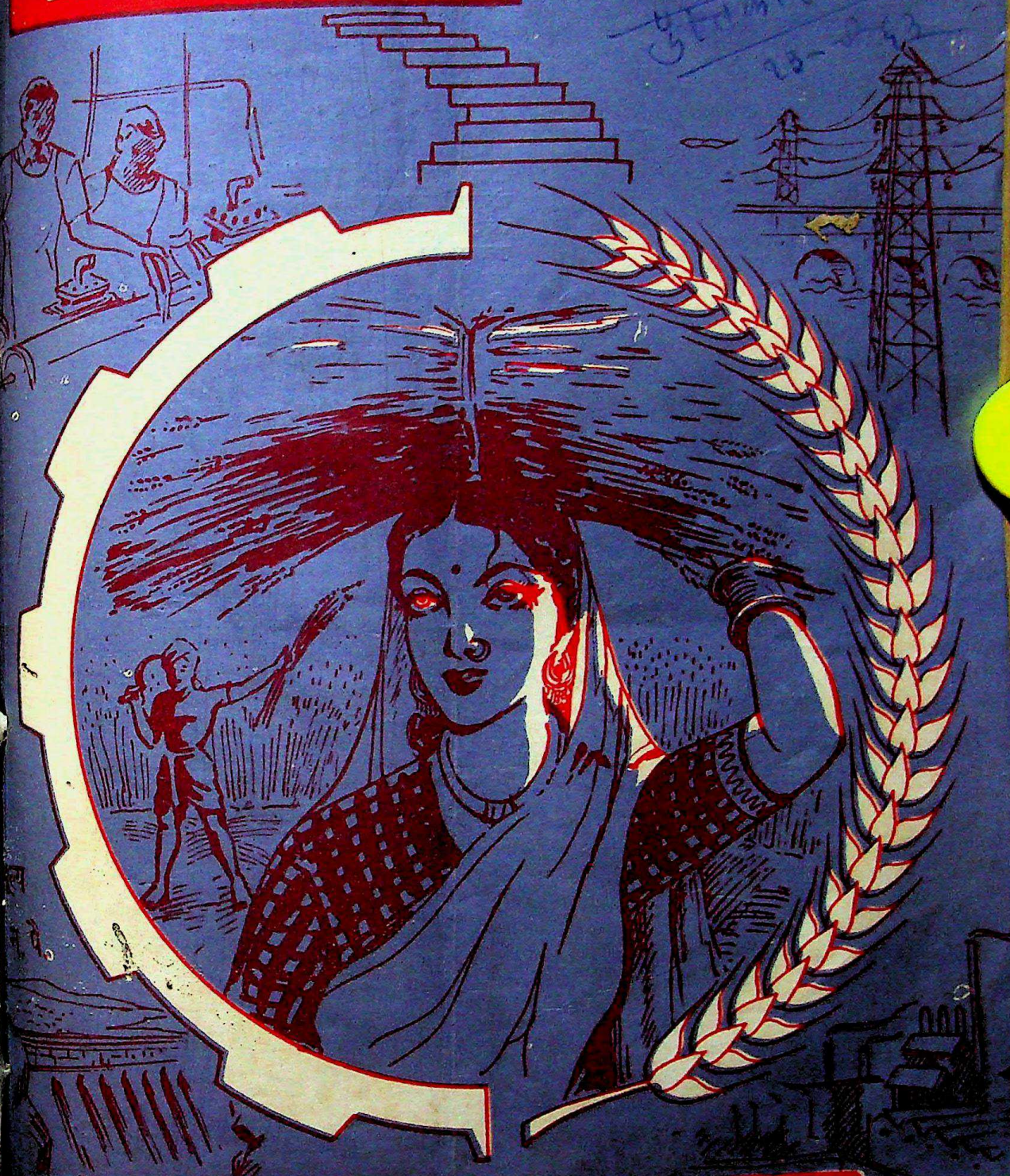

अशोक प्रकाशन मन्दिर शक्ति नगर, दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आयोजित विकास

तीसरी पंचवर्षीय योजना में ८० प्रतिशत से अधिक योजनाएं रक्षा का अत्यावश्यक अंग हैं और शेष पंचवर्षीय योजना भी परोक्ष रूप से इससे सम्बद्ध है।

औद्योगिक विकास की गति तेज करने और रक्षा के लिए अधिक शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से योजना को और ठीक-ठाक कर दिया गया है।

इस्पात और मशीनी औजार, खनिज तथा कच्चे पदार्थों का उत्पादन बढ़ा दिया गया है। इंजीनियरी और सम्बद्ध उद्योगों की क्षमता का पूर्णतम रूप से उपयोग किया जाएगा।

आयोजित विकास रक्षा का मूलाधार ही है। योजना को अधिक तेज रफ्तार और कुशलता से पूरी करके आप रक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और भारत को वास्तविक रूप से अधिक सबल बनाने में सहायक होते हैं।

देश रक्षा के लिए

DA63/F.6

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गुरुकुल कँगड़ी

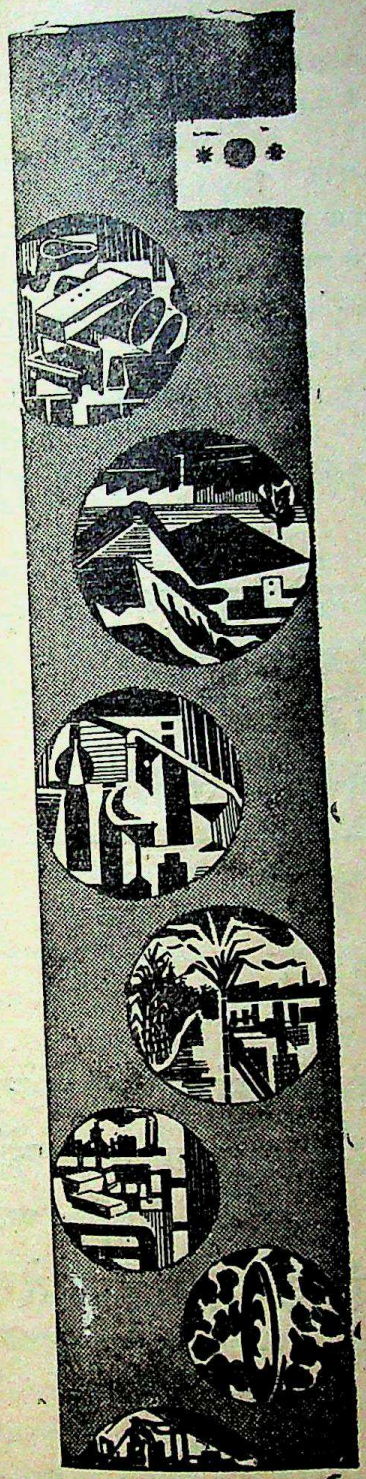

नये क्षितिज

स्वतंत्रता पूर्व युग में भी जनता के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए भारत की योजनाएं और कार्यक्रम थे। पर उनमें मौलिक निर्बलता थी कि उनका सम्बन्ध जनता की अपेक्षा सरकार के साथ अधिक था।

स्वतंत्रता आई और इसके साथ नव-जागरण और जनता की योजनाएं—जनता के लिए और जनता के द्वारा। इसके परिणाम स्पष्ट थे, अधिक से अधिक बेहतर व सस्ती वस्तुएं अधिक से अधिक लोगों के लिए बेहतर जीवन।

डालमिया उद्योग समूह

निरन्तर ऐसे सामान का अधिक से अधिक उत्पादन करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो हमारे जीवन स्तर को ऊंचा करने में सहायक हो। हम यह कामना न केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से, किन्तु लगभग एक चौथाई सदी से कर रहे हैं। यह काम कठिन होते हुए भी हम निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं, इस आशा के साथ कि कल का दिन अधिक उज्ज्वल, नव-प्रभात एवं नये क्षितिज से युक्त होगा।

de
DALMIA ENTERPRISES

डालमिया सिमेंट (भारत) लि., डालमियापुरम् (मद्रास)
डालमिया आयरन एंड स्टील लि., राजगंगपुर व कलकत्ता
डालमिया मेगनेसाइट कार्पोरेशन, सेलम (मद्रास राज्य)
उड़िशा सिमेंट लि. राजगंगपुर (उड़िशा राज्य)
रजा बुलन्द शूगर कं० लि०, रामपुर (उ० प्र०)
दि रामपुर डिस्टिलरी एंड केमिकल कं. लि., रामपुर (उ.प्र.)

राष्ट्र की सेवा में सन्निहित

डालमिया उद्योग-समूह

मुख्य कार्यालय—४, सिन्धिया हाउस, नयी दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विषय सूची

विषय	लेखक	पृष्ठ
१. बैंकों का राष्ट्रीयकरण:संसद् का उचित निर्णय		३३७
२. सम्पादकीय टिप्पणियां		३३८
३. निम्न वर्ग की दैनिक आय कितने पैसे ?	कृष्णचन्द्र विद्यालंकार	३४१
४. भारतीय योजना में समाजवाद	—श्रीमन्नारायण	३४४
५. योजना और पूंजी विनियोग		३४६
६. नियोजन और जन संख्या	—श्री एस० बायना	३४८
७. औद्योगिक कार्य क्षमता	श्री एस० एस० हाश्मी	३५१
८. विदेशी मुद्रा के साधन—कृषि पदार्थ	श्री जे० एस० पटेल	३५४
९. विकासशील आफ्रिका		३५६
१०. दिल्ली में सहकारिता आन्दोलन	श्री एल० सी० जैन	३५८
११. यह लखनऊ है ?		३६०
१२. उत्पादकता आन्दोलन	—श्री हाश्मी	३६२
१३. अर्थ वृत्त चयन		३६५
१४. नया सामयिक साहित्य		३६७
१५. राज्यों की आर्थिक गति विधि		३७१
१६. रासायनिक उद्योग का चमत्कार	श्री जगदीश चन्द्र बंसल	३७३
१७. इस मास की आर्थिक घटनाएं		३७४

सम्पदा का वार्षिक मूल्य रु. ८.५० एक प्रति का मूल्य ८० न. पै.

वी० पी० से मंगाने पर ७५ न. पै. का खर्च अधिक पड़ता है।

इसलिए मनीआर्डर से ही रुपया भेजें।

मैनेजर—सम्पदा २८/११ शक्तिनगर, दिल्ली-६

सर्वोदय-पर्व मनाइये

(बिनोबा जयन्ती से गांधी-जयन्ती तक)

साहित्य समाज का दर्पण है, सर्वोदय उसकी दिशा

११ सितम्बर से २ अक्टूबर तक सर्वोदय-स्वयं सेवकों का यह कर्तव्य है कि वे सर्वोदय-साहित्य को घर-घर में पहुंचा दें।....साहित्य में पुस्तकों के अलावा पत्रिकाओं का भी अपना स्थान है। पत्रिकाएँ नियमित रूप से गाँव-गाँव में पहुँचें, तो लोक-मानव में सतत स्फूर्ति का संचार होता रहेगा।

—बिनोबा का जय जगत्

स्थानीय सर्वोदय-कार्यालय, खादी-भंडार तथा पुस्तक-विक्रेताओं से सर्वोदय-साहित्य खरीदिये।

सर्व-सेवा-संघ, राजघाट, वाराणसी द्वारा प्रसारित

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वर्ष : १२
अंक : ९
सितम्बर : १९६३

सम्पदा

बैंकों का राष्ट्रीयकरण : संसद का उचित निर्णय

समय-समय पर विरोधी दलों की ओर से यह आवाज उठती रही है कि बीमा कम्पनियों की तरह बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिए। संसद के इस अधिवेशन में भी स्वयं एक कांग्रेसी सदस्य ने ही बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव पेश किया। सरकार की ओर से वित्तमंत्री ने राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध यथापूर्व अपना मन्तव्य प्रकट किया और संसद ने भी इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समर्थक कुछ तो वे हैं, जो साम्यवादी और समाजवादी विचारधाराओं के अनुसार प्रत्येक उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना अनिवार्य और वांछनीय मानते हैं। कुछ लोगों की दृष्टि में, आज जब सरकार को अपनी योजनाबद्ध विकास कार्यों की आवश्यकता है, बैंकिंग व्यवसाय सरकार के हाथ में बहुत धन राशि दे सकता है। उसका उपयोग सरकार इच्छानुसार अपनी योजनाओं के लिए कर सकती है। आज बैंक-संचालक अपनी-अपनी इच्छानुसार जिस किसी उद्योग को सहायता देते रहते हैं, और तब सरकार राष्ट्र की आवश्यकतानुसार विशेष-विशेष कार्यों के लिए ही रुपया देगी। आज जिस तरह कुछ थोड़े से लोगों के हाथ में शक्ति एकत्र हो गई है, उसका भी निवारण बैंकों के राष्ट्रीयकरण से हो जायगा।

राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति १९४८ में प्रारम्भ होती है, जब रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वस्तुतः यह बैंक पहले भी सरकारी बैंक के रूप में ही काम करता था। इसलिए इससे स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इसके बाद १९५५ में इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ और १९५६ में जीवन बीमा निगम का उद्योग सरकार ने अपने हाथ में कर लिया। इम्पीरियल बैंक को स्टेट बैंक आफ इण्डिया के रूप में परिणत करते हुए मुख्य उद्देश्य देहातों में बैंकिंग की सुविधाओं का विस्तार और कृषकों को प्रोत्साहन देना था, ताकि किसानों और उनकी सहकारी समितियों को अर्थाभाव की शिकायत न रहे। जीवन बीमा निगम को हाथ में लेते समय सरकार का मुख्य ध्यान पूंजी के एक विशाल स्रोत को अपने हाथ में लेना और निजी उद्योग की शक्ति को कम करना था, यद्यपि इसके लिए कुछ बीमा कम्पनियों का भ्रष्टाचार तात्कालिक कारण बताया गया। इसके साथ ही समस्त व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आवाज जोरों से उठाई जाने लगी, जिसकी परिणति संसद में उक्त प्रस्ताव के रूप में आई।

× × ×

भारत सरकार और संसद ने उक्त प्रस्ताव को अस्वीकृत करके वस्तुतः साहसपूर्ण और प्रशंसनीय निश्चय किया है। मूल प्रश्न यह है कि क्या उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से देश की आर्थिक समस्याएं हल हो जायेंगी, क्या समाज

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सुखी हो जायगा और क्या विभिन्न श्रेणियों में असमानता दूर हो जायगी ? क्या कर्मचारियों के दुख समाप्त हो जायेंगे और क्या बड़े-बड़े उद्योगपतियों के हाथ से उद्योगों के छीन लेने के बाद जनता का शोषण बन्द हो जायेगा ? अब तक का सार्वजनिक उद्योगों का अनुभव इन प्रश्नों का कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं देता। सरकारी संस्थायें (स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आदि) न पदार्थों के मूल्य कम कर सकी हैं और न असमानता को ही दूर कर सकी है। उद्योग का राष्ट्रीकरण वस्तुतः उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है, समाज का सुख। राष्ट्रीयकरण उसी का एक साधन हो सकता है। यह साधन कहाँ तक प्रभावकारी है, यह हमें पिछले वर्षों के अनुभव से देखना चाहिए। यह अनुभव बहुत सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। कुछ सार्वजनिक संस्थाओं ने राष्ट्र के नाम पर जनता का शोषण किया है, तो कुछ उद्योगों ने अपनी अकुशलता से राष्ट्रीय सम्पत्ति को भारी हानि भी पहुँचाई है।

योजनाबद्ध विकास कार्यों को अमल में लाने की समस्त शक्ति आज भी सरकार के हाथ में है। वही आवश्यक उद्योगों को पूँजी जारी करने की अनुमति देती है। कोई उद्योग बिना लाइसेंस प्राप्त किये चल नहीं सकता। फिर रिजर्व बैंक के हाथ में इतने अधिकार हैं, कि वे किसी भी बैंक को गड़बड़ी करने से या रुपये का दुरुपयोग करने से रोक सकता है। यह भी बात नहीं कि बैंकों से सरकार को जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय योजना के लिए रुपया न मिलता हो। उन्होंने न केवल सरकार को भारी मात्रा में ऋण दिया है, सरकार द्वारा नियत कार्यों में रुपये का विनियोजन भी ये करते रहते हैं। सार्वजनिक संस्थाओं में श्रमिकों और कर्मचारियों को अधिक वेतन मिल सकते हैं, इस सम्भावना को भी अब तक का अनुभव सत्य सिद्ध नहीं करता। इसके विपरीत आज श्रम संगठनों को निजी उद्योगों की अपेक्षा सार्वजनिक उद्योगों से अधिक शिकायत है। सार्वजनिक संस्थाओं के अधिकारियों की दृष्टि अधिक सहृदय हैं, यह भी आज हम नहीं कह सकते।

बैंक जितना नफा कमाते हैं, वह सब उनके राष्ट्रीयकरण से सरकार को मिल जायेगा, यह भी भ्रम ही है। आज भी सरकार उन के लाभ पर ७० प्रतिशत कर लगाती है। १९६१-१९६२ में वे कर के रूप में सरकार को २९ करोड़ रुपया दे चुके हैं। शेष लाभ सुरक्षित कोष बनाने, कर्मचारियों को बोनस और शेयर होल्डरों को डिविडेण्ड बांटने आदि में लग जाता है। राष्ट्रीयकरण का केवल इतना ही परिणाम होगा, कि शेयर होल्डरों के डिविडेण्ड बच जायेंगे। परन्तु सरकार जब उन के शेयर खरीदेगी, तो उसे करोड़ों रुपया इस काम में लगाना पड़ेगा और उस रुपये का सूद सरकार को देना होगा। यदि कुछ रुपया बचेगा भी तो वह बहुत कम होगा। थोड़ी सी राशि के लिए सरकार समस्त देश की अर्थ व्यवस्था में उथल पुथल करे तथा करोड़ों रुपये का बोझ अपने सिर पर ले, यह कोई बुद्धिमता भी नहीं थी।

यह ठीक है, कि बैंकों पर कुछ बड़े सम्पन्न व्यक्तियों का नियन्त्रण है, किन्तु वस्तुतः उन का स्वामित्व उन हजारों के पास है, जो मध्यवित्त श्रेणी के हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से भी समस्त शक्ति वस्तुतः संसद के ७५० सदस्यों के हाथ में नहीं, सरकार के कुछ मंत्रियों के ही हाथ में आ जाती है, जिन पर सदस्य प्रभावकारी नियन्त्रण नहीं रख सकते। निजी बैंकों के संचालक शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, इसका उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा है, कि निजी बैंक संचालकों या अधिकारियों के पास केवल १३ प्रतिशत राशि गई है, जब कि स्टेट बैंक के अधिकारी २७ प्रतिशत राशि स्वयं या उनके सम्बन्धी ले चुके हैं। इस तरह बैंकों का स्वामित्व बदलने मात्र से कोई विशेष लाभ हो जायेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत राष्ट्रीयकरण देश में स्वतंत्र व्यक्तित्व और स्वतन्त्र उद्योग की महत्वाकांक्षाओं और परिणामतः जनता के साथ बैंक अधिकारियों के निकट सम्पर्क को भी प्रभावित करेगा। निजी बैंकों ने देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास में जितना महत्वपूर्ण भाग अदा किया है वह भी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रबल समर्थन नहीं करता। भारत के नये वित्त मंत्री श्री कृष्णमाचार्य ने संसद में इस प्रस्ताव को वर्तमान स्थिति में सर्वथा अस्वीकार्य बताते हुये ठीक ही कहा है, कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से आज सरकार को कोई लाभ नहीं है। इसके विपरीत वह

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हमारी उस अर्थ व्यवस्था पर गहरी चोट करेगा, जो आज धीमी गति के कारण पहले ही अच्छी अवस्था में नहीं है। ब्रिटेन की मजदूरदलीय सरकार के नेता श्री ह्यूज गैटस्कल ने भी सभी मामलों में राष्ट्रीयकरण के औचित्य पर सन्देह प्रकट किया था। वित्तमंत्री ने ठीक ही कहा है कि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता तो समृद्धि की गति को बढ़ाने की है, जो बहुत दूर तक निजी क्षेत्र के विकास पर निर्भर करती है। सरकार को आज न केवल सार्वजनिक उद्योगों की वरन निजी उद्योगों के विकास की भी चिन्ता है।

राष्ट्र की प्रतिरक्षा और विकास कार्यों के सम्बन्ध में विचार प्रकट करते हुए वित्तमंत्री ने ठीक ही कहा है कि वर्तमान साधनों को निजी उद्योग से सार्वजनिक उद्योगों की ओर मोड़ने से ही यह समस्या हल नहीं होगी। इसके लिए तो हमें राष्ट्र के स्रोत ही बढ़ाने ही पड़ेंगे। आज भी सार्वजनिक क्षेत्र ८० प्रतिशत कार्यकारी कोष पर नियंत्रण करता है। वित्तमंत्री की सम्मति में सार्वजनिक उद्योग अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करके राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था पर छा सकते हैं। इसके लिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण की नहीं आवश्यकता नहीं।

बोकारो इस्पात कारखाना

बोकारो का लोहे का कारखाना भी एक अजीब पहेली बन गया है। भारत सरकार इसे अमरीका की सहायता से स्थापित करने की सोच रही थी। अमरीका के विशेषज्ञों ने आकर समस्त स्थिति की जांच पड़ताल की और इस योजना से कुछ असहमति प्रकट की। फिर बातचीत चलने पर राष्ट्रपति कैनेडी तथा भारतस्थित अमरीकन राजदूत ने सहायता देने का आश्वासन दिया। लेकिन अब अमरीका के रिपब्लिकन दल ने बहुमत बना कर इस वर्ष बोकारो के लिए सहायता नहीं देने दी। इससे भारत में क्षोभ स्वाभाविक है। प्रतीत होता है कि अब भारत सरकार ने भी बोकारो के कारखाने के निर्माण में और अधिक विलम्ब न होने देने का निश्चय कर लिया है। इस कारखाने के लिए ४४ हजार एकड़ जमीन अधिग्रहण करने का निश्चय किया जा चुका है। पानी, बिजली, कच्चेमाल और परिवहन की क्षमता की भी जांच पड़ताल की जा चुकी है।

इसी सम्बन्ध में डा० एम० एन० दस्तूर की सम्मति भी हमें जान लेनी चाहिए। वे भारत सरकार द्वारा इस्पात उद्योग के लिए सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि बोकारो का कारखाना ५०० करोड़ रुपये में बन सकता है। यह राशि अमरीकन विशेषज्ञों द्वारा बताई गई राशि से २५ प्रतिशत कम है। उन्होंने यह भी बताया है कि अमरीकन सलाहकारों ने ४५० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता बताई है। लेकिन हमें बहुत सा सामान देश में ही मिल सकता है, इस लिए विदेशी मुद्रा की जरूरत भी कम होगी। रांची, रूरकेला, और दुर्गापुर में ही अनेक आवश्यक मशीनरी तैयार हो सकेगी।

परन्तु इस सम्बन्ध में स्वयं भारतीय अर्थशास्त्रियों के दो मत हैं। कुछ लोगों का कहना है, कि हमने जहां अमरीकी सहायता की प्रतीक्षा में धैर्य के साथ दो वर्ष बिताए हैं, वहां एक वर्ष और भी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए और इस अवधि में अमरीका के लोकमत को अपनी तरफ करने का प्रयत्न करना चाहिए। कुछ अमरीकियों की सम्मति में यदि विदेशी इस्पात भारत में तैयार किए गये इस्पात से सस्ता पड़ता है, तो एक वर्ष तक अमरीका से ही इस्पात मंगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह व्यवस्था वैसी ही हो, जैसे पी० एल० ४८० के अन्तर्गत अनाज मंगाया जाता है। दूसरी ओर कुछ लोगों का यह ख्याल है कि अब हमें अधिक प्रतीक्षा न करके, अपने या अन्य देशों के साधनों से ही जितना हो सके, बोकारो का कारखाना तैयार करने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए।

लोहे व इस्पात की कमी

१९६२-६३ में भारत ने ४० लाख टन इस्पात तैयार किया है। इस वर्ष यह उत्पादन ४३ लाख टन का हो जाने की सम्भावना है और यदि सब काम योजना के अनुसार हुआ तो १९६५-६६ तक हम ६६ लाख टन इस्पात तैयार करने लगेंगे, किन्तु ६६ लाख टन का यह उत्पादन भी योजना आयोग के लक्ष्य से कम ही बैठता है। उसने १९६५-६६ में ७४ लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया था। 'नेशनल कौंसिल आफ एप्लाइड इकनौमिक रिसर्च' के मत से हमें ३० लाख टन की कमी पड़ेगी,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लेकिन हम ६६ लाख टन भी तैयार कर सकेंगे, इसमें भी सन्देह है । इस्पात मन्त्री श्री सुब्रह्मण्यम ५६ लाख टन से अधिक उत्पादन की आशा नहीं करते ।

प्रश्न केवल सरकारी या गैरसरकारी क्षेत्र में बड़े कारखानों में इस्पात के उत्पादन का ही नहीं है । इंजिनियरिंग उद्योग के लिए भी योजना आयोग के कथनानुसार १९६५-६६ में १५ लाख टन कच्चे लोहे की आवश्यकता पड़ेगी और फिलहाल १० लाख टन से अधिक कच्चा लोहा उपलब्ध नहीं हो सकेगा, क्योंकि बोकारो के कारखाने से इस योजना की अवधि तक उत्पादन की कोई आशा नहीं। उक्त रिसर्च कौंसिल ने सरकार को यह राय भी दी है कि पचास हजार टन कच्चे लोहे का कारखाना तो शीघ्र ही स्थापित कर देना चाहिए, जिससे इंजीनियरिंग उद्योग को कोई कठिनाई न हो।

रोल्ड एलाय और स्पेशल स्टील के उद्योग के उत्पादन में भी हम अपनी आवश्यकताओं के लक्ष्य से बहुत पीछे हैं। विदेशों से हम ६० हजार टन मंगवाते हैं और स्वयं २५ हजार टन का निर्माण करते हैं, जबकि योजना आयोग की सम्मति में २ लाख टन की हमें आवश्यकता है । यदि हम २ लाख टन स्पेशल स्टील विदेशों से मंगावें तो हमें ५० करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा चाहिए । स्पेशल स्टील का औसतन मूल्य २५०० रुपया प्रति टन पड़ता है । क्या हम आज इतनी विपुल राशि इस विशेष इस्पात के मंगाने पर खर्च कर सकते हैं ? इस पृष्ठ भूमि में बोकारो के कारखाने में विलम्ब हमारे लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो रहा है । राउरकेला और मैसूर के इस्पात कारखानों में कुछ नई योजनाओं को प्रारम्भ करने की स्कीमें कब क्रियान्वित होंगी, यह आज हम नहीं कह सकते ।

नया मंत्रिमंडल

कांग्रेस ने अपने आन्तरिक संगठन को अधिक बलशाली बनाने के लिए यह निश्चय किया है कि कुछ प्रभावशाली उत्तरदायी मंत्री पद त्याग करके कांग्रेस के संगठन में लग जायें । इस निश्चय के परिणाम-स्वरूप केन्द्र और राज्यों के अनेक मंत्रियों के त्यागपत्र पं० नेहरू ने स्वीकार कर लिये हैं। उनकी जगह दूसरे मंत्रियों ने ले ली है । इनमें भी महत्वपूर्ण परिवर्तन केन्द्रीय गृहमंत्री, वित्तमंत्री और कृषिमंत्री के हैं । नये निश्चय के अनुसार श्री गुलजारीलाल नन्दा गृहमंत्री का भी काम कर रहे हैं। श्री कृष्णमाचार्य श्री मोरारजी की जगह वित्तमंत्री बनाये गये हैं । श्री स्वर्णसिंह को कृषिमंत्री बनाया गया है । नयी व्यवस्था में मंत्रिमंडल के विभागों में कुछ और भी परिवर्तन किये गये हैं ।

देखना यह है कि नये वित्तमंत्री और कृषिमंत्री पुरानी नीतियों में कुछ परिवर्तन करते हैं या नहीं । यों सिद्धान्ततः अब तक की सब नीतियों के लिए भी केन्द्रीय मंत्रिमंडल का संयुक्त उत्तरदायित्व था और प्रधानमंत्री पं० नेहरू उन सबके लिए अन्ततः उत्तरदायी थे । इसलिए उनमें परिवर्तन का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होना चाहिए । किन्तु बहुत सम्भव यह है कि मंत्रिमंडल में कुछ परिवर्तनों का लाभ उठाकर भारत सरकार कुछ ऐसी नीतियों में संशोधन कर दे, जिनके कारण जनता में बहुत असंतोष है । अनिवार्य बचत और स्वर्ण नियंत्रण के सम्बन्ध में संशोधन की आवाज भी उठने लगी है । इसी तरह श्री पाटिल की कृषि नीति से भी कुछ असंतोष प्रकट किया जाता है । आगामी १-२ महीने तक इस सम्बन्ध में कोई न कोई आभास अवश्य मिल जायेंगे, ऐसी आशा करनी चाहिए ।

भीषण जलप्रलय

प्रकृति की लीला विचित्र है । एक तरफ सारा देश कृषि उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी ओर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार आदि राज्यों में जल प्रलय के समाचार आ रहे हैं । मई और जून में वर्षा ही नहीं हुई । खेत सूख गये । और अब एक महीने से जो वर्षा हो रही है, उससे स्थान-स्थान पर भीषण बाढ़ें आ रही हैं । हजारों मील क्षेत्रों में पानी फैल गया है, सैंकड़ों गांव डूब गये हैं और फसलें तबाह हो रही हैं । प्रतिवर्ष अगस्त और सितम्बर में यह निश्चय किया जाता है कि हम बाढ़ नियंत्रण की योजना पर अमल करेंगे । लाखों रुपयों की योजनायें बनाई भी जाती है, किन्तु अगला वर्ष आता है और बाढ़ें पहले से भी भयंकर रूप धारण कर के आ जाती हैं । मानव और प्रकृति में यह संघर्ष जारी है । देखें मानव कब विजय प्राप्त करता है ?

सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एक महत्वपूर्ण प्रश्न

निम्न वर्ग की दैनिक आय कितने पैसे ?

(कृष्णचन्द्र विद्यालंकार)

संसद में श्री राममनोहर लोहिया ने ६० प्रतिशत अर्थात् २७ करोड़ भारतीयों की आय औसतन ३ आना है, यह घोषणा करके एक मनोरंजक परन्तु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका तीव्र प्रतिवाद करते हुए यह औसत १५ आने बताई है, जबकि योजना मंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा ने नेशनल सैम्पल सर्वे की जाँच का उद्धरण देते हुए बताया है, कि देश के ६० प्रतिशत का दैनिक व्यय ७।। आना है। संसद में यह विवाद उपस्थित हो और दोनों पक्ष अपने-अपने मन्तव्य को पुष्ट करने के लिए अनेक अंक और युक्तियां प्रस्तुत करें, इससे पहले ही अर्थ-शास्त्रियों में इस प्रश्न को लेकर अच्छा खासा विचार चल पड़ा।

योजना मंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा ने यह सूचित किया कि जो ६० प्रतिशत व्यक्ति औसतन ७।। आना प्रति दिन व्यय करते हैं, उन ६० प्रतिशत में भी प्रथम १० प्रतिशत से लेकर अन्तिम १० प्रतिशत विभिन्न राशि व्यय करने वाले हैं। उनके कथनानुसार इस सम्बन्ध में उपलब्ध नवीनतम आंकड़े यही हैं, जो इस सर्वे से ज्ञात हुए हैं। इस जांच के परिणामस्वरूप गांवों में सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति भी आठ रुपये मासिक व्यय तथा शहरों के निर्धन व्यक्ति १० रुपये मासिक व्यय करते हैं। इस हिसाब से गांवों में प्रति व्यक्ति दैनिक व्यय ४.३ आना और शहरों में ५.३ आना पड़ता है। इन ६० प्रतिशत व्यक्तियों का औसत व्यय निम्नलिखित से स्पष्ट है :—

% प्र. श. जनसंख्या का प्रतिशत	प्रतिमास व्यय रुपयों में		प्रतिदिन प्रति व्यक्ति व्यय (नये पैसों में)	
	देहात	शहर	देहात	शहर
० — ५	७.०९	८.५३	२४	२८
५ — १०	९.०९	११.५५	२७	३३
० — १०	८.०९	१०.०४	२७	३३
१० — २०	१०.६७	१३.८८	३१	४०
२० — १०	१२.८२	१६.६१	३३	४५
३० — ४०	१४.६२	१९.५६	३९	५०
४० — ५०	१६.४७	२१.९४	४२	५५
५० — ६०	१८.७९	२५.५०	४५	६०
६० — ७०	२१.२५	२७.६८	४९	६४
७० — ८०	२४.७०	३५.९५	५३	७१
८० — ९०	२९.९५	४३.८६	५८	८०
९० — १००	५१.१६	८८.७६	७०	१०१
१ १००	२०.८५	३०.३६	७०	१०१

(१ आना = ६.२५ न. पै., ३ आना = १९ न. पै.)

इसका अर्थ यह हुआ कि सबसे अधिक निम्न वर्ग की आय भी डा० लोहिया के अंकों से अधिक ऊंची है। डा० लोहिया और उनके समर्थकों ने व्यय के इन अंकों का फिलहाल प्रतिवाद न करते हुए भी यह कहा है, कि कोई आदमी १० रुपये व्यय करता है, यह इस बात का प्रमाण नहीं है, कि उसकी आमदनी भी १० रुपये है। वह कर्ज भी ले सकता है और दूसरों से सहायता भी ले सकता है। अधिकांश देहाती किसान ऋण-भार से ग्रस्त हैं।

औसत भारतीयों की औसत आय अत्यन्त निम्न होने के पक्ष में दो और मान्यताएं भी पेश की जाती हैं। इनमें से एक स्थापना यह है, कि जनसंख्या का ५ प्रतिशत भाग समस्त आय राशि का ३० प्रतिशत प्राप्त कर लेता है। अर्थात् शेष ९५ प्रतिशत जनता को राष्ट्रीय आय का केवल ७० प्रतिशत मिलता है। दूसरी स्थापना के अनुसार जनसंख्या का एक प्रतिशत ही समस्त राष्ट्रीय उत्पादन का ५० प्रतिशत छीन लेता है और शेष ९९ प्रतिशत में ५० प्रतिशत का वितरण होता है। स्वभावतः इस भारी असमान वितरण से निम्न वर्ग को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। यदि यह दोनों अथवा इनमें से एक भी स्थापना सत्य हो,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तो डा० लोहिया का कथन सत्य के बहुत अधिक निकट जा पहुँचता है। किन्तु बहुत से अर्थशास्त्रियों को इन स्थापनाओं की सत्यता में भारी सन्देह है। योजना आयोग के एक मण्डल द्वारा की गई जांच के परिणाम-स्वरूप आय और व्यय का विभाजन इस तरह है। इस गणना में समस्त जन-संख्या को आय क्रम से १० भागों में बांटा गया है।

आय और व्यय का वितरण

जन-संख्या का प्रतिशत दसवां	प्रतिशत वितरण आय	व्यय	समूहों में अधिकतम व्यय प्रति व्यक्ति (मासिक)
निम्नतम	२.४	२.९८	९.६
दूसरा	३.४	४.४५	१२.६
तीसरा	४.३	५.५६	१५.२
चौथा	४.८	६.६१	१७.९
पांचवां	६.३	७.७४	२०.८
छठा	७.८	९.००	२४.३
सातवां	९.२	१०.५४	२८.६
आठवां	१०.६	१२.५७	३४.६
नौवां	१४.५	१५.६९	४५.१
उच्चतम	३६.६	२४.८६	—

उपर्युक्त तालिका से यह तो स्पष्ट है, कि देश के विभिन्न वर्गों में काफी असमानता है। उच्चतम १० प्रतिशत को ३६.६ प्रतिशत राष्ट्रीय आय होती है, और अधिकतम आय वाले ४० प्रतिशत को राष्ट्रीय आय का ५१ प्रतिशत मिल जाता है। प्रथम ६० प्रतिशत को केवल २९ प्रतिशत मिलता है। इस तालिका से यह भी मालूम होता है, कि सबसे निम्न वर्ग को प्रतिमास ९.६ रुपया व्यय के लिए मिल जाता है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि डाक्टर लोहिया का २७ करोड़ जनसंख्या को ३ आना प्रति व्यक्ति आय का वक्तव्य तो किसी तरह प्रमाणित नहीं हो पाता।

आय बनाम व्यय के अंक

कुछ लोगों ने यह प्रश्न उठाया है, व्यय के अंक आय को सिद्ध नहीं करते। परन्तु यह बात कम समझ में आती है। कोई कर्ज भी लेता है, तो उसको उसकी सामर्थ्य के अनुसार ही कर्ज़ मिलता है। जो लिया हुआ कर्ज चुका ही न सके, उसको कोई कर्ज नहीं देता। इसलिए व्यय के अंकों को नितान्त अप्रामाणिक व भ्रान्तिजनक मान लेना ठीक नहीं।

अखिल भारतीय उद्योग व्यापार संघ के अध्यक्ष लाला भरतराम ने भी आय के वितरण के अंकों की अपेक्षा व्यय के अंकों को ही प्रामाणिक मानने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि आय के वितरण के आंकड़ों की अपेक्षा हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए, कि आम लोगों के व्यय का स्तर क्या हो गया है। देश में अधिकाधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, तथा उनकी खपत निरन्तर बढ़ती जा रही है। इससे यह सिद्ध होता है, कि गरीब लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो रहा है। लोगों के जीवन स्तर में खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चीनी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की सेवाओं पर अधिक व्यय होने लगा है। पिछले १० वर्षों में आबादी में जहां २२ प्रतिशत वृद्धि हुई है, वहां खाद्यान्न का उत्पादन और आयात ४६ प्रतिशत, कपड़े का ६२ प्रतिशत, चीनी का १४० प्रतिशत और वनस्पति घी का उत्पादन ११० प्रतिशत बढ़ गया है। अब ज्वार और बाजरे की बजाय गेहूँ व चावल का प्रयोग भी बढ़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों में ८५ प्रतिशत हस्पतालों के बिस्तरों में ६५ प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। १९५१ में जहां २८०० गांवों में बिजली थी, १९६२ में २७५०० गांवों में बिजली लग गई है। इससे स्पष्ट है कि जनता का जीवन स्तर ऊंचा हो गया है। इन आंकड़ों का अधिक सम्बन्ध देश के समृद्ध वर्ग से न होकर सामान्य जनता से है। यदि आर्थिक विकास का लाभ साधारण जनता तक नहीं पहुँचा, तो उस आर्थिक विकास का लाभ ही क्या है।"

प्रति व्यक्ति आय और व्यय

प्रोफैसर महफूज अहमद ने लोगों की व्यक्तिगत आय और बचत पर एक विद्वत्ता-पूर्ण निबन्ध लिखा है। उन्होंने इस मान्यता का विरोध किया है, कि देश की केवल १ प्रतिशत जन संख्या को राष्ट्रीय आय का ५० प्रतिशत तक मिलता है। उनके कथनानुसार जनता के २॥ प्रतिशत को राष्ट्रीय आयका केवल १९.७ प्रतिशत भाग मिलता है। इस पुस्तक का आधार १९५६-५७ के अंक हैं। इस पुस्तक में दी गई तालिका निम्न लिखित है—

सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रति व्यक्ति मासिक आय (रुपयों में)	औसत प्रति व्यक्ति आय	प्रति व्यय औसत व्यय	व्यक्तियों का प्रतिशत
०— १०	६.४	८.०	२३.५९
१०— १५	११.२	१२.५	२५.७३
१५— २०	१७.२	१७.५	१९.८८
२०— २५	२२.३	२२.२	१०.७०
२५— ३०	२७.१	२६.५	६.०७
३०— ४०	३४.०	३१.८	५.९३
४०— ५०	४४.०	३८.७	२.८३
५०— ६०	५४.०	४५.२	१.५७
६०— ७०	६४.०	५०.२	०.९८
७०— ८०	७४.०	५६.४	०.६२
८०—१००	८८.००	६३.८	०.७३
१००—१५०	१२२.००	८०.४	०.७४
१५०—२००	१७१.०	१०१.५	०.२७
२००—३००	२४५.०	१३२.०	०.२२
३००—५००	३९२.०	१८२.००	०.०८
५०० और उससे ऊपर	७५०.०	२८५.०	०.०६

जीवनी शक्ति का ऊंचा स्तर

इस समस्त विवेचन के साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि १९४७ के बाद से देश में मृत्यु संख्या का अनुपात केवल ५० प्रतिशत रह गया है । १९४७ में मृत्यु संख्या का अनुपात १९.७ प्रति हजार था । १९६० में यह अनुपात १०.३ प्रति हजार रह गया है । इस अवधि में मलेरिया आदि बुखारों से मरने वालों का अनुपात १०.८ प्रति हजार से गिर कर ४.२ प्रति हजार रह गया है । इसी तरह हैजा तथा स्वास आदि से मरने वालों की संख्या भी क्रमशः ०.४ से गिर ०.०५ और १.५ से गिर कर १.० प्रति हजार रह गई है । १९४७ की १४६ प्रति हजार बच्चों की मृत्यु संख्या १९६० में गिर कर ९१ प्रति हजार रह गई । इसी तरह प्रत्येक भारतीय नागरिक की औसत आयु भी बढ़कर ३२ से ४७ वर्ष हो गई है ।

हमने ऊपर लाला भरत राम के वक्तव्य में बताया है, कि विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन बहुत बढ़ गया है। नीचे की तालिका से यह मालूम होगा कि प्रति व्यक्ति विभिन्न उपभोग्य पदार्थों की खपत पिछले १२ वर्षों में कितनी बढ़ गई है :

प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत

पदार्थ	१९५०	१९६१-६२
कपड़ा (मीटर)	११.३	१५.७
नमक (किलोग्राम)	७.८	७.९
मिट्टी का तेल (लिटर)	३.३	६.७
दियासलाई (६० तिल्लियों का बक्स)	१०.९	११.९
चाय (ग्राम)	२१५	२८०
काफी (ग्राम)	५२	१०५
चीनी (किलोग्राम)	३.२	५.८
वनस्पति (ग्राम)	४७२	८०२
साबुन नहाने व कपड़े धोने का (किलोग्राम)	०.२२	०.३३
जूते (जोड़े)	०.०६	०.१२
तम्बाकू (कच्चा) (कि. ग्रा.)	०.७	०.८
सीने की मशीन (प्रति १० लाख व्यक्ति)	१५०	७३०
बाइसिकल (प्रति १० लाख व्यक्ति)	७५०	२०३०

इस समस्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि औसत भारतीय का जीवन स्तर निरन्तर ऊंचा हो रहा है और इसलिए डा० लोहिया ने जो गम्भीर चिन्ता प्रकट की है, स्थिति उतनी गम्भीर नहीं है। फिर भी इसका यह अर्थ नहीं कि हमारी आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक है। अब भी भारतीय की औसत आय अपेक्षाकृत बहुत कम है। उसे निरन्तर बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। पंचवर्षीय विकास योजनाओं के सामने यही लक्ष्य सामने रहना चाहिए। प्रधान मन्त्री पं० नेहरू ने १५ आना आय की बात कही है, वह समस्त राष्ट्रीय आय के वितरण की है, जबकि डा० लोहिया ६० प्रतिशत जनसंख्या की बात करते हैं। इसी तरह गरीब और गरीब हो रहा है, यह युक्ति भी भ्रांत है। अमीर और भी अमीर हो गया है, यह तो माना जा सकता है, पर गरीब और भी अधिक गरीब हो रहा है, वह केवल राजनैतिक दलों की नारेबाजी है। वस्तुतः गरीब का जीवनस्तर भी अधिक ऊंचा होता जा रहा है। ● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय योजना में समाजवाद

श्रीमन्नारायण, सदस्य योजना आयोग

जब से कांग्रेस ने अवाड़ी-अधिवेशन (जनवरी १९-५५) में "समाजवादी नमूने के समाज"—पर प्रस्ताव स्वीकार किया, तब से देश में आयोजित आर्थिक विकास-द्वारा समाजवादी लोकतन्त्र की प्राप्ति के लिए उत्सुकतापूर्ण आकांक्षा प्रकट की गई है। तथ्यात्मक दृष्टि से 'समाजवादी नमूने' शब्द का इस्तेमाल पहले-पहल भारतीय संसद ने १९५४ ई० के एक ग़ैर-सरकारी प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए किया था। यद्यपि कांग्रेस ने 'समाजवादी' शब्द का प्रयोग नहीं किया था, किन्तु समाजवाद का व्यापक मूलतत्त्व बुनियादी अधिकारों के उस प्रसिद्ध प्रस्ताव में किया गया था जिसे कांग्रेस के कराची-अधिवेशन (१९३१) में स्वयं महात्मा गांधी ने पेश किया था। उस प्रस्ताव में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जनसमूह का शोषण बन्द करने के लिए राजनीतिक स्वतन्त्रता में करोड़ों भूखे मरने वालों की असली आर्थिक आज़ादी शामिल की जानी चाहिए। श्री जे० सी० कुमारप्पा की अध्यक्षता में कांग्रेस-देहाती-सुधार-समिति (१९४९ ई०) ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की, उसमें कहा गया कि "भूमि-सम्बन्धी शोषण दूर किया जाय" और यह सिफ़ारिश की कि "विभिन्न प्रकार की खेती के लिए अलग-अलग ढंग की सहयोग-पद्धतियों को अमल में लाया जाय।"

एक जातिहीन, वर्गहीन समाज

आजादी के बाद भारत में आयोजित आर्थिक विकास आवश्यक रूप में भारतीय संविधान से संश्लिष्ट राज्य-नीति के संचालक-सिद्धान्तों पर आधारभूत रहा है। संविधान निर्देशित करता है कि जन-कल्याण की प्रगति के लिए राज्य जहां तक हो सके प्रभावकारी ढंग से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के ऐसे प्रयत्नों की सभी महत्त्व-पूर्ण राष्ट्रीय जीवन की संस्थाओं को सूचना देगा। यह भी कहा गया कि "सभी नागरिकों को पर्याप्त जीवन-यापन के साधन का हक़ है" और यह कि "समुदाय के भौतिक साधनों की मालिकी और नियंत्रण इस ढंग से बंटे होगे जिससे आम लोगों की भलाई हो।" निर्देशक सिद्धान्तों में राज्य को इस दृष्टि से आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जिससे आर्थिक प्रणाली का फल ऐसा न निकले, जिससे परिणाम स्वरूप सम्पत्ति और उत्पादन के साधन आम लोगों के हितों के विरुद्ध क्षतिकारक ढंग से जमा हों।"

ये आम सिद्धान्त जो संविधान में स्थापित किये गये हैं, पहली पंचवर्षीय योजना के प्रकाशन-काल से ही भारतीय योजना की निर्देशक रेखा बने हुए हैं। दूसरी योजना में कहा गया है कि "समाजवादी नमूने की ओर बढ़ने की सबसे अच्छी कसौटी यह होगी कि व्यक्तिगत मुनाफ़ाखोर का स्थान सामाजिक कमाई ले ले।" और "आर्थिक विकास का लाभ अधिकाधिक रूप में समाज के उस वर्ग के लिए जमा हो, जिसे अपेक्षाकृत कम सुविधाएं प्राप्त हैं और आमदनी में सम्पत्ति और आर्थिक शक्ति घनीभूत होने पर लगातार कमी हो।"[1] तीसरी पंचवर्षीय योजना का ध्येय ऐसे समाज की स्थापना करना है, जिसमें "जाति-वर्ग के भेदभाव बिना सुविधाएं समाज के हर व्यक्ति को मिलें और देश के सभी भागों में राष्ट्र की भलाई के लिए पूरे अवसर और सुविधाएं जुटाई जा सकें।"[2]

समाजवाद साम्यवाद नहीं है

भारतीय योजना के अनुसार जिस समाजवादी समाज का खाका पेश किया गया है, उसकी विस्तृत रूपरेखा उपस्थित करने का प्रयत्न करने के पहले यह अच्छा होगा कि हम यह समझ लें कि समाजवाद क्या नहीं है। पहले तो यह बात निस्सन्देह और स्पष्ट रूप में समझ लेनी चाहिये कि भारत का समाजवाद उस प्रकार का नहीं है जैसा कि सोवियत रूस, चीन अथवा पूर्वी यूरोप के देशों में अमल में आ रहा है। इस देश के बौद्धिकों का एक भाग आयोजित आर्थिक विकास को साम्यवादी ढंग के समाजवाद की ओर झुकतामानता है। यह एक बिल्कुल भ्रमपूर्ण ख़याल

१. द सेकण्ड फ़ाइव-इयर प्लन पृ० २२
२. द थर्ड फ़ाइव-इयर प्लान पृ० १९

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है। मार्क्स द्वारा स्पष्टीकृत साम्यवाद के सिद्धान्त आजकी गतिशील दुनिया में ठीक नहीं बैठ पाते। नेहरू जी ने कहा कि—"मार्क्स की अर्थव्यवस्था अनेक प्रकार से पुरानी पड़ गई है और उसका सान्निध्य हिंसा से हो गया है। यह समझा-बुझा और फुसलाकर अर्थात् शान्तिपूर्ण ढंग से परिवर्तन न कर दबाव, बर्बादी और विनाश के द्वारा करना चाहता है।"३

आचार्य विनोबा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गांधीजी का आदर्शवाद या सर्वोदय हिंसा-रहित साम्यवाद नहीं है। सच तो यह है कि ये दोनों आदर्शवाद एक दूसरे से मेल नहीं खाते, उनके अन्दर बुनियादी मतभेद हैं।"४

साधन-शुद्धि

उच्च ध्येय की प्राप्ति के लिए गांधीजी ने साधन-शुद्धि पर बहुत जोर देते हुए कहा है—"यद्यपि रूस को कई उपलब्धियों का श्रेय प्राप्त है, पर उसका काम तब तक टिक नहीं सकता जब तक कि उसके साधन शुद्ध न हों।"५ इसी कारण गांधीजी का यह ख़याल था कि साम्यवाद भारतीय राष्ट्र की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। इसीलिए उन्होंने स्पष्ट किया था कि "भारत-भूमि पर साम्यवाद का पौदा विकसित नहीं होगा।"६ "समाजवाद स्फटिक मणि के समान शुद्ध है इसलिए उसे प्राप्त करने के लिए स्फटिक-वत् साधनों की आवश्यकता है।"७ वर्ल्ड बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष यूजेन ब्लैक ने भी इस बात पर जोर देते हुए कहा है..."आर्थिक विकास जिस प्रणाली के द्वारा प्राप्त किया जाता है, वह कम से कम उतना ही महत्त्वपूर्ण है, जितना कि स्वयं विकास।"८

"स्वतन्त्र उद्यम" नहीं

दूसरे, हमारे लिए यह बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि भारतीय आयोजन के अन्तर्गत समाजवाद का मतलब ऐसी आर्थिक व्यवस्था नहीं है, जिसका आधार 'निजी मुनाफ़ा' और 'स्वतन्त्र उद्यम' हो। पश्चिम के कुछ बहुत विकसित देशों में अबाध व्यापार-नीति के सिद्धान्तों से पूंजीवाद में आमूल परिवर्तन आ गया है और संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी और जापान की आधुनिक अर्थ-व्यवस्था में काफ़ी सम्मिश्रण हो चुका है। बृटिश व्यापारी "अब अपनी औद्योगिक द्विविधा का हल करने के लिए स्वयं उद्योग की शक्ति में विश्वास नहीं रखते।"९ जैसाकि आर्थर लिवि ने कहा है—"अबोध व्यापार में विश्वास करनेवाले अब पागल-से समझे जाने लगे हैं।"१०

पूर्णतः राष्ट्रीयकरण नहीं

तीसरे, यह बात भी स्पष्ट रूप में कह दी जानी चाहिए कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था में समाजवाद का अर्थ पूर्णतः राष्ट्रीयकरण नहीं है। औद्योगिक नीति का प्रस्ताव केवल कुछ बुनियादी या मुख्य उद्योगों—जैसे सुरक्षा का सामान, लोहा और फ़ौलाद, भारी कलें और मशीनरी, कोयला, रेल्वे, जहाज़-निर्माण और खनिज पदार्थों—के लिए था। कुछ और उद्योग—जैसे अलुमिनियम, गैस, लोहे की धातुएं, मशीनी औज़ार, खाद और नक़ली रबड़ ऐसे हैं जो सरकारी और निजी दोनों ही प्रकार के उद्योगों के लिए खुले हैं। इनके अलावा कितनी ही उपभोक्ता-उत्पादन की चीजें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल निजी उद्योगों के लिए खुली हैं—हां, उनके लिए राष्ट्रीय योजना की अन्तर्भुक्त सीमा के अन्दर रहना जरूरी है। प्रधान मन्त्री के बार-बार कहा है कि "उत्कट महत्त्व की बात 'सामाजिक नियंत्रण' है न

(शेष पृष्ठ ३६९ पर)

३. श्री जवाहरलाल नेहरू के ए० आई० सी० सी० इकानामिक रिव्यू के १५ अगस्त, १९५८ के अंक में प्रकाशित लेख से।

४. श्री मश्रूवाला कृत (नवजीवन) 'गांधी और मार्क्स की विनोबाजी कृत भूमिका से।

५. मो० क० गांधी (नवजीवन) कृत 'टुवर्ड्स नान-वायोलेन्ट सोशलिज्म' से

६. ऑल मेन आर ब्रदर्स (यूनेस्को-प्रकाशन), पृ० ८३

७. द डिप्लोमेसी ऑफ़ इकॉनॉमिक डेवलपमेंट, पृ० ९

९. न्यूस्टेट्समेन, लन्दन (द वीक एण्ड रिव्यू) ८ फरवरी, १९६३

१०. प्रिंसिपल्स आफ़ इकॉनॉमिक प्लानिंग, डब्लयू० ए० लिवी कृत, पृ० १४

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

योजना और पूंजीविनियोग

विद्वान लेखक ने योजना और पूंजीविनियोग के सम्बंध में एक दूसरा ही पक्ष रखते हुए कम आवश्यक उद्योगों पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने, उद्योगों के केन्द्रीयकरण तथा बढ़ते हुए स्वार्थ समूह की ओर देश के विचारकों का ध्यान खींचा है। यह पक्ष भी उपेणीय नहीं है।

पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य देश का उद्योगीकरण है। पर इन योजनाओं का निर्माण कुछ ऐसे दोषयुक्त ढंग से हुआ है, जिससे समाज का निर्बल अंग इनसे लाभ उठाने में असमर्थ हो रहा है। इन योजनाओं में दो बड़े दोष हैं। पहला, रोजगार के अवसरों में वृद्धि का अभाव और दूसरा जीवन स्तर का ऊंचा न होना। योजना आयोग के अपने कथनानुसार, दूसरी योजगा की अवधि में बेरोजगारी में लगातार वृद्धि हुई है। इसी प्रकार जीवनस्तर के मुख्य अंग खाद्य में प्रति व्यक्ति अनाज और दालों का प्रयोग उतना ही हुआ है जितना पहले था। उद्योगीकरण भी हमारा उन्हीं क्षेत्रों में हुआ है, जिनमें विदेशी पूंजी का सहयोग मिल सका है।

रेयन उद्योग को बढ़ावा क्यों ?

इस दोषयुक्त आयोजन का परिणाम यह है कि पूंजी विनियोग ऐसी दिशाओं में किया गया है, जिन्हें अभी प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए थी। इसका ठोस उदाहरण दूसरी योजना की अवधि में रेयन उद्योग की स्थापना और विस्तार है। इसका फल केवल यह नहीं है कि पूंजी का विनियोग गलत तरीके से हुआ, किन्तु एक ऐसे स्वार्थ समूह का निर्माण हो गया जिससे भावी पूंजी का प्रवाह भी अशुद्ध दिशा में होने लगा। सबसे अधिक खेदजनक स्थिति यह पैदा हो गयी है कि आय का सन्तुलन बिगड़ गया है। कुछ खास ढंग के भारी उद्योग बड़े-बड़े नगरों में चलाये जा रहे हैं, जिससे एक ऐसी श्रेणी पैदा हो गयी है जिसके हाथ में फालतू धन जमा हो गया है। इसकी आय लगातार बढ़ रही है और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जो इस श्रेणी की प्रवृत्तियों से सम्बद्ध हैं, उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। इस प्रकार, राष्ट्रीय आय की वृद्धि का अनुपात विकृत हो रहा है। इसका प्रभाव, उपभोक्ता व उसकी सशक्त मांग पर पड़ता है और अन्त में उत्पादन उद्योग का स्वरूप इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता।

आज यह आम शिकायत है कि आय का असमान वितरण है। कहा जाता है कि अमीर अधिक अमीर और गरीब अधिक गरीब हो रहे हैं। पर ऐसा क्यों है, इस पर कम ध्यान दिया जाता है। हम देखते हैं कि बाजार में मोटे कपड़े की मांग रुकी पड़ी है पर रायन, एअर कंडीशनर, रिफ्रीजेटर, और निजी मोटर कारकी मांग निरन्तर बढ़ रही है। इस असन्तुलित मांग का प्रबल प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है, और उद्योग एअर कंडीशनों, रिफ्रीजेटर, रायन के उत्पादन पर, मांग बढ़जाने के कारण, अपना ध्यान विशेष रूप से केन्द्रित करने लगता है। समानता के आधार पर निर्मित समाज में विभिन्न पूंजी-विनियोगों के आधार पर बाजार भावों की दृष्टि से सापेक्ष-लाभ की प्राप्ति युक्ति संगत हो सकती है पर ऐसा समाज जिसमें असमानता हो और वह बढ़ रही हो, वहां बाजार भाव के आधार पर दीर्घकालीन पूंजी-विनियोग करना सर्वथा भ्रान्तिपूर्ण होता है। आश्चर्य की बात यह है कि आज भारत में उद्योगीकरण इसी भावना से प्रभावित हो रहा प्रतीत होता है।

उद्योगपतियों को ही लाभ

हमारी आज की आर्थिक नीति का एक महत्त्व का अंग यह है कि वह पूंजीपतियों की बचत की राशि पर निर्भर करती है और जरुरी पूंजी-विनियोग के कई निर्णय पूंजी पतियों के हाथ में ही रहने दिये जाते हैं। बचत की राशियों को इस प्रकार निजी हाथों में रहने देने से अर्थ-नीति प्रभावित होती है। इसके कई स्वरूप है, जैसे, व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष-कर का स्तर, विभिन्न प्रकार की करियायतें आयात लाइसेंसों को नया रूप देना इत्यादि। इन सब का अन्तिम परिणाम एक ही है। कुछ ऊंचे दर्जे की पूंजीपतियों की टोली के द्वारा नियंत्रित आयों में इतनी

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वृद्धि हो जाती है कि वे और उनके साथी पाश्चात्य ढंग से ऊंचा खर्चीला जीवन व्यतीत करके भी इतनी पूंजी बचा लेते हैं और आधुनिक व्यापार के निजी क्षेत्र में उसका विनियोग करते रहते हैं। निर्यात को बढाने की आड़ में आयात को जो नया मोड़ दिया गया है और विदेशी पूंजी का जिस रूप में योगदान मिल रहा है, उससे इस उपर्युक्त नीति को और भी बढ़ावा मिल रहा है। प्रत्यक्ष रूप से तो यह कहा जाता है कि इससे निर्यात वृद्धि होगी, पर वस्तुतः इसका परिणाम यह हो रहा है कि कुछ लोगों के पूंजी के साधन, अनुपात से भी अधिक बढ़ रहे हैं।

कुछ थोड़े लोगों के हाथ में पूंजी जमा होने का दूसरा बड़ा कारण निजी क्षेत्र में विदेशी व्यापारियों का पूंजी विनियोग है। इसका भी वही परिणाम है, पूर्वोक्त श्रेणी के हाथ में पूंजी का जमा होना। विदेशी पूंजी में सहयोग का मतलब है एक करोड़पति का दूसरे करोड़पति के साथ गठबन्धन। इससे प्रादुर्भूत परिणाम आश्चर्यजनक नहीं हो सकते। अपनी महती अतिरिक्त पूंजी के द्वारा ये धनपति ही सर्वोत्तम गुणशाली कर्मचारी वर्ग और योग्य तकनीकियों पर शासन करते हैं।

सन्तुलित विकास की उपेक्षा

तीसरी योजना में जीवन-स्तर ऊंचा करने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसकी समस्याओं के प्रति कोई विशेष जागरूकता नेताओं में नहीं पायी जाती। "सन्तुलित क्षेत्रीय विकास"—इन शब्दों का महत्व केवल मौखिक उच्चारण तक ही है। इस योजना में प्रस्ताव किया गया है कि विभिन्न आकारों की ३०० नयी उद्योगपुरियां छोटे व मझौले कस्बों में स्थापित की जाएगी। पर, आम प्रवृत्ति यही है कि बड़े-बड़े नगरों में विकास की घनता बढ़ायी जाए। इससे हमारी पिछड़ी अर्थ व्यवस्था में और भी असन्तुलन पैदा हो रहा है। योजना का निर्माण उद्योगों की भाषा में किया गया है, उनके स्थान का प्रश्न प्राकृतिक कारणों पर छोड़ दिया गया है। पर आज भारत को जिस चीज की आवश्यकता है, वह मुख्यतः स्थान के शब्दों में होनी चाहिए, उद्योगों के चुनाव का प्रश्न बहुत कुछ, स्थानीय साहस और हालात पर छोड़ देना चाहिए।

जहां तक जनता के जीवन-स्तर को ऊंचा करने का प्रश्न है, यह निश्चित है कि लगभग ८५% लोगों के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक शहरी क्षेत्रों से बाहर समूचे देश का अ-कृषि सम्बन्धी उत्पादन का विकास नहीं किया जाएगा। अ-कृषि भिन्न को बढ़ाने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि (क) भारतीय किसान प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ाने में असमर्थ है, क्योंकि भूमि पर्याप्त कम है। (ख) देहाती आबादी का शहरी आबादी के साथ ऐसा अनुपात है कि अगर प्रत्येक किसान शहरी सामान और सेवाओं के बदले में अधिक फालतू खाद्य-उत्पादन भी कर ले, तब भी शहरों के बाजार इतने बड़े नहीं हैं कि वे सब किसानों की जरूरतों को पूरा कर सकें।

उद्योगों का विकेन्द्रीकरण

शहरी क्षेत्रों में बड़ी तेजी से हो रहा औद्योगिक विकास, यद्यपि ऊपर से अच्छा प्रतीत होता है, पर देश की ८५% जनता के कल्याण के लिए यह भारी खतरा है क्योंकि इससे पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था में अ-कृषि उत्पादन का विनाश हो जाएगा। इसमें एक बड़ा खतरा यह है कि सब शहर एक दूसरे से सम्बद्ध हैं, इस लिए उन्हें "प्राकृतिक रक्षा" प्राप्त नहीं है जो छोटे शहरों व देहात में सुलभ है। कृषि के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि इसका हल केवल आर्थिक नहीं, किन्तु बौद्धिक स्तर पर भी होना चाहिए। कृषि पर अधिक जोर देना बौद्धिक पिछड़ेपन की निशानी है। कोशिश यही होनी चाहिए कि जिले की स्थानीय मौलिक आवश्यकताओं को स्थानीय साधनों से ही पूरा किया जाए न कि बड़ी-बड़ी विदेशी मशीनें लगाकर। इस प्रकार आयात में काफी कमी आ जायगी और विदेशी मुद्रा की बचत हो सकेगी। विदेशी सहायता पर आधारित विकास की योजनाएं आत्म विश्वास और आत्म सम्मान को ठेस पहुँचाने वाली होती हैं।

उद्योगीकरण के सम्बन्ध में तीन चीजों पर जोर देने की आवश्यकता है (१) परिवहन, बिजली और अन्य साधनों का विकास, (२) इस्पात, कोयला, खनिज, भारी रासायनिक इत्यादि मूलभूत उद्योगों का विस्तार और (३) पूंजीगत सामान को पैदा करने वाले उद्योगों का विस्तार। शेष उद्योगों का, योजना के अनुसार, विकेन्द्रीकरण और बिखराव अवश्य होना चाहिए। ● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नियोजन और जनसंख्या की समस्या

श्री एस. बापना, विद्याभवन, रूरल इन्स्टीयूट, उदयपुर

भारत तीन पंच वर्षीय योजनायें बना चुका है। प्रथम योजना १९५२ में प्रारम्भ की गई और अब हम तीसरी योजना में चल रहे हैं, इस प्रकार गत १०-१२ वर्षों से हम अपने प्राकृतिक साधनों व जन शक्ति को इन पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा राष्ट्रीय कार्यों के विकास में लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि हम इन तीनों योजनाओं के उद्देश्यों को देखें तो हमें ज्ञात होगा कि मुख्य उद्देश्य निम्न रखे गये—प्रथम व दूसरी योजना में—(१) राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, जिससे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके (२) आधार भूत एवं भारी उद्योगों के विकास पर जोर देना (३) बेरोजगारी को दूर करना (४) आय व धन की असमानता को दूर करना (५) बेकार भूमि को उपयोग में लाना।

प्रथम योजना में हमारा उद्देश्य मुख्यतया देश में जो आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक व्यवस्था में असंतुलन था, उसको ठीक करना व भविष्य में जो योजनायें बनाई जायं उनके लिये एक प्रकार से नींव तैयार करना था। खाद्य सामग्री के मामले में अपने आपको आत्मनिर्भर बनाना भी हमारा एक उद्देश्य था।

दूसरी योजना में मुख्यतया जोर भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर दिया गया जिससे भविष्य में विकास में गति आ सके तथा आर्थिक बिकास तेजी के साथ हो सके—

परन्तु तीसरी योजना के उद्देश्य कुछ और होते, यदि हमारी जनसंख्या में वृद्धि आशा से अधिक न होती। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने से खाद्य संकट पुनः दृष्टि गोचर होने लगा और हमको हमारी योजना का मुख पुनः प्रथम योजना की भांति खाद्य उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि करने के उपाय की ओर मोड़ना पड़ा—इसी को ध्यान में रखकर योजना के उद्देश्य (१) कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना (२) राष्ट्रीय आय में ६ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से या योजना काल में कुल ३०% वृद्धि करना (३) लोगों के लिये अधिकाधिक रोजगार के स्रोत ढूंढ़ना (४) आय व धन की असमानताओं को दूर करना (५) भारी व आधार सूत उद्योगों को महत्त्व देना आदि रखे गये—

जनसंख्या और आर्थिक विकास एक दूर से जुड़े हुये हैं। किसी भी देश का आर्थिक विकास इस बात पर निर्भर करता है कि देश में जन्म व मृत्यु दरें क्या है। हम एक ओर जीवन स्तर ऊंचा करना चाहते हैं, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना चाहते हैं, अधिक से अधिक देश के लोगों को सुविधायें दे सकने का प्रयत्न करते हैं ताकि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, अधिक लोग शिक्षित हो जायं—अधिक आवागमन तथा डाक तार की सुविधायें प्राप्त हो सकें, आवास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके, आवश्यक खाद्य सामग्री व कपड़े आवश्यकतानुसार उचित कीमत पर उपलब्ध हो सके। दूसरी ओर यदि जनसंख्या बढ़ जाती जाती है तो जो कुछ भी हम योजना बनाकर पूरा करना चाहते हैं उसे पूरा करना अधिक कठिन हो जाता है और अन्त में यही कि हम भली प्रकार से आवश्यकतानुसार सफलता नहीं प्राप्त कर पाते—जनसंख्या वृद्धि से जो आर्थिक स्तर बना हुवा है, उसे बनाये रखना भी कठिन हो जाता है और बिना और विकास के वर्त्तमान स्तर भी धीरे २ गिरना प्रारम्भ हो जाता है!

दो उपाय

यदि हम वर्तमान जीवन स्तर को बनावे रखना चाहते है तो उसके दो उपाय हैं। पहला तो यह कि हम जन्म दर रोके या फिर जिस गति से देश का विकास हो रहा है, उसमें और तेजी लायें। तेजी लाने के लिये अधिक पूंजी व साधनों की आवश्यकता होती है जो एक पिछड़े देश के लिये अधिक कठिन है। जनसंख्या को कम करना याने जन्म दर को घटाना अधिक लाभप्रद व आसान होता है। हमारे देश को ही लें तो हमें ज्ञात होना चाहिये कि जनसंख्या की वृद्धि पहले के अनुपात में अधिक बढ़ रही है। कुछ लोग आश्चर्य कर सकते हैं कि हम एक ओर जीवन-स्तर ऊंचा कर रहे हैं तो हमारी जन्म-दर घटनी चाहिये वृद्धि कैसे हो रही है? आशावादी अर्थशास्त्रियों का भी यही कहना है कि ज्यों २ जीवन स्तर बढ़ता है त्यों २ जन्म दर घटती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मूल

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कारण मृत्यु दर में कमी है। यह निश्चित ही गौरव की बात है कि हमने आज चिकित्सा के क्षेत्र में इतना विकास कर लिया है कि हम मृत्यु दर को बहुत नीचे तक, याने औसत तक ले आये हैं। हर देश में जनसंख्या में वृद्धि अभिशाप बन कर नहीं आती। यह सब अलग २ देशों की जनसंख्या, आर्थिक साधन म अन्य बातों पर निर्भर करता है। भारत के लिये जनसंख्या की वृद्धि अभिशाप ही कही जा सकती है जबकि कनाडा, आस्ट्रेलिया, रूस आदि के लिये एक वरदान सिद्ध होता है। आस्ट्रेलिया में जनसंख्या की वृद्धि को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

अभिशाप

भारत के लिये जनसंख्या अभिशाप इस माने में है कि ज्यों २ जनसंख्या में वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय गिर जाती है, लोगों को चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन आदि सुविधायें कम उपलब्ध होने लगती है तथा देश के सामने खाद्य, कपड़ा, आवास, बेरोजगारी, गरीबी आदि कई एक आर्थिक एवं सामाजिक समस्यायें आ खड़ी होती हैं। पहले ही देश को कई एक समस्याओं को हल करना होता है। इन नई समस्याओं से संतुलन असंतुलन में परिवर्तित हो जाता है और देश की सरकार कठिनाई में पड़ जाती है। भारत में जो साक्षरता का स्तर १९.६% से २३.७ तक पहुँचा, इसी प्रकार औसत आयु ३२ से ४० से अधिक आयु तक पहुँची। यदि हमारी जन्म दर कम होती तो शायद साक्षरता ३०% व औसत आयु ५० तक पहुँच जाती। किसी भी देश के आर्थिक विकास को वहां की राष्ट्रीय आय द्वारा आंका जाता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से देश के विकास की प्रगति की गति को जाना जा सकता है। पर यह जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति की आय में भी औसतन वृद्धि हो। हो सकता है, जिस गति से राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है, उस गति से प्रति व्यक्ति औसतन आय न बढ़ी हो और संभव है पहिले से कम हो गई हो या कम दर से बढ़ी हो। यह सब जनसंख्या की वृद्धि पर निर्भर करता है। यदि जनसंख्या पहिले से कम हो जाय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो तो भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ जायगी। राष्ट्रीय आय पर ही देश की खुशहाली निर्भर करती है। हमारी राष्ट्रीय आय १९५०-५१ में १०,२४० करोड़ रुपये थी जो १९५५-५६ में १२,१३० करोड़ रुपये आंकी गई और जो बढ़कर १९६०-६१ में १४ करोड़ रुपये हो गई—दूसरी ओर प्रति व्यक्ति औसत आय (वार्षिक)—१९५०-५१ में २८४ रुपये १९५५-५६ में ३०६ जो बढ़कर १९६०-६१ में ३३० रुपये हो गई, याने दस वर्ष में प्रति व्यक्ति ४६ रुपये, याने ४.६ रुपये वार्षिक वृद्धि हुई जो संतोषजनक नहीं है। पर यह सब जनसंख्या की वृद्धि का ही परिणाम है। यदि वृद्धि दर कम होती तो निश्चित ही हम प्रति-व्यक्ति औसत आय में अधिक वृद्धि करने में सफल होते।

यदि हम विचार करें तो पता चलेगा कि आयोजकों के सम्मुख भी जनसंख्या वृद्धि अन्य समस्याओं की भांति एक समस्या है और इसके लिये भी एक निश्चित कार्यक्रम की आवश्यकता है, जिससे हम अपनी प्रगति ठीक तरह कर सकें और आवश्यकतानुसार ही जनसंख्या में वृद्धि हो। इसकी वृद्धि को नियंत्रित नहीं करने का अर्थ है कि हम जो भी योजना बनाते हैं उसमें भली प्रकार सफल नहीं होते। अनुमान से अधिक जनसंख्या वृद्धि होने से खाने के लिये अन्न नहीं जुटा पाते, कीमतें बढ़ जाती हैं, कपड़े की कमी हो जाती है, विदेशों से आयात बढ़ाने पड़ते हैं, निर्यात भी उसी अनुसार बढ़ाने होते हैं। निर्यात नहीं बढ़ने पर अन्य आयात सामग्री को कम कर आवश्यक आयात को प्राथमिकता दी जाती है। प्रगति पर इस सबका प्रभाव पड़ता है, उत्पादन प्रति व्यक्ति कम होता है, आय कम होती है, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ती है, तात्पर्य यह कि कई एक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, हम यह भी कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि यदि नियंत्रित न हो तो कई एक समस्याओं का जन्म होता है जो धीरे-धीरे विकट रूप धारण करती है और आयोजक कोई भी योजना बनायें, उसमें उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

उपाय

जनसंख्या वृद्धि रोकने के कई उपाय हो सकते हैं पर यह की स्थिति, सभ्यता, संस्कृति आदि बातों पर निर्भर होता है कि वहां किस प्रकार के उपाय काम में लाये जाय। माल्थस, महात्मा गांधी तो आत्म-संयम को महत्वपूर्ण मानते हैं परन्तु मनुष्य की प्रकृति ऐसी नहीं है कि वह आत्म-संयम से रह सके, इसलिये हमें ऐसे उपायों पर जोर देना चाहिये जिससे मनुष्य काम प्रवृत्ति की संतुष्टि भी कर सके तथा साथ ही साथ जन्म दर में भी कमी आ सके, जैसा कि माल्थस के अनुयायी कहा करते हैं। हमारे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देश में सन्तति निरोध, सन्तति नियमन (Family Plainning) द्वारा हल करने का कार्यक्रम प्रथम योजना व दूसरी योजना में रखा गया, जिस पर ३६५ करोड़ व्यय किया गया। पर तीसरी योजना में इस कार्यक्रम को एक प्रमुख स्थान दिया गया है। इस कार्यक्रम के लिये ३४१ करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। लेकिन इसे सफल बनाने के लिये हमें समाज में जो वातावरण है उसे अनुकूल बनाना होगा, उसके लिये प्रचार व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करना होगा। इसके साथ ही हमें इस परिवार नियोजन के कार्यक्रम को साधारण स्वास्थ्य सेवाओं के साथ समन्वित करना होगा। इसके लिये लोगों को प्रशिक्षण देना होगा, तभी हम इस कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं।

यह निश्चित है कि देश प्रगति के पथ पर चल रहा है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है। हमारे देश में (सामन्यत: अन्य अविकसित देशों में भी) उपभोग की प्रवृत्ति अधिक होने से, व्यक्ति अधिक विवाह व संतान उत्पन्न करने की ओर कुछ समय तक प्रवृत्त रहेगा, जब तक वह एक निश्चित आय तक नहीं पहुँच जाता। हो सकता है कि हमारी जनसंख्या वृद्धि जो अभी २.१% है, १९७१ तक इससे भी अधिक हो जाय, पर सरकार को चाहिये कि वह ऐसे उपाय सोचे जिससे वृद्धि कम से कम हो, वैसे रूढ़िवादिता, अशिक्षा, गरीबी, धर्म, अन्धविश्वास कई एक बाते हैं। इनसे जन-संख्या वृद्धि में प्रोत्साहन मिलता रहेगा—पर नियोजकों को नियोजन द्वारा इस समस्या का भी हल निकालना ही है। कुछ एक निम्न उपाय हो सकते हैं। (१) परिवार नियोजन (२) विवाह की आयु का निश्चित किया जाना और सख्ती के साथ उसका पालन करवाना (३) शिक्षा के प्रसार के कार्यक्रम में वृद्धि करना (४) अन्य प्रचार साधनों द्वारा (५) स्वास्थ्य सुविधायें, परामर्श आदि (६) इस क्षेत्र में अनुसंधान आदि को महत्व देना (७) मनोरंजन के साधनों में वृद्धि करना आदि।

जनसंख्या में वृद्धि की दर

यदि संक्षेप में भारतीय जनसंख्या के वृद्धि के आंकड़ों को देखा जाय तो हमें पता चलेगा कि १८७१ में भारत की जनसंख्या २०.३ करोड़, १९०१ में २८.३ करोड़, १९३१ में ३३.८ करोड़ व १९४१ में ३८.८ करोड़ थी। १९५१ में देश के बंटवारे होने पर भी भारत की जनसंख्या ३६.२ करोड़ हो गई, १९६१ की जनगणना अनुसार जनसंख्या ४३.८ करोड़ है। यह सब देखने पर हमें पता चलता है कि प्रारम्भ में जनसंख्या की वृद्धि दर कम थी। १९२१ के पश्चात वृद्धि दर में कुछ तेजी आई, जो आज १९०१-११ की तुलना ०.५७% में से २.१% तक बढ़ गई है। पहिले वृद्धि दर में कमी के कारण मृत्यु दर का अधिक होना था, जिसका कारण युद्ध, महमारियां, बाढ़, व अन्य दैवीय प्रकोप कहे जा सकते है। आज मृत्यु दर कम हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप जन्म दर अधिक है। निम्न प्रति वर्गमील घनत्व के आंकड़ों को देखकर यह तो हम कह ही सकते हैं कि भारत एक अधिक जनसंख्या वाला देश है।

देश		जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्गमील
भारत	...	३८४
चीन	...	१०५
संयुक्त राज्य	...	४१
रूस	...	२३
कनाडा	...	३
आस्ट्रेलिया	...	२

यदि हम देश के प्राकृतिक साधनों को देखें तो निश्चित ही वर्तमान जनसंख्या से भी अधिक का भरण पोषण करने में भारत समर्थ हो सकता है, फिर भी देश में जो वृद्धि की दर है, वह सामान्य से अधिक है और जिसका नियोजन के साथ संतुलन नहीं रखा जा सकता है। यदि हमें अपनी योजनाओं को सफल बनाना है, देश को खुशहाल देखना है, प्रति व्यक्ति आय अधिक करनी है, अधिक सुविधायें प्राप्त करनी है, जीवन स्तर ऊंचा करना है तो हमें वृद्धि की दर को रोकना होगा। वर्तमान समय में भारत को निराशावादी तथा अंधकार मय भविष्यवक्ताओं की आवश्ययता नहीं है, बल्कि पश्चिम में अपनाये जाने वाले उपायों का अनुमोदन करते हुये उन्हें अपनाना चाहिये तथा आर्थिक व सामाजिक नीतियों का सही दिशा में निर्धारण करना चाहिये ताकि एक ओर देश में द्रुतगति से आर्थिक विकास हो और दूसरी ओर जनसंख्या की वृद्धि की दर में कमी आये।

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

औद्योगिक कार्य क्षमता का मापदंड

श्री एम० एफ० हाश्मी, एम० काम० महारानी लक्ष्मीबाई कालेज ग्वालियर

देश में औद्योगिक इकाइयों की कार्यक्षमता का अध्ययन दो कारणों से महत्वपूर्ण है।

प्रथम तो यह ज्ञात करने के लिये कि औद्योगिक इकाइयां कार्यक्षमता से काम कर रही हैं अथवा नहीं, जिससे कि वे देश व विदेश में प्रतिस्पर्धा कर सकें।

द्वितीय, जो प्रथम से ही सम्बन्धित है, यह कि यदि कुछ इकाइयां कार्यक्षमता से नहीं चल रही हैं तो इस स्थिति के क्या कारण हैं और इन कारणों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, जिससे कि सभी औद्योगिक इकाइयां अधिक कार्यक्षमता से चल सकें।

इस सम्बन्ध में उन घटकों पर भी ध्यान देना लाभदायक होगा, जो किसी एक उद्योग या प्रदेश में किसी एक इकाई या इकाइयों के समूह की कार्यक्षमता पर प्रभाव डालते हैं। औद्योगिक इकाइयों के आकार तथा उनकी कार्यक्षमता के मध्य जो सम्बन्ध होता है और जो भिन्न-भिन्न उद्योगों एवं प्रदेशों में भिन्न-भिन्न हो सकता है, उस पर भी विचार करना होगा। इसके साथ ही किसी औद्योगिक इकाई की उत्पादन क्षमता तथा उसके वास्तविक उत्पादन के मध्य अन्तर का उसकी कार्यक्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर भी विचार करना चाहिये। यद्यपि औद्योगिक इकाइयों के आकार और उनकी उत्पादन क्षमता पर विस्तार से विचार करना कठिन होता है, फिर भी यह जानना तो अच्छा ही होगा कि औद्योगिक इकाइयों की कार्यक्षमता पर उनके क्या सम्भावित प्रभाव पड़ सकते हैं।

देश आज जिस संकटकालीन स्थिति में है, उसकी दृष्टि से औद्योगिक इकाइयों की कार्यक्षमता का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि केवल कार्यक्षमतापूर्ण औद्योगिक इकाइयां ही देश की नागरिक और सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भली भांति कर सकती हैं। अकार्यक्षम इकाइयों का अस्तित्व यह बताता है कि उन क्षेत्रों में या तो साधनों का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग करने में कुछ दोष है या बरबादी पर कठोर नियन्त्रण की कमी है। यदि औद्योगिक इकाइयां कार्यक्षमता से कार्य नहीं कर रही हैं तो इससे यह ज्ञात होता है कि एक ओर तो आन्तरिक सुरक्षित (Sheltered) बाजार में उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य चुकाने पड़ते हैं या निम्न कोटि की वस्तुओं को स्वीकार करना पड़ता है। दूसरी ओर विश्व बाजार में ऐसी वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति अत्यन्त कम हो जाती है। फलतः, नये बाजारों की प्राप्ति तो दूर की बात है, पहले से प्राप्त बाजार के भी हाथ से चले जाने की स्थिति आ जाती है और वे देश, जो औद्योगिक क्षेत्र में कार्यक्षम हैं, बाजारों पर कब्जा कर लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि देश विदेशी विनिमय से जिसकी आज की स्थिति में अत्यन्त आवश्यकता है वंचित हो जाता है। अतः इस संकटकालीन परिस्थिति एवं औद्योगिक विकास की वर्तमान स्थिति में यह उचित ही है कि हम अपनी औद्योगिक इकाइयों की कार्यक्षमता का सूक्ष्म अध्ययन करें।

विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की कार्यक्षमता को मापने तथा यह निश्चित करने के पूर्व कि कौन सी इकाइयां कार्यक्षम है और कौनसी अकार्यक्षम, किसी जांचकर्त्ता को इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा कि कार्यक्षमता एक सापेक्षिक तत्व है, निश्चित (Absolute) नहीं, अर्थात् हम अमुक औद्योगिक इकाई को निश्चित रूप से कार्यक्षम या अकार्यक्षम नहीं कह सकते, वरन् केवल सापेक्षिक रूप से यह कह सकते हैं कि किसी दूसरी इकाइयों की तुलना में अमुक इकाई कार्यक्षम या अकार्यक्षम है।

कार्य क्षमता

दूसरी समस्या यह है कि किसी इकाई को कार्यक्षम या अकार्यक्षम कहने से पूर्व "कार्यक्षमता" (Efficiency) शब्द की पूर्णतः स्पष्ट परिभाषा अति सरल भाषा में दी जाये। कार्यक्षमता शब्द को कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। कभी तो इसका अर्थ कम श्रमिकों की सहायता से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

किसी कार्य को पूरा करने से होता है। ऐसी दशा में प्रति व्यक्ति प्रति घंटा श्रम की उत्पादक-औद्योगिक-कार्यक्षमता को मापने का एक सन्तोषजनक आधार माना जाता है। जब कार्यक्षमता शब्द को अधिक विस्तृत अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका अर्थ कम से कम लागत से अधिकतम परिणाम प्राप्त करने से होता है। ऐसी दशा में प्रति इकाई उत्पादन लागत को कार्यक्षमता का अत्यन्त सन्तोषजनक और विश्वस्त मापक माना जाता है। इसके विपरीत एक उद्योगपति कार्यक्षमता को एक भिन्न अर्थ में समझता है। उसका उद्देश्य विद्यमान परिस्थितियों में अधिकतम लाभ पर वस्तुओं का उत्पादन करना है और इस दृष्टि से उसकी सफलता उसकी उपार्जन शक्ति से निश्चित की जायगी।

तीन आधार

इस प्रकार विभिन्न आकार की औद्योगिक इकाइयों की सापेक्षिक कार्यक्षमता मापने के लिये तीन वैज्ञानिक आधार बताये जाते हैं :

१. विभिन्न इकाइयों की "आय या" लाभ उपार्जन" शक्ति,
२. प्रति व्यक्ति प्रति घंटा श्रम की उत्पादकता, और,
३. प्रति इकाई उत्पादन लागत। लागत जितनी कम होगी, कार्यक्षमता उतनी ही अधिक समझी जायगी।

साधारणतः "लाभ उपार्जन शक्ति" और प्रति इकाई उत्पादन लागत को कार्यक्षमता मापने का आधार माना जाता है। इसमें भी उत्पादन लागत को तुलनात्मक दृष्टि से अधिक सन्तोषजनक और विश्वस्त आधार माना जाता है।

कार्यक्षमता के विषय में एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि कार्यक्षमता को दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देखना होगा, अर्थात्, उत्पादन के क्षेत्र में कार्यक्षमता और विक्रय के क्षेत्र में कार्यक्षमता। यह हो सकता है कि एक इकाई कुछ विशेष कारणों या सुविधाओं से उत्पादन के क्षेत्र में कार्यक्षमता से कार्य कर सके, परन्तु कुछ और कारणवश विक्रय के क्षेत्र में अकार्यक्षम सिद्ध हो। दूसरी इकाई कुछ कारणवश उत्पादन के क्षेत्र में अकार्यक्षम होते हुये भी विक्रय के क्षेत्र में कार्यक्षम समझी जा सकती है। पहली दशा में यह होता है कि सामाजिक नीति के कारण वस्तुओं को एक प्रकार से कम मूल्य पर बेचा जाता है। दूसरी दशा में उत्पादन के क्षेत्र में अकार्यक्षम होने पर भी एकाधिकार जैसी परिस्थितियों के कारण औद्योगिक इकाई को उस वस्तु की बिक्री द्वारा पर्याप्त लाभ प्राप्त हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों के अनेक कारण हो सकते हैं।

किसी औद्योगिक इकाई की कार्यक्षमता को प्रति इकाई उत्पादन लागत की दृष्टि से देखने के साथ-साथ एक और दृष्टि से भी उसकी कार्यक्षमता पर विचार करना होगा और वह है उत्पादित माल की किस्म की दृष्टि से देखना। इस दृष्टि से हम उसी इकाई को कार्यक्षम कह सकते हैं, जो अन्य इकाइयों की तुलना में कम से कम लागत पर उच्चतम श्रेणी के माल का उत्पादन करती है। यह हो सकता है कि सभी दशाओं में श्रेणी का निर्धारण तथा अन्य इकाइयों के माल से उसकी तुलना करना कठिन होगा, परन्तु जिन वस्तुओं के लिये भारतीय प्रमाप संस्था द्वारा प्रमाप निर्धारित कर दिये गये हैं और उसके निरीक्षकों द्वारा बराबर समय-समय पर उनकी किस्म की जांच की जाती रहती है, वहां यह कार्य कठिन नहीं है।

भारत में पूर्ण जागरूकता नहीं

ऐसी परिस्थितियों में भारतीय उत्पादकों में—जिनमें से कुछ थोड़े से उत्पादकों को छोड़कर, आज भी अधिकांश में किस्म सुधार और लागत नियन्त्रण की भावना पूर्णरूप से जागृत नहीं है—उनमें यह भावना अब इस संकटकालीन स्थिति में तो अवश्य अति शीघ्र ही पूर्णतया जागृत करनी होगी और इसके लिये प्रत्येक संभव कदम उठाना होगा। कुछ दशाओं में इस भावना को जागृत करने के लिये कुछ सीमा तक उत्पादकों को वाध्य भी करना पड़ सकता है, परन्तु राष्ट्र की सुरक्षा और आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिये ऐसा भी करना होगा। लागत को कम करने के लिये उत्पादकों द्वारा स्वयं अनेक कदम उठाये जाने चाहिये। इस सम्बन्ध में एक सुझाव यह दिया गया है कि कुछ प्रतिनिधि इकाइयों में "लागत कम करने की समितियों (Cost Reduction Committees) की स्थापना की जानी चाहिये जिनके द्वारा यह बताया जाय कि किसी वस्तु

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की लागत के विभिन्न अंगों में किस-किस क्षेत्र में और किस सीमा तक कमी की जा सकती है ताकि उसकी किस्म पर भी कुप्रभाव न पड़े। यहां इन समितियों के महत्व का अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे औद्योगिक दृष्टि से अग्रगामी देश में ऐसी समितियों को स्थापित किया जा रहा है। अतः स्पष्ट है कि हमारे उद्योगों के लिये जिनकी लागत विश्व मूल्यों से अधिक है इन समितियों की कितनी आवश्यकता है। ○ ●

सम्पदा

आर्थिक प्रश्नों पर ज्ञानवर्धक सामग्री व स्वतंत्र चिंतन की एक मात्र हिन्दी पत्रिका

१. क्या आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं और परीक्षा में सफल होना चाहते हैं ?

२. क्या आप अर्थशास्त्र के अध्यापक हैं और छात्रों को योग्य बनाना चाहते हैं ?

३. क्या आप देश के आर्थिक विकास और आर्थिक प्रश्नों में रुचि रखते हैं ?

४. क्या आप उद्योग व व्यापार की प्रगति व समस्याओं की जानकारी चाहते हैं ?

५. क्या आप पत्रों के सुशिक्षित व विचारशील पाठक हैं ?

तो सम्पदा पर विस्तृत सम्मति पत्र पढ़िये, इसमें आप पढ़ेंगे

—कि छात्रों को सम्पदा ने कैसी सहायता दी ?

—कि विद्वान प्राध्यापकों व शिक्षाविदों के क्या विचार हैं।

—कि केन्द्र व राज्यों के मंत्री 'सम्पदा' के सम्बन्ध में कितनी ऊंची सम्मति रखते हैं ?

—कि प्रमुख उद्योगपति सम्पदा के संबंध में क्या कहते हैं।

और फिर आप सम्पदा मंगाये बिना न रहेंगे।

यह सम्मति-पत्र मंगाने के लिए सिर्फ एक कार्ड लिख कर भेजिये

मूल्य ८.५० रु० वार्षिक

सम्पदा २८।११, शक्तिनगर, दिल्ली—६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विदेशी मुद्रा के साधन कृषि-पदार्थ

डा० जे० एस० पटेल कृषि कमिश्नर, भारत सरकार

भारत के आर्थिक विकास के लिए विदेशी मुद्रा बहुत जरूरी है। भारत को प्रति वर्ष जितनी विदेशी मुद्रा की आमदनी होती है, उसकी लगभग आधी कृषि पदार्थों से प्राप्त होती है। फिर भी दुःख की बात है कि पिछले लगभग दस वर्षों से भारत का निर्यात व्यापार कुछ मंद पड़ गया है। देश के आर्थिक विकास के कारण देश में विभिन्न वस्तुओं की मांग इतनी बढ़ गई है कि उसे पूरी करने के बाद विदेशों को भेजने के लिए उनकी कम मात्रा बचती है। इस कारण जहां संसार का निर्यात-व्यापार बढ़कर लगभग दूना हो गया है, वहां सन् १९६० में भारत का भाग उसमें केवल १.१ प्रतिशत ही रह गया जो सन् १९५० में २.१ प्रतिशत था।

भारत से विदेशों को भेजी जाने वाली उन वस्तुओं की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ जो प्रत्यक्ष रूप से कृषि उत्पादन पर आधारित हैं और देश के निर्यात-व्यापार में जिनका बहुत बड़ा भाग होता है। ऐसी वस्तुओं में चाय, सूती वस्त्र, पटसन की चीजें, तम्बाकू आदि प्रमुख हैं। परन्तु कच्चा लोहा जैसी कुछ नयी चीजों के निर्यात में कुछ वृद्धि हुई है। सन् १९६२-६३ में लगभग ६३३ करोड़ रुपये के मूल्य की कृषि वस्तुएं निर्यात की गईं। भारत से निर्यात की जाने वाली कृषि वस्तुओं के मूल्य की जो सारणी यहां नीचे दी गयी हैं उससे मालूम होता है कि हमारा निर्यात-व्यापार अभी काफी बढ़ सकता है।

भारत से निर्यात की जानेवाली महत्वपूर्ण कृषि वस्तुओं का निर्यात मूल्य (१९६२-६३)

वस्तु	मूल्य (करोड़ रुपये)
१—चाय	१२९.१८
२—चीनी और चीनी से बनी हुई वस्तुएं	१८.०३
३—तम्बाकू (कच्ची)	१८.००
४—काजू	१९.३६
५—कपास	१७.०७
६—जूट से बनी चीजें	१५३.७२
७—मसाले	१३.८६
८—काफी	७.६१

भारत का निर्यात-व्यापार बढ़ाने की तह में हमारा यह विचार कभी भी नहीं रहा कि हम उन वस्तुओं के घरेलू इस्तेमाल को आंशिक रूप से या बिल्कुल बन्द कर दें जिनकी विदेशों में मांग है। हमारा उद्देश्य तो यह होना चाहिए कि भारत से निर्यात की जानेवाली चीजें ऐसी हों जो विदेशी खरीददारों को सन्तुष्ट कर सकें। इसके लिए हमें विशेष वैज्ञानिक तरीके अपनाकर बढ़िया चुनी हुई चीजें पैदा करनी चाहिए और उनको संवारने और सुधारने के लिए भी पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। उनकी कीमत ऐसी रखनी चाहिए कि वे विदेशी बाजारों में दूसरे देश से आनेवाली चीजों का मुकाबला कर सकें।

तम्बाकू व काजू

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तम्बाकू के लिए भारत को केवल दो देशों का मुकाबला करना पड़ता है। ये देश संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन हैं। भारत में इस समय तम्बाकू की वे किस्में अधिकता से उगाई जाती हैं, जिनकी देश में मांग है। यदि ऐसी किस्मों का कुछ क्षेत्रफल घटाकर उनकी जगह निर्यात करने योग्य बढ़िया किस्में उगाई जाएं तो भारत अपना तम्बाकू का निर्यात-व्यापार बढ़ा सकता है।

उदाहरण के लिए पश्चिमी जर्मनी मुख्यतः ऐसी बर्जिनिया तम्बाकू चाहता है, जो स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह पकी हुई हो और पतली और खुले दानों वाली हो तथा जिसमें निकोटीन की मात्रा कम हो। परीक्षणों से मालूम हुआ है कि हम कुछ विशेष कृषि विधियों को अपना कर ऐसी तम्बाकू सफलता से उगा सकते हैं। हमें इसकी क्वालिटी को बनाये रखने के लिए पूरा ध्यान देना चाहिए और इसकी कीमत भी ऐसी निश्चित करनी चाहिए कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन की तम्बाकू की कीमत के मुकाबले में अधिक न हो।

मसालों की जांच समिति की सिफारिशों के आधार

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पर भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में काजू का विकास करने के लिए ध्यान देना शुरू किया है। काजू विदेशी मुद्रा कमाने वाली महत्वपूर्ण वस्तु है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में मद्रास, केरल, आंध्र प्रदेश, असम, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा नामक राज्यों में १.८० लाख एकड़ नयी भूमि में काजू के पेड़ लगाने का लक्ष्यांक निश्चित किया गया था और इस कार्य पर १.७० करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गयी थी। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप लगभग २.४० लाख एकड़ भूमि में काजू के पेड़ लगाये गये। तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी विभिन्न राज्यों में लगभग ८ लाख एकड़ नयी भूमि में काजू के पेड़ लगाने का लक्ष्यांक स्वीकृत किया गया है।

काजू के लिये नये बाजार खोजने और बनाने के लिए प्रयत्न जारी रखना जरूरी है। इस सम्बन्ध में अब तक जो प्रयत्न किये गये हैं, उनमें काफी सफलता मिली है और उनके फलस्वरूप भारत के काजुओं की मांग रूस और दूसरे पूर्वी यूरोपीय देशों में भी होने लगी है। काजू की पैदावार बढ़ाने से संबन्धित किसी भी कार्यक्रम के लिए काजू की खेती में किसानों की रुचि बढ़ाना भी अति आवश्यक है। इस सम्बन्ध में सुसंगठित सहकारी बाजार समितियां अच्छा काम कर सकती हैं। ये समितियां किसानों के घर से पैदावार एकत्र कर सकती हैं।

अखरोट देश के जम्मू-काश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों की पर्वतीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। अनुमान लगाया गया है कि इन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष ११००० से १४००० टन तक अखरोट पैदा होता है। भारतीय अखरोट घटिया किस्म के समझे जाते हैं और विदेशों में इनकी कीमत कम मिलती है। यदि अखरोटों को निर्यात करने से पहले अच्छी तरह साफ करके छांटकर तैयार कर लिया जाए तो उनकी अच्छी कीमत मिल सकती है। पूर्वी और मध्य यूरोपीय देशों में अखरोट के नये बाजार तैयार करने की ओर भी अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

नये बाजार

हमारी कृषि सम्बन्धी वस्तुओं का निर्यात-व्यापार, अधिकांशः कुछ विशेष देशों के साथ है जैसे हमारी चीनी, काजू और काली मिर्च का मुख्य बाजार संयुक्त राज्य अमेरिका है और हमारी तम्बाकू और खलियों का मुख्य खरीददार ब्रिटेन है। यदि प्रचार की उचित व्यवस्था की जाय तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी कृषि वस्तुओं के लिए संसार के अन्य देशों में भी बाजार बन सकते हैं।

कुछ ऐसी नयी फसलें भी हैं जिन्हें हम केवल निर्यात के लिए उगा सकते हैं। रैमी, सिसल और सन की पैदावार दूसरे देशों में सुगमता से बेची जा सकती है। इसी प्रकार और भी अनेक ऐसी चीजें हैं, जो किसी कारण से आजकल हमारे यहां नहीं उगायी जा रही हैं। उन्हें उगाकर हम अपना निर्यात-व्यापार बढ़ा सकते हैं।

नई फसलें

यहां पर हमने अब तक विदेशी मुद्रा कमाने वाली व्यावसायिक फसलों का ही उल्लेख किया है। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हम नहीं उगाते और अपनी जरूरत पूरी करने के लिए उन्हें हम बाहर से मंगाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि बड़ी मेहनत से कमाई हुई बहुत-सी विदेशी मुद्रा हमें इन वस्तुओं के आयात पर खर्च करनी पड़ती है। इसलिए कोशिश यह होनी चाहिए कि हम केवल उन फसलों का ही उत्पादन बढ़ाने की कोशिश तो करें जिनकी हमारे यहां कमी रहती है। इसके साथ ही हम अपनी जरूरत की उन फसलों को भी उगाएं जो इस समय हमारे यहां नहीं उगायी जा रही हैं। खाद्यान्न, कपास, सुपारी, काजू आदि कुछ ऐसी चीजें हैं, जो हमारे यहां पैदा तो होती हैं परन्तु उनसे हमारी अपनी ही मांग पूरी नहीं हो पाती। इनकी पैदादार बढ़ाने की जरूरत है। लौंग, दालचीनी, अनेक गंधवान तेल और कोको आदि कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनकी हमें जरूरत होती है परन्तु हम उन्हें अपने यहां नहीं पैदा कर रहे हैं।

संसार के अधिकांश देशों में राष्ट्रीय आय-का एक बड़ा भाग कृषि वस्तुओं के निर्यात से ही प्राप्त होता है। भारत विदेशी मुद्रा के लिए अधिकांशः कृषि वस्तुओं के निर्यात पर निर्भर है। यह बात भारत की अर्थ व्यवस्था के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। भारत की समृद्धि, अधिकांशः कृषि पर ही निर्भर है। अतः हमारी सभी विकास योजनाएं कृषि की प्रगति और विस्तार पर ही बल देती हैं। इस

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विकासशील आफ्रिका

प्रो० पूरनचन्द रावत, सेक्सरिया कामर्स कालेज, जबलपुर

बीसवीं सदी की, जो कि शायद सबसे अधिक उथल-पुथल का युग कहा जा सकता है, सबसे बड़ी देन आर्थिक एकीकरण है। दुनियां के महानतम शत्रु फ्रांस और जर्मनी ने जो मिसाल सामने रखी है, उसे आर्थिक जगत सदा स्मरण करेगा। आज राजनीति और अर्थनीति दोनों एक रथ के दो पहियों की भांति हैं इससे कोई इन्कार न करेगा। भूखे पेट राजनीति की भक्ति अधिक चलने वाली नहीं है। जो बात औद्योगिक सम्राटों के लिए लागू होती है, वही विकासोन्मुख देशों के लिए भी। वे जमाने लद गए जब साम्राज्यवादी शक्तियां स्वतन्त्रता की सांस लेने-देने में अपनी दम घुटने की बात अनुभव करती थीं। आज तो सबको स्वतन्त्रता और न्याय से जीने का अधिकार है। राष्ट्र स्वयं इतना विकास करें कि उन्हें परमुखापेक्षी न रहकर अपने बल का गर्व अनुभव हो। इसी से अनुप्राणित हो दुनियां से गुलामी की जंजीरें टूट रही हैं और नवोदित स्वतन्त्र राष्ट्र इस अटल सत्य में श्रद्धा रखने लगे हैं। आफ्रिका देशों में जो स्वतन्त्रता की लहर चली वह इसी की प्रतिक्रिया है।

समृद्ध, अफ्रिका

अभी तक आफ्रिका को अंधेरे का महाद्वीप (Dark continent)) की संज्ञा दी जाती थी। या यूं कहिए कि दिलाई जाती थी जिससे कुछ वर्ग विशेष का हित साधन और स्वार्थ सिद्धि हो। भारत की तरह उसे भी लकड़हारा और पानी भरने वाला (Hewers of wood and drawers of water) कहा जाता रहा। लेकिन अब वह अंधेरे का द्वीप न होकर प्रकाश का पुंज हो गया है। इसका क्षेत्रफल अमेरिका, पश्चिमी योरोप, भारत और चीन के संयुक्त क्षेत्रफल से भी विशाल है। अटलांटिक महासागर, हिन्दमहासागर, लालसागर और भूमध्यसागर इसके चरण धोते हैं। विश्व का ९८ प्रतिशत हीरा, ५५ प्रतिशत सोना, २२ प्रतिशत तांबा और अन्य महत्त्वपूर्ण धातुएं जैसे क्रोमियम, मैंगनीज, यूरेनियन आदि इसके विशाल आंचल में विद्यमान हैं। विशाल जल साधनों सहित विश्व का २।३ भाग कोको, और ३।५ भाग ताड़ का तेल यहीं उपलब्ध है। इतने बड़े सम्पन्न देश की ओर विश्व ने उपेक्षा से देखा है। "इन साइड आफ्रिका" नामक पुस्तक में एक स्थान पर लिखा है—

"Africa is not a dark continent at all. It is flashing with viurid light. It is a ktnd of living laboratory, a paradise for the political scientist, anthropologist as well as the businessman.

साधनों की प्रचुरता की दृष्टि से यह भावी विकास की संभावनाओं का केन्द्र है। व्यापारियों के लिये तो यह धन का भंडार ही है। "इकानामिक कमीशन फ़ार आफ्रिका" ने एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पुस्तक "इंडस्ट्रियल प्रोथ इन आफ्रिका" प्रकाशित की है। इसमें आफ्रिका के आर्थिक विकास की संभावनाओं पर वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इस महाद्वीप का जिसकी जनसंख्या संसार [illegible] प्रतिशत है, वर्तमान उत्पादन क्षमता केवल विश्व [illegible] तिशत ही है। स्पष्ट है कि उत्पादन स्तर अत्यन्त [illegible]। औद्योगिक दृष्टि से देखा जाय तो पता चलता है कि ब्रिटेन की वार्षिक आय का केवल आधा हिस्सा ही यहां प्राप्त होता है। प्रति व्यक्ति आय करीब १०० डालर आंकी गई है।

इसी प्रकार विश्व खनिजों का सातवां हिस्सा यहां होता है। औद्योगिक देशों में प्रति व्यक्ति जितनी खेती

सम्पदा

अतः हमारा कर्त्तव्य है कि हम हर तरह से कृषि-वस्तुओं का निर्यात-व्यापार बढ़ाने के लिए उनका उत्पादन बढ़ाय और देश में उनको कम से कम मात्रा में इस्तेमाल करें। आज सारे संसार में एक ही भावना प्रधान है। "निर्यात बढ़ाओ, नहीं तो नष्ट हो जाओगे।" फिर हम ही इससे अछूते कैसे रह सकते हैं। ● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

योग्य भूमि है उसकी तिगुनी यहां प्राप्त है। वैदेशिक व्यापार भी तुलना में कम है। वार्षिक निर्यात ६६०० मिलियन डालर है और आयात ८००० मिलियन डालर। अपने विकास हेतु उसे बहुत सा माल विदेशों से आयात करना पड़ता है। अधिकांश देश कृषि प्रधान है और इस कारण राष्ट्रीय आय का ४० प्रतिशत खेती से प्राप्त होता है। देश में अनेक छोटे उद्योग अवस्थित हैं।

उपर्युक्त परिचय देने का उद्देश्य केवल यह बतलाना है कि आफ्रिका में साधनों की प्रचुरता है लेकिन साज का अभाव है। देश में कोई एक योजना नहीं है जिससे साधनों का समुचित सदुपयोग सम्भव हो सके। जो देश अभी स्वतन्त्र हुए हैं वे भी दो गुटों में बंटे हुए हैं। एक कासाब्लेंका ग्रुप और दूसरा मनरोविया गुट। कसाब्लेंका गुट में घाना, माली, ग्वाइना, मोरक्को, अल्जीरिया और संयुक्त अरब गणराज्य हैं और दूसरे में शेष स्वतन्त्र राष्ट्र। आपस के मामूली झगड़े और विचार भेद इन्हें एक दूसरे से नहीं मिला पाते और परिणामस्वरूप आफ्रिका की एकता स्थापित नहीं हो पाती।

अभी कुछ दिन पूर्व अडिस अबाबा में अफ्रिका देशों का एक शीर्ष सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें मोरक्को और टोगोलैंड उपस्थित नहीं थे। इस सम्मेलन के ३ महत्त्वपूर्ण उद्देश्य थे :—

(१) साम्राज्यवाद के विरुद्ध मोर्चा कड़ा करना।

(२) महाद्वीप की आर्थिक प्रगति हेतु विचार करना।

(३) अफ्रिकन राष्ट्रों की एकता बनाना।

घाना के प्रेसीडेंट नक्रमा ने तो एक महाद्वीपीय संसद बनाने का सुझाव रखा था, जिसमें दो विभाग होंगे। निम्न स्तर पर जनता से चुने हुए प्रतिनिधियों का और उच्च स्तर पर प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों का महाद्वीपीय सरकार को सार्वजनिक मुद्रा चलाने और केन्द्रीय बैंक स्थापना का अधिकार होगा। श्री नक्रमा के अनुसार आफ्रिका संघ के उद्देश्य निम्नलिखित होने चाहिए :

(१) समान वैदेशिक नीति।

(२) समान मिलिटरी और प्रतिरक्षा व्यवस्था।

(३) आर्थिक नियोजन।

उपर्युक्त प्रस्ताव इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि आफ्रिकी देश पर्याप्त जागरूक हो गये हैं और अपना चतुर्मुखी विकास करना चाहते हैं। विभिन्न देशों के प्रस्ताव इस ओर प्रारम्भिक कार्यवाही ही कहे जा सकते हैं। केवल क्षुद्र स्वार्थ त्याग से आफ्रिका का विशाल आंचल एक हो सकता है। क्षेत्रीय नियोजन (Regional Planning) अपना महत्त्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि आफ्रिका की कृषि को यूरोपीय स्तर तक आने के लिए दुगनी उत्पादकता बढ़ानी चाहिए, जबकि औद्योगिकरण स्तर तक आने के लिए २५ गुनी शक्ति। यह तभी सम्भव है जब क्षेत्रीय योजनाएं लागू हों और उनमें आपसी तालमेल रखा जाय। इस हेतु श्री नक्रमा का अफ्रिकन डेवलपमेंट बैंक स्थापित करने का सुझाव बड़ा सामयिक है।

यह निर्विवाद है कि यदि तमाम दुनिया के काले लोग जागृत हो जाय तो गोरों को दांतों चने चबवा सकते हैं। प्रश्न केवल अवसर की समानता और विकास की गति प्रदान करने मात्र का है। आफ्रिका के नवोदित राष्ट्र इस बात को समझने लगे हैं। यहां तक कि "आफ्रिकन कामन मार्केट बनाने तक की बातें सामने आ रही हैं। लोगों की जागृति प्रगति का पहला सोपान रही है। आफ्रिका विशाल साधन सम्पन्न प्रयोगशाला है। गुटबन्दी, स्वार्थ, आपसी मतभेद भाषा भेद आदि समस्याएं दूर कर, आफ्रिका को एक वैभव सम्पन्न राष्ट्र बनाया जा सकता है और तमाम राष्ट्रों से आर्थिक सहयोग बढ़ाकर न केवल अफ्रिकी लोगों का स्तर उठाया जा सकता है वरन् विश्व-विकास की ओर भी महत्त्वपूर्ण कदम बढ़ सकता है। ● ●

विज्ञापन के लिए

सम्पदा

सर्वोत्तम

साधन है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली में सहकारिता आंदोलन की प्रगति

श्री एल० सी० जैन

सहकारी समितियों तथा सदस्यों की संख्या और उनकी पूंजी यदि आन्दोलन की प्रगति का माप दंड है तो दिल्ली सहकारी आन्दोलन को शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण कहा जा सकता है। किन्तु वस्तु स्थिति इससे भिन्न है। केवल सदस्य संख्या और पूंजी से हम प्रगति को नहीं आंक सकते। देखना यह है कि सहकारी समितियां, किसान को, मजदूर को, पिछड़े वर्ग को, उपभोक्ता को या अपने सदस्यों को किस प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रही हैं। क्या गांव में बहु-उद्देश्यीय समिति की सेवाओं से किसान को उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिली है? क्या समूचे गांव का उत्पादन बढ़ा है? या नगर में उपभोक्ता सहकारी भंडार कीमतों के बढ़ने और मिलावट को रोकने में कामयाब हुए हैं? इस कसौटी पर देखने से आन्दोलन की आन्तरिक शक्ति और उसका वास्तविक रूप दृष्टिगोचर हो सकेगा। दिल्ली क्षेत्र में इस समय लगभग २२०० भिन्न प्रकार की सहकारी समितियां हैं, जिनके २ लाख से अधिक सदस्य हैं, अर्थात् लगभग ४० प्रतिशत आबादी सहकारी क्षेत्र से सम्बन्धित है। सहकारी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार ३० जून १९६३ को २०१९ सहकारी संस्थाएं थीं और इनका सरकारी व्यवस्था के अनुसार वर्गीकरण निम्न प्रकार था—

क	६७
ख	१३८
ग	९५१
घ	५७०
बिना वर्ग की	३९३
	२०१९

इस वर्गीकरण के अनुसार केवल क और ख समितियां जिनकी संख्या २०५ होती है, सफलता पूर्वक सेवाएं प्रदान कर रही हैं और इनमें भी अधिकता ऋणदात्री समितियों की होगी। यह कहना कि दिल्ली प्रशासन और दिल्ली सहकारी विभाग इस दुर्बलता से परिचित नहीं, अनुचित होगा, क्योंकि पिछले दो वर्षों में सहकारी विभाग ने निकम्मी समितियों को समाप्त करने और दुर्बल समितियों को पुनः सशक्त बनाने का उल्लेखनीय कार्य किया है। विभाग ने कई समितियों के रजिस्ट्रेशन में भी सख्ती शुरू कर दी है और निकम्मी समितियों को तेजी से बंद किया जा रहा है। पिछले वर्ष १४२ नयी समितियां बनाई गयीं। इसी बीच कार्य-वाहक पूंजी ९९० लाख रु० से बढ़कर १३२१ लाख रु० हो गई। निदेशन शिक्षा तथा आडिट कार्यों को भी सुदृढ़ किया जा रहा है।

> दिल्ली राज्य में सहकारी आन्दोलन क्यों सफल नहीं हो सकता है, ऋण देने के अतिरिक्त इन समितियों की प्रवृत्तियां बहुत सीमित हैं, नगर में उपभोक्ता भंडार सर्वथा अपर्याप्त हैं—इन सब समस्याओं का विश्लेषण लेख में पढ़िये—

उपभोक्ता क्षेत्र

विश्व सहकारी आन्दोलन में उपभोक्ता सहकारी भंडारों का विशेष महत्व है। सहकारिता का जन्म ही उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिये हुआ था। दुर्भाग्यवश दिल्ली नगर में उपभोक्ता सहकारी समितियां ही सबसे अधिक दुर्बल, हीन और निरर्थक हैं। बढ़ती हुई कीमतों और मिलावट की भूमिका में यह समितियां उल्लेखनीय सेवा कर सकती हैं, जो नहीं हो रही है। संकटकालीन स्थिति घोषित होने के पश्चात् केन्द्रीय प्रशासित योजना के अन्तर्गत गत वर्ष ५२ नये सहकारी भंडार खोले गये हैं और २२ को पुर्नजीवित किया गया है। प्रत्येक भंडार की सदस्य संख्या १०० से अधिक है। एक थोक सहकारी संघ भी संगठित किया गया है। सरकार पूंजी और कार्यवाहक निधि में उचित सहयोग दे रही है, किन्तु फिर भी कीमतों, मिलावट और बाजार की पद्धति पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। वितरण स्तर पर, कहां तक मूल्यों में वृद्धि और मिलावट होती है, यह एक अन्वेषण का विषय है। प्रकट यह होता है कि छोटे छोटे उपभोक्ता भंडारों को वितरण स्तर पर प्रतियोगिता में ठहरना कठिन हो जायगा। सदस्य उपभोक्ताओं का सक्रिय सहयोग न होगा, पूंजी, साधन, अनुभव तथा कुशल व ईमानदार कर्मचारियों की कमी इत्यादि अनेक समस्यायें हैं, जिनका हल ढूंढना होगा। पिछले महायुद्ध और नियंत्रण के समय काफी सहकारी

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भंडार खोले गये थे, जिनके अवशेष असफलता की कहानी कह रहे हैं। उपभोक्ता सहकारी भंडार संकटकालीन स्थिति के उपरान्त भी स्वतन्त्र मंडी पर अंकुश बनाये रखकर सरकारी छत्र-छाया के बिना उपभोक्ता की सेवा करते हैं। क्या इससे लक्ष्य पूरा हो सकेगा ?

पिछड़े वर्ग की सेवा

सहकारी आयोजन का दूसरा प्रमुख उद्देश्य पिछड़े शक्तिहीन वर्ग को संगठित कर उसका जीवन-स्तर ऊंचा करने में सहायता प्रदान करना है। इसकी विवेचना करने पर भी यह प्रकट होता है कि दिल्ली क्षेत्र में हमारे प्रयत्न सफल नहीं रहे। दिल्ली में खेती-योग्य भूमि बहुत सीमित है, अतएव गरीब जनता को छोटे उद्योग धन्धों द्वारा रोजगार मुहय्या करना मुख्य काम है। इसके लिए औद्योगिक सहकारी समितियां संगठित की जाती हैं। दिल्ली में इस समय लगभग ४०० औद्योगिक सहकारी संस्थाएं हैं, जिनकी सदस्य संख्या १०००० है। कुल समितियां मिला कर ८५ लाख रु० का माल बेचती हैं और ११ लाख रुपया वेतनों में देती है। बहुत सी संस्थाओं में केवल एक या दो व्यक्ति काम करते हैं। इनके सामने सबसे बड़ी समस्या कार्यवाहक पूंजी तथा माल को बेचने की है। इंडियन-कोआपरेटिव-यूनियन तथा दूसरे दो एम्पोरियम हाथ करघे के वस्त्र तथा हाथ की बनी वस्तुओं को आधुनिक ढंग से बेचते हैं अतएव हाथकरघा और हाथ-उद्योग समितियों को कुछ काम मिल जाता है। सरकार की ओर से ३॥ प्रतिशत ब्याज पर इन समितियों के लिये ऋण की व्यवस्था की गई है। तकनीकी सहायता भी पहुँचाई जा रही है, किन्तु फिर भी अच्छा कार्य करने वाली समितियां बहुत कम हैं। "रिजर्व बैंक" की 'गारंटी स्कीम' भी चालू की गई है। उच्च स्तर का माल न बना पाने और बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता—यह दोनों इनकी भीषण समस्याएं हैं।

श्रम सहकारी समितियां

दिल्ली में श्रम सहकारी समितियों के लिये विशाल क्षेत्र पड़ा है। लगभग १ लाख व्यक्ति ठेकेदारों के पास मजदूरी करते हैं इनका बहुत शोषण होता है, किन्तु एक दर्जन से भी कम समितियां कार्य कर रही हैं। पिछले कुछ दिनों से विभाग ने इस ओर ध्यान दिया है। कुछ समाज-सेवी संस्थाएं भी प्रोत्साहन दे रही हैं। सड़क के किनारे, गन्दी बस्तियों में बिना पानी बिजली के झुग्गी-झौंपड़ियों में रहने वाले लाखों व्यक्तियों को सहकारी-संगठन में पनाह मिल सकती है। केवल सरकारी कर्मचारियों और प्रशासन के सतर्क होने की आवश्यकता है।

ऋण-दात्री संस्थाएं

ऋण देने वाली समितियां नगर तथा देहाती क्षेत्र दोनों ही जगह सफलता से काम कर रही हैं। देखा जाय तो सहकारी आंदोलन की प्रगति के आंकड़े इन्हीं पर बनते हैं। देहात में बहु-उद्देश्यीय समितियां अधिकतर कर्ज देने का काम ही करती हैं, इनकी दूसरी सेवाएं तो बहुत सीमित हैं। बजट में सरकारी कर्मचारियों तथा बड़े प्राइवेट संस्थानों की ऋण समितियां बहुत अच्छी चल रही हैं। दिल्ली स्टेट कोआपरेटिव बैंक का काफी रुपया इस क्षेत्र में लगा है। कुछ समितियों को छोड़कर अधिकतर सोसायटियों में सदस्यों की अपनी बचत का अनुपात सन्तोषजनक नहीं है। दूसरे, ऋण अधिकतर उत्पादन कार्यों के लिये नहीं दिये जाते, वरन व्यक्तिगत कार्यों पर लगा दिये जाते हैं। नगर में बढ़ती हुई चिट-फंड कम्पनियों और उनकी अनियमित कार्यवाही देखते हुए ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना शेष है। ऋण सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों को बचत करने के लिये उचित प्रेरणा दी जानी चाहिये, अन्यथा ऋण के झंझट से वह कभी मुक्ति नहीं पा सकेंगी। शहर में लगभग ६०० ऋण सहकारी समितियां हैं, जिनकी सदस्य संख्या ९० हजार के करीब है और वह २५० लाख रुपया कर्ज देती हैं। देहात में ३६० समितियां हैं, जिनके २५००० सदस्य हैं और वह ३५ लाख रुपया कर्ज देती हैं।

विभिन्न

इसके अलावा परिवहन, सहकारी खेती, भवन-निर्माण, बाजार-हाट, भट्टे, शिल्प इत्यादि बहुत तरह की समितियां हैं, जिनका विस्तार पूर्वक उल्लेख करना कठिन है। सहकारी आंदोलन में जीवन आता है, सदस्यों के सक्रिय सहयोग और उनके विश्वास से। इसके लिये दिल्ली की सहकारी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यह लखनऊ है !

(सम्पन्नता व दरिद्रता की नगरी)

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनक है। जो देखता है उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। शानदार शहर, शानदार असेम्बली, शानदार कौंसिल, शानदार यूनिवर्सिटी ! पुराना नवाबी विलास-वैभव लखनऊ की गली-गली में बिखरा पड़ा है। फैशन, व्यसन, नजाकत, विनोद, मनोरंजन सबकी अनोखी बहार इस शहर में दीख पड़ती है। यह है लखनऊ का बाह्य रूप।

लेकिन लखनऊ का आन्तरिक रूप दूसरा ही है। हाल में प्लानिंग कमीशन (योजना आयोग) की तरफ से, और लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से लखनऊ के निवासियों की जो सर्वे हुई, वह किसी की भी आंखें खोल देने के लिए पर्याप्त है।

सर्वे से पता चलता है कि :

लखनऊ के ५० प्रतिशत से अधिक निवासी ऋण-ग्रस्त हैं।

कर्ज की यह मात्रा किसी परिवार पर ४५) है तो किसी पर ७००० रु०।

२.५ प्रतिशत परिवारों पर ५० रु० से कम कर्ज है।

३८ प्रतिशत लोगों पर १०० रु० या उससे अधिक कर्ज है।

६ प्रतिशत परिवारों पर ५०० रु० से अधिक कर्ज है।

१००० में से ४८८ परिवारों पर कुल ८५००० रु० कर्ज है। ५० प्रतिशत कर्ज पुराने साहूकारों और महाजनों से लिया जाता है।

३७ प्रतिशत कर्ज मित्रों और रिश्तेदारों से लिया जाता है।

७ प्रतिशत कर्ज सहकारी समितियों या व्यापारी बैंकों से लिया जाता है।

ब्याज की दर प्रति रुपये पर प्रतिमाह एक पैसा से लेकर एक आना तक रहती है। अर्थात् सालाना १८॥ रु० से ७५ रु० प्रतिशत !

जिनके पास जमानत के साधन नहीं हैं, या जो थोड़े समय के लिए कर्ज लेते हैं, उन्हें अधिक ब्याज देना पड़ता है।

मतलब यह कि लखनऊ के निवासी कर्ज के फंदे में बुरी तरह फंसे हैं।

इतना ही नहीं, सर्वे से यह भी पता चलता है कि लखनऊ में १०० में ११ आदमी ऐसे हैं, जिनके पास न तो अपना मकान है, न भाड़े का। वे या तो मित्रों या सम्बन्धियों के साथ रहते हैं, या बंगलों में नौकरों के कमरे में पड़े रहते हैं।

लखनऊ में केवल ४० प्रतिशत लोगों के पास अपने मकान हैं। शेष लोग भाड़े के मकानों में रहते हैं।

सौ में ४ आदमी ऐसे हैं, जिनका जमीन ही बिस्तर है और आसमान ही चादर। सड़क की पटरियों पर, फुटपाथों पर ही पड़े रहकर रात काट देते हैं।

लखनऊ में कुल ४१ हजार मकान हैं। इनमें ७२७५ मकान पुराने हैं, खण्डहर हैं, रहने के लायक ही नहीं हैं।

१० प्रतिशत परिवार प्रतिमास २० रु० या उससे अधिक भाड़ा देते हैं। शेष लोग २० रु० से कम भाड़ा देते हैं।

१५ प्रतिशत परिवार केवल एक कमरे के भीतर रहकर गुजर करते हैं। ११ प्रतिशत लोगों के पास ४ या ४ से अधिक कमरे हैं।

२७ प्रतिशत परिवार ऐसे मकानों में रहते हैं जहां न संडास हैं, न स्नान घर : न रसोई-घर है और न भण्डार घर।

हर मकान में औसतन २.२७ परिवार रहते हैं या १२ आदमी। किसी मुहल्ले में प्रति एकड़ में ११० व्यक्ति रहते हैं, किसी में ४०० व्यक्ति।

शहर के ५१६ मुहल्लों में केवल १४ प्रतिशत मुहल्ले ऐसे हैं, जहां बिजली की बत्ती जलती है। ३० प्रतिशत

सम्पदा

संस्था द्वारा शिक्षा और प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। सरकार इस कार्य में भी उचित आर्थिक सहयोग दे रही है। ×

× यह लेख "दिल्ली विकास अंक" के लिए आया था। देर से प्राप्त होने पर विशेषांक में प्रकाशित नहीं हो सका।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मुहल्लों में मिट्टी के तेल की ढिबरी जलती है। शेष अंधेरे में रहते हैं।

एक ओर ट्यूब लाइट की जगमगाहट और दूसरी ओर मिट्टी के तेल की ढिबरी भी नहीं! एक ओर सम्पन्नता दूसरी ओर गरीबी। एक ओर वैभव का विलास, दूसरी ओर कर्ज, गरीबी और अभावों का चीत्कार!

(भूदान यज्ञ से)

श्री अशोक मेहता योजना आयोग में

अब यह प्रायः निश्चित हो गया है कि प्रजा समाजवादी दल के नेता श्री अशोक मेहता योजना आयोग के उपाध्यक्ष बनाये जावेंगे। यह पद ग्रहण करते ही वे प्रजासमाजवादी दल से त्यागपत्र दे देंगे। उनके आने से आयोग में मंत्रि-सदस्यों का अनुपात और भी कम हो जायगा।

इससे पहले वे करघावस्त्र उद्योग समिति के भी सदस्य रह चुके हैं।

★

बोकारो-संयंत्र में रूस की रुचि

जब से अमेरिका बोकारो के इस्पात कारखाने के निर्माण में टाल-मटोल करने लगा है, रूस उसके निर्माण में अधिक रुचि लेने लगा है और अब तो उसकी रुचि बहुत स्पष्ट हो गई है।

सपना

सच्चा हुआ

नन्हे बच्चों के सपने बड़े ही मधुर होते हैं - मिठाइयों, बिस्कुटों आदि से भरे हुए!
उनके सपनों की ऐसी ही प्यारी चीजों में से हैं...स्वादिष्ट व पौष्टिक
साठे मार्टेक्स बिस्कुट
जिन्हें खाकर उनका सपना सच्चा हो जाता है।

साठे बिस्कुट
रोटियों के लिए रुचि!

साठे बिस्कुट एण्ड चॉकलेट कंपनी लिमिटेड, पूना - २

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उत्पादकता आंदोलन : तीन मुख्य स्तम्भ

श्री एम० एफ० हाश्मी, महारानी लक्ष्मीबाई कालेज, ग्वालियर

देश में हो रही आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने तथा जनता के जीवनस्तर को ऊंचा करने के लिये – उत्पादकता बढ़ाने की परम आवश्यकता को अनुभव किया ही जा रहा था और इस ओर प्रयत्न भी किये जा रहे थे, परन्तु वर्तमान संकटकालीन स्थिति में इस बात की सबसे अधिक आवश्यकता है कि आर्थिक प्रयत्नों के प्रत्येक क्षेत्र में भरसक प्रयत्न किये जायें। देश की सुरक्षा व्यवस्था को अत्यन्त दृढ़ बनाने के लिये अर्थ-व्यवस्था को अधिकतम कार्यक्षमता से चलाना है। अभी तक आर्थिक विकास का एक मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना रहा है। अब हमें वर्तमान सुरक्षा-सम्बधी आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य को भी स्पष्टतः सामने रखकर कार्य करना है और इन दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उत्पादकता को बढ़ाना ही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस उत्पादकता को बढ़ाने की जिम्मेदारी तीन मुख्य वर्गों पर हैं और वे हैं—उद्योगपति, सरकार और श्रमिक।

इनमें से प्रत्येक की जिम्मेदारी और उसके कर्त्तव्य पालन पर विचार करने से पहले यह समझ लेना चाहिए कि उत्पादकता बढ़ाने के लिये अपने-अपने कर्त्तव्यों का सुचारु रूप से पालन करने के लिये प्रत्येक वर्ग को अपनी विचारधारा में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने होंगे तथा उत्पादन की नई-नई विधियों को काम में लाने के लिये तत्परता दिखलानी होगी। उत्पादकता में वृद्धि के लिये दो महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं—प्रथम का सम्बन्ध सभी वर्गों में सामान्य रूप से और उद्योगपति वर्ग से विशेष रूप से उत्पादकता की भावना को बढ़ाने तथा उत्पादकता बढ़ाने सम्बन्धी क्रियाओं की सूचनाओं को शीघ्रातिशीघ्र उद्योगपतियों में संचारित करने से है, दूसरे, का सम्बन्ध उद्योगों में लगे हुए श्रमिकों को (तथा अन्य व्यक्तियों को, जो उत्पादन क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं) प्रशिक्षण प्रदान करना तथा उत्पादकता बढ़ाने के तरीकों का व्यावहारिक प्रदर्शन देने से है। यद्यपि इस सम्बन्ध में इन दोनों बातों पर ध्यान दिया जाता रहा है और सराहनीय कार्य हुआ है, फिर भी बहुत कुछ बाकी है। यह कहना भी अनुचित न होगा कि उत्पादकता में वृद्धि की अनेक योजनाओं को व्यावहारिक रूप देने और तीव्र गति से लागू करने के लिये यह अत्यन्त अनुकूल स्थिति है और सभी वर्गों को देश के सामान्य हित एवं सुरक्षा की दृष्टि से अपने कर्त्तव्यों का सुचारू रूप से पालन करना चाहिए। इंगलैंड तक अपने उद्योगों की उत्पादकता को बढ़ाने में प्रयत्नशील है, क्योंकि वह यह अनुभव करता है कि अन्य देशों की तुलना में उत्पादकता वृद्धि में वह पीछे रह गया है। जब इंगलैंड जैसे औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देश के लिये आज उत्पादकता बढ़ाना अनिवार्य हो गया है तो स्पष्ट ही है कि हमारे लिये जबकि हमारे उद्योगों की उत्पादकता इंगलैंड की तुलना में अत्यन्त कम है, उत्पादकता में वृद्धि करना कितना जरूरी है।

तीन मुख्य स्तम्भ

भारतीय उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता एवं वर्तमान संकटकालीन स्थिति में उसकी अनिवार्यता पर विचार करने के बाद अब उन तीन मुख्य वर्गों के कर्त्तव्यों और जिम्मेदारियां पर विचार करना है, जिन्हें भारतीय उत्पादकता आन्दोलन के तीन मुख्य स्तम्भ कहा जा सकता है और वे हैं—उद्योगपति, श्रमिक और सरकार। जितने भी व्यक्तियों ने उत्पादकता का सूक्ष्म अध्ययन किया है, उनका यही विचार है कि उत्पादकता बढ़ाने में श्रमिक जो योगदान दे सकते हैं, उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता, परन्तु उद्योगपतियों को भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करना है क्योंकि श्रमिकों से काम वे या उनके प्रतिनिधि ही लेते हैं और उत्पादकता बढ़ाने के लिये उन्हें ही पहले योजनायें बनानी होंगी और अपनी नीति में श्रमिकों का सहयोग प्राप्त करना होगा।

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने में प्रबन्धकों का महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और भारत जैसे देशों में जो औद्योगिक विकास के मार्ग पर तेजी से चले जा रहे हैं, इसका महत्व और भी अधिक है। आज भारतीय उद्योग अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण का सम्बन्ध वित्त की व्यवस्था, यन्त्र और मशीनों के पुनः स्थापन, माल के लिये बाजारों की खोज, अच्छे श्रम-सम्बन्ध बनाये रखना, उत्पादकता की उच्चतम विधियों को प्रयोग में लाना तथा उत्पादित माल की प्रतिस्पर्धा शक्ति को बढ़ाने आदि से है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि उत्पादकता, प्रबन्धकों के हाथों में एक ऐसी कल है जिसके द्वारा जनता को कम लागत पर अच्छी और अधिक मात्रा में वस्तुएं और सेवायें उपलब्ध की जा सकती हैं।

उत्पादकता को बढ़ाने में प्रबन्धक कितना महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि औद्योगिक इकायइों में किसी भी प्रकार के सुधार की इच्छा को सामने रखना और आगे बढ़ाना उनका ही कर्तव्य है। इसी प्रकार से कार्य करने की आवश्यक स्वास्थ्यकर दशाओं, श्रमिकों तथा निरीक्षक करने वाले कर्मचारियों द्वारा अच्छे प्रयत्नों के लिये प्रेरणा प्रदान करने की व्यवस्था और आनन्दमय तथा हार्दिक कार्य के लिये वातावरण बनाने सम्बन्धी सब बातों की व्यवस्था प्रबन्धकों द्वारा ही की जा सकती है। अच्छे से अच्छे प्रयत्न तथा उत्पादकता वृद्धि के लिये कारखाने के प्रत्येक स्तर पर सहयोग प्राप्त करने तथा प्रेरणा देने के लिये प्रबन्धकों को सक्रिय रूप से भरसक प्रयत्न करने होंगे। दूसरी ओर वैज्ञानिक अनुसन्धान एवं खोज को भी उद्योगपतियों या प्रबन्धकों द्वारा प्रेरणा प्रदान की जा सकती है, जिसके फलस्वरूप कुछ तांत्रिक सुधार संभव हो सकते हैं, सरलीकरण हो सकता है तथा लागत को कम करने के लिये कुछ क्रियाओं (operations) को बिल्कुल हटाया जा सकता है। ऐसे श्रमिकों के कल्याण का बहुत ध्यान रखना होगा जो ऐसे परिवर्तनों से प्रभावित होने से भयभीत हों। उत्पादकता बढ़ाने की नई विधियों को काम में लाने की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रबन्धक किस सीमा तक इस सम्बन्ध में श्रमिकों का सहयोग एवं श्रम-संगठनों का विश्वास प्राप्त करने में सफल हो सकता है।

जहां तक कर्मचारियों और समाज के प्रति प्रबन्ध के कर्त्तव्य और जिम्मेदारी का सम्बन्ध है इसकी सफलता इस बात पर आधारित है कि कहां तक प्रबन्धक निम्न-उत्पादकता (Low Productivity) के कारणों को दूर करने तथा बढ़ती हुई कार्य क्षमता और उत्पादकता से प्राप्त होने वाले लाभों को बढ़ाने में सफल हो सकता है।

भारतीय उत्पादकता आन्दोलन का दूसरा मुख्य स्तम्भ श्रमिक है। उत्पादन क्रिया में श्रम को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और उत्पादकता को बढ़ाने में श्रमिक बड़ा सहयोग प्रदान कर सकते हैं। परन्तु यह दुख की बात है कि श्रमिक वर्ग 'उत्पादकता' शब्द से भयभीत एवं शंकित होता है। जब भी उत्पादकता को किसी उद्योग में बढ़ाने और इसकी विधियों को अपनाने की चर्चा की जाती है, श्रमिकों द्वारा इसका विरोध होता है क्योंकि वे उत्पादकता से यह तात्पर्य लेते हैं कि उनका कार्यभार बढ़ जायगा, अधिक परिश्रम करना पड़ेगा और मिल मालिक के लाभ में वृद्धि होगी। परन्तु वास्तव में उत्पादकता की वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग के ऐसे परिणाम कभी नहीं होते, अतः श्रमिकों के मस्तिष्क में जो गलत भावना उत्पादकता के विषय में उत्पन्न हो गई है उसे दूर करना होगा। वास्तव में कार्य अध्ययन तथा इसी प्रकार की अन्य विधियों के प्रयोग का उद्देश्य यह होता है कि कुशल कार्य सरलता पूर्वक किया जा सके, जिसके फलस्वरूप श्रमिकों को कम थकान महसूस हो, क्योंकि समय और गति दोनों में बचत होती है। श्रमिकों द्वारा उत्पादकता की विधियों का विरोध इस आधार पर भी किया जाता है कि उसके फलस्वरूप श्रमिकों में बेकारी फैल जायगी। यह एक गम्भीर प्रश्न है और इस विरोध में सत्यता का अंश है। अल्पकाल में तो इसका बेरोजगार पर जो प्रभाव पड़ेगा, उससे पूर्णरूप से इन्कार नहीं किया जा सकता। परन्तु दीर्घकालीन दृष्टि से यह उत्तर दिया जाता है कि उत्पादकता बढ़ने से सस्ती वस्तुओं की पूर्ति मांग में वृद्धि करेगी, फलतः अधिक माल का उत्पादन करने के लिये अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जा सकेगा और यह बिल्कुल संभव है कि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पहले निकाले गये श्रमिकों की अपेक्षा और अधिक श्रमिकों को रोजगार मिले। दूसरी बात यह भी ध्यान में रखनी है कि यदि आज इस समय की पुकार पर ध्यान नहीं दिया जायगा तो यह बिल्कुल सम्भव है कि ये अधिक लागत के कारण घाटे पर चलने वाले उद्योग बाध्य होकर बन्द करने पड़ें और उस स्थिति में कहीं अधिक श्रमिक बेकार हो जायेंगे। सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर इस स्थिति का जो कुप्रभाव पड़ सकता है, वह भी समझा जा सकता है। उत्पादकता की विधियों के प्रयोग का विरोध करना एक प्रकार से देश के आर्थिक विकास का विरोध करना है और प्रगति के मार्ग में रोड़े अटकाना है, जो किसी के लिये लाभ-दायक नहीं कहा जा सकता।

भारत के श्रमसंघ के नेता श्रमिकों को इस आन्दोलन का महत्व समझाने में बड़ा योगदान दे सकते हैं और उन्हें श्रमिकों को यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि कार्यक्षमता की वृद्धि के प्रत्येक उपाय में इनका बड़ा हित है। उन्हें इस बात को समझना है कि उद्योग अधिक मजदूरी का भुगतान तभी कर सकते हैं, जबकि वे लाभ से चलें।

श्रमिकों के मस्तिष्क में एक और भावना यह है कि उत्पादकता वृद्धि का सम्पूर्ण लाभ उद्योगपतियों की तिजोरियों में जायगा। उत्पादकता के फलस्वरूप लाभ में जो वृद्धि हो, उसके बंटवारे के सम्बन्ध में श्रमिकों और मालिकों के मध्य उत्पादकता की विधियों को अपनाने से पूर्व ही एक न्यायसंगत आधार पर समझौता किया जा सकता है। जैसे वे मजदूरी या बोनस की दर तय कर लेते हैं, इसे भी तय कर सकते हैं। उत्पादकता की वृद्धि से होने वाले लाभों के बटवारे के सम्बन्ध में समझौता करते समय श्रमिकों और मालिकों का यह नैतिक कर्त्तव्य होगा कि उपभोक्ताओं के हितों का शोषण न करें और उनको भी इस लाभ से वंचित न रखें।

उत्पादकता वृद्धि में श्रमिकों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिये प्रेरणा की योजना को भारतीय उद्योगों में कार्यान्वित करना अत्यन्त आवश्यक माना जाता है। ऐसी योजनाओं को कार्यान्वित करने से पूर्व उनसे सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण व्यावहारिक बातों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना जाना चाहिए। अभी हाल ही में Dr. R.L. Mitchell (Chief of the I.L.O. Productivity Mission) ने एक विचरगोष्ठी में इस प्रश्न के इस पहलू पर पर्याप्त जोर दिया।

उनके अनुसार प्रेरणा प्रदान करने की कोई योजना तभी सफल हो सकती है, जबकि वह निम्नलिखित तीन शर्तों को पूरा करती हो :—

१—योजना इतनी सरल हो कि श्रमिकों द्वारा सुविधा से समझी जा सके।

२—पारिश्रमिक इतना पर्याप्त हो कि श्रमिकों में उच्चतम प्रयत्न करने का जोश उत्पन्न कर सके, और

३—पारिश्रमिक का भुगतान जितनी जल्दी संभव हो, किया जाय और कम से कम श्रमिकों को उनके द्वारा उपार्जित पारिश्रमिक के सम्बन्ध में सूचना तो शीघ्रातिशीघ्र दे दी जानी चाहिए।

श्रमिक और श्रम संगठनों के नेता इन योजनाओं को संदेहात्मक दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उनको यह भय बना रहता है कि ऐसी योजनाओं की आड़ में प्रबन्धकों का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों से लगभग पहिली मजदूरी दर पर या उससे भी कम अनुपातिक दर पर अधिक उत्पादन प्राप्त करना होता है। इस भ्रम को भी दूर करना होगा।

सरकार

उद्योगों की उत्पादकता वृद्धि में सरकार को भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। सरकार प्रशासकीय तथा वित्तीय नीतियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकता वृद्धि को प्रोत्साहित या हतोत्साह कर सकती है। उत्पादकता वृद्धि में सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि सन्तुलित आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन प्रदान करके अधिक उत्पादकता के लिये अधिक अनुकूल वातावरण बनाये। इसी प्रकार विभिन्न संस्थाओं की स्थापना तथा उन्हें वित्तीय एवं तांत्रिक सुविधायें प्रदान करके राज्य उत्पादकता की वृद्धि में बड़ा योगदान दे सकता है। राज्य के द्वारा प्रबन्धकों, तान्त्रिक विशेषज्ञों तथा निरीक्षकों

(शेष पृष्ठ ३६६ पर)

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थ वृत्त चयन

चूजों की आड़ में व्यापार युद्ध

अमेरिका और यूरुपीय सांझा बाजार के बीच, लगभग गत एक वर्ष से, व्यापार-युद्ध चल रहा है। यूरुपीय सांझा बाजार देशों ने अमेरिकी अंडों व चूजों आदि के आयात पर ५ सेंट से बढ़ाकर १३ सेंट प्रति पौंड शुल्क लगा दिया है। अगर यूरुपीय सांझा बाजार के देशों ने इस वर्ष अक्तूबर तक यह आयात शुल्क न हटाया तो अमेरिका इसके प्रतिशोध के रूप में, यूरुप से अमेरिका में बड़ी मात्रा में आयात होने वाले निर्मित सामान और फार्म के उत्पादनों पर आयात शुल्क लगा देगा। इस श्रेणी में शामिल कुछ चीजें ये हैं, सिगरेट, पुस्तकें, सिन्थेटिक सूत, इस्पात की कुछ चीजें, कैंची, बिजली का हजामती सामान, ट्रक, बसें और चल चित्र की फिल्में। फार्म-सामान में कई प्रकार की शराबें पनीर फुलनुमा बल्ब भी शामिल हैं।

अमेरिका से सर्वाधिक डालर निष्कासन करने वाली चीजों में स्काच व्हिस्की (शराब) का विशिष्ट स्थान है। अमेरिकी शराब निर्माताओं की शिकायत है कि अगर उनके देशवासियों में तनिक देशभक्ति की भावना हो तो लाखों डालरों का विदेशों में प्रवाह रुक सकता है। पर, इस समय तो अतलांतिक के दोनों ओर के महाद्वीपों में "चूजा-युद्ध" की गरमा-गरम चर्चा है। यह आश्चर्य की बात है कि इस छोटी वस्तु को लेकर दोनों ओर के महाद्वीप के देशों में इतना तनाव पैदा हो। आखिर, अमेरिका से यूरुप को अंडों का जितना निर्यात होता है, वह उसके कृषि उत्पादन का लगभग एक प्रतिशत ही है।

जर्मनी में यह आम प्रचार किया जा रहा है कि अमेरिकी किसान मुर्गियों को "होरमोनेस" नाम की एक ऐसी चीज खिलाते हैं, जिससे उनकी वृद्धि में तीव्रता आ जाए। जर्मन कृषिविज्ञ अपने देश के लोगों को इन अंडों का इस्तेमाल करने से यह कह कर रोक रहे हैं कि इनसे खाने वाले की पुरुष शक्ति का ह्रास हो जाता है। एक वर्ष पूर्व जब यह आयात शुल्क लगाया गया था, तब यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि यह व्यापार-युद्ध यहां तक पहुँच जायगा। कुछ भी हो, दोनों पक्षों का यह तनाव किसी भी समय उग्र रूप धारण कर सकता है। अमेरिका का यह कहना है कि इस शुल्क से अमेरिकी निर्यात को ४ करोड़ ६० लाख डालर की क्षति हो रही है, जब कि ई. ई. सी. (यूरोपियन इकोनामिक कमीशन) का कहना है कि यह राशि सिर्फ १ करोड़ ९० लाख है। जी. ए. टी. टी. (जनरल एग्रीमेंट आन ट्रेड एण्ड ट्रैफिक) की संधि के अनुसार संकटग्रस्त पक्ष को यह अधिकार है कि वह क्षति की राशि के तुल्य तट-कर लगा सकता है। इसलिए अमेरिका ४ करोड़ ६० लाख डालर का तट कर लगा सकता है। तब, ई. ई. सी. भी बदले के रूप में, आयात कर बढ़ायेगा। इसका परिणाम होगा पूर्णरूप में तट-कर संघर्ष। वाशिंगटन और ब्रुसेल्स दोनों ओर के समझदार और ठंडे दिमाग के नेता इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रयत्नशील हैं।

रूस में स्वर्ण

कुछ विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले सोवियत रूस लगभग २५ करोड़ डालर के मूल्य का स्वर्ण उत्पादन कर रहा था। रूस में कितने स्वर्ण का उत्पादन होता है और कितना पश्चिमी देशों को बेचा जाता है, यह एकदम गुप्त रखा जाता है। सोवियत गुट के बाहर के स्वर्ण-उत्पादक देशों द्वारा, फिर भी, इस बारे में जानकारी मिलती रहती है। अनुमान यह है कि पश्चिमी देश मिलकर जितना स्वर्ण बेचते हैं, सोवियत रूस का उत्पादन उससे बहुत अधिक है। अनुमान यह है कि रूस में १९५८ में ३० करोड़ डालर से लेकर ३५ करोड़ डालर तक स्वर्ण उत्पादन हुआ। और बिक्री २३ करोड़ ५० लाख वार्षिक के आस-पास युद्धोत्तरकाल में हुई। कुछ सूत्रों के आधार पर यह भी अनुमान लगाया गया है कि सोवियत रूस अपने सम्पूर्ण स्वर्ण उत्पादन को बाजार में बेच देता है। इसका अभिप्राय यह है कि उसके पास संचित स्वर्ण की राशि अधिक नहीं है। अगर स्वर्ण का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ जाए—जैसा कि कुछ पूंजीपति देश इसके पक्ष

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

में है, तो सोवियत रूस को लाभ ही है।

विज्ञापनों में अत्युक्ति से काम न लें

अमेरिका में फ्लोरिडा के मशहूर इंजीनियरिंग कंपनी में श्री एडविन ग्रीन काम करते थे। इनकी मृत्यु केन्सर रोग से हुई। उनकी पत्नी ने इसके बारे में वे जिस कंपनी की बनी सिगरेट पीते थे, उस पर नुकसान की पूर्ति का दावा किया और कोर्ट ने इसके सम्बन्ध में सिगरेट बनाने वाली कंपनी और विक्रेता को जिम्मेदार माना। अमेरिका में इस तरह के दावे अब जगह-जगह पेश होने लगे हैं। इस कारण अमेरिका के सिगरेट कारखानों के कानूनी सलाहकार श्री चेस्टर एवाल्ड ने कहा है "नाक-गला और संबंधित अवयवों को नुकसान नहीं होता है, इस तरह का जो विज्ञापन सिगरेट का किया जाता था, वह न किया जाय।"

खराब अखरोटों के तेल से वार्निश

कश्मीर राज्य में प्रतिवर्ष २,६१,००० किलो अखरोट पैदा होता है। अनुमान है कि प्रतिवर्ष लगभग ९३,०००-१,१२,००० किलो गिरी व्यर्थ जाती है। इन गिरियों से, ३७,०००-५६,००० किलो तेल प्राप्त किया जा सकता है। खराब अखरोटों का यह तेल हल्के रंग का खराब गंध वाला होता है। इसे खाने के काम में नहीं लाया जा सकता है।

इस तेल को रंग और वार्निश बनाने के काम में लाने के लिए प्रयोग किये गये हैं। यह देखा गया है कि यद्यपि गर्म करने से उसके सूखने के गुण में सुधार हो जाता है, पर बाद में चिपक बाकी रही जाती है। इसलिए इस तेल को वार्निश बनाने के लिए ऐसे ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

विश्व के सभी भागों में टेलिफोन के तार

१ करोड़ ९० लाख की लागत से तैयार किया गया अमेरिकी जहाज, "लौंग लाइन्स" अन्ततः विश्व के सभी भागों में ऐसी व्यवस्था करना सम्भव बना देगा, जिसके द्वारा अधिक तेजी एवं स्पष्टता के साथ टेलीफोन पर बातचीत की जा सकेगी।

अमेरिकन टेलिफोन एण्ड टेलिग्राफ कम्पनी का यह जहाज आगामी तीन वर्षों में अतलान्तक, कैरेबियन तथा प्रशान्त सागरों में लगभग १६,००० मील (लगभग २५,००० किलोमीटर) लम्बे तार बिछायेगा।

अमेरिका तथा ब्रिटेन के मध्य प्रथम सीधा टेलीफोन तार बिछाने का कार्य प्रारम्भ हो गया है। यह संसार में टेलिफोन का सबसे लम्बा अनेला तार है। "लौंग लाइन्स" की दूसरी योजना मिड वे, वेक तथा ग्वाम के मार्ग से होनोलूलू को जापान के साथ मिलाने के लिए तार बिछाना होगी। १९६४ में यह व्यवस्था चालू हो जायेगी। एक तार पहले ही अमेरिका की मुख्य भूमि को हवाई के साथ मिलाता है।

(पृष्ठ ३६४ का शेष)

को उत्पादकता की विधियों को बड़े पैमाने पर उद्योगों में लागू करने के लिये प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने इन कार्यक्रमों के विस्तार के सम्बन्ध में उल्लेख किया है, परन्तु आज आवश्यकता इस बात की है कि योजना को कार्यान्वित करने में सामान्य रूप से जो दोष या कठिनाइयां दृष्टिगोचर हुए हैं, उत्पादकता के कार्यक्रम भी उससे अलग नहीं है। अतः उनको कार्यान्वित करने के लिये विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और उन्हें सुचारू रूप से तेज़ी के साथ कुशलता पूर्वक कार्यान्वित करना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि इस संकटकालीन स्थिति में सरकारी संस्थाओं के संगठन के ढांचे में मूलभूत सुधार द्वारा ऐसे उपाय किये जाएं कि कम से कम सरकारी क्षेत्र के उद्योग "उत्पादकता की भावना प्राप्त प्रशासन के नमूने" (Models of Produetvity-Conseious Administration) बन जायें और उत्पादकता की विधियों तथा उनसे उत्पन्न लाभों को व्यावहारिक रूप में प्रदर्शन कर सकें। उत्पादकता बढ़ाने की क्रियाओं की सूचनाओं को शीघ्राति-शीघ्र उद्योगपतियों तक पहुँचाने में भी सरकार बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है।

आशा है कि यदि भारतीय उत्पादकता आन्दोलन के यह तीनों स्तम्भ दृढ़ एवं शक्तिशाली बनकर अपने कर्त्तव्यों का पालन करेंगे, तो देश का आर्थिक आधार बहुत दृढ़ बन जायगा।

सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नया सामयिक साहित्य

आर्थिक विचार धारा—लेखक—श्री कृष्णदत्त भट्ट प्रकाशक—सर्व सेवा संघ, राजघाट, वाराणसी। मूल्य—६ रुपये सजिल्द। पृष्ठ संख्या ४८३।

पिछले ३-४ वर्षों में अर्थशास्त्रीय साहित्य हिन्दी में भी अच्छा प्रकाशित होने लगा है। अनेक पुस्तकें अर्थ-शास्त्र के इतिहास और आर्थिक विचारधाराओं के विकास पर लिखी गई है। परन्तु श्री भट्ट की यह विद्वत्तापूर्ण पुस्तक अपनी विशेषता रखती है। प्रायः अन्य लेखक केवल अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों को ही दृष्टि में रखकर इतिहास लिखते रहे हैं, जबकि इस पुस्तक के लेखक इतिहास के साथ-साथ विचार और चिन्तन की भी प्रेरणा पाठक को देते हैं। यह केवल इतिहास की शुष्क कृति नहीं है, बल्कि विभिन्न कालों और विभिन्न देशों में उत्पन्न परिस्थितियों और आर्थिक विचार धाराओं के परस्पर सम्बन्ध से पाठक को परिचित भी करती है। राजनीतिज्ञों की तरह अर्थ-शास्त्री भी अपने देश और काल की उपज होते हैं। इसीलिए उनकी विचारधारा को सार्वकालिक सत्य मानना हमारी भूल होगी।

इस पुस्तक की दूसरी विशेषता यह है कि लेखक विदेशी अर्थ-शास्त्रियों के अन्धानुसरण की प्रवृत्ति में न बह कर भारतीय विचारधारा का भी यथोचित परिचय देता गया है। भारतीय विचारकों की भी अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण देन है। उनकी देन यह है कि मानव की प्रवृत्तियों का प्रेरक कारण केवल पैसा नहीं है। प्रेम, दया और नैतिकता आदि का भी मानव संस्कृति के इतिहास में विशेष स्थान रहा है और है। गांधीवादी विचारधारा तो आधुनिक अर्थशास्त्र को अनर्थशास्त्र कहती है, क्योंकि वह मानव हित के विशुद्ध उद्देश्य की उपेक्षा कर देता है। भौतिक उन्नति ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, मानवता नैतिकता और आध्यात्मिक उन्नति भी जीवन का उद्देश्य है।

सदियों से मानव आर्थिक और जीवन-सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करता आया है। उसकी विचार धारा समय-समय पर बदलती रही है। वह विकसित हुई है। उसने अनेक दिशायें बदली हैं और समय-समय पर अनेक मोड़ लिए हैं। एक-एक शाखा से अनेक शाखाएं प्रस्फुटित हुई हैं। विद्वान लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक में प्लेटो, अरस्तु से लेकर आदम स्मिथ, माल्थस रिकार्डो साइमन, मार्शल, पेगू, कीन्स तथा मार्क्स आदि बीसियों प्रमुख अर्थशास्त्रियों के विचार देते हुए सब विचार-धाराओं की प्रगति व परिवर्तन आदि के विकास का क्रमबद्ध परिचय दिया है और यह बताया है कि मानव शनैः शनैः मानवतावाद की ओर जा रहा है। समाजवाद उसी की एक सीढ़ी है, किन्तु उसकी चरम परिणति सर्वोदय में है जो आर्थिक दृष्टि से विकेन्द्रीकरण का संदेश देकर समाज में से शोषण को सर्वथा समाप्त करना ही नहीं चाहता, किन्तु सच्चा मानव भी बनाना चाहता है। प्रत्येक प्रकरण के अन्त में संक्षिप्त मूल्यांकन बहुत सुन्दर हुआ है।

हमें आशा है कि अर्थशास्त्र के विद्यार्थी ही नहीं, हिन्दी भाषी संसार का शिक्षित वर्ग भी इस पुस्तक से अपना ज्ञान वर्द्धन करेगा, और चिन्तन की नई प्रेरणा पायेगा। आज यह चिन्तन इसलिए और भी आवश्यक है कि हम राष्ट्र का पुनर्निर्माण करने जा रहे हैं। हमारी मौलिक नीति एकांगी न होकर सर्वांगीण बने तथा विविध पहलुओं और दृष्टियों से विचार कर हम भविष्य की नीति का निर्धारण करें।

भारतीय नियोजन—पौपुलर प्रकाशन ३५ सी तारदेव रोड, बम्बई ३४. (डब्ल्यू. बी.) द्वारा प्रकाशित। मूल्य १ रु०।

प्रस्तुत पुस्तक में देश की कुछ वर्तमान योजना संबंधी आर्थिक समस्याओं पर अनेक प्रमुख अर्थशास्त्रियों के लेखों का संग्रह किया गया है। लेखकों में श्री ए. डी. श्राफ, श्री वी. आर शिनाय, श्री एम. ए. मास्टर तथा श्री मुशरजी वैद्य आदि सभी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। प्रायः सभी लेखों में योजना का दूसरा पक्ष उपस्थित किया गया है और योजना की नीति व कार्यपद्धति पर अपने दृष्टिकोण से विचार किया गया है। हमारी नम्र सम्मति में सत्य पर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

केवल योजना आयोग का एकाधिकार नहीं है, दूसरे पक्ष में सत्य का अंश हो सकता है, इसलिए विचारकों को निष्पक्ष होकर उन विचारों का भी अध्ययन करना चाहिए। यह छोटी सी पुस्तक इस दृष्टि से उपयोगी होगी।

महिला मणि कीर्तनम्—प्रणेता—पं० धर्मदेव विद्या वाचस्पति। प्रकाशक: आनन्द कुटीर, ज्वालापुर (उत्तर प्रदेश) मूल्य ३) रु. सजिल्द।

प्रस्तुत पुस्तक में देश तथा विदेशों की दिवंगत या माननीय महिलाओं की प्रशस्तियां दी गई हैं। विद्वान लेखक ने इन सब को संस्कृत पद्यों में लिखा है। छन्दों की भाषा सरल है और प्रतिपादन शैली सुबोध है। लेखक ने अत्यन्त उदार दृष्टि से जहां भारत की सीता, अरुन्धती, सावित्री, दमयन्ती, कस्तूरबा, सुलभा, गार्गी, मैत्रेयी, भारती, लक्ष्मीदेवी, दुर्गाबाई, मीराबाई, सरोजनी, कमला नेहरू आदि भारतीय महिलाओं का गुण स्तवन किया है, वहां विदेशों की जौन आफ आर्क, फ्लोरेंसनाइटिंगेल, एनी बेसेण्ट, मार्गरेट, कर्जन्स, मेरी क्यूरी आदि महिमामयी महिलाओं का स्तवन करके भी न्यायप्रियता व उदारता का भी परिचय दिया है। लेखक ने समस्त पुस्तक को पतिव्रता, आदर्श माता, विदुषी, वीर क्षत्रिया, देश भक्त, कवयित्री विदेशी महिला आदि खण्डों में विभक्त किया है। रजिया बेगम, चांद बीबी ताजकुमारी आदि का परिचय भी यह बताता है कि लेखक साम्प्रदायिकता से ऊंचा उठकर लिख रहा है।

सर्व साधारण के लाभार्थ संस्कृत पद्यों का हिन्दी में अर्थ भी दे दिया गया है। इसके लेखन से लेखक जहां महिलाओं का स्तवन करके स्त्री जाति के प्रति उपेक्षा का प्रायश्चित करना चाहता है, वहां संस्कृत साहित्य को भी नई देन देता है। कुछ अप्रसिद्ध महिलाओं का परिचय संभवतः लेखक की आत्म तुष्टि के लिए है, किन्तु इससे पुस्तक की उपादेयता में कमी नहीं आती।

साठे न्यूज़—(अंग्रेजी) साठे बिस्कुट एण्ड चाकलेट कम्पनी लिमिटेड, पूना-२ द्वारा प्रकाशित।

यह छोटी-सी पत्रिका बिस्कुट उद्योग और उनकी विविध समस्याओं के बारे में जानकारी देती है। आजकल व्यापार में कलापूर्ण पैकिंग का महत्त्व बढ़ता जा रहा है, इस सम्बन्ध में भी एक संक्षिप्त लेख पढ़ने योग्य है। इसी तरह उक्त कम्पनी द्वारा की जा रही अनेक प्रवृत्तियों की भी इससे सूचना मिलती है। इसकी छपाई सफाई बहुत सुन्दर है।

गन्ना-उपकर का सदुपयोग!

प्रान्त	गन्ना उपकर प्राप्त	गन्ना उत्पादन में किया गया व्यय
	(लाख रुपयों में)	
उत्तर प्रदेश	६६०.८३	१२६.२९
बिहार	१२४.४८	३०.८७
पंजाब	१२.००	८.५९
महाराष्ट्र	१६.७६	३०.५६
मध्य प्रदेश	०.५९	३.०७
आन्ध्र प्रदेश	१३०.१८	४०.२७
मद्रास	२०.९२	१४.३६

गन्ना-उपकर इसलिए लगाया गया था कि इसकी आय से गन्ने की खेती के विकास की खोज की जाय, जिससे प्रति एकड़ अधिक मात्रा में अच्छे किस्म की खेती होने लगे। लेकिन राज्य सरकारें इस आय का ठीक कार्य के लिए बहुत कम उपयोग करती हैं और जितना व्यय करती भी हैं, उसमें से अधिकांश अफसरों व कर्मचारियों के वेतन तथा उनके भत्तों और कोठियों पर खर्च हो जाता है। परिणामतः गन्ने की न किस्म में विशेष सुधार होता है और न उसकी उपज की मात्रा ही बढ़ती है।

विज्ञापन के लिए

सम्पदा

सर्वोत्तम साधन है

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय योजना में समाजवाद

(पृष्ठ ३४५ का शेष)

कि 'सम्पूर्ण राष्ट्रीयकरण'।"११ दूसरे शब्दों में भारत-सरकार 'विवेकपूर्ण समाजवाद'१२ की नीति का अनुसरण करती रही है। जैसा कि प्रो० लिवि ने कहा है—"आर्थिक जीवन में सरकार की समस्या यह है कि वह अत्यधिक योजना बनाने और कम योजना बनाने के बीच का मार्ग ग्रहण करे और इसी तरह बहुत अधिक व बहुत कम राष्ट्रीयकरण के बीच का रास्ता पकड़े।"१३ दूसरे विश्वव्यापी महायुद्ध के बाद से ब्रिटिश अर्थ-नीति निजी उद्योगों पर निरीक्षण रखनेमात्र की रही है—सीधे नियंत्रण या राष्ट्रीयकरण की नहीं।"१४ आधुनिक जगत् में हमें राज्य के केन्द्रीकृत नियंत्रण और शक्ति का विकेन्द्रीकरण या समुदाय के हाथों में करने के बीच सन्तुलन कायम रखना है। थोड़े में यह कह सकते हैं कि "जरूरत योजना बनाने की है, अनुशासन की नहीं।"१५ उद्योगों के अधिक राष्ट्रीयकरण से "स्वयं राज्य की नौकरशाही ही उस शक्ति को केन्द्रित करने वाली बन जायगी, जिसने कि हमारी आजादी को भयभीत कर रखा है।"१६

स्वर्णिम मध्यमक

भारत स्वतंत्र उद्यम और संगठित समाजवाद के बीच आयोजित आर्थिक विकास के द्वारा एक स्वर्णिम मध्यमक विकसित करने का प्रयत्न करता रहा है। राज्य को अपने अनावश्यक निजी उद्योगों को लेकर अल्प साधनों को बिखेरना नहीं चाहिए। उसे तो विभिन्न सांसदिक संविधानों के द्वारा बड़े सामूहिक जनहित के लिए निजी उद्योगों को नियंत्रित और व्यवस्थित करना चाहिए। तो भी यह जरूरी है कि सभी उद्योग जो "बुनियादी और युद्धविषयक महत्व के हैं, अथवा जो सार्वजनिक सेवा की दृष्टि से उपयोगी हैं, वे सरकारी उद्योग में हों।"१७

अगर किसी निजी क्षेत्र के उद्योग का, चाहे वह देशी हो या विदेशी, राज्य इसलिए राष्ट्रीयकरण कर ले कि वह सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो भारत-सरकार उसके लिए उचित मूल्य चुकाने को बाध्य है। संविधान के (चतुर्थ) संशोधन बिल के सिलसिले में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था—"सरकार किसी को मुआवजा दिये बिना उसकी जायदाद नहीं लेना चाहती। अगर कोई देश विदेशी जायदाद के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देता है तो वह दुनिया में बदनाम हो जाता है।"

लोकतंत्रीय ढांचा

इसके सिवा भारत में समाजवाद की नींव सत्तावादी नियंत्रण के विरुद्ध जनतंत्रीय सिद्धान्तों पर रखी गयी है। संविधान के अनुसार भारत 'सम्पूर्ण' प्रभुत्वसम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है जिसे अपने सभी नागरिकों के लिए "सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और पूजा की आजादी; दर्जे और अवसर की समानता दिलानी चाहिए, और उन (नागरिकों) में भाईचारे का संवर्द्धन, व्यक्ति के गौरव और व्यक्ति तथा राष्ट्र की एकता"—१८ का आश्वासन प्रदान कराना चाहिए। शायद संसार में भारत ही ऐसा पहला देश है, जिसने गणतंत्रीय ढांचे के अन्तर्गत व्यापक आर्थिक योजना द्वारा समाजवादी समाज स्थापित करने का प्रयोग शुरू किया है। संयुक्त राज्य अमेरीका और ब्रिटेन-जैसे पश्चिमी गणतंत्र में ऐसी योजना टुकड़े-टुकड़े करके की जाती है—जैसा कि प्रेसिडेण्ट रूजवेल्ट ने नये सुधार (न्यू डील) के नाम से प्रस्तुत किया था और लार्ड बेवरिज ने "समाज-सुरक्षा-योजना" के नाम से। भारत में सामा-

११. टुवर्ड्स ए सोशलिस्टिक आर्डर, जवाहरलाल नेहरू कृत, ए० आई० सी० सी० प्रकाशन

१२. स्टडीज़ इन एशियन सोशलिज्म, अशोक मेहता कृत, पृ० २३

१३. थियरी आफ़ इकॉनॉमिक ग्रोथ, प्रो० ए० लिवी कृत, पृ० ४१३

१४. ब्रिटिश इकानामिक पालिसी सिन्स द वार (पेंगुइन स्पेशल) एडवर्ड्स शोनफील्ड कृत, ६, १७३ (देखें १६-१७)

१५. फ्रीडम, पावर एण्ड डेमोक्रेटिक प्लानिंग, कार्ल मेनहीम कृत, पृ० २६

१६. सोशलिज्म ऐण्ड द न्यू डेस्पाटिज्म, आर० एस० ग्रासमेन, पृ० १२

१७. इण्डस्ट्रियल पालिसी रेजोल्यूशन, गवर्नमेंट आफ़ इण्डिया, अप्रैल १९५६

१८. प्रियम्बल आफ़ द कांस्टीट्यूशन पृ० १ से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जिक और गणतंत्रीय योजना के अन्तर्गत अब तक जो अनुभव प्राप्त किये गये हैं वे पूर्णतः सन्तोषजनक रहे हैं और यह जानना परितोषजनक है कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रयोग हाल ही के आजाद बने एशिया और अफ्रीका के देशों में आर्थिक योजना के रूप में चलाकर सहायक सिद्ध किये जा रहे हैं।

विकेन्द्रीकरण

तो भी यह बात याद रखने की है कि भारत अतिशय केन्द्रित नमूने का अनुसरण करने का इरादा नहीं रखता, जैसा अधिकांश पश्चिमी देशों में प्रचलित है। विकेन्द्रित गणतंत्र का पंचायती नमूना भारत में चिरकाल से प्रचलित है। एक के बाद एक राजवंश आये और गये, क्रान्ति के बाद क्रान्ति हुई, किन्तु ग्राम-समुदाय ज्यों के त्यों रहे। "हर ग्राम-समुदाय का यह छोटा-मोटा राज्य मिलकर ऐसा बन गया कि उससे सभी क्रान्तियों और परिवर्तनों के कारण हुए कष्टों से रक्षा हुई।"१९ युगों से भारतीय गणराज्य उस संयुक्त जीवन के अस्तित्व पर आधारित रहा है, जो सर्वसम्मत या निकटतम सर्वसम्मत निर्णय के अनुसार प्रस्थापित है। जबकि भारत ने न्यूनाधिक रूप में ब्रिटिश संसदीय गणतंत्र का ढांचा अपने संविधान में समाविष्ट किया है, उसके निर्देशक सिद्धान्त राज्य को आदेश देते हैं—"ग्राम-पंचायतों का संगठन करना और उन्हें ऐसे अधिकार तथा सत्ता प्रदान करना, जो सरकारी इकाई का काम करने के लिए आवश्यक हों।"

पश्चिम के अनेक प्रसिद्ध सामाजिक और राजनीतिक विचारक इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि "यदि मनुष्य के सामाजिक क्रियाशीलताओं सम्बन्धी विश्वास को अनुप्राणित करना है तो राज्य को विभाजित अर्थात् विकेन्द्रित करके उसके काम बांट दिये जाने चाहिए।"२० अलडुअस हक्सले ने भी इस बात की पुष्टि इन शब्दों में की है—"एक अच्छे समाज का राजनीतिक मार्ग वह है जो उसे विकेन्द्रीकरण और उत्तरदायी स्वशासन की ओर ले जाता है।२१ प्रो० लास्की ने विकेन्द्रीकरण को इसलिए वांछनीय बताया है कि आदेश-पालन वास्तव में केन्द्रित राज्य में कभी-कभी ही सर्जनात्मक होता है; वह तांत्रिक और जड़ बन जाता है।२२ लिवी मम्फर्ड ने कहा है कि केन्द्रीकरण से स्थानीय नेतृत्व का गला घुट जाता है और सुदूर शाखा से केन्द्र तक सूचना आने-जाने में व्यर्थ ही समय और धन की बर्बादी होती है।२३

नैतिक और मानवीय मूल्य

अन्त में बात यह है कि भारत का समाजवाद केवल भौतिक कल्याण की बात ही नहीं सोचता। वह जीवन के नैतिक और मानवीय मूल्य पर बहुत जोर देता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना एक महत्वपूर्ण बात यह कहती है—"यद्यपि योजना में काफी पूंजी लगती है, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण चीज है 'मनुष्य रूपी पूंजी। इसके सिवा हर वक्त नैतिकता, मानवता और आध्यात्मिक मूल्यों का ख्याल रहना चाहिए क्योंकि यही आर्थिक प्रगति को अर्थ प्रदान करते हैं।२४ प्रो० टोयनबी का ख्याल है कि भारतीय किसानों के जीवन का मानदण्ड ऊपर उठाना कोई भौतिक ध्येय नहीं है, यह तो प्रमुख आध्यात्मिक महत्वों में से एक है, क्योंकि यह आध्यात्मिक क्रियाशीलता के लिए जरूरी क्षमता प्रदान करता है।२५

गांधीजी न केवल जिन्दगी का मापदण्ड ऊपर उठाना चाहते थे, बल्कि जीवन के मापदण्ड को सुन्दर भी बनाना चाहते थे। एक से अधिक अर्थों में आधुनिक जगत् अब इस तथ्य को समझ चुका है कि मनुष्य रोटी से ही जीवित नहीं रहता।"*

---

१९. सर चार्ल्स मेटकाफ़ की प्रसिद्ध मिनिट (१८३०) से

२०. माडर्न पोलिटिकल थियरी, प्रो० जोड कृत, पृ० १२०

२१. एण्ड्स ऐण्ड मीन्स, प्रो० अलडुअस हक्सले कृत, पृ० ६३

२२. द इंट्रोडक्शन आफ़ पालिटिक्स, हैराल्ड लास्की कृत, पृ० ५३

२३. सेंट्रल प्लानिंग इन पोलेण्ड, जान माइकेल मोशिटआस कृत, पृ० ६

२४. द थर्ड फ़ाइव-इयर प्लान १८-१९

२५. वन वर्ल्ड एण्ड इण्डिया, प्रो० अर्नाल्ड टोयन्बी कृत, पृ० ६२-६३

*शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाली लेखक की अंग्रेजी पुस्तक 'सोशलिज्म इन इंडियन प्लानिंग' से।

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राज्यों की आर्थिक गतिविधि

- विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय।
- गुजरात का आर्थिक विकास।
- उत्तर प्रदेश में चार क्षेत्र।
- मध्यप्रदेश में आदिम जात।

विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय

आर्थिक अनुसन्धान समिति ने विभिन्न राज्यों के सम्बन्ध में प्रति व्यक्ति आय की एक तालिका प्रकाशित की है। राज्यों के अपने-अपने साख्यिकीय विभागों ने भी इसी सम्बन्ध में अपने अनुमान किए हैं। दोनों के अनुमानों में अन्तर है। किसी राज्य में यह अन्तर बहुत अधिक है, किसी में कम। इस तालिका से मालूम होता है कि दोनों संस्थाओं की सम्मति में कौनसा राज्य अधिक सम्पन्न है और कौनसा राज्य कम सम्पन्न।

राज्य	आर्थिक अनुसंधान समिति का अनुमान	राज्यों के सांख्यिकीय विभागों का अनुमान
	१९५५-५६	१९५५-५६
आन्ध्र	२२९	२२६
आसाम	२६८	२८१
बिहार	१४९	—
गुजरात	२७०	२७५
केरल	२२८	२२८
मध्य प्रदेश	२१६	२३४
मद्रास	२३०	२५७
महाराष्ट्र	२८७ ×	२९२
मैसूर	२०३	—
उड़ीसा	१८७	२४४
पंजाब	२७७	३१६❀
राजस्थान	२३२	—
उत्तर प्रदेश	१७८	११२
पश्चिमी बंगाल	२९५	२६२

× १९५४-५५ का अंक
❀ १९५६-५७ का अंक

गुजरात का आर्थिक विकास

गुजरात के सम्बन्ध में किये गये आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, इस राज्य की बजट-स्थिति अच्छी नहीं है। इसकी प्रति व्यक्ति कर-आमदनी अन्य कई राज्यों से कम है। सूद का बोझ काफी बढ़ गया है और अपने योजना-व्यय के लिए इसे बहुत कुछ केन्द्र पर निर्भर करना पड़ता है।

राज्य के निर्देश पर किये गये तकनीकी व आर्थिक अध्ययन से पता चलता है कि इस स्थिति को सुधारने के लिए भूमिका लगान बढ़ाना होगा और बिक्रीकर अधिक करना होगा।

राज्य के योजना-व्यय के बारे में स्थिति यह है कि राज्य के साधनों और स्रोतों से कुल प्राप्त अनुमानित राशि ३१३ करोड़ रु. है और ५७२ करोड़ रु. की कमी रह जाती है। इस अभाव को भरने के लिए अतिरिक्त कर और केन्द्रीय सरकार से सहायता लेनी होगी। इंजिनीयरी उद्योग ही इस राज्य के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। इसके अन्तर्गत रासायनिक उद्योग की मशीनरी, यातायात का सामान, मशीनी पुर्जे, बिजली के उपकरण और अर्ध-परिष्कृत सामान तैयार किये जा सकते हैं। समिति ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि गुजरात में छोटे पैमानों के इंजिनीयरी उद्योग को जापानी ढंग पर विकसित किया जाए। ये उद्योग परम्परागत कुटीर-उद्योगों की अपेक्षा आधुनिक ढंग के और संगठित इकाइयों के रूप में होने चाहिए। यह सुझाव दिया गया है कि समूची आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य के अनुसार और बुनियादी क्षेत्र में हुई विकास की सम्भावना से, इन निर्माण-उद्योगों के उत्पादन में, इस राज्य में, १७० प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। समिति का यह भी मत है कि साधनों पर आधारित उद्योगों में गुजरात में इन उद्योगों के विकास की अधिक सम्भावनाएं हैं— पेट्रोलियम, पेट्रोलियम-परिष्कार, पेट्रो-रसायन, और सिरेमिक्स, वनस्पति तेल, अन्य कृषि पदार्थों का निर्माण, मछली और जंगलात पर आधारित उद्योग।

समिति ने राज्य के परिवहन के कार्यक्रम को विस्तृत करने पर भी बल दिया है। इसका मुख्य अंग यह है कि अहमदाबाद को झंद के द्वारा कांदला बन्दरगाह से जोड़ दिया जाए। भावनगर और तारापुर के बीच बड़ी लाइन का सम्पर्क बनाया जाए ताकि सीमेंट, सोडा भस्म और

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अन्य उद्योगों का विकास हो सके। सौराष्ट्र में इन उद्योगों के शीघ्र चालू होने के अवसर हैं।

गुजरात में पिछले दशक में विकास के जो प्रयत्न हुए हैं, उनके फलस्वरूप आय और रोजगार के साधन बढ़ गये हैं। राज्य का उत्पादन दूसरी योजना की अवधि में ५.३ प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ रहा है, जब कि देश में यह ३८ प्रतिशत है। वृद्धि की यह ऊंची दर फसलों में बहुत तीव्र गति से वृद्धि के कारण है पर, समिति का यह ख्याल है कि पहले के कम अनुमानों के कारण, यह वृद्धि तेज प्रतीत होती है। राज्य में कार्यक्रम ऐसे बनाने की सम्मति इस समिति ने दी है जिससे राज्य में ५२ प्रतिशत खेती के उत्पादन में, १७० प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन में और ९५ प्रतिशत वृद्धि १९६०-६१ और १९७५-७६ के बीच होनी चाहिए। अच्छे बीजों, उर्वरक और सघन खेती पर जोर देने के लिए कहा गया है। किसान का भला इसी में है कि व्यापारी और नग फसलें अधिक उगायी जाएं। इसमें ३५७ करोड़ रु० लगाने का सुझाव दिया गया है, जिस में २६२ करोड़ रु० राज्य का हिस्सा होगा।

गुजरात का समुद्रतट १ हजार मील लम्बा है। इससे लाभ उठाकर मछली उद्योग को विकसित किया जाना चाहिए। मछली के निर्यात से राज्य को लाभ होगा। इसी प्रकार नौका-यान को प्रोत्साहित करना होगा।

नर्मदा जल विद्युत योजना से गुजरात को लाभ उठाना चाहिए और १०,००० टन का अलुमीनियम प्लांट लगाना चाहिए। जामनगर में शीघ्र ही इसका प्लांट लगने वाला है। समिति का ख्याल है कि १९७५ तक गुजरात में बिजली की मांग बढ़कर ५,३४० मिलियन किलोवाट तक हो जाएगी, जबकि १९६० में १.२६१ मिलियन किलोवाट थी। इसका मतलब है, ३६० प्रतिशत वृद्धि।

उत्तर प्रदेश में योजना की प्रगति

यदि गुजरात राज्य की योजना सम्बन्धी आर्थिक स्थिति बहुत सन्तोष जनक नहीं है, तो उत्तर प्रदेश के भी योजना कार्यों को बहुत सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह विचार प्रकट किया था कि तीसरी योजना के ५ वर्षों में ४९७ करोड़ रुपये की राशि पर्याप्त नहीं होगी। किन्तु इस योजना के पहले तीन वर्षों के अनुभव ने बताया है कि इस छोटी सी राशि का भी पूर्ण उपयोग सम्भवतः नहीं किया जा सकेगा। प्रथम वर्ष के व्यय लक्ष्य ७२.५९ करोड़ रुपये था, लेकिन वास्तविक व्यय ७०.१२ करोड़ रुपये ही हुआ। दूसरे और तीसरे वर्षों में व्यय के लक्ष्य ८८.९८ और १०३.२७ करोड़ रुपये रखे गए, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि ये लक्ष्य भी पूर्ण नहीं होंगे। योजना की प्रगति बहुत अधिक समय ले रही है। इसका कारण सरकारी मशीनरी की अविचार शीलता है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने योजना की प्रगति को अधिक सक्रिय बनाने के लिए समस्त राज्य को चार भागों में—हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून (२) गोरखपुर, देवरिया (३) नैनी, रिहन्द, मुगलसराय और (४) बुलन्दशहर, गाजियाबाद, मेरठ में बांटने का निश्चय किया है। इससे यह आशा की जाती है कि प्रत्येक क्षेत्र में उस क्षेत्र के कर्मचारी अपनी-अपनी क्षेत्र की समस्याओं को जल्दी से जल्दी सुलझाने का प्रयत्न करेंगे और योजना के लक्ष्यों को पूर्ण करने की ओर अधिक ध्यान देंगे।

आदिम जाति की आय

मध्य प्रदेश के आदिम निवासियों के क्षेत्र में नेशनल कौंसिल आफ़ एप्लायड इकनामिक रिसर्च ने एक अध्ययन वहां प्रतिव्यक्ति आय के सम्बन्ध में किया था। इस अध्ययन के अनुसार मध्य प्रदेश के आदिम जाति के लोगों की प्रतिव्यक्ति आय ५० न. पै. है और बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र में भी २९ नं. पै. है। बिलासपुर में तो ६२ नं. पै. से कम दैनिक आय नहीं है। मानडला, बालाघाट और बिलासपुर में आदिम जाति के लोग १७१ रुपया प्रति वर्ष औसतन कमाते हैं। रतलाम, धार, खरगोन और झाबुआ, दुर्ग तथा बस्तर में १६२ रुपये प्रति वर्ष कमाते हैं। इस अध्ययन से भी यह स्पष्ट हो जाता है, कि डा० लोहिया की ३ आना दैनिक आय की स्थापना बहुत भ्रान्तिपूर्ण है।

—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रासायनिक उद्योग का चमत्कार

श्री जगदीशचन्द्र बन्सल

कुछ वर्ष पूर्व संसार के अर्थशास्त्री कहा करते थे कि जो देश ज्यादा सलफ्यूरिक एसिड, ज्यादा कागज तथा ज्यादा साबुन उत्पन्न करेगा, वह अपने को ज्यादा सभ्य बना सकेगा। सलफ्यूरिक एसिड से अनेक रासायनिक चीजें बनती हैं, कागज से ज्यादा संख्या में समाचार पत्र, पुस्तकें आदि छप सकेंगी और साबुन से मनुष्य अपने को अधिक साफरसुथरा रख सकेगा।

वास्तव में सभ्यता के स्तर की पड़ताल करने के लिये अब विविधता इतनी अधिक बढ़ गई है जो उस समय के अर्थशास्त्री सोच भी न सके थे। अगर कुछ वर्ष पूर्व कोई रासायनिक कहता कि उसके कपड़ों का सूट किसी गैस से बनेगा तो जनता आश्चर्य करती। ठंडे देश की जन तके लिये ऊन का भारी मूल्य है। ऊन की वर्तमान रूप में इस्तेमाल करने में हजारों वर्ष लगे। इसकी आवश्यकता की पूर्ति न तो रेशम और न रुई के कपड़े कर सके थे, परन्तु रसायन विद्या की कृपा से वह दिन आ गया, जब उसके बदले की चीज या जिसे उसी की बराबरी का माना जाता है, भारी तादाद में पैदा होने लगी।

आश्चर्यजनक विकास—पिछले बीस वर्ष में रूमानिया ने इस क्षेत्र में जो प्रगति की है, उससे इसके महत्व व बढ़ती हुई लोकप्रियता का पता चलता है। आज इस देश में यह दूसरा बड़ा उद्योग है। प्रथम उद्योग है खनिज द्वितीय महायुद्ध से पूर्व की तुलना में १९६१ के अन्त तक सलफ्यूरिक एसिड का उत्पादन ६ गुना बढ़ा। इससे सुपरफोस्फेटस की पैदावार बढ़ गई, जिसके उपयोग ने कृषि की पैदावार बढ़ाने में सहयोग दिया। साबुन भी चार गुना अधिक बना। कागज का उत्पादन भी इस काल में दुगना हो गया, जिससे पुस्तकों की संख्या ज्यादा प्रकाशित होने लगी। १९६१ में पुस्तकों की साढ़े पांच करोड़ प्रतियां छपी थीं। रासायनिक उद्योग की अन्य आवश्यक चीजों का उत्पादन इस अनुपात से भी अधिक बढ़ा है। रासायनिक खादों का उत्पादन १९५० की तुलना में १२९ गुना बढ़ा। १९५५ की तुलना में कारबन बलैक १८ गुना अधिक बनाया गया।

उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिये इस उद्योग क्षेत्र में नये-नये कल कारखाने खोले गये, क्योंकि द्वितीय युद्ध से पूर्व रूमानिया में यह उद्योग नाम मात्र का था। समस्त देश के औद्योगिक उत्पादन का २.७ प्रतिशत रासायनिक उत्पादन होता था, परन्तु अब इसका नम्बर देश के उद्योग-धन्धों में दूसरा है। रूमानिया की सरकार ने इसके विकास के लिये भारी प्रयत्न किये और खूब पूंजी लगाई थी। गत वर्ष जितनी पूंजी समस्त उद्योगों में लगाई गई, इसका १७.७ प्रतिशत रासायनिक उद्योग में ही रहा। २० कम्बाइन व रासायनिक कारखाने खोले गये और इनमें ६० नये विभाग। पुराने कारखानों में नई मशीनें लगाई गईं। इन जोरदार प्रयत्नों का प्रभाव यह हुआ कि १९३८ की तुलना में रासायनिक उद्योग का उत्पादन १८ गुना बढ़ गया। इस समय यह उद्योग ३५०० प्रकार की चीजें बनाकर देश के राष्ट्रीय उद्योग को आगे बढ़ा रहा है। वर्तमान योजना के अनुसार इन विविध चीजों की संख्या आगामी वर्षों में दुगनी हो जायेगी।

आजकल नाईलोन भारत में अधिकाधिक लोकप्रिय हो रहा है। यह भी रासायनिक उद्योग का फल है। रूमानिया में यह विशाल तादाद में बनाया जा रहा है। यहां के एक कारखाने में यह इतना रोज बनता है जो विषुवत रेखा से १५ गुना अधिक होता है। गत वर्ष यह १६०० टन पैदा हुआ था, जिससे अनेक प्रकार की चीजें जैसे मौजे, बनियान, धागा, सिलेसिलाये कपड़े आदि बनाये गये।

रूमानिया का रासायनिक उद्योग ३०० तरह के रंग बनाता है, जो सभी तापमानों के योग्य होते हैं। यह कपड़ा रंगने और खालों को तैयार करने में भी इस्तेमाल किये जाते हैं। ३०० तरह के पैन्ट, वार्निशें, इनेमिल, ७०० तरह की दवाएं आदि बनती हैं। मानव जीवन का अब शायद ही कोई ऐसा पहलू बचा हो, जिसमें रासायनिक चीजों का कुछ न कुछ उपयोग न होता हो। ● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस मास की आर्थिक घटनाएं

दो प्रश्न

भारत सरकार आजकल जिन प्रश्नों पर विचार कर रही है उनमें से दो हैं, पूंजी बाजार को निम्रित करने के लिए नीति निर्धारण और कारमोह कांफ्रेंस द्वारा बढ़ाये गए जाहजी भाड़ों के सम्बन्ध में कुछ उचित उपायों पर विचार। पहले के अनुसार सरकार कम्पनी कानून में कुछ परिवर्तन करने पर विचार कर रही है, जिससे वह जायन्ट कम्पनियों की व्यवस्था में अधिक नियन्त्रण कर सके। दूसरे के अनुसार भारतीय जहाजरानी को अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे विदेशी कम्पनियां भाड़े के बारे में मन मानी न कर सकें।

चीनी व गन्ना

नए कृषि मन्त्री श्री स्वर्णसिंह के कथनानुसार दूर से मिलों को पहुँचाने वाले गन्ने के दर बढ़ाये जायेंगे। मिलों को गन्ना ठीक पहुँच सके, इसलिए गुड़ और खांडसारी के गन्ने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये जायेंगे। चीनी मिलों को अतिरिक्त उत्पादन पर उत्पादन कर में छूट दी जायगी। किसानों को गन्ने की कीमत ठीक समय पर मिल सके इसकी व्यवस्था की जायेगी।

खाद्य-उत्पादन

श्री सुब्रह्मण्यम इस्पात तथा प्रधान उद्योग मन्त्री के कथनानुसार तीसरी योजना के खाद उत्पादन के लक्ष्य पूर्ण नहीं होंगे। जिन निजी उद्योगों को खाद उत्पादन के लाइसेंस दिए गये थे, वे बिल्कुल असफल हुए हैं। इस लिए योजना आयोग ने भी तीसरी योजना का लक्ष्य १० लाख टन से घटाकर ७॥ लाख टन कर दिया है।

—भारत सरकार ने बकरियों की खालों पर निर्यात कर शिथिल कर दिया है। योजना आयोग कृषि उत्पादन के लिए १८ करोड़ रुपया अधिक लगाने पर विचार कर रहा है।

मोटर उद्योग के लाभ में कमी

पिछले कुछ वर्षों से, विशेषतः चीनी आक्रमण के बाद मोटर निर्माण उद्योग में वृद्धि हुई है। सशस्त्र सेनाओं की गतिविधि में मोटर-यातायात का विशेष महत्व है। यद्यपि मोटरों की मांग बढ़ रही है, पर अब इस उद्योग में लाभ की मात्रा बहुत कम रह गयी है। इसके कारणों में से कुछ यह हैं—(१) निर्माण व्यय में वृद्धि (२) सुरक्षा सेवाओं के लिए सुहय्या किये गये वाहनों पर सरकार की ओर से विशेष रिबेट जारी करना।

अतिरिक्त लाभ कर

भारत की ६ प्रमुख मोटर कम्पनियों का हाल ही में सर्वेक्षण किया गया था। इन कम्पनियों की बिक्री से हुई आय १९६१-६२ में ९४.५७ करोड़ रु० से बढ़कर ९६.५८ करोड़ रु० हो गई और बाद के वर्ष में १०५.६६ करोड़ रु० तक पहुँच गयी। १९६१-६२ में उत्पादन का मूल्य जहां ९६.३३ करोड़ रु० था, वहां १९६२-६३ में बढ़कर १०६.१५ करोड़ रु० हो गया। पर इसके साथ ही कच्चे माल की कीमत निर्माण-व्यय, वेतन और मजदूरी, उत्पादन-शुल्क, उधार और उस पर सूद की मात्रा—इन सब में भी पर्याप्त बढ़ोतरी हो गयी है। ग्रास मुनाफा १९६१-६२ में ९.८७ करोड़ रु० बढ़कर १९६२-६३ में १०.०२ करोड़ रु० हो गया। आय-कर से पहले के लाभ १९६१-६२ में ८.२८ करोड़ रु० से कम होकर १९६२-६३ में ८.०९ करोड़ रु० रह गये। १९६२-६३ में करों में विशेष वृद्धि होने से नेट लाभ जहां १९६१-६२ में ४.३६ करोड़ रु० था, वहां १९६२-६३ में कम होकर वह ३.३३ करोड़ रु० रह गया। चूंकि डिविडेंड में कोई परिवर्तन न आकर वह २.७३ करोड़ रु० ही रहा, इसलिए रिटेंड लाभ १.६३ करोड़ रु० १९६१-६२ से कम होकर १९६२-६३ में कुल ६० लाख ही रह गया। इसका स्पष्ट मतलब यह है कि लाभों का मुख्य भाग करों में खप गया और हिस्सेदार को नेट वापसी बहुत कम मिली।

यह ऐसा व्यापार है जिसमें उधार की राशि बहुत होती है। १९६२-६३ में यह राशि २५.४२ करोड़ रु० थी, जो पेड-अप केपिटल के लगभग समकक्ष ही हैं। इस ऋण-राशि का मुख्य अंश—२०.१८ करोड़ रु०—बैंकों से ही लिया गया था। गत तीन वर्षों से यह स्थिति लगभग ऐसी ही रही है। छः मोटर कम्पनियों के कुल एसेट जहां १९६१-६२ में १३.७७ करोड़ रु० थे, वहां १९६२-६३ में कम होकर ८.०३ करोड़ रु० रह गये।

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सबसे सस्ता सचित्र हिन्दी मासिक

जागृति

जिसे भारत के सभी प्रमुख कवियों,
और कहानीकारों का सहयोग प्राप्त है।

उत्प्रेरक कविताएं, ज्ञानवर्धक लेख, सांस्कृतिक निबंध,
रोचक कहानियां, बाल संसार, साहित्य आगे
बढ़ता है, आदि स्तम्भ

तिरंगा आवरण, अनेकों इकरंगे चित्र
सम्पूर्ण छपाई आर्ट पेपर पर
इस पर भी मूल्य केवल २५ नये पैसे

एजेंटों को ५ से १० प्रतियों पर २५ प्रतिशत और इससे ज्यादा पर ३३⅓ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। डाक का खर्च प्रकाशकों के जिम्मे। एजेन्ट नमूने की प्रति के लिए आज ही लिखें।

—सूचना व प्रकाशन विभाग चण्डीगढ़ (पंजाब)

आरसी

(सचित्र पारिवारिक मासिक)

कहानी * कविता * लेख * कढ़ाई * बुनाई * पाठशाला * माँ और शिशु * ढोलक के गीत * बाल-मन्दिर * चलचित्र-जगत् * पुस्तक परिचय * इसके साथ ही प्रति माह एक कढ़ाई का नमूना उपहार में।

१ प्रति, ५० न० पै० वार्षिक मूल्य ६.०० रु०

आज ही ग्राहक बनिये।

विशेष सूचना—आरसी का अगस्त अंक "राजेन्द्र-स्मृति-अंक" था। एजेन्ट अपनी प्रतियां मंगवा लें।

व्यवस्थापिका, आरसी, श्वाकर टाउन
सिकन्द्राबाद (आ० प्र०)

हिन्दी का एकमात्र
विशिष्ट महिलोपयोगी मासिक

शृङ्गार

- जो सुखी पारिवारिक जीवन का आदर्श पथ-प्रदर्शक है
- जिसे सुप्रसिद्ध लेखिकाओं, लेखकों, पत्रकारों, चित्रकारों कवयित्रियों तथा कवियों का सहयोग प्राप्त है।
- जिसे ५०००० से ऊपर की संख्या में पाठक प्रतिमास पढ़ते हैं।
- जिसकी प्रतियां न्यूज़ एजेन्टों के पास पहुँचते ही समाप्त हो जाती हैं।
- जो महिला जागृति का प्रतीक है। जो सबकी प्रिय पत्रिका है।

वार्षिक : सात रुपये
एक प्रति : ६० नये पैसे

सम्पादका : लावण्य प्रभा
कार्यालय : १३।३७, शक्तिनगर, दिल्ली-६।

खादी पत्रिका

* खादी ग्रामोद्योग तथा सर्वोदय विचार पर विद्वत्तापूर्ण रचनाएँ।
* खादी ग्रामोद्योग आन्दोलन की देशव्यापी जानकारी।
* कविता, लघुकथा, मील के पत्थर, साहित्य समीक्षा, संस्था परिचय।
* सॉरूपकी पृष्ठ आदि स्थायी स्तम्भ।
* आकर्षक मुख पृष्ठ, हाथ कागज पर छपाई।

वार्षिक मूल्य ३) रु., एक प्रति पच्चीस नये पैसे

संपादक—ध्वजाप्रसाद साहू, जवाहिरलाल जैन
राजस्थान खादी संघ, पो. खादीबाग, (जयपुर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद का मुख्य पत्र

स्वस्थ जीवन

प्रधान सम्पादक — श्री राधकृष्ण नेवटिया
प्रबन्ध सम्पादक — श्री धर्मचन्द सरावगी
एक प्रति ५० न० पै० — वार्षिक ५) रुपया मात्र

साहित्य के साथ अपने सुन्दर स्वास्थ्य के लिए कविता, कहानी, संस्मरण तथा डायरी और परिषद की गतिविधि पढ़ें। आज ही पांच रुपया भेजकर ग्राहक बन जाइए। विज्ञापन देकर लाभ उठावें। सहयोगी बन्धु अपनी नवीन कृतियां हमें भेजें।

कार्यालय :—

"जैन हाउस"

८।१ एस्प्लेनेड ईस्ट,
कलकत्ता-१

ग्राम राज

(मास में तीन बार प्रकाशित)

सम्पादक—श्री गोकुलभाई भट्ट

"ग्रामराज बहुत ही शानदार और बहुत ही सुन्दर पत्र निकल रहा है। सब तरह की जानकारी इसमें रहती है। राजस्थान के हर शिक्षित भाई बहन के हाथ में यह पत्रिका होनी चाहिए।"
—विनोबा

वार्षिक चन्दा ३) रु०

कार्यालय का पता :

ग्रामराज, किशोर निवास

जयपुर

उषा

* सामाजिक कहानियां, शिक्षाप्रद कथानक विचारोत्तेजक, मनोरंजक लेख, राशिफल, सरस कविताएं आदि।
* हानिकारक वस्तुओं व अश्लील फिल्मों के विज्ञापन स्वीकार नहीं किये जाते।

—यदि आपने अभी तक उषा नहीं देखी है, तो शीघ्र ही ३२ न. पै. के टिकिट या मनि-आर्डर भेजकर नमूनाँक मंगा देखिये। हमें पूरा विश्वास है कि एक बार 'उषा' को देखने के बाद आप हमेशा के लिए उसके हो जाएंगे।

: अन्य जानकारी के लिए लिखिये :

सचित्र मासिक उषा कार्यालय,

जवाहर मार्ग, इन्दौर।

शीघ्र ही प्रेस में जा रहा है—

न र्म दा

का

पं० बालकृष्ण शर्मा नवीन अंक

इस विशेषांक की सबसे बड़ी विशेषता पत्रकार प्रवर पं० बनारसीदास चतुर्वेदी को लिखे गए उनके व्यक्तिगत पत्रों का प्रकाशन होगा, जो स्व० नवीनजी का अलमस्ती, हंसोड़ वृत्ति और निश्छल स्नेह भाव का एक अत्यन्त मनोहर रूप पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर देंगे।

इस विशेषांक द्वारा नर्मदा का प्रयास नवीन जी के साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और मानवीय व्यक्तिगत विविध पक्षों पर पूरा प्रकाश डालने का है।

इस विशेषांक के सम्पादक हैं :

पं० बनारसीदास चतुर्वेदी • श्री शम्भुनाथ सक्सेना

पृष्ठ संख्या १५०, अनेक व्यक्तिगत व पारिवारिक चित्रों सहित · मूल्य ३ रु०

नर्मदा कार्यालय, नूतन प्रिंटिंग प्रेस,

ग्वालियर (म० प्र०)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संचालक, पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश

की

विज्ञप्ति संख्या ४।२२८० : २७।३३, दिनांक १५

द्वारा

पस्तकालयों के लिए स्वीकृत

सुन्दर पुस्तकें

		रु०	आ०
वेद सार	प्रो० विश्वबन्धु	१	८
प्रभु का प्यारा कौन ? (२) भाग			
सच्चा सन्त			३
सिद्ध साधक कृष्ण			२
जीते जी ही मोक्ष			३
आदर्श कर्मयोग			३
विश्व-शान्ति के पथ पर			१
भारतीय संस्कृति	प्रो० चारुदेव		
बच्चों की देखभाल	प्रिंसिपल बहादुरमल	१२	१
हमारे बच्चे	श्री सन्तराम बी. ए.	३	१३
हमारा समाज		३	
व्यावहारिक ज्ञान		२	१२
फलाहार		१	४
रस-धारा		०	१४
देश-देशान्तर की कहानियां		१	
नये युग की कहानियां		१	१२
गल्प मंजुल	डा० रघुबरदयाल	१	
विशाल भारत का इतिहास	प्रो० वेदव्यास	३	८

१० प्रतिशत कमीशन और ५० रु० से ऊपर के आदर्शों पर १५ प्रतिशत कमीशन।

विश्वेश्वरानन्द पुस्तक भंडार

साधु आश्रम, होशियारपुर, पंजाब

आर्थिक समीक्षा

सम्पादक : श्री हरतीर्थ सिंह

- हिन्दी में अनूठा प्रयास
- आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख
- आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत

भारत के विकास में रुचि रखनेवाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक।

वार्षिक मूल्य : ५ रु० एक प्रति २२ नये पैसे

लिखें—व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, नई दिल्ली

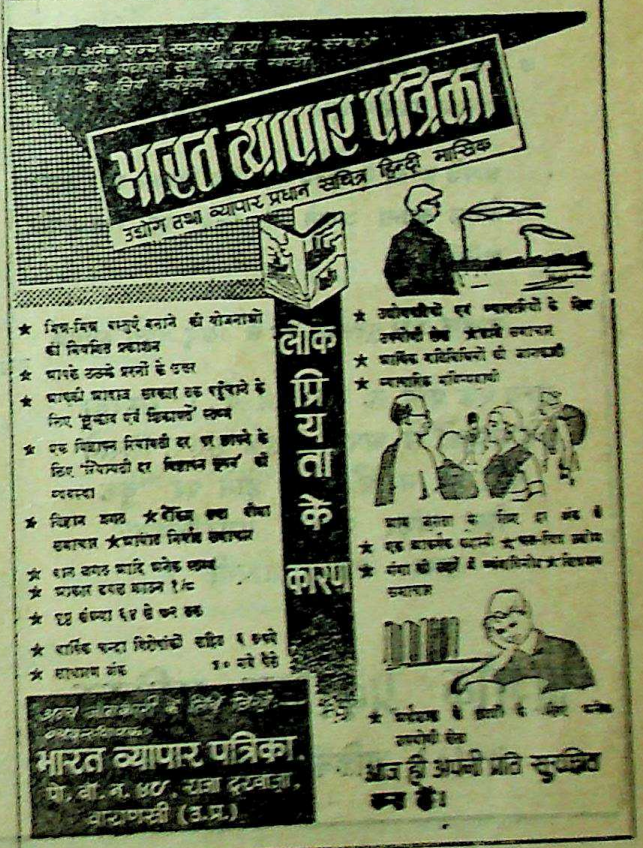

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सुभाषित रत्न-माला

दूसरा संस्करण

सम्पादक : कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

८ वर्ष पूर्व इस पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था और हाथों-हाथ बिक गया था कई वर्षों से यह पुस्तक अप्राप्य थी और इसकी मांग निरन्तर बढ़ रही थी। अब परिवर्धित संस्करण आकर्षक रूप सज्जा में प्रकाशित हुआ है। इस संग्रह में पढ़िये —

- वैदिक एवं संस्कृत-साहित्य के अगाध भंडार से चुने गये ऐसे सरल सुन्दर श्लोक और मंत्र, जिन्हें छोटे-बच्चे भी सुविधा के साथ कंठस्थ कर सकते हैं।
- प्रत्येक श्लोक और मंत्र का सरल सुबोध हिन्दी में अर्थ।
- पुस्तक के अंत में अर्थ-सहित कुछ ऐसी सूक्तियां, जिनका उपयोग छात्र अपने निबन्धों में कर सकें।

आपके बच्चों के स्वस्थ मानसिक विकास और उनमें नैतिक चेतना जगाने के लिए यह रत्न-माला अनिवार्य है।

उपहार और पुरस्कार देने के लिए बहुत उपयुक्त।

मूल्य एक प्रति रु. १.१५ न. पै.। "सम्पदा" के ग्राहकों से अपनी ग्राहक संख्या लिखने और ८५ न. पै. प्राप्त होने पर "बुक पोस्ट अंडर पोस्टल सार्टिफिकेट" द्वारा भेजी जाएगी।

अशोक प्रकाशन मन्दिर

२८/११ शक्तिनगर, दिल्ली-६

भारत की उद्योग नीति

भारत सरकार ने १९४८ में जो उद्योग नीति निर्धारित की थी, १९५६ में संशोधन के बाद से वही आज भी हमारी उद्योग-नीति का आधार है। इसलिए उद्योग नीति को समझाने के लिए उक्त पुस्तिका का अध्ययन बहुत लाभदायक होगा।

मूल्य : डाक-व्यय सहित ७५ न. पै.

लेखक : प्रो० रामनरेश लाल

"सम्पदा" के ग्राहकों को अपनी ग्राहक संख्या लिखने और ६० न. पै. का टिकट भेजने पर रियायती मूल्य में यह पुस्तक भेजी जाएगी। वी० पी० से नहीं भेजी जाएगी।

अशोक प्रकाशन मन्दिर,

२८/११, शक्तिनगर, दिल्ली-६

जीवन साहित्य

हिन्दी के उन मासिक पत्रों में से है, जो—

* लोकरुचि को नीचे नहीं ऊपर ले जाते हैं,
* मानव-मानव से लड़ाते नहीं, मिलाते हैं।
* आर्थिक लाभ के आगे झुकते नहीं, सेवा के कठोर पथ पर चलते हैं।

जीवन साहित्य की सात्विक सामग्री को छोटे-बड़े, स्त्री-बच्चे सब निःसंकोच पढ़ सकते हैं। उसके विशेषांक एक से एक बढ़कर होते हैं।

वार्षिक शुल्क ४) रु. भेजकर ग्राहक बन जाइये

ग्राहक बनने पर मंडल की पुस्तकों पर आपको कमीशन पाने की भी सुविधा हो जायगी।

सस्ता साहित्य मंडल

नई दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एक मनोवैज्ञानिक बात....

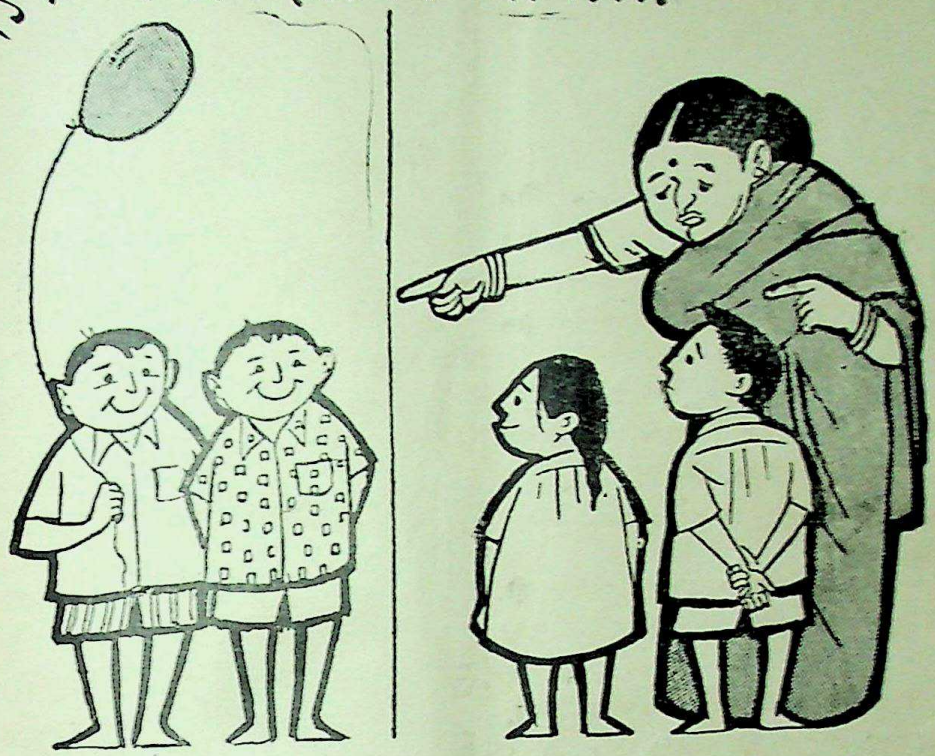

मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि हमें अपने बच्चों की दूसरों के बच्चों से तुलना नहीं करनी चाहिए। उनके अनुसार इससे बच्चों के स्वाभाविक विकास में बाधा पहुंचती है। यही बात मेट्रिक बाटों के सम्बन्ध में है। नन्हे मुन्नों और मेट्रिक बाटों के गुणों को परखिये और उन्हें ज्यों का त्यों अपनाइये। मेट्रिक बाटों का उनके मूल्य के अनुसार ही इस्तेमाल कीजिए जैसे १०० ग्राम, २०० ग्राम, ५०० ग्राम व १ किलोग्राम।

मेट्रिक तोल का जोड़ तोड़ करके सेर न बनाइये।

इसमें आपका समय व्यर्थ ही नष्ट होगा और लेन-देन में नुकसान हो सकता है।

सही और सुविधाजनक लेन-देन के लिए

पूर्ण इकाइयों में

मेट्रिक बाटों का प्रयोग कीजिए

डी ए ६३/७

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
Regd. No. D. 361

क्या आपको फूलों वाले प्रिन्ट, 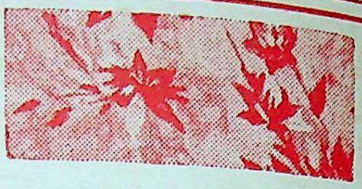 सुन्दर

धारियां, 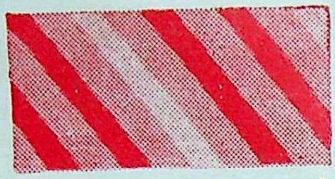 हलके रंग पसन्द हैं ? 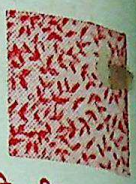

चाहे जो आपका चुनाव हो, हमारे यहाँ सभी कुछ उपलब्ध है। डी सी एम की साड़ियाँ हलकी, सुन्दर व टिकाऊ होती हैं...और कितनी सस्ती—रु० १२.३४ से रु० १८.४६ प्रति साड़ी.

डी सी एम के सभी रिटेल स्टोरों, व्होलसेल एजेन्टों व स्टाकिस्टों से प्राप्य हैं.

डी सी एम कपड़ों की सुन्दरता व मज़बूती का प्रतीक

दि दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कं० लि०, दिल्ली.

JWT/DCM 2741 M

सम्पादक—कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा नवचेतन प्रेस (प्रा०) लि० (लीजिज ऑफ अर्जुन प्रेस) दिल्ली-६ से मुद्रित
अशोक प्रकाशन मन्दिर २८/११, शक्तिनगर, दिल्ली-६ से प्रकाशित।
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा

वर्ष : १२ अंक : १०

मूल्य
न. पै.

अशोक प्रकाशन मन्दिर शक्ति नगर, दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद का मुख्य पत्र

स्वस्थ जीवन

प्रधान सम्पादक — श्री राधकृष्ण नेवटिया
प्रबन्ध सम्पादक — श्री धर्मचन्द सरावगी
एक प्रति ५० न० पै० — वार्षिक ५) रुपया मात्र

साहित्य के साथ अपने सुन्दर स्वास्थ्य के लिए कविता, कहानी, संस्मरण तथा डायरी और परिषद की गतिविधि पढ़ें। आज ही पांच रुपया भेजकर ग्राहक बन जाइए। विज्ञापन देकर लाभ उठावें। सहयोगी बन्धु अपनी नवीन कृतियां हमें भेजें।

कार्यालय :—

"जैन हाउस"

८।१ एस्प्लेनेड ईस्ट,
कलकत्ता-१

ग्राम राज

(मास में तीन बार प्रकाशित)

सम्पादक—श्री गोकुलभाई भट्ट

"ग्रामराज बहुत ही शानदार और बहुत ही सुन्दर पत्र निकल रहा है। सब तरह की जानकारी इसमें रहती है। राजस्थान के हर शिक्षित भाई बहन के हाथ में यह पत्रिका होनी चाहिए।"

— विनोबा

वार्षिक चन्दा ३) रु०

कार्यालय का पता :

ग्रामराज, किशोर निवास

जयपुर

उषा

* सामाजिक कहानियां, शिक्षाप्रद कथानक विचारोत्तेजक, मनोरंजक लेख, राशिफल, सरस कविताएं आदि।

* हानिकारक वस्तुओं व अश्लील फिल्मों के विज्ञापन स्वीकार नहीं किये जाते।

—यदि आपने अभी तक उषा नहीं देखी है, तो शीघ्र ही ३२ न. पै. के टिकिट या मनि-आर्डर भेजकर नमूनाँक मंगा देखिये। हमें पूरा विश्वास है कि एक बार 'उषा' को देखने के बाद आप हमेशा के लिए उसके हो जाएंगे।

: अन्य जानकारी के लिए लिखिये :

सचित्र मासिक उषा कार्यालय,

जवाहर मार्ग, इन्दौर।

शीघ्र ही प्रेस में जा रहा है—

न र्म दा

का

पं० बालकृष्ण शर्मा नवीन अंक

इस विशेषांक की सबसे बड़ी विशेषता पत्रकार प्रवर पं० बनारसीदास चतुर्वेदी को लिखे गए उनके व्यक्तिगत पत्रों का प्रकाशन होगा, जो स्व० नवीनजी का अलमस्ती, हंसोड़ वृत्ति और निश्छल स्नेह भाव का एक अत्यन्त मनोहर रूप पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर देंगे।

इस विशेषांक द्वारा नर्मदा का प्रयास नवीन जी के साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और मानवीय व्यक्तिगत विविध पक्षों पर पूरा प्रकाश डालने का है।

इस विशेषांक के सम्पादक हैं :

पं० बनारसीदास चतुर्वेदी • श्री शम्भुनाथ सक्सेना

पृष्ठ संख्या १५०, अनेक व्यक्तिगत व पारिवारिक चित्रों सहित · · मूल्य ३ रु०

नर्मदा कार्यालय, नूतन प्रिंटिंग प्रेस,

ग्वालियर (म० प्र०)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संकट काल में आपका सहयोग

देश सेवा का अवसर सभी के लिए

किसान :

* अधिक उत्पादन करें
* ग्राम रक्षा दल के सदस्य बनें
* श्रम बैंक में योग-दान करें
* सहकारिता को अपनायें

मजदूर :

* खूब उत्पादन बढ़ायें
* हड़ताल न करें
* विवादों को बातचीत से सुलझायें

व्यापारी :

* मुनाफा खोरी न करें
* माल का अनुचित संग्रह न करें
* कीमतें न बढ़ायें

महिलाएं :

* फिजूल खर्ची न करें
* स्वर्ण दान करें
* गृह उद्योगों में भाग लें
* बालकों को राष्ट्र प्रेम सिखायें

सामान्य नागरिक :

* होमगार्ड्स के सदस्य बनें
* सेना में भर्ती होवें

●●

राजस्थान सरकार द्वारा प्रचारित

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विषय-सूची

सं०	विषय	लेखक	क्रम संख्या
१.	अन्तर्राष्ट्रीय समृद्धि के लिए विचारणा	सम्पादक	३८४
२.	सम्पादकीय टिप्पणियां		३८५
३.	देश की आय अरबों रु० बढ़ सकती है !	श्री उ० न० ढेबर	३९१
४.	ये रहीं हमारी पंचवर्षीय योजनाएं !	आचार्य विनोबा	३९३
५.	मलयेशिया व उसकी आर्थिक स्थिति	कृष्णचन्द्र विद्यालंकार	३९४
६.	आधुनिक अर्थशास्त्र के क्रान्तिकाल—१	श्री कृष्णदत्त भट्ट	३९६
७.	तीसरी योजना में उद्योगों की प्रगति		३९९
८.	सांख्यिकी; उत्पादन कर में वृद्धि : कृषि से आय मित्र देशों से सहायता		४०२
९.	देश का उपेक्षित, परन्तु महत्त्वपूर्ण वर्ग	श्री ब्रजभूषण सरन	४०३
१०.	पोलैण्ड व भारत के आर्थिक सम्बन्ध		४०४
११.	दिल्ली उद्योग की दो समस्याएं	श्री भीकराम जैन व श्री एस० पी० बरमानी	४०५
१२.	अतिलाभ कर के आर्थिक परिणाम	श्री धीरजलाल मगनलाल	४०७
१३.	रेलों में डीजलीकरण	श्री सरदारमल जैन	४०९
१४.	सुरक्षित भण्डारों से अन्न मूल्य का नियंत्रण	श्री स० का० पाटिल	४११
१५.	विज्ञान से अमेरिका में कृषि क्रान्ति	बायरन टी० शा	४१३
१६.	विदेशी यात्रियों का व्यवसाय	श्री राजबहादुर	४१५
१७.	दिल्ली में चिटफण्ड और वित्त कम्पनियां	श्री आर० चड्ढा	४१७
१८.	श्रमिक वर्ग प्रबन्ध में भागीदार हो	श्री खण्डूभाई देसाई	४१८
१९.	अर्थवृत्तचयन—राष्ट्रीय आय के प्रवाह, यूनिटट्रस्ट, अति उत्पादन भी एक समस्या, चीनी मंहगी क्यों ?		४२०
२०.	राज्यों की आर्थिक गतिविधि—राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आदि		४२४
२१.	विविध आर्थिक प्रश्नों की चर्चा		४२९
२२.	इस मास की आर्थिक घटनाएं		४३८

●

सम्पदा का वार्षिक मूल्य : ८.५० रु०

टैलिफोन नं० २२५८७३ प्रति अंक मूल्य : ०.८० रु०

वी० पी० से मंगाने पर ७५ न. पै. का खर्च अधिक पड़ता है ।

इसलिए मनीआर्डर से ही रुपया भेजें ।

मैनेजर—सम्पदा २८/११ शक्तिनगर, दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वर्ष : १२
अंक : १०
अक्तूबर : १९६३

सम्पदा

अन्तर्राष्ट्रीय समृद्धि के लिए गंभीर विचारणा

शान्ति की तरह से समृद्धि भी अविभाज्य है, यह उक्ति आज बहुत प्रसिद्ध हो गई है। दुनिया भर के अर्थ-शास्त्री इस सिद्धान्त को मानते हैं। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकासोन्मुख देशों की सहायता देने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की थी। इस बैंक की सहायता के लिए ही राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्थाओं की स्थापना की गई थी। इन सबकी ओर से विकासशील देशों को अपनी विकास योजनाओं की पूर्ति के लिए सहायता दी जा रही है। यह सहायता करोड़ों डालरों में है। भारत भी इनसे पूरा लाभ उठा रहा है। १९६२-६३ में ही इन संस्थाओं से भारत को २०.८ करोड़ डालर मिले। अन्य देशों को भी ये संस्थायें करोड़ों रुपया दे रही हैं। वर्ल्ड बैंक ने १९६२-६३ में ही विभिन्न देशों को ४४.८६ करोड़ डालर ऋण दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने भारत को ३० जून १९६३ तक करीब ४ करोड़ ८५ लाख डालर दिया है। अन्य देशों को भी समय-समय पर सहायता मिली है। परन्तु अफ्रीका के बीसियों राष्ट्रों के स्वतन्त्र होने के बाद तथा एशियाई देशों ने जिस तरह अपनी विकास योजनाएं बनानी शुरू की हैं, उसे देखते हुए विश्व कोष और तत्सम्बन्धी दूसरी संस्थाओं का भारी खजाना भी कम पड़ रहा है। ये संस्थाएं एक नियत मात्रा से अधिक तो सहायता नहीं दे सकतीं, और विशेषकर उस अवस्था में, जबकि मांगने वाले देश बहुत अधिक हों। इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ने यह आवश्यक समझा कि वह अपने सदस्य सम्पन्न देशों से कुछ और रुपया ले। विभिन्न सम्पन्न देशों से ७५ करोड़ डालर सदस्य कोष में देने के लिए ऋण की मांग की गई है। कुछ डिबैन्चर भी जारी किये गये हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी, इटली, स्वीडन और जापान ने अपनी बहुत-सी मुद्रा और स्वर्ण अन्तर्राष्ट्रीय कोष को प्रयोग के लिए दे भी दिये हैं। वस्तुतः इन सब राष्ट्रों का हित भी इस बात में है कि विकासोन्मुख देश शीघ्र से शीघ्र आर्थिक विकास कर लें, ताकि वे उन राष्ट्रों से ली हुई राशि वापस करने की स्थिति में हो सकें। कर्जदार को अपना कर्जा चुकाने की क्षमता ही यदि न होगी तो वह देनदारों को कैसे दे सकेगा। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए यदि वे समर्थ नहीं होंगे तो विकसित देशों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यही कारण है कि ये अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें आज गम्भीरता से अपने वित्तीय कोष बढ़ाने और उन्हें विकासोन्मुख देशों में वितरित करने के लिए विचार विनिमय कर रही हैं।

विकासोन्मुख देशों की आवश्यकतायें अनेक प्रकार की हैं। आज उन्हें कृषि के विकास की सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि विकासोन्मुख देशों की अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर करती है। दूसरी आवश्यकता उद्योगों को

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दीर्घकालीन ऋण देने या सहयोग की है। विभिन्न देशों के उद्योगपतियों के द्वारा विकासोन्मुख देशों के विकास में पूंजी लगाने की आवश्यकता भी अनुभव की जा रही है। और यह पूंजी अथवा ऋण दीर्घकालीन होने चाहिएं। आज दिक्कत यह है कि विदेशी उद्योगपति यह चाहते हैं कि किसी निजी उद्योग में पूंजी लगाने या ऋण के रूप में सहायता करने से पहले उन्हें सरकार द्वारा गारण्टी मिलनी चाहिए। किन्तु विभिन्न देशों की सरकारें यह गारंटी देने में संकोच करती हैं। इसलिए भी विश्व मुद्रा कोष को बढ़ाने की अधिक आवश्यकता है। इसलिए कोष के सदस्यों से यह अनुरोध किया जा रहा है, कि वे कोष को बढ़ाने में अपना योगदान अधिक उत्साह से करें। आशा की जानी चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की यह प्रवृत्ति विकासोन्मुख देशों के आर्थिक विकास में बहुत सहायक होगी।

लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति के सुधार से ही अविकसित देशों की समस्या हल होने वाली नहीं है। विकासोन्मुख देशों को सहायता देने के लिए यह आवश्यक है, कि उन्हें जो सहायता दी जाय, वह कम ब्याज दर पर दी जाय और उसे चुकाने की अवधि लम्बी हो। दूसरी आवश्यकता यह है कि विकसित देश अविकसित देशों से अधिक से अधिक माल का आयात करें। सहायता नहीं, व्यापार (ट्रेड, नाट एड) असल में अविकसित देशों की विदेशी मुद्रा की समस्या को हल कर सकता है। उक्त सम्मेलन में ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी और जापान आदि देशों ने अधिक उदार शर्तों पर अधिक से अधिक ऋण देने पर सहमति प्रकट की है। उक्त निश्चयों का परिणाम निकट भविष्य में प्रकट होगा। भारत के प्रतिनिधि श्री झा का इन निश्चयों में प्रमुख भाग रहा। उन्होंने यह भी आशा प्रकट की है, कि भारत को अब अधिक सहायता मिलेगी। ● ●

निर्यात वृद्धि कैसे हो ?

आज निर्यात वृद्धि की समस्या विकट रूप से प्रस्तुत है। सरकार ने एक नारा लगाया है कि निर्यात करो या नष्ट हो जाओ। किन्तु हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि निर्यात वृद्धि केवल हमारे चाहने से नहीं होगी। अनेक ऐसी परिस्थितियां होती हैं, जिन पर हमारा कोई वश नहीं होता। हमारी तरह अन्य देश भी स्वावलम्बी होना चाहते हैं और इसलिए वे अपने अपने उद्योग के विकास के लिए भारतीय माल पर भी तटकर आदि प्रतिबन्ध यदि लगावें, तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता।

भारत के वस्त्र निर्यात में ब्रिटेन बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। ब्रिटेन के साथ भारत का एक समझौता कुछ वर्ष पूर्व हुआ था, उसके अनुसार भारत प्रतिवर्ष ब्रिटेन को लाखों रुपये का कपड़ा भेजता है। किन्तु अब ब्रिटेन में यह मांग निरन्तर बढ़ रही है, कि भारतीय वस्त्र के आयात पर वह प्रतिबन्ध लगाया जाय। पुराने समझौते की अवधि १९६५ में समाप्त हो जावेगी, इसलिए भारत का व्यापारिक मण्डल श्री कस्तूर भाई लाल भाई के नेतृत्व में ब्रिटेन गया था। वर्तमान समझौते के अनुसार भारत ने यह वचन दिया था, कि वह १९.५ करोड़ गज से ज्यादा कपड़ा ब्रिटेन को नहीं भेजेगा। यह ठीक है, कि हम इतना कपड़ा भी निर्यात नहीं कर पा रहे। हमारे वस्त्र का निर्यात निरन्तर कम हो रहा है। सूती कपड़े के निर्यात से भारत को १९५०-५१ में ११८ करोड़ रुपये की आय हुई थी, जबकि १९६२-६३ में कुल आय ४६ करोड़ रुपये ही की हुई। यही हाल जूट का है। उक्त दोनों वर्षों में जूट निर्यात के अंक क्रमशः २६० करोड़ और १५५ करोड़ रुपये हैं। ब्रिटेन और अन्य देश इस समय जो रुख अपना रहे हैं, उससे यह भय उपस्थित हो गया है, कि हमारा वस्त्र-निर्यात और भी कम न हो जाये। ब्रिटेन से की जाने वाली बातचीत अभी कुछ समय के लिए स्थगित हो गई है। यद्यपि यूरोप के विकसित देशों ने अविकसित देशों से अधिक वस्त्र मंगाने का वचन दिया था, तथापि वे अपने वचन के पालन में उत्सुक नहीं हैं। स्वयं अमेरिका भी, जो उक्त सिद्धान्त का प्रबल समर्थक था, भारतीय वस्त्र अधिक मात्रा में मगाने को तैयार नहीं है। वह तो १९५९-६० के स्तर पर सवा तीन करोड़ गज कपड़ा भी मंगाना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में भारतीय वस्त्र उद्योग के सामने एक विकट समस्या है। फैडरेशन ऑफ इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अध्यक्ष श्री भरतराम ने अपने एक भाषण में निर्यात की समस्याओं को हल करने के लिए चार उपाय बताये हैं। इनमें सबसे अधिक महत्व-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पूर्ण उपाय यह है, कि हम दुनिया के बाजार में प्रतियोगितात्मक मूल्य पर पदार्थों का उत्पादन कर सकें और इसके लिए सरकार की सहायता अनिवार्य है। किन्तु उसके लिए जहां हमारी मशीनरी में पूर्ण आधुनिकीकरण आवश्यक है, वहां यह भी आवश्यक है कि हमारे उद्योगों का कच्चा माल हमें सस्ता पड़े, और इसके लिए हमारी कृषि का विकास अनिवार्य है। भारत में कपास की प्रति एकड़ उपज १२० पौंड के लगभग है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में ४३८ पौंड है। अमेरिका जैसे देशों से कपास मंगा कर जापान और हांगकांग अधिक सस्ता कपड़ा बेच सकते हैं।

निर्यात के बढ़ाने के लिए जनता का सहयोग भी अनिवार्य है। यदि हम स्वयं कारखानों में उत्पादित वस्त्र, चीनी तथा अनेक वस्तुओं के उपयोग पर कुछ नियन्त्रण लगा दें तो अतिरिक्त वस्तुएं विदेशों में आसानी से जा सकेंगी। ब्रिटेन ने युद्धोत्तर काल में स्वयं कष्ट सहन और त्याग का एक आदर्श रखा था। उसी के कारण वह अपने निर्यात को बहुत बढ़ा सका। कभी कभी सरकार देश में खपने वाली अनेक वस्तुओं पर उत्पादन कर बढ़ा कर देश में उपभोग को सीमित करना चाहती है। किन्तु इसमें जनता का सहयोग उसे प्राप्त नहीं होता। श्री भरतराम ने इसीलिए निर्यात के बढ़ाने के लिए आवश्यक त्याग की जन साधारण द्वारा स्वीकृति को आवश्यक बताया है। परन्तु क्या हममें राष्ट्रीयता की ऐसी प्रबल भावना विद्यमान् भी है, या नहीं?

● ●

रूस में कृषि उत्पादन की समस्या

पिछले महीनों से रूस से जो समाचार आ रहे हैं, वे हमें एक नई दिशा की ओर सोचने के लिए विवश करते हैं। रूस ने कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक साधनों का पूर्ण उपयोग किया है। वहां बड़े-बड़े ट्रैक्टर, कम्बाइन, रासायनिक खाद, सुधरे हुए बीज तथा अन्य वैज्ञानिक उपकरण भारी मात्रा में प्रयुक्त किये जा रहे हैं। फिर भी वहां के अधिकारियों को चिन्ता है कि उनके कृषि लक्ष्य पूर्ण नहीं हो रहे और अपनी जनता के पेट भरने के लिये रूस कैनेडा, फ्रांस, आस्ट्रेलिया तथा रूमानिया से आटा या गेहूँ लेना रहा पड़ है। यह भी सम्भव है कि वह अमेरिका से भी गेहूँ लेने की बात करे। स्थिति इतनी गम्भीर है कि एक किसान को बकरी के लिए रोटी खरीदने पर जेल की सजा दी गई है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रूस की आबादी भारत की आधी से कम २१-२२ करोड़ है और उस के पास विस्तृत भूखण्ड है, जो भारत से कई गुणा है, फिर भी कृषि की दृष्टि से वह स्वावलम्बी नहीं हो रहा।

इस स्थिति पर विचार करते हुए अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। आखिर रूस जैसे उन्नत देश को कृषि उत्पादन में सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही? क्या कृषि का वैज्ञानिक व यांत्रिकीकरण ही सफल नहीं हो रहा? क्या वहां की भूमि नीति ही उत्पादन में बाधक है अथवा वहां कृषि नीति को चलाने वाली सरकारी मशीनरी ही कमजोर है? जब अमरीका, जर्मनी आदि विज्ञान की सहायता से कृषि का उत्पादन निरन्तर बढ़ा रहे हैं, तब रूस में भी विज्ञान सफल न हो, यह मानने में संकोच होता है। रूस ने तो बड़े-बड़े अनुपजाऊ प्रदेशों को लहलहाते खेतों में बदल दिया है और वहां सैंकड़ों मील लम्बे फार्म बन गये हैं, जहां, सिंचाई की सुविधाएं भी अब उपलब्ध होने लगी हैं। वहां ऐसे बड़े-बड़े यंत्रों की भी कमी नहीं है, जो गहरी जुताई कर सकते हैं। तब प्रश्न यह रह जाता है, कि वहां की कृषि-पद्धति में ही क्या कोई दोष नहीं है? वहां कृषि भूमि किसानों की नहीं है। वह सब सरकार की है और सरकार बड़े-बड़े सामूहिक खेत बनाकर किसानों से खेती कराती है। किस खेत में कौन-सी फसल बोई जाय, कब और कैसे बोई जाय, कब सिंचाई हो और कब कटाई हो, आदि का निर्णय सरकारी अधिकारी ही करते हैं। किसानों को अपने प्रयोग के लिए जो थोड़ी बहुत जमीन दी जाती है, उसमें कहीं अधिक उत्पादन होता है, कहीं अधिक मुर्गियां अण्डे देती हैं, और कहीं अधिक सूअर पाले जाते हैं। क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि जब भूमि और भूमि उपज से किसान का अपना स्वामित्व सम्बन्ध हो तो किसान अधिक रुचि और परिश्रम से काम करता है। यदि इस सत्य को हम स्वीकार कर लें, तो रूस में पैदावार की कमी का एक कारण समझ में आ जाता है। एक कारण यह कहा जा सकता है, कि रूस के सरकारी कर्मचारी कुशल न हों और उनके गलत निश्चयों के कारण ही पैदावार कम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

होती है। रूस में मजबूत शासन तंत्र के होते हुए यह भी मानने को जी नहीं करता। और यदि यह मान भी लिया जाय तो हमें यह सोचना चाहिए कि कुछ सरकारी अफसरों के गलत निर्णय का परिणाम कितना प्रतिकूल हो सकता है। इसलिए केन्द्रीकरण की अपेक्षा विकेन्द्रीकरण का अपनाना ज्यादा लाभकारी होगा। इस विकेन्द्रीकरण के साथ यदि किसानों में ममत्व की बुद्धि पैदा कर दी जाय तो वे वैज्ञानिक साधनों का सहयोग पाकर निःसन्देह कृषि उत्पादन की समस्या को सुलझा सकेंगे। ● ●

विज्ञान का प्रयोग एक सीमा तक

पाठक इस अंक में अन्यत्र क्रमशः अमेरिका की कृषि में क्रान्ति तथा अत्युत्पादन भी एक समस्या नामक लेख व टिप्पणी पढ़ेंगे। हम उनकी ओर अपने पाठकों और विचारकों का ध्यान खींचना चाहते हैं। आज अमेरिका की १०प्रतिशत जनता ही वहां कृषि सम्बन्धी समस्त आवश्यकताएं पूर्ण कर सकती है। जिस फसल को पैदा करने में ६ महीने लगते थे, अब विज्ञान की सहायता से वह बहुत कम समय में तैयार हो जाती है। अब मुर्गियां २-२ सौ तक अण्डे देने लगी हैं और भेड़ों पर ऊन भी कई गुणा आने लगी हैं। दक्षिणी फ्रांस में भी बहुत थोड़े लोगों ने अंगूरों की इतनी फसल बोई और इतनी शराब बनाई कि वह समस्त देश के लिए पर्याप्त है। आज फ्रांस के किसानों के सामने यह समस्या पैदा हो गई कि वे अपनी पैदावार की खपत कैसे करेंगे?

विज्ञान के द्वारा अति-उत्पादन भी एक सीमा तक युक्ति-युक्त कहा जा सकता है। उत्पादनमात्र की अन्धाधुन्ध वृद्धि हमारा लक्ष्य नहीं हो सकती। वह तो हमारी आवश्यकता पूर्ति का एक साधन-मात्र है। उसको लक्ष्य मान लेना गलती है, और फिर भारत में तो स्थिति ही दूसरी है। यहां श्रम शक्ति को आजीविका देने का प्रश्न भी है। यदि विज्ञान की मशीनरी हमारे देश के नागरिकों की ही रोजी छीन ले तो यह किसी तरह वांछनीय नहीं है। इस लिए हमें कृषि उत्पादन के लिए विज्ञान का प्रयोग एक सीमा तक ही करना पड़ेगा। बिना विवेक के विज्ञान का अधिकाधिक प्रयोग एक नई समस्या उत्पन्न कर देता है, जो आज की समस्या से भी अधिक विकट हो सकती है।

चौथी योजना के दो उद्देश्य

तीसरी पंचवर्षीय योजना की आधी अवधि समाप्त हो चुकी है और २-२॥ वर्ष बाद ही चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हो जायगी। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि योजना आयोग चौथी पंचवर्षीय योजना के निर्माण में प्रवृत्त हो। इसके लिए योजना आयोग की ओर से नियुक्त २६ कार्यकारी मण्डल अध्ययन भी कर रहे हैं। इन मण्डलों की ओर से चौथी योजना की अवधि में विभिन्न उद्योगों के ऊंचे ऊंचे लक्ष्य भी निर्धारित किये जा रहे हैं। इस्पात सम्बन्ध कार्यकारी मण्डल ने चौथी योजना में इस्पात उत्पादन का लक्ष्य २०० लाख टन रखा है। इसी तरह कृषि उत्पादन के भी लक्ष्य बहुत ऊंचे रखे जा रहे हैं।

पिछले दिनों संसद् में इस बात पर बहुत बहस हुई थी कि प्रति व्यक्ति भारत में कितनी आय होती है। डाक्टर लोहिया ने ६० प्रतिशत लोगों की आय ३ आना दैनिक बता कर देश के विचारकों और प्रशासकों को झकझोर दिया था। यद्यपि सरकार ने ६० प्रतिशत की आय ७॥ आना प्रतिदिन बताई थी, तथापि देश में यह अत्यन्त गम्भीरता पूर्वक अनुभव किया गया कि हमारी आय बहुत कम है। इसलिए स्वभावतः योजना आयोग प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ाने की दिशा में विचार कर रहा है। योजना आयोग के सदस्य श्री श्रीमन्नारायण ने आगामी दो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि के लिए निर्धारित दो मुख्य लक्ष्यों की घोषणा की है। एक तो यह है कि प्रति परिवार निम्नतम आय १०० रुपया मासिक अथवा २० रुपया प्रति व्यक्ति हो जाय। इसका अर्थ यह है कि १० आना दैनिक प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए। उन्होंने दूसरा उद्देश्य बताया है कि जो काम करना चाहें, उन्हें उपयोगी काम अवश्य मिले। योजना आयोग ने वस्तुतः पहली बार जनता के लिए आय की क्षमता का निम्नतम स्तर अपने जिम्मे करने का निश्चय किया है। आज जो स्थिति है, उसे देखते हुए १० आना दैनिक के अत्यन्त सामान्य लक्ष्य भी बहुत ऊंचे दीखते हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या हम ये लक्ष्य भी पूर्ण कर सकेंगे? इसी अंक में अन्यत्र प्रकाशित लेख से पाठक जान जायेंगे,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कि तीसरी योजना के अनेक लक्ष्य अभी तक अपूर्ण हैं और कई परियोजनाओं को चौथी योजना में ही पूर्ण करने की बात की जाने लगी है। ● ●

केन्द्र में विवादों का समाधान

भारत के नये गृहमंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा ने नये विभाग का कार्य सम्भालते ही जो एक सुन्दर निश्चय किया है, वह है सरकारी कर्मचारियों के विवादों के हल करने की व्यवस्था। इस निश्चय के अनुसार सरकारी कर्मचारियों और सरकार में जो विवाद उत्पन्न होंगे, उनका निर्णय कराने के लिए वे हड़ताल नहीं करेंगे। उनसे हड़ताल का अधिकार छीना तो नहीं गया है लेकिन कर्मचारी संघों ने स्वयं हड़ताल न करने का निश्चय किया है। अब पारस्परिक विवाद संयुक्त परामर्श से हल किये जायेंगे। एक संयुक्त राष्ट्रीय परिषद् होगी, जिसमें कर्मचारियों और सरकार के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। यह परिषद् न्यूनतम वेतन, महंगाई भत्ता और निम्न कर्मचारियों के वेतन क्रम आदि के मामलों पर विचार करेगी। कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, उनकी कुशलता और काम का ऊंचा स्तर आदि भी इस विचार परिषद् का काम होगा। यदि संयुक्त परिषद् में कोई निर्णय न हुआ तो एक पंचमण्डल की नियुक्ति की जायगी, जिसका निर्णय दोनों पक्षों को माननीय होगा। प्रशासन कर्मचारियों के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक कर्मचारियों के लिए भी ऐसी समिति नियुक्त की जायगी।

'सम्पदा' के पाठक सरकारी कर्मचारियों की उस हड़ताल को नहीं भूले होंगे, जो २-३ वर्ष पहले जुलाई, १९६० में कुछ राजनीतिक नेताओं ने संगठित की थी, परन्तु जनता की सहानुभूति न मिलने के कारण वह विफल हो गई थी। यद्यपि यह हड़ताल सफल नहीं हुई थी, तथापि इससे कम नुकसान नहीं हुआ। किसी भी प्रशासन में कर्मचारियों को हड़ताल का अधिकार देना बहुत अच्छी परम्परा नहीं है। इसलिए श्री गुलजारीलाल नन्दा की उपर्युक्त घोषणा बहुत प्रशंसनीय है। विभिन्न विभागों और क्षेत्रों में भी इसी तरह की संयुक्त परिषदें स्थापित होंगी। इन परिषदों से हठ व दुराग्रह की बजाय शान्ति पूर्ण विचार को बल मिलेगा। ● ●

सहकारियों को सहायता

भारत सरकार सहकारिता आन्दोलन को अधिक से अधिक प्रश्रय देने की नीति पर चल रही है। सरकार के अनुरोध पर भारतीय सूती मिल संघ ने यह निश्चय किया है, कि सहकारी स्टोरों को मिल की कीमत पर ही कपड़ा दिया जाय, ताकि ये स्टोर अन्य दुकानों से, जिन्हें मिलें ४ प्रतिशत लाभ लेकर कपड़ा देती हैं, अधिक सस्ते मूल्य पर कपड़ा बेच सकें। सहकारिता आन्दोलन सिद्धान्त रूप से बहुत अच्छा है, परन्तु उसे प्रश्रय देने से पहले यह आवश्यक है, कि सहकारी आन्दोलन को भ्रष्टाचार और स्वार्थ साधना की प्रवृत्ति से मुक्त किया जाय। सहकारी स्टोरों का पिछला अनुभव बहुत उत्साहजनक नहीं है। सहकारी समितियों को सरकार का प्रश्रय या सहयोग उसी सीमा तक मिलना चाहिए, जिससे समितियों के सदस्य अपने पांव पर खुद खड़े हो सकें और वे सरकार अर्थात् करदाता पर भार न बन जायें। ● ●

संयुक्त सहकारी कृषि

कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के बाद सहकारिता की दिशा में सहकारी कृषि की प्रवृत्ति को बहुत बल दिया गया। इसके पक्ष में सरकार ने काफी प्रचार किया तथा इस पर विपुल राशि व्यय की है। जगह-जगह सहकारी कृषि समितियां संगठित की गईं, और उन्हें सहायता देने के लिए सरकार का सामुदायिक योजना विभाग तैयार हो गया। १९५९-६० में ऐसी कृषि समितियां २६३१ थीं। किन्तु दूसरे वर्ष इनकी संख्या ६३२५ हो गई। इन समितियों के कार्य की जांच पड़ताल की गई है और वह बहुत संतोषजनक सिद्ध नहीं हुई। संयुक्त और सामूहिक कृषि समितियों की अपनी सम्पत्ति बहुत कम है, जबकि उनकी देनदारियां बहुत हैं। संयुक्त कृषि समितियों को सरकार ने लाखों रुपया सहायता दी। इन समितियों में एक बड़ी संख्या ऐसी है, जिन्हें न केवल लाभ नहीं हुआ, बल्कि हानि भी हुई है। इन सबका प्रबन्ध व्यय बहुत भारी है। यदि सरकार सहायता न देती तो अन्य भी बहुत-सी समितियां नुकसान में जातीं। सामुदायिक विकास मंत्री श्री एस० के० डे ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि सहकारी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कृषि का कार्यक्रम अभी तक भी लोगों को आकृष्ट नहीं कर सका। ६-७ लाख गांवों के भारत में कुछ सौ समितियों का निर्माण इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

हमारी नम्र सम्मति में सहकारी कृषि के प्रश्न पर किसी वाद के आग्रह से नहीं, स्वतंत्र दृष्टि से विचार होना चाहिए। इसके पक्ष और विपक्ष में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों पर शान्त दृष्टि से विचार करना चाहिए। महज़ नारेबाजी हमारे निर्णय में साधक नहीं होनी चाहिए।

● ●

एक मास में ३५ करोड़ रु० कर-वृद्धि

संसद के बजट अधिवेशन में बजट प्रस्तावों की यह कहकर सदा आलोचना की जाती है कि इससे सरकार की आय निरन्तर बढ़ती जाती है और उससे भी अधिक, जितनी आय का वित्तमंत्री अनुमान करते हैं। इस तरह वित्तमंत्री अपनी कार्य कुशलता का प्रमाण दिया करते हैं। निम्न अंक इसी की पुष्टि करते हैं।

केन्द्रीय सरकार जिन चीजों पर कर और शुल्क लगाती तथा वसूल करती है, उनसे १९६३-६४ वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में ४०८ करोड़ १३ लाख रु० वसूल किये गये। इसमें से ११० करोड़ ३८ लाख रु० जुलाई १९६३ में वसूल किये गये, पिछले वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में ३०५ करोड़ ६४ लाख रु० और जुलाई १९६२ में ७५ करोड़ ४३ लाख रु० वसूल किये गये थे। विभिन्न मदों में वसूल किये गये राजस्व का ब्यौरा इस प्रकार है :

(लाख रु० में)

राजस्व मद	जुलाई १९६३	जुलाई १९६२
१. सीमा शुल्क	३५६३	१७६७
२. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (इसमें नमक, कोयले और कच्चे लोहे के कर शामिल नहीं है)	५८७९	४६३६
३. निगम-कर	५९७	२७५
४. आय-कर	९३२	७९१
५. सम्पदा-शुल्क	२५	११
६. सम्पत्ति-कर	२३	१२
७. व्यय-कर	२	१
८. उपहार-कर	५ (अस्थायी)	४
९. अफीम-कर	१२	९
कुल	११०२८ (अस्थायी)	७५५१

एक मास में ही सरकार को ५० करोड़ रु० की अधिक आमदनी हुई।

● ●

वाद बनाम यथार्थ

पश्चिमी यूरोप के कामन मार्केट की तरह पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों ने अपने व्यापारिक और औद्योगिक विकास के लिए 'कामीकौन' के नाम से एक संगठन बनाया हुआ है, जिसमें रूस के अतिरिक्त यूरोप के अन्य साम्यवादी देश भी सम्मिलित हैं। यह संगठन पिछले १५ वर्षों से स्थापित है। किन्तु अब अनेक देश अनुभव करने लगे हैं, कि पारस्परिक सहयोग के नाम पर रूस को अधिक लाभ हो रहा है और उन-उन देशों की जनसंख्या तथा विचार विनिमय में उनकी आवाज कम होने के कारण वे देश कम लाभ उठा रहे हैं। रूस की जनसंख्या २२॥ करोड़ है। जैकोसलोवेकिया, हंगरी और पूर्वी जर्मनी की जनसंख्याएं क्रमशः १.४,१ और १.७ करोड़ है। वहां श्रमिकों की संख्या भी कम है और साधनों की भी बहुत कमी है। रूमानिया इनका अपवाद है। वहां जनसंख्या बहुत है और बहुत कम को अच्छा रोजगार मिलता है। इस लिए रूमानिया यह अनुभव कर रहा है कि यदि उसने अपने विकास को 'कौमीकौन' देशों के साथ जोड़ लिया तो उसके अपने विकास की गति शिथिल पड़ जायगी। यही कारण है कि रूमानिया पश्चिम से मशीनरी खरीदने लगा है, क्योंकि वह साम्यवादी देशों से अधिक अच्छी और सस्ती होती है। आर्थिक विकास में वाद की अपेक्षा अपना यथार्थ हित ही प्रमुख होता है, यह एक सत्य है।

—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देश की आय अरबों रु. बढ़ सकती है !!!

श्री उ० एन० ढेवर

आज भी देश में इतने अपार स्रोत अछूते पड़े हैं, जिनके समुचित दोहन से राष्ट्र की आय करोड़ों-अरबों रु० बढ़ सकती है, परन्तु देश का उधर ध्यान ही नहीं, यह बताते हुए विचारशील लेखक ने इस लेख में उन उपेक्षित स्रोतों का उल्लेख किया है। पर क्या देश के अर्थशास्त्री व प्रशासक इधर ध्यान भी देंगे ?

—सम्पादक

यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर है, किन्तु जन-शक्ति व सामग्री दोनों ही क्षेत्रों में अपार अछूते साधन स्रोत छिपे पड़े हैं। राष्ट्र-जीवन के सभी क्षेत्रों में विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया का आरम्भ कर राष्ट्र नायकों का कर्तव्य है कि वे अछूते विपुल स्रोतों को सक्रिय बना दें। देश के देहाती क्षेत्रों में अपूर्व अत्यधिक साधन-स्रोत अछूते पड़े हैं, जिन्हें यदि सक्रिय बनाया जाय तो वे राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को बहुत अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। उदाहरणार्थ,

अछूते अपार स्रोत

१. भारत की प्रति दिन, पूर्ण और अर्ध-बेकारी के कारण, कम से कम क्रमशः एक करोड़ तथा डेढ़ करोड़ मनुष्य दिनों के बराबर श्रम शक्ति की हानि होती है। यह अधिकांश जन-शक्ति गांवों में है, जहां उन्हें तथा उनके निवासियों को सहायता प्रदान करने के लिए काम की कमी नहीं है;

२. भारत में जिन लोगों के पास काम है, वे भी अपनी क्षमता के ६० प्रतिशत से भी कम काम करते हैं;

३. भारत में कम से कम डेढ़ करोड़ एकड़ भूमि ऐसी है, जिसे बिना किसी विशेष कठिनाई के खेती के अन्तर्गत लाया जा सकता है;

४. कृषि योग्य ३० लाख एकड़ भूमि के लिए सिंचाई-सुविधाएं हैं, जिनका देश में अत्यावश्यक कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अभी तक उपयोग नहीं हुआ है;

५. भारत में २,७५,००० वर्ग मील में जंगल है। यहां प्रति वर्ग मील केवल २,००० घनफुट हमारी लकड़ी और ईंधन का ही उपयोग होता है, जबकि विश्व का औसत ४,००० घन फुट है। जंगलों में जो कुछ हम प्राप्त करते हैं, उसके बदले वहां पर कोई काम हम शायद ही करते हों। वस्तुतः यह बड़े दुःख की बात है;

६. भारत में २० करोड़ पशु हैं, जिनका एक चतुर्थांश भैंसे हैं। भारत में प्रति पशु प्राप्ति विश्व के अन्य किसी भी देश की प्रति पशु प्राप्ति का चौथा अथवा छठा भाग है; और

७. भारत में ५ करोड़ ५० लाख भेड़ें हैं। उनसे ऊन प्राप्ति अन्य देशों की भेड़ों की तुलना में आधी ही है।

कृषि से ५० करोड़ रु० की अतिरिक्त आय

ये बहुत विशाल प्राप्ति स्रोत हैं। रुपये पैसे में गिनती की जाय, तो दो करोड़ मनुष्य दिनों में प्रति मनुष्य दिन न्यूनतम २५ नये पैसे के बराबर उत्पादन से भी भारत को रोजाना ५० लाख रुपये का उत्पादन प्राप्त होगा। एक करोड़ कृषि योग्य भूमि से ५० करोड़ रुपये का अतिरिक्त कृषि उत्पादन प्राप्त होगा। सिंचित ३० लाख एकड़ जमीन कम से कम दस लाख टन अतिरिक्त अन्न दे सकेगी। प्रति दिन एक पौण्ड अतिरिक्त दूध के हिसाब से भी ५ से ७ करोड़ तक गायें हमारे बच्चों में नव जीवन का संचार कर देंगी। जंगल और भेड़ें भी हमारे लिए पर्याप्त सम्पत्ति का स्रोत बन सकते हैं। फिर भी दुःख तो इस बात का है कि देश की अर्थ व्यवस्था के इस पहलू की ओर हमने कोई विशेष दिलचस्पी नहीं प्रकट की है। सरकार को परामर्श देने वाले शायद ही आत्म-निरीक्षण करते हों। इसका परिणाम यह निकलता है कि समाज तथा उसके कर्णधार एक दूसरे में दोष निकालने में व्यर्थ समय गंवाते हैं। आज वस्तुतः प्रतिरक्षा की समस्या केवल पाश्चात्य देशों से सैनिक सहायता प्राप्त करने की ही नहीं, बल्कि हमारे मस्तिष्क, हमारी विचार-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

धारा के अभिनवीकरण की समस्या भी है। हमें यह महसूस करना पड़ेगा कि आज का यह सीमा-विवाद कभी भी परिपूर्ण घमासान युद्ध में बदल सकता है। सर्वोच्च परीक्षा के समय जिस बात की आवश्यकता है वह यह कि हम ऐसे सीधे-सादे, सरल व तुरन्त उपलब्ध तौर तरीके खोज निकालें, जिनसे उक्त साधन-स्रोतों का उपयोग किया जा सके। इसके लिए ऐसी नई तकनीकें तथा तौर तरीके खोज निकालने की योग्यता की आवश्यकता है, जिन्हें जनता बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के समझ कर हृदयंगम कर सके, और उनका प्रयोग कर सके।

गांवों में क्रान्ति

इस दृष्टि से मैं सुझाव दूंगा कि भारत को युगों से उपेक्षित अपनी अर्थ-व्यवस्था के कृषि-औद्योगिक विभाग की क्षतिपूर्ति के लिए कम से कम कुछ समय के लिए तो इस विभाग पर अपना बहुत अधिक ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। भारतीय अर्थ व्यवस्था के कृषि-औद्योगिक विभाग को अपेक्षाकृत उच्च प्राथमिकता देनी पड़ेगी। यह एक ऐसा प्रश्न है, जो सभी व्यक्तियों को प्रभावित करता है, यदि वे अपना अस्तित्व कायम रखना चाहते हैं। गांवों को उनकी वर्तमान अवस्था में ही बने रहने देकर उनसे शक्ति प्राप्त करने की बात सोचना हास्यप्रद है। परिवर्तन जीवन का नियम है। महान् संघर्ष से होकर गुजरने में मानव महान् परिवर्तनों के कारण ही जीवित रह सका है। मैं कृषि-औद्योगिक आयोजन के क्षेत्र में बड़ा भारी परिवर्तन करने की आवश्यकता स्वीकार करता हूँ और इसीलिए मैं इस पहलू पर बार-बार जोर देता हूँ। मैं एक व्यापक पैमाने पर ऐसी नयी तकनीकों का समावेश चाहता हूँ, जो आर्थिक ढांचे के स्वतन्त्र रोजी (सेल्फ इम्पालॉयमेण्ट) वाले गुण में कोई बाधा न पहुँचायें और खर्चीली या शोषणकारी साबित न हों तथा जिनसे जनता में एक वेग आ जाय, वह सक्रिय रूप से वेगवान हो उठे एवम् जो ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की गति को तीव्र बना दे। साधन-स्रोतों का संग्रहण भी आवश्यक होगा। उत्पादन तकनीकों में परिवर्तन, साधन-स्रोतों का संग्रहण और बिक्री-व्यवस्था का पुनर्गठन करने से निस्सन्देह उत्पादन बढ़ेगा और उसके साथ ही रोजगारी के वैकल्पिक मार्गों का भी विस्तार होगा।

भारतीय जनता को सक्रिय व गतिशील बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए एक ऐसे कार्यक्रम अथवा कार्यवाही की आवश्यकता है, जो भारत के आकार और उसकी जन-संख्या की विशालता के समान ही व्यापक प्रभाव उत्पन्न कर सके। ग्राम नवीनीकरण के अतिरिक्त इस क्षेत्र में कम से कम एक सर्व-स्वीकृत कार्य योजना की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त, विज्ञान और संगठन की सहायता से उत्पादन बढ़ाने के लिए एक ऐसा अखिल भारतीय आन्दोलन चलाना, जिसमें राष्ट्रपति से लेकर देश का गरीब से गरीब व्यक्ति आ जाय—सरकार तथा जनता की शक्ति के भीतर है, बूते के बाहर की चीज नहीं और यही राष्ट्रीय संकटकालीन स्थिति की तात्कालिक आवश्यकता है।

• •

संसार की जनसंख्या ३ अरब से भी ऊपर

१९६१ में संसार की जनसंख्या ३ अरब ६ करोड़ ९० लाख थी। १९६० की अपेक्षा यह संख्या ६.१ करोड़ अधिक थी अर्थात् अरजैण्टाइना की कुल जनसंख्या की तिगुनी एक वर्ष में बढ़ गई।

१९५०-६१ के ग्यारह वर्षों में संसार की जनसंख्या ५६ करोड़ बढ़ गई, जो भारत की कुल जनसंख्या के सवाये से भी अधिक है। इस जनसंख्या-वृद्धि में एशिया का भाग ६० प्रतिशत है अर्थात् ३३.७ करोड़। ये सब आंकड़े अन्तर्राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रकाशित ईयर बुक १९६२ से लिये गये हैं। इससे देशों का क्षेत्रफल, जनता, अन्य भौगोलिक स्थिति तथा परिवार आदि सब बातों का विवरण है।

इसके अनुसार १० वर्ष पूर्व संसार में आबादी की घनता १८ प्रति वर्ग किलोमीटर थी, अब यह बढ़कर २३ प्रति वर्ग किलोमीटर हो गई है। सबसे अधिक घनी आबादी नीदरलैण्ड में है अर्थात् ३४६ प्रति किलोमीटर, आस्ट्रेलिया में प्रति किलोमीटर १ भी कम जनसंख्या है।

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ये रहीं हमारी पंचवर्षीय योजनाएं !!!

आचार्य विनोबा द्वारा कठोर आलोचना

दो-दो पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं, अब तीसरी चल रही हैं। फिर भी हिसाब यह है कि देश में जो नीचे का तबका है, मजदूर वर्ग है, उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। दो पंचवर्षीय योजनाओं पर अरबों रुपया खर्च हुआ, फिर भी नीचे के जीवन में सुधार नहीं हुआ! क्यों नहीं हुआ? नीचे के तबके तक मदद न पहुँचे, योजना करने वाले ऐसा सोचेंगे, यह तो हम नहीं कह सकते। फिर भी यह सत्य है कि नीचे के तबके को मदद नहीं पहुँची?

यह समझना चाहिए कि योजना जिस पद्धति द्वारा होती है, उस पद्धति में ही दोष है। केवल दौलत बढ़ेगी, तो नीचे के तबके तक पहुंचेगी, यह योजना बनाने वालों ने मान लिया। अगर देश एक रस होता तो ऐसा होने की संभावना थी। लेकिन वह एकरस नहीं है। उसमें जाति-भेद है, मालिक-मजदूर भेद है, नगर-देहात में कशमकश है! ऐसी हालत में बाहर से देश में केवल उत्पादन बढ़ेगा, तो सबको कुछ-न-कुछ मिलेगा, ऐसी आशा रखना गलत है।

सर्वसामान्य पोषण शरीर को मिले, वह जरूरी है; लेकिन उसके सिवाय पांव के फोड़े की ओर खास ध्यान देना पड़ता है। इसी तरह समाज में करना होता है। पंच-वार्षिक योजना बनाते समय यह बात ध्यान में नहीं आयी। अब आयी है; लेकिन अब ज्यादा खर्च नहीं किया जा सकता, ऐसी नौबत आई है। इस हालत में हमको सोचना चाहिए कि गांव में मजदूर हैं, दुःखी हैं, गरीब हैं, उनकी चिन्ता कौन करेगा? उसके लिए गांव को भी तैयार होना चाहिए। सरकार थोड़ी मदद दे सकती है, लेकिन जब तक गांववाले ताकत नहीं बनाते और उनको प्रेरणा नहीं होती। गांव में जब तक परिवार भावना नहीं बनती—तब तक गांव ऊपर नहीं उठेगा। गांव ऊपर नहीं उठेंगे, तो देश मजबूत नहीं बनेगा। इसलिए अब जरूरत है कि गांव में गांव की ताकत पैदा हो।

दस प्रतिशत भी ४॥ करोड़

प्लानिंग कमीशन वालों के आंकड़ों के अनुसार दस प्रतिशत लोगों की आमदनी सात रुपया महीना, याने पौने-चार आना रोज़ है। यह तीन आने के करीब पड़ता है।

हिन्दुस्तान में ४५ करोड़ लोग हैं। उनका दस प्रतिशत याने साढ़े चार करोड़ लोग। दुनिया में साढ़े चार करोड़ आबादी वाला तो एक देश ही माना जायगा। साढ़े चार करोड़ लोगों को पोने चार आने रोज मिलता है। यह पर्याप्त दुःख है। इससे ज्यादा दुःख की जरूरत नहीं। यह तो सबसे नीचे वाले दस प्रतिशत लोग हैं, उनकी बात है। उनके ऊपर के दस प्रतिशत लोगों के सरकार ने जो आंकड़े जाहिर किये हैं, उस हिसाब से उनको दस रुपया महीना मिलता है, याने सवा पांच आने रोज। इसका मतलब यह हुआ कि और साढ़े चार करोड़ लोगों को पांच-सवा पांच आना रोज मिलता है। यानी दोनों मिलकर नौ करोड़ लोग हुए। नौ करोड़ कोई कम संख्या नहीं है। चार आना और पांच आना आमदनी में पूरा खाना भी नहीं मिल सकता। दूसरी आवश्यकताएं तो दूर किनार।

उपनिषद् कह रही है: "अन्नं बहु कुर्वीत तद् व्रतम्।" यह ब्रह्म विद्या का ग्रंथ बोल रहा है। यह प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट नहीं, या किसी राजनैतिक पक्ष का आह्वान

(शेष पृष्ठ ३९५ पर)

असली सवाल

एक आदमी को नदी पार करनी थी। उसको कहा गया कि नदी औसत दो फीट गहरी है। वह उसी की बात पर भरोसा करके पैदल गया, तो बीच में दस-बारह फुट गहरा पानी आने पर डूब गया। दूसरे ने उसे बचा लिया, तो वह कहने लगा, गफलत हुई। हम समझे थे कि पानी दो फुट गहरा है, लेकिन निकला दस फुट गहरा। था तो दो फुट ही, लेकिन वह औसत दो फुट था। इसलिए पन्द्रह आना आमदनी खास काम की बात नहीं हो सकती। सवाल इतना ही है कि सबसे नीचे का जो वर्ग है, उसकी आमदनी कितनी है?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नये राष्ट्र का उदय

मलयेशिया की आर्थिक स्थिति

(कृष्णचन्द्र विद्यालंकार)

१५ और १६ सितम्बर ६३ की बीच की रात को ठीक १२ बजकर १ मिनट पर भारत के दक्षिण पूर्व में एक नये राष्ट्र का जन्म हुआ है। मलाया, सिंगापुर, सारवाक और ब्रिटिश उत्तरी बोर्नियो ने संयुक्त होकर मलयेशिया का निर्माण किया है। इस नये राज्य में अनेक जातियां निवास करती हैं। इनकी कुल जनसंख्या १ करोड़ १ लाख ८७ हजार है। इस जनसंख्या में भारतीयों की जनसंख्या ९ लाख ५५ हजार है अर्थात् वे कुल जनसंख्या का ९.४ प्रतिशत हैं। चीनियों की जनसंख्या ४३ लाख है। शेष जातियां मलाया और इण्डोनेशिया की हैं। सारवाक और बोर्नियो की भी कुछ जातियां निवास करती हैं। मलाया का कुल क्षेत्रफल १ लाख २८ हजार ५५८ वर्ग मील है। इस राष्ट्र में सम्मिलित होने वाले विभिन्न भागों की आबादी की घनता भी अलग-अलग है। सारवाक और बोर्नियों में जिसका नया नाम साबहा है, प्रतिवर्ग मील केवल १६ व्यक्ति रहते हैं। मलाया में आबादी की घनता १४३ वर्ग मील है। सिंगापुर इस दृष्टि से बहुत आगे बढ़ा हुआ है। वहां यह संख्या ७८० है।

राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय

१९६१ में मलयेशिया की कुल राष्ट्रीय आय ८६५ करोड़ मलय डालर थी। इसमें से भी सिर्फ मलाया की राष्ट्रीय आय ५२२ करोड़ और सिंगापुर की ३२० करोड़ मलय डालर थी। (१ मलाया डालर अधिकृत रूप में १ रु० ९ आने के बराबर और बाजार में सवा दो रुपये के बराबर होता है) प्रति व्यक्ति वार्षिक आय सारवाक में सबसे कम है—५५० म० डालर, परन्तु यह आय भी समस्त एशिया में जापान को छोड़कर सबसे अधिक है। भारत में ही यह आय करीब ३०० रुपया है। नये राष्ट्र के विभिन्न विभागों में प्रति व्यक्ति आय निम्न रूप से है—

(मलय डालरों में)

मलाया	८००
उत्तरी बोर्नियो	७००
सिंगापुर	१३००
सारवाक	५५०

वर्ल्ड बैंक के अध्ययन के अनुसार कुल मलयेशिया की औसत आय प्रति व्यक्ति ८६० म० डालर है। इसी से मालूम हो जाता है, कि मलयएशिया आर्थिक दृष्टि से कम समृद्ध नहीं है।

निर्यात व्यापार

१९६१ में मलयेशिया के कुल निर्यात (पदार्थ और सेवा) ४०० करोड़ मलय डालर थे। मलयेशिया की मुख्य फसल रबर है। १९६१ में ६९७७ वर्ग मील में रबर की खेती हुई थी। इसमें से अधिकांश खेती मलाया के ६१३० वर्ग मील में हुई। २०५१ वर्ग मील में चावल, १०५.२ वर्ग मील में नारियल और २४० वर्ग मील में ताड़ की खेती हुई। रबड़ के निर्यात से मलयेशिया को १९५९, १९६० और १९६१ में क्रमशः १७७, १८७ और १४७ करोड़ मलाया डालर मिले।

रबड़ के बाद विदेशी मुद्रा की दृष्टि से टीन का स्थान है। प्रायः समस्त टीन का निर्यात होता है, और १९६१ में ४३.२ करोड़ मलय डालर की उपलब्धि मलाया को हुई। सारवाक और साबहा से लकड़ी का भी निर्यात होता है, और अब तो मलाया से आयरन ओर का भी निर्यात होने लगा है। ताड़ के तेल और काली मिर्च आदि का, निर्यात करोड़ों डालर दे जाता है। सिंगापुर में डब्बाबन्द खाद्य सामग्री का अच्छा उद्योग चलता है।

१९६२ के अन्त में मलयेशिया के सभी भागों का कुल निर्यात ३८० करोड़ मलय डालर था। यह करीब कुल आयात को पूरा कर लेता था। १९६२ के अन्त में समस्त देश पर कुल ७० करोड़ मलय डालर विदेशी ऋण था और सरकार के पास १८० करोड़ डालर विद्यमान था।

नई समस्या

विज्ञान ने कृषि प्रधान देशों के सामने कृत्रिम साधनों

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के रूप में एक विकट समस्या उपस्थित कर दी है। मलाया भी उसका अपवाद नहीं है। कृत्रिम रूप से बनने वाले रासायनिक रबड़ ने मलाया के असली रबड़ की कीमतें कम कर दीं। अब तो वैज्ञानिक रबड़ खेतों में उत्पन्न रबड़ से भी अधिक मात्रा में तैयार होने लगा है। इस वर्ष अगस्त में मलाया का रबड़ सिंगापुर में ७० सैंट प्रति पौंड से भी कम में बिका। अगस्त १९६१ के बाद दो वर्षों में इस रबड़ के मूल्य २१ सैंट प्रति पौंड कम हो गये हैं। यह कमी मलाया के लिए कितनी गम्भीर और महत्वपूर्ण है, इसका अन्दाज इसी से हो जाता है, प्रति पौंड एक सैंट की कीमत में कमी का अर्थ है मलाया को १ वर्ष में २॥ करोड़ रुपये की क्षति। मलाया सरकार की एक जांच के अनुमान के अनुसार इन दो वर्षों में मलाया को रबड़ की कीमत में कमी से करीब ६० करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। इससे मलाया की समस्त अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मलाया के योजना आयोग ने अपनी समस्त विकास योजनायें इस आधार पर निर्धारित की थीं कि रबड़ की कीमत प्रति पौंड ८० मलाया सैंट रहेगी और अब उसमें १५ सैंट प्रति पौंड की कमी हो गई है।

उद्योग

आज मलय एशिया में बड़े-बड़े उद्योग बहुत कम हैं, यद्यपि वहां उद्योगों के विकास की सम्भावना कम नहीं है। डनलप, शैल, एस्सो, इम्पीरियल कैमीकल, पामोलिव, जेनरल इलैक्ट्रिक, कैरियर, इन्टरनेशनल आदि विदेशी कम्पनियों ने वहां अपने कुछ उद्योग स्थापित किये हैं। इन उद्योगों में स्थानीय व्यवसायियों ने भी सहयोग दिया है। अभी तक कुल राष्ट्रीय आय में उद्योगों का स्थान सिंगापुर में १४ प्रतिशत, मलाया में ६ प्रतिशत सारवाक में २॥ और बोर्नियो में २ प्रतिशत है। वर्ल्ड बैंक के अध्ययन के अनुसार कुल मलय एशिया में उद्योगों से ७॥ प्रतिशत आय होती है। किन्तु अब यह आशा करनी चाहिए कि मलय एशिया में विदेशी उद्योगपतियों के सहयोग से औद्योगिक विकास कुछ तेजी पकड़ लेगा। सरकार भी उद्योगों के विकास को बहुत सहायता दे रहा है।

मलाया की राजधानी कुआला लमपुर से कुछ मील दूर दो नये उपनगर बन गए हैं, जिनमें सैकड़ों एकड़ भूमि केवल उद्योगों के लिए रिजर्व कर दी गई है। सिंगापुर में जूरोंग में नया उद्योग नगर विकसित हो गया है। यहां एक टायर फैक्टरी, स्टील मिल और एक शिपयार्ड बन चुके हैं। कुछ सप्ताह पूर्व एशिया की सबसे बड़े आटे की मिल भी सिंगापुर में खुल चुकी है। दो आयल रिफायनरियां मलाया में हैं और एक सिंगापुर में है।

भविष्य

इस नये राष्ट्र का आर्थिक भविष्य दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो यह है कि इस नये राष्ट्र के चारों विभाग अपने-अपने स्वार्थ की अपेक्षा समस्त राष्ट्र के हित को अधिक महत्वपूर्ण समझें। और दूसरा यह है कि इण्डोनेशिया ने इस राष्ट्र के अस्तित्व के विरुद्ध जो संघर्ष छेड़ दिया है, वह शान्त हो। अन्तर्राष्ट्रीय शान्त वातावरण में ही कोई देश अपनी विकास योजनाओं को सफलतापूर्वक चला सकता है और तभी अन्य देश भी वहां अपना विनियोजन निस्संकोच कर सकते हैं।

● ●

(पृष्ठ ३९३ का शेष)

नहीं है। यह ब्रह्म विद्या सम्राट बोल रहा है। लोग अन्न बहुत बढ़ायें। किस प्रकार से बढ़ायें? किन साधनों से बढ़ायें? क्या कुंआ खोदेंगे, नहर निकालेंगे, बांध बांधेंगे? उपनिषद् कहती है—"यया कया च विधया बहु अन्नं प्राप्नुयात्" जिस किसी पद्धति से अन्न प्राप्त हो सके, कीजिए। अन्न-निर्माण में उपनिषद् वाद उपस्थित नहीं करता। कपड़ा अम्बर चरखा से निकाला जाय या मिल से लाया जाय, यह वाद का विषय है। जिस किसी विधि से अन्न-उत्पादन कर सकते हैं, करें। यह समझने की बात है।

पन्द्रह साल हो गये। अब भी बाहर से अन्न मंगवाना पड़ता है। बहुत दुःख की बात है। १९५१ में पं० नेहरू ने जाहिर किया था कि १९५३ के बाद हम बाहर से अन्न नहीं मंगवायेंगे। लेकिन पन्द्रह साल हो गये, आज भी बाहर से अन्न मंगवा रहे हैं। योजना में यह आदेश है कि देश के लिए पर्याप्त अनाज देश में पैदा होना चाहिए। यह राष्ट्र की अत्यन्त आवश्यकता है। यह जो आदेश है, उसी के अनुसार योजना बनानी चाहिए।

● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आधुनिक अर्थशास्त्र के क्रांतिकाल—१

श्री कृष्णदत्त भट्ट

आधुनिक अर्थशास्त्र की विचारधारा को भलीभांति समझाने के लिए वाणिज्यवादी युग के क्रांतिकारी परिवर्तनों का अध्ययन आवश्यक है, जिनके कारण आधुनिक अर्थशास्त्र के अंकुर उत्पन्न होने लगे। विद्वान् लेखक ने संक्षेप से उन्हीं परिवर्तनों का इन पंक्तियों में उल्लेख किया है।

वर्तमान अर्थशास्त्र ने १६वीं और १७वीं शताब्दी में बहुत उन्नति की। यूरोप के विभिन्न विचारकों ने इन सदियों में अर्थ शास्त्र के अनेक नये सिद्धान्तों और वादों की कल्पना की है, क्योंकि ये सदियां यूरोप के इतिहास में बहुत क्रान्तिकारी हुई हैं। जिन अनेक वादों का इस युग में जन्म हुआ, उन सब को हम वाणिज्यवाद के नाम से पुकार सकते हैं। इन सब वादों में यह मूल धारा व्याप्त रही कि व्यापार वाणिज्य का अधिकतम विकास हो और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए राज सत्ता को अपना साधन बनाया जाय।

इस काल में इतिहास भी करवटें ले रहा था। धर्म की विचारधारा में सुधारवाद (रिफार्मेशन) का उदय हो रहा था। पुरातन चर्च व्यवस्था की सर्वशक्ति-सम्पन्न सत्ता डगमगाने लगी थी। मार्टिन लूथर जैसे उग्र सुधारवादी लोगों के विचार अपना प्रभाव दिखाने लगे थे। धर्म की बन्दिशें ढीली पड़ने लगी थीं। संकुचितता के स्थान पर राष्ट्रीयता की भावना विकसित होने लगी थी।

उधर सभ्यता और संस्कृति, में कला और साहित्य में, दर्शन और विज्ञान में भी पुर्नजागरण दृष्टिगत हो रहा था। 'मानवतावाद' पर भी बल दिया जाने लगा था। मानव के कल्याण की बात को केन्द्र मान कर सोचना आरम्भ हो गया था। मानवता की प्रसन्नता और संस्कृति का विकास उसका लक्ष्य बनने लगा था। भौतिकवादी दृष्टि इसके मूल में थी। अफलातून और अरस्तू के राज्य के सिद्धान्त, राज्य के साथ व्यक्ति का सम्बन्ध एवं श्रम विभाजन आदि की विचार धारा ने पुनर्जागरण की इस भावना को परिपुष्ट किया। राष्ट्रीयता और शक्तिशाली शासक की भावना भी उत्तरोत्तर विकसित होने लगी थी, पर उसमें लोक-हित या जनकल्याण की भावना अन्तर्भूत थी।

सन् १५१६ में सर टामस मोर की पुस्तक 'उतोपिया' का प्रकाशन हुआ। उसमें दोनों ही बातों का समावेश है यूनानी विचारधारा के अनुकूल सांस्कृतिक आत्मविकास की पुनर्जागरण की भावना और लोकतांत्रिक समानता की ईसाई भावना। उसके सुझाव थे :

१. ६ घंटे का दिन माना जाय।
२. प्रत्येक व्यक्ति श्रम करे।
३. व्यक्तिगत सम्पत्ति के सीमित अधिकार रहें।

ये विचार समय के अनुकूल न होने से पल्लवित नहीं हो सके, यह बात दूसरी है, पर इन से इतना तो स्पष्ट हो जाता है, कि विचारकों ने शासन आर्थिक जीवन एवं जन-कल्याण की दिशा में विचार करना आरम्भ कर दिया था।

ये थे वाणिज्यवाद के उदय के दूरवर्ती कारण। उसके निकट वर्ती कारण थी १५वीं शताब्दी की समाप्ति के लग-भग होने वाली राजनीतिक और आर्थिक प्रगति। इस प्रगति के फलस्वरूप ही नव राष्ट्रों के उदय हुए।

तात्कालिक कारण

अभी तक कृषि का ही सर्वश्रेष्ठ स्थान रहा था, परन्तु १६वीं शताब्दी के आरम्भ से वाणिज्य ने पैर पसारने से आरंभ कर दिए थे। देशी एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का तीव्र गति से विकास होने लगा था और मुद्रा का प्रचलन बहुत बढ़ने लगा था। महारानी एलिजाबेथ के शासन-काल में इंग्लैंड ऊन का निर्यात करने के स्थान पर ऊनी माल का निर्यात बढ़ाने लगा था। व्यापारियों के श्रेणी-समूहों की शक्ति और सत्ता बढ़ने लगी थी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रतिद्वन्द्विता और मुद्रा

मजदूरों की समस्या भी दूसरा रूप ग्रहण करने लगी थी। एक 'स्वतन्त्र' मजदूर-वर्ग का उदय होने लगा था, प्रतिद्वन्द्विता आने लगी थी, वितरण की समस्या उठ खड़ी हुई थी, एकाधिकारियों का विरोध होने लगा था।

मुद्रा के बिना अत्यधिक विनिमय, एवं विदेशी व्यापार सम्भव ही कैसे था? अमेरिका में चांदी की नयी खानों के आविष्कार (सन् १५४०-१६००) ने इस समस्या को सुलझा दिया। बैंक आफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। सोने चांदी के प्रवाह के कारण तथा मुद्रा में भ्रष्टता का प्रचलन होने के कारण वस्तुओं के मूल्य में भयंकर रूप से वृद्धि हो उठी। सट्टेबाजी को बल मिला। उधर राज्य का व्यय और अपव्यय अन्धाधुन्ध बढ़ने लगा, जिसका भार जनता पर कर वृद्धि के रूप में पड़ने लगा। बचत और बैंकिंग पर जोर दिया जाने लगा।

राष्ट्र की भावना और राज सत्ता

वाणिज्यवादी राष्ट्र की सम्पत्ति बढ़ाने के लिए उतने उत्सुक नहीं थे, जितने राष्ट्र की शक्ति बढ़ाने के लिए। एक ओर नगर बढ़ रहे थे, श्रेणियां बढ़ रही थीं, सामन्त लोग सिर उठा रहे थे, एकाधिकार बढ़ रहे थे; दूसरी ओर इन सब पर नियन्त्रण करने का प्रयत्न हो रहा था। इस बात की चेष्टा की जा रही थी कि सब मिलकर एक राष्ट्र की भावना में योगदान करें। उसके लिए एक शक्तिशाली नृपति की आवश्यकता प्रतीत होने लगी थी। वाणिज्यवाद ने शासक की इस सर्वग्रासी सत्ता पर ही जोर दिया।

हाब्स ने 'लिविएथन' (सन् १६५१) में राज्य की तत्कालीन भावना की अभिव्यक्ति करते हुए लिखा है कि वह मनुष्य की व्यक्तिगत इच्छा से ऊपर था। उसका अधिकार था कि वह वाणिज्य को प्रोत्साहन दे। वाणिज्यवादी अपने व्यापार को फैलाने के लिए या सुरक्षा की दृष्टि से राजसत्ता को शक्तिशाली बनाने के पक्ष में थे। उनका सिद्धान्त था, कि व्यक्ति राज्य के लिए है, राज्य व्यक्ति के लिए नहीं। इस दृष्टि से वाणिज्यवादियों को हम फासिज्म का जनक कह सकते हैं।

वाणिज्य पर जोर

स्वतन्त्र मज़दूर वर्गके प्रादुर्भाव तथा सामन्तवाद के पतन के कारण लोकतन्त्र की भावना क्रमशः विकसित होने लगी थी। व्यापारी लोगों को सार्वजनिक मामलों में व्यापारी हितों की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाने लगा था। इस काल की आर्थिक रचनाओं की निर्मिति में बड़े-बड़े व्यापारियों का बड़ा हाथ है। अन्तर्देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य-व्यापार का नियंत्रण और विकास करने के लिए उन दिनों जिन कानूनों की रचना हुई, उनमें भी वही बात परिलक्षित होती है। ऐसा माना जाने लगा था, कि केवल वे ही सरकारें प्रभुत्व प्राप्त करने में समर्थ हो सकती हैं, जो राष्ट्र एवं राज्य के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए इस बात को समझती है, कि तीव्रता, साहस एवं स्पष्टता के साथ कैसे अपनी नौ-सेना, तथा बेड़े की शक्ति का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है और जो निराक्रम्य कर आदि के सम्बन्ध में उपयोगी और हितकर कानून बनाती हैं।

पैसा ही मूल लक्ष्य

वाणिज्यवादी काल में सेना तथा युद्ध के सम्बन्ध में भी कुछ भावना परिवर्तित हो गई थी। पहले वीरता एवं शौर्य की प्रशंसा की जाती थी, परन्तु इस काल में ऐसी मान्यता होने लगी थी कि उस राजा को ही विशेष रूप से सफलता एवं विजय प्राप्त होगी, जो अपनी सेना को खिलाने-पिलाने, पहनाने ओढ़ाने और वेतन चुकाने के लिए पैसे का आयोजन ठीक ढंग से कर सकेगा। शूर-वीर सैनिकों वाले राजा का उसके समक्ष कोई मूल्य नहीं।

वाणिज्यवाद-काल के युद्ध में हमें ऐसे ही युद्धों का बाहुल्य दीख पड़ता है, जिनका मूल उद्देश्य वाणिज्य सम्बन्धी प्रभुता की स्थापना करना ही था।

तत्कालीन स्थिति का प्रभाव

वाणिज्यवाद के विचारकों में आधुनिक अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों की पूर्व कल्पनायें दृष्टिगत होने लगी हैं। मूल्य ब्याज, जनसंख्या, कर प्रणाली आदि के सम्बन्ध में आगे चल कर जिन सिद्धान्तों का विकास हुआ, उसके बीज

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वाणिज्यवादी लेखकों की रचनाओं में भरे पड़े हैं। यह ठीक है कि तत्कालीन स्थिति ने इन विचारकों को प्रभावित किया है। उनमें अनेक भूलें और भ्रान्तियां विद्यमान हैं, परन्तु जिन दिनों युद्ध का बाहुल्य था, पारस्परिक स्वार्थों में सतत संघर्ष होता रहता था, बैंक और मुद्रा प्रणाली का आज की भांति विकास नहीं हुआ था, उस समय यदि इन विचारकों ने सोने और चांदी को अपना मूल लक्ष्य बनाया, तो इसमें अस्वाभाविक क्या है ?

इस काल में जिसके पास सोने चांदी की सिलें रहती थीं, उसके हाथ में सत्ता तथा शक्ति भी रहती थी। जहां इन धातुओं की खानें नहीं थी, वहां यह स्वाभाविक था, कि लोग व्यापार वाणिज्य के माध्यम से सोना-चांदी जुटा कर अपनी शक्ति का संवर्द्धन करें। और यह तो है ही, कि अर्थार्थी अपना ही लाभ देखता है। अतः वाणिज्य-वादी विचारकों ने सत्ता को प्रभावित करने का जो प्रयास किया, उसमें विचित्र एवं असंगत लगने जैसी कोई बात नहीं है। वे व्यावहारिक लोग थे और आदर्शों तथा सिद्धान्तों पर केवल उतना ही बल देते थे, जितने से अपने मूल लक्ष्य में बाधा न आये।

अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वाणिज्यवादियों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, घरेलू उद्योगों का संरक्षण तथा राज्य द्वारा प्रतिरोधक नियमों के निर्माण पर सब से अधिक बल दिया। फ्रांस में कोल्बर्ट साहब ने प्रतिरोधक कानूनों को तो इस सीमा तक बढ़ा दिया, कि वाणिज्यवाद का एक नाम 'कोल्बर्टवाद' भी पड़ गया।

वाणिज्यवाद के प्राथमिक लेखकों में दो लेखक अत्यन्त प्रमुख हैं मजियावेली और जीन बोडिन।❀

● ●

❀ लेखक की आर्थिक विचारधारा से—सेवासंघ वाराणसी द्वारा प्रकाशित।

पाकिस्तान में बोकारो-काण्ड

भारत की तरह पाकिस्तान भी पंचवर्षीय योजनाएं बना रहा है। आजकल वहां दूसरी योजना चल रही है। इस योजना के अन्तर्गत कराची व चटगांव में क्रमशः ३५ व १५ लाख टन की क्षमता के इस्पात कारखाने बनाने का निश्चय किया गया। चटगांव में तो कारखाना बन रहा है किन्तु कराची का कारखाना बोकारो की तरह खटाई में पड़ गया है।

इस कारखाने की योजना विश्व बैंक व अमरीका ने स्वीकार कर ली थी, लेकिन जब उस योजना के अन्तर्गत पाकिस्तान ने कर्ज मांगा तो बैंक ने यह कहकर इंकार कर दिया कि अभी इस योजना के क्रियात्मक पहलुओं पर—परिवहन, कच्चा माल, तकनीकी ज्ञान तथा उत्पादन व्यय आदि पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और वह अपने विशेषज्ञों द्वारा ही करवाएंगे। इससे पाकिस्तान चकरा गया है, क्योंकि उसकी आर्थिक विकास योजनाओं का आधार भी इस्पात उद्योग है।

सरकारी कारखानों का प्रबन्ध

इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री श्री सुब्रह्मण्यम ने बताया है कि सरकारी कारखानों के प्रबन्ध में जो परिवर्तन करने का विचार है, उनसे कारखानों के प्रबन्धकों को अधिक अधिकार मिलेंगे और उनके प्रबन्ध के बारे में इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय की जांच की आवश्यकता बहुत कम हो जाएगी। इसी प्रकार इन कारखानों के मुख्यालयों, जैसे हिन्दुस्तान स्टील लि० और फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा भी उक्त कारखानों के काम की अधिक जांच करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

उन्होंने बताया है कि कर्मचारियों को नियुक्त करने, उन्हें तरक्की देने और नौकरी से हटाने सम्बन्धी अधिकार दुर्गापुर और सिन्दरी के कारखानों के प्रबन्धकों को ही सौंपे जा रहे हैं। इन कारखानों के जनरल मैनेजर अपने कारखाने के प्रबन्ध के प्रति उत्तरदायी होंगे और ये लोग अपने कारखानों के विभागों के अध्यक्षों को कुछ अधिकार सौंपेंगे।

उचित समय पर कारखाने के लिए सामान खरीदने की जिम्मेदारी पूरी तरह से जनरल मैनेजरों और उनके खरीद विभागों की होगी और उन्हें यह अधिकार होगा कि वे वित्त सलाहकार की राय को न मानें, यदि ऐसा करना कारखाने के हित में हो।

सादम्म

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तीसरी योजना में उद्योगों की प्रगति

तीसरी पंचवर्षीय योजना को शुरू हुए २॥ वर्ष हो चुके हैं। इसलिए योजना आयोग ने स्वयं ही अब तक की प्रगति के सम्बन्ध में एक जांच पड़ताल की थी। इस जांच पड़ताल से मालूम पड़ता है कि हम अपनी इस योजना के सब लक्ष्य शेष अवधि में पूर्ण नहीं कर सकेंगे और कुछ को चौथी योजना में ही पूर्ण करना होगा। बोकारो का कारखाना तो खटाई में पड़ ही गया है। अन्य अनेक उद्योग भी स्थापित होने की दिशा में कोई प्रगति नहीं कर सके। अनेक उद्योगों के तो अभी प्रारम्भिक अनुमान-पत्र भी तैयार नहीं हुए। इसलिए योजना आयोग ने स्वयं ही तीसरी योजना की अवधि में उन उद्योगों को प्रारम्भ करने का विचार ही छोड़ दिया है। हम इस लेख में कुछ उद्योगों की प्रगति का संक्षिप्त सिंहावलोकन करना चाहते हैं।

बिजली के ट्रान्सफार्मर और मोटर—इन उद्योगों में अच्छी प्रगति हो रही है और यह आशा की जाती है, कि १९६५-६६ तक इन उद्योगों के लक्ष्य पूर्ण हो जायेंगे। श्री एस० एस० कुमार की अध्यक्षता में नियत कमेटी ने बताया था, कि आवश्यकताओं को देखते हुए जैनरेटरों, ट्रांसफॉर्मरों, स्विच गीयर आदि की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। इनमें होने वाली कमी को पूर्ण करने के लिए कुछ निजी उद्योगों को निर्माण के लायसेंस भी दे दिये गये हैं।

रासायनिक खाद—कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों के उत्पादन पर विशेष बल दिया जा रहा है। तीसरी योजना में नायट्रोजन खाद की उत्पादन क्षमता और उत्पादन के लक्ष्य १० लाख और ८ लाख टन क्रमशः रखे गये थे। आज उत्पादन क्षमता सिर्फ ३ लाख ५८ हजार टन है। इस कमी को पूरा करने के लिए अनेक परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों को लायसेंस दे दिए गये हैं। भारी उद्योग-मंत्रालय के अनुमान के अनुसार १९६५-६६ तक हमारी उत्पादन क्षमता ६४० हजार टन तथा उत्पादन ५ लाख टन होने लगेगा। रासायनिक खाद के उत्पादन में भारी कमी का कारण निजी क्षेत्रों की उदासीनता या शिथिलता है। ४ लाख टन की उत्पादन क्षमता के लायसेंस निजी क्षेत्रों को दिये गये थे। अब तक इस क्षेत्र में किसी बड़ी परियोजना के बाकायदा प्रारम्भ किए जाने की सूचना नहीं मिली। इस सम्बन्ध में निजी उद्योग का कहना यह है, कि वे किसी विदेशी संस्थान से उचित सहयोग प्राप्त करने में अब तक सफल नहीं हुए न विदेशी मुद्रा की सुविधा मिली है।

रासायनिक खाद की दूसरी किसम फास्फेटिक खाद की है। योजना आयोग ने तीसरी योजना की अवधि के अन्त तक इसकी उत्पादन-क्षमता और उत्पादन के लिए क्रमशः ५ लाख और ४ लाख टन लक्ष्य नियत किये थे। आज ये दोनों क्रमशः एक लाख २० हजार और ८० हजार टन है। १९६५-६६ तक उत्पादन में २ लाख टन से बढ़ने की सम्भावना नहीं है।

रासायनिक उद्योग—किसी देश के औद्योगिक विकास में रासायनिक उद्योगों का महत्वपूर्ण भाग होता है। ख्याल यह है, कि कास्टिक सोडा के उत्पादन का लक्ष्य तो सम्भवतः पूर्ण हो जाय, परन्तु सलफ्यूरिक एसिड और सोडा ऐश के लक्ष्य अपूर्ण ही रहेंगे। सलफ्यूरिक एसिड की उत्पादन क्षमता का लक्ष्य १७.५ लाख टन रखा गया था। लेकिन इस योजना के अन्त तक १५ लाख टन से अधिक होने की आशा नहीं है। इस का मुख्य कारण यह है, कि फास्फेटिक खाद ही कम तैयार हो रहा है, क्योंकि उसे भी तैयार करने में सलफ्यूरिक एसिड की आवश्यकता होती है। अब यह विचार किया गया है, कि सिन्दरी के पास ४०० टन प्रति दिन उत्पादन क्षमता का एक संयत्र लगाया जाये।

मोटर टायर—मोटर टायरों को उत्पादन-क्षमता और उत्पादन के लक्ष्य क्रमशः ३७ और ३० लाख टन रखे गये थे। आज उत्पादन क्षमता २४ लाख टन है। योजना आयोग ने नई आवश्यकताओं को देख कर कुछ लक्ष्य अधिक ऊंचे नियत किये हैं। किन्तु योजना के अन्त तक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यदि पहले के भी नियत लक्ष्य पूर्ण हो जावें तो गनीमत है। टायरों के लिए रबड़ और मिश्रित रबड़ रेयन कॉर्ड कार्बन ब्लाक आदि कच्चे माल की आवश्यकता होती है। बरेली में मिश्रित रबड़ का एक कारखाना खोल दिया गया है, जिस का उत्पादन क्षमता ३० लाख टन वार्षिक है। नेशनल रेयन्ज का कार्ड बनाने का कारखाना भी चालू है।

अखबारी कागज—अखबारी कागज के मंगाने में देश की करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय हो जाती है। इसलिए योजना आयोग ने इसके विकास के लिए भी निम्न लिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे। आज सरकारी नेपा मिल में वर्तमान स्थिति यह है—

लक्ष्य		वर्तमान स्थिति
उत्पादन क्षमता	उत्पादन	उत्पादन
१,५०,००० टन	१,२०,००० टन	२५,००० टन

कागज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ योजनायें बनाई गई हैं, किन्तु यह सम्भावना कम है कि इस योजना की अवधि में उन पर अमल हो सके।

सीमेंट—आजकल देश में सीमेंट के ३५ कारखाने हैं। इनकी उत्पादन क्षमता ९७ लाख टन है। १९६२-६३ में ८८ लाख टन सीमेंट तैयार हुआ होगा, जब कि तीसरी योजना का लक्ष्य १३० लाख टन है। पिछले कुछ वर्षों से सीमेंट की मांग लगभग बढ़ रही है। शहरों, कारखानों, रेलवे पुलों, छोटे व बड़े बांधों में सीमेंट का खर्च भीषण गति से बढ़ता जा रहा है। इसलिए यह सम्भव है कि हमें अपने लक्ष्य और भी ऊंचे करने पड़ें। प्रस्तावित लायसेंस प्राप्त परियोजनाओं के पूर्णतः अमल में आने पर १८८ लाख टन उत्पादन क्षमता हो जायगा। सीमेंट के कारखानों के लिए अभी तक हमें पूरी मशीनरी उपलब्ध नहीं होती। इसलिए भी नये कारखाने बनाने में विलम्ब हो रहा है। उत्तर प्रदेश और आन्ध्र में सार्वजनिक क्षेत्र में पोलैंड व जैकोस्लोवेकिया की सहायता से ४०० टन दैनिक क्षमता के दो कारखाने खोलने का निश्चय किया गया है। भिलाई, दुर्गापुर और रूरकेला के कचरे से भी सीमेंट बनाने की योजना विचाराधीन है।

कपड़ा—तीसरी योजना में सूती कपड़े का उत्पादन लक्ष्य ५८० करोड़ गज और सूत का २२५ करोड़ पौंड रखा गया है। इसके लिए लूम और तकुए क्रमशः २.२५ और १६५ करोड़ तक बढ़ाये जायेंगे। आज देश में ४६० सूती मिलें हैं और उनमें १३९ लाख तकुए और २ लाख सांचे हैं। १९६२-६३ में कपड़े और सूत का उत्पादन क्रमशः ५२० करोड़ गज और १९० करोड़ पौंड हुआ था। तीसरी योजना के अन्त तक दोनों के लक्ष्य पूर्ण हो जाने की सम्भावना हो सकती है, किन्तु निर्यात का लक्ष्य ८५ करोड़ गज पूर्ण हो सकेगा, इसमें सन्देह है। अभी तो वस्त्र निर्यात में निरन्तर कमी हो रही है। सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए मिलों से कहा है कि हम स्वचलित लूम चलाने की अनुमति उन कारखानों को देंगे, जो अपने उत्पादन का ५० प्रतिशत निर्यात करने की गारण्टी दें। उन्हें प्रति लूम १३,३३३ गज उत्पादन करना होगा। कितनी सूती मिलें यह गारण्टी दे सकेंगी यह हम नहीं कह सकते।

जूट—१२ लाख टन प्रति पाली उत्पादन क्षमता तथा १३ लाख टन उत्पादन के लक्ष्य तीसरी योजना में रखे गये हैं, जबकि आज जूट का उत्पादन ११ लाख टन होता है। पाठकों को सम्भवतः मालूम होगा कि जूट की कमी के कारण जूट मिल संघ ने अपने सदस्य मिलों पर समय और सांचों की पाबन्दी लगाई थी। अब वह पाबन्दी कच्चा माल आवश्यक मात्रा में मिलने के कारण हटा ली गई है। जूट के निर्यात का लक्ष्य योजना आयोग ने ९ लाख टन वार्षिक रखा है। इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए एक कमेटी ने जो सिफारिशें की थीं, उन पर सरकार विचार कर रही है।

चीनी—आज भारत के चीनी उद्योग की उत्पादन-क्षमता २६.७ लाख टन वार्षिक है। जिन नये व्यवसायियों को चीनी उत्पादन के लायसेंस दिए गए हैं, यदि वे काम करने लगें तो ३३.५ लाख टन उत्पादन क्षमता पूरी हो जायगी, यों लक्ष्य ३५ लाख टन का है। परन्तु इन सब नये कारखानों के बन जाने और पूरी ताकत से काम करने की सम्भावना कुछ कम है। १९६०-६१ में गन्ने की फसल बहुत अच्छी हुई थी, और गन्ना पेरने के दिन भी कुछ अधिक हो गये थे, इसलिए ३० लाख टन चीनी पैदा हुई। ३० लाख टन चीनी का खपाना कुछ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कठिन हो गया, इसलिए दूसरे वर्ष अतिरिक्त चीनी उत्पादन के लायसेंस नहीं दिए गए। परिणाम यह हुआ कि १९६१-६२ में चीनी का उत्पादन केवल २७ लाख टन हुआ और १९६२-६३ में तो २३ लाख टन से अधिक की आशा नहीं है। इस अवधि में निर्यात की सम्भावना भी बढ़ चुकी है। विदेशों में चीनी के मूल्य भी काफी बढ़े हैं।

चीनी मिलों के सामने आज एक नया प्रश्न भी पैदा हो गया है। गन्ने की खोई कागज बनाने के काम आ सकती है। किन्तु चीनी मिलें उसको ईंधन के रूप में प्रयोग करती हैं। यदि उन्हें कोई नया ईंधन सस्ते मूल्य पर मिल सके, तो वे खोई को कागज के लिए दे सकती हैं।

मशीनों का निर्माण—भारत के उद्योग तब तक स्वावलम्बी नहीं हो सकते, जब तक हम स्वयं कारखानों की मशीनें न बनाने लगें। रासायनिक खाद, इस्पात, रसायन, चीनी, सीमेंट, कागज और सूती कपड़ा आदि के कारखानों के लिए मशीनरी भारत में ही बनानी चाहिए। इस दिशा में भारत ने इस अवधि में कुछ न कुछ प्रगति अवश्य की है, अनेक भारी-भारी मशीनों के कारखाने बने भी हैं और बन भी रहे हैं। भोपाल में भारी मशीनों का कारखाना शीघ्र ही और अधिक विकसित किया जायगा। जैकोस्लोवेकिया और रूस आदि इस उद्योग में भारत को सहयोग दे रहे हैं। किन्तु इस उद्योग के लिए भी यह जरूरी है, कि हम बढ़िया कोयले और लोहे की खानों का विकास करें। यातायातकी सुविधायें भी हमें बढ़ाने होंगी।

यद्यपि हमने अनेक उद्योगों में काफी प्रगति की है तथापि लोहे इस्पात, मशीनी औजार, खाद, कागज, सीमेंट आदि उद्योगों में हम पिछड़े हुए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में अभी तक भारी उद्योग प्रारम्भिक अवस्था में ही हैं। इसलिए यह सम्भावना अवश्य है, कि हमें अनेक प्रयोजनायें चौथी योजना में पूर्ण करनी पड़ें। कोटा और केरल में सूक्ष्म औजारों तथा भूपाल, रानीपुर, और रामचन्द्रपुरम के कारखाने भी इस योजना में पूर्ण होने की आशा नहीं है। इस अवधि में प्रारम्भ की गई अनेक योजनाओं का फल भी सम्भवतः आगामी २ वर्षों में दीखने लगेगा।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड का विस्तार हो रहा है। और बहुत सम्भवतः तीसरी अवधि के अन्त तक यह पूरा भी हो जायगा। योजना के अनुसार कार, व्यापारिक गाड़ियों, जीप, और स्टेशन वैगन आदि का उत्पादन लक्ष्य भी पूरा हो सकेगा, इसमें सन्देह है। ६० हजार व्यापारिक गाड़ियों का लक्ष्य शायद ५४ हजार से ऊपर न जा सके। बाइसिकलों का लक्ष्य २० लाख निर्माण का है, किन्तु जब तक साइकलों का मूल्य कम न हो, तब तक यह लक्ष्य पूरा हो सकेगा, यह नहीं कहा जा सकता।

● ●

मित्र देशों की सहायता

भारत मित्र देशों ने अगस्त में पुनर्विचार के बाद जो जो राशि विकास-योजनाओं की सहायता के लिए देने का निश्चय किया है, वह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जायगा—

(मिलियन अमेरिकन डालरों में)

	१९६१-६२	१९६२-६३	१९६३-६४
अमेरिका (सं.रा.)	५४५	४३५	४३५.०
आस्ट्रिया	—	५	७.०
इटली	—	५१	४५.०
कनाडा	२८	३१	३०.५
जर्मनी (पश्चिमी)	२२५	१३९	९९.५
जापान	५०	५५	६५.०
फ्रांस	१५	४५	२०.०
बैल्जियम	—	१०	१०.०
ब्रिटेन	१८२	८४	८४.०
नीदर लैंड	—	११	११.०
विश्व बैंक	२५०	२००	२४५.०
	१२९५	१०७०	१०५२.०

अतिरिक्त सहायता

मित्र-देश—पं जर्मनी, ब्रिटेन व जापान	३०
अन्य देश	३०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सांख्यिकी :

उत्पादन कर निरन्तर बढ़ रहे हैं—भारत को कृषि से आय—राज्यों में प्रति एकड़ उपज—मित्र देशों की भारत को सहायता।

उत्पादन कर में निरन्तर वृद्धि

वर्ष	कराधान पदार्थ	केन्द्र का कुल उत्पादन कर	कुल करों से केन्द्र को आय	कुल करों का प्रतिशत उत्पादन कर
१९२०-२१	२	२.८५	६०.८५	४.६८
१९२५-२६	३	३.२१	७२.८६	४.४१
१९३१-३२	४	६.१९	७५.६२	८.१९
१९३८-३९	८	८.७२	८१.८७	१०.६५
१९४८-४९	१५	५०.०९	३८५.१८	१३.००
१९५३-५४	१५	९३.५२	४२४.६४	२२.०२
१९५४-५५	१९	१०७.९१	४६०.२५	२३.४५
१९५५-५६	२७	१४६.८६	४९२.२२	२९.८४
१९५६-५७	३०	१९०.५७	५७८.७२	३२.९३
१९५७-५८	३२	२७४.४४	७०४.३३	३८.९६
१९५८-५९	३२	३१२.७४	७२२.६६	४३.२८
१९५९-६०	३२	३६४.२३	८२३.१८	४४.२५
१९६०-६१	४१	४१३.१६	९१७.७७	४५.०२
१९६१-६२	५८	४८१.७९	१०६३.५३	४५.३०
१९६२-६३	६७	५५०.५९×	११९०.२४×	४६.२६
१९६३-६४	६७	६९६.३२××	१५०१.०८×	४६.३९

× संशोधित बजट किए आंकड़े

×× बजट के अनुमानित आंकड़े

कृषि से आय (करोड़ रु० में)

	१९५५-५६	१९६०-६१
भारत	—	६२७२
आंध्र	३७८.८	४६७.७
आसाम	१४८.४	२१७.५
उड़ीसा	१६५.८	२७५.८
उत्तर प्रदेश	५६५.३	१०३९.६
केरल	१७३.८	२४९.९
गुजरात	२०८.८	३३३.५
पंजाब	२३६.७	३९१.०
पश्चिमी बंगाल	२६५.८	५१३.४
बिहार	३७२.५	४४६.२
मद्रास	३१५.८	४५१.८
मध्यप्रदेश	३६४.३	४८३.५
महाराष्ट्र	३२७.५	६१८.०
मैसूर	२२४.३	३६०.४
राजस्थान	२०२.२	२५५.५

राज्यों में प्रति एकड़ उपज (रुपयों में)

	उपज	उपज के अनुसार क्रम
आंध्र	१५६.६५	१०
आसाम	३४७.७८	२
उड़ीसा	१८०.८०	६
उत्तर प्रदेश	१६७.०९	७
काश्मीर	२३१.११	५
केरल	४४५.४४	१
गुजरात	१३६.७७	१३
दिल्ली	१६४.७३	८
पंजाब	१५५.५५	११
पश्चिमी बंगाल	३१३.३१	३
बिहार	१६१.५३	९
मद्रास	२८२.८७	४
मध्यप्रदेश	१०६.१०	१६
महाराष्ट्र	१३२.८	१५
मैसूर	१३७.९४	१२
राजस्थान	७१.३४	१७
हिमाचल	१३६.०४	१४
सब राज्य	१६०.६१	

—दोनों तालिकाएं नेशनल कौंसिल आफ़ एप्लाइड इकानामिक रिसर्च की एग्रिकलचरल इन्कम बाई स्टेटस (१९६०-६१) से।

(पृष्ठ ४०१ भी देखिये)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

देश का उपेक्षित, किन्तु महत्त्वपूर्ण वर्ग

श्री ब्रज भूषण सरन, अध्यक्ष दिल्ली हिन्दुस्तानी मर्केंटाइल एसोसियेशन

कृषकों के बाद दूसरे स्थान पर व्यापारी

हमारे देश में अधिकांश जनता खेती करके अपना निर्वाह करती है। इसके बाद दूसरा बड़ा वर्ग व्यापार करके तरह-तरह की चीजों को लाकर और वितरण करके तथा उन्हें जनता तक पहुँचा कर अपनी जीविका पैदा करता है। इसके बाद तीसरा वर्ग कारखानों में काम करने वालों का बनता है और फिर चौथा वर्ग ऐसा बनता है, जिसे सरकारी सेवा में रहने का सौभाग्य प्राप्त है। सारा देश सरकारी सेवा करके जीविका उपार्जन कर सके, यह हमें अपने देश में आशा नहीं है। ऐसी प्रणाली साम्यवादी यानी कम्यूनिस्ट देशों में है। हमारा ध्येय सारे देशवासियों को केवल सरकारी कर्मचारी बनाने का नहीं है। इसलिए हमारे देश में ऐसे लोग अवश्य रहेंगे, जो सरकारी कर्मचारी न रहकर भी जीविका उपार्जन कर सकें। सारे देश के लोग खेतीबाड़ी में भी नहीं लग सकते। वास्तव में देश के कोने-कोने में व्यापार करना और चीजों का वितरण करना भी आवश्यक होगा। इसलिए देश की काफी सख्या व्यापार में लगी रहेगी और उसी से अपनी जीविका उपार्जन कर सकेगी।

आज दुर्भाग्यवश आजादी के बाद भी व्यापारी वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है तो सरकार द्वारा उपेक्षित है। यह जानते हुए भी कि देश की कुल जनसंख्या में हमारा खेतीबाड़ी करने वालों के बाद दूसरा नम्बर है, हमसे सरकार कोई मशवरा तक लेना जरूरी नहीं समझती। आखिर क्यों? किस लिए?

सबसे सस्ती मशीनरी

मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख हो रहा है कि आज देश के व्यापारी वर्ग को बिचौलिया (मिडल मैन) कहकर एक अनावश्यक वर्ग समझकर हटाने का प्रयत्न किया जा रहा है और नये तरीके अपनाकर व्यापार की श्रृंखला को छिन्न-भिन्न करने का प्रयत्न किया जा रहा है। हम सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जिस व्यापारी वर्ग को आप मिडिल मैन कहकर हटा देना चाहते हैं, उससे सस्ती और तत्पर सेवा करने वाली दूसरी कोई भी मशीनरी न बन सकी है और न बन सकेगी। सही मायनों में देश की आबादी सात लाख गांवों में, जो काश्मीर से कन्याकुमारी तक रेतीले मैदानों, पहाड़ी स्थानों तथा दुर्गम ऊबड़-खाबड़ स्थानों में बसी हुई है, उनकी आवश्यकताओं की वस्तुएं पहुंचाना सिर्फ व्यापारी ही के बस की बात है। क्या उन छोटे-छोटे गांवों में जिनकी आबादी १०० से भी कम है, कोई और साधन व्यापारियों के अलावा उनकी आवश्यकताओं को पूरी कर पाएगा और उसी लगन और मेहनत से जैसे कि आज तक व्यापारी सदैव से करता चला आया है। आज वितरण की कोई भी नई योजना व्यापारी वर्ग को हटा कर चालू करना किसी भी तरह से देश की जनता और सरकार के हित में नहीं है। अगर ऐसी कोई नई योजना थोपने की कोशिश की भी गई तो उसके कई भयानक परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक ओर करोड़ों व्यक्ति बेरोजगार हो जायेंगे, जो स्वयं में एक बहुत बड़ी समस्या हो जायेगी। दूसरी नई मशीन उस सेवा भाव से और कम खर्च पर कार्य नहीं कर सकती जो आज व्यापारी वर्ग कर पा रहा है। अगर सरकार वर्तमान वितरण कार्य में कुछ दिक्कत महसूस करती है, तो हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि वह देश में फैली हुई व्यापारिक संस्थाओं (Associations) को विश्वास में लेकर और उनसे मशवरा करके उनके कन्धों पर इसकी जिम्मेवारी डाले। हम यकीन और पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकते हैं और सरकार को विश्वास दिलाते हैं कि हम अपनी जिम्मेवारी को निभायेंगे और एक नया आदर्श देश के सामने रख सकेंगे। सरकार केवल वैधानिक तरीके से उन एसोसिएशनों को थोड़ी सी क्षमता उन कार्यों को पूरा करने के लिए प्रदान करे।

क्या उद्देश्य पूरे हो रहे हैं?

आज हमारे वस्त्र व्यवसाय के सामने तो बहुत सी

(शेष पृष्ठ ४२६ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पोलैण्ड व भारत के आर्थिक सम्बन्ध

सफलताएं व सम्भावनाएं

प्शोमिस्वाज ओग्रोजिंस्की

पोलैण्ड तथा भारत के बीच सहयोग अनेक वर्षों से सुचारु रूप से बढ़ रहा है। दोनों पक्षों के लिए लाभपूर्ण इस रचनात्मक सहयोग का एक ज्वलन्त उदाहरण है, आर्थिक सम्बन्ध, जो वस्तुतः हर साल अधिकाधिक महत्व-पूर्ण होता जा रहा है, दोनों देशों के विदेश व्यापार में अधिकाधिक महत्व ग्रहण करता जा रहा हैं। यह बढ़ता हुआ सम्बन्ध इस सिद्धान्त की सचाई की पुष्टि करता है कि औद्योगीकरण में लगे दो देशों के बीच फलप्रद सहयोग सम्भव ही नहीं है, बल्कि इस सहयोग के फलदायक विकास की वस्तुपरक सम्भावनाएं भी मौजूद हैं।

हम भारत को खान-मशीनें सप्लाई करते हैं, पर साथ ही हम भारत में खान-मशीनें तैयार करने वाले कारखानों के निर्माण का भी जिम्मा खुशी-खुशी लेते हैं। और, हम उन दिनों की उत्साहपूर्वक प्रतीक्षा करेंगे, जब ये कारखाने "भारत में निर्मित" खान-मशीनें तैयार करना शुरु कर देंगे, जो आपके देश के और भी औद्योगीकरण में, भारत की महत्वाकांक्षी आर्थिक योजनाओं की सफल पूर्ति में सहायक होंगी।

पोलैण्ड तथा भारत के बीच वार्षिक व्यापार-आवर्त एक गुणात्मक पहलू प्रकट करता है कि दोनों देशों के आपसी आर्थिक सम्बन्ध विकास पर हैं। १९५९ में पोलिश-भारतीय व्यापार-आवर्त ५८३ लाख रुपये का रहा था। १९६० में यह बढ़कर ६८८ लाख रुपये का हो गया, और १९६१ में १२ करोड़ रुपये पर पहुँच गया। १९६२ में यह व्यापार-आवर्त १९ करोड़ रुपये से अधिक हो गया। इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि १९६३ में यह २० करोड़ रुपये से भी ऊपर पहुँच जाएगा।

पिछले वर्षों में हमारे व्यापारिक आदान-प्रदान की रचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उदाहरणार्थ, हमारे व्यापारिक सम्बन्धों के प्रथम वर्षों के विपरीत, अब भारत से पोलिश आयातों में भारतीय उद्योग के उत्पादन अधिकाधिक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करते जा रहे हैं, जिनमें टैक्स-टाइल मशीनरी का उल्लेख किया जा सकता है। दूसरी ओर, आज भारत को पोलिश निर्यातों में पूर्ण औद्योगिक कारखानों का मुख्य तथा बुनियादी स्थान है। ये कारखाने भारत को दो ऋण-समझौतों के अन्तर्गत प्रदान किये जाते हैं—एक १९६० का और दूसरा १९६२ का। इन दोनों समझौतों के अन्तर्गत पोलैण्ड द्वारा भारत को २९.८ करोड़ रुपये मूल्य के पूर्ण औद्योगिक कारखानों की डिलीवरी की व्यवस्था है। उपर्युक्त समझौतों में परिकल्पित परि-योजनाओं में जिनका निर्माण शुरू हो चुका है या शीघ्र ही शुरू होने वाला है, सुदामडीह में गहरी कोयला खान, बरौनी में बिजलीघर, गींडी में एक कोल-वाशरी, हैदराबाद में एक मशीनरी औजार फैक्टरी, फरीदाबाद में एक मोटर-साइकिल तथा स्कूटर फैक्टरी, और बम्बई बन्दरगाह में खत्तियों का जिक्र किया जा सकता है।

इसके अलावा, भारत के राज्यीय शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया को पोलिश निर्मित मालबाही जहाजों (१०००० डी० डब्लू० टी०) की डिलीवरी के लिए अनु-बन्धों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। पोलैण्ड भारत को कुल ७०० मैगावाट क्षमता के ताप-बिजलीघरों की सप्लाई के लिए भी केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग के साथ बात-चीत कर रहा है।

सम्भवतः, पोलिश-भारतीय आर्थिक सहयोग का सबसे महत्वपूर्ण भाग कोयला खान उद्योग के क्षेत्र में सहयोग का है, जो हमारे दोनों देशों के परस्पर लाभ के लिए सफलता-पूर्वक विकसित हो रहा है।

पोलैण्ड का कोयला खान उद्योग में लगभग २०० साल का अनुभव है। यह प्रतिवर्ष ११ करोड़ टन कोयला पैदा करता है और दुनिया के अग्रणी कोयला निकालने वाले देशों में है। यह भारत में इस महत्वपूर्ण उद्योग के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, करना चाहता है और सम्भवतः करेगा। हमने भारत में

(शेष पृष्ठ ४२५ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली-उद्योग की दो समस्याएं

दिल्ली की अपनी विशेष परिस्थिति के कारण यहाँ उद्योगों के सामने दो समस्याएं अधिक विषम रूप में उपस्थित होती हैं। इस सम्बन्ध में दिल्ली व्यापार संघ के भूत-पूर्व दो अध्यक्षों के विचार यहां दिये जा रहे हैं।

श्रमिकों का आन्दोलन

श्री भीकूराम जैन

दिल्ली के उद्योग को जिन कुछ कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनमें से एक मुख्य समस्या यहां श्रम आन्दोलन है। यों तो प्रायः सभी औद्योगिक केन्द्रों में किसी न किसी रूप में श्रम समस्या विद्यमान है किन्तु राजधानी होनेके कारण दिल्ली की समस्या और भी कठिन हो गई है। यहां संसद होती है और विविध राजनैतिक दलों के नेता यहां प्रायः आते रहते हैं। यह राजनैतिक दल कोई न कोई आन्दोलन छेड़ने के लिए यहां की जनता को और विशेषकर मजदूर जनता को अपना औजार बनाये रखते हैं—संसद के सदस्य और केन्द्रीय अधिकारी इन राजनैतिक नेताओं की बात किसी तरह सुन लें, इसके लिये वे शहर के बाजारों में जलूस, प्रदर्शन तथा प्रमुख स्थानों पर सभाओं का आयोजन करते हैं। दिल्ली की इस स्थिति और उसके कारण उत्पन्न कठिन समस्या को पूरी तरह अनुभव नहीं किया गया। इस विशेष परिस्थिति के कारण दिल्ली के श्रमिकों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अनुशासन को कायम रखना बहुत कठिन हो गया है।

श्रमिकों के अधिकारों पर कुठाराघात न करते हुये भी यह तो आवश्यक दीखता है कि मजदूर संघों को बाहर के राजनैतिक दलों और नेताओं के अनुचित प्रभाव से मुक्त रखा जाये। श्रमिकों को उन राजनैतिक आन्दोलन कारियों के हाथों का औजार बनने से रोका जाये, जो पार्लियामेंट और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिये प्रयत्न करते हैं। दिल्ली के उद्योगपतियों का यह अनुभव है कि मजदूर नेता ऐसे कार्यों के लिए जलूस निकालते और प्रदर्शन करते हैं जिनका केवल मजदूरों से खास सम्बन्ध नहीं होता। वे राजनैतिक उद्देश्य से आन्दोलन करते हैं और उसका मूल्य चुकाना पड़ता है दिल्ली के उद्योग के उत्पादन में अनुशासन को। इसलिए मेरी नम्र सम्मति में इण्डियन ट्रेड कानून में दिल्ली के मजदूर संघों पर यह पाबन्दी लगा देनी चाहिये कि वे किसी बाहरी आदमी को अपना अधिकारी न चुनें।

दिल्ली के उद्योग को श्रमिकों की ऐसी मांगें भी सुननी पड़ती हैं, जो उद्योग की क्षमता से बाहर होती हैं। दूसरे औद्योगिक केन्द्रों में ऐसी मांगें नहीं की जातीं। औद्योगिक विवाद का प्रश्न निर्णय के लिये ट्रिब्यूनल को सौंपने का कानून १३ वर्षों से जारी है। श्रमिक इसी प्रश्न को औद्योगिक विवाद कहकर न्याय के लिये ट्रिब्यूनल के पास पेश करने की मांग करते हैं, लेकिन बिना किसी विचार के हर एक प्रश्न को ट्रिब्यूनलों के पास भेजने से हर एक प्रश्न खटाई में पड़ जाता है। जिन प्रश्नों पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुका है, उनको बार-बार ट्रिब्यूनलों के पास नहीं भेजा जाये। १७ वें भारतीय श्रम सम्मेलन में कुछ ऐसे आधार निश्चित किए गए थे, जिनको देखते हुए ही एक प्रश्न का ट्रिब्युनल के पास भेजने या न भेजने की सलाह दी गई थी।

बिजली की कमी

श्री एस० पी० बरमानी

दिल्ली को अब अधिकारियों ने नागरिक और औद्योगिक क्षेत्र स्वीकार कर लिया है और इससे दिल्ली के उद्योगों के बाहर चले जाने का खतरा भी कम हो गया है। उद्योगों के प्रति उदासीनता की नीति ने दिल्ली के उद्योगों को बहुत नुकसान पहुँचाया है। इस कारण आज यह आवश्यक है कि हम अपनी उस क्षति पूर्ति के लिए प्रभावकारी कदम अधिक तेजी से उठावें।

दिल्ली में सबसे पहली आवश्यकता उद्योगों को बिजली पहुंचाने की है। यह बहुत दुख की बात है कि दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

म्युनिसिपल कार्पोरेशन स्वयं तो बिजली पहुँचाने की अपनी जुम्मेवारी निभाने में असमर्थ है और यदि कोई उद्योग स्वयं बिजली पैदा करता है तो उस पर भी कार्पोरेशन ने टैक्स लेकर अपनी आमदनी बढ़ाने का तरीका ढूंढ़ लिया है। वह टैक्स लगाकर उद्योगों को स्वयं बिजली पैदा करने से अनुत्साहित करता है, दूसरी ओर वह स्वयं बिजली देने में भी असमर्थ है। दिल्ली बिजली निगम ने उद्योगों को यह स्पष्ट कह दिया है कि वह कुछ वर्ष तक औद्योगिक विस्तार के लिए अधिक बिजली नहीं दे सकेगा। इस समस्या का एक ही हल है कि उद्योगों को स्वयं बिजली पैदा करने की अनुमति दी जाये।

दिल्ली राज्य की अधिकांश आबादी नगरों में रहती है। इस कारण यह स्वाभाविक ही है कि देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा दिल्ली में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत अधिक है। फिर दिल्ली में अपेक्षाकृत अधिक आमदनी वालों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। इससे भी यह स्वाभाविक है कि दिल्ली में प्रति व्यक्ति की खपत अधिक है। दिल्ली की बहुत बड़ी संख्या बिजली के पंखों, रेडियो तथा हीटर आदि में बिजली उपयोग करती है। इसका परिणाम यह होता है कि विभिन्न उद्योगों को उनकी अपनी आवश्यकता से बहुत कम बिजली मिल पाती है। इस कारण यह आवश्यक है कि दिल्ली की बिजली समस्या को हल करने के लिए शीघ्र ही प्रभावकारी कदम उठाये जायें।*

*ये विचार दिल्ली विकास अंक में स्थानाभाव से नहीं दिये जा सके थे। —सम्पादक

सपना सच्चा हुआ

नन्हे बच्चों के सपने बड़े ही मधुर होते हैं—मिठाइयों, बिस्कुटों आदि से भरे हुए!
उनके सपनों की ऐसी ही प्यारी चीजों में से हैं...स्वादिष्ट व पौष्टिक साठे माल्टेक्स बिस्कुट
जिन्हें खाकर उनका सपना सच्चा हो जाता है।

साठे बिस्कुट
पीढ़ियों के लिए शक्ति!

साठे बिस्कुट एण्ड चॉकलेट कंपनी लिमिटेड, पूना—२

SPI/SSC-187 HIN

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अति लाभकर के आर्थिक परिणाम

श्री धीरजलाल मगनलाल उपाध्यक्ष, इंडियन मर्चेन्ट्स चेम्बर

वितमंत्री ने अपने बजट भाषण में नये कराधान के तीन उद्देश्यों का उल्लेख किया था: (१) देश की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाना; (२) देश में उत्पादन की वृद्धि करना और (३) औद्योगीकरण तथा पूंजी-निर्माण में सहायता देना। लेकिन हाल ही के वर्षों में पूंजी बाजार की इतनी असन्तोषजनक स्थिति किसी अन्य कारण से नहीं हुई, जितनी कि अकेले अति लाभ कर ने कर दी है।

देश की अधिकांश जनता ने प्रतिरक्षा सम्बन्धी जिम्मेदारी को देखते हुए अधिक कर देने की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया है, लेकिन इसके साथ-साथ यह भी आशा की गई थी कि वित मंत्री इस तरह से अपने कर लगायंगे, जिससे कि उत्पादन निवेश में अवरोध पैदा न होगा, जो निस्सन्देह हमारे प्रतिरक्षा-प्रयत्नों का प्रमुख आधार है।

सच यह है कि १९६३-६४ के बजट पेश होने के बाद की घटनाओं का असर वितमंत्री की आशाओं के विपरीत ही हुआ। शेयर बाजार एक तौर से खत्म हो गये और शेयरों की कीमतें गिर गईं। निवेश की इस वर्तमान अवरुद्ध दशा का सबसे बड़ा कारण है अति लाभ कर। इस योजना के अन्तर्गत एक कम्पनी को उस समय अति लाभ कर देना पड़ता है, जब उसकी आमदनी आयकर और अतिकर काटने के बाद अदा की गई शेयर पूंजी और आरक्षित रकमों से ज्यादा होती है। हालांकि एक साधारण व्यक्ति अति लाभ कर कानून को पढ़ने के बाद यही समझता है कि यह कर "अति" लाभों पर ही लगाया जाता है, लेकिन सामान्य लाभों एवं अति लाभों के बारे में सरकार की अपनी मान्यताएं होती हैं। सरकार के अनुसार करों के अदा करने के बाद अदा की गई शेयर पूंजी की ६ प्रतिशत तक की मात्रा ही सामान्य लाभ मानी जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा किये गये ऐसी १००१ कम्पनियों के एक सेम्पल सर्वे के अनुसार, जिनकी १,०६० करोड़ रुपये की पूंजी और आरक्षित निधियों पर कर अदा करने के बाद सालाना अन्दाजन ११० करोड़ रुपये का लाभ था, पता चला है कि एक कम्पनी की सामान्य लाभ की दर १० प्रतिशत है। अतः लाभों के बारे में सरकार के विचार गलत हैं और वास्तव में जिस पर कर लगाया जाता है "अति" लाभ नहीं है, बल्कि सामान्य लाभ है।

आज शेयर बाजार में विश्वास बहुत शिथिल हो गया है और इस कारण लोग पूंजी नहीं लगाते हैं। बजट की घोषणा के बाद से बाजार में एकदम मन्दी आ गई और औद्योगिक सेक्यूरिटियों के विभिन्न डिविडेण्डों को सूचनांक मई १९६२ के १९५ से तेजी से गिर कर दिसम्बर १९६२ में १७१ (सीमा पर आक्रमण तथा अनिश्चित वातावरण के कारण) हुआ और फिर नये बजट के पेश होने के बाद १९६३ में यह सूचकांक १५९ की अत्यन्त निम्न सतह तक पहुँच गया है। शेयर बाजर की कीमत में २० प्रतिशत गिरावट के आधर पर १८३० करोड़ रुपये की कुल कीमत पर पूंजी लगाने वालों को ३६० करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। डिवीडेण्डों की गिरावट से पूंजी लगाने वाली जनता का विश्वास पूरी तरह से हिल गया है। अपेक्षा तो यह की गई थी कि कम से कम सरकार पिछले अनुभवों तथा १९५६ से लागू किये जानेवाले विभिन्न "समाजवादी" बजटों से होनेवाली पूंजी बाजार की प्रतिक्रियाओं से कुछ सीखेगी। वर्ष १९५२-५३ (१००) से सूचकांक में क्रमशः वृद्धि हुई और १९५६ में वह १४१ तक पहुंचा। लेकिन टी. टी. के बजट के बाद, जिसे १९५६ में पेश किया गया था और जिसने तथाकथित "प्रगतिशील" के युग का सूत्रपात किया, साया ढा गया और बाजार में यकायक २५ प्रतिशत की मन्दी आ गई और सूचकांक ११७ रह गया। यह स्थिति वास्तव में काफी गंभीर थी। उसमें कुछ सुधार करने की कोशिशें भी हुईं। नये वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने कुछ महत्वपूर्ण करों में रियायतें दीं जैसे कि कम्पनियों पर से सम्पत्ति-कर (वेल्थ-टेक्स) की वापिसी, बोनस कर में कमी और कम्पनियों पर लागू होनेवाली अनिवार्य बचत योजना की वापिसी तथा व्यय-कर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

का स्थगन। निस्सन्देह, इन कदमों की वजह से बाजार में विश्वास फिर जग उठा, पूंजी अधिक उत्साही बनी और नई कम्पनियों में रकमें ३५ करोड़ रुपये से बढ़कर ६० करोड़ रुपये सालाना तक जा पहुँचीं और साथ साथ समान आधार पर विदेशी पूंजी का सहयोग भी मिला।

फिर आया अतिलाभ कर

लेकिन अति लाभ कर की शुरुआत से न केवल कम्पनियों द्वारा घोषित डिविडेण्डों में कटौती हुई, बल्कि बाजार में जारी की गई नई पूंजी की मात्रा में भी भारी गिरावट का रुख दिखाई देने लगा है। इस वर्ष १२० कम्पनियों में से, जिन्होंने डिवीडेण्ड घोषित किया है, ३४ बड़े कारपोरेशनों ने डिवीडेण्डों में १० से २६ प्रतिशत कटौती कर दी है। शायद कराधान का यह अत्यन्त निष्ठुर पहलू है।

सरकार ने यह धारणा पैदा की है कि इस कर भार का खास असर कुछ थोड़ी सी बड़ी कम्पनियों पर पड़ेगा। लेकिन बात ऐसी नहीं है। इस कराधान के पीछे "सहन क्षमता" का सिद्धान्त नहीं है, "कमाने की क्षमता" का है। इस दृष्टि से यह कर अन्यायपूर्ण है और वह कुशलता पर कर है क्योंकि, हजारों छोटी कम्पनियों में से अनेकों के पास बहुत थोड़ी पूंजी का आधार है लेकिन उनकी कमाने की क्षमता उनकी पहल, साहस एवं संचालन कार्यकुशलता के कारण काफी अच्छी है। ऐसी छोटी कम्पनियों पर कर का काफी बुरा असर पड़ेगा और छोटी-छोटी रकमें लगाने वालों को इससे सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। वर्ष १९६०-६१ में कराधान के लिए आंकी गई कम्पनियों की कुल संख्या ९,९५९ थी। दो लाख रुपये तक की आमदनी वाली कम्पनियों की संख्या ८,५०० थी। इसी प्रकार २ लाख और ५ लाख रुपये के बीच आमदनी वाली ६५९ और ५ लाख रुपये से अधिक आमदनी वाली ७८० कम्पनियां थीं। कुल १२२ करोड़ रुपये के कर भार में से ये कम्पनियां क्रमशः १० प्रतिशत, ८ प्रतिशत और ८२ प्रतिशत भार वहन करती हैं। वर्ष १९६३-६४ के लिए निगमित क्षेत्र से अधिक कर प्राप्त करने की मात्रा १९६ करोड़ रुपये प्रस्तावित की गई है, जिसका बन्टजारा इन कम्पनियों में क्रमशः १९ करोड़ रुपये, १५ करोड़ रुपये तथा १६२ करोड़ रुपये का किया गया है। अति लाभ कर इसके अलावा वसूल किया जाएगा।

"इकोनोमिक टाइम्स" द्वारा किये गये शेयरों के बाजार मूल्यांकन के सातवें तिमाही सर्वेक्षण से पता चलता है कि जनवरी १९५९ के बाद जारी किये गये दो तिहाई शेयरों का भाव मूल या कम कीमत का है और उन नये शेयरों का भाव जिनकी कीमतें मार्च के अन्त में ९.९ प्रतिशत ज्यादा थीं अब केवल उनकी अदा कीमत से २.५ प्रतिशत ही ज्यादा रह गई हैं। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, इन्दौर और अहमदाबाद के सात शेयर बाजारों पर औपचारिक और अनौपचारिक रूप से खरीद बेच की जाने वाले १५७ नये शेयरों में से ८९ की कीमत बढ़े (डिस्काउन्ट) में, १४ की सम मूल्य (पार) पर और शेष ४४ की मूल्य से ज्यादा (प्रीमियम) बोली जाती है। इस तरह से प्रत्येक सात नये शेयरों में से मोटे तौर पर चार का भाव मूल कीमत से कम है। और फिर रकम लगाने वालों, कि बहुत हानि हुई है। इस बारे में यह ध्यान देने योग्य बात है कि नये शेयरों में से अनेकों ने कोई डिवीडेण्ड नहीं दिया है। इसी तरह पिछले वर्षों की प्रथम छ माहियों में जारी की गई पूंजी की तुलना में १९६१ में ५३, १९६२ में ४४ और १९६३ में केवल १४ ही थी।

अति लाभ करके प्रभाव अब दिखाई देने लगे हैं। इस कराधान से कम्पनियों द्वारा लाभों को फिर से निवेशों में बदलने की दिशा में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे विदेशी पूंजी के सहयोग को तथा विदेशी और कर्जों की अदायगी में भी भारी धक्का लगेगा। बैंकों से लिये गये कर्जों पर प्रायः ८ या ९ प्रतिशत ब्याज की दर चुकानी पड़ती है और इन करों के जरिये ६ प्रतिशत रकम कट जाने से उनकी कर्ज चुकाने की क्षमता में भी भारी बाधा पहुँचेगी। यह कर इस दृष्टि से भी अन्यायपूर्ण है कि इसमें कम पूंजी और अधिक कमाई क्षमता वाली तथा ज्यादा पूंजी और कम कमाई क्षमतावाली कम्पनियों में कोई अन्तर नहीं रखा गया है।

सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रेलों के परिचालन में डीजलीकरण

सरदार मल जैन, बी० काम०, कलकत्ता

अभी तक रेलवे यातायात में एक मात्र भाप का इंजन ही गाड़ी खींचने का साधन मात्र था, पर इधर पिछले कुछ वर्षों से उन्नत देशों में डीजल इंजनों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में डीजल गाड़ियों ने लगभग सभी भाप गाड़ियों को अपदस्थ कर दिया है। वहां आजकल लगभग ३० हजार डीजल इंजन चल रहे हैं। इंग्लैंड में भी डीजल के इंजन काफी संख्या में चल रहे हैं।

परिवर्तन क्यों ?

इस परिवर्तन के मूल में कुछ आर्थिक और तकनीकी कारण हैं। भाप के इंजन की ऊष्मा उपयोगिता कुल ४.५ प्रतिशत है, जबकि डीजल इंजन की २२ प्रतिशत। भाप इंजनों की तुलना में डीजल इंजनों में देख भाल, साफ-सफाई और संचालन पर भी बहुत कम खर्च होता है। इधर में रेल यातायात में वृद्धि और कोयले की सीमित उपलब्धि के कारण कोयले के भाव दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अतः भाप गाड़ियों की बजाय डीजल गाड़ियां चलाना सस्ता पड़ता है। यही कारण है कि अमेरिका में ९०% से ज्यादा गाड़ियां डीजल इंजनों से खींची जाती हैं। डीजल के इंजनोंमें भाप इंजनों से ऊँची कर्षण शक्ति होती है। अतः यह अधिक भार अधिक रफ्तार से खींच सकते हैं। अधिक तेज रफ्तार से चलने के कारण ये इंजन अधिक दूरी कम समय में तय कर लेते हैं। अतः रेल्वे लाइन अधिक समय खाली रहती है और इस प्रकार अधिक सुविधापूर्ण यात्रा के लिए अधिक संख्या में गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। दूसरी ओर अधिक संख्या में गाड़ियां चलाने से रेलों की आमदनी में भी वृद्धि होती है और इस बढ़ी हुई आमदनी से रेलें अधिक सुविधाएँ उपलब्ध कर सकती है।

लम्बी यात्रा वाली गाड़ियां दो या चार डीजल युगमों से खींची जा सकती है, जिन्हें संचालन करने के लिए एक ही चालक काफी होता है। यार्ड में डीजल शंटर सर्वाधिक उपयोगी और मितव्ययतापूर्ण है। मार्शलिंग यार्डों में सामान्यतया १५०० से १६०० अश्वशक्ति के शंटर काम लाये जाते हैं। भारी यातायात वाली कम दूरी के लिए डीज़ल कारें काम में लाई जा सकती है, जो बहुत जल्द तेज रफ्तार कर लेती हैं और पांच मील की दूरी ५ मिनट में तय कर लेती है। इन कारों में डीज़ल भी कम खर्च होता है, अतः यह लाभपूर्ण साधन है।

यह सही है कि डीजल इंजन बहुत ही पेचीदा यंत्र होता है, अतः इसके निर्माण में भाप इंजन से २॥ गुना ज्यादा खर्च होता है, पर निर्माण का यह भारी खर्च इससे होने वाली मितव्ययता के कारण कम ही बैठता है। भाप इंजनों की तरह इसे गर्माने में कई घंटे खर्च नहीं करने पड़ते, साथ ही काम में लाने से पूर्व भाप इंजनों में राख झाड़ने में जो समय खर्च होता है, उसकी भी बचत होती है। डीजल इंजन निर्धारित से अधिक लम्बी यात्रा के लिए भी आवश्यक ईंधन रख सकता है। बिना किसी विशेष प्रकार की देख-रेख और बदलाव के डीजल इंजन एक सप्ताह तक दिन-रात काम कर सकता है। यह इंजन एक्सल लोड को कम रखते हैं, अतः पुलों और रेल पथ को दृढ़ करने का भारी खर्च बच जाता है। इनसे गाड़ियां चलाने से चल स्टाक और स्टेशन साफ रहते हैं। इस तरह इनके रख रखाव और सफाई का खर्च बच जाता है।

भारत में डीजल इंजनों की संभावनाएं

हमारी विकास योजनाओं की सफलता के साथ देश में माल और यात्रियों का यातायात बहुत बढ़ गया है, जिसे भापके इंजन संभालने में असमर्थ हैं। भाप इंजनों की धीमी चाल, बोझ खींचने की कम क्षमता और अत्यधिक ईंधन की खपत ने देश में डीजल इंजनों के महत्व को बहुत बढ़ा दिया है। यद्यपि यह कार्य बिजली के इंजन भी कर सकते हैं, पर इसमें बाधक है देश में बिजली की कम उपलब्धि और रेलवे लाइनों के बिजलीकरण पर होने वाला भारी व्यय। अतः यह तय किया गया है कि पहले डीजल इंजनों की संख्या ही बढ़ाई जावे। इन इंजनों का महत्व इसलिए भी अधिक है कि इनको चलाने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के लिए बिजली इन्जनों की तरह किसी प्रकार के तार खंबे आदि की जरूरत नहीं, अतः ये आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाये जा सकते हैं।

बाधाएं

परन्तु भारत में इनके विकास में कई बाधाएँ भी हैं। डीजल इंजन बहुत कीमती होते हैं और इनके अनुरक्षण पर काफी खर्च करना पड़ता है। दूसरे डीजल इंजन देश में बनते नहीं और डीजल तेल भी कम मात्रा में उपलब्ध है। अतः दोनों ही चीजें विदेशों से मंगानी पड़ती हैं। विदेशी मुद्रा की कमी के साथ-साथ देश के सामने और भी कई बाधाएं हैं। आयात में समय भी ज्यादा लगता है। अभी देश में उपलब्ध डीजल तेल की औसत प्रति टन कीमत ३५० रु० है जबकि देश के विभिन्न भागों में कोयले की प्रति टन कीमत २७ रु० से ४४ रु० तक है। यदि यह मान लिया जाय कि एक टन डीजल तेल आठ टन कोयले की जमा उपयोगिता के बराबर काम करता है, तो ईंधन की लागत में समूची दक्षिण रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे एवं पश्चिमी रेलवे के सौराष्ट्र क्षेत्र में डीजल इंजनों का उपयोग लाभप्रद है। अतः भारतीय रेलों में डीजलीकरण देश में डीजल तेल की प्राप्ति पर निर्भर है। अभी हाल ही में गुजरात में तथा देश के कुछ अन्य भागों में मिले डीजल तेल खानों से भारत में डीजल इंजनों की संभावनाएं बढ़ गई हैं।

डीजल इंजनों के प्रादुर्भाव के साथ ही माल डिब्बों का डिजाइन बदलना भी आवश्यक है, ताकि वे उनके साथ तेज रफ्तार से चल सकें। इसके लिए चौपहिये डिब्बों की जगह बोगी या बम्ब और बाक्सनुमा डिब्बे ठीक रहते हैं। बड़ी लाइन पर २२५० फुट की लूप क्षमता के साथ चौपहिए माल डिब्बे वाली एक गाड़ी १५०० टन कोयला ढो सकती है, जबकि उसी खंड पर बाक्स किस्म के ४३ डिब्बों वाली २४०० टन कोयला ढो सकती है।

वर्तमान स्थिति

भारत में डीजल इंजनों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। प्रथम योजना के अन्त में भारतीय रेलों के पास ९ हजार भाप के इंजन थे और ९० से भी कम डीजल के इंजन। शुरू में बड़े-बड़े मार्शलिंग यार्डों में इन इंजनों से शंटिंग का काम लिया जाता था। बाद में पश्चिमी रेलवे के कंडला-दीगा भाग पर डीजल इंजन चालू हुए, क्योंकि यहां पानी की कमी के कारण भाप के इंजन चलाना कठिन कार्य था। दूसरी योजना में बड़ी लाइनों के लगभग १०० डीजल इंजन अमेरिका से मंगाये गये। तीसरी योजना के अन्त तक अनुमान है कि हमें ५०० से भी अधिक डीजल इंजनों की आवश्यकता होगी। अभी देश में लगभग ३८० डीजल इंजन चल रहे हैं।

आजकल दक्षिण-पूर्व रेलवे पर डीजल इंजन खानों से प्रतिदिन ३४०० टन कोयला, लोहा आदि इस्पात कारखानों को ले जाते हैं। पहले भाप इंजनों द्वारा १७०० से १८०० टन का भार ही ढोया जाता था। पहली दो योजनाओं में रेलों का यातायात अत्यधिक बढ़ा है। दूसरी योजना के दौरान रेलों ने १५ करोड़ ४० लाख टन माल ढोया, जबकि तीसरी योजना के दौरान अनुमान है रेलों को २६ करोड़ टन माल ढोना पड़ेगा। अतः हमें और अधिक डीजल इंजनों की आवश्यकता होगी।

आज तक हमने सभी डीजल इंजन बाहर से मंगाये हैं, क्योंकि देश में इनका निर्माण नहीं होता था, पर अब देश में ही डीजल इंजन बनाने का एक कारखाना वाराणसी में एक अमेरिकन फर्म के सहयोग से खोला जा रहा है। आशा है, इस वर्ष के अन्त तक यह कारखाना चालू हो जायगा। यहां प्रतिवर्ष बड़ी लाइन के १५० डीजल इंजन बनाये जायेंगे। कारखाने का सम्पूर्ण विस्तार हो जाने पर यह क्षमता २५० इंजन प्रतिवर्ष हो जायगी। इस कारखाने के लिए आवश्यक मशीनें अमेरिका से आयेंगी। इसके लिए अमेरिका की Export Import Bank ने रेलवे को १९० करोड़ डालर का ऋण दिया है। इस पर ५¾% ब्याज लगेगा और इसे १५ साल में चुकता करना होगा। इसके अलावा अमेरिकन फर्म द्वारा भारतीय इंजिनियरों को प्रशिक्षित भी किया जायगा। अभी ३ भारतीय इंजिनियर वहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त रेलवे को ५४ डीजल इंजन खरीदने के लिए अमेरिका ने १५.८५ मिलियन डालर का एक और ऋण दिया है, जिस पर ब्याज नहीं लगेगा और इसे ४० साल में लौटाया जा सकेगा। ● ○

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सुरक्षित भंडारों से अन्न के मूल्यों का नियंत्रण

श्री स. का. पाटिल

पिछले वर्षों में हमारी मूल्य नीति के आधार यही रहे हैं कि किसान को न्यूनतम मूल्य अवश्य मिले और उपभोक्ता के हितों की भी रक्षा हो। १९४८ में कुछ समय को छोड़कर, १९४३ से कपास का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य कानून द्वारा निर्धारित रहा है। विभिन्न किस्मों की कपास के मूल्य प्रतिवर्ष निश्चित किये जाते हैं। १९५०-५१ से गन्ने के मूल्य भी प्रतिवर्ष निश्चित किये जा रहे हैं सन् १९५० के शक्कर और गुड़ नियंत्रण आदेश के अनुसार और बाद में १९५५ के गन्ना (नियंत्रण) आदेश के अनुसार। पाट या जूट का न्यूनतम मूल्य भी सन् १९६१-६२ से निश्चित किया जा रहा है और उसका भंडार बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। जून, १९६० में पी० एल० ४८० समझौते के अन्तर्गत चावल और गेहूँ के सुरक्षित भंडार बनने शुरू हो गये। हां, बीच में अनाज की खपत बढ़ जाने से कुछ रुकावट जरूर आई। १९६२ में सफेद गेहूँ का न्यूनतम मूल्य ३४ रु० ८३ न. पै. प्रति क्विन्टल निश्चित किया गया। गेहूँ की दूसरी किस्म के मूल्य भी इसी प्रकार अलग-अलग निश्चित किये गये। १९६२ से सरकार ने न्यूनतम मूल्य पर चावल की खरीद शुरू कर दी। इससे दो लाभ थे, एक तो सरकार के पास चावल का अच्छा भंडार बनना, दूसरे किसान को घाटा न होना। तीसरी योजना की शेष अवधि में भी सरकार चावल व गेहूँ खरीदती रहेगी। १९६३-६४ में सरकार ने इन दोनों जिन्सों के मूल्य कुछ बढ़ा दिए हैं। अब सरकार कुछ निर्धारित मंडियों में सफेद गेहूँ ३४ रु. ५० न. पै. क्विंटल पर खरीदेगी। चावल के खरीद-मूल्य में भी ६७ न. पै. से २ रु. ६८ न. पै. क्विंटल तक की बढ़ती कर दी है। चावल व गेहूँ के बाद तीसरी महत्वपूर्ण जिन्स ज्वार है। इसे भी सरकार ने १९६३-६४ से खरीदना शुरू कर दिया है। सरकार चालू साल में सफेद ज्वार २४ रु. १२ न. पै. और पीली ज्वार २२ रु. ७८ न. पै. प्रति क्विंटल पर खरीदेगी। निश्चय किया गया है कि यदि कभी चावल गेहूँ या ज्वार के भाव गिरे तो सरकार खुद उपर्युक्त निर्धारित दाम पर इन्हें खरीदना शुरू कर देगी। इससे सरकारी भंडार भी बढ़ता रहेगा।

विदेशों से चावल व गेहूं की खरीद

जो न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है, उस पर वास्तव में खरीद हो सके, इसलिए केन्द्रीय सरकार राज्यों में चावल और गेहूँ खरीदती है। उदाहरण के लिए १९६२ में सरकार ने पंजाब, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और राजस्थान में, जहां गेहूँ के भाव गिरने का भय था, कुछ मंडियों में न्यूनतम भाव पर गेहूँ खरीदने के लिए अपने एजेंट नियुक्त किये। लेकिन उत्तरप्रदेश में बुन्देल खण्ड को छोड़कर, और सर्वत्र गेहूँ के भाव निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कुछ ऊपर ही रहे।

सस्ते अनाज की दुकान

उपभोक्ताओं के हित के लिए सारे देश में उचित मूल्य पर अनाज बेचने के लिए दुकानें खोली गई हैं। इस समय सस्ते अनाज की ५१ हजार से अधिक दुकानें हैं, जिनसे करोड़ों कम आमदनी वाले व गरीब लोग सस्ते दाम पर अनाज खरीदते हैं। इन दुकानों में चावल, गेहूँ और अन्य जरूरी जिन्स सस्ते दामों पर मिलती हैं और मूल्य वृद्धि पर रोक रहती है। सरकार अनाज के दामों के चढ़ने पर तभी रोक लगाती है, जब उसके पास अनाज का काफी स्टाक हो। इसलिए मूल्य स्थिर रखने के लिए हमें सुरक्षित अन्न भंडार बनाना बहुत आवश्यक है।

पैदावार में घट-बढ़

यहां खेती की जमीन के केवल पांचवें हिस्से में सिंचाई का प्रबन्ध है और आधे से अधिक भाग वर्षा और मौसम पर निर्भर है, जो अनिश्चित रहता है। इसका पैदावार पर बहुत असर पड़ता है। सिंचित क्षेत्रों में बहुत-सी सिंचाई तालाबों से होती है, जो स्वयं वर्षा पर निर्भर है।

फसल की खराबी और अनिश्चितता से भाव में घट-बढ़ होती है और अगले साल की पैदावार पर भी इसका

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

खराब प्रभाव पड़ता है। जूट में यही हुआ। १९५९-६० और १९६०-६१ में पाट की पैदावार कम होने से उसके भाव काफी बढ़ गये। यह देखकर किसानों ने अगले साल पाट की पैदावार बढ़ा दी और उसका भाव गिर गया। फलतः १९६२-६३ में पाट की खेती कम हुई और भाव फिर बढ़े। इस प्रकार हर साल की घट-बढ़ से योजना के लक्ष्य पूरे होने में रुकावट होती है। इसलिए खेती की महत्वपूर्ण जिन्स का भंडार बनाकर उपज और भावों के इस घट-बढ़ को रोकना जरूरी है। इससे पैदावार अधिक होने पर सरकार, बाजार से फालतू जिन्स खरीद कर भंडार में रख सकती है और कम होने पर भंडार से निकालकर बाजार में दे सकती है और मूल्यों को स्थिर रख सकती है।

यह तर्क गलत है कि विदेशोंसे अनाज मंगाने से घरेलू खेती नहीं बढ़ पाएगी। पी० एल० ४८० के समझौते में अमरीका से आने वाला गेहूँ इसका उदाहरण है। १९६० से अब तक गेहूँ की पैदावार ही नहीं बढ़ती रही, बल्कि इसके भाव भी स्थिर रहे हैं। स्थिर भाव, चाहे वे बाहर से अनाज मंगाने के कारण ही स्थिर हों, किसान को भरोसा दिलाते हैं कि अधिक पैदावार होने पर भी उसे मूल्य कम नहीं मिलेगा।

चावल

विदेशों से अनाज का आयात १० प्रतिशत चावल व ९० प्रतिशत गेहूँ होता है। लेकिन चावल खानेवाले बहुत हैं, और चावल की मांग उसकी पैदावार से कहीं अधिक। इससे चावल का भाव बढ़ता है, जबकि गेहूँ की पैदावार बढ़ रही है और भाव स्थिर है, चावल की पैदावार व भाव दोनों में ही घटबढ़ होती रहती है। पूर्वी चावल क्षेत्र में, चावल की सबसे अधिक खपत वाला बंगाल और सबसे अधिक चावल पैदा करनेवाला उड़ीसा शामिल है। हर साल चावल की पैदावार व भाव में बहुत घट-बढ़ होती है। १९६०-६१ में उड़ीसा में चावल की पैदावार अधिक हुई और भाव बहुत गिर गये थे। १९६१-६२ और १९६२-६३ में जूट की खेती का रकबा बढ़ने और खराब मौसम के कारण इस क्षेत्र में चावल की पैदावार काफी घटी और भाव बहुत बढ़े।

चावल का स्टाक कम होने से सरकार इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर सकी। भावों की घट-बढ़ से किसान को पैदावार बढ़ाने का उत्साह नहीं होता। १९५८-५९ से १९६१-६२ तक, गेहूँ की पैदावार तो २० प्रतिशत बढ़ी, पर चावल की खेती का रकबा और उपज बढ़ाने की अनेक योजनाओं के बाद भी, इसकी पैदावार केवल ६ प्रतिशत ही बढ़ पायी। गेहूँ की तरह, जब चावल का बाजार भाव स्थिर रहेगा, तभी किसान चावल की खेती पर अधिक जोर देगा। इसलिए जरूरी है कि सरकार विदेशों से या देश में खरीदकर, चावल के भंडार बनाए और इसका भाव स्थिर रखे।

गेहूँ

यह खुशी की बात है कि गेहूँ का भंडार बनाने के लिए भारत को, पी० एल० ४८० समझौते के अधीन अमरीका से गेहूँ मिल सका। इसका मूल्य भारतीय रुपए में चुकाया जाता है। इससे इस पर विदेशी मुद्रा नहीं खर्च होती। यह गेहूँ अभाव की स्थिति का सामना करने में सहायक है। इसी समझौते में हम कुछ चावल भी मंगा सकते हैं। हाल में अमरीका से १॥ लाख टन चावल मंगाने का समझौता हुआ है। देसी पैदावार और यदि जरूरी हो तो आयात से भी बड़े भंडार बनाने होंगे, तभी मूल्यों में घट-बढ़ को रोका जा सकता है।

विज्ञापन के लिए

सम्पदा

सर्वोत्तम

साधन है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विज्ञान से अमरीका की कृषि में क्रांति

डा० वायरन टी० शा

• वैज्ञानिक अनुसन्धान के फलस्वरूप पौध-प्रजनन की ऐसी विधियां विकसित हुई हैं, जिनके द्वारा ऐसे पौधे उत्पन्न करना सम्भव हो गया, जिनमें दृढ़ता, देश के क्षेत्रों में बढ़ने की क्षमता, तथा रोगों को रोकने की सामर्थ्य जैसे गुण विद्यमान हों। बहुत से पौधे उत्पन्न किये गये, जो जोतने-बोने, और काटने के लिए प्रयुक्त मशीनों के उपयुक्त थे। उदाहरण के लिए चरी के पौधों को छोटा किया गया, ताकि उसे एक कम्बाइन मशीन द्वारा काटा जा सके। इसी प्रकार सोयाबीन के पौधे को इस प्रकार बढ़ाने की विधि विकसित की गयी, ताकि वह खड़ा रहे।

कृषि अनुसन्धान के फलस्वरूप ऐसे पशु भी विकसित हुए, जो कम से कम चारे पर पल कर कम से कम समय में अधिक मोटे-तगड़े हो सकें। साथ ही, अनुसन्धान के फलस्वरूप मुर्गियों और पशुओं की किस्मों और उत्पादन में आशातीत सुधार हुए हैं। अब हमारे यहां सारे परिवार के लिए पर्याप्त मांस प्रदान करने वाली मुर्गियां, अच्छे मांस वाले सुवर और दोगली नस्ल की ऐसी भेड़ें जो श्रेष्ठतर ऊन उत्पादन कर सकें, उपलब्ध हैं। हमारे यहां ऐसी मुर्गियां हैं, जो साल में २०० अण्डे तक देती हैं। सौ वर्ष पूर्व अण्डे का उत्पादन इस का आधा भी नहीं था।

कृषि अनुसन्धान ने देश के लोगों के आहार में सुधार किया है। अब हम अधिक पौष्टिक भोजन प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें मांस, मुर्गियां, दूध, फल और सब्जियां सम्मिलित हैं। पर्याप्त भोजन मिलने के कारण लोग रोग के शिकार नहीं होते और उनकी उत्पादन-क्षमता बढ़ जाती है। कृषि अनुसन्धान के फलस्वरूप हमें ऐसी मशीनें मिली हैं, जो खेत की एक पट्टी में एक साथ ही पौधे रोप सकती है, उर्वरक फैला सकती हैं और रोगों तथा कीड़ों को रोकने के लिए दवाइयां छिड़क सकती हैं। साथ ही अनेक ऐसी मशीनें भी बनी हैं, जो किसानों का समय और श्रम बचाती हैं और उनकी क्षमता बढ़ाती हैं।

वस्तुतः विज्ञान ने अनेक प्रकार से कृषि को लाभ पहुँचाया है। इन सभी विकासों ने कृषि-क्षमता को बढ़ाने में अपूर्व योग प्रदान किया है। इन में फसलों और पशुओं की सुधरी किस्में, मिट्टी और जल-प्रबन्ध की श्रेष्ठतर विधियां, उर्वरक-प्रयोग के नये ढंग तथा मशीनीकरण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

जार्ज वाशिंगटन के समय में, जब हमारा देश विश्व में अपना स्थान प्राप्त करने के लिए संघर्षरत था, हमारी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ९० प्रतिशत जन-संख्या को खेती करनी पड़ती थी। अब केवल ८ प्रतिशत जन-संख्या हमारी आवश्यकता के लिए पर्याप्त कृषि-पदार्थ उत्पन्न कर लेती है। इस प्रकार, उन्मुक्त श्रम शक्ति सड़कों पुलों, कारखानों और घरों के निर्माण में, कोयले और लोहे की खानें चलाने में, रेल, विमान और मोटर सेवाएं चालू रखने में, स्कूलों और कालिजों में शिक्षा का विकास करने में तथा नगर, राज्य और संघ की सरकारों को चलाने में संलग्न है।

केवल पिछले ५० वर्षों में, हमारी जन-संख्या लगभग दूनी हो गई है, किन्तु इस अवधि में हमारे कृषि-श्रमिकों की संख्या आधी घट गई है। इसका कारण यह है कि अनुसन्धान के फलस्वरूप हमें ऐसी विधियां मालूम हो गयी हैं, जिनके द्वारा हम एक घण्टे में इतना अधिक उत्पादन कर लेते हैं जो ५० वर्ष के उतने समय के उत्पादन के चार गुने से अधिक होता है।

१९१० में एक बुशल अनाज पैदा करने और काटने के लिए फार्म पर १$\frac{१}{३}$ घण्टे श्रम करना पड़ता था, आज एक बुशल अनाज की लागत १२ मिनट के श्रम के बराबर है। गेहूँ तो ११ मिनट से भी कम श्रम द्वारा उत्पन्न हो सकता है। अब एक गैलन दूध उत्पन्न करने में पहले से आधा श्रम लगता है, जब कि एक गांठ कपास पहले से ३।४ श्रम द्वारा उत्पन्न हो सकती है।

इस अवधि में फसलों के उत्पादन में प्रति एकड़ ६० प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जब कि पशुओं के उत्पादन में ८५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। • •

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सबसे सस्ता सचित्र हिन्दी मासिक

जागृति

जिसे भारत के सभी प्रमुख कवियों,
और कहानीकारों का सहयोग प्राप्त है।
उत्प्रेरक कविताएं, ज्ञानवर्धक लेख, सांस्कृतिक निबंध,
रोचक कहानियां, बाल संसार, साहित्य आगे
बढ़ता है, आदि स्तम्भ
तिरंगा आवरण, अनेकों इकरंगे चित्र
सम्पूर्ण छपाई आर्ट पेपर पर
इस पर भी मूल्य केवल २५ नये पैसे

एजेंटों को ५ से १० प्रतियों पर २५ प्रतिशत और इससे ज्यादा पर ३३⅓ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। डाक का खर्च प्रकाशकों के जिम्मे। एजेन्ट नमूने की प्रति के लिए आज ही लिखें।

—सूचना व प्रकाशन विभाग चण्डीगढ़ (पंजाब)

आरसी

(सचित्र पारिवारिक मासिक)

कहानी * कविता * लेख * कढ़ाई * बुनाई * पाठशाला * माँ और शिशु * ढोलक के गीत * बाल-मन्दिर * चलचित्र-जगत् * पुस्तक परिचय * इसके साथ ही प्रति माह एक कढ़ाई का नमूना उपहार में।

१ प्रति, ५० न० पै० वार्षिक मूल्य ६.०० रु०

आज ही ग्राहक बनिये।

विशेष सूचना—आरसी का अगस्त अंक "राजेन्द्र-स्मृति-अंक" था। एजेन्ट अपनी प्रतियां मंगवा लें।

व्यवस्थापिका, आरसी, श्वाकर टाउन
सिकन्द्राबाद (आ० प्र०)

हिन्दी का एकमात्र
विशिष्ट महिलोपयोगी मासिक

शृङ्गार

- जो सुखी पारिवारिक जीवन का आदर्श पथ-प्रदर्शक है
- जिसे सुप्रसिद्ध लेखिकाओं, लेखकों, पत्रकारों, चित्रकारों कवयित्रियों तथा कवियों का सहयोग प्राप्त है।
- जिसे ५०००० से ऊपर की संख्या में पाठक प्रतिमास पढ़ते हैं।
- जिसकी प्रतियां न्यूज़ एजेन्टों के पास पहुँचते ही समाप्त हो जाती हैं।
- जो महिला जागृति का प्रतीक है।
  जो सबकी प्रिय पत्रिका है।

वार्षिक सात रुपये
एक प्रति : ६० नये पैसे

सम्पादिका : लावण्य प्रभा

कार्यालय . . १३।३७, शक्तिनगर, दिल्ली-६।

खादी पत्रिका

* खादी ग्रामोद्योग तथा सर्वोदय विचार पर विद्वत्तापूर्ण रचनाएँ।
* खादी ग्रामोद्योग आन्दोलन की देशव्यापी जानकारी।
* कविता, लघुकथा, मील के पत्थर, साहित्य समीक्षा, संस्था परिचय।
* साँख्यिकी पृष्ठ आदि स्थायी स्तम्भ।
* आकर्षक मुख पृष्ठ, हाथ कागज पर छपाई।

वार्षिक मूल्य ३) रु., एक प्रति पच्चीस नये पैसे

संपादक—ध्वजाप्रसाद साहू, जवाहिरलाल जैन
राजस्थान खादी संघ, पो. खादीबाग, (जयपुर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विदेशी यात्रियों का व्यवसाय

श्री राज बहादुर राज्य मंत्री परिवहन

• किसी भी देश में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति का एक बड़ा साधन विदेशी यात्री होते हैं । भारत में भी विदेशी यात्रियों द्वारा विदेशी मुद्रा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रही है। १९५७ से १९६२ तक विदेशी यात्रियों के आने में ७७.६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। १९५६ की अपेक्षा १९५७ में २२.२ प्रतिशत विदेशी यात्री अधिक आये। इसके बाद भी विदेशी यात्रियों की संख्या निरन्तर बढ़ती रही। १९५८ में १४.५ प्रतिशत, १९५९ में १८.७ प्रतिशत, १९६० में १२.५ और १९६१ में १३.६ प्रतिशत विदेशी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह ठीक है, कि यह वृद्धि निरन्तर एक क्रम से नहीं हुई, किन्तु समस्त विश्व में विदेशी यात्रियों की संख्या के अनुपात से भारत में आने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात अधिक ही रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या १०-११ प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी है, तो भारत में यह प्रतिशत १३ रहा है। १९५७ से लेकर ४ वर्षों में यदि अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा ४२ प्रतिशत बढ़ी है, तो भारत में ६७.९ प्रतिशत।

यात्रियों की संख्या बढ़ी

• रिजर्व बैंक ने १९५५ में यह अनुमान लगाया था, कि विदेशी यात्रियों से भारत को १० करोड़ ३० लाख रुपये की आय हुई है। ५ वर्ष बाद के अनुमान के अनुसार भारत को विदेशियों की यात्रा से २० करोड़ ५० लाख रुपये की आय हुई। इसके बाद विदेशी यात्रियों से आय में थोड़ी बहुत कमी अवश्य हुई है, किन्तु विदेशी यात्रियों की संख्या अवश्य बढ़ती रही है। १९६१ में १,३९,८०४ विदेशी यात्री आये थे। १९६२ में यह संख्या करीब ८॥ हजार कम रही। बहुत सम्भवतः इसका कारण भारत पर चीन के आक्रमण से उत्पन्न अशान्त परिस्थिति रही है, जब कि वायु सेवाएं भी कुछ अनिश्चित हो गईं। भारत का वातावरण भी कुछ क्षुब्ध व अशान्त रहा। पूर्वी एशिया और पूर्वी अफ्रीका से भी अपेक्षाकृत कम यात्री आये। जैसे भारत के सामने विदेशी मुद्रा की कठिन समस्या है, उसी तरह

लेखक

अफ्रीका और एशिया के विकासशील देशों के सामने भी यह समस्या कम विकट नहीं है। इसलिए वे भी विदेशों में जाने की अनुमति संकोच के साथ देते हैं।

जिन विदेशी यात्रियों से देश को आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभ होता है, वे प्रायः ऐसे यात्री होते हैं, जो अपनी छुट्टियां मनाने या सैर सपाटे के लिए भारत में आते हैं। ऐसे यात्रियों की संख्या में २ या २॥ प्रतिशत वृद्धि हो रही है। १९६२ में ही विदेशी यात्रियों में ४८ प्रतिशत संख्या उन लोगों की थी, जो केवल सैर सपाटे के लिए भारत में आये थे। इसलिए भारत सरकार ऐसे लोगों के लिए स्थान-स्थान पर अच्छे होटलों व सैरगाहों के विकास पर अधिक ध्यान दे रही है। ऐसे यात्रियों की सुविधा के लिए वायुयानों की सेवा को भी उन्नत और आरामदेह करने की दृष्टि से भी सरकार प्रयत्न कर रही है। दर्शनीय स्थानों पर अच्छी दुकानें, होटल, और सायंकालीन विनोद की सुविधाएं भी सुलभ हों, यह आवश्यक है। इन सब कामों में काफी रुपया चाहिए। इसलिए शनैः शनैः सरकार आवश्यक स्थानों पर व्यवस्था कर रही है। आर्थिक मामलों के सचिव श्री एल० के० झा के नेतृत्व में नियुक्त एक समिति ने विदेशी यात्रियों को अधिक आकृष्ट और प्रोत्साहित करने के लिए कुछ आवश्यक सुझाव दिये

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हैं, जिनसे विदेशी यात्रा का यह व्यवसाय भारत में विकसित हो सके। *

विशाल देश और अनन्त दर्शनीय दृश्य

हमारा भारत एक विशाल देश है और उसमें यात्रियों के लिए आकर्षक रमणीय दृश्यों व नये या पुराने भव्य ऐतिहासिक स्थानों आदि की कमी नहीं है। हमें इन सब स्थानों पर विदेशी यात्रियों के निवास, भोजन, और आनन्द प्राप्ति की व्यवस्था करनी चाहिए। स्थान-स्थान पर ऐसी दुकानें भी खोलनी होंगी, जिससे यात्रियों की आवश्यकताएं पूर्ण हों। अजोरा और खजूराहो आदि कुछ स्थान मुख्य यात्रा-मार्ग से दूर पड़ते हैं। ऐसे स्थानों पर यातायात के सरल साधन जुटाने पड़ेंगे। अनेक समुद्र तटवर्ती स्वास्थ्यप्रद स्थान हैं, जहां विदेशी यात्री कुछ दिन तक ठहरना पसन्द करेंगे। इसी तरह अनेक पर्वतीय दृश्य भी लोगों को आकृष्ट करेंगे। इन सब स्थानों पर न केवल हमें होटल खोलने हैं, किन्तु सड़कों, पार्कों, बिजली, पानी और पानी के निकास आदि की व्यवस्था भी करनी है।

बहुत कुछ हो रहा है

इस दिशा में काम भी हो रहा है, १९६२ में ही बम्बई, आगरा, फरीदाबाद और उदयपुर आदि में होटल बनाये गए हैं। इनमें कुल ३९१ कमरे हैं। दिल्ली, कलकत्ता, पटना, अर्नाकुलम और श्रीनगर में नये होटल बन रहे हैं। इन सब में ११०० बिस्तरों की व्यवस्था होगी। सरकारी और गैर सरकारी तौर पर नये अतिथि गृह बन रहे हैं। इण्डियन एयर लाइन्ज़ ने विदेशी यात्रियों के लिए कई वायुयान ज्यादा खरीदे हैं। रेलवे ने 'जहां चाहो यात्रा करो' के नाम से रियायती टिकटों की व्यवस्था की है, जिससे कि विदेशी यात्री बहुत लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अनुसार ५६० रुपये में एक टिकट मिलती है, जिससे देश भर में वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा की जा सकती। अनेक स्थानों पर डीलक्स बसों का प्रबन्ध किया गया है। कुछ राजधानियों में नगर के दर्शनीय स्थान दिखाने के लिए आरामदेह बसों की व्यवस्था की गई है। हमें आशा करनी चाहिए कि निकट भविष्य में विदेशी यात्रियों का व्यवसाय भारत के लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने में सहायक होगा।

---

* इस कमेटी ने जो सुझाव दिए हैं, उनमें एक सुझाव यह है, कि देश में ऐसी कम्पनियां बननी चाहिएं, जो विदेशी यात्रियों के आने जाने, ठहरने, उनके लिए टिकट खरीदने, उन्हें परामर्श देने तथा सब सुविधाएं देने की व्यवस्था करें। इस कमेटी ने ऐसे होटल बनाने की भी सलाह दी है, जिनमें ९००० बिस्तरों की व्यवस्था हो सके और जो यात्रियों के लिए बहुत महँगे न हों। अभी तक निजी उद्योग होटलों की स्थापना में बहुत रुचि नहीं ले रहा। इसलिए कमेटी ने यह भी राय दी है कि सरकार स्वयं होटलों का निर्माण करे परन्तु प्रबन्ध के लिए निजी संस्थाओं या व्यक्तियों को सौंप दे। —सं०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिल्ली में चिट फंड और वित्त कम्पनियां

श्री आर० चड्ढा एम० ए०

आज कल दिल्ली में चिटफंड एक लोक प्रिय व्यवसाय बन गया है। इस समय एक सौ से अधिक चिटफंड कम्पनियां हैं, जिनके सदस्य ५० हजार से ऊपर हैं। इनमें से कई कम्पनियां अच्छा कारोबार कर रही हैं।

यह कहना भूल होगा कि यह योजना नयी है। वस्तुतः इसका मूल तो भारत के नगरों के मुहल्लों में चिर काल से काम कर रही "कमेटियों" में पाया जाता है। यह "कमेटी पद्धति" बहुत छोटे पैमाने पर होती थी और बहुत थोड़ा कारोबार कर सकती थी।

चिट फंड क्यों ?

आज की वित्तीय व्यवस्था में मनुष्य को किसी समय बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़ जाती है, जैसे विवाह, शिक्षा, मकान बनाना, व्यापार बढ़ाना इत्यादि। पुश्तैनी साहूकारों और महाजनों से ऋण लेना हमारे लिए सम्भव नहीं होता है, क्योंकि वे इतना सूद मांगते हैं जो हमारे लिए देना मुश्किल होता है। फिर ये साहूकार किश्तों द्वारा रकम की वापसी पसन्द नहीं करते। कुछ लोग चिट-फंड में इसलिए शामिल होते हैं कि वे ऋण को किश्तों में वापस कर सकें चाहे सूद की दर कुछ ज्यादा भी क्यों न हो ?

ऋण लेने का तरीका

चिट-फंड का मेम्बर बन जानेसे एक साथ बड़ी राशि में रकम मिल सकती है और उसे सुगम किश्तों में वापस किया जा सकता है। कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जिनमें ऋण लेने वाला सदस्य उन सदस्यों के साथ, जिन्होंने ऋण नहीं लिया है, डिविडेंड लेने में हिस्सेदार बना रहता है।

दो जिम्मेदार व्यक्तियों की जमानत पर ऋण दिया जाता है। ये जामिन व्यक्ति ऋण लेने वाले व्यक्ति के साथ रकम की वापसी के जिम्मेदार होते हैं। गिरवी रखना भी चल सकता है, पर इसका प्रयोग १ प्रतिशत से अधिक नहीं होता है।

बचत के लिए चिट-फंड

चिटफंड की योजना का एक और पहलू है। एक आदमी ऋण नहीं लेना चाहता है। वह केवल बचत में दिलचस्पी रखता है। एक बैंक के सम्मान चिट-फंड कम्पनी उसे बचत की सुविधाएं प्रदान करती हैं। इन दोनों संस्थाओं में डिपाजिट पर जो वापसी मिलती है, उसमें बड़ा भेद है। चिटफंड द्वारा बचत पर जो मुनाफा दिया जाता है, वह निश्चय ही, बैंक की तुलना में अधिक और लाभकारी होता है। इसलिए चिटफंड की ओर लोग अधिक आकृष्ट होते हैं।

इसमें खतरा भी हो सकता है, पर अगर चिट फण्ड के मेम्बर ईमानदार हों तो कोई खतरा नहीं रहता है। यह ठीक है कि चिट फण्ड कम्पनी को अच्छी तरह चलाने के लिए जहां इसके डाइरेक्टर समर्थ और ईमानदार हों और अपने दैनिक कर्त्तव्यों का बिना पक्षपात के पालन करने वाले हों, वहां इसके सदस्य भी साधन सम्पन्न और शुद्ध व्यवहार होने चाहिए। दोनों ही एक दूसरे के लिए अत्यन्त विशिष्ट और समीपस्थ हैं। एक के बिना दूसरा काम नहीं कर सकता है। यह तो एक बड़े परिवार के समान है, जिसमें सब सदस्य मिलकर एक दूसरे की आर्थिक समस्याओं का हल करते हैं।

चिट-फंड और बीमा कम्पनी

इन दोनों संस्थाओं में तुलना की आवश्यकता है। दोनों ही नियमित रूप से बचत और उस बचत पर वापसी देने के लक्ष्य से काम करती हैं। पर, बीमा कम्पनी एक व्यक्ति के लम्बे समय के जीवन-संकट का इलाज करती है, वहां चिट फंड उस व्यक्ति की तात्कालिक आर्थिक कठिनाइयों को दूर करता है। बीमा कम्पनी जहां बीमा शुदा व्यक्ति के बच्चों की मुस्कराहट प्राप्त करती है, वहां चिटफंड सब मेम्बरों को मुस्कराहट प्रदान करता है।

कुछ चिट कम्पनियों के संचालक व कार्यकर्त्ता अवश्य ऐसे मिल जाते हैं, जो व्यापारिक ईमानदारी व कर्त्तव्य का पालन नहीं करते। ऐसी कम्पनियों के सदस्यों को हानि भी होती है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं चिट कम्पननियों का व्यवसाय ही विश्वासघात का इतिहास है। बेईमान लोग तो सभी व्यापारों में अपवाद रूप से मिल जाते हैं। ● ○

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

श्रमिक वर्ग प्रबन्ध में भागीदार हो

श्री खंडुभाई के० देसाई

राजनीतिक स्वतंत्रता अब प्रत्येक नर-नारी को प्राप्त हो गयी है। इसलिए मौलिक अधिकारों के बारे में किसी प्रकार का प्रश्न पैदा नहीं हो सकता। पर क्या करना चाहिए, यही प्रश्न महत्वपूर्ण है। ट्रेड यूनियनवादी की दृष्टि से इस पर विचार करते हुए हमें सर्वप्रथम जो कार्य करना चाहिए, वह है श्रमिकों का दृढ़ यूनियनों में संगठन। इस काम से हमें कोई रोक नहीं सकता, चाहे मालिक कितनी ही रुकावटें इसमें डालें, विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक एक भाषा में बोलें। ट्रेडयूनियन के अपने ४५ वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सामूहिक नारों, सामूहिक आंदोलनों और क्रांति की घोषणा इत्यादि से मैं सुपरिचित हूँ, पर हमें पश्चिमी नारों को भुलाकर विभिन्न स्तरों पर—कारखाना, प्रदेश, उद्योग और राष्ट्र में शांति और मिल जुलकर काम करना सीखना होगा। आई० सी० एफ० टी० यू० भी यही कोशिश कर रही है कि इसी ढंग पर यूनियन का संगठन किया जाए, अर्थात् ये यूनियनें श्रमिकों की सेवा के लिए संगठित हों, जिससे उद्योग और राष्ट्र की सेवा भी हो सके।

गांधीजी का नुस्खा

मालिकों के साथ व्यवहार करते हुए हमारे दिल में किसी प्रकार का रोष व दुर्भावना नहीं होनी चाहिए और हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उद्योग व व्यापार को—जिसमें हम काम करते हैं—धक्का लगे। पूंजीपति और कम्युनिस्ट—दोनों प्रकार के समाज भी इसी परिणाम पर पहुँचे हैं। हमें पिछले अनुभव से लाभ उठाना चाहिए। गांधी जी ने अनोखे ढंग से कहा है कि कोई मालिक व मजदूर नहीं है, किन्तु जिस उद्योग की वे सेवा करते हैं, उसमें दोनों सहकर्मी और सह-ट्रस्टी हैं। आज के पेचीदे औद्योगिक संगठन में, मालिक और मजदूर दोनों अपने अपने संकुचित स्वार्थों के दायरे में सोचकर उत्पादन

लेखक

के हित में सह-स्वामी और सह-कर्मी बन जाते हैं। उत्पादन ही लक्ष्य नहीं है, पर वह एक कार्यपद्धति का परिणाम है। वस्तुतः उद्योग के मालिक तो उपभोक्ता हैं, अर्थात राष्ट्र है। अन्ततोगत्वा, श्रमिक और मालिक—जिन्होंने क्रमशः अपने श्रम और धन की पूंजी लगायी है—दोनों ही उत्पादन में बराबर के भागीदार हैं। पर गांधीजी ने इस विचार को विभिन्न रूप में रखा है और उन्होंने दोनों को "सह-स्वामी और सहकर्मी" कहा है। मालिकों में यह भावना पैदा की जानी चाहिये कि वे अकेले ही उद्योग के मालिक नहीं हैं, किन्तु वे हजारों अन्य श्रमिकों के साथ सहयोगी व सहकर्मी हैं। इसके साथ ही श्रमिकों में उद्योग के प्रति स्वामित्व की वृद्धि पैदा करनी चाहिए। इसके बाद ट्रस्टी बनने और सह-ट्रस्टी बनने का प्रश्न सामने आता है। क्या यह सम्भव है? मेरा उत्तर है कि यह न केवल सम्भव है, किन्तु अनिवार्य भी है और लोकतंत्री समाज में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जितना शीघ्र इसका प्रसार होगा, उतना ही शीघ्र समाज का, उत्पादन का और सबका भला होगा।

प्रबन्ध में भाग लेने की श्रमिकों की योजना

अब प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या श्रमिक व उनके यूनियन उद्योग के प्रबन्ध में भाग लेने की योग्यता रखते हैं? क्या मैं किसी हिसाब रखने वाले व अन्य व्यक्ति को अपने घर की व्यवस्था करने के लिए बुला सकता हूँ? मैं स्वयं ही प्रबन्ध करता हूँ। मैं प्रतिवर्ष, प्रतिमास, प्रतिदिन बजट बनाता हूँ। इसके लिए अधिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए तो सामान्य व्यवहार बुद्धि ही चाहिए, जो मैं समझता हूँ श्रमिकों में है। अगर श्रमिक अपनी यूनियन का प्रबन्ध कर सकते हैं, तब वे अपने मालिकों के साथ उद्योग में उत्पादन क्यों नहीं कर सकते हैं? काम की शर्तें तो अब बहुत कुछ देश के कानूनों द्वारा निर्धारित होती है, जैसे कारखाना कानून, खान कानून मोटर यातायात कानून, बागान कानून इत्यादि। इन चीजों के लिये अब श्रमिक को लड़ने की आवश्यकता नहीं है। १९वीं सदी में ब्रिटेन और अमेरिका में उनके पूर्ववर्तियों को इन अधिकारियों को लड़ना पड़ा था, पर आज यह सब सुविधाएं हमें कानून से प्राप्त हैं। आज आई० सी० एफ० टी० यू० और आई० एल० ओ० जैसी संस्थाएं श्रमिकों के अधिकारों की प्रहरी हैं।

वितरण की समस्या

आज जिस बात की कमी है, वह है उत्पादन और उसका न्यायसंगत वितरण। फिर, उपनिवेशवाद के दिन लद गये और आज के नूतन विकासोन्मुख देश औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों के अनुभवों से लाभ उठा सकते हैं। सारी समस्या की जड़ तो वितरण है। आधुनिक वितरण शांतिपूर्ण उपायों से हो और संघर्ष, हड़ताल, तालाबन्दी का अन्त हो जायगा तो यह संसार बेहतर बन जाएगा। शान्तिपूर्ण उपायों से मेरा मतलब है, पंचनामा, कानून बनाना, त्रिपक्षीय वेतन-बोर्ड इत्यादि। भारत में विभिन्न वेतन-बोर्डों ने पांच-छः वर्षों में सर्वसम्मति से निश्चय किये हैं और लगभग ३० लाख मजदूरों पर इसका प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार बड़े संगठित उद्योगों में जो स्थान निश्चित किये गये हैं, उनका प्रभाव अन्य छोटे उद्योगों पर अवश्य ही लाभकारी पड़ेगा। यह प्रक्रिया समझौता-मध्यस्थता अन्यथा ट्रिब्यूनल के द्वारा ही कारगर हो सकती है।

यहां मैं व्यक्तिगत रूपसे एक बात लिखना चाहता हूँ। १९५४ में केन्द्रीय श्रम मन्त्री के रूप में मैंने राष्ट्र के सामने रेडियो-भाषण द्वारा तीन मूलभूत विचार रखे थे—प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग लेना, वेतन बोर्ड और श्रमिकों की शिक्षा। ये तीनों बातें मैंने गांधीजी से सीखी थीं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में तीनों को सरकार, इंटक और मालिकों के संगठन को नीति के रूप में मान्यता दी गयी है। इसे कार्यान्वित किया जा रहा है और इससे बड़ा लाभ हो रहा है। पिछले दशक में, बिना हड़ताल, तालाबन्दी व कटुता के श्रमिकों की मजदूरी १५ से २० प्रतिशत बढ़ गयी है। मौलिक वेतन बढ़ गये हैं। दोनों योजनाओं की अवधि में राष्ट्र की बढ़ती हुई समृद्धि में श्रमिकों को भी भाग मिला है।

हड़ताल करने का अधिकार

हड़ताल की सम्भावना सर्वथा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता। अगर श्रमिकों व किसानों के साथ अन्याय किया गया है तो उन्हें हड़ताल करने का अधिकार है। पर विरोध विधेयात्मक होना चाहिए, निषेधात्मक नहीं। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध युग की यही पुकार है। हम सब विश्व की घटनाओं से लाभ उठा रहे हैं, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि श्रमिक दल को स्वामित्व और प्रबन्ध में हिस्सेदारी की चेतना का अनुभव होना चाहिए। केवल पैसे का ही महत्व नहीं है पर हृदय में स्वामी होने की हरकत हो, मिलकर दृढ़ संकल्प की चेतना हो और प्रबन्ध में हिस्सेदार बनने की उत्कंठा हो—किसी भी नाम से कहें—पर इनका होना सर्वाधिक आवश्यक है। मेरे श्रम मंत्री काल में एक अध्ययन मण्डल यूरोप के विभिन्न देशों में श्रमिकों के प्रबन्ध में भागीदार होने के बारे में अध्ययन करने गया था। इसकी बड़ी अच्छी रिपोर्ट मिली, इस में मेरे उन दिनों के विचारों की झलक है। समय-समय पर जो क्रियात्मक प्रश्न उठते हैं, उनकी दृष्टि से इस रिपोर्ट पर विचार करना होगा। मैं यह कहना चाहूँगा कि इस युगकी मांग, चाहे पूंजीवादी, समाजवादी अथवा मिश्रित

(शेष पृष्ठ ४२२ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थ वृत्त चयन

राष्ट्रीय आय के प्रवाह

प्रारंभिक अनुमान के अनुसार हमारी राष्ट्रीय आय, या १९४८-४९ की कीमतों के हिसाब से हमारा '६१-६२ का राष्ट्रीय उत्पादन १३,०२० करोड़ रु० है, जो १९६०-६१ से केवल २.१ प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि का दर पहली तथा दूसरी योजना-काल से स्पष्टतया कम है, जब कि वार्षिक आय की वृद्धि क्रमशः ३.४ प्रतिशत और ४.१ प्रतिशत थी। १९६१-६२ में राष्ट्रीय आय की वृद्धि मुख्यतः कृषि छोड़ कर अन्य खण्डों से हुई। यह १९६०-६१ के विपरीत था, जबकि कृषि व अन्य खण्डों में सर्वत्र सुधार था और राष्ट्रीय आय में ७.५ प्रतिशत की प्रभावी वृद्धि हुई। राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय, जो १९६०-६१ में ५.२ प्रतिशत बढ़कर २९३.७ रु० हुई थी, १९६१-६२ में भी उतनी ही रही। '६१-६२ में २७० करोड़ रु० की वृद्धि इस प्रकार हुई—

खनिज व छोटे उद्योग—९० करोड़,

व्यापार, यातायात और संचार—७० करोड़, और

अन्य सेवाएं—धन्धे, सरकारी नौकरी, घरेलू काम और भवन-सम्पत्ति—१७० करोड़।

खेती, मवेशी-पालन और तत्सम्बन्धी धन्धों का योग ३० करोड़ रु० कम हुआ।

खेती खण्ड का हिस्सा जो ५८-५९ में ४७.७ प्रतिशत था, वह घट कर ६१-६२ में ४५ प्रतिशत हुआ।

[रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की 'मुद्रा और वित्त' विषयक ६२-६३ की रिपोर्ट से]

यूनिट ट्रस्ट

भारत में इन दिनों पूंजी निर्माण के प्रश्न पर विचार हो रहा है, क्योंकि यह अनुभव किया जा रहा है कि रुपये के बाजार में काफी मन्दी आ रही है। सरकार की करनीति तथा विभिन्न परिस्थितियों के कारण लोग कम्पनियों के शेयर खरीदने में संकोच करते हैं। पूंजी निर्माण में प्रोत्साहन देने के लिए जो उपाय सुझाए जा रहे हैं, उनमें से एक प्रस्ताव यूनिट ट्रस्ट की स्थापना का है। गत मास के प्रथम सप्ताह में नये वित्त मन्त्री श्री कृष्णमाचारी ने भी इस प्रस्ताव पर विचार करने की घोषणा की थी।

यूनिट ट्रस्ट का मूल सिद्धांत यह है कि एक आदमी को अपना सब रुपया अपने या किसी एक संस्था के पास नहीं रखना चाहिए। वह विभिन्न स्थानों में बिखेर देना चाहिए। किन्तु साधारण आय वाला व्यक्ति अपना रुपया अलग-अलग जगह बिखेर नहीं सकता। उसकी आय स्वयं अत्यन्त अल्प होती है। फिर उसे यह भी मालूम नहीं होता कि किस जगह रुपया लगाने से उसका रुपया खतरे में नहीं पड़ेगा। इसलिए उसे ऐसे विशेषज्ञों और परामर्श दाताओं की आवश्यकता होती है, जो उसका रुपया सुरक्षित स्थानों पर लगा सकें। यूनिट ट्रस्ट ऐसे ही स्वल्प आय वाले लोगों की संस्था होती है, जो अपनी छोटी बचत को किसी सुरक्षित स्थान में लगाना चाहते हैं, परन्तु स्वयं जानकारी न होने के कारण लगा नहीं सकते। वस्तुतः यूनिट ट्रस्ट ऐसे लोगों की एक सहकारी संस्था होती है। वे इस संस्था को अपना रुपया देते हैं और इसी संस्था के द्वारा यह रुपया औद्योगिक कम्पनियों तथा व्यापारिक संस्थाओं में लगाते हैं।

जब एक विनियोजक यूनिट ट्रस्ट के यूनिट खरीदता है, तब स्वभावतः वह उस प्रत्येक कम्पनी का छोटा शेयर होल्डर बन जाता है, जिस-जिस कम्पनी के शेयर उसके ट्रस्ट ने खरीदे हों। यूनिट ट्रस्ट को मिलने वाला डिविडेण्ड ट्रस्ट के सब सदस्यों में बांट दिया जाता है। एक कम्पनी शेयर १०० या ५०० रुपये का हो सकता है और एक व्यक्ति इतना रुपया नहीं लगा सकता। लेकिन यूनिट ट्रस्ट का मेम्बर होने के नाते वह भी उस कम्पनी के लाभ का अधिकारी हो सकता है।

१९२९ की व्यापक मन्दी में जब ब्रिटेन की बहुत-सी कम्पनियां फेल होने लगीं और लोग कम्पनियों में रुपया लगाने से झिझकने लगे, तब यूनिट ट्रस्ट बनाने का विचार लोगों के सामने आया था। १९३५ में वहां बहुत से यूनिट ट्रस्ट बने और इनकी अव्यवस्था को दूर करने के लिए सरकार ने १९३८ और १९५८ में कुछ कानून भी बनाये। आज अमेरिका में भी यूनिट ट्रस्टों की कमी नहीं है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अति उत्पादन भी समस्या

इस वर्ष दक्षिण फ्रांस के किसानों ने अन्न के अतिरिक्त दूसरी वस्तुएं इतनी पैदा की हैं कि उनके लिए ग्राहक नहीं मिलते। अंगूर की फसल इतनी अच्छी हुई कि उन्होंने कई लाख मन शराब बना डाली। केवल दक्षिण फ्रांस में इतनी शराब तैयार हो गई है कि सारे फ्रांस की जनता उसे एक वर्ष में भी नहीं पी सकती। इसी प्रकार उन्होंने आलू, मटर, अण्डे, मुर्गियां, फल इतने पैदा कर लिए कि उनकी समझ में नहीं आया कि उन चीजों का क्या किया जाय। उन्होंने सरकार से कहा कि इनकी निकासी का कुछ उपाय करे। किन्तु सरकारें, न कम पैदावार की समस्या हल कर सकती हैं और न अधिक पैदावार की। फ्रांसीसी सरकार समस्या पर विचार करने लगी और उधर आलू, टमाटर अण्डे फल आदि सड़ने लगे। शराब रखने के लिए पीपों की कमी हो गई, उसे रखने के लिए बहुतों के पास जगह न रही। मुर्गियों की संख्या इतनी बढ़ गई, कि किसानों के लिए उनका पालन पोषण करना सिर दर्द हो गया। जब सरकार केवल विचार ही करती रही और उसने कुछ न किया, तब जुलाई के महीने में किसानों ने परेशान होकर लाखों मन आलुओं और टमाटरों को सड़कों पर डालकर उन पर ट्रेक्टर चला दिये। मण्डी की सड़कों पर आलुओं और टमाटरों की बलि चढ़ाकर के वे अपने-अपने गांव लौट गये। किसानों का का धीरज छूट गया, वे सरकार से अपने-अपने घाटे की पूर्ति के लिए अनुदान की मांग करने लगे। कुछ होता हुआ न देखकर उन्होंने अपनी मांग के समर्थन में जगह-जगह उपद्रव आरम्भ कर दिये।

जब दंगों का भी कोई फल न हुआ, तो किसानों ने एक नये ढंग का अहिंसक प्रतीकात्मक मोर्चा खोला। उन्होंने सड़कों पर जाती हुई मोटरों को रोकना प्रारम्भ किया। मोटर रोक कर वे सवारियों को एक विज्ञापन देते, जिसमें उनकी दुर्दशा का वर्णन और उनकी मांगों का विवरण छपा था। उसके साथ ही वे मोटर की बैठकियों पर बहुत से फल, चीज (पनीर) अण्डे, मुर्गियों, और शराब की बोतलें डाल देते। केवल एक सप्ताह में ही इन किसानों ने इस प्रकार मोटर वाले यात्रियों को प्रायः २७,००० शराब की बोतलें भेंट कर दी। कितनी मुर्गियां अण्डे और फल आदि भेंट कर दिये, उनकी गिनती नहीं है। किन्तु प्रचार के अतिरिक्त इस मोर्चे से भी कोई ठोस परिणाम नहीं निकला।

—सरस्वती

भारत की चीनी महंगी क्यों ?

अधिक उत्पादन के कारण देश में चीनी उत्पादन की अर्थ व्यवस्था गड़बड़ा गयी है। यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने उत्पादन में १० प्रतिशत कटौती करके इस स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया, पर १९६०-६१ में अति-उत्पादन के कारण जो हानि हुई, उसका इलाज नहीं हो सका। गुड़ के भावों के कारण स्थिति और भी बिगड़ गयी है। कम उत्पादन के कारण जब चीनी में न्यूनता आती है, तब गुड़ के भाव स्वभावतः चढ़ जाते हैं और गन्ने का पर्याप्त भाग गुड़ के उत्पादन में चला जाता है। पर जब चीनी का उत्पादन बढ़ जाता है, तब गुड़ के दाम गिर जाते हैं और गुड़ का उत्पादन लाभदायक नहीं रहता है। ऐसे हालात में जो गन्ना किसी कारखाने के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, उसे भी गन्ना-उत्पादक चीनी के कारखानों में तस्करी द्वारा पहुँचा देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि थोड़ी प्राप्ति पर भी गन्ने का मौसम लम्बा हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि उत्पादन-व्यय बढ़ जाता है। गन्ना उद्योग में वर्ष-वर्ष के बाद न्यूनता और अति-उत्पादन का चक्कर चलता रहता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थिति को सुधारने के लिए पूर्ण प्रयत्न करने के बावजूद, अभी तक दोनों स्थितियों में सन्तुलन नहीं आ सका है। इसका विशेष कारण यह है कि राज्य सरकारें और गन्ना उत्पादक, दोनों चीनी उद्योग के साथ पूर्ण सहयोग नहीं करते हैं।

चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। इसमें दो लाख से अधिक मजदूर काम करते हैं और गन्ने के न्यूनतम मूल्य द्वारा २० लाख से अधिक किसानों का पालन-पोषण होता है। यह कहा जाता है कि भारतीय चीनी का मूल्य विश्व में सर्वाधिक है। पर यह करों के कारण है। अगर लागत खर्च में से करों को निकाल दिया जाए, तब भारतीय चीनी भी विश्व बाजार में प्रतियोगिता में खड़ी हो सकती है। अगर गन्ने की खेती मिलों

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उसके मूल्य को रेशनलाइज्ड कर दिया जाए और मिलों को उसी मूल्य पर दिया जाए जिस पर विश्व के अन्य कारखानों के लिए सुलभ है, तब, निश्चय ही भारत सबसे सस्ती चीनी के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता कर सकता है। अगर अन्ने की खेती के लिए आधुनिक वैज्ञानिक ढंग अपनाये जाएं तो किसान के हितों को बिना किसी प्रकार की क्षति पहुँचाये, प्रति एकड़ अधिक उपज होगी और अधिक रस निकलेगा।

लगभग २०-३० वर्ष पहले गन्ना—विकास-विभाग खोला गया था, ताकि अधिक-अच्छा और रसदार गन्ना पैदा किया जा सके। इस विभाग ने अच्छा काम किया और उससे लाभ हुआ। अनुसंधान और विकास का व्यय पूरा करने के लिए गन्ना-शुल्क लगाया गया। यह गन्ना-शुल्क लगातार बढ़ रहा है। पर यह खेद की बात है कि यह विभाग अपनी प्रशंसनीय परम्पराओं को कायम नहीं रख सका है। अनुसंधान और विकास—दोनों काम ढीले पड़ गये हैं और राज्य सरकारों की यह प्रवृत्ति बढ़ रही है कि वे गन्ना-शुल्क को सामान्य राजस्व का हिस्सा समझने लगे हैं, यद्यपि प्रारम्भ में, इसका एकमात्र उद्देश्य भारत में गन्ने की उपज में खोज करना और उसमें विकास करना था।

(इंडिया शूगर एंड रिफाइनरीज लि० के चेयरमैन श्री राजेश्वर पटेल के कम्पनी की वार्षिक सभा में दिये गये भाषण का एक अंश) ● ●

श्रमिक वर्ग प्रबन्ध में भागीदार हों

(पृष्ठ ४१९ का शेष)

अर्थ व्यवस्था हो, श्रमिकों द्वारा सामूहिक रूप में मालिकों के साथ प्रबन्ध में भाग लेने की चेतना है। अर्थात् बराबर के रूप में उनके साथ बैठकर उत्पादन मूल्यों का वितरण, लागत इत्यादि का निर्धारण करना। यह स्थिति देरी की अपेक्षा जल्दी आनी चाहिए।

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र

एक ट्रेड यूनियन का कार्यकर्ता होने के कारण मैं सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के रूप में जो कृत्रिम भेद रेखा खींची जा रही है, उसको अस्वीकार करता हूँ। मैं दोनों क्षेत्रों को एक समान समझता हूँ। प्रबन्ध प्रबन्ध ही है, चाहे वह राज्य का हो और चाहे निजी हो। सार्वजनिक क्षेत्र श्रमिकों के साथ उसी ढंग से व्यवहार करता है, जैसे निजी क्षेत्र। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग लेना निजी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जरूरी है। यह विचार नया नहीं है, पर उतना ही पुराना है, जितना विश्व। जब एक छोटे समाज, परिवार व गांव के सामने कोई प्रश्न आता है, उस समय कोई एक आदेश नहीं देता है, पर सब मिलकर बैठते हैं और जो न्यायसंगत व ठीक है, वही निर्णय करते हैं। उद्योगों का प्रबन्ध भी मिलजुलकर होना चाहिए और आज समय की यही मांग है। जितना शीघ्र इस विचार को कार्यान्वित किया जाय, उतना उद्योग जनता के लिए हितकर होगा। हम भूलें कर सकते हैं, पर धीमे-धीमे वे ठीक हो जाएंगी। मेरा विश्वास है, शीघ्र ही इसे "निश्चित तथ्य" के रूप में मान लिया जायगा। इससे समाज में पैदा होने वाले सब झगड़ों का अन्त हो जाएगा।

कोई उद्योग केवल मालिक का नहीं

आज कोई उद्योग किसी मालिक का नहीं है। एक उद्योग का देश में कैसे विकास हो सकता है? यह समाज की सहायता से होता है। सरकार विभिन्न प्रकार से उद्योग की सहायता करती है, आयात-निर्यात नीति व सहायता द्वारा। उद्योग से प्राप्त होने वाले राजस्व में राज्य भी हिस्सा लेता है। लाभ पर कर लगाया जाता है, और यह सरकार के पास जाता है। १९वीं सदी में निजी उद्योग का जो स्वरूप था, वह आज इतना बदल गया है कि पहचाना भी नहीं जा सकता।

आज का श्रमिक वर्ग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि ट्रेड-यूनियन संगठन श्रमिक वर्ग का शिक्षण और निर्देशन करता रहेगा, ताकि वे समाज के प्रति अपने अधिकार और कर्त्तव्य दोनों का एक साथ पालन कर सकें।*

* श्री देसाई के एक भाषण से ● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कुछ सम्मतियां पढ़िये—

सम्पदा का दिल्ली विकास-अंक

सफल सराहनीय प्रयास : ज्ञातव्य सामग्री से परिपूर्ण

इस अंक के लेखों के द्वारा पाठकों को दिल्ली की सार्वजनिक समस्याओं तथा उनके समाधान के लिए किये जा रहे प्रयत्नों की झांकी मिलेगी। आपका यह प्रयत्न सराहनीय है।

—धर्मवीर, चीफ़ कमिश्नर दिल्ली

●

सम्पदा का "दिल्ली विकास अंक" अनुभवी सम्पादक श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ने बहुत परिश्रम से तैयार किया है। इसमें दिल्ली की बहुत-सी समस्याएं आ गई हैं। मैं समझता हूँ कि दिल्ली के विकास से सम्बन्ध या दिलचस्पी रखने वाले सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं और अफसरों को इसका अध्ययन करना चाहिये।

—गोपीनाथ अमन, अध्यक्ष जनसम्पर्क समिति

●

यह अंक देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आपने बड़े परिश्रम से दिल्ली के सम्बन्ध में तथ्यों का संग्रह किया है। मैं आपको इस सुन्दर अंक के प्रकाशन पर बधाई देता हूँ। आपने अपने इस अंक द्वारा सभी तथ्यों और समस्याओं को सामने रख दिया है। अब उन समस्याओं का हल क्या हो सकता है, यह अभी देखना है।

—डा० युद्धवीर सिंह, अध्यक्ष उद्योग परामर्श समिति

●

सम्पदा का दिल्ली विकास अंक बहुत सफल रहा। इसमें दिल्ली के बहुमुखी विकास की पूरी झलक मिलती है। विभिन्न क्षेत्रों से अनुभवी व्यक्तियों ने अपने-अपने दृष्टिकोण दिल्ली की समस्याओं पर महत्वपूर्ण ढंग से व्यक्त किये हैं, तथा उनका समाधान भी प्रस्तुत किया है।

यह सफल प्रयास सचमुच बड़ा सराहनीय है। ऐसे प्रकाशनों से दिल्ली के नागरिकों में अपने प्रदेश के बहुमुखी विकास के प्रति रुचि व उत्साह उत्पन्न होंगे और सरकार व जनता में परस्पर सहयोग बढ़ेगा।

—कृष्णकिशोर, मुख्य सचिव दिल्ली राज्य

सम्पदा के इस "दिल्ली विकास अंक" में राजधानी के आर्थिक, औद्योगिक, व्यापार-वाणिज्य, शिक्षा इत्यादि क्षेत्रों में हुए विस्तार का आंकड़ों सहित दिग्दर्शन कराते हुए उसकी वर्तमान और भविष्य की समस्याओं पर भी अच्छे ढंग से प्रकाश डाला गया है। दिल्ली राज्य के भूतपूर्व चीफ कमिश्नर श्री भगवानसहाय, राज्य के मुख्यसचिव श्री कृष्णकिशोर आदि ने अपने लेखों में जहां सरकारी दृष्टिकोण पेश करते हुए 'मास्टर प्लान' आदि का विवरण दिया है, वहां संसद सदस्य श्री ब्रह्मप्रकाश चौधरी, श्री शिवचरण गुप्त और जनसंघ के नेता श्री बलराज मधोक ने अपनी दृष्टि से विभिन्न समस्याएं प्रस्तुत करते हुए उनका समाधान भी प्रस्तुत किया है। "यह आपकी दिल्ली है।" "कपड़े की भारी मण्डी" (ब्रजभूषण सरन) दिल्ली का औद्योगिक विकास" (एन. एन. टण्डन), "चिरयौवना दिल्ली का नवनिर्माण" (लेखराम) तथा "दिल्ली एक सांस्कृतिक संगम" (गोपीनाथ 'अमन') इत्यादि लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। दिल्ली के मास्टर प्लान का नक्शा देने से अंक की उपयोगिता और बढ़ गई है।

—नवभारत टाइम्स

●

विगत ग्यारह वर्ष से 'सम्पदा' हिन्दी की आर्थिक पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रही है। दिल्ली भारत की गौरवमयी राजधानी रही है। प्रस्तुत अंक में इस ऐतिहासिक नगर और राज्य की आर्थिक प्रगति व विभिन्न आर्थिक समस्याओं पर विचार किया गया है। सर्वश्री श्रीमन्नारायण, भगवान सहाय (चीफ कमिश्नर), कृष्णकिशोर (मुख्य सचिव), चौ० ब्रह्मप्रकाश आदि अपने विषय और क्षेत्र के विशेषज्ञों के उपयोगी लेखों से इस अंक का महत्व बढ़ा है।

—विश्व ज्योति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राज्यों की आर्थिक गतिविधि

१. राज्यों में छोटे मंत्रिमंडल
२. राजस्थान में भूमि-सुधार विधेयक
३. राजस्थान में चीनी की कम खपत
४. उत्तरप्रदेश उद्योगों में पीछे

भूमि सुधार विधेयक

राजस्थान विधान सभा ने भूमि-सुधार विधेयक स्वीकार कर लिया। इस विधेयक का मूल आधार राजस्थान में विचौलियों की समाप्ति तथा भूतपूर्व राजाओं के पास जो भूमि है, उसका मूल्यांकन करके उन पर भी भूमि-सुधार कानून लागू करना है। जागीरदारों, जमींदारों आदि विचौलियों को विभिन्न भूमि सुधार कानूनों द्वारा पहले ही समाप्त करके किसानों का राज्य सरकार के साथ सीधा संबंध कायम करने का प्रयास किया गया है, परन्तु कुछ भूतपूर्व राज्य ऐसे रह गये हैं, जहां विचौलियों की संस्था अब भी मौजूद है। इस विधेयक के जरिये इन विचौलियों की प्रथा समाप्त करके वहां के किसानों को भूमि सुधारों से प्राप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

उत्तरप्रदेश उद्योग व शिक्षा में पीछे

जे. के. इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी के डायरेक्टर डा० राधाकमल मुकर्जी के कथनानुसार उत्तरप्रदेश न सिर्फ औद्योगिक-उत्पादन में, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ है। आर्थिक स्थिति यह है कि उत्तर-प्रदेश के ७३ प्रतिशत काम करने वाले खेती पर लगे हुये हैं, जबकि पश्चिमी बंगाल में ऐसे लोगों की संख्या ५३ प्रतिशत और बम्बई में ६० प्रतिशत है।

उत्तरप्रदेश में ६०० फैक्टरियां हैं, जबकि पश्चिमी बंगाल में १६०० और बम्बई में १७५० फैक्टरियां हैं। यहां भूमिहीन लोगों तथा निरक्षरों की संख्या सबसे अधिक है। तेजी के साथ राज्य का विकास करने के लिए राज्यों ने अधिक केन्द्रीय सहायता की मांग की है। राज्य के आगरा-मथुरा क्षेत्र पूर्वी-क्षेत्र, और हिमालय-क्षेत्र के विकास की विशेष आवश्यकता है।

राजस्थान में चीनी

आज सभी राज्य चीनी की दृष्टि से स्वावलम्बी बनने का प्रयत्न करना चाहते हैं। इसमें बड़ी बाधा केवल यही है कि गन्ने की कम खेती होती है। राजस्थान इसका अप-वाद हो रहा है। वहां गन्ने की खेती पर्याप्त मात्रा में होते हुये भी चीनी बन नहीं रही। इसी के परिणामस्वरूप वहां चीनी की खपत प्रति व्यक्ति बहुत कम है। यह इस तालिका से प्रकट होगा:

प्रति व्यक्ति चीनी की खपत

दिल्ली	२६.२ पौंड
पंजाब	१७.७ ,,
बम्बई	१७.२ ,,
उत्तर प्रदेश	१६.६ ,,
प० बंगाल	१२.८ ,,
मध्य प्रदेश	१०.८ ,,
राजस्थान	६.० ,,

यों जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में प्रति व्यक्ति २ औंस दैनिक के हिसाब से १६५०० टन चीनी दैनिक चाहिए। इसके विपरीत राजस्थान में १६५०० टन कुल चीनी पैदा हुई। १९५६-५७ में राजस्थान ने ६७७६२ टन सफेद चीनी बाहर से मंगाई। अब उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी आदि कुछ जिलों में गन्ना पैदा होने लगा है, पर चीनी की मिल न होने से चीनी बन नहीं पाती। विजय नगर की मिल ११ वर्ष पूर्व बनी थी, पर वह कई वर्षों से बन्द पड़ी है। अब चम्बल के पानी से गन्ने की खेती बहुत बढ़ सकती है और चीनी का उत्पादन भी। देखना है कि क्या खाण्डसारी गृह-उद्योग इस स्थिति का लाभ उठायगा अथवा बड़ी मिलें गृह-उद्योग को पनपने भी देंगी?

भूराजस्व में वैज्ञानिकन वापस

यदि केन्द्रीय सरकार ने स्वर्ण नियन्त्रण तथा अनि-वार्य बचत कानूनों में भारी संशोधन कर के करों में बहुत कुछ छूट दी है, तो मध्यप्रदेश सरकार ने भी पिछले मई में स्वीकृत मध्य प्रदेश भूराजस्व वैज्ञानिकन कानून को वापस लेने का निश्चय किया है। यह कानून इस लिए बनाया गया था कि राज्य के विविध भागों में एक सा

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भू-राजस्व लागू किया जाय । इसके कारण सरकार की आमदनी १ करोड़ ६० लाख रुपया बढ़ गई थी । कामराज योजना के आधीन मध्यप्रदेश में समस्त मंत्रिमण्डल के परिवर्तन और श्री द्वारिकाप्रसाद मिश्र के मुख्य मंत्री बनने का यह प्रथम परिणाम है ।

राज्यों में छोटे मंत्रिमण्डल

कामराज योजना का एक परिणाम यह हुआ है, कि प्रायः सभी राज्यों में मंत्री मण्डलों को छोटा करने की प्रवृत्ति काम करने लगी है । जहां जहां नये मंत्रिमण्डल बने हैं, वहां वहां यह प्रयत्न किया जा रहा है कि अपेक्षाकृत छोटे मंत्रिमंडलों से काम चलाया जाय । वस्तुतः ये बहुत शुभ लक्षण हैं । मंत्रिमण्डल की संख्या घटने के साथ-साथ विरोधियों का मंत्रिमण्डल पर होने वाले अनापशनाप खर्चों की ओर भी ध्यान गया है । एक-एक मंत्री हजारों रुपये यात्रा भत्ते के नाम पर खर्च करता है । उनके बिजली पानी के बिल भी प्रतिमास सैकड़ों रुपये के होते हैं । यदि कामराज योजना का यह परिणाम भी निकले और शासन में मितव्ययता आये तो वह भी कम लाभ नहीं होगा । • •

पोलैण्ड व भारत के आर्थिक सम्बंध

(पृष्ठ ४०४ का शेष)

नौ गहरी कोयला खानों का निर्माण शुरू कर दिया है या शीघ्र ही शुरू कर देंगे, जिनमें से प्रत्येक का नियोजित वार्षिक उत्पादन २०-३० लाख टन होगा । ये कोयला खानें भारत के कोयला उत्पादन में दो-ढाई लाख टन प्रतिशत की, अर्थात् मौजूदा कुल उत्पादन में लगभग ४० प्रतिशत की वृद्धि कर देंगी । कहने की जरूरत नहीं कि यह भारत की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, भारत के औद्योगीकरण की ऐतिहासिक प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा । ये कोयला खानें भारत के उत्तर-पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र के विशाल इस्पात संयंत्रों के लिए कोक सप्लाई करेंगी और हमारी यह आशा है कि ये भारतीय भारी उद्योग के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी ।

इन नौ खानों के अतिरिक्त हमने भारत के साथ कोयला धोने के कारखानों के निर्माण के लिए भी अनुबन्ध किये हैं । हमने खान मशीनरी तैयार करने का एक कारखाना तैयार करने का और पोलैण्ड द्वारा निर्मित कोयला-खानों से उत्पन्न कोयले से चलने वाले बिजलीघरों के निर्माण का जिम्मा लिया है । और जब तक भारत अपनी जरूरत भर के लिए खान-मशीनरी का निर्माण नहीं करने लगता, तब तक हम भारत को खान-उपकरण सप्लाई करना जारी रखेंगे । इस सहयोग में निपुण कर्मियों की ट्रेनिंग का काफी महत्व है । पोलैण्ड इस दिशा में भारत की सहायता को तत्पर है ।

पारस्परिक सम्बन्ध को और भी सुदृढ़ करने, समृद्ध बनाने और विस्तृत करने की सम्भावनाएं बहुत विपुल हैं । वस्तुतः अभी यह सहयोग केवल कोयला खान उद्योग के क्षेत्र में ही पूरे जोरों पर है । ऐसे अनेकों अन्य क्षेत्र हैं, जिनमें हमारे दोनों देशों के पास ऐसे सहयोग का विस्तार करने अथवा आरम्भ करने की विशद सम्भावनाएं हैं ।

विशिष्ट इस्पात-उत्पादन, मशीन निर्माण, तकनीकी स्टाफ और योजना स्टाफ की ट्रेनिंग के क्षेत्र हमारे दोनों देशों के बीच सम्भव सहयोग के अनेक क्षेत्र हो सकते हैं । भारत के कुछ अर्थशास्त्री वारसा में योजना के लिए उच्चतर पाठ्यक्रम में भाग ले रहे हैं । इसी किस्म के नये कोर्स शुरू भी होने वाले हैं । भविष्य में हम सम्भवतः कोयला खान, जहाज-निर्माण, इत्यादि विषयों में भी ऐसे ही पाठ्यक्रम संगठित करने का प्रयास करेंगे । • •

दिल्ली विकास अंक : एक सुन्दर संकलन

मैं दिल्ली विकास-अंक बहुत उत्सुकता से पढ़ा गया । आपने सचमुच दिल्ली की प्रायः सभी आर्थिक समस्याओं व गतिविधियों का सुन्दर संकलन कर दिया है ।

—बलराज मधोक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(४०३ पृष्ठ का शेष)

समस्यायें उपस्थित हैं । हमारे व्यापार पर पाबन्दियां लगी हुई हैं। उनको लगाते समय हमसे कोई मशवरा नहीं किया जाता और न इतने बड़े वस्त्र व्यवसाय को किसी तरह भी विश्वास में लिया जाता है लेकिन क्या इन कानूनों और पाबन्दियों से सरकार का उद्देश्य पूरा हो रहा है ? क्या जनता को सस्ता और अच्छा कपड़ा मिल रहा है ? हमें यह कहने में बिलकुल झिझक नहीं है कि इन आदेशों और पाबन्दियों ने ही कपड़ा उद्योग व व्यवसाय के सामने कई नई कठिनाइयां उत्पन्न कर दीं और सरकार ने जिस उद्देश्य को लेकर यह कदम उठाये थे, वह पूरे नहीं हो सके और उपभोक्ता के हितों को नुकसान पहुँचा। आज जरूरत इस बात की है कि देश में कपड़े का उत्पादन तेजी से बढ़े, क्वालिटी में सुधार हो और हमारा देश अपने प्रतियोगी देशों के मुकाबले में स्टैन्डर्ड (उच्च स्तर) का कपड़ा बनाकर सस्ते दामों में अन्य देशों की मंडियों को निर्यात कर सके, जिससे हमारी साख बनी रह सके। दूसरी ओर देश की व्यापार श्रृंखला को मजबूत करके देश के व्यापार को एक नया जीवन मिल सके।

१८ प्रतिशत लाभ ?

सन् १९५९-६० में जब सूती कपड़े की कीमतें बढ़ने लगीं तो तो भारत सरकार ने मिल वालों से परामर्श करके कपड़े पर दाम छापने की नीति अपनाई और उत्पादन से उपभोक्ता तक कपड़ा पहुँचाने के मार्जिन की सीमा (Margin of profit) १८ प्रतिशत निश्चित कर दी। बगैर इस लिहाज के कि चाहे वह माल मिल के बाहर दस कदम पर किसी स्टोर पर बिके या काश्मीर की घाटियों पर जाकर बिके। यह सब, कपड़े के इतने बड़े व्यापारी वर्ग से, जो हिन्दुस्तान के कोने-कोने में लाखों की संख्या में फैला हुआ है, बिना सलाह लिए किया गया । सरकार ने यह भी आवश्यक नहीं समझा कि वह उन कारणों का पता लगाए, जिनके कारण उस समय कुछ मामूली सी कपड़े की कीमतें बढ़ी थीं। अगर सरकार उस समय एक "इंक्वायरी कमेटी" बनाकर उसके हर पहलू पर विचार करती और मंहगाई के कारणों की जांच करके उन कारणों को दूर कराती तो हम विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि सरकार कभी इस मूल्य छापने की नीति को पसंद नहीं करती।

१८ प्रतिशत का लाभ कुछ मुनासिब मालूम दीखता है, मगर यह एक भुलावा है, जिसमें जनता को रखा जा रहा है। यह मार्जिन आफ प्राफिट, रेल भाड़ा, मजदूरी, बैंक चार्जेज, ब्याज, अन्य बढ़े हुए खर्चों को निकाल कर तथा सरकार द्वारा कपड़े पर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई हुई है और जिस पर मुनाफा लेना वर्जित है, उस रकम की लागत को लगाकर, इतना कम रह जाता है कि जिस पर व्यापार ईमानदारी से चलना कतई नामुमकिन है।

आज जनता में गलत फहमी फैल रही है कि व्यापारी १८ प्रतिशत में भी सब्र नहीं करते, जबकि ईमानदारी से एक व्यापारी को सही रूप में उसके सरमाये का जो कि उसने व्यापार में लगाया है, ब्याज भी नहीं मिलता। दूसरी ओर मिल वालों को यह छूट दे दी गई कि वह अपने कपड़े पर मन चाहे दाम छाप दें। चुनांचे मिल वालों ने मनमाने दाम अपनी "क्वालिटियों" पर छापे, क्योंकि उनके सामने अब किसी किस्म की खुली प्रतियोगिता का सवाल ही बाकी नहीं रह जाता है। व्यापारी ही एक ऐसा माध्यम था, जो मिलों को मजबूर करता था कि वह प्रतियोगिता में एक दूसरी से अच्छी 'क्वालिटीज' को बनवाएं। अपने कपड़े की क्वालिटी को मार्केट में प्रचलित करने के लिए मिलें एक दूसरे के मुकाबले में भाव रखती थीं और किस्मों के सुधार की ओर विशेष ध्यान देती थी।

व्यापार की इतनी बड़ी मशीनरी जिसमें अनेकों तरह के पुर्जे, चाहे वह होल-सेलर हों, आढ़ती, रिटेलर, हाकर हों, उनके लिये सिर्फ १८ प्रतिशत लाभ निर्धारित करके और अपने आप मुनाफे की किसी सीमा में न बन्धकर मिल वालों ने जो गत वर्षों में लाभ कमाया है, वह एक उदाहरण है। हमें दुःख है कि इससे भी सब्र न हुआ और वे अपने स्टोर स्वयं खोलने की नीति को अपना कर तेजी से उस ओर कदम बढ़ा रहे हैं । इस प्रकार वह १८ प्रतिशत के लाभ को भी स्वयं ही ले लेना चाहते हैं।

देश की जनता का बड़ा भाग व्यापार में लगा है। ऐसा कोई काम अब न किया जाए, जिससे उस वर्ग में बेकारी फैले। कपड़े के मिल स्टोर और कोआपरेटिव स्टोर खोलना जनता के इस वर्ग में बेकारी को फैलाना है।

सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विविध आर्थिक प्रश्नों की चर्चा

आत्मनियंत्रण की आवश्यकता

चीन के आक्रमण के समय अखिल भारतीय फेडरेशन और अखिल भारतीयों के व्यापारिक संगठन ने देश में मूल्य वृद्धि और मिलावट को रोकने तथा अपने सदस्यों या असदस्य व्यापारियों पर नियन्त्रण करने का निश्चय किया था। उनका वह निश्चय आज शिथिल पड़ गया है। यदि निजी उद्योग को अपनी आत्म-प्रतिष्ठा की रक्षा करनी है, तो उसका यह कर्तव्य है कि वह देखे कि उनका कोई सदस्य अनीतिपूर्ण, नियम विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि का कोई कार्य न करे, अन्यथा उसे उसी तरह अपने संगठन या समाज से निकाल दिया जाय, जिस प्रकार पहले जातीय पंचायतें अपराधियों का सामाजिक बहिष्कार करती थीं। पिछले दिनों में कलकत्ते या अन्य स्थानों के व्यापारियों के पतन के सम्बन्ध में जो अवांछनीय समाचार मिले हैं, वे इस आत्म-नियंत्रण की आवश्यकता को और भी अधिक आवश्यक सिद्ध करते हैं।

—जी० एस० पथिक

विदेशी उद्योगों का सहयोग अथवा ऋण

कुछ वर्षों से अनेक भारतीय उद्योग विदेशी प्रतिष्ठानों का भी सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। भारत सरकार भी ऐसे संयुक्त उद्योगों को चलाने की अनुमति देती है। इन उद्योगों के चलाने का मुख्य कारण विदेशी मुद्रा का अभाव है। यह मानते हुए भी हमें यह नहीं भुलना चाहिए कि विदेशी प्रतिष्ठानों के सहयोग से उद्योग खड़ा करने पर भारतीय उद्योगपति और देश भली प्रकार लाभ नहीं उठा पाता। हम जो ऋण लेते हैं, उसका केवल ब्याज देना पड़ता है, और मूलधन चुकता होने पर देश उसके भार से मुक्त हो जाता है, पर निजी क्षेत्र में विदेशी पूंजी लगने पर देश में विदेशी आर्थिक उपनिवेश कायम हो जाता है। यदि विदेशी सहयोग नियत काल के लिए हो, तो वह अनुचित नहीं है। अन्यथा यह अनन्त काल तक शोषण का स्रोत बना रहता है। विदेशी विनियोजक मनमाने भावों में अपनी मशीनें देता है, कच्चे माल के ऊंचे दाम लेता है, अपने पैटर्न की स्थायी रायल्टी लेता है, डिविडेण्ड लेता है और उनके टैकनिशियन भारी वेतन के अलावा मुनाफे में भी भारी हिस्सा लेते हैं।*

—सुभाष

*यदि कोई पाठक इसका दूसरा पक्ष रखेंगे, तो हम उसे सहर्ष स्थान देंगे। —सम्पादक

बोकारो सार्वजनिक क्षेत्र में ही

भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बोकारो स्पात का कारखाना १०० प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र में ही बनेगा। अभी भारत के प्रमुख उद्योगपति श्री जे० आर० डी० टाटा ने वाशिंगटन में भाषण देते हुए कहा था कि इस देश में एक भी ऐसा उद्योगपति नहीं है, जो इतनी भारी पूंजी (५०० करोड़ रु०) इस उद्योग में लगा सके। रिजर्व बैंक के अंकों से भी यही सिद्ध होता है। बोकारो के कारखाने में ५०० करोड़ रु० पूंजी की जरूरत होगी। १९६२ में देश में कुल १३० करोड़ रु० की पूंजी का विनियोजन हुआ था। १९६१ और १९६० में क्रमशः १३० और ११० करोड़ रु० नई पूंजी बाजार में आई। १९५९ में तो १०० करोड़ रु० की पूंजी भी नहीं निकल सकी। इन अंकों में बोनस के रूप में जारी किये गये शेयर भी शामिल हैं। इसलिए यह तो असम्भव है कि कोई एक उद्योगपति या कुछ उद्योगपति मिलकर इतने भारी पूंजी-व्यवस्थित उद्योग को चलाने में रुचि लें।

—डा० एम० एन० दस्तूर

सम्पदा

का

एक नया ग्राहक बनाना आपका परम कर्त्तव्य है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्वर्णनियंत्रण तथा अनिवार्य बचत : नये परिवर्तन

संसद के दोनों सदनों में अधिवेशन के अन्तिम दिन वित्तमन्त्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने दो महत्त्वपूर्ण घोषणाएं कर अनिवार्य-बचत योजना आय-कर देने वालों को छोड़कर सबके लिए खत्म कर दी और शुद्ध सोने के पुराने जेवरों को तुड़वाकर उतनी ही शुद्धता के नए जेवर बनाने या बनवाने की छूट दे दी। उन्होंने कहा—

सोने का तस्कर व्यापार रोकने के लिए सोने, विशेष रूप से शुद्ध सोने की बिक्री कम करने और देश में जेवरों के लिए सोने की मांग घटाने के उद्देश्यों को सरकार राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से बिल्कुल सही मानती है और उन्हें छोड़ने का कोई सवाल नहीं। इन रियायतों का यह मतलब नहीं है कि सोने की खपत कम करने की सरकार की बुनियादी दीर्घकालीन-नीति में कोई परिवर्तन किया जा रहा है। नये जेवर हर दशा में १४ कैरट सोने के ही बनवाए जा सकेंगे। जेवर बनाने की छूट केवल उन सुनारों को है, जो जेवर बनाकर ही अपना गुजारा करते हैं। इसके लिए उन्हें नाममात्र की फीस पर लाइसेंस दिए जाएंगे।

जहां तक बड़े लाइसेंस-शुदा व्यापारियों के आर्डर पर अपने घरों में बैठकर जेवर बनाने वाले स्वर्णकारों का सम्बन्ध है, उन्हें अपने घरों में १४ कैरट तक (एक नियत मात्रा में) सोना रखने की छूट रहेगी।

पुराने जेवरों को उतनी ही शुद्धता के नये जेवरों में बदलवाने की छूट उन लोगों के लिए है, जो अपने पुराने जेवरों को तुड़वाकर नए जेवर बनवाना चाहते हैं और उन सुनारों के लिए है, जो जेवर बनाकर ही अपनी आजीविका चलाते हैं। १४ कैरट से ज्यादा शुद्धता के जेवरों को व्यापारी न बेच सकेंगे और न ही अपनी दुकानों पर प्रदर्शित कर सकेंगे।

अनिवार्य बचत योजना की समाप्ति

"अनिवार्य बचत योजना अधिनियम, १९६३, के अन्तर्गत इन पांच प्रकार के लोगों के लिए पांच योजनाएं बनायी गयी थीं : लगान देने वाले, शहरी अचल सम्पत्ति के मालिक, बिक्री-कर देने वाले, आय-कर न देने वाले और आय-कर देने वाले। इनमें से पहले तीन प्रकार के लोगों से सम्बन्धित योजनाएं अभी चालू नहीं हुई हैं। ये तीनों योजनाएं राज्यों और स्थानीय प्रशासनों की मार्फत लागू की जानी हैं। इनके मसौदे राज्य सरकारों की राय जानने के लिए भेजे गये थे। राज्यों ने इन्हें लागू करने के बारे में अनेक दिक्कतों का जिक्र किया है, अन्य दो योजनाओं के बारे में भी यह कहा गया है कि इनके अन्तर्गत रुपया इकट्ठा करने में बहुत सी दिक्कतें आयेंगी। बहुत-सी नगरपालिकाएं शहरी सम्पत्ति पर कोई कर नहीं लगाती। अतः वहां अनिवार्य बचत की रकम वसूलने में दिक्कत पड़ेगी। राज्य सरकारों ने यह भी कहा है कि जो लोग बिक्री कर देते हैं, उनसे अनिवार्य बचत की रकम वसूलने में बिक्री कर अधिकारियों को और ज्यादा दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा इन योजनाओं से बहुत कम रुपया इकट्ठा होने की आशा है।

"लगभग सभी राज्यों के मुख्य मंत्री इस बात के पक्ष में थे कि लगान देने वालों पर यह योजना लागू न की जाए और अधिकांश की यह राय थी कि शहरों में जायदाद के मालिकों और बिक्री-कर देने वालों पर भी यह योजना लागू न की जाए।

"भारत सरकार ने निर्णय किया है कि लगान देने वालों, शहरों में अचल सम्पत्ति के मालिकों और बिक्री-कर देने वालों पर, जिन पर यह योजना अब तक लागू नहीं की गयी है, आगे भी लागू न की जाए। ऐसे वेतनभोगी कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो आय-कर नहीं देते, सरकार ने इसी तरह की छूट देना उचित समझा। जिन कर्मचारियों ने इस योजना के अन्तर्गत धन जमा कर दिया है, उन्हें बिना विलम्ब किए, ब्याज सहित उनकी रकम लौटाने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन जो लोग आय-कर देते हैं,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उनकी बात दूसरी है। उन्हें अब पहले की अपेक्षा बढ़ी दर से आय-कर देना पड़ता है, लेकिन अनिवार्य बचत योजना में धन जमा कराने पर उन्हें आय-कर की बढ़ी दर में छूट मिलेगी। अगर यह योजना उन पर लागू न की जाए तो उन्हें ज्यादा कठिनाई होगी, क्योंकि वापस मिलने वाली बचत के बदले उन्हें कर के रूप में रुपया देना होगा। इसलिए आय-कर देने वालों पर यह योजना लागू रहेगी। मुझे विश्वास है कि सदन इन संशोधनों का समर्थन करेगा।

"मैंने अभी जिन निर्णयों की घोषणा की है, उनसे सरकार की आय काफी कम हो जाएगी, लेकिन सरकार को आशा है कि इस कमी की पूर्ति स्वेच्छा से की गयी बचत से हो जाएगी। चालू वित्त वर्ष के पहले ५ महीनों में छोटी बचतों में ३१ करोड़ रु० जमा हुआ है। पिछले वर्ष की इस अवधि में जितना धन जमा हुआ, उससे यह दुगुना है।"

वस्त्र उद्योग और बिक्री-कर

वस्त्र-उद्योग सदा यह शिकायत करता आया है कि सरकार विविध कर लगाकर वस्त्र का मूल्य बढ़ाने को विवश करती है। बम्बई के मिल मालिक संघ ने बताया है कि महाराष्ट्र में ही वस्त्र-उद्योग से २ करोड़ ६७ लाख रुपए बिक्रीकर के रूप में लिया जाता है।

जो स्थिति महाराष्ट्र में है, करीब वही स्थित अन्य राज्यों में भी है। इस बिक्री कर का प्रभाव निर्यातित वस्त्र के मूल्य पर भी पड़ता है।

—योजना आयोग के खाद-सम्बन्धी कार्यकारी मंडल ने चौथी योजना के लिये ३० लाख टन रासायनिक खाद बनाने का लक्ष्य रखने की सलाह दी है। इसमें २० लाख टन नाइट्रोजन खाद होगा और १० लाख टन फास्फेट। सिंदरी और नांगल के कारखानों को बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसी मण्डल ने दो और कारखाने बनाने की राय दी है और इनके लिये दुर्गापुर, कानपुर, बरौनी, रिहन्द तथा उदयपुर के नाम सुझाये हैं।

—इकनौमिक टाइम्स के अध्ययन के अनुसार १९६२-६३ में विविध उद्योगों में ३१२ करोड़ रु० की नई पूंजी लगी है। इसमें नई पूंजी तथा विभिन्न उद्योगों द्वारा अपनी बचत भी शामिल है।

—बोकारो का कारखाना इसी योजना में बनाने का सरकार का दृढ़ निश्चय है। मालूम हुआ है कि जापान की कुछ कम्पनियों ने मिलकर प्रस्ताव किया है कि वे यह कारखाना खोलने में सरकार को सहयोग देंगी।

—भारत सरकार ने नई घोषणा के द्वारा अगली छःमाही के लिये आयात की वही मात्रा स्वीकार की है, जो पिछली छःमाही में थी।

—भारत सरकार ने रूस से २२९० और पोलैंड से एक हजार ट्रैक्टर मंगवाने का निश्चय किया है, यह सूचना देते हुए कृषि मन्त्री श्री रामसुभग सिंह ने यह भी बताया है कि हम पूर्वी योरप के दूसरे देशों से भी ट्रैक्टर मंगाने की बातचीत कर रहे हैं।

—भारतीय उर्वरक निगम को १९६२-६३ में, पिछले वर्ष की अपेक्षा १ करोड़ २५ लाख रु० से भी अधिक का शुद्ध लाभ हुआ। निगम के सिन्द्री और नगंल के कारखानों का उत्पादन भी बढ़ा।

निगम द्वारा महाराष्ट्र में ट्राम्बे, आसाम में नामरूप, उत्तरप्रदेश में गोरखपुर और मध्यप्रदेश में कोरबा में नये उर्वरक कारखाने खोले जा रहे हैं।

—गंगा में पानी का स्तर कम हो जाने के कारण कानपुर में बिजलीघर बन्द होने लगा है और परिणाम-स्वरूप ७ अक्तूबर से कानपुर के उद्योगों को बिजली मिलनी बन्द हो गई है। कपड़ा चमड़ा, रासायनिक कारखाने बन्द हो गये हैं और एक लाख श्रमिक बेकार हो हो गये हैं।

—कारमहोम कांफ्रेंस की जहाजी कम्पनियों ने जहाजी भाड़े की दर १२॥ फ़ीसदी बढ़ाकर भारतीय व्यापार के लिए एक समस्या पैदा कर दी है। बम्बई की ए० पी० जे० लाइन्स ने इन कम्पनियों के मुकाबले में अपनी सेवा जारी करने का निश्चय किया है। इसके जहाज लन्दन व यूरोप के बन्दरगाहों तक जाया करेंगे। इसके जहाजों के नाम हैं—सुषमा, अंजलि और आकाश।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संचालक, पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश

की

विज्ञप्ति संख्या ४।५५८० : २७।३३, दिनांक १५

द्वारा

पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत

सुन्दर पुस्तकें

		रु०	आ०
वेद सार	प्रो० विश्वबन्धु	१	८
प्रभु का प्यारा कौन ? (२) भाग			
सच्चा सन्त		३	
सिद्ध साधक कृष्ण		३	
जीते जी ही मोक्ष		३	
आदर्श कर्मयोग		३	
विश्व-शान्ति के पथ पर		१	
भारतीय संस्कृति	प्रो० चारुदेव		
बच्चों की देखभाल	प्रिंसिपल बहादुरमल	१२	१
हमारे बच्चे	श्री सन्तराम बी. ए.	३	१३
हमारा समाज		३	
व्यावहारिक ज्ञान		२	१२
फलाहार		१	४
रस-धारा		०	१४
देश-देशान्तर की कहानियां		१	
नये युग की कहानियां		१	१२
गल्प मंजुल	डा० रघुबरदयाल	१	
विशाल भारत का इतिहास	प्रो० वेदव्यास	३	८

१० प्रतिशत कमीशन और ५० रु० से ऊपर के आदर्शों पर १५ प्रतिशत कमीशन।

विश्वेश्वरानन्द पुस्तक भंडार

साधु आश्रम, होशियारपुर, पंजाब

आर्थिक समीक्षा

सम्पादक : श्री हरतीर्थ सिंह

- हिन्दी में अनूठा प्रयास
- आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख
- आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत

भारत के विकास में रुचि रखनेवाल प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक।

वार्षिक मूल्य : ५ रु० एक प्रति २५ नये पैसे

लिखें—व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, नई दिल्ली

भारत के अनेक राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा-संस्थाओं, वाचनालयों, पंचायतों एवं विकास खण्डों के लिए स्वीकृत

भारत व्यापार पत्रिका

उद्योग तथा व्यापार प्रधान सचित्र हिन्दी मासिक

लोकप्रियता के कारण

- मिश्र-मिश्र वस्तुएं बनाने की योजनाओं का नियमित प्रकाशन
- आपके उलझे प्रश्नों के उत्तर
- आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए 'सुझाव एवं शिकायतें' स्तम्भ
- एक विज्ञापन रियायती दर पर छापने के लिए 'रियायती दर विज्ञापन कूपन' की व्यवस्था
- विज्ञान जगत ★ देशिक तथा बीमा समाचार ★ आयात निर्यात समाचार
- दान जगत आदि अनेक स्तम्भ
- आकार डबल क्राउन १/८
- पृष्ठ संख्या ६४ से ७२ तक
- वार्षिक चन्दा विशेषांकों सहित ६ रुपये
- साधारण अंक १० नये पैसे

- उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के लिए उपयोगी लेख ★ सारे संसार
- आर्थिक गतिविधियों की जानकारी
- व्यापारिक भविष्यवाणी
- आम जनता के लिए दो अंक
- एक आकर्षक कहानी ★ घर-घर प्रयोग
- गंगा की लहरें ★ व्यवसायों ★ विज्ञान समाचार
- अर्थशास्त्र के छात्रों के लिए अत्यन्त उपयोगी लेख

आज ही अपनी प्रति सुरक्षित कर लें।

अन्य जानकारी के लिये लिखें:—
व्यवस्थापक
भारत व्यापार पत्रिका,
पो. बो. नं. ४८, राजा दरवाज़ा,
वाराणसी (उ.प्र.)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सुभाषित रत्न-माला

दूसरा संस्करण

सम्पादक : कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

८ वर्ष पूर्व इस पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था और हाथों-हाथ बिक गया था कई वर्षों से यह पुस्तक अप्राप्य थी और इसकी मांग निरन्तर बढ़ रही थी। अब परिवर्धित संस्करण आकर्षक रूप सज्जा में प्रकाशित हुआ है। इस संग्रह में पढ़िये -

- वैदिक एवं संस्कृत साहित्य के अगाध भंडार से चुने गये ऐसे सरल सुन्दर श्लोक और मंत्र, जिन्हें छोटे-बच्चे भी सुविधा के साथ कंठस्थ कर सकते हैं।
- प्रत्येक श्लोक और मंत्र का सरल सुबोध हिन्दी में अर्थ।
- पुस्तक के अंत में अर्थ-सहित कुछ ऐसी सूक्तियां, जिनका उपयोग छात्र अपने निबन्धों में कर सकें।
- आपके बच्चों के स्वस्थ मानसिक विकास और उनमें नैतिक चेतना जगाने के लिए यह रत्न-माला अनिवार्य है।

उपहार और पुरस्कार देने के लिए बहुत उपयुक्त।

मूल्य एक प्रति रु. १.१५ न. पै.। "सम्पदा" के ग्राहकों से अपनी ग्राहक संख्या लिखने और ८५ न. पै. प्राप्त होने पर "बुक पोस्ट अंडर पोस्टल सार्टिफिकेट" द्वारा भेजी जाएगी।

अशोक प्रकाशन मन्दिर

२८/११ शक्तिनगर, दिल्ली-६

भारत की उद्योग नीति

लेखक :

प्रो० रामनरेश लाल

भारत सरकार ने १९४८ में जो उद्योग नीति निर्धारित की थी, १९५६ में संशोधन के बाद से वही आज भी हमारी उद्योग-नीति का आधार है। इसलिए उद्योग नीति को समझने के लिए उक्त पुस्तिका का अध्ययन बहुत लाभदायक होगा।

मूल्य : डाक-व्यय सहित ७५ न. पै.

'सम्पदा' के ग्राहकों को अपनी ग्राहक संख्या लिखने और १० न. पै. का टिकट भेजने पर रियायती मूल्य में यह पुस्तक भेजी जाएगी। वी० पी० से नहीं भेजी जाएगी।

अशोक प्रकाशन मन्दिर,

२८/११, शक्तिनगर, दिल्ली-६

जीवन साहित्य

हिन्दी के उन मासिक पत्रों में से है, जो—

- लोकरुचि को नीचे नहीं ऊपर ले जाते हैं,
- मानव-मानव से लड़ाते नहीं, मिलाते हैं।
- आर्थिक लाभ के आगे झुकते नहीं, सेवा के कठोर पथ पर चलते हैं।

जीवन साहित्य की सात्विक सामग्री को छोटे-बड़े, स्त्री-बच्चे सब निःसंकोच पढ़ सकते हैं। उसके विशेषांक एक से एक बढ़कर होते हैं।

वार्षिक शुल्क ४) रु. भेजकर ग्राहक बन जाइये

ग्राहक बनने पर मंडल की पुस्तकों पर आपको कमीशन पाने की भी सुविधा हो जायगी।

सस्ता साहित्य मंडल

नई दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्या आपको फूलों वाले प्रिन्ट, सुन्दर

धारियां, 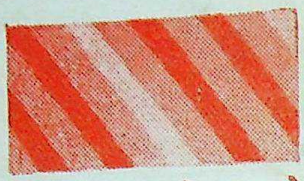 हलके रंग पसन्द हैं ? 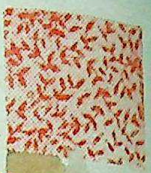

चाहे जो आपका चुनाव हो, हमारे यहाँ सभी कुछ उपलब्ध है। डी सी एम की साड़ियाँ हलकी, सुन्दर व टिकाऊ होती हैं...और कितनी सस्ती—रु० १२.३४ से रु० १८.४६ प्रति साड़ी.

डी सी एम के सभी रिटेल स्टोरों, व्होलसेल एजेन्टों व स्टाकिस्टों से प्राप्य है.

डी सी एम कपड़ों की सुन्दरता व मज़बूती का प्रतीक

दि दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कं० लि०, दिल्ली.

13 NOV 1963 क्रमांक ६३२

JWT/DCM 2741 H

सम्पादक—कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा जनचेतन प्रेस (प्रा०) लि० (लांजिज ऑफ अर्जुन प्रेस) दिल्ली-६ से मुद्रित
अशोक प्रकाशन मन्दिर २८/११, शक्तिनगर दिल्ली ६ से प्रकाशित।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा

वर्ष : १२ अंक : ११

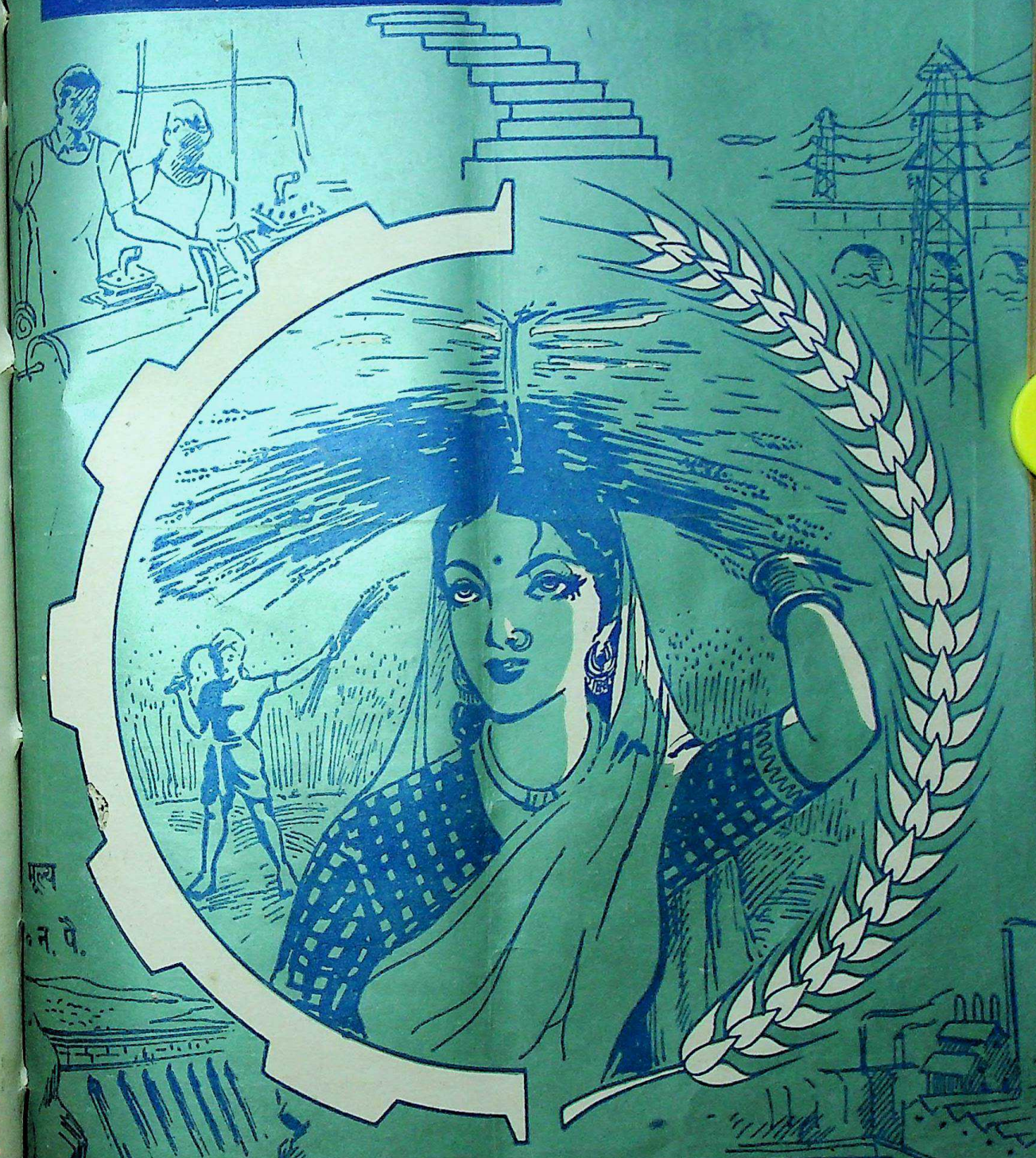

मूल्य
० न. पै.

अशोक प्रकाशन मन्दिर शक्ति नगर, दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद का मुख्य पत्र

स्वस्थ जीवन

प्रधान सम्पादक — श्री राधकृष्ण नेवटिया
प्रबन्ध सम्पादक — श्री धर्मचन्द सरावगी
एक प्रति ५० न० पै० — वार्षिक ५) रुपया मात्र

साहित्य के साथ अपने सुन्दर स्वास्थ्य के लिए कविता, कहानी, संस्मरण तथा डायरी और परिषद की गतिविधि पढ़ें। आज ही पांच रुपया भेजकर ग्राहक बन जाइए। विज्ञापन देकर लाभ उठावें। सहयोगी बन्धु अपनी नवीन कृतियां हमें भेजें।

कार्यालय :—

"जैन हाउस"

८।१ एस्प्लेनेड ईस्ट,
कलकत्ता-१

ग्राम राज

(मास में तीन बार प्रकाशित)

सम्पादक—श्री गोकुलभाई भट्ट

"ग्रामराज बहुत ही शानदार और बहुत ही सुन्दर पत्र निकल रहा है। सब तरह की जानकारी इसमें रहती है। राजस्थान के हर शिक्षित भाई बहन के हाथ में यह पत्रिका होनी चाहिए।"
— विनोबा

वार्षिक चन्दा ३) रु०

कार्यालय का पता :

ग्रामराज, किशोर निवास

जयपुर

उषा

* सामाजिक कहानियां, शिक्षाप्रद कथानक विचारोत्तेजक, मनोरंजक लेख, राशिफल, सरस कविताएं आदि।
* हानिकारक वस्तुओं व अश्लील फिल्मों के विज्ञापन स्वीकार नहीं किये जाते।

—यदि आपने अभी तक उषा नहीं देखी है, तो शीघ्र ही ३२ न. पै. के टिकिट या मनि-आर्डर भेजकर नमूनाँक मंगा देखिये। हमें पूरा विश्वास है कि एक बार 'उषा' को देखने के बाद आप हमेशा के लिए उसके हो जाएंगे।

: अन्य जानकारी के लिए लिखिये :

सचित्र मासिक उषा कार्यालय,

जवाहर मार्ग, इन्दौर।

शीघ्र ही प्रेस में जा रहा है—

न र्म दा

का

पं० बालकृष्ण शर्मा नवीन अंक

इस विशेषांक की सबसे बड़ी विशेषता पत्रकार प्रवर पं० बनारसीदास चतुर्वेदी को लिखे गए उनके व्यक्तिगत पत्रों का प्रकाशन होगा, जो स्व० नवीनजी का अलमस्ती, हंसोड़ वृत्ति और निश्छल स्नेह भाव का एक अत्यन्त मनोहर रूप पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर देंगे।

इस विशेषांक द्वारा नर्मदा का प्रयास नवीन जी के साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और मानवीय व्यक्तिगत विविध पक्षों पर पूरा प्रकाश डालने का है।

इस विशेषांक के सम्पादक हैं :

पं० बनारसीदास चतुर्वेदी • श्री शम्भुनाथ सक्सेना

पृष्ठ संख्या १५०, अनेक व्यक्तिगत व पारिवारिक चित्रों सहित · मूल्य ३ रु०

नर्मदा कार्यालय, नूतन प्रिंटिंग प्रेस,

ग्वालियर (म० प्र०)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गुरुकुल काँगड़ी

अरे भई मैं तो आशावादी हूँ —और आप ?

खरेदी के कई नये बिल लाकर सामने पटकने पर भी जो अपनी पत्नी की ओर भवें चढ़ाकर नहीं देखता उल्टा प्रसन्न होकर कहता है, 'ओ हो, उसने ज्यादा रुपये नहीं खर्च किये यह क्या कम है?" आप उस व्यक्ति को आशा वादी कह सकते हैं और मैं उनमें से एक हूँ।

चाहे कर चुकाने हों या उसके साथ अनिवार्य बचत की रकम देनी हो मैं तो, बिना शिकायत के, इस नये बोझ को उठा लेता हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कोई भाग्यवान मनुष्य हूँ! किन्तु मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ कि एक न एक दिन इससे मुझे या मेरे बालबच्चों को एक पूँजी मिलेगी। और उन के सुख के लिए क्या इतने भी कष्ट नहीं उठा सकता? हाँ, इन पैसों को देते समय थोड़ी परेशानी जरूर महसूस होती है।

अजी साहब! मैं मुँह से चूँ न निकालते हुए यह सब कुछ कर लेता हूँ ऐसा कृपया न समझिए। पोस्टमन कभी प्रीमियम नोटिस देकर लौट जाता है तब थोड़ी देर के लिए हौआ बनकर चिन्ता मुझे भयभीत कर देती है। लेकिन यह स्थिति झट से बदल जाती हैं। चिन्ता के बादल हट जाते हैं। और मैं किसी न किसी तरह प्रीमियम चुका देता हूँ। तब मैं मन ही मन कहता हूँ कि चलो, एक प्रीमियम कम हुआ और बोझ उतना ही कम हो गया। पालिसी के पैसे मिलने की अवधि भी और निकट आ गयी। इन विचारों से मन को तसल्ली सी मिल जाती है। "मेरी पत्नी और मेरे बच्चे सुरक्षित हैं।" यह भावना ही बचत के लिए मुझे प्रोत्साहन देती है और मेरा आशावाद और भी दृढ हो जाता है।

"मैं आशावादी हूँ!"—यह विचार मानो प्रेरणा का नया स्रोत है।

ASP/LIC-E-32 Hin

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विषय सूची

सं०	विषय	लेखक	पृष्ठ
१.	कांग्रेस और उसका समाजवाद		४२७
२.	सम्पादकीय टिप्पणियां		४२८
३.	लोकतंत्रीय समाजवाद		४३२
४.	गांधीवाद और समाजवाद	श्री आर० एस० तिवारी	४३३
५.	योजना आयोग और प्रशासन	कृष्णचन्द्र विद्यालंकार	४४६
६.	गौरवशाली मन्दिर—भाखड़ा बांध		४४८
७.	संविधान में १७ वां संशोधन	श्री रुस्तम कपूर	४५१
८.	आधुनिक अर्थशास्त्र के क्रान्तिकाल—२	श्री कृष्णदत्त भट्ट	४५५
९.	भारत में इंजिनीयरिंग उद्योग	श्री प्रकाशचन्द्र सेठी	४५६
१०.	विकास के लिए विदेशी सहायता	श्री ग० ला० मेहता	४५९
११.	उद्योगों की सहायक वित्तीय संस्थाएं	श्री अशोक	४६२
१२.	१३ वर्षों में १२ अरब रुपये		४६५
१३.	अणुशक्ति व पेय जल की समस्या		४६७
१४.	गांवों की उन्नति के लिए पशुपालन		४६८
१५.	भारतीय फल व सब्जियां	श्री नारायणदास बतरा	४६९
१६.	नया सामयिक साहित्य		४७१
१७.	नेपाल और भारत का सहयोग		४७६
१८.	सांख्यिकी		४७७
१९.	इस मास की आर्थिक घटनाएं		४८१

सम्पदा का वार्षिक मूल्य : ८.५० रु०

टैलिफोन नं० २२५८७३ **प्रति अंक मूल्य : ०.८० रु०**

वी० पी० से मंगाने पर ७५ न. पै. का खर्च अधिक पड़ता है।

इसीलिए मनीआर्डर से ही रुपया भेजें।

मैनेजर—सम्पदा २८/११ शक्तिनगर, दिल्ली-६

आवश्यक सूचना—पत्र व्यवहार करते समय अपना ग्राहक नम्बर जरूर लिखिये। इसके बिना कोई कार्रवाई बहुत कठिन हो जाती है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वर्ष : १२
अंक : ११
नवम्बर : १९६३

सम्पदा

कांग्रेस और उसका समाजवाद

कांग्रेस ने १९३१ में सबसे पहले समाजवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया था। इसके बाद भी वह सामाजिक विषमता को दूर करने के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करती रही। भारत का संविधान बनाते समय भी सामाजिक न्याय की वह दृष्टि उसके सामने थी। १९५६ के आवड़ी अधिवेशन में समाजवादी ढांचे के समाज की रचना का सिद्धान्त स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। इसके पश्चात् और अधिक उत्साह के साथ कांग्रेस के नेता समाजवाद की चर्चा करने लगे। यहां तक कि संसद ने भी समाजवाद के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया। नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में समाजवाद की स्थिति तक पहुँचने के लिए संयुक्त सहकारी कृषि को स्वीकार किया गया। देश में प्रबल आन्दोलन के कारण आज स्थिति वह हो गई है है कि सभी राजनीतिक दल समाजवाद को अपनी नीति के रूप में घोषित करने लगे हैं।

यह ठीक है कि जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई है; राज्यतन्त्र समाप्त हो गया है; मजदूरों के लिए तरह-तरह के नियम बन गए हैं; उनके वेतन बढ़ गए हैं; निम्नतम वेतन निर्धारित कर दिए गए हैं; और अब तो उद्योगों के प्रबन्ध में भी श्रमिकों के भाग लेने की दिशा में कुछ कदम उठाये गये हैं। सम्पत्तिशाली वर्ग पर आज तरह-तरह के कर लगाए गए हैं और असमानता को कम करने का नारा ज्यादा जोर से बुलन्द किया जाने लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां कृषि क्षेत्र में जमींदार और मध्यवर्ती वर्ग को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया है, तथा उच्चतम भूमि सीमा निर्धारित कर दी गई है, वहां उद्योगों के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्रों को अधिकाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता जा रहा है। अनेक उद्योग निजी क्षेत्र के लिए वर्जित कर दिए गए हैं। सामान्य नागरिक के लिए शिक्षा चिकित्सा आदि की सुविधाएं अधिकाधिक देने का प्रयत्न किया जा रहा है। सहकारी संस्थाओं को निरन्तर प्रोत्साहन मिल रहा है।

यह सब होते हुए भी आज स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। देश की अधिकांश सामान्य जनता ही नहीं, बड़े बड़े नेता भी यह स्वीकार करते हैं कि समाजवाद की दिशा में प्रगति बहुत ही शिथिल हो रही है। जयपुर में इन दिनों अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन हुआ। इसमें प्रायः सभी वक्ताओं ने एक स्वर से वर्तमान स्थिति के प्रति असन्तोष प्रकट किया है। स्वयं योजना आयोग के अध्यक्ष और प्रधान मन्त्री पण्डित श्री जवाहरलाल ने वर्तमान स्थिति पर असन्तोष प्रकट करते हुए कहा, कि अगर देश में समाजवाद नहीं लाया गया तो कुछ वर्षों में जनता धीरज खो और आर्थिक क्रांति के शान्तिपूर्ण तरीकों पर सर्वथा विश्वास खो बैठेगी। यदि समाजवाद नहीं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लया गया, तो १० वर्ष बाद जनता क्या करेगी, यह मैं नहीं जानता। योजना और गृहमन्त्री श्री नन्दा ने भी वर्तमान स्थिति पर गम्भीर क्षोभ प्रकट करते हुए कहा कि जिन लोगों को लोकतन्त्र और आयोजन में आस्था नहीं है, उनके लिए इस दल में कोई स्थान नहीं है। श्री उ. न. ढेबर ने वर्तमान प्रगति पर बहुत असन्तोष प्रकट करते हुए कहा, कि हमारे विकास की गति इतनी धीमी है, कि यदि इसी गति से हम बढ़ते रहे, तो अन्न, वस्त्र, आवास, शिक्षा, और काम इन पांच आधारभूत आवश्यकताओं के लिए हमें पचासों वर्ष लग जायेंगे।

पाठक इसी अंक में अन्यत्र कांग्रेस कमेटी में प्रस्तुत वह वक्तव्य पढ़ेंगे, जिसमें समाजवाद की आवश्यकता पर बल देते हुए उसे प्राप्त करने के उपायों की चर्चा है। कांग्रेस का लक्ष्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमें गरीबी, बीमारी और निरक्षरता का नामोनिशान न रहेगा; जहां सम्पत्ति और विशेषाधिकार बहुत सीमित रहेगा; जहां सभी नागरिकों को प्रगति का समान अवसर मिलेगा और जहां हमारे आचार विचार और आध्यात्मिक मूल्य हमारे वैयक्तिक और सामाजिक जीवन को समृद्ध बनायेंगे।"

जहां तक आदर्शों का सम्बन्ध है, किसी को मतभेद नहीं हो सकता। प्रश्न वहां पैदा होता है जहां इस आदर्श को क्रियान्वित करने का प्रश्न उठाता है। इस वक्तव्य में बताया गया है कि उत्पादन के प्रमुख साधन समाज की सम्पत्ति हों, उन पर पूरे समाज का नियन्त्रण हो, उत्पादन निरन्तर तेजी से बढ़ाया जाय और राष्ट्रीय सम्पत्ति का समान वितरण हो। विशेषाधिकार, असमानता और शोषण को समाप्त करना चाहिए। अधिकाधिक लोगों को रोजगार देने के लिए विकेन्द्रित कुटीर उद्योगों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। सुनियोजित अर्थ व्यवस्था में विभिन्न स्तरों पर नियन्त्रण व नियमन आवश्यक हैं। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है, और विशेषकर भारी या बुनियादी उद्योगों में निजी क्षेत्र को भी राष्ट्रीय विकास योजना की परिधि के अन्तर्गत ही अपनी उन्नति करनी होगी। उद्योगों के प्रबन्ध में मजदूरों को साझीदार बनाना चाहिए। बढ़ते हुए मूल्यों पर नियन्त्रण करना चाहिए। जमीन जोतने, बोने वाले का राज्य से सीधा सम्बन्ध हो, और मध्यवर्ग को समाप्त कर दिया जाय। भूमि सुधार के कार्यक्रम का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। कृषि तथा उद्योग दोनों क्षेत्रों में सहकारिता को निरन्तर महत्त्व मिलना चाहिए, क्योंकि यह समाजवाद की प्रथम सीढ़ी है।

इसी वक्तव्य में प्रत्येक नागरिक की भोजन, वस्त्र, घर, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन आधार भूत पांच आवश्यकताओं को शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करने पर बल देते हुए कहा गया है कि "यदि ये आवश्यकतायें पूर्ण नहीं होतीं तो फिर जन साधारण के लिए आयोजन और प्रगति का कोई अर्थ नहीं रह जाता।" इस कथन का देश में शायद ही ऐसा कोई नागरिक हो जो विरोध करने का साहस रख सके। परन्तु इसे प्राप्त करने के उपर्युक्त उपायों की व्यावहारिकता पर कहीं-कहीं मतभेद हो सकता है। यदि सरकारी क्षेत्र के प्रशासक और अधिकारी अधिक कुशल और ईमानदार होते तो अब तक का अनुभव लोगों को समाजवाद की ओर प्रेरित करने में अधिक सहायक होता। प्रशासकों का—मंत्रियों तक का निजी जीवन इस दृष्टि से आदर्श नहीं रहा। समाजवाद की भावना उन में घर नहीं कर पा रही। इसका एक उदाहरण देना काफी होगा। जब जयपुर में समाजवाद के नारे लगाये जा रहे थे, तब उत्तरप्रदेश में अधिकारी यह घोषणा कर रहे थे, कि—न्यून आय वालों का चीनी का राशन कम कर दिया जायगा, और अधिक आय वालों का राशन बढ़ा दिया जायगा। गुड़ उद्योग की मिलों के हित के लिए बलि दी जा रही है। वर्गभेद को समाप्त करने के लिए सभी उद्योगों पर सरकार का स्वामित्व इतना आवश्यक नहीं है, जितना देश की विभिन्न श्रेणियों के जीवनस्तर में समानता लाना आवश्यक है। और इसके लिए निसंन्देह मंत्रियों, शासन के उच्च अधिकारियों और उद्योगपतियों की आय को सीमित करना आवश्यक होगा; खर्चीले जीवन स्तर पर पाबन्दी लगानी होगी; और निर्माण मन्दिरों में—शिक्षणालयों में, जहां राष्ट्र की भावी सन्तति का निर्माण होता है, ऊंचनीच की भावना समाप्त करने के लिए खर्चीले पब्लिक स्कूलों की संस्था को बन्द करना होगा; कानून में ऐसे परिवर्तन करने होंगे, जिनमें धन के कारण को विशेष सुविधा प्राप्त न कर सके। वैभव का प्रदर्शन चाहे वह मंत्री

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

करें या उद्योगपति कम होना चाहिए । हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य सामान्य नागरिक है । उसका हित साधन ही हमारा दृष्टि बिन्दु होना चाहिए और यह उद्देश्य कृषि और उद्योग के राष्ट्रीयकरण और केन्द्रीयकरण मात्र से पूर्ण नहीं हो सकता । आर्थिक व्यवस्था पर सरकार का नियन्त्रण तो आवश्यक है, किन्तु वह एकाधिकार के रूपमें न हो कर जन सुविधा के लिए होना चाहिए । पंडित नेहरू ने ठीक-ठीक कहा है कि सरकार द्वारा कारखाना खोलने से समाजवाद नहीं आ जायगा । सम्पत्ति के उचित वितरण पर भी हमें उचित बल देना चाहिए, पर एक निरपवाद नियम नहीं बन सकता कि अमुक मात्रा से अधिक दो नागरिकों में अन्तर न हो ।

प्रतीत ऐसा होता है कि समाजवाद को देश में लाने के उपायों पर कांग्रेसी वक्ताओं में इतना मतभेद है कि इस वक्तव्य पर अन्तिम विचार आगामी वार्षिक अधिवेशन के लिए स्थगित कर देना पड़ा ।

वस्तुतः आवश्यकता इस बात की है कि जनता में असमानता को कम करने का प्रयत्न करना चाहिए और इसके लिए महात्मा गांधी के सर्वोदय और आचार्य विनोबा के साम्ययोग को किसी तरह समन्वित करना होगा । यूरोप की भौतिकवादी संस्कृति का आकर्षण हमें छोड़ना होगा ।

● ●

विकसित और अविकसित राष्ट्र

'१० सप्ताहों से भी कम अवधि में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जितनी राशि का विनियोजन करता है, वह भारत की उस राशि से भी बड़ी है, जो हम कुल तीसरी पंचवर्षीय योजना में व्यय करना चाहते हैं । अमरीका इन्हीं १० सप्ताहों में करीब इतनी ही धन राशि का अर्जन कर लेता है ।' इस तथ्य की चर्चा करते हुए योजना आयोग के होने वाले उपाध्यक्ष श्री अशोक महता ने राष्ट्र संघ की सभा में अविकसित राष्ट्रों की दुर्बल स्थिति को स्पष्ट किया है । उन्होंने भाषण में यह भी कहा कि जब १९६१ में कुल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ४३६.७ करोड़ डालर का हुआ, तब अविकसित देशों ने ब्याज, लाभ और डिविडेण्ड आदि के रूप में ही सम्पन्न देशों को ३३१.३ करोड़ डालर दिए । ये दोनों संख्यायें सम्पन्न और अविकसित देशों के बीच भारी अन्तर को प्रकट करने के लिए पर्याप्त हैं । इसलिए सम्पन्न राष्ट्रों का यह कर्तव्य है, कि वे अपनी राष्ट्रीय आय का कम से कम १ प्रतिशत अविकसित राष्ट्रों के विकास के लिए सहायता दें । वस्तुतः समस्त विश्व की समृद्धि पर ही विकसित राष्ट्रों का ही उज्जवल भविष्य निर्भर है ।

लघु उद्योग की बलि

जयपुर में कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन में समाजवाद की चर्चा करते हुए उद्योगों के विकेन्द्रीकरण को प्रोत्साहन देने पर बल दिया गया है । किन्तु दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और पंजाब में किसानों पर गन्ना बेचने के सम्बन्ध में कुछ पाबन्दियां लगायी जा रही हैं । किसानों को चीनी मिलों के क्षेत्र में बाध्य किया जा रहा है कि वे उन्हें ही गन्ना बेचें । चीनी उद्योग हमारे लिए कितना ही महत्त्वपूर्ण क्यों न हो, गुड़ और खाण्डसारी का उद्योग भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । शायद भारत के आर्थिक इतिहास में यह पहली घटना है, कि जब लघु उद्योग की कीमत पर बड़े उद्योगों को प्रश्रय दिया जा रहा है । सर्व सेवा संघ ने इस नई नीति का विरोध अवश्य किया है, किन्तु भारत सरकार इस विरोध की कुछ भी चिन्ता करेगी, यह नहीं दीखता ।

● ●

नयी वित्तीय नीति

भारत के नये वित्त मंत्री श्री कृष्णमाचार्य ने जब अपना पद ग्रहण किया, तब देश के औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्रों में निराशा फैल रही थी । शेयरों के मूल्य लगातार कम हो रहे थे । पूंजी का बाजार मन्दा पड़ रहा था । नये वित्त मंत्री ने इस स्थिति में सुधार का जो प्रयत्न किया है, वह प्रशंसनीय है । रिजर्व बैंक के उद्योगों को क्रेडिट की अधिक सुविधायें देने का निश्चय किया गया है । लाइफ इंश्योरेंस कार्पोरेशन भी शेयर बाजार में प्रवेश करने लगा है । यूनिट ट्रस्ट बनाने की भी योजना विचाराधीन है । पूंजी नियन्त्रण परामर्श समिति ने पूंजी संग्रह की अनुमति के लिए आवश्यक १० लाख रुपये की सीमा को १५ लाख रुपये करने की सलाह दी है । भारत सरकार ने उद्योगों के आवेदन पत्रों के भुगतान में विलम्ब को कम करने का निर्णय किया है । वित्त मंत्री ने कर लगाने की विधि को भी अधिक सरल करने के पक्ष में अपनी राय दी है । अनिवार्य बचत और स्वर्ण नियन्त्रण में अनेक संशोधन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

करके वित्त मन्त्री ने बाजार में स्वस्थता लाने का प्रयत्न किया है। हमें आशा करनी चाहिए कि इन सब प्रयत्नों का परिणाम आर्थिक क्षेत्र के लिए शुभ होगा।

राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय

केन्द्रीय अंक संकलन संगठन ने प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सरसरी तौर से अनुमान लगाया है कि १९६१-६२ की अपेक्षा १९६२-६३ में भारत की राष्ट्रीय आय में २ प्रतिशत की वृद्धि हुई। शुरू में अनुमान लगाया गया था कि १९६१-६२ में (१९४८-४९ के भावों पर) १३,०२० करोड़ रु० की राष्ट्रीय आय हुई थी। अब आंशिक संशोधन के बाद यह १३,०९० करोड़ रु० बैठी है, जो १९६०-६१ की राष्ट्रीय आय १२,७५० करोड़ से २.७ प्रतिशत अधिक है। १९६२-६३ में सरसरी तौर पर एक अनुमान के अनुसार इस वर्ष १३,३५० करोड़ रु० की राष्ट्रीय आय हुई। यह १९६१-६२ के प्रारम्भिक अनुमान से २.५ प्रतिशत और आंशिक रूप से संशोधित अनुमान से २ प्रतिशत अधिक है।

उपर्युक्त अंक हमारी पंचवर्षीय योजना की विफलता को प्रकट करते हैं। किसी योजना की सफलता आय और व्यय के ठीक अनुमानों पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय आय का अनुमान जहां पूरा नहीं हो रहा, वहां व्यय अनुमान से बहुत अधिक बढ़ रहा है। १९५३-५४ में राष्ट्रीय आय में ६ प्रतिशत वृद्धि हुई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में यह वृद्धि १९५८-५९ और १९६९-६१ में क्रमशः ७.० और ७.५ प्रतिशत तक बढ़ गई थी। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना के १९६१-६२ में केवल २.१ और १९६२-६३ में २.० प्रतिशत बढ़ी।

प्रति व्यक्ति आय में तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। १९५३-५४, १९५५-५६ और १९६०-६१ में क्रमशः ४.१, ४.८ और ५.२ प्रतिशत आय बढ़ी थी; किन्तु इस वर्ष ०.३ प्रतिशत की कमी हुई है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में भारी अन्तर का कारण जनसंख्या में वृद्धि लगती है। इस आय की कमी के कुछ भी कारण बताये जायें, उनसे सन्तोष नहीं हो सकता। दूसरी ओर योजना में अनुमानित व्यय भी निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। इन बढ़ते हुए खर्चों को देखकर कर अब योजना आयोग भी चिन्तित हो उठा है, और प्रत्येक परियोजना में व्यय करने के लिए उप समितियां नियत की जा रही हैं। जब तक हमारे आय और व्यय के अनुमान तथ्यों के निकट नहीं पहुँचेंगे, तब तक हमारी पंचवर्षीय योजनायें सफल नहीं कही जा सकती।

• •

पाकिस्तान निरन्तर बढ़ रहा है

नीचे की तालिका बतायेगी कि पाकिस्तान जूट के निर्यात में किस तरह भारत का प्रतिस्पर्धी हो रहा है। सभी देशों में पाकिस्तान का निर्यात व्यापार बढ़ा है, और भारत का निर्यात कम हुआ है। इस तालिका पर कुछ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह अंक स्वयं अपनी बात साफ कह रहे हैं।

देश का नाम	१९५७ (निर्यात हजार टन)		१९६० (निर्यात हजार टन)	
	भारत	पाक	भारत	पाक
नाइजीरिया	१७.०	—	९.१	१२.८
अफ्रीका	९५.२	५.६	५०.८	१४.८
बर्मा	२४.९	७.२	५.२	१२.०
आस्ट्रेलिया	८१.४	०.६	५६.५	२०.१
वेस्ट इंडीज	४.९	१.८	१.७	४.०
क्यूबा	५१.४	१.२	३४.४	१०.४
पेरू	१०.४	०.५	५.३	५.५

गौरवमयी सफलता

पाठक इसी अंक में अन्यत्र भारत की एक महान सफलता का वर्णन पढ़ेंगे। भाखड़ा का बांध वस्तुतः हमारे लिए गर्व और गौरव की वस्तु है। सतलुज नदी पर यह बांध बनने का विचार पहले पहल १९०८ में तत्कालीन पंजाब के लै० गवर्नर सर लूईस डेन की कल्पना है, किन्तु वह कल्पना ५५ वर्ष बाद पूर्ण हुई है। इस बांध का पंजाब और राजस्थान की समृद्धि पर बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। एक अनुमान के अनुसार भाखड़ा बांध की सिंचाई योजनायें १०.१ करोड़ टन अनाज, ८ लाख गांठें कपास, और ५ लाख टन गन्ना वार्षिक ज्यादा पैदा करेंगी। सिंचाई के अतिरिक्त ८ लाख किलोवाट बिजली पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में उद्योगों के विस्तार में बहुत सहायक होगी। हमें गर्व

सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

करना चाहिए, कि भाखड़ा बांध की पूर्णता द्वारा कई दशाब्दि पूर्व पंजाब की समृद्धि का जो स्वप्न लिया गया था, वह पूर्ण हो गया।

रूस में सोना

पिछले दिनों में रूस द्वारा अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और फ्रान्स से गेहूँ खरीदने के समाचार मिले हैं। इसके लिए कीमत का भुगतान करना आसान काम नहीं था और रूस के पास ऐसा कोई सामान तैयार नहीं होता, जिसे वे इन देशों को भेजकर विदेशी मुद्रा अर्जित कर सके। परन्तु सौभाग्य से रूस के पास विपुल मात्रा में स्वर्ण भंडार मौजूद है। डा० एम० ए० क्रिज (फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक आफ न्यूयार्क) के अनुमान के अनुसार रूस में प्रतिवर्ष १ से १॥ करोड़ औंस तक सोना निकलता है, जिसकी कीमत ३५ से ६० करोड़ डालर तक होती है। इसका अर्थ यह है कि दक्षिणी अफ्रीका के बाद रूस ही सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। एक और अनुमान के अनुसार रूस के पास इस समय चार अरब डालर का सोना विद्यमान है। पिछले दिनों में रूस ने इसी भंडार का उपयोग किया है। सितम्बर से अब तक एक अनुमान ने अनुसार वह अनुमानतः २८ करोड़ डालर का ३०० टन सोना विदेशों को भेज चुका है।

सोना पूंजीवादी संसार की चीज है। इसलिए रूस सोने के उत्पादन या व्यापार को प्रायः गुप्त रखता रहा है। लेनिन ने रूस के स्वर्ण भंडार पर गर्व करते हुए कहा था जब हम संसार को जीत लेंगे, तो इस सोने से सार्वजनिक शौचालय बनाएंगे किन्तु उन्होंने साथ यह भी कह दिया कि हम सोने को आज यथासंभव बचाएंगे और इसे उच्चतम मूल्य में बेचकर कम से कम कीमत में सामान खरीदेंगे। जब हम भेड़ियों के बीच में रहते हैं तो भेड़ियों की तरह से ही गुर्रायेंगे।

यह कम आश्चर्य की बात नहीं है कि रूस जो औद्योगिक समृद्धि की दौड़ में बहुत आगे बढ़ने पर गर्व कर सकता है, अब तक ऐसा सामान तैयार नहीं कर सकता, जो वह अमरीका, आस्ट्रेलिया और कनाडा आदि को बेचकर उसके बदले में गेहूँ मंगवा ले। उसने भारी उद्योगों पर ही अधिक शक्ति लगाई है और इन भारी उद्योगों का विकास अमरीका आदि में पहले से ही है। आज वस्तुतः रूस ऐसी स्थितियों से गुजर रहा है, जब उसे अपनी समस्त आर्थिक नीति पर गम्भीरता से पुनर्विचार करना होगा।

● ●

भूदान और ग्रामदान में अन्तर

●

योजना आयोग ने इस महीने के प्रथम सप्ताह में भूदान, ग्रामदान, भूमि का विकास और भूमि हीन कृषक मजदूरों को पुनर्वास आदि प्रश्नों पर विचार किया था। इसी अवसर के लिए श्री राधाकृष्ण ने भूदान और ग्रामदान का जो अंतर सम्मेलन को बताया, वह निम्नलिखित है—

(क) भूदान व्यक्ति द्वारा दिया जाता है। (ख) जमीन की मालकियत व्यक्तियों में कायम रहती है।

(ग) इसका लाभ एक व्यक्ति या उन व्यक्तियों को मिलता है, जिनको दाता अंकित कर देता है।

दूसरी तरफ ग्रामदान की विशेषताएं निम्न हैं—

(क) समुदाय द्वारा किया जाता है।

(ख) व्यक्तिगत मालकियत खत्म हो कर ग्राम-समुदाय की मालकियत हो जाती है।

(ग) इसका लाभ ग्राम के पूरे समाज को मिलता है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लोक तंत्रात्मक समाजवाद

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जयपुर अधिवेशन में समाजवाद के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण वक्तव्य उपस्थित किया गया था। इसमें कांग्रेस की लोकतन्त्र और समाजवाद सम्बन्धी नीति और कार्य-पद्धति पर प्रकाश डाला गया। इस पर फिर भुवनेश्वर में होने वाले राष्ट्रीय महासभा के अधिवेशन में किया जायगा। समाचार पत्रों में प्रकाशित विवरण के अनुसार इसके कुछ अंश निम्नलिखित हैं :—

कांग्रेस की विचारधारा (आइडियालाजी) 'लोकतन्त्र पर आधारित लोकतन्त्रीय समाजवाद' होगी और मानव मात्र का सम्मान एवं सामाजिक न्याय इसके अभिन्न अंग होंगे। लोकतन्त्रीय समाजवाद की स्थापना के लिए यह जरूरी है कि आर्थिक विकास में तेजी आये और कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन का स्तर बढ़े।

योजना आवश्यक

अब तक आर्थिक प्रगति बहुत धीमी रही है और इसका कारण यह है कि हम अपनी जनशक्ति और प्राकृतिक साधनों का पूरा-पूरा उपयोग नहीं कर सके। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में जो प्रगति हुई, हम उसका लाभ उठा सकने में असफल रहे।

कांग्रेस के मान्य सुनियोजित आर्थिक विकास के सिद्धांत को न्यायसंगत ठहराते हुए इसमें यह कहा गया है कि भौतिक साधनों, कौशल और तकनीकी जानकारी की कमी है, इसलिए इनका पूरा-पूरा इस्तेमाल करने के लिए प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करना जरूरी हो जाता है और उनको कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त संगठनात्मक व्यवस्था भी आवश्यक हो जाती है।

औद्योगिक नीति से सम्बन्धित प्रस्ताव का हवाला देते हुए कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र में बड़े पैमाने के उद्योगों और व्यापार विशेषकर भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास होना चाहिए।

मजदूरों को उद्योगों की प्रबन्ध-व्यवस्था में शामिल किया जाय और इस दिशा में तेजी से प्रगति की जाय।

कांग्रेस का लक्ष्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना है, जिसमें गरीबी, बीमारी और निरक्षरता का नामोनिशान नहीं होगा, जहां सम्पत्ति और विशेषाधिकार का बहुत सीमित महत्व होगा, जहां सभी नागरिकों को प्रगति का समान अवसर प्राप्त होगा और जहां हमारे आचार-विचार और आध्यात्मिक मूल्य हमारे वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन को समृद्ध बनायेंगे।

कांग्रेस के आवड़ी अधिवेशन (१९५५) में यह तय किया गया था कि कांग्रेस के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के लिए आयोजना-पद्धति को अपनाना जरूरी है, जिससे समाजवादी ढांचे के समाज की रचना की जा सके, उत्पादन के प्रमुख साधन समाज की सम्पत्ति हों, उन पर पूरे समाज का नियन्त्रण हो, उत्पादन निरन्तर तेजी से बढ़ाया जाय और राष्ट्रीय सम्पत्ति का समान वितरण हो।

१९५७ में कांग्रेस ने समाजवादी ढांचे के समाज की रचना को अपना उद्देश्य स्वीकार कर लिया। कांग्रेस निरन्तर इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करती रही है। आयोजना और समाजवाद के सवाल पर दो आम चुनाव जीते जा चुके हैं और पंचवर्षीय आयोजनाओं को तैयार करते समय हमेशा इस उद्देश्य को ध्यान में रखा गया। संसद ने भी आर्थिक विकास के लिए समाजवादी दृष्टिकोण को स्वीकार किया है।

क्रांति

कांग्रेस भारतीय समाज के आर्थिक और सामाजिक सम्बन्धों में क्रांति लाने के लिए प्रयत्नशील है। जनता के व्यवहार और दृष्टिकोण में और उन संस्थाओं एवं माध्यमों में आमूल परिवर्तन करके, जिनके द्वारा भारतीय जनजीवन चलता है, यह क्रांति लाती है। जनशक्ति और भौतिक साधनों के पूरे-पूरे इस्तेमाल से देश में समृद्धि लाना अभीष्ट है, जिसमें प्रत्येक नागरिक की खुशहाली निश्चित हो जाय; सबको तरक्की का समान अवसर प्राप्त हों;

(शेष पृष्ठ ४८० पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आज का विचारणीय प्रश्न

गांधीवाद और समाजवाद

श्री आर. एस. तिवारी

गांधीवादी और समाजवादी सिद्धांतों का उल्लेख प्रत्येक राजनैतिक और आर्थिक नीति के व्याख्याताओं द्वारा प्रायः होता रहता है। इन दो विचारधाराओं के संबंध में भी यथेष्ट चर्चा हो चुकी है, किन्तु अभी तक कोई सर्व-सम्मत हल प्रस्तुत नहीं हुआ और प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में ऐसा कोई हल उपस्थित होगा भी नहीं।

समाजवाद एक विशेष प्रकार की आर्थिक एवं राज-नैतिक व्यवस्था का परिचायक है, जिसमें व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामूहिक हित पर अधिक जोर दिया जाता है किन्तु समाजवाद के भिन्न-भिन्न समर्थकों ने उसके स्वरूप के सम्बन्ध में विभिन्न विचार व्यक्त किए हैं। इसी को लक्ष्य कर लौक हुड ने कहा था—"समाजवाद के भिन्न-भिन्न अर्थ किये गये हैं और बहुत सी बातों को समाजवाद का नाम दे दिया गया है।" विचारों की इसी भिन्नता के कारण समाज-वाद के अनेक प्रकार हो गए हैं। और उसका स्वरूप निर्धारण कठिन हो गया है, जैसा कि सी. ई. एम जोड ने कहा "समाजवाद एक ऐसी टोपी है, जिसकी शक्ल इसलिए बिगड़ गई है कि सभी उसे पहन लेते हैं।" फिर भी सरलता के लिए हम इस स्थान पर समाजवाद को उसके अंतिम क्रांतिकारी समाजवाद अथवा मार्क्सवाद के रूप में लेकर एक कठिनाई से मुक्ति पा सकते हैं। अगर इस विचारधारा को आगे बढ़ावें तो इसे लेनिनिज्म भी कह सकते हैं। अन्य शब्दों में समाजवाद वह विचारधारा है, जिसे रूस ने अपनाकर न केवल अपने देश में, अपितु विश्व में आर्थिक, राजनैतिक और दार्शनिक स्तर पर क्रांति कर दी है। संक्षेप में इस समाजवाद या मार्क्सवाद के तीन आधारभूत तत्व हैं—

तीन आधारभूत तत्व

प्रथम, दार्शनिक धरातल पर साम्यवाद की आधार-शिला 'द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद' है, जो 'हीगेल' के दार्शनिक विचारों पर आधारित है। मार्क्स के अनुसार द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद बाह्य जगत और मानवीय विचार, दोनों क्षेत्रों में गति और परिवर्तन का विज्ञान है। मार्क्स कहता है—"अब तक दर्शन ने संसार का मार्गदर्शन किया, अब उसे संसार को बदलना भी होगा।" दूसरे शब्दों में, इस विचार से मानव किसी मानवोपरि शक्ति के हाथ का खिलौना नहीं, अपितु उस संसार या उस समाज का, जिसमें वह रहता है, स्वयं स्रष्टा है। यह पूर्णतः भौतिकवादी विचार है, जिसमें किसी अलौकिक सत्ता को स्थान नहीं है। मार्क्स ने स्पष्ट किया है कि किसी भी विचार या परिकल्पना की कुछ समय पश्चात प्रतिक्रिया होती है और परिणाम-स्वरूप एक तीसरे नवीन संविचार का जन्म होता है जो कालांतर में भविष्य की पीढ़ी के लिए पुनः विचार (Thesis) का कार्य करता है और यह प्रक्रिया अनवरत रूप से चली आ रही है। इस स्वाभाविक विकासक्रम में पूंजीवाद समाप्त होगा और समाजवाद की स्थापना होगी। यह किसी विशिष्ट स्थिति के परिणामस्वरूप नहीं होगा, अपितु आवश्यकता की मांग मात्र ही उसका कारण है। जिस प्रकार सामन्तवाद के पश्चात पूंजीवाद की स्थापना हुई, उसी प्रकार पूंजीवाद का स्थान एक उच्चतर समाज व्यवस्था 'समाजवाद' लेगी, जिसमें समाज का केवल एक वर्ग बचेगा, जो कि दूसरों की तुलना में सर्वाधिक प्रगति-शील व क्रान्तिकारी है। मार्क्स ने इस वर्ग को Proletariat या सर्वहारा कहा है। उसकी सम्मति में पूंजीवादी समाज की सबसे बड़ी परिणति इस सर्वहारा समाज में होगी।

आर्थिक धरातल पर समाजवाद यह मानकर चलता है कि अर्थ का मूल कारण श्रम है। अर्थ संग्रथित श्रम ही है (Value is cangealed labour)। पूंजीपति, श्रमिकों द्वारा कुल उत्पादित में से एक छोटा सा भाग मजदूरी के रूप में उन्हें देते हैं, जिससे कि वह तथा उनका परिवार जीवित रह सके और उसकी सेवा कर सके। शेष लाभ के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नाम पर स्वयं अपनी कोठियों में भरते जाते हैं। यह पूंजीपति के द्वारा श्रम का शोषण है। पूंजी ही एक व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह दूसरे का शोषण कर सके। अतः उत्पादन, विनिमय और वितरण के साधनों पर से व्यक्तिगत स्वामित्व उठाना आवश्यक है। समाजवाद इस प्रकार की प्रत्येक व्यक्तिगत सम्पत्ति को मिटाना चाहता है, जो एक व्यक्ति को दूसरे का शोषण करने योग्य बनाती है। इसीलिए सम्पत्ति पर समस्त समाज का स्वामित्व होना चाहिए, केवल थोड़े से पूंजीपतियों का नहीं। पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजी ही शोषण की शक्ति है, जो समाज के एक अल्पसंख्यक वर्ग के हाथ में है और वे इसी शक्ति के द्वारा बहुसंख्यक वर्ग का शोषण करते हैं। इस शोषण को किसी भी प्रकार समाप्त करना आवश्यक है। अंततः समानता स्थापित हो जावेगी।

वर्ग संघर्ष

राजनैतिक धरातल पर मार्क्सवाद उस युद्ध का उल्लेख करता है, जो शोषित और पीड़ित वर्ग के द्वारा शक्ति हस्तगत करने के लिए आरंभ किया जाता है। पूंजीवाद में पूंजीपतियों की पीठ पर राज्य होता है, जो उनको संरक्षण प्रदान करता है और शोषण शक्ति के उपयोग का अवसर देता है। जब सम्पत्तिहीन बहुमत के संगठित प्रयत्न और इच्छा के विपरीत सम्पत्तिशाली इस शोषण को त्यागना नहीं चाहते, तब वह वर्गसंघर्ष के रूप में सामने आ जाता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण से राजनीति में दबाव (Pressure) आवश्यक है, क्योंकि पूंजीपति न तो अपनी पूंजी छोड़ना चाहेंगे और न अधिकार। अंततः बलप्रयोग अनिवार्य हो जावेगा। संक्षेप में यही मार्क्सवाद की रूपरेखा है।

गांधी वाद

दूसरी ओर गांधीवाद के सम्बन्ध में तो यही स्पष्ट करना कठिन है कि ऐसा कोई वाद है भी अथवा नहीं। स्वयं गांधी जी ने कहा है—वाद नाम की कोई चीज नहीं है। मैं अपने पीछे कोई सम्प्रदाय नहीं छोड़ना चाहता। गांधीजी के अनुयायियों में भी इस सम्बन्ध में यथेष्ट मतभेद है, फिर भी यदि गांधीवाद सदृश कोई वाद है, तो उसमें सामान्य रूप से निम्न तत्व प्रमुख हैं—

१. गांधीवाद का दार्शनिक आधार परंपरागत हिन्दू धर्म या हिन्दू दर्शन ही है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है और धर्म तथा सदाचार मानव जीवन के अनिवार्य अंग हैं। अहिंसा गांधीवाद का मूल गुण है। इस विचारधारा के अन्तर्गत अहिंसा केवल निषेधात्मक नहीं, अपितु उसका रचनात्मक एवं सक्रिय स्वरूप है। सत्य और अहिंसा के आधार पर ही सर्वोदय समाज की स्थापना की जावेगी। अहिंसा और सत्य ही क्रांति के अस्त्र हैं। सत्याग्रह इसी परम्परा में आने वाला अहिंसात्मक रचनात्मक कार्य है। यह अहिंसा व्यक्तिगत नहीं, सार्वजनिक है। "जो अर्थशास्त्र शक्तिशाली को दुर्बल का शोषण कर सम्पत्ति संग्रह करने का समर्थन करता है, वह झूठा और निराशाजनक विज्ञान है। वह मृत्यु की ओर ले जाता है। सच्चा अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय और नैतिक मूल्यों को अपना आधार मानता है।" उनके अनुसार मनुष्य का जीवन धर्ममय होना चाहिए और सदाचार सभी अवस्थाओं में हमारा पथ-प्रदर्शन करेगा, किसी विशेष परिस्थिति में नहीं। हम गांधीवादी दर्शन को आध्यात्मिक विचारों से पूर्ण कह सकते हैं, जिसमें मानवमूल्यों का पूर्ण महत्व बना रहता है।

२. आर्थिक दृष्टि से गांधीवादी दर्शन में अनेक तत्व सम्मिलित किए जा सकते हैं। अर्थशास्त्र के सम्बन्ध में उनके विचार उन्हीं के शब्दों में—'मानव-मूल्यों को महत्व देने के कारण वे मानवीय श्रम को अत्यधिक महत्व देते थे और यंत्रों के प्रयोग को शीघ्रता से हटा देना चाहते थे।' 'चरखा' इसी उद्देश्यपूर्ति में सहायक था। श्री श्रीमन्नारायण के अनुसार "गांधीजी के लिए श्रम प्रकृति का नियम है और इसका उल्लंघन ही हमारे आर्थिक भ्रमों का कारण है।" स्वयं उनके शब्दों में "हम निर्जीव यंत्रों को अधिक महत्व देकर मानवों के जीवित यंत्रों को नष्ट कर रहे हैं।"

उनके लिए कार्लाइल का Work is worship कथन पूर्णतः सत्य था और वे आलसी मनुष्य को शैतान का घर मानते थे। उन्होंने एक स्थान पर कहा है—"मेरे विचार में श्रम ही सच्चा धन है, सोना चांदी नहीं।"

वे प्राचीन पद्धति की सामाजिक व्यवस्था को अपनाना चाहते थे, जिसकी मुख्यतः तीन विशेषतायें हैं—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१. सबके लिए समान भूमि
२. प्रतियोगिता का पूर्ण अभाव और सहकारिता की सक्रियता ।
३. अभिभावकता (ट्रस्टीशिप)

अर्थात् गांधीवाद के अन्तर्गत समाज के आर्थिक विभाजन का रूप ऐसा होगा, जिसमें जमींदार भी रहें और किसान भी, करोड़पति भी और अकिंचन भी, केवल आवश्यक तत्व यह है कि धनवान अपने को गरीबों का अभिभावक समझें। यह कोई नवीन और मौलिक विचार नहीं है। विलियम गाडविन ने लगभग दो शताब्दि पूर्व अपनी पुस्तक 'पोलिटिकल जस्टिस' में भी इसी प्रकार के विचार प्रस्तुत किये हैं। यह एक सुधारवादी वृत्ति है। गांधीजी ने एक स्थान पर स्पष्ट किया है—'मैं जिस राम-राज्य का स्वप्न देखता हूँ, उसमें राजाओं और भिखारियों दोनों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।' वे सरलता मय जीवन का समर्थन करते थे और प्राचीन महर्षियों के समान 'सादा जीवन उच्च विचार' की भावना के पोषक थे। आवश्यकताओं की वृद्धि के स्थान पर वे उन्हें न्यून करने पर जोर देते थे। सभ्यता आवश्यकताओं की वृद्धि में नहीं, उन्हें स्वेच्छापूर्वक कम करने में है। गांधीजी के आर्थिक विचारों के मूल में है भारतीय इतिहास और भारत की आर्थिक दशा। भारत की आर्थिक और सामाजिक दशायें पाश्चात्य दशाओं से बहुत भिन्न हैं, अतः पाश्चात्य आर्थिक सिद्धांत यहां पर लागू नहीं किए जा सकते। —डा० शिवानंद झा

३—राजनैतिक दृष्टि से गांधीवादी नीति अधिकारों तथा सत्ता के विकेन्द्रीकरण की नीति पर आधारित है। वास्तव में वे राज्यहीन समाज के समर्थक थे, जो कि आर्थिक और राजनैतिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण द्वारा संभव हो सकता था। अतः पंचायत स्थापना श्रेष्ठ है। स्वतंत्रता व जनतंत्र की स्थापना ही गांधीवादी नीति है किंतु केवल शांतिपूर्ण विधि से। उनका रचनात्मक कार्यक्रम, सत्याग्रह प्रणाली, अहिंसात्मक आंदोलन सभी प्रजातंत्र व स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए थे। अपनी व्यवस्था को वे 'राम-राज्य' कहते थे। प्रमुख रूप से, गांधीवाद के राजनैतिक आदर्श हिंसा के अतिरिक्त सभी क्षेत्रों में समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र स्थापना हेतु थे।

उपर्युक्त विश्लेषण के पश्चात् दोनों विचारधाराओं का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है, (किन्तु वह आगामी अंक में)

दि नेशनल इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज़ जयपुर

बाल एराड रोलर बेयरिंग्ज
स्टील बाल, रोलर स्पिडराडल इन्सर्ट्स और
इन्जनों तथा वैगनों के लिए एक्सल बॉक्स
आदि के निर्माता

दि नेशनल इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज़

अपने सब ग्राहकों के प्रति
दीपावली का अभिनन्दन करते है और नव वर्ष की
समृद्धि की कामना करते हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

योजना-आयोग और प्रशासन

कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

● १९५२-५३ में योजना आयोग में ७६ गजटेड आफिसर काम करते थे। दस वर्ष बाद १९६२-५३ में इनकी संख्या २६५ हो गई। इसी तरह नान गज़टेड कर्मचारियों की संख्या १२६ से बढ़कर ५०३ हो गई। अफसरों का वेतन ४.८ लाख रु० से बढ़कर २४.४६ लाख रु० हो गया और कर्मचारियों का खर्च २.८३ लाख रु० से बढ़कर १६.५ लाख रु० हो गया। यह दो संख्याएं योजना आयोग के बढ़ते हुए खर्चों को बताने के लिए काफी है।

भारत के प्रधान मन्त्री और योजना आयोग के स्वयं अध्यक्ष श्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं योजना आयोग के बढ़ते हुए भारी भरकम शरीर पर अचरज प्रगट किया है और कहा है कि योजना आयोग बहुत भारी हो गया है और व्यवहारतः सरकार के प्रत्येक विभाग को सलाह देने लगा है। हर एक विभाग के लिए दो-दो संगठन बन गए दीखते हैं, जो एक दूसरे को हमेशा चिट्ठियां भेजते रहते हैं। सरकारी मंत्रालयों को छोटी-छोटी बातों के लिए योजना आयोग आदेश देता है और इस तरह प्रत्येक काम में असाधारण बिलम्ब होता जाता है। भारत सरकार के भूतपूर्व आडिटर जनरल श्री ए. के. चांदा ने तो योजना आयोग को उच्चस्तरीय मन्त्री मण्डल (Super Cabinet) का नाम दिया है, जो अनेक मन्त्रालयों का सदा अतिक्रमण करता है।

पाठकों को स्मरण होगा कि बारह-तेरह वर्ष पूर्व तत्कालीन वित्त मन्त्री श्री जोन मथाई ने योजना आयोग के संगठन और अधिकार क्षेत्र पर यही आपत्ति की थी। वे योजना आयोग के कार्य क्षेत्र से इतने असंतुष्ट थे कि उन्होंने वित्त मन्त्री के पद से ही त्यागपत्र दे दिया। योजना आयोग का मुख्य कार्य विकास योजना के लक्ष्य निर्धारित करना है। उन्हें किस तरह क्रियान्वित किया जाय, इसके सम्बन्ध में भी वह कुछ परामर्श दे सकता है किन्तु उसे क्रिया में परिणत करना और उसके विस्तार में जाना प्रशासन विभाग का काम है।

इसमें संदेह नहीं कि योजना आयोग की आलोचना में काफी सत्य है किन्तु इसका एक दूसरा पक्ष भी है और वह यह है कि प्रशासन विभाग की मशीनरी भी आज बहुत दूषित है। जिन कार्यों में योजना आयोग का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, वे कार्य भी सरकारी फाइलबाजी के कारण महीनों और वर्षों खटाई में पड़े रहते हैं। योजना आयोग जिन प्रयोजनों के लिए रुपया देता है अथवा जिन विशेष कार्यों के लिए कर लगाए जाते हैं, उन कार्यों के बजाय रुपया दूसरे कामों में लग जाता है। एक पार्लियामेंटरी कमेटी ने बताया था कि दूसरी योजना की अवधि में १०४४ करोड़ रुपया अतिरिक्त करों के रूप में प्राप्त किया गया था, किन्तु योजना के कार्यों में केवल ४३९ करोड़ रुपया लगाया गया। शेष रुपया योजना-भिन्न कार्यों में ही व्यय कर दिया गया। विभिन्न मन्त्रालय जिस तरह रुपये का अनाप-शनाप खर्च करते हैं, वह किसी से छिपा नहीं है। रूरकेला में रासायनिक खाद का कारखाना बनाने पर व्यय का अनुमान १६ करोड़ रुपये का था, किन्तु उस पर खर्च हुआ २६ करोड़ रुपया। ३१ मार्च, १९६३ तक हिन्दुस्तान स्टील प्लान्ट पर ६९८ करोड़ रुपया खर्च हो चुका था और उसे ६१.५ करोड़ रुपए का नुकसान भी हो चुका था। इन सब कार्यों की ओर यदि योजना आयोग राज्यों व केन्द्र के मन्त्रालयों का ध्यान बार-बार खींचे तो यह अनुचित नहीं होगा। ऐसा करना उसका कर्त्तव्य ही है।

यह ठीक है कि योजना आयोग टेक्निकल विशेषज्ञों का संगठन नहीं है। उसे अनेक राजनीतिक तत्त्व सदा प्रभावित करते रहते हैं और इसलिए यह सम्भव है कि लोक तन्त्रात्मक सांचे में अनेक योजनाएं बनानी पड़ती हैं। किन्तु दूसरी तरफ यह भी सच है कि योजना आयोग अपनी योजनाएं बनाते समय सैकड़ों इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से परामर्श लेता है और जब वह देखता है कि उसकी अभिलाषाएँ पूर्ण नहीं हो रहीं, उसके लक्ष्य

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

योजना आयोग के दो नये सदस्य

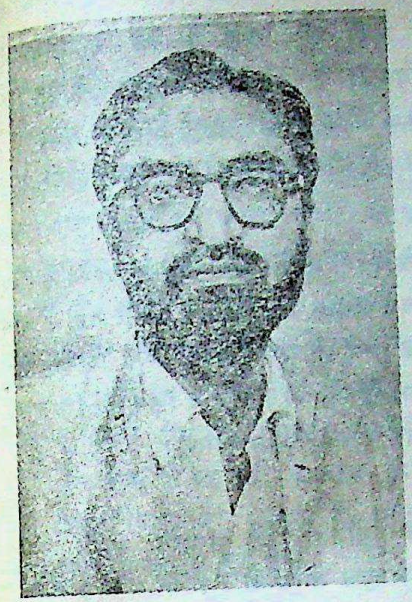

श्री अशोक मेहता

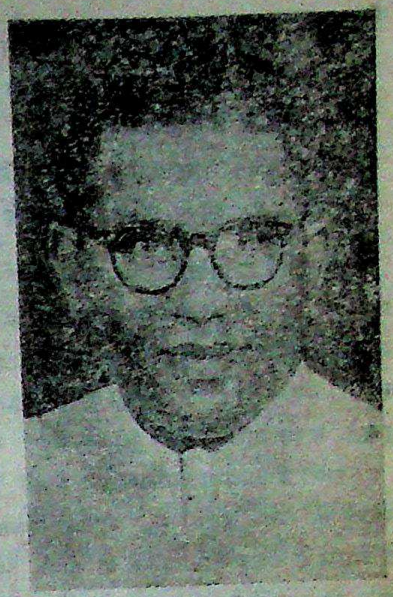

श्री बलीराम भगत

बहुत धीमी गति से बढ़ रहे हैं तो उसे क्षोभ होता है और फिर वह योजना के लक्ष्य पूर्ण न होने की जिम्मेदारी राज्यों तथा केन्द्र के मन्त्रालयों पर डालने लगता है।

आवश्यकता इस बात की है कि योजना आयोग और प्रशासन में अधिक तालमेल बैठाया जाय। योजना आयोग भी लक्ष्य रखते समय व्यावहारिक कठिनाइयों का ध्यान दे, उदाहरण के तौर पर हम कर नीति और भूमि सुधार का नाम ले सकते हैं। जब केन्द्रीय सरकार को ही विवश होकर अनिवार्य बचत और स्वर्ण नियन्त्रण में भारी सुधार करने पड़े तो राज्य सरकारों को जिन पर जनता अधिक दबाव डाल सकती है, कितना संकोचमूलक कदम उठाना पड़ता होगा? राज्य सरकारों को ही भूमि सुधारों के सम्बन्ध में व्यावहारिक कठिनाइयों का ज्ञान होता है। नई दिल्ली की शानदार इमारतों में बैठकर योजना आयोग उपदेश दे सकता है, राज्य सरकारों की कठिनाइयों का अनुभव नहीं कर सकता। उसे ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करते समय यह नहीं भूल जाना चाहिए कि व्यावहारिक मार्ग क्या है? इसी प्रकार विभिन्न मन्त्रालयों और प्रशासक कर्मचारियों का भी यह कर्त्तव्य है कि वे लक्ष्यों को पूर्ण करने में अधिक ईमानदार और सक्रिय हों। उनका यह भी कर्त्तव्य है कि वे भय और संकोच छोड़कर योजना आयोग को स्पष्ट बता दें कि कौन सी नीति व्यवहार्य नहीं है। हमारी नम्र सम्मति में किसी एक बड़े नेता और संगठन की हां में हां मिलाने और अपना मत स्पष्ट रूप से व्यक्त न करने के कारण भी अनेक कठिनाइयां उपस्थित हो जाती हैं। भूमि सुधारों की अव्यवहार्यता के सम्बन्ध में अनेक मुख्य मंत्रियों ने श्री नन्दा को निजी रूप में जो कुछ कहा, वह सार्वजनिक रूप से कहने का साहस नहीं कर सके।

जो हो, आज देश के विचारकों और प्रशंसकों का ध्यान योजना आयोग के संगठन की ओर गया है। मितव्ययता का उपदेश देने वाले योजना आयोग का जहां यह कर्त्तव्य है कि वह अपने भारी भरकम और जटिल स्वरूप को सरल करे, वहां उसका यह भी कर्त्तव्य है कि वह ऊंची उड़ान न भरे। देश की सामर्थ्य का भी उसे ध्यान रखना चाहिए, दूसरी ओर प्रशासकों और मंडलों का भी यह कर्त्तव्य है कि वह सरकार द्वारा नियत आदर्शों को व्यवहार में लाने में शिथिलता न दिखावें। इसके लिए उन्हें अधिक परिश्रमी बनना पड़ेगा और कुछ अधिक दूरदर्शिता से काम लेना होगा।

• •

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आधुनिक भारत का गौरवशाली मन्दिर : भाखड़ा बांध

७४० फुट ऊंचा भाखड़ा बांध २२ अक्तूबर को प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने देश के नाम समर्पित कर दिया। सतलुज नदी के पूरे पानी को सिंचाई और बिजली के लिये इस्तेमाल करने के हेतु १९४८ में भाखड़ा-नंगल योजना शुरू की गई थी। इससे ३,००० मील लम्बी नहरें निकाली गई; जिनसे ३६ लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होगी। इससे ८ लाख किलोवाट बिजली भी तैयार होगी, जिसके उपयोग से अनेक उद्योग बढ़े और देश समृद्धि की ओर बढ़ेगा।

देश की आर्थिक उन्नति और समृद्धि के लिए उसके प्राकृतिक साधनों को विकसित करना और उनका भरपूर उपयोग करना आवश्यक है। हमारे देश में पानी की सम्पदा अपार है, पर उसका अधिकांश व्यर्थ जाता है। इसके उपयोग से देश की समृद्धि बहुत बढ़ सकती है।

पानी के उपयोग के लिए देश में जो अनेक नदी घाटी योजनाएं चल रही हैं, भाखड़ा-नंगल योजना उन में प्रमुख है। यह एशिया भर में अपने किस्म की पहली और सबसे बड़ी है। इसे पंजाब और राजस्थान मिलकर चला रहे हैं। यह १९४८ में शुरू की गई थी।

इस योजना का प्रमुख अंग बांध है। १९५८ में इस बांध का कुछ भाग तैयार हो गया था। तब से उसमें सतलुज का पानी जमा कर के उसे सिंचाई और बिजली के लिए दिया जाने लगा था। अब बांध पूरा हो गया है। इसके जलाशय का घेरा ५५ मील है, जिसमें ८० लाख एकड़ फुट (१ एकड़ फुट=४३,५६० घन फुट) पानी समाता है। इतना पानी पूरे देश में साल भर तक घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त है। इसमें से ६३ लाख ३५ हजार एकड़ फुट पानी सिंचाई और बिजली के लिए दिया जायगा।

बांध तथा बायीं ओर के बिजलीघर की इमारत बनने पर लगभग ७२ करोड़ रु० खर्च हुआ। यह सीमेंट कंकरीट का बना है और नींव की निचली सतह से ७४० फुट ऊंचा है। नीचे इसकी चौड़ाई १,३०० फुट है, जो ऊपरी सतह पर १,७०० फुट फैली हुआ है।

बांध बनाने में इंजीनियरी के कुछ चमत्कारपूर्ण बड़े काम हुए हैं। बांध बनाने से पहले सतलुज के पानी के बहाव को मोड़ने के लिए दो सुरंगें बनाई गई थीं। ये सुरंगें दुनिया की सबसे बड़ी सुरंगें थीं। बांध बनाने के लिए ७४ लाख घन गज जमीन और चट्टानें खोदी गईं। बांध तक रेत भेजने के लिए जो घूमने वाली पट्टी लगाई गई, वह एशिया में सबसे बड़ी थी। बांध के लिए कंकरीट बनाने के सबसे आधुनिक कारखाने लगाए गए।

लाभ

भाखड़ा-नंगल योजना की सफलता इससे मानी जाएगी कि इस पर कुल जो पूंजी (१ अरब ७५) लगेगी, उससे कितना लाभ मिलेगा। आर्थिक लाभ पानी-कर, बढ़े हुए लगान, खुशहाली कर और बिजली की बिक्री से होगा। लेकिन इसके अलावा जो अप्रत्यक्ष लाभ हैं, वे इनसे कहीं अधिक हैं। इससे जनता खुशहाल होगी; अकाल नहीं पड़ेंगे; अनाज और नकदी फसलों की पैदावार बढ़ेगी; उद्योग बढ़ेंगे; बंजर जमीन खेती योग्य बनेगी और विस्थापित अच्छी तरह बसेंगे।

योजना में लगभग ६७ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई की व्यवस्था है। अनुमान है कि ३६ लाख एकड़ जमीन में सिंचाई का प्रबन्ध सुधारा जा चुका है और सरहिन्द तथा पश्चिमी जमुना नहरों का पानी भी काफी बढ़ाया गया है। इस योजना के कारण अब भाखड़ा क्षेत्र में गेहूं, अमेरिकी कपास और गन्ना भी उगाना संभव हो गया है। अनुमान है कि इससे ११ लाख टन अनाज, ८ लाख गांठ कपास और ५ लाख टन गन्ना अधिक पैदा होगा।

इस योजना के अन्तर्गत लगभग ८ लाख किलोवाट बिजली तैयार होगी। इससे बिजली की कठिनाई तो दूर होगी ही, साथ ही उद्योग बढ़ने से इस क्षेत्र की समृद्धि भी बढ़ेगी। इससे ५,००० गांवों में बिजली पहुंचेगी, जिससे वहां छोटे उद्योग बढ़ेंगे। इस प्रकार गन्ना, तेलहन,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कपास की पैदावार बढ़ने और सस्ती बिजली मिलने से अनेक कारखाने खड़े होंगे और देश उन्नति की ओर बढ़ेगा।

योजना के मुख्य अंग

भाखड़ा-नंगल योजना के मुख्य अंग हैं—भाखड़ा बांध और भाखड़ा बिजलीघर—एक बांए किनारे तथा दूसरा दाएं किनारे पर; नंगल बांध; नंगल नहर; नंगल नहर पर गंगुवाल और कोटला में दो बिजली घर; रोपड़ हेडवर्क और सरहिन्द नहर का सुधार; भाखड़ा नहरें; बिस्ट दुआब नहर तथा बिजली के तारों का जाल।

१९५४ में नंगल बांध बनने के बाद ही इस योजना से लाभ मिलने लगा था। नंगल नहर और प्रणाली जुलाई १९५४ से चालू हो गई थी। गंगुवाल बिजलीघर १९५५ और कोटला बिजलीघर १९५५ में चालू हो गया था। अन्य काम भी पूरे हो चुके हैं।

बिजलीघर

बाएं किनारे का बिजलीघर तैयार हो गया है और वहां से बिजली दी जाने लगी है। वहां ९०-९० हजार किलोवाट के ५ यंत्र है, जिनमें से तीन से नंगल के नये खाद कारखाने को बिजली दी जाएगी और शेष अन्य सब कामों के लिए। यह बिजलीघर देश का सबसे बड़ा बिजली घर है।

तीसरी योजना के अन्त तक दाएं किनारे का बिजलीघर भी चालू हो जाएगा। यह बाएं किनारे के बिजलीघर से भी बड़ा होगा। इसमें भी ५ यंत्र लगे होंगे और प्रत्येक यंत्र १ लाख २० हजार किलोवाट का होगा।

गंगुवाल और कोटला बिजलीघर

नंगल नहर पर गंगुवाल और कोटला बिजलीघर हैं। नंगल से गंगुवाल १२ मील दूर है और गंगुवाल से कोटला ६ मील। दोनों बिजलीघरों से १,५४,००० किलोवाट बिजली तैयार होती है।

गंगुवाल में १९५५ में २४-२४ हजार किलोवाट के दो यंत्र लगाए गये और फिर कोटला में २४-२४ हजार किलोवाट के दो यंत्र लगाए गये। बाद में दोनों बिजलीघरों में २९-२९ हजार के तीसरे यंत्र लगाये गये।

बिजली

बिजली पहुँचाने के लिए चारों ओर तार हैं। एक दुहरी सर्किट २२० किलोवाट की लाइन दिल्ली को गई है। दूसरी दुहरी सर्किट १३२ किलोवाट की लाइन लुधियाना को गई, जो बाद में दो भागों में बंट जाती है उसमें से एक जलंधर जाती है और दूसरी मोगा और मुक्तसर को। एक इकहरी सर्किट ३१२ किलोवाट लाइन पानीपत से हांसी, हिसार, राजगढ़ और रतनगढ़ को गई है। अम्बाला, पानीपत, दिल्ली, लुधियाना और जलंधर में बिजली-शृंखला सब-स्टेशन हैं, और ये सब मिलकर एक पूरी बिजली शृंखला बनाते हैं।

नंगल बांध

नंगल बांध सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध से ८ मील नीचे है। यह ६५ फुट ऊंचा है। इस बांध से सतलुज का पानी बिजली तैयार करने और सिंचाई के लिए नंगल नहर को मोड़ा गया है।

नंगल नहर बांध के ऊपर बाएं किनारे से निकाली गई है। यह ३९.६ मील लम्बी है और इससे १२,५०० क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है। नहर की चौड़ाई ८० फुट और गहराई २० फुट है।

सरहिन्द नहर

सरहिन्द नहर को पूरा पानी देने के लिए पानी की मात्रा ९००० क्यूसेक से बढ़ाकर १२,५०० क्यूसेक की गई, ताकि नये क्षेत्र को भी पानी दिया जा सके। इसके लिए हरिके हेडवर्क्स में पानी की सतह को २ फुट ऊंचा किया गया।

बिष्ट दुआब क्षेत्र में सिंचाई के लिए रोपड़ हेडवर्क्स के दाहिने किनारे से बिष्ट दुआब नहर निकाली गई। इस नहर में १,६०१ क्यूसेक पानी छोड़ा जा सकता है।

भाखड़ा नहर प्रणाली

भाखड़ा मुख्य नहर से फतेहाबाद और भाखड़ा शाखनहरें निकलती हैं और आगे चलकर उनसे अनेक गूलें निकाली गई हैं, जिनसे हिसार जिले में, पेप्सू के कुछ भाग में और राजस्थान में सिंचाई होती है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भाखड़ा बांध एक दृष्टि में

१—भाखड़ा बांध की ऊंचाई ७४० फुट है और यह कुतुब मीनार से तिगुना ऊंचा है। एशिया में इससे ऊंचा कोई बांध या इमारत नहीं है।

२—इसका घनत्व इतना अधिक है कि इसमें १ लाख कमरों वाली गगनचुम्बी इमारत समा सकती है।

३—इसकी नहरें ३ हजार मील लम्बी है, जिनसे ३६ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है।

४—इसके सब बिजलीघरों की कुल उत्पादन-क्षमता ८ लाख किलोवाट होगी।

५—बांध की ५५ मील लम्बी झील में ८० लाख एकड़ फुट पानी है, जो एक साल के देश भर के घरेलू उपयोग के लिए काफी है।

६—यह बांध बनाने में ७४ लाख घनगज मिट्टी और चट्टानें खोदी गईं।

७—अब भाखड़ा क्षेत्र में गेहूँ, अमरीकी कपास और गन्ने की खेती की जा सकती है। इससे ११ लाख टन अनाज, कपास की ८ लाख गांठों और ५ लाख टन गन्ने का अधिक उत्पादन होगा।

८—५ हजार गांवों में बिजली पहुँचने से छोटे उद्योगों में वृद्धि होगी।

९—इस बांध का बाएं किनारे का विशाल पन बिजलीघर देश के सब बिजलीघरों में बड़ा है। इसकी कुल उत्पादन-क्षमता ४ लाख ५० हजार कि० वा० है और इसमें ९० हजार कि० वा० के पांच जेनरेटर लगे हैं। ● ●

केवल मेट्रिक नापों का प्रयोग कीजिए

● यहां कुछ खास-खास कपड़ों की मीटरों में लम्बाई दी गयी है:

अब देश भर में नाप-तौल की मेट्रिक प्रणाली ही एकमात्र कानूनी प्रणाली है।

बुश शर्ट	१.८५ मीटर
कमीज (पूरी बांह की)	प्रत्येक के लिए
कोट	२.७५ मीटर
पतलून	
ब्लाउज़	०.९० मीटर

उचित और सुविधाजनक लेन-देन के लिए

मीटर में खरीदिये

डी ए ६३/२४५

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संविधान में १७वां संशोधन

श्री रुस्तम सी० कूपर

संसद् के इस शरद् अधिवेशन में भारत के संविधान में एक महात्वपूर्ण संशोधन पर विचार होगा। किसानों के अधिकारों से इसका सम्बन्ध है। प्रस्तुत लेख में विद्वान् लेखक ने सशोधन का विरोधी पक्ष प्रस्तुत किया है।

संविधान का १७वां संशोधन पार्लियामेंट में ६ मई १९६३ को पेश किया गया है। १९५० में भारत का संविधान स्वीकृत होने के बाद सिर्फ १३ वर्षों में १६ संविधान किये जा चुके हैं। मूल रूप से स्वीकृत संविधान में १४, १३ और ३१ अनुच्छेद थे, जिनका नागरिकों के मूल अधिकारों से काफी महत्व का सम्बन्ध था। प्रस्तुत लेख में हमारा सम्बन्ध संविधान के दो महत्वपूर्ण अधिकारों से है—(क) सम्पत्ति के अर्जन धारण और व्ययन का अधिकार : और (ख) कोई वृत्ति उपजीविका का व्यापार या कारबार करने का अधिकार। संविधान के ३१वें अनुच्छेद में किसी भी व्यक्ति को कानूनी अदालत के बिना अपनी सम्पत्ति से वंचित न करने की व्यवस्था की गई है।

सरकार ने संविधान में पहिला संशोधन करने में कोई बहुत देर नहीं लगाई थी। संविधान स्वीकार होने के बाद एक साल ही में यह संशोधन किया गया था। फलस्वरूप अनुच्छेद ३१ क लागू किया गया, जिसने नागरिकों के मूल अधिकारों को काफी हद तक बदल दिया। अनुच्छेद ३१ क ने भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा देने के सवाल को अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया था। इसका अर्थ यह था कि कोई भी कानूनी अदालत इस बात की जांच नहीं कर सकती कि प्राप्त की गई सम्पत्ति की वर्तमान बाजारी कीमत को देखते हुए मुआवजा काफी है या कम। अनुच्छेद ३१ क में "सम्पदा" की परिभाषा जागीर, इनाम या मुआफी या अन्य समान प्रकार के अनुदान के रूप में की गई है। सभी प्रकार की जमींदारी को जागीरदारी माना गया।

अनुच्छेद ३१ क को लागू करने का जब संशोधन प्रस्ताव संसद के सामने मौजूद था, उसी समय कुछ विचारकों ने सरकार और भारत की जनता को इस उपबन्ध से पैदा होने वाले अत्यन्त गम्भीर परिणामों के विरुद्ध चेतावनी दी थी। स्वयं संसद में भारी आलोचना के बावजूद भी उसने उक्त विधेयक पास कर दिया।

चौथा संशोधन

१९५५ में संसद ने समाजवाद के नाम पर भारत के संविधान का चौथा संशोधन पास किया। इस बार अनुच्छेद ३१ क में संशोधन किया गया, ताकि न केवल जमींदार, बल्कि भूमि के बारे में मध्यवर्ती तक भूमि के मुआवजे के बारे में न्यायलयों में ले जाने से वंचित कर दिये गये। नतीजा यह हुआ कि सरकार और किसानों के बीच तमाम मध्यवर्तियों को बिना उचित मुआवजा दिये ही खत्म कर दिया गया। विभिन्न राज्य सरकारों ने १९५५ के बाद लगभग १२४ विभिन्न प्रकार के कानून बनाये, जिनके जरिये विभिन्न प्रकार के जमीनों के मालिकों के अधिकारों की काटछांट कर दी गई और उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

रैयतवारी भी छिनेगी ?

इसके बाद कुछ ऐसी घटना हुई, जिसकी कल्पना अनुच्छेद ३१ क और संविधान के चौथे संशोधन को प्रस्तुत करते समय सरकार तक नहीं कर सकी थी। केरल की कम्युनिस्ट सरकार एक कदम और आगे बढ़ गई। उसने केरल भू सम्पर्क विधेयक पारित किया, लेकिन वह अधिनियम नहीं बन सका, क्योंकि राष्ट्रपति ने उसे अस्वीकार कर दिया। चौथे संशोधन के बाद अनुच्छेद ३१ क ने रैयतवारी को हाथ नहीं लगाया था। केवल जमींदारी और मध्यवर्ती पद्धतियां ही खत्म की गई थीं। बाद में केरल विधानसभा ने एक संशोधित भू-सम्पर्क अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम की वैधता को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसने उसे भारत के संविधान को भंग करने वाला ठहराया। सर्वोच्च न्यायालय की मान्यता थी कि वह अधिनियम इस प्रकार का पक्षपातयुक्त

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और अधिकार जप्त करने वाला है, जिसे संविधान का संशोधित अनुच्छेद ३१ क भी वैध नहीं ठहराया है। सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि रैयतवाडी जमीनों के बारे में केरल भू सम्पर्क अधिनियम १९६२ संविधान के अनुच्छेद १४, १९ और ३१ को भंग करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की सम्मति में रैयतवाडी जमीन को अनुच्छेद ३१ क का संरक्षण प्राप्त नहीं है, क्योंकि वे "सम्पदायें" (एस्टेट) नहीं हैं।

इसी तरह मैसूर, आंध्रप्रदेश और मद्रास में स्वीकृत अधिनियमों ने भी संविधान को भंग किया था, क्योंकि उनमें भी उसी प्रकार के उपबन्ध थे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की वजह से सरकारों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न सुधार अधिनियमों को अमल में लाना कठिन हो गया।

संयुक्त सहकारी कृषि

हमें उन कुछ घटनाओं को भी स्मरण रखना चाहिए जो १९५५ के बाद घटित हुई थीं और जिनका सम्बन्ध प्रस्तावित १७वें संशोधन से है। कांग्रेस पार्टी ने १९५९ में नागपुर प्रस्ताव पास किया था, जिसमें खाद्यान्नों के व्यापार पर राजकीय एकाधिकार, भू-सीमा निर्धारित करने तथा "संयुक्त कृषि सहकारिताओं" की स्थापना के लिए सिफारिशें की गई थी। लेकिन यह प्रस्ताव प्रभावशून्य रहा। प्रस्ताव में मांग की गई थी कि तीन वर्षों के भीतर किसानों को स्वेच्छा से संयुक्त कृषि सहकारिताएं बनाने के लिए समझाया जाय। लेकिन भारत के किसानों ने संयुक्त कृषि सहकारिताओं में सम्मिलित होने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाई।

फिर नया संशोधन

अब संविधान (१७वां) संशोधन विधेयक १९६४ के जरिये भारत के संविधान खास कर अनुच्छेद ३१ क में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक "सम्पदा" की परिभाषा में संशोधन करना चाहता है, ताकि इसके अन्तर्गत रैयतवाडी बन्दोबस्तों के आधीन जमीन को भी शामिल किया जा सके। विधेयक में ९वीं अनुसूची को भी संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे कि उसमें भूमि-सुधारों से सम्बन्धित विभिन्न राज्य के अधिनियमों को भी शामिल किया जा सके, ताकि उनकी वैधता के बारे में प्रतिकूलता या सन्देह न रह सके।

अतः "सम्पदा" या एस्टेट की प्रस्तावित नयी परिभाषा से किसानों की भारी संख्या पर असर पड़ेगा और रैयतवाडी जमीनों के मालिकों को संविधान के अनुच्छेद १४, १९ और ३१ से मिलने वाले संरक्षण से वंचित कर दिया जायगा।

इस १७वें संशोधन का एक पहलू यह भी है कि "सम्पदा" की नई परिभाषा को पिछले समय से ही अमल में लागू समझा जाय। इस पिछले समय की तिथि १९५० से ही प्रस्तावित की गई है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के किसी भी सामान्य किसान की मालिकी के किसी भी जमीन के टुकड़े को "सम्पदा" मान लिया जायगा और वह १९५० से ही अर्थात् संविधान की रचना होने के समय से ही उसे "सम्पदा" समझ लिया जायगा। यदि यह संशोधन कानून बन गया तो न केवल १२३ कानून जिसकी वैधता संदिग्ध है, कानूनी बन जायेंगे, बल्कि उनको पिछली तिथि से ही अमल में लाया गया समझा जायगा।

किसान का क्या होगा ?

इसलिए प्रस्तावित संशोधन से होने वाले नतीजों पर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। संविधान में संशोधन इतनी आसानी से ही नहीं कर देना चाहिए। मोटे तौर पर प्रस्तावित संशोधन के जरिये अब भारतीय किसान अपनी भूमि का मालिक नहीं रह सकेगा, अपने आप काम पर लगने वाले किसान का सफाया हो जायगा, उसे विस्थापित और सरकारी या संयुक्त सहकारी फार्म में एक भूमि-हीन मजदूर बना दिया जायगा।

प्रोफेसर डेविड मिट्रेनी ने अपनी पुस्तक "मार्क्स वर्सस दि पेजेन्ट" (मार्क्स बनाम किसान) में बताया है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसे कम्यूनिस्ट अन्य किसी भी व्यक्ति से ज्यादा घृणा करते हैं तो वह है थोड़ी बहुत जमीन की मालिकी वाला किसान, क्योंकि छोटे किसानों के रहते हुए कम्यूनिस्ट अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। किसान स्थायित्व और स्वाधीनता का प्रतीक होता है। भारत जैसे देश में केवल किसान ही ऐसा समुदाय है, जो किसी पार्टी को सत्ता दे या छीन सकता है। भारत में

(शेष पृष्ठ ४७५ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आधुनिक अर्थशास्त के क्रान्तिकाल—?

श्री कृष्णदत्त भट्ट

• आधुनिक अर्थशास्त्रियों की ऐसी मान्यता है कि वैज्ञानिक रूप में अर्थशास्त्र का उद्भव प्रकृतिवाद से ही होता है। प्रकृतिवाद में उसकी नींव पड़ी और अदम स्मिथ ने उस पर शास्त्रीय पद्धति के विशाल भवन का निर्माण किया। अभी तक अर्थशास्त्र के विचार हमें धर्मशास्त्र, दर्शन, नीति शास्त्र, न्यायशास्त्र आदि में यत्र तत्र बिखरे हुए मिलते रहे हैं। वाणिज्यवादियों ने उन्हें किंचित् व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया, परन्तु अठारहवीं शताब्दी के मध्य भाग में ही वैज्ञानिक रूप में अर्थशास्त्र का विकास आरम्भ हुआ।

प्रकृतिवादी विचारधारा की पूर्व पीठिका में भिन्न-भिन्न विचार रखने वाले अनेक विचारक हैं। इनमें डेका और स्पिनोजा भी है। हाब्स और पेट्टी भी है, लाक और नार्थ भी है, ला और ह्यूम भी हैं, केंटीलन और स्टुअर्ट भी हैं। इनमें फ्रांस के संक्रांतिकालीन लेखक मेलन और बोय गिल्बर्ट भी हैं, मार्शल, बौवन और फैलां भी है। इनमें ग्रेशियस पूफेण्ड्राफ और माटेस्क्यू भी है, मेलब्रांश और हेलवेशस भी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि प्रकृतिवादी विचारधारा में अनेक प्रवृत्तियों का सम्मिश्रण दृष्टिगोचर होता है। प्रकृतिवाद में भौतिकता, व्यक्तिवाद, व्यक्तिगत, स्वार्थ, प्राकृतिक नियम और आशावाद, सबका समन्वय है।

प्राकृतिक नियम

प्राकृतिक नियम प्रकृतिवादियों का केन्द्र बिन्दु है। उनकी समस्त विचारधारा केने द्वारा प्रतिपादित इस नियम पर ही निर्भर करती है।

प्राकृतिक नियम का अर्थ यह है कि जिस प्रकार ईश्वरीय आदेश के अनुसार प्राकृतिक व्यवस्था विधिवत् चलती रहती है, उसी नियम के अनुसार आदर्श सामाजिक व्यवस्था का परिचालन होता है। मानवीय नियमों एवं आदेशों से जिस व्यवस्था का संचालन होता है, वह कृत्रिम है और प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है। यह कृत्रिम व्यवस्था ही मानव के सारे दुःखों का कारण है। मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यवस्था अनेक प्रकार के नियंत्रण एवं बन्धनों की सृष्टि करती है, जिनके कारण मनुष्य प्राकृतिक नियम से दूर चला जाता है।

प्रकृतिवादी उसे ही उत्तम अर्थशास्त्र मानते हैं, जिसमें खर्च तो कम से कम हो और आनन्द अधिक से अधिक मिले। उनके प्राकृतिक नियमों का लक्ष्य यही है। उनकी मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति जब प्राकृतिक नियम के अनुकूल चलेगा तो उसे न्यूनतम व्यय में अधिकतम आनन्द की उपलब्धि होगी। व्यक्ति अपने स्वार्थ को भलीभांति पहचानता है। व्यक्ति का स्वार्थ समष्टि के स्वार्थ में नहीं है। परन्तु यह तभी सम्भव है, जब मनुष्य के मार्ग में कोई प्रतिबन्ध न हो।

प्रकृतिवादियों के मत से कृषि के द्वारा ही, धन की उत्पत्ति होती है। उसकी 'शुद्ध-उत्पत्ति' ही सारे समाज के जीवन, रक्षण एवं पोषण का साधन ही यही कारण है कि उन्होंने कृषि पर ही सबसे अधिक बल दिया है।

प्रकृतिवादियों का अनुदान

प्रकृतिवादी विचारकों का अनुदान जीद के अनुसार निम्नलिखित है।

सैद्धान्तिक दृष्टि से प्रकृतिवादियों का अनुदान :

१ प्रत्येक सामाजिक तत्व किसी नियम से संचालित होता है और वैज्ञानिक अध्ययन का उद्देश्य यही है कि ऐसे नियमों का ठीक ढंग से पता लगाया जाए।

२ व्यक्तिगत स्वार्थ यदि मनुष्य पर ही छोड़ दिया जाए तो वह स्वयं इस बात की खोज कर लेगा कि उसके लिए सर्वोत्तम क्या है और जो बात एक व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम है, वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम होगी।

३ मुक्त वाणिज्य कर द्वार सबके लिए खुला रहे। इससे ग्राहक और विक्रेता दोनों के लिए उपयोगी मूल्य निर्द्धारण सरलता से हो सकेगा तथा अत्यधिक ब्याज लेने या मुनाफा कमाने की पद्धति समाप्त हो जाएगी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

४. प्रकृतिवादियों ने उत्पादन तथा सम्पत्ति के वितरण की उत्तम परन्तु अधूरी व्याख्या की है।

५. भू-सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रकृतिवादियों ने अच्छे तर्क उपस्थित किए हैं।

व्यावहारिक दृष्टि से प्रकृतिवादियों का अनुदान—

१. श्रम की स्वतन्त्रता।

२. देश के अन्तर्गत मुक्त व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बन्धन मुक्त करने के लिए जोरदार अपील।

३. राज्य के कार्यों का मर्यादीकरण।

४. अप्रत्यक्ष कर पर प्रत्यक्ष कर की उत्तमता का प्रतिपादन।

वाणिज्यवाद से अन्तर

वाणिज्यवाद ने अपनी अर्थ पिपासा द्वारा आर्थिक क्षेत्र में जो भयंकरता उत्पन्न कर दी थी, उसी की तीव्र प्रतिक्रिया प्रकृतिवाद के रूप में प्रकट हुई। दोनों विचारधाराओं के दृष्टिकोण में मुख्य अन्तर इस प्रकार है—

वाणिज्यवाद	प्रकृतिवाद
(१) सोना-चांदी ही एकमात्र सम्पत्ति है।	(१) उत्पादक शक्ति ही वास्तविक सम्पत्ति है।
(२) सम्पत्ति, प्राप्ति का एकमात्र साधन है—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार।	(२) सम्पत्ति-प्राप्ति का सर्व-प्रधान साधन है—कृषि
(३) राष्ट्र को सम्पन्न बनाने के लिए कृत्रिम कानून बनाये जाएं।	(३) राष्ट्र को सम्पन्न बनाने के लिये सारे कृत्रिम कानून उठा दिए जाएं।

नवीन क्रांति व संघर्ष

वाणिज्यवादी और प्रकृतिवादी विचारधाराओं की नींव पर ही अठारहवीं शताब्दि के अन्तिम चरण में अर्थशास्त्र की शास्त्रीय विचारधारा का उदय हुआ। अदम स्मिथ और बैंथम ने इस विचारधारा को विकसित करने का प्रयत्न किया। आगे चलकर माल्थस और रिकार्डो ने स्मिथ की विचारधारा को भलीभांति परिपुष्ट किया। ये तीन महान् विचारक ही पश्चिमी अर्थशास्त्र के प्रतिष्ठापक माने जाते हैं।

वस्तुतः स्मिथ के साथ ही वर्तमान युग का श्री गणेश होता है। एक ओर स्मिथ का शास्त्रीय चिन्तन चलता है, दूसरी ओर विज्ञान के नवीन आविष्कार अपने चमत्कार दिखाने लगते हैं।

वर्तमान युग क्रांतियों का विशेष युग है। केवल औद्योगिक क्रांति ही नहीं, इसमें हमें बौद्धिक क्राति भी देखने को मिलती है, राजनीतिक क्रांति भी।

हारग्रेव की स्पिनिंग जेनी का सन् १७६४ में आविष्कार होता है। पांच साल बाद वाट साहब भाप के इंजन का आविष्कार कर डालते हैं। सन् १७७० में आर्कराइट का वाटरफ्रेम निकलता है तो सन् १७७६ में वाट साहब कोयले की खदान का इंजन तैयार कर देते हैं। इधर इंग्लैंड में स्मिथ की वेल्थ आफ नेशन्स का प्रकाशन होता है, तो इधर अमेरिका में स्वतन्त्रता की घोषणा होती है। एक ओर वैज्ञानिक आविष्कार दिन-दिन बढ़ते चलते हैं और उनके कारण औद्योगिक विकास होने लगता है तो दूसरी ओर केन्द्रीकरण के अभिशाप दृष्टिगत होने लगते हैं।

और तभी फ्रांसीसी क्रान्ति हो जाती है।

औद्योगिक क्रान्ति और पूंजीवाद के विकास के बीच उन्नीसवीं शताब्दी का आरम्भ होता है। उसके साथ-साथ इंग्लैंड और यूरोप में फ्रान्स और रूस में विश्व के विभिन्न अंचलों में जन-जागरण का शंखनाद सुनाई पड़ने लगता है। केन्द्रीकरण एवं यन्त्रों के अभिशाप स्पष्ट होने लगते हैं। दुर्भिक्षों और अकालों की मार अलग से पड़ती है। संघर्ष, रक्तपात, युद्ध, क्रांति आदि के बीच समाजवाद और साम्यवाद पनपता है। पूंजीवाद, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के भयंकर पंजों में फंसी जनता संत्रस्त हो उठती है।

उन्नीसवीं शताब्दी इन्हीं सब परस्परविरोधी विचार-धाराओं के बीच बढ़ती पनपती है। सहकारितावाद, अराजकवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद आदि अनेक भिन्न-भिन्न मतों और वादों का प्रतिपादन होता है। अर्थशास्त्र पर भी इनकी छाप पड़े बिना नहीं रहती।

और तभी उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में गांधी का प्रादुर्भाव होता है, जो होश संभालते ही कह उठता है कि पश्चिम के अर्थशास्त्र की बुनियाद ही गलत

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दृष्टि बिन्दुओं पर डाली गयी है, इसलिए वह अर्थशास्त्र नहीं 'अनर्थशास्त्र' है।

अदम स्मिथ और उसकी मान्यताएं

अदम स्मिथ ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा वाणिज्यवाद एवं प्रकृतिवाद के विचारकों की मान्यताओं का विश्लेषण किया, उन्हें सुव्यवस्थित रूप दिया एवं अपनी कल्पना का पुट देकर ऐसी मान्यताएं प्रस्थापित करने का प्रयत्न किया, जो कि अर्थशास्त्र की आधारशिला बन गयीं।

स्मिथ के विचारों का मनन और अनुशीलन पर्याप्त हुआ है। उनकी आलोचना भी हुई है। आधुनिक अर्थशास्त्री स्मिथ के प्रमुख विचारों के सम्बन्ध में इस प्रकार मत व्यक्त करते हैं।

स्मिथ का श्रम विभाजन उसकी मौलिक देन तो नहीं है, पर उसने उसे नया जामा पहनाकर सारी आर्थिक कार्यवाही का मूल आधार बना दिया है। उसकी दृष्टि यह है कि श्रम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समुचित स्थान मिलना ही चाहिए। उसके श्रम विभाजन के सिद्धांत से ही सब पर कर भार पड़ने की धारणा का उदय हुआ है। इसे परवर्ती अर्थशास्त्रियों ने ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर लिया है।

स्मिथ के मूल्य-सिद्धांत को भी परवर्ती विचारकों द्वारा पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। उसका उत्पादन-लागत सम्बन्धी सिद्धांत दोषपूर्ण माना जाता है। साम्य की धारणा उसके समक्ष स्पष्ट नहीं हो सकी थी। दोषपूर्ण होने पर भी कीमतों सम्बन्धी स्मिथ की धारणा बहुत प्रख्यात है। उसके श्रम-सिद्धान्त को परवर्ती समाजवादी विचारकों ने अपना एक अस्त्र ही बना डाला और इस अर्थ में स्मिथ को समाजवादी विचारधारा का पूर्वज भी कहा जा सकता है।

उत्पादन लागत सम्बन्धी सिद्धांत एक शताब्दी तक शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों में अपना अडिग स्थान बनाए रहा। बाद में आस्ट्रियन विचारकों के उपयोगिता सिद्धान्त ने उसका स्थान ग्रहण किया। उपयोगितागत मूल्य के संबंध में स्मिथ के विचार कुछ अधिक पुष्ट और परिष्कृत होते, तो मार्शल के पहले ही मूल्य सम्बन्धी स्पष्ट धारणा परिपक्व हो गयी होती।

सामान्यतः स्मिथ का वितरण का सिद्धांत भ्रमपूर्ण है। उसमें असंगतियां भरी पड़ी हैं। उसमें प्रकृतिवादी विचारधारा के दोष विद्यमान हैं। पर उसने परवर्ती विचारकों के विचार के लिए समुचित सामग्री प्रदान की, इस विशेषता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

उसके मजदूरी कोष का सिद्धान्त आगे के विचारकों ने तथा साधनों और जनसंख्या की परस्पर-निर्भरता का सिद्धान्त मैल्थस ने विकसित किया।

स्मिथ ने श्रम और पूंजी के विरोध में जो विचार प्रकट किए, वे आगे चलकर समाजवादी विचारकों की आधारशीलता बन गए।

अन्य बातों में स्मिथ आशावादी था, पर वितरण के सम्बन्ध में वह निराशावादी हो गया था। भू-स्वामियों और पूंजीपतियों की 'पराये' धन पर 'लक्ष्मी नारायण' की वृत्ति उसने समझ ली थी। इस विचार ने समाजवादियों को बड़ी प्रेरणा दी।

स्मिथ के कर-प्रणाली सम्बन्धी विचारों की महत्ता इसी से प्रकट है कि अर्थशास्त्रियों ने उसे यथावत् स्वीकार कर लिया है। लगान को उसने करों का एकमात्र वांछनीय साधन माना है। इस बात को अर्थशास्त्री गलत मानते हैं।

स्मिथ के स्वाभाविकतावाद का आगे चलकर जो विकास हुआ, उसको मनुष्य स्वार्थ का एकमात्र पुतला मान लिया गया, पर वस्तुतः स्मिथ की ऐसी धारणा नहीं थी। उसका तो केवल यही कहना था कि मनुष्य में स्वार्थ के अतिरिक्त भी अनेक वृत्तियां रहती हैं, पर उसके अधिकांश कार्य आर्थिक-स्वार्थ कीमूल प्रेरणा से प्रेरित होकर होते हैं।

यह सही है कि स्मिथ के विचारों में अनेक असंगतियां हैं और कितनी ही बातों में वह स्वयं अनिश्चित है कि कौन मार्ग ठीक-ठीक है कौन गलत, फिर भी अर्थशास्त्र में उसका अनुदान नगण्य नहीं। उसका स्थायी एवं व्यापक, प्रभाव इसका प्रमाण है। उसकी 'वेल्थ ऑफ नेशन्स' वह गंगोत्री है, जिसमें से परवर्ती अंग्रेजी और फारसीसी, जर्मन और अमेरिकन विचारधाराएं प्रस्फुटित एवं विकसित हुई हैं।*

---

* लेखक की आर्थिक विचारधारा के कुछ कुछ अंश। अ० भा० सर्व सेवा संघ वाराणसी द्वारा प्रकाशित।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत में इंजीनियरी उद्योग की प्रगति

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी, उपमंत्री इस्पात व भारी उद्योग

"इंजीनियरिंग उद्योग" को किसी परिभाषा में बांधना आसान बात नहीं है। इंजीनियरिंग उद्योग के अन्तर्गत एक छोटे से पुर्जे से लेकर रेलवे इंजन तक आ जाते हैं। उनके आकार में गांव के एक छोटे से लोहार की दुकान से लेकर मोटर गाड़ी के एक बड़े कारखाने तक का अन्तर है। इनमें सब प्रकार की धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर लोहा, इस्पात, अलुमिनियम, तांबा और मिश्रित धातुएं आदि। प्राचीन काल से ही धातुओं ने मनुष्य को प्रकृति पर विजय प्राप्त करने और उसे अपने काम के हेतु उपयोग करने में महत्वपूर्ण योग दिया है। शान्ति और युद्ध, हर दशा में, मनुष्य धातुओं का आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता रहा है। भारी इंजीनियरी उपकरण भी धातुओं के बने होते हैं, लेकिन यह वजन और आकार में बड़े होते हैं। उदाहरण के लिए इस्पात के कारखाने को ले लीजिए। इसमें धमन भट्टियां होती हैं, जिनकी ऊंचाई १०० फुट से अधिक, व्यास २५ फुट और वजन लगभग २००० टन होता है। यह इस्पात की मोटी प्लेटों को मोड़ कर और वैल्ड करके बनाई जाती हैं। इस्पात कारखाने की रोलिंग मिल को चलाने में बड़ी-बड़ी मोटरों का इस्तेमाल होता है, जिनकी शक्ति कई हजार हार्स पावर की होती है। इसमें बड़े-बड़े गियर होते हैं, जिनका वजन कई टन होता है।

बड़ी मशीनों की आवश्यकता

इस प्रकार के इंजीनियरी के बड़े-बड़े उपकरणों के निर्माण के लिए बड़ी मशीनों की आवश्यकता होती है। इनमें विपुल धनराशि लगानी पड़ती है। इनके लिए विशेष तकनीकी ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है। इस्पात, कोयले, सीमेंट उर्वरक, बिजली, जहाजी व अन्य फौजी सामान के लिए भी इंजीनियरिंग उद्योग बहुत जरूरी हैं। हमें यह सब बड़े कारखाने लगाने के लिए करोड़ों रुपये का सामान आयात करना पड़ता है। सन् १९५६-५७ में हमने लगभग २५३ करोड़, १९५७-५८ में ३१० करोड़,

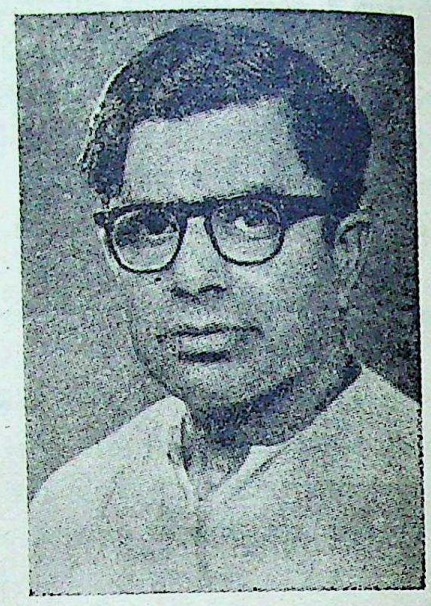

श्री सी० सुब्रह्मण्यम

१९५८-५९ में २४९ करोड़, १९५९-६० में २७९ करोड़ और १९६०-६१ में ३३२ करोड़ रुपये के विभिन्न प्रकार की मशीनरी और औजारों का आयात किया है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि मूल उद्योगों की उन्नति के लिए हम काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर रहे हैं। अतएव हमारे लिए यह लाजमी हो गया है कि हम इस बात पर विचार करें और इस दिशा में कदम उठाएं कि औद्योगिक विकास के लिए हमें मशीनों और इंजीनियरी उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। इसी दृष्टि से हमने इंजीनियरिंग उद्योग के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। ९ अप्रैल सन् १९६२ को राष्ट्रपति जी द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार भारी उद्योग विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में स्थानान्तरित किया गया और श्री सी० सुब्रह्मण्यम इस विभाग के मंत्री नियुक्त हुए। यह विभाग भारी उद्योगों की मशीनों के उपकरणों के नियंत्रण, विकास और नियमन के लिए पूर्णरूप से उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त यह विभाग

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्राच्य साहित्य के प्रकाशन में

राजस्थान सरकार का महत्त्वपूर्ण योग

राजस्थान प्राच्य विद्या के प्रतिष्ठान जोधपुर के सात संग्राह्य नये प्रकाशन

राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला—प्रधान सम्पादक : मुनि जिनविजय, पुरातत्त्वय

१. काव्य प्रकाश—भट्ट सोमेश्वर विरचित संकेत सहित। जैसलमेर ग्रन्थ भंडार से प्राप्त प्राचीनतम प्रति के आधार पर प्राध्यापक रसिकलाल छोपरिख द्वारा सम्पादित अन्यतम संस्करण (दो भागों में) मूल्य—प्रथम भाग १२.००, द्वितीय भाग ८.२५।

२. वस्तुरत्न कोष—अज्ञात कर्तृक नाना वस्तु प्रतिपादक विशिष्ट कोशग्रन्थ सम्पादिका—प्रियबाला शाह एम. ए., पी. एच. डी., डी. लिट्। मूल्य ४.००।

३. मुंहता नेणसी [सात भाग]—जोधपुर के प्रधानामात्य मुंहता नेणसी लिखित मूल भाषा में राजस्थान का इतिहास। सम्पादक—बदरीप्रसाद साकरिया। मूल्य ८.५० न. पै.।

४. भगतमाल—चारण ब्रह्मदास विरचित राजस्थानी काव्य मय भक्त चितरावली। सम्पादक उदयराज उज्ज्वल। मूल्य १.७५ न. पै.।

५. रघुवर जशप्रकाश—चारण कवि किशना जी आढ़ा निर्मित राजस्थानी भाषा में काव्य शास्त्र सम्बन्धित ग्रन्थ। सम्पादक—सीताराम लालस। मूल्य ८.२५ न. पै.।

६. राजस्थान हस्तलिखित—भाग १ मूल्य ४.५० न. पै.

ग्रन्थों की सूची :

७. राजस्थान प्राच्य-विद्या के प्रतिष्ठान के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची भाग—२ मूल्य १२.००।

प्राप्ति स्थान :

राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, रेजीडेंसी रोड, जोधपुर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सीमेंट, उर्वरक आदि अन्य वस्तुओं के भी विकास एवं नियत्रण के लिए उत्तरदायी है। किन्तु इन पंक्तियों का सम्बन्ध केवल इंजीनियरी उद्योग से है।

इंजीनियरी उद्योग की उल्लेखनीय प्रगति

पिछले वर्षों में वैसे तो सभी उद्योगों ने उत्पादन की नई सीमाएं कायम की हैं, किन्तु विशेष तौर पर मशीनी औजार, रेलवे वैगन, इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर, शुगर मिल मशीनरी, मोटर कारें और उसके सहायक उद्योगों और कनवेयरों के उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सन् १९६२-६३ में तेज रफ्तार के सेंट्रीफ्यूगल, हैवी ड्यूटी गीयर, शावल्स और बुल-डोजर्स जैसी मशीनों और उपकरणों का पहली बार इस देश में निर्माण हुआ। यह निःसंदेह है कि मशीन उद्योग का निर्माण और विकास ही विदेशी मुद्रा की कठिनाई को हल करने का एकमात्र दीर्घकालीन उपाय है। इस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में कई योजनाएं बनाई गई हैं, जिन से व्यापक पैमाने पर विभिन्न प्रकार की मशीनरी और उपकरणों का निर्माण किया जावेगा।

मशीनों का निर्माण

इस समय देश में कई प्रकार की मशीनरी का उत्पादन हो रहा है। मसलन, शक्कर मिल मशीनरी लगभग ६ करोड़ ४३ लाख रुपये कैमिकल मशीनरी लगभग ३ करोड़ ६७ लाख रुपये, चाय की पत्ती तैयार करने की मशीनरी लगभग १ करोड़ ६५ लाख रुपये, औद्योगिक बायलर लगभग २ करोड़ ६२ लाख रुपये, कृषि सम्बन्धी मशीनरी १ करोड़ ४२ लाख रुपये, सीमेंट मशीनरी ७१ लाख रुपये, टेक्सटाइल मशीनरी १४ करोड़ रुपये। जहां तक टेक्सटाइल (कपड़ा) मशीनरी का सम्बन्ध है, उसका उत्पादन सन् १९६३ में दुगना यानी २७ करोड़ के लगभग करने की योजना बनाई गई है और उसकी स्थापित क्षमता ४४ करोड़ रुपये प्रति वर्ष के लगभग है। इस समय हम देश में ५७,७४४ मोटर गाड़ियां, २५,००० स्कूटर मोटर साईकल आदि तैयार कर रहे हैं। इस समय कमर्शियल मोटर गाड़ियों के पुर्जों के भारतीय उत्पादन का औसत ७० प्रतिशत के करीब है और कार का लगभग ६० प्रतिशत के करीब है। आशा यह की जाती है कि यह औसत १९६४ के अन्त तक ९० प्रतिशत के लगभग पहुँच जाएगा। इसके अतिरिक्त कृषि में उपयोग होने वाले १०२७ ट्रैक्टरों का भी निर्माण हो रहा है। तृतीय पंच वर्षीय योजना के दौरान में स्पन पाइप, स्टील ट्यूब, तार, इलेक्ट्रोड, तार के रस्से और विभिन्न प्रकार की लोहे व इस्पात की ढलाई व गढ़ाई तथा इमारती धरन आदि की क्षमताएं निश्चित की गई हैं और उनको पूरा करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग उद्योग की और अन्य उद्योगों की स्थापना में इस तमाम चीजों का अत्यधिक महत्व है।

भारी उद्योग

मशीन उद्योग के निर्माण और विकास के साथ-साथ सन् १९६२-६३ में भारी उद्योगों के निर्माण में भी हमने प्रगति की है। रांची में रूसी सहायता से कारखाना स्थापित किया जा रहा है। इसमें आधुनिक इस्पात कारखाने के लिए समस्त साज सामान का निर्माण किया जा सकेगा। इसमें उर्वरक कारखाने में लगने वाली मशीनें व उपकरण भी बनाए जा सकेंगे। इसमें कोयले, तेल और दूसरे उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली बड़ी मशीनें भी बनाई जा सकेंगी। इस आयोजना पर लगभग १५० करोड़ रुपये व्यय होंगे। इसमें पूरे जोर शोर से काम हो रहा है और अगले वर्ष इसमें प्रारम्भिक स्तर पर उत्पादन होने लगेगा। अन्त में इस कारखाने में लगभग ८०,००० टन के वजन की भारी मशीनें तैयार होंगी, जिनका मूल्य ५० करोड़ रुपये होगा। यह संसार के बड़े कारखानों में से होगा। इसी प्रकार हम रांची में चेक सहायता से भारी मशीनी औजारों का भी एक कारखाना स्थापित कर रहे हैं।

कोयला उद्योग की मशीनें

हमारा कोयले का उत्पादन तृतीय पंचवर्षीय योजना में ४८४० लाख टन और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में २,००० लाख टन आंका गया है। इतना कोयला निकालने के लिए स्वाभाविक है कि हमें कोल माइनिंग (खान की) मशीनरी की बड़े पैमाने पर आवश्यकता होगी। अतएव रूसी मदद से और पौलैंड की सहायता से कोल माइनिंग मशीनरी के भी कारखाने स्थापित कर रहे हैं। इसके

(शेष पृष्ठ ४७५ पर)

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विकास के लिए विदेशी सहायता

श्री ग० ला० मेहता

भारत को विदेशों से मिलने वाली सहायता की मात्रा और उसका स्वरूप ।

निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी योजनाओं में विदेशी सहायता का उत्तरोत्तर योगदान बढ़ता रहा है :

तालिका १ : योजनाओं के लिए विदेशी सहायता
(करोड़ रुपयों में)

	पहली योजना[1]	दूसरी योजना[1]	तीसरी योजना[2]
१. कुल व्यवस्था	१,९६०	४,६००	७,५००
२. विदेशी सहायता	१८८	१,०९०	२,२००
३. औसत प्रतिशत (२:१)	१०	२४	२९
४. सीमान्त (मार्जिनल) प्रतिशत	—	३४	३८

इसमें ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी और तीसरी योजना के लिए बढ़ी हुई निर्धारित व्यय राशि का आधार आन्तरिक बचत में वृद्धि न होकर विदेशी सहायता ही है ।

सभी सूत्रों द्वारा अधिक सहायता देने की घोषणा करने से ही विदेशी सहायता पर निर्भरता सम्भव हो सकी है । यह बात निम्न तालिका से स्पष्ट है :

तालिका २ : अधिकृत विदेशी सहायता
(करोड़ रुपयों में)

	पहली योजना	दूसरी योजना	तीसरी योजना: प्रथम दो वर्ष	तीसरी योजना: वर्ष के लिए क्लब से सहायता
अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं	५७.३	२६२.७	२०२.६	११६.६
कनाडा	३२.३	७३.५	३३.४	१४.५
फ्रांस	—	—	२८.६	६.५
पश्चिम जर्मनी	—	१३६.०	१२६.१	४७.३
इटली	—	—	२५.६	२१.४
जापान	—	३५.५	४२.६	३०.६
ब्रिटेन	०.४	१२३.०	१२६.६	४०.०
अमरीका	२१३.६	१५२७.१	४६४.१	२०७.१
रूस	६४.७	३२०.२*	—	—
अन्य देश	१३.५	७४.२**	२६.४	१३.५
योग	३८१.८	२५५२.२	१०७६.३	५००.६#

निम्न तालिका से सहायता के उपयोग का पता चलता है :

तालिका ३ : विदेशी सहायता का उपयोग
(करोड़ रुपयों में)

	पहली योजना	दूसरी योजना	तीसरी योजना (प्रथम दो वर्ष)
अधिकृत	३८१.८	२५५२.२	१,०७६.३
कुल उपलब्ध	३८१.८	२७३२.३	२,३७८.९
प्रयुक्त राशि	२०१.७	१४२९.७	७८४.९
अवशिष्ट	१८०.१	१३०२.६	१,५९४.०

यह स्पष्ट है कि औसत सहायता, जो प्रथम योजना में प्रति वर्ष ७५ करोड़ रु० थी, बढ़ कर दूसरी योजना में ४५० करोड़ रु० से भी अधिक हो गई तथा तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में और भी बढ़ कर ६०० करोड़ रु० हो गई ।

१ वास्तविक
२ योजना

* इसमें तीसरी योजना के लिए निर्धारित २३८.१ करोड़ रु० की राशि शामिल है ।

** तीसरी योजना के लिए निर्धारित ४२.१ करोड़ रु० की राशि सहित ।

+ सहायता क्लब से बाहर के देशों से २८.६ करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मार्च १९६३ तक ४,०१०.३ करोड़ रु० की कुल अधिकृत सहायता राशि में से २९७.४ करोड़ रु० अनुदान के रूप में, २,५२१.९ करोड़ रु० ऋण के रूप में हैं और शेष राशि सहायता के अन्य रूपों में है। बाद की राशि को हमें वापिस करना है। वास्तविकता यह है कि हमें चालू रखने के व्यय में प्रति वर्ष पहले ही १०० करोड़ रु० व्यय करना पड़ रहा है। अतः ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि इस सहायता राशि का उपयोग इस प्रकार किया जाए, जिससे हमारी उत्पादन और ऋण अदायगी दोनों की क्षमता बढ़े।

विदेशी मुद्रा की स्थिति

हम अपनी मुद्रा को मजबूत करने के लिए न्यूनतम आवश्यक राशि को छोड़ कर अपने सारे विदेशी मुद्रा कोष को खर्च कर चुके हैं और अर्थ-व्यवस्था के लिए आवश्यक वार्षिक विदेशी मुद्रा के लिए हम पूर्णतः निर्यात और विदेशी सहायता पर निर्भर करते हैं। यह आवश्यकता भी प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। प्रथम, हमने जो अनेक कारखाने खोल दिए हैं, उनके रख-रखाव के लिए हमारा आयात भी बढ़ गया है। उपभोक्ता सामग्री के आयात को न्यूनतम करने के बाद भी रख-रखाव के लिए हमारी आयात आवश्यकता प्रति वर्ष ७०० करोड़ रु० की है। तीसरी योजना के लिए यही स्तर निश्चित किया गया है। योजना के प्रारम्भ होने के समय आयात की दर से यह काफी ऊंचा है और यदि केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही आयात करने की खुली छूट दी जाए, तब यह और भी अधिक हो जाएगा। दूसरे, जैसे-जैसे योजनाएं आकार-प्रकार में बड़ी होती जाएंगी, वैसे-वैसे उनके आयात की वस्तुएं भी आनुपातिक रूप से बढ़ जाएंगी। यह बात तालिका १ में दिए गए मार्जिनल रेट के आंकड़ों से स्पष्ट है। इस समय मशीनी सामान के लिए हमारी आवश्यकताएं ५०० करोड़ रु० प्रति वर्ष है। इन आवश्यकताओं के विपरीत, जो घटने के स्थान पर बढ़ती ही जाएंगी, हमारा निर्यात अनेक प्रोत्साहनों व नियन्त्रणों के बाद भी कई वर्षों से जहां का तहां लगभग ६१० करोड़ रुपए का है। आयात-निर्यात के इस अन्तर को अन्य देशों की उदार सहायता के द्वारा ही पूरा किया जा रहा है।

सहायता की शर्तें

गत कुछ वर्षों में विदेशी सहायता और उसके पीछे निहित विचारधारा में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। इन परिवर्तनों में दो का भारत से सम्बन्ध है: (अ) अर्द्ध-विकसित देशों के सामने उपस्थित विशाल समस्या को देखते हुए विदेशी सहायता की शर्तों को काफी नरम कर दिया गया है, यद्यपि हाल ही में अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने दो प्रतिशत ब्याज लेने का जो निर्णय किया है वह चिन्ताजनक है। अब यह एक स्वीकृत सी परम्परा बन गई है कि ३० से ५० वर्ष तक के लिए ऋण दिया जाए और इस पर सूद न लेकर केवल एक प्रतिशत वार्षिक सेवाव्यय लिया जाए। अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण तथा विश्व बैंक से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने इन्हीं शर्तों पर धन प्रदान किया है। इसी बात को देखते हुए अन्य देशों ने भी अपने ऋणों की शर्तों को ढीला कर दिया है। (आ) दूसरे, विदेशी सहायता को अधिकाधिक राशि की निश्चित परियोजना से बांधा नहीं गया है, यद्यपि यह ठीक है कि इस अधिकांश राशि का प्रयोग दाता देश से ही माल खरीदने की शर्त रखी जाती है।

ये दोनों ही बातें भारत के लिए विशेष महत्व की हैं, क्योंकि भारत की विदेशी मुद्रा विनिमय के जहां वायदे बढ़ गए हैं, वहां उसकी मूलधन और सूद को चुकाने का दायित्व भी बढ़ गया है, जैसे ऊपर बताया गया है। यह प्रतिवर्ष १०० करोड़ रुपए से भी अधिक है। इस प्रकार हमें अपने पिछले वायदों की पूर्ति के लिए अपने १५ प्रतिशत निर्यात और २० प्रतिशत विदेशी सहायता की राशि को दे देना पड़ता है। सहायता की संशोधित शर्तों की विशेषता यह है कि इनसे ऋणों की लौटाई जाने वाली कुल राशि में एकदम कमी हो जाती है, क्योंकि लम्बी अवधि तक का ऋण होने के कारण इस पर दिए जाने वाले मूलधन और सूद की राशि बहुत कम हो जाती है। इस समय भारत के सामने स्थापित उद्योगों को पूरी क्षमता से चलाने की समस्या है। बिना किसी परियोजना से बंधी राशियां रख-रखाव की वस्तुएं आयात करने में बड़ी सहायक हैं।

चुनौती

दूसरे देश हमारे प्रति चाहे कितने मैत्रीपूर्ण और

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उदार क्यों न हों, हमें अपनी व्यवस्था को ठीक रखना चाहिए और उनकी उदारता का कम से-कम लाभ उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। न केवल औचित्य की दृष्टि से, अपितु अपने हित में भी यह आवश्यक है।

इसके कारण स्पष्ट हैं। पहला, जैसा कि तालिका २ में दिखाया गया है, भारत को मिलने वाली वार्षिक विदेशी सहायता ६०० करोड़ रु० हो गई है। इस वर्ष की बातचीत से स्पष्ट है कि इसमें और अधिक वृद्धि की आशा अबुद्धिमत्तापूर्ण होगी। भविष्य में जैसी कि आशा है, हमारी योजनाएं अधिकाधिक विशाल होती जाएंगी। उनके साथ ही हमारी विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं भी बढ़ जाएंगी। इसलिए यह जरूरी है कि अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं हम स्वयं अपना निर्यात बढ़ा कर पूरी करें। यह एक ऐसी चुनौती है जिसको हम टाल या दरगुजर नहीं कर सकते।

इसके साथ ही इस समय मिलने वाली विदेशी सहायता का कुछ भाग परियोजनाओं से बंधा नहीं है। दूसरे शब्दों में हम अपनी चालू परियोजनाओं के रख-रखाव के लिए निर्यात की आवश्यकताएं इस राशि में से ही पूरी करते हैं। अतः यह बात हमारी भावी उत्पादन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं करती है। यह एक ऐसी स्थिति है, जिसे हम अपने भावी भुगतान-सन्तुलन की स्थिति को खतरे में डाले बिना स्वीकार नहीं कर सकते।

यदि हम अपने रख-रखाव सम्बन्धी आयात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा इसके साथ ही वर्तमान स्तर से भी अधिक मशीनी सामान के आयात के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा को स्वयं जुटाने का लक्ष्य सामने रखते हैं, तो अपने विदेशी मुद्रा कोष को बढ़ाने का लक्ष्य भी हमें तय करना जरूरी है। गत पांच वर्षों में विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में हमारी स्थिति बड़ी कमजोर रही है तथा हम उचित समय में कम खर्च में माल आयात करने की क्षमता खो बैठे हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक ऐसी परियोजना को प्रारम्भ करने के लिए जिसमें कि माल को आयात करना आवश्यक है, सहायता देने वाले देश से अनुमति लेनी पड़ती है—चाहे वह परियोजना हमारी अर्थ-व्यवस्था के लिए कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों न हो।

हमारी स्वतंत्रता

हम विदेशी सहायता पर बहुत और अत्यधिक निर्भर हो गए हैं और इस प्रक्रिया में बहुत हद तक स्वयं योजना बनाने और धन को स्वेच्छा से खर्च करने की स्वतन्त्रता भी खो बैठे हैं। अर्थ-व्यवस्था के लिए विदेशी सहायता एक अस्थायी उपादान है तथा दीर्घकालीन आयोजन का स्थायी आधार नहीं है। हमें यह समझ लेना है कि विदेशी सहायता आत्म-निर्भरता का विकल्प नहीं हो सकती। ●

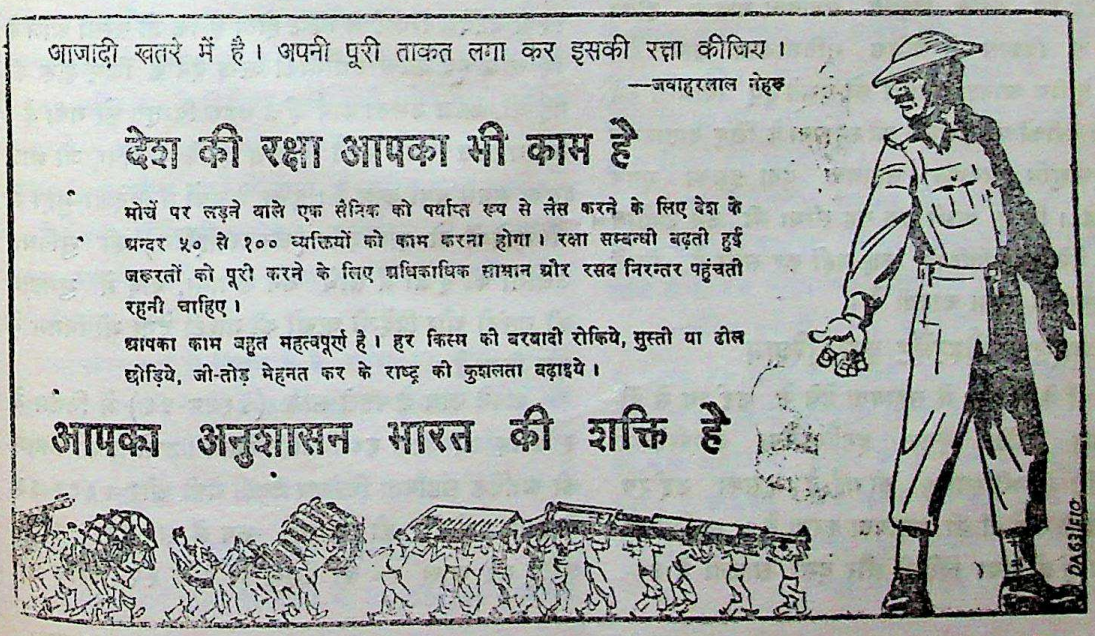

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उद्योगों की विपुल सहायता : नई वित्तीय संस्थाएं

देश में नये उद्योगों को प्रोत्साहन व सुविधा देने के लिए सरकार ने केन्द्र व राज्य स्तर पर अनेक वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की है। ये सभी संस्थाएं स्वतन्त्र सत्ता रखती हैं। इनका उद्देश्य उद्योगों को लम्बी अवधि के लिए वित्तीय सहायता देना है। इनमें सबसे पुरानी संस्था उद्योग वित्त निगम है, जिसकी स्थापना १५ वर्ष पूर्व हुई थी। इसको सहायता देने का क्षेत्र सीमित था, इसलिए अन्य भी अनेक संस्थाएं स्थापित की गईं, ताकि उद्योगों को नई प्रेरणा व सहायता मिल सके। उद्योग वित्त-निगम बड़े उद्योगों को अखिल देशीय स्तर पर सहायता देता था। इसलिए राज्यीय वित्त निगम स्थापित किये गये। उनका उद्देश्य छोटे व मध्यम उद्योगों को अपने अपने क्षेत्र में सहायता देना है। इन राज्यीय निगमों का कार्य बहुत सन्तोषजनक नहीं हुआ, इसलिए रिजर्व बैंक इन्हें अधिक गतिशील बनाने के लिए कुछ कदम उठाने पर विचार कर रहा है।

नें. इ. डि. कारपोरेशन

एक नई संस्था नेशनल इण्डस्ट्रियल डिवेलपमैण्ट कारपोरेशन (NIDC) की स्थापना भी की गई है। इसका उद्देश्य केवल वित्तीय सहायता मात्र न होकर उद्योगों के विकास में अधिक गतिशीलता लाना है। अखिल देशीय आवश्यकताओं को देखते हुए विभिन्न नये तकनीकी तरीकों पर उद्योगों की स्थापना के लिए वातावरण और पृष्ठभूमि बनाकर सहायता देना इसका मुख्य उद्देश्य है। किन्तु अभी तक यह संस्था भी उन उद्योगों को ऋण देने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकी है, जिन्हें सरकार स्थापित करना चाहती है।

क्रैडिट एण्ड इनवैस्टमैंट कारपोरेशन

उद्योगों के विकास में सहायता देने के उद्देश्य से ही इण्डस्ट्रियल क्रैडिट एण्ड इनवैस्टमैण्ट कारपोरेशन (ICICI) की भी स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के उद्योगों की सहायता करना है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों तथा विदेशी और देशी साधनों के उपयोग में समन्वय और तालमेल रखना इसका मुख्य कार्य है। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में यह एक महान् परीक्षण है।

पुनर्वित्तीय निगम

उद्योगों को वित्तीय सहायता की दिशा में एक नई संस्था पुनर्वित्तीय निगम या रिफाइनैंस कारपोरेशन है। यह बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को इसलिए रुपया देता है, ताकि उद्योगों को मध्यम या दीर्घ अवधि के लिए ऋण दे सके। निर्यात व्यापार को बढ़ाने के लिए भी यह निगम सहायता करता है।

लघु उद्योग को तरह तरह की सहायता देने के लिए नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन बनाया गया है। यह वस्तुत: एक विकास बैंक है, जो लघु उद्योगों की पूंजी में भी भाग लेता है।

उद्योग वित्त निगम

इन सब संस्थाओं में सबसे पुरानी और शिरोमणि संस्था उद्योग वित्त निगम है। इसने अपना कार्य क्षेत्र का बहुत विस्तार कर लिया है।

भारतीय उद्योग वित्त निगम की हाल में प्रकाशित १५वीं वार्षिक रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि जो संस्था आज से १५ साल पूर्व केवल उद्योगोंको ऋण देने के लिए शुरू की गई थी, आज उसका कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। उद्योग वित्त निगम रुपये में ऋण देने के अलावा, जो आज इसका सबसे बड़ा काम है। इधर के वर्षों में विदेशी-मुद्रा में भी उद्योगों को हामीदारी (अण्डरराइटिंग) की सुविधा, उद्योगों की पूंजी में सीधे धन लगाना, बाद में भुगतान की गारंटी और विदेशी ऋणों की गारंटी देना भी निगम ने शुरू किया है।

अपने काम के पहले साल (१९४८-४९) में निगम ने ३ करोड़ २५ लाख रु० वितरित किया। उद्योगों को निगम की आर्थिक सहायता निरन्तर बढ़ती गयी और १९६२-६३ में उसने उद्योगों को विभिन्न रूप में, सहायता में ३९ करोड़ ८९ लाख रु० की मंजूरी दी और २२ करोड़ ४३

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लाख रु० बांटा। अब तक निगम १ अरब ६४ करोड़ ३३ लाख रु० की सहायता की मंजूरी दे चुका है और इस राशि में से १ अरब २ करोड़ ५७ लाख रु० दिया जा चुका है।

भारतीय और विदेशी मुद्राओं में ऋण

१९६२-६३ में रुपये और विदेशी मुद्राओं में २२ करोड़ ६१ लाख रु० के ऋण मंजूर किये गये, जबकि पिछले साल इन ऋणों की राशि १९ करोड़ १५ लाख रु० थी। आलोच्य वर्ष में १४ करोड़ १२ लाख रु० और इससे पिछले वर्ष १० करोड़ ७८ लाख रु० ऋण में दिया गया। आलोच्य वर्ष में १८ आवेदकों को ३ करोड़ ४ लाख रु० के विदेशी-मुद्रा के ऋण दिये गये।

हामीदारी

३ करोड़ ३७ लाख रु० की हामीदारी (अण्डरराइटिंग) के १८ प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। वर्ष के अन्त में ६ करोड़ ३४ लाख रु० की हामीदारी की २५ अर्जियां विचाराधीन थीं। आलोच्य वर्ष में आयल इंडिया लि० के विस्तार कार्यक्रमों के लिये आवश्यक धन के लिये १९६६-६७ के ६॥ प्रतिशत के जो डिबेंचर जारी किये गये निगम ने उनके लिए हामीदारी दी। यह हामीदारी बहुत महत्व-पूर्ण है और अब तक किसी एक कम्पनी ने इतने अधिक डिबेंचर भारतीय बाजार में जारी नहीं किये। आयल इंडिया लि० ने ३० करोड़ रु० की पूंजी जारी की, जिसमें से १७॥ करोड़ रु० के डिबेंचर जारी किये गये। उद्योग वित्त निगम ने १ करोड़ ६८ लाख रु० के डिबेंचर शेयरों की हामीदारी दी और इसके अलावा १ करोड़ ८२ लाख रु० के डिबेंचर सीधे भी खरीदे। आलोच्य वर्ष के अन्त में निगम कुल ७ करोड़ ६६ लाख रु० की पूंजी की हामी-दारी दे चुका था।

आलोच्य वर्ष में निगम ने ३ करोड़ ३५ लाख रु० के बाद में भुगतान के आठ प्रस्तावों को मंजूरी दी। कोई भी अर्जी नामंजूर नहीं की गयी। यह गारण्टी देश और विदेशों में खरीदी जाने वाली मशीनों के लिये हैं।

विदेशी-मुद्रा के ऋणों की गारंटी

विदेशी बैंकों और संस्थाओं से विदेशी-मुद्रा के ऋणों की गारंटी की तीन अर्जियों में से निगम ने दो को मंजूरी दी। निगम ने कुल ८ करोड़ ९९ लाख रु० के ऋणों की गारंटी दी।

आलोच्य वर्ष के अन्त तक उद्योग सहकारियों को कुल ३६ करोड़ ८६ लाख रु० के ऋणों की मंजूरी दी गयी। यह मंजूरी ५० सहकारी चीनी कारखानों, तीन सहकारी कताई कारखानों और वनस्पति बनाने वाले एक सहकारी कारखाने को दी गयी। इन सहकारी उद्योगों को जो सहा-यता मंजूर की गयी, वह निगम द्वारा स्वीकृत कुल सहायता का लगभग २२ प्रतिशत है। इससे स्पष्ट होता है कि निगम सहकारी क्षेत्र को आर्थिक सहायता में कितनी ऊंची प्राथ-मिकता देता है। ११ राज्यों की सहकारियों को निगम ने सहायता दी। महाराष्ट्र की २१ सहकारियों को, मद्रास की ६ सहकारियों को, आन्ध्र प्रदेश की ५ सहकारियों को और पंजाब की ५ सहकारियों को यह सहायता दी गयी।

साधन

निगम बाण्ड जारी करके, रिजर्व बैंक आफ इंडिया और केन्द्रीय सरकार से तथा विदेशी-मुद्रा में ऋण लेकर अपने आर्थिक साधन जुटाता है। ये निगम की अपनी चुकता-पूंजी की संरक्षित निधि और अधिशेष (सरप्लस) के अलावा हैं। वर्ष के अन्त तक में निगम के पास कुल ८७ करोड़ ७९ लाख रु० था। आलोच्य वर्ष के अन्त में निगम द्वारा जारी कुल बाण्डों की राशि २८ करोड़ २४ लाख रु० थी। जनवरी १९६३ में निगम ने बाण्डों की व्यवस्था का काम अपने हाथ में ले लिया। अब तक यह काम रिजर्व बैंक करता था।

निगम ने केन्द्रीय सरकार से ५ करोड़ रु० लिया। वर्ष के अन्त में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत ऋणों की राशि में से २४ करोड़ ७५ लाख रु० की राशि शेष थी।

आलोच्य वर्ष में निगम को पश्चिम जर्मनी की मुद्रा २ करोड़ ५० लाख डी० मार्क का ऋण मिला। निगम ने फ्रांस व जापान से भी ऋण लिया है। इस वर्ष कारपोरेशन को कुल आमदनी ३.९६ करोड़ रु० की हुई। ऋण का ब्याज निकालकर १.६८ करोड़ रु० और टैक्स निकालकर ८२.६७ लाख रु० बचत रही। गत वर्ष यह लाभ ७१.८८

(शेष पृष्ठ ४६६ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विशेष महत्व की बातें

प्रत्येक विचारशील भारतीय के लिए यहां दी गई बातें विशेष महत्व की हैं। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए, बहुत जरूरी हैं क्योंकि राष्ट्र का भविष्य बहुत कुछ इस पर ही निर्भर करता है कि चीनी आक्रमण से देश की रक्षा किस तरह की जाय। हमारा देश एक शांति प्रिय राष्ट्र है और हम शांति प्रिय लोग हैं। पर हम आक्रमण के सम्मुख कभी घुटने नहीं टेक सकते।

चीनी खतरा

सच्चाई यह है कि हमारी सीमाओं पर चीनी आक्रमण अब भी बना हुआ है, हलांकि वास्तविक लड़ाई बन्द है। चीन अब भी लद्दाख में भारतीय प्रदेश का १४,००० वर्ग-मील क्षेत्र दबाये हुए है तथा वह हमारी सीमाओं पर बड़े पैमाने पर सेनायें इकट्ठी कर रहा है। हमें प्रत्येक नये आक्रमण का मुकाबला करने के लिए तैयार होना है। हमें अपनी यह प्रतिज्ञा फिर से दुहरानी है कि जब तक हम अपनी धरती से एक एक आक्रमणकारी को पूरी तरह न खदेड़ दें, तब तक चैन नही लेंगे।

अनुपम सहयोग

जब हमारे प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय रक्षा कोष में मदद देने के लिए जनता से अपील की तो सभी वर्गों के लोगों ने बड़े शानदार ढंग से उस अपील का जवाब दिया।

हमने उदारता से दिया—दिल खोल कर दिया—क्योंकि हम समझते थे कि आज़ादी की रक्षा के लिए कोई भी कुर्बानी ज्यादा नहीं है।

दृढ़ संकल्प

हमें इस बात का दृढ़ संकल्प करना है कि हम इसी प्रकार मदद देते रहेंगे, जब तक कि हमारी आज़ादी को खतरा खत्म नहीं हो जाता। हम सबको सोना देना है। क्योंकि आज के ये स्वर्ण कंगन क्या काम आएंगे, यदि कल हम सब लौह शृङ्खलाओं में जकड़ लिये जाते हैं। हमें रुपया भी देना है। क्योंकि हमारे निरंतर योगदान से ही हमारी प्रतिरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहयोग मिलेगा।

हमें क्यों देना चाहिए ?

१—क्योंकि इससे आप और आपकी संतान के भविष्य की रक्षा होती है।

२—क्योंकि इससे आपकी मातृभूमि की प्रादेशिक अखण्डता सुरक्षित होती है।

३—क्योंकि इससे भारत में और संसार भर में शांति कायम रह सकती है।

इन सवालों पर विचार कीजिए

क्या हम अपने सम्मान को खतरे में देख कर भी अपने कर्तव्य से विमुख होंगे ? क्या हम चाहेंगे कि शूरमा जवान हमारे लिए बलिदान करते रहें और हम उनकी शक्ति नहीं बढ़ायें ? क्या हम आज स्वार्थी बन कर उन सब चीजों को, उन आदर्शों को खतरे में डाल देंगे जिन्हें हम बहुत मूल्यवान समझते हैं, प्यार करते हैं ? क्या हम स्वदेश से पहले स्वार्थ, साहस से पहले लालच और स्वतंत्रता से पहले सम्पत्ति को ज्यादा महत्व देंगे ?

खूब विचार कीजिए

राष्ट्र की तैयारी में हाथ बटाइए

DA63/P.14

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१३ वर्षों में १२ अरब रु० :

कोलम्बो योजना पर एक दृष्टि

कोलम्बो योजना की सलाहकार समिति की १५ वीं बैठक बैंकाक में ३० अक्तूबर से प्रारम्भ हो गई है, जो १५ नवम्बर तक चलेगी। यह समिति कोलम्बो योजना की सर्वोच्च संस्था है। दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया का आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से १३ वर्ष पूर्व कोलम्बो योजना का जन्म हुआ था।

जनवरी, १९५० में राष्ट्रमण्डल देशों के विदेश मन्त्रियों की एक बैठक हुई थी, जिसमें विश्व की समस्याओं और खास कर दक्षिण व दक्षिण-पूर्व एशिया की जरूरतों पर विचार किया गया। इसी बैठक में कोलम्बो योजना का जन्म हुआ। इस क्षेत्र की जरूरतों का सर्वेक्षण करने, साधनों का अनुमान लगाने, यहां के विकास की समस्याओं पर विश्व का ध्यान आकर्षित करने और इस क्षेत्र के लोगों का रहन-सहन सुधारने में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की नींव डालने के लिए सलाहकार समिति की स्थापना की गई। समय-समय पर इसकी बैठकें होती रहती हैं।

शुरू में आस्ट्रेलिया, कनाडा, श्रीलंका, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंग्लैंड, मलय और ब्रिटिश बोर्नियो इसके सदस्य थे। सिडनी में मई, १९५० में इसकी पहली बैठक में यह निश्चय किया गया कि इस क्षेत्र में पड़ने वाले राष्ट्र-मंडलीय देश १ जुलाई, १९५१ से ६ वर्ष की अवधि के लिए विकास कार्यक्रम बनाएं तथा दूसरे देशों से भी ऐसा करने के लिए कहा जाए। अमेरिका व जापान भी इसके सदस्य हो गये हैं। पिछले साल कोरिया गणराज्य और भूटान को भी कोलम्बो योजना में शामिल किया गया। बर्मा, नैपाल, कम्बोडिया, वीतनाम, इण्डोनीशिया और थाईदेश पिछले वर्षों में शामिल हो चुके थे।

इस योजना के अन्तर्गत सहायता देने वाले और लेने वाले देशों के बीच सीधे बातचीत होती है, किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की मार्फत नहीं। इस प्रकार किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं होता और आपसी वार्तालाप द्वारा बिना विलम्ब काम चलता रहता है। सलाहकार समिति और दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में शिल्पिक सहयोग की कोलम्बो योजना परिषद् में आपसी विचार-विमर्श द्वारा सामूहिक दृष्टिकोण से इस योजना पर विचार होता है।

प्रगति

दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के आर्थिक विकास में कोलम्बो योजना के अन्तर्गत पिछले १३ वर्षों से सहायता मिल रही है। इससे इस क्षेत्र की कई समस्याएं सुलझी हैं और यहां की काया पलटी है। सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में बताया गया था:—

"काफी लम्बे समय से एशिया के लोग गरीब और भूख के शिकार रहे हैं। यहां के देशों को स्वतन्त्रता मिलने के बाद भी यह स्थिति नहीं सुधरी है, किन्तु जनता का रहन-सहन सुधारने की समस्या पर नये ढंग से विचार अवश्य होने लगा है और प्रत्येक देश अपने आर्थिक विकास की योजनाएं बना रहा है। इससे जनता की आशाएं और इच्छाएं बढ़ गई हैं।"

"दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में जितनी तेजी से राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, उतने विश्व के इतिहास में देखने को नहीं मिलते। यहां के देश स्वतन्त्र हुए, जनतांत्रिक सरकारें बनीं और विकास कार्यक्रम चलाने का जोश पैदा हुआ। इन सरकारों का आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण विस्तृत हुआ है और वे आर्थिक विकास की समस्याएं सुलझा रही हैं, जो सामाजिक स्थिति और स्वतन्त्रता को दृढ़ करने के लिए आवश्यक है। इस क्षेत्र की ही नहीं बल्कि विश्व की राजनीतिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए भी यह जरूरी ही है कि इन सरकारों के प्रयत्न सफल बनाये जाएं।"

"इस क्षेत्र के देशों का, विश्व की अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। यहां होने वाला अनाज और कच्चा माल विश्वभर के विकसित देशों में उपयोग में आता है। विश्व युद्ध से पहले यह क्षेत्र दुनिया भर की जूट और रबड़ की लगभग सारी चाय की तीन चौथाई से भी ज्यादा, टीन की दो तिहाई और तेल की दो तिहाई और तेल तथा चर्बी की एक तिहाई जरूरतें पूरी करता था। रबड़, टीन और जूट पश्चिमी देशों को यहीं से निर्यात होता है। यहां से चाय और तेल यूरोप को जाते हैं। इसके बदले में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पश्चिमी देशों से कपड़ा, मशीनें, लोहा और इस्पात आदि मिलता है।"

इस पहली रिपोर्ट में जिन समस्याओं का जिक्र है, उनमें से अनेक इन १३ वर्षों में सुलझाई जा चुकी हैं। कोलम्बो योजना के सहयोग से इस क्षेत्र में अनेक नये बांध और कारखाने बनाए जा रहे हैं, लाखों करोड़ों एकड़ जमीन की सिंचाई होने लगी है और हजारों स्कूल व अस्पताल खुल रहे हैं। इन १३ वर्षों में कुल १२ अरब डालर की सहायता मिल चुकी है। सहायता देने वाले देशों से ७ हजार से भी अधिक शिल्पिक इस क्षेत्र के देशों में काम कर चुके हैं और सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र में अनेक शिल्पिकों और प्रशासकों को उत्पादन के आधुनिक तरीके सिखाये जा चुके हैं। ३१ हजार से भी अधिक छात्रों को उच्च अध्ययन के लिए वृत्तियां दी जा चुकी हैं।

इस सम्पूर्ण क्षेत्र में दुनिया की एक चौथाई आबादी रहती है, जबकि इसका क्षेत्रफल संसार के कुल भूभाग का केवल छठा भाग है।

आपसी सहयोग

इस योजना की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अब इस क्षेत्र के देश एक दूसरे को स्वयं भी सहायता देने लगे हैं। इससे एशियाई देशों में आपसी सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा। पिछले साल मेलबोर्न में इस सलाहकार समिति ने अपने आगे के काम को इस प्रकार व्यक्त किया :—

"कोलम्बो योजना की सार्थकता सिद्ध हो चुकी है और इसीलिए इसकी अवधि बढ़ाई गई है। हाल में इसकी अवधि १९६६ तक बढ़ाई गई और १९६४ में सलाहकार समिति की बैठक में इसे और बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में १९६० से १९७० तक की अवधि को विकास की 'संयुक्त राष्ट्र दशाब्दी' के रूप में मनाने का निश्चय किया और अब अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसी ओर काम कर रही हैं। कोलम्बो योजना के देश इस महत्त्वपूर्ण कार्य के प्रवर्तकों में गिने जा सकते हैं। आज विश्वभर में यह विचार और प्रबल होता जा रहा है कि अनेक देशों के विकास के लिए दशाब्दियों के प्रयत्न की जरूरत है। इस महान कार्य में कोलम्बो योजना क्या योग दे सकती है?

बैंकाक में इस बैठक में इस क्षेत्र की समस्याओं का फिर से मूल्यांकन किया जा रहा है, ताकि जो देश एशिया के सुखद भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, उनमें नया दृष्टिकोण पैदा हो और वे आपसी सहयोग की भावना से ही काम करें।

(पृष्ठ ४६३ का शेष)

लाख रु० था। पिछले ५ वर्षों में इसकी आय दुगनी हो गई है।

निगम ने आलोच्य वर्ष में जो ऋण दिये, उनका उद्योगवार ब्यौरा इस प्रकार है :

चीनी	६ करोड़ ५ लाख रु०
कपड़ा	६ करोड़ १३ लाख रु०
नकशी रेशा	३१ लाख रु०
कागज	१ करोड़ ७७ लाख रु०
रबड़	५० लाख रु०
मूल औद्योगिक रसायन	४ करोड़ ३९ लाख रु०
विविध रसायन	८७ लाख ३३ हजार रु०
कांच	८ लाख रु०
चीनी-मिट्टी क बर्तन	१० लाख रु०
सीमेंट	१५ लाख रु०
लोहा और इस्पात	१ करोड़ ६० लाख रु०
अलौह धातु	६ करोड़ ७७ लाख रु०
धातु का सामान	२ करोड़ ६५ लाख रु०
मशीन	१ करोड़ ३२ लाख
बिजली की मशीनें तथा सामान	१ करोड़ ३ लाख रु०
मोटर गाड़ियां और पुर्जे	१ करोड़ ४९ लाख रु०
साइकिलें	११ लाख रु०
खान और खनन : (क) कोयला	५० लाख रु०
(ख) पेट्रोल और प्राकृत गैस	३ करोड़ ५० लाख रु०
योग	८० लाख ५० हजार रु०
कुल योग :	४० करोड़ १४ लाख रु०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समुद्रों का खारा पानी पेय

अणु-शक्ति व पेयजल की समस्या

• अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अमेरिका की पेय जल-सम्बन्धी आवश्यकताएं १९७५ तक ही इतनी बढ़ जायेंगी कि कोलोराडो नदी जैसी ७ नदियों का दैनिक जलोत्पादन भी उसकी पूर्ति करने में अपर्याप्त सिद्ध होगा। जहां तक शेष संसार का सम्बन्ध है, संयुक्तराष्ट्र-संघ से सम्बद्ध १०० नव-विकासोन्मुख देशों में से कम से कम ६० देशों को किसी न किसी रूप में पानी के अभाव का सामना करना पड़ेगा, जिसे अन्ततोगत्वा अ-परम्परागत साधनों, अर्थात् खारे कुएं और समुद्र से, पूरा किया जा सकेगा।

यह प्रकृति की विडम्बना है कि संसार में पानी के असीम स्रोत उपलब्ध होने पर भी, अधिकांश जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह नमकीन, अपेय और खेती तथा उद्योग के लिए व्यर्थ है। मीठे पानी के स्रोत न केवल थोड़े हैं, बल्कि अत्यन्त असमान रूप से वितरित भी हैं।

उद्योग या कृषि की दृष्टि से बहुत से विकसित देश जल-स्रोतों का सीमा से अधिक उपयोग करने लगे हैं। यदि यही स्थिति बहुत समय तक जारी रही, तो न केवल उनके विकास की दर घटेगी, बल्कि जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ-साथ, लोगों के रहन-सहन का स्तर भी गिर जायगा। अतः इन राष्ट्रों को भी अन्ततः पेय जल के लिए समुद्रों की ओर जाना पड़ेगा। कुछ का विचार है कि २० वर्ष के भीतर स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो जायगी। दूसरे वैज्ञानिक भी हैं, जिनका विचार यह है कि पानी का अभाव और भी पहले, जैसे १० वर्ष में, प्रारम्भ हो जायगा।

अणु-शक्ति पेय जल के अभाव को दूर करेगी

किन्तु क्या मनुष्य समुद्र के खारे पानी को व्यावहारिक और सस्ते ढंग पर पेय जल में परिणत करने सम्बन्धी अपने युगों पुराने स्वप्न को कभी साकार कर सकेगा? इस प्रश्न का उत्तर अब भ्रामक या अनिश्चित नहीं रह गया है। आजकल खारे जल को मीठे पानी में परिणत करने के मार्ग में कोई प्रमुख प्राविधिक समस्या नहीं रह गयी है। सच तो यह है कि इस प्रकार की समस्या कभी भी नहीं रही। सदियों से छोटे पैमाने पर इस प्रकार के खारे पानी को मीठे पानी में परिवर्तित किया जाता रहा है। अरस्तू ने बहुत पहले, ईसा से ३५० वर्ष पूर्व, इस दिशा में यूनान में किये गये प्रयोगों का उल्लेख किया है।

विश्व-व्यापी आधार पर खारे पानी को क्षार-रहित बनाने के मार्ग में मुख्य बाधा लागत की है, जो इस समय इतनी ऊंची है कि आर्थिक दृष्टि से ऐसा करना उपादेय नहीं। यह लागत भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न है। अमेरिका में इस लागत का औसत प्रति हजार गैलन ५ रुपये है, जबकि प्राकृतिक साधनों से पेय जल की पूर्ति की औसत लागत १ रुपये से लेकर १॥ रुपये तक पड़ती है।

जहां तक मात्रा का सम्बन्ध है, समुद्र एक सरल समाधान प्रस्तुत करता है। यदि महासागरों के पानी को भूमण्डल के समस्त निवासियों के बीच वितरित कर दिया जाये, तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में १० हजार करोड़ गैलन (३८ करोड़ किलोलिटर) समुद्री पानी आयेगा। किन्तु उसे खारे से पेय जल में परिवर्तित करना पड़ेगा। प्राचीन काल से ही खारे पानी को उबाल कर भाप से मीठा पानी तैयार करने की परम्परा चली आ रही है। पिछले अनेक वर्षों से अमेरिका में कुछ निजी कम्पनियां इस समस्या को लसुझाने में संलग्न हैं। वे सारे पानी को उबाल कर मीठा पानी तैयार करने की परम्परागत विधि के स्थान पर कोई अधिक उपयुक्त विधि ढूंढ निकालने के लिए प्रयत्नशील है। परम्परागत विधि के अन्तर्गत अत्यधिक मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है, जिससे यह विधि बहुत महंगी पड़ती है। इसके अतिरिक्त ब्वायलरों के क्षरण और क्षार को हटाने-फैकने की समस्या भी बहुत कठिन है।

हाल के एक भाषण में, प्रैसिडैण्ट कैनेडी ने कहा था अन्त में चलकर खारे पानी को क्षार-रहित बनाने का कार्य-क्रम 'चन्द्रमा पर मनुष्य को पहुँचाने सम्बन्धी हमारे

(शेष पृष्ठ ४७२ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गांवों की उन्नति के लिए पशुपालन

हमारे देश में ढोरों की संख्या बहुत बड़ी है, पर पश्चिमी देशों की बनिस्बत दूध बहुत कम होता है। हमें हल चलाने के लिए बहुत अच्छे बैल भी चाहिए। यह काम वैज्ञानिक पशुपालन और नस्ल सुधार से ही हो सकता है। इस दिशा में क्या हो रहा है, यह इन पंक्तियों में पढ़िये।

देश में लगभग ३३ करोड़ पशु होने का अनुमान है। इनमें से गाय-भैंसों की संख्या २२ करोड़ यानी, दो तिहाई और संसार भर के गोवंश का चौथाई है। पर हमारी गाय-भैंसें दूध कम देती हैं। देशी गाय एक ब्यात में लगभग ४०० पौंड और भैंस १,१०० पौंड दूध देती है, जबकि पश्चिम के उन्नत देशों में लगभग ५ हजार पौंड दूध देती है।

तीसरी योजना में पशु-पालन के लिए ५४ करोड़ रु० रखा गया है। दूसरी योजना में २१ करोड़ और पहली योजना में ८ करोड़ रु० रखा गया था।

चार काम

पशुपालन की उन्नति के लिए चार काम करने हैं—१. पशुओं की नस्ल सुधारना, २. बूढ़े और बेकार ढोरों को हटाना, ३. अच्छे चारे का प्रबन्ध करना और ४. बीमारियों की रोकथाम।

पहली योजना में १४६ आदर्श पशु-ग्राम-खंड चालू किए गये। दूसरी योजना में १९६ नये खंड खोले गये और १४४ चालू खंडों को बढ़ाया गया। दूसरी योजना के अंत तक लगभग २ हजार गांवों में यह कार्यक्रम चालू हो गया था। तीसरी योजना में आदर्श पशु-ग्राम-खंड कार्यक्रम को और बढ़ाया जाएगा। नये खंडों में अब १०-१० गांव रहेंगे।

नस्ल सुधार

ढोरों की नस्ल सुधारने का कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने तैयार किया है, जिसे केन्द्र और राज्य सरकारों ने मंजूरी दे दी है। देश में गायों की २५ और भैंसों की ६ नस्लें हैं। इनमें से कुछ दुधारू हैं और कुछ हल जोतने और भार ढोने के काम के हैं। हरियाना, कांकडेज और अंगोल नसल के ढोर दोनों काम देते हैं: नस्ल सुधार का उद्देश्य यह है कि अधिक दूध देने वाली गाय और बढ़िया बैल दोनों मिल सकें। तीसरी योजना में प्रयोग के तौर पर कुछ विदेशी और देशी नस्लों का मेल किया जाएगा। इस काम के लिए पहाड़ों में फार्म खोले जा रहे हैं।

अच्छे सांड़ों की कमी ढोरों की नस्ल सुधारने में बाधक होती है। इस समय देश में ढोरों की नस्ल सुधारने के १२५ सरकारी फार्म हैं, पर अब तक केवल ५ हजार अच्छे सांड तैयार किये जा सके हैं, जो बहुत कम हैं। तीसरी योजना में अच्छे सांड तैयार करने के लिए ११ फार्म या गो सदन चालू किए जाएंगे और सरकार अच्छी नस्ल के ३० हजार बछड़े पालने के लिए सहायता देगी।

इसके अलावा कुछ और पशु शालाएं भी खोली जाएंगी। अच्छी नस्ल के सांडों को उत्पन्न करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ाया जा रहा है। १९६० तक ६७० कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले गये। तीसरी योजना में आदर्श पशु ग्राम खंडों में बहुत से कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले जाएंगे। दूसरी योजना में २४६ गोशालाओं में अच्छी नस्ल के सांड तैयार करने का काम शुरू किया गया।

फालतू ढोरों की समस्या

ढोरों की नस्ल सुधारने के लिए घटिया ढोरों को हटाना जरूरी है। इसके लिए गो सदन स्थापित किए गये। बेकार या ठांठ ढोरों को जंगलों में गो सदनों में रख दिया जाता है। पिछली दो योजनाओं में ५९ गो सदन खोले गए और तीसरी योजना में २३ और खोले जाएंगे। गो सदनों के प्रबन्ध में सुधार की लगातार कोशिश की जाती है, जिससे इनका खर्च कम हो। मृत ढोरों की खाल, हड्डियों और सींगों का उपयोग भी किया जाता है।

चारे की समस्या

तीसरी योजना में ढोरों को पूरा चारा और अच्छा पोषण देने के लिए गोचर बनाए जाएंगे, और चारा उगाया जायगा और उसे रखने का अच्छा प्रबन्ध किया जाएगा। खली आदि के समुचित उपयोग की भी व्यवस्था की जाएगी।

सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय फल और सब्जियां

श्री एन० डी० बत्रा

भारत एक विशाल उप-महाद्वीप है। इसमें स्थान और जलवायु के अनुसार मौलिक और जलवायविक अन्तर विद्यमान हैं। यहां हर प्रकार के फल और तरकारियां उपजती हैं। सेव, अन्जीर, नाशपाती जहां काश्मीर, हिमाचल-प्रदेश, कुल्लू और कुमाऊं की पर्वतीय ढलानों पर पाये जाते हैं, भारत के अन्य भागों में आम, संतरा, लीची मौसमी, केला आदि उपजते हैं। इसी प्रकार अन्य सभी प्रकार की तरकारियां यथा, आलू, बैंगन, तोरी और पत्तों वाली सब्जियां आदि भी भारत के अन्य भागों में उपलब्ध हैं।

फल और तरकारियां स्वास्थ्य के लिए रोग-निरोधक भोजन हैं। कैलशियम, फासफोरेस और फौलाद आदि क्षारों की प्राप्ति के लिये उपर्युक्त पदार्थ एक अक्षय स्रोत हैं। उदाहरणार्थ केले में विटामिन ए०, बी०, सी०, डी० और ई० होते हैं। इसके अतिरिक्त पोटाश, फासफोरेस, कैलशियम और फौलाद केले में किसी भी अन्य पदार्थ से अधिक मात्रा में पाये जाते हैं।

आंवला विटामिन 'सी' के लिये प्रसिद्ध है। टमाटर और मौसमी में भी विटामिन 'सी' पाया जाता है। पत्तों वाली सब्जियां और टमाटर में भी विटामिन 'सी' भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जबकि टमाटर में विटामिन 'ए' और 'बी' भी होते हैं। इसके अतिरिक्त विटामिन 'ए' गाजर, चुकन्दर, आलू और बन्द गोभी में भी पाया जाता है।

रोग निरोधक उपर्युक्त आहार स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि फल और तरकारियों का प्रयोग मानसिक क्रियाओं को सुदृढ़ बनाता है। यदि भोजन विटामिन युक्त है तो हमारा स्वास्थ्य आनन्ददायी होगा तथा साधारण रोगों के आक्रमण से हम मुक्त रहेंगे। गर्भवती-स्त्रियों और बच्चों के लिए फल बहुत ही उपयुक्त हैं।

त्योहारों, सामाजिक उत्सवों और धार्मिक उपासना में फलों के प्रयोग को असाधारण स्थान दिया गया है। किसी भी उत्सव की समाप्ति पर प्रायः फलों का प्रसाद बांटा जाता है। उपवास में भी लोगों को आदेश दिया जाता है कि वे फलों का प्रयोग करें। कई फल तो देवताओं के नामरूप ही रखे गये हैं, यथा सीताफल, रामफल।

भारत में फलों का उपयोग, संसार के अन्य देशों की अपेक्षा कम है। फलों की वार्षिक उपज ६० लाख टन और तरकारियों की ४० लाख टन है। सिद्धान्ततः १.६ औंस फल और १.३ औंस तरकारी प्रति मनुष्य प्राप्त होती है, जबकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मत है कि स्वस्थ जीवन के लिए प्रति मनुष्य ३ औंस फल और १० औंस तरकारी सन्तुलित भोजन हो सकता है।

स्पष्ट है कि देश में जहां फलों और तरकारियों की अधिक उपज की तीव्र आवश्यकता है, वहां उनके उपभोग का क्षेत्र भी विस्तृत है। यदि हम अधिक फलों और तरकारियों को उपजाते हैं तो इससे एक ओर हमारे अन्न आदि भोज्य-पदार्थों में कटौती होगी और दूसरी ओर फलों के प्रयोग से हमारा भोजन संतुलित होगा। इसके अतिरिक्त कच्चे फल, तरकारियों के रूप में प्रयोग किये जा सकते हैं और पके फल भोजन और पेय पदार्थों का काम दे सकते हैं। हम फलों के सूखने के पश्चात भी उनका प्रयोग कर सकते हैं। यथा अंजीर और खुमानी। फल, अचार, मुरब्बा, चटनी आदि में भी प्रयोग किये जाते हैं। वस्तुतः फल और तरकारियां एक लाभप्रद प्राकृतिक भोज हैं।

आठ हजार अस्पताल

तीसरी योजना में पशुओं के अस्पतालों और दवाखानों की संख्या दुगनी की जाएगी। इस समय ४ हजार अस्पताल और दवाखाने हैं। पशुओं के रोगों की रोकथाम के लिए अधिक टीके तैयार किए जाएंगे। आशा है कि १९६३-६४ तक देश के सब गाय-बैलों को टीके लग जाएंगे। अब तक १० करोड़ ढोरों को टीके लगाए जा चुके हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उत्पादन कैसे बढ़े ?

प्रश्न यह है कि इनकी उपज को कैसे बढ़ाया जाये। इसके लिये कई उपकरण जुटाये जा सकते हैं। इनमें से एक फलों के लिये जुताई जाने वाली भूमि में वृद्धि का हो सकता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रयोग में लाई जाने वाली कार्य-प्रणाली के अनुसार जहां उपवनों के लिये लक्ष्य लगभग १,३३,३०० एकड़ भूमि जुटाना था, वहां पुराने बागों की लगभग ५ लाख एकड़ भूमि को सुधारना भी था। इसी मद में लगभग ५ करोड़ रु० प्रान्तीय योजनाओं में भी निर्धारित किये गये थे।

दूसरा तरीका कृषि प्रणाली में सुधार कर वर्तमान जोती जाने वाली भूमि से ही अधिक उपज का प्राप्त करना है। समुचित मात्रा में उपज में विकास करके आधुनिक त्रुटियों को दूर भी किया जा सकता है। यह त्रुटियां उपवनों की अव्यस्थित स्थिति, द्वितीय श्रेणी के बीजों का प्रयोग, क्रमिक चुनाई, कटाई और सामयिक सुधारों का अज्ञान, कीटाणुओं से बचाव के उचित साधनों का अभाव, उपवनों की श्रेणी निर्धारित करने की अक्षमता, फलों की समुचित पैकिंग और बाजार में भेजने के उचित साधन तथा उपभोग से अधिक फलों के बच जाने की स्थिति में उन्हें वातानुकूलित स्थानों पर रखने का अभाव आदि हैं। कृषि, बागवानी, रसायन विज्ञान, जीवाणुविज्ञान-के सिद्धांतों के योग में आज बहुत विकास हो चुका है।

व्यापार

यद्यपि कुटीर-उद्योगों में फलों एवं सब्जियों की सुरक्षा बहुत प्राचीन है, और वस्तुतः चटनी, अचार और मुरब्बा प्रायः प्रत्येक भारतीय घर में बनती है, व्यावसायिक स्तर पर फलों का उत्पादन अभी हाल की चीज है। बोतलों और टोकरियों में बन्द मुरब्बा (जाम), मीठी चटनी (जेलि), नारंगी का मुरब्बा (मार्मलेड्) स्क्वैश तथा सौस फल और सब्जियां आदि नई वस्तुएं हैं। अवश्य ही मौसम में अधिक मात्रा में बचाने से बहुलता रुकेगी, और इस प्रकार, वह भारतीय बागबानी के लिए एक वरदान सिद्ध होगा।

बहुत पहले ही इस बात को महसूस किया जा चुका है कि अच्छे व्यापारिक उत्पादन के लिए शुद्धि नियंत्रण अनिवार्य गुण है। १९४६ में फ्रूट प्रोडक्ट कन्ट्रोल आर्डर (फल उत्पादन नियंत्रण नियम) की घोषणा की गई थी। इन नियम ने उत्पादक संस्थाओं के न्यूनतम स्तर एवं तैयार माल के गुण को निर्धारित किया। १९५५ में फ्रूट प्रोडक्ट आर्डर का स्थान फल और सब्जियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से फ्रूट प्रोडक्ट कन्ट्रोल आर्डर ने ले लिया।

द्वितीय एवं महत्वपूर्ण पद्धति है कृषि के उपयुक्त भूमि की वृद्धि। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत (१,३३,३००० एकड़ भूमि की) पुष्पवाटिका एवं फिर से पुरानी पुष्पवाटिकाओं को नया रूप देने की भूमि का लक्ष्य लगभग ५ लाख एकड़ था। इस कार्य के लिए राज्य-योजनाओं में ५ करोड़ रुपये रखे गये। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति काल तक फलों सब्जियों की सालाना उपज को बढ़ाकर ५०,००० टन का लक्ष्य रखा गया। इसी प्रकार निर्यात का लक्ष्य बढ़ाकर ५,००० टन तक रखा गया। कुछ भी हो, यह लक्ष्य लगभग पा ही लिये गये थे।

उत्तरी हिमालय, नेफा से लद्दाख तक में बागबानी का विशेष महत्व है। इसका विशेष महत्व इसलिये भी है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र का २० प्रतिशत भाग ही कृषि-योग्य होता है और शेष भाग का विशेष रूप से समशीतोष्ण-कटिबन्ध का उपयोग फलों एवं सब्जियों के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इससे न केवल पर्वतीय प्रान्तों की बचत में वृद्धि होगी, अपितु यह देश में फलों की कमी को दूर करेगा और भूमि-कटाव को भी रोकेगा। बहुत-सी प्रांतीय एवं केन्द्र सरकारों द्वारा भी बड़े स्तर पर बागबानी पर विशेष बल दिया जा रहा है। आसाम, पश्चिमी बंगाल और बिहार की प्रान्तीय सरकारें सीमावर्ती क्षेत्रों में हरी सब्जियों के उत्पादन को बिना ब्याज के ऋण एवं छोटे करों द्वारा प्रोत्साहित कर रही हैं। इस कार्य के लिये १४,५०० एकड़ का लक्ष्य रखा गया है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में शहरों में फलों और सब्जियों के लिए गहरी खुदाई की योजनाएं भी योजना संस्था द्वारा बनाई गई हैं। इस योजना के अन्तर्गत, जो प्रायः सभी प्रान्तों पर कार्यान्वित होती हैं, खुदाई के अन्तर्गत लाने वाली भूमि का स्वीकृत लक्ष्य महाराष्ट्र में ही ४७,४२० एकड़ भूमि सब्जियों के लिए तथा २८,९८० एकड़ फलों के लिए है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नया सामयिक साहित्य

'सम्पदा' (मराठी) (उत्पादकता विशेषांक)—सम्पादक आ० रा० भट्टा। मराठा चैम्बर भवन, तिलक रोड़ पूना से प्रकाशित। वार्षिक मूल्य ६ रुपया। इस अंक का मूल्य ३ रुपया।

यह पत्र मराठा चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा प्रकाशित होता है। प्रस्तुत अंक में आज की उद्योगों की प्रमुख समस्या उत्पादकता पर विचार किया गया है। उत्पादकता वृद्धि का अर्थ केवल नई मशीनरी अथवा कठोर परिश्रम द्वारा ही उत्पादन में वृद्धि नहीं है, उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए व्यापार, प्रबन्ध कुशलता, श्रमिकों के प्रति न्याय व्यवहार, परिवहन कच्ची सामग्री, स्टोर सामग्री का क्रय विक्रय तथा मिलों में सुरक्षा व्यवस्था, पैकिंग आदि सबका समन्वय करना पड़ता है। आजकल मानक संस्था के द्वारा निर्धारित मान दण्ड भी उत्पादकता बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। इस तरह प्रस्तुत अंक में उत्पादकता के विभिन्न पहलुओं पर भली भांति प्रकाश डाला गया है। भारत में उत्पादकता वृद्धि के जो प्रयत्न हो रहे हैं, उनका भी परिचय पत्रिका के पाठकों को इस अंक से मिल सकता है। मराठा चैम्बर की २९ वीं बैठक का विस्तृत विवरण करीब ४० पृष्टों में दिया है, जिस का विषय के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध न भी हो तो भी पत्रिका की संचालक संस्था के नाते इतना अधिक स्थान उसे दिया गया है।

साहित्य सन्देश—(बाबू गुलाब राय स्मृति अंक) सम्पादक—श्री महेन्द्र। मूल्य-१ रुपया। वार्षिक मूल्य ५ रुपया। प्रकाशक—साहित्य सन्देश, आगरा।

स्वर्गीय गुलाब राय का वर्तमान भारतीय साहित्य के इतिहास में अपना महत्व है। साहित्यिक और आलोचनात्मक लेख लिखने में वे बहुत प्रवीण थे। उनकी लेखन शैली बहुत सरल और सुबोध थी। प्रस्तुत अंक में साहित्य के अनेक विद्वानों द्वारा बाबू गुलाब राय के जीवन और साहित्य इन दोनों के सम्बन्ध में विविध पहलुओं पर परिचयात्मक लेख दिये गये हैं।

सर्वश्री नरेन्द्र, विजयेन्द्र, पद्मसिंह शर्मा, बलदेव प्रसाद मिश्र, विश्वम्भर मानव, श्री गोपालप्रसाद व्यास आदि के लेख उनके जीवन के विभिन्न गुणों का अच्छा परिचय देते हैं। उनकी साहित्य के प्रति विभिन्न विचार धाराओं के परिचय से हिन्दी इतिहास के विद्यार्थी को भी बहुत सहायता मिल सकती है। वे वस्तुतः जहां अच्छे निबन्ध लेखक थे, वहां उच्चकोटि के साहित्य-शास्त्री भी थे।

कार्पोरेट मैनेजमेण्ट

(अंग्रेजी) एसोसिएशन आफ कम्पनी सैक्रेटरीज एण्ड एक्जीक्यूटिव्ज १३४/१ महात्मा गांधी रोड कलकत्ता द्वारा प्रकाशित। मूल्य ३ रुपया।

आजकल कम्पनी के प्रबन्ध विभाग में नई-नई प्रवृत्तियों के कारण काफी परिवर्तन हो रहा है। मैनेजिंग एजेंसी समाप्त हो रही है। मैनेजिंग डायरेक्टरों के बारे में नये-नये कानून बन रहे हैं। सरकार का नियन्त्रण क्रमशः बढ़ता जा रहा है। इन सब परिवर्तनों की जानकारी देने के लिए २६ पृष्ठों की यह छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की गई है। इन्हीं प्रश्नों पर विचार करने के लिए उक्त एसोसिएशन की ओर से एक विचार गोष्ठी बुलाई गई थी। उसी विचार गोष्ठी में प्रकट किये गये विचारों का इस पुस्तिका में संग्रह किया गया है।

जीवन साहित्य (राजेन्द्र संस्मरण अंक)—सम्पादक श्री हरिभाउ उपाध्याय, और श्री यशपाल जैन। प्रकाशक-सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली। इस अंक का मूल्य १.५० रुपया। पृष्ठ संख्या ८६।

स्वर्गीय डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद का भारत के वर्तमान राजनीतिक जीवन में असाधारण महत्व है। उनके समस्त जीवन को राष्ट्रीय संग्राम के योद्धा, राष्ट्रपति और साहित्यिक व सामाजिक कार्य-कर्त्ता के रूप में विभक्त किया जा सकता है। इन तीनों दृष्टियों से श्री राजेन्द्र बाबू का परिचय प्रस्तुत अंक में मिलेगा। राजेन्द्र बाबू राजनीतिक संग्राम में योद्धा ही नहीं रहे, उससे अधिक महत्व उनके व्यक्तिगत चरित्र का है। भारतीय संस्कृति से प्रेम, हृदय की विशुद्धता जीवन में नम्रता और सादगी आदि गुणों के कारण वे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सदा स्मरणीय रहेंगे। प्रस्तुत अंक में उनके जीवन से परिचित लेखकों के ही लेख दिए गए हैं। उन सब लेखों में आत्मीयता की छाप है और इस लिए वे बहुत रोचक हैं। इन लेखों के संग्रह के लिए सम्पादक धन्यवाद के पात्र हैं।

सर्वोदय साहित्य

१. जीवन दृष्टि,
२. अहिंसक शक्ति की खोज
३. चीन भारत सीमा संघर्ष
४. काश्मीर के बारे में
५. धर्म क्या कहता है ?
६. जाति वाद और कौम बाद
७. नशाबन्दी क्यों और कैसे ?

उपर्युक्त पुस्तकों में से १,२,३ और ४ पुस्तकें आचार्य विनोबा की लिखी हुई है। ५ और ६ श्री कृष्णदत्त भट्ट द्वारा लिखी हैं। और नशाबन्दी श्री रमावल्लभ चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई है। जीवनदृष्टि में आचार्य विनोबा की विचार धारा का परिचय मिलता है। इनमें जीवन के गम्भीर तत्व ब्रह्मचर्य, समाजवाद, वैराग्य और निष्काम कर्म आदि प्रश्नों पर विनोबा की सूक्ष्म दृष्टि का परिचय मिलता है। इन्हें पढ़कर पाठक आध्यत्मिक आनन्द की भी प्राप्ति करेंगे। दूसरी पुस्तक में आराम बाग (पश्चिम बंगाल) में उनके अहिंसा तथा साम्यवाद और सर्वोदय आदि विषयों पर दिए गए भाषणों का संग्रह किया गया है।

तीसरी पुस्तक में चीन और भारत के संबन्ध में आचार्य विनोबा द्वारा समय पर प्रकट किए गए विचारों का संग्रह है। ये विचार सिद्धांत और दर्शन की पृष्ठ भूमि से भले ही ठीक हों, किन्तु ठोस सैनिक संघर्ष और आक्रमण की स्थिति में इन विचारों का पालन कहां तक उचित व व्यवहार्य है, यह पुस्तक पढ़ने के बाद भी संदिग्ध रह जाता है। कश्मीर के बारे में आचार्य विनोबा के उन भाषणों का संग्रह है, जो उन्होंने काश्मीर की पद-यात्रा के दौरान में दिए थे। धर्म क्या कहता है ? इस पुस्तक के लिखने उद्देश्य सर्व साधारण को और विशेष कर बच्चों को सब धर्मों का सार मानवता है, यह बताना है। लेखन शैली बहुत सरल और सुन्दर है। सब धर्मों में समानता की दृष्टि ही इस पुस्तक का उद्देश्य दीखता है। जाति वाद और कौमवाद में आजकल की जात-पात की कठोर आलोचना है। सातवीं पुस्तक का विषय नाम से ही स्पष्ट है।

• •

(पृष्ठ ४६७ का शेष)

समस्त प्रयत्नों से अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।"

आंतरिक विभाग के अन्तर्गत 'सैलाइन वाटर' नामक कार्यालय के माध्यम से, अमेरिकी सरकार नमूने के तौर पर प्रयोगात्मक संयन्त्रों का निर्माण करके अनुसन्धान और प्रयोग का एक व्यापक कार्यक्रम चला रही है। अमेरिका की वर्तमान योजनाओं के अन्तर्गत ५ संयन्त्र हैं। इनमें से ३ संयन्त्र पानी को छानकर क्षारहीन बनाने के लिए हैं, जबकि दो संयन्त्र पानी को बिजली द्वारा विशुद्ध करके और जमा कर पेय जल में परिणत करने वाले हैं। इनकी क्षमता १०, २।। तथा १० लाख गैलन है।

इस समस्या का अध्ययन करने के बाद ११ वर्षों में खारे पानी को पेय जल में परिणत करने की लागत प्रति हजार गैलन ५ डालर से घटकर १ डालर तक आ गयी है। आशा है कि अनुसन्धान और ५ प्रयोगात्मक संयन्त्रों द्वारा अगले ५ वर्षों में 'समान दर' पर खारे पानी से पेय जल तैयार करना सम्भव हो जायगा।

अन्तर्राष्ट्रीय अणुशक्ति एजेन्सी द्वारा आयोजित पहली गोष्ठी में यह स्वीकार किया गया था कि सामान्य घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए खारे पानी को पेय जल में परिणत करने के उद्देश्य से अणुशक्ति का प्रयोग किया जायगा। इसके परिक्षण सफलता प्राप्त कर रहे हैं। यह बात विकासोन्मुख व विकसित दोनों देशों के लिए समान रूप से महत्त्व की है।

विज्ञापन के लिए

सम्पदा

सर्वोत्तम

साधन है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थ वृत्त चयन

चीन की विफल अर्थनीति

रूस के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थी मास्लेनकोव ने एक लेख में चीन की विफल अर्थनीति की चर्चा की है। इस में वे लिखते हैं :

चीनी नेताओं ने काम के अनुसार भौतिक रूप में श्रमिक या किसान को प्रोत्साहन स्वरूप पारिश्रमिक देने के सिद्धान्त की अवहेलना की है। उन्होंने कम्यून में सबको काम या उत्पादन की चिन्ता किये बिना एक समान वेतन देने की नीति अपनाई। हमारी कम्यूनिस्ट पार्टी ने इस खतरनाक और हानिकारक परीक्षण की गलती को शीघ्र ही अनुभव कर लिया। आर्थिक सिद्धान्तों की उपेक्षा का मार्ग हानिकारक होता है। अन्य समाजवादी देशों का भी यही अनुभव है। चीनी नेताओं ने हमारी इस सलाह को ठुकरा दिया कि नये समाज निर्माण की पहली सीढ़ियों की उपेक्षा करके सीधी छलांग मारना खतरनाक है।

समय और अनुभव ने सिद्ध कर दिया कि चीनी नेतृत्व का मार्ग ठीक नहीं था। अवैज्ञानिक नीति से बने क्रूड आयल की भट्टियों में ऐसा लोहा तैयार हुआ जो काम लायक न था और उन पर बेहद खर्च हो गया। एक ही वर्ष में इन सब भट्टियों को छोड़ दिया गया। १९५७-५९ की तुलना में उनका उत्पादन एक तिहाई कम हो गया। कृषि में भी ऐसी ही असफलताएं हुईं। १९६१-६२ में वहां १५ से १६ करोड़ टन उत्पादन हुआ, जो १९५७ की पैदावार से भी कम हुआ।

साम्यवाद की स्थिति को एक ही छलांग में नहीं प्राप्त किया जा सकता। पूंजीवाद से समाजवाद की सीढ़ी भी आवश्यक है। इतिहास घुड़दौड़ नहीं है, जहां जबर्दस्ती चल जाती है। समाज को भी एक छलांग में कहीं नहीं ले जाया जा सकता।

संसार में मांस की खपत

आप इसे पसन्द करें या न करें, मांस की प्रति व्यक्ति खपत संसार के सब देशों में बढ़ती जा रही है। ३७ देशों से प्राप्त विवरण के अनुसार १९५३ में प्रति व्यक्ति मांस की खपत ८ पौंड वार्षिक थी। १९६२ में ३९ देशों से प्राप्त विवरण के अनुसार यह ९६ पौंड हो गई है।

१९६२ में संसार की आबादी ३.१ अरब थी। १९५३ से यह जनसंख्या २९ प्रतिशत बढ़ी है अर्थात् ६५ करोड़। चीन को छोड़कर मांस का उत्पादन ८४ अरब पौं० से बढ़कर १०९ अरब पौंड हो गया अर्थात् ३० प्रतिशत वृद्धि हुई। १९६२ की रिपोर्ट के अनुसार २८ देशों में मांस की खपत बढ़ी है। ६ देशों में कम हुई है और ५ देशों में खपत वैसी ही रही है। सबसे ज्यादा मांस की प्रति व्यक्ति खपत २३५ पौंड न्यूजीलैंड में होती है और सबसे कम जापान में। १९६२ में विभिन्न देशों से खपत की तालिका निम्नलिखित है—

	पौंड		
न्यूजीलैंड	२३५	आस्ट्रेलिया	२२१
यूरोगुआ	२१३	आरजेंटाइना	२०२
सं०रा० अमेरिका	१६४	ब्रिटेन	१३८
कैनाडा	१३७	डेनमार्क	१३३
फ्रांस	१३०	स्विटजरलैंड	१२३
प० जर्मनी	११८	आस्ट्रिया	११७
बैलजियम	११३	स्वीडन	१११
नीदर लैंड	१०८	रूस	६८
जापान	१२		

जापान में भी लगातार मांस की खपत बढ़ रही है। १९६१ की बजाय १९६२ में २ पौंड खपत प्रति व्यक्ति बढ़ी है। फिलिपाइन पेरु, मैक्सिको, ग्रीस युगोस्लाविया आदि अन्य देशों में ३० व ४० पौंड के बीच में खपत है।

यह भी हिसाब लगाया गया है कि अन्य देशों में कौन सा मांस किस अनुपात में खाया जाता है। जो मांस ५० प्रतिशत, ४० प्रतिशत सुअर, ९ प्रतिशत बकरी व भेड़ तथा घोड़े का मांस ½ प्रतिशत।

भारत तथा अन्य एशियायी देशों के शायद विव-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रण ही प्राप्त नहीं हुए।

लद्दाख में नया जीवन

विज्ञान की सहायता से क्या हो सकता है, इसका एक उदाहरण लद्दाख है। लद्दाख की अगम्यता और पृथकता दूर हो चुकी है। सारे जिले की आर्थिक स्थिति बदल गयी है। पहले एक मन सामान की ढुलाई ६० से १०० रु० तक लगती थी। इस साल १० रु० ही लगी। यहां सहकारी समितियों का जाल बिछ चुका है। अनाज के सहकारी गोले खुले हैं, जो अनाज रख कर कर्ज देंगे। पशुपालन के काम शुरू हुए हैं। याक की नस्ल सुधारने का कार्यक्रम चालू है। खेती की सुविधाएं बढ़ाने और भूमि को कटाव से बचाने के कार्यक्रम चला रहे हैं। दवाखाने व अस्पताल खोले गए हैं। घरेलू उद्योगों की मदद की जा रही है। लद्दाख में नया जीवन जाग उठा है।

दुनिया में घर

कम विकसित देशों में सामान्य लोगों के पास एक या दो कमरों के घर हैं। अधिकांश यूरोपियन देशों में तीन या चार कमरों के घर हैं। ग्रीनलैण्ड व अन्य विकसित क्षेत्रों में ८० प्रतिशत घरों में प्रति कमरे में दो या अधिक व्यक्ति रहते हैं।

पुस्तक-प्रकाशन

संसार के देशों में सबसे अधिक पुस्तकें प्रकाशित करने वाले देश हैं रूस, ब्रिटेन व जापान।

रूस में १९६१ में कुल ७३९९९ पुस्तकें प्रकाशित हुईं, जिनमें ३७०७३ पुस्तकें विज्ञान व शिल्प के सम्बन्ध में थीं और ८५८१ साहित्य की। ब्रिटेन में जितनी पुस्तकें प्रकाशित हुईं, उनकी एक तिहाई ८६१५ साहित्य सम्बन्धी थीं।

१९६० में चालीस देशों में ३१३८४ अनुवादित पुस्तकें प्रकाशित हुईं। इनमें ३५ प्रतिशत अंग्रेजी से, १६ प्रतिशत रूसी से, १३ और १० प्रतिशत क्रमशः फ्रैंच व जर्मनी से अनुवाद की गईं। इन में से ५८ प्रतिशत साहित्य व कला सम्बन्धी थीं, २९ प्रतिशत समाज विज्ञान की और शेष विज्ञान की।

चीन को छोड़कर १९६१ में अखबारी कागज १४० लाख मीट्रिक टन पैदा हुआ। १९६० की अपेक्षा यह ३ प्रतिशत और १९४८ की अपेक्षा ८८ प्रतिशत अधिक था। पिछले कुछ वर्षों में अखबारी कागज की खपत बहुत बढ़ गई है।

प्रति व्यक्ति सबसे अधिक खपत अमेरिका में थी—३६३ किलो। इण्डोनीशिया, जौर्डन, लिबिया और सीरिया में सबसे कम खपत ०.२ किलो थी।

मछली-उद्योग

देश में मछली पालन उद्योग से लगभग १० लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलता है और प्रतिवर्ष ६० करोड़ रु० की आमदनी होती है। इस समय देश में करीब १४ लाख टन मछलियों का उत्पादन होता है। इनके निर्यात से करीब ४ करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तीसरी योजना में इस उद्योग के विकास के लिए करीब २९ करोड़ रु० खर्च करने की व्यवस्था है। इसी प्रकार उत्पादन तथा निर्यात-मूल्य को बढ़ाकर क्रमशः १८ लाख टन तथा १२ करोड़ रु० करने की भी व्यवस्था है।

वज्र कंकरीट के चौखटे

रुड़की की केन्द्रीय इमारत अनुसंधान संस्था ने दरवाजों और खिड़कियों के वज्र कंकरीट के चौखटे तैयार किए हैं। पहले भी वज्र कंकरीट के चौखटे इस्तेमाल किए गए थे, पर इनमें किवाड़ लगाने की उचित व्यवस्था न होने के कारण इनका प्रचलन न हो सका। ये चौखटे देखने में भी सुन्दर नहीं होते थे।

नये प्रयत्नों के फलस्वरूप इन चौखटों में किवाड़ आदि लगाने के लिए दो व्यवस्थाएं की गईं। एक में ३ इंच व्यास की अलमुनियम की नलियां लगाई गईं। चौखटे ढालते समय इन नलियों को लगा दिया जाता है। दूसरी में, लकड़ी के पेचों पर तार लपेटकर (वायर हेलिक्स) उन्हें उक्त विधि से चौखटों में लगाया गया। चौखटों को सुन्दर बनाने के लिए इन्हें कार्बोरेंडम पत्थर से रगड़ा जाता जाता है और फिर सीमेंट-रोगन किया जाता है।

वज्र कंकरीट के इन चौखटों पर बढ़िया लकड़ी के चौखटों से आधी लागत आती है।

• •

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(पृष्ठ ४५२ का शेष)

किसानों का बहुमत है। इसलिए अन्देशा है कि प्रस्तावित संशोधन सरकार के हाथों में एक ऐसा हथियार सौंप देगा, जिसके जरिये भारत के किसानों को उनकी उन जमीनों से वंचित किया जा सकता है, जो उनके पास परम्पराओं से चली आ रही हैं।

यदि आज सरकार भूमि अधिग्रहण कानून के अन्तर्गत जो देश का एक सामान्य कानून है, २०,००० रुपये की कीमत का खेत लेना चाहती है तो उसे किसान को २०,००० रुपये मुआवजे के रूप में देना पड़ता है। वह कानूनी अदालत में जा सकता है और अदालत इस बात का ध्यान रखती है कि किसान को उस भूमि के बदले में, जिससे कि उसे वंचित किया गया है, पर्याप्त मुआवजा दिया जाय। केरल कानून और भू-सीमा सम्बन्धी अन्य कानूनों के अन्तर्गत कभी-कभी मुआवजा की मात्रा इतनी कम निर्धारित की गई है कि उसका प्रमाण, भूमि अधिग्रहण कानून के अन्तर्गत निर्धारित मात्रा का एक प्रतिशत ही होता है। अतः २०,००० रुपये की कीमत वाले किसान को अब उस रकम का १ प्रतिशत भाग अर्थात् २०० रुपये दिया जा सकेगा।

उपज गिर जायगी ?

हमारे सामने कम्यूनिस्ट रूस और चीन के उदाहरण मौजूद हैं, जहां पर जमीन से होने वाले उत्पादन की मात्रा सामूहिक खेती या संयुक्त सहकारिताओं के कारण निम्नतम सीमा पर पहुँच गई है। यंत्रीकरण के बावजूद भी इन देशों का उत्पादन संसार में सबसे कम है। खाद्य एवं कृषि संगठन की जांच द्वारा पता चलता है कि संसार भर में चीन की प्रति एकड़ उपज सबसे कम है। संसार में सबसे ज्यादा प्रति एकड़ उपज फारमूसा और जापान में है, जहां पर किसान छोटे-छोटे प्लाटों में खेती करते हैं जो शायद भारत के प्लाटों से भी छोटे होते हैं। यह बात हमेशा सच नहीं होती है कि फार्मों का छोटापन उत्पादकता में बाधक होता है। फारमूसा और जापान के बाद डैनमार्क का नम्बर आता है, जहां पर बहुत छोटे फार्म हैं। इसके बाद इंगलैंड है, जहां पर मध्यम आकार के फार्म हैं, उसके बाद सूची में अमेरिका और उसके बाद रूस और चीन आते हैं।

सोवियत रूस में राजकीय फार्मों तथा कृषि सहकारिताओं की स्थापना के बाद फार्मों की उत्पादकता में काफी गिरावट हुई। लेकिन सोवियत रूस ने छोटी स्वतन्त्र जमीनों को जिन्हें "किचिन गार्डन" (रसोई उद्यान) कहते हैं, मान्यता दे दी है जहां पर किसान जो चाहे पैदा कर सकते हैं और उनकी उपज को बेच सकते हैं।

यदि हम इन सब बातों का विचार करें तो प्रस्तावित १७वें संशोधन की अवांछनीयता के बारे में दो मत नहीं हो सकते हैं। क्या किसानों के हित का दावा करने वाले संसद् के सभी सदस्य कांग्रेसी या गैर कांग्रेसी इस पर किसानों की और फलतः देश के हित की दृष्टि से विचार करेंगे ?

(पृष्ठ ४५८ का शेष)

अतिरिक्त निजी क्षेत्र में भी कुछ कारखाने तत्संबंधी मशीनें बनावेंगे। इसके साथ ही साथ कोयले को धो कर साफ करनेवाले कारखानों की भी आवश्यकता है और इसको निर्मित करने वाले कारखाने यूनाइटेड किंगडम और अमरीका की सहायता से लगाये जा रहे हैं।

बिजली

इसी प्रकार हमारे देश में बिजली के उत्पादन की भी अधिक से अधिक क्षमता स्थापित की जाने की है और यह ख्याल किया जाता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक २३ लाख किलोवाट शक्ति हम प्रति साल पैदा करेंगे। उसी हिसाब से हमें बिजली के पैदा करने की मशीनें और उपकरण मुल्क में बनाना लाजमी है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगभग ८० करोड़ रुपये और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में १२० करोड़ रुपये की लागत की बिजली की मशीनों की आवश्यकता होगी। इसको ध्यान में रखते में हुए भोपाल में एक भारी विद्युत् कारखाना स्थापित किया गया है। इसमें ट्रांसफारमर, स्विच गियर ट्रेक्शन मोटर और सर्किट ब्रेकर आदि तैयार हो रहे हैं। इसमें जल और ताप बिजली के बड़े जनरेटर भी तैयार होंगे। टर्बाइन और बड़ी मोटरों आदि के निर्माण के लिए रानीपुर (हरिद्वार) के समीप तथा रामचन्द्रपुरम् (आंध्र प्रदेश) में भी कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और साथ ही मद्रास स्टेट के त्रिची नामक स्थान पर बायलर बनाने का भी एक बड़ा कारखाना स्थापित किया जा रहा है।

निजी और सरकारी, दोनों क्षेत्रों में प्रगति

मशीनी औजारों के निर्माण में निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में उत्साहवर्द्धक प्रगति हुई है। सरकारी कारखाने में १९६२ में ५ करोड़ ८० लाख रुपये की कीमत के औजार बने हैं और कई प्रकार के मशीनी औजार, मसलन फ्लेक्सिबल शैफ्ट मशीन और मेगनेटिक चक्कस्, पहली बार भारत में निर्मित हुए हैं। हिन्दुस्तान मशीन टूल अभी पिंजोर (पंजाब) में तथा केरल में भी कारखाने स्थापित करने जा रहा है और आंध्र प्रदेश के बारे में भी विचार किया जा रहा है। इस प्रकार हमने इस दिशा में अच्छी प्रगति की है। मशीनरी निर्माण में हमारी प्रगति इससे आंकी जा सकती है कि हम इस समय प्रति वर्ष शक्कर के १४ कारखानों की मशीनरी का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार इंजीनियरिंग उद्योग में उपयोग में आने वाली अन्य आवश्यक वस्तुओं (मसलन स्ट्रक्चर्स स्टील पाइप और ट्यूब्स, रेलवे वैगन और क्रेन आदि) के निर्माण में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई।

मित्र राष्ट्रों से सहायता

इन उद्योगों के स्थापित करने में और विकास करने में कई मित्र राष्ट्रों से हमें विभिन्न प्रकार से सहायता मिली है। वहां से न केवल हमें रकम उधार मिली है, बल्कि हमें भारी मात्रा में तकनीकी सहायता भी प्राप्त हुई है। इस क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान व रूपांकन यानी डिजायन और टेक्नोलाजी का अत्यधिक महत्व है। जब तक हम अपने देश में शिल्प ज्ञान में पूर्ण और प्रशिक्षित जन-शक्ति तथा अनुसंधान करने वाले दक्ष और प्रशिक्षित वैज्ञानिकों को तैयार नहीं करते, तब तक हम इन उद्योगों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण काम नहीं कर सकते और यह सब काम न केवल महत्त्वपूर्ण हैं, बल्कि कठिन भी हैं और उनको स्थापित करने में और विकसित करने में समय लगना स्वाभाविक है। फिर भी पिछले चन्द सालों में इस दिशा में हमने जो प्रगति की है, वह न केवल महत्त्वपूर्ण है बल्कि सन्तोषप्रद भी है, और हमें पूरी आशा है कि हमारी सफलता के यह चरण आगे बढ़ते जाएंगे। ● ●

नेपाल और भारत का सहयोग

पिछले महीने में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार का शिष्टमंडल नेपाल सरकार के नियन्त्रण पर नेपाल गया था। वहां की सरकार की इच्छा यह है कि भारतीय उद्योगपति नेपाल में पूंजी लगाकर कुछ उद्योगों का विकास करें। बिरला बन्धुओं ने नेपाल में सहयोग देकर एक सूती मिल स्थापित भी की है। इसकी स्थापना के लिए नेपाल सरकार ने बिरला बन्धुओं को अनेक सुविधाएं दी हैं और कारखाना कानून की अनेक धाराओं में संशोधन तक किया है।

नेपाल सरकार ने भारत के उद्योग पतियों को उद्योग विकास के लिए जो सुविधाएं दी हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :—

१. नये उद्योगों पर दस वर्ष तक कर नहीं लगेगा।
२. उद्योग की मशीनरी पर केवल एक% सांकेतिक आयात कर लगेगा।
३. पूंजी और आय को विदेशी मुद्रा में बदलने की गारण्टी।
४. भारतीय और नेपाली उद्योगपतियों में कोई भेद भाव नहीं रहेगा।
५. लोहा, खनिज आदि उद्योगों में लगी विदेशी पूंजी पर पांच वर्ष के लिए पांच प्रतिशत लाभ की गारण्टी।
६. आयात के लिए एक सीमा तक विदेशी मुद्रा की अनुमति।

नेपाल सरकार ने भारतीय शिष्टमंडल से सोलह उद्योगों के विकास की इच्छा प्रगट की थी, लेकिन शिष्टमंडल ने केवल दस उद्योगों के विकास की व्यावहारिकता को स्वीकार किया---जूट, कागज, सीमेंट, प्लाइवुड, तारपीन तेल, साइकिल, गत्ता, पेय द्रव्य और फलों की डिब्बा बन्दी आदि।

कुछ समय पहले नेपाल सरकार को चीन ने अनेक उद्योगों के विकास में सहायता देने के बड़े-बड़े वायदे किए थे, किन्तु उन वायदों में कोई सार न देखकर अब नेपाल ने भारत सरकार की ओर मुख किया है। ● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सूती कपड़े का विश्व निर्यात

(मिलियन गजों में)

१९६२		१९६१	१९६०	१९५९
५३९.७४	भारतवर्ष	५८२.४४	७२३.९८	७४६.७२
१,३९९.८२	जापान	१,४१०.८०	१,४२४.६०	१,२६२.०४
३६४.६०	हांग कांग	३७६.२८	३१२.४४	१४०.५२
६३.३०	पाकिस्तान	५३.७२	७५.६०	१६.९६
N.A.	फारमूसा	N.A.	९४.००	११.८४
२३५.२१	यूनाइटेड किंगडम	२८६.६६	३२७.०८	४७४.१६
२८५.८२	बेल्जियम व लक्सम्बर्ग	२६६.२०	२७४.२४	२२१.८८
४२६.८७	फ्रांस	४८४.४४	५३२.८८	३१५.४०
२४५.२८	पू० जर्मनी	२७९.४०	२८४.८०	२०६.५६
२८८.९१	नीदर लैंड्स	३०७.००	३३९.९६	२५५.८८
८७.७३	इटली	११२.७२	११६.६८	९५.६८
१७०.६३	पुर्तगाल	१४५.९६	१८०.१६	११५.१६
६८.४४	स्पेन	१३१.४८	१६६.६२	३३.२४
४९.७१	स्विटजरलैंड	५५.४४	६३.०४	५९.५६
४०३.२०	अमेरिका	४७१.९२	४३८.७२	५१८.८८
१५४.३९	दूसरे देश	१९४.८८	३०६.६६	९७.५८
४,७८०.६५	योग स्वतंत्र विश्व	५,१५९.३४	५,६६२.४४	४,५७२.०६
अप्राप्त	चीन	३९४.५२	५०४.००	२८६.७२
,,	जेकोस्लोवाकिया	१३५.९६	१५०.४०	१३५.४०
,,	पोलैंड	११०.९६	१०१.१२	१०१.४०
,,	दूसरे कम्युनिस्ट	४०५.८५	५२१.५७	३६३.३५
,,	योग कम्युनिस्ट का	१,०४७.२९	१,२७७.०९	८८६.८७
४,७८०.६५	कुल योग	६,२०६.६३	६,९३९.५५	५,४३८.९३

भारत, जापान, ब्रिटेन से कपड़े का निर्यात

	१९६२	१९६१	१९६०
भारत	५०८.३६	५७४.२०	६९४.८३
जापान	१,४४८.१७	१,४१२.००	१,४२५.८०
ब्रिटेन	२३५.२१	२८६.६६	३२७.०९

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बैंकों द्वारा विकास के लिए ऋण

(रुपए करोड़ों में)

	अप्रैल १९६१		अक्तूबर १९६१		मार्च १९६३	
	कुल	प्रतिशत योग	कुल	योग का प्रतिशत	कुल	योग का प्रतिशत
उद्योग	६८८	५२.७	६६९	५४.५	९२१	५७.२
वाणिज्य	४०८	३१.३	३५१	२८.६	४४४	२७.६
वित्तीय	६७	५.१	६३	५.१	८४	५.२
व्यक्तिगत, व्यवसायिक	९९	७.५	१०६	८.६	१११	६.९
कृषि सम्बन्धि	५	०.४	६	०.४	४	०.३
अन्य दूसरे	३८	२.९	३३	२.७	४६	२.८
योग	१,३०६	१००.०	१,२२७	१००.०	१,६११	१००.०

सूती कपड़े का संसार में उत्पादन

(मिलियन गजों में)

	१९६२	१९६१	१९६०	१९५६
भारतवर्ष	७,६६३.००	७,७३४.००	७,२४३.००	७,०९४.००
अमेरिका	९,७२०.८६	९,१५६.०८	९,३२८.२८	१०,३१७.०८
चीन	६,७५५.१०	७,४३१.५०	८,३९२.७०	६,३१२.००
रूस	५,७६६.७५	५,८६०.३९	६,६२०.००	५,९६४.००
जापान	३,७२६.६४	४,०४७.२०	३,८५३.१२	३,४७५.६४
फ्रांस	१,९४२.९२	१,९८८.९६	२,११२.८८	१,६५७.०८
प० जर्मनी	१,५७०.००	१,५७३.५६	१,६७३.८४	१,५४७.७६
ब्रिटेन	१,०५६.०४	१,२३४.७२	१,२९३.५६	१,६११.५६
इटली	१,३२८.२८	१,३११.९६	१,३३५.६४	१,०६३.५६
बेल्जियम, लक्संबर्ग	७१४.९२	७३३.९८	७६०.७९	७२२.५६
नीदरलैंड	५८८.४८	६३३.२४	६३९.७२	६१९.५६
हांग कांग	४९५.००	४८३.६०	४६१.४८	१७०.७१
अन्य देशों सहित				
योग	५७,०६०.००	५६,३४०.००	५५,७६१.१२	४९,७७५.६४

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संचालक, पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश

की

विज्ञप्ति संख्या ४।५५८० : २७।३३, दिनांक १५

द्वारा

पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत

सुन्दर पुस्तकें

		रु०	आ०
वेद सार	प्रो० विश्वबन्धु	१	८
प्रभु का प्यारा कौन ? (२) भाग			
सच्चा सन्त			३
सिद्ध साधक कृष्ण			३
जीते जी ही मोक्ष			३
आदर्श कर्मयोग			३
विश्व-शान्ति के पथ पर			१
भारतीय संस्कृति	प्रो० चारुदेव		
बच्चों की देखभाल	प्रिंसिपल बहादुरमल	१२	१
हमारे बच्चे	श्री सन्तराम बी. ए.	३	१३
हमारा समाज		३	
व्यावहारिक ज्ञान		२	१२
फलाहार		१	४
रस-धारा		०	१४
देश-देशान्तर की कहानियां		१	
नये युग की कहानियां		१	१२
गल्प मंजुल	डा० रघुबरदयाल	१	
विशाल भारत का इतिहास	प्रो० वेदव्यास	३	८

१० प्रतिशत कमीशन और ५० रु० से ऊपर के आर्डरों पर १५ प्रतिशत कमीशन।

विश्वेश्वरानन्द पुस्तक भंडार

साधु आश्रम, होशियारपुर, पंजाब

आर्थिक समीक्षा

सम्पादक : श्री हरतीर्थ सिंह

- हिन्दी में अनूठा प्रयास
- आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख
- आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत

भारत के विकास में रुचि रखनेवाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक।

वार्षिक मूल्य : ५ रु० एक प्रति २५ नये पैसे

लिखें—व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, नई दिल्ली

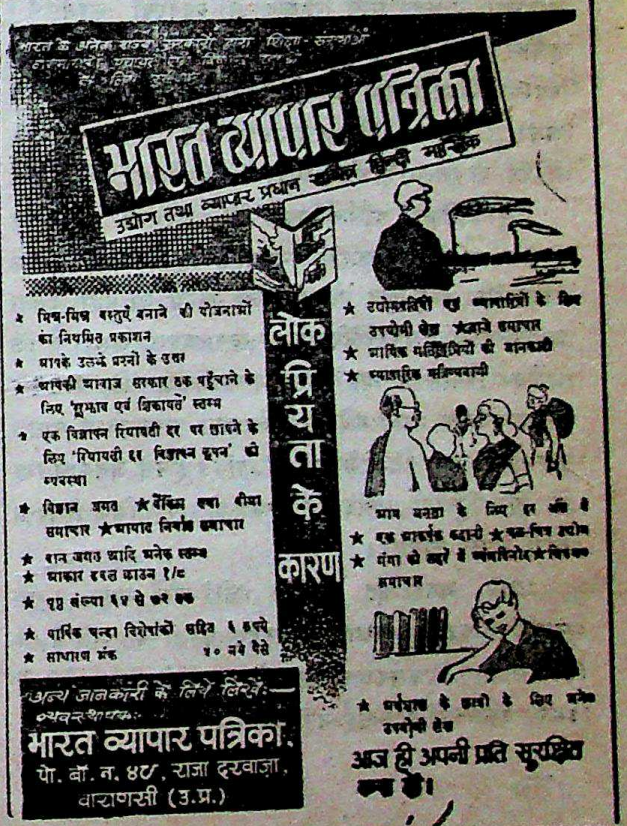

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(पृष्ठ ४३२ का शेष)

प्रगति में सबको न्यायोचित हिस्सा मिल सके तथा विशेषाधिकार, असमानता और शोषण समाप्त हो।

यह परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीकों से और जनता की सहमति से करना है। इस प्रक्रिया में संविधान में निहित लोकतन्त्रीय पद्धति और लोकतन्त्रीय मूल्यों की रक्षा भी करनी है।

इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस की विचारधारा लोकतन्त्र पर आधारित लोकतन्त्रीय समाजवाद है, मानव मात्र की प्रतिष्ठा और सामाजिक न्याय उसके अभिन्न अंग हैं।

आधुनिक अर्थ-व्यवस्था

अर्थ-व्यवस्था को आधुनिक ढांचे में ढालने और उत्पादन का स्तर ऊंचा उठाने के लिए यह जरूरी है कि देश की उत्पादन व्यवस्था को यथाशीघ्र आधुनिक आधार पर संगठित किया जाय। कृषि पिछड़ी हुई स्थिति में है। कृषि-तकनीकी प्रगति का अधिकतम लाभ किसानों को प्राप्त होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है और निरन्तर बढ़ती जा रही है जो बेरोजगार हैं इनके लिए रोजगार की व्यवस्था करनी है। इसलिए विकेन्द्रित छोटे कुटीर उद्योगों को देश की अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता रहेगा। यह भी जरूरी है कि छोटे और कुटीर उद्योगों के उत्पादन-कौशल में तेजी से सुधार हो और गांवों में बिजली पहुँचाई जाय।

सुनियोजित अर्थ-व्यवस्था में विभिन्न स्तरों पर नियंत्रण व नियमन जरूरी हो जाता है। इसी से उत्पादन के लक्ष्य और आयोजन के सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यह निश्चित कर लेना बहुत जरूरी है कि आर्थिक विकास का यह परिणाम न निकले कि आय की असमानता बढ़ जाय और सम्पत्ति तथा उत्पादन के साधन कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रित हो जावें। इससे जनसाधारण को क्षति पहुँचेगी। यदि ऐसा हुआ तो सामाजिक स्थिरता खतरे में पड़ जायगी।

यदि जनता यह देखे कि धीरे-धीरे न्याय संगत सामाजिक व्यवस्था यथार्थ रूप ग्रहण करती जा रही है तो विकास कार्य में उसका उत्साह और सहयोग प्राप्त होने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी।

न्यूनतम आवश्यकता

यह सबसे अधिक महत्व की बात है कि प्रत्येक नागरिक की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करने की व्यवस्था जितना शीघ्र सम्भव होसके, उसके खाने, कपड़े, घर शिक्षा और स्वास्थ्य की न्यूनतम जरूरतें पूरी हों। इस मामले में देश को अपने सामने एक लक्ष्य रखना चाहिये। ये लक्ष्य पांचवीं योजना के अंत तक काफी हद तक पूरी हो जानी चाहिएं। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर जनसाधारण के लिए आयोजन और प्रगति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। असमानता को दूर करने में इससे मदद मिलेगी। इस असमानता को दूर करने के लिए और भी कदम उठाने पड़ेंगे।

सरकारी और निजी क्षेत्र

औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार व्यापार और उद्योग के क्षेत्र सरकारी क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। व्यापार और बड़े पैमाने के उद्योगों में सरकारी उद्योग क्षेत्र का निरन्तर विकास होना चाहिए। विशेषकर भारी और बुनियादी उद्योगों में सरकारी क्षेत्र का विस्तार जरूरी है। देश की अर्थ-व्यवस्था में निजी उद्योग क्षेत्र का विशेष महत्व है। इस क्षेत्र को राष्ट्रीय विकास योजना की परिधि के अन्तर्गत ही अपनी भूमिका अदा करनी होगी, निजी क्षेत्र में सहकारिता को निरन्तर महत्व प्राप्त होता जायगा, विशेषकर कृषि, लघु, उद्योग और खुदरा व्यापार में।

उद्योगों को समुचित प्रोत्साहन दिया जाय, परन्तु समाज, उपभोक्ता और मजदूर के हितों की रक्षा करना जरूरी है। प्रबन्ध में मजदूर को साझेदार बनाना चाहिए। इस दिशा में तेजी से कार्य होना चाहिए। इससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।

मूल्य-स्तर

कम आय वालों पर कीमतों में वृद्धि का तत्काल असर पड़ता है। कीमत बढ़ने के साथ-साथ आय नहीं बढ़ती। यद्यपि सबसे अधिक जोर उत्पादन वृद्धि पर देना है, परन्तु जब अभाव की स्थिति पैदा हो या सप्लाई कम पड़ जाय तो ऐसे कदम उठाये जाने चाहिएं, जिससे उपभोक्ता को

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस मास की आर्थिक घटनाएं

—इग्लैंड में भेड़ें पालने वाले एक अंग्रेज व्यापारी ने एक परीक्षण करके यह ज्ञात किया है यदि सख्त सर्दियों में भेड़ों को जूट का कोट पहिनाया जाय तो वे न केवल अधिक स्वस्थ ही होती हैं, बल्कि उनका ऊन भी मात्रा में अधिक और किस्म में भी अधिक अच्छा होता है। भेड़ों को यह कोट पहिनाने से खर्च भी बहुत अधिक नहीं बैठता। यह कोट पहिनाकर मकान की जरूरत भी नहीं रहती।

—कार्मोडिम कान्फ्रेन्स के सदस्य जहाजी कम्पनियों ने जहाजी भाड़े में एक अगस्त से साढ़े बारह प्रतिशत की वृद्धि की थी। अब इस कान्फ्रेंस के सदस्यों ने भारत सरकार के अनुरोध तथा प्रतिस्पर्धा की आशंका से अपनी दर २॥ प्रतिशत कम कर दी है। भारत सरकार ने साढ़े सात प्रतिशत तक रखने की सलाह दी थी।

—भारत सरकार ने इस मौसम में गन्ने का मूल्य बारह नए पैसे प्रति मन बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही उसने गुड़ के अन्त: राज्यीय यातायात पर भी नियन्त्रण करने का निश्चय किया है। सरकारी वक्तव्य के अनुसार गन्ने की वर्तमान कीमतें आज की आवश्यकताओं को देखते हुए अपर्याप्त थीं। नये निश्चय के अनुसार गन्ने की कीमतें १.५६ रु० से बढ़कर १.६८ रु० हो गई हैं। कुछ क्षेत्रों में जहां गन्ने के मूल्य बहुत अच्छे हैं, मिलें २ रु० मन तक भी ले सकेंगी।

सरकार के इस निश्चय से गन्ने की कीमतें बढ़ने के परिणामस्वरूप चीनी के दाम भी बढ़ेंगे। इससे जहां जनता में असंतोष उत्पन्न होगा, वहां किसानों को भी संतोष नहीं होगा।

—रुपए के बाजार में लगातार बढ़ती हुई तंगी को दूर करने के लिए भारत सरकार जहां दूसरे कदम उठाने का विचार कर रही है, वहां रिजर्व बैंक ने बैंकों के प्रति कुछ उदार नीति स्वीकार की है जिससे कि वे अब पहले की अपेक्षा उद्योगों को अधिक मात्रा में ऋण दे सकेंगे। अब बैंक शेयरों के बदले भी चालीस प्रतिशत ऋण दे सकेंगे।

—योरुप के कामन मार्केट के देशों से भारत सरकार तट-कर में छूट देने की बातचीत कर रही थी। कुछ समय-पूर्व कामन मार्केट के देशों ने १८ वस्तुओं पर छूट की अनुमति दी थी, लेकिन अब यह भी संभावना की जा रही है कि कुछ अन्य वस्तुओं पर भी तट कर में कमी हो जाय।

—योरुप के कामन मार्केट के मुकाबले में पूर्वी योरुप के साम्यवादी देशों ने भी एक संगठन (कौम-कौन) बनाया हुआ है। इस संस्था की कार्य समिति ने सदस्य देशों के लिए एक साझा बैंक बनाने का निश्चय किया है। इस संगठन के सदस्य निम्नलिखित हैं:

सोवियत रूस, बलगेरिया, हंगरी, पूर्वी जर्मनी, पौलैंड, रूमानिया, जैकोस्लोवाकिया और मंगोलिया। अब उक्त बैंक ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अन्य देशों के साथ रुबल की मुद्रा में कारोबार करेगा। साम्यवादी देशों ने विभिन्न देशों को जो ऋण दे रखे हैं, उन सबका लेन देन भी इसी बैंक के द्वारा होगा।

• •

शोषण करने का मौका न मिले। जब बहुत जरूरी हो नियंत्रण या कन्ट्रोल लागू किया जाय। जनता कन्ट्रोल के इतने खिलाफ नहीं जितनी वह दोषपूर्ण प्रशासन के खिलाफ है। कुशल और ईमानदार प्रशासन के द्वारा कन्ट्रोल व्यवस्था को सफल बनाने की कोशिश की जानी चाहिए और जनता का सहयोग प्राप्त करना चाहिए।

भूमि

कांग्रेस की नीति है जो जमीन जोतता-बोता है उसका राज्य से सीधा सम्बन्ध हो और बिचौलिया वर्ग खत्म हो। यह भी जरूरी है कि जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित हो। भूमि सुधार का लक्ष्य ग्रामों की सहकारी अर्थ-व्यवस्था होना चाहिए। देश में भूमि के सुधार का कार्यान्वयन समान ढंग से नहीं हुआ। अगले दो वर्ष में भूमि सुधार कार्यक्रम को पूरा-पूरा लागू करने की ईमानदारी से कोशिश की जानी चाहिए।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सबसे सस्ता सचित्र हिन्दी मासिक

जागृति

जिसे भारत के सभी प्रमुख कवियों,
और कहानीकारों का सहयोग प्राप्त है।
उत्प्रेरक कविताएं, ज्ञानवर्धक लेख, सांस्कृतिक निबंध,
रोचक कहानियां, बाल संसार, साहित्य आगे
बढ़ता है, आदि स्तम्भ
तिरंगा आवरण, अनेकों इकरंगे चित्र
सम्पूर्ण छपाई आर्ट पेपर पर
इस पर भी मूल्य केवल २५ नये पैसे

एजेंटों को ५ से १० प्रतियों पर २५ प्रतिशत और इससे ज्यादा पर ३३⅓ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। डाक का खर्च प्रकाशकों के जिम्मे। एजेन्ट नमूने की प्रति के लिए आज ही लिखें।

—सूचना व प्रकाशन विभाग चण्डीगढ़ (पंजाब)

आरसी

(सचित्र पारिवारिक मासिक)

कहानी * कविता * लेख * कढ़ाई * बुनाई * पाठशाला * माँ और शिशु * ढोलक के गीत * बाल-मन्दिर * चलचित्र-जगत् * पुस्तक परिचय * इसके साथ ही प्रति माह एक कढ़ाई का नमूना उपहार में।

१ प्रति, ५० न० पै० वार्षिक मूल्य ६.०० रु०

आज ही ग्राहक बनिये।

विशेष सूचना—आरसी का अगस्त अंक "राजेन्द्र-स्मृति-अंक" था। एजेन्ट अपनी प्रतियां मंगवा लें।

व्यवस्थापिका, आरसी, श्वाकर टाउन
सिकन्द्राबाद (आ० प्र०)

हिन्दी का एकमात्र
विशिष्ट महिलोपयोगी मासिक

शृङ्गार

- जो सुखी पारिवारिक जीवन का आदर्श पथ-प्रदर्शक है
- जिसे सुप्रसिद्ध लेखिकाओं, लेखकों, पत्रकारों, चित्रकारों कवयित्रियों तथा कवियों का सहयोग प्राप्त है।
- जिसे ५०००० से ऊपर की संख्या में पाठक प्रतिमास पढ़ते हैं।
- जिसकी प्रतियां न्यूज़ एजेन्टों के पास पहुँचते ही समाप्त हो जाती हैं।
- जो महिला जागृति का प्रतीक है।
- जो सबकी प्रिय पत्रिका है।

वार्षिक सात रुपये
एक प्रति : ६० नये पैसे

सम्पादिका : लावण्य प्रभा

कार्यालय १३।३७, शक्तिनगर, दिल्ली-६।

खादी पत्रिका

* खादी ग्रामोद्योग तथा सर्वोदय विचार पर विद्वत्तापूर्ण रचनाएं।
* खादी ग्रामोद्योग आन्दोलन की देशव्यापी जानकारी।
* कविता, लघुकथा, मील के पत्थर, साहित्य समीक्षा, संस्था परिचय।
* सांख्यिकी पृष्ठ आदि स्थायी स्तम्भ।
* आकर्षक मुख पृष्ठ, हाथ कागज पर छपाई।

वार्षिक मूल्य ३) रु., एक प्रति पच्चीस नये पैसे

संपादक—ध्वजाप्रसाद साहू, जवाहिरलाल जैन
राजस्थान खादी संघ, पो. खादीबाग, (जयपुर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

76310

सुभाषित रत्न-माला

दूसरा संस्करण

सम्पादक : कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

८ वर्ष पूर्व इस पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था और हाथों-हाथ बिक गया था कई वर्षों से यह पुस्तक अप्राप्य थी और इसकी मांग निरन्तर बढ़ रही थी। अब परिवर्धित संस्करण आकर्षक रूप सज्जा में प्रकाशित हुआ है। इस संग्रह में पढ़िये -

- वैदिक एवं संस्कृत साहित्य के अगाध भंडार से चुने गये ऐसे सरल सुन्दर श्लोक और मंत्र, जिन्हें छोटे-बच्चे भी सुविधा के साथ कंठस्थ कर सकते हैं।
- प्रत्येक श्लोक और मंत्र का सरल सुबोध हिन्दी में अर्थ।
- पुस्तक के अंत में अर्थ-सहित कुछ ऐसी सूक्तियां, जिनका उपयोग छात्र अपने निबन्धों में कर सकें।

आपके बच्चों के स्वस्थ मानसिक विकास और उनमें नैतिक चेतना जगाने के लिए यह रत्न-माला अनिवार्य है।

उपहार और पुरस्कार देने के लिए बहुत उपयुक्त।

मूल्य एक प्रति रु. १.१५ न. पै.। "सम्पदा" के ग्राहकों से अपनी ग्राहक संख्या लिखने और ८५ न. पै. प्राप्त होने पर "बुक पोस्ट अंडर पोस्टल सार्टिफिकेट" द्वारा भेजी जाएगी।

अशोक प्रकाशन मन्दिर

२८/११ शक्तिनगर, दिल्ली-६

भारत की उद्योग नीति

लेखक :

प्रो० रामनरेश लाल

भारत सरकार ने १९४८ में जो उद्योग नीति निर्धारित की थी, १९५६ में संशोधन के बाद से वही आज भी हमारी उद्योग-नीति का आधार है। इसलिए उद्योग नीति को समझाने के लिए उक्त पुस्तिका का अध्ययन बहुत लाभदायक होगा।

मूल्य : डाक-व्यय सहित ७५ न. पै.

'सम्पदा' के ग्राहकों को अपनी ग्राहक संख्या लिखने और ६० न. पै. का टिकट भेजने पर रियायती मूल्य में यह पुस्तक भेजी जाएगी। वी० पी० से नहीं भेजी जाएगी।

अशोक प्रकाशन मन्दिर,

२८/११, शक्तिनगर, दिल्ली-६

जीवन साहित्य

हिन्दी के उन मासिक पत्रों में से है, जो—

* लोकरुचि को नीचे नहीं ऊपर ले जाते हैं,
* मानव-मानव से लड़ाते नहीं, मिलाते हैं।
* आर्थिक लाभ के आगे झुकते नहीं, सेवा के कठोर पथ पर चलते हैं।

जीवन साहित्य की सात्विक सामग्री को छोटे-बड़े, स्त्री-बच्चे सब निःसंकोच पढ़ सकते हैं। उसके विशेषांक एक से एक बढ़कर होते हैं।

वार्षिक शुल्क ४) रु. भेजकर ग्राहक बन जाइये

ग्राहक बनने पर मंडल की पुस्तकों पर आपको कमीशन पाने की भी सुविधा हो जायगी।

सस्ता साहित्य मंडल

नई दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्या आपको फूलों वाले प्रिन्ट, सुन्दर

धारियां, 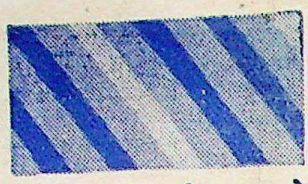 हलके रंग पसन्द हैं ?

चाहे जो आपका चुनाव हो, हमारे यहाँ सभी कुछ उपलब्ध है। डी सी एम की साड़ियाँ हलकी, सुन्दर व टिकाऊ होती हैं...और कितनी सस्ती—रु० १२.१४ से रु० १८.४६ प्रति साड़ी.

डी सी एम के सभी रिटेल स्टोरों, व्होलसेल एजेन्टों व स्टाकिस्टों से प्राप्य हैं.

डी सी एम कपड़ों की सुन्दरता व मज़बूती का प्रतीक

दि दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कं० लि०, दिल्ली.

JWT/DCM 2741 H

सम्पादक—कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा नवचेतन प्रेस (प्रा०) लि० (लांजिज ऑफ अर्जुन प्रेस) दिल्ली-६ से मुद्रित
अशोक प्रकाशन मन्दिर २८/१५, शक्तिनगर, दिल्ली ६ से प्रकाशित।
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा

वर्ष : १२ अंक : १२

मूल्य
न. पै.

अशोक प्रकाशन मन्दिर शक्ति नगर, दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

टैक्समेको

टैक्सटाइल मशीनरी कॉरपोरेशन लिमिटेड,

बेलघरिया, २४ परगना

पश्चिमी बंगाल

भारत के प्रमुख उद्योगों तथा नव-निर्माण में संलग्न

विविध उद्योगों के लिए हमारे उत्पादन

—टैक्सटाइल मशीनरी

—विविध प्रकार के रोलिंग स्टाक

—बायलर्स तथा वाटर ट्यूब बाइलर्स

—स्ट्रक्चलर्स

—शुगर मिल मशीनरी

— स्टील कास्टिंग तथा कास्ट आईरन कास्टिंग

विश्व की ख्याति प्राप्त फर्मों के सहयोग

से कार्यरत

मैनेजिंग एजेन्ट्स

बिरला ब्रदर्स (प्रा०) लि०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंजाब नेशनल बैंक

सेविंग्स खातों के लिए

विशेष सुविधाएं प्रस्तुत करते हैं

★ एक वर्ष में १४० दफा पैसा निकाला जा सकता है।

★ पैसा निकालने के लिए साप्ताहिक या मासिक कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

★ पहले सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं

सदा अपना धन
दि पंजाब नेशनल बैंक लि०
द्वारा बचायें

आधुनिक भारतीय बैंकों में सबसे प्राचीन
देश भर में ४३४ कार्यालय

सम्पदा का १३ वां

विशेषांक

★ १९६४ में शीघ्र ही प्रकाशित होगा लेकिन

★ वह किस विषय पर निकलेगा ?

★ किस महीने में निकलेगा ?

★ क्या विशेषताएँ होंगी ?

★ आदि की जानकारी के लिए

आपको कुछ प्रतीक्षा करनी होगी। यह विशेषांक सभी दृष्टियों से पहले के विशेषांकों से बाजी मार जायेगा, यह विश्वास हम दिला सकते हैं।

व्यवस्थापक

सम्पदा

२८/११ शक्तिनगर दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विषय-सूची

सं०	विषय	लेखक	पृष्ठ
१.	तीसरी पंचवर्षीय योजना की गतिविधि		
२.	सम्पादकीय टिप्पणियां	श्रीश्यामधर मिश्र	
३.	सहकारिता से समाजवाद	श्री रामशंकर तिवारी	४९५
४.	समाजवाद और गांधीवाद में अन्तर	श्री सुभाष	४९९
५.	क्या देश में मौनोपली बढ़ रही है ?		५००
६.	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मूल आधार		५०२
७.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की प्रगति	श्री कृष्णदत्त भट्ट	५०३
८.	आधुनिक अर्थशास्त्र के क्रान्तिकाल—३	कृष्णचन्द्र विद्यालंकार	५०५
९.	वैदिक अर्थ-व्यवस्था	श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल	५०७
१०.	भारत को अमरीकी योगदान		५११
११.	भारत का सीमेंट उद्योग		५१३
१२.	काण्डला : भारत का छठा बड़ा बन्दरगाह		५१६
१३.	नया सामयिक साहित्य		५१७
१४.	बैंक बीमा स्तम्भ—बैंकों पर नये नियंत्रण, जीवन बीमा निगम, कम्पनियों के डिपाजिट		५१९
१५.	सम्पदा का सांख्यिकी पृष्ठ		५२१
१६.	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मण्डल	श्री मोरारजी वैद्य	५२३
१७.	अर्थवृत्त चयन		५२४
१८.	इस मास की आर्थिक घटनाएं		५२६

तुलना न कीजिए .....

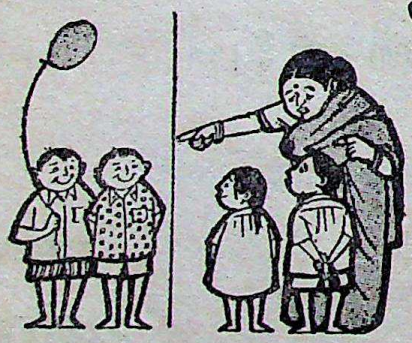

इससे सदैव निराशा होती है। जब आप मेट्रिक बाट व नापों की पुराने बाट जैसे कि सेर आदि से तुलना करते हैं तब भी यही होता है। ऐसा करने से आपका समय नष्ट होता है और लेन-देन में अक्सर नुकसान रह सकता है।

उचित और सुविधाजनक लेन-देन के लिए

मेट्रिक बाटों का प्रयोग कीजिए

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वर्ष : १२
अंक : १२
दिसम्बर : १९६३

सम्पदा

तीसरी पंचवर्षीय योजना की गतिविधि

संसद का शरतकालीन अधिवेशन वस्तुतः आर्थिक प्रश्नों दर विचारगोष्ठी बन गया है । स्वर्ण आभूषण-घोषणा, बैंकिंग और कम्पनी कानूनों में संशोधन, यूनिट ट्रस्ट की स्थापना, चीनी और गुड़ की वर्तमान स्थिति, सरकारी उद्योगों की जांच पड़ताल के लिए एक संसदीय समिति की स्थापना, जीवन बीमा निगम का साधारण बीमा क्षेत्र में प्रवेश आदि अनेक विषयों पर संसद् में विचार किया गया। किन्तु सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण विवाद पंचवर्षीय योजना के मध्याविधि मूल्यांकन पर हुआ है। संक्षेप में जो मुख्य आपत्तियां योजना पर की गई है, वे निम्नलिखित हैं :—

१. राष्ट्रीय आय में लक्ष्य से बहुत कम—६ प्रतिशत के बजाय २.५ प्रतिशत वृद्धि हुई है।

२. कृषि का उत्पादन लक्ष्य से बहुत पिछड़ गया है।

३. उद्योगों का उत्पादन भी लक्ष्य से बहुत कम हुआ है।

४. महंगाई लगातार बढ़ती गई है। इस योजना के प्रथम वर्ष मूल्यों के निदेशक अंक में ३.६ प्रतिशत की कमी हुई थी, किन्तु दूसरे और तीसरे वर्ष क्रमशः ३ और ८ प्रतिशत मूल्य बढ़ गये हैं । इन सबके परिणाम-स्वरूप जनता की असुविधायें बहुत बढ़ गई हैं और जीवन स्तर निरन्तर नीचे गिरता जा रहा है।

५. बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही है।

६. विदेशी मुद्रा की स्थिति भी कठिन होती जा रही है। २१ सौ करोड़ रुपये की मुद्रा मिलने के आश्वासनों के बावजूद हमें अभी ४५० करोड़ रुपये की और सहायता की आवश्यकता है।

७. तीसरी योजना के ३ वर्षों में जो व्यय हुआ है, वह भी कुल लक्ष्यों से बहुत कम है। कृषि और सामुदायिक योजनाओं में हम केवल ५३ प्रतिशत व्यय कर सके हैं, जबकि हमें ६६ प्रतिशत तक खर्च कर देना चाहिये था। इसी तरह छोटी बड़ी सिंचाई योजनाओं, और ग्रामोद्योगों के विकास आदि में भी हम ६६ प्रतिशत की जगह ५२ और ४८ प्रतिशत ही व्यय कर पाये हैं। अन्य उद्योगों की भी यही स्थिति है।

८. समाज सेवाओं की दिशा में भी अभी तक कोई सन्तोषजनक प्रगति नहीं हुई। अधिकांश गावों में पीने का पानी आज भी दुर्लभ है। रद्दी और गन्दे छोटे-छोटे झोंपड़ों में अभी तक करोड़ों जनता निवास करती है। भूमि सुधार और सहकारिता आदि में भी हम अभी तक पिछड़े हुए हैं ।

इसी तरह के अनेक आक्षेप योजना-प्रगति पर किये गये हैं। सार्वजनिक उद्योगों की प्रगति भी बहुत शिथिल हुई है। योजना प्रगति की कठोर आलोचना केवल विरोधी सदस्यों तक ही सीमित नहीं रही, अनेक कांग्रेसी सदस्यों ने भी वर्तमान गतिविधि की कठोर आलोचना की है। सदस्यों ने आलोचना करते हुए गम्भीर असन्तोष प्रकट किया है और योजना आयोग के संगठन तथा सदस्यों तक में परिवर्तन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

करने की राय दी है। सरकार की ओर से इन आलोचनाओं का जो जवाब दिया गया है वह निश्चय से देश को आश्वस्त करने वाला नहीं है। स्वयं योजना मंत्री श्री बलीराम भगत ने अपने भाषण में यह स्वीकार किया है, कि योजना के अनेक लक्ष्य अभी तक पूर्ण नहीं हुए। वे इन कमियों की लीपापोती नहीं करना चाहते, किन्तु वे इसके दूसरे पहलुओं पर सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करके यह बताना चाहते हैं कि योजना को पूर्णतः असफल नहीं कहा जा सकता। यह कम गौरव की बात नहीं है कि चीन के आकस्मिक आक्रमण के बावजूद हम अपनी विकास योजनाओं को चालू रख सके हैं, जबकि देश की रक्षा की तैयारी के कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था पर बहुत भारी बोझ पड़ा है। अनेक सार्वजनिक क्षेत्रों में संतोषजनक प्रगति हुई है। राष्ट्रीय आय भी इतनी न गिरती, यदि मौसम के प्रतिकूल होने के कारण कृषि उत्पादन बहुत कम न होता। स्वयं योजना आयोग ने भी यही रुख लिया है।

आयोग ने योजना की असफलता की जिम्मेदारी मौसम के अलावा अन्य दो तत्वों पर भी डाली है। एक तो निजी क्षेत्र है, जो मिश्रित धातु के पुर्जों, स्टेनलैस स्टील, स्टील, कास्टिंग, मशीन टूल, रासायनिक खाद, सीमेंट, कागज आदि के उत्पादन में अपने लक्ष्यों से बहुत पिछड़ गया है। दूसरे, वे राज्य हैं, जिनमें न लक्ष्यों के अनुरूप अपनी आय के साधन बढ़े हैं, और न कृषि उत्पादन और सामुदायिक योजना में उन्होंने अपना भाग पूरी तरह से अदा किया है। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की सुस्ती, दफतरशाही और अनुभवशून्यता आदि पर भी शिथिलता की जिम्मेदारी डाली गई है।

हम इस बहस में नहीं जाना चाहते कि योजना की शिथिलता के लिए कौन जिम्मेदार है? अनेक कमियों को तो योजना आयोग ने स्वयं स्वीकार किया है। अच्छा होता कि वह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विवाद से अपने को मुक्त रखता। किन्तु हम योजना आयोग के सदस्यों और देश के प्रशासकों से यह नम्र निवेदन अवश्य करना चाहते हैं कि बहस में विरोधियों को चुप करने के लिए वे भले ही कुछ कह दें, अच्छा यह है कि वे इन समस्त आलोचनाओं पर शान्त और तटस्थ दृष्टि से विचार करें। बहुत सम्भव है कि विरोधी सदस्यों द्वारा की गई आलोचनाओं में उन्हें भी सत्य के दर्शन होने लगें।

योजना आयोग में हाल ही में कुछ परिवर्तन हुए हैं। आयोग के नये उपाध्यक्ष श्री अशोक महता का प्रवेश बहुत सम्भवतः नये क्रान्तिकारी दृष्टिकोण को उपस्थित करेगा। प्रो० ठाकुर भी आयोग छोड़ रहे हैं। श्री महता जनता के अधिक सम्पर्क में रहे हैं और उसके दुःख दर्द को शायद ज्यादा जानते हैं। वे स्वयं विदेश यात्रा में सरकार की औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में किये गये प्रश्नों से परेशान हो चुके हैं। स्वयं भारी उद्योग मन्त्री श्री सुब्रह्मण्यम ने उद्योगों पर लगाये गये अनेक नियंत्रणों से हानि को स्वीकार किया है और कहा है कि ये नियंत्रण किसी कार्य को बिलम्बित करने की बजाय कोई लाभ नहीं पहुंचाते। श्री बलीराम भगत नये योजना मन्त्री बने हैं। हम योजना आयोग के सदस्यों और प्रशासकों से पुनः यह अनुरोध करना चाहते हैं कि वे दूसरों पर जिम्मेदारी न डाल कर स्वयं यह सोचें कि क्या उनकी नीति में ही कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है? क्या देश के सामर्थ्य को देखते हुए उन्होंने ऐसी महत्वाकांक्षापूर्ण योजना नहीं बनाई है, जो पूर्ण न हो सके अथवा अपने आदर्शवादी दृष्टिकोण में वे वास्तविक तथ्यों की ही उपेक्षा नहीं कर रहे हैं? मौसम की प्रतिकूलता का तर्क जनता को सन्तोष नहीं दे सकता। यदि भारत की शस्यशामल भूमि को सुजला बनाया जाय तो अनावृष्टि बहुत दुःख नहीं देगी। बड़े उद्योगों पर इतना अधिक ध्यान देना कि उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन कम हो, जनता के कष्ट का कारण बनता है। यदि इन प्रश्नों पर किसी प्रकार पूर्वाग्रह छोड़ कर विचार किया जायगा, तो हमें निश्चय है कि हम योजना के लक्ष्य वास्तविक बना सकेंगे और अनेक आलोचनाओं से बच सकेंगे।

स्वर्गीय श्री कैनेडी

अमेरिका के महान् राष्ट्रपति श्री कैनेडी मानवता की वेदी पर अपने पुनीत बलिदान के द्वारा विश्व के इतिहास में अपना नाम अमर कर गये हैं। इस बलिदान पर संसार के सभी देशों ने अपनी श्रद्धांजलि प्रकट की है। हम भी सम्पदा के पाठकों की ओर से उस दिवंगत आत्मा के प्रति

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

श्री कैनेडी का जीवन अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण रहा है। काले गोरे के भेदभाव को समाप्त करने के मानवता पूर्ण उद्देश्य के लिए तो उनका बलिदान ही हुआ है। विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति-स्थापना के लिए उन्होंने जो महान् प्रयत्न किये, उनका भी अपना विशेष महत्त्व है। सदा प्रतिस्पर्धी व शक्तिशाली रूस के साथ वे अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर रहे थे और जहां भी संघर्ष के अवसर आये, वहां उन्होंने अत्यन्त दृढ़ता व विवेक से काम लिया। क्यूबा, बर्लिन, अणुशस्त्रों के परीक्षण तथा वीयतनाम के सम्बंध में उन्होंने जो कुछ किया, उससे उनके गौरव की वृद्धि हुई।

दो अन्य कारणों से भी स्व० कैनेडी का नाम स्मरणीय है। स्वयं अमेरिका के आर्थिक विकास में उनका शासनकाल प्रशंसनीय रहा। तीन वर्ष पूर्व अमेरिका का राष्ट्रीय उत्पादन ५०० बिलियन (५०० अरब) डालर था, अब ६०० बिलियन के करीब हो गया है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार ७ करोड़ नरनारी काम पर लगे हुए थे। कारखाने के कारीगर की औसत आमदनी १०० डालर साप्ताहिक से अधिक हो गई थी। टैक्स आदि देने के उपरान्त कम्पनियों की आमदनी ४३ प्रतिशत बढ़कर तीन वर्षों में २७.४ बिलियन डालर वार्षिक हो गई थी। मूल्य भी अपेक्षाकृत स्थिर रहे थे। वैज्ञानिक प्रगति, अणुविज्ञान तथा अन्तरिक्ष यात्रा की दिशा में जो अरबों डालर व्यय हुए तथा अमेरिका ने जो सफलता प्राप्त की, उसका गौरव भी श्री कैनेडी के शासनकाल को है।

हम भारतवासी भी श्री कैनेडी के प्रति विशेष कृतज्ञ हैं। भारत की विकास योजनाओं में तथा चीन के आकस्मिक नृशंस आक्रमण से रक्षा के लिए अमेरिका ने जो अमित सहायता प्रदान की है, भारतीय भुला नहीं सकते। इन पंक्तियों में उनका विवरण देने का न स्थान है, न आवश्यकता। वे तो बोकारो के लोह-संयत्र के लिए भी करोड़ों रुपया देना चाहते थे, परन्तु भारतविरोधी तत्त्वों ने उन्हें देने नहीं दिया। केवल भारत ही नहीं, अन्य अविकसित देशों के भी आर्थिक विकास में वे अनवरत सहायता देने के प्रबल समर्थक थे।

वे महान् स्वप्न द्रष्टा थे। अमेरिका के नव राष्ट्रपति श्री जौनसन ने अपने भाषण में उनके कुछ स्वप्नों का उल्लेख इस तरह किया है: अतलांतक समुद्र पार के देशों से सहयोग, कम विकसित देशों में शान्तिदल, देश के समस्त बालकों के लिए शिक्षा, सबको रोजगार, वृद्ध लोगों की चिन्ता, मानसिक रोगों के विरुद्ध जोरदार जहाद और सबसे अधिक अमेरिका के सब लोगों के लिए समान नागरिक अधिकार।

उस महान् दिवंगत आत्मा की स्मृति उनकी भावनाओं की पूर्ति से हो सकेगी और समस्त विश्व को, विशेषकर अमरीका को अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए।

पिछले अनुभवों से लाभ

सिद्धान्त या आदर्श बहुत सुन्दर होते हैं। उनके पालन का सदा प्रयत्न करना चाहिए, किन्तु उन पर सदा जड़वत् आग्रह व्यावहारिक नहीं होता। समय-समय पर परिस्थितियां लचकीलेपन के लिए विवश कर देती है। जो इन परिस्थितियों की उपेक्षा करने का दुःसाहस करता है, वह खतरा उठाता है। यह हर्ष की बात है कि योजना आयोग भी अनुभवों की अब उपेक्षा नहीं करना चाहता। उद्योगों का विकेन्द्रीकरण एक अच्छा सिद्धान्त है। समस्त देश में उद्योगों का समान वितरण करने का प्रयत्न करना चाहिए, परन्तु इसका कठोरता से पालन कभी-कभी बाधक भी बन जाता है। इसलिए योजना आयोग ने उद्योग खनिज, परिवहन और बिजली के भावी लक्ष्यों का निर्धारित करने वाली कार्य-मण्डलियों को सुझाव दिया है कि परियोजनाओं का स्थान चुनने में इसका पूरा ध्यान रखा जाय कि वहां परिवहन, बिजली, पानी तथा नगर बसाने आदि की कितनी सुविधाएं हैं। इसका ध्यान न रखने से उद्योगों की स्थापना में जहां विलम्ब लग जाता है, वहां उत्पादन-व्यय भी बहुत अधिक बढ़ जाता है।

पिछले अनुभवों से लाभ उठाकर योजना आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि किसी विशेष परियोजना को शुरू करते समय विभिन्न कार्यविधियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए। आयोग का विचार है कि पिछली योजना के कार्यक्रम चुनने से पहले उनकी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लागत और लाभ का ब्योरेवार अनुमान नहीं लगाया गया।

हमारा एक बड़ा अनुभव यह है कि हम अपनी सामर्थ्य की चिन्ता किये बिना महत्वकांक्षापूर्ण वृहदाकार योजनाएं बना लेते हैं, जिनमें पीछे से काट छांट करनी पड़ती है। योजना आयोग का विचार है कि भविष्य में योजना इतनी बड़ी नहीं बनाई जानी चाहिए कि समय पर लक्ष्य पूरे न हो सकें। इसलिए भविष्य में वह कार्यक्रम योजना में शामिल नहीं किया जाएगा, जिसकी अवधि में पूरा होने की सम्भावना न हो। योजना आयोग, चौथी योजना को अन्तिम रूप देने से पहले विदेशी मुद्रा तथा प्रारम्भिक काम की मंजूरी के लिए भी कार्रवाई शुरू कर देना चाहता है। अनुभवों से लाभ उठाना और नारे बाजी पर दुराग्रह अन्त में हानि कारक ही सिद्ध होता है। ● ●

राष्ट्रीय आय का वितरण

श्री प्रशान्तचन्द्र महालनवीस (योजना आयोग के सदस्य) की अध्यक्षता में एक समिति करीब दो वर्ष पूर्व बनाई गई थी। यह समिति अब मालूम हुआ है, कि शीघ्र ही अपनी यह रिपोर्ट देगी, कि पिछले १०-१२ वर्षों में राष्ट्रीय आय में ४२ प्रतिशत की जो वृद्धि हुई है, उसका वितरण कैसे हुआ है। प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दूसरी योजना की समाप्ति पर यह आश्चर्य प्रकट किया था कि राष्ट्रीय आय में इतनी अधिक प्रतिशत वृद्धि होने पर भी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम बढ़ी है। यह बढ़ी हुई आय आखिर गई कहां? इसी प्रश्न के निर्णय के लिए श्री महालनवीस की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। यह समिति अब शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट देने वाली है। हम नहीं जानते कि यह समिति किस परिणाम पर पहुँचेगी। लेकिन पिछले दिनों अनेक उत्साही वक्ताओं ने समय समय पर यह आलोचना की है, कि सरकार की वर्तमान योजनाओं और कार्य-नीति का परिणाम यह हुआ है, कि अमीर ज्यादा अमीर हो गये हैं, और गरीब ज्यादा गरीब। इसी प्रश्न पर कलकत्ते में विवेचना करते हुए श्री कृष्णकुमार बिड़ला ने अपने भाषण में बताया है कि—

"सम्पत्ति-कर के सम्बन्ध में जो नवीनतम आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, उनसे अनेक तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है। १९६०-६१ और १९६१-६२ में जिन पर सम्पत्ति कर लगाया है, वे प्रायः दो लाख और १२ लाख रु० के बीच हैं। १९६१-६२ में २३८१५ लोगों पर सम्पत्ति-कर लगाया गया है। इनमें २२,४०७ ऐसे व्यक्ति थे, जिनकी सम्पत्ति २ लाख से १२ लाख रु० के अन्दर-अन्दर थी। जिनकी सम्पत्ति १२ लाख से ऊपर थी, ऐसे व्यक्ति कुल १४०८ थे। महत्व की बात यह है कि कम सम्पत्ति वाले करदाताओं की संख्या बढ़ गई है, जबकि ऊंचे स्तर के सम्पत्ति करदाताओं की संख्या कम हो गई है। प्रति व्यक्ति औसत सम्पत्ति का भी स्तर नीचे गिरा है। प्राप्त विवरण से मालूम होता है कि ५० लाख से ऊपर सम्पत्ति रखने वालों की संख्या कम हो रही है। १९६०-६१ में यदि ऐसे व्यक्ति १९१ थे, तो १९६१-६२ में ऐसे व्यक्ति १६५ रह गए हैं, अर्थात् उनमें १४ प्रतिशत की कमी हुई है। यदि यही रफ्तार रही, तो वह दिन दूर नहीं है, जबकि ऐसे सम्पत्तिशाली वर्ग का लोप हो जाएगा।"

अपने विचार की पुष्टि में उन्होंने आय-कर के भी कुछ अंक उपस्थित किये हैं। इन अंकों के अनुसार १९५६-५७ और १९६१-६२ के बीच में कम आय के लोगों की न केवल संख्या बढ़ी है, बल्कि उनकी ओर से दी जाने वाली आय-कर की रकम भी बढ़ गई है। इसके विपरीत ऊंची आय वाले लोगों की संख्या कम हो गई है। १५,००० रु० तक की आय वाले करदाताओं की संख्या ४,२२,३२८ (१९५६-५७) से बढ़कर १९६१-६२ में ८,२०,४४१ अर्थात ९५ प्रतिशत बढ़ गई है। कर-योग्य आय भी २९४.९५ करोड़ रु० से बढ़कर ५११.९६ करोड़ अर्थात ७५ प्रतिशत बढ़ गई है। दूसरी ओर २ लाख रु० से ऊपर आय वालों की संख्या ६५० से गिरकर ५४३ अर्थात ६ प्रतिशत गिर गई है। इन कर-दाताओं की कर योग्य आय भी २७.०७ करोड़ रु० से गिरकर २०.१० करोड़ अर्थात २६ प्रतिशत गिर गई है।"

इन अंकों से पता चलता है, कि सम्पत्ति का वितरण बंटता गया है। किन्तु इस प्रश्न पर हम अन्तिम विचार तभी कर सकेंगे, जब श्री महालनवीस की विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित हो जायगी। तभी इस प्रश्न के विविध पहलुओं पर कुछ अधिक प्रकाश पड़ सकेगा। ● ●

सम्पद

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

औद्योगिक प्रगति के पथ पर

यों तो प्रत्येक वर्ष ही भारत की औद्योगिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण होता है; तथापि पिछला मास अनेक दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण रहा है । प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने रांची में बड़ी मशीनें बनाने वाले-कारखाने का उद्घाटन करके देश में एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय का सूत्रपात किया है । हैवी इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन की ओर से स्थापित तीन इकाइयों में से यह एक इकाई है । यह कारखाना भारी मशीनरी तैयार करेगा। हम बहुत अधिक समय तक कारखानों की मशीनों के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रह सकते ।

कोयला खानों के लिए मशीनें बनाने वाले एक संयंत्र का उद्घाटन भी प्रधान मंत्री ने दुर्गापुर में किया । यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है । चित्तरंजन के कारखाने से ए. सी. बिजली के रेलवे इंजन का रेलमार्ग पर आ जाना अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है । बिजली के इंजन जब देश में बनने लगे हैं; तब देश अपनी बहुत सी विदेशी मुद्रा बचा सकता है ।

जहां औद्योगिक क्षेत्रों में यह क्रान्तिकारी कदम बहुत हर्ष व गौरव का विषय है, वहां कृषि की उपेक्षा करना बहुत अनुचित होगा । देश की समस्त अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कृषि ही है । कृषि उत्पादन से ही न केवल राष्ट्रीय आय बढ़ सकती है, अपितु प्रति व्यक्ति आय बढ़ने में भी बहुत सहायता मिलेगी ।

यूनिट ट्रस्ट

संसद ने इस अधिवेशन में यूनिट ट्रस्ट आफ़ इण्डिया बिल स्वीकृत कर लिया है । इसके अनुसार ट्रस्ट का बोर्ड ९ सदस्यों का होगा और वे रिजर्व तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा मनोनीत होंगे । इसकी अधिकांश पूंजी भी इन्हीं के द्वारा प्राप्त होगी । जीवन बीमा निगम भी इसके शेयर खरीदेगा। इस ट्रस्ट को किसी प्रकार का आय कर और अग्निकर आदि नहीं देना पड़ेगा । यूनिट होल्डरों को १००० रुपये तक की आय-कर से छूट मिल गई है । खर्च निकाल कर ९० प्रतिशत लाभांश बांटा जायगा । इस कारण इसे हानि की सम्भावना नहीं है । यह ट्रस्ट किसी भी कम्पनी के शेयर खरीद सकता है । इसलिए कुछ लोगों को यह संदेह है, कि सरकार को इससे किसी भी कम्पनी के राष्ट्रीयकरण में सुविधा हो जायगी ।

सेंचुरी मिल्स बम्बई की प्रसिद्ध फैशन फ्रैब्रिक्स

★ असली आरगंडी ★ लेक्स ब्यूटी मलमल ★ मोती वायल और फुल वायल
★ परमसुख धोती ★ एम्बास्ड प्रिंट्स ★ खादी और धारीदार पाप्लीन,
नित्य नवीन डिजाइनों में छपी हुई चमकदार छींट, लट्ठा, ड्रिल्स, चादरें, तौलिये,
काटन वेस्ट, कम्बल, आदि आदि

नवीन आकर्षण

प्रिश्रङ्क—सेंचुराइज्ड शर्टिंग, पाप्लीन और ड्रेस मेटीरियल

★ निर्माता ★

दी सेंचुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कं. लि.

इन्डस्ट्रीज हाउस, १५९ चर्चगेट, रिक्लेमेशन बम्बई

मैनेजिंग एजेंट्स : बिरला ग्वालियर प्रा० लि०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रक्षा और

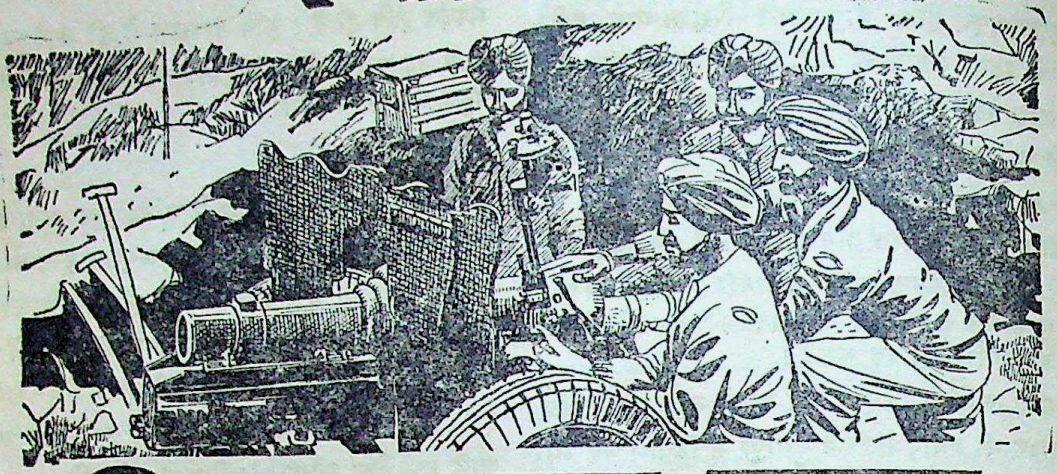

विकास का काम

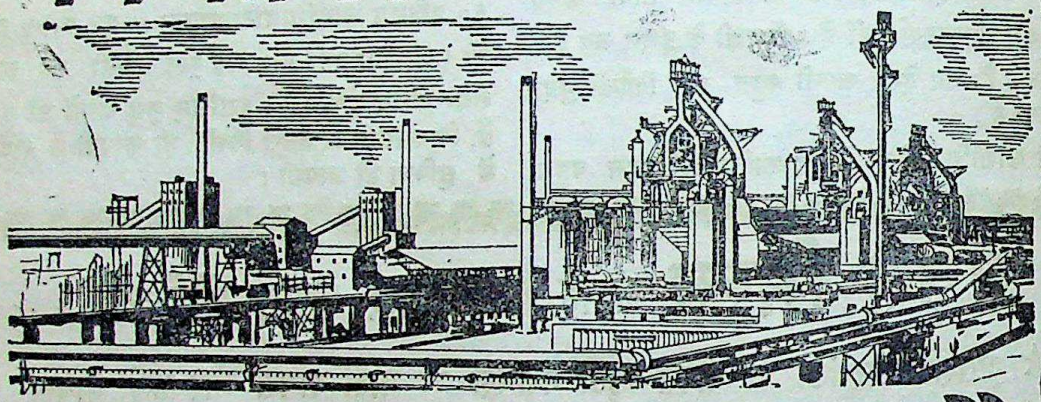

साथ साथ चलता है

देश की विकास योजनाएं हमारी रक्षा-व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं। संकट का सामना करने के लिए नई प्राथमिकताएं निश्चित की गई हैं और बिजली योजनाओं, इस्पात, मशीन, मशीनी औजार, बिजली का साज-सामान, कोयला खनन, रेलवे जैसे बुनियादी उद्योगों, इंजीनियरी और चिकित्सा कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर तेजी से अमल करने की व्यवस्था की गई है।

शक्ति की ठोस बुनियाद पर ही रक्षा की तैयारी निर्भर करती है। यही हमारी समस्या का एकमात्र हल है।

इस कार्य में मन, वचन और कर्म से पूरा पूरा सहयोग दीजिए। भारत के करोड़ों नागरिकों की निरन्तर और निस्वार्थ सेवा-भावना और कठोर परिश्रम से ही देश की रक्षा-सामर्थ्य बढ़ सकती है।

योजना को सफल बनाइये

भारत की रक्षा-व्यवस्था को सुदृढ़ कीजिए

डी ए-६३/३६४

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सहकारिता से समाजवाद

श्री श्यामधर मिश्र

ब्रिटेन के प्रसिद्ध नेता विलियम ग्लैडस्टन की राय में सहकारिता का सिद्धान्त १९वीं शताब्दी का सबसे बड़ा आर्थिक आविष्कार है। वास्तव में सहकारिता पूंजीवाद और साम्यवाद का मध्यम मार्ग है।

पूंजीवाद में मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति प्रधान होती है और इस देश का धन क्रमशः बटुर कर कुछ लोगों की मुट्ठी में जमा होता है। पूंजीवाद का आधार यह है कि उद्योग-व्यापार में कोई हस्तक्षेप न किया जाय और जो आदमी जितना कमा सके, उसे कमाने दिया जाय। अर्थात् मुनाफा कमाने की होड़ाहोड़ पर कोई रोकटोक न हो। इस होड़ में वही टिकेगा, जो सबसे तगड़ा होगा। छोटे और कमजोर व्यापारी खतम हो जाएंगे। फलतः विशालकाय उद्योग या व्यापार के साम्राज्य कायम होते हैं। दूसरी तरफ साम्यवाद में, इस प्रकार की हानिकर प्रतियोगिता को रोका जाता है और उत्पादन, वितरण और विनिमय के सब साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है।

इन दोनों पद्धतियों में आर्थिक शक्ति सिमटकर थोड़े से लोगों की मुट्ठी में आ जाती है। कहने को तो पूंजीवादी व्यवस्था में प्रतियोगिता को खुली छूट दी जाती है, लेकिन वास्तव में बड़ी कम्पनियों और कारबारों के सामने कोई व्यक्ति या छोटा कारबार टिक नहीं सकता और प्रतियोगिता की स्वतंत्रता नाम को ही रह जाती है, क्योंकि बड़ी-बड़ी कम्पनियां न केवल भाव निश्चित करती हैं, बल्कि यह भी तय करती हैं कि कितना माल बने और कैसे उसका वितरण हो। अस्तु, व्यावहारिक रूप में पूंजीवादी व्यवस्था भी नियंत्रित व्यवस्था ही होती है। साम्यवाद में इससे भी बुरी हालत होती है। साम्यवादी व्यवस्था या सरकारी पूंजीवाद में सारे काम-धन्धे सरकारी संस्थाओं के हाथ में होते हैं। इसलिए पूंजीवाद और साम्यवाद इन दो छोरों के बीच लोकतंत्री समाजवाद सुन्दर मध्य मार्ग है। अब कुछ पूंजीवादी देश भी लोकतंत्री समाजवाद की ओर झुकने लगे हैं। इस व्यवस्था में उत्पादन और वितरण का काम केन्द्रित नहीं हो पाता। अधिकतर उत्पादन और वितरण का काम जनता के हाथ में ही होता है। यह व्यवस्था सहकारी व्यवस्था से, जिसका जन्म १९वीं शताब्दी में हुआ, बहुत कुछ मिलती है।

सहकारिता क्या है?

सहकारिता, परस्पर सहयोग से स्वावलम्बन का प्रयत्न है। सहकारिता का आधार लोकतंत्र है। इसमें सहयोग पर जोर दिया जाता है, पूंजी पर नहीं। सहकारी काम-धन्धे का स्वामित्व पंचायती होता है। सहकारी संगठन में प्रत्येक सदस्य का केवल एक वोट होता है, चाहे उसके पास कितने ही शेयर हों। एक व्यक्ति, निर्धारित संख्या से अधिक शेयर नहीं खरीद सकता। इसी तरह लाभांश पर भी नियंत्रण होता है। जितना लाभ होता है, उसका एक अंश ही, हिस्सेदारों को मिलता है, बाकी सबके हित के कामों में लगाया जाता है। सहकारी या सांझे प्रयत्न से गरीब और साधनहीन व्यक्ति मिलकर वे काम कर सकते हैं, जो अकेले नहीं किया जा सकता। जो काम मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति से नहीं हो सकता, वह सेवा और सहयोग की भावना से किया जा सकता है।

जो काम व्यापारी संस्थाएं नहीं कर सकती हैं, वह सहकारी संस्थाएं कर सकती हैं, मसलन लोगों को सस्ती चीजें देना।

अमरीका का उदाहरण

१९३५ में अमरीका में केवल १० प्रतिशत गांवों में खेती या घरेलू कामों के लिए बिजली उपलब्ध थी। बाद में सहकारी ढंग से बिजली पैदा करने और उसके वितरण का प्रबन्ध किया गया, और २० वर्षों के अन्दर ही २५ प्रतिशत अमरीकी खेतों में बिजली पहुँच गई। बड़ी बिजली कम्पनियां गांवों में बिजली लगाने को तैयार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नहीं थीं, क्योंकि इससे उनका खर्च बढ़ता और मुनाफा घटता। इसलिए सहकारियों ने यह काम अपने हाथ में लिया और उसे बखूबी पूरा किया।

अमरीका में धन का केन्द्रीकरण

निजी उद्योगों के कारण अमरीका में पूंजी थोड़े लोगों के हाथों में इकट्ठी होती गई। बड़े उद्योगों के मुकाबले छोटे उद्योगों का टिकना असम्भव हो गया। अमरीका में ८५ प्रतिशत व्यापार बड़ी कम्पनियों के हाथ में है। केवल २ प्रतिशत व्यापार सहकारियों के हाथ में है। लेकिन इनके हिस्सेदारों की संख्या बड़ी कम्पनियों के हिस्सेदारों की ढाई गुनी है। १९५६ में अनुमान लगाया गया था कि लगभग ५० बड़ी कम्पनियों के हाथ में अमरीका की ६० प्रतिशत उत्पादन-क्षमता है। और यही रुख रहा तो १९७८ तक देश के सभी कारखाने इन्हीं कम्पनियों के हाथ में आ जाएंगे। इस तरह उत्पादन और वितरण पर चन्द लोगों का कब्जा हो जाने से कितना और कैसा माल बनाया जाए, और किस दाम पर बेचा जावे, इसका निर्णय भी थोड़े से लोगों के हाथ में हो जाता है। एक क्षेत्र में एकाधिकार होने से, दूसरे क्षेत्रों पर भी एकाधिकार होता जाता है और अखबार भी इस इजारेदारी से नहीं बचे हैं, जिनसे उनकी स्वतन्त्रता पर काफी गहरा आघात पहुँचा है। अमरीका में ९० प्रतिशत चीजों का भाव, बड़ी कम्पनियां तैयार करती हैं। इन भावों का खर्च या लागत से कोई सम्बन्ध नहीं होता।

१९५९ में इस्पात और मोटरगाड़ियों का निर्माण, मांग से बहुत अधिक था, लेकिन इसके बावजूद उनके दाम घटने के बजाय बढ़ गये। इससे पता चलता है कि थोड़े से लोगों की मुट्ठी में आर्थिक शक्ति और पूंजी के चले जाने से जनसाधारण का कैसा शोषण होता है। इससे बचने का उपाय सहकारी संगठन है।

सहकारी संगठन ही एकाधिकार का मुकाबला कर सकता है। छोटे कारबार सहकारी संगठन बनाकर बड़ी कम्पनियों का मुकाबला कर सकते हैं।

भारत में सहकारी आन्दोलन

भारत में लगभग ३ लाख सहकारियां हैं, जिनके ३ करोड़ ३६ लाख सदस्य हैं और उनकी कुल हिस्सा-पूंजी २२० करोड़ रु० होती हैं। देश में लगभग १९,००० निजी कम्पनियां है, जिनकी चुकता पूंजी लगभग १००० करोड़ रु० है। इससे जाहिर है कि निजी कम्पनियों में पूंजी कितने थोड़े लोगों के हाथों में जमा है।

उदाहरण के लिए शक्कर उद्योग को देखिये। देश में लगभग १७५ शक्कर कारखाने हैं, जिनमें ३० सहकारी कारखाने हैं। लेकिन हर सहकारी चीनी कारखाने के हिस्सेदार २००० से ४००० किसान हैं, जबकि निजी चीनी कारखानों का स्वामित्व इने-गिने लोगों के हाथ में है। अर्थात् सहकारी चीनी कारखानों का लाभ बहुत से लोगों को मिलता है, जबकि निजी कारखानों का कम लोगों को। फिर सहकारी चीनी कारखाने घाटे पर भी नहीं चलते। इसलिए और चीजों के भी सहकारी कारखाने खुल रहे हैं, जैसे उर्वरक, सूती कपड़ा, पटसन और फल के पदार्थ तैयार करने के कारखाने। इन कारखानों की प्रगति से, समाजवादी ढंग समाज की स्थापना में ही मदद नहीं मिलेगी, बल्कि लोकतंत्र की जड़ें भी मजबूत होंगी।

जापान में खेती की जिन्सों को बनाने और बेचने की सहकारियां, अमरीका की ग्रीन बेल्ट (उपजाऊ क्षेत्र) की उपभोक्ता सहकारियां और ब्रिटेन, प० जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क और नार्वे की सहकारी दुकानें, सहकारी सफलता के बड़े अच्छे उदाहरण हैं। इन सहकारियों से लोगों को उचित भाव पर सामान ही नहीं मिलता, बल्कि लोगों में सहयोग का भाव भी पैदा होता है। स्वीडन में सहकारी दुकानों के खुलने से बिजली के लट्टुओं की कीमत ४० प्रतिशत घट गई। इसी तरह दूध, मक्खन, डबल रोटी, बिस्कुट, जूते, चीनी मिट्टी के बर्तन और अन्य जिन्सों के दाम भी घटे।

भारत में भी पिछले दस वर्षों में, सहकारी बैंकों की मार्फत किसानों को खेती के लिए ऋण की काफी सुविधाएं मिली हैं और ब्याज की दर भी घटी, जिससे खेती को बढ़ावा मिला। साहूकार लोग किसानों से पहले २० से ३० प्रतिशत वार्षिक ब्याज लेते थे, लेकिन सहकारी बैंकों के कारण, अब वे १०-१५ सैकड़े से अधिक ब्याज नहीं ले पाते। सहकारियों के मुनाफे का कुछ अंश हिस्सेदारों को मिलता है और बाकी सबके हित के कामों के लिए रखा जाता

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गुरुकुल कांगड़ी

है। इससे सहकारी अस्पताल, होटल, रेस्टोरां, स्कूल आदि खोले गए हैं। सहकारियों के कारण लोगों की दशा भी सुधरी है।

सहकारियों में हर सदस्य अपना मालिक है, जबकि बड़ी कम्पनियों में हिस्सेदारों की कोई आवाज नहीं होती। सहकारी में तो प्रत्येक स्वयं काम करने वाला, भोगने वाला और वितरक होता है। सहकारियों को मालिक-मजदूरों के झगड़ों का सामना नहीं करना होता। सहकारियों के सदस्य, स्वयं मजदूर और मालिक दोनों होते हैं।

सहकारी बीमा

जहां-कहीं भी बीमा सहकारियां शुरू की गईं, उन्हें सफलता मिली। अगर सहकारियों को देश के आयात और निर्यात व्यापार में भी हिस्सा मिले तो कम दाम पर सामान बना और बेच सकती हैं। अगर सहकारियों को विभिन्न उद्योगों में थोड़ा-थोड़ा भाग भी दिया जाए, तो निजी कम्पनियों पर उसका प्रभाव पड़ेगा और उपभोक्ता को फायदा पहुँचेगा।

सहकारिता आन्दोलन में बाधाएं

सहकारिता आन्दोलन में फिलहाल अनेक अड़चनें और त्रुटियां हैं। यह आन्दोलन अभी बचपन में ही है। नये विचार आ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह अमल में नहीं लाये गये हैं। सहकारियों के प्रबन्ध की समस्या भी काफी बड़ी है। सहकारियों में हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, क्योंकि सदस्यों के सम्मिलित प्रयत्न से ही सहकारियां सफल होती हैं। अधिकांश व्यक्तियों को व्यापार का अनुभव नहीं होता, इसलिए अभी सहकारियां कुशलता से नहीं चल पातीं।

सहकारियों का संगठन भी अभी मजबूत नहीं है। सहकारी कार्यकर्त्ता और संस्थाओं में सहयोग अभी नहीं के बराबर है। सहकारी समितियां अपनी सफलता पर ही सन्तोष कर लेती हैं, वे सहकारिता आन्दोलन को बढ़ाने में उत्साह नहीं दिखाती हैं। अनेक सहकारियां, दूसरी सहकारियों की मदद करने में हिचकती है। अधिकांश विज्ञापन नहीं करतीं। उनका बढ़ाव भी तेजी से नहीं होता। व्यापारी कम्पनियों के ही समान, सहकारियां भी फेल होती हैं, लेकिन सहकारियों की छोटी-छोटी विफलताओं को भी बहुत बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है।

संसार के सभी देशों में सहकारियों का तेजी से विकास हो रहा है। साम्यवाद का जवाब पूंजीवाद से नहीं दिया जा सकता। साम्यवाद से बचने का असली उपाय तो सहकारी व्यवस्था को बढ़ाना है। इन्डोनेशिया सहकारियों का तेजी से विकास करके ही साम्यवाद के चंगुल से बच सका। मिस्र में पैट्रोल की चीजों की ४ प्रतिशत बिक्री सहकारियों की मार्फत होती है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी सहकारिता बढ़ रही है। अन्तर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम सहकारी संघ के सदस्यों में अमरीका, स्वीडन, मिस्र, हालैंड, फ्रांस, नार्वे, यूगोस्लाविया, जर्मनी, इजरायल और लगभग १२ अन्य देश हैं। अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन बन सकता है। सहकारिता देश में ही नहीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी मेल-मिलाप को बढ़ावा देती है।

समाजवादी समाज रचना में सहकारिता का योग

हमारा लक्ष्य देश में समाजवादी ढंग का समाज बनाना है। पंचवर्षीय योजनाओं और विधानों, कानूनों तथा आर्थिक नीतियों और उपायों से हम इस लक्ष्य को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम चाहे जितने कड़े कानून बनाएं, केवल उनसे ही पूंजी को थोड़े से लोगों के हाथ में जाने से नहीं रोक सकते। इसके लिए सभी क्षेत्रों में सहकारियों को बढ़ावा देना जरूरी है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सभी मंत्रालयों और विभागों को मिलकर सहकारी संगठन को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। जब तक हम सहकारिता को, अपनी राष्ट्रीय नीति और साधन के रूप में न अंगीकार करेंगे, हम तेजी से विकास नहीं कर सकेंगे। उत्पादन और व्यापार सहकारियों के अलावा, हमें काफी संख्या में श्रम व इमारती सहकारियां भी बनानी चाहिएं। सहकारियों को यदि स्थापत्य के बड़े काम सौंपे जाएं, तो हम ठेकेदारी से छुटकारा पा सकते हैं और धन की विषमता हटाने का रास्ता साफ कर सकते हैं।

●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समाजवाद और गांधीवाद में अन्तर

(श्री रामशंकर तिवारी)

मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों के पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में विद्वानों के भिन्न-भिन्न विचार हैं। गांधीजी के कुछ अनुयायियों ने इन दोनों विचारधाराओं में कोई आधारभूत अन्तर नहीं माना है और इसके विपरीत कुछ के अनुसार यह कहना अधिक अनुपयुक्त न होगा कि दोनों दर्शन केन्द्र से दो ध्रुवों के समान एक दूसरे के विपरीत और दूर हैं। उनके अनुसार—दोनों में कोई स्वर नहीं है। इसके विपरीत प्रथम श्रेणी के विचारक दोनों के मध्य किसी भी प्रकार की विभाजन रेखा के अस्तित्व को स्वीकार करने को तत्पर नहीं। श्री कुमारप्पाजी का विचार है कि रूस में गांधीजी के सिद्धांतों का पालन किया जा रहा है, किंतु यह सही प्रतीत नहीं होता। यह कहना कि गांधीवाद और साम्यवाद एक ही चीज है, दोनों के साथ अन्याय करना होगा।

संभवतः इस विवाद के जन्म का मूल कारण स्वयं गांधीजी के कुछ विचार थे, जो उन्होंने हरिजन पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किये और अपने विचारों को समाजवादी नाम दिया। लुई फिशर द्वारा उद्धृत गांधीजी के इस कथन से इस प्रकार का निष्कर्ष निकाला जाना स्वाभाविक ही था कि "आज समाज में भारी असमानता है। समाजवाद का आधार ही आर्थिक समानता है। आज की असमानता ईश्वरीय नियम नहीं है कि कुछ लोग सोने चांदी में खेलें और कुछ को खाना भी नसीब न हो। मैं तब भी समाजवाद के सिद्धांत को मानता था, जब दक्षिणी अफ्रीका में था।" इसी प्रकार अनेक स्थलों पर उन्होंने कहा कि वे सच्चे समाजवादी हैं। किंतु इस उनके कथन से दोनों विचारधाराओं का अन्तर स्पष्ट हो जाता है।

"साम्यवाद से मेरा वहां मतभेद है, जहां यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा का आश्रय लेता है।"

भीषण अन्तर

इस दृष्टि से देखा जावे तो दोनों वादों में अगर कहीं समानता है, तो वह गरीबों एवं शोषित वर्ग के प्रति तीव्र सहानुभूतिपूर्ण रचनात्मक कार्य से सम्बन्ध रखने में है। किंतु सम्भवतः इन्हीं विचारों को ध्यान में रख श्री जे. सी. कुमारप्पा ने गांधीवाद और साम्यवाद के सम्बन्ध को इस प्रकार स्पष्ट करना चाहा—

'गांधीवाद = मार्क्सवाद — अहिंसा — ईश्वर।'

विपरीत विचारधारा के लोगों ने इसका तीव्र विरोध किया। श्री घनश्याम मश्रुवाला के अनुसार यह अन्तर इतना अधिक है कि उसे साधारण धन (+) और ऋण (—) के समीकरण द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। आचार्य विनोबा ने इसका समर्थन करते हुए कहा—"इस ऋण (—) हिंसा की तीव्रता इतनी गम्भीर है कि वह इस समीकरण को इतना काल्पनिक और महत्वहीन बना देती है जितना यह कहना कि लाल = हरा—पीला+नीला, अथवा एक कीड़े की इस प्रकार परिभाषा करना कि वह एक विषरहित सर्प है।" श्री मश्रुवाला ने एक कदम आगे बढ़कर कहा "यह अन्तर उतना ही है, जितना लाल और हरे रंग में है, भले ही अन्धों के लिए इनमें कोई अन्तर न हो।"

वास्तव में इन दोनों वादों में बहुत समानता दिखाना कवि कल्पना का आश्रय ले लेने के सदृश होगा जैसे कि एक संस्कृत कवि ने 'राम' और 'रावण' में 'रा' वर्ण की सदृशता के आधार पर समानता खोजने का प्रयास किया है। मूलरूप से इन दोनों विचारधाराओं में कोई साम्य नहीं है। बल्कि 'विनोबाजी' के अनुसार इन दोनों में आपस में पूर्ण विरोध है। उनके अनुसार एक बार पूंजीवाद और साम्यवाद (मार्क्सवाद) में साम्य खोजा जा सकता है, क्योंकि दोनों भौतिकवादी हैं, किंतु गांधीवाद का आधार आध्यात्मिकता है। रिचार्ड ग्रिग ने अपने एक लेख में लिखा है कि "साम्यवाद आवश्यक रूप से द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है, किन्तु गांधीदर्शन भौतिक से अध्यात्म की श्रेष्ठता पर आधारित है।" बर्ट्रांड रसल कहता है—"मार्क्स ने केवल भौतिक आवश्यकताओं पर बल दिया है, और उदार मानवीय भावनाओं की उपेक्षा की है, जबकि गांधीजी मानवीय भावनाओं को अधिक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

महत्व देते हैं और भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा करते हैं।" स्वयं 'गांधीजी' ने स्पष्ट किया कि जहां तक साम्यवाद हिंसा पर आधारित है और ईश्वर से विमुख है—मुझे अप्रिय है। लेनिन ने एक स्थान पर कहा है कि धर्म का प्रथम शब्द ही झूठ है। किन्तु गांधीजी के लिए धर्म ही सर्वस्व है। एक साम्यवादी के लिए धर्म अफीम सदृश नशीला पदार्थ है।

प्रो० हीरेन मुकर्जी ने अपनी पुस्तक Gandhiji a Study' में गांधीजी से एक बार पूछे गये प्रश्न व उसके उत्तर को उद्धृत किया है, जिससे गांधीजी के विचारों पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है।

मानव का व्यक्तित्व बनाम राज्य

श्री मुकर्जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए गांधी जी ने कहा कि "मैं चाहता हूँ कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को बहुत कम कर ले और पूंजीपति द्वारा शोषण की संभावनाओं को समाप्तप्राय कर ले। राज्य की बढ़ती हुई शक्ति को भी मैं भय की दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि यद्यपि यह प्रत्यक्षतः शोषण को कम करने का प्रयत्न करता है, तथापि यह मानव के उस व्यक्तित्व को ही समाप्त करके उसकी बहुत बड़ी हानि भी कर देता है, जो सब उन्नतियों का मूल कारण है।

गांधीजी ने आदर्शों की प्राप्ति के लिए साधनों और विधियों की पवित्रता पर जोर दिया है। यदि साधन उचित व न्यायपूर्ण हैं, तब उसका परिणाम या उद्देश्य आवश्यक रूप से अच्छे होंगे, किंतु मार्क्सवादियों के लिए उद्देश्य ही सर्वस्व है, साधन महत्वहीन है। गांधी जी ने कहा—'साधन और साध्य बीज और वृक्ष के सदृश हैं, जैसा बीज होगा वैसा ही फल।'

गांधी जी लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण के पक्ष में थे। इसके विरुद्ध साम्यवादी के लिए यह पूंजीवादी विचार है। श्रमजीवी इसे सहन नहीं कर सकते, वे मानते हैं कि और उनकी केन्द्रीय शक्ति का ही प्रभुत्व (डिक्टेटरशिप आफ प्रोलिटैरियट) होगा।

इस विचारधारा के विपरीत श्री एम. एस. नम्बूद्रीपाद ने अपनी पुस्तक 'गांधीजी और उनका बाद' में उल्लेख किया है कि गांधी जी के विचारों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट दीखता है कि वे जनता को सदैव पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व में चलाना चाहते थे। उनका रुख समस्त अभाव-ग्रस्तों के प्रति ऐसा था कि व्यवहारतः पूंजीपति को सहायता मिली। उनका अभिभावकता का सिद्धांत, राजनीति में कुछ नैतिक मूल्यों का पालन, अपने गैर संसदीय कार्य-कलाप (रचनात्मक कार्यक्रम और सत्याग्रह) का अपने सहकारियों के संसदीय कार्यकलाप के साथ कुशलतापूर्वक मेल बैठाना, शत्रु के विरुद्ध जनता का प्रत्यक्ष आन्दोलन चलाते हुए उससे बातचीत भी करते जाने का विशिष्ट सिद्धांत आदि सभी इसी बात के द्योतक हैं। इस प्रवृत्ति के दो परिणाम निकले—१. सामान्य जनता साम्राज्य के विरुद्ध हो गई और एक राष्ट्रीय व सर्ववर्गी आन्दोलन का जन्म हुआ। २. किन्तु जनता को क्रान्तिकारी जन-आन्दोलन से रोका गया। अन्ततः वे पूंजीपति वर्ग के नेता बन गए।

गांधीजी के प्रारम्भिक जीवन के आदर्शों का स्वाभाविक परिणाम यही था, किन्तु परवर्ती विचारधाराएं पूंजीपति वर्ग के हित में नहीं थी, यह स्वयं ई. एम. एस. नम्बूद्रीपाद को स्वीकार करना पड़ा—"कतिपय नैतिक मूल्य मान्यताओं के बारे में गांधी जी का आग्रह एक समय पूंजीपति वर्ग के लिए काम की चीज थी, किन्तु उनके जीवन के अन्तिम दिनों में वह उनके (पूंजीपति वर्ग के) राह का रोड़ा बन गई।"

दर्शन में अन्तर

मार्क्सवाद का सिद्धान्त है कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से सत्ता का परित्याग नहीं करना चाहता, किन्तु गांधीवाद इसी आदर्श पर आधारित है। मार्क्सवाद व्यक्तिगत सम्पत्ति को सामूहिक रूप से समाप्त करने पर तुला बैठा है, गांधीवाद समझौते की नीति में विश्वास रखता है और अभिभावकता-सिद्धांत (ट्रस्टीशिप) का अनुमोदन करता है तथा समझाने की नीति को ही उचित उपाय मानता है।

मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से श्रमिक वर्ग की मनोवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है और अधिकतम अधिकार का इच्छुक है। वह समस्त सामाजिक क्रियाओं की जांच आर्थिक मापदण्ड से ही करता है। इसके विपरीत

(शेष पृष्ठ ५२५ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्या देश में मौनोपली बढ़ रही है ?

श्री सुभास

● अनेक वर्षों से भारत के दुर्भाग्य से निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में एक अप्रिय विवाद चल रहा है। दोनों क्षेत्र एक दूसरे की कठोर आलोचना करते रहते हैं। समाजवाद की स्थापना का पक्ष प्रस्तुत करते हुए अनेक उत्साही वक्ताओं ने निजी उद्योगों की अक्षमता, भ्रष्टाचार, अकुशलता तथा सामान्य जनता के शोषण आदि की ओर देश का ध्यान विशेषरूप से खींचा है। यदि समाजवादी विचारधारा का समर्थन मात्र होता और सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को उत्साह के साथ बढ़ाती जाती, तो शायद यह विवाद अप्रिय रूप धारण न करता। उत्साह और आवेश में की गई निजी उद्योग की कठोर आलोचना ने दूसरे पक्ष को भी जैसे को तैसा उत्तर देने को प्रेरित किया है। वह भी सरकार की प्रत्येक नीति व गतिविधि की कठोर आलोचना करने लगा है। सरकारी आडिट रिपोर्टों में दिखाई जाने वाली त्रुटियां व असफलता उनकी आलोचना को रोज नई से नई सामग्री प्रदान करती जाती है।

यह सम्भव है कि यदि समाजवादी वक्ता तथा विचारक कुछ अधिक संयम से काम लेते और आवेश में न आकर अत्युक्ति और कठोर भाषा से बचते, तो न केवल इस विवाद का रूप अधिक अप्रिय न होने देते, बल्कि विचारशील जनता में भी अपने प्रति अधिक विश्वास उत्पन्न कर लेते।

अभी हाल ही में कांग्रेस महासमिति के जयपुर अधिवेशन में अनेक उत्साही वक्ताओं ने भाषण दिये हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार का समर्थन करते हुए निजी उद्योग पर एकाधिकार (मौनोपली) का गम्भीर आरोप लगाया है। उन्होंने विवाद को अधिक अप्रिय रूप देते हुए यह भी कहा है कि तीन हजार करोड़ रुपया अमीरों के पास ऐसा है, जिसका कोई हिसाब नहीं मिलता। इन दोनों आक्षेपों का उत्तर श्री कृष्णकुमार बिड़ला ने अपने हाल ही के भाषण में दिया है। देश में कुछ सम्पन्न लोगों द्वारा एकाधिकार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इस आक्षेप का उत्तर देते हुए श्री बिड़ला ने कहा कि भारत में आज ४६५ सूती मिलें और ३०९ चीनी मिलें विद्यमान हैं। देश के इन दोनों प्रमुखतम उद्योगों में एकाधिकार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का क्या यही प्रमाण है ? देश में बिजली की मोटरें बनाने वाले २७ और डीजल इंजन बनाने वाली २८ संस्थाएं हैं। अन्य उद्योगों के सम्बन्ध में भी इसी तरह की संख्यायें उपस्थित की जा सकती हैं। इसके विपरीत भारत में तो लायसेंस इतनी उदारता से दिये जाते हैं कि मौनोपली की प्रवृत्ति यहां पनप ही नहीं सकती।

स्वयं संसद् में भारत सरकार के तत्कालीन उद्योग मन्त्री श्री मनुभाई शाह ने भी १९६१ में भारत में एकाधिकार की प्रवृत्ति को मानने से इंकार करते हुए कहा था, कि "भारत में लोक जागृति इतनी तेज है कि यहां एकाधिकार की प्रवृति जन्म ही लेने नहीं पाई है। अमेरिका और इंगलैंड में इस प्रवृत्ति ने खतरे का रूप धारण कर लिया था, इस लिए वहां एण्टी शर्मन एक्ट तथा कमीशन आफ मौनोपली बनाने पड़े। भारत में तो उपभोग्य वस्तुओं में कोई एक भी ऐसा उद्योग नहीं है जिस के हाथ में कुल राष्ट्रीय उत्पादन का ५ प्रतिशत या उससे अधिक हो। मैटल बाक्स कम्पनी, एसोसिएटिड सिमेंट कम्पनी, विमकों आदि कुल चार संस्थान इसके अपवाद अवश्य हैं। लेकिन इन क्षेत्रों में भी हम नये लोगों को आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हम यदि यह देखेंगे कि कोई भी उद्योग मौनोपली स्थापित करने की थोड़ी बहुत कोशिश करता है तो हम उसे कुचल डालेंगे।" इस स्पष्ट उक्ति के बाद भी यदि कुछ उत्तरदायी कांग्रेसी नेता अत्युक्ति पूर्ण आवेशयुक्त भाषण करते हैं, तो इससे उन्हीं का पक्ष अधिक कमजोर होगा।

हमें यह भी मालूम है कि सरकार बहुत तेजी से सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार कर रही है। तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में सरकारी और निजी क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित राशियों का नियोजन निश्चित किया गया।

	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र
पहली योजना	६० करोड़	३३० करोड़

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दूसरी योजना	७२० करोड़	८५० करोड़
तीसरी योजना	१,५०० करोड़	१२०० करोड़

इस राशियों में बिजली उत्पादन पर खर्च होने वाली सरकारी क्षेत्र की राशियाँ सम्मिलित नहीं हैं, जो तीनों योजनाओं में क्रमशः २६०,४६० और १०४० करोड़ रुपया है, जब कि निजी क्षेत्र में ये राशियाँ केवल ४२,६५ और ५० करोड़ रुपया हैं। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि भारत में कुछ एक व्यक्तियों के हाथ में सम्पत्ति के केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को बढ़ने नहीं दिया जा रहा।

श्री कृष्णकुमार बिड़ला ने अपने भाषण में इस आक्षेप का भी उत्तर दिया है कि ३ हजार करोड़ रुपये का हिसाब ही नहीं मिलता। १९६०-६१ के अन्त में सरकार द्वारा प्रकाशित अंकों में बताया गया था कि २ हजार करोड़ रुपया निजी क्षेत्र में लगा है और अब एक अनुमान के अनुसार ३ हजार करोड़ रुपया समस्त निजी क्षेत्र में लगा हुआ है। यह समझना कठिन है कि उद्योगों में कुल विनियोजन के बराबर की राशि हिसाब में आने से रह गई हो। उद्योगपति तो विनियोजन की संभावना देखते ही उसमें रुपया लगाने को आतुर हो उठते हैं और उसे बेकार पड़ा नहीं रहने देते। समस्त व्यापारी लोग देश में एक समानन्तर सरकार चला रहे हैं, यह आरोप भी उपहासास्पद व भ्रामक है।

श्री मनुभाई शाह ने लोकसभा में भाषण देते हुए स्पष्ट ही कहा था कि आखिर इन लोगों (सम्पन्न वर्ग) के हाथ में ताकत ही क्या है, कानून बनाने का अधिकार हमें है; हम ही नीति का निर्धारण करने वाले हैं और सार्वजनिक क्षेत्र में रुपया कैसे और कितना लगाया जाय, इसका निर्णय भी हम ही कर सकते हैं, तो हम उनसे क्यों भयभीत हों?

श्री कृष्ण कुमार बिड़ला ने अपने भाषण में रिजर्व बैंक की रिपोर्ट उद्धृत करते हुए बताया है कि ७० बड़ी कम्पनियों की कुल पूंजी २७० करोड़ रुपया है, जिन में से २१२ करोड़ रुपया ४ लाख १२ हजार शेयर होल्डरों का है। व्यक्तिगत शेयर होल्डरों में भी ६५ प्रतिशत ऐसे व्यक्ति हैं, जिन के शेयर एक हजार रुपये या उससे नीचे हैं।

यदि कुछ उत्साही वक्ता, अधिक आवेश में आकर ऐसे भाषण देते हैं, जिनका युक्तियुक्त उत्तर दूसरी ओर से मिल सकता है तो उसका प्रभाव उन्ही के पक्ष में बुरा पड़ता है। विचारशील जनता उन्हें अविश्वसनीय समझने लगेगी। इन सब पंक्तियों के लिखने का हमारा यह आशय सर्वथा नहीं है कि हम समाजवाद के विरोधी हैं या पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुछ उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं हैं। हम तो केवल यह नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि हमें अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए भी काफी संयम से काम लेना चाहिए।

दुश्मन को कमजोर

न-समझें

चीनी सेनाएं अब भी हमारी उत्तरी सीमा पर जमा हैं।
चौकस रहिये !

आपका अनुशासन भारत की शक्ति है।

DA63/F18

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मूल आधार

जब तीसरी योजना की पूर्ति में दो वर्ष रह गये हैं, चौथी योजना के सम्बन्ध में अन्तिम रूप रेखा तैयार हो रही है। योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद में इस सम्बन्ध में काफी विचार हो रहा है। इस योजना के सम्बन्ध में योजना आयोग ने राज्यों से कहा है कि—

चौथी योजना का भी मूल आधार खेती और उद्योगों का तीव्र विकास तथा परिवहन, ईंधन, बिजली और शिक्षा की उचित व्यवस्था करना होगा। यह सुझाव है कि औद्योगिक विकास इस प्रकार किया जाए कि विदेशी मुद्रा की दिक्कतों के कारण देश की प्रगति रुकने न पावे। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि देश में बचतें बढ़ाई जाएं, निर्माण-कार्यों की कुशलता सुधरे और निर्यात का काफी विस्तार हो।

आयोग के अनुसार विकास कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य ये होंगे—(१) समाजवादी समाज की स्थापना, (२) देश के विभिन्न क्षेत्रों का सन्तुलित विकास, (३) ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाना और (४) उत्पादन को उस स्तर तक लेजाना जहां से देश की अर्थ-व्यवस्था का शीघ्र ही तेजी से विकास हो और वह आत्मनिर्भर हो जाय।

सब राज्यों को जिला और ब्लाक के स्तर पर किसी योजना की पूर्ति में सहयोग देना चाहिए और पंचायतों का विशेष रूप से यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे योजना के लक्ष्यों को पूर्ण करने में भाग लें। श्री बलीराम भगत (योजना मन्त्री) के कथनानुसार हमें नीचे के स्तर से काम प्रारम्भ करना चाहिए और उन भूलों से बचना चाहिए, जिनके कारण तीसरी योजना की प्रगति में बाधा आई है। हमारा उद्देश्य यह था, कि १९५० से २५ वर्ष के अन्दर अन्दर हमारी राष्ट्रीय आय दुगनी हो जाय और इसी दृष्टि से हमें चौथी योजना की तैयारी करनी चाहिए। विभिन्न राज्यों के मुख्य मन्त्रियों ने भी इस योजना के सम्बन्ध में परामर्श दिये हैं। पंजाब के मुख्य मन्त्री श्रीप्रतापसिंह कैरों के कथनानुसार हमें सब राज्यों को स्वावलम्बी और स्वतः स्फूर्त बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। चौथी योजना के अन्त तक सभी देशवासियों को भोजन वस्त्र और निवास हम दे सकें, यह निश्चय हमें करना चाहिए। अभी तक हमने बेकारी की भीषण समस्या को भी गम्भीरता से नहीं लिया है। इस सम्बन्ध में श्रीमती सुचेता कृपलानी ने राय दी है कि हमें प्रादेशिक असमानताओं को दूर करके आय के एक न्यूनतम स्तर को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। और इस न्यूनतम स्तर का उल्लेख चौथी योजना में कर दिया जाना चाहिए। कृषि उत्पादन में हम बहुत पिछड़ गये हैं। इसे प्रोत्साहन देने के लिए हमें किसानों के सामने अधिक से अधिक आकर्षक प्रस्ताव व कार्यक्रम उपस्थित करने चाहिए।

डा० वी० के० आर० वी० राव, योजना आयोग के सदस्य हैं। वे मानते हैं कि सब लोगों को रोजगार देने की जिम्मेदारी राज्यों की है। प्रत्येक राज्य को यह देखना चाहिए कि उसकी मानव-शक्ति क्या है और कितने लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। जिला परिषदों और पंचायतों के सहयोग से राज्यों को छोटी योजनायें पूर्ण करने की ओर ध्यान देना चाहिए। पिछड़ी हुई जातियों के उद्धार के लिए विशेष रूप से हमें प्रयत्न करना चाहिए।

योजना आयोग के एक सदस्य ग्राम सुधार की योजनाओं से राज्यों में बेकारी को कुछ कम करने के पक्ष में हैं। ग्राम सुधार की योजनायें अधिक उत्पादन की योजनायें हों, न कि उनका रूप दुर्भिक्ष-सहायता का रहे। ग्राम के श्रम को एक व्यवस्थित रूप में कृषि कार्यों में लगाने से लोगों को काम मिल सकता है।

१९६६-७१ के लिए जो चौथी योजना बनेगी, उसमें पांचवीं योजना की भी रूपरेखा दे दी जायगी। पिछले महीने राष्ट्र विकास परिषद में इसकी प्रारम्भिक रूपरेखा पर विचार हुआ है। अनेक स्तरों पर विचार विनिमय के बाद जनवरी १९६५ में चौथी योजना की रूपरेखा प्रकाशित कर दी जायगी। इसके बाद विभिन्न राज्यों द्वारा योजना पर विचार होगा और १९६६ के प्रारम्भ में इसका अन्तिम रूप राष्ट्रीय विकास परिषद में स्वीकृत होकर संसद् के सामने पेश होगा।

सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

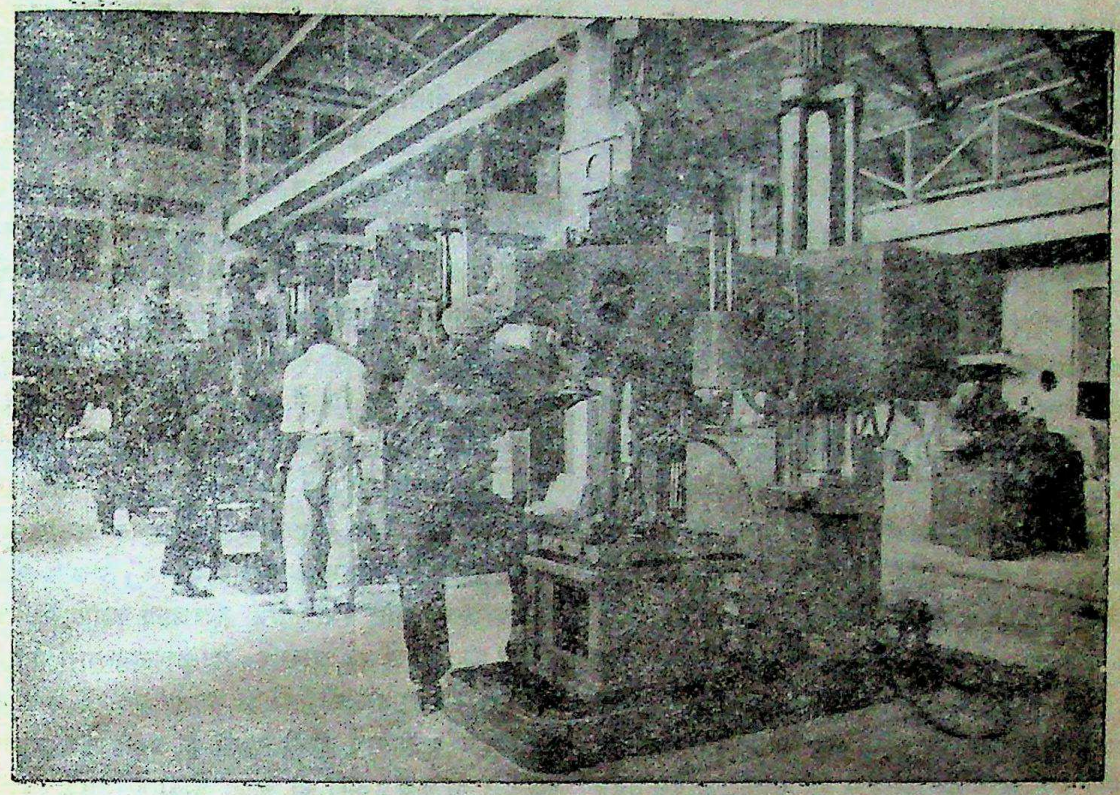

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की प्रगति

इस समय हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के ५ और मशीनी औजार बनाने के कारखाने बन गये या बन रहे हैं। प्रत्येक की वार्षिक क्षमता ५ करोड़ रु० के औजार बनाने की है। इनके अलावा घड़ी बनाने का भी एक कारखाना है, जो प्रति वर्ष ३ करोड़ रु० की घड़ियां बना सकता है। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाना नं० १ १९५५ में चालू हुआ था, और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स नं० २, १९६१ में। बंगलौर में इन दोनों कारखानों में पूरी रफ्तार से उत्पादन हो रहा है। घड़ी का कारखाना १९६२ में चालू हुआ। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स नं० ३ कारखाना, १ अक्टूबर १९६३ को पिंजोर में चालू हुआ। इसके बनने में केवल १७ महीने लगे। इसका उद्घाटन २३ अक्टूबर को प्रधान मन्त्री नेहरू ने किया है। चौथा कारखाना कलमशेरी (केरल) में १९६४ के अन्त तक चालू हो जाएगा और नं० ५ सनतनगर (आंध्र प्रदेश) में १९६५ के शुरू में। इसका मतलब यह हुआ कि १९६१ से प्रति वर्ष, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स एक कारखाना खोल रहा है। ये सब मशीनी औजार कारखाने (नं० १ को छोड़कर) पूरी तरह भारतीय शिल्पिकों ने, बिना विदेशी मदद के बनाये हैं। पांचों कारखाने, जिनकी कुल वार्षिक क्षमता २५ करोड़ रु० की होगी, तीसरी योजना की अवधि में १९६५-६६ तक चालू हो जाएंगे। पहले, तीसरे और पांचवें कारखाने के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लिए धन सरकार ने दिया और दूसरे और चौथे के लिए खुद हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने।

मशीनी औजार

अनुमान है कि १९६५-६६ तक, देश में ६० करोड़ रु० के मशीनी औजारों की जरूरत पड़ेगी, जबकि १९६२ में ४१ करोड़ ४० लाख रु० के औजारों की थी। इसमें से ३० करोड़ रु० के औजार विदेशों से मंगाये गये थे और ११ करोड़ ४० लाख रु० के देश में बनाये गये थे। तीसरी योजना में ३० करोड़ रु० के देशी औजार बनाने का लक्ष्य है—१६ करोड़ रु० सरकारी कारखानों और १४ करोड़ रु० निजी कारखानों के लिए। १६ करोड़ रु० में से हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के जिम्मे १० करोड़ रु० के औजार हैं और बाकी ६ करोड़ में आगा टूल्स के जिम्मे २॥ करोड़ रु०, हेवी मशीन टूल्स फैक्ट्री, रांची के ३ करोड़ रु० और अम्बरनाथ के जिम्मे १ करोड़ रु० के औजार हैं। निजी कारखानों को १४ करोड़ के औजार बनाने हैं, जिन्हें लगभग ५५ कारखाने बनायेंगे। अब तक की प्रगति देखते हुए ३० करोड़ रु० के औजार बनाने का लक्ष्य १९६५-६६ तक पूरा होने की आशा नहीं है। आशा है कि १९६५-६६ में, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, १६ करोड़ रु० के औजार बनायेगा। अर्थात् अपने लक्ष्य १० करोड़ से ६० प्रतिशत अधिक। इस प्रकार तीसरी योजना के अंत तक देश में लगभग २५ करोड़ रु० के औजार बन सकेंगे, जबकि लक्ष्य ३० करोड़ का है और मांग ६० करोड़ रु० की होने का अनुमान है। १९७१ तक मशीनी औजारों की मांग कोई एक अरब रु० तक पहुँच जाएगी। चौथी योजना में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ५-५ करोड़ रु० की क्षमता वाले ५ और कारखाने खोल सकता है। तीसरी योजना के अन्त तक पहले के पांच कारखाने २५ करोड़ रु० के औजार बनाने लगेंगे। इस प्रकार चौथी योजना के अन्त तक दसों कारखाने मिल कर ५० करोड़ रु० के औजार बना सकेंगे। अर्थात् १९७०-७१ में देश की अनुमानित आवश्यकता के आधे औजार हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखानों का समूह बना सकेगा। पिछले सात वर्षों में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने ५०·६० प्रतिशत औजार बनाये हैं।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को जमीन व विदेशी मुद्रा मिलने के बाद बंगलौर में पहला कारखाना खड़ा करने में १४॥ महीने, घड़ी कारखाना बनाने में १६ महीने और पिंजौर के कारखाने में १७ महीने लगे थे। यदि लाल फीताशाही की झंझट न हो तो हिन्दुस्तान मशीन टूल्स जमीन और विदेशी मुद्रा मिलने के एक साल के भीतर एक कारखाना चालू कर देगा। कारखाना लगाने में—एक महीने की देरी से ४० लाख रु० का उत्पादन मारा जाता है और उसके लिए हमें औजारों के आयात पर ४६ लाख रु० की विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, यानी जांच पड़ताल करने से जो कुछ हजारों की बचत होती है, उसके एवज में विदेशी मुद्रा मिलने में देर इतनी अधिक हो जाती है कि उत्पादन में लाखों रुपयों का फर्क पड़ता है। कभी-कभी तो जांच पड़ताल करने में ६ महीने लग जाते हैं। इस प्रकार कोई २ करोड़ ४० लाख रु० का नुकसान होता है।

दिल्ली विकास अंक के बाद

सम्पदा का एक नया वृद्धाकार विशेषांक

इसे प्रकाशित करने की योजना बन चुकी है। लेकिन

१. यह किस विषय पर होगा ?
२. इसकी क्या विशेषताएं होंगी ? और
३. यह कब प्रकाशित होगा ?

आदि जानने के लिए प्रेमी पाठकों को कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी।

—सम्पादक सम्पदा

२८/११ शक्तिनगर दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आधुनिक अर्थशास्त्र के क्रान्ति-काल—३

श्री कृष्णदत्त भट्ट

बैन्थम का उपयोगितावाद

अदम स्मिथ के बाद जिन दो महान आचार्यों ने आधुनिक अर्थशास्त्र में विशेष योगदान दिया, वे हैं मैल्थस और रिकार्डो, परन्तु इनके बीच की श्रृंखला को जोड़ने वाला हुआ बैन्थम।

बैंथम ने उपयोगितावाद के सिद्धान्त को जन्म दिया। इस धारणा का मूल आधार है सुखवादी मनोविज्ञान। बैंथम ऐसा मानता है कि मनुष्य के समस्त कार्यों के मूल में एक ही भावना है और वह है—सुख प्राप्ति की इच्छा और दुःख प्राप्ति की अनिच्छा। बैंथम की दृष्टि से मनुष्य के सुख-दुःख के विचार उसकी भावनाओं और इच्छा शक्ति पर अपना निर्णय रखते हैं; इच्छा-शक्ति उनके सम्बन्ध में बुद्धि से जिज्ञासा करती है। बुद्धि दोनों पक्षों पर विधिवत् विचार करके उपरान्त कुछ निश्चय करती है। उसके उपरान्त मनुष्य उसे कार्य रूप में परिणत करता है।

उपयोगितावाद का यह सिद्धान्त मैल्थस, रिकार्डो, जेम्स मिल, जान स्टुअर्ट मिल के हाथों खूब फूला-फला। आस्ट्रियन विचारधारा ने इसी के आधार पर मूल्य सिद्धांत का विशिष्ट रूप से विकास किया। इसने व्यावहारिक रूप भी ग्रहण किया। १९वीं शताब्दी में इंग्लैंड में जो सुधार हुए, उनमें इसका बड़ा हाथ रहा।

मैल्थस का जनसंख्या-सिद्धान्त

मैल्थस का उदय उस युग में हुआ, जिस युग में औद्योगिक क्रान्ति का अभिशाप स्पष्ट होने लगा था और उसके दोष प्रकट होने लगे थे। स्मिथ के सामने तो इस क्रान्ति का जन्म हो रहा था, पर मैल्थस के सामने औद्योगिक क्रान्ति के दोष बेकारी, भुखमरी और दुर्भिक्ष की काली छाया समाज पर मंडराने लगी थी। धन के असमान वितरण एवं दिन-दिन बढ़ने वाले दारिद्रय ने स्थिति भयंकर बना दी थी।

प्रश्न था कि ऐसी भयंकर स्थिति में से कौन-सा मार्ग निकाला जाय। यह काम किया मैल्थस ने।

जनसंख्या और खाद्य की समस्या को लेकर रोबर्ट मैल्थस ने अपना प्रसिद्ध निबन्ध लिखा, जिसमें उसने यह घोषणा की कि जनसंख्या सामाजिक प्रगति में इतनी बड़ी बाधा है कि उसे सहज ही पार कर लेना सर्वथा असम्भव है। खाद्य पदार्थों का उत्पादन जिस मात्रा में होता है, उससे कहीं बड़ी मात्रा में जनसंख्या में वृद्धि होती है। इस जनसंख्या-वृद्धि का ही परिणाम है—भुखमरी, संकट और मृत्यु। मैल्थस ने इस बात पर जोर दिया कि गाडविन के अनुसार राज्यसत्ता का अन्त कर दिया जाय, तो भी जनसंख्या की समस्या हल होने वाली नहीं। कारण, हमारे दुःख और दुर्भाग्य का मूल तो हमारे अपने दुर्बल एवं अपूर्ण स्वभाव में ही विद्यमान है।

मैल्थस के जनसंख्या-सम्बन्धी सिद्धान्त की मुख्य तीन आधार शिलाएं हैं :—

(१) जनसंख्या वृद्धि का गुणात्मक क्रम।

(२) खाद्यान्न की पूर्ति का समान्तर क्रम और

(३) नियंत्रण के दैवी एवं मानवीय उपाय।

मैल्थस मानता है कि जनसंख्या की वृद्धि ज्यामितीय या गुणात्मक क्रम में होती है, जबकि खाद्यान्न की पूर्ति समानान्तर क्रम में हुआ करती है।

मैल्थस की मान्यता यह है कि मनुष्य में प्रजनन की असीम शक्ति है। आज के प्राणिशास्त्रज्ञ कहते हैं कि स्त्री के शरीर में जन्म के समय ७० हजार अपक्व स्त्री-बीज रहते हैं। १५ से ४५ वर्ष की आयु में उनमें से ४०० स्त्री बीज परिपक्व होते हैं। पुरुष के एक बार के सम्भोग में २०० करोड़ से अधिक पुंबीज गिरते हैं, जिनमें से यदि केवल एक का परिपक्व स्त्री-बीज के साथ सम्पर्क हो जाय, तो गर्भ स्थिति होकर सन्तान का जन्म हो सकता है। इस असीम प्रजनन शक्ति पर यदि कोई नियंत्रण न रहे तो जनसंख्या की वृद्धि अनिवार्य है। पृथ्वी की उत्पादन-क्षमता समान अनुपात में नहीं बढ़ती। अतः यह आवश्यक है कि जनसंख्या-वृद्धि पर अंकुश लगाया जाय, अन्यथा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रकृति स्वयं ही विनाश की लीला आरम्भ कर देगी।

मैल्थस ने अति-उत्पादन और व्यापारिक मन्दी के सम्बन्ध में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विचार प्रगट किए हैं। एक ओर अत्यधिक अमीरी, दूसरी ओर अत्यधिक गरीबी; एक ओर बाजार में वस्तुओं का बहुत उत्पादन, दूसरी ओर उनका कोई खरीददार नहीं; एक ओर अत्यधिक उत्पादन, दूसरी ओर अत्यधिक बेकारी देख कर मैल्थस इसके कारणों की खोज में लगा।

कारण की खोज

मैल्थस की मान्यता यह है कि समृद्धि-काल में आयके समान वितरण के अभाव में थोड़े से अमीर पर्याप्त बचत कर लेते हैं। फलत: विनियोग एवं उत्पादन में वृद्धि होती है। पर चूंकि सभी लोगों की आय नहीं बढ़ती और साथ ही साथ उपयोग सम्बन्धी आदतों में भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उत्पादन की मात्रा के अनुपात में वस्तुओं की मांग बढ़ नहीं पाती। इसी का यह परिणाम होता है कि बाजार वस्तुओं से पटा रहता है और कोई खरीददार नहीं रहता। अति-उत्पादन और बेकारी बढ़ने लगती है।

मैल्थस पहला अर्थ शास्त्री है, जिसने सामाजिक समस्याओं की ओर अत्यन्त तीव्रता के साथ विचारकों का ध्यान आकृष्ट किया। मैल्थस ने आंकड़ों को सबसे पहले शास्त्रीय विवेचन में स्थान दिया। उसने 'जनसंख्या विज्ञान' को जन्म दिया। डारविन के विकासवाद के सिद्धांत का वह प्रेरक बना। अर्थशास्त्र में अनुमान-पद्धति का विकास मैल्थस से ही प्रारम्भ होता है। उसी के कारण अर्थशास्त्र और समाज-शास्त्र का पारस्परिक सम्बन्ध घनिष्ठ होने लगा। उसने अपने विचारों से रिकार्डो और केन्स जैसे विचारकों को प्रभावित किया।

संघर्षकाल में आया रिकार्डो

अदम स्मिथ के समय में पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था का जन्म ही हो रहा था, परन्तु ५० वर्ष बाद ही रिकार्डो के समय में इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति में अत्यधिक परिवर्तन हो चुका था। औद्योगिक विकास के साथ-साथ उसके दुष्परिणाम भी प्रकट होने लगे थे। व्यापार निर्बाध गति से चलने लगा था, जनसंख्या की वृद्धि हो रही थी, अन्न की कमी होने से वस्तुओं के मूल्य चढ़ रहे थे, गरीबों और अमीरों के बीच पार्थक्य बढ़ रहा था, भूस्वामियों और उद्योगपतियों के स्वार्थों में संघर्ष हो रहा था, पूंजी और भूमि तथा श्रम और पूंजी के बीच टकरें हो रही थीं। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बड़े-बड़े कारखाने खुल चुके थे। मजदूर गांव छोड़कर शहरों में आकर बसने लगे थे और मिल मालिकों के विरुद्ध मजदूरी बढ़वाने के लिए आन्दोलन करने लगे थे। गरीबी, बेकारी, प्रतिस्पर्धा, जनसंख्या की वृद्धि और मूल्य-वृद्धि का चारों ओर जाल फैल गया था।

युद्ध तथा व्यय-भार से पीड़ित सरकार ने मुद्रा-स्फीति कर रखी थी, जिसके कारण वस्तुओं का मूल्य और भी चढ़ रहा था। अनाज की कमी होने से कम उर्वर भूमिखण्ड जोते जाने लगे थे। मिल-मालिक सस्ते दामों पर कच्चा माल चाहते थे और भू-स्वामी इसके लिए सचेष्ट थे कि उन्हें उनकी उपज का अच्छा पैसा मिले।

यह सब क्यों हो रहा है? ऐसी भयंकर स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई है?—यह था वह मूलभूत प्रश्न, जो रिकार्डो के सामने मुंह बायें खड़ा था।

यद्यपि रिकार्डो के आर्थिक विचारों का क्षेत्र बहुत व्यापक रहा है, तथापि सुविधा की दृष्टि से उसके विचारों का इस प्रकार विभाजन किया जा सकता है—

१. वितरण के सिद्धांत

(१) भाटक-सिद्धांत
(२) मजूरी-सिद्धांत
(३) लाभ-सिद्धांत

२. मूल सिद्धांत

(१) विदेशी व्यापार।
(२) बैंक तथा कागदी मुद्रा।

इस क्रम से रिकार्डो का अध्ययन करना अच्छा होगा।

रिकार्डो का योगदान

रिकार्डो ने—अर्थशास्त्रीय विचारधारा को अत्यधिक प्रभावित किया है। उसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं—

(१) उसने वितरण की समस्याओं का विस्तार पूर्वक विवेचन किया।

(शेष पृष्ठ ५१० पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वैदिक अर्थ-व्यवस्था

श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

आज की अर्थशास्त्र की परिभाषा में यदि कोई महानुभाव वेदों में अर्थशास्त्र का अनुसंधान करना चाहे तो शायद उसे सफलता नहीं मिलेगी। किन्तु वेदोक्त समाज-व्यवस्था में अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त अवश्य मिल सकते हैं। वेद भगवान को शरीर की उपमा देते हुए उसके सब अंगों और उपांगों की विविध शास्त्रों के रूप में कल्पना की गई है। इस प्रसंग में अर्थशास्त्र को वेदरूपी शरीर का उदर बताया गया है।

"मूर्तिमान् भगवान् वेदो राजतेऽङ्गैः सुसंहतैः
छन्दः पादौ स्मृतावस्य, हस्तः कल्पोऽस्य पठ्यते,
मुखं व्याकरणं प्रोक्तं, शिक्षा घ्राणं तथोच्यते,
ज्योतिषामयनं चक्षुः, निरुक्तं श्रोत्रमीर्यते,
आयुर्वेदः स्वयं प्राणः धनुर्वेदो महाभुजौ,
गान्धर्वो रससम्पृक्तः शिल्पवेदोऽस्थिपंजरः
कामशास्त्रं तु जघनं अर्थशास्त्रमथोदरम्,
हृदयं मानवो धर्मः मूर्धा वेदान्त इष्यते॥

हम इन पंक्तियों में वेदों द्वारा प्रतिपादित अर्थ-व्यवस्था के बारे में कुछ फुटकर विचार उपस्थित करेंगे।

शक्ति का सम सन्तुलन

यदि वैदिक अर्थ-व्यवस्था का मूल हम एक शब्द में कहना चाहें तो वह वर्णाश्रम-व्यवस्था है। इस व्यवस्था के द्वारा वेदों में जिस सामाजिक संगठन का उपदेश दिया गया है, वह आज की अनेक आर्थिक समस्याओं का निराकरण कर सकती है।

आज सामाजिक शक्ति का मूल केन्द्र धन या अर्थ है। यही कारण है कि समाज में शक्ति का असन्तुलन है, अतएव व्यापक असन्तोष उत्पन्न हो चुका है। किसी समय समाज में शक्तिशाली क्षत्रिय की प्रतिष्ठा थी अथवा धर्माधिकारी ब्राह्मण की। वैदिक व्यवस्था में समाज में शक्ति का सन्तुलन भली भांति किया है। वैश्य व्यापारी या उद्योगपति रुपया अवश्य कमाता है, लेकिन समाज में ब्राह्मण का सम्मान उससे अधिक होता है, क्योंकि वह विद्वान्, त्यागी, सच्चरित्र होता है। इसी तरह क्षत्रिय भी अपने धन की वजह से नहीं, परन्तु प्रजारक्षण के उत्तरदायित्व के कारण सम्मान पाता है। परन्तु उसे भी त्यागी संन्यासी ब्राह्मण के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। इस तरह प्रतिष्ठा का मूल कारण धन न होकर जन-सेवा है। यह सुन्दर शक्ति-सन्तुलन था।

धन बनाम त्याग व सेवा

पूंजीवाद में धन को ही सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है, किन्तु वर्ण-व्यवस्था त्याग और सेवा को अधिक महत्त्व देती है। वर्ण-व्यवस्था के साथ-साथ यदि आश्रम का महत्त्व भी हम समझ लें तो समाज-व्यवस्था भोग प्रधान न होकर कर्म प्रधान बन जाती है। ब्रह्मचारी को गुरुकुल में पढ़ना पड़ता था, जहां अमीर और गरीब का कोई भेद-भाव नहीं था। गृहस्थ आश्रम भी एक नियत काल के लिए होता था, जिसके बाद नागरिक को वानप्रस्थी या संन्यासी बनना पड़ता था। इस व्यवस्था से भी आज की अनेक समस्याओं का समाधान हो जाता है। बेकारी बढ़ने नहीं पाती थी, क्योंकि पचास या पचपन वर्ष में हर एक को अर्थ संग्रह का काम छोड़कर नौजवानों के सुपुर्द करना पड़ता था। फिर विद्वान वानप्रस्थ वा संन्यासी समाज की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करते थे। इन सामाजिक सेवाओं के कारण शिक्षा, चिकित्सा आदि अनेक वे सब सुविधाएँ समाज को निःशुल्क मिलती थीं, जिनके लिए आज का साम्यवादी मांग करता है।

समान वितरण

आज के अर्थशास्त्र में प्रत्येक नागरिक को भोजन, वस्त्र और निवास की सब सुविधाएं समान रूपेण देने पर जोर दिया जाता है। वेद मन्त्रों द्वारा अपनी दिव्यवाणी में यही गम्भीर सन्देश हमें दिया गया है। ऋग्वेद का एक मन्त्र में कहा गया है—निश्चय से ही परमात्मा ने भूख को मृत्यु का साधन नहीं बनाया है।

न वा उ देवाः क्षुधमिद्वधं ददुः। ऋग. १०।७.१।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

साम्यवाद का सच्चा आदर्श वेद के इन मन्त्रों में मिलता है, जिनमें सब मनुष्यों को मिलकर अन्न और जल की प्राप्ति तथा समान रूप से अर्थ-प्राप्ति के लिए उपदेश दिया गया है।

समानी प्रपा सह वो अन्नभागः,
समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि।
सम्यंचोऽग्निं सपर्यतारा नाभिमिवाभितः
॥अथर्व॥ ३.३०.६॥

वस्तुतः वर्णाश्रम व्यवस्था उस त्यागमय जीवन पर बल देती है, जिसके पालन से आज की सब आर्थिक समस्याओं का समाधान हो जाता है। वेद किसी को धन के अनुचित संग्रह का अधिकार नहीं देता। वैदिक संस्कृति के अनुसार यम नियमों का पालन अत्यन्त आवश्यक है। और इन यम नियमों में शौच, सन्तोष और विशेषकर अस्तेय और अपरिग्रह का असाधारण महत्त्व है। इनके पालन से ही पूंजीवाद का वह विषमय रूप नष्ट हो जाता है, जो अमीरों द्वारा शोषण के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो गया है। वेद स्पष्ट शब्दों में आदेश देता है कि—

मा गृधः कस्यस्वित् धनम् ॥यजुः ४०।१॥

वेद तो इस मन्त्र के द्वारा संसार का त्यागभाव से उपभोग का उपदेश देता है। अथर्ववेद के एक मन्त्र में उपदेश दिया गया हैं कि सौ-सौ हाथों से कमाओ, लेकिन हजार-हजार हाथों से इसे समाज में वितरित भी कर दो।

शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर।
अथर्व० । ३.२४.५१.।

स्थान-स्थान पर अथर्ववेद में दान देने का और त्यागमय जीवन का प्रतिपादन किया गया है। जो पूंजीपति समाज का शोषण करके सब कुछ अपने पास रखना चाहता है, राजा को आदेश दिया गया है कि वह उससे धन छीन ले।

सम्राट् अदित्सन्तं दापयति ''। यजु ९. २४।

उपर्युक्त पंक्तियों में हमने वेदों के जिस त्याग भाव की चर्चा की है, अग्निहोत्र में प्रत्येक आहुति के साथ

"इदम् न मम"

कहकर हम उसी भाव को अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयत्न करते हैं। यह समस्त जीवन वेद की परिभाषा में एक यज्ञ ही है, जो दान, सेवा, कर्त्तव्य-परायणता के अतिरिक्त कुछ नहीं है।

अर्थ का महत्व

हमारे उपर्युक्त विवेचन से यह नहीं समझना चाहिए कि वेद में अर्थ का कोई महत्व ही नहीं है। वेदों में ऐसे सैकड़ों मन्त्र हैं, जिनमें भगवान से धन की प्रार्थना की गई है। हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं।

स्याम वयम् पतयो रयीणाम्।

हम सम्पत्तियों के स्वामी बनें। वेद माता से भी जो चीजें मांगी गई हैं, उनमें प्रजा, पशु और धन भी है।

आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं, द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्।

अथर्व वेद के इन निम्नलिखित सूत्रों में पशु, पुत्र धनधान्य, हाथी, घोड़े आदि सम्पत्ति साधनों की चर्चा की गई है। २-२६, ३-१०, ३-१४, ३-२३, ५-११। तीसरे कांड का पन्द्रहवां सूक्त तो वाणिज्य के लाभ की ही चर्चा करता है। इस सूक्त में व्यापार द्वारा धन उपार्जन वायु, स्थल या जल मार्गों से व्यापार और धन के उपार्जन का उपदेश दिया गया है। व्यापारी के रूप में इन्द्र को धन-प्राप्ति का आदेश दिया गया है और भगवान् से कहा गया है कि वह ईशान हमारे लिए धन वाला हो।

वायु और अग्नि—दोनों तत्वों को शीघ्र स्वभाव वाला माना गया है और दोनों पदार्थों के निर्माण करने वाले कारखानों के निमित्त अत्यन्त उपयोगी बतलाए गए हैं :—

"उग्रा सन्ता हवामह उपेदं सवनं सुतम्।
इन्द्राग्नी एह गच्छताम् ॥"

व्यापार

स ईशानो धनदा अस्तु मह्यम्।

इसी सूक्त के दूसरे मन्त्र में व्यापार के द्वारा धन उपार्जन का स्पष्ट उपदेश दिया गया है।

ये पन्थानो बहवो देवयाना,
अन्तरा द्यावापृथिवी संचरन्ति।
ते मा जुषन्तां पयसा घृतेन यथा,
क्रीत्वा धनमाहराणि।

कितने स्पष्ट शब्दों में व्यापार का उपदेश वेद देता है। इसी सूक्त के चौथे मन्त्र में प्रपण, विक्रय, प्रतिपण

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आदि की चर्चा की गई है। पांचवें मन्त्र में कहा गया है कि मैं जिस धन से व्यापार करता हूँ, वह धन निरन्तर बढ़ता रहे। उसमें किसी तरह कमी न आए।

येन धनेन प्रपणं चरामि,
धनेन देवा धनमिच्छमानः।
तन्मे भूयो भवतु मा कनीयोऽग्ने,
सातघ्नो देवान् हविषा नि षेध।
तस्मिन् म इन्द्रो रुचिमादधातु,
प्रजापतिः सविता सोमो अग्निः ॥५॥

वेदों में ऐसे सैंकड़ों मन्त्र हैं, जिनमें प्रजा, पशु और धन धान्य, रायस्पोष आदि की प्रार्थना की गई है। गृहिणी के लिए कहा गया है कि तुम घी के घड़े भरो।

पूर्णं नारि प्र भर कुम्भमेतं,
घृतस्य धारामृतेन संभृताम्।

वेदों के राष्ट्र गीत में कर्त्तव्य-पालन करने वाले चारों वर्णों की याचना के साथ दूध देने वाली गौ, भार-वाही बैल, तीव्रगामी अश्व, गृहस्थ का भार धारण करने वाली नारी की प्रार्थना कहते हुए इच्छा और आवश्यकता के अनुसार वर्षा और फलवती औषधियों के पकने की भी प्रार्थना की गई है। वस्तुतः वैदिक धर्म केवल वैराग्य, दारिद्रय और ईश्वर उपासना का ही धर्म नहीं है। वह तो इस समस्त जीवन का धर्म है, जिसमें मानव को संसार के सब सुख भोगते हुए आगे बढ़ना है। अपनी उन्नति के मार्ग में जो भी बाधाएं आएं और जो भी शत्रु हों, उन सब का सामना करते हुए वीरता, और साहसपूर्वक मानव को जीवन यापन करना है। किन्तु इसके साथ-साथ आध्यात्मिक सम्पत्ति की भी उपेक्षा नहीं करनी है।

वेदों में पाप से धनार्जन की निन्दा करते हुए बहुत से मन्त्रों में मनुष्य को उपदेश दिया गया है।

अक्षैर्मा दीव्यः कृषिमित्कृषस्व,
केवलाघो भवति केवलादी।

यजुर्वेद के बीसियों मन्त्रों में भिन्न-भिन्न पेशों से अपनी आजीविका करने वालों की चर्चा हुई है। इन से मालूम होता है कि वैदिक अर्थ-व्यवस्था में किसान, लुहार, स्वर्णकार, कुम्भकार रथकार, शस्त्रकार आदि बीसियों पेशों का समावेश होता है। यह सब वैदिक अर्थव्यवस्था के अंग हैं।

पृथ्वी-सूक्त

अथर्ववेद का उपवेद अर्थवेद माना जाता है। यह अर्थ वेद जैसा कि नाम से ज्ञात होता है, आर्थिक विषयों से सम्बद्ध होगा, किन्तु आज वह उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसके आधार पर वैदिक अर्थव्यवस्था का विवेचन सम्भव नहीं है। किन्तु यदि अथर्ववेद के प्रसिद्ध पृथ्वी-सूक्त पर एक दृष्टि डाली जाय तो किसी राष्ट्र के लिए आवश्यक अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ न कुछ जानकारी मिल सकती है। इसमें ऐसी मातृभूमि की कल्पना की गई है, जहां कृषि बहुत अन्न उपजाती है, जिसमें नदियों और समुद्रों की कमी नहीं है, जिसमें गौओं और अश्वों तथा खनिज पदार्थों की बहुतायत है।

"यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवुः।"
"हिरण्यवक्षा जगती निवेशनी"
"यां मायाभिरन्वचरन् मनीषिणः।"

इसी सूक्त में मनुष्यों के लिए कृषि, पशुपालन, समुद्र और नदियों के पानी के प्रयोग की चर्चा है और कहा है कि जिस भूमि में पानी निरन्तर बरसता है या बहता है, वह भूमि हमें धन-धान्य दे। भूमि के गर्भ और भूमि के ऊपर जो तेज है, उसका हम उपयोग करें। अथर्ववेद के अन्य सूक्तों में भी कृषि और गोपालन पर ध्यान दिया गया है।

ऋग्वेद में भूमि अथवा पृथ्वी, उत्तम अन्न और जल से युक्त, विविध पदार्थों की दात्री, अतएव बड़ी भारी, गौ आदि पशुओं से समृद्ध मानी गई है। वह भूमि में बीज वपन करने वाले एवं राजा को कर आदि देने वाले या ध्यान और मनोयोग देने वाले उद्योगी पुरुष को पक्के फलों से लदी शाखा के समान सदा परिपक्व, धान्य सम्पदाओं से युक्त होकर, उसे नाना भोग्य सुख प्रदान करती है :—

"एवा ह्यस्य सूनृता विरप्शी गोमती मही।
पक्वा शाखा न दाशुषे ॥"

अथर्ववेद में भी भूमि की महिमा 'देवी' के रूप में गौरवान्वित है :—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"शिला भूमिरश्मा पांसुः
सा भूमिः संधृता धृता।
"तस्यै हिरण्यवक्षसे।"
पृथिव्या अकरं नमः॥" (१२-१-२६)

सत्रहवां अठारहवां सूक्त तो कृषि और वनस्पति के सम्बन्ध में ही है। स्थानाभाव से हम यहां उनके उद्धरण नहीं देते। शाला निर्माण के सम्बन्ध में अथर्ववेद में जो मंत्र दिये गये हैं, उनसे स्पष्ट है कि वेद जन-सामान्य को सुख सम्पत्ति और पशु तथा धन-धान्य देना चाहता है। एक मन्त्र में अश्वावती गोमती, ऊर्जस्वती, पयस्वती, घृतवती शाला की कामना की गई है। वेद में जहां नौकाओं का वर्णन है, वहां बहुत सुन्दर छिद्ररहित और मजबूत नावों की चर्चा की गई है। अथर्ववेद के ११वें सूक्त में ब्रह्मौदन की चर्चा करते हुए कृषि के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ कह दिया गया है। स्थान-स्थान पर वेदों में शत्रु विनाश और युद्ध के प्रसंग में ऐसे शस्त्रास्त्रों की चर्चा है, जो बिना भौतिक और वैज्ञानिक समृद्धि के बन ही नहीं सकते। समृद्धि, श्री, वसु आदि की प्रार्थना करते हुए वेद कहता है, हे मनुष्य, तू सौ सौ हाथों से कमा और हजार-हजार हाथों से दान दे।

ऋषि दयानन्द ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका' में कहा है कि वेदों में विमानों, सुन्दर नौकाओं और स्थल मार्ग से चलने वाली सवारियों की काफी चर्चा है। समुद्र, भूमि और अन्तरिक्ष में चलने वाले यान वैदिक अर्थव्यवस्था का परिचय देते हैं। उन्होंने तो ऋग्वेद का एक मन्त्र देते हुए यहां तक लिखा है कि विद्युत के प्रयोग से दूर-दूर तक समाचार भेजने वाले तारों का भी वेदों में उल्लेख है। राजा के लिये प्रतिपादित कर्तव्यों को यदि हम देखें तो वैदिक समृद्ध अर्थव्यवस्था की अच्छी जानकारी होती है।

लेख के अन्त में हम यह पुनः स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि वेद की अर्थव्यवस्था में जहां भौतिक समृद्धि का उल्लेख पाया जाता है, वहां उससे भी अधिक सामाजिक न्याय, भगवान के बनाये गये सब मानवों को अन्न-भोजन, शिक्षा आदि की समान सुविधा की भी प्रार्थना की गई है और इसीलिए वेद में सरल त्यागमय जीवन और दान आदि पर बहुत बल दिया गया है। भौतिक और आध्यात्मिक, लौकिक और पारलौकिक, अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों वेद को अभीष्ट हैं। इसीलिए संसार को त्यागपूर्वक भोगने और किसी दूसरे का अधिकार अपहरण न करने का वेद आदेश देता है। यही वेद का अर्थशास्त्र है।

म. गांधी के सर्वोदय के साथ भौतिक समृद्धि वेद को स्वीकारणीय है।*

(पृष्ठ ५०६ का शेष)

(२) भाटक-सिद्धांत उसकी अमूल्य देन है। उसमें उसने दो तथ्यों पर विशेष बल दिया।

१. भाटक अनुपार्जित आय है।

२. भू-स्वामियों के हित समाज के व्यापक हितों के विरोधी हैं।

(३) अपने मूल्य-सिद्धान्त द्वारा उसने इस धारणा का प्रतिपादन किया कि श्रम ही वास्तविक लागत है।

(४) उसने मुक्त-व्यापार का समर्थन करते हुए तुलनात्मक लागत-सिद्धांत का प्रतिपादन किया।

(५) कागदी मुद्रा के नियन्त्रण सम्बन्धी उसके विचार आधुनिक जगत में अधिकांश में स्वीकृत हो चुके हैं।

(६) मैल्थस के उत्पादन-ह्रास-नियम को उसने विकसित किया।

(७) रिकार्डो ने अर्थशास्त्र में निगमन-प्रणाली को जन्म दिया।

(८) समाजवादियों ने आगे चलकर मुख्यतः रिकार्डो के विचारों पर ही अपने विचारों का भव्य प्रासाद खड़ा किया। व्यक्तिगत पूंजी का विरोध, वर्ग-संघर्ष, मार्क्स का प्रख्यात श्रम सिद्धान्त—इन सबके विकास के लिए रिकार्डो अधिकांश में उत्तरदायी है।

ग्रेक का कथन सत्य ही है कि "यदि मार्क्स और लेनिन की ऊर्ध्व काय मूर्तियां खड़ा करना अपेक्षित है, तो उनकी पृष्ठ भूमि में रिकार्डो की प्रतिमूर्ति होनी ही चाहिए।"

---

* सर्व सेवा संघ द्वारा प्रकाशित लेखक की आर्थिक विचार धारा से उद्धृत कुछ अंश।

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आर्थिक निर्माण में

भारत को अमरीकी योगदान

(श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल)

अपनी स्वाधीनता की रक्षा करने और अपनी जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए आत्म निर्भर अर्थ-व्यवस्था के निर्माण में आज देश संलग्न है। निश्चय ही यह एक ऐसा महान प्रयास है जो अपने सम्पूर्ण साधनों ने विदोहन करते हुए भी मित्र राष्ट्रों के सहयोग के बिना पूरा करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। हमारे इस प्रयास और प्रयत्न की कहानी मित्रों के सयहोग के उल्लेख बिना अपूर्ण रहेगी। हमारे इस विकासोन्मुख प्रयत्न में जहां एक ओर रूस अपना सहयोग दे रहा है, वहां अमरीका भी इस प्रयत्न में पूरा हाथ बटा रहा है।

अमरीकी योगदान इस दिशा में प्रथम है। नीचे हम उसी की संक्षिप्त झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं—

इस समय भारत को अमरीकी सहायता निम्नलिखित एजेंसियों द्वारा दी जाती है :

१. अन्तर्राष्ट्रीय विकास की अमरीकी एजेंसी (यू० एस० ए० आई० डी०—

समस्त अमरीकी आर्थिक सहायता को स्वीकृत प्रशासन के अन्तर्गत लाने के लिए ३ नवम्बर १९६१ को यह नई एजेंसी स्थापित की गई थी। वे सभी कार्यक्रम जो पहले 'इंटरनेशनल कोआपरेशन मिशन' के अन्तर्गत होते थे और जिनका प्रतिनिधित्व भारत में टेकनिकल कोआपरेशन मिशन (प्राविधिक सहयोग मिशन), डेवलपमेंट लोन फण्ड (विकास ऋण कोष) और शांति के लिए खाद्य कार्यक्रम (जन-कानून ४८०) द्वारा किया जाता था, अब अन्तर्राष्ट्रीय विकास की अमरीकी एजेंसी के कार्यक्षेत्र में आ गये हैं।

यह एजेंसी विकास ऋण और अनुदान दोनों देती है। अमरीकी सहायता कार्यक्रम के आरम्भ से अब तक अन्तर्राष्ट्रीय विकास की अमरीकी एजेंसी और उसके पूर्ववर्ती प्राविधिक सहयोग मिशन तथा अमरीकी विकास ऋण कोष ने ६,१५.२ करोड़ रुपये की सहायता दी है। इसका विवरण निम्न प्रकार है।

(i) मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, उच्चतर शिक्षा, राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद, शिल्पियों का प्रशिक्षण, डेरी विकास- सामुदायिक विकास, खेती तथा कई अन्य परियोजनाओं के लिए अनुदान दिये गये हैं। कुल मिलाकर १७०.८ करोड़ रुपये के विकास अनुदान दिये जा चुके हैं, जिनका भुगतान नहीं किया जाना है।

(ii) नवम्बर १९६१ के पूर्व प्राविधिक सहयोग मिशन ने कुल मिलाकर ७४.३ करोड़ रुपये के ऋण दिये थे। इन ऋणों का भुगतान रुपयों में हो अथवा डालरों में, यह भारत सरकार की इच्छा पर छोड़ा गया है।

(iii) अमरीकी विकास ऋण कोष ने, जो अब अन्तर्राष्ट्रीय विकास की अमरीकी एजेंसी में ही मिला दिया गया है, १९५८ और १९६१ के बीच भारत को कुल २४४.५ करोड़ रुपये के ऋण दिये। इन ऋणों का भुगतान रुपयों में ही होना है।

(iv) अन्तर्राष्ट्रीय विकास की अमरीकी एजेंसी, नवम्बर १९६१ में अपने स्थापना काल से अब तक कुल १२५.६ करोड़ रुपये के विकास ऋण दे चुकी है। इन ऋणों का भुगतान डालरों में होना है। इन ऋणों पर ब्याज नहीं लिया जायेगा। उन पर केवल एक प्रतिशत के तीन चौथाई हिस्से की अत्यन्त निम्नतम दर से उधार खाता शुल्क लगेगा।

२. पब्लिक ला—४८० कार्यक्रम —

जन-कानून—४८० भारत को समुचित मूल्यों पर कृषि सामग्री उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इस कार्यक्रम के तीन शीर्षक हैं :

(i) अमरीका और भारत के बीच भारी मात्रा में गेहूँ, चावल, मोटे अनाज, रुई, दूध का पाउडर और तम्बाकू सप्लाई करने के लिए कई समझौते हुए हैं। इन समझौतों के अन्तर्गत कुल ११३७.९ करोड़ रुपये के मूल्य की सामग्री प्राप्त हो चुकी है। भारत इन सामग्रियों के मूल्य का भुगतान रुपयों में करता है। इस राशि में ३७०.४ करोड़ रुपये के अनुदान भी सम्मिलित हैं।

(ii) आपत्कालीन सहायता के अन्तर्गत ३.७ करोड़

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

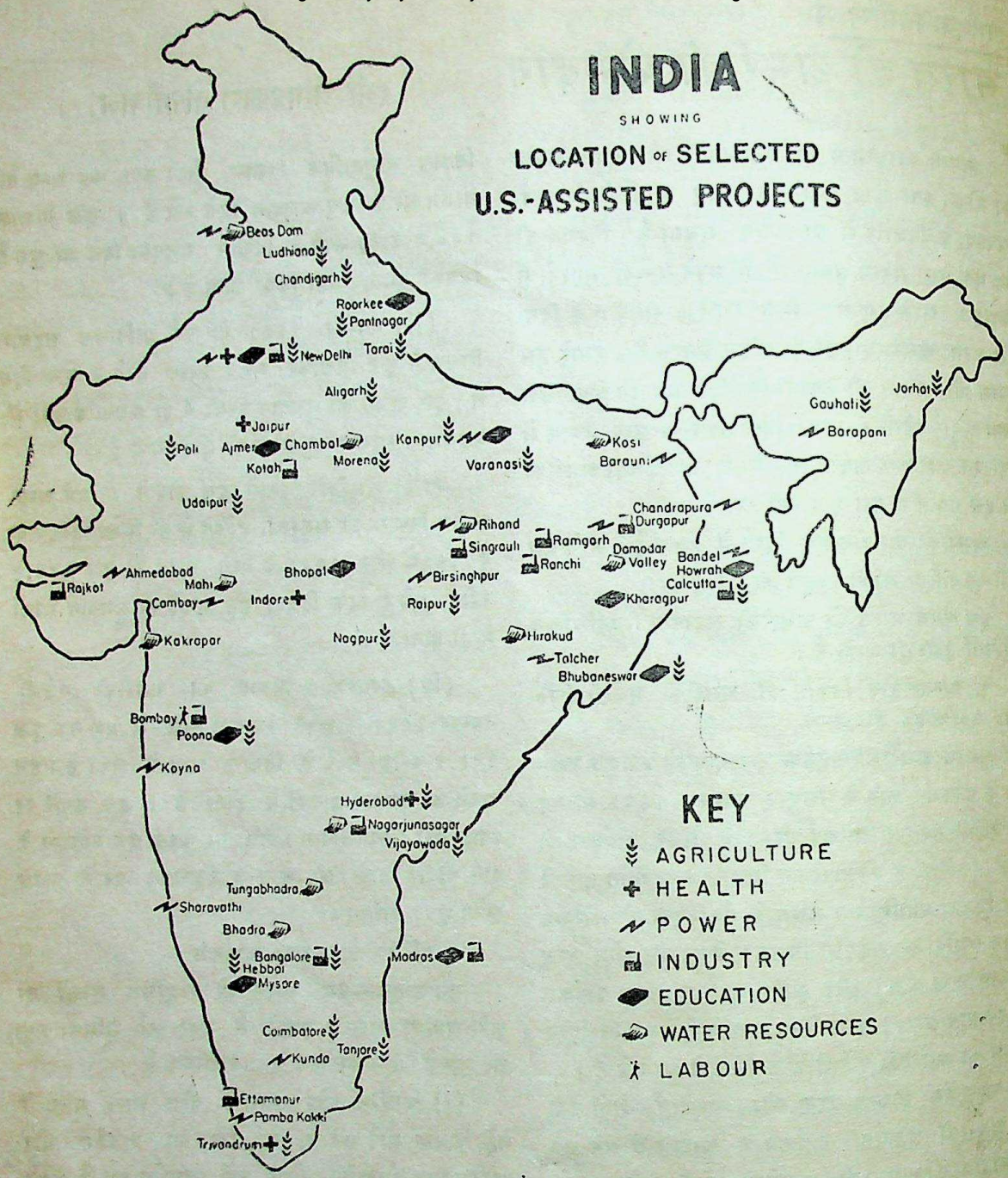

रुपये की कृषि सामग्री प्राप्त हुई है।

(iii) जन-कानून--४८० के तृतीय शीर्षक के अन्तर्गत एजेंसियों द्वारा भारत में ७३.४ करोड़ के मूल्य का दूध का पाउडर, गेहूँ, चावल, मक्का, बिनौले का तेल आदि सामग्रियां वितरित की गईं।

३. आयात—निर्यात बैंक :

इस बैंक ने भारत को ११७.६ करोड़ रुपये के नौ ऋण दिए हैं। इन ऋणों का उपयोग यहां के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के अनेक उद्योगों के लिए विभिन्न प्रकार

(शेष पृष्ठ ५१८ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत का सीमेण्ट-उद्योग

सीमेन्ट का उद्योग भारत के सबसे पुराने बुनियादी उद्योगों में से एक है। यद्यपि भारत में उद्योग के संगठित रूप का पता १९०४ से ही लगता है, किन्तु देश के मध्य-कालीन निर्माणों में प्राकृतिक सीमेन्ट मसाले को गारे के रूप में उपयोग में लाने के प्रमाण मिलते हैं। सदियों पहले दक्षिणी भारत में बने पक्के बांधों में प्रयुक्त सीमेन्ट मसाला अवश्य ही सीमेन्ट जैसे ही किसी देशी मसाले से निकला होगा।

"सर्वे आव इंडियन इंडस्ट्रीज" (भारतीय उद्योगों का सर्वेक्षण) से यह पता चलता है कि जोसेफ एस्पडिन को पोर्टलैंड सीमेन्ट बनाने के प्रयोगों में सफलता मिलने के दो वर्ष बाद ही १८२६ में, मद्रास में उपलब्ध, पोर्टलैंड सीमेन्ट बनाने के योग्य खनिजों पर सरकारी तौर पर विचार किया था। उससे कुछ निकटवर्ती काल सन् १८८९ में प्रकाशित डिक्शनरी आव इकोनामिक प्राडक्ट्स आव इंडिया" में मटीले कंकड़ों तथा भारी चूना-पत्थरों से कलकत्ते में पोर्टलैंड सीमेन्ट बनाने का उल्लेख मिलता है।

भारत में सीमेन्ट बनाने का पहला संगठित प्रयत्न बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ था। सीमेन्ट बनाने का एक कारखाना १९०४ में मद्रास में खोला गया था, किन्तु किन्हीं कारणों से वह बहुत दिनों तक चल न सका। दूसरा कारखाना १९१४ में गुजरात में खोला गया था। पहले विश्व युद्ध के दौरान मध्य प्रदेश व राजस्थान में दो और कारखाने खोले गए थे और उस अवधि में देश में सीमेन्ट की खपत का अधिकांश इन तीन कारखानों द्वारा ही पूरा किया जाता था। १९२२-२३ तक सात कारखाने और स्थापित हो गये तथा कुल उत्पादन क्षमता ५.९ लाख टन प्रतिवर्ष हो गई थी। इस अवधि में मांग में भारी गिरावट आ गई जिससे देशी उद्योग को संकट का सामना करना पड़ा। आयात की मात्रा बढ़ जाने के कारण उसी समय कीमतें लागत से भी नीची हो गईं और कई कारखाने जो प्रतियोगिता में टिक न सके, बन्द कर देने पड़े। अतः देशी उद्योग ने टैरिफ संरक्षण की प्रार्थना की, पर वह स्वीकृत नहीं हुई। फिर भी सीमेन्ट के आयात पर एक राजस्व कर लगा दिया गया। भारतीय सीमेन्ट निर्माता संघ की स्थापना १९२६ में हुई। तत्पश्चात् देश में सहकारी विक्रय व उत्पादन के लिए विभिन्न प्रयत्न किए गए, जिसके फलस्वरूप १९३६ में चालू दस कम्पनियों के सहयोग से एक नया कारखाना खोला गया।

१९३७ के बाद उद्योग तेजी से बढ़ा और कई नये कारखाने स्थापित हो गए। दूसरे विश्व युद्ध के प्रारम्भ में देश में १८ कारखाने थे तथा युद्ध के दौरान तीन और कारखानों में काम चालू हो गया। युद्ध के अन्त तक कारखानों की कुल क्षमता २६६ लाख टन प्रति वर्ष थी। देश के विभाजन के फलस्वरूप भारत में केवल १८ कारखाने रह गये।

कारखानों की संख्या तथा क्षमता

१९४८ और १९५९ की अवधि में विश्व में सीमेन्ट का उत्पादन दुगना होकर २९२० लाख टन हो गया। १९४८ में भारत में सीमेन्ट का उत्पादन १५७८ हजार टन था जो विश्व उत्पादन का १.५ प्रतिशत था। १९५९ तक भारत का उत्पादन साढ़े तीन गुना बढ़कर ६९ लाख मी० टन हो गया जो कि विश्व उत्पादन का २.४ प्रतिशत था। उस समय सीमेन्ट के सबसे बड़े विश्व निर्माताओं में भारत का स्थान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, पश्चिमी जर्मनी, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन देश के बाद नवां था।

१९५०-५१ में भारत में २१ कारखाने थे, जिनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता ३३ लाख टन प्रति वर्ष थी। पहली पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक कुल ५० लाख टन की क्षमता वाले २७ कारखाने थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में १९६०-६१ तक सीमेन्ट उद्योग की क्षमता का अनुमानित लक्ष्य १६० लाख टन तथा उत्पादन १३० लाख टन रखा गया था। बाद में क्षमता के लक्ष्य को संशोधित करके उसे ११० लाख टन रखा गया था। दूसरी योजना के अन्त तक सीमेन्ट उत्पादन करने वाले कारखानों की संख्या ३४ थी तथा कुल अधिष्ठापित क्षमता ९२ लाख टन प्रति वर्ष के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आस-पास थी। राज्यक्रम से कारखानों की संख्या निम्न थी-- बिहार में ७, आंध्र प्रदेश में ५, गुजरात में ५, मद्रास में ४, मध्य प्रदेश में ३, मैसूर में ३, पंजाब में २, तथा राजस्थान, उत्तर प्रदेश व केरल में एक-एक। सीमेन्ट का उत्पादन १९५५-५६ के ४७ लाख टन से बढ़कर १९६०-६१ में ७९ लाख टन हो गया। १९५२ से बाद के सीमेन्ट उत्पादन के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं—

वर्ष	कारखानों की संख्या	उत्पादन (लाख टन)
१९५२	२३	३६
१९५३	२४	३८
१९५४	२५	४५
१९५५	२७	४६
१९५६	२८	५०
१९५७	२८	५७
१९५८	३१	६२
१९५९	३२	६९
१९६०	३२	७८
१९६१	३४	८४

उत्पादन लक्ष्य तथा अनुमित मांग—देश के विशाल निर्माण-कार्यक्रमों के फलस्वरूप सीमेंट की खपत पिछले कुछ सालों से काफी बढ़ गई है। सीमेंट की खपत आजकल प्रतिवर्ष १० प्रतिशत बढ़ने की आशा है। देशीय खपत तथा निर्यात दोनों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सीमेन्ट उद्योग के उत्पादन तथा क्षमता के १९६५-६६ तक लक्ष्य क्रमशः १३० लाख व १५० लाख टन रखे गए हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले साल में तीन चालू कारखानों की क्षमता (१७० टन कचरा सीमेंट की क्षमता सहित) बढ़ाने तथा मैसूर में एक नया कारखाना खोलने की योजना पूरी होने वाली थी। लाइसेंस प्राप्त नये कारखानों में से दो आंध्रप्रदेश व एक-एक जम्मू और काश्मीर, मद्रास, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में खुल रहे हैं। १४ चालू कारखानों को बढ़ाने की योजना के लिए भी लाइसेंस दिये जा चुके हैं। गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मद्रास और पंजाब में नये कारखाने खोलने की प्रयोजनाओं को अभी आयात लाइसेंस नहीं मिला है।

कचरा सीमेंट—भारत के सीमेंट उद्योग को कच्चे माल की बहुतायत की वजह से बहुत बल मिला है। पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल ये हैं :— चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी, जिप्सम और कोयला। कोयले का इस्तेमाल ईंधन तथा कच्चे माल दोनों तरह से होता है। चूंकि देश में अच्छी किस्म के चूना-पत्थर की उपलब्धि सीमित है तथा दूसरे उद्योगों में भी इसकी मांग आजकल बढ़ गई, है अतः नये ढंग के कच्चे माल जैसे कि धमन भट्ठी कचरा तथा पोल्स्वालानिक मसाले से काम चलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। लोहा व इस्पात संयंत्रों से प्राप्त धमन भट्ठी कचरे को जरूरत के अनुसार तैयार कर लेते हैं। अनुमान है कि कचरा सीमेंट संयंत्र आदि के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा पोर्टलैंड सीमेंट उपस्कर से कम बैठेगी।

पहली पंचवर्षीय योजना में कचरा सीमेंट बनाने की क्षमता का विकास नहीं हो पाया। किन्तु दूसरी योजना के अन्त तक कुल १८ हजार टन प्रतिवर्ष कचरा सीमेंट बनाने की क्षमता स्थापित हो गई। बाद में, बिहार की एक सीमेंट फैक्टरी को, १७० हजार टन कचरा सीमेंट प्रतिवर्ष बनाने के लिए, मंजूरी दी गई। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के दो नये तथा बिहार व उड़ीसा के चार चालू कारखानों द्वारा कचरा सीमेंट के उत्पादन की १२ लाख टन प्रतिवर्ष की क्षमता ऐसी योजनाओं में शामिल है, जिन्हें अभी आयात लाइसेंस नहीं मिला था और जिनमें देशी उपकरणों का उपयोग किया जायेगा।

केरल के कोट्टायम और गुजरात के पोरबंदर में स्थित दो कारखानों ने सफेद सीमेंट बनाना शुरू कर दिया है। मद्रास के एक नये व मध्य प्रदेश के एक चालू कारखाने द्वारा सफेद तथा रंगीन सीमेंट बनाने को ०.४ लाख टन की क्षमता तीसरी योजना की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता में शामिल की गई है।

सजावटी जलसह सीमेंट लेप, सीमेंट जलरोधी यौगिक तथा विभिन्न रंगों का रंगीन पोर्टलैंड सीमेंट भी अब भारत में बनता है।

आजकल एस्बेस्टस सीमेंट कुल २४७,००० टन प्रतिवर्ष की स्थापित क्षमता वाले छः कारखानों में बनता है।

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१९६० व १९६१ में एस्बेस्टस सीमेंट का वास्तविक उत्पादन क्रमशः २११,२७० व २१४,००० टन था।

निवेश—१९६५-६६ तक १५० लाख टन की उत्पादन क्षमता के लिए लगभग ५५ से ६० करोड़ रु० की कुल पूंजी लगाना जरूरी होगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाये गये कार्यक्रमों पर अमल करने के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा लगभग १३.२५ करोड़ रु० होगा।

किस्म नियंत्रण—भारतीय मानक संस्था द्वारा धमन भट्ठी कचरा सीमेंट (पोर्टलैंड), तथा जल्दी जमने वाला व मंदताप सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट एवं पोर्टलैंड सीमेंट में असंयुक्त चूने के निश्चय की परीक्षण पद्धति के लिये विशिष्ट विवरण तैयार किये गये हैं।

आयात—भारत में सीमेंट की कमी के कारण १९६१-६२ में ४८,८०,१५० रु० के मूल्य का ४३,५२९ टन सीमेंट का आयात हुआ जबकि १९६०-६१ में केवल ५,७४,९९८ रु० का १,१५३ टन सीमेंट आया था। १९६१-६२ में मुख्यतः ब्रिटेन, संयुक्तराज्य अमेरिका, स्वीडन, नीदरलैंड्स, पश्चिम जर्मनी व पश्चिम पाकिस्तान से आयात हुआ। भारत में एस्बेस्टस सीमेंट की लहरदार चद्दरों आदि जैसे इमारती सामान का १९६०-६१ के ८,२२,४६२ रु० के मुकाबले में १९६१-६२ में ४९,३६,३०२ रु० के मूल्य का आयात हुआ।

निर्यात—१९६०-६१ तथा १९६१-६२ में भारत से निर्यात किये गये विभिन्न प्रकार के सीमेंट का परिमाण क्रमशः ९२,०२६ और ९७,५९१ टन है तथा मूल्य क्रमशः ६३,९८,६११ और ९०,२०,३०२ रुपये हैं। १९६०-६१ व १९६१-६२ में भारत से विदेशों को निर्यात किये गये पोर्टलैंड धूसर सीमेंट के आंकड़े नीचे सारिणी में दिये गये हैं :—

	१९६०-६१		१९६१-६२	
	परिमाण (टन)	मूल्य (रु०)	परिमाण (टन)	मूल्य (रु०)
पाकिस्तान	५८,६३८	३४,८९,५६९	३,९०९	३,९९,७७९
श्री लंका	१७,९०७	१२,८७,५८५	३१,१८१	२४,९२,८९७
पूर्वी पा०	३,९३१	४,७१,३७१	४५,५७५	४४,१५,९८२
ईरान	१,२५५	१,३१,६९७	३०५	२३,९१४
मसकत	२,२४१	१,४६,११४	२,९५७	२,२४,४९२
अफगानिस्तान	५१२	५,४९,८६५	३,३१९	३,४८,५८६
अन्य देश	११६	६,२६५	९३	१३,३११
योग	८८,९६०	६०,८२,४६६	८७,३३९	७९,१८,६६१

कीमतें—१९६१ में टैरिफ आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नियत तथा बिक्री दोनों प्रकार की कीमतें तीसरी योजना के दौरान लागू रहेंगी। टैरिफ आयोग की सिफारिशों पर पहली नवम्बर १९६१ से कीमतों में संशोधन किया जाय। अलग-अलग कारखानों से निकले माल की कीमत पहले वास्तविक लागत के अनुसार रखी जाती थी। निर्माताओं को अपनी कार्य-कुशलता बढ़ाने तथा लागत खर्च घटाने के लिये प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सरकार ने काफी ऊंची लागत-खर्च वाले ९ कारखानों को छोड़कर अन्य सभी के लिये खुले सीमेंट की कीमत ६९.५० रु० प्रति टन की एक-सी दर से तय कर दी है। सीमेंट का विक्रय तथा वितरण राज्य व्यापार निगम के द्वारा होना जारी है। खुले सीमेंट की बिक्री कीमत ९४रु० प्रति टन है, जो कि उत्पादन कर से अतिरिक्त है।

• •

विज्ञापन के लिए

सम्पदा

सर्वोत्तम

साधन है

नये विशेषांक की

प्रतीक्षा कीजिये

२८-११ शक्तिनगर, दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कांडला : भारत का छटा बड़ा बन्दरगाह

जब १९३० में कच्छ के तत्कालीन महाराजा ने स्थानीय जरूरतें पूरी करने के लिए कांडला में एक छोटा-सा घाट बनाने का निर्णय किया था, तब उन्हें यह ख्याल भी न होगा कि अगले तीस सालों में यह देश के बड़े बन्दरगाहों में से एक हो जाएगा और यहां जहाजों के घाट लगाने, उन पर माल लादने, उतारने और भंडारों तथा संचार की आधुनिकतम सुविधाएं होंगी।

उपयुक्त साधन

स्वतन्त्रता से पहले, उत्तर गुजरात, राजस्थान मध्य-प्रदेश, पंजाब और जम्मू-कश्मीर की जरूरतें कराची बन्दरगाह पूरी करता था। विभाजन के बाद इस प्रदेश को अन्य उपयुक्त बन्दरगाह की जरूरत पड़ी। पौने तीन लाख वर्गमील क्षेत्रफल और ६ करोड़ की जनसंख्या वाले इस पृष्ट प्रदेश के पश्चिमी छोर में स्थित कांडला सही माने में उपयुक्त स्थान था, क्योंकि बम्बई की अपेक्षा यह इस प्रदेश से २०० मील पास में पड़ता है। कांडला अहमदाबाद के बीच बड़ी रेल लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण हो जाने पर और भी अधिक बड़ा क्षेत्र बन्दरगाह का लाभ उठा सकेगा।

पर्याप्त तटीय गहराई तथा सुरक्षित होने के कारण यह प्राकृतिक बन्दरगाह है। इसमें काफी बड़े आकार के जहाज भी ज्वार भाटे की मदद से आ जा सकते हैं। नये औजारों के जरिये इसकी गहराई को बढ़ाया जा रहा है।

कांडला बन्दरगाह ने थोड़े ही समय में काफी तरक्की की है। १९५७-५८ में यहां से ८ लाख ५८ हजार मीट्रिक टन का आयात-निर्यात हुआ था, जो १९६२-६३ में बढ़कर १७ लाख ४२ हजार मीट्रिक टन हो गया, जो बन्दरगाह के निर्धारित लक्ष्य के निकट है। हाल में बड़े बन्दरगाहों के सम्बन्ध में जो विधेयक पास हुआ है, उसके अनुसार कांडला बन्दरगाह के संचालन के लिए स्वायत्त बन्दरगाह ट्रस्ट बनाया जाएगा। इनकी प्रगति का अन्दाज इससे ही लग सकता है कि आसाम के एक ताप-बिजली घर की भारी मशीनों का आयात इसी बन्दरगाह से हुआ। इन मशीनों में तीन बहुत भारी ट्रांसफार्मर भी थे, जिनमें से प्रत्येक का भार ४९ टन था।

निर्माण की कठिनाइयां

इस बन्दरगाह को बनाने में बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ऊंचे ज्वार को रोकने के लिए ६२ फुट ऊंचा एक समुद्री घाट अनिवार्यतः बनाना पड़ा। यह ऊंचाई विश्व के सबसे ऊंचे घाटों के बराबर समझी जाती है। बन्दरगाह के इलाके में समुद्र के नीचे की मिट्टी चिकनी मुलायम थी। इसलिए घाट के आधार के खंभों की नींव ७५ से ९० फुट तक गहराई पर रखनी पड़ी।

बन्दरगाह के विकास का काम पहली पंचवर्षीय योजना में हाथ में लिया गया और १४ करोड़ २३ लाख रु० की लागत से, जहाज ठहरने के चार गहरे घाट तथा माल गोदाम आदि १९५७ के मध्य तक तैयार हो गये। अब बन्दरगाह में ३८२५ फुट लम्बा एक जहाज-घाट है। इसमें साधारण आकार के पांच और छोटे आकार का एक जहाज एक साथ आ सकते हैं। जिन मालवाही जहाजों को मुख्य घाट में स्थान न मिल सके, उनके लिए तीन बांध घाट और नमक बनाने वाले जहाजों के लिए एक बांध घाट है। नौलाखी से नाव आदि द्वारा आने जाने वाले यात्रियों के लिए भी दो यात्री-घाट बनाया गया है।

सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध

बन्दरगाह में सब आवश्यक सुविधाएं हैं। यहां तीन ट्रांजिट शेड हैं, जिनमें १५,००० टन माल आ सकता है। शेड के पास चार, दुमंजिले माल गोदाम हैं, जिनमें ६०,००० टन माल रखा जा सकता है। ट्रांजिट शेड की पहली मंजिल पर पुल बना दिए गए हैं। माल ऊपर ले जाने के लिए माल गोदाम में बिजली से चलने वाले १६ लिफ्ट भी हैं। माल की आवत-जावत तेजी से करने के लिए घाट, ट्रांजिट-शेड व गोदामों को रेल लाइनों से सम्बद्ध किया गया है।

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नया सामयिक साहित्य

व्यापारिक क्रियाशीलन प्रशासन एवं प्रबन्ध—लेखक—डा० के० सी० भण्डारी, और जे० आर० कुम्मट, प्रकाशक—लक्ष्मीनारायण, आगरा। पृष्ठ संख्या ६४०; मूल्य सजिल्द १५ रुपया।

हिन्दी के शिक्षा का माध्यम होने के साथ ही हिन्दी में जिस तरह विभिन्न शास्त्रों का उच्च साहित्य तैयार होने लगा है, उसका यह ग्रन्थ एक उत्कृष्ट प्रमाण है।

पंचवर्षीय विकास योजनाओं के साथ-साथ भारत में निरन्तर औद्योगिक क्षेत्र व्यापक, विशाल और विस्तृत होता जा रहा है। प्रायः प्रत्येक राज्य में सरकारी या गैर सरकारी सैंकड़ों उद्योग छोटे बड़े और वृहदाकार स्थापित हो रहे हैं और इसीलिए अब उद्योगों का संचालन अपनी विविध समस्याओं के साथ कठिन और पेचीदा होता जा रहा है। अब कुछ थोड़े से व्यापारी पूंजीपति उद्योगों का संचालन नहीं कर सकते। उद्योगों के प्रशासन और प्रबन्ध तथा कारखानों के निर्माण आदि के लिए आज हमें ऐसे विशेषज्ञों की आवश्यकता है, जो वस्तुतः आज के वैज्ञानिक युग में कारखानों का सुचारु संचालन कर सकें। यही कारण है कि विदेशों की तरह भारत में भी वाणिज्य प्रशासन, भवन निर्माण आदि का विषय महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है और वैज्ञानिक रूप धारण करता जा रहा है। प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखकों ने ४३ अध्यायों में उद्योग संचालन के विविध वर्तमान पहलुओं का विस्तार से परिचय दिया है। इसमें उद्योग संचालन के अर्थ से लेकर इति तक प्रायः सभी विषयों का परिचय दिया गया है। स्नातकोत्तर परीक्षाओं के छात्र तो इससे लाभ उठायेंगे ही, इस पुस्तक से वे व्यापारीयों और प्रबन्धकर्त्ता जो आज विभिन्न संस्थानों में बिना कालिज में वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त किए काम कर रहे हैं, अपने विविध कार्यों का विधिवत व्यवस्थित शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। हम इस पुस्तक के प्रकाशन और लेखन के लिए प्रकाशक और लेखकों का धन्यवाद करना चाहते हैं। अनेक पारिभाषिक शब्द हिन्दी में नये बनाये गये हैं। पाठकों की सुविधा के लिए उनके अंग्रेजी प्रचलित शब्द भी साथ-साथ दे दिए गये हैं।

कामायनी में शब्दशक्ति चमत्कार—लेखक—डा० विमलकुमार जैन। प्रकाशक—हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली-६। मूल्य ५ रुपया। पृष्ठ संख्या १६०.

साहित्य और काव्य के दो अंग होते हैं। भाव पक्ष उसकी आत्मा है, और कला पक्ष उसका शरीर। प्रस्तुत विवेचन में विद्वान लेखक ने कामायनी का, जो इस सदी का सम्भवतः सर्वश्रेष्ठ हिन्दी महाकाव्य है, कला पक्ष लिया है। कामायनी के अभिधा सौन्दर्य, लाक्षणिक प्रयोग, भाव व्यंजना और अलंकार सौन्दर्य इन चार अध्यायों में समस्त पुस्तक विभक्त की गई है।

विद्वान लेखक हिन्दी साहित्य के सुयोग्य अध्यापक हैं। अपने दीर्घ अध्ययन काल में कामायनी का बार-बार पाठ करते हुए उन्हें जिस आनन्द और रस की अनुभूति हुई और महाकवि प्रसाद के अद्भुत कला चमत्कार पर जिस तरह वे मुग्ध हुए, उसने लेखक को यह ग्रन्थ लिखने के लिए विवश कर दिया।

काव्य शास्त्र के विद्यार्थियों और काव्य के रसिकों दोनों को यह विवेचन आनन्द प्रदान करेगा। कामायनी केवल मनोविनोद की कृति नहीं, इसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि बहुत गम्भीर भी है। उसे स्थल-स्थल पर समझने के लिए भाव-व्यंजना का प्रकरण विशेष रूप से सहायक रहेगा।

कोड ऑफ कण्डक्ट : चारटर्ड अकाउन्टैंट—

ये दोनों पुस्तकें अंग्रेजी में हैं और इन्स्टीच्यूट आफ चारटर्ड अकाउन्टैंटस आफ इण्डिया द्वारा प्रकाशित की गई हैं। प्रथम पुस्तक में चारटर्ड अकाउन्टैंटों को यह बताया गया है कि उन्हें अपने कार्य में किस तरह से ईमानदार होना चाहिए। इस सम्बन्ध में जो सरकारी कानून बने हुए हैं, उनका विस्तार से परिचय दिया गया है। इसे पढ़कर चारटर्ड अकाउन्टैंट उन गलतियों से बच सकेंगे, जो कानून के द्वारा निषिद्ध हैं।

दूसरी पुस्तक में अकाउन्टैण्टों और आडिटरों के लिए अनेक सूचनाएं दी गई हैं। उनकी आज की समस्याओं का इसमें परिचय दिया गया है। पिछले दिनों

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

में अनेक कम्पनियों के आय व्यय की जांच को लेकर कुछ क्षेत्रों में आय व्यय के कार्य का ही राष्ट्रीयकरण करने की मांग की गई थी। वस्तुतः आडिटर का काम अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यदि यह कार्य ईमानदारी से हो तो उद्योग में भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। इस दृष्टि से दोनों पुस्तिकाओं का महत्व बहुत अधिक है।

नवनीत (दीपावली अंक)—सम्पादक--श्री सत्यकाम विद्यालंकार। प्रकाशक—नवनीत प्रकाशन लि० ३४१ तार देव, बम्बई।

प्रस्तुत विशेषांक में सामग्री का सुन्दर संकलन, बाह्य रूप रंग और चित्र भूषा आदि वे सब परम्परायें अपनाई गई हैं, जिनके कारण नवनीत हिन्दी पाठकों में अत्यन्त लोकप्रिय और प्रतिष्ठित बन गया है। इसमें अनेक सुन्दर विचारपूर्ण, ज्ञानवर्द्धक और स्वस्थ प्रवृत्ति के सूचक लेख दिये गये हैं। इन लेखों से यह स्पष्ट हो जाता है, कि हिन्दी का पाठक केवल हल्के साहित्य में रुचि नहीं लेता, वह कुछ जानना चाहता है, और मानव-जीवन की समस्याओं के सम्बन्ध में भी कुछ गम्भीर विचार चाहता है।

डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, श्री कन्हैयालाल मुन्शी, श्री श्रीगोपाल नेवटिया, श्री काका कालेलकर आदि के लेख जहां प्रेरणादायक हैं, वहां श्री सत्यकाम विद्यालंकार श्री के० बी० नारायण, श्री कुमार मंगलम् के लेख और दुनिया की दौड़ में हम कहां तथा अणु शस्त्र का अशुद्ध त्रैराशिक आदि ज्ञानवर्द्धक लेख हैं। कहानी, और कविताओं के अतिरिक्त मेरे जीवन की एक बड़ी भूल बहुत सुन्दर और मौलिक सूझ है। स्थान-स्थान पर सुन्दर उक्तियां नवनीत की अपनी विशेषता है, जो इस अंक में भी पाठकों को ऊंचे विचार के लिए प्रोत्साहन देती हैं।

● ●

(पृष्ठ ५१२ का शेष)

के साज सामानों की खरीद में किया गया है। उन उद्योगों में से कुछ हैं : अलुमिनियम, रेयान, कागज, मशीनी औजार, खान, बिजली, उड्डयन, संचार आदि। इन ऋणों का अनुमान डालरों में होना है।

गेहूँ ऋण : १९५१ में अमरीकी कांग्रेस ने भारत को ९०.०३ करोड़ रुपये का ऋण देने के लिए कानून बनाया, जिससे कि भारत खाद्यान्नों की तीव्र कमी का सामना करने के लिए २० लाख टन गेहूँ खरीद सकें। इस ऋण का भुगतान डालरों में होना है।

इस सबके अतिरिक्त संकट कालीन बाढ तथा अकाल सहायता के अन्तर्गत २.६ करोड़ रुपये की सहायता मिली है। इस प्रकार आर्थिक सहायता कार्यक्रम के आरम्भ से भारत को दी जाने वाली अमरीकी सहायता जून १९५१ से जून १९६२ तक निम्न प्रकार रही है :

	करोड़ रुपयों में
अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमरीकी एजेंसी	६१५.२
पब्लिक ला ४८०	१,२१५.०
आयात-निर्यात बैंक	११७.६
१९५१ का गेहूँ ऋण	९०.३
संकट कालीन बाढ तथा अकाल सहायता	२.६
कुल योग	२,०४०.७

२०४०.७ करोड़ रुपये की सहायता में अनुदान, ऋण जिनका भुगतान रुपयों में किया जाना है और ऋण जिनका भुगतान डालरों में होना है, उनका विवरण निम्न प्रकार है :

	रु० करोड़ों में	कुल ऋण का प्रतिशत
१. अनुदान	६२७.९	३०.८
२. ऋण, जिनका भुगतान डालरों में	३३३.५	१६.३
३. ऋण, जिनका भुगतान स्थानीय मुद्रा में होनी है।	१,०७९.३	५२.९
कुल योग	२,०४०.७	१००.०

इस विवरण से पता लगता है कि कुल सहायता के लगभग छटे अंश का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाना है। लगभग ३१ प्रतिशत अनुदान के रूप में है। शेष ५३ प्रतिशत का भुगतान रुपयों में होना है।

● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बैंकों पर नये कठोर नियंत्रण

(श्री संजय)

भारत सरकार के वित्तमंत्री यह स्पष्ट कर चुके हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। स्वयं प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने भी यही घोषणा की है। किन्तु एक बैंक अधिकारी के शब्दों में बैंकों पर नये नियंत्रण का विधेयक अप्रत्यक्ष रूप से बैंकों का राष्ट्रीयकरण ही है। उसके शब्दों में सरकार बैंकों का व्यावहारिक रूप से राष्ट्रीयकरण ही कर रही है, इस सतर्कता के साथ आने वाली जिम्मेदारियों से वह मुक्त रहे। यद्यपि यह कथन अत्युक्ति पूर्ण ही है, तथापि बैंक सम्बन्धी नये विधेयक के द्वारा रिजर्व बैंक के अधिकार इतने अधिक बढ़ गये हैं कि बैंकों की स्वतंत्रता समाप्त प्राय हो गई है।

नये विधेयक के अनुसार रिजर्व बैंक किसी भी बैंक के संचालकों और प्रमुख अधिकारियों को बर्खास्त कर सकेगा तथा अपनी ओर से पांच संचालक नियुक्त कर सकेगा। रिजर्व बैंक किसी भी कर्जदार को बैंक द्वारा ऋण देने की मात्रा पर प्रतिबन्ध भी लगा सकेगा। वह किन्हीं बैंकों के परस्पर विलीन होने की योजना भी चालू कर सकता है और इन सब कार्यों में कानूनी अदालतें कोई दखल नहीं दे सकेंगी। इसका अर्थ है कि रिजर्व बैंक अपने इन अधिकारों का प्रयोग बिना किसी अपील के खतरे के कर सकता है। किसी भी शेयर होल्डर को कुल मतों के एक प्रतिशत से अधिक वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। आजकल यह अधिकार पांच प्रतिशत तक सीमित है। बैंकों के अतिरिक्त उन सब औद्योगिक और व्यापारिक संस्थानों पर भी रिजर्व बैंक नियंत्रण रख सकेगा, जो लोगों के रुपये जमा करके सूद देते हैं, जो खरीद बिक्री में वित्तीय सहायता देते हैं, जो साहूकारा करते हैं और जो विनियोजन ट्रस्ट का काम करते हैं। इसका अर्थ यह है कि रिजर्व बैंक को प्रायः सभी कम्पनियों के कारोबार में हस्तक्षेप करने का निरंकुश अधिकार मिल जायगा।

अन्य किसी भी देश में केन्द्रीय बैंक को इतने निरंकुश और असीम अधिकार प्राप्त नहीं हैं। इस विधेयक की धाराओं का यदि किसी भी तरह दुरुपयोग किया गया तो उसके परिणामस्वरूप भारत के उद्योग और बैंकिंग क्षेत्र की स्वतन्त्रता सर्वथा नष्ट हो जायगी। कोई उद्योग चलाने के लिए जिस साहस, पहल और सूझ की आवश्यकता होती है, उस पर इस नियंत्रण का बुरा असर पड़ेगा। रिजर्व बैंक जिन डायरेक्टरों को अपनी ओर से नियत करेगा, उनमें क्या-क्या योग्यताएं होनी चाहिएं और किन-किन विशेष अवस्थाओं में ही किसी संचालक या अधिकारी को बैंक बर्खास्त कर सकता है, इसका नये विधेयक में कोई उल्लेख हो, यह हमें अब तक ज्ञात नहीं है।

जब पीड़ित व्यक्ति को अदालत में अथवा किसी भी उच्चतर अधिकारी के पास जाने का भी अधिकार नहीं, तो यह बहुत सम्भव है कि रिजर्व बैंक के अधिकारी निरंकुश हो उठें और बैंकों के कारोबार में ऐसी मनमानी करने लगें, जिससे भारत के आर्थिक विकास में भारी बाधा पड़े। यदि किसी तरह जनता को यह मालूम हो जाय, कि रिजर्व बैंक एक बैंक के कार्य संचालन में हस्तक्षेप करने वाला है तो यह असम्भव नहीं है कि डिपाजिटर उस बैंक से एकदम रुपया निकालना शुरू कर दें और इस तरह बाजार में एक अवांछनीय हलचल मच जाय।

कुछ लोगों को यह भी सन्देह है कि यदि सरकार बैंकों का यह राष्ट्रीयकरण अप्रत्यक्ष रूप से करने जा रही है, तो उसका कारण यह है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण की स्पष्ट घोषणा से विदेशों में भारतीय नीति के प्रति सन्देह और आशंका उत्पन्न हो जायगी, और फिर बैंकों के राष्ट्रीयकरण का स्पष्ट परिणाम यह भी होगा, कि विदेशी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण करना होगा। आज सरकार विदेशों को नाराज नहीं करना चाहती। इसलिए राष्ट्रीयकरण की घोषणा न करते हुए भी भारतीय बैंकों को व्यावहारिक रूपेण सरकार के कठोर नियन्त्रण में लाने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। यह ठीक है कि कुछ बैंकों के संचालकों ने अपनी सत्ता का अनुचित उपयोग किया है, किन्तु इसका परिणाम समस्त बैंक व्यवसाय को दण्डित करना नहीं होना चाहिए। स्वयं अनेक सरकारी क्षेत्रों में भी अधिकारी गड़बड़ करते हैं। तो उसका अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि समस्त सरकारी क्षेत्र ही भ्रष्टाचार का शिकार है। ● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जीवन बीमा निगम की प्रगति

जब जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तब यह भारी सन्देह प्रकट किया गया था कि सरकार इस व्यवसाय को भलीभांति चला सकेगी। अनेक वर्षों के कठोर परिश्रम, अध्यवसाय और कुशल संचालन ने अब यह सन्देह दूर कर दिया है। नये वर्ष के विवरण से यह ज्ञात होता है कि १९६२-६३ के १५ महीनों में १७.६९ लाख पालिसियों के अन्तर्गत ७४६ करोड़ रु० का नया कारोबार हुआ, जबकि १९६१ में १४.७० लाख पालिसी ६०९ रु० पालिसियां ली गई थीं। इससे भी अधिक प्रसन्नता की बात यह है कि १२.२२ लाख करोड़ रु० पालिसियां उन उन लोगों ने लीं, जिनने इससे पहले एक भी पालिसी नहीं ली थी। इनमें से भी ६.७७ लाख बीमे देहाती क्षेत्रों में लिये गये। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि निगम के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने इस वर्ष नये लोगों में बीमे की चेतना पैदा की। अब नये नियमों के अनुसार सहकारी समितियां व पंचायतें निगम एजेन्ट के रूप में काम कर सकेंगी। इससे निगम को न केवल बहुत सुविधा हो गई है, बल्कि उसका कार्यक्षेत्र भी बहुत व्यापक हो गया है, क्योंकि देहातों में प्रीमियम की वसूली की कठिन समस्या का हल निकल आया है। गांवों में डाक्टरी परीक्षा की सुविधा नहीं थी, इसलिए बिना डाक्टरी परीक्षा की योजना वहां चालू कर दी गई है।

अब तो निगम ने आगामी वर्ष से आग, पानी, दुर्घटना, चोरी आदि के साधारण बीमे के क्षेत्र में भी प्रवेश का निश्चय किया है। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस नये कदम का अर्थ साधारण बीमे का राष्ट्रीयकरण नहीं है। अन्य बैंकों के साथ जिस तरह स्टेट बैंक भी अपना बैंकिंग कारोबार करता है, उसी तरह निगम भी अन्य बीमा कम्पनियों के साथ रहता हुआ कारोबार करेगा।

इस वर्ष के विवरण से यह जानकर कुछ दुख होगा कि लीन या लैप्स का अनुपात बढ़ता गया है। बीच में प्रीमियम बन्द कर देने वालों का अनुपात पिछले दो वर्षों के ६.६ और ७ प्रतिशत से बढ़कर ८.१ प्रतिशत तक हो गया है। इसकी ओर निगम को विशेष ध्यान देना चाहिए। सम्भव है, इसका कारण बढ़ती हुई महंगाई हो। ● ●

कम्पनियों के पास लोगों के डिपाजिट

साधारणतः बैंकों का यह मुख्य कार्य है कि वे जनता की बचत को एकत्र करके, देश के उद्योग व व्यापार में सहायता देने के लिए लगावें। बैंकों की आय का भी यह बड़ा भारी साधन है। किन्तु पिछले कुछ वर्षों से रुपये के बाजार में तंगी आने तथा बैंकों पर अनेक नियंत्रणों के कारण अब बहुत से उद्योग बैंकों पर निर्भरता छोड़ कर रुपये की व्यवस्था स्वयं करने लगे हैं।

उद्योग स्वयं जनता का रुपया जमा करते हैं और लोगों को बैंकों की अपेक्षा अधिक सूद देते हैं। यह आकर्षण जनता के लिए बहुत बड़ा होता है। विविध उद्योगों के पास कितना रुपया जमा है, इसकी आज कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। रिजर्व बैंक ने कुछ वर्ष पहले बहुत सी कम्पनियों से जो जानकारी प्राप्त की थी, उसके अनुसार १९५८ में कम्पनियों के पास लोगों का २४ करोड़ रुपया डिपाजिट था। यदि तीन करोड़ रुपया प्रति-वर्ष डिपाजिट बढ़े तो यह अनुमान किया जा सकता है कि इस समय करीब ४० करोड़ रुपया कम्पनियों के पास निजी रूप से जमा होगा।

स्वभावतः कम्पनियों की इस प्रवृत्ति को बैंक क्षेत्र प्रसन्नता के साथ नहीं देखता। बैंकों पर जो कानूनी नियंत्रण हैं, उन्हें देखते हुए वह बहुत सम्भवतः डिपाजिटरों को अधिक सुविधा दे भी नहीं सकता। कुछ लोगों का कहना यह है कि बैंकिंग व्यवसाय को बचाने के लिए कम्पनियों पर कुछ पाबन्दी लगानी होगी। किंतु इससे उद्योग को अपनी आवश्यकता के लिए पर्याप्त रुपया जुटाने में जहां कठिनता होगी, वहां मध्य वर्ग को भी अधिक ब्याज का लाभ मिलना बन्द हो जायगा। वस्तुतः इस प्रश्न के दोनों पहलुओं पर खूब अच्छी तरह विचार करने की आवश्यकता है। ● ●

—रिजर्व बैंक ने बैंक आफ अमेरिका को अपनी एक शाखा बम्बई में खोलने की अनुमति दे दी है। फस्ट नेशनल सिटी बैंक न्यूयार्क ने अपनी पहली शाखा नई दिल्ली में खोली हैं। अब भारत में इसकी चार शाखाएं हो गई हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा का सांख्यिकी पृष्ठ

विश्व में अनाज का उत्पादन : भारत में उत्पादन में कमी : भारत के खेतिहर मजदूर : विभिन्न देशों की नागरिकों की समृद्धि।

अनाज का उत्पादन और संभावनाएं

अधिक आय वाले देश

(मिलियन मैट्रिक टन)

अनाज	उत्पादन	खपत	सन्तुलन
गेहूँ १९५७-५९	९१	७७	+१४
१९७० निम्न	११५	८३	+३२
उच्च	११५	८२	+३३
मोटा अनाज १९५७-५९	२१८	२१२	+६
१९७० निम्न	२८०	२५५	+२५
उच्च	२८०	२६०	+२०
चावल १९५७-५९	१९	१८	+१
१९७० निम्न	२६	२०	+६
उच्च	२१	२०	+१
सब अनाज १९५७-५९	३२८	३०७	+२१
१९७० निम्न	४२१	३५८	+६३
उच्च	४१६	३६२	+५४

कम आय वाले देश

गेहूँ १९५७-५९	४३	५४	—११
१९७० निम्न	५९	७१	—१८
उच्च	६६	८३	—१७
मोटा अनाज १९५७-५९	८६	८३	+३
१९७०. निम्न	१०६	१०९	—३
उच्च	१२५	१०८	+१७
चावल १९५७-५९.	१११	१११	०
१९७० निम्न	१४९	१५६	—७
उच्च	१७३	१६७	+६
सब अनाज १९५७-५९	२४०	२४८	—८
१९७० निम्न	३१४	३४२	—२८
उच्च	३६४	३५८	+६

इस तालिका से स्पष्ट है कि सम्पन्न देशों में कृषि उत्पादन खपत की अपेक्षा १९७० में बहुत बढ़ जायगा, जबकि कम सम्पन्न देशों में खपत की अपेक्षा उत्पादन बहुत न्यून रहेगा।

विभिन्न देशों में गेहूँ का उत्पादन

निम्न लिखित तालिका से मालूम होता है कि कुछ देशों में १९०९-१३ की अपेक्षा १९५८-६० में गेहूँ का उत्पादन कम हो गया है, जबकि कुछ देशों में उत्पादन भिन्न-भिन्न मात्रा में बढ़ा है। भारत उन देशों में है, जिनमें उत्पादन कम हुआ है।

प्रतिशत कमी

मोरक्को	२३	पाकिस्तान	६
भारत	६	कनाडा	४

प्रतिशत वृद्धि

अल्जीरिया	३	रूस	५९
स्पेन	७	आस्ट्रेलिया	६०
स्वीडन	१३	ब्रिटेन	६१
द० अफ्रीका	१४	इटली	७०
हंगरी	१७	अमेरिका	७१
ट्यूनीशिया	१९	जापान	७४
डैनमार्क	३०	फ्रान्स	८३
पौलैंड	३४	अर्जेन्टाइना	८९
मिश्र	३७	स्वीट्जरलैंड	४७
ग्रीस	५६	मैक्सिको	२८२
बलोरिया	१८१		

नोट—यह सब अंक सं० रा० संघ की रिपोर्ट से लिये गये हैं।

—

भारत के खेतिहर मजदूर

दैनिक मजदूरी के आंकड़े

	१९५०-५१	१९५६-५७
प्रौढ़ स्त्री	६८ न० पै०	५९ न० पै०
प्रौढ़ पुरुष	१०९ न० पै०	९६ न० पै०
बालक	७० न० पै०	५३ न० पै०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा १३ वें वर्ष में

योजना-प्रगति-परिशिष्ट

आगामी अंक से सम्पदा १३ वें वर्ष में प्रवेश करेगी। इस अंक की विशेषता होगी—**योजना प्रगति-परिशिष्ट**। इस परिशिष्ट में तीसरी पंचवर्षीय योजना की सफलता, असफलता तथा समस्याओं पर स्वतंत्र विवेचन किया जायगा। ग्राफ व तालिकाएं इसकी विशेषताएं रहेंगी।

नये वर्ष से अन्य भी अनेक विशेष स्तम्भ प्रारम्भ करने का विचार है।

वर्ष में काम के दिन

	१९५०-५१	१९५६-५७
खेती हर मजदूर	२०० दिन	१९७ दिन
बच्चे	१६५ दिन	२०४ दिन

खेतिहर मजदूर परिवारों की औसत आय

१९५०-५१	१९५६-५७
४४७ रु०	४३७ रु०
मध्यप्रदेश	३०१ रु०

खेतीहर मजदूर का जीवन व्यय आय का प्रतिशत

भोजन	७७.३
अन्न	५६.९
चिकनाई	२.६
गुड़ चीनी	१.७
दूध दही	२.४१
नमक	.०४
मांस मछली	२.५
अन्य पदार्थ	१.७५
ईंधन व रोशनी	७.८७
मकान	.०४
कपड़ा-जूते	६.०५
सेवा आदि	८.७

खेतिहर मजदूरों पर कर्ज़

प्रति खेती हर	१९५०-५१	१९५६-५७
मजदूर पर कर्ज	१०५ रु०	१३८ रु०
कुल कर्ज	८० करोड़ रु०	१४३ करोड़ रु०

इन सब तालिकाओं से स्पष्ट है कि खेतिहर मजदूरों की स्थिति निम्न से निम्नतर हो गई है। पर मजदूरी कम हो गई है, औसत आय कम हुई है और वर्ष में काम के दिन कम हो गये हैं तथा उन पर कर्ज बढ़ गया है।

विभिन्न देशों में व्यक्तियों व सामग्री का अनुपात

	पैसेंजर कार	रेडियो	टेलीफोन	चिकित्सक
आस्ट्रेलिया	५	४	५	८५४
कनाडा	४	२	३	९२७
फ्रान्स	८	३	१०	१,००४
जर्मनी (पच्छिम)	१३	३	९	७०७
इटली	२५	६	१४	६९१
जापान	२२२	६	१७	१,०३०
ब्रिटेन	९	३	६	८०६
अमेरिका	३	१	२	—
भारत	१,५४५	२०१	९९०	४,९९७

प्रति व्यक्ति भोजन की खपत

	प्रति वर्ष अनाज (आटा)	चीनी	दूध (वसा)	प्रति दिन कैलोरी	प्रोटीन (ग्राम)
	किलोग्राम				
आस्ट्रेलिया	८८	५०	७	३,२६०	९३
कनाडा	७१	४५	८	३,१५०	९६
फ्रान्स	१०७	३२	६	२,९४०	९८
जर्मनी (पच्छिम)	८३	२९	६	२,९४०	८०
इटली	१४२	२५	४	२,७४०	७८
जापान	१५१	१४	१	२,२१०	६८
ब्रिटेन	८४	५०	७	३,२९०	८७
अमेरिका	६६	४१	८	३,१२०	९२
भारत	१३६	१४	३	१,९८०	५३

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मण्डल

श्री मोरारजी जे. वैद्य

स्वतन्त्र विश्व के व्यापारिक संगठनों के मस्तिष्क में अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मण्डल (इन्टरनेशनल चेम्बर आफ कामर्स) को वही स्थान प्राप्त है, जो राजनीतिज्ञों के विचार में संयुक्त राष्ट्रसंघ को है। यह स्वतन्त्र विश्व के तमाम वाणिज्य मण्डलों और व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। इसकी स्थापना १९१९ में प्रथम महायुद्ध के बाद हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सारे संसार में विश्व व्यापार बढ़ाने के मूलभूत लक्ष्य से निजी उद्योग को बढ़ाना और उसका प्रतिनिधित्व करना है।

यह मण्डल विगत ४४ वर्षों से अनेक प्रकार के कार्य कर रहा है और इसकी सदस्य संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। साठ से भी ज्यादा देशों में उसके सदस्य हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मण्डल पेरिस में विद्यमान अपने सदर मुकाम से अपने अनेक विशिष्ट आयोगों (कमीशनों) के जरिये कार्य करता है। इस अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य-मण्डल ने संयुक्तराष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तथा अन्य अन्तः सरकारी संगठनों से कार्यवाही सम्बन्ध स्थापित कर लिये हैं जैसे कि जनरल एग्रीमेंट आन ट्रेड एण्ड टेरिफ (जी० ए० टी० टी०) आर्थिक सहकार और विकास संगठन (आर्गेनीजेशन फार इकोनोमिक को-ओपरेशन एण्ड डेवलपमेंट) विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और सीमा शुल्क सहकार परिषद आदि। न्यूयार्क जेनेवा एवं बैंकांक स्थित संयुक्तराष्ट्र के कार्यालयों में इस मण्डल के स्थायी प्रतिनिधि विद्यमान हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य-मण्डल (आय० सी० सी०) की राष्ट्रीय समितियां है, जो मण्डल के केन्द्र और उसके आयोगों तथा विभिन्न देशों के अनेक वाणिज्य संगठनों के बीच सम्पर्क कड़ियों का काम करती हैं। आय० सी० सी० का उद्देश्य विभिन्न सरकारों तथा विभिन्न देशों के वाणिज्यिक और औद्योगिक संगठनों की मदद करना है ताकि वे व्यापार, उद्योग, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, सीमा-शुल्क, पद्धतियों, फैसलों आदि के बारे में एक समान नीति अपना सके।

इस मण्डल का आगामी अधिवेशन दिल्ली में होगा

यह मण्डल अपने कार्य विभिन्न कमीशनों के जरिये करता है।

प्राथमिक उत्पादन, प्रतिस्पर्धा निषेध,
विज्ञापन, प्रदर्शनियों में सहयोग
सूचना, औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षण आदि।

इनके अलावा इस मण्डल ने और दो विशिष्ट कमीशनों की स्थापना की है: (१) योरोपीय मामलों पर कमीशन (सी० इ० ए०) (२) एशिया और सुदूरपूर्व के मामलों पर कमीशन, जिसका सदर मुकाम नई दिल्ली में है। इस मण्डल की एक अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक पंच अदालत भी है, जो एक स्वतन्त्र संगठन है और वह व्यापारियों के तथा सदस्य देशों के व्यापारिक संगठनों के बीच के वाणिज्यिक विवादों का निपटारा करता है। अनुचित विज्ञापन पद्धतियों को रोकने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञापन पद्धति परिषद की स्थापना भी की गई है।

संसार के विभिन्न लोकतांत्रिक देशों में इसकी ४१ राष्ट्रीय समितियां हैं। हाल ही में युगोस्लाविया में भी एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई है। छब्बीस देश इसके एसोसियेटेड सदस्य हैं।

प्रत्येक दो वर्ष बाद अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य-मण्डल का वार्षिक अधिवेशन होता है। दूसरे महायुद्ध के बाद इस प्रकार की कांग्रेस टोकियो, नेपिल्स, वाशिंगटन, कोपेनहेगन में हो चुकी है। पिछली कांग्रेस गत वर्ष अप्रैल में मेक्सिको में हुई थी और आगामी वर्ष दिल्ली में होगी।

मैक्सिको अधिवेशन के विवरण में कहा गया है :—

"वर्तमान व्यापक एवं तीव्र तकनीकी प्रगति के युग में मानवीय जरूरतों तथा उनको पूरा करने के सन्दर्भ में यह बात साफ है कि मनुष्य के भाग्य को श्रेष्ठतर बनाने वाला कोई भी प्रयत्न तब तक सम्पूर्णतया सफल नहीं हो सकता है, जब तक कि वह राजनैतिक सीमाओं से परे न हो। आज अन्तर्राष्ट्रीय सहकार राष्ट्रीय समृद्धि की एक शर्त बन चुका है।"

● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थ वृत्त चयन

एक टिक टिक, तीन बच्चे

घड़ी की प्रत्येक टिक-टिक के साथ ही दुनिया में तीन बच्चे पैदा होते हैं ।

वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया है कि आज से सत्रह साल बाद दुनिया की आबादी चार अरब और ३७ साल बाद छः अरब हो जायेगी ।

रोजाना दस हजार आदमी इसलिए मर जाते हैं कि उनको भरपेट और पौष्टिक भोजन नहीं मिलता ।

भारत में अगले दस साल में पांच करोड़ नन्हे मुन्नों की मौत सिर्फ इसलिए होगी कि, परिवार बड़ा होने के कारण माता-पिता उनको पौष्टिक आहार नहीं दे सकेंगे ।

जिन देशों में आबादी कम है, लोगों ने अपनी आर्थिक हालत सुधार ली है । उदाहरण-स्वरूप अमरीका में । वहां हर आदमी रोज औसत से ४.६६ पौण्ड भोजन खाता है । लेकिन भारत में, जहां आबादी तेजी से बढ़ रही है और पैदावार उसी तेजी से नहीं बढ़ती, प्रत्येक व्यक्ति को रोज औसत करीब १.२३ पौण्ड भोजन ही मिल पाता है ।

काफी उद्योग

काफी उद्योग में किये गये अनेक विकास कार्यों का राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ा है । १९५० के मध्य तक काफी उद्योग केवल घरेलू बाजार तक ही सीमित रहा । १९५५-५६ से काफी उद्योग का निर्यात व्यापार सुदृढ़ होना आरम्भ हुआ । काफी उद्योग देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाने में जो योग दे रहा है, वह निम्न तालिका से स्पष्ट है—

वर्ष	(मीट्रिक टनों में) उत्पादन	निर्यात	निर्यात बिक्री से प्राप्त धन-राशि (लाख रु० में)
१९५५-५६	३५,०२८	८,०८२	५५३.२१
१९५६-५७	४२,५७२	१५,४७२	८४१.०९
१९५७-५८	४४,४९०	१४,२८१	६२४.०५
१९५८-५९	४६,६०५	१६,४००	६३३.७९
१९५९-६०	४९,७४०	१८,१८०	६५१.५५
१९६०-६१	६७,७९४	३२,२७१	८८७.६४
१९६१-६२	४५,७४२	३१,९५१	९५२.४८
१९६२-६३	५४,६७२	१०,९१३ (३०-६-६३ तक)	उपलब्ध नहीं

सहकारिता ध्वज

२ नवम्बर से ९ नवम्बर तक देश भर में सहकारिता सप्ताह मनाया गया था । इस अवसर पर सहकारिता का सतरंगी झण्डा फहराया गया ।

इंद्र धनुष, एकता, शांति और सहयोग का प्रतीक रहा है । इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सहकार आंदोलन के लिए इन्द्र धनुषी ध्वज चुना गया है । सब से पहले यह झंडा, फ्रांस में सहकारिता के अग्रदूत, चार्ल्स फोरियर ने अपनाया । १८३७ में फोरियर की मृत्यु के बाद भी हर वर्ष उनके अनुयायी यही झण्डा फहराते रहे । १८९६ में सहकार संघ के दूसरे सम्मेलन में जो पेरिस में हुआ था, एक प्रतिनिधि एफ० बनीरदा ने यह सुझाव दिया कि यह इन्द्र धनुषी झंडा ही अन्तर्राष्ट्रीय सहकार संघ का झंडा बनाया जाए । १९२४ में घेट में अन्तर्राष्ट्रीय सहकार सम्मेलन में जो प्रदर्शनी आयोजित की गयी, उसमें यह झंडा फहराया गया । बाद में कार्यकारिणी समिति ने सात रंगों की आड़ी पट्टियों वाला झंडा स्वीकार किया । यही मौजूदा झंडा है । यह झंडा इस बात का प्रतीक है कि अलग-अलग जाति और देशों के भेदभाव को भूल कर विश्व में सहकारी ढंग के समाज की स्थापना का आदर्श सामने रखना है । इसी से संसार में सामाजिक न्याय, समानता और शांति स्थापित हो सकती है ।

आज के सात पाप

ब्रिटिश इंस्टीट्यूट की पत्रिका "डायरेक्टर" के अनुसार आज "सात नये पाप" जिनका देश की आर्थिक प्रगति के साथ सम्बन्ध है, निम्नलिखित हैं—

(१) कल्पना रहित होना —शांत जीवन बिताने की इच्छा ।

(२) उद्देश्य हीनता—कोई सामने लक्ष्य न होना, जिसके लिए त्याग की भावना अथवा खतरा उठाने की आशंका पैदा हो ।

(३) अनिश्चयता—दिक्कतों व आर्थिक उथल-पुथल से तत्काल विचलित हो जाना

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(४) लचकीलापन न होना—नये तरीके और विचारों का परीक्षण करने में अनिच्छा ।

(५) हठधर्मिता—विदेशी बाजारों का अध्ययन और विदेशी प्रतिस्पर्द्धियों से सीखने से इंकार करना ।

(६) अनुदारता—"मालिक" और "नौकर" के रूप में विभक्त संसार के प्रति संकुचित दृष्टिकोण ।

(७) उदासीनता—सबसे अधिक भयंकर पाप ।

एशिया में सड़कों का निर्माण

१९५८ में जब इस्तमबुल से सैगांव और सिंगापुर तक सड़कें बनाने की योजना सामने आयी, उस समय सभी देशों में इसकी काफी चर्चा हुई । योजना के अनुसार एशिया की मौजूदा सड़कों की मरम्मत कराके उन्हें मोटरगाड़ियों के आने-जाने योग्य बनाया जाना है । योजना पूरी हो जाने पर एशिया में ३४ हजार मील लम्बी सड़कें हो जाएंगी, जिससे २५ लाख वर्गमील क्षेत्र में रहने वाले लगभग ६० करोड़ लोगों को लाभ होगा ।

नवम्बर, १९५८ में जब बैंकाक में इकाफे सम्मेलन हुआ था, उस समय सड़क निर्माण विशेषज्ञों के सामने एशिया में सड़कें बनवाने की योजना रखी गई थी ।

पूरी योजना तो बहुत बड़ी है, किन्तु तुर्की सीमान्त से सैगांव के बीच ६,५०० मील में सड़कें बनाने के काम को सबसे पहले किया जाएगा । कौन सी सड़कों की मरम्मत करायी जाएगी, यह भी तय कर लिया गया है । सड़कों के मरम्मत के काम में सम्बद्ध सरकारें काफी धन खर्च कर रही हैं ।

भारत में कलकत्ता और बैंकाक के बीच तथा पश्चिमी पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में सड़कों का सर्वे कराया जा चुका है । जल्दी ही लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम और इंडोनेशिया में भी सड़कों का सर्वे कराया जाएगा । सर्वे पर लगभग १९ लाख डालर खर्च किया जाएगा, सर्वे के बाद जहां जरूरी होगा, वहां निर्माण कार्य विशेष तत्परता के साथ किया जाएगा ।

इस काम के लिए अफगानिस्तान २० करोड़ डालर, पाकिस्तान ३ करोड़ डालर, भारत लगभग ७७ लाख डालर और ईरान ३० लाख डालर खर्च करेगा । इसके अलावा एशिया के कुछ अन्य देशों की सरकारों ने भी सहायता का आश्वासन दिया है । थाईलैंड और बर्मा की सरकारें सड़क का कुछ हिस्सा स्वयं बनवाएंगी ।

इस प्रकार एशिया में इस बड़ी सड़क के बन जाने से एशियाई देशों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और उनमें परस्पर सद्भाव बढ़ेगा ।

इस अन्तर्राष्ट्रीय सड़क योजना से एशिया के देशों को बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ भी होंगे । इससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा । जिन देशों की सीमाओं पर समुद्र नहीं है, उन देशों को विशेष रूप से ऐसी सड़कों से लाभ होगा । उन्हें अपने पड़ोसी देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ाने और समुद्र तट तक पहुँचने में बहुत सुविधा मिलेगी । ● ●

(पृष्ठ ४९९ का शेष)

गांधीवाद समस्त मानव समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हुए भी राष्ट्रीयता का पोषक है । वह आवश्यकताओं के न्यून करने पर जोर देता है और सादे जीवन तथा उच्च-विचार का पोषक है ।

मार्क्सवाद पाश्चात्य विचारधारा का क्रांतिकारी स्वरूप है, गांधीवाद पूर्वीय आध्यात्मिकवाद का सक्रिय स्वरूप है । मार्क्सवाद में मानव मूल्यों का कोई विशेष महत्व नहीं है, किन्तु गांधीवाद की आधारशिला मानव मूल्यों पर ही स्थित है ।

इस आधार पर स्पष्ट है कि दोनों में यथेष्ट अन्तर है । आचार्य विनोबा ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है—"हमारा दावा है कि सर्वोदय के सामने एक दर्शन है, यह दर्शन केवल परिस्थितियों के स्वरूप नहीं बना है । परिस्थिति के अतिरिक्त मनुष्य के स्वभाव और आध्यात्मिक भूमिका ध्यान में लेकर यह बना है । 'कम्यूनिज्म' एक प्रतिक्रियामात्र है । गांधीवाद प्रतिक्रिया नहीं । 'कम्यूनिज्म', 'कैपिटलिस्ट सोसाइटी' की प्रतिक्रिया है । सर्वोदय स्वयंभू विचार है, समन्वित विचार है और समग्र विचार है ।"

अन्त में गांधीवाद और समाजवाद का मेल गांधीजी के ही शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है । "समाजवाद की जड़ में आर्थिक समानता है, जैसे व्यक्ति के सब अंग बराबर होते हैं, वैसे ही समाजरूपी शरीर के सारे अंग भी बराबर होते हैं, यह समाजवाद है । इसे सर्वोदय भी कह सकते हैं । अन्ततः दोनों में समानता का आधार आर्थिक समानता की भावना ही है, भिन्नता के आधारों की शृंखला यथेष्ट लम्बी है ।" ● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस मास की आर्थिक घटनाएं

—१ जनवरी १९६४ से बाइसिकल उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा से मिलने वाला संरक्षण समाप्त हो जायगा। साइकल उत्पादक और व्यापारी मूल्य न बढ़ा दें, इस दृष्टि से १८ जुलाई ६३ के मूल्य अधिकतम मूल्य घोषित कर दिये जायेंगे। यदि इससे अधिक मूल्य रखने होंगे, तो सरकार की अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। सरकार ने यह निर्णय टैरिफ कमीशन की सिफ़ारिशें स्वीकार करके किया है। फुटकर विक्रेताओं को थोक मूल्य पर १५ प्रतिशत तक अधिक लेने का अधिकार होगा।

—सरकार ने बिजली से चलने वाले मोटर के उद्योग, बिजली वितरण और ट्रांसफ़ार्मर तथा रेशम बनाने के उद्योगों को ३१ दिसम्बर १९६५ तक संरक्षण देना स्वीकार कर लिया है।

—भारत सरकार ने सूती कपड़ा बनाने की मशीनों के उद्योग को और तीन वर्ष तक संरक्षण देने की सिफारिश मान ली है। अब उनको ३१ दिसम्बर १९६६ तक, मूल्य के १० प्रतिशत का घटा हुआ संरक्षण शुल्क जारी रहेगा।

चीनी के नये मूल्य

चीनी के मूल्य पर पुनर्विचार किया गया है और निश्चय किया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में चीनी के कारखाने पर के भाव में प्रति क्विन्टल ३ से ८ रु० तक की वृद्धि की जाए। नए भाव १८ नवम्बर से लागू हो गये। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे विभिन्न क्षेत्रों के कारखानों से ली गई चीनी के औसत भावों के आधार पर चीनी का वितरण करें, ताकि कम भाव वाले क्षेत्रों और ऊंचे भाव वाले क्षेत्रों के अन्तर का लाभ ग्राहक को पहुँचे, थोक व्यापारियों को नहीं।

एयर इंडिया ने पहला लाभांश दिया

एयर इंडिया के अध्यक्ष श्री जे० आर० डी० टाटा ने केन्द्रीय परिवहन मंत्री श्री राजबहादुर को ६६,६९,७२५ रु० का एक चैक दिया है। एयर इंडिया कारपोरेशन में सरकार की जितनी पूंजी लगी हुई है, उसका ५० प्रतिशत इक्विटी हिस्सा-पूंजी के रूप में है। उक्त चैक इस इक्विटी पूंजी पर ५ प्रतिशत के हिसाब से लाभांश के रूप में सरकार को दिया गया है। यह एयर इंडिया की इक्विटी पूंजी पर पहला लाभांश है। अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियां घाटे में चल रही हैं। एयर इंडिया को १९६२-६३ में काफी लाभ हुआ।

इस कारपोरेशन के विमान विश्व के २६ शहरों में जाते हैं। १९५४-५५ में इसके यात्रियों की संख्या ४० हजार थी, जो १९६२-६३ में बढ़कर १ लाख ६६ हजार हो गई। इसी प्रकार इसकी आय भी ४ करोड़ ८३ लाख रु० से बढ़कर २४ करोड़ ५३ लाख रु० हो गई।

—केन्द्रीय सरकार ने १९५५ के श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध व्यवस्था अधिनियम की धारा ९ के अन्तर्गत श्रमजीवी पत्रकारों का वेतन मण्डल नियुक्त किया है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, श्री जी० के० शिन्दे इसके अध्यक्ष हैं।

—भारत और हंगरी के बीच ५ वर्ष की अवधि का व्यापार और भुगतान समझौता हुआ है, जो १ जनवरी, १९६४ से लागू होगा। आशा है कि इस समझौते के फलस्वरूप १९६६ तक दोनों देशों का आपसी व्यापार दुगुना हो जाएगा। आजकल दोनों ओर से लगभग ८ करोड़ ५० लाख रु० का व्यापार हो रहा है। दोनों ओर से १९६४ में १२ करोड़ ५० लाख रु०, १९६५ में १४ करोड़ ५० लाख रु० और १९६६ में १७ करोड़ रु० का निर्यात होने लगेगा।

—राष्ट्रपति ने १९६३ के बम्बई के भूमि-अधिग्रहण (अवधि विस्तार) विधेयक को स्वीकृति दे दी है।

इस विधेयक में बम्बई भूमि-अधिग्रहण अधिनियम को ३१ दिसम्बर, १९६८ तक बढ़ाने की व्यवस्था की गयी है, क्योंकि वहां की आवास स्थिति में पर्याप्त सुधार नहीं हुआ है।

सम्पदा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संचालक, पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश

की

विज्ञप्ति संख्या ४।२२८० : २७।३३, दिनांक १५

द्वारा

पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत

सुन्दर पुस्तकें

		रु०	आ०
वेद सार	प्रो० विश्वबन्धु	१	८
प्रभु का प्यारा कौन ? (२) भाग			
सच्चा सन्त			३
सिद्ध साधक कृष्ण			
जीते जी ही मोक्ष			३
आदर्श कर्मयोग			३
विश्व-शान्ति के पथ पर			१
भारतीय संस्कृति	प्रो० चारुदेव		
बच्चों की देखभाल	प्रिंसिपल बहादुरमल	१२	१
हमारे बच्चे	श्री सन्तराम बी. ए.	३	१३
हमारा समाज		३	
व्यावहारिक ज्ञान		२	१२
फलाहार		१	४
रस-धारा		०	१४
देश-देशान्तर की कहानियां		१	
नये युग की कहानियां		१	१२
गल्प मंजुल	डा० रघुबरदयाल	१	
विशाल भारत का इतिहास	प्रो० वेदव्यास	३	८

१० प्रतिशत कमीशन और ५० रु० से ऊपर के आदर्शों पर १५ प्रतिशत कमीशन।

विश्वेश्वरानन्द पुस्तक भंडार

साधु आश्रम, होशियारपुर, पंजाब

आर्थिक समीक्षा

सम्पादक : श्री हरतीर्थ सिंह

- हिन्दी में अनूठा प्रयास
- आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख
- आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत

भारत के विकास में रुचि रखनेवाल प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक।

वार्षिक मूल्य : ५ रु० एक प्रति २२ नये पैसे

लिखें—व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, नई दिल्ली

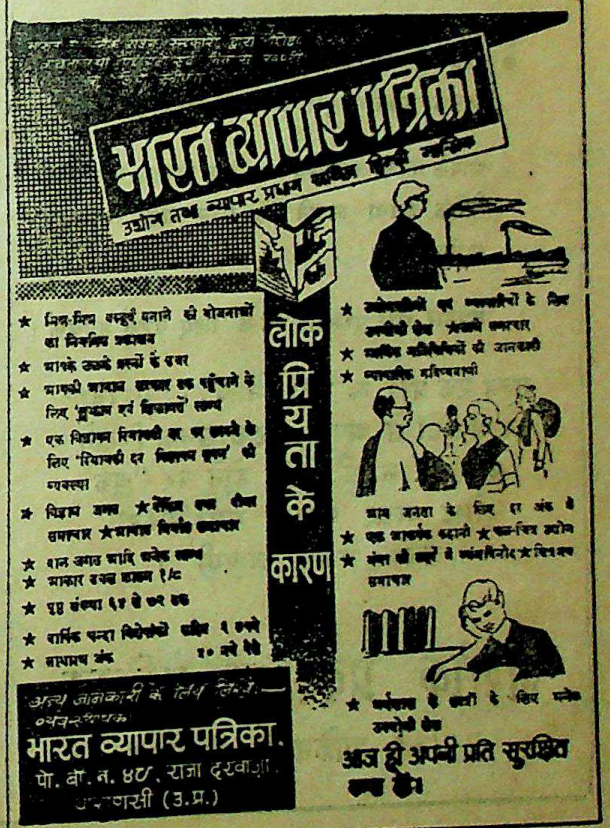

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

113079

सुभाषित रत्न-माला

दूसरा संस्करण

सम्पादक : कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

८ वर्ष पूर्व इस पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था और हाथों-हाथ बिक गया था कई वर्षों से यह पुस्तक अप्राप्य थी और इसकी मांग निरन्तर बढ़ रही थी। अब परिवर्धित संस्करण आकर्षक रूप सज्जा में प्रकाशित हुआ है। इस संग्रह में पढ़िये —

- वैदिक एवं संस्कृत-साहित्य के अगाध भंडार से चुने गये ऐसे सरल सुन्दर श्लोक और मंत्र, जिन्हें छोटे-बच्चे भी सुविधा के साथ कंठस्थ कर सकते हैं।
- प्रत्येक श्लोक और मंत्र का सरल सुबोध हिन्दी में अर्थ।
- पुस्तक के अंत में अर्थ-सहित कुछ ऐसी सूक्तियां, जिनका उपयोग छात्र अपने निबन्धों में कर सकें।

आपके बच्चों के स्वस्थ मानसिक विकास और उनमें नैतिक चेतना जगाने के लिए यह रत्न-माला अनिवार्य है।

उपहार और पुरस्कार देने के लिए बहुत उपयुक्त।

मूल्य एक प्रति रु. १.१५ न. पै.। "सम्पदा" के ग्राहकों से अपनी ग्राहक संख्या लिखने और ८५ न. पै. प्राप्त होने पर "बुक पोस्ट अंडर पोस्टल सार्टिफिकेट" द्वारा भेजी जाएगी।

अशोक प्रकाशन मन्दिर
२८/११ शक्तिनगर, दिल्ली-६

भारत की उद्योग नीति

लेखक :
प्रो० रामनरेश लाल

भारत सरकार ने १९४८ में जो उद्योग नीति निर्धारित की थी, १९५६ में संशोधन के बाद से वही आज भी हमारी उद्योग-नीति का आधार है। इसलिए उद्योग नीति को समझाने के लिए उक्त पुस्तिका का अध्ययन बहुत लाभदायक होगा।

मूल्य : डाक-व्यय सहित ७५ न. पै.

"सम्पदा" के ग्राहकों को अपनी ग्राहक संख्या लिखने और ६० न. पै. का टिकट भेजने पर रियायती मूल्य में यह पुस्तक भेजी जाएगी। वी० पी० से नहीं भेजी जाएगी।

अशोक प्रकाशन मन्दिर,
२८/११, शक्तिनगर, दिल्ली-६

जीवन साहित्य

हिन्दी के उन मासिक पत्रों में से है, जो—

* लोकरुचि को नीचे नहीं ऊपर ले जाते हैं,
* मानव-मानव से लड़ाते नहीं, मिलाते हैं।
* आर्थिक लाभ के आगे झुकते नहीं, सेवा के कठोर पथ पर चलते हैं।

जीवन साहित्य की सात्विक सामग्री को छोटे-बड़े, स्त्री-बच्चे सब निःसंकोच पढ़ सकते हैं। उसके विशेषांक एक से एक बढ़कर होते हैं।

वार्षिक शुल्क ४) रु. भेजकर ग्राहक बन जाइये

ग्राहक बनने पर मंडल की पुस्तकों पर आपको कमीशन पाने की भी सुविधा हो जायगी।

सस्ता साहित्य मंडल
नई दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सबसे सस्ता सचित्र हिन्दी मासिक

जागृति

जिसे भारत के सभी प्रमुख कवियों,
और कहानीकारों का सहयोग प्राप्त है।
उत्प्रेरक कविताएं, ज्ञानवर्धक लेख, सांस्कृतिक निबंध,
रोचक कहानियां, बाल संसार, साहित्य आगे
बढ़ता है, आदि स्तम्भ
तिरंगा आवरण, अनेकों इकरंगे चित्र
सम्पूर्ण छपाई आर्ट पेपर पर
इस पर भी मूल्य केवल २५ नये पैसे

एजेंटों को ५ से १० प्रतियों पर २५ प्रतिशत और इससे ज्यादा पर ३३⅓ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। डाक का खर्च प्रकाशकों के जिम्मे। एजेन्ट नमूने की प्रति के लिए आज ही लिखें।

—सूचना व प्रकाशन विभाग चण्डीगढ़ (पंजाब)

आरसी

(सचित्र पारिवारिक मासिक)

कहानी * कविता * लेख * कढ़ाई * बुनाई * पाठशाला * माँ और शिशु * ढोलक के गीत * बाल-मन्दिर * चलचित्र-जगत् * पुस्तक परिचय * इसके साथ ही प्रति माह एक कढ़ाई का नमूना उपहार में।

१ प्रति, ५० न० पै० वार्षिक मूल्य ६.०० रु०

आज ही ग्राहक बनिये।

विशेष सूचना—आरसी का अगस्त अंक "राजेन्द्र-स्मृति-अंक" था। एजेन्ट अपनी प्रतियां मंगवा लें।

व्यवस्थापिका, आरसी, श्वाकर टाउन
सिकन्द्राबाद (आ० प्र०)

हिन्दी का एकमात्र
विशिष्ट महिलोपयोगी मासिक

शृङ्गार

- जो सुखी पारिवारिक जीवन का आदर्श पथ-प्रदर्शक है
- जिसे सुप्रसिद्ध लेखिकाओं, लेखकों, पत्रकारों, चित्रकारों कवयित्रियों तथा कवियों का सहयोग प्राप्त है।
- जिसे ५०००० से ऊपर की संख्या में पाठक प्रतिमास पढ़ते हैं।
- जिसकी प्रतियां न्यूज़ एजेन्टों के पास पहुँचते ही समाप्त हो जाती हैं।
- जो महिला जागृति का प्रतीक है। जो सबकी प्रिय पत्रिका है।

वार्षिक : सात रुपये
एक प्रति : ६० नये पैसे

सम्पादका : लावण्य प्रभा

कार्यालय : १३।३७, शक्तिनगर, दिल्ली-६।

खादी पत्रिका

* खादी ग्रामोद्योग तथा सर्वोदय विचार पर विद्वत्तापूर्ण रचनाएं।
* खादी ग्रामोद्योग आन्दोलन की देशव्यापी जानकारी।
* कविता, लघुकथा, मील के पत्थर, साहित्य समीक्षा, संस्था परिचय।
* सांख्यकी पृष्ठ आदि स्थायी स्तम्भ।
* आकर्षक मुख पृष्ठ, हाथ कागज पर छपाई।

वार्षिक मूल्य ३) रु., एक प्रति पच्चीस नये पैसे

संपादक—ध्वजाप्रसाद साहू, जवाहिरलाल जैन
राजस्थान खादी संघ, पो. खादीबाग, (जयपुर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद का मुख्य पत्र

स्वस्थ जीवन

प्रधान सम्पादक — श्री राधकृष्ण नेवटिया
प्रबन्ध सम्पादक — श्री धर्मचन्द सरावगी
एक प्रति ५० न० पै० — वार्षिक ५) रुपया मात्र

साहित्य के साथ अपने सुन्दर स्वास्थ्य के लिए कविता, कहानी, संस्मरण तथा डायरी और परिषद की गतिविधि पढ़ें। आज ही पांच रुपया भेजकर ग्राहक बन जाइए। विज्ञापन देकर लाभ उठावें। सहयोगी बन्धु अपनी नवीन कृतियां हमें भेजें।

कार्यालय :—

"जैन हाउस"

८।१ एस्प्लेनेड ईस्ट,
कलकत्ता-१

ग्राम राज

(मास में तीन बार प्रकाशित)

सम्पादक—श्री गोकुलभाई भट्ट

"ग्रामराज बहुत ही शानदार और बहुत ही सुन्दर पत्र निकल रहा है। सब तरह की जानकारी इसमें रहती है। राजस्थान के हर शिक्षित भाई बहन के हाथ में यह पत्रिका होनी चाहिए।" — विनोबा

वार्षिक चन्दा ३) रु०

कार्यालय का पता :

ग्रामराज, किशोर निवास
जयपुर

उषा

* सामाजिक कहानियां, शिक्षाप्रद कथानक विचारोत्तेजक, मनोरंजक लेख, राशिफल, सरस कविताएं आदि।
* हानिकारक वस्तुओं व अश्लील फिल्मों के विज्ञापन स्वीकार नहीं किये जाते।

—यदि आपने अभी तक उषा नहीं देखी है, तो शीघ्र ही ३२ न. पै. के टिकिट या मनि-आर्डर भेजकर नमूनाँक मंगा देखिये। हमें पूरा विश्वास है कि एक बार 'उषा' को देखने के बाद आप हमेशा के लिए उसके हो जाएंगे।

: अन्य जानकारी के लिए लिखिये :

सचित्र मासिक उषा कार्यालय,
जवाहर मार्ग, इन्दौर।

शीघ्र ही प्रेस में जा रहा है—

न र्म दा

का

पं० बालकृष्ण शर्मा नवीन अंक

इस विशेषांक की सबसे बड़ी विशेषता पत्रकार प्रव पं० बनारसीदास चतुर्वेदी को लिखे गए उनके व्यक्ति पत्रों का प्रकाशन होगा, जो स्व० नवीनजी का अलमस्ती हंसोड़ वृत्ति और निश्छल स्नेह भाव का एक अंत्यन मनोहर रूप पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर देंगे।

इस विशेषांक द्वारा नर्मदा का प्रयास नवीन जी के साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और मानवीय व्यक्ति गत विविध पक्षों पर पूरा प्रकाश डालने का है।

इस विशेषांक के सम्पादक हैं :

पं० बनारसीदास चतुर्वेदी • श्री शम्भुनाथ सक्सेन

पृष्ठ संख्या १५०, अनेक व्यक्तिगत व पारिवारिक चित्रों सहित · मूल्य ३ रु०

नर्मदा कार्यालय, नूतन प्रिंटिंग प्रेस,
ग्वालियर (म० प्र०)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Gu. Pad
1959-2059

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri